ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਚੰਡੀਗੜ।

ਮਿਤੀ	ਵਾਲੀਯਮਜ	ਨੰ:	ਹੋ
3.11.65	2	15	1
4.11.65 (ਸਵੇਰ)	2	16	1
4.11.65 (ਸ਼ਾਮ)	2	17	1
5.11.65	2	18	1
15.11.65	2	19	1
16.11.65	2	20	1
17.11.65	2	21	1
18.11.65	2	22	1
19.11.65	2	23	1
22.11.65	2	2 4	1
23.11.65	2	25	1
24.11.65	2	26	1
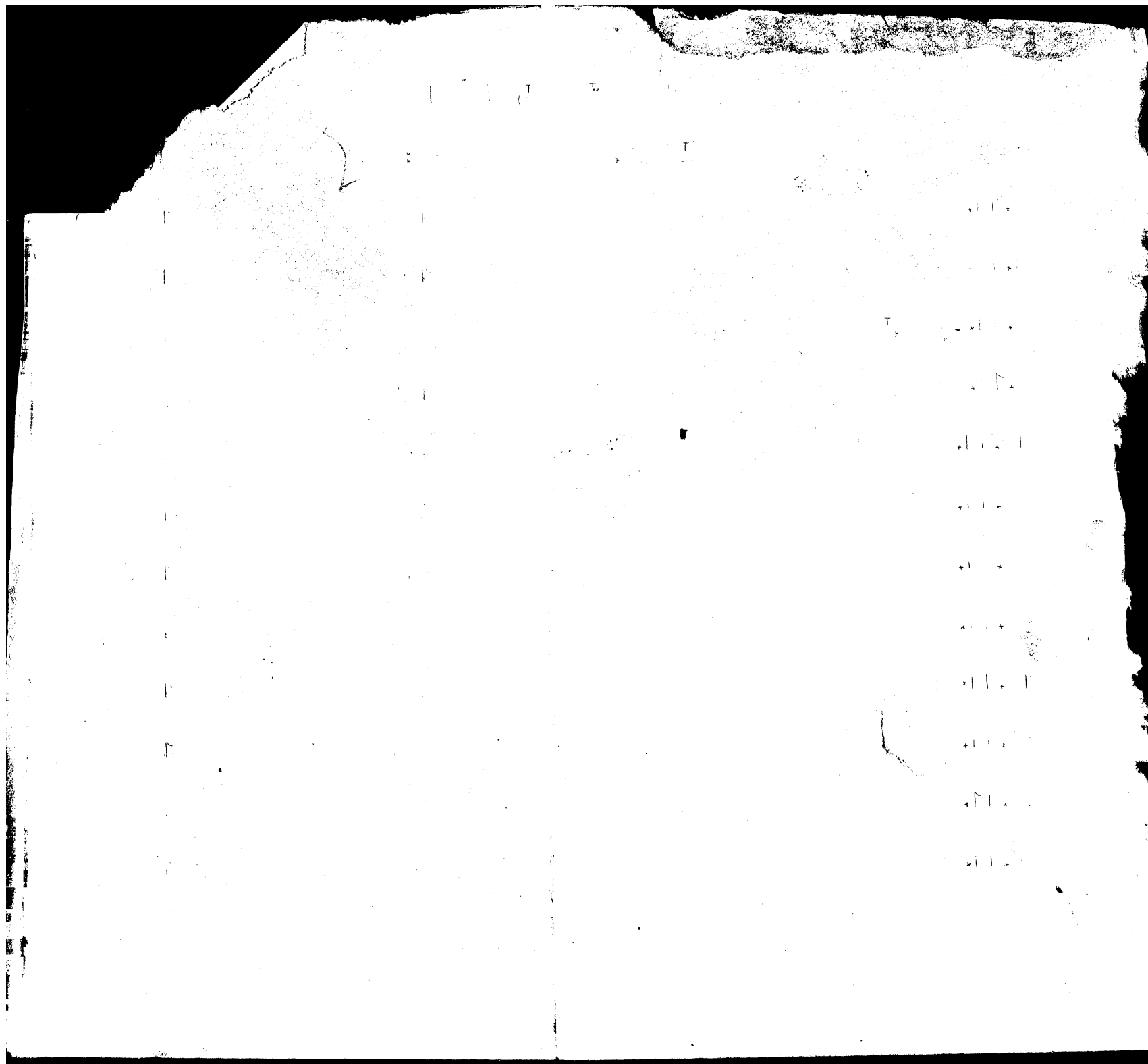
Punjab Vidhan Sabha Debates

3rd November, 1965

Vol. II—No. 15

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Wednesday, the 3rd November, 1965

Price : Rs. 4.75 P.

ERRATA

TO

PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATES, VOL. II, NO. 15, DATED THE 3RD NOVEMBER, 1965

Read	*For*	*Page*	*Line*
admitted	adm tted	(15)12	6
infringes	isfringes	(15)19	19
ਕਰਾਂਗਾ	ਕਰਾਂਗੇ	(15)21	3 from below
में दी	म दी	(15)22	6
Government	G vernment	(15)23	4
इम्पार्टैंट	इम्पार्टेन्ट	(15)23	12
	इम्पार्टर्टैंट	(15)32	16 from below
इत्तिफाक	इत्तिफ क	(15)27	4
ब्राडकास्ट	व्राडकास्ट	(15)28	12 from below
कहे	कह	(15)28	12 from below
चौधरी नेत राम	चौधरी नेत राम	(15)30	5
Shri Yash Paul	Shri Yash pal	(15)30	20
ਕਾਮਰੇਡ	ਕਾਮਰਡ	(15)30	6 from below
पैटरीआटिज़म	ौटरीआटिज़म	(15)31	7
का	क	(15)32	4
Parliamentary	Parliamentry	(15)48	1
Minister	Ministers	(15)48	18
ਕਾਮਰੇਡ	ਕਮਰੇਡ	(15)58	9 from below
का मुलाहज़ा	मुलाहज़ा	(15)65	13 from below
मेकिंग	मैंगिक	(15)67	4 from below
Friend	Fr end	(15)68	11
रिटर्न	रिर्टन	(16)71	3
ਬਲਕਿ	ਕਿ ਬਲਿਕ	(15)72	3

PUNJAB VIDHAN SABHA

Wednesday, the 3rd November, 1965

The Sabha met in the Vidhan Bhawan, Sector 1, *Chandigarh at* 9.00 *a.m. of the Clock. Mr. Speaker (Shri Harbans Lal) in the Chair.*

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

श्री बलरामजी दास टंडन: स्पीकर साहिब, मेरे सवाल पर कब सप्लीमैंटरी करने की इजाजत दी जाएगी ?

श्री अध्यक्ष : वह भी प्रापर टाईम पर टेक अप किया जाएगा । (It will be taken up at the proper time.)

श्री बलरामजी दास टंडन : मेरा विचार है कि वह सवाल इस सैशन में दोबारा नहीं आ सकेगा ।

श्री अध्यक्ष : वह सवाल आएगा । (It will be taken up).

Representation from the residents of certain villages in tehsil Nurpur, district Kangra for supply of drinking water

***8464. Comrade Ram Chandra :** Will the Minister for Health be pleased to state—

(a) the names of villages in Nurpur Tehsil, district Kangra, the residents of which have applied to the Department for the supply of sanitary drinking water since January, 1965 up-to-date ;

(b) whether the Health Department has so far made any survey of the said villages and submitted any schemes with estimates for the supply of drinking water to the residents thereof ?

Shri Prabodh Chandra (Education Minister) :

(a)—(1) Palli.
(2) Jakhahra.
(3) Chulhar.
(4) Patti Barwana.
(5) Patti Jattan.
(6) Sial.
(7) Piplan.
(8) Sanorth.
(9) Dihari.
(10) Mukhar.
(11) Muhar.
(12) Lahu Bandhar.
(13) Latwala.
(14) Rahang.
(15) Sukral.
(16) Bambhat.

[Minister for Education]

(17) Batkee.
(18) Kudha.
(19) Gadhauli.
(20) Bah.
(21) Bohal.
(22) Chander Nehar.
(23) Thather.
(24) Jeor.
(25) Harnooha.
(26) Jangoli.
(27) Tika.

(b) Directions have been issued by the Chief Engineer, Public Health to the field staff to survey these villages and collect the necessary data for the preparation of the estimates of these villages.

कामरेड राम चन्द्र : जिन देहातियों ने डिपार्टमेंट को दरखास्तें भेजी थीं कि उन को पीने का पानी मुहैया किया जाए, उस के बारे में सरकार ने मुझे जो लिस्ट सप्लाई की है, वह मुकम्मल नज़र नहीं आती है, क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इस लिस्ट में बाकी गांवों को शामिल कर लिया जाएगा और कंसंर्ड चीफ इंजीनियर को हिदायत भेज दी जाएगी कि जो बाकी गांव रह गए हैं, उन का सर्वे भी कर दिया जाए ताकि उन्हें पीने का पानी मिल सके ?

Minister : Sir, the hon. Member should be grateful if something could be done about these villages. In view of paucity of funds, there is hardly any scope for the water-supply arrangements to be made in these very villages. Sir, it will not be any satisfaction for the hon. Member if I prolong the list.

Comrade Ram Chandra : Sir, may I draw the attention of the hon. Minister for Education to the fact that even survey takes months and years. The Government would not have to incur very great expenditure if survey is carried out. The question of sanctioning the amount will arise much later.

Minister : Sir, when survey is carried for water-supply or other health schemes, wrong hopes are created in the minds of the people of the area that something will be done and when that thing is not done, the people feel disillusioned and dismayed. Therefore, to avoid disillusionment, the Government is taking up survey of only those villages which are likely to be benefited in the near future.

Raids on Beoparis/Traders indulging in adulteration

***8634. Comrade Ram Chandra :** Will the Minister for Health be pleased to state the number of raids conducted in the State during 1964-65 and 1965-66 (todate on the premises of big beoparis and traders responsible for adulteration together with the results of such raids ?

Shri Prabodh Chandra (Education Minister) : A statement is laid on the Table of the House.

Statement regarding raids conducted for seizing of sample from Big Ecoparis durin 1964-65, 1965-66 under the prevention of Food Adulteration Act, 1954.

1964-65

Number seized	Sent to P.A.	Found adultera-ted	Prosecu-tion launched	Convic-- tions	Acquit-tal	Fine	Impri-sonment	Fine and impri-sonment (Both)	Amou
									Rs
4,905	4,569	1,158	1,416	1,400	98	838	52	510	1,03,245
1965-66									
2,691	1,979	438	398	383	43	184	19	190	40,387

कामरेड राम चन्द्र : 1964-65 में 4905 जगहों पर रेड्ज़ किए गए और उन केवल 1158 केसिज़ में ही एडल्ट्रेशन करते हुए साबित हुए। इस तरह से काफी संख्य में लोगों को रेडज़ करते हुए हरासां किया गया। क्या मंत्री महोदय कृपया बतायेंगे कि सरकार ने लोगों को इस हैरासमेंट से बचाने के लिये कोई स्कीम बनाई है और क्या कार्यवाह करना चाहती है ?

Minister : Sir, as the hon. Member knows, there is nothing wron about the raids. In between the raids and the findings of the Court, a number of things happen. That is why the case fails. To begin with the raids are done in right earnest.

कामरेड राम चन्द्र : वज़ीर साहिब ने फरमाया है कि जहां पर रेड्ज़ किये जात वहां पर एडल्ट्रेशन होने में फर्क पड़ता है। 1964-65 में 4905 रेड्ज हुए, उन में 40 के करीब केसिज ड्राप किए गए, 4596 के पी. ए. को सैम्पल्ज भेजे गए, 1158 केसिज़ म एडल्ट्रेशन साबित हुई। इन फिगर्ज़ से साबित होता है कि काफी लोगों को रेड्ज करत वक्त तंग किया जाता है। मैं मंत्री महोदय से दरियाफत करना चाहता हूं कि लोगों को इस हैरासमेंट से बचाने के लिये सरकार क्या कदम उठाना चाहती है ?

Minister : I have, Sir, already explained that when the raids were made, they were made in right earnest and on the basis of the information that there was adulteration. There are, Sir, certain stages in the process of law. When the enquiry starts some people can manage or can afford to meet some Inspectors and it is with their connivance that some of the cases fail.

श्री अमर सिंह : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह ठीक है कि इंस्पैक्टर दुकानदारों से महीनावार रुपये लेते हैं और जो दुकानदार उन इंस्पैक्टर्ज़ को पैसे देने से इन्कार कर देते हैं, वह उन की दुकानों पर रेडज़ करते हैं और उन को अननेसैसरीली हैरास किया जाता है ?

मन्त्री : माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है, उस में कुछ सदाकत है। गवर्नमेंट के इल्म में है कि इंस्पैक्टर्ज़ ने दुकानदारों से माहवारी बांधी हुई है। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता लेकिन सरकार उन की बुरी आदतों को रोकने के लिये जल्दी से जल्दी कदम उठाने की कोशिश कर रही है।

श्री श्रोम प्रकाश अग्निहोत्री : सवाल के जवाब से पता चलता है कि 440 केसिज में एडल्ट्रे-
शन साबित न होने के कारण केसिज वापस लिये गये। क्या मंत्री महोदय कृपया बतायेंगे
क इन केसिज़ को वापिस लेने की क्या वजह है? क्या इंस्पैक्टर्ज़ ने गलत चालान किए
? अगर उन्होंने गलत चालान किये थे तो उन इंस्पैक्टर्ज़ के खिलाफ क्या ऐक्शन लिया
ा रहा है ?

मन्त्री : मैं ने हाउस से कोई भी बात छुपाने की कोशिश नहीं की। मैं ने पहले
ी अर्ज़ की कि कुछ इंस्पैक्टर्ज़ हेरा फेरी करते हैं और उन्होंने दुकानदारों से माहवारी बांधी
ई है। सरकार इस बात को अच्छी तरह से जानती है और सरकार कोशिश भी कर रही
कि उन की इस बुरी आदत को ही जल्दी ही रोका जाए। इंस्पैक्टर्ज़ की तंखाह 100
ा 150 रुपए होती है लेकिन उन्हें ऊपर से ज्यादा रुपए मिल जाते हैं। कई केसिज़ में
ह दुकानदारों से मिल जाते हैं जिस की वजह से कई केसिज़ फेल हो जाते हैं।

कामरेड राम प्यारा : मंत्री महोदय ने जवाब देते हुए फरमाया है कि गवर्नमेंट के
ोटिस में है कि इंस्पैक्टर्ज़ ने दुकानदारों के साथ माहवारी बांधी हुई है। क्या वज़ीर साहिब
ताने की कृपा करेंगे कि सरकार को इस बारे में कब से इल्म है और इस बुराई को दूर
रने के लिये कब से प्रबन्ध कर रही है ?

मन्त्री : जैसे जब से दुनिया बनी है तब से ही ऐसी बुरी आदत चल रही है। हम कोशिश
र रहे हैं कि इस बुरी आदत को जल्दी से जल्दी रोका जाए।

Pandit Chiranji Lal Sharma: Sir, may I know from the hon. Minis-
er for Education whether in view of the mal-practices of the Pure Food
nspectors, the Government is considering the desirability of appointing
Gazetted Officers for stopping or putting an end to such practices ?

Minister: Sir, there is already supervision over these Inspectors.
But there is a limit to the number of Gazetted Officers who can be de-
ployed to look after and control these Inspectors. Unless the human
nature changes, there is likelihood of the lapses occurring here and there.

श्री सुरेन्द्र नाथ गौतम : आम तौर पर छोटे दुकानदार ही एडल्ट्रेशन के केस में
पकड़े जाते हैं और उन को तंग किया जाता है। क्या सरकार इस चीज़ को मुख्य रखते
हुए फस्ट स्टेज पर रेड करने के लिये तैयार है ताकि बड़े २ दुकानदार और मैनूफैक्चरर्ज़
ही पकड़े जा सकें ?

मन्त्री : हां जी। सरकार फस्ट स्टेज पर सैम्पल्ज़ लेती है और उन बड़े २ घाघों
को पकड़ने की कोशिश भी करती है लेकिन इस में मुश्किल यह है कि जब उन को पकड़ते
हैं तो वह इस ज़िम्मेदारी को अपने ऊपर लेने से इन्कार कर देते हैं। वह कहते हैं कि जब
हम माल बेच देते हैं तो उस के बाद हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं रह जाती है। वह तो
छोटे २ दुकानदारों पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वह माल खरीदने के बाद एडल्ट्रेशन करते हैं।
इस बारे में हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि मैनूफैक्चरर्ज़ और बड़े २ दुकानदारों ने एडल्ट्रेशन
की। उन के सैम्पल्ज लिये जाते हैं अगर उन की चीजों में एडल्ट्रेशन की हुई साबित हो
जाए तो उन के विरुद्ध ऐक्शन लिया जाता है।

कामरेड राम चन्द्र: जब सरकार को इल्म है कि बड़े २ दुकानदार ही चीज़ों मे एडल्ट्रेशन करते हैं तो क्या इस के बारे में सरकार कोई कदम उठाने का विचार रखती है कि जिन देहाती छोटे दुकानदारों ने वाकई एडल्ट्रेशन न की हो उन को तंग न किया जाए ?

मन्त्री : मैं ने पहले अर्ज़ किया है कि जिन केसिज़ में यह पता लग जाए कि बड़े मैनुफैकचरर्ज़ ने एडल्ट्रेटिड माल सप्लाई किया है तो उन को पकड़ते हैं और छोटे दुकानदारों को छोड़ देते हैं। मगर कई गुनाह हमारी नज़रों के सामने होते हैं लेकिन हम मजबूर होते हैं। दुनिया जैसी है आप जानते ही हैं।

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਸਿਲ-ਸਿਲੇ ਵਿਚ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਬਲਾਕਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਥੇ ਕਿ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਐਗ੍ਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਤਹਿਸੀਲ ਜਾਂ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਨਾਲ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ?

ਮੰਤਰੀ : ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸੀਲੈਕਟਿਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਰਖ ਕੇ ਉਥੇ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਸਜੈਸ਼ਨ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਉਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗ਼ੌਰ ਕਰੇਗੀ।

Pandit Chiranji Lal Sharma : Will the hon. Minister for Education, in view of this clear and straightforward admission that this is a deep rooted disease, kindly state whether the Government finds itself helpless to put an end to this mal-practice ; if so, what measures it proposes to take in this direction ?

मन्त्री : कई केसिज़ में हम हैल्पलैस भी महसूस करते हैं। हमारी नज़रों के सामने बेईमानी होती लेकिन कानून ऐसा कम्पलीकेटिड है कि वे लोग निकल जाते हैं। अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश करते हैं कि इस बुरी आदत को दूर किया जाए। हम तो चाहते हैं कि एडल्ट्रेशन को ट्रीज़न के तौर पर ट्रीट किया जाए as it deals with the health of the people and is more dangerous than any other thing. इस चीज़ को सामने रखते हुए गवर्नमैंट पूरा ज़ोर लगा रही है कि एडल्ट्रेशन की बुरी आदत को दूर किया जाए।

पंडित मोहन लाल दत्त : क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जिन खाने पीने की चीज़ों का प्रबन्ध सरकार के हाथ में है जैसे कि दूध वगैरह के प्लांट हैं और जहां पर क्रीम वगैरह बनती है वहां जो एडल्ट्रेशन होती है उस को बंद करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

Minister : Sir, the human nature is the same every where; whether he is a Government employee, a private practitioner or a private shopkeeper. So, unless we are angels and change the human nature, these things will continue to happen. But, we are doing our best to weed out such corrupt officials at least from the Government Establishment.

कामरेड राम चन्द्र : क्या मैं दरियाफत कर सकता हूं कि आया गवर्नमैंट कोई ऐसी कार्यवाही कर रही है कि जिस से तमाम तर तवज्जोह एडल्ट्रेशन के सिलसिले में बड़े बड़े व्योपारियों को ही पकड़ने पर लगाई जाए और देहात के लोगों को हैरास न किया जाए?

Mr. Speaker: This question has already been replied to.

चौधरी अमर सिंह : क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि साल 1964-65 में बहुत ज्यादा रेड हुए हैं, इस का क्या कारण है?

मन्त्री : गवर्नमैंट ने कुछ इंटैंसिव एरियाज़ मुकर्रर किये थे और कुछ वीक्स भी फिक्स किये थे कि जिस तरह से कुछ हफ्ते मनाए जाते हैं उसी तरह से एडल्ट्रेशन को रूट आऊट करने के लिये खास खास दिन मनाए जाएं। आई एम नाट डबली शोयर कि कितने दिन मनाए गए हैं लेकिन गवर्नमैंट ने ऐसी इंस्ट्रक्शन ज़रूर दी थीं कि जो लोग एडल्ट्रेशन करते हैं वे देश के सब से बड़े दुश्मन हैं, देश को उन से निजात दिलाई जानी चाहिये।

Export of Milk from Gurgaon to Delhi

***8751. Shri Roop Lal Mehta** : Will the Minister of State for Animal Husbandry and Agriculture be pleased to state—

(a) whether it is a fact that milk worth a crore of rupees is exported from Gurgaon to Delhi ;

(b) the details of the steps so far taken to improve the breed of milch cattle ;

(c) whether the Government propose to entrust the export of milk to the Milk Co-operative Societies so that milch cattle owners may get a fair price for their product and produce better quality of milk ;

(d) whether any complaints have been received by the Government to the effect that the Delhi Milk Supply Scheme authorities secure the supply from interested persons for benefiting their own scheme and better quality of milk is not supplied if so, the action taken therefor ?

Captain Rattan Singh : (a) No information is available on this subject as the sale of milk is made by private producers directly to interested parties.

(b) A statement is laid on the Table of the House.

(c) No.

(d) No.

Statement

The details of the steps so far taken in the Gurgaon District to improve the breed of milch cattle.

(i) Under the All India Key Village Scheme, two Key Village Centres at Faridabad and Ballabgah are functioning. Each A.I Centre has six Key Village Units. During the year, 1964-65, 338 cows and 644 buffaloes were artificially inseminated at the A.I. Centre was started towards the end of the 1964-65.

(ii) 138 pedigree Hariana bulls and45 Murrah buffalo bulls were supplied by Government for the Development of cows and Buffaloes from it, 570 cow-bulls and 162 Murrah buffalo bulls were supplied out of the Zila Parishad funds for the improvement of the breed of cattle and buffaloes.

(iii) Under the Scheme for the Preservation of top-class milk yielding animals, 11 cows and 11 buffaloes received subsidy. The former at Rs. 20 per mensem and the latter at Rs. 25 per mensem. In addition, 59 selected calves received a subsidy of Rs. 10 per mensem each out of the above mentioned schemes for the preservation of the top-quality animals and All India Key Village Scheme.

(iv) Four Gaushalas, one each at Gurgaon and Bawal and two at Rewari in Gurgaon District has been developed at Rs. 13,000 each for the production of more milk and pedigree animals.

श्री रूप लाल मेहता : दिल्ली मिल्क सप्लाई स्कीम अपने दूध की सप्लाई बल्लभगढ़ आदि सेंटर्ज से हासिल करती है तो क्या मैं मन्त्री महोदय से यह पूछ सकता हूं कि उन्होंने यह इत्तलाह देने की तकलीफ क्यों नहीं की कि कितना दूध गुड़गांवां से दिल्ली को जाता है ?

राज्य मंत्री : दिल्ली मिल्क सप्लाई स्कीम गवर्नमेंट आफ इंडिया से सम्बन्ध रखती है इस लिये हमारे पास यह इनफर्मेशन नहीं है ।

श्री रूप लाल मेहता : यह इत्तलाह तो बल्लभगढ़, पलवल और सोहणा से आसानी से ली जा सकती थी, इस में कौन सी मुश्किलात थीं जिन की वजह से यह जवाब नहीं दिया गया ?

राज्य मंत्री : स्पीकर साहिब, इस का जवाब तो मैं दे चुका हूं ।

डाक्टर बलदेव प्रकाश : क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब में सर्विसिज़ के लिये और जनता के लिये दूध की कमी को पूरा करने के लिये सरकार ने तो यह हुक्म दे रखा है कि दूध से कोई क्रीम, खोया और दूसरी प्रेपेरेशन्ज़ न बनाए तो क्या यह बात सरकार के नोटिस में है कि पंजाब से गए हुए दो हजार मन दूध का रोज़ाना खोया दिल्ली में बनता है, और इतनी मात्रा में जो दूध पंजाब से बाहर जाता है उस को रोकने के लिये सरकार ने क्या सोचा है ?

राज्य मंत्री : कितना दूध जाता है और उस से खोया कितना बनता है इस की सही फिगर्ज़ तो किसी के पास नहीं हो सकतीं । हां, मैं गवर्नमेंट आफ इंडिया पर ज़ोर दे रहा हूं कि यह कानून दिल्ली में भी लागू किया जाए ।

श्री बलरामजी दास टंडन : क्या मंत्री महोदय इस का कारण बताने की कृपा करेंगे कि सरकार की जो अपनी डेरी फार्म्ज़ हैं वहां पर तो क्रीम और घी वगैरह दूध से तैयार किया जाता है लेकिन प्राइवेट लोगों को इस बात की इजाज़त नहीं है ?

राज्य मंत्री : श्री बलरामजी को तो पहले ही से मालूम है कि वेरका प्लांट में जितना भी घी वगैरह बन रहा है वह सब का सब डीफैंस फोरसिज़ के लिये बन रहा है ।

श्रीमती सरला देवी शर्मा : अभी अभी राज्य मंत्री महोदय ने बताया है कि उन्होंने सेंटर की सरकार को लिखा है कि दिल्ली में भी यही कानून लागू किया जाये, इस बात का यह ज़ोर दे रहे हैं, क्या मैं पूछ सकती हूं कि आया यह उन पर ज़ोर ही दे रहे हैं या कि उन का कोई जवाब भी इन को मिला है ?

राज्य मंत्री : मैं ने उन को लिखा नहीं है बल्कि मैं ने श्री सुबरामनियम से परसनली यह अर्ज़ की थी । उन्होंने कहा था कि हम पूरी कोशिश कर रही हैं कि यह कानून वहां पर भी लागू कर दें ।

श्री रूप लाल मेहता : मैं ने सवाल के पार्ट 'सी' में पूछा था कि आया सरकार दूध की एक्सपोर्ट का काम कोआप्रेटिव सोसाइटीज़ के हवाले करने का इरादा रखती है या नहीं। इस के जवाब में गवर्नमेंट ने कहा है कि नो। मैं पूछना चाहता हूं कि जब सरकार कोआप्रेटिव सोसाईटीज़ के काम को तरजीह देना चाहती है तो क्या वजह है कि यह काम उन के सुपुर्द नहीं किया जा रहा? प्राईवेट इंडीविजुअल्ज़ को क्यों यह काम दिया जा रहा है?

राज्य मंत्री : गुड़गांवां में इस लिये नहीं कर रहे क्योंकि दिल्ली मिल्क सप्लाई स्कीम का प्रोक्योरमेंट का अपना मैथिड है हम उस में टांग नहीं अड़ाना चाहते। लेकिन उन को यह बात कह रहे हैं कि जितना दूध खरीदना है हम डेरी फार्म्ज़ को लोन देंगे और आप उन से दूध खरीदें। हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं लेकिन जहां तक उन का क्वालेटी प्रेपेरेशन का ताल्लुक है हम उस में दखल अंदाज़ी नहीं करते।

डाक्टर बलदेव प्रकाश : इन्होंने कहा है कि सुबरामनियम से मिल कर इन्होंने परसनली बात की है। यहां तो मन्त्री महोदय सब बातें अपनी सेंटर से कह देते हैं लेकिन मैं पूछता हूं कि क्या उन्होंने इन की बात को सुना भी है?

राज्य मंत्री: बड़ी अच्छी तरह से सुनते हैं।

श्री रूप लाल मेहता : जवाब के बी पार्ट की स्टेटमेंट में इन्होंने बताया है कि 138 पिग्रीज हरियाणा बुल्ज़ की, 45 बफेलोज़ गवर्नमैंट द्वारा और 570 काउ बुल्ज़ और 162 बफेलोज़ जिला परिषद फंडज़ से डीवैपमेंट के लिये सप्लाई किये गये। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या वास्तव में यह जानवर उन को सप्लाई किये गये हैं कि केवल कागज़ों पर ही यह स्कीमें हैं?

राज्य मंत्री: पिग्रीज की तो कोई बात नहीं है, पैडीग्रीज़ ज़रूर हैं। यह फिगज़ कागज़ों पर ही नहीं हैं बल्कि सही हैं।

ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ : ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਨ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਦੁਧ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਮਿਲਟਰੀ ਪਰਸਾਨਲ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਘਿਉ ਨਾਭਾ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ : ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗਲ ਜਾਣ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨਾਭਾ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਧ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। (Cheers)

श्रीमती सरला देवी : राज्य मंत्री महोदय ने अभी अभी जवाब दिया है कि सैंट्रल गवर्नमैंट इन की बहुत सुनती है। क्या मैं उन से यह पूछ सकती हूं कि श्री सुब्रामनियम जी के साथ जब आप ने बात की तो उस के बाद उन की बात का कुछ थोड़ा बहुत अमल भी सामने आया है या नहीं?

ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਚਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਵਰਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਗਲ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਦੀ ਹੈ।

या और किसी तरह से इस सूबे के अंदर मुनाफरत फैलाने की कोशिश करते हैं, मैं समझ हूं वह इस सूबे के ही दुशमन नहीं हैं, बल्कि इस देश के दुशमन हैं । (*Interruptio*) अगर आप की मांग छोटी है तो दिल तो आपको बड़ा रखना चाहिये प्रार्थना यह है कि मैं सरदार गुरनाम सिंह जी से इत्तिफाक करता हूं और उन के स आवाज़ में आवाज़ मिला कर पंजाब गवर्नमैंण्ट से मुतालबा करता हूं कि कोई भी आद जो यह कहता है कि सिख पाकिस्तान के साथ मिल जायेंगे, वह देश के साथ गद्दारी करता और उस के लिये सरकार को ऐसा कदम उठाना चाहिए कि ऐसी सिचुएशन पैदा न हो। लेकि एक बात स्पष्ट कर दूं, हमें सिक्खों और अकालियों में तमीज़ करनी पड़ेगी। जहां तक इ वक्त की नाज़ुक परिस्थिति का सवाल है, मैं समझता हूं कि धैर्य से काम लेना चाहिए मैं ने पहले ही कहा है कि जहां तक सिक्खों का सवाल है, उनकी नीयत पर शक नहीं करन चाहिए। वह इस देश के नागरिक हैं। हमारा देश सैक्युलर है इस लिये हिन्दू सिख नाम पर कोई सवाल पैदा नहीं होता। इस देश की हर बात और हर चीज में सिख भी ही हिस्सेदार हैं, जितना कि कोई हिन्दुस्तानी नागरिक। जो पुरानी पृष्ठभूमि है, उस असहमति प्रकट नहीं करता लेकिन आज जो फिरकापरस्ती की बिना पर वोट मांगे जाते हिन्दू सिख के नाम पर वोट मांगे जाते हैं, इन पहलुओं को नज़रअंदाज़ नहीं किया ज चाहिए (विघ्न) और जो फिरकापरस्ती फैलाते हैं, हिन्दू सिख के नाम पर वोट मांगते हैं कम्यूनल डिसहारमनी क्रिएट करते हैं उस की इजाजत नहीं होना चाहिए। मेरी निश्चित राय कि यदि हमारे देश में कम्यूनल आधार पर राजनीतिक पार्टियां बनाने की इजाजत न दी जा तो आज हमारे देश में इतना तनाव न होता। (विघ्न)

Sardar Gurnam Singh : This gentleman is responsible for all trouble.

श्री अध्यक्ष : इस ऐडजर्नमैंट मोशन पर कोई रैगूलर बहस नहीं हो रही है। डिसअलाऊ हो चुकी है।(*Interruption by Shri Jagan Nath*)

Shri Jagan Nath, I am so sorry. You are Member in this House and you can take l लेकिन कुछ स्ट्रांग फीलिंग्ज़ हैं इस लिये मैं ने एक एक दो दो मिनट बोलने क दे दी है कि ग्रुप लीडर्ज़ अपनी अपनी बात कह लें। लेकिन रेगूलर डिसकशन नह (No regular discussion on this adjournment motion has b allowed. In fact the motion has already been disallowed (*Interruption by Shri Jagan Nath*)

(Shri Jagan Nath, I am so sorry. You are a new Member in this House and you can take all liberty.

I have allowed the group leaders to speak for one or two minutes each because of the strong feelings on the subject, so that they may express their views on it. But regular discussion would not take place.)

Sardar Gurnam Singh : Shri Yash is a prominent member of this Ekta Samiti and they have stated that the Punjabi Suba demand is supported by Pakistan.

Shri Yash Pal : I am not a member of this Ekta Samiti. I contradict it. The hon. Member should not make a misstatement.

इस एकता समिति के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैं इस का मैम्बर भी नहीं हूं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : अगर किसी मैम्बर के खिलाफ इस हाउस में कोई ... लगाया जाए और वह उसे कंट्राडिक्ट कर दे फिर भी अगर कोई चार्ज ... परसिस्ट करता है तो मैं समझता हूं कि इसकी इन्क्वायरी करनी पड़ेगी ।

(If a charge is levelled by a Member against another and despite latters cantradiction, the former persists in making that allegation, then I feel the matter requires investigation.)

Shri Yash Paul : I am prepared for it.

Sardar Gurnam Singh : Yes please, make the enquiries.

चौधरी देवी लाल (फतेहबाद) : स्पीकर साहब, चूंकि एकता समिति की तरफ से मैमोरेंडम पेश किया गया है, इस लिये यह मामला बहुत ज्यादा अहम है। इस पर देश की किस्मत का फैसला होना है। मैमोरेंडम में यह क्लियरली कहा गया है कि अगर यह सिख सूबा बन गया तो पाकिस्तान को इजाज़त होगी कि वह सिख सूबे में से गुज़र कर हिन्दुस्तान पर हमला करे। यह कहते हैं कि मैं मैम्बर तक नहीं हूं, लेकिन मैं यह बतलाना चाहता हूं कि इनकी सदारत में ही एकता समिति की मीटिंग हुई और उस एकता समिति का सबूत आज यह मिला कि कितना तूफान उठ रहा है। इसलिये मैं गुज़ारिश करूंगा कि जिस कौम की प्रशंसा में देश का राष्ट्रपति ब्राडकास्ट करे और होम मिनिस्टर ब्राडकास्ट करे और कहे कि इस कौम ने देश की रक्षा की है और यह भी कहा कि कि संत फतेह सिंह बड़े देशभक्त हैं और इन्होंने ऐसे मोके पर अपना व्रत तोड़ कर देश की बड़ी भारी मदद की है और उस कौम को गद्दार कहें, यह बहुत ही अफसोसनाक बात है। स्पीकर साहब, इनका तो ... ही बन चुका है। आज मुझे भी ग़द्दार कहा जा रहा है। जब मैं सरदार प्रताप सिंह की ... करता था तो शेरे पंजाब कहलाता था और छोटू राम की मुखालफत करता था ... देशभक्त कहलाता था और आज यही अखबार मुझे ग़द्दार कहते हैं क्योंकि इनकी ... के खिलाफ में काम करता हूं। इनका क्या जब आपत्ति आएगी तो फाइलें लेकर हैदराबाद जा सकते हैं या त्रिवेन्द्रम जा सकते हैं लेकिन अपनी मातृभमि के लिये हमने लड़ना है, हम ने मरना है। मैं गवर्नमैंट को यह चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर ऐसी बातों की इजाज़त दी गई तो इस की जिम्मेदारी गवर्नमैंट पर होगी। मैं समझता हूं इसका हल यहां पर नहीं होगा। इसका हल करने के लिये तो दिल्ली की सरकार बैठी

है। यहां पर वावेला मचाने वाले तो चन्द खानदान ही हैं जो इस आग को भड़का
हैं। आप हिन्दुओं में रिफरैंडम करवा कर देख लें 89 परसेंट इस के हक में होंगे अ
सिर्फ 11 परसैंट ऐसे होंगे जो इस के खिलाफ होंगे जिन में यह आते हैं। सवाल
यह है कि इस पर दोबारा गौर करें और जो इस एडजर्नमेंट मोशन पर फैसला हो चुका
उस को स्पीकर साहब आप रिवाइज़ करें।

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ (ਰੋਪੜ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਮੈਂ, ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾ
ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਔਰ ਏਕਤਾ ਸਮਿਤਿ ਨੇ ਇਕ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਲ ਡਿ
ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਯਸ਼, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਫਿਰਕਾਪਰਸਤ ਅਖਬਾਰ ਪੰਜਾਬ
ਫਿਜ਼ਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਲਾ
ਭਰਦੇ ਰਹੇ (ਵਿਘਨ) ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਗ
ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਅਖਬਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔ
ਯਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਜੱਦ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ
ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਚੰਦ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਖਾਨਦਾਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ
ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਹਵਾ ਨੂੰ ਚੈਕ ਕੀ

(*Comrade Makhan Singh Tarsikka stood upto speak*)

Mr. Speaker : Mr. Tarsikka, please take your seat.

ਕਾਮਰੇਡ ਮਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਅਲਾਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰ
ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।

Mr. Speaker : Only Group Leaders have been allowed.
resume your seat.

ਕਾਮਰੇਡ ਮਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ : ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ।
ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਲਾਊ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਇਕ ਗਰੁਪ ਨੂੰ
ਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਸਦੀ ਬਾਹਰ ਉਚੇਚੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ।

Mr. Speaker : I am sorry. Two members cannot make a
Please take your seat.

ਕਾਮਰੇਡ ਮਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਅਲਾਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ?

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਕਾਮਰੇਡ ਤਰਸਿਕਾ, ਇਹ ਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ
ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੋ ਗਰੁਪਸ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਜ਼ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਆ ਗਏ ਹਨ।
(Addressing Comrade Makhan Singh Tarsikka) No regular discussion ca
take place on this motion. The views of the leaders of groups in th
Opposition have come.)

ਕਾਮਰੇਡ ਮਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿਕਾ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਕ ਗਰੁਪ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹਾਂ
ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੋਗ ਮਹਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ—ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਸ਼ੋਭਦਾ ਨਹੀਂ

Mr. Speaker ; I am sorry. Two members cannot make a gro
That convention cannot be set.

ਕਾਮਰੇਡ ਮਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। (ਵਿਘਨ) ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।

Mr. Speaker : Please take your seat. That cannot be allowed.

चौधरी नेत राम : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। स्पीकर साहिब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर यह है कि .... (विघ्न) (शोर)

श्री अध्यक्ष : चौधरी नेत राम, बैठ जाइए। (Chaudhri Net Ram may please take his seat.)

चौधरी नेत राम : स्पीकर साहिब, मैं भी कुछ कहना चाहता हूं।......

श्री अध्यक्ष : चौधरी नेत राम, मैं आप को वारनिंग देता हूं आप बैठ जाइए। (I warn the hon. Member, Chaudhri Net Ram, he should take his seat.)

चौधरी नेत राम : जब आप ने यह रूलिंग दिया है कि हर पार्टी के लीडर्ज़ बोल सकते हैं मैं भी एक आल इंडिया पार्टी को रिप्रेजंट करता हूं, मुझे भी इजाज़त दी जाए।

श्री अध्यक्ष : चौधरी नेत राम, आप को ग्रुप तसलीम नहीं किया जा सकता, आप बैठ जाइए। (The hon Member, Chaudhri Net Ram, cannot be considered as a Group. He should resume his seat.)

चौधरी नेत राम : मैं चाहता हूं कि फिरकापरस्ती को खत्म किया जाए (विघ्न)।

Mr. Speaker : Please take your seat.

Shri Yash pal : On a point of personal explanation, Sir.

श्री अध्यक्ष : देखिए, पर्सनल एक्सप्लेनेशन की बात तब उठेगी जब कोई ऐलीगेशन हो। एक एलीगेशन आप पे लगाया गया कि आप एकता समिति के मेंबर हैं, आप ने उसे कन्ट्राडिक्ट कर दिया। जो बात मेंबर साहिब पर रिफ्लेक्शन करती है मैं उस की इंक्वायरी करूंगा। और कोई एलीगेशन नहीं है। आप कोई दूसरा प्वायंट कह सकते हैं।

श्री यश पाल : सरदार गुरनाम सिंह ने कहा है कि हमने एकता कमेटी की तरफ से कोई मैमोरैंडम भेजा है। मेरी प्रार्थना है कि जिस एकता कन्वैन्शन के साथ मेरा ताल्लुक है उस ने अभी तक कोई मैमोरैंडम भजा ही नहीं। पता नहीं यह किसका ज़िक्र कर रहे हैं। मैं यह पोज़ीशन क्लीयर करना चाहता हूं।

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ। ਯਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਏਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਏਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।

ਮਿਸਟਰ ਸਪੀਕਰ : ਪਲੀਜ਼ ਟੇਕ ਯੁਅਰ ਸੀਟ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਮਿਸਟਰ ਯਸ਼ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ

Appointment of Director of Animal Husbandry

*8752. **Sardar Gurdarshan Singh :** Will the Minister of State for Animal Husbandry and Agriculture be pleased to state—

(a) the name of the person recently appointed as Director of Animal Husbandry ;

(b) whether it is a fact that the person referred to in part (a) above was appointed as such on some earlier occasion also; if so, the reasons why he was transferred from that post ;

(c) the reasons for which the said post was not advertised and whether Government intend to advertise it now ;

(d) the names and qualifications of the officers who were considered along with Shri M.S. Malhi for the said post together with the reasons for which they were ignored ?

Captain Rattan Singh : (a) Shri Mohan Singh Malhi.

(b) *First Part.*—Yes.

Second Part.—Unsatisfactory work.

(c) Shri Malhi has been appointed as Director, Animal Husbandry, in a purely stop-gap arrangement. The matter of regular appointment to the post is under the consideration of Government.

(d) Shri Malhi is the Senior most P.V.S. (Class I) Officer according to the Joint Seniority List. The question of ignoring any officer thus does not arise.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਡੰਗਰ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ...(ਹਾਸਾ) ਤੁਸੀਂ ਹਸਦੇ ਹੋ, ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਡੰਗਰ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । (ਫੇਰ ਹਾਸਾ)

श्री बलरामजी दास टंडन : श्रान ए प्वायंट श्राफ श्रार्डर, सर। मेरा प्वायंट श्राफ श्रार्डर यह है कि कम श्रज कम यह भाषा को मिक्स करके न बोलें। एक तरफ 'डंगर. शब्द इस्तेमाल किया है श्रौर दूसरी तरफ 'पालन'। या तो पशु पालन मन्त्री कहें या बिल्कुल दूसरी भाषा के शब्द कहें। इस तरह के श्रपमानजनक शब्द इन्हें नहीं कहने चाहिए। (हंसी)

श्री जगन्नाथ: श्रान ए प्वायंट श्राफ श्रार्डर, सर। क्या इस में खोता श्रौर ढोर मन्त्री नहीं चलता है ? (हंसी)

Mr. Speaker : Order please.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਡੰਗਰ ਪਾਲਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਣ ਸਨ ?

ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਐਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਰਸਨ ਸਿੰਘ : ਆਨਰੇਬਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਰਟ 'ਬੀ' ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵਰਕ ਅਨਸੈਟਿਸਫੈਕਟਰੀ ਸੀ । ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵਰਕ ਅਨ-ਸੈਟਿਸਫੈਕਟਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ?

ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ । ਫੇਰ ਰੀਪੀਟ ਕਰ ਦਿਓ ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ : ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਾਰਟ ਬੀ' ਵਿਚ ਇੱਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵਰਕ ਅਨਸੈਟਿਸਫ਼ੈਕਟਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਟਰਾਇਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਫੇਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

[ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ]
ਮੈਂ ਇਹ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਅਨਸੈਟਿਸਫੈਕਟਰੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਵਿਚ ਕੀ ਖੂਬੀ ਆ ਗਈ ਕਿਹੜੀ ਲਿਆਕਤ ਆ ਗਈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਫ਼ੇਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ?

ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ : ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਅਨਸੈਟਿਸਫੈਕਟਰੀ ਸਮਝਿਆ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦ ਕਿ 55 ਸਾਲ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ । ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਪਿਊਰਲੀ ਸਟਾਪ ਗੈਪ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ ।

कंवर राम पाल सिंह : क्या पशुपालन मन्त्री साहिब यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन डायरैक्टर साहिब को उन्होंने हटाया है उन को कोई पे दी जाती है या नहीं दी जाती और अगर दी जाती है तो क्या यह एक वेस्टफुल ऐक्सपैंडीचर नहीं है ?

ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ : ਜੋ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਵੇਸਟਫੁਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਸਟੇਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਬਰਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ—ਵਿਕਟੇਮਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ?

ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ : ਇਹ ਗਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ 55 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਉਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ—ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮਲ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਰੀਕੁਆਇਰਡ ਕੁਆਲੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਫੁਲਫ਼ਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਔਰ ਫੇਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ?

ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ : ਗਲ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ । ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਐਪੀਅਰ ਹੋਏ ਸੀ—ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਰਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਲਹੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ...........

ਇਕ ਆਵਾਜ : ਇਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ.........(ਵਿਘਨ)

......ਮਲਹੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਵਾਈ ।

ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ : ਔਰ ਇਕ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਕੋਹਲੀ ਸੀ। ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਟ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਐਪੀਅਰ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸ੍ਰੀ ਮਲ੍ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।

Sardar Gurnam Singh : May I know from the hon. Minister the duties that have been assigned to the previous incumbent of this post ; and if no duties have so far been assigned, is the Government going to assign some duties to him ?

ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਫ਼ੀਸਰ ਆਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ । ਬਾਕੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਮੇਰੇ ਬੁਜ਼ੁਰਗ—ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ । ਉਹ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ? ਜਦ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ।

ਕਾਮਰੇਡ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ : ਕੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਜਦ ਮਲ੍ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰ: ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੋਸਟ ਉਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ? ਕੀ ਇਸਦਾ ਇਹ ਕਾਰਣ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਸਨ ?

ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ : ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ।

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਕੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਊਟੀ ਉਤੇ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ?

ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ : ਵਾਰ ਅਵੈਕਟਿਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਵਿਚ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਸਪਰੈਡ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । 4 ਅਗਸਤ, 1965 ਨੂੰ ਅਪਣੀ 55 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਏ ਹਨ ।

Pandit Chiranji Lal Sharma : May I ask the hon. Minister for Animal Husbandry and Agriculture as to whether there used to be an Officer-on-Special duty in this Department prior to this appointment ?

Minister of State : I have no information.

ਕਾਮਰੇਡ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ : ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਦ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਉਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਬਰਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ?

ਰਾਜ਼ ਮੰਤਰੀ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ । ਗੌਰਮੈਂਟ ਅਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਲਈ ਅਸਾਂ ਇਕ ਚੰਗਾ ਆਦਮੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਹਾਂ । ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਘਾਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਵਿਚ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਆਦਮੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈਏ । ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਮਲ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਗੈਪ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਵਿਚ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

श्री फतेह चन्द विज : क्या मिनिस्टर साहिब बतायेंगे कि मल्ही साहिब के मुताल्लिक सरदार प्रताप सिंह कैरों को यह एतराज था कि उस ने जनरल इलैक्शन में कामरेड मक्खन सिंह तरसिक्का की मदद की और इसी लिये उस वक्त उन्हें नहीं लिया गया था ?

ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ : ਇਹ ਗਲ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ।

श्री सुरेन्द्र नाथ गौत्तम : मिनिस्टर साहिब ने अभी अभी बताया है कि मल्ही साहिब को बतौर स्टाप गैप अरेंजमेंट के लगाया है और जो रैगुलर एप्वायँटमेंट है वह सरकार के ज़ेरे गौर है। मैं उन से दरियाफत करना चाहता हूं कि उस रैगुलर एप्वायंटमेंट का काम आप कब तक पूरा कर सकेंगे ?

राज्य मंत्री : यह मामला गवर्नमैंट की एकटिव कनसिड्रेशन में है।

Sardar Gurdarshan Singh : Will the Minister for Animal Husbandry be pleased to state whether the present Director, Shri Malhi, ever represented to the Establishment Board against his supersession?

Minister of State: He did represent before the Establishment Board and his representation was admitted.

श्रीमती सरला देवी : क्या स्टेट मिनिस्टर साहब बतायेंगे कि जैसा कि उन्होंने अभी बताया है कि वह ज्यादा अच्छी कुआलीफिकेशन्ज़ वाला आदमी ढूंढ रहे हैं तो मैं पूछना चाहती हूं कि सरदार मोहन सिंह मल्ही जो इस वक्त डाइरैक्टर एनीमल हज़बेंडरी लगे हुए हैं उन की क्या कुआलीफिकेशन्ज़ हैं और जो आदमी वह ढूंढ रहे हैं वह किस कुआलीफिकेशन्ज वाला होगा ?

राज्य मंत्री : मैं ने कुआलीफिकेशन्ज़ की बात नहीं कही थी। मैं ने तो कहा था कि कोई अच्छा और योग्य आदमी ढूंढ रहे हैं।

चौधरी इन्दर सिंह : क्या पशु पालन मंत्री बतायेंगे कि जब दो दफा गवर्नमैंट के नोटिस में यह बात आ चुकी थी कि पहले डाइरेक्टर का वर्क अनसैटिसफैक्टरी है तो उस के खिलाफ क्यों एकशन नहीं लिया गया था ?

राज्य मंत्री : उस के खिलाफ और एकशन हम क्या ले सकते थे जब हम ने उसे डाइरैक्टर की पोस्ट से हटा कर डिप्टी डाइरैक्टर लगा दिया था।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਆਦਮੀ ਢੂੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਚੰਗੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਡੀਫਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤਾਕਿ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਦਮੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ?

ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ : ਚੰਗੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕੇ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਛਾ ਆਦਮੀ ਢੂੰਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ?

Minister of State : I have already stated, that is under the active consideration of the Government.

श्री रूप लाल महता : क्या मिनिस्टर साहिब बतायेंगे कि जिस आदमी को अब डाइरैक्टर एनीमल हज़बेंडरी लगाया गया है क्या उस की कुआलीफिकेशनज़ सरदार प्रीतम सिंह बरार से जो पहले इस पोस्ट पर लगा हुआ था जिस को हटा कर दूसरे को लगाया गया है बैटर हैं ?

राज्य मंत्री : मैं ने यह नहीं कहा कि उस की कुआलीफिकेशन्ज़ बैटर हैं। मैं ने तो यह कहा है कि वह सीनियर मोस्ट है इस लिये उसे लगाया गया है।

पंडित मोहन लाल दत्त : मिनिस्टर साहिब ने बताया है कि बरार साहब को आफीसर आन स्पेशल डियूटी लगाया गया है। तो मैं उन से पूछना चाहता हूं कि अब उन की स्पेशल डियूटीज़ क्या क्या हैं ?

श्री अध्यक्ष : इस का जवाब आ चुका है। (This has already been replied to)

ਕਾਮਰੇਡ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਮਲ੍ਹੀ ਸਾਹਬ ਨੂੰ ਇਸ ਪੋਸਟ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ? ਕਿਤਨੀ ਮਿਆਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ? ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ?

ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ : ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁਛੋ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ।

Arrangement for Girls Hostel in Government College, Dharamsala

***8742. Chaudhri Hari Ram** : Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) whether there is a girls Hostel for the Government College, Dharamsala ;

(b) if the reply to part (a) above be in the negative whether Government intends to make some hostel arragements for girls in the near future in the interest of the institution as also for the welfare of the backward area ?

Shri Prabodh Chandra : (a) No.

(b) 50 seated girls hostel will be provided in the IVth Five-Year Plan subject to the availability of funds.

Corruption Charge against an Assistant Excise and Taxation Officer, Karnal

***8797. Comrade Ram Piara** : Will the Minister for Finance be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that one of the Assistant Excise and Taxation Officers of Karnal district was caught taking a bribe red handed during the period from 1st July, 1965 to date; if so, his name, the date when he was so caught and the amount recovered from him ;

(b) whether it is a fact that upto the 29th September, he was not suspended; if so, the reasons therefor ;

(c) whether he received any communication on the above-mentioned subject during the period from 25th September, to 5th October, 1965, from any legislator of Karnal district as also from same business man of Shahabad district Karnal; if so a copy of the same together with the action, if any, taken thereon be laid on the Table of the House ;

(d) whether it is the policy of the Government/Department to suspend the Officer immediately in case he is caught taking a bribe red handed, if so, the reasons for departure from this policy in this case ;

(e) whether any responsibility has been fixed on any officer responsible for not suspending the officer referred to in part (a) above, if no responsibility has been fixed, the reasons for the same ;

(f) the final action, if any, taken by the Department so far together with the designation of the persons who ordered and asked the Department to suspend the A. E. T. O. with immediate effect ?

Sardar Kapoor Singh : (a) Yes, Sir. Shri Man Singh, Assistant Excise and Taxation Officer, Karnal (now under suspension) was apprehended at Pipli Rest House on the 13th August, 1965, after he had allegedly accepted a bribe of Rs 200.

[Minister for Finance]

(b) Yes, Sir. The reasons for delay were that the local officers had not intimated as to whether Shri Man Singh, Assistant Excise and Taxation Officer, had actually been arrested and detained in custody. This necessitated a back reference and subsequently the matter had to be referred to the Legal Remembrancer twice for the clarification of a legal point.

(c) Yes, Sir. A copy of the letter dated the 27th/28th September, 1965, received from Shri Ram Piara, M. L. A., and a copy of the reply sent to him are laid on the Table of the House.

(d) Yes, but because of the reasons indicated against (b) above the suspension orders could not be issued earlier.

(e) As the officers concerned acted in accordance with the rules and the requirements of the case, the question of fixing any responsibility does not arise.

(f) Orders for the suspension of Shri Man Singh, Assistant Excise and Taxation Officer, had been issued on the 1st October, 1965. Further necessary action in the matter is being taken by the Police. It is regretted that the designation of the persons who ordered and asked the Department for the suspension of the Assistant Excise and Taxation Officer, cannot be disclosed in pulbic interest.

Ram Piara Comrade, M.L.A.

Phone No. 172
Model Town,
27/28th September, 1965,
Karnal.

To

Shri Kapoor Singh Ji,
Finance Minister,
Chandigarh.

Subject.—Shri Man Singh A.E.T.O., Karnal, District Karnal caught red handed still not suspended by the Department.

DEAR FRIEND,

On 25th September, 1965 a complaint was brought to the Notice of Chief Minister Punjab that though Shri Man Singh Assistant Excise and Taxation Officer, District, Karnal was caught red handed yet he has not been suspended, so far, for the reasons best known to the Government. However Chief Minister assured to look into the matter.

The most important point which impelled me to write to you, is the "Charcha" whispering that as Shri Man Singh Assistant Excise and Taxation Officer is somewhat close or known to Shri Kapoor Singh Finance Minister, therefore, he has not been suspended.

Normally I presume that the Government immediately suspends its officer in case, he has been arrested, if it is so, the absence of suspension, do create doubts and in this case doubts not only exist but are openly expressed. Just possible that the incident of Shri Man Singh's redhanded capture might not be in your know but I shall suggest to ask the Department to explain reasons for the departure of normal practice of suspending such type of officers in this very case.

He should be suspended without any further loss of time in case other are suspended, if they are caught red handed.

I shall be grateful to you if I hear a line in reply immediately

Yours faithfully,
RAM PIARA M.L.A.,

D.O. No. 1810-FMS/65,
Secretary to Finance.
October, 14, 1965.

DEAR COMRADE SAHIB,

I am directed to refer you to your letter dated the 28th September, 1965 regarding Shri Man Singh, A.E.T.O., Karnal, and to inform you that the needful has since been done. I had informed you verbally also when you met me last.

Yours Sincerely,
(Sd.) SHIV KUMAR KAPUR.

Comrade Ram Piara, M.L.A.
Model Town,
Karnal.

कामरेड राम प्यारा : क्या आनरेबल फिनांस मिनिस्टर साहिब बतायेंगे कि आया इन्होंने गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट में या कैरों रजीम में भी कभी कोई ऐसा वाक्या उन की नजर में आया है जब कोई अफसर दो सौ रुपए रिश्वत लेता हुआ रैड हैंडिड पकड़ा गया हो और उस को लगभग दो महीने तक सस्पेंड न किया गया हो ?

मन्त्री : मेरे नोटिस में तो कोई ऐसा केस नहीं है। अगर आनरेबल मैंबर को किसी का पता है तो वह बता दें। मैं पता कर लूंगा।

कामरेड राम प्यारा : मिनिस्टर साहब ने सवाल के जवाब में बताया है क्योंकि लोकल अफसर ने उन को यह नहीं लिखा था कि यह अफसर रिश्वत लेता हुआ जब पकड़ा गया था तो वह एक्चुअली एरेस्ट कर लिया गया था और डिटेन किया गया था तो मैं पूछना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ने जब उसे सस्पेण्ड किया था तो उस आर्डर के साथ जो इस ने रैफरेंस भेजा था उस की डिटेल्ज़ क्या हैं ?

मंत्री : बात यह है कि अगर मुझे पहले पता चल जाता तो वह उसी वक्त सस्पेंड कर दिया जाता क्योंकि उन्हें मेरी कलम का पता है। अगर मुझे पहले इस का पता होता तो मैं उसी वक्त मान लेता। I knew that one anonymous application had come to me and I had enquired from the Department as to what action had been taken thereon but I received no information. Sir, when the hon. Member verbally told me about it, I immediately issued the orders.

Pandit Chiranji Lal Sharma : May I ask the Finance Minister if the investigation of the case has been completed and whether the challan has been put in the Court ?

Minister : I cannot say definitely.

कामरेड राम प्यारा : क्या मिनिस्टर साहिब बतायेंगे कि सवाल के जवाब में जो उन्होंने यह बताया है कि जिस अफसर के आर्डर्ज़ के नीचे वह सस्पैंड किया गया था उस का नाम डिसक्लोज़ करना पब्लिक इनट्रैस्ट में नहीं है तो मैं पूछना चाहता हूं कि वह कौन सी वजूहात हैं जिन की बिना पर उस का नाम नहीं बताया जा सकता और अण्डर दी रूल्ज़ कौन एथारेटी उस को सस्पेंड कर सकती थी ?

मंत्री : सस्पेंड मैं ने किया था। मुझ को वह अफसर समझ लो।

कामरेड राम प्यारा : मैं मिनिस्टर साहब से यह पूछना चाहता हूं कि जब यह केस उन के नोटिस में लाया गया था तो उन्होंने उस को सस्पेंड कर दिया तो क्या उन्होंने सैक्रेटरी से इस बारे में पूछताछ की जब इस बारे में गवर्नमेंट की इनस्ट्रक्शन्ज़ कलीयर हैं कि जिस वक्त कोई आदमी रिश्वत लेता हुआ पकड़ लिया जाए तो उस को उसी वक्त सस्पेंड कर दिया जाए तो इस केस में क्यों एक महीना या 20 दिनों तक इन इनस्ट्रक्शन्ज़ की कम्प्लायंस नहीं की गई ?

मंत्री : कौनसी फेसिलेटीज़ मांगते हैं ? (हंसी)

Comrade Ram Piara : Mr. Finance Minister, my question is whether it is the policy of the Government to immediately suspend a man when he is caught red-handed and if so, why this man has not been suspended so far and why has the Government not taken action against the officer who was competent to suspend the A.E.T.O. ?

मंत्री : रूल्ज़ के मुताबिक सब चीज़ देखनी पड़ती है। अगर तो किसी केस में रूल्ज़ के मुताबिक कोई चीज़ कलीयर हो उसी वक्त सस्पेंड कर दिया जाता है और अगर कलीयर न हो तो उसके बारे में पूछ ताछ कर के ऐकशन लेना पड़ता है।

Pandit Chiranji Lal Sharma : May I ask the hon. Finance Minister if he was pleased to order the suspension of the officer on the verbal request of Comrade Ram Piara or on some report from the Department?

Minister : Sir, the fact is that Comrade Ram Piara told me that such and such officer of this Department had accepted bribe and was arrested. I issued order immediately without having any report becauase I knew that sometime back another anonymous complaint against that Officer had come to me and on that complaint I had asked the Department to let me know what action the Department has taken against that Officer.

Comrade Ram Piara : Will the Finance Minister be pleased to state whether it is the general practice of the Government to refer all such cases where some Officers are caught red-handed, to the L.R. before suspending them ?

ਮੰਤਰੀ : ਜਿਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਖਿਆਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਸਪੈਂਡ ਨਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਵਰਨਾ ਰਿਟਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੋਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

Appointment of Harijan Lambardars in Sangrur and Patiala Districts

***8764. Shri Amar Singh :** Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) whether Government propose to appoint the Harijan Lambardars in Sangrur and Patiala Districts where Harijans have so far not been appointed; if so when ;

(b) whether there is any proposal under the consideration of the Government to grant Panchotra to the Harijan Lambardars in the State; if so, the details of the steps so far taken in this behalf ;

(c) the difference, if any, between the duties entrusted to the Harijan Lambardars and other Lambardars?

Sardar Harinder Singh, Major : (a) & (b) The matter is yet under consideration.

(c) Duties of ordinary lambardars are shown in Annexure A, a copy of which is laid on the Table of the House, except the duties shown against Serial Nos. (i) to (iv), a Harijan Lambardar performs all the duties shown in the Annexure.

ANNEXURE 'A'

Duties of Ordinary Lambardars

(Rule 20 of the Land Reveneue Rules).

In addition to the duties imposed upon headmen by law for any purpose, a headr shall —

(i) collect by due date all land revenue and all sums, recoverable as land reve from the estate, or sub-division of an estate in which he holds office, pay the same personally or by revenue money-order or by remittance currency notes through the post or at places where treasury busi is conducted by the Imperial Bank of India, by cheque on a local B at the place and time appointed in that behalf to the Revenue Officer assignee empowered by Government to receive it ;

(ii) collect the rents and other income of the common land, and account for th to the persons entitled thereto ;

(iii) acknowledge every payment received by him in the books of the la owners and tenants ;

(iv) defray joint expenses of the estate and render accounts thereof as may duly required of him ;

(v) report to the tehsildar the death of any assignee of land revenue or Gover ment pensioner residing in the estate, or the marria e or re-marriage a female drawing a family pension and residing in the estate ; or t absence of any such person for more than a year ;

(vi) report to the tehsildar all encroachments on roads (including village road or on Government waste lands and injuries to, or appropriation of nazul property situated within the boundasries of the estate ;

(vii) report any injury to Government buildings made over to his charge.

(viii) carry out, to the best of his ability, any orders that he may receive from th Collector requiring him to furnish information, or to assist in providin on payment supplies or means of transport for troops or for officers c Government on duty ;

(ix) assist in such manner as the Collector may from time to time direct at a crops inspections, recording of mutations, surveys, preparation pf record of right or other revenue business carried on within the limits of the estate ;

(x) attend the summons of all authorities having jurisdiction in the estate, assist all officers of the Government in the execution of their public duties, supply, to the best of his ability, any local information which those officers may require, and generally act for the land owners, tenants and residents of the estate or sub-division of the estate in which he holds office in their relations with Government.

(xi) report to the patwari any outbreak of disease among animals or human beings.

(xii) report to the patwari the deaths of any right-holders in their estates ;

(xiii) report any breach or cut in a Government Irrigation canal or channel to the nearest canal officer, ziladar or canal Patwari ;

(xiv) under the general or special directions of the Collector, assist by the use of his personal influence and otherwise all officers of Government and other persons duly authorised by the Collector, in the collection and enrolement of recruits for military service whether combatant or non-combatant ;

(xv) render all possible assistance to the village postman while passing the night in the village, in safeguarding the cash and other valuables that he carries.

Shri Amar Singh: Sir, Part (b) of my question is—

"(b) whether there is any proposal under the consideration of the Government to grant Panchotra to the Harijan Lambardars, in the State; if so, the details of the steps so far taken in this behalf ;

यह पूछना चाहता हूं कि क्या अभी तक कोई स्टैप्स भी लिये हैं या मैटर अंडर कन-सिडरेशन ही रहेगा ?

Mr. Speaker: The reply has come that the matter is under consideration.

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਹਰੀਜਨ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੱਚਰ ਮਨਿਸਟਰੀ ਵੇਲੇ ਐਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਲੰਬੜਦਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹਕੂਕ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਕੀ ਉਹ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋਰ ਲਗੇਗਾ ?

Revenue Minister : Sir , I have already replied that the matter is under consideration and that it will be finalised at the very earliest.

चौधरी इन्द्र सिंह मलिक : 5-6 साल हुए कुछ हरिजन लम्बड़दार जींद में एप्वायंट किये गये थे मगर उस के बाद वह फाईल वैसे ही पड़ी हुई है। इन केसिज़ को कब फाइनलाईज़ किया जायगा और कब पंचोत्रा उन को दिया जायगा ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਸਵਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਬਾਰੇ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਸੈਪੇਰੇਟ ਨੋਟਿਸ ਦਿਉ ।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਹਰੀਜਨ ਨੰਬਰਦਾਰ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਹਨ ਜਿਥੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਹਰੀਜਨ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ । ਉਥੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵਿਚ ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਚੋਤਰਾ ਇਨਵਾਲਵਡ ਸੀ । ਪੰਚੋਤਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਚੂੰਕਿ ਉਸ ਨੇ ਫਿਨਾਂਸਿਜ਼ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅੰਬੈਜ਼ਲਮੈਂਟ ਜਾਂ ਮਿਸਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਨੰਬਰਦਾਰ ਪਾਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਚੂੰਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਪਾਸ ਕੋਈ ਪੂੰਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਉਹ ਬਤੌਰ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਦੇ ਸਕਣ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲੈਂਡ ਰੈਵੀਨਿਉ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ । ਇਸ ਲਈ ਦੇਰ ਲਗ ਰਹੀ ਹੈ । ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਾ ਅੰਡਰ ਕਨਸਿਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ।

श्री अमर सिंह : ऐसे बहुत से केसिज़ मैच्योर हो कर डेढ़ साल से डी. सी. संगरूर और पटियाला के दफतर में पड़े हैं। क्या ऐसे केसिज़ उन के नोटिस में आए हैं ? अगर आए हैं तो कब तक फाइनेलाइज़ होंगे ?

ਮੰਤਰੀ । ਹਰੀਜਨ ਭਰਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਜੈਂਟਮੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪਾਰ ਟਰੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਅਨੈਕਸਚਰ ਵਿਚ ਐਟ ਸੀ ਨੰਬਰ ਵਨ ਟੂ ਫੋਰ ਹਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਤਿਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜੋ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਤਮੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹਲ ਢੂ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, the matter is under consideration.

ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਆਨੈਸਟ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇਬਲ ਹਰੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿਸਨੂੰ ਰੈਵੇਨਿਊ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇੰਟਰੈਸਟ ਕਰ ਸਕਣ ? ਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਚੂਏਸ਼ਨ ਰੀਫਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਤੇ ?

ਮੰਤਰੀ : ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਰੀਫਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨ ਹੈ । ਮਗਰ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਜੋ ਪਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹਨ, ਸਟਰਿਕਟਲੀ ਇਨ ਕਨਫਰ ਵਿਦ ਦੋਜ਼ ਪਰੋਵੀਜ਼ਨਜ਼ ਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਰਬਿਟਰੇਰੀਲੀ ਨਹੀਂ ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਜ ਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜੋਤਰਾ ਨ ਦਿੰਦੇ । ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਜਟ ਜ਼ੀਮੀਂਦਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਨੰਬਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮੁਕਾ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਨੰਬਰਦਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ? ਕੀ ਉ ਤੋਂ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ?

Minister : It appears that the hon. Member has some particular c in his mind. If he brings to my notice any such case which isfringes provisions of the laws in force, definitely it is the bounden duty of Government to take action.

श्री जगन्नाथ : क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि यह जो आप ने आनरेरी नम्बर बना रखे हैं, बिना पंचोतरे के क्या ऐसे नम्बरदार किसी और स्टेट में भी हैं।

Minister : Separate notice is required so that information could collected from other States in India.

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਮਾਰਚ, 1960 ਵਿਚ ਉਠਿਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅੰਡਰ ਕਨਸਿਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ । ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ 5½ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ?

ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਇਸ ਤ ਦੀ ਪਰਪੋਜ਼ਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਕਨਸੌਲੀਡੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ 30 ਰੁਪਏ ਪੰਚੋਤਰਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ।

Minister : Not to my knowledge.

कामरेड राम प्यारा : क्या सरकार ने किसी स्टेज पर हरिजन नम्बरदारों कहा है कि वह अगर ज़मानत दे दें तो उन को पंचोत्रा दिया जायगा ?

ਮੰਤਰੀ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਰੈਵੇਨਿਊ ਰੂਲਜ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਸ਼ਖਸ ਐਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, definitel his case will be considered.

चौधरी रण सिंह : पहले भी हरिजन लम्बरदारों को पंचोत्रा देने के बारे में इस
त में जवाब दिया जा चुका है कि 'the matter is under consideration'
भी यह कहा जा रहा है। तो क्या यह ऐसे ही रहेगा या इस का कभी फैसला भी होगा ?

Mr. Speaker : Not allowed.

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ
ਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਵਾਲ ਦੇ ਪਾਰਟ 'ਏ' ਵਿਚ ਇਹ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ—
'hether Government propose to appoint the Harijan
ımbardars in these districts?

ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਗਿਆਂ ਇਹ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰ ਗਏ
; ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚੋਤ੍ਰੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਥੇ
ੀਜਨਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਹੈ ਉਥੇ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਹਰੀਜਨ ਲੰਬਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ
ੀ ਇਨਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਥੇ ਹਰੀਜਨ ਨੂੰ ਨਬਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ?

ਮੰਤਰੀ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ
ਲ ਮਟੋਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਰਬ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਐਸੇ ਹਰੀਜਨ ਵੀਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਬਗੈਰ ਪੰਚੋਤ੍ਰਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ
ਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਸੋ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ।

ਕਾਮਰੇਡ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਗਲ
ਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਪਾਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ
ਾਲੀਸੀ ਹਰੀਜਨ ਨੰਬਰਦਾਰ ਮੁਕਰਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ? ਕੀ ਇਹ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਚਮਕਾ
ਣ ਵਾਲੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ?

Minister : Sir, it is a matter of interpretation.

Tehsil Building at Hansi, district Hissar

***8770. Shri Amar Singh :** Will the Minister for Revenue be pleased
o state :—

(a) whether it is a fact that the Tehsil building at Hansi in Hissar District has been declared unserviceable; if so, since when ;

(b) if the reply to part (a) above be in the affirmative whether Government intend to construct a new Tehsil building: if so when ?

Sardar Harinder Singh Major : (a) Yes, since June, 1960.

(b) Government have provided Rs 2,15,550 for the construction of a new tehsil building at Hansi, in the State budget for 1965-66. However, the construction work has been deferred for the present on account of the present emergency.

श्री अमर सिंह : क्या रैवेन्यू मिनिस्टर साहिब बताने की कृपा करेंगे कि जब इस के
लिए ईंटें और दूसरा बिल्डिंग मैटीरियल पड़ा है तो फिर एमरजंसी के नाम पर इस की
तामीर को पोस्टपोन करने का क्या कारण है ?

ਮੰਤਰੀ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਸ ਲਈ ਲੇਬਰ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੁਝੇ ਛਿਪੇ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਅਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਜਿਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਕ ਇਕ ਪੈਸਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਪੋਸਟਪੋਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ।

श्री अमर सिंह : क्या यह बात मन्त्री महोदय के नोटिस में है कि एक एम्पलाई इस इमारत के एक कमरे में बैठा था और ऊपर से छत से एक ईंट गिर गई जिस से उस का सर फट गया था ?

Minister : This is not to my knowledge.

Evacuee land purchased by Harijans in the State

***8766. Shri Amar Singh :** Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) the total area of evacuee land in acres purchased by the Harijans in auction during the period from July, 1964 to date region-wise and district-wise ;

(b) the total amount given by the Government in the State for the purchase of evacuee land during the said period district-wise ;

(c) the total number of families settled by the Government on the evacuee land in the State during the above mentioned period district-wise ;

Sardar Harinder Singh, Major : The time and labour involved in collecting information will not be commensurate with any possible benefit to be obtained.

ਸ੍ਰੀ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਸਰ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ । ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਇਸ ਸਵਾਲ ਵਿਚ ਪੁਛੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੈਕਰੇਟਰੀਏਟ ਵਿਚ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਚੁਕੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਇਨਵਾਲਵ ਹੋਣੀ ਸੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਗ਼ਲਤ ਪਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ । (ਵਿਘਨ)

Mr. Speaker : Please do not make a speech.

ਸ੍ਰੀ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਜੇਕਰ ਜਵਾਬ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਉ ਕਿ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ।

Mr. Speaker : Please take your seat.

श्री अमर सिंह : आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर, सर। मैं इस बात पर आप की रूलिंग चाहता हूं कि इस सवाल में पूछी गई इन्फरमेशन से ज्यादा इन्फरमेशन इस हाउस में दी जा चुकी है और यह इनफरमेशन तो सैक्रेटेरीएट में मौजूद है और इवेकूई लेंड के बारे में सरकार ने एक सैपरेट आफीसर इस काम के लिये लगाया हुआ है जो सैक्रेटरी के रेंक का है तो फिर किस वजह से मिनिस्टर साहिब यह इनफरमेशन देने से इन्कार कर रहे हैं ? इस तरह की इन्फरमेशन तो पहले भी हाउस में दी जा चुकी है।

Mr. Speaker : Please take your seat.

Starred Question No. 8759

Mr. Speaker : Extension has been applied for in regard to question No. 8759

श्री जगन्नाथ : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। जनाब, इस सवाल के जवाब देने के लिये एक्सटेन्शन मांगी गई है हालांकि सिर्फ तहसील भिवानी के बारे में सवाल था और काल अटेन्शन मोशन भी दी गई है। इस के बारे में मिस्टर फलेचर 18, 19 और 20 को वहां पर गए और दौरा कर के आए हैं इस लिये यह मुनासिब नहीं कि इस का जवाब देने के लिये एक्स्टेन्शन मांगी जाए।

ਮੰਤਰੀ : ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕੁਐਸਚਨ ਟੂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹਿਜ਼ ਮੈਮੋਰੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਐਕਸਟੇਨਸ਼ਨ ਲਈ ਰੀਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ Information regarding parts (a) and (b) is available with the Government while in regard to part (c) it is to be collected from the Deputy Commissioner concerned. It is only on that account that extension has been applied for.

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ। ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਪੌਣੀ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਇਮਪਾਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਜੇਕਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਉ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਵਾਬ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਦੇ ਦੇਣ।

Mr. Speaker : Unless the whole of the reply is available, how can he answer the Question ?

Starred Questions No. 8792 and 8791

Mr. Speaker : In regard to Questions Nos. 8792 and 8791 extension has been applied for.

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ। ਜਨਾਬ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਬੈਕਵਰਡ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।

Mr. Speaker : Please take your seat.

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਜਨਾਬ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਕਨਸੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।

Mr. Speaker : The hon. Member should please resume his seat. If the Government does not want to answer a Question, I am sorry, I cannot help it.

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ : ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵੇਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਵੀ ਚਾਹੁਣ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

It is not the intention of the G vernment to conceal any information (*Cheers*)

ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਲ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿਚ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। Through you, Sir, I would say that it is not fair to the Government.

कामरेड राम प्यारा : ग्रान ए प्वाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर, सर। ग्राप ने स्पीकर साहिब, ग्रभी फरमाया है कि गवर्नमेंट ग्रगर जवाब न देना चाहे तो उसे फोर्स नहीं किया जा सकता तो ग्रगर सवाल बहुत इम्पार्टन्ट हो ग्रौर जवाब मिल सकता हो तो ग्राप इन्हें प्रसूएड तो कर सकते हैं कि जवाब दिया जाए।

Mr. Speaker : Of course, I can make a request that they should reply to the questions that are admitted by me.

श्री ग्रमर सिंह : मेरा प्वायंट ग्राफ ग्रार्डर यह है कि एक सवाल जब ग्राप ने एडमिट किया है, सरकार की तरफ से जो इसे बार-बार एकसटैंड कराया जाता है ग्राप तो कम ग्रज़ कम इन्हें इमप्रैस करें कि वह जवाब दें।

Mr. Speaker : I have already stated that I can make a request to Government to reply to questions admitted by me.

UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS

Loss of Service Books in D.E.O's. Office, Hoshiarpur

3035. Shri Surinder Nath Gautam ; Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) whether it is a fact that service books of certain teachers and Mistresses of Government Primary Schools have been lost in the D.E.O's., office, Hoshiarpur ;

(b) if the answer to part (a) be in the affirmative, the names of such teachers/Mistresses along with the date of loss of the Service Books, tehsilwise ;

(c) whether any enquiry into the matter regarding the loss of Service Books was held, if so, the names of the officials or officers of the said D.E.O.'s office held responsible for the said loss;

(d) whether new Service Books of the teachers/Mistresses referred to in part (b) above have been prepared and annual increments granted to them or they are still not getting their annual increments ?

Shri Prabodh Chandra : (a) No. The service books of two teachers were, however, lost in transit in the office of th e Accountant General, Punjab ;

[Minister for Education]

(b) The names of teachers whose service books were lost in the office of the Accountant-General Punjab's are as below :—

Serial No.	Name	Date on which service book was lost	Tehsil
1	2	3	4
1	Smt. Hukam Devi, Government Girls Middle School, Charatgarh	3-11-63	Una
2	Smt. Manjit Kaur, Government Primary School, Raipur	3-11-63	Una

(c) Yes. Responsibility cannot be fixed as the service books were lost in the office of the Accountant General, Punjab, Simla.

(d) The service books of these teachers are being re-constructed. However, incremensts have not been granted as yet.

Water Supply Schemes in Block Una, district Hoshiarpur

3036. Shri Surinder Nath Gautam ; Will the Minister for Health be pleased to state the names and the details of the water supply scheme proposed to be taken up in Block Una, district Hoshiarpur, in the year 1965-66 ?

Shrimati Om Prabha Jain :

	Rs
Providing water supply scheme for oustees colony for villages Mehdimajra, Kathera, Bari Kanchera and Rampur at Nangal	60,000
Providing water supply in villages Nangal Khurd and Nangal Kalan and Lalehri	1,95,430

Mr. Speaker ; Now we pass on to the next item on the Agenda.

ADJOURNMENT MOTIONS

10.00 a. m.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ (ਮੋਗਾ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਇਕ ਐਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡਿਸਅਲਾਊ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਪਰ ਮੈਂ ਇਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬੜੀ ਹੁਬਲਵਤਨ ਹੈ, ਬੜੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਤੱਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਦਨੁਮਾ ਧਬਾ ਲਾਉਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ

ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗ਼ੈਰਵਾਜਬ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ । ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਪਈ ਅਗੇ ਵਧ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇਣੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਸਿਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਤੇ ਇਕ ਚੋਟ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ । ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਅਜ ਮਹਿਜ਼ ਅਖਬਾਰਾਂ ਬੇਚਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਕ ਕੌਮ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਰਹੇ ਹਨ......(ਸ਼ੇਮ, ਸ਼ੇਮ)

Mr. Speaker : Please do not make a speech.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰਗਿਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ।

Mr. Speaker : Please take your seat. The adjournment motions of a similar nature were received. These were based on certain undesirable news appearing in a section of the Press. I have disallowed them on the ground that anything published in the Press cannot form the basis of such motions.

Besides, the Government does not come into the picture. It does not relate to the administration of the State. So, it cannot be the basis of an adjournment motion.

Sardar Gurnam Singh : With due respect to your feelings, I would like you, Sir, to see the Adjournment Motion.

Mr. Speaker ; It would be better if you discuss this matter with me in the Chamber .

Sardar Gurnam Singh : Since the matter has now been raised here, let me please speak for a minute or two only .

Mr. Speaker ; I have disallowed the motion. Let this matter be now discussed in my Chamber.

Sardar Gurnam Singh : Just for a minute please. What I want to emphasize is that the Government should take action against these Papers as they have done in the case of 'Jathedar' and 'Prabhat'. I do not know why they are sleeping over this matter. We cannot tolerate this. Sikhs have died and made huge sacrifices for the sake of their country, whereas these people had been saluting the 'Jhanda' of Pakistan. How can we tolerate all this ? Has this Hindu press usurped monopoly of loyalty to the country, must it go on maligning the Sikhs who inhabit this country ? I do not want to go further in this aspect, but I cannot understand how the Government can escape their responsibility in not taking action against 'Pradeep', 'Hind Samachar' and Milap' under the Defence of India Rules, when they have already taken action against 'Jathedar' and 'Prabhat'. These Papers are maligning the Sikhs and should be taken to task.

Mr. Speaker : Please take your seat. Your point has come.

Sardar Gurnam Singh : Not yet, Sir. I would like to invite your attention, in this connection to the Emergency Powers contained in Chapter II of the Defence of India Act, 1962. It is stated therein :

> " (2) (7)......Without prejudice to the generality of the powers conferred by sub-section (1), the rules may provide for, and may empower any authority to make orders providing for all or any of the following matters, namely:—
>
> (7) (a) prohibiting the printing or publishing of any news-paper, news-sheet, book or other document containing matters prejudicial to the defence of India and civil defence, the public safety, the maintenance of public order, the efficient conduct of military operations or the maintenance of supplies and services essential to the life of the community ....,

[Sardar Gurnam Singh]

In view of these provisions of the Act, I would humbly submit that you must reconsider your earlier decision and admit this motion, so that we may have an opportunity to tell the hon. Members of this House that while the Sikhs, Jats and Dogras fought for the country recently, these people were found indulging in black-marketing and making money at the cost of the country. They have now the audacity to talk in the press like this.

Mr. Speaker ; Please do not make a speech and take your seat.

डाक्टर बलदेव प्रकाश (अमृतसर शहर) : स्पीकर साहिब, जो सवाल इस हाउस में आया है मैंने अखबार नहीं देखा कि उस में क्या है मगर जैसा कि आनरेबल मैम्बर्ज़ सरदार गुरचरन सिंह और सरदार गुरनाम सिंह ने बताया है मुझे यह बात सुन कर सख्त अफसोस हुआ है। सिख संप्रदाय के बारे में इस तरह की बातें करना चाहे हालात आज की बजाये अमन वाले क्यों न हों मैं समझता हूं, मगर जो भी कोई इस तरह की बातें करते हैं वह देश के सब से बड़े दुशमन हैं। सिखों के बारे इस तरह कहना जिन की हमेशा ट्रैडीशन्ज ही ऐसी हैं जो देश प्यार से भरी हुई हैं आज इस तरह की बात करना । मैं समझता हूं इस से बड़ा पाप और कोई नहीं है अगर इस तरह की बातें इस सूबे के अंदर चलती हैं और इस से किसी को एनकरेजमैंट मिलती है तो सरकार को चाहिये कि वह इसे दुरुस्त करे और इस के खिलाफ मज़ीद कार्यवाही होनी चाहिए।

ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ (ਦਸੂਆ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਤਾਂ ਅਲਗ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਯਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਤਨਾ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ (ਤਾਲੀਆਂ) ਐਸੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ । ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇ । ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ (ਧਾਲੀਵਾਲ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿਖਾਂ ਤੇ ਹੀ ਸ਼ਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਫੌਜੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫੌਜ ਵੀ ਓਧਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਇਤਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧ ਹਨ । ਇਹ ਐਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਐਡਮਿਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਏਥੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ । ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁਆਮਲੇ ਤੇ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ। ਐਸੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਛਾਪਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

श्री यश पाल (जालंधर शहर): स्पीकर साहिब सरदार गुरनाम सिंह जी ने जो सवाल उठाया है, मैं समझता हूं जो कुछ भी उन्होंने कहा है वह जज़बात की रौ में कहा है। जो व्यक्ति हिंदू और सिख के नाम पर वोटें मांगते है, हिन्दू और सिख में तमीज़ करत हैं, धर्म के नाम पर राजनीति चलाते हैं.........

(*Interruption*)

The President has called Sant Fateh Singh, who is the President of the Akali Dal, the patriot of the highest order. ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਗਰ ਇਹ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

मुख्य मंत्री (श्री राम किशन) : स्पीकर साहिब, जो कुछ आज हाउस में हुआ मुझे इस से काफी दुख और अफसोस हुआ है। स्पीकर साहिब, जहां तक सिख कम्यूनिटी का ताल्लुक है इस बात का कोई रत्ती भर शक्को शुबा नहीं है कि सिख मिलिटरी का सारा इतिहास हिरोआटिज़म, शूरवीरता और बहादूरी का एक नया और पुराना इतिहास है जिसको कोई झुटला नहीं सकता और इस पर न सिरफ इस पंजाब को बल्कि सारे देश को पूरी तरह से नाज है। सिख भाइयों ने हिंदुस्तान की आज़ादी के एतिहास में और आज़ादी के बाद हिंदुस्तान की रीकंस्ट्रक्शन में और हिंदुस्तान की सुरक्षा में एक बड़ा भारी पार्ट प्ले किया है जिस को कोई भी झुटला नहीं सकता। और सारा हिन्दुस्तान इसका पूरी तरह से कृतज्ञ है बल्कि अगर मैं यह कहूं कि जहां तक सिख कौम का यह जो पुराना इतिहास है और जो महान गुरुओं ने बड़ा आदेश दिया उससे सारे देश को इंस्पीरेशन और प्रेरणा मिलती है। इसमें कोई शको-शुबा वाली बात नहीं है कि हिंदुस्तान के कलचरल, आर्थिक और राजनतिक इतिहास में बड़ी भारी कंट्रीब्यूशन इस कम्यूनिटी की है। जो भाई इस कम्यूनिटी पर हमला करता है वह ठीक नहीं समझता है। इसमें कोई शक-शुबा वाली बात नहीं। (विघ्न) स्पीकर साहिब, मैं यह अर्ज़ कर रहा था कि जहां तक इसका सवाल जो उठा है गवर्नमेंट का किसी तरह से डाइरेकटली या इनडाइरेक्टली कोई वास्ता नहीं है। लेकिन इस में दो बातें उठाई गई हैं। एक जथेदार और प्रभात की बाबत कहा गया है। उनके अंदर कुछ लेख निकले जिन को गवर्नमेंट आफ इंडिया ने मौजूं नहीं समझा, तो गवर्नमेंट आफ इंडिया ने उन पर पाबन्दी लगा दी और उसके बाद उन के मालकान ने सारी बात को एक्स्प्लेन किया और गवर्नमेंट आफ इंडिया ने उन पर से पाबन्दी उठा ली। जिन अखबारों का ज़िक्र किया गया मैं आप की विसातत से यह कहना चाहता हूं कि प्रेस कंसलटेटिव कमेटी की मीटिंग हो रही है, उस में हम इन सारी चीजों पर पूरी तरह से गौर करेंगे।

सरदार गुरनाम सिंह : ऐक्शन।

मुख्य मन्त्री : गवर्नमेंट का ही फर्ज़ नहीं है बल्कि मैं यह समझता हूं कि सारे राज्य का, सारी स्टेट का यह फर्ज़ है कि हम पंजाब में हर कीमत पर कम्यूनल हारमनी रखें। अगर किसी तरह से ताल्लुकात डिस्टर्ब होते हैं और एक दूसरे के जज़बात को ठेस पहुंचती है या किसी तरह से ठेस पहुंचती है तो सिवाए पाकिस्तान के और किसी को फायदा नहीं पहुंचता और पंजाब के स्ट्रक्चर पर जो पुराना सदियों से बना हुआ है और पूरी तरह से हमारे इतिहास का एक हिस्सा बन चुका है एक गहरी ज़र्ब लगती है। स्पीकर साहिब, मैं आपके ज़रिए यह सारे हाउस को यकीन दिलाना चाहता हूं कि जहां तक इस पंजाब गवर्नमेंट का ताल्लुक है हमारा यह फर्ज़ है कि हम आपस के ताल्लुकात को न सिरफ बेहतरीन बनाएं बल्कि इन ताल्लुकात को इतना पक्का करें कि किसी तरह के इंतशार की बू न आने पाए। कुछ पंजाबी सूबे का सवाल उठाया गया। मैं आशा रखता था कि इस सवाल को

[मुख्य मन्त्री]

न उठाया जाता। गवर्नमैंट आफ इंडिया ने जिस भावना और स्पिरिट से एक कमेटी कायम की है उस स्पिरिट के मुताबक पंजाब के लोगों को उसी तरह से अपने विचार पेश करने चाहिए। प्रेस और प्लेटफार्म से इन सवालों का हल नहीं हो सकता। इन सवालों क हल होगा कि हम जितनी भी कम्यूनिटीज़, सैक्शन्ज़ और रिजन्ज़ हैं, जितन लोग हैं एक दूसरे के सैंटीमेंट्स, एक दूसरे की इंसपरेशन्ज़ को एप्रीशिएट करें। और उस के मुताबिक ही पंजाब का हमें हल निकालना होगा। इस मौका पर पंजाब ने बड़ी हिम्मत और बहादरी का सबूत दिया है और इस लड़ाई में सब भाई, सिख, डोगरे, गोरखे, जाट, राजपूत, अहीर, हरिजन और दूसरे सब शानाबशाना लड़े हैं। यह सब बतौर हिन्दुस्तानी अपने देश की रक्षा के लिय लड़े हैं और सिख, डोगरा, जाट राजपूत, होने के नाते नहीं लड़े हैं (शोर), इस से सारे हिन्दुस्तान का नाम ऊंचा हुआ है। मुझे स्पीकर साहिब आप की मारफत सारे हाउस से यह अपील करनी है कि अपने जज़बात का इज़हार करते वक्त निहायत रवादारी से काम लें। हमें किसी के जज़बात से खेलने और ठेस पहुंचाने की हरगिज़ कोशिश नहीं करनी चाहिए। मैं आशा रखता हूं कि सब लोग, प्रैस वाले, पार्टीज़, इन्डीविजुअल इस सारी चीज़ को मद्देनजर रखेंगे और फिर कोई बात करेंगे क्योंकि पंजाब में कम्युनल हारमनी की जितनी आज ज़रूरत है उतनी पहले कभी नहीं थी। मैं आशा रखता हूं कि पंजाब का एक अच्छा खातर खाह हल निकल आएगा। में फिर आप के ज़रिए तमाम भाइयों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि जहां तक पंजाब गवर्नमैंट का ताल्लुक है यह डायरेक्टली या इन्डायरेक्टली किसी को भी कम्युनल जज़बात इनसाईट करने की इजाज़त नहीं देगी। हम चाहते हैं कि पंजाब के अन्दर कलम से और जबान से जो कुछ निकले वह ऐसा हो जो कि कम्युनिटीज़ के ताल्लुकात को अच्छा करने वाला हो न कि उन में इन्तशार पैदा करने वाला हो। मैं सिख भाइयों को यकीन दिलाना चाहता हूं (ऐकशन क्या लेंगे की आवाज़ें) कि किसी को उन के जज़बात से खेलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी (शोर)। हमें आप की कुर-बानियों की और आप की वीरता की कदर है और आपने हिन्दुस्तान में एक इम्पार्टटैंट पार्ट प्ले किया है जिसके लिये सारा देश कृतज्ञ है। मैं आशा रखता हूं कि जिस भावना से मैं ने यह लफज़ कहे हैं उस के मुताबिक ही वह इस पर अमल करेंगे और सारी चीज़ को लेंगे और पंजाब के अमन को कायम रखने के लिये सारे के सारे भाई अपनी पूरी कन्ट्रीब्यूशन देंगे। मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि प्रैस कंसलटेटव कमेटी इस सारी चीज़ पर गौर करेगी (शोर) और सारी बात को देखेगी और फिर हम देखेंगे। मैं फिर यह अपील करना चाहता हूं कि चाहे प्रैस हो, पार्टीज हों या इन्डीविजुअल कोई ऐसी बात न करें जिस से किसी के जज़बात को ठेस पहुंचे और किसी एक कम्युनिटी पर हमला हो। हर एक कमुनिटी के अन्दर अच्छे और बुरे आदमी होते हैं लेकिन मजमूई तौर पर किसी कम्युनिटी को कोसा नहीं जा सकता है। मैं आशा रखता हूं कि जिस भावना से मैंने यह बात कही है उसके मुताबिक सारे भाई कोआप्रेशन दे कर पंजाब में अच्छा वायु-मंडल पैदा करने में हमें मदद देंगे (तालियां)।

Mr. Speaker : I have disallowed these two motions and that order stands. But I do hope that if any statement has been published in the Newspapers which is in violation of any provision of the Constitution, Government will take due notice of it and take immediate action.

Sardar Gurnam Singh : The Chief Minister has not said that he will take any action. He has only sermonised us. This is not proper. Government should take action under the Defence of India Rules. He has only said that he will take up the matter in the Press Consultative Committee. These very persons are the members of the Press Consultative Committee. We are not going to listen to it. We have tolerated it for years and now we are not going to tolerate it any more. Government should take action against them. The Home Minister should tell us what action they are going to take under the Defence of India Rules.

ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿਉ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲੇ ਕੋਲ (ਸ਼ੋਰ)......

चौधरी देवी लाल : ग्रान ए प्वायंट ग्राफ ग्रार्डर, सर । यह सवाल इस लिय उठाया गया है कि इस की बड़ी भारी ग्रहमियत है ।.....(शोर)

श्री ग्रध्यक्ष : यह ग्राप की बात ग्रा गई है। (This you have already said)

चौधरी देवी लाल : मेरा प्वायंट ग्राफ ग्रार्डर यह है कि जिस ढंग से चीफ मिनिस्टर साहिब ने इस चीज़ का जवाब दिया है कि प्रैस कन्सलटेटव कमेटी की मीटिंग होगी ग्रौर फिर गवर्नमैंट उस पर गौर करेगी इस से किसी की तसल्ली नहीं हुई है, जिस कमेटी की यह बात करते हैं उस में भी तो यही 11 फीसदी ग्रादमी हैं जिन ने इस किसम का माहौल पैदा किया है ग्रौर इस गवर्नमैंट में भी वही 11 फीसदी ग्रादमी हैं। ग्रापने स्पीकर साहिब इस बात को कन्सिडर नहीं किया ग्रौर ग्रपना फैसला दे दिया है। ग्रापकी तरफ से गवर्नमेंट पर जोर पड़ना चाहिए कि वह यह फैसला करें ग्रौर हाउस की तसल्ली कराएं।

श्री ग्रध्यक्ष: मैं ने यह कह दिया है। (I have said so.)

Sardar Gurnam Singh : The Chief Minister did not even say that he would get the matter examined from the Law Department. Government is encouraging this communal Press and communal bodies everyday. We are not going to tolerate this. Days are gone when we were tolerating this.

ਸਰਦਾਰ ਜੋਇੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ। ਮੈਂ ਜਸਟਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ......(ਇਸ ਵਕਤ ਹਾਉਸ ਵਿਚ ਐਨਾ ਸ਼ੋਰ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਬ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ) ।

डाक्टर बलदेव प्रकाश : जहां तक किसी एक खास कम्युनिटी के बारे में बात लिखने की बात है उस की सारे हाउस की तरफ से यूनैनीमसली मुज़म्मत की गई है जो यह कहा गया कि ऐक्शन लिया जाये तो ग्रगर सरकार ने विश्वास नहीं दिलाया है तो वह दिलाना चाहिए ग्रौर मैं हाउस से ग्रपील करना चाहता हूं कि यहां इस हाउस में इस बात को बढ़ाया न जाए ग्रौर इसे यहीं खत्म किया जाए क्योंकि इसका ग्रच्छा ग्रसर नहीं पड़ता। सरदार गुरनाम सिंह जी जो इतने गरम हो रहे हैं ग्रौर देश भक्ती के नाम पर ग्रपील कर रहे हैं उन्हें मैं याद दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने सिखों को स्पेशल स्टेटस देने का लुध्याना में रज़ोल्यूशन मूव किया था। क्या यह उन की देश भक्ति थी जिस की दुहाई यहां दे रहे हैं। (शोर) जहां तक लिंगुइस्टिक स्टेट्स का सवाल है इस सवाल को सैपरेट ही रहने देना चाहिए इस को जोड़ कर बात को ग्रागे ग्रौर न बढ़ाया जाए। इस बात पर ग्रगर बहस करनी है तो बाकायदा हाउस में बहस की जाए हम तैयार हैं।

चौधरी देवी लाल : डाक्टर बलदेव प्रकाश जी ने कहा है कि जस्टिस गुरनाम सिंह ने सिखों के लिये सैल्फ डिटरमीनेशन का रज़ोल्यूशन पेश किया था । मैं पूछना चाहता हूं कि यह हालात पैदा किस ने किये हैं ? यह हालात इन्हीं 11 फीसदी लोगों ने पैदा किये हैं और मैं कहता हूं कि इस तरह से यह हालात चलते रहे तो सिख स्टेट का मुतालबा इन की तरफ से होगा (शोर) मैं कहता हूं कि यहां हाउस में इस पर बहस होनी चाहिए और फैसला होना चाहिए। यह पंजाब सरकार तो हिन्दु सिख फसाद कराना चाहती है। इन के पास अब और कोई रास्ता ही नहीं रह गया कि हिन्दु जज़बा उभार कर इस इम्पार्टैंट मसला को हल न होने दें और रुकावट डालें (शोर) ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸੇ ਕੰਮ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਹਨ (ਵਿਘਨ)। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਸੈਲਫ ਡੀਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਵਿਦ ਇਨ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਡਿਸਲਾਇਲਟੀ ਦੀ ਸੀ । ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਲਾਇਲ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ । ਇਹ ਦਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਲਾਇਲਟੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਗੁਣ ਗਾਂਦੇ ਹਨ ਲੇਕਨ ਹਨ ਡਿਸਲਾਇਲ ਇਸ ਮੁਲਕ ਲਈ। (ਸ਼ੋਰ) (इस वक्त हाउस में बहुत शोर था और कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था)

श्री अध्यक्ष: Order Please. मैं अब हाउस के आनरेबल मैम्बरों से रिक्वैस्ट करूंगा कि माननीय सदस्यों ने अपनी २ बात कह ली है, अब इस मामला को खत्म किया जाए। (आपोजीशन की यरफ से विघ्न)

I am sorry. Order please I would now request the hon. Members that there should be no noise and interruptions in the House. The House will now take up the next item on the agenda. (*Noise*).

अगर मैम्बर्ज चाहते हैं कि हाउस की कार्यवाही ठीक ढंग से न चले तो I will adjourn the House.

(Order please. I would request the hon. Members that since enough has been said on the subject, the matter may now be treated as closed. (*Interruptions by the opposition*) I am sorry. Order please. I would now request the hon. Members that there should be no noise and interruptions in the House. The House will now take up the next item on the agenda. (*Noise*) If the hon. Members do not want the business of the House transacted properly then I would like to adjourn the House.)

Some voices : No please.

ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ । ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ?

Mr. Speaker : Please take your seat. This matter has been closed finally.

चौधरी नेत राम : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। स्पीकर साहिब, हाउस के अन्दर काम रोको प्रस्ताव आया और आप ने उस को रद्द कर दिया । यह आप की पावर्ज़ में है कि अगर आप उस को उचित समझें तो उस को मंजूर कर लें और उस को ठीक न समझें

तो उसको रद्द कर दें। आपने उसको रद्द कर दिया। लेकिन यह बहुत ही ज़रूरी सवाल था। जब हाउस में आ ही गया तो—

श्री अध्यक्ष : अब यह मामला खतम हो गया है। आप बैठ जाइए। (This matter stands closed now. Please take your seat.)

चौधरी नेत राम : स्पीकर साहिब, मैं अभी अपनी बात कहना चाहता हूं और आपने मुझे बैठने के लिये कह दिया। मेरी अभी बात खत्म नहीं ई —

श्री अध्यक्ष: आप बैठ जाएं। Please take your seat)

(इस समय बहुत से आनरेबल मैम्बर्ज़ अपना २ प्वायंट आफ आर्डर रेज़ करने के लिये खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष: आर्डर, प्लीज़। मैं हाउस के तमाम मैम्बरों से रिक्वैस्ट करूंगा कि मैंने एडजर्नमेंट मोशन के बारे में फाइनल आर्डर दे दिये हैं। इसको चेलेंज नहीं किया जा सकता है और इस पर नहीं प्वायंट आफ आडर रेज करने की इजाजत दी जा सकती है। अगर प्वायंट आफ आर्डर के बहाने से यह मामला रेज़ करने की कोशिश की गई तो that will be deemed as obstructions in the proceedings. (Order please. I may tell the hon. Members that I have given my final decision regarding this Adjournment Motion Niether this order can be challenged nor any permission to raise points of order on the subject can be given. If any attempt is made to raise this question under the pretext of a point of order, then that would be treated as an obstruction in the proceedings.)

Naming of a Member

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ। ਰੂਲਜ਼ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਐਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ **ਇਸ** ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਾ ਡਿਸਕਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਲਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਲਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ।.........(ਸ਼ੋਰ)

Mr. Speaker : The hon. Member should please resume his seat I give him a warning.

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ.........

Mr. Speaker : The hon. Member Babu Ajit Kumar is not obeying the Chair. He is obstructing the proceedings of the House. I order him to withdraw from the House.

(*Noise and Interruptions in the House*)

I order Shri Ajit Kumar to withdraw from the House.

(*Noise in the House*)

I order Shri Ajit Kumar to withdraw from the House.

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ........

(ਸ਼ੋਰ)

Mr. Speaker ; I asked the hon. Member but he did not stop. I, therefore, order him to withdraw from the House. This is a sort of obstruction which cannot be tolerated.

(*Noise and Interruptions*).

Shri Ajit Kumar should please withdraw from the House.

(*At this stage, Shri Ajit Kumar rose to say something.*)

Mr. Speaker : No please. I order him to withdraw from the House.

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਿਰ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਹਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਵਿਦਡਰਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ?

Mr. Speaker ; The hon. Member Shri Ajit Kumar should please withdraw fromthe House. I give him a final warning. He should withdraw from the House. He did not obey the Chair. In spite of my repeated requests, he did not stop.

ਸਰਦਾਰ ਮਖਣ ਸਿੰਘ ਹਰੂਵਾਲ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਸਰ।.........

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਜਦੋਂ ਸਪੀਕਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। Please take your seat

The hon. Member Shri Ajit Kumar should please withdraw from the House.

(When the speaker is on his legs no point of order can be raised. The hon. Member may take his seat.

The hon. Member Shri Ajit Kumar should please withdraw from the House.)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਆਪ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਉ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਦੋਨੋਂ ਵਲੋਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਓਥੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਨਫਾਰਚੂਨੇਟਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਰੀ-ਕਐਸਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ।

Mr. Speaker : Let him assure that he will obey the Chair in future.

Sardar Gurcharan Singh : Sir, he will certainly obey the Chair in future.

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਡੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੂਲਜ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਐਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।........ (ਸ਼ੋਰ) (ਵਿਘਨ)

Mr. Speaker : Please take your seat.

चौधरी नेत राम : स्पीकर साहिब, मेरा व्यवस्था प्रश्न है-- (शोर) (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाएं। (The hon. Member may resume his seat.)

चौधरी नेत राम : स्पीकर साहिब, मैं व्यवस्था प्रश्न करना चाहता हूं कि --

श्री अध्यक्ष : आप को प्वायंट आफ आडर रेज करने की इजाजत नहीं दी जाती। आप बैठ जाएं। (The hon. member is not allowed to raise a point of order. He may please take his seat.)

चौधरी नेत राम : स्पीकर साहिब, मैंने पहले भी व्यवस्था प्रश्न उठाया था और आपने मुझे कहने नहीं दिया। अब भी आप मुझे कहने की इजाजत नहीं दे रहे हैं-- (शोर) (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाएं नहीं तो मैं आप के विरुद्ध ऐक्शन लूंगा। (The hon. Member may resume his seat or I will have to take action against him)

चौधरी नेत राम : स्पीकर साहिब, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि मुझे अपना व्यवस्था प्रश्न उठाने की इजाजत नहीं दी जाती है और आपने बिना सुने ही अपने आर्डर पास कर दिये। मैं तो सिर्फ मुख्य मंत्री ने जो भाषण दिया है, उस के बारे में अर्ज करनी चाहता हूं कि--(शोर) (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, प्लीज। आप बैठिए। (Order please. The hon. Member should resume his seat.)

Next item please.

CALL ATTENTION NOTICES

(*Serial No.* 84)

Comrade Bhan Singh Bhaura ; Sir, I beg to draw the attention of the Minister concerned towards the statue of queen Victoria in Baradari Gardens, Patiala, on which the inscription :

"*Victoria, Queen of England,*
Empress of India,
Mother of Her people"

infringes our national sentiments at this time when U.K. is playing treachery with us even through her tamed dogs like Bhutto. Now the Government should at once demolish this statue and replace it with any one our National Heroes. I hope the Punjab Government would take it seriously and assure the House by making positive statement.

Mr. Speaker ; This is admitted. Government to make statement.

(*Serial No.* 85)

Sardar Ajaib Singh Sandhu : Sir, I beg to draw the attention of the Government to sad state of affairs of the Sports Department of the Punjab Government in not recruiting persons belonging to the Scheduled Castes in the Department. There is no officer belonging to the Scheduled Castes either in the Directorate or as a District Sports Officer in the State. It shows that the Department has got anti-Scheduled Cate bias. The order of the Punjab Government reserving 22 per cent of the posts for the members of the Scheduled Castes are not at all cared for by the Department. Hence the question of giving them 10 per cent reservation in promotion cases does not arise.

The posts of the District Sports Officers are either filled through the Public Service Commission or through Selection by the Selection Committee of the Department. If these posts are to be filled through the Public Service Commission the minimum qualifications are B.A. and Diploma of the National Discipline Scheme and if the same are to be filled through the

[Sardar Ajaib Singh Sandhu]

Selection Committee of the Department the minimum qualifications are Matric with Diploma of National Discipline Scheme. Why this difference ?

Recently two posts of District Sports Officers were to be filled by the Selection Committee of the Department. Both these posts were reserved for the members of the Scheduled Caste. And the Scheduled Castes candidates over-fulfilling the qualifications were available. But the Selection Committee did not try to see the orders of 22 per cent reservation for the members of the Scheduled Castes in recruitment. The Committee wanted to oblige one of its members and they did actually oblige him. The Scheduled Caste candidates were ignored and non-Scheduled Castes persons were selected against the reserve vacancies.

Will the Hon'ble Minister concerned look into the matter and cancel these selections made by the Selection Committee and give these posts to the Scheduled Caste candidates who were not selected in spite of the fact that they were fully qualified for the same ?

And, also, will the Hon'ble Minister for Sports assure this Hon'ble House that the order of reservation in recruitment and promotion shall be strictly compied with by the Department in future and apprise this Hon'ble House about the steps he wishes or will take to put an end to this sad state of affairs ?

Mr. Speaker : This is admitted. Government to make statement.

(*Serial No.* 86)

Sardar Ajaib Singh Sandhu ; Sir, I beg to draw the attention of the Minister concerned towards a move initiated by a dozen I.A.S. Officers of the State for demanding immediate reduction in top heavy administration in the State facing national emergency. These Officers feel that the Secretariat in recent years has expanded beyond reasonable proportion. These Officers demand that as a first step, the number of posts in the Secretariat be reduced by one-third and the process of reduction be completed in three months. They recommend the establishment of a Committee at the highest level to find out the scope of further reduction both in the Secretariat and in the field. For the successful implementation of their recommendation, they suggest several measures, including more economical and simpler ways of working in the Secretariat and delegation of more powers to the field officers.

The suggestion of these I.A.S. Officers are reasonable and are in the interest of the nation, which must be given top consideration so as to save lakhs of rupees for the country. The matter being most important and urgent be discussed in the House.

Mr. Speaker ; This Notice is admitted. Call Attention Notices Nos. 91, 92 and 96 also deal with the same matter and they should be taken up together.

(Serial No. 91)

Sardar Balwant Singh : Sir, I beg to draw the attention of the Minister concerned towards the move initiated by a dozen I.A.S. Officers for the immediate reduction in the top heavy administration in the State. The senior officers feel that the whole administration, particularly the Secretariate has expanded beyond reasonable proportions and that it can be effectively reduced by 1/3rd. At present out of a total Revenue Budget of Rs 127 crores for the year 1965-66, the State Government is spending Rs 6 crores on General Administration alone. Another sum of Rs 9 crores is being spent up on Police. The percentage of expenditure on service with regard to the total budget is considerably high. In view of the Nationaly interest and in the contest of collecting additional resources for the fourth

Plan, will the Government encourage the move and save the tax payer from the burdens of additional taxation to the extent, the economics can be achieved by reducing the 'top heavy administration' ?

(Serial No. 92)

Sardar Gurbakhsh Singh Gurdaspuri : Sir , I beg to draw tne attention of the Government to the fact that in view of a move by the I.C.S. and I.A.S. Association for an immediate reduction in the Top Heavy Administration in the State, there is an imperative and urgent need for the establishment of a High Power Retrenchment Committee comprising of members from all the parties of this Assembly and some members of the Association to effect the required reduction and economy within three months.

(Srial No. 96)

Shri Balramji Dass Tandon : Sir, I beg to draw the attention of the Government towards the resolution of some I.A.S. and I.C.S. Officers, wno have clearly said tnat some 1/3rd number of officers are surplus and likewise all ranks of officers and employees are surplus. As such in these days of the naked agression of Pakistan Government, when economy is called for all round and sufficient funds are required for national defence, this situation of over staffing has caused anxiety to the people of the State.

Repeatedly tne Government has said that any allegation of over staffing on the part of the State Government is baseless. But this statement is a strong rebuff of the statements of tne State Government. As such it calls for serious thought. Therefore, Government sholud clear the position as to what steps tne Government is taking to economise on this issue.

मुझे एक मिनट के लिये आप इजाज़त दें। हमारे कहने का मतलब केवल यही है कि चीफ मिनिस्टर साहिब ने यहां पर उस वक्त भी कहा था कि हमारे हां टाप हैवी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। लेकिन अब तो इतने सीनियर अफसरान ने यह बात कही है।

श्री अध्यक्ष : आप की बात आ गई है । (The hon. Member has made out his point.)

मुख्य मंत्री : स्पीकर साहिब, मुझे इस मामले में यही कहना है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन रिफार्म्ज़ कमीशन हम ने अप्वायंट किया है उस की टर्म्ज़ आफ रेफ्रेंस में यह चीज़ है कि वह इस बात पर भी गौर करेगी। चुनांचि कमीशन इस बात पर भी गौर कर रही है कि जहां कहीं कोई रिडक्शन हो सकती है उस पर भी रिपोर्ट करे। वह इन सारी बातों पर गौर कर रही है, जब उस की रिपोर्ट आ जाएगी तो उस पर सरकार पूरा गौर करेगी इस लिये मेरी अर्ज़ है कि इस मोशन को एडमिट करने की कोई बात नहीं है।

(interuption)

ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਹੈ (ਵਿਘਨ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਮਜੀਏਟ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੀਫਾਰਮਜ਼ ਕਮੀਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਮੀਜੀਏਟ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

Mr. Speaker : Please take your seat. Your motion has already been admitted.

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ। ਤੁਸਾਂ ਮੇਰੀ ਕਾਲ ਅਟੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਠ ਕੇ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਲਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਲਿੰਗ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮਝਾਂ ਜਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲ ਨੂੰ ?

Mr. Speaker : Please do not try to argue. The Chief Minister has made a statement that the matter is already under the consideration of the Administrative Reforms Commission and it will be dealt with in accordance with their recommendations.

(Serial No. 87)

Sardar Kulbir Singh : Sir, I beg to draw the attention of the Minister concerned to the matter, namely, State Government's Order banning the manufacturing of the cream and other articles of food from the milk has rendered about 2 lakhs and 50 thousand workers unemployed. Ghee is prepared from the cream and the separation of cream is banned. This occupation is carried out by the people of lower middle class who are unable to invest in any other business. Most of the dairies are being run from the last forty to fifty years. Majority of them are refugees since 1947. They should have been given some alternative profession to earn their living. If they are not allowed to carry on their profession or are not provided with alternative livelihood will be compelled to migrate from the State. Therefore it is strongly demanded that the order banning separation of the cream from the milk be modified so to enable the small dairies to carry on the business of ghee making out of the cream and save them from hunger due to unemployment.

Mr. Speaker : This is admitted. Government to make statement.

Minister of State for Animal Husbandry and Agriculture (Captain Rattan Singh) : Sir, it is necessary, in this connection, to explain in some details, the background of the orders issued by the Government.

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਜੇਕਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਲੇ ਕਰ ਦਿਓ। (If the statement is a small one the hon. State Minister may read it out. But if it is a lengthy one then he may place it on the table of the House.)

ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ : ਕਾਪੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।

Mr. Speaker : You can do it tomorrow.

Minister of State for Animal Husbandry and Agriculture : I can just now read out the Statement, Sir.

Mr. Speaker : But you may make a very brief statement about it.

Minister of State for Animal Husbandry and Agriculture : Instead of making a brief statement, I would place a detailed statement on the Table of the House tomorrow.

(Serial No. 90)

Sardar Kulbir Singh : Sir, I beg to draw the attention of the Minister concerned towards the fact that thousands of acres of land were released by the Indo-Pak Treaty in 1962 which was originally owned by the Canal Department situating on right and left mariginal bund, Ferozepore. The entire land was returned to the original owner, i.e., Irrigation Department. Secretary, Revenue was, good enough to issue orders to the local revenue officers to hand over the possession to the Irrigation Department. Since

then the matter is being delayed by the local revenue officers. They are not handing it over to the Canal Department since 1962. The poor landless peasants are looking at it with hope as this whole area is to be allotted to them by the Government. Thousands of acres of land is lying waste which is cultivable and productive while the country is suffering of food shortage. Therefore, it is brought to the notice of the Reveneu Department that they should hand over the entire area to the Irrigation Department and thus implement its own decision, also have mercy on poor landless tenants who are waiting their allotment since 1962.

Mr. Speaker : This is admitted. Government to make statement.

(Serial No. 94)

Comrade Bhan Singh Bhaura : Sir, I beg to draw the attention of the Minister concerned towards the fact, namely, brutal beating given by the police of Patiala in broad day light in District Court compound on 27th October, 1965, to a farmer Shri Mohinder Singh. The advocates of the Court tried to check the police from beating but the S.I., Shri Des Raj did not care for. When the Chairman of the Bar Association interfered the poor farmer was saved but it is reported that the police is going to register a false case against some advocates who interfered at that time. This action of the police has created unrest in Patiala City. I hope the Government would clear the position.

Mr. Speaker : This is admitted. Government to make statement.

(Serial No. 100)

Comrade Babu Singh Master : Sir, I beg to draw the attention of the Government towards the paucity of Doctors in the Hospitals and Dispensaries in the State. The matter is of public utility and importance at this crucial stage when many of them are deputed to serve the wounded in the Indo-Pak conflict. The dispensaries are lying vacant due to the shortage of doctors.

The candidates who have been declared successful in the L.S.M.F. Examination on 29th October, 1965, be allowed for admission in the Condensed Course for which class has been started recently and the seats are lying vacant still at the Government Medical College, Amritsar.

Hence the matter is of grave concern and be discussed in the House to find out ways and means to meet the shortage of Doctors and to avoid the wastage of time for the L.S.M.F. Doctors who can be of great service to the country and the nation.

Mr. Speaker : This is admitted. Government to make statement.

आगे के लिये मैम्बर साहिबान को चाहिए कि जब वह काल अटेंशन मोशन का नोटिस दें तो उस में यह न लिखा करें कि यह मामला डिस्कस होना

11·00 a.m.

चाहिए। यह कन्फ्यूजिंग सी बात है। (This is admitted. Government to make statement. The hon. Members may note it for future guidance that while giving notice of a Call Attention Motion, they need not write in it that the matter be discussed. It is confusing.)

चौधरी नेत राम : स्पीकर साहिब, आप ने 26 अक्तूबर, 1965 को कहा था कि जो जो काल अटेंशन मोशन्ज मन्जूर हो जाएं, एडमिट हो जाएं तो उन का जवाब सरकार

[चौधरी नेत राम]

की तरफ से पंद्रह दिन के अन्दर अन्दर आ जाना चाहिये। मैं आप के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं बहुत सी काल अटैंशन मोशंज़ कितने कितने दिनों से एडमिट हुई हुई हैं लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक उन का कोई जवाब नहीं आया मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उन का जवाब हमें मिलना चाहिए क्योंकि अभी दो चार दिन तक असैम्बली का सैशन भी खत्म हो जाएगा और बाद में यह झूठमूठ बात करते रहेंगे।

श्री अध्यक्ष : फिकर न कर। जवाब आ जाएंगे। (Please do not worry. The replies will be forthcoming).

स्वास्थ्य मंत्री (श्रीमती ओम प्रभा जैन) : स्पीकर साहिब, अगर आप इजाज़त दें तो जिस काल अटैंशन मोशन (No. 100) को कामरेड बाबू सिंह मास्टर ने मूव किया है, उस की बाबत मैं अभी जवाब दे दूं।

Mr. Speaker: Yes.

स्वास्थ्य मंत्री : जहां तक स्टेट के अन्दर डाक्टर्ज़ की सर्विसिज़ का ताल्लुक है, जिस की तरफ आनरेबल मेम्बर साहिब ने भी ध्यान दिलाया है, मैं इस बात को वाज्या कर देना चाहती हूं कि इस बात की तरफ गवर्नमेंट की ऐन्ज़ाइटी बड़ी जबरदस्त है और हम ने कुछ अर्सा से कई ऐसे स्टैप्स लिये हैं जिन से यहां पर डाक्टर्ज की कमी को दूर किया जा सके। जो एडमिशंज़ हमारे मैडीकल कालेजिज़ में होती थी उन में स्टूडैंट्स की संख्या को बढ़ाया गया है। अमृतसर और पटियाला मैडिकल कालेजिज में पहले हर साल सौ एडमिशंज़ होती थीं और अब वहां पर 150 की गई हैं। इसी तरह से रोहतक मैडिकल कालेज में एडमिशंज़ की संख्या 50 की जगह पर सौ कर दी गई है। लुधियाना में जो आर्य मैडिकल स्कूल था उस को मैडिकल कालेज बना दिया गया है और वहां 50 स्टूडैंट्स हर साल ऐम. बी. बी. ऐस. में दाखिल होंगे जिस के लिये यूनिवर्सिटी से रैकगनिशन भी मिल चुकी है। इस के अलावा जो बहुत से स्टूडैंट्स स्टाईपेन्डस वगैरा लेते हैं उन को सर्विस के लिये बाऊंड किया जाता है। जो स्टूडैंट्स रिज़र्व सीट्स में लिये जाते हैं, जिन की एडमिशन रिज़र्व सीट्स में होती है उन को तीन और पांच साल के लिये रूरल एरीयाज़ में सर्विस करने के लिए बाऊंड करने की व्यवस्था की गई है। इस के अलावा जो ऐल. ऐस. ऐम. ऐफ. स्टूडैंट्स की एडमिशन एम. बी. बी. एस. होती है उन के लिये भी तीन साल की सर्विस वहां पर करने की बाइंडिंग है। रीज़र्व सीट्स के लिये, शिडयूल्ड कास्ट, बैकवर्ड एरीयाज़ और गर्ल्ज स्टूडैंट्स के लिये भी बाइंडिंग है। इस तरह से बहुत से स्टेप्स इस दिशा में हन ने पिछले साल से लिये हैं।

इस के अलावा एक और महत्वपूर्ण स्टैप जो हमने लिया है वह यह है कि ऐफीशैंसी बार को क्रास करने पर भी इस बात की शर्त लगाई गई है कि जो डाक्टर दो साल रूरल एरिया में सर्विस नहीं करेगा उसे ऐफीशैंसी बार क्रास करने की इजाज़त नहीं होगी। इस तरह आप देखें कि हर प्रकार से इस तरफ इम्प्रूवमेंट करने के लिये मुनासिब कदम उठाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, हमारे हैल्थ डिपार्टमैंट की ऐडवाइज़री कमेटी भी बनाई हुई है। अगर आनरेबल मैम्बरान के पास कोई भी सजैन्शन्ज हों तो वह बड़ी खुशी से

उस कमेटी में लाएं। उन पर पूरी संजीदगी के साथ गौर किया जाएगा। गवर्नमैंट को कोई भी वह कदम उठाने से गुरेज़ नहीं जिस से रूरल एरीयाज़ में डाक्टरों की कमी को दूर किया जा सके। हम ने तो यहां तक किया है कि डाक्टरों का रैज़िगनेशन भी ऐक्सैप्ट नहीं किया जाएगा जब तक कि वह चार साल तक की जनरल सर्विस न कर लें। इस प्रकार से जितनी गवर्नमेंट की पावर्ज़ है, वह इस तरह कदम बढ़ा रही है। जहां तक ऐल. ऐस. ऐम. ऐफ. को जाब्ज़ देने का ताल्लुक है उन को अभी भी जाब्ज़ मिल सकते हैं और वह नान गज़ेटिड पोस्ट्स के अगेन्स्ट काम कर सकते हैं।

(Serial No. 102)

Shri Sita Ram Bagla : Sir, I beg to draw the attention of the Minister concerned to the fact that Sirsa Tehsil (District Hissar) is in acute grip of famine. The crops have failed and fresh sowing could not be done on account of failure of rains and non-supply of canal water. The revenue, therefore, in this area should immediately be remitted and also realisation of past dues should be postponed.

Mr. Speaker : This is admitted. Government to make statement.

(Serial No. 104)

Comrade Gurbakhsh Singh Dhaliwal : Sir, I beg to draw the attention of the Minister concerned to the failure of the Department to notify in the Official Gazette the revised rates of Professional Tax as decided by the Municipal Committee, Chheharta, district Amritsar. Legally the rates of Professioal Tax framed by a Municipal Committee do not need the sanction of the Government which is duty bound as a matter of routine to issue notification on its behalf. Delay in the issuance of the necessary notification is inexplicable.

It is urged upon the Government, therefore, to issue the required notification forthwith.

Mr. Speaker : This is admitted. Government to make statement.

(Serial No. 107)

Shri Balramji Dass Tandon : Sir, I beg to draw the attention of the Government to the fact that in these days when the whole nation is engaged in achieving self-sufficiency in food, and the State Government is also making strong appeals to this effect, the Government has taken no steps to utilise the vast area of landlying vacant at Chandigarh, and at many other places acquird by the Government in public interest. It is also strange that the land acquired by the different Improvement Trusts and other agencies are lying vacant. As such, it will really be strange on the part of the Government to give "grow more" slogan on one side and tight on and taking no action regarding lands lying vacant in the Capital and in the whole of the State.

Mr. Speaker : This is admitted. Government to make statement.

(Serial No. 108)

Comrade Makhan Singh Tarsikka : Sir, I beg to draw the attention of the Government regarding C Class treatment meted to some communist detenu in State Jails and not granting family allowances even to most deserving cases.

C Class treatment given to those who are of long standing leaders of Mass Organisations and even Municipal Commissioners and Panchayat Samiti members. During Shri Gopi Chand Bhargo and Shri Sachar

Comrade Makhan Singh Tarsikka]
Ministries all the detenus were given better class treatments, irrespective of their status as required by Jail laws.

Mr. Speaker : This is admitted. Government to make statement.

(Serial No. 109)

Sardar Kulbir Singh : I beg to draw the attention of the Minister concerned to the fact that property tax was assessed long ago when property had some price and importance in the border towns. But now when people of the border towns of the Border Districts gone through heavy Bombings and shellings and every body is taking it nervelously with courage and is ready to sacrifice everything which he owns. The Government should have appreciated the conditions and economic circumstances of the Border towns. Therefore, the attention of the Governmet is seriously drawn to slum in the prices of the property , therefore, present new assessment of property tax be cancelled forthwith and abolish the property tax at Ferozepore City, Ferozepur Cantt., Guru Harsahai and Fazilka.

Mr. Speaker : This is admitted. Government to make statement.

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਅਟੈਨਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨ ਕਾਮਰੇਡ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ੧੭ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਵਲੋਂ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਚੁਕੇ ਹਨ That has been read out.

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾ, ਮੈਂ ਇਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਗਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਅਟੈਨਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨ ਤਰਸਿੱਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ, ਮਿਨਿਸਟਰਜ਼ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦ ਹੈ ਤਾਕਿ ਗਲ ਕਰ ਲਈਏ।

श्री इन्दर सिंह मलिक : स्पीकर साहिब, मेरी भी काल अटैंशन मोशन थी।

श्री अध्यक्ष : यह या तो पैंडिग होगी या डिसएलाऊ हो गई होगी।
(It will either be pending or may have been disallowed)

श्री इन्द्र सिंह मलिक : इस में डिसएलाऊ होने का सवाल ही नहीं था। वह तो डिसएलाऊ हो ही नहीं सकती।

श्री अध्यक्ष : तो मुझे मेरे चेम्बर में मिल लीजिए।

(Then the hon. Member may see me in my chamber)

Announcement by the Speaker

Mr. Speaker : I have to inform the House that the Committee of Privileges has not been able to make its Report on the question of privilege regarding the publication of the alleged wrong version of the speech of Sardar Lachhman Singh Gill, M.L.A. in the Daily 'Evening News', Ludhiana, by the date, i.e., the 31st October, 1965, prescribed for the purpose. The Chairman of the Committee of Privileges, who is not attending the Session on account of his illness, has desired that the time for making the Report on the aforesaid reference be extended up to the end of December, 1965.

The time for making the Report on the said issue be extended accordingly by the House up to the end of December, 1965.

The time was extended

Mr. Speaker : As required under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly I have to inform the House that two weeks parole granted to Comrade Makhan Singh Tarsikka, M.L.A., has been extended for a period of two months with effect from 3rd November, 1965.

Third Report of the Business Advisory Committee

Mr. Speaker : I have to report the time table recommended by the Business Advisory Committee in their Third Report which reads :—

The Committee, after some discussion, recommended that from 3rd November, 1965 onwards the business in the House shall be transacted as follows :—

Wednesday, the 3rd November,	Legislative Business.
Thursday, the 4th November ..	Legislative Business instead of Non-official business. If the Legislative Business is not finished during the normal hours of the sitting i.e. from 9.00 A.M. to 1.30 P.M. then there will be a second sitting from 3.00 P.M. to 6.30 P.M. without Question Hour.
Friday, the 5th November, ..	The House will meet from 9.00 A.M. to 2.00 P.M. and there shall be no Question hour. From 9.0 a.m to 12.30 P.M. non-official business already ballotted for Thursday, the 4th November, will be taken up and from 12.30 P.M. to 2.00 P.M. the Annual Accounts of the Pepsu Road Transport Corporation for the year 1962-63 together with financial review and Audit Report, will be taken up.
Saturday, the 6th November ..	(1) (i) Eleventh Annual Report and Accounts of the Punjab Financial Corporation for the year ended the 31st March, 1964, and (ii) First Annual Report and Accounts of the Punjab Export Corporation limited for the year 1963-64. (For two hours only). II. Motion Under Rule 84 by Sarvshri Shamsher Singh Josh and Gurnam Singh, regarding leasing of Agricultural Farm to Birla Brothers. (For the remaining time). III. There shall be no (a) Question hour, and (b)—Adjournment Motions and Call Attention Notices, etc.

Chief Parliamentary Secretary (Shri Ram Partap Garg) : Sir, I beg to move——

That this House agrees with the recommendations contained in the Third Report of the Business Advisory Committee.

Mr. Speaker : Motion moved—

That this House agrees with the recommendations contained in the Third Report of the Business Advisory Committee.

Mr. Speaker : Question is —

That this House Agrees with the recommendations contained in the Third Report of the Business Advisory Committee.

The motion was carried

Statements laid on the table by the Chief Parliamentary Secretary

Chief Parliamentary Secretary (Shri Ram Partap Garg) : Sir, I beg to lay on the Table of the House statements in regard to Call Attention Notices Nos. 57, 73 and 81.

STATEMENTS

(i) **Re. call attentions notice (No. 57) by Comarade Shamsher Singh Josh, M.L.A., Regarding Delay in the opening of Cooperative Consumers store, Chandigarh.**

In the year 1964, Government decided to convert the Fair Price shops at Simla, Nangal and Chandigarh, run by the Food and Supplies Department, into Consumers Co-operative Stores. In Pursuance of this decision, a consumers Co-operative Store was registered at Chandigarh in the first Week of March, 1965. The matter was again discussed in a meeting, held on the 10th August, 1965. between the Chief Minister, Irrigation & Power Minister, Secretary Food & Supplies and Secretary Co-operative and it was decided that the management of Fair Price Shops at Chandigarh, Simla and Nangal be transferred to Consumers Co-operative Stores simultaneously. It was also decided that to enable the Cooperation Department to organise Cooperative Stores at Simla and Nangal the financial provisions which existed in the budget of Food & Supplies Department for running Government Fair Price Shops at Chandigarh, Simla and Nangal be transferred to Cooperation Department for providing financial assistance as working capital loan etc. to Consumers Co-operative Stores to be organised at these three places. In pursuance of this decision Finance Department was moved to provide necessary funds to the extent of Rs 14,05,000 in the Supplementary Estimates 1965-66 (First Instalment).

2. Papers relating to the diversion of a sum of Rs 14,05 lacs, from the Food & Supplies Department have since been received back from the Finance Department with the observations that the Food and Supplies Department should in the first instance be requested to agree to surrender this amount from their allocation. The papers have been marked to the Secretary, Industries, Food & Supplies Department for necessary action.

3. The matter could not be finalised as yet and is being pursued. It is hoped that the Cooperative Consumers Store would be opened shortly.

(ii) RE CALL ATTENTION NOTICE

(Serial No. 73)

By Comrade Shamsher Singh Josh, regarding increase of visiting percentage of patients in General Hospital, Sector 16, Chandigarh, with the growing population of Chandigarh, & the Hospital remains under staffed and even the allocation of Medicines has also not been increased.

There are 69 posts of Medical & Para-medical staff sanctioned for the General Hospital Sector 16, Chandigarh details of which are given in the annexure. Out of the total strength of these posts only 4 posts three of Pharmacists and one of Laboratory Assistant Grade II have been lying vacant since April, 1965. It has not been possible to fill in these posts, due to non-availability of qualified personnel. Neces sary steps to make recruitment against these posts are already being taken in consultation with the Subordinate Services Selection Board.

The total number of patients who visited the General Hospital during the year 1964 was 3,91,018 as against 3,81,783 in the year 1963. Though there has been some increase in the number of visiting patients, yet keeping in view the general shortage of medical and para-medical staff, the present strength of Doctors, Dispensrers, Pharmacists, Nurses, etc. in this Hospital is considered quite sufficient. Moreover, the staffing position in this hospital is far better than that in any other district headquarters' hospital in Punjab. Besides, the Public of Chandigarh and surrounding areas have also the facility of getting treatment at the Post Graduate Institute, Sector 12, which is open to Public and Government employees. In addition to these two big institutions, there are five dispensaries in Chandigarh in different sectors where the public can get themselves treated.

Keeping all the factors in view, it is felt that there is hardly any necessity of further strengthening the staffing position in the General Hospital, for the present.

3. As regards the medicines, a total sum of Rs 6,13,896 was spent on the purchase of medicines in the year 1964-65 as against the total amount of Rs 6,73,191 in the year 1963-64. This expenditure includes the medicines for other dispensaries also which are attached to the General Hospital. The short fall of about Rs 59,295 during the year of 1964-65, is mainly due to the fact that some medicines actually purchased during the year 1964-65 could not be accounted for on the expenditure side as the payment of these medicines could not be made during this year. If this expenditure is taken into account, then it can be said that there had been no short fall in the allocation of medicines for this hospital in spite of the tight financial position.

4. It may also be mentioned that the scheme for granting re-imbursement of medical charges to Government employees stationed at Chandigarh was discontinued 4-5 years ago. Lately, Government have taken congnizance of the general feeling that the funds allocated for medicines for the Sector 16 hospital are not adequate. The case for enhancing the allocation and making some modification in the operation of the scheme regarding re-imbursement of medical charges to some categories of Government servants stationed at Chandigarh has been taken up.

ANNEXURE

(ii) The details of the posts sanctioned for General Hospital, Sector, 16, Chandigarh		(iii) Posts at present lying vacant	since when
(Gazetted)			
1. Principal Medical Officer ..	1	..	..
2. Senior Medical Officer (Women) ..	1	..	..
3. Senior Medical Officer Medical (Specialist) ..	1	..	..
4. P.C.M.S. Class III/C Hospital ..	1	..	..
5. Anaesthetist ..	1	..	..
6. Pathologist ..	1	..	..
7. Eye & ENT Specialist ..	1	..	..
8. Casuality Medical Officers (Non Gazetted)	3	..	..
9. Assistant Medical Officer X-Ray & Anaesthesia ..	1	..	..
10. Assistant Medical Officers (Women)	1	..	..
11. House Surgeons ..	2	..	..
12. Pharmacists ..	12	3	Since April 1965 May, 65 July, 1965
13. Radiographer ..	1	..	..
14. Laboratory Assistant, Grade I ..	2	..	..
15. Laboratory Assistant, Grade II ..	3	1	May, 1965
16. Dark Room Assistant ..	1	..	—

[Chief Parliamentry Secr etary]

17. Operation Theatre Assistant ..	2	..	..
18. Nursing Superintendent ..	1	..	..
19. Nursing Sisters ..	7	..	..
20. Staff Nurses ..	25	..	..
21. Nurse Dai ..	1	..	..

(iii) RE CALL ATTENTION NOTICE

(Serial No. 81)

By **Comrade Shamsher Singh Josh,** re. postponement of elections to the Zila Parishads of Ambala, Hoshiarpur, Gurgaon and Karnal.

Statement by S. Darbara Singh Home & Development Minister.

The postponement has been necessitated in view of the existing emergency and with a view to ensure that the attention of the people should continue to be focussed on war efforts.

BILLS

The Punjab State Legislature Officers, Ministers and Members (Medical Facilities) Bill, 1965.

Transport and Elections Ministers (Sardar Gurdial Singh Dhillon) : Sir, I beg to introduce the Punjab State Legislature Officers, Ministers and members (Medical Facilities) Bill.

Transport and Elections Minister (Sardar Gurdial Singh Dhillon):I beg to move —

That the Punjab State Legislature Officers, Ministers and Members (Medical Facilities) Bill be taken into consideration at once.

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਜਨ ਖਾਹ ਉਹ ਪਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਹਨ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਹਨ, ਜੋ ਜਨਤਾ ਦੀ ਖਿਦਮਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਾਰਾ ਵਕਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਰੀਲੀਫ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿਤਾ ਜਾਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਫਸਰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਔਰ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਕਿਤਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਈ ਸੀ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਆਏ ਦਿਨ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹਕ ਹਾਸਲ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਐਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਅਲਾਉਂਸ ਵੀ ਤਿੰਨ ਸੌ ਦੀ ਥਾਂ ਚਾਰ ਸੌ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਗਰ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਾਤ ਕਰ ਕੇ ਅਲਾਉਂਸ ਤਾਂ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਬਿਲ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਏ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾ ਹੈਸੀਅਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਮਨਿਸਟਰ ਐਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਫੇਅਰ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਹਥੋਂ ਸੇਵਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਅਜੀਜ਼ ਕਾਮਰੇਡ ਤਰਸਿੱਕਾ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪੁੱਤਰ ਕਪੁੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮਾਂਪੇ ਕੁਮਾਪੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। (ਹਾਸਾ) ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਐਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਐਰ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਵ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Mr. Speaker : Motion moved —

That the Punjab State Legislature Officers, Ministers and Members (Medical Facilites) Bill be taken into consideration at once.

पंडित मोहन लाल दत्त (अम्ब) : स्पीकर साहिब, मुझे अपने इस सदन के मैम्बर साथियों से बड़ी सहानुभूति है और हमदर्दी है और मैं चाहता हूं कि इन की ज़रूरियात जो हैं वह पूरी की जाएं मगर कुछ असूली बिना पर और बलंद आदर्शों की बिना पर जो कांग्रेस के नेताओं ने इन के सामने रखे थे और जिन पर उन्होंने ज़ोर दिया है, उन आदर्शों की बिना पर मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं कि खासतौर पर इस मौका पर और एमरजैंनसी के समय एक ऐसा बिल लाना जिस में सहूलतें मांगी हुई हैं और इस के साथ ही जनता पर माली बोझ डाला गया हुआ है, मैं समझता हूं कि यह एक बहुत ना-मुनासिब कदम उठाया गया है और आज वक्त का तकाज़ा यह है कि अपने लिए आराम और सहूलतें न मांगी जाएं और उस की जगह पर देश में कुर्बानी की हवा पैदा की जाए और बजाए लेने की देने की हवा पैदा की जाए। इस नुक्ता निगह से यह एक बहुत गल्त कदम उठाया जा रहा है और हमारी इस सरकार ने अपने असूलों और आदर्शों के विरुद्ध कदम उठाया है जो अपने लिये मखसूस रियायतें मांगने लगे हैं। मैं इन से अर्ज़ करता हूं कि कहां तक आप को यह शोभा देता है जब कि कांग्रेस के बड़े नेता जिन की आज तक हम पूजा करते हैं और जिन की आदम कद तस्वीर यहां पर रखी हुई है उन के आदर्श कुछ और ही कहते हैं। क्या उन के आदर्शों पर चलने का दावा करते हुए यह आप को शोभा देता है। देश की गुरबत को देखते हुए उन्होंने कहा था जब तक देश में लाखों भूखे नंगे लोग हैं मैं तब तक वस्त्र नहीं पहनूंगा। यह था आदर्श जो आप के सामने रखा गया उन की तरफ से जिन के आप नाम लेवा हैं। आप दिन प्रति दिन अपने लिये सहूलतें और एलाउंस ज़्यादा से ज़्यादा ले रहे हैं। मैं ढिल्लों साहिब से पूछना चाहता हूं कि यह कहां तक आप को मुनासिब और ज़ेब देता है। मैं ने जो इस बिल को सरकुलेट करने की मांग की है यह बिल्कुल जमहूरी असूलों के मुताबिक है। यह लोगों का राज है। आप उन के सेवक हैं तो आप को अपने मालिक यानी अवाम से यह मैनडेट लेना चाहिए कि वह आप को इन सहूलियात की इजाज़त देते हैं या नहीं। इस लिये मैं ने यह मांग रखी है कि इस बिल को मुश्तिहर किया जाए, लोगों की राय ली जाए। स्पीकर साहिब जो इस मुल्क के अवाम हैं उन की दशा

[पंडित मोहन लाल दत्त]
क्या है। यहां पर एक ग्राल इंडिया स्टडी टीम मुकर्रर हुई यह जायज़ा लेने के लिये कि देश की क्या हालत है। उस की यह रिपोर्ट है कि देश के 80 फीसदी लोगों की सालाना ग्रामदन एक हज़ार रुपये से कम है। ग्राप उस भारी ग्रकसरियत के नुमायंदे हैं, रक्षक हैं, उन की सेवा का दम भरते हैं। वह भारी ग्रकसरियत हर किसम की तिबी इमदाद से महरूम है। यह ग्रसूल है कि जिस की ग्रामदनी डेढ़ सद रुपये से कम होगी माहवार ग्रामदनी, उस को ही सरकारी हस्पतालों से मदद मिलेगी। मतलब यह है कि यहां के भूखे नंगे लोग तो दवाई को तरसते रहें ग्रौर उन के सेवक वह ग्राज मांग कर रहे हैं कि उन की सहूलतें ग्रौर बढ़ाई जाएं। पहले दस रुपये रोज़ का ग्राप के लिये मुकर्रर था डी. ए. उसे बढ़ा कर 25 कर लिया। ग्राप 300 रु० भी लो, डी. ए. भी लो ग्रौर ग्रब यह मांग ले कर ग्रा गए हैं। ग्राप की हवस की कोई हद भी होनी चाहिए। (विघ्न) (घंटी)

स्पीकर साहिब इस में एक ग्रौर कमी है जिस की तरफ मैं हाउस का ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस में बहुत ज्यादा लोगों को सहूलियात की मांग की गई है। सरदार दीदार सिंह चीदा की मौत का कैपीटल बना रहे हैं। मैं ग्रर्ज़ करता हूं मेरे पास पुराने बिल की कापी है, मैं इस को टेबल पर भी रख देता हूं। इस में सिर्फ लैजिस्लेटर्ज को ही सहूलतें देने का जिक्र है मगर ग्रब न जाने डिप्टी मिनिस्टर, मिनिस्टर, स्पीकर, चेयरमैन ग्रौर भी दूसरे भी शामिल किये गये हैं। मैं समझता हूं कि यह बात इन वुज़रा साहिबान, चेयरमैन ग्रौर स्पीकर साहिब को तो शोभा नहीं देती। ग्राज ऐमरजेंसी के हालात हैं। यह ग्रौरों के साथ ग्रपना भी गड्डा निकलवा रहे हैं। (हंसी) ग्राप बातें तो करते हैं डैमोक्रेसी सोशलिस्ट पैटर्न की मगर ग्रसल में चला रहे हैं वह पुरानी ग्रफसर शाही ग्रौर वही सहूलतें मांग रहे हैं। यह लोक राज की बातें नहीं हैं यह तो रजवाड़ाशाही की बातें हैं, पुराने तर्ज़ की हकूमत की बातें हैं। सही बात तो यह है कि यह सहूलतें मरीज़ की गरीबी को देख कर, उस की ज़रूरत के ग्राधार पर मिलनी चाहिएं मगर यहां तो सब कुछ ग्रपने लिये ही हो इस की दौड़ धूप चल रही है। मैम्बर साहिबान मुझे माफ करें जब मैं यह कहूं कि वह ग्रपने साथ ही मोह न रखें गरीब का भी ख्याल रखें, ग्रपने ग्रादर्शों का भी ख्याल रखें। ग्राप जरा सरकारी कर्मचारियों का जो छोटे हैं गरीब हैं उन का भी ख्याल रखें। मैं ग्रर्ज करता हूं कि यह जो ग्राप पालिटीशन्ज़ को इतनी एहमियत दे रहे हैं तो पालिटीशन्ज़ की तो कोई ऐहमियत नहीं है, ऐहमियत किसान की है। इसी लिये नारा लगाया गया है जय जवान, जय किसान। इन लोगों को ज्यादा से ज्यादा सहूलतें दें। ग्राप देखें पालिटीशन्ज़ क्या करते हैं सिवाये तकरीरें झाड़ने के ग्रौर कुछ नहीं करते। इस बारे में मैं ग्राप के सामने जौनाथन स्विफट का हवाला देना चाहता हूं। उन का कथन है :

"Whoever could make two ears of corn, or two blades of grass to grow upon a spot of ground, where only one grew before, would deserve better of mankind and do more essential service to his country then the whole race of policiticians put together".

तो यह जो सहूलतें हैं यह छोटे तबके को, किसान को जिन की कि देश में भारी ग्रकसरियत है, उन को मिलनी चाहिए न कि बड़े 2 लोगों को। यह लोक राज नहीं डिमोक्रेसी नहीं ढोंग है, पुराना रजवाड़ाशाही है। (घंटी)

श्री अध्यक्ष : पंडित जी, आप की बात आ गई, आप बैठिए ।

(The hon. Member may resume his seat. His point has come.)

ਕਾਮਰੇਡ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ : (ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ): ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੋ ਅਫਸਰ ੨੪ ਘੰਟੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਿਲਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਗਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁਕੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਠਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਚੀਦਾ ਹੋਰੀਂ ੩੦੦ ਰੁਪਏ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਸੀ. ਏ. ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਥੇ ਹਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀਆਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ। ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਪਾਸ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਟੀ. ਏ. ਦੇ ਰੇਟ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ੩੦੦ ਤੋਂ ੨੦੦ ਕਰ ਦਿਉ ਜਾਂ ੧੦੦ ਕਰ ਦਿਉ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਖਾਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਕਈ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਵਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਰੀਸਰਚ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਹਨ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਵਡਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਦੇ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਕ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

(Shri Ram Saran Chand Mittal a member of the panel Chairmen in the Chair)

परिवहन तथा निर्वाचन मन्त्री (सरदार गुरदयाल सिंह ढिल्लों) : चेयरमैन साहिब, अगर आप की इजाज़त हो तो इस में चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी का नाम भी शामिल कर लिया जाए। और इस की एमन्डमेंट कर ली जाए।

आवाज़ें : लिख दो जी।

परिवहन तथा निर्वाचन मंत्री : मैं चेयरमैन साहिब अर्ज़ करना चाहता हूं कि इस बात की बहुत देर से ज़रूरत थी कि लैजिस्लेटर्ज़ को मैडिकल की सहूलियतें दी जातीं। इस पर पंडित मोहन लाल दत्त जी ने एतराज़ किया है और सुझाव दिया है इस के बारे में अगर मान लिया जाए तो यही सोचा जा सकता है कि सरकार की तरफ से यही प्रसक्राइब कर दिया जाए कि हरेक लैजिस्लेटर के पास दो लंगोटे और कमीज़ें दी जाएं और मिनिस्टरान के पास एक साइकल हो और उसे खेती बाड़ी करने और व्योपार करने की इजाज़त दे दी जाए और इस के साथ वह वज़ारत भी करें और किसी किस्म की उन्हें तनखाह लेने की ज़रूरत नहीं। (हंसी) मैं पंडित जी को बताना चाहता हूं कि मैं बाहर के मुल्कों में लैजिस्लेटर्ज़ को जो अमेनेटीज़ हैं वह देख आया हूं हरेक लेजिस्लेटर के पास सरकारी गाड़ी है वहां पर भी विधान सभाएं हैं उन्हें आफिस मिला हुआ है हर एक के पास ज़िला हैडक्वार्टर पर एक छोटा सा दफतर है जहां पब्लिक की कम्पलेंटस आती हैं और फिर हरेक को टाईपिस्ट मिला हुआ है। यहां पर तो ऐसी कोई बात ही नहीं और यहां के मिनिस्टरज़ को होल डे ही नहीं, होल नाइट को भी इन्हें काम करना पड़ता है इस लिये अगर बिमारी की हालत में किसी को नबज़ दिखा लें या हस्पताल में जा कर इलाज कराने की सहूलत इन्हें हों तो कोई ज्यादा नहीं। इस लिये, चेयरमैन इसको पास कर देना चाहिए।

श्री सभापति : आप जो एमैंडमैंट देना चाहते हैं वह डेफीनीशन में आ जाती है इस लिये किसी फरदर एडीशन की ज़रूरत ना होगी। (The amendment proposed to be given by the hon. Minister is covered by the definition. There is no need for making any further addition.)

परिवहन तथा निर्वाचन मंत्री : मैं तो यह समझता हूं कि इधर कौंसिल आफ मिनिस्टर्ज़ में तो चीफ पार्लियामैंटरी सैक्रेटरी शामिल हैं इस लिये अगर वैसे ही इस में बगैर किसी एमैंडमैंट के शामिल हो सकें तो फिर किसी तरमीम देने की ज़रूरत नहीं।

बाबू बचन सिंह : आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर, सर। बात यह है कि पिछले दिनों इस असैम्बली के स्पीकर ने एक रूलज़ कमेटी बनाई थी और उस में इस बात पर काफी बहस हुई और काफी मिन्त और खुशामिद के बाद इन्हें वज़ीरों को लिस्ट में शामिल किया गया था और अब अगर आप रूल्ज़ को उल्ट देंगे तो इस रूल की दुरगत हो जाएगी। रूल्ज़ कमेटी कहती है कि चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी को वज़ीरों की लिस्ट में शामिल समझा जाए और आप कहते हैं कि उन्हें अलग रखा जाए।

श्री सभापति : कोई दुरगत नहीं होगी। (This will involve no contravention of any rule.)

पंडित चिरंजी लाल शर्मा : मैं कोई तकरीर इस बिल पर करने के लिये नहीं खड़ा हुआ। मैं तो सिरफ इतना ही अर्ज़ करना चाहता था कि ढिल्लों साहिब ने दूसरे मुमालिक का हवाला दिया है कि वहां पर कितने वसीह पैमाने पर लैजिसलेटर्ज़ को ऐमेनेटीज़ दी

गई हैं और हम ना तो टाइपिस्ट मांगें ना कोई आफिस मांगें आप इतना तो कर दें कि हरेक लैजिसलेटर्ज़ को गाड़ी दे दें और अगर मुफत न देना चाहें तो पैसों पर ही दे दें। (हंसी) ।

Mr. Chairman : Question is —

That the Punjab State Legislature Officers, Ministers and Members (Medical Facilities) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Chairman : The House will now consider the Bill Clause by Clause. Clause 2 is before the House.

Pandit Chiranji Lal Sharma, a Members of the Panel of Chairmen in the Chair).

Sardar Gurnam Singh (Raikot) : Sir , I beg to move —

In sub-clause (1), for the words 'by rules made by the State Government in this behalf" namely, the following words shall be substituted —

"in this behalf by rules made, in respect of persons referred to in clauses (i), (ii) and (iii), by the State Government and in respect of persons referred to in (iv), by the Chairman of the Punjab Legislative Council so far as members of such Cou' cil are concerned and by the Speaker of the Legislative Assembly so far as Members of such Assembly are concerned, namely".

In sub-clause (2), between the words "shall' and "be", occurring for the first time, the words' come into force on being notified and" shall be inserted.

Mr. Chairman : motion moved —

In sub-clauses (1), for the words "by rules made by the State Government in this behalf namely", the following words shall be substituted —

"In this behalf by rules made, in respect of persons referred to in clauses (i), (ii) and (iii), by the State Government and in respect of persons referred to in clause (iv), by the Chairman of the Punjab Legislative Council so far as members of such Council are concerned and by the Speaker of the Legislative Assembly so far at Members of such Assembly are concerned, namely"

In sub-clause (2), between the words 'shall' and 'be', occurring for the first time, the words' come into force on being notified and' shall be inserted.

श्री राम सरन चन्द मित्तल (नारनौल) : मैं ने जो अमैण्डमैंट दी है इस का कारण यह है कि अगर इस बिल को मौजूदा शक्ल में पास कर दिया गया तो एक लैकूना नज़र आएगा। यहां यह पहले लिखा हुआ है कि

"..........shall be entitled to such medical facilities for himself and for members of his family as may be prescribed by rules........"

यह गड़बड़ नज़र आएगी। इस लिए मेरी एमैण्डमैंट यह है जो मैं पेश करता हूं।

In sub-clause(1), lines3-4, for "such medical facilities for himself and for members of his family" substitute "all medical facilities available in Government dispensaries, medical colleges and institutes or other medical institutions in the prescribed manner for himself and for such members of his family ".

मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर फैमिली की डैफीनीशन रूलज़ के अंदर आ जाये तो इस से यह कलियर हो जायेगा कि किस मैम्बर आफ फैमली को रखा जाये और किस

को ना रखा जाये। इसी तरह फैसिलीटीज़ के लिये भी रूल्ज़ में आ जाये कि वह मैम्बर्ज़ को किस तरह मिलनी चाहियें। मेरी इसकी एमैंडमैंट है कि :—

"In sub-clause (2), line 1, between "shall and "be" insert come in to force on the day of its publications in the Punjab Government Gazette and".

मैं अर्ज़ कर रहा था कि इस के मुतालिक रूलज़ बना दिये जायें इन इलफाज़ के आ जाने से जो इस के लिये हमें अथार्टी चाहिये वह भी हो जायेगी और यह एक लैकुना है जो दूर हो जायेगा।

Mr. Chairman : Motion moved—

In sub-clause (1), lines 3-4, for "such medical facilites for himself and for members of his family" substitute "all medical facilities available in Government dispensaries, hospitals medical colleges and institutes or other medical institutions in the prescribed manner for himself and for such members of his family".

In sub-clause (2), line, 1 between "shall" and "be" insert "come into force on the day of its publication in the Punjab Government Gazette and".

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ) : ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਗਵਰਮੈਂਟ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰੂਲਜ਼ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਨਸ਼ਲ ਇਮਪਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਹੋਣ ਜਿਥੋਂ ਤਕ :—

So far as Parliamentary Secretariate is concerned and so far as relations of the presiding officers with the Government are also concerned ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕਿਆ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹੋ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਇਕ ਰੂਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਦੀ ਪਾਵਰਜ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨਾਨੀਮਿਟੀ ਆਫ ਰੂਲਜ਼ ਵੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਮੈਂਟ ਸਰਵੈਂਟਸ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਡੀਮਾਂਡ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਰੂਲਜ਼ ਉਹ ਇਸ ਵਿਚ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਗਵਰਮੈਂਟ ਦੇ ਇੰਮਪਲਾਈਜ਼ ਤੇ ਐਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਘਟ ਵਧ ਫੈਸਿਲੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਐਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਟਸਲ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ (ਲੁਧਿਆਣਾ ਉੱਤਰ) : ਮੈਂ ਇਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਕ ਨੁਕਤਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਬੜਾ ਚਿਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਮਨਿਸਟਰ ਬਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁਲ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।......

(ਇਕ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ-ਕੁਰਸੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੀਮਾਗ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)

ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ। ਇਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਬਦਲਨ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਔਰ ਅਕਲ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਅਸਰ ਪਿਆ ?

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਲਾ ਦੀ ਅਮੈਂਡਿੰਗ ਪਾਵਰ ਦਾ ਤਅੱਲੁਕ ਹੈ ਇਹ ਪਾਵਰ ਇਸ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਨੂੰ ਹੈ ਗਵਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ ਬਨਿਸਬਤ ਗਵਰਮੈਂਟ ਦੇ। ਜੇ ਗਵਰਮੈਂਟ ਰੂਲਜ਼ ਬਣਾਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਥੇ ਇ ਬੋਲ ਵੀ ਨਾ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਲੇਜਿਸਲੇਚਰਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਗਵਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਸਪੀਕਰ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਹਨ ਗਵਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਫਾਇਨੈਂਸ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਇਸ ਮੁਆਮਲੇ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅੰਡਰ ਰੂਲਜ਼ ਜੋ ਹੋਵੇ ਉਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਸਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਾਜ਼ਾ ਕਰਨ।

श्री सभापति : चौधरी दर्शन सिंह आप के प्वायंट आफ आर्डर के जवाब में बता दूं कि जब से मैं इस कुर्सी पर आया हूं मैं किसी एक पार्टी को नहीं देखता, सब को भूल जाता हूं। इतना फरक मेरे में आया है। (I may tell the hon. Member Chaudhri Darshan Singh that when I occupy this Chair forget my party affiliation. This is the change that I feel in myself.)

Transport and Elections Minister (Sardar Gurdial Singh Dhillon) **:** Mr. Chairman, the observations made by you are of temporary character. You should know the hardness of this Chair. I can well imagine and judge your observations having occupied this Chair for 10/12 years.

Now coming to the Bill, I very much appreciate the suggestions made by my honourable friend, Justice Gurnam Singh. They will be kept in view, and I may assure him that so far as the Members are concerned, we will take into confidence, both the Speaker of the Vidhan Sabha and the Chairman of the Vidhan Parishad, while finalising the Rules and even the subsequent amendments of these Rules. So far as Shri Mital's amendment is concerned, if we go by the words it makes no difference. We have got already in this connection, a prescribed procedure for the public servants and we cannot go beyond that. We have taken points from the Rules governing the Lok Sabha and the Rajya Sabha in this connection. As for the coming into force of the Act, we will see that it is notified, alongwith the Rules, as early as possible. The Bill, when passed, as you know, has yet to go to the Upper House. So such things take some time to finalise. I may also assure that the Member, his family and dependents will be properly defined as has been done in the Rules governing Government Servants. I think, these assurances will suffice. With these observations, Sir, I would request these hounourable friends, who have brought forth their amdnements, to withdraw them.

Sardar Gurnam Singh : Mr. Chairman, as far as my amendment at No. 1 is concerned, in view of the assurances given by the hon. Minister, I would seek the permission of the House to withdraw it.

Mr. Chairman : Has the hon. Member leave of the House to withdraw his amendment ?

Voices : Yes.

The amendment was, by leave withdrawn

Sardar Gurnam Singh : As far as the second amendment regarding insertion of the words "come into force on being notified and" between the words "shall" and "be" occuring for the first time in sub-clause (1), I would suggest that the experience of rule making power given to the Government is rather sad. It takes sometimes six months and sometimes even one year for making the rules and some time rules are not made at all. I think this is a very innocent amendment and I still appeal to him to accept it.

Transport and Elections Minister (Sardar Gurdial Singh Dhillon) :I assure the hon. Sardar Gurnam Singh that we will bring those Rules very shortly. As a matter of fact I think the draft Rules are almost ready. I do not know if he will be able to avail of it.

Sardar Gurnam Singh : I am sorry, I do not want to avail of it.

Then, Mr. Chairman, in view of what the hon. Minister has said, I would seek the permission of the House to withdraw this amendment as well.

Mr. Chairman : Has the hon. Member the leave of the House to withdraw his amendment ?

Voices : Yes.

The amendment was, by leave, withdrawn

Mr. Chairman : Now I will put the amendment of Shri Ram Saran Chand Mital to the vote of the House .

Shri Ram Saran Chand Mital : Mr. Chairman, I beg to seek the permission of the House to withdraw my amendments at Nos. 4 and 5.

Mr. Chairman : Has the hon. Member the leave of the House to withdraw his amendments ?

Voices : Yes.

The amendments were, by leave, withdrawn

Mr. Chairman : Question is —

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried

CLAUSE 1

Mr. Chairman : Question is —

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried

TITLE

Mr. Chairman : Question is —

That the title be the title of the Bill.

The motion was carried

Elections and Transport Minister (Sardar Gurdial Singh Dhillon): Sir, I beg to move —

That the Punjab State Legislatire Officers, Ministers, and Members (Medical Facilities) Bill, be passed.

Mr. Chairman): Motion moved —

That the Punjab State Legislature Officers, Ministers and Members (Medical Facilities) Bill, be passed.

कामरेड राम प्यारा (करनाल) : चेयरमैन साहिब, मैं इस लिहाज़ से तो गवर्नमैंट का मशकूर हूं कि एम. एल. एज. और उन की फैमिलीज़ के लिये गवर्नमैंट ने कुछ सोचा। मैं एक बात गवर्नमैंट के नोटिस में लाना ज़रूरी समझता हूं कि आनरेबल मिनिस्टर ने एक आनरेबल मैम्बर पंडित जी की बात का मज़ाक उड़ाया और कहा कि क्या लंगोटी लगा के रहें, या झोंपड़ी में रहें वगैरह वगैरह, लेकिन यह हकीकत है कि जो यह बिल ला रहे हैं और पास कर रहे हैं उस से भी बड़े आदमी ही फायदा उठायेंगे और गरीब लैजिस्लेटर

फिर रह जाएगा। मैंने असैम्बली में एक सवाल पूछा था जिसका जवाब मुझे मिला था। सवाल यही था कि क्लास फोर से ले कर क्लास वन तक दवा की री-एम्बर्समेंट का क्या रेशो बनता है तो जवाब मिला था कि क्लास फोर को सिर्फ 2 आने पर हैड, और कांस्टेबल से इंस्पैक्टर तक 1 रुपया पर हैड मैडीकल रिलीफ मिला लेकिन डी. एस. पी. और आई. जी. पुलिस तक लोगों को 34 रुपया पर हैड मिला। यह रेशो था जो गवर्नमेंट को खर्च करना पड़ा था। तो हालत यह है जनाब कि हम कहते तो हैं कि सोशलिस्ट पैटर्न बनायेंगे या बना रहे हैं मगर जिन की तनखाह ज्यादा है वही बहुत ज्यादा फायदा उठाते हैं और जिनकी कम है वह बहुत कम। हालांकि रैवेन्यू सारे ही देते हैं। मैं गुस्ताखी तो नहीं करना चाहता लेकिन यश जी, मेजर हरिन्दर सिंह, सरदार दिलबाग सिंह या बहुत सारे और ऐसे हैसियत के मैम्बर्ज़ हैं कि इन को मैडीकल रिलीफ मिल जाए तो ठीक है, और न मिल जाए तो भी ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पंडित जी ने जिस भावना से अपनी बात कही वह पूरी नहीं की जा रही है। पहले भी कहा गया था कि अगर रिलीफ ही सोचना है तो मैम्बरों का अलाउंस 300 की बजाए 400 रुपया कर दिया जाए मगर इमरजैंसी को मद्देनज़र रख के यह नहीं किया गया। आनरेबल मिनिस्टर ने यहां यह हवाला दिया कि फारेन कंट्रीज़ में लैजिस्लेटर्स को बड़ी सहूलियात मिलती हैं मगर यहां इस बिल में कोई रियायत दिखाई नहीं देती। हां, जो रियायत मिलेगी वह चन्द आदमी जो यहां चंडीगढ़ में रहते हैं, जैसे जस्टिस साहब को ज़रूर इलाज की पूरी फैसिलटी मिल जाएगी और जो मैम्बर साहबान दूर रहते हैं उन को तो वही एक या दो आने की गोली मिलेगी। यह बिल ज्यादा पुरअसर हो सकता था अगर ऐसा कर दिया जाता कि जिन की आमदनी थोड़ी है उन को फसिलटी दी जाएगी। अब जो शहरों में रहते हैं उन को तो मैडिकल फैसिलिटी बैस्ट और चीपैस्ट मिलेगी लेकिन जो दूरदराज़ रहते हैं जैसा मैंने कहा है उन को बहुत कम मिलेगी और बहुत मामूली किस्म की दवाएं मिलेंगी। यहां पर एक और सवाल पैदा हुआ था कि तनखाहें बढ़ाओ और अलाउंस कम करो मगर उस में चूंकि कैपीटलिस्ट तबके के लोग हैं उन को फायदा नहीं होता क्योंकि अलाउंस पर तो टैक्स है नहीं और इनकम पर है इस लिये उन्होंने ऐसा नहीं होने दिया। और यही नहीं मैं उस बात की तरफ जाना नहीं चाहता मगर लैजिस्लेटर्स की अगर वह लिस्ट देखी जाए कि नैशनल रिलीफ फंड में किसने कितना कितना दिया तो कलई खुल जाएगी। और उन्हीं लोगों पर गवर्नमैंट की तरफ से हुए खर्च को देखा जाए तो भी यह पता चल जाएगा कि वे कौन लोग हैं जिन पर ज्यादा खर्च हुआ है? वे चेयरमैन साहिब, वही लोग है जिन की माली हालत अच्छी है। बस मैं इतना ही कहना चाहता था। आगे गुस्ताखी करने की हिम्मत इस लिये नहीं होती कि सभी आनरेबल मैम्बर या जस्टिस साहब यही कहेंगे कि कामरेड ने हमारे मुताल्लिक बातें कहीं हैं। इस लिये आप का धन्यवाद करता हुआ बैठता हूं।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਕਾਮਰੇਡ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਲਦੀ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ੯—੧੦ ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਮਗਰ ਮੈਂ ਇਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਭੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਹਾਂ, ਜਿਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ

[ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ]
ਕਾਮਰੇਡ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਲਿਆ ਦੇਣੇ ਹਨ ।

कामरेड राम प्यारा : जनाब, मैं ने यह तो नहीं कहा कि जज साहिब, ऐक्सप्लायट करेंगे बल्कि और बहुत से बड़े आदमी हैं वह फायदा उठायेंगे। यह तो उन के मन का चोर है जो खड़ों की हिमायत करके कुरप्ट आदमी की हिमायत करते हैं। मैं ने तो कैपीटलिस्टों की तरफ इशारा किया है। जो गरीब लैजिस्लेटर्स होंगे उन्हें फिर भी सहूलतें नहीं मिलेंगी।

पंडित मोहन लाल दत्त (अम्ब) : चेयरमैन साहिब, मुझे बहुत खुशी प्राप्त हुई कि एक सारे हाउस में मैं समझता था कि शायद मैं ही पागल हूं जो इसका विरोध करता हूं।

12-00 noon

(हंसी) यह तो बाहर पब्लिक फैसला देगी कि कौन पागल हैं और कौन होश में हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यह जो सुझाव है इस का फिनांस मिनिस्टर साहिब ने भी कुछ न कुछ अपने तौर पे मेरी अमैंडमैंट की ताइद करने की कोशिश की है । उन्होंने फरमाया है कि यह जो मोहन लाल ने 4,000 रुपये की लिमिट रखी है यह कुछ कम जचती है। उन के एम.एल. ए. बताते हैं कि वज़ीर बनाने वाले हम हैं यह नहीं। मेरे ख्याल में एक और बात है। अगर 4,000 रुपये की लिमिट कुछ थोड़ी है तो यह अपनी नेकनियती से रखें, इस को 5,000 कर दें। यहां पर लाख लाख रुपया कमाने वाले मेरे भाई सदस्य हैं उन्हें इस की ज़रूरत ही नहीं । अंतर होना चाहिए, कोई न कोई डिस्टिंक्शन होनी चाहिए, कोई तमीज़ होनी चाहिए। जो मुस्तहिक हैं, जो बेचारे बीमार हैं, कोई बेचारे गरीब एम. एल. ए. हैं उन को तो दें। मैं इस पर इतराज़ नहीं करता। इस लिये मैं ने यह अमैंडमैंट पेश की थी कि कुछ न कुछ अंतर होना चाहिए। मेंबर और मेंबर में कुछ अंतर भी है । कुछ लिमिट चाहिए । आप ने अवाम के लिये तो लिमिट मुकर्रर की है। 150 रुपये माहवार से ज्यादा आमदनी वाले को यह सुविधा नहीं देते। यहां भी डिस्टिंक्शन है। यह हाउस पब्लिक का अक्स है, रिफ-लैक्शन है। यह समाज की एक पिक्चर, इमेज है। इस में भी अंतर चाहिये जैसे अवाम में है, एक डिस्टिंक्शन, तमीज़ पैदा की हुई है। यहां भी जो बड़े मालदार हैं, काफी आमदनी वाले हैं, 5,000 या 6,000 रुपए की लिमिट कर दें।

ਕਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ (ਰੋਪੜ) : ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਰਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇਹ ਬਿਲ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਦੇ ਮੰਤ੍ਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਕ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਵਲ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਅਲਾਊਂਸਿਜ਼ ਐਂਡ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਐਕਟ ਹੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਅੰਡਰ ਡੀਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਲਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਅਲਾਊਂਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਡੀਟੈਨਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਅਲਾਉਂਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗਲ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ। 1942 ਵਿਚ ਇਹ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਈ

ਸੀ। ਓਦੋਂ ਸਕੰਦਰ ਦੀ ਮਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲ ਲਿਆ ਕੇ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਛ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਗਸਤ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ। ਉਸ ਸਕੰਦਰ ਮਨਿਸਟਰੀ ਨੇ 40, 50 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਡੀਟੈਨਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਅਲਾਉਂਸ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਗਸਤ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਲਿਆਂਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਮਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਊਸ ਦੇ 35 ਜਾਂ 40 ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਤ ਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਟਰੇਜ਼ਰੀ ਬੈਂਚਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਰਖਣ ਲਈ। ਜੋ ਦੋ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ ਕਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਮਰੇਡ ਮਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਭਠਲ ਛੇ ਸਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਡਰ ਲੀਗਲ ਡੀਟੈਨਸ਼ਨ ਹਨ। 1961 ਵਿਚ ਮੈਂ ਵੀ ਅੰਡਰ ਡੀਟੈਨਸ਼ਨ ਰਿਹਾ, ਪੰਜ ਚਾਰ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਨ। ਗਲ ਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਦੇ ਮੰਤ੍ਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਲਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਈਕੁਏਟ ਕਰਨ ਲਈ ਗਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ, ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਲਾਊਂਸਿਜ਼ ਤੇ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਐਕਟ ਵਿਚ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਐਕਟ ਕਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਲੀਗਲ ਡੀਟੈਨਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਅਲਾਉਂਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਤਾਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦਿਕਤ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕੇ।

परिवहन तथा निर्वाचन मंत्री (सरदार गुरदयाल सिंह ढिल्लों) : चेयरमैन साहिब, कामरेड राम प्यारा जी ने कुछ अदादो शुमार दिये पुलिस कंस्टेबलों के। हमारे बारे में तो कोई सवाल नहीं न कांस्टेबलों का, न ऊपर के अफसरों का। जो मिनिस्टरों ने लेना है वही मैम्बरों ने लेना है। कामरेड जी, बाकी जब आप को ज़मीन पर लिटाया गया था करनाल में तो आप को हस्पताल में दाखिल नहीं कर रहे थे, मेरा सिवल सर्जन से झगड़ा हो गया था, उन का प्रबन्ध नहीं होता था अगर हमारे पास यह होता तो आपको निग्लैक्ट न करता। आप ने भी कहा था कि वह उस वक्त ताश खेलने चला गया था। यह कहा था। फिर दोबारा कभी ऐसा मौका हो तो वह ऐसा नहीं कर सकता। कामरेड जी, बाकी तो यह प्यार की बातें हैं। पंडित मोहन लाल जी ने कुछ कहा है। पंडित जी का मैं पिछले 20 साल से बड़ा श्रद्धालू हूं। सब बातों में तो मैं उन की श्रद्धा पूरी नहीं कर सकता। इनकी समाज सेवा का ख्याल है। जहां तक दुन्यावी चीजों से ताल्लुक है मैं इख्तलाफ रखता हूं वरना मेरे से ज्यादा उनके लिये क्या श्रद्धा हो सकती है।

कामरेड राम प्यारा : जो ढिल्लों साहिब ने फरमाया है . . . . (विघ्न)

आन ए प्वायंट आफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन, सर। ढिल्लों साहिब ने फरमाया है कि अगर उस वक्त हमें यह अख्तियार होता तो ऐसा न होता। मुझे ठीक वक्त पर हस्पताल में पहुचाया गया। सिवल सर्जन देखते ही ताश खेलने के लिये चला गया। इस गवर्नमेंट को हक है कि उसका एक्सप्लेनेशन काल करने के लिये कहे। गवर्नमेंट ने गलती की है, उसका एक्सप्लेशन नहीं लिया। मेरा पहली दफा 300 रुपये की इन्कम के हिसाब से बिल बन कर

[कामरेड राम प्यारा]

आया था। मैंने वह बिल दोबारा बनवाया था। इसलिये मुझे उस की जरूरत नहीं थी। मैं तो एक ही बात कहता हूं जो सोशलिस्टिक पैटर्न वाली है कि जो ज्यादा आमदनी वाले हैं उन को कम रिलीफ दिया जाए और जो कम आमदनी वाले है उन को ज्यादा मिलना चाहिए।

Mr. Chairman : Question is —

That the Punjab State Legislature Officers, Ministers and Members (Medical Facilities) Bill, be passed.

The motion was carried

THE PUNJAB GRAM PANCHAYAT (AMENDMENT) BILL, 1965

Home and Development Minister (Sardar Darbara Singh): Sir I beg to move for leave to introduce the Punjab Gram Panchayat (Amendment) Bill, 1965.

Mr. Chairman : Motion moved —

That leave be granted to introduce the Punjab Gram Panchayat (Amendment) Bill.

Mr. Chairman : Question is —

That leave be granted to introduce the Punjab Gram Panchayat (Amendment) Bill.

The leave was granted

Home and Development Minister (Sardar Darbara Singh): Sir introduce the Punjab Gram Panchayat (Amendment) Bill, 1965.

I also beg to move —

That the Punjab Gram Panchayat (Amendment) Bill, be referred to the Regional Committees with a direction to make a report by the 31st January, 1966.

Mr. Chairman : Motion moved —

That the Punjab Gram Panchayat (Amendment) Bill be referred to the Regional Committees with a direction to make a report by the 31st January, 1966.

पंडित मोहन लाल दत्त (अम्ब) : चेयरमैन साहिब, मैं ने इस सम्बन्ध में मुख्तसर सी अर्ज़ करनी है। सरकार पंचायती राज को अच्छा बनाने का इरादा रखती है और उस के लिये एक स्टडी टीम बना रखी है जिस ने सारी जांच पड़ताल कर के कि इस पंचायती राज में कहां खामियां हैं अपनी रिपोर्ट देनी है। तो मैं वज़ीर साहिब से यही निवेदन करना चाहता हूं कि उस की रिपोर्ट आ लेने दें और जो सुझाव वह देते हैं उन की रौशनी में आप फिर एक कम्परीहैंसिव बिल लाएं। इस तरह पीस मील लैजिलेशन लाना कोई अच्छी बात नहीं है। इस तरह तो रोज अमैंडमैंटस ला कर न तो पंचायती राज ही ठीक होता है और न इस का जनता पर अच्छा असर पड़ता है। इस तरह तो समय और पैसा ही बरबाद होता है। यह बिल काफी समय तक रीजनल कमेटियों में घूमता रहेगा और इस तरह काफी समय और रुपया बरबाद होगा। जब आपने डीसीज़न लिया हुआ है कि सारे पहलुओं पर विचार करके पंचायती राज को अच्छा बनाना है तो फिर आप उस रिपोर्ट को क्यों नहीं आ लेने देते? मैं अर्ज़ करता हूं कि इतनी हेस्ट में इस लैजिस्लेशन को रन थ्रू न करें। जिस तरह महात्मा गांधी जी राम राज बनाना चाहते थे वह अभी तक नहीं बना है। अगर पंचायती राज को अच्छा बनाना है तो बड़े सोच विचार के बाद इस बिल को लाएं।

चौधरी इन्दर सिंह मलिक (सफीदों) : चेयरमैन साहिब, आप को भी पता है कि सरदार दरबारा सिंह ने रिजनल कमेटी में फरमाया था कि इस सिलसिले में वह पंजाब के तमाम लैजिस्लेटर्ज़ और ज़िला परिषदों और समितियों के चेयरमैनों को बुला कर एक मीटिंग करेंगे और उन से सारी सलाह करेंगे कि पंचायती राज को सुधारने के लिये कौन कौन सी अमैंडमैंटस लानी ज़रूरी हैं लेकिन अब यह उस मीटिंग को बुलाए बगैर यह अमैंडिंग बिल ले कर आ गए हैं। इस तरह से पीस मील लैजिस्लेशन लाने का कोई फायदा नहीं है। इस में जो डिफैक्टस हैं वह दूर करने ज़रूरी हैं। इस लिये उन को मीटिंग बुला कर सारी चीज़ डिसकस करके एक कम्परीहैंसिव बिल लाना चाहिए। जब यह रिजनल कमेटियों में जाएगा और पास होगा । उस वक्त तक रिपोर्ट नहीं आएगी। और अगले साल यह फिर अमैंडमैंट ले कर आएंगे इस लिये मैं कहूंगा कि अब इस बिल को वापस लें और मीटिंग बुला कर सारी चीज़ डिसकस करने के बाद इसे यहां लाएं।

Mr. Chairman : If I mistake not the Hon'ble Minister addressed a letter to the Legislators inviting their suggestion.

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ (ਸਿਧਵਾਂ ਬੇਟ ਐਸ. ਸੀ.) : ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ ਹੈਡ ਆਫ ਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਥੇ ਕੁਝ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਉਸਦੇ ਉਲਟ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰਾਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਦੇ ਕੇ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਬਲਕ ਫੰਡਜ਼ ਦੀ ਵੇਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜ ਦੀ ਗਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਅਤੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਤੇ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਥੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਵੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਐਸ. ਕੇ. ਡੇ. ਆਏ ਸਨ। ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੇਰੇ ਗੌਰ ਲਿਆਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਐਸਾ ਕੰਪਰੀਹੈਨਸਵ ਬਿਲ ਲਿਆਂਦੀ ਜਿਸ ਤੇ ਕੋਈ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇਸ ਗਲ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇ (ਵਿਘਨ) ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਰੀਜਨਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰੀਜਨਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਰੋਜ਼ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਫਿਨਾਂਸ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਦੇ ਤੇ ਅਕਲ ਦੀ ਗਲ ਦਸਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਓ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਥੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ।

ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ) : ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਰਜ਼ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਤੇ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਲਿਆਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਪਰ ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ ਘਟ ਰਿਸਪਾਂਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਇਕੱਠ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਰੀਜਨਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਸ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

[ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ]

ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਨ ਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਜੋ ਇਸ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਮਪਰੀਹੈਨਸਿਵ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਗੈਰ ਸੋਚੇ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕੋਈ ਘਬਰਾਣ ਵਾਲੀ ਗਲ ਨਹੀਂ।

Mr. Chairman : Question is— 27

That the Punjab Gram Panchayat (Amendment) Bill be referred to the Regional Committees with a direction to make a report by the 31st January, 1965.

The motion was carried

THE PUNJAB GENERAL SALES TAX (AMENDMENT) BILL, 1965 (RESUMPTION OF CONSIDERATION)

Mr. Chairman : Now the House will resume discussion on the Punjab General Sales (Amendment) Bill, 1965. When the House adjourned, yesterday, Shri Ramsaran Chand Mittal was still on his legs. He may resume his speech.

श्री राम सरन चन्द मित्तल (नारनौल) : चेयरमैन साहिब, कल सदन स्थगित होने से पूर्व मैं यह निवेदन कर रहा था कि सेल्ज़ टैक्स शुरू शुरू में बड़ा मामूली टैक्स होता था लेकिन अब इस का महत्व बहुत बढ़ गया है और गवर्नमेंट रेवैनियू का मेन सोर्स बन गया है। यह लैंड रैवेन्यू से कई गुना ज्यादा वसूल होता है लेकिन अफसोस इस बात की है कि इस के सम्बन्ध में लोगों में बहुत प्रैजुडिस है और यह प्रैजुडिस एक तबके में नहीं है कई तबकों में है जिसका नतीजा यह होता है कि सैल्ज़ टैक्स के बारे में जब भी विचार किया जाता है तो यह किसी न किसी prejudice का शिकार बन जाता है और सही हल इस का नहीं निकल पाता। इस बात से किसी को इन्कार नहीं कि गवर्नमेंट को रैवेनियू चाहिए और रैवेनियू में जो इवेज़न होता है उसे चैक करने के लिये हर एक उपाय करना चाहिये लेकिन इन सब बात में कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि इसे चैक करने का सही रास्ता अख्तियार नहीं हो पाता। ब्रिटिश राज में डिवाइड एंड रूल की पालिसी थी। उन्होंने अर्बन रूरल, एग्रीकल्चरिस्ट नान-एग्रीकल्चरिस्ट ट्रेडर नान-ट्रेडर वगैरा 2 कई सैक्शन सुसायटी के बना दिये थे और ऐसी बातें करने में ही उन की सत्ता रह जाती थी। हमें इन बातों में नहीं जाना चाहिए कि अर्बन, रूरल का इस में कोई सवाल पैदा किया जाए। हमें तमाम मामला को डिसपैशनेटली विदाउट एनी एगर एंड प्रैजुडिस मैरट पर ग़ौर करना चाहिए और जो सही बात हो उसे पकड़ना चाहिए और जो गल्त हो उसे छोड़ना चाहिए।

मैं ने इन्हीं तकलीफों को सामने रखते हुए कुछ सुझाव सदन में रखे हैं। मैं हाउस को कहना चाहता हूं कि व्यापारियों को किस तरह की दिक्कतें पेश आती हैं। समझा तो

**Note*—for previous discussion on the Bill, please refer to P.V.S. debate, Vol-II-No. 14, dated the 2nd November, 1965.

यह जाता है कि सेल्ज़ टैक्स व्यापारियों से वसूल किया जाता है। व्यापारी इस सेल्ज़ टैक्स को पे करने से घबराते हैं इसी वजह से व्यापारी इस टैक्स को अपोज़ करते हैं। जिस तरह से गांव का नम्बरदार जमींदार से लैंड रैवेन्यु इकट्ठा करता है और सरकार को दे देता है उसी प्रकार से व्यापारी और दुकानदार आम जनता से सेल्ज़ टक्स वसूल करता है और सरकार को दे देता है। व्यापारी अपने जेब में से कोई टैक्स नहीं देता। इसी तरह से एक रजिस्टर्ड डीलर दूसरे रजिस्टर्ड डीलर से माल खरीदता है तो उसे कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। आखिरकार यह टैक्स अन रजिस्टर्ड डीलर्ज़ और कनज्यूमर्ज़ को देना पड़ता है। उन से यह टैक्स वसूल होता है और सरकार को टैक्स इकट्ठा करके दे दिया जाता है। यह चीज़ हर शहर में काम करने वाले दुकानदार और गांव में काम करने वाले दुकानदार पर लागू होती है। कोई भी दुकानदार हो, वह अपने पास से कुछ नहीं देता। आखिरकार सारा बोझ कनज्यूमर्ज़ पर पड़ता है। यह एक फंडामेंटल असूल है। इस के साथ मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि कई बार सुना होगा और माननीय सदस्यों को पता भी होगा कि कोई कोई नम्बरदार जमींदारों से लैंड रैवेन्यू इकट्ठा करता है लेकिन उस को सरकार के खज़ाने में दाखिल नहीं करता। इस तरह से लैंड रैवेन्यू में भी इवेज़न होती है, जब इस के बारे में पता चलता है तो उस नम्बरदार के बर्खिलाफ ऐक्शन लिया जाता है और कई हालात में उस को प्रासीक्यूट भी किया जाता है और सजा भी हो जाती है। अगर इसी तरह से सेल्ज़ टैक्स भी इवेज़न होता है तो डिफाल्टर्ज़ के विरुद्ध एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। इस बात से कोई भी इन्कार नहीं करेगा कि सेल्ज़ टैक्स की इवेज़न को चैक करना चाहिए। इस को रोकने के लिये जितने भी सरकार कदम उठाए, उस के बारे में इस हाउस के सब माननीय सदस्य सहमत होंगे लेकिन ऐसे कदम उठाने चाहिएं जिस से व्यापार खत्म न हो। जहां पर ट्रेड के नाजायज़ तौर पर चैक किया जाता है तो उस देश में प्रौसपैरिटी नहीं आ सकती। आप किसी मुल्क को देख लें। हर मुल्क के अन्दर ट्रेड, कामर्स और इंडस्ट्रीज को डिवैल्प किया जाता है और यह तभी हो सकती है जब सब तरफ से पूरी २ कोअप्रेशन हो, कोई भी टैक्स की इवेज़न न करे। (विघ्न) सरकार को सेल्ज़ टैक्स जरूर देना चाहिए। इस में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं पहले ही अर्ज़ कर चुका हूं कि व्यापारी को अपनी जेब से कुछ भी पे करना नहीं पड़ता। गवर्नमैण्ट व्यापारियों के ऊपर कितना भी टैक्स बढ़ा दे उस का इस कम्युनिटी पर कोई असर नहीं पड़ता है। मैं मानता हूं कि इस टैक्स की इवेज़न से सरकार के रैवेन्यू में जरूर फर्क पड़ता है। लेकिन इस के साथ यह देखना भी चाहिए कि व्यापारियों को कौन सी दिक्कतें आती हैं। मैं अपने वक्त की मिसाल हाउस में रखना चाहता हूं। (विघ्न) में सेल्ज़ टैक्स के दफ्तरों में सेल्ज़ टैक्स की प्रैक्टस नहीं करता हूं। मैं ने और मेरे पूजनीय दादा जी ने कभी भी व्यापार नहीं किया लेकिन मेरे नोटिस में जो बातें आई, उन में से कुछ हाउस में रखना चाहता हूं। यह आम लोगों की शिकायतें थीं। एक सिख सज्जन जो पहले हमारे पैप्सू की पी.सी.सी. को दफतर में था। वह स्पोर्टस गुड्स को मैनूफैक्चर करता है। उस की मैनुफैक्चर करने की फैक्टरी जालन्धर में है उस की दूसरी दुकान इलाहाबाद में है। वह मेरा दोस्त है। उस ने बताया कि उस की अलाहाबाद दुकान के पास एक दूसरे आदमी की दुकान है। वह भी स्पोर्टस का माल बेचता था। वह जालन्धर में हमारे से ही सामान खरीदता

[श्री राम सरन चन्द मित्तल]

है और उसे 2 प्रतिशत सेल्ज़ टैक्स सी फार्म पर अदा करना पड़ता है। लेकिन अगर हम अपना माल ले कर अहलाहाबाद जाएं तो हमें 6 प्रतिशत सेल्ज़ टैक्स देना पड़ता है। वह सामान हमारी निस्बत सेल्ज़ टैक्स की वजह से ही कम कीमत में बेचता है। जहां पर लोगों को कम कीमत पर वही चीज़ मिल सके तो लोग हमारे से सामान क्यों खरीदेंगे? इस तरह से हमारे काम में काफी नुक्सान हो रहा है क्योंकि हमें सामान 6 प्रतिशत सेल्ज़ टैक्स लगा कर बेचना पड़ता है। अलाहाबाद वाला दुकानदार हमारे से माल खरीद कर 2 प्रतिशत सेल्ज टैक्स लगा कर बेचता है। इस तरह से यहां के दुकानदारों को नुक्सान हो रहा है। यही नहीं लुधियाने में हौज़री के व्यापारियों की शिकायत थी कि कलकत्ता वगैरह और जगह के व्यापारी हम से माल खरीद कर प्रदेश में हम से माल सस्ती कीमत पर बेचते हैं क्योंकि उन्हें 2 फी सदी टैक्स देना पड़ता है और हमें 6 फी सदी। पठानकोट के टिम्बर मरचैंट्स को ले लीजिए। जगाधरी के टिम्बर मरचैंटस को ले लीजिये, जींद के व्यापारियों को ले लीजिए। उन की भी यही शिकायत थी कि हमें दूसरी स्टेटों के मुकाबले में ज्यादा सेल्ज़ टैक्स देना पड़ता है। इस से उन का व्यापार दूसरे सूबों के मुकाबले में पनपता नहीं है। यह चीज पंजाब की ट्रेड के लिये डिसएडवांटेजिज़ है। इस की वजह से व्यापारियों को तकलीफ है। यह बातें मेरे नोटिस में आई थीं, उन को दूर करने की कोशिश की मैंने इस शिकायत को दूर किया, कानून बदला, लेकिन मैं ही जानता हूं जो दिक्कत आई, कितनी रेज़िज़टैंस हुई, कई बातें सीक्रेट नेचर की हैं, नहीं बता सकता। (विघ्न)

वित्त मंत्री : चेयरमन साहिब, यह बिल तो इन्होंने ही बनाया था और मैं ने इसको हाउस में पेश किया है।

श्री राम सरन चन्द मितल : फिनांस मिनिस्टर मेरे पास आए और पंडित मोहन लाल के पास भी आए। इन्होंने हमें कहा कि देखना कि ऐसी कोई बात न कहना जिस से जवाब देने में मुशकिल पैदा हो जाए। अच्छा, मैं इसी प्वायंट को टेक अप कर लेता हूं क्योंकि माननीय मंत्री ने यह प्वायंट रेज़ कर दिया है। इस के बारे में हम ने अपने वक्त में कैबनिट में डिटेल्ज़ में डिस्कशन की थी और इस डिपार्टमैंट में सैक्रेटरीज़ और फिनांशल कमिश्नर को अलहदा किया। केबनिट की बातें यहां पर करनी नहीं चाहिए क्योंकि सीक्रेटस लीक आउट हो जाते हैं। यह मुनासिब बात नहीं है (विघ्न) अगर यह माना ही जाये कि यह बिल मैंने तैयार किया था। जब हम ने रीज़ाइन किया और उस के बाद नई मिनिस्ट्री फार्म हुई। यह अपनी की हुई बातों में शेखियां मारते हैं। यह कहते हैं कि पिछली सरकार के बुरे काम बदल दिए। यह कहेंगे कि यहां पर ऐसी बातें नहीं होनी चाहिएं। मैं इन से पूछना चाहता हूं कि जब इन्होंने ग्राम रक्षा दल को तोड़ा और इसी तरह कई और फैसलों को रद्द किया तो इस बिल की कमियों को दूर करने की कोशिश क्यों नहीं की। यहां पर नक्शे कदम पर चलने की क्यों कोशिश की जब कि इन्हें पता था कि यह बिल गलत बना हुआ है। उस को फिर क्यों लाए। इस में एमैंडमैंट क्यों नहीं की? मैं ट्रेडर्ज़ की एक और मिसाल हाउस में रखना चाहता हूं। ट्रेडर्ज़ को एसैसिंग आथार्टी के बारे में शिकायत है। उन को शिकायत है कि सरकार ने एक ही आदमी को फाइनल अपीलेंट मुकर्रर किया है। और डिपार्टमैंट का हैड मुकर्रर कर दिया है, वह सैक्रेटरी टू दी गवर्नमेंट और फाइनैंशल कमिश्नर है। चाहिए

तो यह था कि इस के लिये दो अलहदा अफसर होते। अगर इस के नीचे का कोई अफसर इस के कहने के मुताबिक काम नहीं करता तो उस अफसर को हटा सकता है। छोटे अफसर ने बड़े अफसर के कहने के मुताबिक काम करना होगा और बड़ा अफसर अपनी मनशा के मुताबिक काम करा लेगा। पब्लिक की यह जायज़ शिकायत है। मैं समझता हूं कि उनकी इस शिकायत पर गौर किया जाए। जिस वक्त इस डिपार्टमैंट का चार्ज मेरे पास आया, उस वक्त भी एक ही सैक्रेटरी और फाइनैंशल कमिश्नर होता था। मैं ने लोगों की तकलीफ को देखते हुए इस डिपार्टमैण्ट का सैक्रेटरी जुदा कर दिया और फाइनैंशल कमिश्नर की अलहदा पोस्ट क्रीएट करायी ताकि यह काम बखूबी से चल सके। यह दोनों पोस्ट्स इंडीपैंडेंट कर दीं। यहां पर वर्तमान सरकार ज्यूडीशरी को सेपरेट करने पर शेखियां मारती है। इस के बारे में मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि शिमला में हम ने ही ज्यूडीशरी को एक्ज़ैक्टिव से अलहदा करने का फैसला किया था। इस बात को चौधरी देवी लाल ने अपनी स्पीच मे माना था कि इस के लिये फैसला पिछली सरकार ने कर दिया था और बिल वर्तमान सरकार ने ला कर पास करा दिया। मेरे कहने का मतलब यह है कि इन्होंने उस फैसले को इम्पलीमैंट ही किया। यहां पर ऐसी बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि पार्टी तो एक ही है जिस ने यह काम किया। (विघ्न) मैं अर्ज़ कर रहा था कि मैंने सैक्रेटरी टू दी, गवर्नमैण्ट और फाइनैंशल कमिश्नर की दो पोस्टें बना दी थीं लेकिन हमारे रीज़ाइन करने के बाद इन्होंने उन दोनों पोस्टों को फिर यूनाइट कर दिया जो कि सरकार ने अनडचू काम किया। अब आप बताइये कि हम ने अच्छा किया या बुरा किया? सभापति जी, मौजदा ला का जो सैक्शन 23 है उस के मातहत अगर कोई सेल्ज़ टैक्स एक्ट के किसी प्रोविज़न की कंट्राविनशन करता है तो उस के लिये

> "(23). .shall be punishable with fine not exceeding one thousand rupees, and when the offence is a containing one, with a daily fine not exceeding fifty rupees during the period of the continuance of the offence. :
>
> Provided that no of the same for an offence under this Act shall be instituted in respect prosecution facts on which a penalty has been imposed under this Act".

कोर्ट्स को यह अख्तियार दिया गया है कि प्रासीक्यूशन होने पर सज़ा दे सकती है। अब जो बिल सरदार कपूर सिंह लाए हैं इस में सैक्शन 23 की अमैण्डमैंट मुलाहज़ा फरमा लें। वह क्लाज़ 15 है, उस में लिखा है :—

> "15. **For section 23 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely—**
>
> "23. (1) Whosoever contravenes, or fails to comply with, any of the provisions of this Act or the rules made thereunder or any order or direction made or given thereunder, shall if no other penalty is provided under this Act, for such contravention or failure, be liable to imposition of a penalty, not exceeding two thousand rupees. . . ."

Penalty

If is further laid down here :

> "**An officier of the rank of a Deputy Excise and Taxation Commissioner appointed under sub-section (1) of section 3 may, aftdr affording to the dealer a reasonable opportunity of being heafmpose the penalty mentionedin sub-**

[श्री राम सरन चन्द मित्तल]

सभापति जी, अब देखिए कि उस में तो कोर्ट्स को यह अख्त्यार दिया गया है कि वह लोगों को सजा दे सकती है। उस समय लोगों को कोर्ट्स में फेथ था। लेकिन अब कोर्ट्स से वह पावर छीनी जा रही है और एक्साईज एंड टैक्सेशन के अफसरान को यह पावर दे दी गई। वहां पर एक हजार फाईन था यह दो हजार करते हैं। इस के इलावा ..

Any contravention of any provision of Law or the Rules made there under except when penalty is provided elsewhere

अब बतलाईये कि ज्यूडीशरी और एग्जेक्टिव की सेपरेशन का यह क्या ननूमा है ? कोर्टस से पावर छीन कर डीपार्टमेंट के अफसरान को दे दी गई। अफसरान में ज्यादा फेथ हो गया कि

"for any contravention whatsoever....

हमारा बिल आप देख लीजिये कि किस तरह से है। चूंकि यह बातें बीच में ले आए थे इस लिये मुझे इन का जवाब देना पड़ा। अब मैं अपने मेन सबजैक्ट पर आता हूं।

जनाब सभापति महोदय, मरचैंट्स यह चाहते हैं कि उन को ठीक तरह से काम करने दिया जाए। अगर उन को इमानदारी से काम करने दिया जाए तो ओनेस्ट मरचैंट्स बहुत खुश होंगे। मरचैंट्स इमानदार भी है और डिसऑनेस्ट भी है। हर तबके में एसा होता है। लेकिन मरचैंट्स चाहते हैं कि उन का बिजनैस ठीक तरह से चले ताकि वह लोग मुनाफा वसूल कर सके। दिल्ली और पंजाब के रेट्स डिफ्रैंट हैं। इसी तरह से दूसरी स्टेट्स में भी डिफ्रैंट रेट्स हैं। नतीजा यह होता है कि उन को नुकसान होता है। इसी लिये उस वक्त से ही कहते चले आ रहे हैं कि रेट्स ठीक होना चाहिये, यूनीफार्म होना चाहिये। यह मसला जोनल कौंसिल में भी पेश हुआ था दूसरी स्टेटस में भी यह सवाल आता रहा है लेकिन इस की इम्पलीमेंटेशन अभी तक नहीं हुई। इस के लिये मैं इन को दोषी नहीं ठहराता क्योंकि इस का प्रोसेस स्लो है लेकिन फैक्ट यह है कि यह सोर्स आफ ट्रबल जरूर है। मरचैंट्स चाहते हैं कि उन को रोजमर्रा की दिक्कतों से निजात मिले। कितनी बार इंस्पेक्टर आते हैं उनकी बहियों को ले कर चले जाते हैं, उन के अकाउंट्स चैक किये जाते हैं, रेड्ज होते हैं। वे चाहते हैं कि यह दिक्कतें न हों। इसी लिये वे कहते हैं कि टैक्स इकट्ठा ले लो, जहां पर गुड्ज मैनुफैक्चर होते हैं वहीं पर ले लो, सोर्स पर टैक्स होना चाहिये। पहले वाली गवर्नमेंट ने यह प्रिंसीपल एक्सेप्ट किया हुआ है कि टेक्स सोर्स पर लगना चाहिये। लेकिन यह बात यहीं की गवर्नमेंट के अख्तियार में नहीं है। तमाम स्टेट्स एग्री करें तो हो सकता है। वे चाहते हैं कि जिस तरह से सेंटर न टेक्सटाईल्ज पर टैक्स लगा रखा है उसी तरह से हो जाए। टैक्सटाईल्ज के मरचैंट्स फ्री हैं। उन को न तो दफ्तरों में जाना पढ़ता है और न ही बही खाते दिखाने पड़ते हैं। जैसे उन के मन में आए वे माल खरीदते हैं और बेचते हैं। उन पर कोई चैक नहीं है। टैक्स कंज्यूमर को ही देना पडता है। वे लोग इन दिक्कतों से बच जाते है। अगर टैक्स सोर्स पर हो, यूनीफार्म हो, उन को किसी प्रकार की हैरेसमैंट न हो तो उन को कोई ट्रबल नहीं होगी। रोजमर्रा की प्रेक्टिस क्या है ? इस में कोई शक नहीं है कि उन को बहुत सी दिक्कतें होती है। एक डिसऑनेस्ट मरचैंट चोरी से माल खरीद लाता है वह टैक्स नहीं पे करता। बिना टैक्स के बेचता है तो उस का माल सस्ता बिकता है।

जब सस्ता बिकेगा तो ज्यादा माल बिकेगा। इस के मुकाबला में एक ऑनेस्ट ट्रेडर जो कि ओपनली माल लाता है जिस को तमाम डाकूमैंट्स दिखाने पड़ते है उस को पूरा टैक्स देना पड़ता है। उस का माल महंगा बिकेगा इस लिये वह ज्यादा नहीं बिकेगा। अब वे ऑनेस्ट मरचैंटस कहते हैं कि क्या करें। आप ने देखा होगा कि आज इस हाउस में एडल्ट्रेशन के सम्बन्ध में सवाल आया था तो यहां पर बहस होती रही कि इंसपैक्टर तंग करते हैं। अफसरान तंग करते हैं। जहां तक इन अफसरों का ताल्लुक है मैं अपने तजरबे की बिना पर बताना चाहता हूं कि बहुत से अफसर अच्छा काम करने वाले हैं मैं उन को ट्रीबयूटस पे करता हूं कि मामूली सी तनखाह ले कर बड़ी दिक्कत से अपना गुजारा करते हैं लेकिन वे ओनेहैटली काम करते हैं। यह बात लीनाई नहीं की जा सकती कि बीच में बलैक शीप्स भी होती है। मैं चाहता था कि उन की सर्विस कंडीशनन्ज इम्प्रूप की जाएं, जो लोग अच्छा काम करने वाले हैं उन के पे स्केल बढ़ाए लेकिन वह नहीं हो सका। मैं यह बात मानता हूं कि बहुत से अफसर अच्छा काम करने वाले हैं। लेकिन यह भी फैक्ट है कि मरचैंटस को तकलीफ होती है, हैरानी होती है अगर वे किसी की इललीगल डीमांड को पूरा न करें तो उन को मुश्किल का समाना करना पड़ता है। अब आप समझिये कि कुरप्शन का सवाल कहां पैदा होता है जब मरचैंटस को इन की डीमांडज़ मीट करनी होती है तो कम मे गुजारा करते हुए भी वे इसी सिपिरट से काम करते हैं लेकिन उन को डिसऑनेस्ट मरचेंटर का भी मुकाबला करना पड़ता है फिर कुरप्शन बढ़ती है, इवेजन होता है। उन को चैक करने के लिये जितना ज्यादा सखत कानून आप बनाएंगे उतना ही ख्यादा मर्ज बढ़ता है। इस लिये मैं अर्ज करूंगा कि इन तमाम बातों के मद्देनजर यह जरूरी हो जाता है कि कि ला को बनाते वक्त ऑनेस्ट मरचैंटस के प्वायंट आफ व्यू का भी ख्याल रखा जाए। ऑनेस्ट मरचेंट के साथ डील करने के लिए उस को इतनी फैसिलीटीज़ मिलनी चाहियें जिन से वह अच्छी तरह से काम कर सके। उन के साथ फेयर डीलिंग करने के सम्बन्ध में चन्द मोटी मोटी बातों की तरफ सदन की तवज्जोह दिलाना चाहता हूं....

श्री सभापति : आप कितना टाईम और लेना चाहेंगे? (How much more time does the hon. Member wish to take?)

श्री राम सरन चन्द मित्तल : मैं आप की रूलिंग का सबजैक्ट हूं। जैसे आप चाहेंगे वैसे ही मैं करूंगा। अगर आप समझते हैं कि मैं इरेलेवेंट हो गया हूं......

Mr. Chairman : I do not want to put any check on any Member to speak so long as he is relevant. But, since so many other Members want to speak, I would request you to be as brief as possible.

श्री राम सरन चन्द मित्तल : मैं अर्ज करूंगा कि यह बिल ऐसा है जो कि चंद लोगों को ही एफैक्ट नहीं करता। इस का असर तमाम ट्रेडर्ज़ पर और कंज्यूमर्ज़ पर पड़ता है। तमाम पंजाब के ट्रेडर्ज इस से असर पज़ीर होते हैं। बड़ा इम्पार्टेंट बिल है। मैम्बर को रेलेवेंट, ब्रीफ और विदाउट मैंगिक एनी रेपीटीशन बोलना चाहिये। मैं किसी तरह की रेपीटीशन नहीं करूंगा। बहुत से मैम्बरान ने एमर्जेंसी का ज़िक्र किया है, वार का ज़िक्र किया है कि वार का इफैक्ट पड़ा है। मैं इन बातों को रीपीट नहीं करूंगा। मेरे फाज़ल दोस्त ने इस के बारे में बहुत कुछ बताया है।

[श्री राम सरन चन्द मित्तल]

अर्ज यह है कि मुझे बोलने दिया जाए। मैं कोशिश करूंगा जल्दी खत्म करने की लेकिन जिस तरह से सेल्ज़ टैक्स की इवेज़न पर चैक लगाया जा रहा है आप मुझ पर चैक न लगाएं, मैं किसी प्रकार की कोई इवेज़न नहीं कर रहा हूं (हंसी)।

बाबू बचन सिंह : आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। मिस्टर चेयरमैन, मित्तल साहिब बहुत अर्सा से ऐक्साईज़ और टैक्सेशन मनिस्टर थे। इन को इन बातों के मुताल्लिक पूरी वाकफियत है। इस लिये ऐक्स मनिस्टर पर इस तरह की कोई पाबन्दी लगाना, मेरा ख्याल है कि इस बिल के साथ बेइन्सफी होगी। मैं समझता हूं कि उन पर टाइम की किसी तरह की कोई पाबन्दी नहीं लगनी चाहिए।

Shri Ram Sharan Chand Mittal : I am very thankful to my hon. Friend.

श्री सभापति : ये बैंचिज भी आप को एकामोडेट कर रहे हैं।

(*These Benches are also accommodating him.*)

श्री राम सरन चन्द मित्तल : सभापति महोदय, इस बिल के अन्दर जो कुछ प्रोपोज़ल्ज़ गवर्नमेंट इन अमैंडमैंट्स के ज़रिए ला रही है, मैं उन की बाबत तफसील में तो नहीं, ब्रीफली कुछ अर्ज करता हूं। सब से बड़ी और अहम अमैंडमैंट यह है कि जो रजिस्ट्रेशन के लिये टैक्सेबल टर्न ओवर की एमाऊंट है उसे पचास हज़ार से घटा कर तीस हज़ार रुपया करने का सरकार का इरादा है। इस के बारे में जाती तौर पर तो मुझे कोई एतराज नहीं, गवर्नमेंट जैसा मुनासिब समझे कर सकती है, उन्होंने ठीक ही समझा होगा। आखिर जितना टैक्स है, वह कन्ज़्यूमर को ही पे करना पड़ता है चाहे यह रकम पचास हजार हो लेकिन इस से जो दिक्कत व्यापारियों को आने वाली है उस की बाबत मैं अर्ज करने वाला हूं। गवर्नमेंट को भी कुछ एक नई प्राबलम्ज़ का सामना करना पड़ेगा और वह क्या है? टैक्नीकली स्पीकिंग इस लिमिट को पहिले से आधा, या आधे के करीब किया जा रहा है। इस से क्या होगा? असैसमैंट करने के लिये आप को स्टाफ दुगना करना पड़ेगा..... ई. टी. ओज़, ए. ई. टी. ओज़, इन्स्पैक्टर्ज़ और सब-इन्स्पैक्टर्ज़ की पोस्ट्स को बढ़ाना होगा। क्लर्क और असिस्टैंट्स की जाब्ज़ को बढ़ाना होगा। आप इस को एफीशैंटली और इफैक्टिव ढंग से नहीं निभा पायेंगे जब तक कि आप स्टाफ ज्यादा न बढ़ायेंगे।

वित्त मंत्री : नहीं बढ़ाएंगे।

श्री राम सरन चन्द मित्तल : काम चल नहीं सकेगा बढ़ाए बगैर। तो बहर हाल मैं आप की बात को भी मानने के लिये तैयार हूं लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि काम बहुत ज्यादा बढ़ेगा और उसे कोप विद करना काफी मुश्किल हो जाएगा। आप को एकाऊंट बुक्स देखनी है। इवेज़न की देखभाल करने के लिये एक जगह से एकाऊंट बुक्स देखने के बाद दूसरी जगह पर जाकर फिर देखनी पड़ेंगी, एक शहर में से देख कर फिर उसी की बाबत फिगर्ज़ को टैली करने के लिये, दूसरी बातों की इनक्वायरी करने के लिये दूसरे शहर में जाकर मुतअल्लिका मरचैंट्स की एकाऊंट बुक्स को देखना पड़ेगा। यह सारा काम बगैर स्टाफ के कैसे होगा? आखिर असैसमैंट तो आप को करनी ही है और जब इस लिमिट को कम कर दिया तो लाजमी तौर पर उसी प्रोपोरशन

से स्टाफ भी ज्यादा करना पड़ेगा नहीं तो इफैक्टिवली और एफीशैंटली काम चल नहीं सकेगा और जिस मकसद के लिये आप यह स्टैप्स ले रहे हैं वह पूरा नहीं हो पाएगा। लाजमी तौर पर असैसमैंट का काम डबल हो जाएगा। मैं मानता हूं कि कुछ थोड़ा सा रुपया रैविन्यू का बढ़ जाएगा। लेकिन यह देखते हुए कि कितनी दिक्कत होगी, कितना खर्चा होगा और फरदर कुरप्शन का कितना स्कोप बढ़ेगा, इन बातों को ध्यान में रखते हुए यह प्रोविजन करना मुनासिब नहीं होगा।

फिर इसके अलावा इसी सैक्शन तीन के पार्ट । ए में जो प्रोविजन है वह मेनचीज है। जैसा कि सरदार कपूर सिंह जी ने बताया, सरकार का मरचैंट्स के साथ कुछ एग्रीमैंट है कि फर्स्ट स्टेज पर ही टैक्स लिया जाए ताकि उन के साथ धक्काशाही न हो। इसका बेसिज यह है कि उन को किसी तरह की हरसमेंट न हो, एकाउंट्स न दिखाने पड़ें और और किस्म की दिक्कतों से वे बच सकें। इसी लिए वह चाहते हैं कि जो टैक्स की रकम है वह एक ही जगह पर इकट्ठी दी जाए। लेकिन शायद आप इस बात को नजर अन्दाज कर गए कि जो सभी कन्ज्यूम होने वाली चीजें हैं वह पंजाब में ही नहीं पैदा होतीं। वह पंजाब के बाहर से व्यापारी लोग मंगवाते हैं और यहां पर बेचते हैं। मिसाल के तौर पर बनस्पति घी है। अगर वह सारे का सारा पंजाब में मैनुफैक्चर हो और यहां पर कन्ज्यूम हो फिर तो ठीक है कि आप उस पर जितना टैक्स है वह एट सोर्स लगा लें, मैनुफैक्चरिंग की स्टेज पर लगा लें और आगे जाकर रीटेलर्ज़ की सिरदर्दी खत्म हो जाए। लेकिन जब वह बाहर से आता है तो आप मैनुफैक्चरिंग की स्टेज पर कैसे लगा सकते हैं।

फिर इस के साथ ही साथ जो प्रोवीजो इस क्लाज़ के साथ रखा है वह आप देखें कि क्या है। यहां तक तो ठीक है कि जो आदमी इस टैक्स से एग्जैम्पशन चाहता है वह रजिस्टर्ड डीलर से एक सर्टिफिकेट लाकर दे दे कि उसने उस से फलां फलां चीज खरीदी है तो वह इस बादरेशन से बच जाएगा कि बार बार उस को एकाऊंट्स को देखना पड़े और तंगी हो इस से पता लग जाएगा कि वाकई उस ने पहली स्टेज पर टैक्स अदा कर दिया है। लेकिन जब इस बात का तकाज़ा होगा कि उस के सर्टिफिकेट की चैकिंग होगी, किताबें देखी जाएंगी और सारा सिलसिला होगा तो मैं यह महसूस करता हूं कि जो दिक्कत आप इस से दूर करने का विचार रखते हैं वह सैंट पर सैंट नहीं मिट सकेगी, सैवंटी फाईव परसैंट भी नहीं मिट सकेगी। हां, हो सकता है कि इस से 25 परसेंट वह दिक्कत दूर हो जाए और कुछ थोड़ा सा रिलीफ हो लेकिन सैवंटी फाईव परसैंट दिक्कत बदस्तूर जारी रहेगी। वह नहीं मिटेगी। वह सरटीफिकेट देगा तो उस की दिक्कत बच जाएगी और अगर सरटिफिकेट नहीं देगा तो वही सब कुछ जारी रहेगा। वैसे मुझे उन के साथ हमदर्दी है, जो कुछ उन के लिये हो जाए वह ठीक है लेकिन इसे कामयाबी के साथ चलाया नहीं जा सकेगा, हां, जैसे शूगर और टैक्सटाईल्ज़ के लिये है यह तमाम उसी तरह से किया जाए तो सब से अच्छी बात है लेकिन उस के लिये क्या क्या मुश्किलात हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं इन की बाबत मैं पहले ही जिक्र कर आया हूं और उन को दुहरा कर आप का ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। लेकिन इस तरह से यह कोई इफैक्टिव चीज नहीं बनेगी क्योंकि इसी बिल की क्लाज़ 4 के अन्दर जो पावर्ज़ आप लेने जा रहे हैं उस के

[श्री राम सरन चन्द मित्तल]

काफी हद तक मिसयूज़ होने की गुंजायश है। इस में लिखा है कि आप उस के सर्टिफिकेट को कैंसल भी कर सकते हैं। अब यह एक ऐसा ब्राड प्रोविज़न है, ऐसी वाईड डिस्क्रिशनरी पावर्ज़ हैं कि जिस के मिसयूज़ होने से सारे बिल का परपज़ ही डिफीट हो जाएगा। हां अगर यह साबत हो जाए कि जो टैक्स है वह अनपेड रहा है विदाऊट सफिशैंट रीज़न, फिर तो बात समझ में आ सकती है और इस बात को उसकी रीन्युअल के वक्त देखा जा सकता है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इस सारे प्रोसीज़र से निकलने के लिये मरचैंट को बहुत ज्यादा हरैसमेंट का सामना करना पड़ेगा। तो इस तरह से यह जो वाईड पावर्ज़ असैसिंग अथारिटी को सर्टिफिकेट देने की और रीनिऊअल की है इनका मिसयूज़ होगा, इसका कोई फायदा नहीं होगा। मैं इस बात को भी मानता हूं कि आप ने यह सट्रिक्ट प्रोविज़न इस लिए रखा है कि जो बोगस लोग रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं उन को चैक किया जाए ताकि जो एक दफा रजिस्ट्रेशन करा कर लाखों रुपए का माल खरीद लेता है, भाग जाता है और पता नहीं लगता कि वह फर्म भी कहां है और जैसा कि पंडित मोहन लाल जी ने कहा उसके लिये आप सिक्योरिटी या शोरटी रखना चाहते हैं। लेकिन इस में दिक्कत क्या है ? शोरटी देने के लिये जो आदमी पहले एप्लाई करेगा वह सर्टिफिकेट लेगा, फिर और दूसरे मुश्किलात का उसको सामना करना पड़ेगा। कम अज़ कम, मैं यह समझता हूं कि प्रोविज़न इस तरह का हो कि अगर किसी डीलर के मुतािल्लक शिकायत है कि उस का टैक्स अनपेड रह गया है तो जब वह फ्रैश एप्लाई करता है तो उसे चैक कर लिया जाए, यह देख लिया जाए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उस की तरफ से टैक्स की रकम अनपेड रह गई है। लेकिन यह नहीं कि जिस तरह से चाहे ले लिया जाए, आखिर कोई मैथड होना चाहिए। इस के लिए जो डिस्क्रीशनरी पावर्ज़ हैं उन को कम किया जाए। जिस पर शक हो उसी से सिक्योरिटी ली जावे और यह नहीं कि हर एक से यह सिक्योरिटी आप लें।

अब मैं, चेयरमन साहिब, क्लाज़ 6 की तरफ भी आता हूं। इस में जिस अमैंडमैंट को आप करना चाहते हैं इसमें दो चीजें हैं। एक तो यह है कि जो रीटर्न असैसिंग अथारिटी को दी जाती है तो उसके साथ एक ऐफीडैविट भी होना चाहिए। आप अन्दाज़ा लगाएं कि ऐफीडैविट के लिये खास प्रोफारमा होगा, फिर किसी मैजिस्ट्रेट के पास जाकर उस को अटैस्ट कराना होगा वगैरा वगैरा। इस के साथ ही जो क्लाज़ 6 का आखिरी पोरशन है.....

Finance Minister : Mr. Chairman, may I make a request to the Hon'ble Member that all these points may be raised by himwhen the Bill is taken up Clause by Clause.

श्री राम सरन चन्द मित्तल : मैं ने अब सिर्फ एक दो बातें और कहनी हैं बाकी मैं उस वक्त कह लूंगा।

तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि अगर एक आदमी अपनी टैक्स रिर्टन भर कर देता है और उस में वह फर्ज़ किया करता है कि यह 600 रुपए है लेकिन जब उस की एसेसमेंट की जाती है तो एसैसिंग एथारेटी वह 650 रुपये बनाती है तो इस में जो प्रोवीज़न की

गई है इस में दिया हुआ है कि जो उस को पैनल्टी होगी वह 50 प्रसेंट ग्राफ दी एमाऊंट ग्राफ दी टैक्स इन एडीशन टू दी टैक्स डियू होगी यानी अगर टैक्स 650 बनता है और उस ने 600 अपनी रिटंन में भरा है तो उस के इन के हिसाब से 325 रुपए पैनेल्टी के तौर पर देने पड़ेंगे यानी उसे कुल मिला कर 975 रुपये टैक्स के देने पड़ेंगे। मैं समझता हूं कि यह उस के साथ बड़ी ज्यादती होगी। अगर उस ने रिटंन भरते वक्त गल्ती से 50 रुपए कम अपने हिसाब से भर दिये हैं तो उस को उस 50 रुपये की बजाए 350 रुपए देने के लिये कहना ठीक न होगा। उस से ग्राप वह 50 रुपये ले लीजिए और अगर उस पर पैनेल्टी ज़रूर लगानी ही है तो ज्यादा से ज्यादा 25 रुपए पेनल्टी लगा लीजिए। उस को 50 रुपए रिटंन में कम भरने के लिये 350 रुपए देने के लिये कहना मैं समझता हूं कि इट इज़ नाट फेयर।

चौधरी नेत राम : ग्रान ए प्वायंट ग्राफ ग्रार्डर सर। इस बिल को पेश करते हुए वित्त मंत्री जी ने कहा है कि यह बिल पुरानी मिनिस्टरी का बिल है। तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब यह कहते हैं कि हम पुरानी मिनिस्टरी के वारिस नहीं बनना चाहते तो इन को क्या अधिकार है कि यह उस के बने हुए बिल यहां लाएं।

श्री सभापति : यह प्वायंट ग्राफ ग्रार्डर नहीं है। (This is no point of Order.)

श्री श्याम सरन चन्द मित्तल : फिर इस में एक चीज़ रिफण्ड के बारे में दी हुई है। इस में कहा गया है कि अगर कोई डीलर तीन साल के ग्रन्दर २ रिफण्ड के लिए अपनी एप्लीकेशन नहीं देता तो उस की वह रकम फोरफीट हो जाएगी क्योंकि वह टाईम बार्ड हो जाएगी। इस बारे में मैं अर्ज़ करता हूं यह उस के साथ ज्यादती होगी क्योंकि कई दफा एसैसिंग एथारेटी ग्ररबीटरेरली टैक्स एसैस कर देती है और जो मरचैंट होता है वह समझता है कि उस का टैक्स ज्यादा एसैस कर दिया गया है तो वह इस के लिये अपील करता है। अपील करने के लिये उसे पहले उस सारे टैक्स की पेमैंट करनी होती है हालांकि अपील के फैसला होने तक कई २ साल लग जाते हैं। अगर अपील का फैसला उस के हक में हो जाता है तो चाहिए तो यह कि गवर्नमैंट यानि डिपार्टमैंट वाले उस का वह रुपया जो टैक्स के तौर पर उस ने फालतू पे किया हुआ होता है और जिस के रिफण्ड का वह अपील के फैसले पर हकदार बन जाता है वह उस की एप्लीकेशन की इन्तज़ार किए बगैर उस को वापस कर दें और अगर यह रकम उसे तीन महीने के अन्दर २ वापस अगर नहीं की जाती और उस के बाद जब वापस की जाए उस रकम पर उतनी देर के लिये उस पर जितना इनट्रस्ट बने उस को साथ दिया जाए। इनसाफ तो यही कहता है कि उस को उस रुपए का जो उसे रिफण्ड होना है उस पर उतनी देर के लिये इनट्रस्ट दिया जाए क्योंकि अगर कोई डील्लर अपना टैक्स वक्त पर ग्रदा नहीं करता तो डिपाटमट उस पर उस के लिये पनल्टी लगा लेता है इसी तरह अगर डिपार्टमैंट उस को उस का रुपया रिफण्ड नहीं करता तो उस को उस पर इनट्रैस्ट पे करना चाहिए लेकिन इस की बजाए कि यह उस को इनट्रैस्ट पे करते यह उलटा यह कर रहे हैं कि अगर वह उस रुपये के रिफन्ड के लिए तीन साल के अन्दर अन्दर एप्लाई नहीं करता तो उस का यह रुपया टाईम बार्ड हो जाएगा।

ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੋਰਾ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਫਤ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਲਿਕ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਿਸਟਰ ਵਿਦਾਊਟ ਪੋਰਟ ਫੋਲੀਓ ਲੈ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਰਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਆਨਰੇਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ। (ਹਾਸਾ)

श्री सभापति : यह कोई प्वाईंट आफ आर्डर नहीं है। (This is no point of order.)

श्री राम सरन चन्द मित्तल : तो मैं अर्ज कर रहा था कि इस तरह गवर्नमेंट का यह फर्ज हो जाता है कि वह उस का रुपया उस को उस के घर पर पहुंचाए। और, अगर गवर्नमेंट तीन महीने के अन्दर २ नहीं करती तो उस पर उसे इनट्रैस्ट पे करे और यह विदआऊट एप्लीकेशन होना चाहिए क्योंकि जब तक उस की अपील चलती रहती है एक तो उस का वह रुपया कलाक्ड रहता है लेकिन अपील का फैसला हो जाने के बाद तो उस का रुपया उसे उस के घर पर डिपार्टमेंट को पहुंचाना चाहिए।

इसी तरह से अपील के लिये इस में एक प्रोवीज़ो आती है जिस में दिया हुआ है कि अगर एसेसिंग एथारेटी सेटिशफाईड हो जाती है कि अगर अपील करने वाला इज़ अनेबल टू पे दी टैक्स और पेनल्टी या दोनों तो वह उस को यह पे करने से एगज़ेम्पट कर सकता है और अगर सेटिसफाईड नहीं होता तो उसे अपील करने से पहले वह सारा पे करना पड़ेगा। तो इस के बारे में मैं अर्ज करता हूं कि अगर एक दूकानदार की दुकान के अन्दर माल तो है और उस का मकान या दुकान भी अपना है लेकिन उस के पास अपील के लिए टैक्स या पैनल्टी की रकम जमा कराने के लिये पैसे कैश में नहीं हैं तो एसेसिंग एथारेटी को उसे भी अनेबल टू पे का सर्टीफिकेट दे देना चाहिए। जब मैं इस महकमे का इनचार्ज था तो मेरे नोटिस में एक इसी तरह की बड़ी दर्दभरी कहानी आई थी। एक दुकानदार ने अपील करनी थी लेकिन उस के पास कैश रुपए उस के लिये नहीं था हालांकि उस की दुकान के अन्दर हज़ारों रुपए का माल था और उस की अपनी जायदाद भी थी। वह वेचारा आ कर रो पड़ा। तो इस तरह के कई केस होते हैं जिन के पास कैश तो नहीं होता लेकिन दुकान में हज़ारों रुपए का माल होता है। और इस वजह से वह अपील नहीं कर सकते। मेरे कहने का मतलब यह है कि एसे आदमियों को भी अनेबल टू पे का सर्टीफिकेट दिया जाना चाहिए जिन के पास पेनल्टी या टैक्स की रकम अपील करने के लिये इन हैंड न हो हालांकि उन की दूकान के अन्दर माल बेशक हो।
(**वित्त मन्त्री** : इस तरह तो टंडन साहिब वाली स्कीम है।)

फिर इस बिल में हाउस की सर्च के लिये भी प्रोवीजन की गई है। वैसे तो इस के अन्दर एक अमैण्डमैंट यह भी लाई गई है कि हरेक दुकानदार को अपनी दुकान के अन्दर एक लिस्ट आफ एकाऊंट बुक्स एसैसिंग एथारेटी से अथैंटीकेट करवा कर रखनी होगी और उस की एक कापी डिपार्टमेंट को देनी होगी। इस के साथ ही यह भी इस में प्रोवाईड

किया हुआ है कि अगर असैसिंग एथारेटी चाहे तो वह उस डीलर की दुकान में एन्टर हो कर उस की एकाऊंट बुक्स अपने कब्जे में ले सकती है। तो मैं कहता हूं कि जब एक दुकानदार ने अपने एकाऊंट बुक्स की लिस्ट अथेंटीकेट करवा के एक कापी अपने पास रखी हुई है और उन की लिस्ट दुकान में रखी हुई है और उस लिस्ट की एक नकल डिपार्टमेंट को भी दी हुई है तो फिर उस के घर में इस मतलब के लिये रैड करने की क्या ज़रूरत रह जाती है।

इस बारे में एक बात मैं और भी गवर्नमैंट के नोटिस में लाना चाहता हूं कि अगर एसेसिंग एथारेटी किसी डीलर को यह आर्डर दे कि वह अपनी बुक्स एथेंटीकेट कराने के लिए उस के दफतर में ले आए और जब वह वहां पर जाए तो वह अपना काम छोड़कर बैठा रहे यह ठीक नहीं होगा। इस की बजाए यह होना चाहिए कि एसेसिंग एथारेटी या तो खुद या किसी इन्सपैक्टर को इस काम के लिए आथोराईज़ कर के या उसे उस की दुकान पर इस काम के लिये भेजे या खुद वहां जा कर कर आए। दुकानदारों को इस बारे में ज़रूर सहूलत मिलनी चाहिए। चेयरमैन साहिब, मैं ने यह देखा है कि व्योपारियों को वहां दफतर में जा कर बहुत देर तक इन कामों के लिये इन्तज़ार करनी पड़ती है। मैं ने तो इस बारे में कोशिश भी की थी कि एसेसीज़ के साथ अच्छा सलूक किया जाए। अमृतसर में मैं एक बार गया था। वहां पर जो एकसाइज़ का आफिस है वह बहुत बड़ा आफिस है वहां पर एकसाईज़ कमिश्नर के दफतर के मुकाबले में भी ज़्यादा स्टाफ है। मैं ने देखा था कि सैंकड़ों की तादाद में एसैसीज़ अपनी किताबें अपनी गठड़ियों में उठाए हुए बैठे हैं और वहां न उन के बैठने की इतनी जगह थी और न ही उन के वकीलों के बैठने की जगह थी जिन को वह लोग अपने साथ लाए हुए थे और न ही उन के लिये पीने के पानी का इंतज़ाम ही था। इस लिये मैं ने वहां कहा भी था कि एसेसीज़ को रसपैक्टेबल वे में ट्रीट किया जाए और उन को दुपहर से पहले या बाद दुपहर खास वक्त देकर बुलाया जाए ताकि उन को बिजनैस के काम में कोई आबस्ट्रकशन न हो।

श्री सभापति : आप अब वाइण्ड अप कीजिए। (The hon. Member may now wind up please.)

श्री राम सरन चन्द मित्तल : मैं आप का हुकम ज़रूर मानूंगा।

श्री बलरामजी दास टंडन : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। मेरा प्वायंट आफ आर्डर यह है कि जब किसी बिल पर कोई मैम्बर बोल रहा हो और अगर वह इरेलेवेंट न हो और रिपीट न कर रहा हो तो उस के बोलने पर क्या कोई टाइम लिमिट लगाई जा सकती है?

श्री सभापति : आप का प्वायंट आफ आर्डर ठीक है। मैम्बर को इस बारे में बोलने के लिये अनफेटरड राइटस हासल हैं। वह उस वक्त तक बोल सकता है जब तक वह इररेलेवेंट नहीं है और रिपीट नहीं कर रहा। (The hon. Member's point of order is correct. A Member has an unfettered right to continue speaking so long as he is not irrelevant or does not indulge in repetition.)

श्री राम सरन चन्द मित्तल : मैं यह अर्ज़ कर रहा था कि इस डिपार्टमैंट को कमरशियल बेसिज़ पर अपना काम करना चाहिए और फियूडल इकानोमी के बेसिज़ पर या एरेस्टोक्रेटिक वे में काम नहीं करना चाहिए। इन को व्योपारियों के साथ जो के अच्छे खातेपीते लोग होते हैं अच्छी तरह से पेश आना चाहिए और कमरशियल सिप्रिट से काम करना चाहिए।

एक बात मैं पक्के आढ़तियों के बारे में अर्ज़ करनी चाहता हूं कामरेड साहिब यहां मौजूद हैं। एक वक्त यह नवांशहर या जालन्धर के मरचैंन्ट्स का डैपूटेशन लेकर आए थे। उनकी शिकायत थी कि हम रजिस्टर्ड डीलर्ज हैं लेकिन पक्के आढ़तियों का काम करते हैं। बाहर के मरचैण्ट्स के आर्डरज को हम C. form पर ऐग्जीक्यूट करते हैं। अब हम से पूरा टैक्स मांगा जाता है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का मिसयूज होना बताया जाता है। मैं ला ग्रेजुएट ज़रूर हूं लेकिन कभी सेल्ज़ टैक्स की प्रैक्टिस नहीं की। यू. पी. में जिस सीनियर एडवोकेट के पास मैं ने काम सीखा उन्होंने "ला आफ ऐजंसी" पर एक स्टैंडर्ड किताब लिखी है। मैं इस ला को समझता था। व्यापारियों की शिकायत सही और दरुस्त थी। मैंने उन की दिक्कत मिटा दी।

ईमानदार व्यापारियों की तरफ से यह कहा जाता है कि रैवेन्यू हम आप का बढ़वा देंगे लेकिन जो आप का असैसमैंट का तरीका है वह ग़लत है, यह हम को अपने पाकिट से पे करना पड़ता है। अगर हम कन्ज्यूमर से वसूल करें तो इस को पे करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप के इन तरीकों से ट्रेड नहीं रहती, व्यापार नहीं रहता, यह रौंग वे है ट्रेडरज़ के साथ डीलिंग का यह काम कर्माशियल स्पिरिट से होना चाहिए। (घंटी) चेयरमैन साहिब दो मिनट में मैं एक बात अर्ज़ कर के खत्म कर दूंगा। मैं एक ऐसे कालिज में पढ़ता था जहां पर योरपियनज़ भी पढ़ाते थे। तो वहां पर जब भी ट्रेडर्ज़ की बात चलती थी तो यह आम सुनने में आता था कि हिन्दोस्तानी ट्रेडर्ज़ डिसओनैस्ट होते हैं। इस पर हम उन से लड़ पड़ते थे। अब हम देखते हैं कि उन को डिसऔनेस्ट हम बनाते हैं, डिपार्टमैंट बनाता है, इस में ऐसी लैजिसलेशन का हाथ है। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि यह ओनैस्ट बनें, इन की ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और यह पूरी तरह से टैक्स दें, इन की रैपुटेशन बने हिन्दोस्तान की रैपुटेशन बने, हमारे ट्रेडर्ज़ का नाम दूसरे मुल्कों में ऊंचा हो। चेयरमैन साहिब, आप बार २ मेरी तरफ देख रहे हैं, मुझे आपसे बड़ा डर लगता है इस लिये मैं इस स्टेज पर ज़्यादा न कह कर क्लाज बाई क्लाज़ डिसकशन के वक्त मौका मिला तो अपनी बात आप के सामने रखूंगा। धन्यवाद।

1-00 p.m.

(At this stage the Chief Minister rose to speak.)

डाक्टर बलदेव प्रकाश : आन ए प्वाएट आफ आर्डर सर यह बेहतर होता अगर चीफ मिनिस्टर साहिब पहले मैम्बर्ज के व्यूज़ सुन लेते फिर जवाब देते..... (विघ्न)

मुख्य मंत्री (श्री राम किशन) : चेयरमैन साहिब, मैं आप का मशकूर हूं कि आप ने मुझे चन्द मिनट इस बहस के दौरान दिये हैं ताकि मैं चन्द बातों की वजाहत कर सकूं। डा० बलदेव प्रकाश जी की बात ठीक है। मिनिस्टर इनचार्ज मैम्बरान की बात सुन कर

ही जवाब देंगे मगर मैं चाहता था कि कुछ बातों की अगर वज़ाहत हो जाए तो मैम्बरान को बोलने में कुछ आसानी हो जायगी।

(Shri Rup Singh Phul a Member of the panel of Chairmen in the Chair)

मुझे खुशी हुई जब उन साहिबान ने इस बिल की खास २ मदों की तरफ सरकार की तवज्जुह खैंची जिन के वक्त में यह बिल फ्रेम किया गया था। कल फिनांस मिनिस्टर साहिब ने वज़ाहत की थी कि यह बिल पिछली गवर्नमेंट के वक्त में बना था और बिना किसी कौमा भी चेंज किये के यहां पर आया है। जैसे मित्तल साहिब ने याद दिलाया मैं इन के पास डैपुटेशन ले कर गया था और जिन सख्तियों की तरफ मैंने इन की तवज्जुह दिलाई थी वह मुझे अच्छी तरह से याद हैं। मैं ने हाउस में सन 64 के बजट सैशन में कई बातों की तरफ तवज्जुह दिलाई थी और जो २ हार्ड क्लाज़िज़ थीं उन की तरफ उन को इस बिल के ज़रिये हम पूरा करना चाहते हैं। कोई हफ्ता दस दिन हुए जब मैं ने इस बिल पर फिनांस मिनिस्टर साहिब और अफसरों के साथ ग़ौर किया और मैं ने इन से कहा कि जब आप से व्यापार मंडल के साथी मिलें तो उन के साथ सारी बात पर ग़ौर कर लें ताकि अगर मुनासिब हो तो जो हार्ड क्लाज़िज़ हैं उन को या तो डिलीट किया जाए या उन को अमैंड किया जा सके। मगर वह साथी इन से नहीं मिले। क्यों नहीं मिले मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहता। लेकिन जहां तक पंजाब सरकार का ताल्लुक है यह किसी भी तब्के या अदारे पर किसी तरह से भी सख्ती करने को राज़ी नहीं है। हमारी खाहिश है कि जितना भी रिलीफ दिया जा सकता हो दिया जाए। लेकिन आप को मालूम है कि चौथी प्लैन है, डिफैंस का सवाल है इन के लिये पैसे की ज़रूरत है ऐसे ही बिल मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी आ रहे हैं। इस बिल के मुताल्लिक कुछ आपोज़ीशन के साथियों ने और कुछ ट्रैज़री बैंचिज़ के साथियों ने भी कई बातों की तरफ सरकार का ध्यान खींचा है। मैं अर्ज़ करूं कि हम ने कई बातों पर ग़ौर कर के कुछ फैसले किये हैं, उन की तरफ जब क्लाज़ बाई क्लाज़ डिसकशन होगी तो फिनांस मिनिस्टर साहिब जब अमैंडमेंट्स आएंगी तो मुनासिब कार्यवाही करेंगे। मैं पांच सात चीजों की तरफ हाउस का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

आप को मालूम ही है कि हमारे व्यापारी भाइयों की तरफ से और कुछ मम्बरान की तरफ से भी यह मांग बड़े ज़ोर से आई कि पंजाब क अन्दर जहां तक हो सके सल्ज़टक्स फर्स्ट स्टेज पर लगाया जाए। सरकार ने इस बात को इन प्रिंसीपल माना था। अब इस को इम्पलीमैंट करने का सवाल था तो सरकार को वादा खिलाफी का कसूरवार ठहराया जा रहा था। हम ने बार २ कहा कि हम बिल लायेंगे। मगर इस में प्रज़ीडट की मन्ज़ूरी की जरूरत थी अब वह मन्ज़ूरी ली है। तो यह बिल ल आए हैं। सरकार ने इस बिल के अन्दर ऐसी क्लाज़िज़ लाई है जिस के मुताबिक फर्स्ट स्टेज पर सेल्ज़टैक्स लेने के लिये सरकार इख्तयार ले रही है। मैं अर्ज़ करूं कि इस बारे में व्यापार मंडल के रेप्रेज़टेटिव्ज़ और ऐम. ऐल. एज़. की एक कमटी बठा कर उन के मश्विरे से जिन चीजों पर फर्स्ट स्टेज पर टैक्स लगाने की जरूरत होगी, उन पर लगायेंगे। इस का इख्तयार स्टेट गवर्नमेंट के पास रहेगा। गवर्नमेंट आफ इंडिया से बात करक जिन २ चीजों का इस में इजाफा कर सकेंगे, करेंगे। ऐसा इख्तयार हम ले रहे हैं (तालियां)

[मुख्य मंत्री]

एक और बात जो हम पर आया करती थी वह यह थी कि सरकार इस का प्रोसीजर सिम्लीफाई करे। हम खुद इस के हक में हैं और हम इस सारे प्रोसीजर को सिम्पलीफाई करना चाहते हैं। चुनांचि इस के मुताबिक सरकार ने अपनी एक कमेटी बठा दी है जिस के अन्दर सक्रेटरी, एक्साईज़ ऐंड टैक्सेशन, सैक्रेटरी, फिनांस और एक्साइज़ ऐंड टैक्सेशन कमिश्नर होंगे। सरकारी नुमायंदे और एम. एल.ए. साहिबान भी होंगे ताकि इस प्रोसीजर को जितना भी सिम्पलीफाई किया जा सके किया जाए ताकि जनता को कोई तकलीफ ना हो। हम ने अपनी जगह पर कमेटी कायम कर दी है। इस तरह से हम जहां एक कमेटी के ज़रिये लिस्ट आफ कमौडिटीज़ तयार करेंगे जिन पर कि फर्स्ट स्टेज पर टैक्स लगेगा साथ ही यह भी देखेंगे कि प्रोसीजर को कैसे सिंपलीफाई किया जा सकता है।

चेयरमैन साहिब, आप को मालूम है कि जब इस सरकार ने चार्ज सम्भाला था तो इस न ऐलान किया था कि यह इन्सपैक्टोरेट सिस्टम को रैशनलाइज़ करना चाहती है। चुनांचि मैं अर्ज़ करूं कि हम ने एक इम्पार्टेंट कमेटी बिठाई है वह यह काम दिन प्रति दिन कर रही है। इस के अलावा मैं कुछ और बातें भी अर्ज़ करना चाहता हूं।

आप ने देखा है कि इस बिल के जरिए से जो 50,000 रुपये का क्वानटम था उस को कम कर के 30,000 किया जा रहा है। इस बारे में दूसरी स्टेट्स की पोजीशन इस तरह से है: आंधरा प्रदेश, 10,000 रु० आसाम 12,000, महाराष्ट्र 30,000, मध्यप्रदेश 15,000, मद्रास 10,000, उड़ीसा 10,000, उत्तरप्रदेश 12,000, केरला 10,000 राजस्थान 15,000, दिल्ली 30,000, तो हमारी खाहिश थी कि हम भी दिल्ली के साथ हों, इस लिए 30,000 तक लाए हैं। अगर मैम्बरान समझते हैं ....

श्री बलरामजी दास टंडन: आन ए प्वायंट आफ इनफरमेशन। क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन स्टेटस का उन्होंने पहले जिक्र किया है क्या उन में भी यह पहले ज्यादा था और बाद में कम किया गया?

मुख्य मंत्री: मैं ने अर्ज़ किया है कि दूसरी स्टेटस में हम से कम है। तो भी मैं आप के ज़रिये यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि इस में गवर्नमेंट के किसी प्रेस्टीज की बात नहीं है अगर मेम्बरान की यह खाहिश है तो इस मामले में हम इन की राय का एहतराम करेंगे अगर आप यह चाहेंगे कि यह रकम बढ़नी चाहिए। इस बात को ध्यान में रखें कि कन्ट्री में आज रुपये की जरूरत है। लेकिन इतना मैं अर्ज़ कर देना चाहता हूं कि सरकार हर तरह से दुकानदार तब्का को सहूलत देना चाहती है। जैसा कि इस बात के लिये कहा गया है कि छोटे दुकानदारों को वौचर्ज़ वगरा रखने मै तकलीफ होती है इस के बारे में सरकार ने महसूस किया है और हम एक क्लाज़ ला रहे हैं कि उन्हें वौचर्ज़ रखने से मुस्तसना कर दिया जाए और उन के लिये लम्पसम कर दें। यह मांग देर से चलती आ रही थी जिसे गवर्नमेंट ने मनजूर कर लिया है। और फिर जैसा कि आप जानते हैं जितने भी छोटे दुकानदार हैं हलवाइ, ढाबे वाले, कन्फैक्शनर वगैरा जब यह अपनी मैनूफैक्चर के इलावा कोई दूसरी चीज़ रखें तो इस की ज़द में आते हैं इस लिये जैसा कि मैं ने कहा है इन के लिये हम लम्पसम करने जा रहे हैं ताकि यह मुनीमों और वौचरों की तकलीफ से बच जाएं।

चेयरमैन साहिब, एक एतराज़ यह उठाया गया और आज भी कहा गया और कल भी कि इस टैक्स को फर्स्ट स्टेज पर दिया जाए। इस बात को पहले ही सरकार ने माना है और इस के बारे में कारवाई की जा रही है।

इस के अलावा एनूअल रिटर्न के बारे में रजिस्ट्रेशन फी देनी पड़ती है इस के बारे में एतराज़ किया गया। यह बात इस लिए रखी गई कि जितने भी बोगस डीलर हों उन्हें चैक किया जाए। गवर्नमट के पास पावर्ज़ हों इस्तेमाल करने की। इस को भी उड़ा देने का फसला किया गया है इस के उड़ा देने से सरकार को 6 लाख का नुक्सान होगा। इस का मतलब यह नहीं था कि सरकार व्योपारियों को किसी शकोशुबा की निगाह से देखती है बल्कि यह ख्याल था कि व्योपार में इमानदारी आए और इस बात को तकवियत मिले। इस बात में पंजाब के जितने भी ट्रेडर्ज हैं मुझे आशा है कि उन की तरफ से सरकार को पूरा तआवन मिलेगा और पूरी कुआप्रेशन मिलेगी ताकि जितने भी बेईमान व्यापारी हैं उन्हे इलिमिनेट किया जा सके। हम इस हालत में जहां कि अमानदार व्यापारी हैं इस रीन्युअल वाली क्लाज़ से एगज़म्पट कर देंगे। और हमारी खाहिश है कि इस क्लाज़ को डिलीट कर दिया जाए और इस पर जेसा आप चाहेंगे अमल किया जाएगा।

चेयरमैन साहिब एक अर्ज़ और करना है कि जहां तक फरनिशिंग आफ सक्योरिटी का ताल्लुक है इस के बारे में एतराज किया गया। इस के सम्बन्ध में ला है कि कश स्क्योरिटी गवर्नमट इस म पूरी तरह से सहमत है कि केश स्योरिटी न ली जाए इस के लिये पर्सनल स्क्योरिटी का प्रोविज़न किया जा रहा है ताकि व्यापारियों को कैश स्क्योरिटी न देनी पड़ और वह रुपया बचा कर अपने कारोबार में लगा सकें और तजारत को फरोग दे सकें।

चेयरमैन साहिब एक और एतराज़ किया गया है कि टरन ओवर के साथ एफिडेविट दाखिल किया जाए। इस को भी अब हटा दिया जाएगा और इस के साथ जो एफिडेविट न देने का तावान है उसे भी उड़ा देंगे।

एक बात कैश मीमों के बारे में कही गई है हमारी सरकार की यह खाहिश है कि स्टेटस के अन्दर इमानदारी स काम किया जाए इस लिए इस बात को रखा था। अब यह मासूस किया गया है कि छोटे छोटे दुकानदार कैश मीमों हर आइटम के लिये नहीं रख सकते। उन क लिए अब हम ने ३ रू० की बजाए 10 रुपया की हद मुकर्रर कर दी है ताकि उन्हें कोई तकलीफ न हो। जो छोटे दुकानदार हैं, पान वाले, बेकरी वाले, सिग्रेट वाले जो उस ववन्टम में आते हैं उन के लिये सरकार ने अब लम्पसम कर दिया है।

चेयरमैन साहिब, मित्तल साहिब ने एक बात कही है और सरकार की तवज्जो दिलाई है कि जो बिज़नैस प्रिमसिज़ की सर्च और कनफिसकेशन के बारे में पावर्ज़ लेने की है। मैं खुद भी इस बात के बारे में एतराज़ करता रहा हूं जहां तक दूसरे मकानात वगैरा की सर्च करने का तआलुक है सरकार इस क्लाज़ को डीलीट कर दिया गया है। क्योंकि कनफिसकशन में तकलीफ थी।

जहां तक चेक बरियर के ऊपर सामान को ज़ब्त करने का सम्बन्ध है इस को भी डीलीट कर देंगे। मैं यह बात बिलकुल साफ कहना चाहता हूं कि पंजाब गवर्नमंट की नियत नेक है कि पंजाब के व्यापारी को किसी किस्म की तकलीफ न हो हम पंजाब की ट्रेड को और पंजाब के ट्रेडर को जिन्दा रखना चाहते हैं। और इस ट्रेड को एनक्रेज करना

[मुख्य मन्त्री]

चाहते हैं। हम किसी किस्म की दहशत व्यापारियों में पैदा नहीं करना चाहते।मैं ने दस रोज़ हुए फिनांस मिनिस्टर साहिब से बात चीत की थी और इन सारी चीज़ों पर विचार किया था। एक भाई ने इस बिल को काला बिल कहा है। मेरा ख्याल है कि अब इन बदले हुए हालात में वह इस बिल को यह नाम नहीं देंगे। मैं आशा रखता हूं कि आप सब सरकार को पूरी तरह से कुआप्रेट करोगे।

दरअसल यह सारा बिल इस बात के लिये लाया गया था कि टैक्स की इवेज़न होती है और इवेज़न भी मामूली नहीं 10 करोड़ का होता है। और इस को रोकने के लिये भी कदम सरकार की तरफ से जो उठाए जाएं उन को स्पोर्ट आप सब की तरफ से मिलनी चाहिए। और अगर आप सब की स्पोर्ट हो और प्रस भी इस बात की हमायत करे तो पंजाब अपने रिसोर्सिज़ को मज़बूत कर सकता है। इस में आशा है आप सब सरकार को स्पोर्ट करेंगे।

मैं यह बात कहना चाहता हूं कि जहां तक डीलर्ज़ को एडवाइज़ करने का तआलुक है इस बात को कभी भी नज़रअंदाज़ नहीं किया गया। पहले जहां दूसरी चीज़ें रखने वालों के लिये 10 हज़ार की लिमट थी उस को अब उन्हीं की मांग पर 30 हज़ार किया जा रहा है और फिर इस के साथ लम्पसम रखा है ताकि उसे किसी किस्म की तकलीफ न हो।

[*Mr. Speaker in the Chair*]

स्पीकर साहिब, म आप की वसातत से अर्ज़ करना चाहता हूं कि जहां तक यूनीफारम सेल्ज़ टैक्स का सवाल है इस के बारे में प्लानिंग कमिशन से बात चीत की गई है कि सेल्ज़ टैक्स पंजाब के अन्दर दिल्ली और राजस्थान के अन्दर और यू. पी. में यूनीफार्म सेल्ज़ टैक्स हो। यह आप की मांग थी ताकि पंजाब का धन बाहर ना लगाया जाए। इस के बारे मे नार्दन ज़ोनल कौंसिल में भी बात चीत की गई। और इस बात को प्लानिंग कमीशन ने पूरी तरह से माना है, इस लिये मैं आशा रखता हूं कि इन सारी चीजों पर अमल करते हुए हम पंजाब के अन्दर व्योपार को बढ़ा सकेंगे। और इस से पंजाब के रिसोर्सिज़ को मज़बूत करने में मदद मिलेगी। और जो इस कारण इवेज़न होता था उसे रोका जा सकेगा। मैं आशा रखता हूं कि आप इस नुक्तानिगाह से इस सारी चीज़ को देखेंगे और सरकार को पूरी तरह से कुआप्रेशन देंगे और एक अच्छा वातावरण और माहौल पैदा करेंगे। हड़तालों से और एजीटेशनों से कोई काम हल नहीं होता। आज तो गवर्नमेंट वह है जो हर ऐसी बात को जिस के अन्दर वज़न हो और जहां पर सरकार यह समझे कि किसी तबका के साथ सख्ती हो रही है दोबारा गौर करने को त्यार है। आपिस में बात चीत करके पहले भी फैसला किया था। इस लिये मैं आशा रखता हूं कि पंजाब के अन्दर जो हालात आज कल हैं और जिन से हम गुज़र रहे हैं एक अच्छा माहौल पैदा करने की ज़रूरत है। हमें पैसे की जरूरत है डिफैंस के कामों के लिये। इस लिए मैं अर्ज़ करना चाहता था कि आप की जो एमन्डमेंटस आएंगी तो क्लाजों पर हमारे फिनांस मिनिस्टर साहिब गौर करेंगे और जवाब देंगे।

मैं आशा रखता हूं कि सारा हाऊस इस बिल को यूनानीमसली पास करेगा और सरकार को पूरी तरह से कुआप्रेशन देगा। (प्रशंसा)

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ (ਰੋਪੜ): ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਜ਼ਾਹਤੀ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਮੈਂਡਿੰਗ ਬਿਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਇਸ ਵਿਚ ਸਖਤ ਰਿਗੁਰਜ਼ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘਟਾਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਗਲ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਬਿਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਐਮੇਂਡਮੈਂਟਸ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਆਬਜੈਕਟਸ ਅਤੇ ਰੀਜ਼ਨਲ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ—

> "and to provide for the better administration of the Sales Tax law by taking powers to levy tax at the first stage, check evasion, impose restraints on bogus and uncrupulous dealers and generally to bring the Act in conformity with the provisions of similar legislation in other States and more especially in the Northern Zone."

ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਯੂਨੀਫਾਰਮਿਟੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਚ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। Why do you always follow bad precedents. ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਵਾਧੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੋ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ-ਦੇਹ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਪਣੀ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਰਾਏ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਮੰਤ੍ਰੀ ਹਨ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਹਨ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਐਸਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਗਵਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਉਹ 2 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਚਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲੀਸੀ ਕਰਕੇ ਇਤਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਿਉਪਾਰੀ ਤਬਕਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੁਦਾ ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਛੁਰੀ ਬਦਸਤੂਰ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਰਿਸੋਰਸਿਜ਼ ਵਧਨ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਸੋਚੋ ਟਾਪ ਹੈਵੀ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੋੜੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਥੇ ਪੈਸਾ ਫਜ਼ੂਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੈਕ ਕਰੋ, ਪਰ ਏਧਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਨਿਸਟਰੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲਗਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਰਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਾਟੇਖਾਂ ਬਣ ਗਈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਿਚ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿਚ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਦੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਏਥੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਪਾਲੀਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਚ ਕਿ "Head I win tail you lose"। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਪੰਡਿਤ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਏਸ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਇਸ ਸੀਟ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਕਝ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ.....(ਵਿਘਨ)

Shri Ram Pratap Garg (Chief Parliamentary Secretary) : Sir, I want to move a motion that the sitting of the House be extended for one hour today.

Voices from the Opposition : No, No, please.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਲ ਨੂੰ ਡਬਲ ਸਿਟਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਲ ਤਕ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਦੇਨਜ਼ਰ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨੀ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।

Education Minister : May I submit, Sir that according to the decision of the Business Advisory Committee, we are scheduled to meet on Saturday as well. But, if we can do away with that sitting by sitting one hour today, that will be a good proposition.

Sardar Gurnam Singh : According to the recommendation of the Business Advisory Committee, the House has already decided to meet on Saturday as well. We cannot change that decision now.

Shri Mohan Lal Only today we have adopted the Report of the Business Advisory Committee without any discussion thereon, although much could be said against it. According to that Report, the House has to meet on Saturday as well. We are, therefore not prepared to agree to the extension of the sitting of the House today.

Mr. Speaker : All right, Mr. Josh, please carry on.

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼: ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਤਾਂ ਪੰਡਿਤ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਐਸਾ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਖੁਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਅੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬਿਉਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ It is a load on the consumer and unnecessary harassment to the traders; ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਫੇਰ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਇਨਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹਲਵਾਈ ਵਗੈਰਾ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੀ ਮਹਿਜ਼ 7 ਰੁਪਏ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ——————

Mr. Speaker The House stands adjoured till 9 A. M, tomorrow.

1·30 p. m. | *The Sabha then adjourned till 9 a.m. on Thursday the 4th November, 1965.*

7242—PVS. 384—4-5-66 C.,P.&S., Pb., Chandigarh

ੑ, 1965

I want
e hour

ਸਿਟਿੰਗ

ਰਿਪੋਰਟ

:ision
ırday
day,

f the
t on

the
ugh
has
the

ਗੀਂ

ਜਾ

ਤ੍ਰਾਂ

ਗਂ

ı

PUNJAB VIDHAN SABHA

DEBATES

4th November, 1965

(Morning Sitting

Vol. II—No. 16

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Thursday, the 4th November, 1965

Punjab idhan Sabha Secretariat, Chandigarh.

Price : Rs. 4.00

ERRATA

to

Punjab Vidhan Sabha Debates, Vol. II, No. 16, dated the 4th November, 1965 (Morning Sitting)

Read	*For*	*Page*	*Line*
Vidhan	idhan	Title	Last but one
असोशिएट	असोशिस्ट	(16)1	18
कंसिडरेशन	कंसिडेशन	(16)1	22
भेजी	मेजी	(16)2	7
मेरे	मरे	(16)8	1
वजीर	वजीट	(16)8	12 from below
इन्फरमेशन	इन्फमशन	(16)9	15 from below
ਮੰਤਰੀ	ਮਤਰੀ	(16)12	8 from below
(16)28	6)28	(16)28	Page No.
ਪੁੱਛੀ	ਪੁ ੀ	(16)28	6 from below
परिषद	प्ररिष्द	(16)30	8 from below
समर्थन	सपर्थन	(16)31	5 from below
ਕ੍ਰੰਗ੍ਰਿਸ	ਕੰਗ੍ਰਿ ਸ	(16)32	21
forgotten	forgothen	(16)33	
ਮੰਗ	ਮਗ	(16)34	13
ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ	ਟ੍ਰੀਟਮੈਟ	(16)34	19
इंटेन्यूज	इडेन्यज	(16)34	3 from below
come	cone	(16)38	42
decisions	deceisions	(16)39	Last
be	to	(16)40	29
हूं	हुँ	(16)43	20
	हुं	(16)83	6 from below
will	well	(16)63	5
speak	speek	(16)71	10 from below
Order	Nrder	(16)76	15 from below
Delete the word 'ਨੇ' after the word 'ਕਰਮਚਾਰੀ'		(16)77	13
ने	न	(16)83	19
आर्गुमेंट्स	आरगुमेंट्स	(16)83	7 from below
ਨੁਕਸਾਨ	ਨੁਕਸ ਨ	(16)85	14
ਹੋਜਲੀ	ਹੋਜਲੀ	(16)85	15
ਕਹਿੰਦੇ	ਕਹਿ ਂਦੇ	(16)86	13 from below
ਹੋਦੇ		(16)85	7 from below
the	thc	(16)86	6 from below

PUNJAB VIDHAN SABHA

Thursday, the 4th November, 1965
(Morning Sitting)

The Vidhan Sabha met in the Vidhan Bhawan, Sector 1, Chandigarh at 9-00 A. M. of the Clock. Mr. Speaker (Shri Harbans Lal) in the Chair.

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

*Supplementaries to starred Question No. 8731

Sardar Balwant Singh : It is evident from the constitution of the Vigilance Commission that one Chief Vigilance Officer and a Special Inquiry Agency will also be appointed. May I know from the honourable Chief Minister if they have since been appointed ? It may also be stated whether the Legal Officers and Technical Officers have been provided to the Vigilance Commission ?

मुख्य मंत्री : अभी तक उनको एक प्राइवेट सेक्रेटरी, एक स्टैनोग्राफर और एक क्लर्क व एक असिस्टैंट प्रोवाइड किया गया है । हमारा विजीलैंस डिपार्टमैंट उनकी पूरी तरह से मदद कर रहा है । डिपार्टमैंट का जो सैक्रेटरी है वह इसका असोशिस्ट मैम्बर है ।

Sardar Balwant Singh : May I know, Sir, whether the Present Vigilance Department and its Secretariat have since been wound up as required under the Notification issued by Government ?

मुख्य मंत्री : अभी नहीं किया है । मामला अंडर कंसिडेशन है ।

Pandit Chiranji Lal Sharma : May I ask the honourable Chief Minister if he has ever consulted Mr. Justice Tek Chand with regard to the powers, functions and scope of the Vigilance Commissinon ? If so, the results thereof ?

मुख्य मंत्री : उनके मशविरे के साथ ही बातचीत हुई थी । उन्होंने कुछ सुझाव भी दिए थे जिनके आधार पर गवर्नमैंट आफ इंडिया और होम मिनिस्ट्री के साथ खतोकिताबत हो रही है ।

Pandit Chiranji Lal Sharma : Has it come to the notice of the Government that all other States have given much more powers and independence to their Commissions in rooting out corruption than our State ?

Note:— Starred Question No. 8731 along with its reply appears in the P. V. S. Debates Volume II, No. 13, dated the 1st November, 1965.

Mr. Speaker : It is too general a question.

मुख्य मंत्री : यह कमीशन गवर्नमेंट आफ इंडिया के विजीलैंस कमीशन के सैटअप के मुताबिक ही यहां पर सैटअप किया गया है और जो कुछ कमी इसमें रह गई है वह होम डिपार्टमैंट के साथ चल रही खतोकिताबत के फाइनल हो जाने पर पूरी कर दी जाएगी ।

कामरेड राम चन्द्र : अभी जो कुरप्शन की शिकायतें आती हैं क्या वह विजीलैंस डिपार्टमैंट के पास जाती हैं या कि बिजीलैंस कमीशन के पास भेजी जाती हैं ?

मुख्य मंत्री : दोनों जगह प्रोसीजर के मुताबिक जा रही हैं ।

सरदार बलवंत सिंह : क्या मुख्य मंत्री साहिब यह बतलाएंगे कि वह कौनसी स्पैसिफिक वजूहात हैं जिसकी बिना पर गवर्नमेंट चीफ विजीलैंस अफसर मुकर्रर नहीं कर सकी ? क्या सरकार के ख्याल के मुताबिक कोई आदमी नहीं मिल रहा इसलिए अभी तक मुकर्रर नहीं किया गया ?

मुख्य मंत्री : विजीलैंस अफसर के मुकर्रर करने का कोई प्रोवीजन नहीं है ।

Pandit Chiranji Lal Sharma : May I know whether the Government have appointed any Secretary to the Commission and also whether the Commission has started functioning ?

मुख्य मंत्री : कमीशन ने अपना कांम शुरू कर दिया है । मैं ने अभी बताया है कि पंजाब गवर्नमैंट के विजीलैंस डिपार्टमैंट के सैक्रेटरी उसके एसोशिएट मैम्बर है, और वह काम कर रहे हैं ।

सरदार बलवंत सिंह : इस सैट अप में यह बताया गया है कि यह कमीशन गवर्नमैंट को अपनी मंथली रिपोर्ट सबमिट करेगा तो मैं दरयाफ्त करना चाहता हूं कि अभी तक कितनी रिपोर्ट्स सबमिट हुई हैं ?

मुख्य मंत्री : अभी तो काम ही शुरू हुआ है, रिपोर्ट्स कहां से आ जाएंगी ।

Srdar Gurnam Singh : May I know from the honourable Chief Minister if the Vigilance Commission has power to act *suo motu* on cases of corruption ?

मुख्य मन्त्री : उनको काफी अख्तियार मिले हुए हैं ।

ਕਾਮਰੇਡ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ : ਇਸ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਕਮੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਅਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ?

मुख्य मंत्री : यहां पर गवर्नमेंट आफ इंडिया के विजीलैंस कमीशन के मुताबक ही अधिकार मिले हैं । ज़यादा या कम का सवाल पैदा नहीं होता ।

कामरेड राम चन्द्र : यहां पर विजीलैंस डिपार्टमैंट और विजीलैंस कमीशन दोनों को रखा गया है । मैं पूछना चाहता हूं कि आया विजीलैंस डिपार्टमैंट बन्द कर दिया जाएगा ?

मुख्य मंत्री : गवर्नमेंट आफ इंडिया की हिदायत के मुताबिक काम किया जाएगा !

कामरेड राम प्यारा : क्या यह कमीशन नानआफिशियल और आफिशियल दोनों सेक्शन्ज़ के केसिज़ के अन्दर इन्क्वायरी करेगा ?

मुख्य मंत्री : नहीं, नान आफिशियल उसके परव्यू के अन्दर नहीं हैं ।

Pandit Chiranji Lal Sharma : May I ask the hon. Chief Minister if according to the provisions of the notification, the Government have appointed Chief Vigilance Officers in each and every Department ?

मुख्य मंत्री : विजीलैंस कमीशन की हिदायात के मुताबिक अमल किया जायगा ।

श्री बलरामजी दास टण्डन : क्या मुख्य मंत्री साहिब इनन्शिएट करेंगे कि वे क्या ज़्यादा पावर्ज़ हैं जो अपनी स्टेट के विजीलैंस कमीशन को दिए गए हैं ?

मुख्य मंत्री : इसके लिए सैपेरेट क्वैस्चन दीजिए ।

Sardar Gurnam Singh : May I know from the Chief Minister whether the present Vigilance Commission has written a letter to the Government demanding more and proper powers for the functioning of the Commission ?

मुख्य मंत्री : मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि खतोकिताबत चल रही है । सारी स्टेट्स के विजीलैंस कमीशन्ज़ के कमिशनरों की बंगलौर में 8 दिन की मीटिंग हुई थी और जो कुछ तय हुआ था उस लाइट में होम मिनिस्टरी गौर कर रही है । जो कुछ भी किया जाएगा वह सारे हिन्दुस्तान में एक यूनीफार्म तरीके से होगा ।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਕੀ ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੈਡ ਕਾਂਸਟੇਬਿਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ?

मुख्य मंत्री : विजीलैंस कमीशन के कमिश्नर को गवर्नमेंट आफ इंडिया के विजीलैंस कमिशनर के मुताबिक ही अख्तियार हासिल हैं ।

Pandit Chiranji Lal Sharma : May I know, Sir, the remunerations which are being paid to the Vigilance Commission by the State Government ?

मुख्य मंत्री : वे हाई कोर्ट के एक जज हैं ।

कामरेड राम प्यारा : जैसा कि मुख्य मंत्री साहिब ने फरमाया कि यह कमीशन गवर्नमैंट आफिशियलज़ की कुरप्शन को डीलविद करेगा तो क्या नान आफिशियलज़ की कुरप्शन को भी यही कमीशन डील करेगा, ऐसा कुछ गवर्नमेंट के ज़ेरे गौर है ?

मुख्य मंत्री : गवर्नमेंट आफ इंडिया सारी चीज़ पर गौर कर रही है, उसके बाद अगर कोई हिदायात आई तो उसके मुताबिक गौर किया जाएगा।

Sardar Balwant Singh : Mr. Speaker, it has been provided in the notification that the Government may appoint one or two more Members on the Vigilance Commission. In view of this provision, may I know if the Government feel the desirability of appointing more Members on this Commission?

मुख्य मन्त्री : यह सब कुछ काम पर मुनस्सर है, फिलहाल कोई ज़रूरी नहीं।

---

*Supplementaries on Starred Question No. 8705

ਕਾਮਰੇਡ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ : ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਜੋ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ, ਜੋ ਵਡੇ ਜ਼ਿਲੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਘਟ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤ੍ਰੀ ਜੀ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਘਟ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ?

परिवहन तथा निवार्चन मन्त्री : मैं ने उस दिन बताया था कि इसमें ट्रांसमिशन लाईन वगैरह कम हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन शुरू २ में इसी तरह हुई। नई प्लैन में ऐसी बात नहीं की जाएगी।

ਕਾਮਰੇਡ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ : ਕੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਲਾਗਡ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤਾਹ ਨੀਵੀਂ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਉਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹਨ ਤਾਕਿ ਟਿਊਬਵੈਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਣ ?

मन्त्री : वैसे संगरूर ज़िले के पानी की इन्होंने जो इतला दी है उसके बारे में सोचा जा सकता है। ट्यूबवेल तो बहुत लिबरल तौर पर दिए जा रहे हैं। 11000 अभी इन्स्टाल करने हैं जिन्हें बिजली दी जा रही है। दोबारा एक इंस्टालमेंट आ रही है फिर देखेंगे।

चौधरी इंद्र सिंह मलिक : क्या मंत्री साहिब बताएंगे कि संगरूर जिला, जो बहुत पीछे है और खास तौर पर जींद तहसील बहुत पीछे है, उसको अगले साल में इलैक्ट्रीफाई किया जाएगा ?

मंत्री : पिछले तीन साला प्लेन में साढ़े 14 करोड़ रूपए की बिजली देने का प्रोग्राम था। तो पहले ही 2 साल में जो हम ने 1600 गाँव लिए वह हो गए। उसके बाद यह सोचा गया कि यह जो प्लेन है अंडर एस्टीमेटिड है तो कुल 4400 गाँव को बिजली देनी है और इसके लिए 17 करोड़ रुपया सैंट्र ने देना है। पहले साल 825 गाँव को और दूसरे साल 815 गाँव को बिजली दी। पहले सालों में ही

Note—*Starred Question No. 8705 along with its reply appears in the P. V. S. Debate Volume II, No. 13 dated the 1st November, 1965.

फंड्ज़ खत्म हो गए । 17 करोड़ रुपए की गवर्नमैंट आफ इंडिया से तव्वको थी लेकिन चाइनीज़ एग्रेशन के बाद वह रकम दूसरी तरफ ट्रांस्फर हो गई ।

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਕੀ ਮੰਤ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਘਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ?

Mr. Speaker : Not allowed please.

ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ : ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਕਰਦਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਹੈ ?

मंत्री । जब मैंने बयान दिया था उस वक्त पाकिस्तान और हिंदोस्तान की लड़ाई नहीं थी । बाकी अगर 25 या 30 गांव कवर हो गए हैं और पाकिट में एक आध गांव रह गया है तो हम उसे भी कर देंगे । इसका मतलब यह नहीं कि 30, 30 गांव रह गए हैं ।

ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਟ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਗੇ । ਮੈਂ ਇਹ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਅਗਰ ਟਿਊਬਵੈਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੂੰਜੇ ਤੇ ਲਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਕ ਵੀ ਹੋਰ ਖੰਭਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅਲੈਕਟਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਲੈਕਟਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ?

ਮੰਤਰੀ : ਜ਼ਰੂਰ ।

श्री अमर सिंह : वज़ीर साहिब ने कहा है कि पाकिट वाले गांवों में बिजली दी जाएगी । मैं पूछना चाहता हूं कि नरवाना सब-डवीज़न में सिरफ 7 या 8 गांवों में बिजली है । न वहां पाकिट है वहां बिजली देने का सरकार क्यों प्रबंध नहीं करती ?

मंत्री : इनका यह सवाल उस से बिलकुल अलहदा है, पाकिट से । मैं ने अर्ज़ किया था कि साढ़े 14 करोड़ रुपए की जो प्लैन थी उस से 1600 गांव को बिजली देनी थी । तो रिवाइज्ड प्लैन में 4400 गांव को बिजली देनी है और 17 करोड़ रूपए सैंटर से आना था । हम ने 1 करोड़ रूपया गवर्नमैंट आफ इंडिया से और 2 करोड़ रूपया एल. आई. सी. से लिया है ट्यूबवैल्ज के लिए । अगर कहीं आधा काम हुआ है तो बाकी का कर सकते हैं । लेकन फंड्ज का सवाल है ।

श्री रूप लाल महता : क्या गुड़गांव ज़िला में उस एरिया को, जो बैकवर्ड है और इरीगेशन के लिहाज से बैकवर्ड है और जहा सिंचाई के साधन नहीं प्रायर्टी देने के लिए गौर करेंगे ?

मंत्री : प्लैनिंग कमीशन वालों से जो कुछ फंड्ज़ का प्रबंध होगा उसके मुताबक प्रायर्टी भी देख ली जाएगी ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਰਈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਰਾਇਰਟੀ ਦਿਤੀ ਜਾਏਗੀ । ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖ ਕੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੈਕਟਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੈਂ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਉਸ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਰਾਇਰਟਰੀ ਨਹੀਂ ਰਖੀ ਗਈ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖੀਆਂ ਗਈਆਂ । ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਜੋ ਜੁਗਿੰਦਰ ਨਗਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕਢੀ ਗਈ ਉਹ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿੰਕ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ । ਅਗਲੀ ਪਲੈਨ ਵਿਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਖ ਰਖੀਆਂ ਹਨ—ਫਰਟਿਲਿਟੀ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਫੂਡ ਪਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਹੋਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਲਾਕਸ ਹਨ ਜਿਥੇ ਕਿ ਗਰੋ ਮੋਰ ਫੂਡ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼; ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰਖਿਆ ਹੈ । ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਇਕ ਸਕੀਮ ਆਈ ਹੈ । ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਪਾਸ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਵੀ ਆਈ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਐਪਰੂਵਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਾ ਹੋਣ ।

चौधरी रण सिंह : क्या मिनिस्टर साहिब यह बताने की कृपा करेंगे कि रूरल इलैक्ट्रीफीकेशन के लिए जो विलेजिज़ की पाकिट्स बनाते हैं वे कौन सी बातें हैं जिन को सामने रख कर पाकिट्स बनाते हैं ?

श्री अध्यक्ष : चौधरी रण सिंह जी, पाकिट का मतलब तो बिलकुल साफ है, उसमें स्टैंडर्ड की जरूरत नहीं । (Addressing Chaudhri Ran Singh) (The meaning of "pocket" is quite clear and it does not require any standardisation.)

श्री अमर सिंह : जो देहात पाकिट में इंक्लूड नहीं हो सकते वे कब तक हो जाएंगे ?

मंत्री : बात यह है कि मेरे पास काफी दरखास्तें आई थीं कि हमारे इर्द गिर्द के गाँव में बिजली आ गई है, यह अकेले एक या दो गाँव रह गए हैं. जहां कनैक्शन नहीं दिया गया, आध मील पर या 2 मील पर वहां हैं । मैंने चेयरमैन बिजली बोर्ड से बात की उस ने देखा कि कुछ जायज हैं । इर्द गिर्द बिजली दे दी है। तो जो आध मील पर हैं उनको इंक्लूड कर लेंगे और उनका ख्याल करेंगे । तो पाकिट का मतलब यह है, इस का मतलब दूसरा नहीं जो यह समझते हैं ।

श्री फतह चंद विज : जैसा कि आप ने फरमाया है जो मैम्बर अपनी कान्सटिचूएन्सी के मुताल्लिक कुछ तजवीजें दे दें कि वहां बिजली लगानी चाहिए तो क्या आप बिजली देंगे ?

मंत्री : बिजली देना तो बिजली बोर्ड के अख्त्यार की बात है मुझे तो खाहमखाह कह रहे हैं। बिजली बोर्ड के चेयरमैन और बाकी अफसरान से बात की है। यह जो गांव दरम्यान में बगैर बिजली के रह गए हैं उनको बिजली दे दी जाएगी। मेम्बर साहिबान ने जितनी दरखास्तें दी हैं वह मेरे पास पड़ी हैं और दूसरी उनके पास पड़ी हैं। उन्हें दोबारा देखेंगे कि वह बिजली कैसे दी जाए। मुझे तो अभी आए दस दिन भी नहीं हुए।

श्री सुरेन्द्र नाथ गौतम : क्या मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि नंगल भाकड़ा जहां से बिजली पैदा की गई है और दूसरी जगहों को ले जाई गई है, उस के नज़दीक के गांवों को बिजली नहीं दी गई क्या उन बिलेजिज़ की तरफ सरकार ध्यान देगी ?

मंत्री : इस का मैं क्या जवाब दूं। मैंने कहा है कि हमें सैंट्र से 17 करोड़ रुपया नहीं मिला जो कि 1962-63 में मिलना था। एमरजंसी की वजह से नहीं मिला। मजबूरी है। कोशिश कर रहे हैं। एल. आई. सी. से 2 करोड़ रुपया अभी हम ने लिया है। ट्यूब वैल्ज़ को इलेक्ट्रीफाई कराने के लिए गवर्नमैन्ट आफ इंडिया से भी ले रहे हैं। लेकिन यह न्यू विलेजिज़ के लिए नहीं बल्कि कहीं एक आध पाकिट रह गई है तो उस के लिए किया है न्यू विलेजिज़ की स्कीम अभी उन्हों ने ड्राप कर दी है।

श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री : वज़ीर साहिब ने अभी कहा है कि अमल तो बिजली बोर्ड ने करना है। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर ऐसी बात है तो फिर वज़ीर साहिब जो यहां एशोरैंसिज़ देते हैं और बाहर भी वायदे करते हैं उन का क्या फायदा है ?

मंत्री : इस हाउस में सिर्फ वही एशोरैंस दी जाती है जिसकी बात पहले बिजली बोर्ड के चेयरमैन से तय हो जाती है।

SUPPLEMENTARIES ON STARRED QUESTION NO. 8594

Mr. Speaker : Supplementaries on Starred Question No 8594 please.

Sardar Balwant Singh : Sir, in the reply to the question it has been stated that the first unit of the Bhakra Right Bank Power plant is scheduled to be commissioned in March, 1966 and that a few of the transmission lines will be completed by May/June, 1966, i. e. three months after the completion of the unit. I, therefore, want to know how does the Government propose to utilise the energy generated by the Right Bank Power House in the absence of the transmission lines.

*Note:—Starred Question No. 8594 along with the its reply appears in the P. V. S. Debate Vol. II—No. 14 dated the 2nd November, 1965.

परिवहन तथा निर्वाचन मंत्री : वैसे तो पुराने बिजली मंत्री मेरे दाएं पर बैठे हैं लेकिन यह चूंकि मेरे हिस्से में आया है इस लिए मैं अर्ज़ करता हूँ कि यह दाएं वाला पावर हाउस अगले साल मुकम्मल हो जाएगा और जो बाएं वाला है वह स्टैंड बाई होगा ।

Sardar Balwant Singh : Sir, it is evident from the statement that five units of the Right Bank Power House will, in all, generate 600 M. W. of power and in order to distribute that power, the transmission lines have got to be installed and for that purpose import licence is awaited from the Government of India. While the first unit of the Power House will be ready by March, 1966, the transmission lines will not be complete for want of equipment. I want to know how in the absence of the transmission lines the electricity thus generated is going to be distributed ? Is it going to be stored for a certain number of years.

लोक कार्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जहां तक बिजली स्टोर करने की बात उन्होंने कही है, बिजली तो एक मिनट के लिए भी स्टोर नहीं हो सकती है । बिजली उतनी पैदा होती है जितनी खर्च होती है । मेरी समझ में नहीं आया कि क्यों उन को ऐसा ख्याल हो गया । मैं अर्ज़ करता हूँ कि आज भी हमारी जितनी लाइनज़ बिछी हुई हैं और सबस्टेशन काम करते हैं और अगर कल भी कोई यूनिट चालू हो जाता है तो भी हम उनके ज़रिए उस बिजली को इस्तेमाल कर सकते हैं । हमारे लैफ्ट बैंक पावर हाउस की जो जैनरेटिंग कपैसिटी है वह $6\frac{1}{2}$ सौ लाख है लेकिन फर्म पावर जिनके हिसाब से बिजली बांटी जाती है वह मुश्किल से 450 लाख है लेकिन हमारे जो सबस्टेशन बने हुए हैं वह 650 लाख के बेसिज़ पर बने हैं । इस लिए यह जो पहला यूनिट अगले मार्च में चालू होगा जो कि 70/80 हज़ार फर्म पावर पैदा करेगा उस के इस्तेमाल के लिए हमारे पास इन्तज़ाम है और वह मौजूदा लाइनज़ और सब-स्टेशनज़ के ज़रिए इस्तेमाल हो सकती है ।

श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर । मैं आपका रूलिंग चाहता हूँ कि एक महकमा का वज़ीर जिस का कि सवाल हो वह हाउस में हाज़र हो तो क्या उसकी मौजूदगी में दूसरा वज़ीर उस सवाल का जवाब दे सकता है ।

परिवहन तथा निर्वाचन मंत्री : स्पीकर साहिब, इस महकमा के वज़ीर साहिब तो बम्बे गए हुए हैं । मैं तो देहाती बिजली का वज़ीर हूँ और मेरे यह साथी इस महकमा के साबिक वज़ीर हैं । उन की इस नाते ख्वाहिश थी कि वह इसका जवाब दें और मैंने भी कहा कि हां जवाब दे दो । वैसे कोई भी वज़ीर जवाब दे सकता है रूकावट नहीं है । इस में पुज़ीशन यह है कि ट्रांसमिशन लाइनज़ और दूसरे के. वी. सब-स्टेशनज़ के फार्न एक्सचेंज की कमी है जिस की वजह से ढीले हो गई है । मैंने आप को बताया है कि 30 मैगावाट गंगूवाल के ज़रिए और 70 मैगावाट लुध्याना के ज़रिए इस्तेमाल हो जाएगी । इस तरह सारी बिजली इस्तेमाल हो जाएगी और फिर पक्का इन्तज़ाम हो जाएगा ।

श्री अध्यक्ष : अग्निहोत्री जी ने बड़ा इम्पॉर्टेंट प्वायंट आफ आर्डर रेज़ किया है । मैं महसूस करता हूं कि कन्वैन्शन यही होनी चाहिए कि जिस महकमा के वज़ीर का सवाल हो वही उस का जवाब दे क्यों कि प्रापर एशोरैंस उसी की तरफ से हो सकती है । लोक सभा में भी यही कन्वैनशन है । जहां तक मैंने देखा है और बात चीत की है सवाल जवाब देने में ज़िम्मेदारी इन्डीविजुअल मिनिस्टर की है । चीफ़ मिनिस्टर साहिब को बतौर लीडर आफ दी हाउस हक है कि वह जहां मुनासिब समझें जवाब दें और इन्टरवीन करें लेकिन जहाँ तक मिनिस्टर्ज़ का ताल्लुक है इस में कन्वैनशन यही होनी चाहिए कि जिस महकमा के मिनिस्टर का सवाल हो वही जवाब दे क्यों कि वही सारे फैक्टस को जानता है ताकि कंट्राडिकशन न हो । (The hon. Member Shri Agnihotri has raised a very important point of order. My own feeling is that there should be a Convention by virtue of which only the Minister to whom the question relates should reply to it becausee he alone can hold out the proper assurance. This is the convention in Lok Sabha also. So far as my observation goes or I have had a talk on the subject I find that the responsibility for giving reply to a question devolves on the individual Minister. The Chief Minister, as Leader of the House, has a right to intervene and give a reply, whenever he thinks proper but so far as Ministers are concerned, the convention should be that the questions relating to a certain department should be replied by he Minister concerned as he alone is fully posted with the facts and also that any likelihood for contradiction is obviated.)

मुख्य मंत्री : सपीकर साहिब, मैं इस बारे में आपका रूलिंग चाहूंगा कि अगर ऐसा मिनिस्टर जो उस महकमा का वज़ीर रह चुका हो उसके बारे में कोई इन्फमशन देना चाहे तो क्या उस पर कोई पाबंदी है ?

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ : ਆਪਨੇ ਰੂਲਿੰਗ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤ ਜਿਸ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਉਹੋ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਲੇਕਿਨ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਦੋਵੇਂ ਹਾਊਸ ਇਕੋ ਵਕਤ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਇਧਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਧੱਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਲਿੰਗ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਗੀ ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਇਸ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਐਨਟਿਸੀਪੇਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੋਹਾਂ ਹਾਊਸਿਜ਼ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਰੋਸਟਰ ਬਣੇਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਿਸ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਇਧਰ ਹੋਣਗੇ ਉਧੱਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ । (Anticipating such an eventuality and to meet this objection, the Presiding officers of both the Houses have decided that a roster of questions be prepared according to which on any day question, when put on the Agenda for reply by a particular Minister in one House, will not be put for reply in the other House the same day.)

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ : ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Mr. Speaker : It will never happen, Sardar Kapoor Singh.

श्री बलरामजी दास टंडन :—प्वायंट आफ आर्डर तो यह था कि अगर उस महकमा का वज़ीर हाज़िर हो तो क्या उसकी हाज़री में दूसरा वज़ीर जवाब दे सकता है या नहीं लेकिन यह बात को दूसरी तरफ स्टरैच कर रहे हैं ।

Transport and Elections Minister : Mr. Speaker, with due respect to your observation that you have made in this House today I would say that the practice that has been followed since the Joint Punjab, even in this House before yourself and even during your time is that in case a Minister is absent—Ministers' absence sometimes is unavoidable, in the present case Chaudhri Rizaq Ram, Minister for Irrigation and Power is away to Bombay to attend a very important Conference of the Department—he can ask any other Minister to answer the questions on his behalf. Sir, it will be a very hard case if a Minister is debarred to answer questions on behalf of the other Minister. In view of the joint responsibility of the Cabinet, any Minister can answer questions on behalf of the other Minister. I would request you, Sir, to kindly revise or review your ruling because sometimes the Minister incharge's absence is unavoidable or sometimes the other Minister has, due to his previous experience, more knowledge of that question and in that case if he intervenes to elucidate the point it should be allowed.

Mr. Speaker : My observation does not require any revision or review. What I said was that when an hon. Minister gets up to reply a question in the first instance only he should take the responsibility to answer the other supplementaries. Any Minister may be interested to answer a question on behalf of the other Minister but once he gets up to reply the question in the first instance, no other Minister should deem it fit to answer the supplementaries, otherwise there is bound to be some contradiction. If any other Minister has some special information pertaining to that question, he can pass it on to the Minister who is replying the question.

Transport and Elections Minister : Thank you very much, Sir. After this clarification we have no objection.

Sardar Gurnam Singh : Mr. Speaker, I would like to make one observation. You were pleased to remark that if a Minister answers a question on behalf of the other Minister and makes some statement, it cannot form part of the Assurance. Sir, my request is that in view of the joint responsibility of the Cabinet assurance given by any Minister, even on behalf of the other Minister, would be valid.

Mr. Speaker : Any statement made by any Minister will be an Assurance.

श्री बलरामजी दास टंडन : वज़ीर साहिब ने फरमाया है कि जैनरेटिंग कपैसिटी 1 लाख 20 हज़ार एम. डब्लयू. होगी और फर्म 70 हज़ार एम. डब्लयू. के करीब है क्या वज़ीर साहिब बताने की कृपा करेंगे कि व्यास डैम के बनने के बाद इस में कितनी बिजली बढ़ने की आशा है ?

मंत्री : यह टैकनीकल बात है, इस के बारे में पहले अन्दाज़े लगाए जाते हैं कि ब्यास डैम बनने से इतनी जैनरेटिंग और फर्म कपैसिटी में इज़ाफा होगा ।

ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ਿਡੂਲਜ਼ lack of planning at the proper time ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ?

Minister : No, Sir. In part 'C' of the statement which has been supplied to the hon. Member it has been stated that there are certain difficulties about the import of machinery and equipment.

ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਘਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਅਗਰ ਇਹ ਠੀਕ ਗਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਟਿਊਬ ਵੈਲਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਰਿਸਟਰਿਕਸ਼ਨ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ?

लोक कार्य मंत्री : मैंने यह बात नहीं कही, मालूम होता है कि माननीय सदस्य को समझने में फर्क रह गया है ।

SUPPLEMENTARIES TO STARRED QUESTION NO. *8749

श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री : वज़ीर साहिब ने दोनो एग्जैक्टिव अफसरों की एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रोउन्ड पर इन्टरचेंज की है, क्या वज़ीर साहिब बताने की कृपा करेंगे कि इस के लिए गवर्नर साहिब के नाम पर क्यों नोटीफिकेशन जारी की गई ?

ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਮੰਤਰੀ : ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਡਰਜ਼ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਬੀਹਾਫ ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।

ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਸਰੰਡ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਅੱਲਿਕ ਰੀਮਾਰਕਸ ਦਿਤੇ ਕਿ ਉਹ ਆਦਮੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਅਫਸਰੀ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਕਿਉਂ ਰਖ ਲਿਆ ?

ਮੰਤਰੀ : ਅਜਿਹੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਥੇ ਪਾਰਟੀ ਫਰਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ । ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਪਾਰਟੀ ਫਰਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿਤਾ ਸੀ ।

Mr. Speaker : This is a hypothetical question.

Comrade Ram Chandra : Will the Planning and Local Government Minister be pleased to state whether the fault in the Local Bodies lies with the Executive Officer or with the members of the Municipal Committees ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਅਫਸਰ ਦੇ ਬਰਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਬਿਨਾ ਉਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ।

Note :—Starred Question No. 8749 along with its reply appears in the P.V.S. debates vol. II, No. 14 dated 2nd Novemebr, 1965

SALE OF PLOTS TO POLITICAL PARTIES AT CONCESSIONAL RATES IN CHANDIGARH.

***8741. Comrade Bhan Singh Bhaura:** Will the Minister for Capital and Housing be pleased to state—

(a) whether it is a fact that certain plots have been sold to certain political parties at a concessional rate in Chandigarh; if so, the names of such parties;

(b) whether Govt. have received applications from parties other than those referred to in part (a) above for the allotment/sale of plots to them at the concessional rates, if so, the details of action taken thereon ?

Sardar Prem Singh Prem : (a) Yes. The Punjab Pradesh Congress Committee.

(b) A request received from the Punjab State Council, Communist Party of India, for the allotment of land at concessional rates is under consideration of the Government.

ਕਾਮਰੇਡ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕੰਸੈਸ਼ਨਲ ਰੇਟਸ ਉਤੇ ਪਲਾਟ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਮਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੰਸੈਸ਼ਨਲ ਰੇਟਸ ਉਤੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੰਸੈਸ਼ਨਲ ਰੇਟਸ ਉਤੇ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 1957 ਵਿਚ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਰੇਟਸ ਸਨ, ਉਸੇ ਰੇਟ ਉਤੇ ਪਲਾਟ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਜ ਦੇ ਨਾਰਮਲ ਰੇਟਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਲਾਟ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਲਾਟ ਲਈ ਕਦੋਂ ਦਰਖਾਸਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਸ ਆਈ ਸੀ ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੈਪਰੇਟ ਨੋਟਿਸ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਸਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਪਾਲੀਟੀਸ਼ਨਜ਼ just like legislators ਨੂੰ reserved price ਉਤੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਵੈਸੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇਣ, ਉਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ।

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ੇਰੇ ਗੌਰ ਹੈ। ਕੀ 'ਜ਼ੇਰੇ ਗੌਰ' ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਅੰਡਰ ਕੰਸਿਡਰੇਸ਼ਨ ਰਹੇਗਾ ?

ਮੰਤਰੀ : ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਹਦ ਤਕ ਹਲ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਮੈਟਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਹੈ।

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ 1954 ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਨਾਰਮਲ ਰੇਟਸ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : 1954 ਵਿਚ 2 ਕਨਾਲ ਪਲਾਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫੀ ਕਨਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ April, 1962 ਦੇ ਕੈਬੀਨਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ reserved plots ਦੀ ਕੀਮਤ Rs 20 per Sq. yard ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੰਸੈਸ਼ਨਲ ਰੇਟਸ ਉਤੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਫੇਰ ਗਲ ਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਮਿਨਸੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਨ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਰੇਟ ਤੇ ਪਲਾਟ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਉਹ advisability ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਐਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਰੇਟ ਤੇ ਪਲਾਟ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ?

ਮੰਤਰੀ : ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟਸ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਕਿ ਆਕਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਪਲਾਟ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਐਨਾ ਕਨਸੈਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਐਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤਾਂ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨਜ਼ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਕੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨ ਗੇ ਕਿ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਐਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ?

ਮੰਤਰੀ : ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਏਗੀ ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਹ ਤਾਂ ਅਵੇਲੇਬਿਲੀਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।

PROPERTY OFFERED BY MR. SURINDER SINGH KAIRON

*8407. **Comrade Ram Chandra :** Will the Chief Minister be pleased to state——

(a) the details and the estimated value of the property offered by Mr. Surinder Singh Kairon to the Government together with the terms and conditions of the above offer ;

(b) whether it is a fact that Mr. Surinder Singh Kairon has since withdrawn the said offer, if so, the circumstances in which he has done so ?

Shri Ram Kishan : (a) The details of the property offered by Shri Surinder Singh Kairon who is not responsible to the State Government cannot be supplied without his consent. The only condition which was attached with the offer was that the Government was required to accept all the liabilities of Sh. Surinder Singh Kairon while accepting his assets.

(b) The offer was not withdrawn by Sh. Surinder Singh Kairon at any stage, but the offer was rejected by the Government on account of legal and administrative complications.

कामरेड राम चन्द्र : क्या मुख्य मन्त्री जी से मैं दरियाफत कर सकता हूं कि यह जो ओफर थी प्राईवेट तौर पर की गई थी या पब्लिक तौर पर की गई थी ?

मुख्य मन्त्री : सुरेन्द्र कैरों ने और गुरेन्द्र कैरों ने प्राईम मिनिस्टर को लैटर लिखा था जिस के द्वारा उन्होंने अपनी जायदाद की ओफर की थी ।

कामरेड राम चन्द्र : क्या उन्होंने यह भी खाहिश ज़ाहिर की थी कि यह ओफर प्राईवेट तौर पर की गई है और इस को पब्लिक में ज़ाहिर न किया जाए ?

मुख्य मन्त्री : मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है ।

श्री फतह चंद विज : क्या मुख्य मन्त्री साहिब बताएंगे कि इस ओफर को रीजैक्ट करने के क्या कारण हैं ?

श्री अध्यक्ष : इस का जवाब आ चुका है । (The reply has already come.)

Chaudhri Darshan Singh : Sir, may I know from the hon. Chief Minister the legal and administrative complications on account of which the offer was rejected ?

मुख्य मन्त्री : पंजाब गवर्नमेंट के एल० आर० ने एगज़ामिन किया और उस के बाद गवर्नमैंट आफ इंडिया के पास केस भेजा गया ताकि लीगल डीपार्टमेंट उस को अच्छी तरह से एगज़ामिन कर सके । उस के बाद यह राए जाहिर की गई है कि इस ओफर को एकसेप्ट नहीं करना चाहिए ।

चौधरी इन्द्र सिंह मलिक : क्या मुख्य मन्त्री साहिब बता सकते हैं कि उन की लायबिलीटीज़ कितनी थीं और जो जायदाद औफर की गई थी उस की कीमत क्या थी ?

मुख्य मन्त्री : हम तफसील में नहीं गए। केवल यही सवाल एग्ज़ामिन किया गया कि आया इस को एकसेप्ट करना चाहिए या रीजैक्ट करना चाहिये और नतीजे के तौर पर उस को रीजैक्ट कर दिया गया ।

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਸਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਸ ਔਫਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਤਾਂ ਪਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ?

मुख्य मन्त्री : ऐसी कोई बात नहीं है । पंजाब गवर्नमेंट के एल० आर० ने पूरी तरह गौर करने के बाद अपनी राए दी कि इस औफर को एकसेप्ट नहीं करना चाहिए। फिर वह केस गवर्नमेंट आफ इंडिया को भेजा गया कि हमारी यह राए है कि इस को लीगल तौर पर एकसेप्ट नहीं करना चाहिए । लेकिन इस विचार से कि गवर्नमेंट पर किसी तरह से भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई हर्फ न आए वहां पर लीगल डीपार्टमेंट के द्वारा पूरी तरह से इस की छान बीन करवाई गई । उस के बाद पंजाब गवर्नमेंट ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने मुतफिक्का तौर पर यह फैसला किया कि इस औफर को एकसेप्ट न किया जाए ।

सरदार कुलबीर सिंह : क्या मुख्य मन्त्री साहिब फरमाएंगे कि इस औफर को एकसेप्ट करने के रास्ते में लीगल डिफीकल्टीज़ के इलावा मौरल डिफीकल्टीज़ भी थीं ?

मुख्य मन्त्री : यह सवाल ही पैदा नहीं होता ।

Sardar Balwant Singh : Sir, may I know from the hon. Chief Minister whether the liabilities of Mr. Surinder Singh Kairon towards the State Government were higher than the assets offered by him ?

Mr. Speaker : This has already been replied to.

मुख्य मन्त्री : अगर औफर एकसेप्ट की जाती तो फिर लायबिलीटीज़ का सवाल आता था ।

चौधरी इन्द्र सिंह मलिक : क्या मुख्य मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि आया यह औफर कहीं दिखावे के तौर पर ही नहीं थी कि उन्होंने भी दिखावे के तौर पर औफर कर दी और सरकार ने दिखावे के तौर पर ही रीजेक्ट कर दी ? क्या यह सारी बात प्रीप्लांड तो नहीं थी ?

मुख्य मन्त्री : मेरे विचार में इस में दिखावे के तौर पर कुछ नहीं किया गया ।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਕੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਔਫਰ ਰੀਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਲਾਇਬਿਲੀਟੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਨਾਪਾਕ ਸੀ ?

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੀਜੈਕਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਥੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰ ਚੁਕਾ ਹਾਂ ।

ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ : ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਔਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੰਸੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਐਡੀ ਵਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੀਫੈਂਸ ਫੰਡ ਵਿਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ?

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਦਸ ਚੁਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਬੇਸਿਜ਼ ਤੇ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।

I.A.S. AND P.C.S. OFFICERS IN THE STATE

* **8649. Comrade Shamsher Singh Josh :** Will the Chief Minister be pleased to state the number of I.A.S. and P.C.S. Officers in service in the State during the years 1957, 1960, 1962, 1964 and at present separately ?

Shri Ram Kishen : A statement embodying the desired information is laid on the table of the House.

STATEMENT

As on	No. of I.A.S. Officers in service	No. of P.C.S. Officers in service
1.10.1957	91	276
1.10.1960	112	325
1.10.1962	132	366
1.10.1964	136	422
1.10.1965	167	418

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 1957 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 91 ਆਈ. ਏ. ਐਸ ਅਫਸਰ ਸਨ, 276 ਪੀ. ਸੀ. ਐਸ. ਅਫਸਰ ਸਨ ਅਤੇ 1965 ਵਿਚ 167 ਆਈ. ਏ. ਐਸ. ਅਫਸਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ 418 ਪੀ. ਸੀ. ਐਸ. ਅਫਸਰ ਹੋ ਗਏ । ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗ ਭਗ ਦੁਗਣੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਲਿਊਮ ਆਫ ਵਰਕ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧਦੀ ਗਈ ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਵਜੂਦ ਐਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ. ਏ. ਐਸ. ਅਫਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਡੀ. ਸੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਐਸ. ਅਫਸਰ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ?

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦਾ ਡੀ. ਸੀ. ਵੀ ਪੀ. ਸੀ. ਐਸ. ਅਫਸਰ ਹੈ ।

कामरेड राम प्यारा : क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आई०ए०एस० अफसरान ने या पी० सी० एस० अफसरान ने गवर्नमेंट को लिखा है कि उन के पास काम बहुत थोड़ा है और उन का नम्बर रिडयूस किया जाय ?

मुख्य मन्त्री : मेरी इतलाह के मुताबिक कोई रीप्रेज़ेंटेशन नहीं आया। ।

Sardar Gurdarshan Singh : Sir, is the hon. Chief Minister aware of the fact that I.A.S. Organisation has represented or intend representing to the Government that the Administration is top heavy ?

मुख्य मन्त्री : मेरी इतलाह के मुताबिक कोई ऐसा रीप्रेज़ेंटेशन नहीं है ।

श्री अमर सिंह : मुख्य मन्त्री साहिब ने 1965 में बताया है कि आई०ए० एस० अफ़सरान की तादाद 167 हो गई है । क्या मैं उन से दरियाफत कर सकता हूं कि इन में से शेडयूल्ड कास्ट कितने हैं ?

मुख्य मन्त्री : इस के लिए सैपेरेट नोटिस चाहिए। इन में शेड्यूल्ड कास्ट भी हैं । गुरदासपुर के डी०सी० सरदार जोगिन्द्र सिंह शेड्यूल्ड कास्ट हैं ।

ਕਾਮਰੇਡ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ : ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਂ ਸੱਤਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਐਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ ਕੀ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਐਨੀ ਹੀ ਵਧੀ ਹੈ ?

मुख्य मन्त्री : जिस तरह से हमारा प्लान बढ़ा है, काम बढ़ा है, उसी हिसाब से स्टाफ भी हर जगह पर बढ़ा है । (विघ्न)

श्री बनवारी लाल : क्या मुख्य मन्त्री साहिब बताएंगे कि इन आई०ए०एस० और पी०सी०एस० अफसरान में शेड्यूल्ड कास्ट की परसेंटेज को पूरा करने की कोशिश की जाएगी ? (विघ्न) अगर क्वालीफिकेशन के आदमी मिलें तो ?

मुख्य मन्त्री : जिस तरह से रूल्ज़ इजाज़त देते हैं उसी तरह से किया जाता है ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਫੀਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਥੇ ਐਸ. ਪੀ. ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਐਸ. ਐਸ. ਪੀ. ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਥੇ ਜੂਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਡੀ. ਸੀ. ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ?

मुख्य मन्त्री : उन के साथ कोई फवरिटिज़्म नहीं की गई । दोनों डी० सीज० ने निहायत शानदार काम किया हैं, सारा पंजाब उन का मश्कूर है ।

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਕੀ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1-10-1964 ਨੂੰ ਆਈ. ਏ. ਐਸ. ਅਫਸਰ 136 ਸਨ ਔਰ 1-10-1965 ਨੂੰ 167 ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਪੀ. ਸੀ. ਐਸ. ਅਫਸਰ 1-10-1964 ਨੂੰ 422 ਸਨ ਤੇ 1-10-1965 ਨੂੰ 418 ਹੋ ਗਏ ਯਾਨੀ ਆਈ. ਏ. ਐਸ. ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਗਈ ਔਰ ਪੀ. ਸੀ. ਐਸ. ਅਫਸਰ ਘਟ ਗਏ; ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ?

मुख्य मन्त्री . जैसा कि आनरेबल मैंबर साहिब को मालूम है, गवर्नमैंट आफ इंडिया की हिदायात के मुताबिक पी०सी०एस० काडर से आई०ए०ऐस० के लिए कोटा बढ़ता रहता है । उसी के मुताबिक यह फर्क आ गया होगा ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਨਿਊਜ਼ ਆਈਟਮ ਸੀ ਕਿ ਸੈਕਰੇਟੇਰੀਏਟ ਵਿਚ 1948 ਵਿਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 320 ਸੀ ਜਦ ਕਿ 1965 ਵਿਚ 2226 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨਾਲੋਂ ਟਾਪ ਹੈਵੀ ਹੈ ?

मुख्य मन्त्री : आनरेबल मेम्बर को अखबारी खबरों में नहीं जाना चाहिए । अगर कोई आर्थन्टिक रिपोर्ट हो तो मेरे नोटिस में लाएं ।

डाक्टर बलदेव प्रकाश : क्या मुख्य मन्त्री यह बताएंगे कि आई० ए० एस० के अफसर, जो कि गवर्नमेंट के बड़े रेस्पांसीबल अफसर हैं, अगर कोई बात अखबारों के अन्दर रिप्रजैंट करें या जनता के सामने अपने व्यू रखें तो क्या गवर्नमेंट उसका ड्यू नोटिस नहीं लेती ?

मुख्य मन्त्री : जैसा कि आनरेबल मेम्बर साहिब को मालूम है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स को अखबारों के अन्दर किसी तरह की कोई शिकायत वगैरा लाने की इजाज़त नहीं है । यह किस तरह से निकला है, क्या निकला है मेरे इल्म में यह बात नहीं है । लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि जहाँ तक आई०ए०एस० आफीसर्ज़ का ताल्लुक है वह मुझे मिलते रहते हैं । अगर उन की कोई शिकायत हो तो उसे रफा करना गवर्नमेंट अपना पहला फर्ज़ समझती है ।

कामरेड राम प्यारा : क्या चीफ मिनिस्टर साहब यह बताने की कृपा करेंगे कि यह दरियाफत करने के लिए कि बाकी स्टेट्स के मुकाबिले में पंजाब की ऐडमिनिसट्रेशन हैवी है या नहीं, बाकी स्टेट्स से इस सम्बन्ध में फिगर्ज़ मंगवा कर कोई स्टेटमेंट, कोई कम्परेटिव स्टेटमेंट तैयार की गई है या नहीं और अगर की गई है तो उसके मुताबिक गवर्नमेंट किस नतीजा पर पहुंची है ?

मुख्य मन्त्री : मैं कल भी एक सवाल के जवाब में बता चुका हूं कि जो ऐडमिनिस्ट्रेटिव रीफार्मज़ कमिशन की टर्मज़ आफ रैफ्रेन्स हैं उन में यह भी एक आईटम हैं कि जहां तक पंजाब की ऐडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक है कि वह हैवी या किस तरह है, उस पर भी गौर करके वह अपनी सिफारिश करेगी और गवर्नमेंट उस सिफारिश पर पूरी तरह से गौर करेगी ।

ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਟਾਪ ਹੈਵੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ ?

मुख्य मन्त्री : कोई एनक्वायरी करने का सवाल ही पैदा नहीं होता । मेरी इतलाह के मुताबिक इस किस्म की खबरों का आम पब्लिक पर असर होने की कोई बात नहीं है ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੀਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਡੀ. ਸੀ. ਬਾਰੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ । ਕੀ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਡੀ. ਸੀ., ਫੀਰੋਜ਼ਪੁਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਛਡ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਵੈਕੂਏਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ?

मुख्य मन्त्री : जहां तक डी०सी० फिरोज़पुर के काम का ताल्लुक है, सारा ज़िला उसकी तारीफ कर रहा है । उसने बहुत शानदार काम किया है और पंजाब गवर्नमेंट भी उसके लिए खराजे तहसीन देती है ।

DEMAND OF CREATION OF PUNJABI LINGUISTIC STATE

*8676. **Comrade Shamsher Singh Josh :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether the Union Government Sub-Committee set up to consider the demand for the creation of a Punjabi Linguistic State has asked for any information from the State Government on the said subject, if so, a copy of the reply or information supplied by the Government to the said Sub-Committee be placed on the Table of the House ; and

(b) whether apart from the said information, the State Government has sent to the Union Government its views on the subject of Linguistic re-division of the present State of Punjab?

Shri Ram Kishan : It is regretted that it would not be in the Public interest to reply this question on the Floor of the House.

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ । ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਪਣੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਵਿਚ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਅਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਹਨ ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਸ ਬਿਨਾ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰੈਸਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ । ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਲਿੰਗ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਉਤੇ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸੂਚਨਾ ਇਸ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੂਚਨਾ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ? ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਕੈਬੀਨਟ ਨੇ ਇਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਪਬਲਿਕਲੀ ਉਸਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਸਣਾ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰੈਸਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਸ ਇੰਟਰੀਕੇਟ ਪੁਆਇੰਟ ਉਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਲਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ

Mr. Speaker : If the Government claim a privilege with regard to a certain reply, I cannot help it.

Sardar Gurdarshan Singh : In part (b) of the question, it has been asked whether the State Government has sent to the Union Government its views on the subject of linguistic re-division of the present State of Punjab. It is not understood what public interest is involved in replying to this question.

Sardar Gurnam Singh : May I know from the Chief Minister if it is a fact or not that he and some of his Cabinet Ministers made public statements on this issue, and, if so, were they in public interest ?

STARRED QUESTION NO. * 8779 (POSTPONED)

Mr. Speaker : Next Question *(8779) by Comrade Bhan Singh Bhaura. Time for reply has been extended.

---

*Starred question No. 8779 alongwith its answer is printed in P.V.S. Debates Vol. II No. 26, dated the 24th November, 1965.

ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਉਤੇ ਰੂਲਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਵਾਲ ਵਿਚ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਇਤਲਾਹ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਗਲ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀ ਜਸਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ?

Mr Speaker : Extension has already been given please.

INSTALLATION OF TEXTILE MILLS IN PUNJAB

***8651. Sardar Gian Siagh Rarewala :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the number of new Textile Mills proposed to be installed in the Punjab in the current financial year ;

(b) the number out of those referred to in part (a) earmarked for the Erstwhile Pepsu region (Patiala Division);

(c) the names of the places where the said mills are likely to be installed and the time by which these are expected to go into production?

Shri Ram Kishan : The requisite information is laid on the table of the House.

Information regarding installation of Textile Mills in Punjab.

(a) Capacity for the establishment of eight new cotton spinning mills of 12,000 spindles each has become available with the proposed revocation/cancellation of some of the industrial licences issued by the Government of India against State's Third Five-Year Plan quota of cotton spindles. Proposals for the grant of licences to five parties in lieu thereof have been sent to the Government of India. The matter regarding the selection of remaining parties is under consideration.

(b) Four.

(c)

Ferozepur District	Two.
Sangrur District.	One
Bhatinda District	Two.
Patiala District	One.
Karnal District	One.
Rohtak District	One.

According to the conditions attached to the licences granted by the Government of India, the licensees are required to take effective steps within six months and to establish the undertaking within $1\frac{1}{2}$ years from the date of issue of the licence.

INDUSTRIAL ESTATE AT HANSI, DISTRICT HISSAR

***8777. Shri Amar Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under the consideration of the Government to construct an Industrial Estate at Hansi in Hissar District; if so, the steps taken by the Government so far in this respect and the approximate date by which the same is likely to be finalized and the construction of the Estate completed ?

Shri Ram Kishan : Yes; steps are being taken to get the land released from the Colonization Department. It was proposed to complete the construction of this Estate by the end of 1965-66 but due to emergency the construction has been postponed.

श्री अमर सिंह : क्या चीफ मनिस्टर साहिब यह बताने की कृपा करेंगे कि इंडस्ट्रियल ऐस्टेट हांसी के लिए ज़मीन अब तक एक्वायर हो चुकी है या नहीं ?

मुख्य मन्त्री : जैसा कि जवाब में बताया गया है कि अभी उस ज़मीन की बाबत सारा प्रासेस बाकी है । वहां पी· डब्ल्यू. डी. से ज़मीन लेनी थी और उन्होंने 1,6424 रुपया पर एकड़ ज़मीन की कीमत बताई थी जिसकी बाबत यह समझा गया था कि यह बहुत ज्यादा है और अब उन से बातचीत हो रही है । हम आशा रखते हैं कि जल्दी ही फ़ैसला हो जाएगा और ज़मीन हासिल करके कंस्ट्रक्शन शुरू की जा सकेगी ।

श्री इन्दर सिंह मलिक : क्या चीफ़ मनिस्टर साहिब बताएंगे कि एक सवाल के जवाब में पहले भी श्री अमर सिंह को बताया गया था कि तहसील की बिल्डिंग अनसरविसेबल पड़ी है, नई बनाई नहीं गई हालांकि वहां पर इंटें पड़ी हुई हैं, सीमेंट पड़ा हुआ है । उसको बन्द कर दिया गया था अब इंडस्ट्रियल ऐस्टेट हांसी की बाबत भी यही जवाब दिया गया है कि वहां पर अभी ज़मीन नहीं मिली । क्या यह बताएंगे कि वहां पर ये काम इस लिए नहीं किए जा रहे क्योंकि श्री अमर सिंह अभी तक कांग्रेस में एडमिट नहीं हुए ?

मुख्य मन्त्री : ऐसी बात नहीं है ।

ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਰਲ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟਸ ਬਣਣੀਆਂ ਸਨ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਜਗਾ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ? ਕੀ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਰੀਵੀਊ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਬੰਡਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰਖਦੀ ਹੈ ?

मुख्य मन्त्री : रूरल और अर्बन इंडस्ट्रिल ऐस्टेट्स का सारा मामला प्लैनिंग कमिशन के ज़ेरे-गौर है कि इन्हें किस तरह से सारी स्टेट्स में बनाने के लिए सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को आगे फोर्थ फाइव-इयर प्लैन में हिदायत दी जाए ताकि ये ऐस्टेट्स अच्छी तरह से चल सकें ।

Mr. Speaker : Question Hour is over now.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE UNDER RULE 45

STAINLESS STEEL IMPORTED DURING 1965

***8793. Rao Nihal Singh** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total quantity of stainless steel imported into the State through the Punjab State Small Industries Corporation during the year 1965 for non-utensil purpose ;

(b) whether the Government formulated any definite policy for the distribution of the said steel before it was actually distributed; if so, details of the policy be laid on the Table of the House;

[Rao Nihal Singh]

(c) the names and addresses of the parties who have been allotted quotas of stainless steel during the year 1965;

(d) whether it was ensured that the parties who were allotted the quotas had the necessary machines installed for the manufacture of non-utensils articles ?

Shri Ram Kishan : (a) 221.537 Metric tons.

(b) & (c) Yes. The requisite information is laid on the Table of the House (Annexures I-II).

(d) Yes.

ANNEXURE I

POLICY FOR DISTRIBUTION OF STAINLESS STEEL FOR NON-UTENSIL PURPOSES

1. Stainless steel of different gauges was imported from Czechoslovakia and Japan at different prices. It was decided to allot stainless steel sheets to parties in proportionate of 40 per cent from Czechoslovakia (18, 19 & 20 G) 40 per cent from Japan (18, 19 & 20 G) and 20 per cent 26-G from Japan.

2. The Department had recommended the Essentiality Certificates for import of stainless steel for the period October, 1964—March, 1965. These recommendations were withdrawn and the parties were allotted material in proportion to the recommendations made to import authorities for stainless steel in the Government of India.

3. Material was allotted to parties in whose favour it was decided to meet arrear claims.

4. Allotment was made taking into consideration the highest value of Essentiality Certificate for stainless steel sheets issued during the last three licensing periods, of 6 months each, subject to maximum of 6 M. T. and with a minimum standard of half M. T.

5. The new parties who had not been given Essentiality Certificates during the last three periods were allotted imported stainless steel sheets equal to the entitlement as worked out by the field officers for issue of Essentiality Certificates for stainless steel sheets for the period 1965-66.

In case where the entitlement of the party for issue of Essentiality Certificates for stainless steel for the year 1965-66 was more than his share on the basis of Essentiality Certificates for the last three periods, the party was given material equal to the entitlement as worked out for the period 1964-65.

6. The Department is considering to encourage the parties and make allotment of stainless steel sheets for export purposes and also for production of defence articles.

ANNEXURE II

STATEMENT SHOWING THE NAMES AND ADDRESSES OF THE PARTIES ALLOTTED STAINLESS STEEL SHEETS FOR NON-UTENSIL PURPOSES.

Sr. No.	Name of the Party
1.	M/s. Bali Singh Bhagwan Singh, outside Ghee Mandi Gate, Amritsar.
2.	M/s. Indian Weighing Machine, Hide Market, Amritsar.
3.	M/s. Kartar Industries, outside Ram Bagh Gate, Amritsar.
4.	M/s. Akali Kirpan Factory, Malvai Bunga, Amritsar.
5.	M/s. Rumpas Industries, Industrial Estate, Ludhiana.
6.	M/s. Speedway Surgical Co., 583, Pindi Street, Ludhiana.

Sr. No.	Name of the Party
7.	M/s. Sigma Steel Industries, A-2, Industrial Estate, Ludhiana.
8.	M/s. Sat Kartar Cycle Industries, Industrial Estate, Ludhiana.
9.	M/s. T. F. Industrial Corporation, Industrial Estate, Ludhiana.
10.	M/s. Sant Singh Mehta & Co., 17-B, Industrial Estate, Ludhiana.
11.	M/s. Dua Brothers, Industrial Estate, Ludhiana.
12.	M/s. B.S.S. Engineering Works, Gill Road, Millar Ganj, Ludhiana.
13.	M/s. Aero Engineering Works, 439, Karim Pura Road, Ludhiana.
14.	M/s. Jiwan Engineering Works, Industrial Estate, Ludhiana.
15.	M/s. Rama Fancy Works, Ganji Chhaapri, Ludhiana.
16.	M/s. Silara Industries, 455, Emerson Road, Ludhiana.
17.	M/s. New India Engineering Industries, Industrial Estate, Ludhiana.
18.	M/s. Gupta Loom Industry, Industrial Estate, Ludhiana.
19.	M/s. Mahabir Metal Works, Kapurthala.
20.	M/s. Surjit Industries, Industrial Estate, Malerkotla.
21.	M/s. Narendra Stainless Steel Industries, Industrial Estate, Malerkotla.
22.	M/s. Sekhri Brothers, 12-A, Industrial Estate, Batala.
23.	M/s. Kuldip Industries, Village Mamoon, tehsil Pathankot, district Gurdaspur.
24.	M/s United Iron Industries, Sarai Chopta, Bhiwani.
25.	M/s. Punjab Wire Netting Industries, Railway Road, Narnaul.
26.	M/s. Adarsh Metal Industries, Jagadhri.
27.	M/s. Amrit Metal Industries, Jagadhri.
28.	M/s. Associated Industries, Jagadhri.
29.	M/s. Jainco Industries. Spatu Road, Ambala City.
30.	M/s. Kuldip Industrial Corporation, Industrial Area, Chandigarh.
31.	M/s. Kiran Industries, Industrial Area, Chandigarh.
32.	M/s. Raj & Co., Railway Road, Bhatinda.
33.	M/s. J. L. Sumer Chand Jain, Jhajjar Road, Rohtak.
34.	M/s. Punjab Iron and Steel Industries, Butana Road, Gohana.
35.	M/s. Pokhar Dass & Co., Delhi Road, Rohtak.
36.	M/s. National Steel Industries, Industrial Area, Bahadurgarh.
37.	M/s. Trade Industrial Corporation, Industrial Area, Bahadurgarh.
38.	M/s. Hindustan Rolling & Wire Products, Sonepat.
39.	M/s. Saraf Industries, Industrial Area, Bahadurgarh.
40.	M/s. National Manufacturers & Traders, Kaithal.
41.	M/s. India Auto Industries, Kaithal.
42.	M/s. Datta Ram-Ashok Kumar, Kaithal.
43.	M/s. Seema Industrial Corporation, Karnal.
44.	M/s. Relan General Mills, Kaithal.
45.	M/s. New India Tin Bucket & General Manufacturers, Kaithal.
46.	M/s. Puran Chand-Sharwan Kumar, Kaithal.
47.	M/s. Setial Iron & Steel Industries Factory, village Pasina Kalan, 320-L, Model Town, Panipat.
48.	M/s. Bharat General Mills, Kaithal.
49.	M/s. Punjab General Manufacturers, Kaithal.
50.	M/s. Chandera Industries, Nakodar Road, Jullundur.
51.	M/s. Free India Surgical Works, Industrial Area, Jullundur.

[Chief Minister]

52. M/s. Standard Mechanical Works, Mandi Road, Jullundur.
53. M/s. Kwality Industrial Works, 17-G, Industrial Area, Faridabad.
54. M/s. Shamrock Industries, Mathura Road, Faridabad.
55. M/s. P & S (India) Corporation, Gurgaon.
56. M/s. T. R. Metal Engineering Works, Rewari.
57. M/s. Busching Schmitz Private Ltd., 18/6, Mathura Road, Faridabad.

REPORT REGARDING USELESSNESS OF INDUSTRIAL TRAINING CENTRES

***8411. Comrade Ram Chandra:** Will the Chief Minister be pleased to state whether the Deputy Minister for Industries, Punjab has submitted any report to him about the uselessness of Industrial Training Centres in the State; if so, the names of such centres and the total amount spent thereon ?

Shri Ram Kishan : No. Does not arise.

INDUSTRIAL TRAINING CENTRES IN KANGRA DISTRICT

***8412. Comrade Ram Chandra:** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the location of each of the Industrial Training Centres functioning in Kangra District at present;

(b) the total number of persons trained in each of the said centres year-wise since their start;

(c) the number of those, referred to in part (b) above, Centre-wise, who started work in the industry in which they received training at the Centres ?

Shri Ram Kishan : The requisite information is laid on the Table of the House.

Information regarding Industrial Training Centres, in Kangra District.

(a) (i) Industrial Training Institute, Shahpur.

(ii) Economic Uplift Training Centre for Scheduled Castes and Backward Classes, Palampur (since shifted to Hamirpur).

(iii) Government Industrial School for Girls at Dharamsala, Palampur and Hamirpur.

(b) (1) **Industrial Training Institute, Shahpur**

Year	Name of Examination	Number of students passed
1964-65	National Trade Certificate Course	46 trainees

(2) **Industrial Training Centre, Palampur (since shifted to Hamirpur)**

Year	Number of student passed
1963-64	12
1964-65	12

(3) **Government Industrial School for Girls, Dharamsala (started in 1958)**

Year	Name of Examination	Number of students passed
1958	Certificate	26
1959	Diploma	21
1960	Diploma	18
1961	Diploma	13
1962	Diploma	26
1963	Diploma	18
1964	Diploma	17
1965	Diploma	3
(4) **Government Industrial School, Palampur (started in 1964)**		
1965	Certificate	5
(5) **Government Industrial School for Girls, Hamirpur (started in 1961)**		
1962	Certificate	3
1963	Certificate	9
1964	Certificate	5
1965	Certificate	6

(c) The passed out trainees were posted for 6 months compulsory apprenticeship training in factories of repute. No further information is available, either about these trainees or about the trained girls.

RATIONING IN THE STATE

*8685. **Comrade Shamsher Singh Josh** : Will the Chief Minister be pleased to state whether Government is considering any proposal to introduce rationing in certain cities of the Punjab; if so, their names and the time by which it is proposed to be done ?

Shri Ram Kishan : Yes. The names of places where statutory rationing is proposed to be introduced and time by which it will be done have not been finalised yet.

ELECTRIFICATION OF VILLAGES IN SUB-TEHSIL TOHANA, DISTRICT HISSAR

*8774. **Shri Amar Singh** : Will the Minister for Transport and Elections be pleased to state—

(a) the names of the villages so far electrified in sub-tehsil Tohana, district Hissar;

(b) the total number and names of villages proposed to be electrified in the Fourth Five-Year Plan period in the said Sub-Tehsil?

Sardar Gurdial Singh Dhillon : (a) A statement is laid on the Table of the House.

[Transport and Elections Minister]

(b) Selection of new villages to be electrified in different areas of the State during the IV Five-Year Plan has not been finalized as yet.

1. Tahana
2. Mamunpur
3. Rayanwala
4. Bhudanpur
5. Haidarwala
6. Handalwal
7. Lalluwal
8. Kana Khera
9. Shakarpur
10. Girnun
11. Mathuwal
12. Chilewal
13. Mewadkhurd
14. Mewadkalan
15. Sirbalwala
16. Himatpura
17. Purmazra
18. Kundni
19. Shakarpura
20. Babheri Khera
21. Dangra
22. Loha Khera
23. Nangli
24. Nangal
25. Laluda
26. Kamalwala
27. Haidawala Bilaspur
28. Chelewal Bilaspur
29. Kanheri

APPLICATIONS FOR ELECTRICITY CONNECTIONS FOR TUBE-WELLS IN GURGAON AND REWARI TEHSILS

***8795. Rao Nihal Singh :** Will the Minister for Transport and elections be pleased to state—

(a) the total number of applications for electric connections for Tube-wells at present pending in Gurgaon and Rewari Sub-Divisions of Electricity and the number of the applicants among them who have since submitted their test reports;

(b) whether it is a fact that the villagers of Sikandarpur Badha in Gurgaon Tehsil submitted their test reports in the month of December, 1964; if so, whether they have been supplied electricity or not ;

(c) the number of names of the villages electrified during the period from 31st March, 1965 to 30th September, 1965 in district Gurgaon ?

Sardar Gurdial Singh Dhillon : (a)

Name of Sub-Division	Total Number of applications for tube-well connections pending up to 31st October, 1965	Number of applicants who have submitted test reports up to 31st October, 1965
Gurgaon Sub-Divn.	81	35
Rewari Sub-Divn.	328	57

(b) There was a single case of 14 applicants of this village in which 13 applicants submitted their reports in October, 1964. Owing to the failure of the 14th applicant the case became financially unjustified. A

new applicant was substituted for him. He submitted his test report on 7th September, 1965 only.

(c) Khawas Begra and Punheri Khurd.

KILOI-BHALOT ROAD IN DISTRICT ROHTAK

*8745. **Shri Mangal Sein** : Will the Minister for Public Works be pleased to state whether Government has recently decided to metal the Kiloi-Bhalot Road in district Rohtak; if so, the progress made in connection therewith so far ?

Chaudhri Ranbir Singh : Part I.—Yes.

Part II.—Administrative approval for the execution of the work during the current year has since been accorded.

PROMOTIONS AS ASSISTANTS IN THE OFFICE OF THE CHIEF ENGINEER, B & R

*8799. **Lieut. Bhag Singh** : Will the Minister for Public Works be pleased to state—

(a) whether it is a fact that it is the policy decision of the Government to reserve 10 per cent vacancies for Scheduled Caste employees in the matter of promotion to the next grade;

(b) if the reply to part (a) above be in the affirmative, whether any of the Sheduled Caste Clerks in the Office of the Chief Engineer, B & R due for promotion as Assistant in accordance with the said decision have been denied this promotion; if so, the reasons therefor ?

Chaudhri Ranbir Singh : (a) Yes.

(b) No.

SHORT NOTICE QUESTION AND ANSWER

10 a.m.

ESTABLISHMENT OF WAR HEROES HOME IN THE STATE

*8725. **Sardar Gurbakhsh Singh Gurdaspuri** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether Government propose to establish a War Heroes Home in the State for accommodating the families of the officers of the Punjab Police and P. A. P. who were killed in the recent Pak-India conflict; if so, the time by which it is expected to start functioning and a copy of the scheme, if any, formulated in this behalf be laid on the Table;

[Sardar Gurbaksh Singh Gurdaspuri]

(b) if the answer to part (a) above be in the affirmative, whether the proposed Home shall also accommodate the deserving families of the military personnel; if not, the reasons therefor;

(c) the total number of families likely to be accommodated in the said Home ;

(d) whether Government has appointed any Committee for the purpose; if so, the names of its Members;

(e) whether Government propose to associate any General or Ex-General of the Army with the said Committee; if not, the reasons therefor ?

Shri Ram Kishan : (a), (b) & (c) It is proposed to establish a War Home for honouring war heroes and their families. The details of the scheme are being worked out.

(d) Yes. The names of the members of the committee are :—

(1) Chief Secretary.

(2) Additional Chief Secretary.

(3) Home Secretary.

(4) Inspector-General of Police.

(5) Deputy Inspector-General of Police, C. I. D.

(6) Finance Secretary.

(7) Commandant General, Home Guards.

(8) Director, Civil Defence.

(9) Lt.-General Kulwant Singh.

(10) One army representative.

(11) Commissioner, Ambala Division.

(12) Deputy Commissioner, Karnal.

(13) Director, Social Welfare.

(14) Shri R. I. N. Ahooja, I.A.S., S.L.C.P.

(e) Yes.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਪਾਰਟ ਬੀ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁ ੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪੁਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਹੀਰੋਜ਼ ਹੋਮ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਮੋਡੇਟ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਔਰ ਅਗਰ ਐਕਮੋਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਕਿ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਪੀ. ਏ. ਪੀ. ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹੋਮ ਬਣਾਏ ਹਨ ਪਰ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਮੋਡੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ?

मुख्य मंत्री : इस का जवाब मैंने yes में दिया है, और जवाब में बताया है कि उस कमेटी में एक रिटायर्ड जनरल रखा गया है........

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ : ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਪਾਰਟ ਬੀ ਬਾਰੇ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕੀ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਵਿਚ ਐਕਮੋਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ?

मुख्य मंत्री : उस के अन्दर सब को अकमोडेट किया जाएगा खाह वह एयर फोर्स के हों खाह आरमी से ताल्लुक रखते हों खाह पी० ए० पी० के हों। उन सब की फैमेलीज़ को वहां रखा जाएगा। इस बारे में मैं ने आरमी के जनरलज़ के साथ भी बात की है। इस में कोई शक नहीं कि हमारे पी० ए० पी० के जवानों ने बड़ी कुरबानियां इस एग्रेशन के दौरान दी हैं।

श्री बलरामजी दास टण्डन : क्या मुख्य मंत्री जी बताएंगे कि यह जो वार हीरोज होम बनाया जा रहा है क्या यह डिस्ट्रिक्ट वाईज स्पलिट अप होंगे या किसी एक ही जगह पर होगा ?

मुख्य मंत्री : यह सारी चीज़ें अभी सरकार के ज़ेरे गौर है। इस बारे में कमेटी की मीटिंग पहले हो चुकी है और एक मीटिंग कल होने वाली है और इस में यह सारी चीज़ों पर विचार किया जाएगा और यह वर्क आऊट होनी है।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ : ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਪਰਾਪਰ ਨਹੀਂ ਹਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਰ ਹੀਰੋ ਹੋਮ ਇਕ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਯਾਨੀ ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਜਨ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਰੀਆਣੇ ਵਿਚ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਂਗੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਉਥੇ ਹੋਵੇ ?

मुख्य मंत्री : जहां तक मारटीयरज़ का ताल्लुक है उन के बारे रिजनज़ के बेसिज़ पर नहीं सोचा जाता। वह सब के होते हैं। लेकिन इस बारे में मैं, स्पीकर साहब, आप के द्वारा हाउस को यह यकीन दिला देना चाहता हूं कि यह चीज़ गवर्नमैंट के ज़ेरे गौर है हम नोन और अन-नोन सोलजरज़ के लिए, जिन्हों ने इस अग्रेशन के दौरान अपनी जानें बलिदान दी हैं, उन की याद में कोई ऐसी यादगार कायम करें जिस से उन के नाम अमर रहें। जहां तक ज़िला कांगड़ा का ताल्लुक है इस में कोई शक नहीं कि वहां के राजपूतों ने और वहां के डोगरों ने इस लड़ाई में बढ़ चढ़ कर काम किया है और काफ़ी हद तक उन सब ने बड़ी कुरबानियां दी हैं। यह बात कहने में मेरा यह मतलब हरगिज़ नहीं कि किसी दूसरी कौम के जवानों की उन से तुलना हो लेकिन यह बात जरूर कह देना चाहता हूं कि कांगड़ा के जवानों ने अज़हद कुरबानियां दी हैं और इस के साथ ही मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि ज़िला रोहतक की तहसील झज्जर के काफी जवान भी बलिदान हुए हैं। गवर्नमैंट इस बारे में विचार कर रही है कि इन इलाकों में सैनिक रैस्ट हाउस बनाए जाएं या और उन लोगों की याद में यादगारें कायम की जाएं। इस कमेटी की पहले एक मीटिंग हो चुकी है और एक मीटिंग 5 तारीख को यानी कल होने वाली है उस में हम आरमी वालों का भी इन सारी बातों के बारे में मश्वरा लेंगे और उन की सलाह के मुताबिक हम उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे।

ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੀਰੋਜ਼ ਹੋਮ ਵਿਚ ਪੀ. ਏ. ਪੀ. ਤੇ ਆਰਮੀ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਐਕਮੋਡੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਹੀਰੋਜ਼ ਹੋਮ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਕੇ ਆਰਮੀ ਐਂਡ ਪੀ. ਏ. ਪੀ. ਹੋਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ? ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ?

मुख्य मंत्री : इस बारे में केबिनेट के अन्दर डिसियन लिया गया है उस से आप को पता चल जाएगा, जो यह है–

> "that a War Heroes Home/Institution should be set up named after Shri Lal Bahadur Shastri, the Prime Minister, with the object of honouring the war heroes and their families as well as honouring the Prime Minister of the country who has set an excellent example of leadership to the Nation in this Emergency. The details of the Scheme, including a suitable name for it, will be worked out by the Chief Secretary in consultation with the Army Authorities. Chief Secretary will, in consultation with me (C.M.) set up a Committee for drawing up the details of the scheme co-opting suitable representative of the Army Authorities also. He will also consider where this Institution/Home should be located. It was broadly felt that the Home/Institution should be managed by autonomous board to be set up for the purpose. It was further decided that the State Government should set apart a sum up to Rs. 25 lakhs to meet the cost of this scheme—the exact amount to be decided when the details thereof have been worked out."

OBITUARY REFERENCE

Mr. Speaker : Now we pass on to the next item on the agenda—an obituary reference.

चौधरी इन्दर सिंह मलिक : स्पीकर साहिब, इस के इलावा एक चौधरी चन्दर भान जी एडवोकेट जो कि पी० सी० सी० के मैम्बर थे उन का नाम भी इस रेफरेंस में इनक्लूड कर लिया जाए क्योंकि उन का देहांत भी थोड़े दिन हुए हैं, हुआ था इस बारे में मैं. . . . . . .

श्री अध्यक्ष : इस के लिए बेहतर यही रहेगा कि अगर आप किसी वक्त चीफ मिनिस्टर साहब से मिल कर बात कर लें और फिर किसी दिन हाउस में ले आएं। (It would be better if the hon. Member talks about this matter with the Chief Minister at some other time and then bring it in the House on some other day.)

मुख्य मंत्री (श्री राम किशन) : स्पीकर साहिब, मुझे हाउस को बड़े अफसोस और दुख के साथ यह इतलाह देनी पड़ती है कि हमारे विधान परिषद के मेम्बर चौधरी हरेन्दर सिंह की डैथ आज से कुछ दिन पहले हो चुकी है, उन की उमर 55 साल की थी और वह 27 अप्रैल, 1962 में करनाल की लोकल बाडीज़ कानस्टीच्यूएंसी से कौंसल के लिए मुनतखिब हुए थे। वह जनसंघ की पार्टी से ताल्लुक रखते थे लेकिन वह खास तौर पर देहाती कामों में अपनी एकटिविटीज़ महदूद रखते थे और जो हमारी रूरल प्राबलमज़ हैं यानी वाटर लागिंग और फ़लडज़ वगैरा उन में ज्यादा दिलचस्पी लिया करते थे और कौंनसल में वह ज्यादा तर इन्हीं के बारे में स्पीचिज़ किया करते थे और जब कभी उन को इस बारे में कुछ कहने का मौका मिलता था तो वह अपने ख्यालात रखा करते

थे । जब यहां पंजाब में हिन्दी रक्षा समिति अन्दोलन चला था तो उन्हों नें उस में भी हिस्सा लिया था । जितनी भी वह पंजाब के अन्दर स्पीचिज़ किया करते थे उन से लोग एक अच्छा इम्प्रेशन लिया करते थे । वह देहात के लोगों के काज़ के लिए हमेशा काम किया करते थे । वह कैथल की एक अच्छी फैमली में से थे और उन के पिता एक रिटायर्ड फौजी रसालदार थे । उन के बारे में बताया जाता है कि वह एक पुराने फौजी खानदान में से थे और उन के कई रिश्तेदार अब भी फौज में हैं । उन के एक भाई अब भी फौज में हैं और एक दूसरे भाई उत्तर प्रदेश में एक इम्पार्टेंट पोस्ट पर लगे हुए हैं । मुझे अफ़सोस है कि हम उन की मौत से उन की खिदमात से महरूम हो गए हैं । मैं उन की इस बे वक्त मौत पर उन के परिवार से सहानुभूति प्रकट करता हूं । वह अपने पीछे अपनी धर्मपत्नी, चार बच्चे और पांच लड़कियां छोड़ गए हैं । वह जितनी देर कौंसल के मैम्बर रहे बड़ी अच्छी तरह से अपने राज और हलके की सेवा करते रहें । मैं समझता हूं कि यकीनी तौर पर सारा हाउस इस ग़म में शरीक होगा और उन के परिवार से अपनी हमदर्दी जतायगा ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੋ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਿਦਮਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਇਕ ਵਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ । ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।

चौधरी देवी लाल : स्पीकर साहिब, जो शोक प्रस्ताव लीडर आफ दी हाउस ने चौधरी हरिन्दर सिंह जी की बाबत पेश किया है सारा हाउस उस से मुतफ़िक है । चौधरी हरिन्दर सिंह जी ने पंजाब के एक पिछड़े हुए इलाके, हरियाने और खास तौर पर करनाल और कैथल के इलाके, की जितनी खिदमत ऐजुकेशन के सिलसिले में की है वह भुलाई नहीं जा सकती । इस के साथ साथ उन की जो पोलीटीकल सेवाएं हैं, हरियाणा के हित के लिये, वह भी याद रखने के काबिल हैं । वह हर मामले में सब से आगे रहा करते थे । उन के हमारे बीच में से चले जाने से हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ा है और हमें आशा करनी चाहिए कि उस इलाके में और उन की जगह को पुर किया जा सकेगा । उन का इन दिनों, जब कि यहां पर खास हालात हैं उन का हमारे बीच में रहना बहुत ज़रूरी था । उन की मौत बहुत नुकसानदेह साबत हो रही है । मैं आशा करता हूं कि हाउस उन के घर वालों से हमदर्दी ज़ाहिर करेगा । मैं अपनी पार्टी की तरफ से इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि परमात्मा उन की आत्मा को शान्ति दे ।

डा० बलदेव प्रकाश : स्पीकर साहिब, जो शोक प्रस्ताव माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने सदन के सामने रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । चौधरी हरिन्दर सिंह विधान परिषद में करनाल लोकल बाडीज़ की सीट से चुन कर आए थे। वह अपने क्षेत्र के एक बहुत ही अच्छे समाजसेवी और विशेषकर ऐजुकेशन के क्षेत्र में काम करने वाले बहुत अच्छे कार्यकर्ता थे । वह एक बहुत ही पुराने और प्रतिष्ठित परिवार से थे जोकि एक फौजी परिवार है । उन के दादा भी और पिता जी भी फौज

[डा० बलदेव प्रकाश]
के अन्दर रहे। उन्हों ने फौज में रह कर बड़े बड़े तमगे प्राप्त किये। इस ऐमरजैंसी के दौरान भी उन का भतीजा वीर गति को प्राप्त हुआ। चौधरी साहिब के निधन से सारे पंजाब को बड़ा नुकसान हुआ है विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र को जिस में कि वह ज्यादा काम किया करते थे और कर रहे थे। अब भी वह एक स्कूल चला रहे थे। यू० पी० में भी सैदपुर गांव में उन के पिता के नाम पर स्कूल चल रहा है। उनके चले जाने से जहां सारे सूबे को नुकसान हुआ है वहां पर हमारी पार्टी को खास नुकसान हुआ है क्योंकि उन्होंने हमारी पार्टी के लिये अपने इलाके में बहुत काम किया। स्पीकर साहिब, जिस तरह के अच्छे कार्यकर्ता वह थे वह मैं एक छोटा सा उदाहरण दे कर बताता हूं। वह सन 1957 के चुनावों में खड़े हुए मगर हार गए, एक मामूली सी बात के लिये। उन को कहा गया कि अगर फलां फलां आदमी को एप्रोच करो तो उन को कई हज़ार वोटें मिल सकती हैं। उन्होंने कहा कि मुझे किसी को भी एप्रोच करने में नुकसान नहीं है लेकिन चूंकि मेरा उन से बुनियादी मतभेद है, मैं उन से कुछ न कहूंगा चाहे जीतूं या हारूं। तो वह दो तीन सौ के करीब वोटों से हार गए। वह इस तरह के अपने सिद्धांत पर पक्के रहने वाले व्यक्ति थे। इन शब्दों के साथ मैं उन को श्रद्धांजलि भेंट करता हूं और परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उन की आत्मा को शान्ति और उन के परिवार को इस नुकसान को सहने की शक्ति दे।

ਕਾਮਰੇਡ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਚੀਫ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਮਤਾ ਹਾਊਸ ਸਾਹਮਣੇ ਚੌਧਰੀ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਇਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਬੜਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਚਲਾਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਧਾਂਜਲੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਜੋ ਜਜ਼ਬਾਤ ਲੀਡਰ ਆਫ਼ ਦੀ ਹਾਊਸ ਵਲੋਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਲੀਡਰਜ਼ ਵਲੋਂ ਚੌਧਰੀ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹਾਂ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਮਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਧਾਨ ਪਰੀਸ਼ਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਰ ਛੱਡ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੋ ਮਿੰਟ ਖਾਮੋਸ਼ ਖੜੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿਚ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਾਂਗੇ।
(I fully associate myself with all the sentiments expressed by the Leader of the House and other Leaders of the groups while paying tributes to the late Chaudhri Harinder Singh. Chaudhri Sahib had won great popularity and esteem of the people of his ilaqa whom he had

been serving for a long time. I too had an opportunity to know him from a close quarter. His services to the country can never be forgothen. His work and speeches in the Vidhan Parishad, which have left an indelible mark there, will always be remembered. Now we will pay our homage to deceased by standing in silence for two minutes.)

(ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੋ ਮਿੰਟ ਲਈ ਖਾਮੋਸ਼ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ)

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਕਾਪੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰੀਵਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । (A copy of this resolution will be sent to the family of the late Chaudhri Sahib.)

Mr. Speaker : We now pass on to the next item.

Sardar Gurnam Singh : It has been noticed that the people in the galleries also stand up when the House stands on such occasions. I request, Sir, that instructions may be issued that in future the visitors in the galleries should not stand.

Mr. Speaker : That is right. Visitors in the galleries should not stand.

QUESTION OF PRIVILEGE

Mr. Speaker : There is a privilege motion by Comrade Shamsher Singh Josh, Comrade Gurbakhsh Singh, Comrade Babu Singh and Sardar Gurcharan Singh. It is to the following effect—

"we beg to raise the following point of breach of privilege of the Members of the Legislature by publication of the "expunged proceedings" of the Vidhan Sabha sitting held on 2nd November 1965 in Daily Milap-Partap and Pardeep dated on 3rd November, 1965.

These papers have acted in clear defiance of Speaker's order because the hon. Speaker had clearly told the accredited correspondents of these papers not to publish the "expunged proccedings" of Vidhan Sabha, when these correspondents alongwith other Pressmen had met him in his Chamber at about 11.30 A. M. when the Business Advisory Committee was in session in Hon'ble Speaker's Chamber.

Relevant*cuttings of the said Dailies are being attached herewith. It is requested that the matter may be referred to the Privileges Committee for examination".

As our practice is, before taking any final decision, we shall refer the matter to the Press Gallery Committee and then take a decision.

Voices.. That is right.

ADJOURNMENT MOTION

ਕਾਮਰੇਡ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤਾ ਹੈ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 56 ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਡੈਟੇਨਿਊਜ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗਦਰ ਹੀਰੋਜ਼, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਹੀਰੋ, ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਦਿਤ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਵਗੈਰਾ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਕਠਨਾਈ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 9 ਤਾਂ 'C' ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਹਨ ।

*Placed in the Library.

[ਕਾਮਰੇਡ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ]

ਕਿਸੇ ਡੈਤੇਨਿਯੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਰੀਜਨ ਵੀ ਹਨ, ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਮੀਲੀ ਅਲਾਊਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਜਦ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿਸਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਮਦਰਾਸ ਵਿਚ 85 ਡੈਟੇਨਿਊਜ਼ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਮੀਲੀ ਅਲਾਊਂਸ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਥੇ ਇਕ ਐਮ. ਪੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੈਮੀਲੀ ਅਲਾਉਂਸ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਜ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਥੇ ਭੁਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ । ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭੁਖਹੜਤਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਜਾਣਗੇ ।

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਗ ਤਰਸਿਕਾ ਜੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਇਜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਏਨਾਂ ਭੈੜਾ ਸਲੂਕ ਜੇਲ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਰਸਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ । ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿਤੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੈਟੇਨਿਊਜ਼ ਵਿਚ ਦੋ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਅੱਵਲ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਾਊਟ ਲੀਗਲ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀਟੇਨ ਕਰੀ ਰਖਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ । ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਕਰੇ ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਤੂਲ ਨਾ ਦੇਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇਨੀ ਰਿਕੁਵੈਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪਾਸ ਅਤੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਹਾਊਸ ਪਾਸ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

Mr. Speaker : As an Adjournment Motion it cannot be allowed. Hunger-strike has never been the subject of an Adjournment Motion. But the Government may look into their grievances.

चौधरी देवी लाल : स्पीकर साहिब, आप ने इस तरह की मौशनतो कल भी अलाउ नहीं की थी। मैं तो सिरफ इतनी सी अर्ज़ करना चाहता था कि जितने भी हमारे सामने बैठे मेम्बर हैं वह खुद भी इसी रास्ता से गुज़र कर आए हैं और वह भी इस तरह की डिमांडें किया करते थे और उन की डिमांडें पूरी होनी चाहिएं । जितने भी डेटेन्यज़ हैं उनके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए । यह जो कामरेड साहिब और त्रिमूर्ति सामने बैठी है इन्हें उस रास्ते को नहीं भूल जाना चाहिए जिस रास्ते से आए हैं वह ।

मुख्य मंत्री : स्पीकर साहिब, चौधरी देवी लाल जी ने पुराने ज़माने की याद को ताज़ा कराया है । इस संबंध में जैसा कि हाऊस को मालूम है इस वक्त 47 डेटेन्यूज़ 'बी' क्लास में हैं और 2 'ए' क्लास में हैं । इस वक्त हमारी इतलाह के मुताबिक 8 भाई ऐसे हैं जिन्हें 'सी' क्लास में रखा हुआ है । इस हाऊस को मालूम है कि कलासिफिकेशन के बारे में रूल्ज़ बने हुए हैं और उन रूल्ज़ के तहत ही डेटेन्यूज़ को क्लास दी जाती है । इस वक्त गवर्नमैंट की तरफ से मुतलिफ स्टेट्स के अन्दर जो डेटेन्यूज़ की क्लासिफिकेशन है उस की डिटेलज़ जानने के लिए खतो-किताबित हो रही है और फैक्टस इक्ट्ठे किए जा रहे हैं इन सब को कन्सल्ट करने के बाद जो मज़ीद रियायत ज़रूरी समझी जाएगी दी जाएगी ।

CALL-ATTENTION NOTICES

(Serial No. 112)

Comrade Bhan Singh Bhaura M.L.A. : I beg to draw the attention of the Minister concerned to the matter regarding the brutal beating of a poor Harijan named Sucha Singh in village Chaprauda in Police Station Amargarh of district Sangrur by Shri Labh Singh and his son Rabinder Singh landlord of the said village on the 8th October, 1965. The only fault of Shri Sucha Singh was that he had purchased evacuee land under illegal possession of Shri Labh Singh on a bid conducted by the Government.

Sucha Singh could not move for three days from his house because of the strict guards of the Landlord. When he somehow managed to reach the Police Station Amargarh on 11th October, 1965 the Police did not care for the report of the Doctor.

It is reported that the Police registered this case under section 107/151, Cr. P. C. This case has created unrest in the ilaqa and terror among the Harijans and hence this Call-Attention.

Mr. Speaker: This is admitted. Government may make a statement.

Next Call-Attention Motion No. 113 by Shri Jagan Nath.

(*Shri Jagan Nath was not present in the House*).

Next Call-Attention Motion No. 114.

शिक्षा मन्त्री : इस संबंध में मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि आप अगर काल अटेन्शन्ज़ का नम्बर फिक्स कर दें कि एक दिन में सात या आठ काल-अटेन्शन्ज़ नोटिसज़ को लिया जाएगा और बाकी की नैकस्ट डे पर ली जाएंगी तो इस से हाउस का टाइम सेव होगा. . . . . . (विघ्न्)

(**Voices** : No. No.)

Education Minister : I do not say that the Call-Attention Motion which is of importance should be denied. I submit this because the

[Education Minister]

usual business of the House may not suffer as at present a lot of time is taken by the Call-Attention Motions. In Parliament and other State Legislatures this is the rule—a fixed number of Call-Attention Motions are admitted on a particular day and the remaining and over and above of those, which are worthy of admittance are moved on to the next day. This is my submission.

Mr. Speaker : This matter is already under the consideration of the Rules Committee. A decision has been taken and as soon as the rules are finalised that can be implemented.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਦੇਣ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਲ-ਅਟੈਨਸ਼ਨਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ ।

(Serial No. 114)

Sardar Ajaib Singh Sandhu : I beg to draw the attention of the Government to the acquisition of nearly two thousand cultivated evacuee land of village Fatehpur Bhagalan, tehsil Rupar, district Ambala by the Forest Department, Punjab, without giving any prior notice to the Harijan tenants who are tilling these lands for the last sixteen years.

As a result of this nearly thirty Harijan families who are refugees from Pakistan will be uprooted without any justification. The matter deserves immediate notice and action by the State Government. These lands should be transferred to these poor refugee Harijan tenants on nominal prices so that the whole village may not be uprooted. Hence this Call-Attention Notice.

Mr. Speaker : This is admitted. Government may make a statement.

Education Minister : Sir, the motion is not in order. What the hon. Member has said is that "two thousand cultivated evacuee land". It should have been "two thousand acres of cultivated evacuee land".

Sardar Ajaib Singh Sandhu : Sir, I am sorry it is due to mis-print.

(Serial No. 115)

Chaudhri Inder Singh Malik : I beg to draw the attention of the Government to the fact that the supply of water in Kamach Khera Minor, of Sunder Branch in tehsil Jind, district Sangrur, is very short, and due to that the villagers of Kamach Khera, Dorar and Malvi are suffering badly. Their standing kharif crops are withering and the sowing of Rabi crop is being delayed. The canal authorities have constructed an obstruction against the outlet of village Bamanwas and Dorar, which has caused shortage of water in the tail of Kamach Khera Minor. The poor Zamindars will be ruined if immediate steps of removing the obstruction are not taken.

It is, therefore, requested that full supply of water be restored in Kamach Khera Minor at the tail, to relieve the poor Zamindars from ruination.

Mr. Speaker : This is admitted. Government may make a statement.

(Serial No. 116)

Sardar Gurbakhsh Singh Gurdaspuri : I beg to draw the attention of the Minister concerned to the fact that a proper action should be taken immediately against the News papers like "Hind Samachar Daily" and "Pardeep Daily" and other persons concerned who are propagating communal hatred between various communities, lest other papers and leaders are forced to give a befitting reply to them and hence a danger to the breach of peace occurs.

Mr. Speaker : This is admitted. Government may make a statement.

STATEMENTS LAID ON THE TABLE

Shri Ram Partap Garg (Chief Parliamentary Secretary) : Sir, I beg to lay on the Table of the House Statements in reply to Call-Attention Motion :—

(1) No. 87 regarding prohibiting the use of milk for the preparation of cream and various kinds of sweets as well as the sale of these items; and

(2) No. 100 regarding shortage of Doctors in the Hospitals and Dispensaries in the State and the steps that the Government are taking to overcome it.

STATEMENT BY CAPTAIN RATTAN SINGH, MINISTER OF STATE FOR ANIMAL HUSBANDRY AND AGRICULTURE IN REPLY TO CALL-ATTENTION NOTICE (SERIAL NO. 87) BY SARDAR KULBIR SINGH, M. L. A.

It is necessary to explain in some detail the background to the orders issued by the Government on the 7th September, 1965, prohibiting the use of milk for the preparation of cream and various kinds of sweets as well as the sale of these items.

2. Immediately after the Pakistani attack across the International Border on the 1st September, 1965, we were approached by the Army Authorities for assistance in the procurement of milk for the Armed Forces. It is not possible for me, for reasons of security to mention the quantities involved except to say that they were of such a magnitude that we found ourselves utterly unable to meet the demand without taking recourse to special measures designed to secure the necessary supply without letting the prices go out of hand completely. It was considered that if no special steps were taken at that juncture not only would the Armed Forces have been unable to obtain the supplies needed by them but the price of milk in the market would also have reached a level which would have placed it beyond the reach of the ordinary consumer and dealt a heavy blow to civilian morale. It was felt that the only way of meeting the emergent situation was to place a curb on the use of milk for the manufacture of sweets and cream so that the milk released from these uses could be made available to the Armed Forces without in any way interfering with the supply of milk for civilian population.

3. While drawing up the order restricting the use of milk for non-essential purposes, care was taken to ensure that no unnecessary inconvenience was caused to the civilian consumer of milk and curds. Accordingly, the use of milk was prohibited for the production of cream, casein, skimmed milk, khoa, rubree, paneer and any kind of sweets in the preparation of which milk or any of its products except ghee may be an ingredient, and the sale of these items was also prohibited. However, the production of paneer by any person for his *bona fide* domestic purposes

[Chief Parliamentary Secretary]

was allowed as well as the production and sale of ice-cream, Kulfi or Kulfa in the preparation of which no khoa, rubree or cream is used. Provision was also made for permission to be given for the production of the prohibited items for the use of the Armed Forces.

4. Simultaneously with the promulgation of this order, the organised dairy interests in the State were invited to participate in meeting the requirements of Armed Forces and the House will be glad to know that these interests although located in the private sector, co-operated with us to the fullest possible extent and contributed significantly to the effort which we were able to make. This participation is still continuing and we must all appreciate the sacrifice which these concerns have made in partly giving up their normal production lines in order to come to the assistance of the Government at a critical moment.

5. The House will be glad to know that as a result of the measures described above, we were able to ensure the supply of a minimum amount of milk to the Armed Forces and that these supplies undoubtedly constituted a significant contribution to the Defence efforts made by this State. I would also like to mention that I have personally ascertained the needs of the Army in respect of milk and these continue to be much larger than the quantities which we can supply to them even under the existing arrangements. The House is aware of the situation in which we still find ourselves and it is unnecessary for me to say that the time has not come to relax any of our efforts. On the other hand, as far as this particular item is concerned, we are still far from meeting the needs of the Army and the Government intends to keep on doing everything possible to meet these needs without in any way jeopardising the interest of the civilian consumer.

6. It is no doubt true that the restrictions ordered by us have affected certain sections of the community which were concerned with the preparation of cream and sweets from milk. Detailed consultations were held with the respresentatives of these interests shortly after the cease-fire was announced. I am glad to say that as far as the Halwais are concerned, their Union has appreciated the position in which Government finds itself and agreed to substitute milk-based sweets by sweets of other kinds. The general public also, I am proud to say, displayed a very fine spirit in going without milk sweets even during Dussehra and Diwali. The House will be interested to know that as a result of the ban orders, the price of milk has gone down in almost all parts of the State and the quality of milk which is now available to the public has also improved because the supply of skimmed milk for purposes of adulteration is no longer available from creameries. The public has, by and large realised that these steps are for the good of the community and that the consumption of milk sweets was confined almost entirely to a class of people who were comparatively well fed and were not in as much need of milk protein as the ordinary consumer.

7. I will now come to the interests of the creamery owners whose point of view has been ventilated in the Call-Attention Motion. The representatives of the Creamery owners of the State waited on the Chief Minister on the 12th October, 1965, and represented that the ban on the preparation of cream had affected their livelihood. The Chief Minister gave the deputation a very patient hearing and desired that everything possible should be done to relieve their distress. It was, however, made clear by the Chief Minister that it would be impossible for Government to withdraw the ban order. Detailed talks were held with the deputationists by Secretary, Agriculture, and the Milk Commissioner. Thereafter, the deputationists met me in the presence of these officers and we had a very frank and free discussion with regard to their difficulties. The representatives of the creamery owners said that they were faced with the problem of disposing of milk which they were under contract to buy from producers and that there was no other source of livelihood to fall back upon. On behalf of the Government and in accordance with the wishes of the Chief Minister we offered to buy from each creamery owners all the milk which he had on his hands and that too at a special price which provided for a commission at a rate higher than the one which the Dairy Development Department normally offers to its suppliers of milk. The deputationists, however, after holding consultations among themselves said that they were not interested in selling milk to the Department. The only request which they had to make on that day was that sour milk should not be refused by the Government Milk Plant, Amritsar, but should be bought and paid for at a reasonable rate. The rate suggested by the deputationists was Rs 50 per quintal. This rate was accepted by me on behalf of the Government.

8. A further deputation of creamery owners called on me on the 18th October, 1965, under the leadership of Shri Balramji Dass Tandon. All the grievances of the creamery owners were gone into once again in detail in the presence of departmental officers, and after a very exhaustive discussion it was decided to provide the following concessions to the creamery owners who held licences in their own names on 7th September, 1965 and were prepared to sell milk to the Dairy Development Department in excess of the quantities if any which they were supplying to the Department before that date :—

(a) The supplier's commission for such milk would be Rs 4/- per quintal instead of the normal rate of Rs 2/- per quintal.

(b) The milk Commissioner would examine whether the margin allowed for transport charges of 60 Paisas per quintal was adequate. It was felt that if Government cannot arrange for the transport of milk at this rate through its own organisation, it should be prepared to suitably enhance it. The new rate would apply to all suppliers whether creamery owners or not.

(c) The special rate of commission mentioned at (a) above would apply to the creamery owners for a period of one year with effect from the date on which agreements are signed between them and the Milk Commissioner. While the agreements would be in the usual form, Minister for Animal Husbandry and Agriculture said that no penal action would be taken against any creamery owners if they fail to supply, during lean months, 60 per cent of the amount agreed upon in the contracts, provided that supplies did not go below 50 per cent in such quantities. This concession was in the nature of a gentleman's agreement and in consideration of the need to rehabilitate creamery owners.

(d) In the case of purchases at places where the purchase price of milk had not been announced by the Department already, the Department would fix the basic wholesale rates in accordance with market rates and in consultation with the local trade.

(e) The Department would undertake to collect milk from creamery owners wherever they were in business. New collection centres would be opened in this connection within one week of the receipt of information from creamery owners.

(f) The Department would not open any new collection centres for the direct collection of milk in the areas in which creamery owners have been operating.

9. It will be seen from the above account that while the Government had no option but to take the prohibitory action which it did, in the interests of Defence and the maintenance of civilian morale, it also tried to accommodate the affected interests as far as it could. I am as keenly aware as any other person of the hardship which the creamery owners have had to bear but I am also very firmly convinced that the action which we have taken is in the best interests of the community as a whole in the long run. This is so particularly in the case of the ban regarding the production of cream because the by-product of CREAM happens to be skimmed milk which as the House knows, is widely used as a substitute for water in the adulteration of pure milk.

10. Before concluding, I would like to remove the impression sought to be created by the Call-Attention Motion that the number of creamery owners affected is anything like 2½ lakhs. It has not been possible for me to collect the exact figures of licensed creamery owners but I will be surprised if their number is even 1 per cent of what has been claimed in the Call-Attention Motion.

11. Finally, I would like to inform the House that the measures taken by us in prohibiting the use of milk for non-essential purposes have been greatly appreciated by the Government of India who have, in fact, recommended to all other States that they should follow our example. I would accordingly suggest that nothing should be said or done in this House which might indicate any reversal of the steps we have taken and would appeal to all creamery owners to abide by the decisions taken in their meeting with me on the 18th October, 1965, and which decisions have since been approved by the Chief Minister. However, I shall be always prepared to consider any genuine difficulties which might be experienced in the implementation of these deceisions.

(Chief Parliamentary Secretary)

STATEMENT ON CALL-ATTENTION MOTION

(Serial No. 100)

There is no denying the fact that there is shortage of Doctors in the Hospitals and Dispensaries in the State and Government are taking every possible step to overcome this shortage.

2. The final professional LSMF examination takes place twice a year—Regular (annual) in the months of September/October and Supplementary in the months of May/June while admission to Condensed MBBS Course is conducted once a year. The programme for admission to Condensed MBBS Course is adjusted in such a way that instructions in Pathology etc. to Condensed MBBS students are given with the 3rd year regular MBBS students. Since, according to new regulations, the 2nd year regular MBBS students are now promoted to the 3rd year class in March, it has become imperative that admission to the Condensed MBBS Course be made during April each year. Keeping this thing in view, admission to the Condensed MBBS Course at Medical College, Patiala/Amritsar was made in May and June 1965, respectively. Six students each at these institutions were admitted in October, 1965, as a special case, and it was made clear to them that they will be able to take their examination in September, 1966 and not earlier. As the students have advanced much in their studies by now, it is not possible to admit more students to the Condensed MBBS course during the year 1965.

3. Almost all the candidates reported to be declared successful in the LSMF examination on 29th October, 1965, are bonded candidates. They had executed agreement bonds to serve the State Government in the rural areas for a period of 3 years after successful completion of LSMF course. In view of this and the fact that there is shortage of Doctors in the State, these Doctors should first serve the Punjab Government in accordance with the terms and conditions of their bonds. To the extent these bonded candidates join service in hospitals and dispensaries the shortage of doctors would to reduced. Moreover, it is also desirable that candidates joining the Condensed MBBS course should have done about a year's housejob which non of the persons who passed on 29th October, 1965, would have done.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਕਲ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਜੇ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ।

(ਵਿਘਨ)

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮੋਸ਼ਨ ਡਿਸਕਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਅਜੇ ਇਹ ਐਡਮਿਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ । (The hon. Member may have his say when this motion is discussed. It has not yet been admitted.)

THE PUNJAB GENERAL SALES TAX (AMENDMENT) BILL, 1965

(*Resumption of Consideration*).

Mr. Speaker : Now the House will resume discussion on the motion that the Punjab General Sales Tax (Amendment) Bill be taken into consideration at once. Comrade Shamsher Singh Josh who was in possession of the House when it adjourned yesterday, will resume his speech.

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : (ਰੋਪੜ) ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਲ ਸਦਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਠਿਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਕਰੀ ਟੈਕਸ ਬਿਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ । ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਚੀਫ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਏਥੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਮੈਂ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ

ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਕੁਝ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਨਕਦ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਇਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਇਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ । ਜੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਧਨ ਐਸੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਉਪਾਰੀ ਇਸ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸਕਣ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰੁਟੀਆਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਝ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਿਮਿਟ 50,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 30,000 ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਿਉਪਾਰੀ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਉਪਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕਾਨੋਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੈਟਰ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਡੀਮਾਰੇਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹਲਵਾਈ, ਬੇਕਰੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹਨ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਤ ਦਰ ਪੁਸ਼ਤ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ । ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰਖਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਗੇ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ।

ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮਹਿਕਮਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਅਫ਼ਸਰ, ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਆਮ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਦੂਸਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੀਸਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਬਦਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਕ ਇਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ 10-15 ਇਨਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਦਿਨ ਬਦਿਨ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਕ ਸੈਨਿਟਰੀ ਇਨਸਪੈਕਟਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਹਿਜ਼ 125 ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਈ. ਏ. ਐਸ. ਆਫ਼ੀਸਰਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਕ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਮੋਟੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਏ ਅਤੇ ਇਨਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਘਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣੇ ਹਨ । 1965-66 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਦਿਤੀਆਂ ਫ਼ਿਗਰਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਨਸਪੈਕਟਰਾਂ ਤੇ, ਜੋ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ 3,24,00,000 ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਧਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇਕੋ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲੀਸੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿੰਪਲੀਫ਼ਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੰਮਪਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਘਟ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਏਥੇ ਕਲ੍ਹ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ

[ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼]

ਟਰੇਡਰਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਬਹੁਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ 64,63,00,000 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਹਿਸਾ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 46,63,00,000 ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 6 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ 60% ਟੈਕਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 600 ਕਰੋੜ ਇੰਡਾਇ- ਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਜਟ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ 60% ਬਣਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮੇਜਰ ਇਨਕਮ ਲੈਂਡ ਰੈਵੇਨਿਊ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮਗਰ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਮੇਜਰ ਇਨਕਮ ਇੰਡਾਈਰੈਕਟ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਥੇ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਦਾ 40 ਕਰੋੜ 36 ਲੱਖ ਵਿਚੋਂ 17 ਕਰੋੜ ਆਮਦਨੀ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਇਨਕਮ 24-25 ਪਰਸੈਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਵੀ ਆਮਦਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਬਿਉਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਏਗਾ ਗ਼ਰੀਬ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਗ਼ਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਤੇ ਪਏਗਾ । ਔਰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਬਿਉਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। It is a big misnomer, ਇਹ ਟੈਕਸ ਪੜਦੇ ਦੇ ਪਿਛੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੇ ਟਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ। ਰੈਵੇਨਿਊ ਔਰ ਆਬਿਆਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫੈਮੀਲੀ ਜੇ ਸਾਲ ਵਿਚ 1,000 ਰੁਪੈ ਦਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 60 ਰੁਪਿਆ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਸਜੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਾਈਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਵਿਚ ਮੈਂ ਵੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗੀ । ਮਗਰ ਇਹ ਟੈਕਸ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਖੂਨ ਕਿਸਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਖੂਨ ਹੀ ਮੁਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸਤਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਲਗਾਉ ਕਿੰਨੇ ਬਿਰਲੇ ਤੇ, ਟਾਟੇ ਤੇ, ਦਾਲਮੀਆ ਤੇ, ਪੁਰੀ ਤੇ ਜਾਂ ਥਾਪਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਧਨਕੁਬੇਰ ਹਨ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕਈ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ । ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਰਲੇ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਵੇਲੇ 30 ਕਰੋੜ ਐਸਟਸ ਸਨ, ਹੁਣ 350 ਕਰੋੜ ਤਕ ਪੁਜ ਗਏ ਹਨ । ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ 90% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਨ ਕੁਬੇਰ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੇ ਹੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਡਾਲਦੀ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਰੂਰਲ ਜਾਂ ਅਰਬਨ, ਕਾਸਟ ਜਾਂ ਹਰੀਜਨ, ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦੇ ਔਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਥੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਟ

ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਾਂਗੇ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਦਲੇ ਔਰ ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਜੁੱਤੀ, ਘੜੀ, ਜਾਂ ਜੇਬਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾਏ ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਧਨਕੁਬੇਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਵੀ ਉਤਸਾਹਿਤ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ।

ਸਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਡੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਰਗੜਾ ਕਢਿਆ ਔਰ ਕਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਗਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਪੀਨੇਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਡਿਗਰੇਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ । ਬਲੈਕਗੀਪਾਂ ਨੂੰ ਫੜੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿਆਂਗੇ । ਅੰਤ ਵਿਚ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਡਾਈਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸ਼ੋਖ ਬਿਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਪਾਲੀਸੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ।

Mr. Speaker : S. Gurnam Singh.

श्री भागीरथ लाल : जनाब स्पीकर साहिब, मुझे टाइम नहीं मिला। मुझे भी मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। मैंने सरदार गुरनाम सिंह को बुला लिया है।

(The hon. Member may resume his seat. I have called upon Sardar Gurnam Singh to speak.)

श्री रूपलाल महता : तीन रोज से वक्त माँग रहा हूँ, लेकिन मुझे वक्त नहीं मिला।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ (ਰਾਏਕੋਟ) : ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ; ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫ਼ਾਈਨੈਂਸ ਮਨਿਸਟਰ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ । ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਧਨ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੇਯਰ ਹੋਵੇ, ਉਸਦੇ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਾ ਜਾਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਇਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ ਬਲਕਿ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਵੇ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ । ਇਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਦਿਆਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਔਰ ਐਗਜ਼ਕਟਿਵ ਦੀ ਸੈਪੇਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈਟਿਸਫ਼ੈਕਸ਼ਨ ਉਸਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਫ਼ਾਈਨੈਂਸ ਮਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਨਕਮਟੈਕਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁਆਸੀ ਜੂਡੀਸ਼ਰੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਦਾ ਹੈ ।

ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਅਪੀਲਾਂ ਜਾਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿਚ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਗਾ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਨੈਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਜੁਡਿਸਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਲਈ, ਔਰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਇਹ ਮੁਬਾਰਿਕਬਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸਵਾਸ਼ ਰਹੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜਾਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਉਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਣੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ ।

श्री यश पाल (जालंधर शहर, दक्षण पश्चिम) : स्पीकर साहिब, परसों से हम इस बिल पर बहस कर रहे हैं और इस से पहले भी इस पर काफी चर्चा चलती रही है। इस दौरान में मुझे फिनांस मिनिस्टर से कुछ बातें करने का मौका मिला और इस हाउस में उनका ज़िक्र करना चाहता हूं। उन्होंने जो ऐसी क्लाज़ें थीं जिन पर ज्यादा एतराज़ हो सकता था, उनका दूर करने में काफी फराखदिली का सबूत दिया। कल चीफ मिनिस्टर नें जो स्टेटमेंट दिया उस से उन सारी बातों की कन्फर्मेशन भी हो गई है, जो बातें पहले तय हो गई थीं। उन्होंने वे सब मानने का वायदा किया और हाउस को यकीन दिलाया कि अगर क्वेंटम के बारे में हाउस चाहेगा तो वह बढ़ाने के लिए तैयार होंगे। इसलिए मैं सरकार का शुक्रिया अदा करता हूं। इन बातों से इस सारे बिल की रूप रेखा काफ़ी बदल जाती है। लेकिन एक दो बातों की ओर मैं हाउस का ध्यान दिलाना चाहता हूं, स्पीकर साहिब, आप की मारफत। उनका ज़िक्र कल चीफ मिनिस्टर साहिब ने भी किया। उन्होंने कहा कि यह बिल हम इस लिए लाए हैं क्योंकि पिछली बार व्यापारियों ने कहा था कि जो फ़ैसले हो जाते हैं, उन्हें अमली जामा नहीं पहनाते। सरकार ने बिल तो पेश कर दिया लेकिन इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि जब यह बिल हाउस में लाया गया तो पूरी तरह पहले इस पर विचार नहीं किया गया। बिल पेश करने से पहले यह जरूरी था कि उनका ध्यान रखा जाता जिन के लिए यह बिल बनाया जा रहा है। अगर इन सब क्लाज़िज़ पर पूरी तरह बात कर ली जाती तो न इतना बावेला उठता, न इतना झंझट पड़ता और न व्यापारियों को हड़ताल करनी पड़ती, जो मैं आज कल के दिनों में वाजिब नहीं समझता। इस बिल का असल मतालबा दो बातों के लिए किया जा रहा है। पहली बात यह है कि टैक्स स्ट्रकचर इतना सिम्प्लीफाई और इतना आसान बना दें कि कहीं कम्प्लीकेशन पैदा न हो। दूसरा मतालबा व्यापारियों का यह है कि उनको इंस्पैक्टरों के शिकंजे से जितना बचाया जाए बचाएं। चीफ मिनिस्टर और दूसरे भाइयों ने कहा कि व्यापारियों ने तो अदादो शुमार रखने होते हैं, अलटीमेटली टैक्स का बोझ तो जनता ने बरदाश्त करना है। व्यापारियों का इस बात पर एतराज़ नहीं हो सकता क्योंकि यह बोझ लोगों पर ही पड़ता है। यह अलग बात है इसके लिए हम उनके मशकूर न हों कि वे बगैर कोई कमिशन लिए यह टैक्स इकट्ठा कर के देते हैं। जो रेविन्यू इकट्ठा करते हैं, उनको तो पंचोतरा देते हैं। व्यापारियों पर शक और शिकायत रहती है। व्यापारियों को शिकायत है कि इस बिल को जितनी क्लाज़िज़ हैं, वे उनको हिट करती हैं। जो तरीका है, उससे जितना रूपया इकट्ठा होता है, वह गवर्नमेंट के पास तो आता ही नहीं। जो गवर्नमेंट का अमला है, स्टाफ है, जो डाइरेक्टली डील करता है उनकी जेब में भी चला जाता है। उनकी दरखास्त यह है कि इस बिल में कुछ ऐसी तबदीलियां कर लें जिस से जितनी ताकतें इन्स्पैक्टरों के हाथ में हैं, वह न हों टैक्स जितना चाहो ले लो। उन्हें इस महकमें के कर्मचारियों के हाथों से ज़लील न होना पड़े। यह बिल कहां तक इस मकसद को पूरा करता है? फिनांस मिनिस्टर साहिब और गवर्नमेन्ट ठन्डे दिल से गौर करें, क्या इन्होंने व्योपारियों के मुतालबात को पूरा किया है। मैं मुख्तसर सी बातें कहूंगा। व्योपारियों को इन्स्पैक्टरों के

शिकन्जे में और कसा जा रहा है। मैं इस बिल को क्लाज़ बाइ क्लाज़ आप के सामने रखना चाहता हूं ।

Finance Minister : Can I make one submission ? My hon. friend, Shri Yash has started taking clause by clause of the Bill. As a matter of fact it is an amending Bill and he should discuss only the principle involved and not the clauses at this stage.

Shri Yash Paul : I am just explaining my point of view and with a view to establish that I was going to quote the clause(s) concerned.

Finance Minister : It would be better if the hon. Member makes these suggestions when we take up the clause by clause consideration of the Bill.

श्री अध्यक्ष : यश जी क्लाज़ बाइ क्लाज कह बैठे हैं । वह आइटम बाइ आइटम कह लें । (Shri Yash has stated "clause by clause". He should rather say "item by item".)

श्री यश पाल : मैं जो बात एस्टेबलिश करना चाहता हूं वह यह है कि इस बिल से इन्स्पैक्टरों के अख्तियारात बढ़ते हैं, कम नहीं होते। मैं अर्ज़ कर रहा था कि मैं इस बात पर ज्यादा ज़ोर नहीं देता जो क्वैंटम वाली बात है कि क्वैंटम कम होना चाहिए या ज्यादा । आमदनी के नुक्तानिगाह से अमली तौर पर इस से कोई ज्यादा फरक नहीं पड़ता । अब यह लिमिट 50,000 से 30,000 की जा रही है । इस से टैक्स की आमदनी बढ़ने वाली नहीं है । अब रजिस्टर्ड डीलर्ज़ की मारफ़त टैक्स अदा हो जाता है । फिर डायरैक्ट टैक्स मिलेगा । मेरी राय में इस क्वैंटम को बढ़ाना चाहिए बजाए इस के कि इन्स्पैक्टरों के शिकंजे में व्योपारियों को और कसा जाए। पहले सिरफ इस ज़द में वह व्योपारी आते थे जो 50 हज़ार तक के थे । अब लिमिट 30 हज़ार करने से उनकी तादाद बढ़ कर ज्यादा हो जाएगी । 40 हज़ार या 50 हज़ार और बढ़ जाएंगे । इस वक्त 56 हज़ार व्योपारी हैं जो रजिस्टर्ड डीलर्ज़ हैं, अगर यह लिमिट 30 हज़ार कर दें तो उनकी तादाद 1 लाख के करीब हो जाएगी । सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक उनकी तादाद 14 हज़ार बढ़ती है । मेरा अंदाजा है कि उनकी कुल तादाद 1 लाख के करीब हो जाएगी । गवर्नमेंट कहती है कि 14 हजार या 15 हज़ार ही बढ़ेगी । चलो मान लीजिए कि 14 हज़ार या 15 हज़ार ही बढ़ी तो इतने व्योपारियों पर इन्स्पैक्टरों का शिकंजा और कसा जाएगा । जो डीलर अपने आपको रजिस्टर करवाता है, उसकी फ़ीस 5 रूपये है । इस महकमा का कोई कर्मचारी, कोई अफ़सर, इस पंजाब का कोई जानकार इन्सान यह नहीं कह सकता कि 5 रूपये में रजिस्टरी हो जाती है । उसको रजिस्ट्रेशन सरटीफिकेट लेने के लिए 200 या अढ़ाई सौ रूपया खर्च करना पड़ता है । सरकार को 5 रूपये मिलते हैं और बाकी पैसे और लोग ले जाते हैं । इन्स्पैक्टरों के अख्तियारात कम करने चाहिएं । ऐसे हालात पैदा करें कि ऐसे कम लोग इन्स्पैक्टरों की ज़द में आएं। इसी तरह से एक और प्रोवीज़न इस अमैंडिंग बिल में है। सरकार या सरकारी कर्मचारी किसी ट्रक को रोक सकते हैं। उस ट्रक को रोकने के बाद उसके माल को खुलवा सकते हैं । पेटी को तुड़वा सकते

[श्री यश पाल]

हैं और ट्रंक का ताला तुड़वा सकते हैं। जिस तरीका से चाहें उसकी तलाशी ले सकते हैं। ठीक है अगर सरकार को शक पड़े या सरकारी कर्मचारी को शक पड़े कि चोरी हो रही है और माल नाजायज तौर पर लाया जा रहा है तो वह डायरैक्टली इस बात को रोक सकता हैं।

(इस समय श्री राम सरन चन्द मित्तल ने कुर्सी संभाली)

चेयरमैन साहिब, करनाल में पिपली का एक बैरियर था उसे हटा दिया गया है। जब कोई ट्रक माल ले कर आता था तो उसे चैक किया जाता था कि वह माल ज्यादा तो नहीं लादा हुआ। जो ट्रक वाला वहां मौका पर सरकारी कर्मचारी को मुकर्ररा रकम दे देता था उसका ट्रक पास हो जाता था और जो नहीं देता था, उसे परेशान किया जाता था। यह लोग उसके ट्रक की तलाशी लेते थे और उसे झंझट में डालते थे। इस लिये सरदार प्रताप सिंह ने पिपली का बैरियर तोड़ दिया। उस बैरियर के तोड़ने से फायदा हुआ, नुकसान नहीं हुआ, उनको नुकसान हुआ जो यह कोशिश करते थे कि ज्यादा से ज्यादा रुपया नाजायज़ तरीका से ट्रक वालों से लिया जाए। और ऐसे लोग वहाँ बैरियर पर लगने की कोशिश करते थे। तो इस क्लाज़ के कारण से यह होगा कि जो 10 रुपये दे देगा उसके माल को नहीं खोला जाएगा। जो नहीं देगा, उसका ट्रक वहीं कैद रहेगा। जो दे देगा वह निकल जाएगा। कल चीफ मिनिस्टर और फिनांस मिनिस्टर ने कुछ रियायतें देने का एलान किया। मैंने उनका शुक्रिया भी अदा किया। उन्होंने मान लिया कि कैश-मीमो की लिमिट 3 रुपये बढ़ा कर 10 रुपए कर देंगे। इससे थोड़ा फर्क पड़ जाएगा लेकिन यह इस कैश मीमो से तो इन्स्पैक्टरों के अख्तियारात में इज़ाफा करते हैं। लिमिट 10 रुपए की होगी तो अगर दुकानदार 9 रुपए का कैश मीमो नहीं काटेगा तो इन्स्पैक्टर एतराज़ करेगा कि तुम ने 10 रुपए से ज्यादा की चीज़ बेच कर कैश मीमो से बचने की कोशिश की है तो दुकानदार कहेगा कि अच्छा जो तुम ने लेना है वह ले लो और मुझे अपना काम करने दो। इस बात से कौन इन्कार कर सकता है कि इन्स्पैक्टरों ने अपनी अपनी सलतनतें

11-00 a.m.

कायम कर रखी हैं और वहां से बाकायदा जज़िया वसूल करते हैं। जो नहीं देता उसे तंग करते हैं, उसके खिलाफ बत्तीस किस्म की कार्यवाहियां करते हैं और जो चुप चाप दे देता है उसे कोई नहीं पूछता। ज़रूरत इस बात की थी कि इन सलतनतों को खत्म किया जाता और इन्स्पैक्टरों के असीम अख्तियारात को कम करते और ऐसा माहौल पैदा करते कि जिस से टैक्स भी ज्यादा से ज्यादा मिले और कुरप्शन भी कम से कम हो लेकिन सरकार ने उनको और वसीह अख्तियारात दे दिए। फिर एक और क्लाज़ 7(1) रखी है जिसमें "रजिस्टर्ड डीलर" की जगह सिर्फ "डीलर" कर दिया। पहले यह था कि इन्सपैक्टर सिर्फ रजिस्टर्ड डीलर से डील करते थे लेकिन अब जो संशोधन किया जा रहा है और उसका मतलब है कि कोई रजिस्टर्ड है या नहीं, वह इन्स्पैक्टर की ज़द में आ गया। मैं मानता हूं कि इनकी तरफ से एक माकूल दलील यह हो सकती है कि ऐसे कारोबारियों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए जिनका क्वैंटम तो पूरा हो गया लेकिन उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई।

ठीक है ऐसे आदमी के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए, मैं इस बात से इन्कार नहीं करता, लेकिन आप भी इस बात से इन्कार नहीं कर सकते कि इस क्लाज़ का दुरुपयोग हो सकता है क्योंकि इससे अब ज्यादा लोग इन्स्पैक्टरों की ज़द में आ जाएंगे। इसी तरह यह क्लाज़ 7(2) है और इस में आप ने कर दिया है ......

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ । ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਨਾਂਸ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਤੇ ਉਠੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਕਲਾਜ਼ ਬਾਈ ਕਲਾਜ਼ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ । ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਜ਼ 7 (1) ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਨਰਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਕਲਾਜ਼ ਬਾਈ ਕਲਾਜ਼ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

Shri Mohan Lal : Sir, I would like to speak on this issue because it has been raised time and again by some Members and even by some of the Ministers.

The general principles of the Bill can be discussed even by making reference to particular clause at this stage. What the hon. Member is doing is that he is putting before you a point that through this Bill the Government is strengthening the hands of the Inspectorate and for that purpose he is giving illustrations of different clauses of the Bill. This can, undoubtedly, be done at the time when we are discussing the principles of the Bill. The hon. Member is discussing the principles of the Bill and in support of his points he is just citing different clauses of the Bill. Mr. Chairman, there is no bar to the making of a reference to the clauses of the Bill for the purposes of illustrating certain principles.

ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ : ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਐਕਟ ਜੋ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਮੇਨ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਇਕ ਅਮੈਂਡਿੰਗ ਬਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਕੋਪ ਬੜਾ ਲਿਮਿਟਡ ਹੈ ਅਤੇ ਈਵੇਯਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੈ । ਉਹ ਦਸਣ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਈਵੇਯਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ । ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਕਲਾਜ਼ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲਡ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਕਲਾਜ਼ ਬਾਈ ਕਲਾਜ਼ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਐਟ ਰੈਂਡਮ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਾਜ਼ ਬਾਈ ਕਲਾਜ਼ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਬਾਨ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਕ ਹੈ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੀਪੀਟ ਹੋਣਗੀਆਂ । ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਹੁਣ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਕਲਾਜ਼ ਬਾਈ ਕਲਾਜ਼ ਵੇਲੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਨ ਡਿਟੇਲ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ।

श्री चेयरमैन : यह ठीक बात है कि इस स्टेज पर जनरल प्रिंसीपलज़ आफ दी बिल ही डिसकस हो सकते हैं लेकिन सवाल पैदा होता है कि आया जिस तरह यश जी कर रहे हैं उस तरह बिल के प्रिंसीपल डिसकस करते वक्त किसी पर्टीकूलर क्लाज का रैफरैंस दे सकते हैं या नहीं। इस संबंध में मैं सदन की इत्तलाह के

[श्री चेयरमैन[

लिए यह रूल पढ़ देता हूं जिसमें यह बात साफ है । (This is correct that at this stage only the principles of the Bill and its general provisions can be discussed. But the question that arises, is whether or not any reference can be made to a particular clause while discussing the principles of the Bill. In this connection I would like to read out for the information of the House, the relevant rule which clearly lays down—

> 132 (1). On the day on which any of the motions referred to in Rule 130 is made or on any subsequent day to which the discussion thereof is postponed, the principle of the Bill and its general provisions may be discussed but the details of the Bill shall not be discussed further than is necessary to explain its principles".

इस में यह साफ है कि अगर बिल के प्रिंसीपलज़ को ऐक्सपलेन करने के लिए और एलूसीडेट करने के लिए किसी कलाज़ को रैफर करने की जरूरत पड़े तो उसकी रैफरैंस दी जा सकती है । क्लाज बाई क्लाज़ डिसकशन पर तो यही हो सकता है कि किसी पर्टीकुलर क्लाज में क्या तरमीम होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए इस पर बहस हो सकती है । यह ठीक है कि पहली स्टेज पर डिटेल्ड डिसकशन किसी कलाज़ के बारे नहीं हो सकती लेकिन उस की रेफ़रैंस दी जा सकती है और उसकी रैफरेंस दे कर बिल के प्रिंसीपल को डिसकस किया जा सकता है । इस अमैंडिंग बिल में कई बेसिक प्रिंसीपलज़ इन्वाल्वड हैं जैसा कि कैश मीमो, रजिस्ट्रेशन वगैरा वगैरा । तो वह इन प्रिंसीपलज़ को रेलेवैंट कलाज़ों की रेफरैंस देकर डिसकस कर सकते हैं । (It is quite obvious that if with a view to explain and elucidate the principles of the Bill, reference to a particular clause is necessary, then that is admissible. Under clause by clause consideration only this can be discussed as to what amendment or otherwise should be made in a particular clause. Of course this is right that at the first stage of the Bill no detailed discussion of a clause can be allowed. Only a reference can be made to it, and by doing so, the principle of the Bill can be discussed. As regards this Amending Bill certain basic principles concerning the Cash Memos, registration etc., are involved and these can be discussed by making reference to the relevant clauses.

श्री यश पाल:–चेयरमैन साहिब, मैं आपका मशकूर हूं कि आपने मेरी बात को दरुसत करार दिया है । मैं किसी क्लाज़ को इन डिटेल डिसकस नहीं कर रहा हूं, सिर्फ उसकी रैफरैंस ही देता हूं । एक कलाज शायद 10 (1) सिकियोरिटी के

बारे में है जो कि पहले नहीं ली जाती थी । अब इनकी यह दलील हो सकती है कि जब कोई आदमी रजिस्ट्रेशन के लिए आए और सर्टिफिकेट लेने आए और शक हो जाए कि कहीं वह गवर्नमैंट का रूपया ले कर भाग न जाए और ऐसी कई एक मिसालें हुई भी हैं तो उससे सिकियोरिटी लेना ज़रूरी है । दरुसत बात है । जहां तक मुझे इल्म है इस महकमा के लोग पहले भी अपना डिसक्रीशन इस्तेमाल करके बगैर अख्तियार के सिकियोरिटी लेते रहे हैं । लेकिन अब आप बाकायदा उस अख्तियार को वसीह कर रहे हैं और अब हर किसी पर उनका शक हो सकता है । जिस से नाराज़ हुए या जहाँ कोई और मनशा हुआ और उसे कहेगा कि सिकियोरिटी दो । फिर ताजुब की बात है कि इस सिकियोरिटी की ऐक्सपलानेशन कोई नहीं दी गई है । चीफ मिनिस्टर साहिब ने कल कहा था कि परसनल सिकियोरिटी होगी लेकिन इस बिल में तो कोई ऐसी बात का जिकर नहीं कि परसनल होगी, कैश होगी या प्रापर्टी की होगी या और होगी । मैं यह रैफरैंस इस लिए दे रहा हूं कि मनशा यह था कि इस बिल के ज़रिये इन्स्पैक्टोरेट के अख्तियारात को कम करके कुरप्शन को कम करें लेकिन इस बिल में कई कलाज़ें ऐसी ऐड कर दी गई हैं जिन से हैं कि कुरप्शन घटेगी नहीं और बढ़ेगी । फिर जो इवेज़न को रोकने का मकसद है वह भी इस से पूरा होता नजर नहीं आता है । किसी को इस बात से इंकार नहीं हो सकता कि कोई टैक्स न लगें। टैक्स लगाने और लेने पड़ते हैं और इनके बगैर पैसा नहीं आता और सरकारी काम नहीं चल पाता । खास तौर पर आजकल लड़ाई के वक्त और जो डिवैलपमैंट के काम हो रहे हैं उनके लिए रुपया चाहिए । लेकिन यह टैकस की इवेज़न महिज़ कलाजें रख देने से ही नहीं रुकती बलिक इस सारे स्ट्रकचर को तबदील करने से रुकेगी । जब यह सरकार नई नई बनी थी तो इनकी तरफ से दो तीन ऐलानात किए गए थे कि इस टैकस स्ट्रकचर को सिम्पलीफाई करने के लिए कदम उठाएंगें । फिर कहा गया कि इन्स्पैक्टोरेट को रैशनेलाइज किया जाएगा । उसके लिए कमेटी तो जरूर बना दी गई लेकिन अमली कदम अभी तक कोई नहीं उठाया गया है ।

यहां पर कल भी ज़िकर हुआ था कि सेल्ज़ टैक्स के कुलैक्ट करने में सिम्पलीफिकेशन होनी चाहिए । सरकार कुछ चीज़ों पर टैक्स फर्स्ट स्टेज पर लाना चाहती है । सरकार ने इस असूल को मान लिया है । यह उच्छी बात है । इस के लिए मैं सरकार को मुबारकबाद देना चाहता हूं लेकिन इस बिल में कुछ ऐसी बातें लिखी गई हैं जिस से सिम्पलीफिकेशन के बारे में झगड़ा खड़ा हो गया है । इस में यह लिखा है कि—

"Provided that no sale of such goods at a subsequent stage shall be exempted from tax under this Act unless the dealer effecting the sale at such subsequent stage furnishes to the assessing authority in the prescribed form and manner a certificate duly filled in and signed by the registered dealer from whom the goods were purchased."

ऐसा करने से कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं होती बल्कि एक नया झंजट शुरू हो जाता है । सरकार ने कुछ ही चीज़ों पर फर्स्ट स्टेज पर टैक्स लगाने

[श्री यश पाल]

का फैसला किया है। अगर सरकार ने केवल 5,10 चीज़ों पर फर्स्ट स्टेज पर टैक्स लगा भी लिया तो उस से न तो व्यापारियों को ही तथा न ही सरकार को कोई खास फायदा होगा। सरकार को चाहिए था कि ज्यादा से ज्यादा चीज़ों पर फर्स्ट स्टेज पर ही टैक्स लगाती ताकि यह नया झंजट पैदा न होता। व्यापारी और दुकानदार 100 किस्म की चीजें अपने पास रखता है और सरकार ने उन में से कुछ ही चीजों पर फर्स्ट स्टेज पर टैक्स लगा ही दिया तो उन कुछ चीजों को छोड़ कर बाकी चीजों का हिसाब रखना बहुत ही ज़रूरी होगा और उसे टैक्स देना पड़ेगा। इस असूल को लागू करने के लिए यह जरूरी है कि हमारी सरकार सैंट्रल गवर्नमैंट और एडज्वर्णनिग स्टेट्स के साथ मिल कर कोई इफैक्टिव कदम उठाए ताकि यहाँ के व्यापारियों को किसी तरह की शिकायत न रहे और गलतफहमी भी दूर हो जाए। यह सरकार डेढ़ साल से एलान करती आ रही है कि हम लोगों को यह सहूलतें देंगे लेकिन सरकार उन ऐलानों को अभी तक अमल में नहीं ला सकी। मैं फिर अर्ज़ करना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने 5,10 चीज़ों पर फर्स्ट स्टेज पर टैक्स लगा भी दिया तो उस से न व्यापारियों को और न ही सरकार को कोई खास लाभ होगा। सरकार को मजमूई चीज़ों पर ही फर्स्ट स्टेज पर टैक्स लगाना चाहिए ताकि दुकानदारों को कोई फायदा हो सके।

चेयरमैन साहिब, मैं सेल्ज़ टैक्स की सिम्लीफिकेशन के बारे में अर्ज़ करना चाहता हूं। इस बिल में बुनियादी बातों को बिलकुल इग्नोर कर दिया गया है। व्यापारियों की सब से बड़ी मांग है कि एसैसिंग अथार्टी और ऐपीलेट अथारिटी अलहदा अलहदा होनी चाहिए। इन दोनों को डायरैक्टली या इंडायरैक्टली आपस में कोइ ताल्लुक नहीं होना चाहिए। हमारे चीफ मिनिस्टर ने व्यापारियों के साथ अगस्त, 1965 में वायदा भी किया था कि व्यापारियों की तकलीफ को दूर करने के लिए कोई न कोई कदम उठाया जाएगा। व्यापारियों ने चीफ मिनिस्टर की कोठी पर धरना मारा था। वहां पर चीफ मिनिस्टर ने वायदा किया था। व्यापारियों ने इस आश्वासन पर अपना धरना भी छोड़ दिया था। सरकार ने इस महकमा के दो अफसर असैसिंग के लिए और अपील करने के लिए अलग अलग बना दिए हैं। इस से मसला हल नहीं हुआ क्योंकि यह दोनों अफसर एक ही डिपार्टमैंट के हैं। इन का एक ही बड़ा अफसर है और एक ही वज़ीर हैं। छोटे अफसरों ने बड़े अफसरों के कहने के मुताबिक ही काम करना है। वह बड़े अफसरों के कहने पर दुकानदारों को तंग कर सकते हैं। इस से यह मकसद हल नहीं होता। जो अपीलें सुनेगा उस से क्या नतीजा निकलेगा ? मैं समझता हूं कि दुकानदारों को इन्साफ नहीं मिल सकेगा। यह ढांचा गलत सा बन जाता है। व्यापारी टैक्स देने से इन्कार नहीं करते। मैं मानता हूं कि इस बिल से व्यापारियों के शिकंजे ढीले नहीं होते। इस से यह मसला हल नहीं होगा। लोगों को परेशानियां होंगी। अगर आप ने इस बिल में एमेंडमेंट्स करनी ही थी तो सरकार को चाहिए था कि सरकार व्यापारियों को अपने पास

बुलाती, उन से बातचीत करती । मैं समझता हूं कि व्यापारी टैक्स देने के लिए तैयार हैं । अगर वह टैक्स देने के लिए तैयार नहीं होते तो सरकार उन के साथ बातचीत बेशक न करती, जब वह टैक्स देने के लिए तैयार हैं तो उन को बुला कर सब पहलुओं पर बातचीत करती । उन की मांगों को सुनती और उन की तकलीफों को दूर करने की कोशिश करती । लेकिन सरकार ने उन को विश्वास में नहीं लिया । उन से बातचीत किए बगैर यह बिल हाउस में पेश कर दिया अगर अब वह सैटिसफाइड नहीं है तो वह क्या करें। में अर्ज़ करना चाहता हूं कि वह सरकार के साथ बात चीत करने के लिए तैयार हैं । सरकार उन के साथ बातचीत करें और उन की गलतफहमियों को दूर करे । उन की जो तकलीफें अनसैटल्ड रह गई हैं, उन तकलीफों को दूर करने की कोशिश करे ।

चेयरमैन साहिब, इस बिल के द्वारा दूकानदारों को कुछ गलतफहमी हो गई है । सरकार ने एलान किया कि टैक्सों के यूनीफार्म रेट्स फिक्स करेगी । यह तभी हो सकता है जब पंजाब, दिल्ली, राजस्थान और यू० पी० आदि स्टेट्स इकट्ठे हो कर सोचें । पता नहीं कि अब सरकार इस बारे में क्या करना चाहती है । अगर सरकार इस बारे में कुछ कदम उठाना चाहती है तो इस बात का बिल में कहीं ना कहीं ज़िक्र करना चाहिए था । सरकार को हाउस में एशोरेंस देनी चाहिए कि दुकानदारों को कुछ न कुछ यूनीफार्म रेट के बारे में सहूलत देंगे । इस लिए फिनांस मिनिस्टर को हाउस में एशोरेंस लाज़मी देनी चाहिए कि इस में कोई वेरिएशन नहीं होगी । कई स्टेट्स में 2 प्रतिशत टैक्स लिया जाता है और कई स्टेट्स में 4 और 5 प्रतिशत टैक्स लिया जाता है लेकिन हमारी स्टेट में 6 प्रतिशत टैक्स वसूल किया जाता है । इस लिए ज़रूरत इस बात की है कि इस बारे में यूनिफार्म रेट्स होने चाहिए । मैं मानता हूं कि ज्यादा टैक्स होने से पंजाब सरकार के रैवेन्यू में इजाफा तो जरूर होगा और पंजाब में डिवैल्पमेंट भी होगी लेकिन अगर एक जैसे रेट्स हों तो लोगों की हैरासमेंट दूर हो जाएगी ।

चेयरमैन साहिब, मैं ढाबों और तंदूरों के बारे में भी जिकर करना चाहता हूं । सरकार ने इस के लिए 25 हजार रुपए की हद बांध दी है । लेकिन इस बिल में भी ढाबों और तंदूरों की कोई डैफीनीशन नहीं दी । इस से इन के मालिकों के दिलों में गलतफ़हमी जरूर पड़ गई है । इस लिए सरकार को इस बात को ज़रूर डिफाइन करना चाहिए कि ढाबा, तंदूर और रैस्टोरेंट्स की यह डैफीनीशंज हैं । इन के बारे में मैं अर्ज करना चाहता हूं कि वहां पर गरीब लोग, किसान और मज़दूर खाना खाते हैं, यह तो असल में उन गरीबों पर टैक्स होगा जो कि सरकार के लिए अच्छी बात नहीं है । मैं समझता हूं कि इस के बारे में सरकार का इन को हैरास करने का इरादा नहीं है। इस की ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए ।

[श्री यश पाल]

चेयरमैन साहिब, मैं हलवाइयों के बारे में भी अर्ज़ करना चाहता हूं । इस बिल में इन का ज़िक्र आ जाने से मुझे ही नहीं, हलवाइयों को नहीं बल्कि इंस्पैक्टरों को भी गलतफहमी हो गई । यहां तक कि इस के बारे में जो माहरीन हैं, उन को भी गलत फहमी हो गई थी । हलवाइयों के पास इंस्पैकटर्ज़ पहुंच गए और उन्होंने हलवाइयों से पिछले हिसाब किताब के बारे में पूछना शुरू कर दिया । हलवाइयों के हां अच्छी २ चीज़ें मिलती हैं, इस लिए वहां पर इंस्पैक्टरों को पहुंचना ज़रूरी था क्योंकि इस के बारे में ठीक तरह से व्याख्या नहीं की गई थी । इस लिए मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस चीज़ को बिलकुल क्लियर कर दे ताकि उन के दिलों से गलतफहमी दूर हो जाए । मैं तो इस बात का इच्छुक हूं कि इन ढाबों, तंदूरों होटलों और हलवाइयों पर किसी प्रकार की रिस्ट्रिक्शन्ज नहीं लगाई जानी चाहिएं, ताकि वह सरकार के मश्कूर हों । यहां पर गरीब जनता खाना खाती है । अगर टैक्स वसूल किया गया तो यह इनडायरैक्टली गरीब लोगों पर टैक्स लगेगा । लोग इस टैक्स को पसंद नहीं करेंगे ।

चैयरमैन साहिब, मैं डिपो होल्डरों के बारे में अर्ज़ करना चाहता हुं । यह वह डिपो होल्डर्ज़ हैं, जो कि सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए हैं । वहां पर 50 हज़ार से अधिक सेल हो जाती है । वह पहले ही टैक्स पे करते हैं । इसलि उन से दोबारा टैक्स वसूल करने की कोई गुंजाइश नहीं होती । उन को तो आटे में सिर्फ फी किलो एक पैसा बचता है और शूगर में तो इस से भी कम ही बचता होगा । लेकिन उस की सेल 50 हज़ार से ज्यादा हो सकती है । जब उस की सेल इतने से बढ़ जाएगी तो इंस्पैक्टर कहेगा कि वह अपने डिपो को रजिस्टर कराए। उसे माल में एक पैसा फी किल्लो बचता है लेकिन उसे कहा जाएगा कि वह 6 प्रतिशत के हिसाब से सेल्ज़ टैक्स पे करे तो बेचारा कहां से पे करेगा यह बात मेरी समझ में नहीं आई । इस लिए सरकार को यह बात क्लीयर करनी चाहिए । (घंटी)

चेयरमैन साहिब, मैं बेकरियों के बारे में अर्ज़ करना चाहता हूं । उन को भी कुछ गलतफहमी हो गई है, उन को भी संतुष्ट किया जाए और सरकार अपनी पालीसी क्लियर करे । शिडूल्ज़ के अन्दर चिल्लीज़ और फूडग्रेन्ज पर भी टैक्स लगाने के बारे में लिखा है । मैं समझता हूं कि सरकार इन पर ज्यादा टैक्स लगा कर जनता को तंग नहीं करना चाहती है । इस लिए इस पर सरकार अपनी पालीसी क्लियर करे । एक तो इंस्पैक्टरों को कम से कम अख्तियार होने चाहिए । दूसरे इस में सिम्पलीफिकेशन की जाए ताकि लोग संतुष्ट हो सकें । इस समय लोगों के अन्दर अनरैस्ट पैदा नहीं करनी चाहिए । इस वक्त पंजाब में हालात ठीक नहीं हैं, विशेषकर पंजाब के बार्डर ज़िलों में स्थिति नार्मल नहीं है। मैं तो सारे पंजाब की स्थिति नार्मल नहीं समझता । इस वक्त हमें कोशिश करनी चाहिए कि लोगों को टैक्सों में रिलीफ दिया जाए ।

उन को ज्यादा से ज्यादा सहूलतें दी जाएं लेकिन पता नहीं है कि क्या सोच समझ कर हर रोज़ यहां पर ऐसे मैयर्ज़ लाए जाते हैं जिन से लोगों की परेशानी और बढ़ती है । मैं टैक्स के खिलाफ नहीं हूं, टैक्स लगने ही चाहिए मैं बार बार कहता हूं और स्पोर्ट भी करता हूं लेकिन वक्त देखना बड़ा ज़रूरी है । यहाँ पर तो लोग यह महसूस करने लगे हैं कि जिन्हों ने वार फरंट पर काम किया है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है उन को ज्यादा से ज्यादा पीनलाईज़ किया जा रहा है, सज़ा दी जा रही है । पिछले दिनों ट्रक्कों का बिल पास हुआ था । टैक्स बढ़ा दिया, गया सारा हाउस परेशान होता रहा लेकिन सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया । यह ठीक है कि संशोधन करके बिल में कुछ ढील कर दी है लेकिन पिछले पांच सात दिन तक तो पंजाब में तूफ़ान उठा रहा । अब कमर्शियल क्राप्स पर टैक्स लगा रहे हैं । मैं टैक्स के खिलाफ नहीं हूं मैं टैक्सों को स्पोर्ट करता हूं लेकिन इन को लगाने का वक्त होता है, तरीका होता है, ढंग होता, सलीका होता है, अगर आप उस तरीके को और ढंग को नज़र अंदाज़ करते चले जाएंगे तो फिर ठीक है, लोग बगावत करने के मूड में तो नहीं हैं टैक्स तो देंगे लेकिन मेरी प्रार्थना है कि टैक्स लगाने के लिए वक्त ज़रूर देखिए कि लोगों को कुछ सहूलत मिलती है या नहीं, तरीका कुछ सिम्पलीफाई होता है कि नहीं अगर वैसे ही लगाते चले जाएंगे तो कुछ खुशगवार असर नहीं होगा । मैं फिर फ़िनांस मिनिस्टर साहिब का मश्कूर हूं कि उन्होंने काफी अकम्मोडेट किया है लेकिन उन से प्रार्थना करूंगा, जैसे मैं ने पहले भी अर्ज़ किया है, क्वांटम और कैश मीमो वाली बातों का ख्याल रखें। जिन लोगों का शिकंजा कसा है उन को कुछ ढील भी दी जाए ताकि उन की परेशनी दूर हो ।

श्री सीता राम बागला (सिरसा) : चैयरमैन साहिब, आप का मश्कूर हूं कि आप ने मुझे बोलने का समय दिया है । बहुत दिनों से यह शोर था कि पंजाब सरकार नया बिल इस लिये ला रही है कि पंजाब में, राजस्थान में और हिमाचल प्रदेश में यूनीफार्म रेट कर दिया जाएगा और प्रोसीजर सिम्पलीफाई हो जाएगा । बहुत दिनों से यह बात सुन रहे थे कि सरकार इस अमैंडमैंट द्वारा लोगों को कुछ रियायत देगी, व्यापारियों को हैरेसमैंट कम हुआ करेगी उन को रियायतें दी जाएंगी। लेकिन इस बिल को देख कर हमें बहुत मायूसी हुई । एक तरफ तो सरकार यह कहती है कि यह बिल व्यापारियों की खातर लाया गया है और दूसरी तरफ यह कहती है कि पहली सरकार का ड्राफटिंग तैयार हुआ हुआ था उसी के मुताबिक हम ने कर दिया है। हमारे मुख्य मन्त्री साहिब ने कल कुछ वायदे भी किये और कुछ सिम्पलीफिकेशन भी कर दी । लेकिन मैं फिर भी आप के द्वारा सरकार से कहना चाहता हूं कि ऐसे कानून बना कर अफसरों को इतने वसीह अख्तियारात दे कर आप व्यापारियों की इज्ज़त को सेफ नहीं रख सकते । इस लिमिट के घटाने से सरकार को कुछ फायदा पहुंचने वाला नहीं है । जब आप के इंस्पेक्टर साहिबान पचास हज़ार वालों का अकाउंट ही चैक नहीं कर सकते, कम्पेयर नहीं कर सकते तो जब आप लिमिट को घटा कर तीस हज़ार कर देंगे तो उस से काम दुगुना

[श्री सीता राम बागला]

हो जाएगा, वह कैसे चैक करेंगे । इस से तो फायदा कम होगा नुकसान ही होगा । इवेज़न और कुरप्शन बढ़ेगी । मैं आप के द्वारा फिनांस मिनिस्टर साहिब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि इस बिल को कुछ दिनों के लिये मुल्तवी कर देना चाहिये । इस के लिये एक कमेटी बनाई जानी चाहिये और व्यापारियों के साथ बैठ कर बाकायदा सलाह मश्वरा कर के इस का हल सोचना चाहिये । तीस हज़ार और पचास हज़ार का कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, तीस हज़ार वालों को भी टैक्स देना पड़ता है, उन को वापस तो नहीं कर रहे । लेकिन जैसे अकाऊंट वगैरह को इंस्पैक्टर लोग चैक करेंगे तो कुरप्शन बढ़ेगी । तीस हज़ार और पचास हज़ार के अकाऊंटस को वे लोग आपस में चैक नहीं कर सकते, कम्पेयर नहीं कर सकते । मैं समझता हूं कि इस से और खाते बढ़ते जाएंगे और आप को इस डिपार्टमैंट से डबल डिपार्टमैंट रखना पड़ेगा । अगर आप ने अपना डिपार्टमैंट दुगुना ही करना है तो बेशक यह बिल पास करवा दें । लेकिन इस से काम चलने वाला नहीं है ।

अगर आप ने इसी डिपार्टमैंट से काम लेना है तो मैं सरदार कपूर सिंह जी से अर्ज़ करूंगा कि इस से काम नहीं चलेगा । एक तरफ तो आप कहते हैं कि व्यापारियों को रिलीफ देने के लिये यह बिल लाया गया है और दूसरी तरफ कहते हैं कि व्योपारियों को राज़ी करने के लिये ऐसा कर रहे हैं । व्यापारी लोग बहुत दुखी हैं । टैक्स तो वे देना चाहते हैं । हम चाहते हैं कि उन का काम भी ठीक तरह से होता रहे और इवेज़न भी न हो लेकिन इस बिल से न तो इवेजन रुकेगा और न ही कुरप्शन रुकेगी । इस अमैंडमैंट से व्योपारियों को कुछ फायदा होने वाला नहीं है । मैं तो कहता हूं कि पचास हजार से भी ज्यादा लिमिट बढ़ा दो और अगर नहीं बढ़ सकती तो पचास हजार ही रखो ताकि यह डिपार्टमैंट अच्छी तरह से काम करता रहे । हमें खुशी है कि चीफ मिनिस्टर ने कुछ तो रियायत दे दी है और भी कुछ सोच समझ कर उन को रियायतें मिलनी चाहियें, व्योपारियों के साथ सलाह कर के इस का हल निकाला जाए । चेयरमैन साहिब, आप का धन्यवाद ।

कामरेड राम प्यारा (करनाल) : चेयरमैन साहिब, जहां तक इस बिल का ताल्लुक है इस के स्टेटमैंट आफ ऑबजेक्टस एंड रीज़न्ज में क्लियरली लिखा हुआ है कि हम टैक्स इस लिये लगा रहे हैं ताकि बोगस लाइसैंसीज़ न हों, कुछ ऐसे ज़राए तलाश किये जाएं जिन से इवेज़न कम हो तो गवर्नमैंट का रेविन्यू बढ़ेगा । मैं गवर्नमैंट की इस बात से इत्तफाक करता हूं कि इवेजन बहुत ज्यादा होता है और इस बात से भी इत्तफाक करता हूं कि हम लोग ऑनेस्टली टैक्स माइंडिड भी नहीं हैं लेकिन जब हम चाहते हैं कि इवेज़न न हो, टैक्स ज्यादा वसूल हो, हमारा बिगड़ा हुआ माहौल संवरे तो हमें देखना होगा कि आया हम ने कोई ऐसी क्लाज, कोई ऐसी प्रोवीजन रखी है कि जिस से लोगों को यह मैंटेलिटी बदले, मेरा अंदाजा है कि इस में कोई ऐसी बात नहीं

है । मैं इस क्लास से थोड़ा कुनेक्टिड हूं । मेरे अंदाजे के मुताबिक 95 परसेंट इवेजन जो है वह विद दी कोल्यूयन एंड कन्नाईवेंस आफ दी आफिशियाल्ज़ आफ दी डीपार्टमैंट है। बाकी रह गया फाईव परसैंट । मेरे अंदाजे के मुताबिक तीन फीसदी लोग मजबूर हो कर इवेजन करते हैं जो डिसऑनेस्ट दुकानदार अफसरों के साथ मिल कर टैक्स को इवेड करते हैं उन के साथ औनेस्ट लोग कम्पीट नहीं कर सकते और उन के मुकाबले में माल नहीं बेच सकते । मेरे अंदाजे के मुताबिक दो परसेंट के करीब ऐसे होंगे जो कि पुलिटिकल पुल की वजह से या ऑफिशियल पुल की वजह से टैक्ड को इवेड करते हैं । बहुत थोड़ी परसेंटेज डीलर्ज़ की ऐसी होगी जो कि इतने ज्यादा कलैबर होंगे कि बिना किसी पुलिटी-कल पुल के और बिना किसी ऑफिशियल पुल के टैक्स का इवेजन करते हों । वे शायद आधे परसेंट से ज्यादा नहीं होंगे । अब गवर्नमैंट चाहती है कि टैक्स ज्यादा वसूल हो । इस सम्बन्ध में मैं छोटी सी तजवीज़ गवर्नमट के सामने रखता हूं । अगर गवर्नमैंट एक ऐसा बिल लाए और यह फैसला करे कि अगर कोई इंडिविजुअल गवर्नमैंट को यह ऑफर करता है कि फलां जगह पर इवेज़न हुआ है और वह उस आदमी को पकड़वाने के लिये तैयार है तो गवर्नमैंट उस को उस पकड़ी हुई रकम का एक फी सदी, या दो फीसदी या पांच फी सदी देने के लिये तैयार है । अगर कोई आदमी इस तरह से एक हजार रुपया गवर्नमैंट के खजाने में लाने में मददगार होता है तो गवर्नमैंट को अपने खजाने से तो देना नहीं पड़ेगा पचास रुपये उस आदमी को दे दे तो फिर भी 950 रुपये सरकार के खजाने में चले जाएंगे । अगली यह बात है कि माहौल किस तरह से संवर सकता है । इस के बारे में मैं अर्ज करूंगा कि अगर कोई आदमी किसी इवेजन की खबर देता है तो मशीनरी उल्टी उस के साथ नाराज हो जाती है और उस की विक्टिमाई-ज़ेशन होती है। जो मशीनरी के साथ मिलकर टैक्स इवेड करवाते हैं, उस में मदद करते हैं उन को कमिशन मिल जाती है । यह राजपाठ अच्छा है, कमाल का है कि चोरों को तो कमिशन और चोरी पकड़वाने वालों को सजा । इस लिये अगर गवर्नमैंट चोरी पकड़वाने वालों को कोई कमिशन देने को तैयार हो तो मैं इस बात का यकीन दिला सकता हूं कि इस से गवर्नमैंट की आमदनी में बहुत सारा इज़ाफा होगा ।

साथ ही एक और चीज़ भी है और वह यह कि जैसा कि मैं ने अभी अभी बताया, सरकारी मशीनरी की कोल्यूजन और कन्नाईवेंस के साथ ही यह इवेजन होती है। अगर गवर्नमैंट किसी एक जिला में ही चन्द दिनों के लिए तजरुबा करे और टैक्स कुलैक्शन की जो मशीनरी वहां है उसको हटा दे तो मैं दावे से कह सकता हूं कि वहां से टैक्स की रकम इस वक्त से लाजमी तौर पर ज्यादा ही आएगी । क्यों ? कैसे ? आप को यह बात इस तरीके से कम्पेअर करनी होगी कि अगर इस रकम की एक लाख रुपए की कुलैक्शन होती है तो उसपर आप की जो मशीनरी है उसका आठ दस हजार रुपया खर्चा भी आता है । अगर

[कामरेड राम प्यारा]

उस मशीनरी को वहां से हटाने के बाद भी एक लाख रुपया सरकार के खजाने में आ जाए तो इस तरह से गवर्नमैंट की उस आठ दस हजार रुपए की बचत हो जाएगी जो कि उस मशीनरी पर उसे खर्च करना पड़ता है। लेकिन होता क्या है ? जिस आफिशियल या आफिसर की सौ, डेढ़ सौ, दो सौ या तीन सौ रुपया माहवार तन्खाह है उसकी हालत यह है कि उसका महीने का खर्च पांच सौ तक चला जाता है। पाँच छ: सौ रुपए महीने से उसका खर्च कम नहीं होता। तो आसानी से अन्दाजा लगाया जा सकता है कि वह जो ज्यादा पैसा खर्च होता है वह कहाँ से आता है। कई बार वह लोग निहायत शरीफ, बड़ी अच्छी इनकम वालों की मुफ्त में बेइज्ज़ती भी करते हैं और उन की नीयत पर शक करते हैं। मैं इस मौके पर इस बात पर ज़ोर देना चाहूंगा कि गवर्नमैंट कोई ऐसी मशीनरी इवाल्व करे कि जहाँ पर इस बात की व्यवस्था की गई है कि अफसर लोग व्यापारियों के घरों की, उन की दुकानों की तलाशी लें वहाँ साथ ही साथ इस बात का भी प्रोवीज़न होना चाहिए कि इन से सम्बन्ध रखने वाले अफसरों की भी तलाशी ली जाए। अगर कोई भी आदमी पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात की शिकायत करता है और कहता है कि फलाँ अफ़सर के मकान की तलाशी लो, उसकी चैकिंग करो कि वहाँ पर जो जो सामान है वह कहाँ से आया, कैसे आय तो इस चीज़ के लिए भी सरकार को कोई प्रबन्ध करना चाहिए। मैं इस प्रोवीजन की मुखालिफत नहीं करता हालाँकि मेरे कुछ दोस्तों ने इस पर भी एतराज किया है। मैं तो कहता हूं कि न सिर्फ दुकान की बल्कि मकान की भी पूरी तरह से तलाशी होनी चाहिए क्यों कि हमारा मकसद एक इमानदाराना माहौल पैदा करना है ताकि टैक्सों की चोरी न हो, वह रुक सके और इस तरह से जो काली भेड़ें अपने मकानों पर, दुकानों पर सामान रखती हैं, टैक्स को ईवेड करती हैं उन पर ज़रूर छापा पड़ना चाहिए। लेकिन, जैसा कि मैंने कहा, अगर कोई दुकानदार आप की आफिशियल मशीनरी की बाबत यह कहता है, शिकायत करता है कि फलाँ मुलाज़िम फलाँ अफ़सर के मकान पर छापा मारो यह पता करने के लिए कि उसके पास जो सामान है वह कहाँ से कैसे आया तो उसका क्या आप ने कोई इलाज किया है ? मैं दावे से कह सकता हूं कि मैंने और मेरे साथियों ने कई केसिज गवर्नमैंट के नोटिस में लाए लेकिन छापा मारने के लिए कोई नहीं चलता। पिछली दफा ज्ञानी ज़ैल सिंह जी मेरे पास आए, सैशन था, कहने लगे कि चलो। मैंने कहा कि नहीं चल सकता क्योंकि मैंने एक जगह पर छापा मारने के लिए अरेंज किया हुआ है। वहां पर बात यह थी कि उस शख्स ने तीन साल में सिर्फ दस आने सेल्ज टैक्स दिया था। वहां पर छापा पड़ा, कई तरह का मैटीरियल पकड़ा गया डाकयुमैंट्स देखे गए और बारह तेरह सौ रुपया एक साल का और छत्तीस सैंतीस सौ रूपया तीन साल का लगाया गया। लेकिन जब ऐक्साईज़ ऐंड टैक्सेशन कमिश्नर से कहा गया कि इस मामला की पूरी पड़ताल की जानी चाहिए कि क्यों टैक्स नहीं दिया या उससे क्यों इस बारे में जांच पड़ताल नहीं की गई तो मामला ठप। चेयरमैन साहिब, असल बात यह है कि सेल्ज टैक्स

डिपार्टमैंट के बहुत से लोग उस से साढ़े तीन रुपए सेर, चार रुपए सेर अच्छा खालिस घी ले जाया करते थे । मैं यहां हाउस में खड़ा होकर गवर्नमैंट से पूछता हूं कि क्या उन से भी कभी पूछा गया कि तुम ने क्यों पाँच, सात या दस रुपए की खातिर कौम का, स्टेट का इतना रुपया ज़ाया कर दिया ? आखिर उन की पूछताछ क्यों नहीं होती ? चेयर मैन साहिब, कल ही मेरा एक सवाल था श्री मान सिंह ए. ई. टी. ओ. की बाबत । क्या फिनांस मिनिस्टर साहिब इस बात का यकीन दिला सकते हैं कि जो अफसर रिश्वत लेता हो, ट्रेडर्ज़ को तंग करता हो उस की पूछताछ की जाएगी, उसे गिरफ्तार किया जाएगा ? मैं हैरान हूं कि इस मामले में किस कदर कोल्यूज़न और कन्नाईवैंस होती है । हां, तो मान सिंह की बाबत रिपोर्ट हुई । 13 अगस्त को वह पकड़ा जाता है लेकिन हैरानगी की बात है कि पहली अक्तूबर तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होती । मैं पूछता हूं कि इस केस में एक महीना और सतारह अठारह दिन तक कौन सी ऐसी मशीनरी थी जो इस बात की मदद कर रही थी कि उसकी गिरफ्तारी न हो ? यकीनन इस में मशीनरी के वे पुरजे भी हैं जिन में वह जितना रुपया इकट्ठा करता था उस में से आगे उन उन के दरम्यान बांटता था । अगर फिनांस मिनिस्टर साहिब इस तरह के केसिज की पड़ताल करने का यकीन दिलाएं फिर तो इस तरह की लैजिस्लेशन लाने का कोई फायदा भी हो सकता है वरना यह सब कुरप्शन को बढ़ाने वाली बातें ही सिद्ध होंगी ।

इसी तरह दो तीन रोज पहिले ई. टी. सी. मिस्टर दलजीत सिंह के खिलाफ भी मेरा एक सवाल था । वहां भी यही हुआ कि उसकी वजह से गवर्नमैंट का लाखों नहीं करोड़ों रुपया का नुकसान हुआ । लेकिन मैं महसूस करता हूं कि यह नपुंसक गवर्नमैंट उसका भी कुछ बिगाड़ नहीं सकी । मुझे डर है कि उस के हाथ पांव बहुत लम्बे हैं, उसने बेईमानी का इतना रुपया इकट्ठा किया हुआ है कि वह हर तरह का प्रैशर डलवा सकता है और उसकी भी कोई पूछताछ नहीं होगी । अगर कुरप्शन करने वालों की, अगर ईवेजन और ईवेजन में मदद करने वालों की, अगर चोरी करने वालों की इस गवर्नमैंट में कोई पूछताछ नहीं होती, कोई पड़ताल नहीं होती तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि आप जितने चाहें सख्त से सख्त प्रोविजन ले आएं यह टैक्सों की ईवेज़न रुकने वाली नहीं है ।

इस के बाद, चेयरमैन साहिब, मैं यह कहना चाहता हूं कि रेविन्यू, मामला इकट्ठा होता है । इसमें लम्बरदार की कोई इन्वेस्टमैंट नहीं होती । बाप लम्बरदार होता है । उसके बाद उसका बेटा लम्बरदार बन जाता है और बेटे के बाद बेटे का बेटा और उसको उसमें से पांच फीसदी मिलता है । अगर वह एक हजार रुपया इकट्ठा करता है तो उसमें से उसे पांच फीसदी मिल जाता है और वह उसे कमिशन की शकल में मिलता है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि हालांकि यह ट्रेडर्ज गवर्नमैंट की तरफ से टैक्स को इकट्ठा करने की फ्री एजंसी के रूप में काम करते हैं फिर भी उन्हें धक्के मिलते हैं, उन की हरेसमैंट होती है, उनकी बेइज्ज़ती की जाती है,

[कामरेड राम प्यारा]

इन्स्पैक्टर उन की इज्ज़त को छीनने की कोशिश करते हैं, उन की पगड़ी उछालने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है। वे लोग सरकार की तरफ से लाखों नहीं करोड़ों रुपया टैक्स का इकट्ठा करते हैं लेकिन उन के साथ किस किस्म का सलूक अफसरों के जरिए किया जाता है ? मुझे यह कहते हुए अफसोस होता है कि जब वे लोग इन के दफतरों में जाते हैं तो न उन्हें बैठने के लिए जगह दी जाती है, और न ही उन्हें पीने के लिए पानी तक पूछा जाता है। हां तो जिस बात पर मैं आप को लाना चाहता हूं वह यह है कि ब्लैकशीप दोनों तरफ ही है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। जहां तक ट्रेडर्ज का ताल्लुक है उन में से भी बहुत से टैक्स की चोरी करते हैं, इवेजन करते हैं जिस की वजह से सरकार के खजाने में टैक्स की रक्म पूरी नहीं आती और दूसरी तरफ जहाँ तक आफिशियल मशीनरी का ताल्लुक है उन में भी काफी हद तक बददयानती है । और अगर वह बददयानती से काम न लें तो यह जो इवेजन होती हैं, चोरी होती हैं यह हरगिज़ न हो। और यह बिल्कुल ही नहीं तो बहुत हद तक कम हो जाए अगर सरकार इस बात का एलान कर दे, कोई ऐसा प्रोविजन कर दे कि जो इस टैक्स की चोरी को पकड़वाएगा उसे उसमें से कुछ कमिशन दी जाएगी।

अगली बात, चेयरमैन साहिब, यह है कि इन्होंने पांच रुपया रिन्यूअल फीस का प्रोविजन किया है । कुछ दोस्तों ने तो इस पर भी एतराज किया है, लेकिन मैं इसपर भी किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं करना चाहता। आप बेशक इस को लगाएं। क्यों ? आज तो 56,000 डीलर है तो कल एक लाख भी हो सकते हैं । इस तरह से गवर्नमैंट को पांच लाख रुपया सालाना और आमदन हो जाएगी । लेकिन इस में मैं फिनांस मिनिस्टर साहिब को एक तजवीज़ पेश करना चाहता हूं और वह यह है कि बजाय इस के कि साल के बाद हर एक डीलर इस रिन्यूअल के लिए आए और पांच पांच रुपए जमां करायें आप यह कर दें कि जब जब वह सेल्ज़ टैक्स की क्वारटरली जमा कराने आए तो उसी वक्त वह रिन्यूअल फीस दे दे। अगर एसा न किया गया और साल के बाद आप हरेक डीलर से यह उम्मीद करेंगे कि वह रिन्यूअल के लिए दरखास्त दे तो उस से उन को बहुत सी नई मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा । उसके लिए फार्म होगा पांच रुपए की रिन्युअल फीस जमा कराने के लिए उन को खज़ाने में जाना पड़ेगा । वहाँ वक्त नहीं मिलेगा। कई बार ऐसा होगा कि चूंकि फार्म छपे हुए होंगे तो वह खत्म हो सकते हैं । दफतर में जाएगा तो वहां पर फार्म नहीं मिलेगा। इस तरह से आप देखें कि पांच रुपए जमा कराने के लिए कितनी सिरदर्दी और बादरेशन का सामना करना पड़ेगा । इतना ही नहीं पांच रुपए की खातिर एक आदमी का पांच, दस और पंद्रह रुपए तक और ज़ाया हो जाएंगे । इस तरह से बजाय काम आसान होने के गवर्नमैंट के तईं लोगों की डिसकंटैंटमैंट बढ़ जाएगी । इस लिए जैसा कि मैंने सुजैस्ट। किया है, बेहतर यही होगा कि जब जब व्यापारी टैक्स की क्वाटरली जमा कराने आएं उन को यह रिन्युअल फीस भी जमा कराने की इजाज़त हो । उसके लिए उन

के पास भरा भराया फार्म होगा और कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा।

लेकिन इस के साथ साथ, चेयरमैन साहिब, मैं गवर्नमैंट से यह भी पूछना चाहता हूं कि सिनेमा वालों पर, जिनकी आमदन लाखों रुपया सालाना है, आप कुछ हज़ार रुपया रिन्युअल फीस क्यों नहीं लगाते ? क्यों नहीं कोल्ड स्टोरेज के मालिकों पर, जिन को आप ने बड़े बड़े कोटे दिए हुए हैं, लाईसैंस दिए हुए हैं इस तरह से रिन्युअल फीस लगाते ? जिस आदमी को आप ने एक हज़ार रुपए क इम्पोर्ट मैटीरियल का लाईसैंस दिया हुआ है आते ही उसका वह मैटीरियल तीन हज़ार रुपए में बिक जाता है। तो ऐसे लोगों पर क्यों नहीं इस तरह से उन से फीस वगैरा ली जाती ? गवर्नमैंट का ट्रैंड ऐसा है कि जो ग़रीब क्लास के आदमी हैं उन के ऊपर तो चोट पर चोट, टैक्स पर टैक्स लगाया जाए और जो क्लास बड़े बड़े मुनाफे कमाने वालों की है, जो गवर्नमैंट के ज़राये से पैसा कमाते हैं बग़ैर किसी किस्म की मेहनत किए कमाते हैं उन की तरफ गवर्नमैंट की आंख नहीं उठती। इस कीबजाय उन्हें और कई तरह की फेसिलिटीज़ दी जाती है। यह बात गवर्नमैंट के नोटिस में है। यह नहीं कहा जा सकता कि गवर्नमैंट उन की आमदनी से नावाकिफ है। उन की बड़ी बड़ी कन्सर्न्ज़ हैं। उन पर गवर्नमैंट ने अभी तक आंख नहीं उठाई। मैं चाहूंगा कि उन की तरफ भी फौरी तौर पर ध्यान दिया जाए। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर उन को इस तरह की लपेट में लाया जाए तो गवर्नमैंट को लाखों नहीं करोड़ों रुपए की और आमदनी हो सकती है। एक बात और। सरकार ने अब इसमें बोगस लाईसैंसिज के लिए चैक प्रोवाईड किया है। बोगस लाईसैंसिज़ के बारे में मैं खुद कई बार कह चुका हूं। सरदार प्रताप सिंह कैरों के ज़माने में अकेले अमृतसर में कोई सौ के करीब बोगस लाईसैंसीज़ थे। पानीपत में एक मिस्टर जैन को पकड़ा गया। वह सेल्ज़ टैक्स वालों का चार लाख रुपया लेकर भाग गया था। पर सवाल यह है कि बोगस लाईसैंस कौन बनाता है ? यहां पर फिर वही बात कहनी पड़ेगी कि डिपार्टमैंट वाले ही इस के लिए जिम्मेदार हैं। चेयरमैन साहिब, जहां तक इस मिस्टर जैन के केस का ताल्लुक है आप सुन कर हैरान होंगे कि उसकी फाईल भी नहीं मिलती थी। चन्द रुपए लेकर उस फाईल को भी जला दिया गया। क्या फिनांस मिनिस्टर साहिब इस बात का यकीन दिला सकते हैं कि जिन लोगों ने फाईल को जलाने में हिस्सा लिया, जिन्होंने उसके खिलाफ ऐक्शन नहीं लिया उन सभी लोगों को पकड़कर उन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करेंगे ? अगर वह इन लोगों के खिलाफ ऐक्शन लेने के काबिल नहीं हैं तो मैं समझता हूं कि ट्रैडर्ज़ सब कुछ कहने में जस्टीफाईड होंगे। वह यह कहने में जस्टीफाईड हैं कि बग़ैर पैसा दिए, बग़ैर रिश्वत दिए उन का कोई काम नहीं होता। चेयरमैन साहिब, अगर इन का अमला, इन के अफसर आनैस्ट, ईमानदार हों तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि दुकानदारों की जुर्रत नहीं हो सकती कि वह किसी तरह से भी टैक्स की ईवेज़न करें।

[कामरेड राम प्यारा]

अगर वह करते है तो इन की मर्ज़ी से करते हैं और अपने आप नहीं करते !

फिर इस में अपील वाला मामला है जिस बारे व्योपारियों की डिमांड में बड़ा वज़न है। वह चाहते हैं कि जो महकमा सेलज़टैक्स असैस करता है उसी महकमे के अफसर उन की अपीलें न सुनें और उन की बजाए किसी दूसरे महकमें के अफसर उन को सुनें। मैं समझता हूं कि यह माँग उन की जायज़ है। अगर यह मान ली जाए तो इस से बड़ी बात यह होगी कि जो डीलर अपील करता है उस को इस बात का गिला नहीं रहेगा कि जिस महकमे ने टैक्स असैस किया था उसी ने ही उस की अपील नहीं सुनी है और इस के साथ ही साथ यह पड़ताल भी होती जाएगी कि क्या कोई डीलर किसी अफसर के साथ मिल कर टैक्स इवेज़न तो नहीं करता। और इस वक्त यह जो आम शिकायत है कि कई अफसरों के साथ कई डीलरज़ मिल कर टैक्स की चोरी कर लेते हैं यह काफी हद तक दूर हो जाएगी। जो साबका एक्साईज़ कमिशनर थे उन को मैं ने जब लिखा था कि नेशनल मोटरज़ की जो फर्म है वह सेल्ज़ टैक्स नहीं दे रही, तो उस का जवाब जो उस ने मुझे दिया वह बड़ा कनोफ्यूज़िंग था। वह जवाब अब भी मेरे पास है और मैं ने कइयों को वह पढ़ाया है और सब कहते हैं कि यह बड़ा कनफ्यूज़िंग है। उस ने यह जवाब इस लिए दिया क्योंकि वह उस फर्म की फेवर करनी चाहता था। लेकिन उस के बाद जब मैं ने वह मामला खोल दिया तो उस फर्म पर पांच हज़ार रुपए की पेनल्टी लगा दी। इस पर मैं ने फिर यह प्वांयट रेज़ किया कि क्या वजह है कि अगर कोई व्यापारी 10 हज़ार रुपए टैक्स की अदायगी वक्त पर नहीं करता तो उस को दो या ढाई हज़ार रुपए तक पेनल्टी लगा दी जाती है। तो इस फर्म ने जब लाखों रुपए टैक्स के अदा नहीं किए तो इस को क्यों सिर्फ पांच हज़ार रुपए पेनल्टी लगाई गई है। मेरी इस चिठ्ठी पर दोबारा यह मामला टक अप हुआ और उस फर्म पर इन्हें 2 लाख 55 हज़ार रुपए पेनल्टी लगानी पड़ी और जो उस फर्म ने अदा भी की। तो क्या मैं फिनांस मिनिस्टर साहिब से पूछ सकता हूं कि जिस अफसर ने उस पार्टी को यह इस तरह से टैक्स न देने में या कम पेनल्टी लगाने में रियायत दी थी। उस को क्या कोई सज़ा आज तक दी गई है ? मैं जानता हूं कि उस को कोई सज़ा नहीं दी गई। तो अगर ऐसे अफसरों को जो इस तरह से जो बईमान लोगों की इमदाद करते हैं यह सरकार सज़ा नहीं देती तो कैसे उम्मीद की जा सकती है कि यह गवर्नमैंट ईमानदारी से चल सकेगी। इस सिलसिले में मैं फिनांस मिनिस्टर साहिब के नोटिस में ऐसी एक बात और लाना चाहता हूं कि इस टैक्स की इवेज़न को रोकने के लिए जो इस ने एक चेक पोस्ट जी० टी० रोड पर बना रखी है उस पर भी पिप्ली की ट्रैफिक पोस्ट की तरह हो रहा है और वहां पर 10, 10 रुपए ले कर ट्रकों को गुज़ार दिया जाता है। और जो आदमी उन्हें दस रुपए दे देता है उस को तो गुज़र जाने दिया जाता है और जो नहीं देता उस को टैक्स के लिए रोक लिया जाता है। इस लिए मैं यह कहता हूं कि अगर तो गवर्नमैंट चाहती है कि इस को टैक्सों की ज्यादा

बसूली हो तो यह अपनी मशीनरी को इण्डीपेंडेंट बनाए और इस टैक्स इवेज़न को रोकने के लिए जो अमला रखा हुआ है उसे यह साफ करें। इस के साथ ही फिनांस मिनिस्टर साहिब व्योपारियों के रिप्रीज़ेंटेटिवज़ को अपने पास बुलाएं और उन से कहें कि गवर्नमैंट का यह गिला है कि टैक्स में इवेज़न होता है इस को रोका जाए लेकिन इस के लिए गवर्नमेंट को यह एश्योरेंस देनी कि वह ऐसे व्योपारियों को जो इनसपेक्टर्ज़ को 10 या 20 रुपए दे कर उन के ट्रक गुज़ार देते हैं उन को ऐसा नहीं करने देगी। इसी तरह से बोगस लाईसैंस वालों के लिए सिक्योरेटी की बात चलती है। मैं समझता हूं कि यह बोगस लाइसेंस भी तो गवर्नमैंट की मशीनरी की मदद से चलते हैं।

आखर में मैं एक बात और कहना चाहता हूं और यह रिफण्ड वाली बात है। इस बारे में मितल साहिब ने एक बड़ी अच्छी तजवीज़ हाउस के सामने रखी है। कि जिस पार्टी ने वह रुपया जमा कराया हुआ है और उस के रिफण्ड के आर्डर हो जाते हैं तो यह डिपार्टमैंट का फर्ज़ बन जाता है कि वह उस को यह रुपया उस के घर पर पहुंचाए। इस बारे में अब क्या होता है। अब यह होता है कि जिस ने रुपए का रिफण्ड लेना होता है उसे उस में से रिफण्ड करने वाले को हिस्सा देना पड़ता है। मेरी इतलाह के मुताबिक उस को उस में से अफसरों को कमीशन देनी पड़ती है। डीलर तो यह कहता है कि या तो उस का रुपया उसे वापस कर दिया जाए या अगली असेसमैंट में एडजस्ट कर दिया जाए इस लिए वह लेने नहीं जाता, इस लिए उस का यह रुपया टाइम बार नहीं होना चाहिए। गवर्नमैंट को तो चाहिए कि जिस किसी डीललर का रुप्या बचता हो उसे तीन महीनों के अन्दर उसे वह वापस कर देना चाहिए। इस बात की मुझे समझ नहीं आती कि जो गवर्नमैंट मशीनरी इस काम पर लगी हुई है वह यह रुपया उसे क्यों अपने आप वापस न करे, क्या वह इस काम के लिए तन्खाह नहीं लेती। इस के मुकाबिला में डीलर जो है वह बगैर तनखाह के सरकार के इस टैक्स का रुपया इकट्ठा करता है और इस के लिए वह कोई तन्खाह नहीं लेता और अगर उस से ऐसे करते हुए अनजाने में कोई गलती भी हो जाती है तो उस से उस के लिए गवर्नमैंट पूछ ताछ भी कर लेती है। मैं हैरान हूं कि आखिर क्या वजह है कि गवर्नमैंट यह जिम्मेदारी अपने अफसरों पर क्यों नहीं डालती। जिस आदमी का वह रुपया है गवर्नमैंट मशीनरी सूओ मोटो अपने तौर पर उसे वह वापस करे और अगर वह तीन महीनों के अन्दर उसे वापस नहीं करता तो गवर्नमैंट उस अफसर की जवाब तलबी करे कि क्यों उस से इस मामले में कोताही हुई है। इस तरह से अगर वह डीलरज़ के साथ पेश आएंगे और अगर उन को इस में अपने कानफीडेंस में लेंगे तो इस वक्त डीलरज़ जितना टैक्स में चोरी करते हैं वह कम हो जाएगी। इस तरह से जितना हो सके इसे चाहिए कि टैक्स की चोरी को बन्द करे लेकिन इस के साथ ही साथ गवर्नमैंट पहले अपनी मशीनरी में सुधार लाए। अगर यह सुधार नहीं होगा तो पबलिक से इमानदारी की उम्मीद नहीं कर सकेगी।

[कामरेड राम प्यारा]

मैं समझता हूं कि डीलरज़ जो हैं वह आम तौर पर ईमानदार होते हैं और ईमानदारी के साथ काम करना चाहते हैं और गवर्नमैंट को पूरा टैक्स देना चाहते हैं लेकिन कई दफा उन्हें मजबूर हो टैक्स की चोरी करनी पड़ती है क्यों कि वे देखते है कि जो बेईमान व्योपारी हैं वह ऐसा कर के अफसरों को खुश रख सकते हैं तो उन्हें भी ऐसा ही करना पड़ता है । (घंटी की आवाज़) बस जी चेयरमैन साहब, मैं यह आखरी प्वायंट कह कर बैठ जाऊंगा । इस बारे में मैं एक स्जेशन देना चाहता हूं कि जब महकमे वाले व्योपारियों की किताबें चैक करते हैं तो इन्हें चाहिए कि यह उन को कहें कि वह महसूल की परचियां भी साथ ले आया करेंक्यों कि जो व्योपारी टैक्स की चोरी करते हैं वह अपनी किताबों में माल दर्ज ही नहीं करते हालांकि उन्होंने उस माल के ऊपर महसूल दिया हुआ होता है । यह देखने में आया है कि कई दफा माल किताबों में दर्ज नहीं हुआ होता और उस का महसूल उन्हों ने दिया हुआ होता है और कई दफा माल दर्ज होता है लेकिन उन के पास महसूल की परची नहीं होती । इस तरह के 2 या 3 प्रसेंट व्योपारी एसे हैं जो टैक्स की चोरी करते हैं बाकी के नहीं करते । इस लिए गवर्नमैंट को उन को जो चोरी नहीं करते ख्याल रखना चाहिए और उनको रिलीफ देना चाहिए।

श्री सागर राम गुप्ता (भिवानी) : चेयरमैन साहिब, मैं आप का मशकूर हूं जो आप ने मुझे इस बिल पर बोलने के लिए टाईम दिया है-----

(इस पर बहुत सारे मैम्बर बोलने के लिए खड़े हो गए)

श्री सभा पति : आप बैठ जाएं मैं पहले उन साहिबान को टाईम दे रहा हूं जिन को पहले बोलने के लिए बहुत कम वक्त मिला है । वैसे सब को वक्त दिया जाएगा ।

(The hon. Members may please resume their seats. I am permitting those hon. Members to speak first who have been given less time previously. Every hon. Member will of course be given time to speak.)

पंडित भागीरथ लाल शास्त्री : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर । मैं इस बिल पर बोलने के लिए कभी का खड़ा हो रहा हूं लेकिन आप मुझे टाईम नहीं दे रहे ——— (शोर)

वित मंत्री : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर । मैं आप का ध्यान इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि जो बातें अब कही जा रही हैं वह सारा उन बातों का रेपीटीशन है जो यहां पहले कही जा चुकी हैं । इस बारे मे आप अन्दाज़ा लगा लें । वैसे मुझे कोई एतराज नहीं अगर यह चार दिन भी इसी बिल पर बोलते जाएं और यहां बैठें । आखर यह बिल वापस तो लिया जाना नहीं । इस ने तो यहां से पास होना ही है । ऐसी बात तो है नहीं कि इस बिल को मुल्तवी कर दिया जाएगा ।

श्री सभापति: माननीय फिनांस मिनिस्टर का सुझाव ठीक है । इस लिए मैं माननीय मैम्बर साहिबान से यह अर्ज़ करूंगा कि जो बातें यहां इस बिल पर पहले कहीं जा चुकी हैं उन की रिपीट न करें । वह इस बात का ख्याल रख लें ।

(The hon. Finance Minister is right. I well, therefore, request the hon. Members not to repeat what has already been said here on this Bill. They should keep this fact in view.)

श्री सागर राम गुप्ता (भिवानी) : चेयरमैन साहिब, जो जैनरल सैल्ज टैक्स अमैंडमैंट बिल हमारी सरकार ने यहां पर पेश किया है हाउस उस पर बहस कर रहा है । चेयरमैन साहिब, पिछले साल जब यह सरकार वजूद में आई तो हमारे चीफ मिनिस्टर साहिब ने बड़े अच्छे २ बयानात दिये । जो मोटी मोटी बातें उन्होंने अखबारों में, जलसों में या मीटिंगज़ में कहीं उनकी तरफ मैं आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं । एक तो उन्होंनें यह कहा कि उनकी सरकार सोशलिस्ट असूलों पर चलेगी । दूसरी मोटी बात जो उन्हों ने उस वक्त कही वह यह थी कि वह इस स्टेट को आनैस्ट ऐडमिनिस्ट्रेशन देंगे । तीसरी बात जो उन्होंनें कही वह थी कि राज्य में जो इन्स्पैक्टरी राज है उसको काफी हद तक कम किया जायगा और इस से जो लोगों को दिक्कतें आती हैं उनको कम से कम किया जायगा । चौथी बात उन्हों ने यह कही कि जो नियम हैं, कानून है उसको इतना सिम्पलीफाई किया जायगा कि आम लोगों की इस वजह से दिक्कतें कम से कम हो जाएं । तो चेयरमैन साहिब, जब मैंने यह बिल पढ़ा तो मैंने महसूस किया, जैसा कि दूसरे साहिबान ने भीं किहा है, कि यह जो बिल है यह सरकार की किसी भी पालेसी के मुताबिक नहीं है और अगर मैं यह कहूं कि सरकार इस बिल को सदन से पास करवा कर अपनी पालेसी को ही रद्द करवा रही है तो इस में जरा भी मुबालगा आमेजी नहीं होगी । मिसाल के तौर पर यह सोशलिजम की बात कहते हैं ।

चेयरमैन साहिब, यह बात आम जनता को मालूम है कि टैक्स का इवेज़न आम व्योपारी नहीं करता, यह मानी हुई बात है । बल्कि उस आम व्यापारी को तो जितना टैक्स कानून के मुताबिक देना पड़ता है उस से भी कुछ ज्यादा ही इन्सपैक्टरों को रिश्वत की शकल में देना पड़ता है। तो जो इवेयन करता है वह है बड़ा व्योपारी, लाखपति और करोड़पति बिज़नेस हाउसिज़ । इस बिल के ज़रिये सरकार धनी लोगों के मुतअल्लिक कुछ नहीं कर रही जिस से उन पर किसी किस्म की बन्दिश आती हो या उन की चोरी रुकती हो । हां इस के ज़रिये जो छोटा व्योपारी है उसको तंग करने के लिये सरकार खूब मसाला तैयार कर रहीं है ।

चेयरमैन साहिब, यह बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि यह जो सेल्ज़ टैक्स है यह एक इनडायरैक्ट टैक्स है और यह जितना भी लगेगा-बल्कि इस टैक्स

[श्री सागर राम गुप्ता]

की ही बात नही है, इस के साथ साथ जो रिश्वत आदि व्योपारी को इन्स्पैक्टर को देनी पड़ेगी वह सब कांज्यूमर के सिर पर पड़ेगी। तो इस तरह से यह पहले ही काफी ज्यादा बरडन के नीचे पिस रहे कन्ज्यूमर को यह बिल पास करके पीस रहे हैं। चेयरमैन साहिब, मैं मज़दूरों में काम करता हूं जैसा कि आप को मालूम है। आज मजदूरों की हालत को देख कर रोना आता है कि यह सरकार बजाए मजदूरों का स्टैंडर्ड आफ लिविंग ऊंचा करने के इस किस्म के कानून बना कर उनका गला घूंट रही है। (आपोजीशन की तरफ से तालियां) मुझे माफ करें, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं। आप ज़रा वार इफैक्टिड एरियाज़ जैसे अमृतसर वगैरह के जो ज़िले हैं, वहां पर देखें मज़दूरों को काम नहीं मिलता और वह भूखे मर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर साहिब ने एलान किया कि सरकार वहां पर 25 लाख रुपया इन्टरैस्ट फ्री लोन देगी। मगर आप को आश्चर्य होगा यह सुन कर कि एक भी रुपया लोन का किसी मज़दूर को नही मिला, इन्डस्ट्रीज को तो मदद मिली, जो अपरुट हुये उन को कुछ राहत दी गई मगर बेचारे मज़दूर को कुछ नहीं मिला। हालत यह है कि हमारी सरकार आए दिन गरीब मजदूर, किसान और कन्जयूमर पर बोझ लादती चली जाती है। जिन के अन्दर टैक्स देने की कपैसिटी है वह बिल्कुल साफ बच रहे हैं। मैं अर्ज करूं कि यह बिल किसी तरह से भी सोशलिजम के रास्ते को अख्तियार नहीं करता। बल्कि मुखालिफ है।

कुरप्शन की बात लीजिये। हमारी सरकार यही कहती रही है कि यह सूबे को आनैस्ट ऐडमिनिस्ट्रेशन देगी। आप भी जब चेयरमैन साहिब, अपनी सीट से तकरीर कर रहे थे तो आप ने कहा था कि इस डिपार्टमैंट में जितनी कुरप्शन है उतनी शायद ही किसी डिपार्टमैंट में होगी और यह बात किसी भी मैम्बर से छिपी हुई नही है। फिनांस मिनिस्टर साहिब ने फरमाया है कि जब वह इस कुर्सी पर बैठते हैं तो सारे रुल्ज भूल जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि वह सब कुछ भूल गए हैं जो कि इनके इन्स्पैक्टर करते हैं। इन को मालूम होगा कि इन का हर इन्सपैक्टर हर महीने जजिया लेता है। अगर कोई दुकानदार नहीं देता तो उस का अगर कोई कसूर न भी हो तो कसूर बना दिया जाता है। और अब एक और नई बात निकली है (एक आवाज) रिपोर्ट क्यों नहीं करते: । उसकी भी बात बताऊंगा। तो मैं कह रहा था कि एक नई बात निकली है कुरप्शन को हमारे हां हिसार में एक ए. टी. ओ. श्री भल्ला आए हैं।.. (विघ्न) मैं बताता हुं कि कैसे बात सामने आई। मेरा ख्याल है कि इन के कान एक तरफ ही लगे रहते हैं दूसरी तरफ से यह बन्द रखते हैं, इन को दूसरी बात सुनाई नही पड़ती।

श्री सभापति : आफिसर्ज के नाम न लीजिए।

(The hon. Member may avoid mentioning the names of the officers.)

श्री सागर राम गुप्ता : आई ऐम सौरी । तो हिसार में एक इ.टी.ओ. तशरीफ ले गए हैं । उन्हों ने क्या रवैया बना रखा है ? वह जिस भी टाऊन में जाते हैं तो वहां से दस बीस दुकानदारों के हिसाब किताब उठा लाते हैं और जब वह घबरा कर उन की सेवा में हाजरि होते हैं कि साहिब हम ने तो कोई गलती नहीं की है, हम तो बराबर टैक्स देते रहे हैं तो वह साहिब फरमाते हैं कि सीधी सी बात है कि भई हम ने मिनिस्टर साहिब को पैसे देने हैं, हमें भी नौकरी करनी है तो अगर किसी वजह से मिनिस्टर साहिब पैसे मांगते हैं तो हमें उन को देने पड़ते हैं इस लिये तुम दो हजार रुपया ला कर दो (विघ्न) मुझे पता नहीं है कि यह सच है या झूठ ऐसा मैंने सुना है ....

Finance Minister : Mr. Chairman, I protest against the remarks of the hon. Member. Either he shall have to verify this statement or he shall withdraw.

श्री सागर राम गुप्ता : मैं इस के लिए ऐफीडेविट देने के लिये तैयार हूं बलकि दुकानदारों के ऐफीडेविट ला सकता हूं कि इ. टी. ओ. जा कर साफ दुकानदार से कहता है कि मैंने मिनिस्टर को पैसे देने हैं, मैं कहां से दूं, आप से ही लूंगा । फिर चेयरमैन साहिब, फिनांस मिनिस्टर साहिब चाहते थे कि उन का इलाज होना चाहिए । अब इलाज की बात सुन लिजिए । एक मिसाल देता हूं । मेरे हां भिवानी में एक इन्सपैक्टर साहिब हैं, उनका हाल यह है कि वह मिनिस्टर का नाम तो नहीं लेते मगर पैसे वह भी लेते हैं । आप सुन कर हैरान होंगे कि हमारी सरकार के जो प्रेज़ेंट डिप्टी मिनिस्टर हैं, चूंकि उस इन्सपैक्टर की इस वक्त इन्क्वायरी चल रही है, उसकी चीफ मिनिस्टर साहिब से मुलाकात कराने के लिए दिल्ली ले गए और उनको डिप्टी मिनिस्टर साहिब ही कहना चाहिए, उन का जेंडर तो ऐसा ही कुछ और है.... (विघन) नाम क्या लूं जैंडर तो बताया है ।

तो डिप्टी मिनिस्टर साहिब, उस इन्स्पैक्टर को चीफ मिनिस्टर के पास दिल्ली ले गए और उस इन्सपैक्टर की एक बहुत अच्छी तस्वीर सी. एम. साहिब के सामने खींच दी और जान पहचान करवा दी ताकि जो इन्क्वायरी उनके खिलाफ हो रही है अगर उस की रिपोर्ट उस इन्सपैक्टर के खिलाफ हो तो उसे बचाया जा सके। उस इन्सपैक्टर की मुलाकात करवा दी ता कि वक्त पर काम आए । तो चेयरमैन साहिब, इस तरह से हमारे मिनिस्टर साहिबान इन्स्पैक्टरों को पैट्रोनाइज़ करते हैं । इस हालत में छोटे दुकानदार और मेरे जैसा छोटा सा एम. एल. ए. किस तरह से उस का कुछ बिगाड़ सकता है । हम अगर चाहते भी हैं कि उस के खिलाफ रिपोर्ट कर दी जाए तो उसका नतीजा क्या होगा सिवाए इस बात के कि वह मेरे जो रिश्तेदार दुकानदार हैं उन्हें तंग करेगा और बदनाम करेगा, और कुछ नहीं निकल सकता । इस लिए मैं अर्ज करता हूं कि आज जो इन्सपैक्टर हैं वह कुरपट हैं और कुरपशन ओपनली करते हैं । माहौल ही ऐसा बना दिया गया है कि हम चाहने पर भी इन्स्पैक्टरों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते । इस के बारे में, चेयरमैन साहिब, इस बिल

[श्री सागर राम गुप्ता]

के अन्दर कोई भी ऐसा प्रोवीज़न नहीं जो इस बात का अख्तियार सरकार को दे कि वह इन इन्सपैक्टरों के खिलाफ कारवाई कर सके और ना ही यह बिल इस किस्म की ताकत सरकार को देता है । कोई ऐसी पावर नहीं ली जा रही जिस से इस पर चैक हो और ना ही सरकार का ख्याल है इस तरह के अख्तियार लेने का । इस लिए मैं समझता हूं कि कुरपशन की जो सरकार की दूर करने की तय शुदा पालिसी है यह बिल उस के खिलाफ है ।

मैं इस बात पर फिर ज़ोर देना चाहता हूं, चाहे आप कहेंगे कि बार बार एक ही बात को कह रहा है, कि सरकार इन्सपैक्टरी राज को दूर करने के लिए कोशिश नहीं कर रही । इन्हों ने इस बिल के स्टेटमैंट आफ आबजैक्टस और रीज़न्ज़ नें कुछ बातें दर्ज की है । जिन की वजह से यह बिल लाया जा रहा है इस के बारे में कोई अर्ज करू तो फिनांस मिनिस्टर साहिब कहेंगे कि बार बार रीपीट किया जा रहा है पर हम ने देखा है कि रीपीट करने का असर ही सरकार पर होता है चाहे मामूली ही हो, इस बिल के बारे में ब्योपारियों ने हां हुल्ला किया और बार बार इस बात पर ज़ोर दिया कि इस बिल के प्रोविज़न को नर्म किया जाए । तो इस का नतीजा यह हुआ कि इन प्रोवीज़न को कुछ ढीला कर दिया गया है । इस लिए मैं समझता हूं कि इस बिल में ऐसा प्रोवीज़न लाया जाए जिस से इन्स्पैक्टरी राज कम हो और लोगों को आम पबलिक को और दुकानदारों को राहत मिले और ऐसा कानून हो जो लोगों और सरकार के लिए दिक्कत पैदा करने वाला न हो ।

चेयरमैन साहिब, यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि इस सेल्ज़ टैक्स अमैंडिंग बिल से ट्रेडर्ज़ में बेचैनी फैली हुई है और यह बात गलत नहीं कि समय पर जब भी ट्रेडर्ज़ ने एजीटेशन करने की कोशिश की सरकार की तरफ से उनके साथ वायदे किए गए और उन तमाम वायदों के उल्ट यह बिल पेश किया गया है और उन के साथ किए गए वायदों को पूरा नहीं किया गया । इस लिए मैं समझता हूं कि इस बिल को लाने की जरूरत न थी । इस से यह कहीं बेहतर होता कि इस बिल को अगले बज्ट सैशन में लाया जाता और ब्यौपारियों से ट्रेडर्ज़ से और पब्लिक मैन से मिल कर इस बात पर अच्छी तरह से विचार कर लिया जाता ।

आज चेयरमैन साहिब, पंजाब की क्या हालत है। पंजाबियों के दिलों पर और सारे शरीर पर जख़्म है और कुछ किसम की समस्याएं पैदा हो गई हैं इस वक्त इस तरह का बिल लाना लोगों को और तंग करना है और पंजाब की गरीब जनता पर और ज्यादा बोझ लादने की बात की जा रही है । और सरकार अगर यह चाहती है कि लोगों को राहत मिले तो इस तरह का कानून लाना उस बात की उलंघना करता है । यह वक्त इस तरह का बिल लाने के लिए मुनासिब न था और इस के लाने से लोगों के अन्दर सरकार अनरैस्ट पैदा करेगी ।

चेयरमैन साहिब, मैंने अब तक कुछ असूलन बातें इस बिल के बारे में कहीं हैं। अब मैं दो चार जो प्रोवीजन इस बिल में मुनासिब नज़र नहीं आते हैं उनके बारे में अर्ज़ करना चाहता हूं। सब से पहले इस बिल में तमाम डीलर्ज को खाह वह रजिस्टर्ड हैं खाह वह अनरजिस्टर्ड हैं इस की प्रव्यू में लाया गया है जो कि पहले नहीं था और इस तरह से इन्सपैक्टरों के अख्तियार का दायरा वसीह कर दिया गया है"। पहले तो यह था कि जो अनरजिस्टर्ड डीलर्ज़ थे उन्हें भी इन्सपैक्टर डांट डप्ट कर के 10 या 20 रूपए लेकर चल देता था लेकिन अब कानून में इस बात की प्रोवीजन कर देने से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वह किस कदर उन बेचारों छोटे दुकानदारों को तंग करेगा और हर जाइज और नजाईज़ तरीका से रिशवत लेगा। तो जैसा कि मैंनें पहले ही अर्ज़ किया है यह सख्ती ट्रांसफरेबल है। इस सारे का भार कन्ज्यूमर पर पड़ता है चाहे दुकानदार 100 रुपया दे या 10 दे। इस लिए चेयरमैंन साहिब, मैं यह समझता हूं और मेरी ऐसी भावना है कि सरकार इस में किसी रिवेन्ज की भावना से काम कर रही हैं। इस तरह करना जरूरी न था।

यह बात तो किसी से भूली हुई नहीं कि हमारा 70 फीसदी देश देहात का है और आप जानते हैं कि देहात में छोटा व्योपारी होता है और वह ऐसा है जो बिलकुल अनपढ़ और उसे ना पता है कि कानून क्या है न उसे यह पता कि टैक्स कितना देना है और न ही वह हिसाब-किताब रख सकता है। उस को आप यह बिल पास करवा कर इन्सपैक्टरों के रहम पर छोड़ रहे हैं। इस के बारे में मैं इतना ही कह देना चाहता हूं कि अगर आप इस तरह के अख्तियार इन्सपैक्टरों को देंगें और लोगों को तंग करेंगे तो इस का नतीजा सरकार को भुगतना पड़ेगा।

दूसरी बात लिमिट के बारे में है। (विघन) मैं इस के बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता सिरफ इतना ही कहना चाहता हूं कि यह लिमिट 50 हज़ार ही रखनी चाहिए इस को कम नहीं करना चाहिए।

एक बात, चेयरमैंन साहिब, रूपया जमा कराने के बारे में है, पहले भी इस तरह का प्रोवीज़न है प्रापर्टी टैक्स के बारे में कि जो रकम असैस की जाए वह पहले जमा कराई जाए और फिर अपील की जा सकती है वरना नहीं। इसी तरह का प्रोवीज़न इस बिल में भी है। मैं समझता हूं कि यह एक पैनलटी है और नैचरल जसटिस के खिलाफ है। आखिर जब आप अपील का अख्तियार देते हैं तो इस बात का कि जो फैसला आसेसिंग अथौर्टी ने दिया है उस के खिलाफ अपील की जाए तो यह किस तरह की प्रोविज़न है कि वह पैसे पहले भरे और बाद में अपील करे। यह एक गलत बात है। यह ठीक है कि सरकार को पैसा चाहिए और वह चाहती है कि पैसा पहले जमा करवा दिया जाए और बाद में अपील करे। परन्तु यह कोई इन्साफ की बात नहीं और फिर आप जानते हैं कि उस का रिफण्ड लेने में सालों लग जाते हैं। अगर 50 रुपए वापिस लेने हों तो इतनी ही उस बेचारे की रिश्वत लग जाती है ट्रेजरी वालों और इन्सपैक्टरों को देने में। यह बिलकुल गलत बात है और जो अपील करने का

[श्री सागर राम गुप्ता]

राइट कान्सटीच्यूशन में दिया हुआ है उस के मुनाफी है । चेयरमैन साहिब, जब किसी को 20, 30 रूपये जुर्माना या कैद की सज़ा दी जाए तो उस के खिलाफ भी अपील का हुकम है और इस के बारें में भी टाईम लिमिट रखा हुआ है । लेकिन इस बिल में पहले पैसा जमा कराने की बात अनकान्सटीच्यूशनल है। जो इस में लाई गई है ।

चेयरमैन साहिब, आप फिर कहेंगे कि रिपीट करता हूं लेकिन इतना ज्यादा महसूस करता हूं कि कहे बिना नहीं रह सकता । इस बिल में प्रोवीज़न है कि जो जुल्म करनें वाला है वही इन्साफ करने वाला है । असेसिंग अथारेटी को ही मुनसिफ बना दिया गया है कि वह अपील को सुने और इन्साफ करे । यह किसी तरह से भी नैचरल जसटिस नहीं कहा जा सकता । सरकार का विचार ही नहीं था बल्कि सरकार ने हिम्मत की और ज्यूडीशरी को ऐगज़ैकटिव से अलग किया और चेयरमैन साहिब, आप को याद होगा कि जब चीफ़ जसटिस आफ इन्डियन यहाँ पर उस फन्कशन को इनआगोरेट करने के लिए आए थे तो उस वक्त यह सवाल उठाया गया था कि पुलिस और ऐगज़ैकटिव के पास सी० आर० पी० सी० की दफात 107, 110, 111 और 112 के आधीन अख्तियारात हैं । तो उन्होंने कहा था कि यह अख्तियारात भी पुलिस और ऐगज़ैकटिव के पास नहीं रहने चाहिएं । क्योंकि यह सैपेरेशन के असूल के खिलाफ है । लेकिन इस बिल में इस तरह की पालीसी को नहीं अपनाया जा रहा और अपील सुनने का अख्तियार असेसिंग अथारेटी को ही दिया जा रहा है । मैं State Board for Co-operative Construction Societies का मेम्बर हूं जो कि ठेकेदारों के खिलाफ अगर पी० डब्लयू डी० के अफ़सरों ने फैसला दिया हो तो उस की अपील को सुनता है । मैंने स्टेट कुआप्रेटिव बोर्ड में कहा था कि यह बिलकुल गल्त बात है । मैं ने यह भी कहा था कि इन्साफ देना इतना जरूरी नहीं जितना कि इन्साफ देने वाले को यह महसूस करा देना कि उसे इन्साफ मिलेगा इस लिए सरकार हिम्मत करे और असेसिंग अथारेटी के खिलाफ अपील उसी महकमा में ना दे कर कोर्ट को दे दे ताकि इस में जो कुरपशन होती है वह दूर हो । इस से कुरपशन भी दूर होगी और लोगों को इन्साफ भी मिल सकेगा । बेहतर तो यह होगा कि इस बिल को वापस ही ले लिया जाये। अगर वापस नहीं ले सकते तो इस में टरेडर्ज़ की राय लेकर, जनता की राय लेकर कुछ और अमैंडमैंट्स लानी चाहियें ताकि लोगों को और ज्यादा तकलीफ ना हो ।

खान अब्दुल गफ्फार खां (अम्बाला शहर) : जनाबे वाला, यह बिल जो कि एक तरमीमी बिल की शक्ल में हाउस के सामने पेश हुआ है इस के मुतअल्लिक मैं आप की खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूं कि यह एक ऐसा बिल है जिस से पंजाब का हर शख्स मुतअासर है। फारसी का एक शेयर है :—

हर बलाये कज़ा आसमाँ, आयद खाना अनवरी जोयद कुजा बाशुद

यानी जो बला आसमान से टपकती है वो अनवरी का घर ही ढूंढती है । कोई भी बला क्यों न हो उसका असर हमेशा व्यौपारियों पर पड़ता है, या गरीब लोगों पर पड़ता है । इसके मुतअल्लिक व्यौपारियों का एक अहम तबका इस लिए कराह रहा है क्योंकि वह समझते हैं कि हम पर जुल्म हुआ है । वो खुद कहते हैं कि हम पर अन्याय हुआ है, जुलम हुआ है और बहुत ज्यादती हुई है। ठीक है मगर देखने वाली बात तो यह है कि क्या वाकई उनके साथ बे इन्साफी हुई है । यहां पर हमारे फिनांस मिनिस्टर साहिब ने कहा है कि यह बिल वापिस नहीं हो सकता और न ही इसमें कोई तरमीम होगी ।

वित्त मन्त्री : किसने कहा है ?

खान अब्दुल गुफार खां : जनाब फिनांस मिनिस्टर बहादुर–दौलत मदार–दाम इकबाल हूं ने । (हंसी)

वित मन्त्री : यह मेरा हक नहीं है, यह हाउस का राइट है ।

खान अब्दुल गुफार खां ; मगर आपने कहा है । अगर आप इतने एडेमेंट हैं, इतने रिजड हैं यह हमें रबड़ की मोहरें समझते हैं कि जो भी चाहें यह दस्तखत कर देंगे । यह ठीक है कि यह पास जरूर हो जाएगा मगर क्या, जनाब, मैं पूछ सकता हूं कि तीन दिन से इस पर बहस हो रही है । वज़ीर साहिब ज़रा गौर फरमाएं कि आया एक भी मेम्बर इसके हक में अब तक बोला है ?

वित्त मन्त्री : सब हक में हैं, खान साहिब ।

Khan Abdul Ghaffar Khan : Not a single Member supported this Bill that is why Chief Minister has said that he was going to make amendments in this Bill.

बाकी रही यह बात कि विप जारी होता है इसके होने पर आप कहेंगे कि पास करना है। हम भी कहेंगे कि पास करना है, हां मगर न भी करेंगे तो पास हो ही जाना है । मजबूरी का नाम जबर है । मैं मुख्तसर तौर पर अर्ज़ कर रहा हूं क्योंकि आप का इरशाद है कि कोई भी बात रिपीट न की जाए । मगर जनाबेवाला, मुझे यही कहने से हरगिज़ इन्कार नहीं है कि यह एक तबका के साथ ज्यादती हो रही है, सख्ती हो रही है । हमें सच्ची बात तो कहनी ही पड़ती है । जब, जैसे वज़ीर साहिब ने यह फरमा दिया कि हम वापिस लेने वाले नहीं हैं मगर जब एक चीज़ बार बार कही जाए तो उसका असर तो ज़रूर होता ही है। जैसे पानी का कतरा कतरा पत्थर पर अगर गिरता है तो वह भी घिस जाता है । शायद इस पत्थर पर भी कुछ असर हो जाए ।

[Khan Abdul Ghaffar Khan]

मैं दो-तीन बातें कह कर अपनी बात को खत्म करूंगा। एक तो जो आपने आमदनी का क्वायंटम रखा है यह मुनासिब नहीं, इस के हल्का में बहुत ज्यादा लोग आ जायेंगे जिस में छोटे दुकानदार भी हो सकते हैं, इस से कुरप्शन बढ़ेगी। हमारे मिनिस्टर साहिब तो खुद चाहते हैं कि कुरप्शन न हो, मगर यह बढ़ती जा रही है क्योंकि आप ऐसी चीज़ करते हैं जिससे कुरप्शन इंडायरैक्ट तरीका से बढ़ती है। कुरप्शन करने वाला तबका इससे एनकरेज होता है इसलिए मैं कहूंगा कि एक तो आप यह करें कि आमदनी का क्वायंटम 60 हज़ार रुपये या उससे अधिक कर दें।

दूसरी बात जो मैं कहनी चाहता हूं वह यह है कि आप तो कहते हैं कि टैक्स की इवेज़न होती है मगर दूसरी तरफ जो व्यौपारी लोग हैं वह कहते हैं कि सरकारी मुलाज़म तंग करते हैं। यह एक विशियस सर्कल सा बन गया है। आपके इन्स्पैक्टर कहते हैं कि व्यौपारी लोग टैक्स नहीं देते और जो व्यौपारी हैं वे कहते हैं कि यह हमें परेशान कर रहे हैं। मैं तो खुद हैरान होता हूं, जब सुनता हूं, कि टैक्स की वेज़न होती है। एक बात आप मुझे बताएं कि आखिर इवेज़न करने वाला है कौन। Charity begins at home. अगर आप इवेजन बन्द करना चाहते हैं--बेईमानी बन्द करना चाहते हैं तो वो तरीका अख्तियार करें जिस से वह बन्द हो। आप जो इस के इन्सपैक्टर--सब इन्सपैक्टर हैं उनके ज़रा घरों में जा कर तो देखो, उनके लिबास को देखिए, कैसे बन संवर कर निकलते हैं और शाहाना ठाठ से रहते हैं। मैं आपसे अर्ज करूंगा कि जो बड़ा लम्बा चौड़ा हल्का आपनें बनाया है उसको ज़रा मुलाहज़ा फरमायें (वज़ीर साहिब किसी से बातें करने लग गये) खैर कोई बात नहीं ख़ाह कोई सुनें या ना भी सुनें मै इनके बहरे कानों तक अपनी आवाज बुलन्द करता जाऊंगा। इसलिए मैं फिर भी यही कहूंगा कि यह क्वायंटम ज्यादा करना चाहिए। जहां तक सरकारी मुलाज़मों के मुतअल्लिक कोई बात मेरे इलम में है, मैं आपसे यही अर्ज करूंगा कि आपके अमला के 75 फीसदी आदमी कुरप्ट हो चुके हैं, उनकी बीसियों मिसालें मेरे सामने मौजूद हैं, मगर मैं कहना नहीं चाहता। क्योंकि इससे उनको नुकसान पहुंचता है। इसके साथ ही मैं यह भी कह दूं कि जो भी कुछ करता है वह उस वक्त तक नहीं कहता जब तक कि उसको किसी बड़े अफ़सर, मिनिस्टर या डिप्टी मिनिस्टर तक ओहदे वाले की तरफ से हिमायत हासिल न हो। उनको मलूम है कि फलां हमारे साथ है। हम ऐसा कर सकते हैं।

दूसरी बात यह है कि आपने बड़े फख्र से कहा था कि मैंने जुडीशरी और ऐग्ज़ैक्टिव को अलग कर दिया है। ठीक है वह आपके हाथों से ही इम्पलीमैंट हुआ था। इसके लिए आपको मुबारिकबाद है लेकिन उसके लिए मुबारिकबाद उनको भी है जिन्होंने इनीशिएटिव लिया था। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब आप यह कहते हैं और करते भी हैं तो फिर इस बिल में अपील सुनने का भी अख्तियार और किसी अथारिटी को क्यों नहीं देते। मैं फिनांस मिनस्टर को एक शेर सुना कर अपनी तकरीर खत्म करता हूं।

खुद ही कातिल खुद ही साहिद खुद ही मुंसिफ ठहरे
अकरबा मेरे करें खून का दावा किस पर।

आप मेरी बात पर गौर कर लीजिये और अपील का अख्तियार किसी दूसरी अथारिटी को सौंप दीजिए। जहां तक टंडन साहिब की बात का ताल्लुक है. मैं कह सकता हूं कि अगर व्योपारी 20 करोड़ रुपया देने के लिए तैयार हैं तो इसका मतलब यह है कि बहुत ज्यादा इवेज़न होता है। और हो सकता है कि 60 करोड़ तक की आमदनी हो जाए। इसलिए इस पहलू को गौर से देखा जाए। मगर जहां तक कंज्यूमर को टैकस करने का सवाल है, मैं समझता हूं कि उस पर बोझ न डाला जाए।

Mr. Chairman (Shri Ram Saran Chand Mital): Shri Mehta.

Chief Parliamentary Secretary (Shri Ram Partap Garg):

Sir, I beg to move—

That the question be now put.

Enough discussion has taken place on this Bill We have already taken two days on this Bill and today is the third day. Two more Bills have to be passed.

श्री चैयरमैन : अभी तक इस पर 10 मैंबर्स बोल चुके हैं और ग्याहरवें मैम्बर साहब को मैं ने कांल अपौन कर लिया है। मैं समझता हूं कि मैम्बरों को बोलने का मौका मिलना चाहिए। (So far ten Members have participated in the discussion on this Bill and I have called upon the eleventh Member, I feel sufficient opportunity should be given to the Members to express their views.)

Chief Parliamentary Secretary. Sir, I have already moved the motion that the question be now put.

Mr. Speaker in the Chair.

श्री अध्यक्ष : श्री मित्तल जो अभी यहां पर प्रीज़ाईड कर रहे थे, ने बताया है कि उन्होंने श्री रूपालाल जी को काल अपौन कर लिया है, इस लिए अब कुछ समय के लिए श्री रूपलाल जी बोलेंगे। (Shri Mittal who was just a while ago presiding over the meeting, told me that he had called upon Shri Roop Lal Mehta to speek on the Bill. So Shri Roop Lal will make a speech for some time.)

श्री रूपलाल मेहता (पलवल) : इस बिल को जो अमैंड करने के लिए लाया गया है, इस पर तीन दिन से बहस हो रही है। इसका यह मंशा है कि जो नुकायस रह गए हैं 1948 के बिल में उनको दूर किया जाए। आबजैक्ट नेक है, इसलिए उसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन मेरी गुज़ारिश यह है कि यह बिल जिस शक्ल में है अगर ऐसा ही पास कर दिया जाए तो पहले से भी ज्यादा बोझ डालने वाला बन जाता है। इसलिए मैं फाइनैंस मिनिस्टर साहिब को अपील करूंगा कि जो इतना सख्त बिल आप पास करने जा रहे हैं उसको जांच पड़ताल करने के बाद पास कीजिए। आपने देखा है कि इसका आपोज़ीशन सभी सैक्शन्ज़

[श्री रूप लाल महता]

से हुआ है और हाउस में तकरीरें होने से पहले आपको व्योपारियों के डैलीगेशंज भी मिल चुके हैं उन्होंने भी खदशात जाहिर किए हैं और कानफ्रैंस भी हुई है। इसका मतलब साफ़ है कि इसका असर उल्टा होने वाला है। इस लिए इस पर सोचविचार करलेना ज़रूरी है। यह कहा गया है कि यह तो पुरानी मिनिस्ट्री का ड्राफ्ट किया हुआ पड़ा था, तब तो फिर आपको और भी एहतियात से इस को पेश करना चाहिए था। मैं गनीमत समझता हूं कि जब चीफ मिनिस्टर साहिब ने आपोज़ीशन को सुना और तमाम राए उनके सामने आई तो उन्होंने कहा कि इसकी क्लाजिज़ में सुधार कर दिया जाएगा।

जहां तक व्योपारियों का ताल्लुक है, यों तो वह गवर्नमैंट के आनरेरी टैक्स कलैक्टर्स हैं लेकिन उनको जितनी सख्तियां बर्दाश्त करनी पड़ती हैं अगर मैं सुनाने लगूं तो वह बहुत लम्बी चौड़ी दास्तान होगी। हमारे सूबे की आसपास की स्टेटस में जो कानून है, जैसे राजस्थान में, यू० पी० में और दिल्ली में उससे व्योपारियों को बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है इस लिए कम से कम आप उनके भी खदशात से और स्टेट में हो रही सख्तियों से नसीहत ले कर एक ऐसा बिल तैयार करते जिससे सारी खामियों को दूर किया जाता और जनता को रिलीफ होता व सरकार को फायदा होता और बदनामी न उठानी पड़ती। मेरे ज़िले के व्योपारी यहां आए और सरदार कपूर सिंह जी को मिले, तो इन्होंने कहा कि बिल को आसान किया जाएगा लेकिन कुछऐसी धाराएं यहां आई हैं जिस से साफ़ मालूम होता है कि इसको आसान तो क्या किया है। और कई मुश्किलातें आ जाएंगी अगर ऐसे ही पास कर दिया गया तो। जो नई क्लांज इन्ट्रोडूस हुई है और जो एमैन्डमेन्ट की जा रही है यह क्लाज़ 13 है जिस से पुराने एक्ट की सैक्शन 20 की अमेन्ड किया गया है। क्लाज 17 के ज़रिए एक्ट की सैक्शन 27 को अमेन्ड किया जा रहा है। क्लाज़ 12 के ज़रिए सैक्शन 14 को अमेन्ड किया जा रहा है। इन क्लाज़ों की ज़रूरत नहीं थी। मैं कहता हूं कि यह काला बिल है। यकीनन काला बिल ला कर सरकार व्योपारियों को अपने भरोसे में नहीं ले रही है। वह सरकार को करोड़ों रुपया इक्ट्ठा कर के देते हैं उन्हें सहुलियतें दी जानी चाहिएं। व्योपारी करोड़ों रुपया इक्ट्ठा करते हैं। ठीक है ब्लैक शीप भी होते हैं। स्पीकर साहिब, यह हर एक महकमा में और हर एक जगह मौजूद हैं। जहां ऐसे लोग होते हैं इस का मतलब यह है कि ऐसे लोग समाज द्रोही और देश के दुशमन होते हैं व्योपारी सोशल समाज और आर्थिक नीति और इन्डस्ट्री और व्योपार के स्तम्भ हैं सरकार उन के बल बोते पर चलती है। आज हम उन पर डिस्ट्रस्ट करते हैं, और आज देश का इकनामिक स्ट्रक्चर तोड़ना चाहते हैं जिस से व्योपारी लोगों पर से एतबार उठ गया है। अगर वह एक पैसे की हेराफेरी करते हैं तो देश के साथ गद्दारी करते हैं, इन्साफ नहीं करते। यह नहीं कि उन्हें इस तरह से जकड़ दें। मेरे गाँव में एक स्कैन्डल हुआ। टैक्सेशन डिपार्टमेन्ट का

एक अफ़सर जीप ले कर वहां आया और उस आदमी की पड़ताल करने लगा । बाद में उस आदमी पर मुकद्दमा चला और एडमिनिस्ट्रेशन के वकार का सवाल पैदा हो गया। केस अपील में चला गया । लेकिन मैं कहता हूं कि जो ऐसे वाक्यात होते हैं इस लिए सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं । मैं मित्तल साहिब के नोटिस में भी लाया था । वह ई० टी० ओ० रिश्वत बहुत खाता था। मैंने मित्तल साहिब को जबकि वह मन्त्री थे कहा था तो उन्हों ने उस को कहा था गुडगांवा ज़िला में एक ई० टी० ओ० था । मित्तल साहिब नें उस ई० टी० ओ० को बदल दिया था। खैर, खुशकिस्मती से वह बदल गया । उसने 4 व्योपारीयों को हवालात में बंद कर दिया, महज़ इस लिए कि उनके हिसाब किताब में कुछ गलती थी । उनके साथ ऐसा सलूक किया गया । क्योंकि उन्होंने शरात टूटने का महकमें को सूचित नहीं किया था । उन को नोटिस भेज दिया और आरबिटरेरी टैक्स लगा कर 4 व्योपारियों को अंदर डाल दिया। डी० सी० को मैंने कहा कि जेल में बंद रखने से रुपया वसूल नहीं होगा इनको अवसर दें, बाहर जाकर कि यह रकम का प्रबन्ध करें और वह छोड़ दिए गए । वित्त मंत्री साहिब हैरान होते हैं कि व्योपारी पकड़े जाते हैं, व्योपारियों को जेल में डाला जाता है । डी० सी० को अख्तियार है कि वह उन्हें 40 दिन तक अंदर कर सकता है । और वह जो रोटी खाएं उस रोटी का खर्च भी उन से बसूल किया जाए । यह हालत है एडमिनिस्ट्रेशन की जो व्योपारियों के साथ ऐसा करती है । यह जो चार पांच क्लाज़ें हैं यह बताती हैं। मगर मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता । व्योपारियों के साथ हार्डशिप होती है, सरकार यह अमेंडमेंट्स कर रहा है । मैंने इस बिल में एक अमेंडमेंट दी है । व्योपारियों के मकद्दमात डिस्ट्रिक्ट सैशन जज के सिवा कोई न सुने । सरकार ने प्रान्त में जुडीशरी को यहां सैपेरेट कर दिया है । पंजाब ने हिन्दुस्तान को एक न्या सैट अप दिया है । जो व्योपारी सरकार को रेवेन्यू का करोड़ों रुपया इकट्ठा करके देते हैं उन के अपील महकमें में ही सुने जाते हैं । इस लिए उन को टैक्सेशन डिपार्टमैंट से छुट्टी दे कर उनकी अपील डिस्ट्रिक्ट ऐंड सैशन जज के पास जाया करे और वह इसकी समायत करे । मैं कहता हूं कि टैक्सेशन के महकमें में असिस्टेंट टैक्सेशन अफ़सर से लेकर सब के पास रिश्वत चलती है, डिस्ट्रिक्ट टैक्सेशन अफ़सर भी रिश्वत लेता है । मैंने कई बार सोचा कि उन लोगों के नाम लूं लेकिन व्योपारी कहते हैं कि हमारा तो काम बन गया । अगर वह व्योपारी से 5 लेते हैं तो 2 सरकार को देते हैं और 3 आपने पास रखते हैं । जो सेल्ज़ टैक्स के वकील हैं उन का भी हिस्सा है । इस लिए आप व्यापारियों से टैक्स एक स्तर पर लें ताकि हेरा फेरी की गुंजाइश न रहे, उनको इंस्पैक्टरों के रहम पर न रखें । व्योपारी इतना रुपया टैक्स का लेकर देंगे । उन्हें रिटर्नें बनानी पड़ेंगी, दौड़ धूप करेंगे । वे 10 या 20 रुपए इंस्पैक्टर को देंगें और अपना पीछा छुड़ाएंगे। व्योपारियों पर विश्वास करना चाहिए । हर इंस्पैक्टर की मंथली बंधी हुई है । पिछले दिनों एक मंत्री के पास इंस्पैक्टर आए और उन्हों ने अपना ग्रेड वढ़ाने के

[श्री रूप लाल महता]

लिए कहा । तो वज़ीर साहिब ने कहा कि तुम्हारा ग्रेड क्या बढ़ाएं तुम्हारी तो मंथली बंधी हुई है । वे व्योपारियों से रिश्वत लेना नहीं छोड़ते । समाज के कोने कोने में इसकी चर्चा है । जो डेढ़ डेढ़ दो दो लाख के मालिक हैं वे इनके हाथों में आ जाते हैं । मैं देखता हूं कि व्योपारियों को हैरान किया जा रहा है, क्यों न उन के घर पर जाकर असैसमैंट कर ली जाए । अगर इस तरह सख्ती से काम करना है तो यह ठीक नहीं । इस वक्त 59 हज़ार व्योपारी हैं जो सरकार के पास रजिस्टर्ड डीलर्ज़ हैं । पता नहीं एक व्यापारी के हिसाब में क्या गलती थी । उस पर 56,000 रुपया डाल दिया गया । वह कहते हैं कि जितना बनता है वह ले लो । उन के साथ हमदर्दी का सलूक करना चाहिए । जब उन लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है तो यह ठीक नहीं । उन लोगों के साथ इन्साफ का रास्ता अख्तियार करना चाहिए । आप ने इस एक्ट को अमेंन्ड करना है और इस बात को लेकर अपोज़ीशन के लोगों ने सारे पंजाब के वायूमन्डल को खराब किया । व्यापारियों को उकसा कर हड़ताल करवाई । अगर सरकार अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकती तो एक्सपर्ट लोगों की ओपीनियन लेती और मंत्री महोदय उस के मुताबिक बिल लाते । मुख्य मंत्री ने एलान किया । वह दो चार एलान और कर देते ताकि पंजाब के हर रहने वाले को पता लग जाता । व्योपारी इंस्पैक्टर लोगों की तरफ से गालियां खा कर रुपया इकट्ठा करके देता है । मैं मुख्य मंत्री से अर्ज़ करूंगा कि इस मामले में जुडीशरी को सैपरेट करें । जो डिपो-होलडर हैं वह सरकार के गुदामों से राशन का माल लेते हैं उन्होंने लाइसेंस तो लिए हुए नहीं हैं और इंस्पैक्टर कहता है कि जो माल खरीदते समय सेल्ज़ टैक्स वे देते हैं, सेल्ज़ टैक्स पुनः दो । मैं वित्त मंत्री साहिब से कहूंगा कि उन को सारे सेल्ज़ टैक्स की जो उन्होंने दिया है एग्ज़ैंपशन दी जाए । वरना इंस्पैक्टर कहदेंगे कि उनकी इतनी सेल हो गई । (शोर) वित्त मंत्री साहिब ने दया करके कहा कि जिन से ज्यादा टैक्स वसूल किया जा चुका है उनको मुजरा कर देंगे । कमिशनर साहिब कहते हैं कि रिफंड करने का कानून नहीं । मैंने कहा कि जनाब वित्त मंत्री साहिब ने कहा है कि उसे टोटल रेट पर रिबेट लेने का हक है । मैंने कहा कि कुछ तो भला होगा ।

(ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਵਿਘਨ)

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ਼ ਆਰਡਰ, ਸਰ । ਇਹ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਕੀ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ?

ਵਿਤ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੈਂ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ।

श्री रूप लाल महता : जो डिपो-होल्डर हैं वे सरकार से माल ले कर बेचते हैं । उनको चैकिंग होगी । उनकी सेल 50,000 रु० से ऊपर जाती है। रूल कहता है कि उन्हें लाइसैंस देना चाहिए लेकिन डिपार्टमैंट कहता है कि

अगर उस की सेल 50,000 रु० की होगी तब देंगे। तो मैंने वित्त मंत्री से कहा कि इन्हें पिछली रकम मुजरा देनी चाहिए। फिनांस मिनिस्टर साहिब मान गये मगर कमिश्नर साहिब ने कहा कि कानून के रूल से उन्हें टैक्स देना पड़ेगा मगर वित्त मंत्री महोदय ने मेरी प्रार्थना स्वीकार की और कहा कि जो सरकारी गोदामों से या फिलोर मिलों से सेल्ज़ टैक्स देकर माल लाये हैं और उन्होंने लाईसैंस नहीं लिये हैं वह लाईसैंस ले लें परन्तु वह दिये हुए टैक्स को मुजरा ले सकते हैं। मगर अफसर हमेशा रूकावटें पैदा करते हैं जिस से सरकार बदनाम होती है। मैं बिल का विरोधी नहीं हूं। देश की उन्नति के लिये टैक्स लगाने पढ़ते है परन्तु लगाते समय हर बात को ध्यान में लाना चाहिये ताकि विरोधी दलों के लोग सरकार के विरूद्ध लोगों को गुमराह न कर सकें और जो इस बिल में सख्त दफ़ात हैं उनको ढीला किया जाये। मुख्य मंत्री महोदय ने बहुत अच्छा किया कि कुछ रियायतें घोषित कर दीं।

आप कोई ऐसी बात करें जिस से लोग आप का नाम हमेशा के लिए याद रखें कि ऐसी सरकार आई कि उसने इन्सपैक्टरों के जुल्मों सितम से निजात दिलाई। इन शब्दों के साथ मैं अर्ज़ करता हूं कि मैं टैक्स का विरोध नहीं करता लेकिन मैं यह कहता हूं कि इस टैक्स को व्योपारियों को हैरान किए बगैर अच्छे ढंग से वसूल करें।

Shri Ram Partap Garg (Chief Parliamentary Secretary) : Sir, I beg to move—

That the question be now put.

(*Interruption and noise in the House. Voices : No, no. Some hon. Members rose to speak*).

Mr. Speaker : There has been enough debate.

Motion moved—

That the question be now put.

Mr. Speaker : Question is—

That the question be now put.

The motion was carried.

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਤਵਾਤਰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਿਲ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦਸੀਆਂ ਹਨ । ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਕੁਝ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸਾਂ । ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਵਾਤਰ ਖਿਆਲ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਐਨੀ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਇਵੇਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ

[ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ]

ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਿਥੇ ਵੀ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰਕੇ 1963-64 ਵਿਚ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹੋ ਚਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਬੜੀ ਮੰਗ ਆਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿਤਾ । ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਣਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆ ਗਈ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਡਿਮਾਂਡ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਥੋੜੀ ਨਰਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਗਜ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਕਈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ 24 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਗਜ਼ਟ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੈਂ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਾਊਸ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਅਲੁੱਕ ਰਖਦੇ ਸੀ ਰਖੇ । ਉਸ ਵਿਚ ਮਿਤਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਤੇ ਤੇ ਭੇਜੀ ਪਰ ਉਹ ਇਥੇ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਜੋ ਕਿ 26 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਯਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਨ......।

ਪੰਡਿਤ ਸੁਰੇਂਦਰ ਨਾਥ ਗੌਤਮ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ । ਫਿਨਾਂਸ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ 24 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਗਜ਼ਟ ਹੋਇਆ ਤੇ 26 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਇਹ ਹੋਈ । (ਹਾਸਾ)

Mr. Speaker : This is no Point of Nrder. The hon. Member should please resume his seat.

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ : ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਉਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਹਰ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਗਲਬਾਤ ਹੋਈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਜੋ ਰੂਲਜ਼ ਬਣਨੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰੇਗੀ । ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਉਸ ਘਰ ਦੀ, ਜਿਥੇ ਕਿ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿਤੀ । ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ । ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਜ਼ਾਤੇਖੁਦ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬੁਰਾ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਇਸ ਕਲਾਜ਼ ਦਾ ਜੋ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸਬੰਧ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਕਹੋਗੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲੀਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ । ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਲਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣਾ ਸਟਾਕ ਕਢੇ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪੰਡਤ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਚੇ ਤੇ ਫ਼ਿਰ

ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਸਟਾਕ ਕਢੇ ਤੇ ਚੈਕ ਕਰੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁੜ ਔਖਿਆਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਝਗੜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰੀਨਿਊਅਲ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇਕ ਫਾਈਲ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਂਣੇ ਦੇ ਦੋ ਵਪਾਰੀ ਚਾਰ ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲਾ ਕਢ ਦਿਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਇਵੇਜ਼ਨ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਤਨਾਂ ਅਰਸਾ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਸ ਵਿਚ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਈਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਇਵੇਜ਼ਨ ਰੁਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਰਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦੀ ਕਿ ਖਰਾਬੀ ਕਰੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿਥੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਜਿਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਕਿ ਜਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਠੀਕ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਖਦਾ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਗਲਤ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਸੇਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਦੋ ਦੋ ਰਖਦੇ ਹਨ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਡੀਲਰਜ਼ ਦੂਸਰੇ ਡੀਲਰਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੈਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰੇ।

ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਉਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੇ ਰੀਨੀਉਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਅਸਲੀ ਅੜਚਨ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਕ ਵਾਰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਫੱਟੇ ਵੀ ਲਾਹ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ 5, 7 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਉਪਾਰੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਉਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਉ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਆਖਰੀ ਇਨਸਟਾਲਮੈਂਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਟੋਮੈਟੀਕਲੀ ਰੀਨੀਊ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਬਿਉਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿਤੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਿਉਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ 30 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਿਉਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਕਿ ਬਿਉਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੈਰਾਸਮੈਂਟ ਰੁਕ ਸਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਡਿਮਾਂਡਜ਼ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਡਿਮਾਂਡਜ਼ ਮਨ ਵੀ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਇਵੇਜ਼ਨ ਰੁਕਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਨਸਿਡਰ ਕਰਨ ਲਈ 30-10-65 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ 29 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਬਿਉਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਮਾਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਈਵੇਜ਼ਨ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ

[ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ]

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਫਤਵਾ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਫਿਨਾਂਸ ਮਨਿਸਟਰ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਬਣ ਗਏ ਹਨ । ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫਤਵਾ ਮਿਲਿਆ । ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਮੈਂ 1942 ਵਿਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ ਸੀ (ਵਿੱਘਨ)

ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੈਕਰਟਰੀ ਸੀ । ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਿਉਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿਉਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ 30 ਤਾਰੀਖ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਰਖੀ ਲੇਕਿਨ ਬਿਉਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿਤੀ । ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਉਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 25, 26 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ । (ਵਿੱਘਨ) ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਉਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ । ਬਿਉਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਰੀਪ੍ਰੀਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮਪਾਰਟੈਂਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਇਮਪਾਰਟੈਂਸ ਰਖਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿਤੀ । ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕੀਤੀ । (ਵਿੱਘਨ) ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਦਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ । ਇਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਉਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਡੀਮਾਂਡਜ਼ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ । ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਦਲੀਲ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨੀਅਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰਜ਼—ਚਾਹੇ—ਉਹ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬੈਂਚਾਂ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਾਂ ਟਰੈਜ਼ਰੀ ਬੈਂਚਾਂ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ–ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਦੀ ਈਵੇਜ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ । ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗੇ ਸੁਝਾਉ ਦਿਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵੇਲੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਕਿ ਬਿਉਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਣ । (ਵਿੱਘਨ) ਅਗਰ ਉਸ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਸੁਝਾਉ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗਾ ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਕਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਲਜ਼ ਦੀ ਲਿਮਿਟ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ । ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਮਿਟ 25,000 ਕਰ ਦਿਤੀ । ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ । ਪਰ ਉਹ ਉਲਟੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਲੁਟੇ ਗਏ । ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਜਾਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਬੋਲੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ । ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਲਾਜ਼ ਆਵੇਗੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗਾ ।

Mr. Speaker : Before, I put the motion for consideration of this Bill to the vote of the House, I will put the amendments in relation to this motion to the vote of the House. Amendment No. 1 stands in the name of Shri Ram Saran Chand Mital.

1.00 p. m.

Shri Ram Saran Chand Mital : Sir, I beg to seek the permission of the House to withdraw my amendment.

Mr. Speaker : Has the hon. Member the leave of the House to withdraw his amendment ?

Voices : Yes.

The amendment was, by leave, withdrawn

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab General Sales Tax (Amendment) Bill, 1965, be circulated for eliciting public opinion thereon by the 31st December, 1965.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab General Sales Tax (Amendment) Bill, 1965, be circulated for eliciting public opinion thereon by the 1st February, 1966.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab General Sales Tax (Amendment) Bill, 1965, be referred to a Select Committee consisting of (names to be specified at the time of making the motion) with a direction to make a report by the 1st February, 1966.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab General Sales Tax (Amendment) Bill, 1965, be circulated for eliciting public opinion thereon by the 31st December, 1965.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab General Sales Tax (Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now we take up the Bill Clause by Clause.

SUB-CLAUSE (2) OF CLAUSE 1.

Mr. Speaker : Question is—

That Sub-Clause (2) of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 2

Mr. Speaker : Now Clause 2 is before the House. All the following amendments to this Clause will be deemed to have been read and moved and can be discussed along with it :—

57. Shri Yash Paul

In Sub-Clause (1), line 2, *for* "Halwai Shop" *substitute* "halwai-cum-restaurant".

58. Shri Yash Paul

Delete sub-clause (2).

121, Shri Roop Lal Mehta :

Delete sub-clause (2).

Shri Mohan Lal (Batala) : Mr. Speaker, before I formally move my amendment, I would like to have one clarification. There are several amendments of the same nature, seeking amendment of the same clause, given notice of by different hon. Members. Should I presume that the amendments would be taken up in the order of priority in which they were received in the Vidhan Sabha.

Mr. Speaker : This is right. They will be taken in that order. But where the amendment seeks to delete the clause, i.e., has the negative effect, it amounts to oppose the Clause. Therefore such an amendment is out of order.

Shri Mohan Lal : Now, Sir, I formally move—

Delete the clause.

Mr. Speaker : This is no amendment. It is out of order. It comes to opposing the Clause and the hon. Member can oppose the clause under consideration.

Shri Mohan Lal : Yes, Sir, I am opposing this clause.

स्पीकर साहिब, अभी अभी फिनांस मिनिस्टर साहिब ने सब-क्लाज़ 1 की कुछ तशरीह की थी । इस क्लाज़ के दो हिस्से हैं । जैसे आप ने देखा नम्बर एक प्रिंसीपल एक्ट में कुछ इंसरशन के लिए जो क्लाज़ बी है उस में रैस्टोरैंट, हलवाई, बेकरी शैल बी सबस्टीच्यूटिड । इस में इन्होंने कुछ तशरीह की है और अपनी इन्टरप्रेटेशन दी है । जो इन्होंने इन्टरप्रेटेशन दी है इस वक्त उन की अपनी इन्टरप्रेटेशन है । लेकिन मैं कहूंगा कि केवल यही इन्टरप्रेटेशन नहीं हो सकती । इस की और भी इन्टरप्रेटेशन हो सकती है । फिनाँस मिनिस्टर साहिब पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं वे जानते हैं कि जो एक्ट बन जाए उस में किसी मिनिस्टर की भी ओपिनियन बाईंडिग नहीं हो सकती । इंटरप्रेटिंग अथारिटी में वह पावर वैस्ट करती है । उन की अपनी इन्टरप्रेटेशन होती है । जैसे कि जब कोई एक्ट कोर्ट में जाता है तो उन की लीगल इन्टरप्रेटेशन बन जाती है । इस लिये मेरा विश्वास

है कि जो कुछ फिनांस मिनिस्टर साहिब ने कहा वह आखरी बात नहीं है । अगर ऐसा होता तो मैं इस को आगे कुएस्चन ही न करता । लेकिन यह जानते हुए कि जो कुछ उन्होंने कहा है यह आखरी वायस नहीं है। इस इन्टरप्रेटेशन में और उन की राए काबले पाबंदी नहीं । इन्टरप्रेटिंग अथारिटीज़ पर मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो इन्टरप्रेटेशन उन्होंने दी है वही नहीं और भी हो सकती है । मैं इस बात की तफ़सील में जाना चाहूंगा । इस के लिए हमें सब-क्लाज़ डबल बी से पहले इस की ओरिजनल क्लाज़ पढ़नी होगी । ओरिजनल एक्ट के सैकशन 4 के सब-सैक्शन 5 की जो डबल बी क्लाज़ है वह इस तरह से है ।

Section 4 of the original Act says—

In this Act, the expression "Taxable quantum" means......

and then there are clauses (a), (b) and so on. and it is clause (bb) which says as to what is the taxable quantum. It reads—

"(bb) in relation to any dealer, who runs a Tandoor, Loh, Dhaba, Hotel, Restaurant or other similar establishment wherein Indian food preparations, including Tea are served, Rs. 25,000."

यह है टैक्सेबल टरन ओवर जो कि दी गई है इन रीलेशन टू दीज़ एस्टेब-लिशमेंट्स एटसैटरा । इस में एक बात तो यह है कि इस वक्त फिनांस मिनिस्टर साहिब दो क्लाज़ें और लाना चाहते हैं । एक तो बेकरी वालाज़ और एक हलवाई शाप्स । जहां तक बेकरी वालाज़ का सम्बन्ध है वह (बी बी) क्लाज़ में नहीं हैं । हलवाई के मुतअल्लिक कुछ डिफरेंट बात है। यह जो सैक्शन 4, 5 का मैंने अभी अभी ज़िक्र किया । ओरिजिनल सैक्शन 4 क्या है यह प्रेसकाईब करता है कि टैक्सेशन लगेगा ।

4. (1) Subject to the provisions of sections 5 and 6, every dealer "except one dealing exclusively in goods declared tax-free under section 6 whose gross turnover during the year immediately preceding the commencement of this Act exceeded the taxable quantum shall be liable to pay tax under this Act on all sales" The word 'all' is significant—" effected after the coming into force of this Act...."

मैं जानता हूं कि आगे सैक्शन 6 में शैड्यूल में गवर्नमेंट ने पहिले ही कुछ एक्ज़ैम्पशनज़ दी हुई हैं और यहां पर जो रैलेवैन्ट ऐग्ज़ैम्पशंज़ हैं वह हैं "Articles ordinarily prepared by Halwais when sold by them I lay emphasis on the words *Ordinarily prepared by the halwais* और अगर मनशा है हलवाईयों और बेकरी वालों के लिए टैक्सेबल ऐग्ज़ैम्प्शन फिक्स करने का और उन को सैक्शन 4 की ज़द में लाने का मकसद नहीं है तो मैं समझ नहीं पाया कि इस अमैंडमैंट की यहां पर ज़रूरत क्या थी । अगर उन को इसमें इनक्लूड करने का मनशा नहीं है तो इस वक्त इस अमेंडमेंट के लाने की जरूरत ही क्यों पड़ी ? जसा कि मैंने अभी अभी ऐग्ज़ैम्प्शन को पढ़ा, अगर जो आर्डिनरी प्रैपेरेशंज़ हल्वाई करता है उस पर यह लागू नहीं होती तो वह तो पहले

[श्री मोहन लाल]

ही एकट में मौजूद है कि उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। जब उसका नाम वहां पर पहले ही मौजूद है तो फिर वहां पर अब उसे लाया क्यों जाए टैक्सेबल कुएंटम 25,000 मुकरर करते वक्त मैं पूछता हूं कि इस कुएंटम में अब गवर्नमेंट को स्पैसिफिकली उन्हें यहाँ पर लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी ? इस से मैं यह अन्दाज़ा लगाता हूं कि इसमें जो यह लफज़ हैं कि "ऐक्सक्लूसिवली डील विद" करता है उसको यह ऐग्जैम्पशन ग्रांट की गई है। अब एक तरफ आप "ऐक्सक्लयूसिवली डील विद" के अल्फाज़ सामने रखें और साथ ही "ऐग्जैम्पशन" को सामने रखें तो मिसचिफ वहाँ से पैदा होती है। ज़ाहिरा तौर पर, जैसा कि फाइनांस मनिस्टर साहिब ने अपनी इंटरप्रेटेशन में बताया कि "Articl s or inarily pr pared by Halwais when sold by them" में वह कवर हो जाएगा। लेकिन लफज़ हैं "प्रीपेयर्ड बाई"। यानि जब कोई अफ़सर इस सिलसिले में अपनी इन्टरप्रेटेशन करेगा तो वह "प्रीपेयर्ड बाई" को सामने रखेगा। मिसालें तो इस सम्बन्ध में बहुत सी दी जा सकती हैं लेकिन मैं एक ही मिसाल आप के सामने रखता हूं। एक हलवाई है। वह बहुत भारी तादाद में दूध फरोख्त करता है। अब वह दूध मैनुफैक्चर तो करता नहीं। दूध बाहर से आता है और वह दोनों शक्लों में यानि दूध और उसकी चीजें बना कर बेच देता है। जब गर्म करके बेचता है तो उसमें कोई मैनुफैक्चरिंग प्रासैस इनवाल्व नहीं होता लेकिन ऐम्फेसिज़ है "आरडेनेरिली प्रिपेयर्ड" पर। जब कोई अफ़सर इसकी इन्टरप्रिटेशन करेगा तो वह उसे कह देगा कि भाई तू तो इसे मैनुफैक्चर नहीं करता इस लिए तुम इसकी ज़द में आते हो। तो जहाँ तक फिनांस मिनिस्टर साहब की इन्टरप्रेटेशन का ताल्लुक है वह उनकी अपनी हो सकती है। This interpretation can be put forth by an officer of his own department though his own opinion may be different. इसी तरह से दूध से तैयार की हुई और दूसरी चीज़ों के मुतअल्लिक भी कहा जा सकता है। मैं और भी मिसालें दे सकता हूं जो कि सीजनल होती हैं। सीज़नल प्रेपेरेशंज़ होती है जैसा कि आप जानते हैं घियूर बनता है। चन्द दिनों के लिए ही उसकी प्रेपेरेशन होती है लेकिन कल को इन का ही कोई अफसर यह इन्टरप्रेटेशन भी दे सकता है कि यह चीज़ें उस के ज़रिए आरडीनैरिली प्रीपेयर्ड नहीं होतीं। This is a possible interpretation that these things are not ordinarily manufactured. तो कहने का मतलब यह है कि जैसी कि क्लाज रखी गई है, अगर कोई हलवाई दूध भी बेचता है तो वह भी इसकी ज़द में आ जाएगा क्योंकि कोई भी अफसर यह कह देगा कि तुम वह भी चीजें बेचते हो जो कि हलवाई की जद में नहीं आतीं। मिसाल के तौर पर अगर किसी के पास चीनी नहीं और हलवाई से वह एक सेर चीनी ले जाता है तो वह कह सकते हैं कि चूंकि हलवाई चीनी मैनुफैक्चर नहीं करता इसलिए उस पर यह क्लाज़ हावी होगी। इसीलिए मैंने शुरू में इस बात को टेक अप करते हुए लफज़ "आल" पर ऐम्फेसिज़ ले लिया

था। और इसका मतलब यह होगा कि उसके लिए इस ऐग्जेम्पशन का कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि जब इस सम्बन्ध में उन ट्रेडर्ज के लिए आप कोई नई टैक्सेशन की बात नही लाना चाहते थे, ऐसा आप का मनशा नहीं था तो इस सब-क्लाज़ को यहां पर लाने की जरूरत ही क्या थी ? अब यहां पर बेकरी वालों का भी नाम दर्ज कर दिया। वह तो सहूलियत चाहते हैं नहीं। उन को तो असल में आप की इस अमैंडमैंट से खतरा पैदा हो गया है। उन की भी यही मांग है कि अगर वाकई सरकार सहूलियत देना चाहती है तो 'स्टेटस को' रहने दिया जाए। उन के लिए यह सहूलियत नहीं कबाहत बनेगी। इसलिए जो इन्टरप्रेटेशन मैंने की है.....मुझे यकीन है कि जैसी इन्टरप्रेटेशन मैंने दी है ऐसी भी हो सकती है.....फिनांस मिनिस्टर साहिब इस पर दोबारा गौर करेंगे। मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि जो "स्टेटस को" है वही रहने दिया जाए क्योंकि इस नए प्रोविज़न से गलत फहमियाँ पड़ेंगी। इस वक्त आप मानें या न मानें आगे इसमें जरूर नई पेचीदगियाँ पैदा होंगी। कल को अफ़सर अपने अपने प्वायंट आफ व्यू से इसकी नई नई इंटरप्रेटेशंज़ करेंगे और वह कहेंगे कि फिनांस मिनिस्टर की ओपीनियन तो उन की अपनी ओपीनियन है, मेरी इंटरप्रेटेशन तो यह है कि ये लोग भी इस एक्ट की ज़द में आते हैं।

दूसरी बात इस क्लाज़ की सब-क्लाज 2 के बारे में है जिसमें टैक्सेबल टर्नओवर के क्वांटम को 50,000 से कम करके 30,000 रुपये किया गया है। उसके मुतअलिक मैं बहुत तफसील में जाना जरूरी नहीं समझता। गवर्नमेंट न हाउस के अन्दर इस सम्बन्ध में मेम्बर साहिबान की राए देख ही ली है और कल जो चीफ़ मनिस्टर साहिब ने यहाँ पर ऐश्योरेंस दी थी उसकी लाईट में मैं समझता हूं कि मुझे इस पर आगे कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं रही। उन्होंने कल यह कहा था कि अगर मेम्बर साहिबान को इस टैक्सेबल क्वाँटम के बारे में मुखालिफत है तो इसमें जो ओरिजनल यानी 30,000 प्रोवाईड किया गया है उसको कुछ बढ़ाकर 50,000 के पास या कुछ थोड़ा बहुत कम कर देंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। पता नहीं कि कौन सी फ़िगर उन के मन में थी। इसलिए मैं इसमें इस वक्त ज्यादा न जाता हुआ यही अर्ज करूंगा कि जो एश्योरेंस चीफ मनिस्टर साहिब ने कल दी थी कि जब हाउस इस टैक्सेबल टर्नओवर की मुखालिफत करता है तो वह उस सूरत में इसे 30,000 से बढ़ा कर 50,000 के करीब या कम पेश कर देंगे, वह उस पर ध्यान रखेंगे। मैं उसमें और आरगुमेंटस में नहीं जाना चाहता। मैं गवर्नमेंट से आशा रखता हूं कि कल जो एश्योरेंस दी गई थी उसे आज आनर किया जाएगा वरना अगर दी गई एश्योरेंसिज को आनर न किया जाए तो फिर लोगों का गवर्नमेंट से एहतमाद उठ जाता है। आप ने इस बिल की बावत और खास कर इस क्लाज़ की बाबत मेम्बर साहिबान के जज़बात को देखा और सुन लिया है। एक भी ऐसा मेम्बर नहीं है जिस ने इस कलाज़ के हक में बात कही हो। लिहाजा इन अलफ़ाज़ के साथ फिनाँस मनिस्टर और चीफ

[श्री मोहन लाल]

मनिस्टर साहिब से अपील करूंगा कि यह जो 50,000 से 30,000 कर दिया है इसको डिलीट कर दें ।

मुख्य मन्त्री (श्री राम किशन) : स्पीकर साहिब, जहाँ तक पंडित मोहन लाल जी ने इस क्लाज़ के मुतअलिक जो कुछ कहा है, उसका ताल्लुक है मैं आप की विसातत से उन को याद दिलाना चाहता हुं कि उन के ही ज़माने में गवर्नमेंट को हल्वाईज ऐसोसीएशन का एक डैपूटेशन मिला था और उस वक्त जो बातचीत हुई उस वक्त की दस हजार रुपए की जो कुएंटम थी, उन की खाहिश के मुताबिक ही अब इस क्लाज में 25,000 रुपए किया गया है । यह तो उन की ही अपनी खाहिश के मुताबिक किया गया है । जो हलवाई का काम करता है, जो बेकरी का काम करता है, उसके मुताबिक ही उसे ऐग्जेम्प्ट किया गया है । इस लिए जहां तक इस क्लाज का ताल्लुक है, डायरैक्टली या इनडायरैक्टली उस पर कोई असर नहीं पड़ता है ।

लेकिन अगर हलवाई कोई रैस्टोरैंट खोल लेता है, कोई टी शाप खोल लेता है और इसके अलावा कोई और काम साथ में कर लेता है तो नैचुरली उसके मुताबिक, जो कुछ भी इन क्लाजिज में है, वह उन की ज़द में आएगा । लेकिन स्पीकर साहिब, आप के जरिए मैं उन्हें इस बात का यकीन दिलाना चाहता हुं कि अगर उन के जमाने में इस सम्बन्ध में इन्स्पैक्टरों की तरफ से या दूसरी तरफ से कोई बात नहीं हुई है तो हमारे जमाने में भी ऐसी कोई बात नहीं होगी और गवर्नमेंट जिस मनशा को लेकर मुखतलिफ अमैंडमैंट्स इस ऐक्ट के अन्दर लाई है बिलकुल उसी नीयत से सारे ऐक्ट की वर्किंग होगी । और हम देखेंगे कि जहाँ तक हमारे एक्साइज़ एण्ड टैक्सेशन के स्टाफ का ताल्लुक है वह डीलर्ज के साथ अच्छी तरह से बिहेव करेंगे और इस बिल की जो धाराएं हैं उन पर ठीक तरह से अमलदरामद होगा ताकि व्योपारियों को इस से कोई तकलीफ न हो ।

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ (ਲੁਧਿਆਣਾ ਉੱਤਰ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਕਲਾਜ਼ ਦੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਕਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਅਰ ਹਲਵਾਈਆਂ ਤੇ ਅਗੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗੇਗਾ । ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੇਕਰੀਆਂ ਔਰ ਹਲਵਾਈਆਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਲਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਮਿਲੇਗੀ । ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕੀ ਅਗੇ ਕਿਸੇ ਹਲਵਾਈ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੇਕਰੀ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਿਆ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਲਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਫ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਨ ਨੂੰ ਹਥ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਪਰ ਮਰੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਔਰ ਅਜ ਜਿਤਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ....

[ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ]

(ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ) ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਲੁਕਮਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਤਕ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ੋਰ ਵਿਚ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ 80 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹਲਵਾਈ ਜਾਂ ਬੇਕਰੀ ਵਾਲਾ 80 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰੇਗਾ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਇਤਨੀ ਹੀ ਸੇਲ ਵਾਲਾ ਹਲਵਾਈ ਇਸ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜਗਲਰੀ ਆਫ ਵਰਡਜ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲੇ ਥਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਹਲਵਾਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਬੇਕਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੇਜਲੀ ਫਫੇਕੁਟਨ........।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ : ਉਹ ਤਾਂ ਉਠੇ ਹੀ ਨਹੀਂ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਸ੍ਰੀ ਗਰਗ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। (It seems that Sardar Gurcharan Singh does not like that the Chief Parliamentary Secretary should sit opposite him.)

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਸਪੀਕਰ, ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ....।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। (The hon. Member is not relevant.)

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਲਾਜ਼ ਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਫਿਨਾਂਸ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਕਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਲਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਔਰ ਜੋ ਉਹ ਕਹਿਣ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰ ਲੈਣ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਇਸ ਕਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਰਖ ਲਓ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣ ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਰਖੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਢ ਦੇਣ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ ਵਰਨਾ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹਨ।

[ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ]

ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫਿਨਾਂਸ ਮਨਿਸਟਰ ਹਨ, ਇਹ ਬੜੇ ਤੇਜ਼-ਗਾਮੀ ਹਨ ਔਰ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ। ਢਾਬੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਤਕ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਤਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਆਇਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਢਾਬੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਕੋਈ ਕਲੀਅਰ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਉਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਢਾਬੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਈ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨੇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿਚ ਸੰਗਲ ਪਾਈ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਉਪਾਰੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਇਵੇਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਈਵੇਜ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਲੈ ਕੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ 17 ਆਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵੇਚਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਲਿਬੜੀ ਹੋਈ ਮਛ ਸਾਰੇ ਵਗ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਬਿਉਪਾਰੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਈਵੇਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੀਜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ। (The hon Member may allude tothese things during the third reading of he Bill.)

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਨਹੀਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮੈਂ ਇਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਜ਼ਾਰਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਉਪਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਈਮਾਨਦਾਰ ਬਣਨ ਦਿਉ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਮਾਨਦਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿਓ ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕੁਆਂਟਮ ਕਰ ਕੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲ ਦੀ ਬਿਕਰੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਬਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਰਖ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣ ਜਿਸ ਵਿਚ 30,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਵ ਔਰ ਤਦ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਰਖ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ।

(Baboo Bachan Singh was still in possession of thc House when it adjourned)

1.30 p. m.

Mr. Speaker : The House stands adjourned till 3 p.m. today.

(The Sabha then adjourned till 3 p.m. the same day i. e. Thursday, the 4th November, 1965.)

1568—4-2-66—386—C., P. and S., Pb., Patiala,

ਾਮੀ

ਾਲ

ਆ

ਸ਼ਾਂ

ੀਂ

ਥੇ

ਤੇ

ਤ

।

PUNJAB VIDHAN SABHA
DEBATES

4th November, 1965
(Afternoon Sitting)

Vol. II—No. 17

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Thursday, the 4th November, 1965

Punjab Vidhan Sabha Secretariat, Chandigarh.

Price Rs : 3.10

ERRATA

to

Punjab Vidhan Sabha Debates, Vol. II, No. 17, dated the 4th November, 1965 (Afternoon Sitting)

Read	*For*	*Page*	*Line*
ਅਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ	ਟਗ ਕਨਫਰੰਸਾ	(17)3	8
hon.	hono.	(17)3	1
Principal	Parincipal	(17)8	9
ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ	ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ	(17)8	19
Delete the word 'है' word	after the 'इसलियें'	(17)9	14
substitute	substutute	(17)9	4th from below
अमैंडमैंट	एमन्डमेन्ट	(17)13	18
	एमन्डमेंट	(17)13	22
ਵਾਲੀ	ਵਾਲੇ ਵਾਲੀ	(17)15	1
ਬਿਉਰੋਕਰੇਸੀ	ਬਿਉਕਰੇਸਾ	(17)15	6
ਮਨਿਸਟਰ	ਮਨਿਰਸਟ	(17)15	10
ਰੀਨਿਊਅਲ	ਰੀਨੀਊਲ	(17)14	9th from below
	ਰੀਨੀਓਲ	(17)17	9th from below
ਦਿਦਾ	ਦਿਦਾ	(17)19	3
गुज़ारिश	गुजाशि	(17)21	15
लाना	माना	(17)21	19
इंस्पैक्टर	इन्सपकटर	(17)21	Last
पैदा	पदा	(17)22	8
GENERAL	GEMERAL	(17)23	Heading
पीरियाडिकल	पीरिपाडिकल	(17)23	6
ਪੁਆਇੰਟ	ਪਆਇੰਟ	(17)24	12th from below
ਮੈਂ	ਮਾਂ	(17)31	3rd from below
ਹੈਰਸਮੈਂਟ	ਹਰਾਸਟਮੈਂਟ	(17)34	2
ਪ੍ਰੋਵੀਯਨ	ਪਾਵੀਜ਼ਨ	(17)37	2
ਰਕਮ	ਕਰਮ	(17)38	5

Read	*For*	*Page*	*Line*
चेयरमैन	चेयरमन	(17)38	8
उसे	उस	(17)39	6th from below
ਸਰਦਾਰ	ਸਰਦ ਰ	(17)39	Last but one
		(17)53	10th and 14th from below
फ़ाज़िल	फाजिज़	(17)40	25
the	th	(17)40	9th from below
which	whic	(17)40	8th from below
व्यापारियों	व्यापायिों	(17)41	4
ਕਿਸੇ	ਕਿਸੋ	(17)43	14
ਫ਼ਾਈਨੈਂਸ	ਫ਼ਾਈਨੈਸ	(17)43	11th from below
ਗਈ	ਰ ਈ	(17)44	11th from below
ਨੂੰ	ਨੂੰ̐	(17)45	8th from below
मैं	में	(17)47	13th from below
I would	would	(17)47	10th from below
प्रोविज़ो	प्रोविज़	(17)49	3rd from below
सौदा	सौद	(17)50	Last
अमैंडमेंट्स	अमङमेंट्स	(17)51	20
ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ	ਐਗਜ਼ਪਟ	(17)51	Last
ਚਾਹੇ	ਚਾਂਹੇ	(17)51	Last
THE	THC	(17)53	Heading
to	o	(17)57	6
Yash Paul	Yash Pal	(17)57	6
	Yash Pa	(17)57	12
Dr. Balkrishah	Dr. Bal Kishan	(17)57	18

PUNJAB VIDHAN SABHA

Thursday, the 4th November, 1965

(*After-noon Sitting*)

The Vidhan Sabha met in the Assembly Chamber, Vidhan Bhawan, Sector 1, Chandigarh, at 3.00 p.m. of the Clock. Mr. Speaker (Shri Harbans Lal) in the Chair.

BILL

THE PUNJAB GENERAL SALES TAX (AMENDMENT) BILL, 1965

(Resumption of Discussion)

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ (ਲੁਧਿਆਣਾ ਉੱਤਰ) : ਮਿਸਟਰ ਸਪੀਕਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 30,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਚਲਦਾ ਹੈ । ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦੀ 30,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਰਨ ਓਵਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਉਸਦਾ ਮੁਨਾਫਾ 3,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਯਾਨੀ 250 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ । ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 75 ਰੁਪਏ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਗਰ ਮਨੀਮ ਰਖੇ ਤਾਂ (ਵਿਘਨ) ਉਹ ਸੌਦਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜਾਂ ਮਨੀਮੀ ਕਰੇਗਾ 150 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟ ਤੇ ਮਨੀਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ । ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ 25 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲੇ । ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਈਵੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ । ਇਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਾ ਹੈ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨਾਲ ਤਅਲੁਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਖ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇਹ ਟੈਕਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿੰਨੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਆਪ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ । ਸੰਨ 1948 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਸਪੀਕਰ ਸਨ । ਮੈਂ ਵੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ । ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਲਟੀ-ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੇਲਜ਼ ਦੀ ਇੰਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਕ ਹੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲਗਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ । ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ । ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ। ਮਗਰ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਗਾ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ । ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤਕ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋਵੇ ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ

[ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ]

ਡੀਲਰਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਛੋਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਰਖ ਸਕਦਾ । ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਪੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲਰਕਾਂ ਦੇ ਪੰਜੇ ਵਿਚ ਫਸਦਾ ਸੀ । ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੱਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਕਲਰਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਦੇ ਸਨ । ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲਾਉ । ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਕੀ ਉਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ? ਖੰਡ ਤੇ, ਕਪੜੇ ਤੇ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਤੇ ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਇਨਸਪੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟ ਗਏ । ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਖ ਨਹੀਂ । ਜਿੱਥੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਇੰਨਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੇਠ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਉਥੇ ਹੀ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਤੋਂ ਡਰ ਲਗਦਾ ਰਿਹਾ । ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਚਪੜਾਸੀ ਵੀ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸੌਦਾ ਦੇਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ । ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਇੰਨਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਛੁੜਾਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮਗਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਗੁਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ । ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਟਰਨ ਓਵਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨ-ਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇੰਨਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜੇ ਵਿਚ ਲਿਆਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ । ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਇਵੇਯਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਵੇਯਨ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਵਾਂਟਮ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਘਟਾ ਦਿਉਗੇ, 10,15 ਹਜ਼ਾਰ ਤਾਈਂ । ਇਵੇਯਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕੋਈ ਫੂਲ ਪਰੂਫ ਤਰੀਕਾ ਕਢਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ । ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਹੈ । ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀਂ ਖੁਦ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੁਦ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਹਿਦ ਵਿਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦਫਾ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਪਈ । ਇਕ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ । (ਵਿਘਨ) ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ । ਅਗਰ ਇਹ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਈ। 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲ ਲਿਆਏ, 20 ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਰੋਕੋ । ਵਾਪਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ । ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗੇ, ਦੂਜੀ ਇਹ ਕਿ ਇੰਨਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਛੁੜਾਉ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਇਹ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੋਰ ਅਤੇ ਠੱਗ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਾ ਦਿਉ, ਸ਼ਰੀਫਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਿਉ। ਉਹ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗਦੇ । ਅਸੂਲੀ ਛੋਟ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਹੈ, ਯੂ. ਪੀ. ਵਿਚ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਹੈ ਉਹੀ ਇਥੇ ਲਗੇ । ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ੇਕਟਿਵ ਨੂੰ ਅਡ ਅਡ ਕਰੋ । ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ......

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੈ ਗਏ । (The hon. Member is indulging in general discussion of the Bill.)

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਜੀ 30,000 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ 10,000 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ । (ਵਿਘਨ) ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਸਕੋਪ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਿਨਾਂਸ ਮਨਿਸਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਟਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ । (ਹਾਸਾ) ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਹਲੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਫਿਨਾਂਸ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਸੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਂਦੇ ਫਿਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹਦੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰੋ । ਟਗ ਕਨਫਰੰਸਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰੋ । (ਵਿਘਨ) ਜੇਕਰ ਇਹ ਫਿਨਾਂਸ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ 4 ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਐਗਰੀ ਕਰੋ । ਅਤੇ ਜੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੋ । ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਿਮਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉ । ਇਸ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਤੇ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਇਹ ਹਾਊਸ ਵੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ । ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀ ਇਹ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ ਅਸਾਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਵੇਜ਼ਨ ਵੀ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਗਿਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ।

ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਫਿਨਾਂਸ ਮਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਗਰੀਬ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਨਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਇਨਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਥਲੇ ਲਗੇ ਰਿਹਾ ਕਰਨਗੇ । ਕਲਰਕਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆ ਖੁਸ਼ਾਮਦਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ । ਇਸ ਦੀ ਜਦ ਵਿਚ ਹਲਵਾਈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ ਜਾਣਗੇ । ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਦ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਢਣ ਲਈ ਇਸ ਲਿਮਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਬਰਖਲਾਫ ਹਾਂ । ਇਸ ਲਈ ਬਜਾਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਥਾਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਉ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜ ਲਉ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲਗਾ ਪੰਜ ਸਤ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ । ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਠ ਧਰਮੀ ਨਾ ਛਡੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸ ਲਈ ਆਸ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗਲ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ ।

श्री यश पाल (जालन्धर दक्षिण-पश्चिम) : मेरी एक अमेन्डमेन्ट है इस क्लाज़ 2 की सब क्लाज 1 में। जैसा कि पंडित मोहनलाल जी ने कहा है अगरचि चीफ मिनिस्टर साहिब ने इस बात की वज़ाहत कल कर दी थी कि सरकार का मन्शा बेकरी वालों और हलवाइयों पर टैक्स लगाने का नहीं लेकिन फिर भी इस क्लाज में इस बात का ख़तरा है और गुंजाइश भी है। इसलिये अगर गवर्नमेंट का इरादा उन पर टैक्स लगाने का नहीं है तो फिर मेरी यह अमेन्डमेन्ट मान लेनी चाहिए कि जहां पर

[श्री यश पाल]

सब क्लाज (1) में लाइन २ में जहां शब्द हलवाई शाप आते हैं वहां पर "हलवाई-कम-रैस्टोरेंट" कर दिये जाएं।

इसके इलावा मैं एक और अर्ज़ करना चाहता हूँ और यह सारे हाउस की डिमांड है कि जो ३०,००० के कवैंटम की लिमिट है इसको बढ़ा दिया जाए। यह बहुत थोड़ी है। इसमें किसी किस्म की कन्ट्रोसवर्सी का सवाल नहीं। यह मैम्बरों की खाहिश के मुताबिक भी है। इसलिये अगर इसको मनजूर कर लिया जाए तो इस से हलवाई भी मुतमैयन हो जायेंगे और इस हाउस की जो प्रार्थना है उसके अनुसार क्वैंटम भी बढ़ जाएगा।

ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ) : ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਲਿਮਿਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵਧਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਐਨੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਰ-ਕੈਪੀਟਾ ਇੰਨਕਮ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਆਦਮਨੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਸੂਬਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿਚ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿਚ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀ ਕਵੈਨਟਮ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਗਰਜ਼ ਮੈਂ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਫੀਸ਼ਲ ਫਿਗਰਜ਼ ਹਨ। ਆਂਧਰਾ ਵਿਚ ਇਸ ਕਵੈਨਟਮ ਦੀ ਲਿਮਿਟ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਵਿਚ 12 ਹਜ਼ਾਰ, ਬੰਬਈ ਵਿਚ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਜਾਰਤ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 15 ਹਜ਼ਾਰ, ਮਦਰਾਸ ਵਿਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ, ਉੜੀਸਾ ਵਿਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ, ਯੂ. ਪੀ. ਵਿਚ 12 ਹਜ਼ਾਰ, ਕੇਰਾਲਾ ਵਿਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ 15 ਹਜ਼ਾਰ, ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ। (ਵਿਘਨ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਨਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਕ ਖੁਲ੍ਹੀ ਛੁਟੀ ਹੈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ। (ਹਾਸਾ) ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਆਇਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਕਵੈਨਟਮ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਲਿਮਟ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਧ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮਟੀ ਆਫ ਰੇਟਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿੱਥੇ ਤਕ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮਨ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੀਮਾਂਡ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਵੈਂਨਟਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਦੂਸਰੇ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਕਵੈਂਟਮ ਦੀ ਲਿਮਟ ਨੂੰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਲ

ਹੋਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡੀਲਰ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ । ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2 ਲਖ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਦ ਹੇਠ ਆ ਜਾਣਗੇ । ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਦ ਵਿਚ ਇਸ ਕਵੇਂਨਟਮ ਦੀ ਲਿਮਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੇਵਲ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਵਪਾਰੀ ਆਉਣਗੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ । ਇਸ ਲਿਮਟ ਨੂੰ ਘਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ । ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਅਸੀਂ ਅਨ-ਬੇਲ੍ਹਿੰਗ ਕਲਾਜ਼ ਰਖ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਝੰਜਟ ਵਿਚ ਨਾ ਪੈਣ । ਅਤੇ ਅਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੰਪਸਮ ਦੇਣ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣ । ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਫਿਰ ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੋਵੇ । ਮੈਂ ਬਾਬੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਹ ਡੀਮਾਂਡ ਸੀ ਕਿ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਹਰ ਇਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬਾਬੂ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਾਂ ਤੇ ਅਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਾਂ ਤੇ ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਲੁਧਿਆਨਾ ਇਸ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਦ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਲੁਧਿਆਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰਫੈਕਚਰਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜਲੰਧਰ ਸਾਰਾ ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਦ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰਫੈਕਚਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆ ਜਾਣਗੇ । ਇਸ ਪਾਸੇ 2 ਲਖ ਡੀਲਰ ਵਧ ਜਾਣੇ ਸਨ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਬਾਬੂ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਂਦਾ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਕੇ ਇਹ ਬਿਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰਫੈਕਚਰ ਅਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਾਬਲੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗਰੋ ਮੋਰ ਫੂਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦਿਉ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਨਡਸਟਰੀ ਵਧੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁਟਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦੇਈਏ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਲਈ ਇਕ "ਵਾਇਆ ਮੀਡੀਆ" ਕਢਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਫੇਰ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਗਵਰਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੀ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਤਬਕੇ ਵਿਚ ਬੜੀ ਹੈਰੈਸਮੈਂਟ ਹੈ ਘਬਰਾਹਟ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ । ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਬਿਉਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ

[ਵਿਤ ਮੰਤ੍ਰੀ]

ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਤੇ ਲਗਾਓ, ਮੈਨੂੰਫੈਕਚਰਰ ਤੇ ਲਗਾਓ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੈ ।

Shri Mohan Lal : Sir, I would like to have some information before the amendments to clause 2 of the Bill are put to the vote of the House. मैं ने भी अर्ज़ किया था क्वैंटम बढ़ाने के मुताल्लिक चीफ मिनिस्टर साहिब ने भी यहां पर इसे बढ़ाने के लिए एशोरेंस दी थी । इस के इलावा जो भी मेम्बर साहिबान अब तक बोले हैं सब ने 30,000 की लिमिट को बढ़ाने के मुताल्लिक कहा है मगर फाईनेंस मिनिस्टर साहिब ने अभी तक इस के मुताल्लिक कुछ नहीं कहा है । क्या आप इस के मुताल्लिक भी अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे ।

I would request the hon. Minister for Finance to increase the question of the turnover.

Sardar Gurcharan Singh : The hon. Chief Minister has gone to Delhi.

I have respect for the hon. Member Shri Mohan Lal.

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ : ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦਿਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਸਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਆਂਟਮ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਕਰਾ ਕੇ ਛਡਿਆ ਕਿ ਨਾ ! ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਏਥੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਚ ਵਿਚਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਵੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਕੁਆਂਟਮ ਵਧਾ ਕੇ 30,000 ਦੀ ਬਜਾਏ 40,000 ਤਾਈਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ । (ਤਾਲੀਆਂ)

Shri Rala Ram (Mukerian) : Sir, I beg to move—

In Sub-clause (2) for "30,000", substitute "40,000".

Mr. Speaker : Motion moved—

In sub-clause (2), for "30,000", substitute "40,000".

Mr. Speaker : Question is—

In sub-clause (2), for "30,000", substitute "40.000".

The motion was carried.

Mr. Speaker : Amendments Nos. 57 and 58 stand in the name of Shri Yash Pal.

Shri Yash Pal : Sir, I beg to withdraw my amendments Nos. 57 and 58.

Mr. Speaker : Is it the pleasure of the House that the hono. Member Shri Yash Pal be allowed to withdraw his amendmnts ?

Voices. Yes.

The amendments were, by leave, withdrawn.

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2, as amended, stand part of the Bill.

The Motion was carried.

CLAUSE 3

Mr. Speaker : All the amendments given notice of by the various honourable Members to Clause 3 are deemed to have been read and moved. These are—

Sardar Gurbakhsh Singh Gurdaspuri :

In the proposed sub-section (1-A) of sub-clause (1), line 2, for "such" occurring for the first time substitute "all".

Delete the proviso to the proposed sub-section (1-A) of sub-clause (1).

Shri Ram Saran Chand Mital :

In sub-clause (1), lines 1-3, for "in sub-section (1),..............and after sub-section (1) as so amended" substitute "after sub-section (1)".

Thakar Mehar Singh :

In the proposed section (1-A) of sub-clause (1), line 2, for "such" occurring for the first time substitute "all".

Shri Yash Pal :

Delete the proviso to the proposed sub-section (1-A) of sub-clause (1).

Shri Balramji Das Tandon :

Shri Fateh Chand Vij :

Shri Mangal Sain :

Delete the proviso to the proposed sub-section (1-A) of sub-clause (1).

श्री यश पाल (जालन्धर, दक्षिण पश्चिम) : स्पीकर साहिब, गवर्नमेंट ने इस क्लाज़ में यह दिया है कि जिन चीज़ों पर पहली स्टेज पर सरकार टैक्स लगाना चाहे तो वह लगा सकती है लेकिन इसके साथ जो प्राविज़ों लगाया गया है ऐसा लगता है कि जो इख्त्यार उन्होंने लिया है वह इसे इस्तेमाल करना नहीं चाहते । अभी अभी जो स्टेटमेंट फाईनेंस मिनिस्टर साहिब ने दिया उससे जाहिर होता है कि वह इसे अमल में लाना नहीं चाहते । मैं कहता हूँ कि अगर कोई आफिसर agricultural या industrial products पर नाजायज़ तौर पर टैक्स ग़लत स्टेज पर लगाना चाहें तो उसे रोक कौन सकता है । इसका कतई मतलब यह नहीं है । मैंने जो अमैंडमेंट दी

श्री यश पाल]

है वह यह है कि 1st स्टेज की बजाये "at one stage" कर दिया जाये, जब तक ऐसा नहीं किया जायेगा, यह झंझट होता रहेगा ।

इस के इलावा एक झंझट और भी है कि रजिस्टर्ड डीलर को सर्टीफिकेट रखना होगा क्योंकि जब इन्स्पैक्टर ने इसके मुताबिक चैकिंग करनी होगी तो इस प्राविज़ों का सारा मकसद ही ख़त्म हो जाता है । इसलिये मेरी गुज़ारिश यह है कि इस तीसरी क्लाज़ को डीलीट ही कर दिया जाये ।

Shri Ram Saran Chand Mital (Narnaul) : Sir, In sub-section (1) of section 5 of the Parincipal Act, it is stated—

> "Subject to the provisions of this Act, there shall be levied on the taxable turn-over every year of a dealer a tax at such rates not exceeding four n.P. in a rupee as the State Government may by notification direct."

इसके अन्दर यह ऐवरी इयर को उड़ा देते हैं जिससे हैरैसमेंट बढ़ जाती है क्योंकि ऐसी सूरत में ऐवरी मंथ या ऐवरी टू मंथ जब चाहें तब नोटिस दे सकते हैं और ऐसेसमेंट कर सकते हैं। यह हैरैसमेंट को तो बढ़ाता है लेकिन इवैज़न को चैक नहीं करता, इसलिये मैं अर्ज़ करूंगा कि मेरी अमैंडमेंट को मान लिया जाए ।

Finance Minister : I oppose this amendment. The hon. Member is requested to withdraw it.

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ (ਲੁਧਿਆਣਾ ਉਤਰ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਜੋ ਫਰਸਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਨੇਬਲਿੰਗ ਪਾਵਰ ਲਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਹਾਂ । ਲੇਕਿਨ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਫੇਵਰ ਵਿਚ ਹਾਂ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਟੈਕਸ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੇ ਲਾ ਦਿਉ । ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਹੈਰੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਰੇਸਮੈਂਟ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੈ। ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੂੰ ਇਨੇਬਲਿੰਗ ਪਾਵਰ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਦਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਅੰਧੇਰੇ ਵਿਚ ਰਖ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਰੋੜਾ ਪੁਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਹੜ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣ ।

कामरेड राम प्यारा (करनाल) : जनाब, मिनिस्टर साहब ने फैक्ट्रीज़ का जिक्र कर दिया। अगर फैक्ट्रीज़ पर ही लगाया जाए तब तो ठीक है क्योंकि आगे तकलीफ नहीं होगी । लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि that Government is the best that governs the least अगर फर्स्ट स्टेज पर ही लगा दें तो फिर सारे किस्म के टैक्स गवर्नमेंट के घर में आ जाते हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है । मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब को यही कहूँगा कि जहां से ट्रांजैक्शन शुरू होता है उसी जगह टैक्स लगा दिया जाए ताकि आगे चल कर किसी को पता भी न चले और गवर्नमेंट बदनामी का बायस न बने । इस पर गौर किया जाए।

वित्त मंत्री : इसमें जनाब पोज़ीशन यही है कि हमारी जो क्लाज़ इस वक्त है वही रहेगी ।

Mr. Speaker : Question is—

In the proposed sub-section (1-A) of sub- clause (1), line 2, *for* "such" occurring for the first time *substitute* "all".

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

Delete the proviso to the proposed sub-section (1-A) of sub-clause (1).

The motion was lost.

श्री रामसरनचन्द मित्तल : मैं अपनी एमैण्डमेंट विदड्रा तो करता हूँ लेकिन यह जो कुछ इन्होंने कहा है इससे तो काम नहीं चलता । (विघ्न)

Mr. Speaker : Order please.

वित्त मन्त्री : यह सारी बात समझते हैं। वहां पर है ऐवरी इयर—और वह इसलिये है ऐसा किया गया है कि कई दफा हालात ऐसे हो जाते हैं, कि कम अरसे के लिये भी ज़रूरी हो जाता है और असली बात यह है कि It was to some extent in the ruling given by the High Court that we have to change it. मैं समझता हूँ कि आनरेबल मैम्बर इस अमेंडमेंट को विदड्रा कर लें ।

श्री रामसरन चंद मितल : यह बात ग़लत कर रहे हैं।

I withdraw my amendment.

Mr. Speaker : Has the hon. Member leave of the House to withdraw his amendment ?

Voices : Yes.

Voices : No.

Mr. Speaker : Since the leave has not been granted, I will put the amendment to the vote of the House.

Question is—

In sub-clause (1), line 1-3, *for* "in sub-section (i)......................and after sub-section (1) as so amended" *substutute* "after sub-section (1)".

The House then divided.

A yes	..	21
Noes	..	54

[Mr. Speaker]

The motion was declared lost.

Ayes (Total No. 21)

1. Ajaib Singh Sandhu, Sardar
2. Ajit Kumar, Babu
3. Babu Singh Master, Comrade
4. Bachan Singh, Baboo
5. Bhan Singh Bhaura, Comrade
6. Fateh Chand Vij, Shri
7. Gurmej Singh, Sardar
8. Gurbux Singh Dhaliwal, Comrade
9. Gurbakhsh Singh Gurdaspuri, Sardar
10. Gurcharan Singh, Sardar
11. Gurnam Singh, Sardar
12. Inder Singh Malik, Chaudhri
13. Jagan Nath, Shri
14. Jangir Singh Joga, Sardar
15. Kultar Singh, Sardar
16. Makhan Singh, Sardar (Tarsikka)
17. Mohan Lal Dutt, Pandit
18. Om Parkash Agnihotri, Shri
19. Ram Piara, Comrade
20. Ram Sarup, Chaudhri
21. Tek Ram, Chaudhri

Noes (Total No. 54)

1. Abdul Ghaffar Khan, Khan
2. Amar Nath Sharma, Shri
3. Amar Singh, Shri
4. Bal Krishan, Dr.
5. Baloo Ram, Chaudhri
6. Banwari Lal, Shri
7. Bhagirath Lal, Pandit
8. Lient. Bhag Singh, Sardar
9. Brish Bhan, Shri
10. Chandi Ram Verma, Shri
11. Chandrawati, Shrimati
12. Dasondhi Ram, Chaudhri
13. Dilbagh Singh, Sardar
14. Fakiria, Shri
15. Guran Dass Hans, Bhagat
16. Gurbanta Singh, Sardar
17. Gurdarshan Singh, Sardar
18. Gurmail, Shri
19. Harchand Singh, Sardar
20. Harinder Singh Major, Sardar
21. Hari Ram, Chaudhri
22. Hari Singh, Sardar
23. Hira Lal, Shri
24. Jagir Singh Dard, Sardar
25. Karam Singh Kirti, Sardar
26. Kesra Ram, Shri
27. Lakhi Singh Chaudhri, Sardar

28. Mohan Lal, Shri
29. Nihal Singh, Shri
30. Parkash Kaur Dr., Shrimati
31. Partap Singh Bakshi, Shri
32. Piara Singh, Sardar
33. Prem Singh 'Prem', Sardar
34. Pritam Singh Sahoke, Sardar
35. Rala Ram, Principal
36. Ram Dhari Balmiki, Shri
37. Ram Pal Singh, Kanwar
38. Ram Partap Garg, Shri
39. Ram Parkash, Chaudhri
40. Ram Rattan, Chaudhri
41. Ram Saran Chand Mital, Shri
42. Ranjit Singh Nenawalia, Sardar
43. Ranbir Singh, Chaudhri
44. Ran Singh, Chaudhri
45. Roop Lal Mehta, Shri
46. Sagar Ram Gupta, Shri
47. Sunder Singh, Chaudhri
48. Tirlochan Singh Riasti, Sardar
49. Tayyab Hussain Khan, Chaudhri
50. Ujagar Singh, Sardar
51. Jit Ram, Lala.

Mr. Speaker : Question is—

In the proposed section '(1-A) of sub-clause (1), line 2, for "such" occurring for the first time substitute "all".

The motion was lost.

Mr. Speaker : Next amendment stands in the name of Shri Yash Paul.

Shri Yash Paul : Sir, I beg to seek the permission of the House to withdraw this amendment.

Mr. Speaker : Has the hon. Member leave of the House to withdraw his amendment ?

Voices : Yes.

Voices : No.

Mr. Speaker : Since leave has not been granted, I will put the amendment to the vote of House.

Mr. Speaker : Question is—

Delete the proviso to the proposed sub-section (1-A) of sub clause (1).

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

Delete the proviso to the proposed sub-section (1-A) of sub-clause (1).

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That Clause stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 4.

Mr. Speaker : Now clause 4 is before the House. All the following amendments to this Clause will be deemed to have been read and moved and can be discussed along with the Clause :—

4. Shri Mohan Lal :

Delete sub-clause (1).

5. Shri Mohan Lal :

In the proposed sub-section (4) (c) of sub-clause (2), line 1, datete "any other sufficient cause including".

28. Shri Ram Saran Chand Mital :

Delete sub-clause (1).

In sub clause (1), lines 3—5, for "shall there after be renewable .... payment of a prescribed fee" substitute "thereafter on presentation of an application in the prescribed manner and on payment of a prescribed fee not exceeding half the amount charageable at the time of first registration it shall be deemed to have been renewed for the subsequent year."

29. Shri Ram Saran Chand Mital : For sub-clause (2), substitute the following:—

"or on cessation of liability to payment of tax under this Act; provided that no order affecting any person adversely shall be made under this sub-section without affording him a reasonable opportunity of being heard."

60. Shri Yash Paul :

Delete sub-clause (1).

84. Shri Chandi Ram Verma :

Delete sub-clause (1)

156. Comrade Ram Piara :

In sub-clause (1), line 5, between "fee" and ";" insert "which shall be payable along with the tax to be in that very quater so that the dealer is not forced to go to the office for the completion of renewal process."

157. Comrade Ram Piara :

In the proposed sub-section (4) of sub-clause (2), line 2, for "cancel any certificate of registeration on" substitute "impose penalty in case of any default on the basis of".

158. Comrade Ram Piara :

At the end of the clause, add the following:—

"And if the dealer is not satisfied with the findings of Commissioner, he shall have the right to file an appeal before the Government within one month."

211. **Shri Ram Saran Chand Mital :** For the amendment appearing at serial No. 29, the following shall be substituted :—

"In sub-clause (2) for the proposed sub-section (4), *substitute* the following:—

"(4) The Commissioner may from time to time amed or cancel any certificate of registration in accordance with information furnished under section 16 or other-wise received or on cessation liability to payment of tax under this Act; provided that no order effecting any person adversely shall be made this sub-section without affording him a reasonable opportunity of being heard."

श्री मोहन लाल (बटाला) : स्पीकर साहिब, इसमें पहली एमन्डमेन्ट यह है कि सब क्लाज 1 को डीलीट कर दिया जाए। इसके अनुसार रिन्यूअल सर्टिफिकेट को हर साल रिन्यू करवाना पड़ेगा जोकि बिना किसी कारण और लाभ के होगा क्योंकि गवर्नमेंट इसको हटाना मान चुकी है। इसलिये इस पर कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। इन्होंने कहा है कि हम इसे छोड़ देंगे इसलिये सब क्लाज़ 1 को डीलीट करने की जो एमन्डमेंट है वह मान ली जाए। दूसरे मैंने सब क्लाज 2 (C) के बारे में अमैंडमेंट दी है कि "any other sufficient cause including" के लफ्ज़ डीलीट कर दिये जाएं। मैं आशा रखता हूँ कि वजीर साहिब इस तरमीम की अहमियत समझेंगे क्योंकि सफीशैंट काज़ एक बड़ी वाईड टर्म है। यह डीफाइन भी नहीं किया गया कि वह सफीशैंट काज़ क्या होगा। इतनी वाइड और वेग पावर्ज़ दे देना कि जिस किसी का जी चाहे किसी कारण से ही लाइसेंस कैंसल कर दिया जाए निहायत नामुनासिब बात होगी। मैं आशा रखता हूँ कि वह इस तरमीम को मन्जूर करेंगे।

चौधरी इन्द्र सिंह मलिक (सफीदों) : जो कुछ पंडित जी ने इस सब सैक्शन के बारे में कहा है वह ठीक है कि any other sufficient cause बहाना बना कर किसी वक्त भी किसी का लाइसेंस कैंसल किया जा सकता है क्योंकि यह बड़ी वेग और वाइड टर्म है। इसके बारे में जो उन्होंने अमैंडमैंट दी है उसे जरूर मान लेना चाहिए वरना इसका मिसयूज़ होगा। या फिर इस चीज को अच्छी तरह डीफाइन कर दें ताकि यह बात साफ हो जाए और अफसरों के पास वेग पावर्ज़ न रहे वरना बहुत ज्यादा रिश्वत चलेगी।

श्री रामसरन चन्द मित्तल (नारनौल) : अध्यक्ष महोदय कलाज ४ जो है यह ऐक्ट की सैक्शन 7 को डील करती है। मैंने इसकी सब कलाज (1) के बारे में अमैंडमेंट दी थी लेकिन मुझे मालूम हुआ है कि पंडित मोहन लाल जी ने जो अमैंडमैंट उस बारे दी है उसे मान रहे हैं। मेरी भी चूंकि वही अमैंडमेंट है इस लिये मैं उसे प्रैस नहीं करता। अब मैं सब क्लाज (2) के बारे में ही अपनी अमैंडमेंट पेश करता हूँ सब सैक्शन (4) में यह लिखा है

[श्री रामसरन चन्द मित्तल]

"The Commissioner may from time to time amend or cancel any certificate of registration in accordance with information furnished under section 16 or other-wise received."

मैंने जो मौजूदा सैक्शन है उसके अन्दर इतने लफ्ज़ बढ़ा दिये कि अगर किसी रजिस्टर्ड डीलर की टैक्स की पेमैंट की लाइबिलटी खत्म हो जाती है तो इस गराऊंड पर उसका लाइसेंस कैंसल हो सकता है। लेकिन जो लफ्ज़ इन्होंने रखे हैं वह बहुत वाइड हैं और वेग हैं। यह कहते हैं कि :

"information received that the dealer has violated any provision of this Act or the rules made thereunder;"

अगर एक रोज़ की भी डीले हो गई तो यह भी violation हो जाएगी। It is too much इसके बारे अर्ज़ है कि "any other sufficient cause" जो आपने लिखा है यह बड़ी वेग और वाइड टर्म है। इसके लिये मैं यह चाहता हूँ कि जो सब-सैक्शन पहले से है उसमें यह लफ्ज़ बढ़ा दिये जाएं।

"or on cessation of liablility of payment of tax under this Act;"

जो प्रोवाइज़ो इन्होंने रखा है वह भी इसमें आ जाए; मैं सदन से प्रार्थना करूँगा कि वह इस अमैंडमेंट को कबूल करें और खास तौर पर फिनांस मिनिस्टर साहिब से कहूँगा कि वह इसे accept करें। इससे उनका मतलब भी हल हो जाता है। इस तरह से स्टाफ को इतनी वाइड और वेग पावर्ज़ दे देना ठीक नहीं। अगर वह चाहते कि यह लोग नादरशाही चलाएं तो उनकी मर्जी है।

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ(ਲੁਧਿਆਣਾ ਉਤਰ) : ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਲਾਜ਼ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰਮੀਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ 1948 ਦਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਜਿਥੇ ਕੁੜੀ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਡਿਗੀ ਹੈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਕੰਨ ਵੀ ਬਿਨ੍ਹ ਦਿਓ। (ਹਾਸਾ) ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਲ ਬਸਾਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਰੀਨੀਊਲ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਰਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਨਾ ਇਸ ਰੀਨੀਊਲ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਕ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕ ਦਫਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦ ਤਕ ਉਹ ਖੁਦ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕਢੇ। ਰਜਿਸਟਰਡ ਡੀਲਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਰਜਿਸ-ਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵਰਨਾ ਉਸਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਖਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਡੀਲਰ ਗੋਰਮਿੰਟ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਉਸਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਰੀਨੀਊ ਕਰੋ ਜਾਂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਕਿ ਰੀਨੀਊ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ । ਇਹ ਗੱਲ ਪਸਤੌਲ ਤੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਪਿਸਤੌਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ । ਇਹ ਤਾਂ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ । ਦਰਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਿਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਊਰਕਰੇਸੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਹੈ ਇਤਨੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਐਨੀ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੁਰੱਪਟ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਤਾਕਤ ਵਧਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘਟਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਨਾਂਸ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ। ਆਖਰ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਕਿਸ ਲਈ ਹੈ ? ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਹੈ।

ਇਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕਰੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦੀ ਇਵੇਯਨ ਰੋਕੇ । (ਵਿਘਨ) ਪਰ ਤੀਜੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਵੇ । ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਉਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈ । ਮੈਂ ਫਿਨਾਂਸ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੀ ਰੀਨਿਊਅਲ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ? ਇਸਦਾ ਵਿਉਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸ ਦੇ ਹੇਠ ਪਾਵਰਜ਼ ਨਿਚਲੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਾਵਰਸ਼ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਪਾਸ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ । ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁਟਣਗੇ ਬਿਉਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਧਾਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪਾਸ ਪਾਵਰਜ਼ ਹੈ । ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ।

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ (ਸਿਧਵਾਂ ਬੇਟ—ਐਸ. ਸੀ.) : ਮੈਂ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਸ੍ਰੀ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂ ਹੋਰ ਪਾਵਰਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਕਾ ਹੋਵੇਗਾ । (ਵਿਘਨ) ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਸਬ ਇਨਸਪੈਕਟਰਜ਼ ਜਾਂ ਇਨਸਪਕਟਰਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 150 ਜਾਂ 200 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲਾਈਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਿਉਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਅਗਰ ਇਹ ਪਾਵਰਜ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਇਨਸਪੈਕਟਰਜ਼ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁਚਾਉਣਗੇ । ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਨਸਪੈਕਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਸਬ-ਇਨਸਪੈਕਟਰਜ਼ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਫਿਨਾਂਸ ਮਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਕੇ ਵੇਖ ਲਉ । ਇਨਕੁਆਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ 50% ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦਬਾਉ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ

[ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ]
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਨਸਪੈਕਟਰਜ਼ ਹੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਈਵੇਯਨ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਫਾਈਲਾਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨਜ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਈਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਲਾਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਿਲ ਵਿਚ ਕਲਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਫਿਨਾਂਸ ਮਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਡਰਾਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ।

कामरेड राम प्यारा (करनाल): स्पीकर साहिब, आपने फरमाया कि इस बिल के बारे में सब एमेंडमेंट्स मूव्ड ही समझी जाएं। मैं इस के बारे में 3 एमेंडमेंट्स दी हैं । मेरे अन्दाज़े के मुताबिक यह क्लाज़ डिपार्टमेंट के लिये सब से ज्यादा पेइंग है । इसमें महकमे वाले जितना भी रुपया बनाना चाहें उतना रुपया बना सकते हैं। जहां तक लाइसेंस कैंसल करने का ताल्लुक है, उसके बारे में बिल में कोई बात क्लीयर नहीं है। इसलिये मैं ने एमेंडमेंट दी है कि अगर कोई इस धारा को वायलेट करता है तो उसको उसके जुर्म के मुताबिक सजा देनी चाहिए । मैं इसके बारे में एक मिसाल देना चाहता हूँ। अगर कोई आदमी किसी को चोट पहुंचाता है, उसके लिये सजा निश्चित है अगर कोई आदमी किसी को मार देता है तो उसके लिये मौत की सज़ा है । इसलिये यहां पर भी जुर्म के हिसाब से सजा देनी चाहिए । अगर सरकार ने लाइसेंस कैंसल करने की सज़ा रखी तो उससे महकमे वालों को ही फायदा होगा। इस चीज को मद्देनज़र रखते हुए मैंने एक अमेंडमेंट दी है कि जुर्म के मुताबिक १०० रुपये या ५०० रुपये सज़ा रख दी जाए। इस तरह करने से सरकार के रैवेन्यू में भी इजाफा होगा। इसलिये लाइसेंस कैंसल करने की जगह पैनल्टी इम्पोज कर दी जाए । मैं समझता हूँ कि सरकार इस बात को मान लेगी ।

इसके बारे में दूसरी एमेंडमेंट रीनियुल आफ लाइसैंसिज़ की है । मेरे अन्दाज़े के मुताबिक अगर सरकार ने लाईसेंस को रीनियुल करने के लिये 5 रुपये फीस रख भी दी तो उससे सरकार की इन्कम में कोई खास फायदा नहीं होगा । मैंने सुना है कि इस क्लाज को वापस लेने के लिये वित्त मंत्री मान गये हैं। लेकिन उन्होंने अभी तक कोई भी आश्वासन नहीं दिया है । अगर वह यह क्लाज वापस न लें तो मैं इस के बारे में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जब दुकानदार लास्ट क्वार्टली टेक्स देते हैं तो उसके साथ ही सरकार को 5 रूपये फीस ले लेनी चाहिए ता कि दुकानदारों को इसी काम के लिये 2, 3 दिन इधर उधर टैक्सेशन के दफ्तर में और ट्रेज़री के में व्यर्थ में घूमना न पड़े। इसलिये यह फीस लास्ट क्वार्टरली रिटर्न के साथ ही ले लिया जाए।

तीसरी एमेंडमेंट यह है कि दुकानदारों की असैसिंग और अपील सुनने की एजंसी दो होनी चाहिए । इसके बारे में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अगर यह पावर्ज़ एक डिपार्ट-मेंट के पास रह गई तो लोगों को पूरा इन्साफ नहीं मिल सकता है । डिपार्टमेंट

वाला अपने डिपार्टमेंट की बात को ज्यादा मानता है। इस तरह से बहुत ही गोल माल होता है। कई जगहों पर यह अधिकारी फर्मज़ के साथ मिल जाते हैं और उसको फायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मैं इसके बारे में भिवानी तहसील में एक गम गवार फैक्टरी की मिसाल हाउस में पेश करना चाहता हूँ। इस फैक्टरी का मालक बहुत रिसोर्सफुल था। उसने रिटर्न 109 दिन डीले करके टैक्सेशन डिपार्टमेंट को पेश की। उसको 1 लाख रुपये का टैक्स देना था। वह एक्साइज़ एंड टैक्सेशन कमिश्नर को मिल कर इ.टी.ओ. पर प्रैशर डलवाया। उसे किसी ने 5000 रुपये ले लिये और किसी अफसर ने 10 हजार रुपये ले और इस तरह उसने 85,000 रुपये बचा लिये। जब इ.टी.ओ. ने देखा कि उसने सारा टैक्स किसी इंफलुएंशल आदमी के द्वारा मुआफ करा लिया तो वह अफसर छट पटाया और कहने लगा कि मैंने ठीक एसैसमेंट की थी। लेकिन वह कुछ नहीं कर सका क्योंकि वह टैक्स उसके बड़े अधिकारी ने मुआफ कर दिया। अगर अपील सुनने वाली और अथार्टी होती तो वह ई. टी. ओ. भी उसके आगे अपील कर सकता था। और 109 दिन कंडोंन कर दिये गए। अगर गवर्नमेंट अथारिटी होती तो ई. टी. ओ. को छूट होगी कि गवर्नमेंट को नुकसान हुआ है तो वह अपील कर सकता है और अगर डीलर्ज़ को नुकसान होता है।

And he feels himself injured at the hands of the Commissiner, he will have the right to appeal to the Government.

और गवर्नमेंट यही है फाईनेंस मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर। इसलिये मैंने तीनों अमैंडमैंटस दी हैं। मुझे आशा है कि फाइनेंस मिनिस्टर साहिब ज़रूर कुछ न कुछ सोचने की कृपा करेंगे।

ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ (ਧੂਰੀ ਐਸ. ਸੀ.) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਫੋਰਥ ਕਲਾਜ਼ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ Objects and Reasons ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਬਿਲ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਫੋਰਥ ਕਲਾਜ਼ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਿਤ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਲਗਾ ਹਾਂ......(ਵਿਘਨ)

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਦਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਸਬ ਕਲਾਜ਼ 1 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਰੀਨੀਓਲ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਰਖਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਰਖਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਚੂੰਕਿ ਹਾਊਸ ਦੀ ਇਹ ਖਾਹਸ਼ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਛਡ ਦਿਉ। ਪਰ ਜੇ ਕਰ ਮੈਂ ਦਸਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਰਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰਖ ਦਿਉ। (Interruption) ਦੂਸਰੇ ਪਾਰਟ ਨਾਲ ਮੈਂ ਐਗ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ : ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਚਲ ਰਹੀ ਇਹ ਬਿਓਰੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਫਸਰ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਰਖ ਦਿਉ ਤਾਂ ਜੋ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖਾਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ

[ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ]

ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਬੇਸ਼ਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਇਵੇਯਨ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਬੋਗਸ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਚੈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਲਾਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ! ਕਮਿਸ਼ਨਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਤਾਂ ਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲਾ ਰੀਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ। ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰੀਪੋਰਟ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਥਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁਲੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਸਪੈਕਟਰ ਜਾਣ ਕੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਕੇਸ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੰਥਲੀ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਧੰਨੀਆ ਚੁਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਚਿਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਭਜਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬਾਦ ਵਿਚ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਜੋ ਉਸਨੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੰਥਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਵੇਯਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਢ ਦਿਉ ਤਾਂ ਬਿਲ ਚੰਗਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ (ਮੋਗਾ) : ਕਲਾਜ ਨੰਬਰ 4 ਵਿਚ ਸਬ-ਕਲਾਜ਼ (1) ਡੀਲੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਲਈ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸ ਇਵੇਯਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਊਸ ਦਿਆਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਉਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਬਲਕਿ ਅਗਲੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਇਵੇਯਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਵੇਯਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਉਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕ ਸੌ ਰੁਪਿਆ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਤਬਕਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੌ ਰੁਪਿਆ ਆਪ ਕਮਾਵੇ ਅਤੇ ਸਵਾ ਸੌ ਰੁਪਿਆ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਕਹੋ ਕਿ ਜੁਰਮ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਉ ਅਤੇ ਥਾਣੇ ਢਾਹ ਦਿਉ, ਕੀ ਉਸ ਨਾਲ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰ ਜਾਵੇਗੀ ? ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਲੋਕਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਆਦਮੀ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕੰਸਟੀਚਿਊਐਂਸੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਸਕਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਇਵੇਜ਼ਨ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸਬ ਕਲਾਜ਼ 4 ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧੀਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਜੇ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਬੇਕਾਇਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇਵੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰੇ। ਬਾਬੂ ਜੀ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੰਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਦਾ ਹਾਂ ਕਿ

ਜੇਕਰ ਧੰਦੇ ਮਾਰਨ ਲਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਮਿਸ-ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਇਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਹਕਦਾਰ ਹਨ ।

ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ) : ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਚੁਕਿਆ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਬ-ਕਲਾਜ਼ 1 ਹੈ 4 ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਿਚ ਮੈਂ ਐਗ੍ਰੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡੀਲਰਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿਲ ਗਏ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਖਾ ਗਏ । ਜੇਕਰ ਹਰ ਸਾਲ ਰੀਨੀਊਲ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਂਦਾ । ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਆਦਮੀ ਵੀ ਚਸ਼ਮਪੋਸ਼ੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਸਬਕਲਾਜ਼ 1 ਨੂੰ ਛਡਣ ਵਿਚ ਮੈਂ ਐਗ੍ਰੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਨੰਬਰ ਦੋ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

Mr. Speaker : Question is—

Delete sub-clause (1).

The motion was carried.

Mr. Speaker : Amendment No. 5 stands in the name of Shri Mohan Lal.

Shri Mohan Lal : Sir, I beg to withdraw my amendment.

Mr. Speaker : Is it the pleasure of he House that the honourable Member Shri Mohan Lal be allowed to withdraw his amendment ?

Voices : Yes.

The amendment was by leave, withdrawn.

Mr. Speaker : Next amendments (Nos. 28, 29 and 211) have been given notice of by the honourable Member Shri Ram Saran Chand Mital.

Shri Ram Saran Chand Mital : Sir, I beg to withdraw my amendments.

Mr. Speaker : Has the honourable Member the leave of the House to withdraw his amendments?

Voices : Yes.

The amendments were, by leave. withdrawn.

Mr. Speaker : Amendments at Nos. 156, 157 and 158 stand in the name of the honourable Member Comrade Ram Piara.

Comrade Ram Piara : Sir, I beg to withdraw my amendments.

Mr. Speaker : Has the hon. Member the leave of the House to withdraw his amendments ?

Voices : Yes.

The amendments were, by leave, withdrawn.

Mr. Speaker : Question is—

That clause 4, as amended, stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 5

Mr. Speaker : Now Clause 5 is before the House. All the following amendments to this Clause will be deemed to have been read and moved and can be discussed along with it:—

6. Shri Mohan Lal :

In the proposed section 9, line 8, for "give security up to" *Substitute* "furnish surety or sureties for."

30. Shri Ram Saran Chand Mital :
In the proposed section 9, line 1, *for* "officer" *substitute* "Deputy Commissioner."

31. Shri Ram Saran Chand Mital :

At the end of the clause *add* the following :—

"in the following cases only:—

(a) when a dealer applies for registration under section 7 (2) or section 9, and it is found that any amount of tax under this Act has remained unpaid by the dealer or any of his partners, or the dealer or any of his partners has been convicted under this Act, or

(b) during continuance of a registration certificate if it is found that the dealer has without sufficient cause failed to pay any tax assessed under this act during the time permitted to do so under this act.

The amount of security shall not be excessive."

159. Comrade Ram Piara :

In the proposed section 9, line 1, *between* "officer" and "authorised" *insert* "holding rank not less than either P. C. S. or District Excise and Taxation Officer."

श्री यशपाल (जालन्धर शहर, दक्षिण पश्चिम) : स्पीकर साहिब, इस क्लाज़ में यह दर्ज किया गया है कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करने से पहले अगर इशुइंग अथारिटी मुनासिब समझे तो डीलर से सिक्योरिटी मांग सकती है। इसमें लफ्ज़

सिक्योरिटी इस्तेमाल किया गया है । यह नहीं डिफाइन किया गया, इस बात की इसमें वजाहत नहीं की गई कि वह किस तरह की सिक्योरिटी मांग सकता है। यह भी नहीं दर्ज किया गया कि किस बेसिज़ पर वह सिक्योरिटी मांगी जायगी । इन दोनो बातों की क्लैरीफिकेशन न होने के कारण इशुइंग अथारिटी को इतने वसीह अख्तियारात मिल जायेंगे कि उनके मिसयूज़ होने का डर है खास तौर से यह ऐसा प्रोविजन है कि जिस से जब कोई व्यापारी अपने आपको रजिस्टर कराना चाहे तो उसके रास्ते में रुकावट भी पैदा की जा सकती है । यह बात दुरुस्त है कि कुछ व्यापारी ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने इसका मिसयूज़ किया हो लेकिन ऐसी मिसालें बहुत कम मिलेंगी । इसके मुकाबिले में जो अथारिटी मिसयूज होती है उसकी मिसालें बहुत ज्यादा मिल सकती हैं। इसलिये मेरी दरखास्त यह है कि एक तो इसमें इस बात को स्पष्ट किया जाना चाहिए कि किस बेसिज पर सिक्योरिटी मांगी जा सकती है और दूसरे यह कि लफ्ज़ सिक्योरिटी को डिफाइन किया जाना चाहिए कि वह कैसी होगी यानी क्या वह पर्सनल सिक्योरिटी होगी, बांडज़ की सिक्योरिटी होगी, प्रापर्टी के अगेन्स्ट सिक्योरिटी होगी या कैश सिक्योरिटी होगी या चारों किस्म की होगी। इसलिये अगर फाईनेंस मिनिस्टर साहिब इसकी बाबत वजाहत कर दें तो बहुत अच्छा होगा । मैं आपकी मार्फत बड़े अदब से गुजाशि करना चाहता हूँ कि अब तक जहां जहां भी ऐश्योरेंश की ज़रूरत थी फाइनैंस मिनिस्टर साहिब ने उसे बड़ा लाईटली लिया है। यह काबले एतराज़ बात है। जैसे कि शुरू में हलवाइयों का मसला था। न ही उस सम्बन्ध में उन्होंने मुनासिब वज़ाहत की और न ही कोई अमैंडमेंट करने की तकलीफ गवारा की । अगर कोई अमैंड मेंट नहीं माना चाहते तो बेशक न मानें लेकिन इस सम्बन्ध में वजाहत तो कर दिया करें और इसके साथ ही जहां जहां एशोरेंश की ज़रूरत है वह भी हाउस के अन्दर आनी चाहिए । इसलिये इन शब्दों के साथ में फिर यह निवेदन करूँगा कि इन दोनों बातों को इस क्लाज़ के अन्दर साफ कर दिया जाए कि इस सिक्योरिटी का बेसिज़ क्या होगा और वह किस शक्ल में ली जायेगी ।

श्री मोहन लाल (बटाला) : इस क्लाज के अन्दर वज़ाहत के तौर पर मैंने यह अमैंडमैंट दी है कि सिक्योरिटी की जगह पर शोरिटी किया जाए। यह निहायत जरूरी है। इस पर अभी अभी एहतराज़ उठाया गया और मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता। वाकई सिक्योरिटी का जो लफ्ज़ है यह बड़ा मोअमल है । इसमें केश सिक्योरिटी भी आ सकती है। बांड भी आ सकता है। इसलिये जैसा कि अभी अभी कहा गया है इससे हार्डशिप होगी । इसलिये अगर सिक्योयरिटी लेना मकसूद ही है तो शोरिटी ले लें । मेरा ख्याल है कि फाईनैंस मिनिस्टर साहिब ने इस सम्बन्ध में अपना मन बना ही लिया होगा और कोई वादा भी दिलाया हुआ है । इसलिये मेरी अमैंडमेंट उनको ऐक्सैप्टेबल होगी।

कामरेड राम प्यारा (करनाल) : स्पीकर साहिब, इस क्लाज़ के मुताल्लिक पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि जैसा कि मैंने अपनी अमैंडमेंट में तजवीज किया है पहले फिकरे में जहां कमिश्नर आर एनी आफीसर अथोराइज्ड लिखा है वहां 'ऐनी आफीसर' की कोई डैफीनीशन नहीं दी गई । वह "ऐनी आफीसर" सब इन्स्पक्टर से लेकर डिप्टी

(कामरेड राम प्यारा)

ई. टी. ग्रो तक हो सकता है । इसलिये मैंने यह ग्रमैंडमेंट दी है कि वह पी. सी. ऐस. के रैंक का या डिस्ट्रिक्ट ऐक्साईज़ एंड टैक्सेशन ग्राफीसर से कम दर्जे का नहीं होना चाहिए ।

दूसरी बात यह है कि जहां पर सिक्योरिटी मांगी गई है वहां पर इस बात की, जैसा कि एहतराज़ किया गया है, तशरीह नहीं की गई कि वह पर्सनल बांड होगा, कैश सिक्योरिटी होगी या ग्रौर क्या होगा । लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि जहां पर भी कैश का नाम ग्रा जाता है वहां पर करप्शन पैदा होता है। वहां पर माया पैदा करने की बात ग्रा जाती है क्योंकि किसी को कुछ कहा जा सकता है, किसी को कुछ कहा जा सकता है। वैसे तो खुद सरदार कपूर सिंह जी ने इस बात को कबूल किया है कि दफ्तर वाले या ग्राफिशियल्ज़ गड़बड़ पैदा करते हैं। ग्रगर जो ग्रफसर सर्टिफिकेट गलत बनाता है तो जहां पर डीलर से पूछताछ हो वहां पर ग्रफसर की भी पूछताछ होनी चाहिए । बताया गया कि बहुत से बोगस सर्टिफिकेट्स नोटिस में ग्राए हैं इसलिये जरूरी है कि इस सम्बन्ध में ग्रफसरान की भी पूछताछ होनी चाहिए । इसके ग्रलावा सिक्यो-रिटी की नौईयत को डिफाइन किया जाना जरूरी है कि पर्सनल बांड होगा, पर्सनल सिक्योरिटी होगी या कैश सिक्योरटी होगी। ग्रौर हर हालत में जो ग्रफसर गलती करता हो उसकी भी पूछताछ होनी चाहिए ।

श्री राम सरन चन्द मित्तल (नारनौल): स्पीकर साहिब, इस क्लाज़ ५ पर मेरी भी दो ग्रमैंडमैंट्स है। इसमें कोई शक नहीं कि सिक्योरिटी ली जावे लेकिन इस क्लाज के ग्रन्दर यह नहीं लिखा हुग्रा कि सिक्योरिटी किन ग्राऊंड्ज़ पर ली जावे । वैसे सिक्योरिटी लेने का मतलब यह होता है कि गवर्नमेंट का रेविन्यु सिक्योर रहे, उस पर सेफगार्ड होना चाहिए । सिवाय रैविन्यु के सेफगार्ड के ग्रौर कोई दूसरी ग्राऊंड इस सिक्योरिटी की नहीं होनी चाहिए। यही कारण है कि इस क्लाज़ के ग्रन्दर इस सम्बन्ध में जो डिस्क्रीशन दी गई है उसको लिमिट करने के लिये मैंने एक ग्रमैंडमेंट दी है । वैसे ग्रमैंडमेंट तो एक ही है लेकिन उसके दो पार्ट हैं। पहिले केस में तो वह डीलर ग्राएगा जो कि फर्स्ट रजिस्ट्रेशन के लिये ऐप्लाई करेगा । उसके लिये मैंने सिक्योरिटी के सम्बन्ध में यह ग्रमैंडमेंट सुजैस्ट की है

"when a dealer applies for registration under section 7(2) or section 8 and it is found that any amount of tax under this Act has remained unpaid by the dealer or any of his partners, or the dealer or any of his partners has been convicted under this Act;'

यानी जो ग्रादमी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेकर बिज़नस करता है, टैक्स नहीं देता, भाग जाता है ग्रौर दूसरे नाम से एप्लाई करता है तो उसके नाम पर या उसके किसी पार्टनर के नाम पर टैक्स निकलता है तो उस सूरत में उसकी रजिस्ट्रेशन के लिये ग्राप सिक्योरिटी डिमांड कर सकते हैं। यह तो होगा फर्स्ट रजिस्ट्रेशन के लिये इससे सरकार का रैविन्यू सेफगार्ड होगा । दूसरी पोजीशन वह है जबकि रजिस्ट्रेशन की कन्टीन्युऐंस में ही सिक्यो-

रिटी की जरूरत पड़े । उसके लिये सिक्योरिटी की क्या ग्राउंड्ज़ होनी चाहिएं वह मैंने इस अमैंडमैंट के पार्ट बी. में यह तजवीज किया है:

'during continuance of a registration certificate if it is found that the dealer has without sufficient cause failed to pay any tax assessed under this act during the time permitted to do so under this act'

टैक्स पे करने का पीरियाडिकल टाईम होता है और अगर उस वक्त कोई टैक्स पे नहीं करता है, डिफाल्ट करता है तो लाज़मी है कि उन हालतों में सिक्योरिटी हासिल कर ली जाए । इसलिये मैंने ये ऊपर दोनों स्पैसिफिक ग्राऊंड्ज़ दे दिये हैं ताकि अगर इनमें जो जो डीलर कवर होते हों उनसे सिक्योरिटी डिमांड कर ली जाए। यह नहीं होना चाहिए कि हर एक से सिक्योरिटी मांगी जाए ।जो क्लाज़ बिल में प्रोवाईडिड हैं उसमें बड़ी वाईड पावर्ज़ थीं । मैंने इन अमैंडमैंट्स के जरिये उनको स्पैसिफिक और लिमिट कर दिया है ताकि सरकार का रुपया सेफगार्ड हो सके ।

जहां तक मेरी दूसरी अमैंडमेंट का ताल्लुक है उसमें मैंने ऐनी आफीसर की जगह पर डिप्टी कमिश्नर का सुझाव रखा है । यह कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अगर गवर्नमेंट मुनासिब समझे तो ठीक है नहीं तो जैसा है वैसा रहने दिया जाए।

Education Minister (Shri Prabodh Chandra) : On a Point of order, Sir. The honourable Member (Shri Mital) who has now come up with his amendments, is responsible for the this amending Bill as in-charge of the Department, when he was Minister. I have got his signatures sponsoring all the amendments now contained in the Bill. How can he now get up and raise objections to them by bringing forth new amendments? Having once committed himself to the Amending Bill, how can he oppose it ? Nothing has happened since then to warrant this.

श्री रामसरन चन्द मित्तल : यह क्या मौका यह बात करने का है ? अगर मैंटर री स्टार्ट किया जाए तो मैं भी बता दूंगा । यह क्या अननैसैसरी वहां पर मेरे दस्तखतों की बात कर दी ? कैबिनेट सीक्रेटस को यहां पर डाईवलज करना मुनासिब नहीं वरना मुझे अपनी पुज़ीशन को कलीयर करना होगा । मेरे व्यूज़ में और इस बिल के मुताल्लिक मेरे ऐटीच्यूड में पहले में और अब में कोई चेन्ज नहीं है । (विघ्न)

कामरेड राम प्यारा : आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर । मेरा प्वायंट आफ आर्डर यह है कि आनरेबल मिनिस्टर सरदार कपूर सिंह जी ने दो दफा जवाब देते हुए कहा कि इस कुर्सी पर आकर बात भूल जाती है। तो क्या इस कुर्सी पर आकर भी सारी पुरानी बातें नहीं भूल जातीं ? (हंसी)

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ) ; ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਲਾਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਵਰਡ ਬਾਈ ਵਰਡ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਵੇਖੋ , ਇਸ ਕਲਾਜ਼ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ;

"...... shall give security up to an amount and in the manner approved by Commissioner......"

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ ; ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਸੈਪਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ । (Does the hon. Minister accept any amendment ?)

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ : ਜੀ ਨਹੀਂ ।

शिक्षा मन्त्री (श्री प्रबोध चन्द्र) : जनाबे आली, यह जो अमैंडिग बिल हाउस में लाया गया है इसमें जितनी भी सख्त मदें थीं उनको निकाल दिया गया है और म्युचुअल डिस्कशन के बाद जो व्यापारियों के साथ फैसला हुआ था और जो जो बात जैनुइन समझी गई ताकि पंजाब के व्यापार पर बुरा असर न पड़े उन्हें लाया गया है । इस बात को भी मद्देनजर रखा गया है कि एडजाएनिंग स्टेट्स में जो लिमिट है या रेट आफ टैक्स हैं उनके मुताबिक यहां पर भी यूनीफारमिटी हो जाए । व्यापारियों की खाहिशात को सामने रखते हुए ही ये सभी चीज़ें की गई हैं। कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं है जो पहले से न हो ।

So, I would request the honourable Members not to oppose it for the sake of opposition.

अगर कोई रीअल हार्डशिप हो तो हम कोई ऐसी चीज़ नहीं चाहते जिससे न गवर्नमेंट को कोई फायदा हो और जिससे व्यापारी भाइयों को नुक्सान पहुंचता हो । अगर इस स्टेज पर भी कोई यह ऐसी चीज़ ले आएं तो हम उसको मानने के लिये तैयार हैं। जहां हमने कल से दस एमेंडमेंटस मान ली हैं तो एक आध और को भी मानने में कोई एतराज नहीं करेंगे । मगर उनकी बात में वजन हो । मगर मुझे अफसोस इस बात पर है कि आज से दो साल पहले तो यह सारी चीज़ें व्यापारियों के इनट्रेस्ट में समझते थे और गवर्नमेंट के इनट्रेस्ट में समझते थे लेकिन अब यह चीज़ें इनके ख्याल में व्यापारियों और गवर्नमेंट के इनट्रेस्ट में नहीं रही हैं।

(श्री रामसरन चन्द मित्तल की तरफ से विघन)

Mr. Speaker : Order please.

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ । ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਟਰ ਸਪੀਕਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸ੍ਰੀ ਮਿੱਤਲ, ਪੰਡਤ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਯਸ਼ ਲੇਕਿਨ ਸ੍ਰੀ ਪਰਬੋਧ ਤਾਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਿਦਿਆ ਮੰਤਰੀ ; ਨਹੀਂ ਬਾਬੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ।

चौधरी नेत राम : आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर । मैं स्पीकर साहब इस बात पर हैरान हूँ कि इस बिल पर बहस तो तीन दिन से यहां हो रही है लेकिन यह एक लावारस बच्चे की तरह लावारस बिल साबत हो रहा है क्योंकि अब की गवर्नमेंट कहती है कि यह बिल पहले की कैबीनेट का बना हुआ है और पुरानी कैबीनेट कहती है कि नहीं यह इन का बना हुआ है। तुर्रा यह कि वह कहते हैं कि पहली कैबीनेट खराब थी और यह कहते हैं कि इस वक्त की खराब है । तो इससे साफ जाहर है कि सारे कांग्रेसी खराब हैं ।

Mr. Speaker : Order please.

वित्त मंत्री (सरदार कपूर सिंह) : स्पीकर साहिब, यह क्लाज़ जो है यह दिल्ली के ऐक्ट की लफ्ज़ ब लफ्ज़ कापी है और इस स्कोप में पर्सनल सिक्योरिटी भी आ जाती है और कैश सिक्योरिटी आ जाती है इस तरह से इसका स्कोप काफी वाईड है और मेरा ख्याल है कि इसको इसी तरह से ही चलने देना चाहिए। इसलिये इसे इसी तरह से पास कर दिया जाए।

Mr. Speaker : Now I will put the amendments to this Clause to the vote of the House. Amendment No. 6 stands in the name of Shri Mohan Lal.

Shri Mohan Lal : Sir, I beg to seek the permission of the House to withdraw my amendment.

Mr. Speaker : Has the hon. Member the leave of the House to withdraw his amendment ?

Voices : Yes.

The amendment was by leave withdrawn.

Mr. Speaker : Now I will put amendments Nos. 30 and 31 of Shri Ram Saran Chand Mital to the vote of the House.

Shri Ram Saran Chand Mital : Sir, I beg to seek the permission of the House to withdraw my amendments.

Mr. Speaker : Has the hon. Member the leave of the House to withdraw his amendment ?

Voices : Yes.

The amendments were by leave withdrawn.

Mr. Speaker : Question is—

In the proposed section 9, line 1, between "officer" and "authorised" insert "holding rank not less than either P. C. S. or District Ecxcise and Taxation Officer."

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 5 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 6.

Mr. Speaker : Now Clause 6 is before the House. All the following amendments to this Clause will be deemed to have been read and moved and can be discussed along with the Clause itself:—

7. **Sardar Gurbakhsh Singh Gurdaspuri :**

Delete the proposed sub-section (3-A) of sub-clause (1)'

8. **Shri Mohan Lal :**

Delete sub-clause (1).

9. **Shri Mohan Lal :**

Delete sub-clause (2).

10. **Shri Mohan Lal :**

Delete sub-clause (3).

32. **Shri Ram Saran Chand Mital :**

Delete sub-clause (1).

33. **Shri Ram Saran Chand Mital :**

In sub-clause (4), line 3, before "to which" insert the following:—
"which may be found unpaid out of the amount of tax".

62. **Shri Yash Paul**

Delete sub-clause (1).

91. **Shri Chandi Ram Verma :**

Delete sub-clause (1).

122. **Shri Balramji Das Tandon :**

123. **Dr. Baldev Parkash :**

124. **Shri Fateh Chand Vij :**

In sub-clause (1), *delete* "dealer."

125. **Shri Balramji Das Tandon :**

126. **Dr. Baldev Parkash :**

127. **Shri Fateh Chand Vij**

In the proposed sub-section (3) of sub clause (1), lines 3-4, *delete* "supported by affidavit as to the correctness there of".

160. **Comrade Ram Piara ;**

Delete sub-clauses (1), (2) and (3).

श्री चांदी राम वर्मा (अबोहर) : स्पीकर साहिब, मेरी यह छोटी सी अमेंडमेंट इस क्लाज़ की सब क्लाज़ 1 को डिलीट करने के लिये है। यह बड़ी सिम्पल है और मेरा ख्याल है कि फिनांस मिनिस्टर साहिब इसको मन्ज़ूर कर लेंगे। कल चीफ मिनिस्टर साहिब ने भी इसको मानने के लिये इशारा किया था।

Education Minister : The Government accepts it.

Shri Mohan Lal: Mr. Speaker, as I submitted earlier, I would request that in the case of identical amendments to a clause, they be put to the vote of the House in the order in which they were received. Accordingly my amendment No. 8 which seeks to *delete* sub-clause (1) be put earlier than the similar amendment given notice of by Shri Chandi Ram Verma, which would alongwith other identical amendments become unnecessary.

तो इसके लिए मैं सिर्फ इतना ही अर्ज़ करना चाहूँगा कि यह नई क्लाज़ के लाने की गवर्नमेंट को सिर्फ इस लिये ज़रूरत महसूस हुई है क्योंकि वह चाहती थी कि रिटन्र्ज़ वगैरह के साथ एफीडेविट्स लिये जाएं। लेकिन मैं इसकी तफसील में अब नहीं जाना चाहता क्योंकि गवर्नमेंट ने अब इस बात को मान लिया है कि इस एफीडेविट्स वगैरह की क्लाज़ को डिलीट कर दिया जाए इस लिये मैं अब आर्गूमेंट्स में नहीं पड़ता। मैं आपसे यह दरखास्त करता हूँ कि मेरी जो अमेंडमेंट नं० 8 हैं it should be first put to vote.

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ) : ਮੈਂ ਇਸ ਕਲਾਜ਼ ਦੇ ਬਰਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਉਰਿਜਨਲ ਕਲਾਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁਨਾਸਬ ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਬਿਉਪਾਰੀ ਐਫੀਡੇਵਿਟਸ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰਨ ਔਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਰੈਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੀ ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਕਤੱਈ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਬਿਉਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੀਪਰੀਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼ 30 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ।

Mr. Speaker : Now the question is........

श्री राम सरन चन्द मित्तल : स्पीकर साहिब, आपने मेरी एक अमेंडमेंट छोड़ दी है....

Mr. Speaker : I will be putting first the amendment of Sardar Gurbakhsh Singh Gurdaspuri (No. 7) to the vote of the House and will put all the amendments to the House one by one in the order in which they were received.

श्री राम सरन चन्द मित्तल : स्पीकर साहिब, क्लाज़ 6 की सब क्लाज़ 4 के बारे में मेरी एक अमेंडमेंट थी.....

Mr. Speaker : I am taking up all the amendments to Clause 6.

Shri Ram Saran Chand Mital : I have given notice of other amendments to this Clause and I want to say some thing in regard to them.

Mr. Speaker : I am sorry, I cannot allow the hon. Member to speak on the Clause after the hon. Minister has replied to the dabate.

Shri Ram Saran Chand Mital : On a point of order, Mr. Speaker.

Mr. Speaker : The hon. Member will agree that he cannot stand, when I am on my legs.

श्री राम सरन चन्द मित्तल : मैं प्रोसीडिंग्ज़ ओबस्ट्रकट नहीं करना चाहता और बैठ जाता हूँ लेकिन मेरी सिर्फ यह अर्ज़ है.......

Mr. Speaker : I am sorry, the honourable Member did not get up at the proper time and now I cannot allow him since the honourable Minister has already replied.

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਸਰ । ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਰਾਈਟ ਪਰੋਸੀਜਰ ਐਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਫਿਨਾਂਸ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਸਟਰ ਚਾਂਦੀ ਰਾਮ ਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ।

Mr. Speaker : Question is—

Delete the proposed sub section (3A) of sub clause (1)

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

Delete sub-clause (1).

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now I will put amendments regarding deletion of sub-clauses (2) and (3) by Shri Mohan Lal to the vote of the House.

Question is—

Delete Sub-clause (2) and

Delete Sub-clause (3)

The motions were lost.

Shri Mohan Lal : Sir, these are consequential amendments and we have said 'Ayes have it.' Therefore, kindly revise your ruling.

Finance Minister : These are consequential amendments.

Comrade Gurbakhsh Singh : On a point of order, Sir...........

(*Interruptions*).

Mr. Speaker : Please take your seat. Any genuine mistake can be corrected by me any time.

(*Interruption*)

श्री अध्यक्ष : अगर सब-क्लाज वन डीलीट हो जाए तो उसका क्या कनसीक्वेंस होगा ?

(If sub-clause (1) is *deleted*, then what will be the consiquence?)

Finance Minister : With the deletion of sub-clause (1), sub-clauses (2), (3) and (4) will become sub-clauses (1), (2) and (3).

Mr. Speaker : The amendments by the honourable Member are for the deletion of sub-clauses (2) and (3). How are these consequential? These are not consequential but substantial amendments.

Finance Minister : Then we oppose these. We are sorry.

Mr. Speaker : I declare those amendments as lost.

Now I will put the amendment by Shri Ram Saran Chand Mital to the vote of the House.

Question is—

In sub-clause (4), line 3, *before* "to which" *insert* the following:—

"which may be found unpaid but of the amount of tax".

The motion was lost.

Mr. Speaker : Now I will put the amendments by Sarvshri Balramji Dass Tandon, Baldev Parkash and Shri Fateh Chand Vij.

Question is.—

In the proposed sub-section (3) of sub clause (1), lines 3-4, delete "supported by affidavit as to correctness thereof".

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That clause 6, as amended, stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 7

Mr. Speaker : Now we come to clause 7. The following amendment by Shri Ram Saran Chand Mital to this clause will be deemed to have been read and moved and may be discussed with the Clause.

Delete sub-clause (2).

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ (ਲੁਧਿਆਣਾ ਉਤਰ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵਿਚ ਦੋ ਗਲਾਂ ਹਨ ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ 'ਰਜਿਸਟਰ ਡੀਲਰ' ਦੀ ਥਾਂ 'ਡੀਲਰ' ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰਜਿਸਟਰ ਡੀਲਰ ਹੈ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਤਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਅਗਰ ਜਿਸ ਡੀਲਰ ਦੀ ਅਜੇ ਰਜਿਸ਼ਟਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹੜਾ ਘਟ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਡੀਲਰ ਦਾ ਲਫਜ਼ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਰੇੜ੍ਹੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਦ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ! ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣਗੇ ਅਤੇ ਤੰਗ ਕਰਨਗੇ । ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਟੀਡਰ ਨੋਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਚਾਰ, ਅੱਠ ਆਨੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਦੂਜੀ ਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿਉ । ਜਿਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਥ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਚਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਗਰ ਜਿਥੇ ਜਿਥੇ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਘਟ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਫਿਨਾਂਸ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਹਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਕੋਈ ਘਟ ਨੇ ? ਚਲੋ ਕਰ ਲਉ ਇਹ ਗਲ ਰਜਿਸਟਰ ਡੀਲਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪਰ ਜੋ ਲਫਜ਼ ਡੀਲਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਅਗਰ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਜਾਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਜ਼ਿਦ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕੋਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਰਲ ਡੀਲਰ ਵਿਚ ਤਮੀਜ਼ ਕਰੋਗੇ ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਲਾਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਅਗਰ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮਿਸਚਿਫ ਦੇ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਖੁਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਬਿਦਅਤ ਅਤੇ ਬਿਆਰੀ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀ ਡਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ ।

श्री मोहन लाल (बटाला) : स्पीकर साहिब, मैं भी फिनांस मिनिस्टर साहिब से रिक्वैस्ट करूँगा कि वह इस क्लाज़ को ड्राप कर दें । अभी अभी आनरेबल मैम्बर बाबू बचन सिंह जी ने जो बात कही है उसमें बहुत हद तक वज़न है । बहुत ऐसे छोटे छोटे आदमी हैं जो किसी वक्त भी 'रजिस्टर्ड डीलर' की जद में आ ही न सकेंगे मगर 'डीलर' का लफ्ज बड़ा वाइड है और इसमें किसी को भी पकड़ा जा सकता है । इसलिये मैं इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि 'रजिस्टर्ड डीलर' के जो लफ्ज़ पहले ही हैं वही ठीक हैं ।

जहां तक चार से पांच साल तक मियाद बढ़ाने का सवाल है इस बारे में अर्ज़ है कि पहले यह मियाद चार साल भी नहीं थी तीन साल थी । उसको कुछ अर्सा पहले अमैंड करके चार साल किया गया । चार साल से सरकारी कर्मचारियों की तसल्ली नहीं हुई तो आज कह रहे हैं कि पांच साल कर दें । हो सकता है कि कल को इससे भी उनकी तसल्ली न हो तो कहेंगे कि इसको 6 या 7 साल कर दो । तो इस तरह से इसकी लिमिट कहां तक जायगी । अव्वल तो टैक्सेशन के मामले में सारी बात कम से कम अर्से में मुकम्मल होनी चाहिए ताकि न तो डीलर किसी सस्पैंस में रहे और

न ही सरकार के रवेन्यू को सरकारी खजाने में आने में किसी किस्म की देर हो। इसलिये मैं कहता हूँ कि इस वक्त चार से पांच साल करने के लिये कोई जस्टीफिकेशन बनती नहीं है। इसलिये मेरी फिनांस मिनिस्टर साहिब से प्रार्थना है कि चार साल ही खाफी हैं। इसलिये इस क्लाज़ को ड्राप ही कर दें।

चौधरी इन्द्र सिंह मलिक (सफीदों): स्पीकर साहिब, अभी दो आनरेबल मैम्बरान ने इस क्लाज के बारे में अपनी गजारिश की है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से यह डीलर का लफ्ज़ इसमें रखना चाहते हैं इससे बड़ी पेचीदगियां पैदा होंगी। इस तरह से तीस रुपये माहवार कमाने वाला भी इसकी जद में आ जायगा। इस तरह से छोटे छोटे दुकानदारों को भी हैरासमेंट होगी। अफसरों के तो आप जानते हैं कि पहले ही महीने बंधे रहते हैं और अब इसके बाद जो मूंगफली बेचता है या रियोड़ी की रेढ़ी लगाता है उससे भी शाम को इन्स्पैक्टर साहिब चार आठ आने मांगेंगे। इससे छोटे छोटे दुकानदारों को बड़ी हैरासमेंट होगी इसलिये रजिस्टर्ड डीलर के लफ्ज़ रहने चाहिएं। डीलर का लफज़ करने से महकमे को बहुत वाइड पावर दी जा रही है इससे लुट का बाजार और भी गर्म होगा। इसलिये कहूँगा कि 'रजिस्टर्ड डीलर' का लफ्ज़ ही रहने दिया जाए। दूसरा यह कि 4 साल की बजाए 5 साल किया जा रहा है। पंडित जी ने जैसा कि बताया है कि इसको आगे ही बढ़ाया जा चुका है और 3 साल से 4 साल किया गया था। और यह 8 और 9 क्लाज़ में भी आता है इस तरह के इख्तियार क्यों अफसरान को दिये जा रहे हैं जो 4 साल में कुछ न कुछ कर सकें वह 5 में भी न कर पाएंगे यह उनकी एफीशैन्सी का सबूत है। इसलिये मैं यह कहूँगा कि इस सारी क्लाज़ को ही डिलीट कर दिया जाए।

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ (ਸਿਧਵਾਂ ਬੇਟ ਐਸ. ਸੀ.) ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਂਦਿਆਂ ਫਿਨਾਂਸ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡੀਲਰਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੀਅਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਦੁਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਜ਼ ਰਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰ ਡੀਲਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭੇਡ ਬਕਰੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਰੂਪੀ ਭੇੜੀਏ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੀ **ਦਸ਼ਾ** ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਡਰ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਥਾਣੀ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ (ਵਿਘਨ) ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾਂ ਖੰਨੇ ਵਿਚੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਖ਼ਾਣ (ਵਿਘਨ) ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦੇਣ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ

[ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ]

ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਮਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਤੇ ਲਿਆਕਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪੀਟੈਨਸੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਣ ਅਤੇ ਆਪ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾਂ ਭਾਰੀ ਅਸਰ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਗਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਥ ਵਿਚ ਨਾ ਦੇ ਦੇਣ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਲਾਜ਼ ਇਸ ਵਿਚ ਰਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

श्री यश पाल (जालन्धर शहर, दक्षिण पश्चिम): स्पीकर साहिब, मैं इस क्लाज़ के बारे में फिनांस मिनिस्टर साहिब का ध्यान इस बिल की स्टेटमेन्ट आफ आबजैक्टस एन्ड रीजन्ज़ की तरफ दिलाना चाहता हूँ और उसके बाद इस क्लाज़ की तरफ आऊंगा और यह बताऊंगा कि इन दोनों में कितनी कन्ट्राडिक्शन है।

स्टेटमेंन्ट आफ आबजैक्टस एन्ड रीजन्ज़ में इन्होंने कहा है कि——

"The Bill is designed to remove certain flaws and lacunae which have been found from experience to exist in the Punjab General Sales Tax Act, 1948 and to provide for the better administration of the Sales Tax law by taking powers to levy tax at the first stage, check evasion, impose restraints on bogus and unscrupulous dealers......................"

इसका मकसद यह है कि इस बिल में जो खामियां और लैकूना एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रह गई हैं उसे दूर किया जा सके और दूसरी तरफ इस क्लाज़ के द्वारा जो इनके महकमा की इनएफीशैन्शी है कि वह वक्त पर पड़ताल नहीं कर सके उसको छुपाने के लिये 5 साल का अर्सा मुकर्रर किया जा रहा है। जो काम महकमा वाले एक साल में न कर सकें, दो साल और तीन साल में न कर सके और फिर 4 साल करने पर भी न कर पाए उसके लिये अब 5 साल का अर्सा मुकर्रर किया जा रहा है I think this is a cover for inefficiency.

दूसरी बात यह है कि तमाम और बातों में कानून की तीन साल की म्याद मुकर्रर है और इसके बाद जायदुल म्याद करार दिया जाता है। इस बिल में भी यह बात किसी और जगह है कि जिसने रिफन्ड लेना हो वह तीन साल के अन्दर ले सकता है। तो फिर समझ नहीं आता कि आप रिफन्ड देने के लिये तो तीन साल ही रखना चाहते हैं और लेने के लिये 5 साल की मियाद मुकर्रर करना चाहते हैं। यह लेने और, देने के बट्टों में सरकार कब से इस तरह करने लगी कि लेने के बट्टे और देने के और। यह तो कहा करते हैं कि व्यापारी इस तरह करते हैं कि वह माल लेने के वक्त और, देने के वक्त और बट्टे इस्तेमाल करते हैं। इस लिये मैं यह कहूँगा कि इस तरह से तीन साल करना चाहिए था चार की बजाए और आप तो 5 साल कर रहे हैं इससे तो इनएफीशैन्शी बढ़ेगी।

कामरेड राम प्यारा (करनाल): स्पीकर साहिब, मैं तो फिनांस मिनिस्टर साहिब का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि जिन अफसरान ने 4 साल तक इस तरह की गड़बड़ को ओवरलुक किया है क्या उनकी कोई पूछताछ की जायेगी। मैंने करनाल कोआप्रेटिव स्टोर के बारे में बताया और उनकी किताबें ज़ब्त की गईं तो इस गड़बड़ को जांच करने में कोताही करने वाले अफसरान के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? जब पूछा जाए तो कहा जाता है कि अफसर ट्रांसफर हो गए और कुछ रिटायर हो गए। तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि आया उन अफसरान की कोई पूछताछ भी होगी या नहीं कि जो चार साल में न कर पाए, नहीं तो 5 साल कर देने से भी यह अफसरान कुछ न कर सकेंगे।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ (**ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ**) : ਸਾਹਬੇ ਸਦਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਕੇ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਯਸ਼ ਜੀ ਇਸ ਗਲ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਯਸ਼ ਜੀ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਣਾਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਮਾੜਾ ਦਿਸ ਪਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਾਂ ਮੰਨੀਆ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਗ ਪਏ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗਲਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਵੇਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਲ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਗਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 7 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੇਖਣ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕੁਝ ਵਪਾਰੀ ਉਲਟ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਤ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿਉ। ਅਸਾਡੀ ਵੀ ਇਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਵੇਰ ਕੁਝ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗਲ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਅਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਗਲ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿਉ ਇਸ ਲਈ ਇਹ 5 ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਗਲ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਫਾਜ਼ਲ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਸਾਬ ਦਿਖਾਣ ਨਾਲ ਰੀਬੇਟ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਰਖੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਰਖੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਰਿਬੇਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਗਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਬੇਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਬੀਟਵੀਨ ਦੀ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੀਟਵੀਨ ਦੀ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਬੇਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਰਾਹੀਂ ਯਕੀਨ ਦਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗਰੁਪ ਤਾਂ ਮਨ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਭੈੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ

[ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ]

ਕਿ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਸਟਮੈਂਟ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਤ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

Mr. Speaker : All the amendments which seek the deletion of the Clause are out of Order. The amendment given notice of by the hon. Member Shri Ram Saran Chand Mital seeking the deletion of Sub-Clause (2) is in order and I will put this amendment to the vote of the House.

Mr. Speaker : Question is—

Delete sub-clause (2).

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 7 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 8

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 8 stand part of the Bill.

The motion was carried.

(At this stage, Sardar Balwant Singh rose to Speak).

Mr. Speaker : The hon. Member should please resume his seat. I am sorry.

Sardar Balwant Singh : Sir, this is a very important clause.

Mr. Speaker : I am sorry. This is not the stage. The honourable Member should please resume his seat.

Sardar Balwant Singh : On a point of Order Sir. Mr. Speaker......

Mr. Speaker : There should be no discussion about Clause 8.

Sardar Balwant Singh : Sir, I could not get up because you were standing.

Mr. Speaker : No please. The hon. Member was busy other-wise. He should please resume his seat. Clause 8 has already been adopted.

CALUSE 9

Mr. Speaker : The following amendments will be deemed to have been read and moved—

Shri Ram Saran Chand Mital :

For Clause 9, substitute the following—

> "9. Whenever any amount of tax is liable to be refunded under this Act, the Assessing Authority shall refund it even without any application from the claimant there of with in three months from the date on which the claim for refund accrues, failing where in interest would be paid to the dealer at the rate of 3 per cent per annum on the refundable amount of tax from the date on whcih the dealer had deposited or paid the amount of tax till date of tender of the refund voucher to the dealer or the date on which it is deducted from the amount of tax due from him in respect of any other period."

Thakur Mehar Singh :

For the clause subtitute the following—

> "9. Whenever any amount of tax is liable to be refunded under this Act, the Assessing Authority shall refund it even without any application from the claimant, thereof within three months from the date on which the claim for refund accurues, failng where in interest would be paid to the dealer at the rate of 3 per cent per annum on the refundable amount of tax from the date on which the dealer had deposited or paid the amount of tax till date of tender of the refund voucher to the dealer or the date on which it is deducted from the amount of tax due from him in respect of any other period."

Comrade Ram Piara :

For the clause substitute the following—

> "9. Whenever any amount of tax is liable to be refunded under this Act, the assessing authority shall refund it even without any application from the claimant thereof within six months from date on which the claim for refund accrues, failing wherein six per cent interest per annum would be paid to dealer on the refundable amount of tax from the date on which it is deducted from the amount of tax due from him in respect of any other period and officer responsible for his failure of the refund shall have to explain the reasons in writing for the failure to refund the amount to the dealer".

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ (ਲੁਧਿਆਣਾ ਉੱਤਰ): ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਦੀ ਵਸਾਤਤ ਨਾਲ ਇਕ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਫਾਦਰ ਆਫ਼ ਦੀ ਨੇਸ਼ਨ ਜਿਊਂਦੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾਭਾ, ਸਰਦਾਰ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ, ਸਰਦਾਰ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਕਵੀਸ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀ........

ਵਿਦਿਅਕ ਮੰਤਰੀ: ਬਾਬੂ ਜੀ, ਮੁਨਾਸਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਉਂ ਨਾ ਲਓ।

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ: ਚਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਨਾਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਕ ਲੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਜ਼ਾਇਦਉਲ ਮਿਆਦ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ। (ਇਕ ਮਾਨਯੋਗ ਸਦਸਯ: ਬਾਬੂ ਜੀ, ਇਕ ਲੱਖ ਨਹੀਂ 10,000 ਰੁਪਿਆ ਦੇਣਾ ਸੀ) ਚਲੋ ਕੁਝ ਕਹੋ ਦੇਣਾ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਇਕ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਅੱਲੁਕ ਰਖਦਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਿਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਖਲਾਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਲਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ

[ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ]

ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਖਲਾਕ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਇਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਕ ਰੁਪਿਆ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫੇਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ । ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜੇ ਖੁਦ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਿਤਨੀ ਬੋਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ । ਉਸ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਹਕ ਬਜਾਨਬ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 1948 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 1965 ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਲਾਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਕਾਇਆ ਰੀਫੰਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਪਈ ਹੈ । ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਚਾਹੇ ਗਲ ਗੂਠਾ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਰੈਡ ਟੇਪਇਜ਼ਮ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਫੈਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਹ ਜ਼ਾਇਦੁਲ ਮਿਆਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਣ ਉਸ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਤਕ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ । ਨਿਤ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਪਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸਵੇਰੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਕਿ 20 ਦਿਨ ਨੂੰ ਫੇਰ ਆਉਣਾ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ, ਯੂਨੀਨਿਸਟ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵੇਖੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਓਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਬਿਉ-ਪਾਰੀ ਨੂੰ ਇਉ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਦ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ 5-6 ਸਾਲ ਬਾਦ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਇਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਟ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਉਕਾ ਹੀ ਮੁਕਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ । ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਵਧ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਦ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਅੱਛੀ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਹ ਇਕ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇਕ ਗਲਤ ਕਲਾਜ਼ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਪਲੀ ਕੇਡਿਟ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਲਿਆਂਦੀ । ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮੁਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦਵਾਲਾ ਕਢ ਦੇਂਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । (ਇਕ ਮਾਨਯੋਗ ਸਦਸਯ ਬਾਬੂ ਜੀ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਕ ਹੈ). ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੀ ਦਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ । ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰ

ਦਿਆਂਗੇ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਤਾਂ ਤਦ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮਨਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪਾਵੀਜ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਵੋ।

ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ (ਸੁਲਤਾਨ ਪੁਰ): ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਗਲ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਕਲਾਜ਼ 9 ਦੇ ਰੀਫੰਦ ਦੇ ਸਿਲਸਲੇ ਦੇ ਵਿਚ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਉਪਾਰੀ ਪੈਸੇ ਵਧ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੂਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਰਾਪਰ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਕੇ ਪੈਸੇ ਰੀਫੰਡ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਜੀ.ਪੀ.ਓ. ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਵਧ ਪੈਸੇ ਲਾਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਵਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਜੇ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕਮ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਫੀਸਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦੇਵੇ ਕਿ ਵਧ ਪੈਸੇ ਲਗਾਏ ਹਨ ਤਾਂ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਬਿਉਪਾਰੀ ਡੀਮਾਂਡ ਕਰੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰੇ ਜਾਨ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰ ਚੈਨਲ ਥਾਨੀ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰੇ। ਕਲਾਜ਼ 8 ਜਿਹੜੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਡੈਮਾਕਲਸ ਸੋਰਡ ਹੈ ਜੋ ਬਿਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਟੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਬਾਦ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ......

Education Minister : On a point of Order, Sir. The hon. Member is discussing Clause 8 which has already been passed. He cannot discuss that Clause now.

(Sardar Gurnam Singh a member of the panel of Chairmen in the Chair).

Sardar Balwant Singh : Sir, I am speaking on Clause 9. I only referred to Clause 8 while speaking.

Education Minister : I am sorry, I would not like to contradict the hon Member. You had better asked the Members whether he was discussing Clause 8 or Clause 9.

Mr. Chairman : It is unnecessary to go into evidence. Let the hon. Member please speak on Clause 9.

श्री सुरेन्द्र नाथ गौतम : चेयरमैन साहिब इस पर स्पीकर साहिब अपना रूलिंग दे चुके हैं कि यह क्लाज़ पास हो चुकी है। तो मैं आप से रूलिंग चाहता हूं कि जो चीज़ पास हो चुकी हो उस पर क्या कोई बोल सकता है ?

ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ : ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਵੀਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਜੋ ਅਮਾਊਂਟ ਰਿਫੰਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਦੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੀ ਕਲਾਜ਼ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ (ਫੂਲ): ਜਨਾਬ, ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਮਾਊਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਆਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਟੋਮੈਟੀਕਲੀ ਰਿਫੰਡ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਿਮ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪੈ

[ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਂਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ]

ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤਕ ਕੋਈ ਅਮਾਉਂਟ ਵਾਪਿਸ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ ਤਾਂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਵਾਲਿਆਪਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਣ ਦੇ ਅਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਬੱਟੇ ਇਕੋ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੁਲਾ-ਬੁਲਾ ਕੇ ਰਕਮ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚੈਕ ਰਾਹੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਿਆਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

कामरेड राम प्यारा (करनाल) : जब चेयरमन साहब, गवर्नमेंट के पास रुपया ज्यादा चला जाये तो उसे खुद ही वापस करना चाहिए। (विघ्न) एक बात देखने में आती है कि अगर किसी डीलर की किताबों में कोई कमी पेशी आ जाए तो गवर्नमेंट उसे सजा देती है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि यही असूल सरकार के लिये भी इस्तेमाल होना चाहिए कि जब कोई कर्मचारी गवर्नमेंट की किताबों में कोई चीज कमीबेश कर देता है तो उस अफसर पर चार्ज लगना चाहिए और उसे पीनेलाइज किया जाना चाहिए और गवर्नमेंट पर यह पाबन्दी आयद होना चाहिए यह कि रुपया वह सुओमोटो वापस करे। तीन साल की मियाद लगा कर सरकार ने लोगों को शक एंटरटेन करने का मौका दिया है। यह नहीं होना चाहिए। बल्कि जैसा मैंने कहा है कि गवर्नमेंट अपने आप रुपया वापस करे और 6 महीने के अन्दर अगर वह रुपया वापस न हो पाए तो अफसर कन्सर्ण्ड की जवाबतलबी होनी चाहिए ताकि जनता के अन्दर यह कानफिडेंस पैदा हो कि सरकार अपनी है। इसलिये मैं मिनिस्टर साहब से अपील करूँगा कि इसे मंजूर करें।

पंडित मोहन लाल (बटाला) : जनाब चेयरमैन साहिब, मैं उन आरग्यूमेंट को जो मैम्बर साहबान [illegible] कर चुके हैं [illegible] नहीं। जो [illegible] हो जाये उसके लिये मैं सरकार को कहूँगा कि वह अमानत के तौर पर सरकार के पास रहे। चेयरमेन साहब, आपका बहुत तजुर्बा है और आप इस वक्त चेयर में हैं कहीं भी ऐसा कानून नहीं है कि जो रुपया अमानत का हो उसकी कोई मियाद मुकर्रर हो। ट्रस्ट वगैरह के द्वारा भी जो रुपया अमानत का हो उसके लिये भी कोई मियाद नहीं है। मगर हमारी सरकार एक नई बात सिखाने चली है और ३ साल के बाद अमानत के रुपये को जब्त करना चाहती है। यह रुपया आखिर सरकार किस मद्द में एंटर करेगी। हर आइटम्ज़ के लिये हैडज़ हैं जिनमें आया हुआ रुपया क्रैडिट किया जाता है, मैं एक बार फिर पूछना चाहता हूँ कि वह कौन सा हैड होगा जिसमें यह अमानत का रुपया क्रैडिट किया जायगा। यह तो सरकार अमानत में खयानत करने वाली बात कर रही है। इसलिये यह कानून के खिलाफ बात होगी अगर ऐसे रुपये के लिये तीन साल की मियाद मुकर्रर की जाए। मैं आखिर में तमाम मैंबर साहबान के ख्यालात के साथ इत्तिफाक करता हूँ और फाइनेंस मिनिस्टर साहब को प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जिस तरह से वह एक ओर अपनी मियाद 3 साल से 4 साल और 4 साल से 5 साल कर ली है और पता नहीं कहां तक ले जायें मगर दूसरी वह रुपये को लौटाने की मियाद तीन साल कर रहे हैं, यह न करें। यह कहां का इंसाफ है? मैं समझता हूँ कि चूंकि यह क्लाज मुनासिब नहीं है, इसलिये मिनिस्टर साहिब इसे विदड्रा कर लें।

श्री राम सरन चन्द मित्तल (नारनौल) : मैंने यह अर्ज़ करनी है कि एक ओरिजनल कोर्ट का फैसला होता है ......

श्री सभापति : महता साहिब, क्या ट्रब्ल है ? (What is the trouble with the hon. Member, Shri Roop Lal Mehta?)

श्री रूप लाल महता : चेयरमैन साहिब, इस क्लाज़ के प्रोवाइज़ो में लिखा है कि अगर वह तीन साल तक क्लेम नहीं करेगा तो उसे रिफंड नहीं मिलेगा।

> "Provided further that no refund under this section shall be allowed unless the claim for refund is made within a period of three years from the date on which such claim accrues."

Mr. Chairman : Mehta Jee, Shri Ram Saran Chand Mital is already on his legs and he has not finished his speech.

श्री राम सरन चन्द मित्तल : चेयरमैन साहिब, मैं अर्ज़ कर रहा था कि इस में यह हार्डशिप का वाइस बन सकती है । एक जो ओरिजनल कोर्ट है यानी इ. टी. ओ. फैसला करता है कि एक आदमी पर 5000 रुपया टैक्स लगा दिया। डीलर अपील करता है और अपिलेट अथार्टी उसे 3000 कर देती है । वह डीलर अपीलेट अथार्टी के फैसले के खिलाफ चाराजूही करता है और महकमा भी टैक्स बढ़वाने के लिये आगे चाराजूही करता है, यानि अपीलेर्ट अथार्टी के फैसले के खिलाफ दोनों अपील या निगरानी चाहते हैं। और यह चाराजूही यानि अपील या निगरानी तीन साल से ज्यादा अर्सा चले तो रिफन्ड खतरे में हो जाता है क्योंकि महकमा चाराजूही करना चाहता है तो पहले अपील के फैसले के मुताबिक रिफंड नहीं देंगे अगर वह पहले रिफंड के लिये अपलाई करता है तो उसके दूसरे अपील या निगरानी के समय यह एतराज होगा कि चूंकि इसमें रिफंड को क्लेम करके पहले अपील का फैसला मान लिया तो अब उसके खिलाफ मज़ीद चाराजूही करने का हक नहीं रहा । उसकी अपील या निगरानी खतरे में हो जातीहै अगर वह आदमी तीन साल के अन्दर अन्दर क्लेम नहीं करता तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। इसके ऊपर की अथार्टी के पास जाता है और उसका फैसला वही होता है जो एपिलेट अथार्टी ने किया था । अगर वह अपना रिफन्ड क्लेम नहीं करता है और एतराज़ करता है तो उसे कुछ नहीं मिलेगा । अगर वह अथार्टी कुछ इन्हांस कर देती है थर्ड स्टेज यानी टैक्स कम कर देती है पर और चार साल तक मुकद्दमा चलता रहता है तो वह रिफंड क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि उसका क्लेम टाइम बार्ड हो जायगा। अगर आखरी अथार्टी रिजैक्ट कर देती है तो उसे 2000 रुपया जो फस्ट एपिलेट अथार्टी ने उसके हक्क में फैसला देते हुए दिया था वह भी उसे नहीं मिलेगा । चार साल तक मुकद्दमा चलता है तो वह क्लेम उस नहीं मिलेगा क्योंकि वह टाइम बार्ड हो गया है । रिफंड के लिये तो हमेशा कोशिश होनी चाहिए कि उसे क्लेम के पैसे फौरन दिये जाएं । और मेरी तरमीम का मतलब भी यही है कि जल्दी से जल्दी रिफंड मिले । मैंने अमेंडनमेंट दी है कि तीन महीने के अंदर अंदर पे कर देना चाहिए । यह मेरी अमेंडमेंट है।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ (ਮੁਰਿੰਡਾ ਐਸ. ਸੀ.) : ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਲਾਜ਼ 9 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰੋਵਿਜ਼ੋ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 12 ਹੇਠ ਇਹ ਪਰੋਵਿਜ਼ੋ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਗਾ

[ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ]

ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਮੋਰਲ ਹੈ ਅਤੇ ਐਂਟੀ ਪੀਪਲ ਹੈ। ਬਿਲ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਦੀ ਈਵੇਜ਼ਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਈਵੇਜ਼ਨ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਆਪ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਈਵੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੜੀ ਇਮੋਰਲ ਗਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਈਵੇਜ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਈਵੇਡ ਨਾ ਕਰਨ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਰੋਵਾਈਜ਼ੋ ਲਗਾ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਇਰੈਗੂਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਮੋਰਲ ਕਲਾਜ਼ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ੫੦ ਸਾਲ ਤਕ ਹੈ। ਜੇ ਐਡਵਰਸ ਪੁਜ਼ੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿਚ ਨਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੁਪਣੇ ਵਿਚ ਵੀ ਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਪਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲੀ ਗਲ ਇਹ ਇਖਲਾਕ ਤੋਂ ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਗਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਉੜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

शिक्षा मन्त्री (श्री प्रबोध चंद्र) : जनाबे आली एक छोटी सी बात को बहुत लम्बा कर दिया गया है। बाबू जी ने जो कहा है कि इख्लाकी पैमाने हमारी नज़रों के सामने नहीं हैं ऐसी बात नहीं है। इख्लाकी पैमानों की हम ज्यादा पाबन्दी करने वाले हैं। जनाब आप तो हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं। आपको पता ही है, हमारी मजबूरी है। इस क्लाज़ को क्यों लाया गया है एक लिमिट रखी गई है कि वह तीन साल के अन्दर अन्दर अपना रिफन्ड वापिस लेना चाहे तो ले सकता है। मेरे फाजिल दोस्त जब इस कुर्सी पर थे और विचार था। वह कहते हैं कि अगर व्योपारी 4 साल मुकद्दमा लड़ता रहे तो वह तीन साल के अन्दर अन्दर पैसे कैसे ले लेगा। अगर उन्होंने पढ़ा होता और पढ़ कर समझा होता तो उन्हें मालूम हो जाता। यह प्रावाइज़ो इस तरह से है :—

> "Provided further that no refund under this section shall be allowed unless th claim for refund is made within a period of three years from the date on whic such claim accrues."

जब सारा फैसला हो जाए उसके बाद तीन साल का अर्सा दिया है। अगर यह फैसला चार साल तक भी न हो तो कोई ऐसी बात नहीं। इस वारनिंग का मकसद यह है कि आखरी कोर्ट के फैसले के बाद या जो कोर्ट आफ अपील है उसके फैसले के बाद व्योपारी तीन साल के अन्दर अन्दर कह सकता है कि उसका इतना रुपया गवर्नमेंट की तरफ बनता है अगर वह तीन साल के अन्दर एक अर्जी भी डाल दे छे पैसे या १० पैसे खर्च करके कि मेरा इतना रुपया बनता है तो वह ले सकता है

चाहे वह फैसला ५ साल के बाद हो। कई बार ५ या ६ साल के बाद कागज़ गुम हो जाते हैं। यह गवर्नमेंट ने इसलिये रखा है वरना गवर्नमेंट को कोई जरूरत नहीं थी कि इस मद को लाती। हाई कोर्ट की ऐसी रूलिंग के बाद हमारे लिये मजबूरी हो गई है कि ऐसा कानून बनायें। यह व्यापारियों को गाइडेंन्स है कि वह पुराने कानून के तहत गलती से अपने क्लेम फाइल न करें। गवर्नमेंट यह मद् इसलिये लाई है ताकि हर व्योपारी की पाई पाई जो गवर्नमेंट की तरफ रहती है उसको दे दी जाए। अगर हाई कोर्ट का रूलिंग न होता तो गवर्नमेंट को कोई मज़बूरी नहीं थी कि ऐसी क्लाज़ लाती। हम मजबूर होकर यह क्लाज लाए है। जिस दिन आखरी कोर्ट का फैसला होगा—एक्साइज़ एन्ड टैक्सेशन कमिश्नर, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो भी आखरीकोर्ट है उसके फैसले के तीन साल के अन्दर अन्दर वह चिट्ठी डाल दे कि मेरा इतना पैसा बनता है।

Government is bound to pay every penny that we owe to the people.

मेरा ख्याल है कि अब इनके खदशात दूर हो गये होंगे। यह क्लाज इसलिये नहीं कि किसी के पैसे दबा लेने हैं। मजबूरी के साथ लाई गई है। मैं समझता हूँ कि इस क्लाज को जिस तरह से कि यह है उसी तरह पास कर देना चाहिए।

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ (ਸਿਧਵਾਂ ਬੇਟ ਐਸ: ਸੀ:) : ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੈਮਾਨੇ ਰਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੋ ਰੁਪਿਆ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਰੁਪਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਲੈਣ ਦਾ ਤਅਲੁਕ ਹੈ ਉਹ ਫੌਰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਦੇਣ ਦਾਂ ਤਅਲੁਕ ਹੈ ਉਥੇ ਪਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿਤੀ। ਜੇ ਫਿਨਾਂਸ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਰਾਈਟ ਆਫ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਵਪਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕਲੇਮ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ੨ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਫ ਵਿਚ ਆਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ।

ਵਿਦਿਆ ਮੰਤ੍ਰੀ: ਅਗਰ ਉਹ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਨੋਟਿਸ ਹੀ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ।

ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ (ਨਕੋਦਰ) : ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਟ ਦੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 12 ਦੇ ਥਲੇ ਇਹ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

> "Provided further that no refund under this section shall be allowed unless the claim for refund is made within a period of three years from the date on which such claim accrues".

ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਦਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਿਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਅਜ ਤਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਲੀਗਲ

[ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ]

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਛਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ । ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਾਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਐਕਟ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮਿਆਦ ਮੁਕਰਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਵੇਖੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪਰੋਵਿਜ਼ਨ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਰੂਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਰਾਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਐਸਾ ਰੂਲਿੰਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਸਣ ।

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਆਨ ਏ ਪ੍ਰਾਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਸਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਰੂਲਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਬਾਊਂਡ ਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ?

श्री सागर राम गुप्ता : आन ए पाइंट आफ आर्डर मैं रूलिंग चाहता हूं कि क्या कोई मिनिस्टर गवर्नमैंट को डीफैंड करते हुए किसी रौंग रूलिंग का सहारा ले कर हाउस को मिसलीड कर सकता है ?

श्री चेयरमैन : किसी भी आनरेबल मैम्बर को हाउस को मिसलीड नहीं करना चाहिए । (No hon. Member should in any way mislead the House.)

ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ : ਆਨ ਏ ਪ੍ਰਾਇੰਟ ਆਫ ਆਡਰ ਸਰ । ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਮਿਸਲੀਡ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ: ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਂਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਅਖਤਿਆਰ ਸਿਰਫ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝੇ ਅਮੈਂਡ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਜੋ ਚਾਹੇ ਮਿਆਦ ਮੁਕਰਰ ਕਰੇ । ਜੇਕਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਰੂਲਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕੋਟ ਕਰਨ । ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਕੋਈ ਰੂਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਅਸੈਸੀ ਆਪਣੇ ਡਿਊਜ਼ ਦੇ ਰੀਫੰਡ ਦਾ ਕਲੇਮ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਕਿਤਨੀ ਅਜੀਬ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਵਲ ਮਾਲੀਏ ਲੋਨ ਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਰਸਨਜ਼ ਤੇ ਇਨਡੀਵਿਜੁਅਲ ਵਲ ਪੈਸੇ ਡਿਊ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚਾਹੇ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਲੇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਬਲਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਸੂਦ ਦਰ ਸੂਦ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ । ਸੂਦ ਦਰ ਸੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੇ ਪੀਨਲ ਇਨਟਰੈਸਟ ਵੀ ਵਸੂਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸਲ ਸੂਦ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਥੇ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਊਜ਼ ਵਸੂਲ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ ? ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ

ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲੇਮ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੀਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰੀਫੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸੂਦ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਪੈਸਾ ਬਤੌਰ ਟਰਸਟ ਪਿਆ ਰਿਹਾ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜਿਥੇ ਉਹ ਇਹ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਸੈਸੀ ਦੇ ਐਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਪੈਸੇ ਉਸਨੂੰ ਇਮੀਜੇਟਲੀ ਪੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ । ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੇਲਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਾਂ ਕਰੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਅਸੈਸੀ ਦੇ ਐਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਡਰ ਨਾ ਲਿਖੇ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਬਲਕਿ ਅਸੈਸੀ ਕਲੇਮ ਫਾਈਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰੀਫੰਡ ਮਿਲੇ । ਸਾਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਸਮਝੇ ਹੀ ਨਹੀਂ । ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਸਮਝੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਸਣ ਕਿ ਡੇਟ ਆਫ ਐਕਰੂ ਕਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ? ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਅਸੈਸੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ 500 ਰੁਪਿਆ ਡਿਊ ਹੈ । ਅਸੈਸੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵਧ ਪੈਸਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 1970 ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਰਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਜਾ ਕੇ 1970 ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੀ ਆਰਡਰ ਅਪਹੋਲਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ....(ਇਸ ਵਕਤ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਬੜਾ ਸ਼ੋਰ ਸੀ)......

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ । ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਤਕਰੀਰ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਂਗਲੀਆਂ ਨਚਾ ਨਚਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ? (ਹਾਸਾ)

(Mr. Speaker in the Chair.)

ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਦੇ ਉਪਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਲ ਦੇ ਵਿਚ ਡੇਟ ਆਫ ਐਕਰੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੀਗਲ ਫਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਲੀਗਲ ਡਿਫੈਕਟਸ ਹਨ । ਮੈਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਫ਼ਹਿਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇਕ ਬਿਉਪਾਰੀ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਸ 600 ਰੁਪਏ ਆਊਟ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਗੌਰਮਿੰਟ 500 ਰੁਪਏ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ । 1960 ਵਿਚ ਬਿਉਪਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਮੁਕਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲਾ 1965 ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਿਉਪਾਰੀ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਝਗੜੇ ਵਿਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾਂ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਡੇਟ ਆਫ ਐਕਰੂ ਕਿਹੜੀ ਹੋਵੇਗੀ । (ਵਿਘਨ) ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਝਗੜੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹੀ ਡੇਟ ਆਫ ਐਕਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਮਨ ਦੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਣਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। (ਵਿਘਨ)

Mr. Speaker ; Kindly wind up now.

ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ: ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਐਕਟ ਦੀ ਇੰਟਰਪਟੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਜਾਂ ਤਕ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਮਨਿਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾਂ ਕੋਈ ਹੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਡੇਟ ਆਫ ਐਕਰੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਵਿਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤਾਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਅਪੀਲ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੇਟ ਆਫ ਐਕਰੂ ਲਾਸਟ ਡਵੀਜਨ ਪਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼

Income Tax authorities do not ask for claims. When it is decided at the first stage, it is for the deciding authority to pass orders "make payment to so and so". Why do you invite claims when a decision has already been taken ? This is the practice in the Income Tax Department. Why not have the same practice in this Department also ?

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਣੇ ਹੋਏ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ ਪਰ ਰਿਫੂਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਲੇਮ ਅਜੇ ਤਕ ਸੈਟਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਹੀਂ ਰਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Mr. Speaker : Please wind up now.

ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ: ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹਾਂ।

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ: ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਸਰ। ਜਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਆਪਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਊਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਕਰਾਰ ਦਿਤੀ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ?

Mr. Speaker : It cannot be revived.

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ: ਕਲਾਜ਼ 2 ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਬਲਾ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਜੈਕਟ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ।

Mr. Speaker : Subsequently I allowed it because it was passed with the consent of the whole house.

चौधरी नेतराम (हिसार): स्पीकर साहिब, सदन में जनरल सेल्ज़ टैक्स पर बहस हो रही है। मैं भी अपने विचार क्लाज़ 9 के बारे में प्रकट करना चाहता हूँ। अगर किसी दुकानदार के रुपये सरकार के पास पड़े हुए हों तो वह दुकानदार ३ साल के अन्दर अन्दर सरकार से ले ले नहीं तो सरकार उस राशि को ज़ब्त कर लेगी। इसके विपरीत अगर सरकार ने किसी दुकानदार से रुपये वसूल करने हों तो वह ३ साल के बाद कानून का फंदा दुकानदार की गर्दन पर रख कर और हरास करके वसूल करेगी। यह दोनों चीज़ें एक दूसरे से कितनी भिन्न है। यह चीज हर प्रकार से दो मुँहें वाले जानवर से मिलती जुलती है। दो मुंह किस जानवर के होते हैं। इसकी व्याख्या

सदन में करना चाहता हूँ। दो मूँह वाला जानवर सांप होता है। जिस तरह से दो मुंह वाला सांप दोनों तरफ डसता है, उसी तरह से यह सरकार दोनों तरफ से पब्लिक को डसती है। सरकार दुकानदारों को रुपये वापस करने में भी तंग करती है और अगर सरकार ने लेने हों तो दुकानदार की गर्दन पर कुल्हाड़ा रख कर रुपये वसूल करती है। जनता के साथ हर तरह से अन्याय हो रहा है....(विघ्न) (शोर)

Captain Rattan Singh : On a point of order, Sir. Can a hon. Member use unparliamentary words ?

श्री अध्यक्ष : उन्होंने क्या कहा है ?

(What has the hon. Member said ?)

ਕੈਪਟਨ ਰਤਨ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਣਪ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ? (ਸ਼ੋਰ)

Mr. Speaker : Order please.

चौधरी नेतराम : यह तो जंगली वज़ीर है। (शोर)

ਕੈਪਟਨ ਰਤਨ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਜੰਗਲੀ ਵਜ਼ੀਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ (ਸ਼ੋਰ)

चौधरी नेत राम : स्पीकर साहिब, मैं कहना भूल गया हूँ। वह तो डंगरों के वज़ीर हैं, (शोर)

ਕੈਪਟਨ ਰਤਨ ਸਿੰਘ : ਅਗਰ ਇਹ ਡੰਗਰ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ। (ਹਾਸਾ ਤੇ ਵਿਘਨ)

Mr. Speaker : Order please.

चौधरी नेतराम : अगर देश की बागडोर इनके पास दो तीन साल और रह गई तो देश को यह खुद ही बुरी तरह से तबाह कर देंगे।

श्री अध्यक्ष : आप क्लाज़ पर बोलें। बिल की जनरल डिस्कशन न करें। The hon. Member should speak on the clause and not under the general discussion of the Bill.)

चौधरी नेतराम : स्पीकर साहिब, मैं आपको किसी तरह से नाराज नहीं करना चाहता हूँ। आपका धन्यवाद करके अपनी सीट संभालता हूँ।

ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ : (ਸਮਾਣਾ, ਐਸ. ਸੀ.) ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਦਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਸ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਆਊਟ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਅਮਾਊਂਟ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲ ਵਿਚ ਪਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਰੁਪਿਆ ਦੁਕਾਨਦਾਰ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ

[ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ]

ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੰਜ ਸਾਲ ਰਖੀ ਹੈ । ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਅਮਾਊਂਟ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੀਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਕਿਤੇ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੈ ?

ਇਹ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਾਣੀ ਡੰਡੀ ਰਖਦੇ ਹੋ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਕਾਣੀ ਡੰਡੀ ਰਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਰਖੇ ਹਨ, ਇਥੇ ਵੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ । ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕਲ ਤੋਂ ਬਿਲ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਪੈਸਾ ਘਟਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਪੈਸਾ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਕੁਝ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਕੁਝ ਦਿਤਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ? ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਧੇਲਾ ਘਟਿਆ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਧੇਲਾ ਵਧਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਗਲ ਵੀ ਸੀ, ਦੋ ਦਿਨ ਟਕਰਾਂ ਮਾਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ । ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ ।

वित्त मन्त्री (सरदार कपूर सिंह) : स्पीकर साहिब, मैं पहले आपकी खिदमत में वह सैक्शन पढ़ देना चाहता हूँ ताकि पता लग जाए कि जो बहस हो रही है वह किसकी खातिर हो रही है । सैक्शन यह है—

"The assessing authority shall in the prescribed manner, refund to a registered dealer applying in this behalf any amount of tax paid by such dealer under this Act—

(a) if the amount is in excess of the amount due from him under this Act; or

(b) if the amount of tax so paid is in respect of the sale or purchase of any declared goods and such goods are sold...................."

जनाब, बात यह थी कि हम व्यापारियों के लिये घंटी बजा रहे हैं। आपको पता होगा कि अंडर दी लिमिटेशन ऐक्ट रैज़ुडियरी जो आर्टीकल है उसके अंदर जो मिआद थी वह 6 साल की थी । अगर किसी ने रीफंड लेना हो तो वह विदिन सिक्स ईयर ले सकता है । लेकिन अब बाई लैजिसलेशन आफ दी पार्लियामेंट उस मिआद को तीन साल कर दिया गया है । इत्तफाक ऐसा था कि मेरे भाई व्यापारियों को इस बात का पता नहीं था वे तो इस ख्याल में ही थे कि रीफंड विदिन सिक्स ईयर हो सकता है । इसलिये गवर्नमेंट ने मुनासिब समझा कि घंटी बजा कर उनको आगाह कर दिया जाए कि भई जो क्लेम वगैरह लेना है वह 6 साल के अंदर नहीं बल्कि तीन साल के अंदर ही मिल सकता है । एक बात तो यह थी दूसरी बात यह है कि...

ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ : On a point of order, Sir ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ।

वित्त मन्त्री: जिस तरह से मैंने अर्ज़ किया है पार्लियामेंट ने ६ साल की जगह पर ३ साल की मियाद कर दी । पहले एक्ट के मुताबिक जब एक व्यापारी ने हाईकोर्ट में मुकदमा किया उन्होंने उसको टाइम लिमिट के मुताबिक कह दिया कि यह टाईम बार्ड हो चुका है क्योंकि पार्लियामेंट ने इसकी मियाद तीन साल कर दी हुई है । इसलिये मुनासिब समझा गया कि व्यापारियों को यह बता दिया जांय कि क्लेम जो हो सकता है वह तीन साल के अंदर अंदर हो सकता है । मैं मानता हूँ कि यह भी गवर्नमेंट का फर्ज़ है। जहां वह चाहती है कि व्यापारियों से रुपया वसूल करे वहां उसकी यह भी मारल ड्यूटी है कि जहां पर रीफंड करना है उसमें भी उनको व्यापारियों के साथ इंसाफ करे । इसीलिए इसको लाया गया है ताकि यह बात व्यापारियों को बता दी जाए। आप देखेंगे कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से इन्साफ करती है किसी के साथ बेइन्साफी नहीं करनी चाहती । बात यह है कि बाज़े बाज़े आदमी क्लेम भी नहीं करते । अगर वे लोग क्लेम न करें और सोये ही रहें तो यह गवर्नमेंट के फायदे की बात थी । किसी को पता ही नहीं था कि तीन साल की मियाद कर दी गई है वे लोग ६ ही साल समझते थे । लेकिन गवर्नमेंट इन्साफ पर चलना चाहती है केवल कानून का ही ज़यादा ख्याल नहीं करना चाहती । पंडित मोहन लाल जी ने पूछा था कि हमें यह बताओ कि जो आपको रुपया आता है वह किस आईटम में जमा करोगे । मैं उन से अर्ज करना चाहता हूँ कि आईटम्ज़ तो वही हैं जहां पर बाकी असैसमेंट जाती है जहां उनका रुपया जाता है वहीं. पर यह भी जाएगा । जब रिफंड करना होगा तो उसी आईटम से निकाल कर दे देंगे इसलिये मैं आनरेबल मैम्बर साहिबान की खिदमत में यह कहना चाहता हूँ कि जो आदमी रिफंड का हकदार हो गया है गवर्नमेंट उसका रुपया मारना नहीं चाहती वह तीन साल के अरसे में क्लेम कर सकता है । जो एनटाईटल हो जाता है वह ले सकता है । इन अल्फाज़ के साथ में आशा करता हूं कि इसको जल्द ही पास किया जाए ।

Shri Mohan Lal : On a point of information, Sir...............

Mr. Speaker : I am sorry.

Shri Mohan Lal : Sir, would like to have some information. What is wrong with this. I would like to understand for future.

Mr. Speaker : I am sorry. The hon' Member should please resume his seat.

I will now put the amendments to the vote of the House.

Baboo Bachan Singh : On a point of order, Sir...........

Mr. Speaker : No please. I am on my legs. No point of order can be raised when I am on my legs.

Mr. Speaker : Amendment No. 36 stands in the name of Shri Ram Saran Chand Mital.

Shri Ram Saran Chand Mital : Sir , I beg to withdraw my amendment.

Mr. Speaker : Is it the pleasure of the House that the hon. Member be allowed to withdraw his amendment?

Voices : Yes.

The amendment was, by leave, withdrawn.

Mr. Speaker : The next amendment (No. 56) stands in the name of Thakur Mehar Singh.

Thakur Mehar Singh : Sir, I beg to withdraw my amendment.

Mr. Speaker : Has the hon. Member the leave of the House to withdraw his amendment?

Voices : Yes.

Voices : No.

Mr. Speaker : Question is—

For the clause substitute the following—

"9. Whenever any amount of tax is liable to be refunded under this Act, the Assessing Authority shall refund it even without any application from the claimant thereof within three months from the date on which the claim for refund accrues, failing wherein interest would be paid to the dealer at the rate of 3 per cent per annum on the refundable amount of tax from the date on which the dealer had deposited or paid the amount of tax till date of tender of the refund voucher to the dealer or the date on which it is deducted from the amount of tax due from him in respect of any other period."

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

For the clause substitute the following—

"9. Whenever any amount of tax is liable to be refunded under this Act, the assessing authority shall refund it even without any application from claimant, thereof within six months from the date on which the claim for refund accrues, failing wherein six per cent interest per annum would be paid to dealer on the refundable amount of tax from the date on which it is deducted from the amount of tax due from him in respect of any other period and officer responsible for his failure of the refund shall have to explain the reasons in writing for the failure to refund the amount to the dealer."

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 9 stand part of the Bill.

(*After ascertaining the votes of the Members by voices, Mr. Speaker said, "I think the Ayes have it". This opinion was challenged and division was claimed. Mr. Speaker after calling upon those Members who were for "Aye" and those who were for "No", respectively, to rise in their places and on account having been taken, declared that the motion was carried.*)

The Motion was declared carried.

CLAUSE 10.

Mr. Speaker : Now Clause 10 is before the House. All the following amendments to this Clause will be deemed to have been read and moved and can be discussed along with it:—

13. Shri Mohan Lal :

In the proposed sub-section (2) (a) of sub-clause (1), line 1, *for* "three" *substitute* "thirty'.

14. Shri Mohan Lal :

In the proposed sub-section (2) (b) of sub-clause (i), line 2, *for* "five" *substitute* "three".

37. Shri Ram Saran Chand Mital :

In the proposed sub-section (2) (a) of sub-clause (1), line 1, *for* "three" substitute "five".

38. Shri Ram Saran Chand Mital :

In the proposed sub-section (2) (b) of sub-clause (1), line 2, *for* "five" substitute "*four*".

64. Shri Yash Pal :

In the proposed sub-section (2) (a) of sub-clause (1), line 1, *for* "three" *substitute* "fifteen".

107. Shri Yash Pal :

108. Shri Chandi Ram Verma :

In sub-clause (1), line 4, *for* "three" *substitute* "ten".

162. Sardar Harchand Singh :

163. Shri Nihal Singh :

164. Dr. Bal Krishan :

In sub-clause (1), line 4, *for* "three" *substitute* "ten".

6-00 P.M.

श्री **मोहन लाल** (बटाला) : स्पीकर साहिब, इस क्लाज़ में मेरी दो अमैंडमैंट्स हैं। पहली तो यह है कि सब क्लाज़ २ ए. में जहां कैश मीमो इशु करने के लिये तीन रुपये का प्रोविज़ है मैंने अपनी अमैंडमेंट के जरिए यह मांग की है कि वहां पर तीन की बजाय तीस कर दिया जाए। फाइनेंस मिनिस्टर साहिब ने पहले भी बहुत अच्छी रैस्पांस दी है और कई मामलात में कुछ ऐसी क्लाजिज़ हैं जहां पर उन्होंने हाउस की

[श्री मोहन लाल]

सैंस को ध्यान में रखते हुए बहुत सी अमैंडमैंट्स के साथ ऐग्री किया है। इसके लिये मैं उनकी दाद देता हूँ....खास तौर पर जो उन्होंने तीस हजार की टैक्सेबल टर्न अोवर की लिमिट को बढ़ा कर चालीस हजार किया। जहां इस क्लाज़ का ताल्लुक है, मैं उनसे अर्ज़ करूँगा कि बावजूद इस बात के कि चालीस हजार की लिमिट की है उसका मतलब यह होगा कि जिस व्यापारी की, जिस डीलर की 120 या 125 रुपये रोज़ की बिक्री हो.....मैं लफ्ज़ बिक्री पर जोर देता हूँ.....वह भी इस ऐक्ट की ज़द में आएगा। अब मैं उन सारे आरगुमैंट्स को नहीं दुहराना चाहता जोकि पहले आ चुके हैं लेकिन आप इस बात का भी अन्दाज़ा लगा लीजिये कि जिस गरीब आदमी की डेली बिक्री 120 या 125 रुपये होगी उसकी आमदन बहुत थोड़ी होगी और जैसा कि अभी अभी कुछ आनरेबल मैम्बर साहिबान ने हिसाब करके बताया उसका इतना खर्च तो होगा किराये पर, इतना खर्च होगा हिसाब किताब रखने पर और उसके बाद अगर हिसाब किताब इस कैश मीमो का रखने के लिये उसे एक एकाउंटेंट या मनीम रखना पड़े उसे भी उसको 125 या 150 रुपया महीना देना होगा। आप अन्दाज़ा लगायें कि इतने अखराजात के बाद उस गरीब के पास रह क्या जाएगा अपने आपको और अपने बाल बच्चों को पालने के लिये? तो उसके लिये एक बात की ही गुंजायश रह जायगी और वह यह कि अपना कारोबार ही बन्द कर दे। अगर इससे उसका ज़रिया मुआश नहीं बनता और वह अपने बाल बच्चों का पेट नहीं पाल सकता तो फिर ऐसे कारोबार का फायदा ही उसे क्या होगा? अगर यह क्लाज़ ऐसे ही रह जाए कि उसे हर उस खरीददार को जो तीन रुपये की चीज़ें खरीदता है कैश मीमो इशू करना है तो इसका मतलब यह होगा कि कोई दुकानदार जिसके पास मुलाज़म नहीं है दुकान कर नहीं सकेगा, किसी सूरत में भी नहीं कर सकेगा। आज हम देखते हैं कि चाहे कोई भी आदमी किसी दुकान पर जाए वह तीन रुपये से कम की क्या चीज़ खरीदेगा। जरा अन्दाज़ा लगा लीजिये कि छोटी छोटी या थोड़ी थोड़ी भी चीज़ें खरीदनी हों तो पांच, दस, पंद्रह बीस रुपये का बिल बन जाना मामूली सी बात है। इसका मतलब यह होगा कि दुकानदार को हर ग्राहक को, जोकि सौदा खरीदने के लिये उसकी दुकान पर आता है, कैश मीमों इशू करना होगा। इसलिये आप अन्दाज़ा लगायें कि एक गरीब दुकानदार जो अकेला दुकान पर काम करता है कैसे वह सौदा भी तोलेगा और साथ साथ उस सूरत में कैश मीमो भी इशू करेगा जब कि उसकी दुकान पर उसी वक्त तीन चार और ग्राहक सौदा लेने के लिये खड़े होंगे? मतलब यह हुआ कि हर हालत में हर दुकानदार को इस काम के लिये एक अलहदा आदमी ज़रूर रखना होगा जिस का सौ डेढ़ सौ रुपया महीना और खर्चा उसे पड़ जायगा चाहे आमदन उसकी उतनी हो या न हो। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस तीन रुपये वाली शर्त को बढ़ा कर तीस रुपये तो कर दिया जाए....वैसे चाहिए तो इससे भी ज़यादा। इस सम्बन्ध में एक और बात फाइनेंस मिनिस्टर साहब को अर्ज़ करूँगा और वह यह कि जैसा कि आपने इसमें प्रोविज़न किया है इसका मतलब यह होगा कि उसने तीन रुपये से ऊपर वाली रकम के लिये ही कैश मीमो इशू करना होगा और उससे नीचे की रकम का जो सौद

वह देगा उसके लिए कैश मीमो इशू करने की जरूरत नहीं होगी । लेकिन फिर भी टैक्स के परपजिज़ के लिये उसे हिसाब किताब तो सारा ही रखना पड़ेगा । लिहाज़ा अगर तीन की बजाय इस रकम को बढ़ा भी दिया जाए तो कोई हर्ज़ वाली बात नहीं। इससे एक फायदा यह होगा कि वह बेचारा दुकानदार मुफ्त के खर्चे से बच जाएगा जोकि उसे इस मकसद के लिये अलहदा आदमी रखने के लिये करना पड़ेगा । इसलिये मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी जो अमैंडमेंट इस सिलसिले में है फाईनेंस मिनिस्टर साहिब इसको जरूर मान लेंगे । मुझे ऐसा पता है कि यहां पर चीफ मिनिस्टर साहिब ने ऐसा कहा था कि हमने कोई फैसला कर लिया है....शायद तीन की बजाय दस रुपये तक करना उन्होंने मान लिया है और मेरी नाकस राए में दस रुपये भी कम है । यह कम अज़ कम तीस रुपये होना चाहिए ।

दूसरी अमेन्डमेंट मेरी इसी सब क्लाज़ के पार्ट बी. के सम्बन्ध में है जहां पर इन्होंने यह रखा है कि वह कैश मीमो की किताबों को पांच साल तक सम्भाल कर रखेगा । आप अन्दाज़ा लगायें कि गरीब दुकानदार कैश मीमो की इतनी किताबों और कागज़ात को पांच साल तक कैसे सम्भाल कर रख सकता है । एक तरफ तो आपने अभी अभी यह पास किया है कि तीन साल के अन्दर अन्दर उसे पैसा वापिस करेंगे उसके बाद नहीं करेंगे और जहां पर उस गरीब दुकानदार के मतलब की बात आई है वहां आपने फिर पांच साल कर दिया है कि तब तक वह हर कागज़ को, हर कैश मीमो को सम्भाल कर रखे । मेरी राए में यह ज्यादती है । इसलिये मैं अर्ज़ करूँगा कि यह पांच की बजाय तीन साल कर दिया जाए । मैं उम्मीद करता हूँ कि जो रीज़नेबल अमडमेंट्स मैंने पेश की हैं इन्हें मंजूर किया जाएगा।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ (ਮੋਰਿੰਡਾ ਐਸ. ਸੀ) **:** ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਲਾਜ਼ ਦੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰ ਤਕ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਮਾੜੀ ਕਲਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸਾ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਲਾਜ਼ ਦੇ 'ਏ' ਪਾਰਟ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ਮੀਮੂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁਤਫਿਕ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ਮੀਮੂ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ੫੦੦ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਅੌਰ ਇਸ ਦੀ ਇਤਨੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਕੈਸ਼ਮੀਮੂ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । (ਬੜਾ ਸ਼ੋਰ)

Mr. Speaker : Order please.

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ ਜੋ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ।

ਫਿਰ ਇਸ ਸਬ ਕਲਾਜ਼ ਦੇ ਪਾਰਟ 'ਬੀ' ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਸ਼ਮੀਮੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦਾ ਰੀਕਾਰਡ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਰਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅੌਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਰੋਵਾਈਜ਼ੋ ਵੀ ਲਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮਿੰਟ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ੈਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ

[ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ]

ਜਿਹੜੇ ਡੀਲਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ਮੀਮੂ ਨਾ ਰਖਣ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਡੀਲਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੈਸ਼ਮੀਮੂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੀਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਰਖਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਕਲਾਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ।

श्री चांदी राम वर्मा (अबोहर) : स्पीकर साहब, क्लाज़ १० के बारे मेरी एक एमेंडमेंट है। इस क्लाज की जो सब क्लाज 1 है उस की लाइन ४ में जो दिया हुआ है कि तीन रुपये या इससे ज्यादा के कैश मीमो जारी करने पड़ेंगे, मैं समझता हूँ कि यह ३ रुपये की जगह पर १० रुपय कर दिया जाए। यह बड़ी सिम्पल सी एमेंडमेंट है। मुझे उम्मीद है कि मिनिस्टर साहब इसे मन्जूर कर लेंगे ।

ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ (ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਅਨ ਐਂਪਲਾਇਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਲਾਜ਼ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਲਾਜ਼ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਸੇਲ 120 ਰੁਪਏ ਤਕ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰਖਣ ਲਈ ਔਰ ਕੈਸ਼ਮੀਮੂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਖਣੇ ਪੈਣਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਤਨੇ ਐਂਪਲਾਇਮੈਂਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਾਲੇ ਵੀ ਭੇਜ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੁਰਬਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਇਸ ਕਲਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਬਤ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਤਦ ਤਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਲਾਜ਼ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਪਿਛੇ ਕੈਸ਼ਮੀਮੂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ 20 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਰਖਣ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਕੰਮ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਵਿਚ ਦਿਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ any one......"........exceeding three Rupees in value in any one transaction,........"

ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇਕ ਆਦਮੀ ਇਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਕ ਵਕਤ ਤੇ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਮੁਲ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਵਖਰੇ ਵਖਰੇ ਕੈਸ਼ਮੀਮੋ ਕਟਣੇ ਪੈਣਗੇ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਸ਼ ਮੀਮੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦਾ ਰੀਕਾਰਡ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਰਖਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਲੇ ਸਾਡੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬਹੁਤੇ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ ਔਰ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਮੀਮੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਟ ਸਕਦੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੈਸ਼ਮੀਮੋ ਇਤਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਖਣ ਲਈ ਥਾਂ ਵੀ

ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੂਹੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਾਲੇ ਬੜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਢ ਸਕੇ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੰਜ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਰਖਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਪਰੋਵੀਜ਼ਨ ਰਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰੋਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। ...."by notification exempt any class of registered dealers........." ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਸਕਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਵਡੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਇਤਨੀਆਂ ਵਡੀਆਂ ਪਾਵਰਜ਼ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਤਾਰ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਪਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਬਿਨਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਲਾਸ ਆਫ ਪੀਪਲ ਨਾਲ ਡਿਸਕਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ...."Commissioner or any person appointed to assist him ......"

ਫ਼ਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਬ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ according to the Act ਇਹ ਪਾਵਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹਥ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਲਾਜ਼ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਗਲ ਸਾਫ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਫਸਰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਚ ਰੀਜ਼ਨਏਬਲ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀ ਦੇ ਲਫਜ਼ ਦਿਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਫਜ਼ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫੇਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਕਲੈਰੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ What is meant by reasonable opportunity. ਇਹ ਦੋ ਚਾਰ ਗਲਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ਿਨਾਸ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ 10 ਵਿਚ ਉਹ ਮੁਨਾਸਬ ਤਬਦੀਲੀ ਲੈ ਆਉਣ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ (ਮੋਗਾ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਲਾਜ਼ 10 ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਉਂ ਬੜੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ....(ਬੜਾ ਸ਼ੋਰ)

Mr. Speaker : Order please.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਕਨਜ਼ਿਊਮਰ ਤੋਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਨਜ਼ਿਊਮਰ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਨਾਲਾਇਕ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਕਨੇਡਾ ਵਿਚ ਜਮਿਆਂ ਹੈ।

ਫਿਰ ਪੰਡਤ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਕੈਸ਼ਮੀਮੋ ਨਹੀਂ ਕਟ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰ ਸਾਮਾਨ ਚੁਕਣ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ, ਸੌਦਾ ਤੋਲ ਦੇਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕੈਸ਼ਮੀਮੋ ਕਟ ਕੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਗਲਾਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ

[ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ]

ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਫਟਾ ਫਟ ਸਾਮਾਨ ਤੋਲ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਦੋ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਪਰਚੀ ਕਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ । ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਚੀਆਂ ਵੀ ਫਟਾ ਫਟ ਕਟ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਨਾ ਲਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਟੈਕਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਣ । ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੁਲ ਲਉ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਕੈਸ਼ਮੀਮੋ ਮੰਗ ਲਉ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਹੁਣ ਲਗਾ ਲਵਾਂਗਾ । ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਚੀ ਨਾ ਕਟਣੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਲ ਵੀ ਦੁਗਨਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਕਈ ਆਦਮੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ । ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਅਗਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇਵੇਯਨ ਰੁਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਾਉ । ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

(*Interruptions*)

श्री रूपलाल मेहता (पलवल) : स्पीकर साहिब, इस वक्त जो क्लाज हाउस में ज़ेरे बहस है इस पर कुछ मैम्बरान ने अपने विचार रखे हैं। इसमें जो पैरा तीन है उसको पढ़े तो पता चलता है कि इसमें कितना नुक्स है। आप अन्दाज़ा लगायें कि छोटे दुकानदारों को पांच सौ रुपये तक जुरमाना किया जायगा । आप देखें कि उनके लिये कितनी मुसीबत है । उन लोगों को पांच पांच साल तक कैश मीमो और न जाने क्या क्या हिसाब सम्भाल कर रखना पड़ेगा । यह बेचारे तो हिसाब किताब ही ठीक तरह से नहीं रख सकते, बड़ी मुश्किल से हिन्दी वगैरह में किसी तरह हिसाब रखते हैं इसलिये यह क्लाज बड़ी हार्डशिप पैदा करेगी । इसका नाजायज़ इस्तेमाल होगा और व्यापारियों को बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ेगा । इसको उड़ा देना चाहिए (शोर)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज़ । देखिए, अगर आप बैठने के मूड में नहीं हैं

(Order please. The hon. Members may please listen. If they are not in a mood) to transact the business of the House, then the House can be adjourned. On both sides of the House a lot of noise is going on which is not a proper. Even some effort is going on to instigate others to make a noise. I am seeing this with my own eyes. This is not proper. certain members do not want to co-operate, I can adjourn the House.

आपोजीशन की तरफ से आवाजें: कर दो ।

श्री रूप लाल महता: स्पीकर साहिब यह जो तीन रुपये के सौदे के बारे में कैश मीमो काटने की शर्त है और जिसके बारे में वर्मा जी ने कहा है कि दस रुपये तक लिमिट कर दी जाए तो मैं अर्ज़ करूँ कि आजकल के जमाने में यह दस रुपये की रकम भी बहुत मामूली सी रकम है।

ਕਾਮਰੇਡ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ : On a point of order, Sir. ਆਪ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੀਫ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਨਸਰਨਡ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਏ ਹਨ। ਕੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਬੈਠੋ। (The hon. Member may please resume his seat.)

श्री रूप लाल महता: आप देखें कि आज के जमाने में जो मामूली आदमी भी सौदा लेता है तो 10–15 रुपये का बिल बन जाता है, महंगाई इतनी ज्यादा है कि इसमे कम में कुछ खास नहीं आता । मैं समझता हूँ कि वर्मा जी की भी जो प्रोपोज़ल आई है वह भी कम है यह रकम कम से कम 25–30 रुपये होनी चाहिए।

दूसरी बात जो पांच सौ रुपये जुरमाने की रखी है यह आम गरीब दुकानदारों के साथ बहुत ज्यादती है, हार्डशिप है । गांव के दुकानदार से आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वह पूरे बही खाते और एकाउंट रखे और फिर उनकी कारबन कापियां इतने सालों तक सम्भाल कर रखे । आखिर सभी शिमले की माल रोड पर दुकान करते नहीं जिनके पास एक सेल्ज़मैन जुदा हो, तौलने और नापने वाला अलग हो और दूसरे हर तरह के काउंटर और इन्तजाम हो। आम गरीब आदमी पर अगर आप इस तरह की बंदिशें लगायेंगे तो उसको बहुत तकलीफ होगी, वह लोग चिल्ला उठेंगे । इसलिये मैं रिक्वैस्ट करूँगा कि इसको हटाया जाए और अगर आपने सज़ा रखनी है तो पांच सौ की जगह दस रुपये कर दें । मैं समझता हूँ कि इतना ही जुरमान काफी होगी।

ਕਾਮਰੇਡ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ (ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਲਾਜ਼ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ 125 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਦੇਖੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 40 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਜਿਮੀਂਦਾਰ ਕਮਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਛਿਲ ਲਾਹੁਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਮੀਮੋ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ) ; ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਇਲਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਜਾਵੋ ਤਾਂ ਜੇ ਕਹੋ ਕਿ ਕੈਸ਼ਮੀਮੋ ਦੇ, ਤਾਂ

[ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ]

ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਲਗੇਗਾ । ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਫ਼ਾਕ ਹੋਇਆ । ਮੈਂ ਸੌਦਾ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗਾਹਕ ਖੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸੌਦਾ ਲੈ ਹਟੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੈਸ਼ਮੀਮੋ ਮੰਗਿਆ । ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਟੈਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ।

श्री फतेह चंद विज : On a point of order, Sir. यह बताएं कि यह कब की बात है ? तब यह मिनिस्टर थे या चेयरमैन ?

ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ : ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੈਸ਼ਮੀਮੋ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਦਿਉ ਮੈਂ ਪੁਛਿਆ ਇਹ ਟੈਕਸ ਮਾਲ ਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈਸ਼ਮੀਮੋ ਤੇ । ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ । ਗਾਹਕ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਗਲ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ਮੀਮੋ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਲਗੇਗਾ ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਅਗਰ ਇਸ ਕਲਾਜ਼ ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਕਰਾ ਲਉ । (If the hon. Minister wants this clause to be voted upon then he should get it done now.)

ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ; ਬਹੁਤ ਅਛਾ ਜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦਿਤੀ ਹੈ 3 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ 10 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਮੈਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ । (ਤਾੜੀਆਂ)

Mr. Speaker : Now I will put amendments Nos. 13 and 14 by Shri Mohan Lal to the vote of the House.

Shri Mohan Lal : I withdraw them.

Mr. Speaker : Has the hon. Member the leave of the House to withdraw his amendments?

(Voices : Yes.)

The amendments were, by leave of the House, withdrawn.

Mr. Speaker : Now I will put amendments No. 37 and 38 by Shri Ram Saran Chand Mital to the vote of the House.

Shri Ram Saran Chand Mital : I withdraw my amendments.

Mr. Speaker : Is it the pleasure of the House that the amendments be withdrawn ?

(Voices : Yes; **Voices :** No)

Mr. Speaker : Since leave has not been granted I will put them to the vote of the House.

Question is—

In the proposed sub-section (2) (a) of sub-clause (1), line 1, *for* "three" *substitute* "five".

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

In the proposed sub-section (2) (b) of sub-clause (1), line 2, *for* "five" *substitute* "four".

The motion was lost.

Mr. Speaker : Now I will put the amendment by Shri Yash Pal to the vote of the House.

Question is—

In the proposed sub-section (2) (a) of sub-clause (1), line 1, *for* "three" *substitute* "fifteen".

The motion was lost.

Mr. Speaker : Now I will put the amendment by Sarvshri Yash Pal and Chandi Ram Verma to the vote of the House.

Question is—

In sub-clause (1), line 4, *for* "three" *substitute* "ten".

The motion was carried.

Mr. Speaker : The amendment by Servshri Harchand Singh, Nihal Singh and Dr. Bal Kishan is similar to that of the previous one which has been accepted. It need not be put to the vote of the House.

Question is—

That clause 10, as amended, stand part of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : The House stands adjourned till 9 a.m. to-morrow.

6.30 p.m. *(The Sabha then adjourned till 9 a.m. on Friday, the 5th November, 1965).*

1571/P.V.S.—4-2-66—386—C.P., & S.Pb., Patiala.

PUNJAB VIDHAN SABHA

DEBATES

5th November, 1965

Vol. II—No. 18

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Friday, the 5th November, 1965

Punjab Vidhan Sabha Secretariat, Chandigarh.

Price Rs : 5.85

ERRATA

Punjab Vidhan Sabha Debates, Vol. II, No. 18, dated the 5th November, 1965

Read	*For*	*Page*	*Line*
QUESTIONS	QUESUIONS	(18)1	8
for	of	(18)3	27
16, 715.63	16,715,63	(18)7	S.No. 4, Col. 3
UNDER	U DER	(18)9	Heading
Minister	Ministcr	(18)12	3
Comrade Ram Chandra	Comrade Ram Chandera	(18)13	3
Delete the words 'account under which the cost of' after the words 'with the head of'		(18)13	3 from below
during	duridg	(18)18	6 from below
ਰੂਲਿੰਗ	ਰਲਿੰਗ	(18)28	2
concerned	concered	(18)29	21
ਮਾਲੂਮ	ਮਾਲਮ	(18)33	28
ਕੰਡੈੱਮ	ਕਡੈਮ	(18)34	20
ਸੈਬੋਟੇਜ	ਸੈਬਟਾਜ	(18)39	Last but one
ਹੋਣ	ਹੋ	(18)48	8 from below
ਹਾਊਸ	ਹਾਓਸ	(18)49	8
खाद्य	खाद्या	(18)49	16
	द्याद्य	(18)52	1
एम्बैसेडर	एमबसेडर	(18)50	3
हैं	ह	(18)52	10
दोस्ती	दोहस्ती	(18)53	6
अंडरस्टैंडिग	अन्डरष्टैंडींग	(18)55	8
पंजाबियों	जाबियों	(18)65	7
चौधरी नेत राम	चौंधरी नेत राम	(18)73	12 from below
ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ	ਕਾਮਰੇਡ ਗਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ	(18)82	1
placed	placcd	(18)83	13
स्कैंडल	स्कडल	(18)83	7 from below
टैक्स	टक्स	(18)84	19

PUNJAB VIDHAN SABHA

Friday, 5th November, 1965

The Vidhan Sabha met in the Vidhan Bhawan, Sector 1, Chandigarh at 9.00 a.m of the Clock. Mr. Speaker (Shri Harbans Lal) in the Chair.

QUESTION HOUR (DISPENSED WITH)

9.00 A.M.

Mr. Speaker : Question Hour is dispensed with as decided by the House earlier. These questions will be treated as Unstarred Questions. Now we pass on to other items.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESUIONS LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE UNDER RULE 45

ENQUIRY AGAINST A MUNICIPAL COMMISSIONER OF NURPUR, DISTRICT KANGRA

*8396. **Comrade Ram Chandra** : Will the Minister for Planning and Local Government be pleased to state whether the Government have conducted any enquiry during 1965 into the allegations against any Municipal Commissioner of Nurpur, district Kangra for trying to avoid payment of octroi duty by smuggling a truck at night; if so; the result thereof ?

Sardar Ajmer Singh : Yes, the matter was enquired through the Sub-Divisional Officer (Civil) Nurpur. The allegation that a truck was smuggled into the municipal limits of Nurpur by a Municipal Commissioner without payment of octroi duty was not substantiated.

OUTLET AT BURJI NO. 21000 DISTRIBUTARY FATEHGARH OF U.B.D.C., IN GURDASPUR DISTRICT

*8640. **Comrade Shamsher Singh Josh** : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to State—

(a) whether it is a fact that the required amount for turning a kacha outlet at Burji No. 21000 Distributary Fateh Garh of Upper Bari Doab Canal in Gurdaspur district into pucca was deposited by the persons concerned in the year 1961;

(b) whether it is further a fact that the said outlet has not been made pucca so far; if so, the reasons for the delay and the time by which it is expected to be made pucca ?

Chaudhri Rizaq Ram : (a) Yes. The amount deposited is regarding outlet RD 21022-L of Fatehgarh Disty.

(b) Yes. As a result of revised Chakbandi, numerous applications have been given by the shareholders action on which is being taken. As soon as action is finalized, the outlet will be installed on permanent basis. In the meanwhile, the temporary outlet on the basis of present area is existing as pipe outlet. No loss to irrigation has been allowed to occur.

SETTING UP OF A SCREENING COMMITTEE IN THE IRRIGATION DEPARTMENT

***8732. Sardar Balwant Singh** : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) whether it is a fact that Government has set up a Screening Committee in the Irrigation Department, if so, the names of its members;

(b) the details of the work so far done by the said Committee;

(c) the procedure adopted by the said Committee for its working.

Chaudhri Rizaq Ram : (a) Yes. It consists of the Chairman, Punjab Public Service Commission, the Secretary to Government, Punjab, Irrigation and Power Department and the Chief Engineer Irrigation Works, Punjab.

(b) No meeting of the Committee has been held so far.

(c) As laid down in the rule 8 of the Punjab Service of Engineers, Class I P.W.D. (Irrigation Branch) Rules, 1964, the Committee shall screen the cases of officiating Executive Engineers for promotion to PSE, Class—I.

BRIDGES ON HISSAR MAJOR AND PETWAR DISTRIBUTARY IN HISSAR DISTRICT

***8772. Shri Amar Singh** : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether it is a fact that bridges on the Hissar Major and Petwar Distributary on Khanda-Kheri to Narnaund road in Hissar district are not in order and some times traffic is blocked thereon, if so, the steps taken by the Government so far in this connection and the date by which these bridges are expected to be properly repaired ?

Chaudhri Rizaq Ram : Yes. The necessary proposals to make the bridges fit for heavy traffic are under technical scrutiny.

COMPENSATION PAID TO LAND OWNERS IN LIEU OF LAND ACQUIRED FOR RAJASTHAN CANAL

***8783. Comrade Babu Singh Master** : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the total amount of compensation given to the land owners in lieu of their land acquired for the Rajasthan Canal dug out from Harike Pattan;

(b) the rate of compensation given per acre to the said land owners;

(c) whether the water hes been supplied to the adjacent fields in the Punjab area from the Rajasthan Canal;

(d) the total length of the said canal in miles within the boundaries of the Punjab State i.e. from the Harike Pattan upto the place from where Rajasthan boundary starts;

(e) whether the Punjab Government has requested the Central Government for providing water from the Rajasthan Canal to the adjacent fields in the Punjab in order to increase production during the present emergency ?

Chaudhri Rizaq Ram : (a) Rs 54,99,480.

(b) Average Rs 797.09 per acre.

(c) No.

(d) About 110 miles.

(e) No.

CONSTRUCTION OF A BUND AT CHHAINSA ON JAMUNA RIVER

***8790. Shri Roop Lal Mehta** : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the details of steps so far taken for constructing a bund at Chhainsa on the Jamuna River in order to remove the great inconvenience caused by the flood waters which come to the Khadar area of Gurgaon District during the rainy season ?

Chaudhri Rizaq Ram : A scheme for providing protection to villages on right side of river Jamuna in Tehsil Ballabgarh of Gurgaon District is under technical scrutiny.

STENOGRAPHERS IN THE IRRIGATION DEPARTMENT

***8798. Shri Surinder Nath Gautam** : Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the joint seniority list of Stenographers to Superintending Engineers in the Irrigation Branch prepared by the Chief Engineer some time in 1959-60 is now being changed;

(b if the reply to part (a) above be in the negative, whether the posts of senior scale stenographers in the Irrigation Branch in the grade of Rs. 150—10—300 are filled strictly in accordance with the said seniority list, If not, the reasons for the same ?

Chaudhri Rizaq Ram : (a) No.

(b) No. The Stenographers attached to the Superintending Engineers are in the scale of Rs. 106—6—160/8—200 and are borne on the circle cadre. Their seniority list was prepared for the purposes of making confirmation only against the additional permanent cadre sanctioned with effect from 1st August, 1960. The posts of senior scale stenograhers in the scale of Rs. 150—10—200/10—300, being on different cadre, are not filled in by promotion from amongst the Stenographers attached to the Superintending Engineers.

EXPLOSION IN NANGAL POWER STATION

***8786. Comrade Babu Singh Master** : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) whether it is a fact that there was a serious explosion in Nangal Power Station on the night of 15th June, 1965;

(b) whether it is also a fact that the Sub-Station was blown up and two constables were seriously burnt as a result of the said blast; if so, the causes which led to the said blast together with the details of the enquiry, if any, held into the matter?

Chaudhri Rizaq Ram : (a) Yes, Sir.

(b) No Sir,. Only one out of six oil filled Potential Transformers got burnt. Two P.A.P. Constables sleeping outside their barracks near the switchyard got serious burns from hot oil splashed from the damaged potential transformer. The reason for the bursting was a short-circuit of the 220 K.V. lead with sleeve around the core, within the transformer. The cause of the short circuit is being investigated.

GRANT OF OLD AGE PENSION

***8775. Shri Amar Singh** : Will the Minister for Welfare and Justice be pleased to state—

(a) the total number of persons at present getting old age pensions in the State, district-wise, with the number of those, belonging to the Scheduled Castes among them;

(b) whether any applications from Hissar district for the grant of such pensions are still pending, if so, the time by which these are likely to be disposed of ?

Shri Chand Ram :

A statement showing the requisite information is laid on the Table of the House.

STATEMENT

(a) 6,358 as per district-wise detail given hereunder —

District	*No of persons granted pensions*
Jullundur	587
Amritsar	660
Ambala	866
Karnal	242
Rohtak	481
Hissar	131
Gurgaon	420
Simla	28
Patiala	333
Sangrur	226
Mohindergarh	64
Kapurthala	159
Ludhiana	393
Ferozepur	423
Kangra	273
Kulu	15
Hoshiarpur	683
Gurdaspur	279
Bhatinda	93
Lahaul & Spiti	—
Delhi (Not permanent residents of Delhi)	6,358

No separate record of pensioners belonging to Scheduled Caste has been maintained. The time and labour involved in collection of the requisite data will not be commensurate with the benefit likely to be achieved.

(b) Yes. 139. These are likely to be disposed of during the year 1966—67, subject to availability of funds.

PURCHASE OF EVACUEE LAND BY THE HARIJANS

*8736. **Shri Banwari Lal** : Will the Minister for Welfare and Justice be pleased to state—

(a) whether it is a fact that Government have now discontinued advancing loans repayable in ten years to the Harijans for purchasing rural evacuee agricultural land;

(b) if the reply to part (a) above be in the affirmative, the alternative arrangements, if any, made by the Government to enable the Harijans to purchase the above mentioned land ;

Shri Chand Ram : (a) Yes.

(b) The cost of evacuee lands, purchased by Harijans in auction shall, in future, be recovered from them in 20 half-yearly instalments: the recovery commencing from one year after the date of confirmation of the bid.

ALLOCATION IN THE BUDGET FOR THE PURCHASE OF LAND FOR THE SCHEDULED CASTES LAND BENEFICIARIES

*8737. **Shri Banwari Lal** : Will the Minister for Welfare and Justice be pleased to state the total amount allocated in the Budget by the Welfare Department for the purchase of land for the Scheduled Castes land beneficiaries of District Mohindergarh during the year 1965-66 together with the amount, if any, out of the said allocation transferred to district Gurgaon ?

Shri Chand Ram: Rs. 8000/—. The entire amount has been transferred to Gurgaon district to replenish its grant transferred to Mahendragarh during the previous year.

GRANT FOR THE CONSTRUCTION OF WELL IN VILLAGE BUCHOLI, TEHSIL AND DISTRICT MAHENDRAGARH

*8738 **Shri Banwari Lal** :Will the Minister for Welfare and Justice be pleased to state—

(a) whether Government has recently given any grant for the construction of a well for providing drinking water to the Harijans in village Bucholi, Tehsil and District Mahendragarh;

(b) if the reply to part (a) above be in the affirmative, whether Government have received any representation from the public against the said grant. if so, the action, if any, taken by the Government thereon ?

Shri Chand Ram : (a) No.

(b) Question does not arise.

FORESTS IN THE STATE

*8680 **Comrade Shamsher Singh Josh** : Will the Minister for Welfare and Justice be pleased to state—

(a) the total area of land under Forests in the State district-wise in 1964 and 1965 separately;

(b) the total acreage of new lands, if any, acquired by the Government in the State for afforestation, district-wise and village-wise during the said period, year-wise ?

Shri Chand Ram : (a) & (b) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement showing the Area of Land uuder Forests in the State and new lands acquired for afforestation in 1964 and 1965.

Name of District.		(a) Total area in 1964. Hectares	1965. Hectares.
1. Kangra.	..	3,33,672.73	3,33,522.58
2. Kulu.	..	5,32,339.95	5,32,339.95
3. Lahaul and Spiti.	..	6,491.79	5,11.236.91
4. Gurdaspur.	..	16,715.62	16,715,63
5. Hoshiarpur.	..	1,55,311.72	1,55,206.09
6. Simla.	..	15,552.68	15,552.68
7. Ambala.	..	1,16,008.79	1,15,345.34
8. Patiala.	..	10,299.21	11,017.15
9. Sangrur.	..	11,082.98	11,082.98
10. Karnal.	..	11,191.44	11,644.30
11. Hissar.	..	8,883.73	8,209.13
12. Mohindargarh.	..	4,337.54	4,323.69
13. Gurgaon.	..	13,184.51	16,357.08
14. Rohtak.	..	8,323.06	8,259.75
15. Bhatinda.	..	7,720.06	7,720.06
16. Ferozepur.	..	8,152.84	8,464.53
17. Amritsar,	..	7,562.26	7,562.26
18. Jullundur.	..	2,742.26	2,642.26
19. Ludhiana.	..	3,627.12	3,627.12
20. Kapurthala.	..	1,257.81	1,257.80
Total:—		12,74,358.10	17,85,087.29

The increase is mainly due to the inclusion of Lahaul and Spiti area.

(b) New Land acquired for afforestation:—

Year 1964. Nil.

Year 1965.

Name of village.	Name of Distt.	Area.
1. Kartarpur.	Patiala.	167 acres.
2. Plasra H. B No. 81.	Ambala.	138.25 Acres

———

CASES FILED AGAINST SONS OF LATE S. PARTAP SINGH KAIRON

*8408. **Comrade Ram Chandra** : Will the Minister for Home and Development be pleased to state the details of cases filed by the Government against Sarvshri Surinder Singh and Gurinder Singh sons of late S. Partap Singh Kairon together with the stage at which each case ... ent ?

... Singh : A statement is laid on the Table of the

[Home and Development Minister]

Upto-date position in cases registered against Sarvshri Surinder Singh and Gurinder Singh Kairon sons of Late S. Partap Singh Kairon

S. No	Particulars of case	Brief facts	Present position
	District Ambala		
1.	Case FIR No. 656 dated 28-10-64 u/s 364 IPC P. S. Chandigah.	Alleged kidnapping of Bishan Singh by Surinder Kairon. The former was the employee of the latter.	Filed as untraced by Illaqa Magistrate on 22.4.65.
2.	Case FIR No. 581 dated 8-10-64 u/s 420/383 IPC P.S. Chandigarh.	Alleged cheating on the basis of a cheque issued by Surinder Singh Kairon in favour of M/S Globe Steel Works, New Delhi, which was dishonoured.	The case was cancelled by the Illaqa Magistrate on 27-5-65.
3.	Case FIR No. 655, dated 28.10.64 u/s 342/384 IPC P.S. Chandigarh.	Alleged wrongful confinement and extortion practised on the driver of the Truck in which Surinder Singh Kairon had transported goods from Delhi.	The case is being sent up as untraced on the basis of the opinion given by Prosecuting Inspr. & District Attorney.
4.	Case FIR No. 488 dated 22-8-64 u/s 5(2) P. C. Act P. S. Chandigarh. &	Alleged corruption practised in respect of the sanction of the transfer of share in Neelam Cinema in favour of Surinder Singh Kairon and purchase of land by Government at exhorbitant rate for the purpose of settling Harijans, with a view to obtain pecuniary advantage for Surinder Singh Kairon.	Both the cases are under investigation.
5.	Case F.I.R. No. 489 dated 22-8-64 u/s 5(2) P.C. Act P.S. Chandigarh		
6.	Case F.I.R. No, 37, date 18-8-64 u/s 409, 420 and 5(2) P.C. Act P.S. Chamkaur Sahib.	Alleged corruption and misappropriation of material in the construction of Siswan superpassage by Capital Construction Co., owned by Surinder Singh Kairon,	Investigation has been completed and challan will be put in court shortly, after sanctions for prosecution of the Govt. servants [illegible]

7.	Case F.I.R. No. 131 dated 3-8-64 u/s 7 E. C. Act & 420 IPC P.S Sadar, Ambala.	Alleged misuse of controlled material (issued on permits) by M/S Cinemarans, a concern of Kairons,	Challan has since been put in the Court of J.M.I.C. Ambala City.
	District Amritsar		
8.	Case FIR No. 232, dated 27-10-64 u/s 7 E.C. Act P.S. 'A' Division Amritsar.	Alleged misuse of G.C. Sheets obtained on permit by Gurinder Singh Kairon for Cinema construction.	Challan put in the court on 16-6-65 and is fixed for argument for framing of charges.
9.	Case FIR No. 495 dated 27-10-64 u/s 7 E. C. Act. P. S. Sadar Amritsar.	Alleged misuse of G.C. Sheets obtained for Cold Storage by Gurinder Singh Kairon.	The case is fixed for arguments and framing of charge.
10.	Case FIR No. 207 dated 22-9-64 u/s 342/323/384 IPC P. S. 'A' Division Amritsar.	Alleged extortion and wrongful confinement of Shri Harbhajan Singh, Prop. Scale Steel works New Delhi, by Gurinder Singh Kairon when he went to Amritsar to get the payment of furniture supplied to Nandan Cinema.	The Complainant compromised with the accused and did not support the allegations. The case was consequently sent as untraced.
11.	Case FIR No. 193 dated 22-8 64 u/s 5(2) 47 P. C. Act and 120B IPC/P.S.'A' Division Amritsar.	Alleged corruption and mal-practices, misuse of official position for obtaining pecuniary advantage for Gurinder Singh Kairon.	The Investigation is almost complete and legal aspects of the case are being examined by the prosecution agency.
12.	Case FIR No. 254 dated 20-11-64 u/s 7 E. C. Act., P.S. 'A' Division Amritsar	Alleged misuse of G. C. sheets obtained on permits for Cold Storage belonging to Shri Gurinder Singh Kairon.	Some documents in this case are being examined by the Examiner of Question Documents. The case will be put in court on receipt of his opinion.
13.	Case FIR No. 2 dated 5-1-65 u/s 406/420 IPC, P.S. Civil lines Amritsar.	Alleged Cheating and misappropriation of Rs. 500/- obtained by Sarvshri Surinder Singh Kairon and Jai Inder Singh MLA from Gura Singh a brother of Mehain Singh detenue for helping to get his release from detention.	Investigation almost complete and challan will be put shortly.
14.	Case FIR No. 269, dated 20 12-64 u/s 186/353 382 IPC P.S. 'A' Division Amritsar.	Alleged forcible snatching of records by Gurinder Singh Kairon from officials of the Income Tax department.	Challan put in the Court but accused discharged on 23-4-65.
	District Gurgaon		
15.	Case FIR No. 101 date 28-10-64 u/s 6 of East Punjab Bricks Act 1949, P. S. Faridabad (Gurgaon)	Alleged un-authorised purchase of bricks by M/S Fine Films (owned by Surinder Singh Kairon) in contravention of clause 9 of the Punjab Control Of Bricks Supplies Order.	Investigation is being finalised and the challan will be put in court shortly,

S.No.	Particulars of case	Brief facts	Present position
16.	Case FIR No. 102 dated 28-10-64 u/s 420/477 A IPC, P.S. Faridabad (Gurgaon).	Alleged cheating and forgery in respect of a huge loan obtained through deceitful means from Punjab Financial Corporation, Chandigarh for setting up a freezing unit at Faridabad.	The investigation is almost complete and some documents have to be taken into possession from Shri Surinder Singh Kairon.
17.	Case FIR No. 103 dated 28-10-64 u/s 7 E.C. Act, P.S. Faridabad (Gurgaon).	Alleged misuse of G.C. and G-P. sheets obtained by M/s Films (owned by Surinder Singh Kairon) for Neelam Cinema at Faridabad	The investigation has been completed and a prima facie case was made out against Surinder Singh Kairon. As the accused was evading arrest, non-bailable warrants of his arrest were obtained from J.M. Gurgaon. Shri Surinder Singh Kairon was granted bail by A.D.M. Delhi on 31-8-65 in this case, where he surrendered. The case will be completed after the interrogation of the accused.
District Sangrur			
18.	Case FIR No. 149 dated 19-11-65 u/s 406/420 IPC, P.S. Jind	Alleged cheating and fraud practised by Surinder Singh Kairon and his 'mukhtiar' on villagers of V. Dhani inducing them to part with their money but did not transfer the land to them.	Challan prepared in the case and points raised during scrutiny are being complied with.
District Ludhiana			
19.	Case FIR No. 250 dated 23-4-65 u/s 7 E. C. Act, P. S. Sadar Ludhiana.	Alleged misuse of imported material (Zinc and Copper, non-ferrous metals) issued to M/S India Chemical Works, obtained by Gurinder Singh Kairon in the fictitious name of one Amarjit Singh Sodhi.	Case is still under investigation with Ludhiana Police.
District Patiala			
20.	Case FIR No. 65, dated 26-7-65 u/s 420 IPC, P. S. Civil Lines Patiala.	Non-payment of Octroi duty on 29 Bus Chassis delivered by National Motors (owned by Surinder Singh Kairon) Patiala, to the Pepsu Road Transport Corporation, Patiala, during the period from 3rd November 1959 to 2nd August, 1963.	The Case is under investigation.

CLASH BETWEEN ROADWAYS WORKERS AND STUDENTS AT JULLUNDUR

***8509 Comrade Shamsher Singh Josh**: Will the Minister for Home and Development be pleased to state:—

(a) the result of the Judicial Enquiry held in connection with clash which occurred between the Roadways workers and the students at Jullundur in July/August, 1965;

(b) whether the cases registered against the students involved in the said incidents have been withdrawn ?

Sardar Darbara Singh:(a) The Judicial Enquiry is still in progress.

(b) No.

CIVIL DEFENCE ORGANISATION

***8688. Shri Mangal Sein** : Will the Minister for Home and development be pleased to state whether any decision was taken in 1965 to disband the Civil Defence Organisation in the State and to demobilise the P.C.S. Officers deputed for this work; if so, the details of the orders now issued to revive the said Organisation ?

Sardar Darbara Singh: (a) It was never decided to disband Civil Defence Organisation in the State.

(b) The Civil Defence Officers (P.C.S. Officers) are posted in the vulnerable towns when contingencies for such appointments arise. These posts are withdrawn when no longer required.

REWARD TO PERSONS WHO CAUGHT HOLD OF THE PAKISTANI PARATROOPERS

***8693 Shri Mangal Sein**: Will the Minister for Home and Development be pleased to state the nature of rewards so far given by the Government to persons in the state who caught hold of Pakistani paratroopers and the names of the persons so rewarded ?

Sardar Darbara Singh: Rs. 1000 have been paid by Zila Parishad, Bhatinda and Rs. 500 by State Government to the dependents ofConstable Man Singh No. 275 who was killed in encounter with paratroopers. Recommendations for the grant of rewards to a number of Police officials and members of public are under consideration with the authorities concerned.

PERSONS HELD FOR SPYING AND TRANSMITTING INFORMATION TO PAKISTAN

***8694 Shri Mangal Sein**: Will the Minister for Home and Developement be pleased to state the total number of persons held in the State for spying or transmitting information to Pakistan with their names and addresses in each case ?

Sardar Darbara Singh: It is not in public interest to divulge any information.

ENQUIRY AGAINST S. H. O. SIWANI. DISTRICT HISSAR

***8757. Shri Jagan Nath**: Will the Minister for Home and Development be pleased to state whether any enpuiry is being held against the S. H. O. Siwani. district Hissar in regard to the complaints made during the period from August, 1965 to October, 1965, by Lala Narang Rai and Shri Pahlad Singh Members, Panchayat and Ch. Pratap Singh village Isharwal about the alleged smuggling of a Tractor full of grams; if so, the contents of complaints so made and the stage at which the enquiry stands at present ?

Sardar Darbara Singh : Yes; it was alleged that a tractor loaded with grams was caught by a Constable of Police Station Siwani in village Isharwal on 7.8.65 but the culprits were let off by him. Though the matter was brought to the notice of S. H. O. Police Station Siwani, yet no enquiry etc. was made by him. It was further alleged that the S. H. O. himself was indulging in black-marketing. The District Inspector, Hissar is enquiring into this complaint. The complainants have since been examined by him.

COMPLAINTS AGAINST S. H. O. SIWANI, DISTRICT HISSAR.

***8758. Shri Jagan Nath**: Will the Minister for Home and Development be pleased to state whether any written complaints were received by a S.D.O. (Civil) Bhiwani and S.P. Hissar from any M.L.A. during September/October, 1965, against the S. H. O. Siwani (Hissar) about his anti-Harijan attitude, if so, the contents of the said complaints and the action, if any, taken thereon ?

Sardar Darbara Singh : Yes, It was complained that Shri Ratti Ram brother of Shri Jagan Nath, M. L. A. had taken on lease a piece of land belonging to the Custodian, whose possession had also been delivered to him but Shri Sita Ram etc. were not allowing him to enter upon that land and that the S. H. O. was siding with Shri Sita Ram. The complaints also contained general allegation that the S. H. O. was anti-Harijan and was out to involve the M. L. A. in a false case. An enquiry was ordered in this case but parties compromised.

TOUR BY DEPUTY COMMISSIONER, KANGRA IN THE JEEP OF NURPUR DEVELOPMENT BLOCK

***8389 Comrade Ram Chandera**: Will the Minister for Home and Development be pleased to state:—

(a) the number of times when the jeep of the Nurpur Development block was requisitioned by the Deputy Commissioner, Kangra during the period from 1-1-64 to date together with the purpose for which it was requisitioned each time;

(b) the number of days for which the said jeep was used by the Deputy Commissioner during the above mentioned period;

(c) the mileage covered by the Deputy Commissioner in the said jeep and the names of places visited by him;

(d) the quantity of petrol consumed in the said jeep during the said period;

(e) the head of account to which the cost of the petrol so consumed has been debited ?

Sardar Darbara Singh:—

a, b, c, d, e } A statement showing the periods of requisition, mileage covered, consumption of petrol and purpose of journey together with the head of account under which the cost of account under which the cost of petrol so consumed, has been debited. is laid on the Table of the House,

[Home and Development Minister]

Statement regarding the use of Nurpur Block Jeep No. P.N.N. 7002 by the Deputy Commissioner, Kangra, during the period 1st January, 1964, up to-date.

Date	From	To	Mileage	Petrol consumed	Purpose of journey
8-12-1964	Nurpur	Nurpur	65 miles	20 litres	Inspection of the Military Firing Range in Nurpur Sub Division alongwith S.D.O. (C) Nurpur and village touring for Development work.
9-12-1964	Nurpur	Nurpur	8 miles	2 litres	Visited villages Jassur and Chhatroli in connection with rail-head agencys' work.
9-12-1964	Nurpur	Dharamsala	50 miles	20 litres	As the Government jeep with D.C. was sent to Pathankot for repairs, Nurpur Block jeep was used for the return journey to headquarters.
5-1-1965	Nurpur	Nurpur	31 miles	10 litres	Inspection of Development work in village Bassa, Kandi etc.
6-1-1965	Nurpur	Nurpur	60 miles	20 litres	Alongwith S.D.O. held enquiry at Rehan and Development work in Barot and Fatehpur villages.
8-1-1965	Nurpur	Nurpur	21 miles	7 litres	Visited villages Ganoa and Panjahara for inspection of roads and general Administration including development work.
9-1-1965	Nurpur	Nurpur	21 miles	7 litres	Visited villages Sadwan, Manoon, Gurchal, inspection of roads and General Administration including Development work.
10-1-1965	Nurpur	Dharamsala	50 miles	18 litres	Back to headquarters because Deputy Commissioner's jeep was out of order and not working.

15-5-1965	Dharamsala	Palampur	81 K.M.	16 litres	The jeep was requisitioned by D.C. in connection with C.M's visit to Kangra district, having no other jeep at his disposal. Touring in connection with C.M's visit to Palampur, Jogindernagar, Moranda and Baijnath.
16-5-1965	Palampur	Baijnath	39 K.M.	8 litres	
17-5-1965	Baijnath	Baijnath	140 K.M.	28 litres	
18-5-1965	Baijnath	Dharamsala	73 K.M.	15 litres	Back to headquarters.
19-5-1965	Dharamsala	Dharamsala	18 K.M.	4 litres	Local duty at Dharamsala in connection with the visit of Mr. Justice Capoor and inspection of District Courts by him, there being no other jeep at the disposal of the Deputy Commissioner.
20-5-1965	Dharamsala	Nurpur	67 K.M.	13 litres	Tour to Nurpur
21-5-1965	Nurpur	Nurpur	98 K.M.	21.7 litres	Inspection of Flood Protection Works in Indora Block alongwith D.S.P. and S.D.O. Drainage visiting Bhadpur, Re etc. and Development work.
23-5-1965	Nurpur	Nurpur	32 K.M.	6 litres	Visits to B.D. and P.O's office Nurpur and visited village Kamnala.
18-7-1965	Nurpur	Nurpur	54 K.M.	11 litres	Visited villages Bhadwar, Khajjan and Suliali for inspection of Development work.
19-7-1965	Nurpur	Nurpur	71 K.M.	16 litres	Village Touring in connection with Development work visit to Jawali-Dehr Khad regarding dispute between Public Health Department and Irrigation Department.
20-7-1965	Nurpur	Nurpur	50 K.M.	10 litres	Village Touring to Gangeth, Dagla etc. in connection with Development work.

[Home and Development Minister]

Date	From	To	Mileage	Petrol Consumed	Purpose of journey
21-7-1965	Nurpur	Nurpur	46 K.M.	9 litres	Inspection of S.D.O's, Tahsildar's and B.D. and P.O's offices and village touring to Khajjian, inspection of Gosadan.
22-7-1965	Nurpur	Dharamsala	70 K.M.	16 litres	Back to headquarters.
		306 miles and	839 K.M.	277.7 litres	

Note :—(1) All the journeys were on official duty.

(2) All petrol consumed was paid out of XIX General. Administration District Contingencies and not from the block funds.

EX-SARPANCH OF PANCHAYAT KARWAN, BLOCK HODEL, DISTRICT GURGAON

*8763. **Shri Jagan Nath**, : Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

(a) whether any enquiry was conducted against the Ex-Sarpanch of Panchayat Karwan, Block Hodel, district Gurgaon during the period from 1st January, 1964 to date, if so; the details of the action Government proposed to take against him;

(b) whether it is a fact that the Deputy Commissioner, Gurgaon, issued a direction to the Superintendent of Police, Gurgaon, to register a case under section 409 I.P.C. against the said Ex-Sarpanch; if so, with what results;

(c) whether the said Ex-Sarpanch handed over the complete charge of the said Panchayat to the newly elected Sarpanch?

Sardar Darbara Singh: (a) Yes. The Superintendent of Police was asked to register a case against the Ex-Sarpanch u/s 409 I.P.C.

(b) Yes, but the Station House Officer, Hussanpur returned the case to the Block Development and Panchayat Officer, Hodel to furnish the audit report. The Examiner, Local Fund Accounts Punjab, has been asked to arrange for the audit of this Panchayat.

(c) The charge has been handed over to the newly elected Sarpanch partially. Action under section 15 of the Punjab Gram Panchayat Act is being taken to have the complete charge handed over.

SETTING UP JUNIOR AGRICULTURAL COLLEGE AT PALAMPUR IN DISTRICT KANGRA

*8629. **Bakshi Partap Singh** : Will the Minister for Home and Development be pleased to state —

(a) whether it is a fact that the Government has decided to set up a Junior Agricultural College at Palampur in Kangra District;

(b) if the reply to part (a) above be in the affirmative, the amount likely to be spent on the said project;

(c) whether the requisite site of land has been selected, acquired and demarcated for the purpose?

Sardar Darbara Singh : (a) No.

(b) and (c) Does not arise.

Mechanization of Agriculture in the State

***8782. Comrade Babu Singh Master,** : Will the Minister for Home and Development be pleased to state the details of the steps taken or proposed to be taken by the Government to mechanise agriculture in the State together with the results achieved so far ?

Subject :—Starred Question 8782 asked by Comrade Babu Singh Master, M.L.A., regarding mechanization of Agriculture in the State.

Answer to Starred Assembly Question No. 8782 appearing in the list of Starred Questions to be asked at the meeting of the Punjab Vidhan Sabha on the 5th November, 1965, in the name of Comrade Babu Singh Master, M.L.A. is not ready. The reason is that the question was received late from the Vidhan Sabha Secretariat. The requisite reply is still awaited from the Director of Agriculture, Punjab, and it is likely to take some time. This information is being sent to the Speaker, who is requested to extend the time for answering the question under proviso (ii) to Rule 41 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Vidhan Sabha.

2. The Question may be included in the list of Questions for any date after the 19th November, 1965.

Sd-Darbara Singh,
Home and Development Minister
Punjab.

To

The Speaker,
Punjab Vidhan Sabha,
Chandigarh.

U.O. No. 6765-FP (VI)-65/2884
Chandigarh, dated the 4th November, 1965.

UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS

COMPLAINTS RECEIVED BY THE INSPECTOR OF FACTORIES, PATIALA

3005. Comrade Bhan Singh Bhaura : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state —

(a) Whether the Inspector of Factories, Patiala, received any complaints from any Unions duridg the year, 1965;

(b) if the reply to part (a) above be in the affirmative, the names of such Unions, the contents, of the complaints and the details of the action, if any, taken thereon?

Chaudhri Rizaq Ram : A statement containing the requisite information is laid on the Table of the House.

Statement of Complaints Received by the Factory Inspector, Patiala from the various Unions during the year 1965

S. No.	Date of complaint.	Name of the complainant.	Body of the complaint.	Action taken.
1	2	3	4	5
1.	26-6-1965	General Secretary, District Engineering Workers Union, Malerkotla.	Complaint against M/S Rashid and Bashir Industries, Dhobi Ghat, Malerkotla regarding accident enquiry to Shri Khalil Ahmed on 19th May, 1965.	The matter was enquired into by the Factory Inspector, Patiala on 27th September, 1965 in the factory in the presence of the General Secretary of the Union. The attendance and payment of wages register were checked by the Factory Inspector was not found therein. Hence the complaint was filed.
2.	Ditto	Ditto	Complaint against M/s Rashid and Bashir Industries Malerkotla regarding accident enquiry to Shri Abdul Majid on 4th June, 1965.	As against item No. one above.
3.	24-9-1965	Shri Tejinder Singh, Secretary, Engineering Workers Union, Patiala.	Complaint against M/s Raj Industries, Sanori Gate (Mirch Mandi), Patiala regarding accident to Shri Dhiraj Singh on 20th September, 1965.	The matter was enquired into by the Factory Inspector. Patiala and it was found by him that name of the this worker was not entered in the muster roll. Necessary comments have, therefore, been called for by the Factory Inspector, Patiala from the Union, which are still awaited. Hence the matter is pending with the Factory Inspector, Patiala

BRINGING HOTLES AND THEIR MANAGEMENTS UNDER TNE MINIMUM WAGES ACT, 1948.

3006. Comrade Bhan Singh Bhaura : Will the Minister for Irrigation and Power with reference to the reply to Unstarred Question No. 2489 included in the list of Unstarred Questions for 24th March, 1965 be pleased to state whether the Advisory Committee referred to in the said reply has since been constituted, if not, the details of action taken so far in this connection and the present stage of the case ?

Chaudhri Rizaq Ram : Not yet. Particulars of the representatives of the employers/employees and independent members for the constitution of the said Committee had to be collected through the field staff. The requisite particulars have since been received and the matter regarding constitution of the Committee is under active consideration.

ROADS INCLUDED IN THE SECOND FIVE YEAR PLAN PERIOD FOR ERSTWHILE PEPSU STATE

3021 Comrade Hardit Singh Bhathal: Will the Minister for Public Works be pleased to state—

(a) the details of the scheme formulated under Second Five-Year Plan for metalling the roads in the areas of erstwhile Pepsu State;

(b) the names and the total length of the roads referred to in part (a) above;

(c) the number and names of the roads referred to in part (a) above which are in district Sangrur;

(d) the numbers of roads referred to in part (b) which have been completed together with the names of those which are still incomplete;

(e) whether the said incomplete roads have been dropped from the plan, if so, the reasons therefor ?

Chaudhri Ranbir Singh: (a to d) The requisite information is mentioned district wise in the enclosed statement.

(e) No; the question does not arise.

STATEMENT

Roads proposed in the II Five-Year Plan in Erstwhile, Pepsu Districts

Serial No.	Name of Road	Length miles	Cost Rs. in lacs	Present condition.
1	2	3	4	5
	I Patiala District			
1.	Pall-Rara-Dehlon	9.00	6.00	Completed
2.	Chandigarh-Siswan-Nalagarh-Section Siswan Baddi	3.00	1.80	Not yet started

1	2	3	4	5
3,	Patiala-Panjola Chika	10.00	7.50	Almost completed
4.	Metalling Pinjor-Nalagarh Bilaspur	34.00	20.00	Section Pinjore Nalagarh complete, work not started on Nalagarh-Bilaspur section
5.	Ramshar-Narali	8.00	3.60	Work not actually started
6.	Patiala-Sirhind	18.00	12.60	Completed
7.	Jeep tracks in hills	45.00	7.00	Completed
8.	Gulha-Samanal-Bhawanigarh	20.00	15.00	9½ miles completed Earthwork done in 6½ miles and Colletion of material in progress in the remaining miles
9.	Moonak-Tohana	5.00	2.50	Completed
10.	Bhupinder Sagar-Mauran	6.00	2.80	—Do—
11.	Bhunerhari-pehowa	8.00	6.89	Almost completed
12.	Patiala Bhadson	15.50	4.86	34 miles completed in all respects and materials collected in 6 miles
13.	Lal Kalan to Nilon bridge on Ludhiana Samrala Road	0.75	0.40	Completed
	II Bhatinda District			
1.	Jakhal-Budhlada	16.00	8.62	11 miles completed in all respects. Materials collected in the remaining miles
2.	Rathi-Budhlada	11.00	8.25	Completed
3.	Bhatinda-Muktsar	11.00	6.50	Completed
4.	Talwandi Sabo-Rani	14.00	10.50	6 miles completed. Earthwork, construction of B & C and collection of soiling completed in remaining length
5.	Kalanwali-Sardulgarh-Rattia	10.00	7.75	5 miles completed. Work in progress in the remaining miles
6.	Bagha-Purana-Nathana	7.50	5.50	Completed

(Public Works Minister)

1	2	3	4	5
7.	Raman-Talwandi Sabo & Rampura Phul-Maur	21.00	15.30	Section Rampur Phul-Maur (14 m.) completed. Sect on Talwandi Sabo Raman Road. One mile completed in all respects mate-rials collected in 4 miles. Work in pro-gress (7 miles)
8.	Dialpura/Phul Road	9.40	7-43	Completed
9.	Muktsar-Ferozepur	14.00	8.40	2 miles completed in all respects and material i. e. soiling and wearing coat collected in 10 miles.
10	Barnala-Bhadawr-Bajekhana	12.00	7.89	Completed
11.	Bhatinda-Dabwali	24.00	13.80	Do
12.	Faridkot-Dip Singh Wala	16.50	9.40	Do
13.	App. to Mansa Mandi	0.90	0.52	Do
14.	Mahraj-Rampura Phul	2.50	1.20	Do
15.	App. to Maur Mandi	0.88	0.50	Do
	III Sangrur District			
1.	Jakhal-Sunam-Sangrur	31.00	21.70	16 miles completed in all respects. Mate-rials i. e. soiling and wearing coat collec-ted in 4 miles, Bitu-men collected for entire length
2.	Barnala-Rai Kot	19.40	15.00	Completed
3.	Jind-Gohana	10.00	6.56	8 miles completed in all respects. Material collected in 2 miles
4.	Fakhoke-Ramgarh	9.50	7.00	Completed
5.	Jind-Rohtak	21.00	13.65	Do
6.	Uklana-Narwana-Kaithal	34.00	21.00	Do
7.	Jakhal-Budhlada	4.50	3.38	Do
8,	Dhuri Sherpur	8.00	3.20	Do
9.	Dhuri-Bhalwan	11.50	5.70	Do
10.	Dhuri-Mallowal	11.00	5.50	Do
11.	Jind-Pindu Pindara	3.43	1.96	Do
12.	Barnala-Bajekhana	16.20	8.00	Do
13.	Bhupinder Sagar-Moonak	20.50	14,00	Do
14.	Bhupinder Sagar-Mauran	6.00	2.82	Do
15.	Panipat-Safidon-Kaithal	7.60	5.56	Do
16,	Dhangowal-Badhar	4,00	1.60	Do

1	2	3	4	5
17.	App. to Uchana Rly, Station from Jind Nirwana	0.80	0.42	Completed
18.	Kalyat Town to Railway Station	3.00	1.28	Do
	IV Kapurthala District			
1,	Begowal-Miani	3.00	3.00	Completed
2.	Nakodar-Phagwara	5.00	4.00	Do
3.	Kala-Nakodar	2.00	1.60	Do
4.	Nadela-Behowal	6.00	4.50	Do
5.	Sultanpur-Fathu Dingra-K. Taala	16.50	11.03	Do
	V Mohindergarh District			
1.	Dadri-Bhiwani	16.00	8.60	Completed
2.	Narnaul-Singhana	11.00	6.60	Do
3.	Kanina-Atela	16.50	9.83	Earth work done in entire length 7 miles completed in all respects. Material collected in all miles B & C constructed in 3½ miles
4.	Mohindergarh-Kanina.Lakhi	18.00	10.80	Completed
5.	Narnaul-Naampur	7.50	3.75	Do
6.	Dadri-Bond	13.70	4.20	Do
7.	Dadri-Loharu	25.00	11.50	Do
8.	Ateli-Kheri	0.50	2.82	Do
9.	Narnaul-Nangal Chowdhri	11.00	4.89	Do
10.	App. to Jhaju Kalan from Dadri Mohindergarh Road	3.50	1.00	Do
11.	Rasiwas to Dadri Bhiwani Road	3.40	1.47	Do

PERSONS INSURED UNDER THE EMPLOYEES STATE INSURANCE SCHEME AT PATIALA ETC.

3033. Comrade Bhan Singh Bhaura, Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the number of persons insured under the Employees State Insurance Scheme at Patiala, Rajpura, Gobindgarh and Bahadurgarh separately as on 30th September, 1965.

Chaudhri Rizaq Ram : The number of persons insured under the Employees State Insurance Scheme as on 30th September, 1965 was as under—

Patiala	..	1500
Rajpura	..	2100
Gobindgarh	..	2500
Bahadurgarh (Distt. Patiala)	..	700

UNIONS IN PATIALA AND SANGRUR DISTRICTS RECOGNISED UNDER THE CODE OF DISCIPLINE.

3034. Comrade Bhan Singh Bhaura : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to lay on the table a list of Unions in Patiala and Sangrur Districts which have been recognised under the Code of Discipline by the employers ?

Chaudhri Rizaq Ram : The names of the Unions in Patiala and Sangrur Districts which have been recognised under the Code of Discipline are given as under :—

1. Sewing Machine Workers Union, Bassi-Pathana (Patiala District).
2. Malwa Sugar Mills Workers Union, Dhuri (Sangrur District)

ਕਾਮਰੇਡ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਸੀ ਇਹ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸੀ । ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਸਤ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਵਿਚੋਂ ਲਾਹਕੇ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ । * * * * * * * * * * (ਵਿਘਨ)

Mr. Speaker: Please take your seat.

ਕਾਮਰੇਡ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ : ਜਨਾਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਕਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸਨ । ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

Mr. Speaker : Comrade Tarsikka will you please take your seat ?

ਕਾਮਰੇਡ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ: ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਲੈ ਆਇਆ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਕਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

Education Minister : Sir, I seek your indulgence for half a minute, The hon. Member has just now referred in his remarks that two Congress M.L.As. are involved in the murder case. Sir, these words may be expunged. If they are allowed to appear in the Papers, they will leave an impression that we are murderers or some of us are murdrers.

Mr. Speaker : I agree that these are allegations/reflections on some members of this House. They are expunged.

ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਬਸ ਵਿਚੋਂ ਕਢ ਕੇ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ...

---

*Note ; Expunged under the order of the hon. Speaker.

Mr. Speaker : Please take your seat.

ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ : ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਰਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਨ ਤੇ ਮਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੇਫ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਐਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

Mr. Speaker : Will the hon. Member please take his seat. I am so sorry, I have already admitted the Call Attention Motion. Let Comrade Tarsikka read it.

ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ * * * * * * *

* * * *

ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇਨਕਆਇਰੀ ਕਰਵਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

Mr. Speaker: Please take your seat.

ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਮਰਡਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤਕ ਬਾਵਜੂਦ ਉਥੇ ਦੇ ਐਸ. ਪੀ. ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਮਜ਼ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜੇਕਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । (ਵਿਘਨ)

CALL ATTENTION NOTICES

Mr. Speaker : Comrade Tarsikka, will you please read your Call Attention motion ?

(Call Attention Notice No. 117)

Comrade Makhan Singh Tarsikka : I beg to draw the attention of the Minister concerned to the fact that four persons were brutally murdered in a bus near village Kheri Shuraf Ali P.S. Rajaund, District Karnal on 26th October, 1965, in a broad daylight. They were dragged out from the bus and more bullet shots were given to them till they were dead. Six persons alleged to be assassins have been arrested. Now due to the political pressure of a local M.L.A. the case is being damaged and efforts are being made to save some of the murderers. One of the accused namely Gurbux Singh was recently tried for a murder and during the trial his pistol licence was not cancelled, due to political influence. Law and order situation in the State has deteriorated. It is prayed that this case be treated at high level and Minister concerned requested to make a statement ensuring fair investigation.

Mr. Speaker : This is admitted.

---

*Note: Expunged under the orders of the hon. Speaker.

Shri Prabodh Chandra (Education Minister) : Sir, this case is likely to come before the court very soon. Investigations are progressing very vigorously. If at this stage any statement is made, it is likely to prejudice the proceedings in the court.

Mr. Speaker : I have admitted this Motion because the hon. Member has only made a request that there should be some high level investigations.

Education Minister : Sir, the investigations are being made at the highest level. Not only it is being investigated by the district police authorities but other officers from the adjoining district and even from the headquarters are being associated with this enquiry. I can assure the hon. Members that Government is no way interested in giving shelter to the culprits. It is in our own interest that the culprits are apprehended as early as possible.

Mr. Speaker : This is right.

Sardar Gurdarshan Singh : Mr. Speaker, you were pleased to remark that 'this motion is admitted'. Now the hon Education Minister has tried to argue that motion should not be admitted. I would like to know whether this motion has been admitted or not ?

Mr. Speaker : Motion has been admitted and the statement has already been made by the hon. Minister.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ । ਮੇਰਾ ਪਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕਾਲ ਅਟੈਨਸ਼ਨ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਨਿਸਟਰ ਵਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੁਣ ਆਈ ਹੈ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸੰਗੀਨ ਅਤੇ ਸੀਰੀਅਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ?

Mr. Speaker : Please take your seat. It is for the Government to decide as to what statement they are to make. I cannot force the Government to make a particular statement.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਜਨਾਬ ਇਸ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੰਗੀਨ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਕਾਲ ਅਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਹੈ ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੰਡਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਫੇਟ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਸ ਮੋਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ।

(The hon. Member is a seasoned member of this House. This matter is under investi gation and only after the completion of the investigation it can be ascertained as to what the real facts are and what would be its fate. A request was made through this motion that a high level enquiry should be held. A reply from the Government has come that a high level enquiry is being conducted and that no political pressure is being exercised.)

Sardar Gurdarshan Singh :—Sir, my submission is that this is a very important Call attention Motion because in the broad day light 4 persons have been murdered, This speaks of the law and order situation prevailing in the State. The motion should be admitted and it should be replied by the Home Minister who is incharge of the law and order situation.

Mr. Speaker : No, please.

कामरेड राम प्यारा : करनाल में जितने मर्डर हुए हैं उनमें मज़लूमों की कहानी और है और पुलिस और कातलों की स्टोरी और है। हालत यह है कि हाई कोर्ट ने जिला की पुलिस के खिलाफ आबज़र्वेशन्ज़ दी हैं कि पुलिस के अफसर जिला में इन्साफ नहीं देखना चाहते।

Mr. Speaker : Please take your seat.

कामरेड राम प्यारा जिला अफसर ज़ालमों को सजा देने के लिये तैयार नहीं। इस लिये मेरी तो इलतमास है कि होम मिनिस्टर इसके बारे में पूरी स्टेटमेंट दें नहीं तो यही समझा जायगा कि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि ज़ालमों को सज़ा दी जाए।

Mr. Speaker : The hon. Member may please take his seat. Next Call Attention Motion is by Giani Zail Singh.

Giani Zail Singh : I beg to draw the attention of the Minister concerned to the matter regarding unnecessary delay in the location and starting of Biscuit Factory at Patiala which was duly approved and recommended by the Director of Industries, Punjab Government vide his letter No. LMI/2157/Lic/65/16677, dated the 11th May, 1965, to the Central Government for registration with the Development Wing, after which the management of the said Biscuit Factory invested more than Rs. twelve lacs for the construction of the building and installation of the plant. In view of the question of the location of the Biscuit Factory at Patiala having been already approved by the Punjab Government, what is the hitch in conveying fresh concurrence of the Punjab Government as desired by the Central. Government. Delay in conveying fresh concurrence causing unnecessary harassment and pecuniary loss to the management which is contemplating going for production by middle of November, 1965. To allay the apprehensions of the people of this region which require immediate attention of the Government.

Mr. Speaker : This is admitted.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ । ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਰਲਿੰਗ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਕਾਲ ਅਟੈਨਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਲਫਜ਼ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਐਨੇ ਐਨੇ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਰੁਸਤ ਸਮਝੋਗੇ ?

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਤਅੱਲੁਕ ਹੈ ਜੇਕਰ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਥੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਐਨੇ ਐਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲਫਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ? (If any hon. Member reads his motion in the language which has been approved by the House he is permitted to do so. The words Aine Aine are Punjabi words and every hon. Member has got the point. Has the hon. Member not understood this expression ?)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਕੀ ਕਹਿ ਗਏ ਹਨ । ਐਨੇ ਐਨੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੀ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ।

Mr. Speaker: Please take your seat.

मुख्य मन्त्री : बिस्कुट फैक्टरी के मुतालिक जो सवाल उठाया गया है, यह सवाल अभी इंडस्टरी डिपार्टमेंट के ज़ेरे गौर है, इस के मुतालिक हमसे गवर्नमेंट आफ इंडिया ने भी इनफरमेशन मांगी है, अभी हम इस के मुतातिलक डेटा कुलैक्ट कर रहे हैं। अभी कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई आखरी फैसला किया गया हो ।

ज्ञानी जैल सिंह: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। मैं यह जानना चहता हूँ कि एक बिस्कुट फैक्टरी डालमियां की..................

श्री अध्यक्ष : आपकी मोशन ऐडमिट हो चुकी है अब इस पर बहस नहीं हो सकती। (The call Attention Notice has already been admitted. It cannot be discussed now.)

The next Call Attention Notice (No. 120) stands in the name of Comrade Makhan Singh Tarsikka.

Comrade Makhan Singh Tarsikka : Sir, I beg to draw the attention of the Minister concerned towards the miserable condition of 10 Lakhs Dhodis families in the State due to restrictions imposed on them to sell milk to only Government controlled and sponsored dairies in the State.

(1) Government dairies paying to Dhodis Rs. 24 per maund but the rate of milk in the bazar is Rs. 36/- per maund.

(2) Verka Milk Plant is supplying milk for defence purposes at Rs. 150/- per quintal and pays to Dhodis only Rs. 60/- per quintal,

(3) Moreover, due to ban on private dairies from 7th September 1965 more than 10 thousands dairies in the State (privately owned) are ruined thus they are on semi-starvation nowadays.

(4) Dodhis used to sell their milk to private dairies before 7th September for Rs. 32/- per maund and now they are getting only Rs. 24/- per maund.

Thus this loot concerns the lakhs of village peasants. therefore, must be discussed.

Mr. Speaker : This is admitted.

मुख्य मन्त्री स्पीकर साहिब, ऐमरजेंसी के वक्त हमें जवानों के लिये दूध की जरूरत थी। हमने यह दूध मिलटरी के जवानों को देना था । अगर बाहर से मंगवाते तो हमारा बहुत सा रुपया ऐक्सचेंज पर लग जाना था । इसलिये सारी बातों को सोच कर ही ऐसा किया गया है। मैं समझता हूँ हाउस इसे एपरीशियेट करेगा।

Mr. Speaker : The next Call Attention Notice is from the hon. Leader of the Opposition Sardar Gurnam Singh,

(He was not present in his seat.)

Mr. Speaker : I call upon Sardar Kulbir Singh because the next motion has been given notice of by him.

Sardar Kulbir Singh, : Sir I beg to draw the attention of the Minister concered towards the fact, namely, that people of Ferozepur and Ferozepur Cantt, Guruharshai, Jalalabad and Fazilka have suffered to the maximum due to the Pak aggression, bombing, shelling gun-firing and actually being near the battle field. People of the area proved their moral guts by being carrying on their business and stuck to their places. As is known that these towns were virtually uprooted and all business suffered heavily beyond calculation. Government attention is drawn towards this negligence as the Government has not provided the businessmen by granting them loans just to recuprate the business. The Government should treat the businessman as treating the Industrialists of the Border Districts.

Mr. Speaker : This is admitted.

मुख्य मन्त्री: यह बात हाउस में एक बार नहीं बल्कि कई बार दोहराई गई है कि जो भी भाई डिसलोकेट हुए हैं उनको 1,000 से लेकर 5,000 तक का लोन दिया जायेगा, मगर अभी तक हमारे पास कोई एप्लीकेशन नहीं आई। हमारे तरफ से कोई डिले नहीं है। मैं इस बात का आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर मैंबर साहिबान किसी तरह की कोई तकलीफ हमारे नोटिस में लायेंगे तो हम उसको पूरी तरह से हल करेंगे । इस तरह से बार बार इस तरह का सवाल उठाना मुनासिब मालूम नहीं देता। इससे उलझनें घटने की बजाय बढ़ती हैं।

Mr. Speaker : Comrade Bhan Singh Bhaura.

Comrade Bhan Singh Bhaura, : Sir, I beg to draw the attention of the Minister concerned to the matter regarding fifty Harijan families who had been settled by the Government on reclaimed land of Dhano Bir near Malerkotla district Sangrur five years ago. There is one tube well owned by a land lord of Malerkotla in that land. Now the land lord locked the tube-well a few days back. The poor Harijans approached Tehsil and District authorities but no action has been taken so far. The sowing season is in full swing and the poor Harijans are wandering hither and thither. If the Government does not take immediate steps these fifty Harijan families would be ruined, I request the Governmen to take this matter seriously.

Mr. Speaker : This is addmitted.

Chief Parliamentary Secretary (Shri Ram Partap Garg) : Sir, we will look into the matter. We will take necessary action.

Mr. Speaker : It will be better if the Government will make a statement after looking into the matter.

Chief Parliamentary Secretary : It has not been brought to our notice.

Mr. Speaker : The matter may be reported to the House after taking the necessary action.

The next Call Attention Notice (No. 124) is from Sarvshri Ajit Kumar and Net Ram.

(Both the hon. Members were not present in their seats).

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਇਕ ਕਾਲ ਅਟੈਨਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨ ਸੀ । ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਵਰ ਦੇ ਖ਼ਿਆਲ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ । ਮੈਂ ਇਹ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ।

Sardar Gurnam Singh : Sir, I beg to draw the attention of the Government towards the leading article of daily Pardeep of 3. 11. 65 in which it has been stated that if the Punjab i Suba is formed Indian Government will have to keep its armies in Punjab as it is doing in Kashmir.

This is very serious article in which aspersions have been cast on the Punjabi people and the Kashmiri people.

Serious action against such anti-national propaganda be taken immediately.

Mr. Speaker : This is admitted.

मुख्य मन्त्री : स्पीकर साहिब, मेरी आपसे और आपके ज़रिये मैंबर साहिबान से दरखास्त है कि जहां तक अखबारात में खबरें छपने का सवाल है मौजूदा डैमोक्रेसी के अंदर हर शख्स को फरीडम आफ स्पीच है, फरीडम आफ तहरीर और तकरीर है। ऐसे मौका पर हमें आपसी तालुकात को बेहतर बनाने का सबूत देना चाहिए। पंजाबी

सूबा बने या न बने इस बात के लिये एक अलग कमेटी बनी हुई है जिसके सामने यह सवाल आयेगा इसमें हर शख्स को अपने विचार रखने का हक हासिल है? पंजाब में मुख्तलिफ अखबारात हैं कोई किसी के हक में है और कोई किसी के खिलाफ हैं। इस मुआमले के मुताल्लिक जैसे मैंने पहले हाउस को यकीन दिलाया था कि हम इस मुआमला पर अभी गौर कर रहे हैं कि इस पर कैसे ऐक्शन लिया जाये, यह एक प्रोसीजरल मैटर है मौजूदा हालात में इस सवाल का उठाना ठीक न होगा। हम एल. आर. से पूछ कर मज़ीद कारवाई करेंगे। हमें पंजाब के लोगों की खाहिश का पूरी तरह से एहतराम है।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਕਾਲ ਅਟੈਨਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਛੇੜ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਵੇਖਣ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮੈਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਬੇਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖਾਹ ਮਖਾਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਫੋਬੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। Panjabi Suba has absolutely nothing to do with it.

STATEMENTS LAID ON THE TABLE BY THE CHIEF PARLIAMENTARY SECRETARY

Shri Ram Partap Garg (Chief Parliamentary Secretary). Sir, I beg to lay on the Table of the House statements in reply to Call Attention Motions—

1. Nos. 69 and 82 regarding purchase by Government of rice and not of paddy;
2. No. 90 regarding weir area of Ferozepore Headworks; and
3. No. 107 regarding utilisation of open spaces at Chandigarh and other places for achieving self-sufficiency in food.

CALL ATTENTION MOTION NOTICES

Sardar Gurbakash Singh Gurdaspuri :—To draw the attention of the Minister concerned to the fact that the Government purchases only rice and not the paddy and the paddy is to be purchased by the traders for whom he minimum price is fixed provided the moisture is not more than 14%. There is no proper method to guage the percentage of moisture. The Government should devise a method for guaging the moisture and to mark it on every bushel of each producer exposed for sale in the market. The harvesting season is in full swing and is likely to finish in a month. Hence this method should be devised at once.

Statement by Comrade Ram Kishan, Chief Minister, Punjab.

At present, the Food and Supplies Department have provided one moisture testing machine in each of the important paddy producing districts. The Officers of this Department have held a number of demonstrations in the mandis, for determination of the moisture content in paddy, with these machines.

A number of samples of paddy were drawn from the heaps lying in the mandis. In most of the cases, the price being paid by the traders was somewhat higher than the guaranteed minimum price. Since the number of moisture testing machines is limited, it is not possible to check the moisture content of each bushel of a producer, as there is a very large number of heaps of paddy. In some of the mandis, the arrivals sometimes exceed 10,000 bags a day and it cannot be practicable at all to mark the moisture content of each bushel, lying in the market.

[Chief Parliamentary Secretary]

In Amritsar, however, moisture testing machine has been fixed up in the local mandi and an Officer posted to test check the content of paddy as also the price paid for paddy, for the satisfaction of the growers.

3. The Government have also directed the District Officers to enter into the market and purchase paddy as soon as there is a tendency for the prices to fall below the minimum guaranteed prices, subject to the specifications laid down by the Government of India, in this behalf.

4. So far, over 6,000 quintals of paddy have been purchased under the price-support scheme.

STATEMENT IN CONNECTION WITH CALL ATTENTION NOTICE No. 90 GIVEN BY SARDAR KULBIR SINGH, M.L.A. REGARDING WIRE LAND RELEASED BY THE INDO-PAKISTAN TREATY ETC.

As a result of the Ihdo Pak Border Agreement of 1960, the Weir area of Ferozepur Headworks which was in adverse possesion of Pakistan, came to India in January, 1961. It measures approximately 3,645 acres and originally belonged to the Irrigation Department.

2. The Weir area is subject to flooding during the rainy season, and consequently unfit for permanent allotment. In consultation with the Irrigation Department, it was, therefore, decided that this area should be leased out by the Deputy Commissioner for temporary cultivation, for 10 years, on a nominal rent of Re 1 per acre per year. The Irrigation Department, however, desired that the lease money on collection should be credited to the Irrigation Department and also that leases should be subject to the condition that the Irrigation Department would be free to construct any river works within the said area such as Bunds, spurs etc., and to do annual survey operations thereon without any let or hinderance by lessees. Accordingly, the land in the Wier area has been leased out by the Deputy Commissioner to Rai Sikhs and other Border oustees for 10 years. The settlers on this land were given reclamation grant, wherever warranted. It is evident that the Deputy Commissioner, Ferozepur was/is managing the Weir area land on behalf of the Irrigation Department.

3. Subsequently, a question arose as to whether the possession of the Wire area land and its management should remain with the Deputy Commissioner or the Irrigation Department should be asked to look after it themselves. Government in the Revenue Department decided in July, 1963, that the possession of the Weir area in the Ferozepore district be given over to the Irrigation Department, subject to the following conditions:—

(i) That the Irrigation Department would honour the leases already given by the Deputy Commissioner, Ferozepore;

(ii) that they would lease out the remaining area, if any, on the same terms and conditions on which it had been leased out previously ;

(iii) that this area would be leased out to the Border oustees in consultation/ on the recommendation of the Deputy Commissioner, Ferozepur, who was in the best position to know as to who were the deserving oustees.

As a matter of fact, the Irrigation Department has agreed to the leasing out of this area on the terms and conditions on which it had already been leased out by the Deputy Commissioner, Ferozepore. The Irrigation Department was informed accordingly and they were requested to contact the Deputy Commissioner for the return of the possession of this area. They Deputy Commissioner, Ferozepore at the same time was also asked to comply with these orders as soon as the Irrigation Department approached him in this behalf. The Deputy Commissioner has stated that the Irrigation Department has not approached him in the matter so far. There is no dispute about this issue at all and as and when the Irrigation Department approaches the Deputy Commissioner, the needful would be done. As a matter of fact, major portion of the Weir area is already on lease with Rai Sikhs and the Border oustees for agricultural purposes . Only the area under river bed or spurs or which is sandy could not be leased. Consequently at this stage the return of the possession and management of this land to the Irrigation Department would consitute only a mere formality on papers and nothing else.

CALL ATTENTION MOTION NO. 107 MOVED BY SHRI BALRAMJI DASS TANDON, M. L. A., REGARDING UTILISATION OF OPEN SPACES AT CHANDIGARH AND OTHER PLACES FOR ACHIEVING SELF SUFFICIENCY IN FOOD

The question of utilisation of open spaces in Chandigarh has recently been considered by Government and an area of 107 acres out of that to be landscaped has been proposed to be taken up for cultivation of vegetables/food crops, It lies in Sector 7, 16 and 30 and is proposed to be irrigated by accelerating the existing programme of constructing hydrants in these areas. 388 acres were leased out on 3 to 5 years lease some months back for growing crops instead of grazing. Owners of Government and private houses can utilise the lawns and open spaces in their houses for growing vegetables and areas adjoining their houses in the back side can also be leased out for vegetable growing. The Department of Agriculture is running a scheme of 'kitchen gardening' in Chandigarh under which technical guidance and spraying against pests and diseases is given free. The Department of Agriculture has also taken up the question of providing good quality manure in sufficient quantity to residents of Chandigarh,

As regards lands outside Chandigarh, the Deputy Commissioners have been asked to issue immediate notices to owners of vacant lands outside municipal areas that they should put it under crops in the next harvest otherwise it will be acquired under the Utilisation of Lands Act. In municipal areas the Local Bodies have been requested to have the vacant areas surveyed with a view to putting these under crops.

PERSONAL EXPLANATION BY COMRADE MAKHAN SINGH TARSIKKA

ਕਾਮਰੇਡ ਮਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ (ਜੰਡਿਆਲਾ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ 24 ਫਰਵਰੀ, 1965 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰ ਸਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਮਾਲਮ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਕੋਰੇ ਗ਼ਲਤ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਇਥੋਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਤਰਸਿੱਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਚਾਈਨੀਜ਼ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ 'ਤੇ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ, ਗ਼ਦਾਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ.....

ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਵਿਚ ਰਤੀ ਭਰ ਵੀ ਸਚਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਸੀਂ ਚੌਰਾਹੇ ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਹਾਡੀ ਵਸਾਤਤ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਬਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਰਡਿਕਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ......

"Makhan Singh Tarsikka is a patriot having in his record more than 14 years'detention and imprisonment fighting for National Independence during British regime and well being of the people."

This fact has been admitted by the State Government.

ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਰਡਿਕਟ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਬੇਸਲੈਸ ਹਨ, ਅਤੇ ਫੈਬਰੀਕੇਟਿਡ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਇਹ ਚਾਰਜ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਹੱਤਕ ਕੀਤੀ ਹੈ।

[ਕਾਮਰੇਡ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ]

ਪਿਛਲੀ ਬਾਰ ਜਦ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਸਨ ਕਿ ਇਸਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋ—ਚਾਈਨਾ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਤਰਸਿਕਾ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਨੇਸ਼ਨਲਿਸਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਗ਼ਲਤ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਕਾਮਰੇਡ ਤਰਸਿਕਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟ੍ਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ : ਹੁਣ ਐਕਸ—ਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । (Addressing Comrade Tarsikka) (Hon. Member's contradiction has come. His explanation is getting very long.) (Interruptions)

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਸਟਰ ਤਰਸਿਕਾ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਡਿਟੈਨਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਕਾਮਰੇਡ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਦਫਾ ਜਦੋਂ; ਮੈਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਚਾਈਨੀਜ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ । ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਕ ਪੋਸਟਰ ਕੱਢਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਮੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗ਼ਲਤ ਸਨ । 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਚੰਦਰ ਜੀ ਸਪੀਕਰ ਸਨ, ਮੈਂ ਕਾਮਰੇਡ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਉਹ ਝੂਠੇ ਹਨ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਚਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਉ । ਇਹ ਲੈਟਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ । ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਛ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਡੈਮ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਚਿਠੀ ਲਿਖੀ ਔਰ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ । ਜਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਦਾਖਿਲ ਹੋਏ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਮੈਂ ਇਨਫਿਲਟਰੇਟਰਜ਼ ਦੀ ਨਿਖੇਦੀ ਕੀਤੀ, ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਅਟੁਟ ਅੰਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਉ, ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਸਿਕਮ ਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਚਿਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਚਾਇਨਾ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਤਹਿਰੀਕ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਜਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਕ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਟ੍ਰੈਚਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਉ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਫਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਾਫ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਚਾਇਨਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ਤਰੂ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡਾ ਸ਼ਤਰੂ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ । ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਵਲ ਫਰਜ਼ ਹੈ । ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਖਿਆ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ , ਕੋਈ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਸਾਡਾ ਸ਼ਤਰੂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚਾਇਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਰ ਹਮਲਾਵਰ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਨ ਹੈ ।

ਇਹ ਤਾਂ ਹਨ ਸਾਡੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਜਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਸ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੇ ਹਨ । ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਰਡਿਕਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ, ਝੂਠੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਵਰ ਸੀ.....

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ । ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਐਡ-ਵਾਈਜਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕਐਸਚਨ ਆਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । (The hon. Member gets up every time to speak. This is not proper. According to the report of the Business Advisory Committee the Question Hour has been dispensed with for today.)

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਜੰਡੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਵਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਲ ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ.....

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ, ਅਜੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਐਸਾ ਮੇਰਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ । ਬਿਜਨੈਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 10 ਵਜੇ ਫਿਰ ਬੁਲਾਈ ਹੈ; ਸ਼ਾਇਦ ਸੈਸ਼ਨ ਚਲੇਗਾ ਔਰ ਤਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ । (Addressing Babu Ajit Kumar) The whole of the business has not been completed yet. The meeting of the Business Advisory Committee has again been called for today at 10 a.m. It is possible that the Session will be extended further and the hon. Member will get opprtunity to speak on the subject.)

RESOLUTION RE. WITHDRAWAL OF INDIA FROM THE COMMONWEALTH

Comrade Shamsher Singh Josh (Rupar) : Sir, I beg to move—

> That this House recommends to the Government to draw the attention of the Union Government to the general feeling among the people of the State that in view of the anti-Indian role of the British Government in the recent Indo-Pakistan conflict, India should quit the Commonwealth.

ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਨਾਹਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਰਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਇਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਪਾਰਟੈਂਸ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ । ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੇਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੀ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਲੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਫਲ ਸਰੂਪ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਨੇਸ਼ਨਲ ਨਾਹਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਐਂਗਲੋ ਅਮਰੀਕਨ ਬਲਾਕ ਨੇ ਜੋ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨੇਸ਼ਨਲ ਇੰਟ੍ਰਸਟ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ।

(ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼)

ਅਜ ਹਿਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ it has become a slogan of dire necessity and it has become a necessity for our country at this moment.

ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੋ ਚਾਰ ਸਾਲ ਇਹ ਐਂਗਲੋ ਅਮਰੀਕਨ ਬਲਾਕ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਹੀ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ । ਪਰ ਸੰਨ 1952-53 ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੈਰੂਨੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਖੇੜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਫਾਰਿਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਦੋ ਪਲੈਂਕ ਬਣਾਏ ਇਕ ਨਾਨ ਐਲਾਈਨਮੈਂਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨੀਤੀ ਰਖੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧੜੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਅਮਨ ਦਾ ਕਾਜ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਲਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਆਂਗੇ, । ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇਕ ਕਲੈਸ਼ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਚਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਕਨਾਮਿਕ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਲਕ ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਾਂਗੇ । ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਡੀਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਮੁਲਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰਖਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਲਕ ਨੂੰ ਰਾ ਮਟਰੀਅਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਏਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹਣ ਦਿਤੀ । ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਕਵਰਡ ਸੀ । ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਸੀ । (At this stage the Deputy Speaker entered the Chamber and there were cheers.)

ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਮਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰਕੀ ਅਤੇ ਨਾਨ ਐਲਾਈਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ । ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਮਨ ਵੈਲਥ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਨ ਐਲਾਈਨਡ ਹਾਂ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਕਿਸੇ ਗੁਟ ਨਾਲ ਬਝੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ । ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਬਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਮੰਬਰ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ।

Shri Mohan Lal : On a point of Order, Mr. Speaker. My point of order is that while speaking on this resolution we will not be within our rights to criticise the foreign policy which is the subject matter of the Union Government and not the State Government.

I can believe that a reference can undoubtedly be made to the policy factually, as it is. But to pass aspersions directly or indirectly in relation to the foreign policy would be thoroughly outside our jurisdiction and irrelevant.

I would therefore, request you, Mr. Speaker, to restrain any hon. Member from making adverse comments on our foreign policy when he trespasses while making a factual reference thereto.

Comrade Ram Chandra : Mr. Speaker, I differ from the sentiments expressed by my hon. Friend, Shri Mohan Lal in this regard. Once this question or resolution has been admitted, permission has been given to say whatever we like. I may or may not support the resolution in its present form and that would be quite a different thing. Therefore, I would suggest that the opportunity given to the hon. Members to speak out their mind should not be curbed.

Mr. Speaker : The hon. Members will see working of the resolution, which refers to the feelings of the people of our country in view of certain facts. But I do agree with Shri Mohan Lal that it does not lie within our jurisdiction to make any adverse comments on the foreign policy. Of course the hon. Members can make references to the current foreign policy and lay emphasis on their views without adversly commenting on the foreign policy.

ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਤਅਲੁਕ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫਰੀਲੀ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਐਕਸਪਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਨੋ ਕਮੈਂਟਸ ਪਲੀਜ਼ । (Addressing Sardar Kulbir Singh) : (I have made my observation. No comments please.)

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਸਦਾ ਹਾਂ In relation to commonwealth we have decided certain path of non-alignment.

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਕਾਮਰੇਡ ਜੋਸ਼, ਕਮੈਂਟ ਐਵਾਇਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਕਹਿ ਦਿਉ । (Comrade Josh may please have his say by avoiding any comments on it.)

Comrade Shamsher Singh Josh: I am speaking. It is part of my speech on the Resolution. ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਚਲਣਾ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਾਂ । ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਡੇ ਵਰੀ ਅਯੂਬ ਦੇ ਡਿਕਟੇਟਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ । ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ੋਲਿਸ਼ਉਨ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਫ ਕਰੇਗਾ । ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਏਗਾ । ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ।

मुख्य मन्त्री : स्पीकर साहिब, मैं आपके जरिये हाउस से यह दरखास्त करना चाहता हूँ कि हमारे देश की जो फारिन पालिसी है, वह किसी एक पार्टी की पालिसी

(मुख्य मन्त्री)

नहीं है। वह इंट्रनेशनल फारिन पालिसी है। उसके मुताबिक पार्लियामेंट वकतन फवकतन उसको मन्जूर करती है। जहां तक मैंबरान के अपने व्यूज का ताल्लुक है, कोई सैंटीमेंट है तो इस बात को मद्दे नजर रखा जाए कि ऐसी बात न कही जाए जिससे नैशनल फारिन पालिसी पर डाइरैक्टली या इन्डाइरैक्टली कोई हरफ आये। जहा तक सारे देश के सैंटीमेंट का ताल्लुक है उसके बारे में कहना हरेक भाई को हक है। तमाम मैंबरान अपनी तकरीरें करते हुए, अपने विचारें धारा पेश करते हुए इस बात को पूरी तरह मद्दे-नजर रखें कि कोई ऐसी बात न कही जाए जिससे हमारे देश की नेशनल सेल्फ रिस्पैक्ट को धक्का लगे जिसे सारे हिन्दुस्तान का नेशाल पालिसी जो इत्तफाक राए से पास हुई है उसे डाइरेक्टली या इन्डाइरैक्टली नुकसान पहुंचने की तववको हो।

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਕਨਾਮਿਕ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ । ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈਲਫ ਰਿਲਾਇੰਟ, ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੈਂਟ ਅਤੇ ਸੈਲਫ ਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੰਟਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਮਾਨ ਭਰਿਆ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ । ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਕਨਾਮਿਕ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਐਂਗਲੋ ਅਮੈਰਿਕਨ ਬਲਾਕ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ । ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਦੇਣੀ ਪਈ । ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਬਣਾਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਅਸੇ ਸਨ, ਸਮੰਦਰੀ ਬੇੜੇ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਹੋਈ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ । ਇਹ ਕਾਰਨ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ । ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ । ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸੀ ਚਾਲ ਚਲੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਨਾਂ ਹੋਣ ਦੇਈਏ, ਆਰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਕੜਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਈਏ । ਜਾਣ ਲਗਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੋ ਨਵੇਂ ਮੁਲਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਖਿਆ ਇਕਨਾਮਿਕ ਐਕਸਪਲਾਇਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਮਨਾਪੋਲਿਟਸਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰਖੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕਨਾਮਿਕ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ । ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਸਬੂਤ ਹਨ । ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਣ ਲਗਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ :

(At this stage Deputy Speaker occupied the Chair)

ਇਹ ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇਨਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਕ-ਨਾਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਤਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸਦਾ ਦੰਦਾਂਸ਼ਿਕਨ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਤ ਹੋਈ । ਇਸ ਜਿਤ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਹਾਦਰ ਆਰਮੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਹੈ ਉਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਕਾਨਮੀ ਸਟੈਬਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਆਰਮਾਮੈਂਟਸ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਬਣਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ।

ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਹਾਂ ਐਂਗਲੋ ਅਮਰੀਕਨ ਬਲਾਕ ਇਹ ਸਿਰ ਤੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਡਿਵੈਲਪ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮਿਸਾਲਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਹਨ ਪਰ ਮੈਂ ਇਕ ਹੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਆਪਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਲੋਹੇ ਦੀ ਹੈਵੀ ਇਨਡਸਟਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਿਆ ਦੇ ਬਣਾਇਆ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਰ ਹੈਵੀ ਇਨਡਸਟਰੀ ਲਈ ਇਮਦਾਦ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਜਦ ਰੂਸ ਨੇ ਭਿਲਾਈ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤੇ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਗਲੇ ਭਗਤਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁਲ੍ਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਦੇਸ਼ ਰੂਸ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਂਗਲੋ ਅਮਰੀਕਨ ਬਲਾਕ ਸਾਨੂੰ ਕਦਾਚਿਤ ਡਿਵੈਲਪ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਨਾਮੀਕਲੀ ਐਕਸਪਲਾਇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਤੌਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰੂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਰਗਾਪੁਰ ਵਿਚ ਕਾਰਖਾਨਾ ਲਗਾ ਦੇਣਗੇ, ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਵੀ ਰੂੜਕੇਲਾ ਵਿਚ ਲਗਾਣ ਦਾ ਵਾਹਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੁਖਾਰੋ ਵਿਚ ਸਟੀਲ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਲਗਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਵਾਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰੂਸ ਨੇ ਉਥੇ ਲਈ ਵੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਇਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਯੁਗ ਵਿਚ ਸਟੀਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਟੀਲ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਲਗਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਪਰਾਜੈਕਟਸ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਂਗਲੋ ਅਮਰੀਕਨ ਬਲਾਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁਜਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜੋ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਆਫ ਦੀ ਵਰਲਡ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਮਨਾਪਲਿਸਟ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਅਖਬਾਰ ਜੋ ਇਕ ਵਡਾ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ :

"Britain and the United States are not keen that India should become self-sufficient in regard to the establishment of four ordinance factories for which they promised assistance nearly two years ago".

The Khetri copper project, alloy steel project, the zinc smelter project, the expansion of cooking coal producing mines—all these critical areas—the imperialist policy has been nothing short of deliberate sabotage".

ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕਨਾਮੀਕਲੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਰਜ ਵੀ ਲਗਾਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਇਨਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਕਨਾਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੈਬਟਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਜਦ ਕਿ ਕਾਮਨ ਵੈਲਥ ਸਾਡਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਉਸ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਣ ਦਾ

[ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼]

ਜਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚੇ ਕਿ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ । ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ : it is one of the unfulfilled pledges that our national leaders took.

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਆਪਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ 1928 ਵਿਚ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਦਇਨ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਡੂਮੀਨੀਅਨ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅਦਰ ਅੰਦਰ ਯਾਨੀ 1929 ਵਿਚ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੇ ਪਲੈਜ ਲਈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਮਨ ਵੈਲਥ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਰਖਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂਗੇ । ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਇਹ ਚਾਰਜ ਲਗਾਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਕੌਮੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਲੈਜਜ਼ ਲਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਪਲੈਜ ਸੀ ਕਾਮਨ ਵੈਲਥ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੋ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ......

पंडित मोहन लाल : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। अभी अभी जो मैंबर साहिब बोल रहे थे उन्होंने यह बात कही है कि वह नैशनल लीडरशिप पर यह चार्ज लगाते हैं। इससे पहले भी उन्होंने यही बात कही थी । मैंने यह बात पहले भी आपके ध्यान में लाई थी कि नैशनल पालिसी गवर्नमेंट आफ इण्डिया के स्कोप में आती है और उसको हम यहां डायरेक्टली या इन्डायरेक्टली डिसकस नहीं कर सकते। अब फिर मैं यह कहना चाहता हूँ कि मैम्बर साहिब जो बात हमारे विधान सभा के स्कोप में न हो उसे ज़ेरे बहस नहीं ले सकते। इसलिये मैं अर्ज करता हूँ कि यह जो इनके रिमार्क्स हैं। This should be expunged from the proceedings.

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ । ਪੰਡਤ ਜੀ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕੌਮੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲੀ ਤਾਂ ਇਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਲਿਸੀ ਐਡਾਪਟ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਜੇਕਰ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਚਲਣ ਵਿਚ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਤਾਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ?

उपाध्यक्षा : देखिए, जो बात भी यहां कही जाती है उसके एक एक नुक्ता को सारी दुनिया के लोग देखते हैं। मैं अभी बाहर से आ रही हूँ और जो कुछ मैंने वहां देखा उससे बड़ा ताज्जुब हूआ । मैं दोनों तरफ से कहना चाहती हूँ कि मुनासिब होगा अगर वह ज़रा पाबंदी से बोलेंगे क्योंकि देश इस वक्त बड़े नाज़क दौर से गुज़र रहा है ।

(The hon. Members should know that whatever they say here is heard and watched by the whole of the world outside. I have just come back from abroad and what I saw there surprised me. I appeal to both sides of the House that they should speak with some restraint because our Country is passing through a very critical period.)

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਵਧਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ । ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜੋ ਕੌਮੀ ਪਲੈਜ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ 16/17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ......

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਪਾਰਟ ਐਂਡ ਪਾਰਸਲ ਆਫ ਦਿਸ ਕੰਟਰੀ । ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਆਉ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ । (I would advise the hon. Member to always consider himself as part and parcel of this country. It would be better if he avoids discussing the national leadership. He should rather state what we should do and what should not do under the circumstances and how we can maintain our liberty.)

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਟਿਕਟ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਵਰਗੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰ ਤੋੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਤ ਕੇ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹਾਂ (ਵਿਘਨ) ਉਸ ਵਕਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ......(ਸ਼ੋਰ) ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਵਿਊ ਇਥੇ ਰਖਾਂ......

ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਹਨ ਲਾਲ : ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੋਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਜੋ ਸਕੋਪ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦਾ ਹੈ......

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਪੰਡਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਦਾਨਾ ਆਦਮੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਗੈਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਜੋਸ਼ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਕੋਪ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ । ਇਧਰ ਉਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ । (The hon. Member Shri Mohan Lal is an old parliamentarian but still he has started speaking without permission. I would request Comrade Shamsher Singh Josh to say only those things which come under our scope. He should not bring in extraneous matters.)

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਪੰਡਤ ਮੋਹਨ ਲਾਲ, ਐਕਸ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਟਰਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਰਿਟਿਸ਼ ਐਂਬੈਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਅੱਜ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । (ਵਿਘਨ) (ਸ਼ੋਰ)

(At this stage there was a heated exchange of words between Comrade Shamsher Singh Josh and Shri Mohan Lal which were not audible at the Reporters' table.)

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਮੈਡਮ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਹੁਣੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪੰਡਤ ਮੋਹਨ ਲਾਲ, ਐਕਸ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਕਢੀਆਂ ਹਨ ।

(ਕੁਝ ਆਵਾਜ਼ਾਂ : ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਾਲੀਆਂ ਕਢੀਆਂ ਹਨ ?)

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਫੂਲਿਸ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗਾਲੀਆਂ ਕਢੀਆਂ ਹਨ । ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਡਤ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਪੰਡਤ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਬੜੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਅਗਰ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਤਲਖੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਪੰਡਤ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਨੂੰ ਲਫਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹੋ ਤਾਂਕਿ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਚਲ ਸਕੇ ।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ (ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਾਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ) : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਮੈਡਮ। ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮਾ ਗਰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਨਿਹਾਇਤ ਕਾਬਲੇ ਅਫਸੋਸ ਹੈ । ਪੰਡਤ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਫਜ਼ ਕਹੇ ਹਨ in the legal courts these words are not considered objectionable, when you say "what you say is absurd and foolish".

(Interruptions from the Opposition) I am so near, I have heard it. On the other hand Comrade Josh has used more objectionable remarks saying "that you have been the agent of imperialism". To make such personal allegation does not behove at all in this House. So, my submission, Madam, Deputy Speaker, is that the hon. Member should be asked not to repeat such things. We are discussing a very delicate problem of the country. I do not know why this Resolution has been brought on the Agenda. It would have been better if no discussion had been allowed on this Resolution. Any way, we should make speeches keeping in view the situation of our country *vis-a-vis* the whole world and the Pakistan and India-China situation. We should not try to harm the interest of our own country. We should appeal to the good sense of the Members not to repeat such things.

उपाध्यक्षा : मैंने बाबू बचन सिंह और सरदार अजमेर सिंह के प्वायंट आफ आर्डर सुन लिये हैं। हाउस में अनपार्लियामेंटरी शब्द किसी भी आनरेबल मैंबर को बोलने नहीं चाहिए। अगर माननीय मैम्बरों ने हार्ड लफ्ज़ कहे हैं तो वह वापस ले लें। मुनासिब तो यही है कि हाउस की डिगनिटी को रखते हुए हाउस की कार्यवाही होनी चाहिए। (I have carefully listened to the points of order raised by Baboo Bachan Singh and Sardar Ajmer Singh. As a matter of fact no hon. Member in the House should use unparliamentary words or expressions and if the hon. Members concerned have used any such harsh language, they should withdraw it. It is only proper that the dignity of the House should be maintained and business transacted.)

लाला रुलिया राम : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडम। आपने माननीय मैम्बरों को लफ्ज़ वापस लेने के लिये कहा है, लफ्ज़ वापस लेने का कोई फायदा नहीं है। इसके विरुद्ध ऐक्शन लेना चाहिए।

Deputy Speaker : Kindly wind up now.

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : I have just now moved the resolution. ਮੈਂ ਇਸ ਰੈਜ਼ਲਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਆਲਾਤ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਊਸ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਰਖਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਗੌਰਮਿਟ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬੈਂਚਾਂ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਤੌਰ ਤੇ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

Deputy Speaker . The hon. Members should first withdraw the harsh words.

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਹਾਰਸ਼ ਲਫਜ਼ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕਹੇ। ਅਗਰ ਪੰਡਤ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਲਫਜ਼ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। I ignore it. ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਨਿਸਟਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ......

Deputy Speaker : Order please. I am not going to allow it.

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਤੋਂ ਸਬੰਧ ਤੋੜ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਰਵਈਆ 1947 ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਲੈ ਲਉ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ 1/3 ਹਿੱਸਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ Security Council ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਥੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ

[ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼]

ਯੂ. ਐਨ. ਓ. ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਯੂ. ਐਨ. ਓ. ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ । ਪਰ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਯੂ. ਐਨ. ਓ. ਵਿਚ ਬਦਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਸਟੈਪਸ ਉਠਾਏ ਹਨ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਨ ਕਛ ਦਾ ਝਗੜਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਝਗੜੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 3500 ਮੁਰੱਬਾ ਮੀਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹਥਿਆਣ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ । ਉਥੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਲਾਈਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ । ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ । ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਲਿਸ ਕਮੀਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਕਿ ਉਥੇ ਇਸ ਝਗੜੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਝਗੜੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮਲਕਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਝਗੜਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਅਜੇ ਇਸ ਸਮਸਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਇਨਫਿਲਟਰੇਟਰਜ਼ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ । ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਰਸਪੌਂਡੈਂਟਸ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵੈਲੀ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ । ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਅਲਾਵਾ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲਾ ਨੂੰ ਉਲਟੀ ਪੱਟੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ । ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਬਦੁਲਾ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਚੀਨ ਦੇ ਬਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਜਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਸੀ । ਕਿਉਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਟਸ ਭੇਜੇ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ । ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ । ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਹੌਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾ ਭੇਜੀਆਂ ।

ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆਂ । ਫਿਰ ਵੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵਈਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵਈਆ ਅਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਗ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕੁਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਜਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਕਈ ਵਾਰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਅਗ੍ਰੈਸਰ ਠਹਿਰਾਇਆ । ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ । ਯੂ. ਥਾਂਟ ਵੀ ਐਂਗਲੋ ਅਮਰੀਕਨ ਬਲਾਕ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ । ਔਬਜ਼ਰਵਰਜ਼ ਦੇ ਇਕ ਗਰੁਪ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦੋ ਗਰੁਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ । ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਡਿਸ-ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏ । ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੋ ਸਾਜ਼ਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ । To crown all ਹਾਲਾਤ ਇਥੋਂ ਤਕ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸਿਕਿਰਿਊਟੀ ਕੌਂਸਿਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਂਗਲੋ-ਅਮਰੀਕਨ ਬਲਾਕ ਨਾਲ ਡਾਮੀਨੇਟਿਡ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਜਦੋਂ ਭੁਟੋ ਦੀ ਬਦਕਲਾਮੀ ਦੀ

ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ as a protest ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਾਕ ਆਊਟ ਕਰ ਗਏ ਤਾਂ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਵਾਕ ਆਊਟ ਕਰ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਥਗਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ । ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੁੱਟੋ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰੇ । ਉਹ ਸੋਵੀਅਟ ਰਸ਼ੀਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਨਾ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਂਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ U.N.O. ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤਕ ਦੇ ਪੌਲੀਟੀਕਲ ਵਾਕਿਆਤ ਮੈਂ ਗਿਣ ਕੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਂਗਲੋ ਅਮਰੀਕੀ ਬਲਾਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਾਰਮ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ । Pakistan has fought with the teeth of America and Britain.

(At this stage Shri Ram Saran Chand Mital, a member of the Panel of Chairmen, occupied the Chair.)

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਹੈ । ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਨਾਲ ਆਰਮ ਪੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਟੋ ਅਤੇ ਸੈਂਟੋ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ । ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਨਫਲਿਕਟ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਮਜ਼ ਏਡ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਟਰਕੀ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਆਰਮਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜੇਕਰ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਮਜ਼ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਸੀ । ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ । ਰਣ ਕੱਛ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸਾਡੀਆਂ ਐਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਲ ਰਕਬਾ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ । ਇਹ ਰਕਬਾ ਉਸ ਨੇ ਐਂਗਲੋ-ਅਮਰੀਕਨ ਬਲਾਕ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਕਿਧਰ ਅਸਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਿਆਨਕ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ । ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਤਗੜਾ ਹੋਵੇ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਲਫ ਸਫੀਸ਼ੈਂਟ ਹੋ ਸਕੀਏ । ਚੀਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਾਰਡਰ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਇਕ ਪਾਵਰਫੁਲ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਸਕੇ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਲਕ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਖੜੇ ਸਕੀਏ । ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤਗੜਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰੂਸ ਸਭ ਤੋਂ

[ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼]

ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਅਪਨਾਇਆ ਜਾਵੇ । ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਤਲੁਕਾਤ ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਿੱਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਨਾਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੋੜ ਸਕੀਏ । ਅਜਿਹੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਅੱਜ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ ।

Mr. Chairman : You have taken enough time. Please wind up now.

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ । ਤਿੰਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਮਾਏ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਈ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਬਿਰਲੇ ਅਤੇ ਟਾਟੇ ਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਾਂਝਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਹ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਾਮਨ ਵੈਲਥ ਵਿਚ ਰਹੇ । ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਾਮਨ ਵੈਲਥ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚਲੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਪਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਉਹ ਲੋਕ ਇਹੋ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਮਨ ਵੈਲਥ ਨੂੰ ਨਾ ਛਡੋ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਰਤਾਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ਨਜ਼ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਹਿੰਦੁਸ-ਤਾਨ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਿੰਨ ਵਦੇਸ਼ੀ ਤੇਲ ਕਪਨੀਆਂ ਹਨ । ਕਾਲਟੈਕਸ ਐਸੋ, ਅਤੇ ਬਰਮਾ ਸ਼ੈਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇਲ ਮੰਹਿਗਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਡੀਫੈਂਸ ਫਾਈਟ ਨੂੰ ਸੋਬੋਟੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾ ਕਿ Every single drop of diesel oil, which was used by our planes, was Russian oil, because our army men refused even to touch British or American oil.

ਸਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇਲ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ । ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਲੇਨਜ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਤੇਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਲ ਵਿਚ ਗੰਧਕ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਿਗੜ ਗਏ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਪੈਰੇਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਏ । ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਵਾਰਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਤੇਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ that British or American oil will not be used in the defence preparations, but only Russian oil will be used.

ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਸਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦਾ ਕਾਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ । ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ

ਦੇਣ ਦੀ ਰਹੀ । ਰਸ਼ੀਅਨ ਆਇਲ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਰਖੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਸ਼ੀਅਨ ਆਇਲ ਸਾਨੂੰ ਰੁਪਏ ਬਦਲੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਤੇਲ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਪਾਊਂਡ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਰਸ਼ੀਅਨ ਖਰੀਦੀਏ ਤਾਂ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਪਾਲਿਸੀ ਬਦਲੀ । ਰਸ਼ੀਅਨ ਆਇਲ ਚੀਪਰ ਆਇਲ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਬਦਲਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ । ਐਂਗਲੋ ਅਮਰੀਕਨ ਬਲਾਕ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਡਿਸਮੈਂਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰੀਆ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀਤਨਾਮ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲੇ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ੀਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ । ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਲਗਵਾਇਆ । ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮਰੀਕਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਆਸਾਮ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਟੀ ਪਲਾਂਟਰਜ਼ ਹਨ ਇਹ ਸਭ ਫਿਜ਼ੋ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਲਈ ਸ਼ਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਫਿਜ਼ੋ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਹਾਰਾ ਹਨ । They are a source of information, source of help and source of encourgement to Phizo who is demanding the independence of Nagaland.

ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਊਸ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਦਮ ਉਠਾ ਸਕੇ ।

Shri Ram Saran Chand Mital (Chairman) : Motion moved—

That this House recommends to the Government to draw the attention of the Union Government to the general feeling among the people of the State that in view of the anti-Indian role of the Britisth Government in the recent India-Pakistan conflict, India should quit the Commonwealth.

Sardar Gurnam Singh (Raikot) : Sir, I beg to move—

1. In line 4. *between* "feeling" and "among" *insert* "of resentment".

2. In line 5, *delete* "that".

3. In lines 7-8 *for* the sign and words, "India should quit the Commonwealth" *substitute* "and requests the Union Government to convey this resentment to the British Government which is also a member of the Common-wealth".

ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਹੂਬਹੂ ਉਹੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੋਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਮਗਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚੋਂ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਮਾਕੂਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲਾਜੀਕਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋਸ਼

[ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ]

ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਇਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਐਡਾਪਟ ਕਰਨ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ । ਇਲਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ—ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਦੇ—ਸਾਡੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਇੰਟਰੈਸਟ ਫਰੀ ਲੋਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਤੋਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਥੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਜੋ ਪਾਲਿਸੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ।

ਦੂਜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਹੈ, ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਨਹੀਂ । ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਤਾਂ 40–50 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਹੈ—ਐਫਰੋ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਵਿਚ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵੀ ਇਕ ਮਲਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਬੜੀ ਸਟਰਾਂਗਲੀ, ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਔਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਂਜ ਵਿਚ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਨਾਜ਼ਕ ਕਿੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਇਨਵਾਲਵਡ ਹਨ—ਜੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਵਿਚੋਂ ਕਢਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਰਵਈਆ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸੀ । ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਮੁਲਕ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸਾਡੇ ਬਰਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ । ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਤਾਂ ਇਕ ਬਾਡੀ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 40-50 ਮੁਲਕ ਹਨ । ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਤਾ ਤੋੜੀਏ ? ਅਸੀਂ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ? ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਝਗੜੇ ਵਿਚ, ਮੌਜੂਦਾ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਰੈਸ ਨੇ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਰਹਲੇ ਤੇ ਇਕ ਪਾਰਸ਼ਲ ਐਟੀਚਡ ਲਿਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਖ ਲਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕਨਡੈਮ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਐਟੀਚੂਡ ਨੂੰ ਕਨਡੈਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੀ ਰੀਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰੀਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੂੰ ਕਨਵੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬਤੌਰ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦਾ ਇਕ ਲੀਡਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਹੋਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਪਾਰਟ ਪਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਸ਼ਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਅਗਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਤਦ ਤਾਂ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੇ ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਪਾਰਟੀਜ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾਂ ਔਰ ਮੂਵਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਕੂਲ ਹੈ, ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਛੀ ਗਲ ਹੋਵੇਗੀ ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚਿਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਜੀਕਲ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੀਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ ਯੂ. ਕੇ. ਦੀ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਗਰ ਉਸ ਬਾਡੀ ਵਿਚੋਂ ਭਜ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ 40–50 ਮੁਲਕ ਹੋਣ ਦਰੁਸਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ । ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਤਅਲੁਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਇਸ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰੈਲੇਵੈਂਸੀ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲ, ਇਸ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਿਆਂ, ਨਾ ਜਾਈਏ । ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ।

Mr. Chairman ; Motion moved—

In lines 4, *between* "feeling'' and "among" *insert* "of resentment''.

In line 5, *delete* "that."

In line 7-8 *for* the sign and words "India should quit the commonwealth" *substitute* "and requests the Union Government to convey this resentment to the British Government which is also a member of the commonwealth."

श्रीमती चन्द्रावती (खाद्य तथा प्रदाय उप मन्त्री) : चेयरमैन साहिब, यह जो कामरेड जोश ने रेज़ोल्यूशन पेश किया इस पर मैं अपने विचार रखना चाहती हूँ। हमें कामनवेल्थ में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, इस बारे में क्या निर्णय हो इस चीज़ को तो हमें अपने नेताओं पर छोड़ देना चाहिए लेकिन आज इस अवसर पर, चेयरमैन साहिब, ग्रेट ब्रिटेन का जो रवैया है मैं उसकी तस्वीर खेंचना चाहती हूँ।

सब से पहले तो मैं हमारे ऊपर जो ग्रेट ब्रिटेन का फिज़िकल असर है उसकी बात करती हूँ। सदियों से उसने हमारे ऊपर एक ऐसा असर डाला, एक ऐसी मैंटेलिटी पैदा की कि हमें एक रिएक्शनरी तरीके पर सोचने के लिये विवश किया और आज भी हम कुछ कुछ उसी तरीके से सोचते हैं। मैं यह समझती हूँ कि उस मैनटेलिटी के साथ जब तक हम किसी तरह का भी सम्बन्ध कायम रखेंगे, अपने अन्दर से उसे दूर नहीं कर सकेंगे.......(प्रशंसा) मैं समझती हूँ कि हमारे यहां, हमारे देश में एक ऐसी क्लास है जो अपने बच्चों को इंग्लैंड में पढ़ाने के लिये भेजते हैं और ऐसा करने में बड़े गौरव का अनुभव करते हैं। मैं एक मिसाल आपको देती हूँ। मुझे मिसिज़ ठिंडानी के एक लेख की याद आ गई है जो कि ट्रिब्यून में आया था। उसमें उन्होंने लिखा था कि कोई भी गोरी चमड़ी का आदमी, चाहे वह कितना ही छोटा है, हमारे मुल्क के अन्दर किसी भी बड़े से बड़े आदमी, अमीर से अमीर आदमी के मकान में चला जाए तो वहां पर उसे ड्राइंग रूम में जगह मिल जाती है, उसका वहां पर अच्छी तरह से स्वागत होता है चाहे वही आदमी बाहर जाकर हमारे देश के खिलाफ कितना ही ज़हर क्यों न उगले। इसी प्रकार उन्होंने यह भी लिखा कि जब कभी यहां पर कोई एमबैसेडर अपनी गली सड़ी चीज़ों को, अपने पहने हुए कपड़ों को फरनीचर की आर्टिकल्ज़ को

[खाद्य तथा प्रदाय उप मन्त्री]

नीलाम करता है तो उनको भी हम बड़ी खुशी से लेते हैं और इस शान से रखते हैं कि फलां एमबसेडर गया और हम ने ये चीज़ें नीलामी में खरीदीं। तो चेयरमैन साहिब, हमारे देश में एक इस किस्म की मैनटैलिटी वाली क्लास पैदा हो गई है। जब तक हम उस क्लास को नहीं मिटाते, जब तक उस मनटेलिटी को दूर नहीं किया जाता तब तक हम सही मायनों में बरतानिया का बाईकाट नहीं कर पायेंगे। इस लिये सब से पहली बात तो यह है कि उस मैनटेलिटी को दूर करना है।

इसके अलावा, जैसा कि जोश साहिब ने कहा, बरतानिया की सदियों से यह पालिसी रही कि "डिवाईड दी पीपल एंड रूल दी कन्टरी"। लेकिन जब हिन्दुस्तान के लोगों ने आज़ादी का नारा लगाया तो उसने अपनी उस पालिसी को बदल दिया। तब से उसने यह पालिसी अपना ली कि "डिवाईड दी कन्टरी एंड रूल दी पीपल"। उसने इस पालिसी का सब से पहला वार हिन्दुस्तान पर किया। हिन्दुस्तान उसकी इस पालिसी का शिकार बना जबकि "टू नेशंज थ्यूरी" के आधार पर उसने हमारे देश के दो टुकड़े कर दिए। उस वक्त मैं स्टूडेंट थी। उस वक्त पढ़ा था, उसकी तलाश तो मैं इस वक्त नहीं कर सकी लेकिन एक किताब थी 'Mission with Mountbaton'। उसमें लिखा था कि हिन्दुस्तान पर कई सालों तक इनवेडर्ज़ के हमले हुए, कितने नए धर्म उसके अन्दर आए, कितने लोगों ने उस पर आक्रमण किये, कितने लोगों ने यहां के लोगों पर अत्याचार किये पर हिन्दुस्तान कभी मरा नहीं, हिन्दुस्तान की कभी हार नहीं हुई। लेकिन जब हिन्दुस्तान के टुकड़े हुए तो हिन्दुस्तान की डिफीट हुई, हिन्दुस्तान की हार हुई और उसी माऊंटबेटन ने हिन्दुस्तान के साथ सब से बड़ा धोखा किया। इसके टुकड़े करके हिन्दुस्तान और पास्कि-स्तान बनाकर इतनी समस्याएं खड़ी कर दीं, जिनका अभी तक हल नहीं हो पाया। आज तक यहां हर हिन्दु और मुसलमान का झगड़ा खत्म नहीं हुआ। आज भी हमारे दोनों देशों में लोग एक दूसरे के साथ लड़ने को तैयार हैं और अंग्रेज़ अब भी पूरी तरह से इसी बात को सोचते हैं कि कैसे इन मसलों को भड़काया जाए, कैसे इस आग को हवा दी जाए। वैसे जो आग 1947 में भड़की थी उसको ब्रतानिया ठंडी नहीं होने देना चाहता है। ऐसे देश को, जिसका काम ही हमारे खिलाफ बातें करने का हो, हमारा नुकसान करने का हो उसे हम मित्र कहें तो मैं समझती हूं कि इस से बढ़ कर धोखा और क्या हो सकता है।

चेयरमन साहिब, मैं इस मौके पर आपको थोड़ी सी इतिहास की बात बताती हूँ। हम लोग हिटलर को बुरा समझते हैं—इसलिये बुरा समझते हैं कि उसने गैस chamber, में हज़ारों यहूदियों को मरवा दिया। लेकिन अंग्रेज़ों ने आपके साथ क्या कुछ नहीं किया ? उन्होंने हिन्दुस्तान की आत्मा का हनन किया, हिन्दुस्तानियों को कुत्ते कहा और अपनी क्लबों के बाहर यह लिख दिया कि यहां पर हिन्दुस्तानी नहीं आ सकते, होटलों के बाहर लिख दिया कि यहां पर हिन्दुस्तानी नहीं आ सकते। इससे और ज्यादा वह हम को और क्या मार सकते थे। अंग्रेज़ जब यहां पर राज करते रहे हैं तो उस वक्त जो वह हम पर अत्याचार करते रहे थे उसको क्या हम भूल सकते हैं। फिर आज दक्षिणी अफरीका में क्या हो रहा है। मैं कहती हूँ कि बरतानिया की गवर्नमेंट ने और उसके नुमायन्दों ने जहां वह दुनिया में राज्य करते रहे हैं और वहां पर जो अत्याचार करते रहे हैं

उनके साथ हिटलर के अत्याचारों का जो वह यहूदियों के साथ करता रहा है मुकाबिला नहीं किया जा सकता । हिटलर के अत्याचार पीछे रह जाते हैं लेकिन उसके खिलाफ इनका प्रापेगंडा बहुत रहा है जिस करके इन द्वारा किये गए अत्याचार छिपे रह गए हुए हैं। इनका सारे संसार में प्रापेगंडा इतना ज़ोर का रहा है जिसकी वजह से इनकी जो मोहन शक्ति लोगों पर अपना जादू करती रही है इसके कारण इनके अत्याचार भी उनकी आंखों में अत्याचार न रहे । और वह अगर हमें जहर भी देना चाहते थे तो वह शुगर पिलज़ की शक्ल में देते रहे और उनकी गोरी चमड़ी के जादू में आकर हम में इनफिरियारेटी कम्पलेक्स सा पैदा हो गया हुआ था और हम उनको एक तरह से सुप्पर हियूमन से समझने लगे थे । यह सारी बातें हैं जो मैं आपके सामने कहना चाहती हूँ।

चेयरमैन साहिब, मैं आपकी बात सही मानती हूँ कि यह ठीक है कि इस प्रस्ताव के साथ अमेरिका का कोई सम्बन्ध नहीं है लेकिन इसके साथ ही मैं आपसे पूछती हूँ कि वियट नाम में क्या हो रहा है क्या वहां पर भी अंग्रेज का हाथ नहीं है? कांगो में वह क्या नहीं करते रहे । हर जगह पर उनका किसी न किसी शक्ल में हाथ रहा है। फिर उसके बावजूद भी वह कहते हैं कि हिटलर ने बहुत अत्याचार किये थे। लेकिन मैं कहती हूँ कि ग्रेट ब्रिटन के हुकमरानों द्वारा किये गए जितने अत्याचार इस धरती पर देखने में आते हैं उतने न किसी ने कहीं कभी किये हैं और न आगे कोई कर सकेगा । आज भी आप देख लें कि दक्षिणी अफरीका में वह क्या कर रहे हैं और मिस्टर समिथ रोडेश्या में क्या कर रहा है जहां पर इनसानों को ब्लैक एलीफेंट कह कर निकाल दिया जाता है और उन्हें रास्तों पर भी नहीं चलने दिया जाता । फिर इन तमाम चीज़ों के होते हुए भी यह कहा जाता है कि वह हिन्दुस्तान के मित्र हैं लेकिन मैं कहती हूँ कि न पहले कभी वह हमारे मित्र रहे हैं और न ही रह सकते हैं। मिस्टर चर्चल ने अपनी जीवनी में लिखा था कि जब वह हिन्दुस्तान में फौज में भरती होकर आया था तो बंगलौर में रहा था। उसका यह तजुरुबा है कि हिन्दुस्तान आराम में रहने के लिये सबसे अच्छी जगह है क्योंकि वहां पर हर काम के लिये अलग नौकर मिल जाता है, यानी कपड़े सम्भालने के लिये अलग मिल जाता है, जूते उठाने के लिये अलग मिल जाता है इसी तरह से हरेक काम के लिये वहां अलग अलग आदमी होते हैं। यहां तक कि valet सम्भालने के लिये भी अलग आदमी हैं। जब वह ऐसे देश को छोड़ने पर मजबूर कर दिये गए तो उनसे इस देश की कभी भी मदद करने की उम्मीद नहीं की जा सकती । हममें से जो वहां जा कर पढ़ते हैं अगर यह समझते हैं कि वह हमारी मदद करेंगे तो यह उनकी भूल होगी ।

चेयरमैन साहिब, मैं एक बात और कहना चाहती हूं जो हमारे ट्रिब्यून अखबार में छपी थी जो गोबलज़ के झूठ को भी मात कर देती है। जब पिछले दिनों में अम्बाला में बम्ब पड़ा था तो अमेरिका के अखबार ने यह खबर निकाली थी कि उस दिन अम्बाला में हिन्दुस्तान के 25 हवाईजहाज़ नष्ट हो गए थे । इससे आप अन्दाज़ा लगा सकते हैं कि जितनी झूठी खबरें वह हमारे बारे में निकालते हैं। इसके बारे में ट्रिब्यून

[खाद्य तथा प्रदाय उप मन्त्री]

ने लिखा था कि यह खबरें वहां का प्रेस कहां से लेता है तो उसने यह भी बताया था कि उन्होंने यहां अपने प्रेस को रिपोर्टस भेजने के लिये एक लड़की रखी हुई है जो पहले से ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो की फिगरज़ तैयार करके रखती है और जो भी खबर यहां के किसी अखबार में छपे उसके साथ वह अंक ज़ीरो फैक्टस के साथ लगा कर भेज देती है। इस तरह से उनकी खबरें तैयार हो जाती हैं। आप ही बताइये कि गोबलज़ के झूठ में और इनके झूठ में क्या फर्क रह गया है। इन चीज़ों के बावजूद यह कहते हैं गोबलज़ ज्यादा झूठें बोलने वाला था। इसलिये मैं कहती हूँ कि हमारे कई लोगों को जो गोरी चमड़ी की एलयोरमेंट है उसे इनको छोड़ देना चाहिए और जो रीयेलेटीज़ है उनको मानने के लिये तैयार हो जाना चाहिए। कि कौन हमारे मित्र ह और कौन शत्रु हैं। (घंटी की आवाज़) बस चेयरमैन साहब, एक बात और कह कर मैं खत्म कर दूंगी। और हाउस का ज्यादा समय नहीं लूंगी। आपने देखा होगा कि जब भी इनको मौका मिलता है यह कश्मीर का हऊआ दिखाने लगते हैं और जो आग यह यहां पर हिन्दुस्तान के दो टुकड़े करके पाकिस्तान और हिन्दुस्तान बना कर आग लगा गये थे उसको यह सदा धधकते देखना चाहते हैं। फिर यह बात किस से छुपी हुई है कि अमेरिका में और कई दूसरी जगहों पर यह सलेवज़ की ट्रेड करते रहे हैं और उन लोगों से यह जिस तरह का बरताव किया करते थे तो वह किस से छुपा हुआ है। अगर कोई सलेव किसी के पास से भाग जाता था तो यह उसको पकड़ कर फिर उसके मालिक के पास पहुंचा देते थे। इसके बावजूद यह कहते हैं कि अंग्रेज़ कौम एक सवेलाईज़ड कौम है क्या इसी को सिवलीज़ेशन कहते हैं कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में सलेव लेजा कर उनकी ट्रेड की जाये। चेयरमैन साहिब, जो अंग्रेज़ इस बारे में करते रहे हैं और जो इस बारे में संसार का इतिहास बतलाता है क्या हम उस को भूल सकते हैं। अगर हम इस इतिहास को भूलने की कोशिश करेंगे तो हमें इससे बड़ी हानि उठानी पड़ेगी। मैं नहीं कहती कि हमें कामनवेल्थ को छोड़ देना चाहिए। इस बारे में तो गवर्नमेंट आफ इण्डिया के जो हमारे नेता है वह सोच कर फैसला कर सकते हैं लेकिन यह बात हमें ज़रूर याद रखनी चाहिए कि हमारे दिमागों में जो यह मैंटेलिटी बन गई है या बनती जा रही है कि हमने अगर अपने बच्चों को पढ़ाना है तो हम उन्हें इंगलैंड में भेजना मुनासिब समझते हैं या अगर कोई इलाज कराना है तो हम चाहते हैं कि इंगलैण्ड में जा कर कराएं ऐसा जो लोग महसूस करते हैं उनका ऐसा सोचना देश के हित में नहीं है और यह एक गलत चीज़ है। क्या हमारे देश में उनके बच्चों को पढ़ाने के लिये मास्टर नहीं हैं? और क्या बीमारियों के इलाज कराने के लिये हमारे अपने देश में डाक्टर नहीं हैं? कम अज़ कम हमें अपने बच्चों को पढ़ाने के लिये इंगलैण्ड में तो नहीं भेजना चाहिए। अगर बाहर भेजना ही है तो और भी तो छोटे छोटे मुल्क हैं जहां यह सारी सुविधाएं मिल सकती हैं। बेशक वहां जाए लेकिन बरतानिया में नहीं जाना चाहिए।

इस सिलसिले में मैं एक बात और कह कर, चेयरमेन साहिब, बैठ जाऊंगी। जब हम देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो यह अंग्रेज़ यहां पर हिन्दुओं और मुसलमानों

में नित्य झगड़े कराते रहते थे और जब हमारे जलूस निकलते थे तो यह उन पर लाठियां और गोलियां चलवा देते थे और निहत्थे लोगों को पीटा और मारा जाता था और उन पर तरह तरह के अत्याचार किये जाते थे । क्या हम यह सब बातें भूल गये हैं। अब फिर यही लोग पाकिस्तान और हिन्दुस्तान को लड़ाते हैं और इसके साथ ही कहते हैं कि हम सब के दोस्त हैं । आज सब लोगों को पता चल गया है कि यह किस तरीके से दोस्ती निभाते हैं या निभाते चले आए हैं।

श्री मोहन लाल (बटाला) : चेयरमैन साहिब, इस रैज़ोल्यूशन के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा तो यह है कि इंडिया और पाकिस्तान के कन्फलिक्ट में जो इन्गलस्तान का वतीरा रहा है उसके मुतअल्लिक इस हाउस के और पंजाब के लोगों के फीलिंग्ज़ कनवे किये जायें और दूसरा हिस्सा यह है कि हम रिकमैंड करें कि गवर्नमेंट आफ इंडिया कौमनवैल्थ से नाता तोड़ ले ।

जहां तक पहले हिस्से का ताल्लुक है, इसके मुतअल्लिक पंजाब की दो राएँ नहीं हो सकतीं, उस रोल के मुतअल्लिक जो इस झगड़े में इँगलिस्तान और अमरीका ने हिन्दुस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान के हक में प्ले किया । बल्कि इससे पहले भी खास तौर पर कश्मीर के मामले में इनका जो रोल रहा उसके बारे में रहा यहां पर दो राएँ नहीं हो सकतीं । शुरू से लेकर इनका वतीरा हिन्दुस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान के हक में रहा है । इसका तफसील में जिक्र मैं बाद में करूँगा ।

जहां तक दूसरे हिस्से का ताल्लुक है मैं सरदार गुरनाम सिंह जी से ऐग्री करता हूँ कि यह बात इस सभा की जूरिसडिक्शन से बाहर है । हमें अपनी हद में ही महदूद रहना चाहिए । हां जो हमारे फीलिंग्ज़ हैं—और वह बहुत वाजया फीलिंग्ज़ हैं—उनको कनवे करना हमारा हक बनता है और हमें यह बहुत मज़बूती के साथ ऊपर तक पहुंचाने चाहिएं । लेकिन अपने दायरे से बाहर जाकर हम मदाखलत करें इसका हमें हक नहीं पहुंचता और न ही यह मुनासब होगा । इसी लिये मैंने शुरू में ही कहा है कि मैं इस बारे में सरदार गुरनाम सिंह जी से इत्तफाक करता हूँ कि कौमनवैल्थ से हम अपना रिश्ता तोड़ें या कायम रखें यह हमारे दायरे की बात नहीं है और इसमें सिर्फ आज के यही हालात ही नहीं आते, उनका यही वतीरा नहीं आता और भी इन्टरनैशनल पालिटिक्स की बातें इसमें इनवोल्वड हैं जोकि हमारे दायरे से बाहर की हैं। हमारा यहां पर बैठ कर, महदूद से नालेज के साथ अपने आपको इनटरनेशनल ऐटमासफियर के ऐक्सपर्टस ज़ाहिर करना नामुनासिब होगा । यहां पर इनटरनैशनल एफेयर्ज़ डिस्कस नहीं होते उनकी जांच पड़ताल यहां पर नहीं होती और न ही हम उन से वाकफियत रखते हैं इसलिये इस बारे में कोई ऐडवाइस देना नामुनासिब होगा । इस बारे में अगर हम नुक्ताचीनी करें और हिन्द सरकार पर हम अपनी राय ठोसें तो यह ठीक नहीं होगा । अभी सरदार गुरनाम सिंह जी ने एक बड़ी वाज़ेह बात कही थी कि कामनवेल्थ में सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं है और भी बीस इक्कीस मुल्क इसमें हैं, ब्रिटेन के ही हाथ में सारी बात नहीं है हां यह बात ज़रूर है कि वह कामनवैल्थ का एक सीनियर मैम्बर है, मगर

[श्री मोहन लाल]

वही सब कुछ नहीं है। कामनवेल्थ से नाता तोड़ने का मतलब होगा कि न सिर्फ ब्रिटेन से ही नाता तोड़ना बल्कि दूसरे 20, 21 मुल्कों से भी नाता तोड़ना। उन से तो हमें कोई गिला नहीं है। तो यह जो सारी बात है यह हिन्द सरकार सोचे और भी दुनिया के पोलीटीकल चैसबोर्ड पर ऐसी बातें हैं जो हमारे नौलज में नहीं हैं, मगर उनके सामने हैं उन सारी पेचीदगियों को सामने रख कर वह सोचें कि हमारे मुल्क का यहां की जनता का भला किस बात में है। बाकी इसमें जो हमने हिस्सा डालना है वह यह है कि हम उनको बता दें कि हमारे फीलिंग्ज़ अमरीका और इंगलैंड के बारे में क्या हैं। इसमें शक नहीं है कि इन मुल्कों का जो रोल रहा है उससे हम सभी दुखी हैं, नाराज़ हैं, और इस बारे में किसी सबूत की भी ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि अभी पाकिस्तान के साथ होस्टैलीटीज़ शुरू ही हुई थीं कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया को ऐग्रेसर करार दिया था, ब्रिटिश प्रेस का भी रुझान हमारे खिलाफ और पाकिस्तान के हक में रहा है। इस बारे में किसी सबूत या दलील की जरूरत नहीं है, वह पार्शल थे पाकिस्तान के हक में। फिर इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि करीब डेढ़ महीने के बाद, ब्रिटिश हाई कमिश्निर इस बात को तसलीम करता है कि उनके प्राइम मिनिस्टर ने जो ब्यान दिया था वह गलतफहमी पर मबनी था, उनके सामने सारे वाकयात न थे। यह उसने एक प्रैस कांफ्रेंस में कबूल किया। अब आप देखें कि ब्रिटेन इससे ज्यादा हमसे क्या नाइनसाफी कर सकता था कि कामनवैल्थ का एक सीनियर मैम्बर का प्रधान मन्त्री बिना सारे फैक्टस को जाने इंडिया के खिलाफ बयान दे दे। एक इतना बड़ा इनटरनैशनल प्राबलम हो, हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का आपस में कनफिलिक्ट हो उसमें बिना पता किये कि उसमें ऐग्रेसर कौन है एक प्राईम मिनिस्टर इंडिया को ऐग्रेसर बताये तो इससे बड़ी गैरजिम्मेदारी की बात क्या हो सकती है। मैं समझता हूँ कि इनटरनैशनल स्फीयर में इससे बड़ा ज़ुलम और हो नहीं सकता। उनको मानना पड़ा कि यह उनकी भूल थी, गलती थी। इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की ज़रुरत नहीं क्योंकि उन्होंने खुद ही माना कि यह उन से गलती हुई, जो कुछ कहा वह गैरजिम्मेदारी की बात थी। इसके साथ ही साथ इस बारे में भी दो राय नहीं हो सकतीं कि शुरू से ही ब्रिटिश प्रेस का ऐटीच्यूड एन्टी इंडियन रहा है। यही हाल अमरीका का रहा है। इससे बड़ा और अमरीका के वतीरे में क्या सबूत हो सकता है कि इस कन्फलिक्ट में पाकिस्तान ने हिन्दोस्तानी फोर्सिज़ के खिलाफ आर्म्ज़ इस्तेमाल किये वह सारे के सारे अमरीकन हथियार थे और दुनिया जानती है कि जब वह हथियार अमरीका पास्कितन को दे रहा था तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहिब ने अमरीका को वार्निंग दी थी कि आप इनको मत आर्म्ज़ स्पलाई करिये वह हमारे खिलाफ इस्तेमाल होंगे। उस वक्त अमरीका के प्रेज़ीडेंट ने पाकिस्तान से अंडरटेकिंग ली और हमें अंडरटेकिंग दी कि वह जो आर्म्ज़ दे रहे हैं वह हिन्दुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होंगे। वह तो कम्युनिस्ट कन्ट्री चाइना वगैरह के खिलाफ डिफैंस के लिये हैं। आज जो पैटन टैंक हमारे कब्ज़ा में हैं हमारे खिलाफ जिन्हें इस्तेमाल किया गया और जो बेकार कर दिये गए यह सारे के सारे हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुए यह अमेरिका के थे। इस बात को आज

दुनिया जानती है । आज उन पैटन टैंकों और हवाईजहाज़ों की हालत को देख कर अमेरिका के मन में घबराहट और परेशानी पैदा होती है । दुख और अफसोस होता है उन्हें देख कर कि इतने मज़बूत पैटन टैंकों और हवाई जहाज़ों को हिन्दुस्तान के बहादुर जवानों ने तहश नहश कर दिया है । उन्हें घबराहट और शरमिन्दगी होती है अपने तहश नहश हुए टैंकों और हवाई जहाज़ों को देख कर इनकी हालत का आज वह तमाशा देखने आते हैं। दुनिया वाले इस बात को जानते हैं कि जहां अमेरिका वालों ने हिन्दुस्तान को अन्डरटेकिंग दिया हो कि यह सामान और टैंक वगैरा हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना होंगे और इस बात की अन्डरष्टैंडींग दी हो कि यह हवाई जहाज़ इस्तेमाल न होंगे हिन्दुस्तान के खिलाफ और फिर वह आनर न करे अपनी उस दी हुई कमिटमेंन्ट को तो क्या समझा जाए। इस बात के बावजूद भी कि यह कमिटमेंट दी हुई है फिर उलटा पाकिस्तान मांग करे और आर्म्ज़ लेने की अमेरिका से तो क्या समझा जाए। चाहे अभी तक उनका कोई फैसला नहीं हुआ कि अमेरिका वाले हथियार दे रहे हैं या नहीं लेकिन एक बात तो सारी दुनिया पर बिलकुल वाज़ेह है कि पाकिस्तान की कोशिश जारी है कि जो नुकसान पाकिस्तान का आर्मज़ का हुआ है और जो कमी हुई है उसको पूरा करने के लिये उसकी कोशिश जारी है और इसके लिये अमेरिका पर ज़ोर दिया जा रहा है। इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि अमेरिका ने हिन्दुस्तान के साथ अपनी कमिटमेंट का पालन न करके निहायत नाइनसाफी की है ।

मैं इस बात को जानता हूँ चेयरमन साहिब, कि अमेरिका के अन्दर भी इस हिन्दुस्तान के साथ की गई नाइनसाफी के खिलाफ आवाज़ उठाई गई है। अमेरिका में भी इस बात की पूछ ताछ हुई है और एडमिनिस्ट्रेशन से भी पूछा गया है कि हिन्दुस्तान के साथ की गई कमिटमेंट के बाद क्यों और किन हालात में पाकिस्तान ने अमेरिका का सामान हिन्दुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया । और यह जो नालायकी की बात थी इसका कौन ज़िम्मेदार है। अमेरिका वाले इस बात पर काफी सोच विचार कर रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा जा रहा है कि क्यों और किस ढंग से उल्लंघना हुई उस कमिटमेंट की । इसका नतीजा कुछ भी हो हमारी उससे गर्ज़ नहीं । हमारी गर्ज इस बात से है कि इस तरह से की हुई कमिटमेन्ट का उलंघन हो और आज तक अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ कोई इफैक्टिव कदम न उठाए जाएं और उसके खिलाफ कोई एक्शन ना लिया जाए। इसके बरअक्स यह हुआ कि इंगलैंड और अमेरिका वाले हिन्दुस्ता पर नाजायज़ दबाव डाल रहे हैं काश्मीर के मसला में । यह किसी से छिपी हुई बात नहीं और यह बात हमारे देश के लीडर्ज़ की तरफ से बार बार कही जा चुकी है कि काश्मीर के मामला में अमेरिका वाले हम पर ज़ोर डाल रहे हैं कि हिन्दुस्तान बड़ा मुल्क है और इसे काश्मीर के मामला में फराखदिली से काम लेना चाहिए । यह इस बात का साफ सबूत है कि जहां तक काश्मीर का मामला है अमेरिका वाले क्या और क्या इंगलैन्ड वाले उन सब का एटीच्यूड पाकिस्तान के मसला में पारश्यल रहा है । और हिन्दुस्तान के बरखलाफ एटीच्यूड है । इन हालत में इन मुल्कों से किसी किस्म के इन्साफ की तवक्को हम नहीं कर सकते । इन्होंने हर पहलू में और हर वक्त काश्मीर के

[श्री मोहन लाल]

सिलसिले में पाकिस्तान का मददगार बनना चाहा । मैं सिक्यूरिटी कौंसिल की प्रोसीडिंग्ज़ की तफसील में नहीं जाना चाहता क्योंकि यह बात मुनासिब नहीं मालूम देती कि इतनी बड़ी इन्ट्रनेशनल बाडी की प्रोसीडिन्गज़ की डिटेल्ज़ को यहां पर बताया जाए और शायद इस असैम्बली के स्कोप में भी यह बात न आ सके कि देखा जाए कि इनका वहां पर कैसा रवैय्या था ।

हां मैं इस बात को मानता हूँ कि जहां तक हिन्दुस्तान का संबंध है अगर किसी मुल्क ने इसके साथ हमदर्दाना सलूक किया है तो वह सोवियत रूस है । जिस तरह की मदद स्कयोरिटी कौंसिल में और इन्ट्रनेशल स्फीयर में इन्साफ की बिना पर की वह सोवियत रूस की ही है । इसमें कोई दो राएं नहीं हो सकतीं । और हम इस इमदाद के लिये मशकूर हैं। आज भी और पहले भी रूस हमारा मददगार रहा है और आज भी है। हम उनकी इमदाद के लिये मशकूर हैं और इस बात को हमें इकबाल करना है कि अगर इन्टरनैशनल सफीयर में रूस की हमें इमदाद न होती तो न जाने हमें आज किस कोने में अपने आपको कारनर करना पड़ता ।

(इस समय उपाध्यक्षा ने कुर्सी संभाली)

फिर, डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमने किसी ढंग से अपने असूल से बाहर नहीं जाना है। आज हमारी जो पालेसी है नान-अलाइन्मेंट की उस पालेसी का यहां पर हमें चर्चा नहीं करना है । और मैं यह महसूस करता हूँ कि यह बात हमारे डिसकशन के स्कोप से बाहर होगी । हमें नान अलाइन्मेंट रखना है जिस ढंग से और जैसे भी इसका संबंध हो यह इन्ट्रनेश्नल पालेसी है और सेंटर से सम्बन्ध रखती है। इसलिये, मैं अपने आपको एक्सप्रेशन आफ फीलिंग्ज़ तक महदूद रखना चाहता हूँ।

हमें दुःख है और हम नालां हैं उस रोल पर जोकि ब्रिटेन वालों और अमेरिका वालों का हमारे सम्बन्ध में इन्ट्रनैशनल स्फीयर में रहा है और खुशी महसूस करते हैं सोवियत रूस की मदद देने पर जिन्होंने हर वक्त इमदाद की ।

मैं आखिर में एक बात कह कर खत्म करूँगा कि इस रैज़ोल्यूशन का संबंध सिर्फ इन्डो पाकिस्तान कानफलिक्ट जो हुई उससे ही है लेकिन फिर भी मैं यह नहीं समझ सका कि अमेरिका जो रोल आज पाकिस्तान के सम्बन्ध में या जो रोल इंगलेण्ड का है क्यों इस तरह का बना । अमेरिका आज अपना सब से बड़ा दुशमन चाइना को मानता है और आज चाइना और पाकिस्तान की मिली भगत है वरना पाकिस्तान की हिम्मत क्या थी हिन्दुस्तान पर हमला करने की । और आज बातें सामने आ रही हैं और वाक्यात का पता चल रहा है कि सब से बड़ा हाथ चाइना का था पाकिस्तान के इस हमला करने में । अब एक तरफ तो चाइना बड़ा दोस्त है पाकिस्तान का और दूसरी तरफ चाइना अमेरिका का सब से बड़ा दुशमन मगर इसके बावजूद आज

इंगलैंड और अमेरिका पाकिस्तान से दोस्ती का दम भरें मैं इस बात को समझ नहीं पाया । आज इंगलैंड वालों और अमेरिका वालों ने हमें लैट डाऊन किया है और पाकिस्तान की मदद की है। इस बात के होते हुए भी कि हमें कमिटमेन्ट अमेरिका ने दी हुई है उसकी क्या पालेसीज़ हैं मैं तो समझ नहीं पाया।

जहां तक हमारी और मेरी ही नहीं सारे पंजाब के लोगों की फीलिंग्ज़ हैं पाकिस्तान और इण्डिया में जो कानफलिक्ट चली आ रही है, इस सिलसिले में जहां तक काश्मीर का संबंध है, मैं अपनी आवाज़ को और अपनी ही नहीं सारे पंजाब के लोगों की आवाज़ को अपने प्राईम मिनिस्टर श्री लाल बहादुर शास्त्री की आवाज़ में शामिल करता हूँ जो स्टेन्ड उन्होंने लिया और चाहे कितना ही दबाओ ज्यादा से ज्यादा, चाहे अमेरिका का हो या इंगलैंड का हो हमारे पर डाला क्यों न जाए, हम अपने प्राईम मिनिस्टर के साथ हैं और हम उन्हें यकीन दिलाते हैं कि पंजाब किसी भी दबाव में आकर बल्कि सारा देश ही खाह दबाव कितना ही बड़े से बड़ा हो काश्मीर क्या अपनी किसी भी धरती का एक इन्च और रत्ती भर भी हिस्सा छोड़ने को तैयार न होंगे । (प्रशंसा) काश्मीर हिन्दुस्तान का है और हिन्दुस्तान का ही रहेगा और हमें इसे अपना बना कर रखना पड़ेगा (तालियां) अगर काश्मीर के मुताल्लिक किसी भी किस्म की कमज़ोरी दिखाई गई तो मैं कहूँगा कि इसे हमारी जनता बिलकुल भी कबूल नहीं करेगी। ऐसा उनका हक है । जिस तरह की आज इंट्रनेशनल स्फीयर पर बात हो रही है, इसके मुताल्लिक मैं फिर अपने फीलिंग्ज़ इस तरह से पुट करता हूँ कि हमें इस रैज़ोल्यूशन का यह जो सैकंड पार्ट है वह गवर्नमेंट आफ इंडिया पर ही छोड़ना चाहिए।

पंडित मोहन लाल दत्त (अम्ब) : डिप्टी स्पीकर साहबा, अगर ग़ौर से देखा जाये तो इंगलैंड इस संसार का सब से बड़ा जाबर और इमपीरियलिस्ट मुल्क है जो अपने किये हुए आज़ाद कंटरीज़ को भी इंटरनेशनल सफीयर में अपने पंजे में रखना चाहता है। आज दुनिया के हालात ने सब बड़े मुल्कों को मजबूर कर दिया है कि जितने भी छोटे छोटे मुल्क उनकी गरिफ्त में हैं उनको छोड़ दिया जाये, उन्हें आज़ाद कर दिया जाये । मगर फिर भी अभी तक इंगलैंड के हुकमरान, जिनमें कि डामिनेटिंग तबका पूंजी वादियों का है, के दिल से लूट खसूट का जज़बा खत्म नहीं हुआ। मुल्क गीरी की हवस अब भी उनमें बाकी है। आज अपनी चाल बाज़ियों के द्वारा वह इस संसार में अब भी बेईमानियां करते चले आरहे हैं। एक मुल्क को दूसरे से लड़ा रहे हैं और अपना उल्लू सीधा करने पर लगे हुए हैं।ऐशिया और अफरीका के जितने भी बड़े बड़े डिवैलपिग कंटरीज़ हैं यह अपनी मंडी बनाना चाहते हैं और साथ ही साथ ऐसी चालबाज़ियां भी करते जाते हैं कि यह मुल्क चाहे आज़ाद क्यों न हो गये हों, यह चाहते हैं कि यह पहले की तरह हमारे मुहताज रहें । मगर हिटलर और मसौलीनी जैसे न रहे अब इनकी चालबाजियां भी और देर तक चलेंगी नहीं। दुनिया अब बहुत होशियार हो गई है । इनको अब अकल आ गई है, इन मुल्कों की चालबाज़ियां अब चलने वाली नहीं हैं। हमें जज़बात की रौ में बहना नहीं चाहिए, हमें दुनिया के हालात को मद्दे नज़र रखते हुए और अपने देश

[पंडित मोहन लाल दत्त]

के नाज़ुक हालात को मद्दे नज़र रखते हुए अपनी नीति को अपनाना चाहिए। ऐसी नीति अपनानी चाहिए जो हमारे देश के लिये लाभदायक हो। जो नीति हमारे नेता पंडित जवाहरलाल ने इंट्रनैशनल सफीयर में अपनाई थी मैं समझता हूँ इससे बेहतर और कोई नीति हमारे देश के हित में हो ही नहीं सकती। यह नीति क्या थी कि भाई सब दुनिया से मित्रता रखी जाये इसके साथ ही हमारी यह नीति भी हो कि हम किसी के आगे झुकें न, हम किसी के आगे अपनी इज्ज़त को फरोखत न करें। हम अपनी अपनी ताकत पर खड़ा होने का प्रयत्न करते रहें और दूसरों को खाहमखाह नाराज़ भी न करें। ऐसी नीति पर चल कर ही हमारा भला है। मैं तो आपोज़ीशन के लीडर सरदार गुरनाम सिंह ने जैसे ख्यालात का उन्होंने इज्हार किया उसका समर्थन करता हूँ। हमें इस तरह से जज़बात की रौ में बह कर खाहमखाह किसी से दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए। जो नीति इंगलैंड ने हमारे मुतअल्लिक अपनाई है, जो रोल इन्होंने कामनवैल्थ कंटरीज़ ने हमारी इस जंग के दिनों में प्ले किया वह शर्मनाक था और हमारे देश के लिये घातक था। कामन वैल्थ कंटरीज़ में हम इसलिये जाकर अपनी आवाज़ रखते हैं कि जो वहां की राये आमा है वह सही शकल में सुनी जाये। हम ने जो रोल प्ले करना है वह यह है कि हम अपनी राये आमा की आवाज़ का सही पक्ष पेश करके हमने उनको मजबूर करना है कि जो हमारी नीति है वह सही हैं। मगर इंगलैंड वाले हमारी नीति को गलत बता रहे हैं। हमें इनकी परवाह न करते हुए इनकी नाराज़गी की कोई परवाह न करते हुए अपने देश को मज़बूत करने का प्रयत्न करना चाहिए और यह तभी होगा अगर हमारे मुल्क में सोशलिज्म आये। इसको जल्दी से जल्दी कायम करने का प्रयत्न करना चाहिए। मगर यहां पर जो नीति चल रही है वह पूंजीवाद नीति है। जैसे बहन जी ने फरमाया था कि यहां पर तो वह नीति चल रही है, जोकि अंग्रेज़ों की है, पूंजीवादियों की है....................

खान अबदुल गफ्फार खां: पंडित जी, इस रैज़ोल्यूशन से आपकी तकरीर का क्या तअल्लुक है ?

पंडित मोहन लाल दत्त: खां साहिब, इससे तअल्लुक है, मैं यह कह रहा हूँ कि आप अंग्रेज़ों को बुरा कहते हैं पहले आप उन का पूंजीवाद का सिस्टम तो छोड़ें जोकि यहां पर बड़े ज़ोरों पर चल रहा है। हम देख रहे हैं कि कैसे गरीबों की लूट खसूट हो रही है यह नीति उन लोगों की अपनाई हुई है जो इस वक्त इस मुल्क पर हकूमत कर रहे हैं। इसको आज भी सैंटर की सरकार अपना रही है। हमें पहले अपने घर को ठीक करना होगा। एक बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि रूस के हम बहुत मशकूर हैं जिन्होंने काश्मीर के संबंध में हमारी हमायत की। मगर इसके साथ ही हमने यह भी देखना होगा कि हमने रूस से गठजोड़ करके या किसी और मुल्क से बातचीत करके किसी एक ब्लाक में जाना नहीं है। हमने तो इंडियन सोशलिज्म कायम करना है, उस नीति को ही अपनाना है जो इस मुल्क के लिये सही हो उनके निज़ाम के साथ, उनकी नीति से हमारा कोई वास्ता नहीं है, हमने दीदा-दानिस्ता उनमें नहीं जाना। इस पर मैं और ज्यादा नहीं कहना चाहता, इतना ही कहूँगा कि जो रज़ोल्यूशन कामरेड शमशेर सिंह जोश ने पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूँ इसको इसी सूरत में ही पास किया जाये।

FOURTH REPORT OF THE BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

उपाध्यक्षा: पेशतर इसके हाउस की अगली कार्रवाई चले मैं बिज़नैस एडवाईज़री कमेटी की रिपोर्ट आपके सामने रखती हूँ। (I would like to place before the House the report of the Business Advisory Committee before we proceed further.)

> "The Committee, after some discussion, recommended that the House at its rising today shall stand adjourned till Monday the 15th November, 1965, at 2.00 P. M. and that there shall be no sitting on Saturday, the 6th November, 1965, as previously decided."

Shri Ram Partap Garg (Chief Parliamentary Secretary) : Sir, I beg to move—

> That this House agrees with the recommendations contained in the 4th Report of the Business Advisory Committee.

Deputy Speaker : Motion moved—

> That this House agrees with the recommendations contained in the fourth Report of the Business Advisory Committee.

11.00 A.M.

Deputy Speaker : Question is—

> That this House agrees with the recommendations contained in the 4th Report of the Business Advisory Committee.

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਇਕ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਇੰਸਟੀਚੂਟ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਯੂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋ ਬਾਰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਉਸ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਹਨ, ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੋ ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਸੱਦ ਲਉ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਐਡਾਪਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਉ । (The report of the Business Advisory Committee has been adopted. The hon. Member may please resume his Seat.)

RESOLUTION RE. WITHDRAWAL OF INDIA FROM THE COMMON WEALTH (RESUMPTION OF DISCUSSION)

कामरेड राम चन्द्र (नूरपुर) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, आज का प्रस्ताव बड़ा महत्वपूर्ण है। इससे यह ज़ाहिर होता है कि आज कौम में एक खाहिश पैदा हो रही है कि जिन चीजों का हमें लड़ाई के दौरान तजुर्बा हुआ है उनकी रोशनी में कोई नया रास्ता अख्तियार करें ।

बादा है नीम रस अभी से शौके ना रसा अभी
रहने दो सर पे खुम के तुम खिश्ते कलीसा अभी ।

[कामरेड राम चन्द्र]

डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जहां तक बर्तानवी सल्तनत का और देशों के साथ ताल्लुक रखने का सवाल है, अगर उसको ग़ौर से देखा जाए तो पता चलता है कि उसकी तारीख यही रही है कि देशों को फाड़ो और हकूमत करो। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब वह हिन्दुस्तान से रवाना हुए तो उन्होंने जो फिरका-दाराना खूँरेज़ी और फसादात का मंज़िर यहां पैदा किया, वह हमारे दिमागों से ओझल नहीं हुआ है । उन्हों देखा कि अब वे हिन्दुस्तान को काबू में नहीं रख सकते तो एक मुस्लिम लीग पार्टी खड़ी कर दी और जब यह देखा कि इस पालिसी के बावजूद वे सारी कौम को नहीं लड़ा सकते और सारे मुल्क को गुलाम नहीं रख सकते तो उन्होंने मुल्क के दो हिस्से कर दिए। और उसका नतीजा यह है कि अब हम हिन्दुस्तान और पाकिस्तान आपस में लड़ रहे हैं। और फिर अमेरिका ने ऐसे हालात पैदा कर दिये कि पाकिस्तान को लड़ाई का सामान दिया गया । जब हिन्दुस्तान ने प्रोटैस्ट किया तो उत्तर मिला कि यह हथियार चीन के विरुद्ध इस्तेमाल होंगे । इस प्रकार पाक को बाकायदा माडर्न वैपन्ज़ से लेस किया गया है। हमें वादा देते हुए उस वक्त के अमेरिकन प्रेज़ीडेंट ने और सेक्रेटरी आफ स्टेट्स ने यह विश्वास दिलाया था कि यह हथियार हिन्दुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होंगे । लेकिन जब इस्तेमाल हुए तो अमेरिका चुप साधे रहा और उसने आज भी एक लफ्ज़ नहीं कहा कि पाकिस्तान ने हिन्दुस्तान के खिलाफ वे हथियार क्यों इस्तेमाल किये जो चीन के साथ लड़ने को दिये गए थे । आज नहीं, दुनियां की तारीख में कई बार यह साबित हो चुका है कि इनके यह कौल और वादे सिफर के बराबर हैं। पहली लड़ाई के बाद अमेरिका के प्रेज़ीडेंट विलसन ने 14 नुकती प्रोग्राम दिया और गुलाम मुल्कों के बारे में यह कहा कि उन्हें आत्मनिर्णय का हक दिया जाएगा। लेकिन जंग के बाद आत्म निर्णय करने का हक किसी को नहीं मिला । हिन्दुस्तान में मार्शल ला लगाया गया जिसमें हजारों लोग अंग्रेज़ों की गोलियों से जगह जगह पर भून दिये गए । यह एंग्लो-अमेरिकन ब्लाक की पुरानी हिस्ट्री है । अमन कायम होने पर क्या हुआ ? कि गुलाम मुल्क गुलाम रहे । हमें मार्शल ला मिला और दूसरे गुलाम मुमालिक को जीतने वालों ने बांट लिया और अपने अपने कब्ज़े में कर लिया ।

हमारी बार भी अमेरिका ने बार बार कहा कि यह हथियार हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दिये जायेंगे लेकिन हुए । इससे क्या साबित होता है? यही कि अमेरिका के यह वादे सिफर के बराबर हैं। और बर्तानिया ने जो रोल प्ले किया उससे साफ ज़ाहिर हो गया है कि आज नौबत यहां तक आ गई है कि हमें रैज़ोल्यूशन के ज़रिये अपनी सरकार को यह सिफारिश करनी पड़ी है कि वह अपने तअल्लुकात उससे तोड़ लें, लेकिन यहां पर मेरे फाज़िल दोस्त श्री जोश साहब ने सरकार की व लीडरों की जिस ढंग से नुक्ताचीनी की मैं समझता हूँ कि वह इस रज़ोल्यूशन के दायरे के बाहर थी। इससे परहेज़ किया जाता तो अच्छा था लेकिन वह इसलिये कहे गए कि वह जज़्बात की रौ में बह गये / वह नावाजिब सी चीज़ हो गई, लेकिन हकीकत तो यह है कि हमें जो तजुर्बा हुआ है उसकी बिना पर हमें सोचना होगा कि

हम क्या करें! उस वक्त भी जब हम आज़ाद हुए तो यह फैसला हुआ था कि हम मुकम्मल तौर पर अपने आपको आज़ाद कर लें और अंग्रेज़ी हकूमत से कोई सम्बन्ध न रखें। बाद में कामनवैल्थ में चले गए। यह हमारी ही पहनी हुई सोने की ज़ंजीरें हैं जिन्हें हम जब चाहें तब तोड़ सकते हैं। यह कामनवैल्थ अंग्रेज़ों का कामनवैल्थ नहीं बल्कि कामनवैल्थ आफ नेशंज़ है बहुत से मुल्कों और कौमों का जोड़ है और इसमें हमारे ऊपर कोई पाबन्दी नहीं है कि किसी फैसले को ज़रूर मानें। लेकिन कामनवैल्थ में रह कर हमें मौका मिला है दूसरे मुल्कों से कांटैक्ट कायम करने का जिसका फायदा हम तभी उठा सकते हैं जब हमारी डिप्लोमेसी मज़बूत हो। लेकिन हकीकत यह है कि हमें उसका फायदा नहीं हुआ। मैं फारेन पालिसी में नहीं जाना चाहता लेकिन यह बात ठीक है कि कामनवैल्थ में जितने भी अफ्रीकी और एशियाई मुल्क हैं वह अंग्रेज़ों की पालिसी से नालां हैं। अगर हमारी डिप्लोमेसी अच्छी हो तो हम अंग्रेज़ों को इसमें कार्नर कर सकते हैं। जनूबी अफ्रीका में अपार्थीड की पालिसी है, रोडेशिया में सफेद कौम का गलबा है, जिससे अफ्रीका में बेचैनी है और अंग्रेज़ आज आज़माइश में हैं। उनकी गलत पालिसीज़ एक दिन मजबूर कर देंगी कि यह कामनवैल्थ टूट जाय लेकिन जो चीज़ खुद बखुद टूट रही है और टूटने वाली है, आज के कुछ ऐसे हालात हैं, हमें उस पर ज़रब लगाने की ज़रूरत नहीं है। उस पर ताकत ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। हमें वे हालात पैदा करने चाहिएं जिससे अंग्रेज़ कार्नर हो जाएं और जो अफरीका और एशिया के मुल्क कामनवैल्थ में शामल हों वे हमारे साथ हों। हमारी पालिसी यह रही है कि हम शांति के हक में हैं, सब अच्छे हैं, अंग्रेज़ों को और दूसरों को कहें कि अच्छे हैं। खुद यह कहते रहें कि हम शांति की पालिसी पर चलेंगे। हमने अपनी ताकत नहीं बनाई। यह जो तजुरबा हमें हो गया उसमें हमने देखा कि रूस के सिवा किसी मग़रबी मुल्क ने हमारी मदद नहीं की। रूस, योगोस्लाविया, चैकोस्लावेकिया, ग्रीक, रोमानिया और दूसरे पूर्वी योरूप के मुल्कों ने हमारी मदद की है और आड़े वक्त वे हमारे काम आए हैं। हम उनकी हमदर्दी को कभी भुला नहीं सकते। आज हम फैसला कर सकते हैं कि कौन हमारा दोस्त है और कौन दुश्मन है। इसलिये जहां हमें दोस्त मुल्कों के साथ अपने ताल्लुकात मज़बूत बनाने चाहियें वहां मैं समझता हूँ कि दुनिया में किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। मैं तो शास्त्री जी के इस कौल से मुतफिक हूँ कि आखिर में अपनी ताकत ही काम आती है। हमें अपनी ताकत, फौजी ताकत बनानी चाहिए। अपनी पुरानी पालिसी को बदलना चाहिए। मैं आशा रखता हूँ कि अब ऐसा ही होगा। मुल्क में आवाज़ पैदा हो गई है। बहुत जल्दी वह वक्त आ जाएगा जब हम दुनिया के 6 या 7 मुल्कों में--जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, अमरीका, रूस, चीन हैं--शामल हो जायेंगे। अब आप उस दर्जे पर पहुंच जायेंगे यह कामनवैल्थ आपके मुताबिक चलेगी। या यह कामनवैल्थ की कड़ी जिसको ज़ेवर समझ कर पहना है वह कड़ी खुद-बखुद टूट जायेगी। इस कौम का मूड पहली बार बदला है। मुझे फानी का यह शेर याद आता है: —

मशाले सोज़े ग़म हाए निहानी देखते जाओ
भड़क उठी है शमा-ए-ज़िंदगानी देखते जाओ।

[कामरेड राम चन्द्र]

आज संसार में इंपीरियलिज़म की बरबादी के सामान जरूर पैदा हो गए हैं। फिर भी मैं एक चीज़ कहता हूँ। हम में हुब्बलवतनी पूरी तरह नहीं आई है। शास्त्री जी ने कहा है कि हम पर दबाव पड़ रहा है कि अमरीका हमें अनाज नहीं देगा। इस सम्बन्ध में हमें अमरीका से कहना है कि हम भूखे रहेंगे लेकिन दबाव में नहीं आएंगे। इसीलिये हमें अमरीका से कम से कम अनाज न मंगवाने के लिये सोमवार को शाम का खाना नहीं लेना चाहिए। मिस ए मील वन्स ए वीक करना चाहिए। अभी यह बात पूरी तरह नहीं चली है। मैं इससे खुश नहीं हूँ। चाहिए यह कि हमारे अखबार, हमारा तमाम मुल्क, हमारे देहात, हमारे शहर इस बात से गूंज उठें कि हम सोमवार शाम को खाना नहीं खाएंगे। (इस समय कोरम न होने पर कोरम की घंटी बजाई गई। तब कोरम पूरा हुआ) डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं यह कह रहा था कि हम में जोश तो जरूर है लेकिन अभी तक हम अमली चीज़ के साथ नहीं चल रहे इस पर ग़ालिब का यह शेर सादिक आता है--

रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल
जो आंख ही से न टपके तो फिर लहू क्या है।

इसलिये मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जब मैं हिस्टारिकल फैक्टस को देखता हूं तो पता चलता है कि जो बृटिश एंपायर थी वह आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है। अंग्रेज़ों ने अपना गलबा रखने के लिये उसे कामनवैल्थ की शकल दी। अब इस पर से अंग्रेज़ों का होल्ड खिस्क रहा है, हम और अंग्रेज दोनों शतंज खेल रहे हैं। तो इसमें जो मोहरे बनते हैं वह खिस्क रहे हैं, इधर उधर हो रहे हैं। इंग्लैंड एक लूज़िंग गेम खेल रहा है और इसमें हमें फौरी कदम उठाने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने आपको ताकतवर बनाएं, Atom Bomb बनायें, अपनी फौज को बढ़ाएं। शास्त्री जी ने miss a meal के लिये जो कहा है उस पर अमल करें। हम कालेजों में बोर्डिंग हाउसिज़ में भी यह लागू करें। हत्ताकि हम अमेरीका की इंपोर्ट बंद कर दें। भूखे तो रहेंगे लेकिन अपनी आज़ादी कायम रखेंगे।

खान अब्दुल गफ्फार खां (अंबाला शहर): जनाब डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस वक्त जो रैज़ोल्यूशन हमारे सामने हैं वह अहम भी है और जरूरी भी है। गिला है अंग्रेज़ों से या दूसरी और कौमों से, दूसरे मुल्कों से। अंग्रेज़ों से गिला करना तो मैं बिलकुल फज़ूल समझता हूँ क्योंकि अंग्रेज़ों से उनकी राजनीति से किसी किस्म की भलाई की उम्मीद रखना अपने आपको धोखा में डालना है। जनाब डिप्टी स्पीकर साहिबा, अंग्रेज़ों के मुतअलिक एक मशहूर बात थी Sun never sets on the British Empire. लेकिन उसके साथ साथ लोगों को तजुरुबा हुआ और उन्होंने पूछा कि why the Sun never sets on the British Empire? तो जवाब है because even God will not trust an Englishman in the dark.

तो जनाब डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह गिला उनसे इस बात का क्या करना है। मैं तो समझता हूँ कि इसका कोई फायदा नहीं है। उन्होंने हमें गुलाम बनाए रखा और

उसके बाद हमें यहां तक गरीब बना दिया कि हमारी तमाम खाहशात और हमारे तमाम जज़बात कुचल कर रख दिए और हमें बिलकुल नाकारा बना कर रख दिया। आज आजादी हासिल होने के बाद देखते हैं कि 18 साल के अन्दर मुल्क कहां से कहां पहुंचा और कितनी तरक्की की। आज एक साहिब ने यह फरमाया कि हमने तैयारी नहीं की और हम यह कहते रहे कि हम लड़ेंगे नहीं। मैं समझता हूँ कि यह बात कोई मुनासिब नहीं कही गई क्योंकि जिस नीति पर आप यह कहते हैं कि हमने तैयारी नहीं की वही नीति थी कि जिसने कि तैयारी कराई। पंडित जवाहर लाल नेहरू महबूब राहनुमा की यह नीति थी कि मुल्क में अनो मअमान रहे। कोई झगड़ा या लड़ाई न हो किसी मुल्क से ताकि अमन के ज़माने में हम अपनी तरक्की कर लें। जनाब, डिप्टी स्पीकर साहिबा, आपको खुशी होगी यह मालूम करके जैसा कि आप पहले से ही जानती हैं कि इन 16–17 साल में जब पंडित जवाहर लाल जी ज़िन्दा थे उन्होंने मुल्क में अमनोअमान कायम रखा और आज मुल्क की दफाह के लिये जितना आरमामेंट है उसका 80 फीसदी इसी मुल्क में बनता है। यह जवाहरलाल जी की बर्कत से बनता है। जब दौराहा में इलैक्शन था और जब वह वहां गए तो मैं उनके साथ था। उस वक्त जो तकरीर उन्होंने की थी वह मुझे याद आती है। उन्होंने फरमाया कि लड़ाई लड़ाई की तो बड़ी रट लगाते हो लेकिन एक bolt तक अपने मुल्क में बना नहीं सकते हो, लड़ाई किस तरह करोगे ? उन्होंने ने कहा अमन कायम रखो, पैदावार बढ़ाने की कोशिश करो और जब मुल्क ताक्तवर होगा तो कोई दूसरा हमारे मुल्क की तरफ आंख उठाने की जुरर्त नहीं करेगा। वह बात अब सही साबत हुई। अब जो हमने कहा कि हम लड़ाई के लिये तैयार हैं और हम लड़े तो इसकी वजह यह है कि हमें मालूम था कि हम ताकतवर हैं और हममें हिम्मत है कि हम पाकिस्तान को नाकों चने चबा दें और चीन को छटी का दूध याद करा दें। अगर हम में ताकत न होती तो कामरेड साहिब, हम लड़ नहीं सकते थे हम इसलिये लड़े और जीते कि हम में ताकत थी और ताकत है जिसकी वजह से हमारे मुहतरिम प्राइम मिनिस्टर साहिब ने चीन और पाकिस्तान से कहा कि दोनों आ जाओ हम दोनों से निपट लेंगे (तालियां) और सारे हिन्दुस्तान ने और पंजाब ने उनकी इस आवाज़ को बैक किया लेकिन यह बात कहना कि पहले यह बात नहीं थी और हममें ताकत नहीं थी, हमारी पालिसी गलत थी सरासर गलत बात है। मैं कहता हूँ कि आज जो हमारे सर-बरा हैं, वह कौन हैं ? वही शास्त्री जी हैं जो पंडित जवाहर लाल के ट्रेनी हैं और उनसे उन्होंने यह सारी ट्रेनिंग हासल की है जो कहते थे कि अभी अमन रहना चाहिए, लड़ाई नहीं होनी चाहिए। जब देख लिया कि तमाम के तमाम हालात हमारे मुवाफिक हो गए तो हमने लड़ाई के लिये कह दिया। मुझे एक बात का ज़रूर अफसोस ज़ाहर करना है वह यह है कि किसी किसम का कोई मसला आए आपोजीशन की तरफ से चाहे relevant हो या irrelevant हो कांग्रेस और कांग्रेस सरकार को कोसने की कोशिश की जाती है। मैं पूछता हूं कि इसमें कौन सी मनतक थी कि नैशनल लीडरशिप को कोसने की कोशिश की जाए। आखिर इस का फायदा क्या है कि रैजोल्यूशन कुछ हो और मौका कांग्रेस, कांग्रेस हकूमत और वज़ीरों को कोसने का निकाला

[खान अब्दुल गफ्फार खां)

जाए । इससे सिवाए इसके कि हमारी सारी की सारी कौम ridiculous पोज़ीशन में पड़ जाए और कुछ इससे नहीं होता है। एक बात मैं अंग्रेज़ों के मुताल्लिक भी कह देनी चाहता हूँ। मेरा ख्याल है लिंकन साहिब, जो अमेरिका के बड़े मशहूर प्रज़ीडेंट हुए हैं उन्होंने यह बात ग़ालबन अंग्रेज़ों के मुताल्लिक ही कही थी कि उन्होंनें कोशिश की तमाम दुनिया को धोका में डालने की लेकिन वह बात कुछ अर्सा तक चल सकी । उन्होंने इसी धोका से हिन्दुस्तान को दो सौ ढाई सौ साल गुलाम रखा लेकिन हिन्दुस्तानियों ने आखर उनको इस तरह निकाल बाहर किया जिस तरह कहते हैं दूध से मक्खी और मक्खन से बाल निकाल दिया जाता है। वह भी किस तरह निहत्ता होते हुए हमारे पास कोई हथियार नहीं था।हमने साबत कर दिया कि लड़ते हैं मगर हाथ में तलवार भी नहीं। अंग्रेज़ के मुतअल्लिक हमारी ही नहीं दुनिया के किसी मुल्क की राए अच्छी नहीं । एशिया और अफ्रीका के जितने मुल्क हैं सब उनकी करतूतों से तंग आए हुए हैं। अंग्रेज़ ही नहीं योरप के जितने मुल्क हैं उनकी हमेशा से यह नीति रही है कि कोई मुल्क हो उसमें फितना फसाद बर्पा रहना चाहिए। और उनका अपना हलवा-मांडा चलता रहना चाहिए । हमारी भी एक गलती थी और मैं कहना चाहता हूँ कि निहायत सख्त गल्ती थी और मैं उस गल्ती को मानने में नदामत महसूस नहीं करता कि हमने अपने मुल्क की तक़सीम को मंजूर किया । इस गलती का खम्याज़ा हम आज भुगत रहे हैं। आज अंग्रेज़ और उन के दूसरे साथियों में इतनी ताकत नहीं रही कि अब दूसरे मुल्कों को अपने शकंजे में रख सकें। लेकिन करते क्या हैं कि इधर किसी मुल्क की आज़ादी का ऐलान करते हैं उधर फितना फसाद खड़ा करके सिवल वार जारी करा देते हैं। आखिर कांगो में क्या हुआ ? अब रोडेशिया में यही खेल खेला जा रहा है । वहां एक लाख गोरे आदमियों के प्राइम मिनिस्टर को यह जुर्रत होती है कि वह अंग्रेज़ों से कहता है कि हम unilateral आज़ादी का ऐलान करते हैं। कितनी शर्मनाक बात है कि एक लाख गोरे आदमी रोडेशिया के कई लाख आदमियों पर हकूमत करने के लिये साज़ बाज़ कर रहे हैं। विल्सन साहिब जब वहां पर जाते हैं तो समिथ साहब कहते हैं कि नहीं हम तो खुद अपनी आजादी का ऐलान कर देंगे। इसके माने हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अब कमज़ोर से कमज़ोर होती जा रही है । मैं कहता हूँ कि अब उसके हिस्से बिखरे होकर रहेंगे और वह इतना ही जज़ीरा रह जायेगा जितना कि पहले था । मैं यह भी कहता हूँ कि वह इसी तरह हिन्दुस्तान को धोका में रखने और जुल्ल देने की कोशिश करते रहेंगे और धोके फरेब करते रहेंगे ।लेकिन हमें होशियार रहना चाहिए हमें फख्र है कि हमारे लीडर्ज़ इस बात से पूरी तरह खबरदार हैं और उनकी किसी मक्कारी को चलने नहीं देंगे । अब रह गई अमेरिका की बात । बात यह है कि अमेरिका और इंगलैंड को चीन का बड़ा भारी खतरा लगा हुआ है । चीन का ऐसा हऊआ उनके सामने मौजूद है हालांकि वह हऊआ है कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी उससे बचने के लिये जो भी जायज़ नाजायज़ बात कर सकते हों करने के लिये तैयार रहते हैं। चुनांचि अमेरिका ने पाकिस्तान को मसल्लह किया और बेहतरीन आरमामेंट से मुसल्लह किया । यह कह कर कि कमयुनिज़म

का मुकाबला करने के लिये ऐसा किया जा रहा है। हमारे लीडरों ने काफी प्रोटेस्ट किया कि यह जो हथियार तुम दे रहे हो उनको लेकर पाकिस्तान हमारे मुकाबले पर आएगा लेकिन उन्होंने **हम** यकीन दिलाया कि ऐसा कभी नहीं हो सकेगा। उन हथियारों को हिन्दुस्तान के मुकाबले में इस्तेमाल नहीं होने देंगे। उनके पैटन टैंकस और सैबर जैटस हमारी सरहदों पर उसी तरह से पड़े हुए हैं जिस तरह खिलौने टूटे हुए पड़े होते हैं। हमें अपनी बहादुर फौज पर फख्र है जिन्होंने सारे हिन्दुस्तान की इज्ज़त को बरकरार रखा है और जाबियों ने अपनी बहादुरी का सिक्का सारी दुनिया पर बिठा दिया है। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हम अपनी फीलिंग्ज़, अपने जज़बात आपके द्वारा अपनी केन्द्रीय सरकार की खिदमत में पहुंचना चाहते हैं कि हिन्दुस्तान का बच्चा बच्चा आपके साथ है। लेकिन एक बात कीजिये कि मुल्क का कोई हिस्सा और कोई टुकड़ा इस वक्त हमारे मुलक के पास है, उसको ज़रा भी हम किसी तरह देने के लिये तैयार नहीं हैं और न होंगे। हम अपने मुल्क का ज़रा ज़रा खाह कितना भी फरटाइल हो, या सहराई हो, वह हमारे लिये मुतबरक है, मुकद्दस है और वह हमारे लिए पवित्र स्थान है। उस ज़रे को कायम रखने के लिये हम अपने खून का आखरी कतरा भी बहा देंगे। हम कभी भी बरदाश्त नहीं कर सकते कि हमारे मुल्क का कोई हिस्सा कोई ले लें। बहुत ही दुख की बात है कि दूसरे मुल्क कहते हैं कि आप बड़े भाई है। छोटा सा हिस्सा इनको दे दिया जाए वह कहते हैं कि वह हमारा छोटा भाई है। ऐसे छोटे भाई को दे दें जो हमारी गर्दन पर दुधारी तलवार रखता है। जो हमें खत्म कर देना चाहता है। उसने हमारी गैरत पर और इंटैगरिटी पर हमला किया। हम कभी भी बरदाशत नहीं करेंगे। हम उस को कोई भी हिस्सा हरगिज नहीं देंगे और किसी भी हालत में नहीं देंगे। हम मर जायेगे लेकिन हम कभी भी नहीं देंगे। इस रैज़ोल्यूशन के दूसरे हिस्से के बारे में पंडित मोहन लाल ने ठीक कहा है। वह बात अपनी सरकार पर छोड़ देनी चाहिए जिस तरह चाहे, उसी तरह करें। लेकिन आपकी मार्फत हाउस अपनी फीलिंग्ज का इजहार करना चाहता है और मैम्बर साहिबान फीलिंग्ज़ जाहिर भी कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारी सरकार उसी तरह मजबूत है और आयंदा के लिये भी मज़बूत रहेगी। कोई भी मुल्क हिन्दुस्तान की तरफ बद नजर उठाएगा तो उसकी आंख निकाल दी जाएगी। डिप्टी स्पीकर साहिबा, इन इलफाज़ के साथ आप का शुक्रिया अदा करता हूँ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ (ਧਾਰੀਵਾਲ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਟਰ-ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਾਬਲਮ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਲੇਕਿਨ/ਅੱਜ ਆਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ/ਚੋਕੰਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਡਤ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹਦ ਤਕ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੁਸਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚ/ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਦਾਖਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ

[ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ]

ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਮਦਾਖਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਦਾਖਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਫਾਈਨਲ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਫੀਸ਼ਲ ਡੇ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਲੋਂ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਖ਼ਿਆਲ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਦੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਬਦਲੇ। ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। 1947 ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਲਿਸੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਕ ਅਸੀਂ ਚੁਪ ਹੀ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਬਰ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਲਬਰੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਵਿਚ ਰਹੇ। ਸਾਡਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 1929 ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨ-ਵੈਲਥ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ 1947 ਵਿਚ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਅਜੇ 1947 ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਕਸਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੀ ਸੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਵਿਚ ਮੁਤਜ਼ਾਦ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਖ਼ੁਦ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਪ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਅਰਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਡਬਲ ਪਾਰਟ ਪਲੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਣਦਾਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਯੂ. ਐਨ. ਓ. ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 1947 ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਯੂ. ਐਨ. ਓ. ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਖਤ ਗ਼ਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ (ਘੰਟੀ) ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਛ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਝਗੜੇ ਵਿਚ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਵਈਆ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 5 ਅਗਸਤ, 1965 ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਇਨਫਿਲਟਰੇਟਰਜ਼ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਹਮਲਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਿਰੋਲ ਹਮਲਾ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਐਗਰੈਸਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਛੰਬ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਉਥੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਐਗਰੈਸਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਛੰਬ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 6 ਸਤੰਬਰ, 1965 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਫੌਜ ਭੇਜੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਗਰੈਸਰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਖਿਆਲ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ

ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸਵਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜੀ ਸਾਮਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਉਹ ਸਾਮਾਨ ਚੀਨ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿਚ ਚੀਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦਾ ਬੜਾ ਹੱਥ ਹੈ । ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਰਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।

ਯੂਰਪੀਅਨ ਬਲਾਕ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਰਡਵਾਰਜ਼ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਹੁਣ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਰੋਪ ਵਰਡ ਵਾਰ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਨਾ ਬਣੇ, ਇਹ ਅਖਾੜਾ ਉਥੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਖਾੜਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ । ਅਤੇ ਇਹ ਅਖਾੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ । ਅੰਗਰੇਜ਼ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਗੜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਣ ਜਾਵੇ । ਦੂਸਰੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਬਲਾਕ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਚਾਇਨਾ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਯੂਰਪ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ । ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਵਿਚ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਲੜਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੀਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੌਖਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਚੀਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਵੀ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਛਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਗੜਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਜਾਂ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਹੈ ਉਹੋ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਥੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮਾੜਾ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ । ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਭੁਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਹੈ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 1962 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਬਲਾਕ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯਰੋਪੀਅਨ ਬਲਾਕ ਸਾਡੀ ਸਦਦ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਰਵਈਆ ਵੀ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨ-ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਕੌਣ ਅਪਨਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਅਪਨਾ ਸਕਦਾ । ਤਗੜਾ ਆਦਮੀ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਅਪਨਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਕਾ

[ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ]

ਵਿਖਾ ਕੇ ਰਾਹ ਰਾਸਤ ਤੇ ਲੈ ਆਵੇ । ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੇਖ ਲੌ, ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਡਾਂਗ ਵਾਲਾ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗੋਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਮਾੜਾ ਕੁਝ ਕਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਭਲਵਾਨ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਹੈ । ਨਾਨ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਉਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਤਰਾ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਬਲਾਕਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ । ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁਧ ਹਨ । ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤਦ ਹੀ ਕਰੋਗੇ ਜਦੋਂ ਬੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੋ । ਸਾਨੂੰ 16 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅਰਸਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦਿੰਦੇ । ਪਰ ਅਸੀਂ ਟਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ । ਜੇ ਤਾਂ ਤਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਦਖਲ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਾਂ । ਕੋਰੀਆ ਵਿਚ ਅਸਾਂ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਂਗੋ ਵਿਚ ਅਸਾਂ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵੀਤਨਾਮ ਵਿਚ ਵੀ ਹੁਣੇ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਕਮਾਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਈਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਭੁਲ ਹੈ । ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਗਰੂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਰਾਹੇ ਰਸਤ ਤੇ ਚਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਗੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਤਗੜੇ ਹੋ ਜਾਈਏ । ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਤਗੜੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਤਾਂ ਚੁਪ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਵਿਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ । ਉਹ ਨਾਨ-ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਅਪਨਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਚੁਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਕਿਸੇ ਪਾਵਰ ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ । ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਚੁਪ ਹੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਨਾ ਤਗੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲ ਸਕਦੇ । ਮੈਂ ਪੰਡਤ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਨਾਲ ਮੁਤਫਿਕ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪੱਖ ਪਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬਲਕਿ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਿਚ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਨੰਗੇ ਹੋ ਖਲੋਂਦੇ ਹਨ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਦਈਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਤਕਲੀਫ ਭੁਗਤਣੀ ਪਵੇ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ amendment ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹਰ ਇਕ ਆਦਮੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਤੇ ਰੀਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਦਮ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪਾਵਰ ਬਦਲ ਜਾਵੇ ।

ਸਾਨੂੰ ਰੀਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਇਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰੀਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਉ । ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ in the meantime ਐਨੇ ਤਗੜੇ ਕਰੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ । ਧੰਨਵਾਦ ।

(At this stage S. Gurnam Singh, a Member of Panel of Chairmen, occupied the Chair.)

चौधरी नेतराम (हिसार सदर): आदरणीय चेयरमैन साहिब, आज का ग़ैर सरकारी प्रस्ताव जोकि आपोजीशन के तकरीबन सभी मैम्बरों के दस्तखतों से विचारने के लिये

हाउस में रखा गया है इस पर आपोज़ीशन के साथी जो सब से पहले इस प्रस्ताव पर बोले हैं जोकि इसके पेश करने वाले हैं, उन्होंने कामनवैल्थ के सम्बन्ध में काफी अच्छा भाषण दिया है और आज़ादी के बाद की काफी अच्छी बातें बताई हैं। उन्होंने बताया है कि हिन्दुस्तान के कामलनवैल्थ में रहते हुए ब्रिटेन ने कैसी घातक नीति इसके प्रति अपानए रखी जिस का नतीजा आज भारत भोग रहा है। परन्तु मैं आज़ादी के पहले की भी एक दो बातें हाउस के सामने रखना चाहता हूँ। जब ब्रिटन भारत पर शासन करता था तो यहां की जनता ने उनके हर फेल से, हर तौर तरीके से दुखी होकर और संसार में अपना गौरव ऊंचा करने के लिये आज़ादी की लड़ाई लड़ी और अंग्रेज़ों को यहां से खदेड़ दिया। उस समय हमारी कांग्रेस पार्टी जो स्वतंत्रता के लिये लड़ती थी उसके नेता देश के कोने कोने में यह बात कहते थे कि जब भी देश आज़ाद होगा, जब बरतानिया की गुलामी की जंजीरों से हम छुटकारा हासिल कर लेंगे तो उस वक्त अगर बरतानिया के साथ हम कोई बात करेंगे तो हमारे दरम्यान—बरतानिया और हिन्दुस्तान के दरम्यान भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और दूसरे शहीदों की लाशें बीच में होंगी और उन लाशों को सामने रखते हुए ही हम बरतानिया के साथ कोई बातें करेंगे यानी उस नज़रिये से ही हम बरतानिया को नापेंगे। लेकिन, चेयरमैन साहिब, उस वक्त के नेता जब हुक्मरान बने, जब उनकी यहां पर हकूमत बनी तो वे उस भावना को, उस आदर्श को भूल गए। उन आदर्शों को उन्होंने बालाय ताक रख कर अपनी खुदगर्ज़ी को सामने रखते हुए पाकिस्तान को माना। पाकिस्तान बनने से पहले उस वक्त के हिन्दुस्तान के नेताओं ने कहा था कि पाकिस्तान हमारी लाशों पर बनेगा, मगर अफसोस, पाकिस्तान उनकी लाशों पर नही हिन्दुस्तान के हज़ारों बिलकते हुए किसान मज़दूरों के बच्चों की लाशों पर बना। उन नेताओं ने अपने आपको बतौर हुकमरान कायभ रखने के लिये बिल्कुल अंग्रेज़ों के से हथकन्डे अपनाए, चाहे उससे देश का मान घटा, देश के गौरव को चोट लगी, चाहे देश का नुक्सान हुआ और चाहे देश की आर्थिक हानि हुई लेकिन कहते हुए दुःख होता है कि उस वक्त के नेताओं ने अपनी हकूमत को कायम रखने के लिये अपनी पहली ऐलानशुदा नीति में परिवर्तन कर लिया। चेयरमैन साहिब, मैं आपके द्वारा इस प्रस्ताव पर पूरी मज़बूती से, पूरी हिम्मत से, ज़ोरदार भावना प्रकट करना चाहता हूँ और पंजाब की जनता की तरफ से यह भावना प्रकट करना चाहता हूँ।

आज उन कांग्रेसी बैंचों पर से बोलते हुए आनरेबल मैम्बर कहते रहे हैं कि हमारे अख्तियार में कोई चीज़ नहीं है। मैं उनसे कहूँगा कि भाई, इस तरह की हीन भावना को छोड़ो। आखिर हम कौन सा कानून पास करने जा रहे हैं। इस मौके पर तो हम अंग्रेज़ों के खिलाफ पंजाब की जनता की हार्दिक भावना ही प्रकट करने जा रह हैं। ताकि भारतवर्ष की जो केन्द्रीय सरकार है वह उनके सम्बन्ध में अपनी मूल नीति को तब्दील करे जिसके कारण भारत के गौरव पर भारत की आज़ादी को खतरा है और जिसके कारण हमारे कई आर्थिक मसले सुलझने में दिक्कतें आ रही, रुकावटें पैदा हो रही हैं। चेयरमैन साहिब, जब भारत को आज़ादी मिलने के कुछ समय बाद भारत के प्राइम मिनिस्टर ने कामनवैल्थ के साथ नाता जोड़ा तो उस वक्त सोशलिस्ट पार्टी के एक महान

[चौधरी नेत राम]

नेता, जो कि दुनिया की सब से बड़ी यूनिवर्सिटी के वाइस चान्सलर रह चुके हैं, इतने अच्छे और रौशन दिमाग वाले आचार्य नरेन्द्र देव ने बिहार में, पटना शहर में एक आम सभा में भाषण देते हुए कहा था कि ऐ आज के हाकिमों, हिन्दुस्तान के प्रधान मन्त्री और बरतानियां के वक्त के हिन्दुस्तान के कांग्रेसी नेताओ, क्या तुम इस बात को भूल गये हो कि तुमने यह कहा था कि जब भारत आज़ाद होगा तो उसके बाद अगर हम अंग्रेज़ से कोई भी बात करेंगे तो उस वक्त भगतसिंह, सुखदेव, राजगुरु और दूसरे शहीदों की लाशें हमारे ध्यान में होंगी ? आज कहां गईं वह लाशें, कहां गए तुम्हारे वह वायदे ? लेकिन अफसोस, कि आज़ाद होते ही पहली हीनभावन का हथकंडा इन्होंने यह दिखाया कि फौरन भारत को कामनवैल्थ में शरीक कर लिया। इस सम्बन्ध में उन्हीं महान नेता आचार्य नरेन्द्र देव ने लेख भी लिखे । उन्होंने सन् 1948 और 1949 में लेख लिखे थे । आज 17–18 साल होने को आए हैं, देश आज़ादी के उन्नीसवें साल में से जा रहा है । इस बात को उस वक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेताओं ने लिया था, इस कांग्रेसी हकूमत को चेतावनी दी थी, उसके बाद बार बार सोशलिस्ट पार्टी ने इस सम्बन्ध में जद्दोजहद की लेकिन इस कांग्रेस के नेताओं ने, और आज के हाकिमों ने कहा कि ऐसी बातें करना बचपना है । अगर उस वक्त की ये बातें बचपना थीं तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आज आपने उनके हाथों मज़ा चख लिया है या नहीं ? आज क्यों दुनिया के अन्दर गिड़गिड़ा रहे हो कि बरतानिया ने हमारे साथ धोखा किया है हमारे साथ धक्का किया है । अगर उसी वक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेताओं की बात को ध्यान में रखते, उस वक्त से ही आपने सही पालिसी को अपनाया होता तो आज दुनिया के अन्दर हिन्दुस्तान की यह दुर्दशा न होती जो कि अंग्रेज़ों के साथ रह कर हुई है ।

चेयरमैन साहिब, यह बात कहना कितना कमज़ोरपना है कि अगर हमने कामनवल्थ से रिश्ता तोड़ लिया तो बरतानिया हमारे साथ नाराज़ हो जायगा । क्या कामनवैल्थ के अन्दर दूसरे मुल्क नहीं हैं ? क्या उनका बर्तानिया कुछ बिगाड़ रहा है ? आज चीन यूनाइटिड नेशंज में नहीं है, कामनवैल्थ में नहीं है। उसका किसी ने क्या बिगाड़ लिया है ? अमरीका कामनवैल्थ में नहीं है । लेकिन आज वह उसके साथ इसलिये मित्रता नहीं निभा रहा क्योंकि वह अमरीका है, वल्कि मैं समझता हूँ कि इसलिये क्योंकि वह ताकतवर है, वह अपनी बात किसी भी वक्त मनवा सकता है । दुनिया ताकत को मानती है। दुनिया कमज़ोरों की नहीं माना करती। अगर भारत में ताकत हो, हिम्मत हो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि चाहे भारत कामनवैल्थ में हो या न हो, चाहे यू.एन. ओ. में हो या न हो भारत की हर देश बात मानने के लिये तैयार होगा। लेकिन, चेयरमन साहिब, कांग्रेस की गलत नीति ने, कांग्रेस की पालिसी ने भारत के गौरव को घटा दिया है । भारत को इस कदर कमज़ोर बना दिया है कि आज हम उसकी सज़ा भुगत रहे हैं ।

श्री सभापति: चौधरी साहिब, कांग्रेस का कामनवैल्थ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। (I would like to point our to the hon. Member that the congress has nothing to do with the Common-Wealth).

चौधरी नेत राम: चेयरमैन साहिब, कांग्रेस से मेरा मतलब कांग्रेसी सरकार से है, कांग्रेस पार्टी से नहीं तो चेयरमैन साहिब, मैं आपके द्वारा अर्ज करूँगा कि....

एक माननीय सदस्य: इनका नाम भी यू.एन. ओ. के डैलीगेशन के लिये रेकमेंड करदो।

चौधरी नेत राम: चीन यू. ऐन. ओ. में नहीं है और न ही कामनवैल्थ में है। पाकिस्तान कामनवैल्थ में है अंग्रेज़ों के साथ उसका मुआइदा है, बरतानिया के साथ कामन-वैल्थ के अन्दर रहते हुए हर उस पालिसी को मानने का मुआइदा है जोकि इनके इन्ट्रैस्ट के खिलाफ न हो लेकिन वही पाकिस्तान आज चीन के साथ गठजोड़ किये हुए है। आज पाकिस्तान चीन के साथ मिल कर हर वह हरबा इस्तेमाल कर रहा है कि जिससे हिन्दुस्तान की ताकत को छिन्न भिन्न किया जाए, हिन्दुस्तान पर हमला करके उसकी ताकत को कमज़ोर किया जा सके। जो हमला उसने पीछे हिन्दुस्तान पर किया वह किया भी चीन की शह पर। वह आज बरतानिया के साथ भी है, अमरीका भी उसकी बात को मानता है। उसी कामनवैल्थ का वह सदस्य है जिसका नेता बरतानिया कहलाता है।

श्री जगन्नाथ: तो बरतानिया से कामनवैल्थ का नेतृत्व छीन लो।

चौधरी नेत राम: चेयरमैन साहिब, मैं आपके द्वारा यह अर्ज़ करूँ कि हमेशा दुनिया में ताकत की ही पूजा होती है इसलिये मैं इस बात की चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर कांग्रेसी सरकार की मौजूदा नीति जारी रही तो भारत कभी भी तरक्की नहीं कर सकेगा और वह एक शक्तिशाली देश नहीं बन सकेगा। इसलिये आज हमारे पास अवसर आया है कि पंजाब की यह विधान सभा कांग्रेसी सरकार की इस मौजूदा नीति को तबदील करवाने के लिये पूरी मज़बूती के साथ अपनी राए का अज़हार करे। पंजाब की जनता के दृढ़ विचार, हार्दिक भाव इस सम्बन्ध में मज़बूत शब्दों में इस प्रस्ताव के द्वारा पास करके केन्द्रीय सरकार के पास भेजे ताकि वह इस बात के लिये मजबूर हो जाए कि वह इस संस्था से अपने ताल्लुकात को तोड़े। लेकिन इसके साथ ही साथ, चेयरमैन साहिब, आपके द्वारा एक और बात निवेदन करना चाहता हूँ और वह यह है कि यहीं पर एक मन्त्री महोदय ने एक सच्ची बात कही। उसकी बाबत तो यह कहा गया कि यह बचपना है, लड़कपन है लेकिन जो गलत बात कही उसकी आलोचना नहीं की गई। उस मन्त्री महोदय ने कहा कि पैटन टैंक के केक बना कर तोड़ना बचपना है। उस पर तो प्रधान मन्त्री श्री लाल बहादुर शास्त्री को खुश करने के लिये इन लोगों ने हंगामा छेड़ दिया कि साहिब यह क्या कह दिया। यह गलत बात है, लेकिन

[चौधरी नेत राम]

उसी मन्त्री ने उसी लहज़े में जब यह कहा कि अमरीका और बर्तानिया को नाराज़ मत करो, उनको खुश रखो तो उस वक्त किसी ने नहीं कहा कि यह क्या बचपने की बातें हैं। क्या पेटन टैंक के केक बना कर उनको तोड़ने से पैटन टैंक टूट जायेंगे ? उनको तोड़ा जायेगा ताकत से और वह ताकत हमें अपने अन्दर पैदा करनी होगी। जब बर्तानिया और अमरीका भारत के साथ खुल्लमखुल्ला विश्वासघात कर रहे हैं तो उनके साथ अपना नाता तोड़ लेना चाहिए, उन्हें यह कहना चाहिए था। अफसोस से कहना पड़ता है कि जब वे देश हमारे साथ खुल्लमखुल्ला ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, हमारे खिलाफ हमारे शत्रु को भड़काने वाली कार्यवाहियां कर रहे हैं हमने उनके साथ अपने सम्बन्धों पर पुर्नविचार करने की बाबत नहीं सोचा। मैं चेयरमैन साहब आपसे क्या अर्ज़ करूँ। यह सरकार....

12.00 Noon

श्री सभापति (सरदार गुरनाम सिंह): कौन सी सरकार की बात करते हैं आप ? (Which Government the hon. Member is refering to ?)

चौधरी नेतराम इस कांग्रेस सरकार की बात कर रहा हूँ।

श्री सभापति: आप रैंजोल्यूशन पर ही बोलें। आपने जो कुछ कहना है इसी पर कहें। (The hon. Member should restrict his speech to the resolution now under discussion)!

चौधरी नेतराम: मैं चेयरमैन साहब, इसी पर ही बोल रहा हूँ। और बता रहा हूँ कि इस सरकार ने जो गलत काम किये हैं वह देश के लिये बड़े नुक्सानदेह साबत हुए हैं। इसने आज तक देश के आर्थिक मसलों को हल नहीं किया और इसकी वजह से हमारे देश का जो आर्थिक ढांचा है वह कमज़ोर हो गया है और इसकी वजह से हमारे देश को अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाने के लिये मजबूर कर दिया है--

श्री सभापति: चौधरी साहब, इस वक्त हाउस के सामने सवाल यह है कि इसने कामनवैल्थ में रहना है या नहीं रहना। आप इसी बारे में बोलें। (The hon. Member Ch. Net Ram should please note that now resolution before the House is whether or not our country should continue to be member of the Commonwealth. He should confine his speech to it.)।

चौधरी नेतराम: हमने इसमें नहीं रहना है और इसके लिये हमने वार्निंग दी हुई है। लेकिन यह सरकार कहती है कि हमने कामनवैल्थ से निकलना नहीं है क्योंकि यह समझती है कि इसमें भारत को घाटा है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या इस बात में घाटा नहीं है कि हमारा देश कमज़ोर होता जा रहा है। आपको याद होगा कि अमेरिका ने पाकिस्तान को हथियार देते हुए कहा था कि यह हथियार हिन्दुस्तान के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान नहीं इस्तेमाल करेगा लेकिन उसने इनको इस्तेमाल किया है ....

श्री सभापति: चौधरी साहब, अमेरिका तो कामनवैल्थ में नहीं है। (The hon. Member should not forget that America is not a member of the Commonwealth.)

चौधरी नेतराम: लेकिन चेयरमैन साहिब, आज इनकी गलत पालसियों की वजह से आज देश में भूखमरी बनी हुई है और इसके लिये हम अमेरिका से अनाज लेने के

लिये मजबूर हो रहे हैं और इसके बदले में अमरिका कश्मीर के मसला पर अपनी बात हम पर दवाब डाल कर मनवाना चाहता है। मुझे इनकी इस बात की समझ नहीं आती कि क्या इस सरकार ने देश को कमज़ोर बना दिया है और देश को दूसरे मुल्कों का अनाज लेने के लिये मोहताज बना दिया है, यह यही अनाज यहां क्यों पैदा नहीं करवाती ? मैं इन से पूछता हूँ कि इसके लिये इसको कामनवैल्थ में रहने से क्या लाभ है ? अमेरिका खुद भी कामनवेल्थ में शामल नहीं है और जो दूसरे देश कामनवैल्थ में शामल नहीं हैं क्या वह अमेरिका से दोस्ती नहीं रखते । क्या इरान और ट्र्की जोकि कामनवैल्थ में नहीं हैं अमेरिका से दोस्ती नहीं बनाए हुए और क्या उनको अमेरिका से हथियार नहीं मिल रहे ?

सरदार बलवंत सिंह: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर । चेयरमेंन साहब, अगर यह ऐसी बात कहने से न हटे तो हमारी तरफ से चौधरी सुन्दरसिंह बोलने के लिये और इनकी बातों का जवाब देने के लिये तैयार हो जाएंगे ।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज़ । (Order please)

चौधरी नेतराम: आज भी हम देखते हैं कि इस जंग के दौरान जो हथियार अमेरिका और बर्तानिया ने पाकिस्तान को दिये थे वह उसने हिन्दुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किये हैं। और जब जंग चल रही थी तो ट्र्की और इरान ने भी पाकिस्तान को हथियार दिये थे और आज भी दे रहे हैं।

चौधरी सुन्दर सिंह (राज्य मन्त्री): चौधरी नेत राम ने फर्माया है कि हिन्दुस्तान कामनवैंल्थ में से निकल जाए । मैं उनसे कहता हूँ कि भारत तो कामनवैल्थ में रहेगा लेकिन इन्होंने विधानसभा का मेम्बर नहीं रहना।

Mr. Chairman (S. Gurnam Singh) : This is no point of Order and is least expected of a Minister.)

चौधरी नेतराम: चेयरमैन साहब, एक तो यह हरिजनों के मिनिस्टर हैं और वैसे भी सीधे सादे आदमी हैं इस लिये मैं इनकी बात का इनको जवाब नहीं देता। इनको इतना भी पता नहीं कि मुझे जनता ने यहां चुन कर भेजा हुआ है और यह न इनके हाथ में है कि मुझ को यह यहां से निकाल दें और न ही इनकी गवर्नमैंट के हाथ में है और न ही यह असैंबली ही मुझे हटा सकती है ।

तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि जो हथियार ट्र्की या इरान पाकिस्तान को दे रहे हैं वह उन देशों के अपने बनाये हुए नहीं हैं। वह तो बर्तानिया ने ही उन्हें दिये हुए थे और आज बर्तानिया चाहता है कि पाकिस्तान हिन्दुस्तान से लड़े ताकि यह एक कमज़ोर देश बना रहे । यह भारत को एक शक्तिशाली देश बनता नहीं देख सकता। यह चाहता है कि हिन्दुस्तान जो एक जमहूरी मुल्क है यह कमज़ोर हो क्योंकि अगर यह ताकतवर बन गया तो इसके सामराज्यवाद को खतरा पैदा हो जायेगा । यह सब इस सरकार की गलत पालिसियों की वजह से हो रहा है । जब यह देश आज़ाद हुआ था

[चौधरी नेत राम]

तो बर्तानिया ने हमारे देश का 44 अरब रुपया देना था लेकिन इनकी गल्त पालिसियों की वजह से वह सारे का सारा इसने खत्म कर दिया। उसमें से इसने 22 अरब रुपये तो उसे मुआफ ही कर दिये और बाकी के 22 अरब रुपये के लिपस्टिक और पाऊडर मंगवा मंगवा कर खत्म कर दिये । एक तरफ तो यह सरकार इस तरह अरबों रुपये देश की जनता के तबाह कर रही है और दूसरी तरफ आप देखें कि जो हमारे गरीब कर्मचारी हैं उनको दो वक्त रोटी ही नसीब नहीं हो रही । आप असैंबली के क्लर्कों और रिपोर्टरों को ही देखिए । यह बेचारे 24, 24 घंटे काम करते हैं लेकिन इनको इतनी तनखाहें नहीं मिलतीं जिनसे यह अपना और अपने बाल बच्चों का पेट पाल सकें। इनको किसी तरह की कोई सुविधा नहीं दी जाती मगर दिन रात यहां काम करते रहते हैं। इनको न तो कोई ओवर टाइम ही मिलता है और न ही कोई ज्यादा देर तक काम करने का किसी भी शक्ल में इवज़ाना मिलता है । यह सब सरकार की गल्त नीतियां हैं जिनकी वजह से देश दिन बदिन कमज़ोर होता चला जा रहा है । इसलिये मैं हाउस से अपील करता हूँ कि वह इस रेज़ोल्यूशन को पास कर दे और सैंटर की सरकार को ज़ोर देकर कहे कि वह कामनवेल्थ में से निकल जाए।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ (ਨਾਭਾ) : ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਤਾਲਕ ਹੈ —

This House recommends to the Government to draw the attention of the Union Government to the general feeling. . . . . .

ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟਰਾਂਗ ਫੀਲਿੰਗਜ਼ ਅਤੇ ਸਟਰਾਂਗ ਰੀਜ਼ੈਂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੀਕਮੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜੰਗ ਵਿਚ ਜੋ ਪਾਰਟੀਜ਼ਨ ਐਟੀਚੂਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਰੀਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਨਾਸਬ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇ । ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੈਜ਼ੂਲੀਊਸ਼ਨ ਇਥੋਂ ਤਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ । ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੈਜ਼ੋਲੀਊਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਇਹ ਰੀਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਨੂੰ ਕੁਇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿਚ ਜੋਸ਼ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਅੌਰ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹਨ, ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਲੀਊਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਨਹੀਂ ਛੋੜਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸਗੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦੀ ਕੰਪੋ-ਜ਼ੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਅੌਰ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ । ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਕੰਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ 17 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਰਿਟਨ, ਕਨੇਡਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨੀਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਚਾਰ ਵਾਈਟ ਰੇਸ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹਨ ਅੌਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਘਾਨਾ, ਸਿੰਘਾਪੁਰ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਨਾਈਜੇਰੀਆ, ਟਾਂਗਾ ਨੀਕਾ, ਆਦਿ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ ।

ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਕਾਮਨ ਫੋਰੱਮ ਹੈ । ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਂਪਾਇਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਛੁਪਦਾ । ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਖਰ ਹੈ, ਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਂਪਾਇਰ ਦਾ ਸੂਰਜ ਸਦਾ ਲਈ ਡੁਬੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦੀ ਹੈਡ ਕਵੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਗਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੇ ਇਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਰਿਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਂਪਾਇਰ ਦਾ ਸੂਰਜ ਡੁਬੋ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਵਿਚੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ । ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜੋ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕਹਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਪਾਰਟੀਜ਼ਨ ਐਟੀਚੂਡ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ।

A Voice: Impossible.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ : Word 'impossible' is found in the dictionary of fools.

(ਵਿਘਨ) ਕੀ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਬੁਜ਼ਦਿਲੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ।

Mr. Chairman : You can settle this outside the House.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ : ਇਹ ਡਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਚੀਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰਨ ।

ਕਾਮਰੇਡ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ : On a point of order, Sir. ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ?

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ : ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਸਰਹਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹੀ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ । ਉਹ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ......

Mr. Chairman : Let us not go into that question.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ : ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਾ ਸਕਣ ਉਥੋਂ ਉਹ ਵਾਕ ਆਊਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਸਾਡੇ ਵਿਯੂ ਵਿਚ ਸਚਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਫਰੀਕੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਵਿਚੋਂ ਕਢੀਏ ਅਤੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦਾ ਹੈਡ ਕੁਆਰਟਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀ ਵਿਚ ਰਖੀਏ । ਅਗਰ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦੀ ਕੁਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ । ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ । ਪਿਛਲਾ ਜਦੋਂ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਨ ਦਾ ਅਗਰ ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਡੀਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਅੱਜ ਵੀ ਉਸਦੀ ਇਹੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਥੇ ਫੁਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ । ਫਿਰ ਦੋ ਟੋਟੇ ਬਣਾਏ । ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੜਾ ਪਾਰਟੀਜ਼ਨ ਐਟੀਚੂਡ ਅਪਣਾਇਆ । ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਛਡਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਤਾਂ ਤਦ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕਢ ਦੇਈਏ ਅਤੇ ਆਪ ਨਾ ਨਿਕਲੀਏ ।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : (ਮੁਰਿੰਡਾ, ਐਸ. ਸੀ.) : ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਮਤਾ ਕਾਮਰੇਡ ਜੋਸ਼ ਨੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲ-ਫਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਕਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਤਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਤੇ ਦੋ ਸੌ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਰਖ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਕ ਬੜੀ ਗੰਦੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ । ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਐਸੇ ਮਸਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਦੇਸ਼ ਆਪਸ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕਣ । ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਪਾੜਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ । ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਲੰਗੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ । ਇਸੇ ਲਈ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਬਣਾਈ । ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਮਿਲੇਗਾ ਮਗਰ ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹ ਮੁਖਾਲਫ ਹੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜਦ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹਿਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪਿਠ ਵਿਚ ਛੁਰਾ ਘੋਂਪਿਆ । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਮਦੱਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਘਟੋ ਘਟ ਨੀਉਟਰਲ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ । ਇਹ ਜੋ ਹੁਣੇ ਜੰਗ ਹੋਈ ਇਹ ਵੀ ਐਂਗਲੋ ਅਮਰੀਕਨ ਬਲਾਕ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਹੋਈ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ । ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਵੇਖਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣੇ ਰਹੀਏ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਟੇ ਖਾਂ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਗਲਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਵਿਚੋਂ ਕਢ ਦਿਉ । ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੀਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਪਾਟੇ ਖਾਂ ਬਣਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿਚ ਰਖ ਸਕਣ । ਮਗਰ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਨਾਪਾਕ ਰੋਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਭਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਅੱਜ ਵਕਤ ਹੈ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛਾਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਕੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਮਦੱਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ? ਸੀਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਜਦ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਐਂਗਲੋ ਅਮਰੀਕਨ ਬਲਾਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ਰੀਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ।

ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਨੂੰ ਕਵਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਕਾਫੀ ਖਰਚਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇਕ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਨੂੰ ਕਵਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । (ਵਿਘਨ) ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਭਾਈ ਜਾਣਗੇ ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਜੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ । ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰੈਜ਼ੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । (ਵਿਘਨ) ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ । ਦੀ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਡਯੂਰਿੰਗ ਦੀ ਕੋਰਸ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਸਪੀਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕੋਈ ਹਕਮਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਇਸ ਰੈਜ਼ੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ । (ਵਿਘਨ)

12.20 p.m.

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰੀਸੈਂਟ ਜੰਗ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਹੱਥ ਵਟਾਇਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਸਤੀਨ ਦਾ ਸਪ ਬਣ ਕੇ ਡਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕੀ ਸਬੰਧ ਤੋੜ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਵਿਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਮੁਲਕ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੂਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਸ ਵਰਗੇ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਮੁਲਕ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾਪਾਕ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸਟ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਵੱਡੀ ਨਾਪਾਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ । ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੂਸ ਵਰਗੇ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਆੜੇ ਵਕਤ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 200 ਸਾਲ ਤਕ ਗੁਲਾਮ ਰਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਸਾਨੂੰ ਨੀਵਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਵਕਤ ਤਾਕ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਇਤਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ । ਪਰਤਿਆਏ ਹੋਏ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਪਰਤਿਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਰਵ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੀ ਹਰ ਵਕਤ ਮਦੱਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਨੰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ।

ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ (ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ) : ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ੂਲੇਸ਼ਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਸਟਡੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਰੌ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਜੋ ਦੋਸਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਦੱਦ ਇਮਪੀਰੀਲਿਸਟ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਵਿਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ । ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਇਕ ਮਿਤਰ ਨੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਨੂੰ ਕਵਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ । ਹਰ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫਾਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਇਨਟ੍ਰੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ

[ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ]

ਵਿਚ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਆਪੋ ਵਿਚ ਲਿਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਫਾਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਵਰਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਟੇਟਸ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹਰ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਾਵਰਨ ਕਾਨਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਤੋਂ ਅਲਗ ਹੋ ਜਾਈਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫਾਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨਲ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਸਬਜੁਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ । ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲਤ ਸਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਫਸੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਨੰਗੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਜਿਪਟ ਦੀ ਮਦੱਦ ਕੀਤੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਾਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨਲ ਪਾਲੇਸੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ । ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਤਾਂ ਇਕ ਲਿੰਕ ਹੈ ਕਲੋਨੀਅਲ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਐਫਰੋ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਜਾਰਟੀ ਹੈ । ਇਹ ਇਕ ਫੋਰਮ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਿ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਇਡੀਆਜ਼ ਨਾਲ ਇਨਫਲੂਅੰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਮ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦਾ ਹੈ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਮ ਖ਼ਿਆਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉਤਾਂਹ ਉਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਰਖਦਾ ਹਾਂ । ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਤੋਂ ਕਵਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵੀ ਇਸ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦਾ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਨੰਗੇ ਹੋਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਰਮਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੰਗੀ ਸਾਮਾਨ ਦਿੱਤਾ । ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂ. ਐਨ. ਓ. ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਗ ਕਹਿ ਕੇ ਸਦਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਯੂ. ਐਨ. ਓ. ਨੇ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਕਿ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦਾ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਉਠ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਵੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਝਗੜਾ ਦੋ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੋਵੇ । ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਲਡ ਪਾਲੇਟਿਕਸ ਵਿਚ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦਾ ਕੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ । ਜਦ ਚੀਨ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ (The hon. Member Sardar Balwant Singh was still in possession of the House when the next item on the list of Business was taken up.)

ANNUAL ACCOUNTS OF THE PEPSU ROAD TRANSPORT CORPORATION FOR THE YEAR 1962-63 TOGETHER WITH FINANCIAL REVIEW AND AUDIT REPORT

Mr. Chairman (Sardar Gurnam Singh) : The House will now resume discussion on the motion—

> "That the Annual Accounts of the Pepsu Road Transport Corporation for the year 1962-63 together with the financial review and Audit Report laid on the Table of the House on the 15th September, 1964, be discussed."

The hon. Member Comrade Gurbaksh Singh was on his legs last time. He may resume his speech.

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ (ਨਿਹਾਲਸਿੰਘ ਵਾਲਾ) : ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਨੂਅਲ ਅਕਾਊਂਟਸ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ । ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਦਜੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਪਲਾਨ ਵੇਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ—

(ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਫੂਲ, ਪੈਨਲ ਆਫ਼ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਸੰਭਾਲੀ)

ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨੇਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਜ਼ਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਪਲਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਪਸੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੋ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਪਲਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਨ ਕਿ ਰੋਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨੇਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੈਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ । ਉਸ ਪੈਪਸੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨੇਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ । ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਕ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । (ਵਿਘਨ)

ਚੀਫ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ : ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਨਲਾ-ਇਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ 1969 ਵਿਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । (ਵਿਘਨ)

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜੰਮ ਪਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਕਤਅਨ ਨਾਵਾਕਫ ਹਨ । ਜਿਹੜੀ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1956 ਦੇ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਇਕ ਹਵਾਲਾ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ, ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਉਸ ਵਿਚ ਇਹ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤਕ ਯਾਨੀ 1959 ਤਕ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 1969 ਤਾਈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇਹ ਪੈਪਸੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ । ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚੰਦ ਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਇਹ ਚੰਦ

[ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ]

ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਾਪਲੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਰੇਡ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਚਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ । ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਪਲੈਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੂਲੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ । ਹੁਣ ਇਹ 1969 ਵਿਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਫੇਰ ਇਹ 1972 ਵਿਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਊਠ ਦੇ ਬੁਲ੍ਹ ਵਾਂਗ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੇ ਲਮਕਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਮੁਆਮਲੇ ਨੂੰ ਖਟੇ ਪਿਆਂ ਇਹ ਹੋਰ ਲਮਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ । ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਲ ਤੁਰੰਤ ਲਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਮਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਰੂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਨਰਮ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲਿਆ ਹੈ । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਕ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ । ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹੋ ਜੇਹੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ । ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੋਆਪਰੇਟਰਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਹੈ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹੋ ਵਜਾਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਸ਼ਲਾਘਾ-ਯੋਗ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁਕੇ ਗਏ । ਮੈਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਦੋ ਮਿਸਾਲਾਂ ਆਪਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਖੇਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ।

ਪੈਪਸੂ ਮੋਟਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਡੀਪੂ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਲੇ–ਲੈਂਡ ਮਾਰਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ । ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਇਹ ਡੀਪੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਲੇ–ਲੈਂਡ ਫਰਮ ਨੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਿਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 40 ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ 20 ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ । ਪਰ ਡੀਪੂ ਇਸ ਲਈ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿਚ ਲੇ–ਲੈਂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਡੀਪੂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਰਾਈਵੇਟ ਮੋਟਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਗਠ–ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿਚ ਲੇ ਲੈਂਡ ਡੀਪੂ ਫੌਰਨ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਬਸ ਸਰਵਿਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਗਡੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕ ਰੋਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ।

ਪੀ. ਟੀ. ਏ. ਨੇ ਇਕ ਰੂਟ ਪਬਲਿਕ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਹੰਦ ਚਨਾਰਥਲ ਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਤਕ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲਮਕਦਾ ਹੀ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸਦੀ ਵਜਾਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਿਲ ਆਇਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੰਪ ਬਠਿੰਡਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਹਿਸਾਰ ਆਦਿ ਵਿਚ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ।

ਬਠਿੰਡੇ ਵਿਚ ਇਕ ਆਈ. ਓ. ਸੀ. ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਪੰਪ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਵੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਤਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ।

(ਇਕ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ : ਕੋਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ)। (ਘੰਟੀ ਵਜਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਕੋਰਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ।)

ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਪ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ? ਪਰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੁਆਮਲੇ ਨੂੰ ਐਡਮਨਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰੈਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਕਾ ਹੀ ਏਧਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ । ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੰਪ ਹਨ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਉਭਰ ਆਈਆਂ ਸਨ । ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਦੇ ਡੀਪੂ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਟਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਵਈਆ ਹੁਣ ਬਦਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਨਿਸਟਰ ਅੱਗੇ ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪੈਪਸੂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 18 ਲਖ ਰੁਪੈ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ । ਜੇ ਇਹ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਖੁਲ੍ਹੇ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿਚੋਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 18 ਲੱਖ ਦਾ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ । ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੈਨੂੰਫੈਕਚਰਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪਾਰਟਸ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਸੇਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ 25 ਪਰਸੈਂਟ ਕਮੀਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਇਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ 25 ਜਾਂ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਡੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਡੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਮੀਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਕਾਨਟਰੇਕਟਰਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸਾ ਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜੇ ਇਹ ਪਾਰਟਸ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ । ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੀ ਤਵਜੁਹ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਵਲ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਰੁਪਿਆ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀ ਸਜੈਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੈਪਸੂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਗਾ ਕੇ ਖਰਾਦ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਖ਼ਿਆਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ

[ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ]

ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਨਿਸਟਰ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਉਥੇ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਘਿਉ–ਖਿਚੜੀ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ । ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਇਹੋ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ । ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਕਾਮਰੇਡ ਭੌਰਾ ਨੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਪੁਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੂਨੀਅਨ, ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਰਿਕਾਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ? ਲੇਕਿਨ ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੀਤ ਹੈ । ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ :

"Review on the Annual Report on the working of the Industrial Disputes Act, 1947, in the Punjab During the year 1963".

ਇਸਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਪਾਰਟ (4) ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ:

"The State Evaluation and Implementation Committee was re-constituted for one year in 1963 but no meeting of this Committee was held during this year. Six managements recognised the unions of their workers during this year under report particulars of which are given below:—

Serial No.	Name of the Management	Name of the Union recognised
1.	M/s Pepsu Road Transport Corporation, Patiala.	Pepsu Road Transport Corporation Workers Union Patiala.

ਮੈਂ ਇਹ ਕੋਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਦਨ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਰੀਕਗਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ 'ਨਾ' ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਇਕ ਬੰਦਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਔਰ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਚੰਦਾ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਵਸੂਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਦੂਜੀ ਸਹੂਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਕਮਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਟ੍ਰਿਬੂਨਲ ਦੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ । ਅਸਲ ਵਿਚ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।

ਫੇਰ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਇਮਪਲਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਇਕ-ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ । (ਘੰਟੀ) ਬਸ, ਮੈਂ ਇਕ ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ । ਬੋਨਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ । ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੈਪਸੂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਡਿਸਪੂਟ ਨੂੰ ਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਏ । ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੈਪਸੂ

ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਪੀਪਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਹੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਜਿਹੜੀ ਕੈਰੋਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ । ਪੈਪਸੂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰੂਟਸ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਮਗਰ ਅਸੂਲ ਚੰਗਾ ਸੀ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਵਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ।

सरदार रणजीत सिंह नैनावालिया (माहल कलां) : जनाब, सफा 16 में, रिपोर्ट में जो कुछ दिया गया है, उसके बारे में एक बड़ा भारी स्कैंडल है। लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं लिखा गया –– तो जनाब चेयरमन साहिब, 12 पी. ग्रार. टायर का ग्रार्डर दिये पी. ग्रार. के टायर एक्सेप्ट कर लिये विदग्राऊट रिड्यूसिंग दी प्राइस। ग्राप इनकी यूटिलिटी देख लीजिये ।

> "36 imported cordatic tyres of 8.25X20X12 P.R. with tubes and flaps were ordered at a total cost of Rs.14,040 against orders placed on the 8th August, 1962, and 1st October, 1962, for 18 sets each. Actually, however, tyres of 6 ply rating were received and accepted without any reduction in price. Out of this, 24 tyres put on vehicles rendered on the average 11,714 miles service each....."

Mr. Chairman (Shri Rup Singh Phul) : The hon. Member may please take his seat. There is no quorum in the House.

(At this stage quorum bells were sounded till the House was in quorum).

Mr. Chairman : The hon. Member, Sardar Ranjit Singh, may please continue his speech.

> "The normal average service rendered by tyres of 12 ply rating of standard makes during 1962-63, was 41,702 miles. The remaining 12 tyres are still in stock".

सरदार रणजीत सिंह नैनेवालिया: जनाब, यह कितना भारी स्कडल है। पब्लिक चाहती है कि नेशनलाईजेशन हो ताकि फायदा हो । हम काम चलाते हैं। मगर यह स्कैंडल हो रहा है। ग्रार्डर दे रहे हैं। 12 पी. ग्रार का ग्रौर ले रहे हैं 6 पी. ग्रार। मैं मिनिस्टर साहिब से दरखास्त करूँगा कि इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए। जो ग्रफसर इसमें इन्वाल्व हैं विदाउट ऐनी फीयिर ग्रौर फेवर दे शुड बी पीनेलाइज्ड। सफा 15 पर बताया है कि 1961–62 में इनके पास 152 बसों का फलीट था ग्रौर 1962–63 में 134 का। मुझे इत्तलाह मिली है कि 1964–65 में यह 230 एरेंज कर दी है। जो

[सरदार रणजीत सिंह नैनेवालिया]

मुनाफा है एक्सपैंडीचर वगैरा करके वह प्राफिट है वह इस तरह है--1961-62 में 27 पैसे पर बस माईल है और 1962-63 में भी 27 पैसे है। प्राफिट में कोई फायदा नहीं हुआ। जो इफैक्टिव माइलेज है वह 1961-62 में 67 लाख थी और 62-63 में 80 लाख थी। मुझे जहां तक इसका पता है जो एवरेज इस वक्त चल रही है वह इससे आगे बढ़ गई है। जनाब चेयरमैन साहिब अगर हमें मुनाफे में इजाफा नहीं होना है तो फिर कोई फायदा नहीं। इफैक्टिव माइलेज बढ़ रही है मुनाफा वहीं खड़ा है। एस्टबलेशमेंट चार्जिज बढ़ रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के चार्जिज बढ़े हैं मुनाफा नहीं बढ़ाया गया। मैं तो मिनिस्टर साहिब से दरखास्त करूँगा कि वह इसकी भी इन्क्वायरी करें कि हमारा मुनाफा क्यों नहीं बढ़ रहा है। 1961-62 में प्राफिट 18 लाख रुपये का था, 1962-63 में 21 लाख था और 1963-64 में 27 लाख रुपये हो रहा है। यह हमारा प्राफिट बढ़ रहा है। यह अच्छा फीचर है। हम प्राफिट पर इन्कम टेक्स मोर दैन 50 परसेंट सैंटर को देते हैं जो 22 लाख रुपये के करीब सैंटर को दे चुके हैं। हम सेल्ज़ टैक्स 12 परसेंट दे रहे हैं, 10 परसेंट इस स्टेट को और 2.2 परसेंट के करीब बाहरली स्टेटों को। पैसेंजर टैक्स 25 परसेंट देते हैं जो 27 लाख दे चुके हैं। रोड टैक्स 2750 रुपए फी बस के हिसाब से हम 7 लाख के करीब दे चुके हैं। हम अपनी स्टेट को 94 लाख के करीब प्राफिट दे चुके हैं। यह बड़ा अच्छा फीचिर है। चेयरमैन साहिब, यह बात कम्पेयर कीजिये। पंजाब रोडवेज़ सैंटर को दो परसेंट सेल्ज़ टैक्स दे रही है। पैप्सू रोडवेज़ इन्कम टैक्स 51 परसेंट सेल्ज़ टक्स 12 परसेंट और पेसैन्जर टेक्स दे रही है। पंजाब रोडवेज़ यह टैक्स नहीं दे रही। मैं मिनिस्टर साहिब से यह दरखास्त करूँगा कि वह पैप्सू रोडवेज़ को पंजाब रोडवेज़ के एट पार ले आएं। आखिर इससे पंजाब के स्टेट को इन्कम ही आएगी जैसे कि पैप्सू रोडवेज़ से स्टेट में आ रही है। इन दोनों को एट पार कर दीजिये। हमारी पैप्सू रोडवेज़ की इन्कम काफी ज्यादा हो रही है। यह नेशनलाइज़ेशन के लिये फायदे वाली चीज़ है। वह इन्कम तो हमारी ही है। इससे नेशन्लाइज़ेशन करने के लिये जो व्यू है उसकी एक पिक्चर आ जाएगी। चेयरमैन साहिब मैं एक और दरखास्त करूँगा कि हमने डाज गाड़ियां 171 खरीदी थीं और वह बिल्कुल फैल्योर साबित हुईं। यह किन्होंने खरीदीं किन्हों ने मुनाफा खाया इसका पता नहीं। उसकी सरविस फायदे वाली बात नहीं हुई उसके बारे में भी एक इन्क्वायरी करनी चाहिए। यह क्या बात है कि इतने ब्रेक डाऊन्ज़ होते हैं। डाज के इंजन में कोई नुक्स है। उसमें इफैक्टिव सरविस नहीं दी। वहां डाज एक फैल्योर साबित हुई है। अब यह 80 या 90 के करीब लेलेण्ड खरीद रहे हैं। यह पहले क्यों नहीं खरीदीं। अब क्यों ऐसा कर रहे हैं? मैं फिनांस मिनिस्टर से दरखास्त करूँगा कि यह नुकसान हो रहा है। पब्लिक से रुपया लेकर पब्लिक को फायदा नहीं दे रहे। चेयरमैन साहिब मैं एक और दरखास्त करना चाहता हूँ। पैप्सू रोडवेज़ कारपोरेशन का जो फलीट चल रहा है उसमें 213 के करीब गाड़ियां चल रही हैं। और 28,000 आप्रेटिव माइल कवर करती हैं। लेकिन प्राइवेट सैक्टर में 650 बसें चलती हैं और वह 37000 आप्रेटिव माइलज़ कवर करती हैं। चेयरमैन साहिब मैं आपके ज़रिये दरखास्त करूँगा कि यह

650 बसें जो चल रही हैं वह इसमें एक या दो कम्पनियां ऐसी हैं जिनकी बहुत सी बसें हैं। मैं यह समझता हूँ कि प्राइवेट सैक्टर को हमें अगर इन्कर्ज करना है तो उनको छोटे छोटे रूट दीजिये लेकिन यहां मनाप्ली बनी हुई है। प्राइवेट सैक्टर में भी दो चार इतनी बड़ी कम्पनियां हैं जो सारे पैप्सू में छाई हुई हैं वह हर चीज़ के टैक्स में इवेज़न कर रही हैं। उन्हें मनाप्ली दी गई है और पैप्सू रोडवेज की मनाप्ली तोड़ रहे हैं। दो चार प्राइवेट कम्पानियों वालों की मनाप्ली बनाई गई है। उसमें तमाम अफसर शामिल हैं। यहां तक कि शायद हमारे मिनिस्टर भी उनके ज़ेर असर हैं। कितनी हैरानी

1.00 p.m.

की बात है कि यही दो चार बड़ी बड़ी कम्पनियां चारों तरफ नज़र आती हैं और उनकी बसें ही हर रूट पर चलती नज़र आती हैं। जो भी नया रूट निकलता है वह इन्हीं बड़ी कम्पनियों को मिलते हैं और हर बात में उनका ही फेवर होता है। एक तरफ तो यह ऐलान करते हैं कि प्राइवेट सैक्टर को डिसक्रेज करना है और नेशनलाइज़ेशन की बातें करते हैं दूसरी तरफ इन चंद बड़े बड़े कैपीटलिस्टस को बसों की मनाप्ली दी जा रही है। मैं चाहता हूँ कि वज़ीर साहिब, इस बात की इन्क्वायरी करायें कि आखिर इन चंद बड़ी बड़ी बस कम्पनी वालों को क्यों इतना फेवर किया जा रहा है। यही कम्पनियां हमारे खिलाफ ज़ोर शोर से प्रापेगंडा कर रही हैं और नैशनलाइज़ेशन के खिलाफ प्रापगंडा कर रही हैं। अगर आप नैशनलाइज़ेशन की तरफ जाना चाहते हैं तो फिर हमारा जो हमला हो वह पहले इन बड़े बड़े मनापलिस्टस पर होना चाहिए और इनको डिसक्रेज़ करना चाहिए और छोटे छोटे बस वालों को पहले नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। एक दरखास्त मैं यह करना चाहता हूँ कि यह ब्रेक डाउनज़ को बीमारी बहुत ज़ोर पकड़ती जा रही है और चार पांच साल से तो यह बाकायदा एक फीचर बन गया है कि ब्रेक डाउन होते हैं। सैशन में दो बजे आना होता है तो बनूड़ के पास ब्रेक डाउन हो जाता है। रात को आखरी बस से जाते हैं तो रास्ते में बस का ब्रेक डाउन हो जाता है और सवारियां औरतें बच्चे आदमी रात को खराब होते हैं। हैरानी इस बात की होती है कि बसें वर्कशाप से तो अच्छी निकलती हैं, अड्डे पर इन आर्डर होती हैं लेकिन दस मील पर जा कर ब्रेक डाउन हो जाता है। आखिर इसकी वजह क्या है? मैं समझता हूँ कि वर्कशाप का जो ऐडमिनिस्ट्रेशन है उसमें कोई न कोई खराबी है। वहां जो अफसरों, टैकनीशियन्ज़ अप्रेटर्ज़ वगैरा में कोई रस्साकशी है जिसकी वजह से मशीनें खराब होती जा रही हैं। इसकी इन्क्वायरी होनी चाहिए। मुझे पता लगा है कि वहां अफसरों और दूसरे मुलाज़मों में दो दो चार चार पार्टियां बनी हुई हैं। कोई किसी को फेवर करता है कोई किसी को फेवर करता है और इस तरह सख्त पार्टी बाज़ी चलती है लेकिन नुकसान पब्लिक उठा रही है। इसकी जरूर इन्क्वारी कराई जाए। फिर आप देखें जितने अड्डे हैं वहां पैसिंजर्स के लिये शैडज़ का इन्तज़ाम नहीं है। कहीं दो चार बैंच तो बना दिये हैं लेकिन पूरी फैसिलिटीज़ नहीं है। पटियाला को ही देख लें कितना बड़ा अड्डा है लेकिन मुसाफिरों के लिये दो चार बैंचों के

[सरदार रणजीत सिंह नैनावालिया]

अलावा और कुछ नज़र नहीं आता है। और तो छोड़ो गरमियों के दिनों में ठंडा पानी पीने का कोई इन्तजाम नहीं है। आप जाकर देख लें कि अफसरों के लिये तो रीफ्रजीरेटर लगे हुए हैं, उनके लिये कारें हैं नौकर चाकर हैं लेकिन जिन पैसिंजर्स की वजह से उनको इतनी फैसिलटीज़ मिली हुई हैं उनका उन्हें कोई ख्याल नहीं है। सख्त गर्मी में ठंडा पानी तक पीने को नहीं मिलता है। अगर कहीं रीफ्रजीरेटर लगा भी है तो वह इन आर्डर नहीं होता। फिर बठिंडा की बात मैं आपको बताता हूँ कि वहां एक यूरीनल और लैटरीन बनाई गई थी लेकिन उसे बने एक साल भी नहीं हुआ कि उसकी ईंटें तक गायब हो गई हैं। यूरीनल का नाम निशान मिट गया है कोई ईंट इधर पड़ी है तो कोई उधर पड़ी है। उस ठेकेदार के खिलाफ जिसने वह युरीनल बनाया था उसकी इन्क्वायरी कराइ जाए कि उसने कैसा मैटीरियल लगाया था जो वह एक साल तक भी कायम न रहा। लोग इतने टैक्स देते हैं लेकिन उनके लिये कोई फैसिल्टीज़ पानी, शैड, युरीनल वगैरा की नहीं (घंटी) मैं दरखास्त करूँगा कि एक हाई पावर कमीशन बिठाया जाए जिसमें इस हाउस के मैम्बर भी एसोशियेट हों जो वर्कशाप के अंदर जा कर देखें कि यह ब्रेक डाउन क्यों होते हैं, इतने सकैंडल्ज़ क्यों हो रहे हैं और मुनाफा क्यों ज्यादा नहीं हो रहा है। मुसाफिरों की फैसिलटीज के बारे भी वह रपोर्ट दे। (घंटी) आखिर में मैं यह कहना चाहता हूँ कि वज़ीर साहिब ने assure किया है कि 1969 तक नैशनलाइजेशन हो जानी चाहिए। मैं भी कहता हूँ कि इसके लिये स्टैपस लें और इसकी नैशनलाइजेशन कर देनी चाहिए हम इसके हक में हैं। आपका शुक्रिया।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ (ਮੋਰਿੰਡਾ, ਐਸ. ਸੀ.) : ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਪਸੂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਕਿਤਨੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਸਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਥੇ ਹੀ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚਰਚਾ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਡਾਜ ਫਾਰਗੋ ਬਸਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੇਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਵਾਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਜੈਂਸੀ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਗਈ ਉਸ ਨੇ ਇਹੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਨਾਜ਼ਕ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏ. ਜੀ. ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਰੀਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬਸਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨਾਕਸ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਬਸਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਇਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਫੇਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੂੰਕਿ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਸਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ ਸਿਵਾਏ ਉਥੇ ਦੇ ਪਟਰੌਲ ਪੰਪ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਪਟਰੌਲ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਬਸ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਚਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਤੇਲ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੇਲ ਮੁਕ ਗਿਆ ਉਥੇ ਹੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਬਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਲ ਲਿਆਂਦੀ

ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਵਿਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਇਮਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਟੀ ਦੀਆਂ ਬਸਾਂ ਚਲਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਦੂਰ ਹੋਵੇ । ਇਕ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਮਲਾ ਜੋ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜੋ ਰੂਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਸਦਾ ਅਮਲਾ ਵੀ ਫੇਰ ਕਰਕੇ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਮਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਸਾਂ ਨਾ ਚਲਣ । ਇਕ ਦਫਾ ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਦਫਾ ਉਸਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਗੀਅਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ । ਉਸ ਨੇ ਵਰਕਸ ਮੇਨੇਜਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੀਅਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਟ ਫਸਾ ਲੈਣੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ।

ਅਗਰ ਇਹ ਇਟਾਂ ਫਸਾ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਸਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਉਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਆਮਦਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸੂਦ ਵਿਚ ਹੀ ਚੁਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ।

(ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਕੋਰਮ ਲਈ ਘੰਟੀ ਵਜਾਈ ਗਈ ।)

Mr. Chairman (Shri Rup Singh 'Phul') : (Addressing the hon. Minister for Transport and Elections) How is it that the House does not remain in quorum ? Lobby Bells have already been sounded two, three times.

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੰਤਰੀ : ਜਿਹੜੀ ਮੋਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੈ, ਉਸ ਉਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ । ਅਗਰ ਆਪ ਨੇ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਐਡਜਰਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਮ ਸੇ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਐਡਜਰਨ ਕਰਨਾ ।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖਾਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬਸਾਂ ਚਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ । (ਘੰਟੀ)

ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਸਟੀਚੂਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ । ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਰੀਕਗ-ਨੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ । ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਸਬੰਧ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਜ਼ ਹਨ ਉਹ ਡਿਸਮਿਸਡ

[ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ]

ਐਮਪਲਾਈਜ਼ ਹਨ । ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਟੇਮਾਈਜ਼ਡ ਹੋਏ ਹਨ । ਉਥੇ ਦੇ ਵਰਕਰਜ਼ ਆਪਣੇ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਫਿਸ.ਬੇਅਰਰਜ਼ ਚੁਣਦੇ ਹਨ । ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਖ਼ੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਟੇਮਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਰੀਕਗਨੀਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਕੰਡਕਟਰਜ਼, ਡਰਾਈਵਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਹੁਤ ਘਟ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਇੰਨੀ ਘਟ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਇਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । 1961 ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀ । ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇ । (ਘੰਟੀ)

ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੋਰਡ, ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਸ਼ਿਡੂਲਡ ਕਾਸਟਸ ਦੀ ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਰੂਲਜ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ਿਡੂਲਡ ਕਾਸਟਸ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਇਨ ਟੋਟੋ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 1/5 ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਿਡੂਲਡ ਕਾਸਟਸ ਪਾਪਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ (ਘੰਟੀ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਫਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹਾਂ ।

ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ (ਧੂਰੀ, ਐਸ. ਸੀ.) : ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 1956 ਵਿਚ ਬਣੀ ਸੀ । ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪੈਟਰਨ ਆਫ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਸੂਲ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਮਾਂਇਡਿਡ ਬਣ ਸਕਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਣ । ਲੇਕਿਨ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ । ਅਗਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਸਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਸ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਜਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਸ ਵਿਚ ਸਫਰ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਫੀਲੰਗਜ਼ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੁਕਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਰਕਰਜ਼ ਵਿਚ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਘਰ ਜੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ । ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੀਟ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਟ ਲੋਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹਾਊਸ ਰੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰਖਿਆ ਗਿਆ । ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ

ਕੰਮ ਸਫਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਕਿ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟਰੀ ਸਲੂਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗ਼ਲਤ ਫਹਿਮੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕੇ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਲਿਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਉਤੇ ਫੋਟੋ ਸਟੈਟ ਕਾਪੀਆਂ ਰਖੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਡਿਪੂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਸਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਲਿਆਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਸਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਡਿਸਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਫਾਈਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸਟੈਟ ਕਾਪੀਆਂ ਹਾਊਸ ਦੀ ਟੇਬਲ ਉਤੇ ਰਖੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਗੁਮ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਫਾਈਲ ਗੁਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਕਿ ਫਾਈਲ ਕਿਵੇਂ ਗੁਮ ਹੋਈ। ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੂੰ ਮਿਸਲੀਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। (ਘੰਟੀ)

ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਤਦ ਤਕ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਗੇ।

(ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਕੋਰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਹਾਊਸ ਦਾ ਕੋਰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਰਮ ਬੈਲ ਵਜਾਈ ਗਈ।)

ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ : ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੈਨੀ—ਟੀਜ਼ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਅੱਡੇ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦਾ ਅੱਜ ਤਕ ਕਿਧਰੇ ਅੱਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਹੋਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਬਸਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਡਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਚਾਹ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਉਪਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਥੇ ਯੂਰੀਨਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਨਵਾਂ ਅੱਡਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਵਾਂ ਅੱਡਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਬਣੇਗਾ, ਉਥੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਣਾ ਦਿਉ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਅੱਡਾ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਉਥੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਸਾਂ ਲਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣ ਲਗੋ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬਸ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਭਜ ਦੌੜ ਕੇ ਬਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸ ਵਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਆਂਦੀ **ਸੀ** ਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬਸ ਚਲ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 11 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ

[ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ]

10 ਵਜੇ ਹੈ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬਸਾਂ ਪੌਣੇ 6 ਵਜੇ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਥੋਂ 7 ਵਜੇ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਰਾਤ ਆ ਕੇ ਪਟਿਆਲੇ ਠਹਿਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਤਰਕੀ ਕਰੇ, ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਰਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਬੋਨਸ, ਬੋਨਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਥੇ ਬੋਨਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੀ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੀ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਨਕੰਮ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਨਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਵਰਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੋਨਸ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਸਟੈਟ ਕਾਪੀਆਂ ਰਖੀਆਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਦੋਂ ਤਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਭ ਫਾਲਤੂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੇਬਰ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਐਕਟ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਉਧਰੋਂ ਸਭ ਫਜ਼ੂਲ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਖੇਗੀ।

(At this stage House was not in quorum. The bells were sounded and the quorum was complete.)

ਸਰਦਾਰ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ (ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ) : ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੈਪਸੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੈਪਸੂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੈਪਸੂ ਵਿਚ ਲਦ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਥੇ 50:50 ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਔਪਰੇਟਰਜ਼ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਬਸਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਿਓਂ ਚਲ ਕੇ ਆਦਮੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਗਡੀਆਂ ਬਦਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਖ ਚੁਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਬਠਿੰਡਿਓਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਕ ਥਰੂ ਬਸ ਚਲਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।

ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਖਰਾਬੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਬਲਾਢੇ ਤੋਂ ਸਰਸੇ ਨੂੰ ਚਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਕਰ 10 ਮੀਲ ਤੇ ਵੀ ਤੇਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੰਪ ਤੋਂ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਟਿਆਲੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਨਗੇ, ਉਥੋਂ ਤੇਲ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਚਲੇਗੀ। ਮੁਸਾਫਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਥੇ ਟੰਗੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੈਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਤੇਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।

ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਥੇ 4, 5 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ । ਉਹ ਬਸਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ । ਇਧਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਉ ।

ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਥੋਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਬਦਲੇ । ਇਕ ਮੈਨੇਜਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਸ ਨੇ 800 ਰੁਪੈ ਦੀ ਇਨਕੰਮ ਵਧਾਈ ਅਤੇ 22 ਲਖ ਰੁਪੈ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਦੱਸਿਆ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਓਪਰੇਟਰਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਣਗੇ । ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਥੇ ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ । 1½ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਉਥੇ ਲੱਗ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤਕ ਉਸ ਦਾ ਸੂਦ ਹੀ ਵਾਪਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ । ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਥੇ ਇਕ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ । ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਾ ਅੱਡਾ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਉਥੋਂ ਦੀ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਬਠਿੰਡੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅੱਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ । ਉਥੇ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਮੁਸਾਫਰ ਬੈਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ । ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਅੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਟੱਟੀ ਪੇਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਉਥੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ । ਬੜੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ । ਹੁਣ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਢਿਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਾਰਜ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਹਨ । ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੈਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ । ਢਿਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਸ ਰਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਕਦਮ ਚੁਕਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰੇ ।

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਚੋਣ ਮੰਤਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ) : ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਪੇਸ਼ਤਰ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਇਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਚੀਰਫਾੜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਬੜੀ ਮੁਫੀਦ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਹੋ ਸਕਿਆ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦੇਰ ਦੇ, ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਮਸਨੂਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਰਾਂਗਾ-ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਸਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮਿੰਗਜ਼ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਕਨਵੀਨੀਐਂਟ ਟਾਈਮਿੰਗਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿਧਰੇ ਘਟ ਹਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ-ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਦਨ ਫਰਦਨ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ । ਬਾਕੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਭੇਜ ਦੇਣ ਤਾਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਪਸੂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।

[ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੰਤਰੀ]

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਪੈਪਸੂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਔਰ ਕੁਝ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੋਈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਮਨਿਸਟਰ ਬਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ—ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਵਾਕਫੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਕਢਵਾ ਕੇ, ਵੇਖ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੋਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । (Thumping of desks).

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਸ਼ਡੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੰਨ 1965–66 ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰ ਦੇਈਏ । ਸੋ, ਉਥੋਂ ਲਈ ਲੇਲੈਂਡ ਬਸਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਐਕਵੀਜ਼ੀਸ਼ਨ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਡਿਊਲਡ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ।

ਦੂਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਸਰਹੰਦ ਬਰਾਸਤਾ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਰੂਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਕ ਇਤਫਾਕ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਿਟ ਹੋ ਗਈ । ਕੁਝ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਤੇਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਟ੍ਰਬਲ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਣ ਹਨ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਪੁਜੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਈ. ਓ. ਸੀ. ਦੇ ਪੰਪ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਬੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਬੜੇ ਮੌਕੇ ਸਿਰ ਮਦੱਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਰੀਮਾਈਂਡਰਜ਼ ਭੇਜੇ ਹਨ ਔਰ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗਾ ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਦਾ ਤੁਅਲਕ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਾਫੀ ਬਦਲੀ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਓਰਿਜਨਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਨਸੀਲਰੀ ਯੂਨਿਟਸ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ । ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੀ, ਮੈਂ ਇਕ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੁਲਾਈ ਸੀ ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਸੈਟ ਅਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਕਿ ਜੋ ਦਰਮਿਆਨੀ ਔਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਸਟਾਕ ਚਲਦਾ ਰਹੇ । ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਹਨ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸ਼ੁਦਾ ਫਰਮਾਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਟੈਂਡਰ ਰਾਹੀਂ ਔਰ ਜੇਕਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪੁਆਇੰਟਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਖੇ ਔਰ ਮਿਸਟਰ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ । ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੋ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਪਵਾਂ ।

ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ । ਯੂਨੀਅਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਡਿਸਮਿਸਡ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ । ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਲੇਬਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਔਰ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਔਰ ਕੁਝ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਦਰਮੀਆਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਬਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਥੇ ਕੀ ਰਿਵਾਜ ਹੈ । ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ । ਇਸ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਕਫੀਅਤ ਦੇ ਸਕਾਂ ।

ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਟਾਇਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 12 ਪੀ. ਆਰ. ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਹੋਏ 6 ਪੀ. ਆਰ ਦੇ । ਉਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਹਦ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਉਸ ਵਿਚ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਜੋਗਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਪਸੂ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ । ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਪੈਪਸੂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ । ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿ ਚ ਹੋ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇੰਟਰੈਸਟ ਇਸ ਵਿਚ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਦਸੇ ਹੋਏ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰਚਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਿਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਓਪਰੇਟਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਵੈਸਟਿਡ ਇੰਟਰੈਸਟਸ ਜੋ ਭੀ ਹਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੱਸਲੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਿਰ ਦਰਦੀ ਕੀਤੀ, ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਹੋਈ । ਔਰ ਤਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਸਟਵਾਈਲ ਪੈਪਸੂ ਏਰੀਏ ਨਾਲ ਸਟੈਪ-ਮਦਰਲੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਉਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਆਦਮੀ ਪੈਪਸੂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੈਪਸੂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਜੋ ਜਨਰਲ ਸੈਟ ਅਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੀਸੋਰਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰਕੀ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟ ਅਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਛਡ ਦੇਈਏ । ਐਸਾ ਕਰਨਾ ਬੜੀ ਗ਼ਲਤ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ । ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਪੈਪਸੂ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਐਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਾਂ ਕਾਰਸਪਾਂਡੈਂਸ ਨਾਲ ਤਸੱਲੀ ਕੀਤੀ । ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹ ਖ਼ਿਆਲ ਕਰੇ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੈਟਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਛਡ ਦਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਗ਼ਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਚੌਥੀ ਪਲੈਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਾਡਾ 77 ਲਖ ਰੁਪੈ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੀ

[ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੰਤਰੀ]

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਰਕੇ ਫੰਡਜ਼ ਘਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 45 ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 12 ਲਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸਲਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹਾਂ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫੰਡਜ਼ ਦੀ ਹੀ ਕਮੀ ਹੈ । ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਉਸ ਉਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਓਪਰੇਟਰਜ਼ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਧਕੇਜ਼ੋਰੀ ਨਾਲ ਕਨਵਿੰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਫਾਈਲਾਂ ਨਾਲ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਸੀ ਅਤੇ ਰੀਗਰੈਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ।

ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗਲ ਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਓਪਰੇਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਾ ਕਰਨ । ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੀ ਇਹ ਸੈਟ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ । ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਇਨਚਾਰਜ ਵਜ਼ੀਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੌ ਫੀ ਸਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ ਤਾਂ 95 ਫੀਸਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਗੀ । ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੌਥੀ ਪਲਾਨ ਵਿਚ 77 ਲਖ ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਰਖਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ, ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਕਮ ਨਾਲ 1966–67 ਵਿਚ 80 ਨਵੀਆਂ ਬਸਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ 74 ਬਸਾਂ 1967–68 ਵਿਚ ਐਡ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ । ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਦੇ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਾਤ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਐਕਸਪੈਕਟਿਡ ਸੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਟ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ 15 ਲਖ ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਲਰੇਟਿਡ ਪਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰਦੋ ਬਦਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 1966–67 ਵਿਚ 80 ਨਵੀਆਂ ਬਸਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 11 ਬਸਾਂ ਰੀਜ਼ਰਵ ਵਿਚ ਰਖਣੀਆਂ ਸੀ ਔਰ 1967–68 ਵਿਚ 74 ਨਵੀਆਂ ਬਸਾਂ ਐਡ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਧਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਪਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਘਟ ਹੈ । ਇਹ ਵੀ ਤਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਚੌਥੇ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵਿਚ ਵਨ ਯੀਅਰ ਬੇਸਿਜ਼ ਤੇ ਐਸਟੀ–ਮੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਇਕ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈਵੀ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਕ ਵਾਰ ਟੋਰਨ ਸਟੇਟ ਹੈ ਔਰ ਗੌਰਮਿੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲਾਵਾ ਆਫ ਅਵਰ ਓਨ ਅਸੀਂ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਹਰ ਹਾਲੇ ਇਹੋ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 10 ਕਿਲੋ ਆਟੇ ਦੀ ਥਾਂ 16 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਤਨੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ ਇਤਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ । ਲੇਕਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਤਨੀ ਰੀਡਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਸੈਟ ਬੈਕ ਹੋਵੇਗਾ । ਮੈਨੂੰ ਫਿਗਰਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਬਾਰੇ

ਮੈਂ ਕੁਝ ਬਰਾਡ ਆਊਟ ਲਾਈਨਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ—

According to the accelerated programme it is proposed to add 80 vehicles during the current financial year, another 80 vehicles during 1966-67 and 74 vehicles during the year 1967-68 (second year of this Fourth Five-Year Plan). It is anticipated that after complete nationalisation is achieved, an additional income of Rs. 24 lakhs per year will accrue to the State."

ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਅਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਈ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨ ਦਿਲਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਰੀਅਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕਾਨੋਮੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਸੈਂਟਪਰਸੈਂਟ ਮੁਕਾ ਦਿਆਂਗੇ ਔਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਸੈਂਟ ਪਰਸੈਂਟ ਕਵਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੇਜਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ । ਆਪਣੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਔਰ ਕੁਝ ਫਿਨਾਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ-ਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੇਹੌਂਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ । ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਸੋਰਸਿਜ਼ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਣ ਜਾਂ ਪਲਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸ਼ਡੀਊਲਡ ਪਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।

ਇਸ ਦੇ ਅਲਾਵਾ ਇਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1962–63 ਵਿਚ ਜੋ ਮੁਨਾਫਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨਾਲੋਂ 1963–64 ਵਿਚ ਘਟ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀਆਂ ਫਿਗਰਜ਼ ਦਾ ਕੰਪੇਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦਸਿਆ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1962–63 ਔਰ 1963–64 ਦੀਆਂ ਫਿਗਰਜ਼ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 1962–63 ਵਿਚ ਜੋ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ 21.69 ਲਖ ਸੀ ਔਰ ਮਾਈਲੇਜ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ 1963–64 ਵਿਚ 3.21 ਲਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਾਲਤੂ ਇਨਕੰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ । ਇਸ ਦੇ ਅਲਾਵਾ 1963–64 ਵਿਚ 92.41 ਲੱਖ ਮੀਲਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਪੈਸੇ ਫੀ ਮੀਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧ ਹੋਈ ਉਹ 2.77 ਲਖ ਰੁਪਏ ਸੀ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1963–64 ਵਿਚ ਕੁਲ ਮੁਨਾਫਾ 27.64 ਲਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ । ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਆਮ ਹਾਲਾਤ 1963–64 ਵਿਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1962–63 ਵਿਚ ਸਨ ਤਾਂ 27.67 ਲਖ ਰੁਪਏ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ । ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੇ । ਇਕ ਤਾਂ 15.21 ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਉਤੇ 1 ਅਪਰੈਲ, 1958 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ, 1964 ਤਕ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 9 ਫੀਸਦੀ ਸੂਦ ਦਾ ਰੇਟ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਨਾਲ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ । ਇਸ ਦੇ ਅਲਾਵਾ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਕਾਸਟਸ ਦੇ ਵਧ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਈ ਮੱਦਾਂ ਹੇਠ ਹੋਈ ਖਰਚ ਵਿਚ 10.17 ਲਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਖਰਚ ਵਿਚ ਇਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ 22 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 1962–63 ਵਿਚ ਇਹ 21.2 ਪੈਸੇ ਫੀ ਮੀਲ ਸੀ ਪਰ 1963–64 ਵਿਚ ਇਹ 27.7 ਪੈਸੇ ਫੀ ਮੀਲ ਹੋ ਗਿਆ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਬਜ਼ ਵਿਚ 4.6 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ 1962–63 ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ 2.2 ਪੈਸੇ ਫੀ ਮੀਲ ਸੀ ਉਥੇ ਇਹ 1963-64 ਵਿਚ 3.2 ਪੈਸੇ ਫੀ ਮੀਲ ਹੋ ਗਿਆ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਇਰਾਂ ਅਤੇ ਟਿਊਬਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਵੀ 23.12 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ

[ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੰਤਰੀ]

1962–63 ਵਿਚ 12.7 ਫੀਸਦੀ ਫੀ ਮੀਲ ਸੀ ਤਾਂ 1963–64 ਵਿਚ ਇਹ 16.2 ਫੀਸਦੀ ਫੀ ਮੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੇਅਰਜ਼ ਵਿਚ ਵੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹ 36.1 ਫੀ ਮੀਲ ਹੋ ਗਿਆ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੇਅਰਜ਼ ਵਿਚ ਵੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹ 36.1% ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਹ 1963-64 ਵਿਚ 47.1% ਹੋ ਗਿਆ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 10.17 ਲਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇ ਅਨਫੋਰਸੀਨ ਹਾਲਾਤ ਕਰਕੇ ਹੋਣੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 1963–64 ਦਾ ਜੋ ਫਾਲਤੂ ਮੁਨਾਫਾ 1962–63 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਫਾਲਤੂ ਖਰਚ ਵਿਚ ਖਪ ਗਿਆ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ 1963–64 ਵਿਚ 2.57 ਲਖ ਮੁਨਾਫਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿਚ 15.21 ਲਖ ਰਪਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਨਟਰੈਸਟ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਦੇਣੇ ਪਏ ਔਰ 10.17 ਲਖ ਰੁਪਏ ਜੋ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ 27.95 ਲਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 1963–64 ਵਿਚ ਵੀ 1962–63 ਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਉਤਨਾ ਹੀ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ।

ਫਿਰ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬਸਾਂ ਦੇ ਬਰੇਕ ਡਾਊਨ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਰੇਕ ਡਾਊਨ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ । ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 1963–64 ਤਕ ਪੈਪਸੂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਲੀਟ ਵਿਚ ਫਾਰਗੋ, ਤੇ ਡਾਜ਼ ਗਡੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਰਕਿਨ—ਪੀ–6 ਜਾਂ ਮੀਡੋ ਇੰਜਨ ਲਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਮੀਡੋ ਇੰਜਨਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਬਰੇਕ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੀਡੋ ਇੰਜਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗਡੀਆਂ ਨਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੇ ਲੈਂਡ ਲਈਆਂ ਜਾਣ । ਚੁਨਾਂਚਿ ਹੁਣ ਜਿਤਨੀਆਂ ਗਡੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਲੇ ਲੈਂਡ ਹੀ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ: ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਜ਼ ਔਰ ਫਾਰਗੋ ਬਸਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੋਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦੀ ਰਿਸਪਾਨਸਿਬਿਲੇਟੀ ਹੈ ?

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੰਤਰੀ: ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ । 58 ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਸਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੀਡੋ ਇੰਜਨ ਫਿਟ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸੀ, 15 ਬਸਾਂ ਰੀਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਅਲਾਵਾ ਸਪੈਸੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਇਲ ਔਰ ਇੰਡੀਜੂਨਸ ਸਪੇਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਬਰੇਕ ਡਾਊਨ ਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ।

ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡੀਟੇਲਜ਼ ਹਨ, ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ, ਸਰਵਿਸਿੰਗ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂ ਤਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਲਗ ਜਾਣਗੇ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਰਗੋ ਇੰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟ ਆਫ ਪਲੇਸ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੇਲੈਂਡ ਬਸਾਂ ਰਖੀਆ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ ।

ਬਾਕੀ ਪਟਿਆਲੇ ਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਯੂਰੀਨਲਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਪਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਯੂਰੀਨਲਜ਼ ਦੀ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਸਫਾਈ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਵਿਚ ਕਲੀਨਲੀਨੇਸ ਨਹੀਂ ਰਖੀ ਜਾਂਦੀ । ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਇਕ ਹੈਬਿਟ ਹੁੰਦੀ

ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾਂ ਹਾਂ—ਝਾੜਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ—ਪਰ ਤਵਜੁਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਵਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਈ ਚਾਨਸ ਯੂਰੀਨਲ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ਾਬ ਕਰਾਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਉਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਪਵੇ । ਮੈਂ ਉਥੇ ਦੇ ਇਨਚਾਰਜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ਾਬ ਕਰ ਉਥੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕਰ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ । ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ੇਮਫੁਲ ਹਨ । ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਅਡੇ ਤਾਂ ਹਨ ਹੀ ਮਿਉਂਸੀਪੈਲਟੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡਜਸਟ-ਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਵੇ । (ਵਿਘਨ) ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਲ ਜੁਲਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ।

(ਇਕ ਆਵਾਜ਼ : ਬੋਨਸ ਬਾਰੇ ਦਸੋ) । ਬੋਨਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : On a point of Information. ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਡੂਲਕਾਸਟਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ । ਇਹ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉ ।

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੰਤਰੀ : ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਧੂ, ਢਿਲੋਂ, ਗਿਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਡਲਡ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ । (ਹਾਸਾ) ਦੂਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦੱਦ ਕਰਾਂਗੇ । (ਘੰਟੀ)

1572—10-6-66 384 Copies C. P., and S., Pb. Patiala.

APPENDIX
to
P.V.S. Debates Vol. II—No. 18, dated the 5th November, 1965

MECHANIZATION OF AGRICULTURE IN THE STATE

***8782. Comrade Babu Singh Master :** Will the Minister for Home and Development be pleased to state the details of the steps taken proposed to be taken by the Government to mechanise agriculture the State, together with the results achieved so far.

Sardar Darbara Singh : The required information is laid on the Table of the House.

STATEMENT

The following steps have been/are proposed to be taken to mechanise agriculture :—

(1) The State Government is floating loans for the purchase of tractors by every cultivator possessing about 30 acres of land. He is entitled to get a loan to the extent of Rs. 20,000 for a heavy tractor and Rs. 10,000 for a small tractor. This loan carries the usual interest, and is recovered as taccavi loan after a period of grace of one year from the date of payment of the loan in eight equated half-yearly instalments.

(2) During the year 1964-65 a sum of Rs. 21.20 lakhs was advanced as loan to the cultivators for the purchase of tractors in the State and a sum of Rs. 26.20 lakhs will be advanced during 1965-66.

(3) During the year 1947, there were only about 900 tractors in all throughout the State. With efforts to encourage mechanized agricultural farming in the State, the number of tractors has risen to about 12,000 tractors.

(4) The State is getting very little spare parts of imported tractors due to import difficulties. The Government of India have been approached for allotting 700 Byelarus 48 H.P. Russian Tractors and about 172 Zector (Czecholovakia) tractors for the Punjab State. The Government of India expected that 6,750 tractors of different H.P. ranges will be produced in India during the year 1965, and allocated the following types and number of tractors to this State :—

		Number
(I)	Massy Furguson 32 H.P.	50
(II)	Hindustan 35 (32 H.P.)	100
(III)	Escort 37 (35 H.P.)	100
(Iv)	Escort (22.7 H.P.)	100
(V)	Internation B 275 (35 H.P.)	50
(VI)	Eicher 110/5 (19.20 H.P.)	25
(VII)	Eicher 115/8 (26.27 H.P.)	25

The Government of India were also requested to make arrangements for the procurement of about 100 DT Russian Tractors as there is great demand for the same. The Government of India have since instructed the firms manufacturing tractors of the above types to make immediate arrangements for supply of 450 tractors to the Punjab State. Due to heavy booking with the Russian tractor dealers in the Country, the Government of India have desired that the cultivators should be advised to adopt the use of Escort 27 and Hindustan 50 instead of DT 14.

(5) There are more than 2,500,000 holdings comprising of an area not exceeding 10 acres each. For taking up mechanized cultivation on these holdings, there is a great demand for small tractors and power tillers in the State. In order to cope with the increased demand, power tillers are being imported from Japan. One hundred Venmar Power tillers shipped from Japan are being distributed by the State Co-operative Marketing Federation. In addition, Government of India have also been approached for the import of another 100 power tillers from Japan under the Fifth Yen Credit. Efforts are being made to set up a plant in the State for manufacturing power tillers according to our requirements. Proto types of different types of power tillers have been procured and these are being tried under different soil conditions in the Punjab State.

(6) For keeping tractors in working condition, a scheme for setting up tractor hire and service Stations in the State has also been formulated and it will be put into operation during the Fourth Five Year Plan. This scheme will provide commendable facilities to the cultivators having small holdings for taking up mechanized cultivation and getting their tractors repaired at a reasonable cost.

(7) Loans for installation of pumping sets and tubewells are being advanced. During the year 1964-65, about 6,800 tubewells, pumping sets were energized. It was proposed to energize 11,000 tubewells/pumping sets during 1965-66. It is tentatively proposed to instal about 51,000 tubewells and pumping sets in the Fourth Five Year Plan.

Result Achieved

The result so far achieved as result of the efforts to mechanise agriculture are as under :—

(1) Number of tractors of all types operating in the State	12,000	approximately
(2) Number of pumping sets, engine driven	15,000	,,
(3) Number of pumping sets, Electric driven	15,000	,,
(4) Number of Power Wheat threshers drummy type	2,000	,,
(5) Number of Power Wheat threshers, complete with grader and elevator	1,000	,,
(6) Number of Power sprayers and Dusters	500	,,

PUNJAB VIDHAN SABHA

DEBATES

15th November, 1965

Vol. II—No. 19

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Monday, the 15th November, 1965

Punjab Vidhan Sabha, Secretariat, Chandigarh

Price : Rs. 3.00

ERRATA
to
Punjab Vidhan Sabha Debates Vol. II, No. 19, dated the 15th November, 1965

Read	*For*	*Page*	*Line*
concerned	cencerned	(19) 1	20
that	hat	(19)1	26
School	Scnool	(19)2	Last but one
Schools	School	(19)3	17
Minister	Mlnister	(19)4	1
Agricultural	Agriculturai	(19)6	10 from below
Service	Servicc	(19)7	9
Zila	Zil	(19)8	2
Parishads	Parishad	(19)8	4
the	this	(19)9	11 from below
Teachers	Teaehers	(19)10	2
information	infoation	(19)10	28–29
already	alr ady	(19)11	18 from below
Educational	Edueational	(19)11	10 from below
into the conditions	nto the condltions	(19)12	8 from below
Govt.	Grant	(19)13	1
schools	school	(19)13	1
Fourth	Fourtn	(19)14	11 from below
Education	ducation	(19)16	1
QUESTIONS	QUESTIION	(19)17	Heading
immediately	immcdiately	(19)17	2–3
Vol. II	Vol.	(19)18	3 from below
Delete the word 'the' after the word 'to'		(19)19	6
Centres	eentres	(19)19	7 from below
Ayurvedic	Ayurvepic	(19)19	5 from below
गवर्नमेंट	गर्वनमैंट	(19)21	5 from below
किया	क्या	(19)22	13
सकता	सकत	(19)26	5
सहूलियत	सहूलियते	(19)26	15
निर्वाचन	निर्यायन	(19)28	13
दिक्कतें	क्कतें	(19)31	20
गंदम	ंदम	(19)31	21

P.T.O.

Read	*For*	*Page*	*Line*
करने के	करने के ये	(19)31	23
समझता हूं	समझता	(19)31	24
300 रुपये	3 0 रुपये	(19)33	13
सरकार	सरकार के	(19)33	7 from below
अदालत	आदलत	(19)35	1
हुए हैं	हुए	(19)35	14 from below
अच्छा	अभ्छा	(19)37	7
की	को	(19)37	9 from below
14(6)	14( )	(19)37	6 do
ਖੁੱਲ੍ਹਾ	ਖਲ੍ਹਾ	(19)40	13
ਈਵੇਜਨ	ਈਵੇ ਨ	(19)41	19
गिरी	गरी	(19)45	9
60	50	(19)46	6
काम	का	(19)46	11
50,000	50,000 ਹਜ਼ਾਰ	(19)46	24
ਕੋਈ	ਜੋਈ	(19)48	15
ਕਾਮਰੇਡ	ਕ ਮਰੇਡ	(19)50	27
निकला	निकल	(19)51	16
चेयरमैन	चेयरमन	(19)53	3
टैक्सेशन	टक्सशन	(19)53	21
हमने	हसने	(19)53	13 from below
substitute	sustitute	(19)53	6 do
ਇਹ	ਿ ਹ	(19)56	6
लगाया	लगाना	(19)57	14
ਦੀ	ਦੇ	(19)59	5 from below
Pandit	andit	(19)66	18
ਚੌਧਰੀ	ਚਧਰੀ	(19)67	16
withdrawn	withd awn	(19 67	22
श्री फतेह चन्द विज	श्री फसेह चन्द विज	(19)68	10
Excise	Exise	(19)72	19
can	can so	(19)72	5 from below
mala fide	mala fied	(19)78	9 and 11-12
ਲਿਆਉਣੀ	ਲਾਉਣੀ	(19)79	12
attentively	attent tively	(19)80	15
प्लाट	प्लान	(19)82	23

PUNJAB VIDHAN SABHA

Monday, the 15th November, 1965

The Vidhan Sabha met in the Assembly Chamber, Vidhan Bhawan, Sector 1, Chandigarh at 2.00 P. M. of the Clock. Deputy Speaker (Shrimati Shanno Devi) in the Chair.

ANNOUNCEMENT BY SECRETARY

RE. UNAVOIDABLE ABSENCE OF MR. SPEAKER

Secretary : I have to inform the House that the Speaker will be unavoidably absent for the rest of the sittings of the Vidhan Sabha during this Session. The Deputy Speaker will, therefore, take the Chair.

(*At this stage the Deputy Speaker occupied the Chair*)

UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS

COMPLAINT AGAINST CHIEF MEDICAL OFFICER, LUDHIANA

3022. Shri Shamsher Singh Josh : Will the Minister for Home and Development be pleased to state whether it is a fact that the Deputy Commissioner, Ludhiana has reported to the Government against the Chief Medical Officer, Ludhiana complaining that the latter was not co-operating with the District Administration in Civil Defence Works, if so, the action, if any, taken by the Government on the said report ?

Sardar Darbara Singh : Yes. On receipt of the report, he was immediately transferred. Further action against the cencerned Doctor is also under consideration.

KALSERA-BASDERA APPROACH ROAD IN UNA BLOCK DISTRICT HOSHIARPUR

3037. Shri Surinder Nath Gautam : Will the Minister for Public Works be pleased state :—

(a) whether it is a fact hat stones for the construction of Kalsera Basdera appraoch road under Pilot Project Scheme in Una Block, district Hoshiarpur, have been stocked there for the last one year and demarcation of the road culverts has also been completed;

(b) if the answer to para (a) above be in the affirmative, the progress made so for in completing the said approach road and the approximate date by which it is likely to be completed,

Sardar Darbara Singh : (a) Yes. With regard to the demarcation of culverts it may be stated that no culverts are proposed to be constructed on the said road:

(b) The Panchayat Samiti of Una Block, the election of which had been set aside, did not agree to sanction the amount required for the construction of the said road project and as such no progress has been made in this regard. The matter regarding completion of this road will be taken up with the Panchayat Samiti as and when one is formed.

MODEL SCHOOLS IN THE STATE

3038. Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) the total number with names of the Model Schools in the State, district- wise, at present;

(b) the total number of students on the rolls of the said schools at present;

(c) the rate of fees charged from the students by the said schools and the annual income derived from such fees, class-wise, during the year 1964-65;

(d) the educational qualifications prescribed for the teachers employed in such schools and also of those employees in the conventional schools;

(e) the establishment charges in all such schools per year; school-wise, during the year 1964-65;

(f) The educational standards prescribed by the Education Department and pass percentage of terminal examinations in Model Schools as compared with the conventional schools during the said period;

(g) the educational qualifications of teachers at present working in the Model Schools situated in Amritsar District with the date of joining of each ?

Shri Prabodh Chandra :

The information is laid on the Table of the House:

District	Number of Schools	Names
Patiala	3	(i) Junior Model School, Nabha.
		(ii) Junior Model School, Civil Lines, Patiala.
		(iii) Govt. Model Higher Secondary Scnool Pheel Khana, Patiala.

District	Number of Schools	Names
Ambala	2	(i) Govt. Junior Model School, Chandigarh
		(ii) Govt. Senior Model School, Chandigarh
Ludhiana	2	(i) Govt. Model High School, Cemetry Road, Ludhiana.
		(ii) Govt. Model School, Millarganj, Ludhiana
Jullundur	1	Govt. Model Higher Secondary School, Jullundur
Hoshiarpur	1	Govt. Special School, Nangal Township
Ferozepore	1	Junior Model School, Abohar
Rohtak	1	Govt. Model School, Rai
Hissar	1	Model School, Sirsa.

(b) 4,330.

(c) The information is given in annexure I.

(d) It has been decided to make appointments in Model School out of a special pool of teachers who have secured at least 50% marks in the subject/subjects taught by them and have put in at least five years, service. For other schools there is no such restriction.

(e) Rs. 4,50,000. The time and labour involved in collecting this information, school-wise, will not be commensurate with any possible benefit to be obtained.

(f)

(1)	Junior Model School, Nabha.	There is no terminal examination,
(2)	Junior Model School, Civil Lines, Patiala	There is no terminal examination
(3)	Govt. Junior Model School, Chandigarh	There is no terminal examination.
(4)	Govt. Model Higher Secondary School, Pheel Khana, Patiala	100%
(5)	Govt. Senior Model School, Chandigarh	96.6%

[Education MInister]

(6) Govt. Model High School, Cemetry Road, Ludhiana. .. 89.1%

(7) Govt. Model Hr. Sec. School, Jullundur. .. 80%

(8) Govt. Special, School. Nangal Township .. 80%

(9) Govt. Model School, Millarganj, Ludhiana. .. 100%

(10) Junior Model School, Abohar .. 100%

(11) Govt. Model School. Rai Newly opened

(12) Govt. Model School, Sirsa .. 94%

The overall University/Departmental pass percentage of the following terminal examinations is given below :—

Middle Examination .. 77.88%

High School Examination .. 67.29%

Higher Secondary School Examination:—

(i) Part I .. 56.80%

(ii) Part II .. 42,89%

(g) The question does not arise as no Model School exist in Amritsar District.

ANNEXURE I

			Fees class-wise p. m.
(i)	1.	Junior Model School, Nabha	Rs 5 p.m. from Nursery to VI Standard
	2.	Junior Model School, Civil Lines, Patiala	Rs 8 p.m.
	3.	Govt. Model Higher Secondary School, Pheel Khana, Patiala	Rs. 5 p.m, from Nursery to VIII Rs 7 p.m. IX Standard Rs 8 p.m. X ,, Rs 9 p.m,. XI .,
	4.	Govt. Junior Model School, Chandigarh	Rs 10 p.m.
	5.	Govt. Senior Model School, Chandigarh	Rs. 10 p.m. L. K. G to V Standard Rs 15 p.m.VI to VIII Standar

6.	Govt. Model High School, Cemetary Road, Ludhiana	Rs 4 p.m. from I to V standard Rs 6 p,m. from VI to VIII, ,, Rs 7 p.m. from IX to X ,,
7.	Govt. Model School, Miller-ganj, Ludhiana	Rs 4 p.m, from L.K.G. to III Rs 6 p.m. from IV to VI
8.	Govt. Model Higher Second-ary School, Jullundur City	Rs 10 p.m.(Pre-K.G. to VI St.) Rs 12 p.m. (VII to IX St.)
9.	Govt. Special School, Nangal Township	Rs 10 p.m.
10.	Junior Model School, Abohar	Rs 10 p.m.
11.	Govt. Model School, Rai	Rs 10 p.m.
12.	Govt. Model School, Sirsa	Not yet decided
(ii)	Total Income derived during 1964-65.	Rs 2,97,594

The time and labour involved in collecting this information class-wise will not be commensurate with any possible benefit to be obtained.

DEPOTS GIVEN TO CO-OPERATIVE SOCIETIES

3039. Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) the number of cases in which the Assistant Registrars, Co-operative Societies of Amritsar and Tarn Taran recommended the depots for the sale of controlled commodities to be given to the Co-operative Credit and Service Societies during the period from 1st January, 1964 to date;

(b) the names and number of the Co-operative Societies which were alloted depots on the recommendations of the Assistant Registrars;

(c) the number and names of those Societies in respect of which the recommendations of the Assistant Registrars were ignored and the reasons for not accepting the recommendation in each case;

(d) the names of persons who were given depots ignoring the societies recommended by the Assistant Registrars, and the reasons for giving preference to those individuals over the Co-operative Societies.

Chaudhri Rizaq Ram : (Irrigation and Power Minister)

(a) Forty-six

(b) Forty-five List attached

(c) One. The case of Majitha Co-operative Service Society was recommended by the Assistant Registrar, Co-operative Societies, Amritsar on 27th September 1965, but the depot was not allotted. It was intimated by the District Food and Supplies Controller, Amritsar that no new depots were being allotted under instructions of the Food and Supplies Department.

(d) Question does not arise.

[Irrigation and Power Minister]

List of depots for the sale of controlled commodities sanctioned by the District Food and Civil Supplies Officer, Amritsar from 1st January, 1964 to date.

Sr. No. Name *af the Society.*

TARN TARAN CIRCLE

1. The Tappa Co-operative Agricultural Service Society.
2. The Gharyala Co-operative Agricultural Service Society.
3. The Makhi Kalan Co-operative Agricultural Service Society.
4. The Thakar Pura Patti Mahuka Co-operative Agricultural Service Society.
5. The Hari Ke Nau Co-op. Agricultural Service Society.
6. The Manhiala Jai Singh Co-op. Agricultural Service Society.
7. The Dhagana Co-operative Agricultural Service Society.
8. The Valtoha Co-operative Agricultural Service Society.
9. The Poonian Co-operative Agricultural Service Society.
10. The Mian Wind Co-operative Agricultural Service Society.
11. The Jallanbad Co-operative Agricultural Service Society.
12. The Verowal Co-operative Agricultural Service Society.
13. The Nagoke Jadid Co-operative Agricultural Service Society.
14. The Sakian Wali Co-operative Agricultural Service Society.
15. The Chohla Sahib Co-operative Agrl. Service Society.
16. The Mohan Pur Co-operative Agricultural Service Society.
17. The Fatehabad Co-operative Agricultural Service Society.
18. The Bhojian Sardaran Co-operative Agricultural Service Society.
19. The Lalu Ghuman Co-operative Agricultural Service Society.
20. The Khot Dharam Chand Khurad Co-op. Agricultural Service Society.
21. The Tharu Patti Talwali Co-operative Agri. Service Society.
22. The Pala Saur Sikhan Co-operative Agrl. Service Society.
23. The Chobhal P. Pando Co-operative Agricultural Service Society.
24. The Thati Sohal Co-operative Agricultural Service Society.
25. The Padri Kalan Co-operative Agricultural. Service Society.
26. The Dhotian Co-operative Agricultural Service Society.
27. The Noshera Panwan Co-operative Agricultural Service Society.
28. The Sheron Co-op. Agricultural Service Society.
29. The Bhatal Bhai Ke Co-operative Service Society.
30. The Doburji Co-operative Agricultural Service Society.
31. The Ratanal Co-op. Agricultural Service Society
32. The Pandori Ran Singh Co-op. Agricultural Service Society.
33. Tarn Taran Mohala Nanaksar Co-op. Thrift and Credit Society.
34. **The Bala Chak Co-op. Agricultural Service Society.**

35. The Baghrian Co-op. Agricultural Service Society.
36. The Jodh Pur Co-op. Agricultural Service Society.
37. The Attari Co-op. Agricultural Service Society.
38. The Gandiwind Co-op. Agricultural Service Society.
39. The Cheema Kalan Co-op. Agricultural Service Society.
40. The L hian Co-op. Agricultural Service Society.
41. The Bhuse Co-op. Agricultural Service Society.
42. The Dhand Co-op. Agricultural Service Society,
43. The Kasain Co-op. Agricultural Servicc Society.
44. The Gharinda Co-op. Agricultural Service Society.

AMRITSAR CIRCLE

45. The Ajnala Co-operative Marketing Society Ltd. ,Ajnala.

PROFESSION TAX CHARGED FROM TEACHERS

3040. Comrade Makhan Singh Tarsikka : Will the Minister for Home and Development be pleased to state —

(a) the rate at which profession tax was charged by the Zila Parishad, Amritsar from the teachers in Amritsar District during the years 1957 and1962, respectively;

(b) the details of the concessions, if any, that were given to the said teachers in the matter of said tax at the intervention of late Maulana A. K. Azad, the then Union Education Minister;

(c) whether the said concessions were later withdrawn, if so, when; and the reasons therefor,

(d) whether it is a fact that the teacher's Unions have demanded the exemption for the teachers from the payment of the said tax, if, so, the steps, if any, Government proposes to take to give relief to the teachers in this regard ?

Sardar Darbara Singh : (a) There was no Zila Parishad in Amritsar in the year 1957. Professional tax at the following concessional rates was levied on teachers by the District Board Amritsar in the year 1957 ;—

Income of the teacher per annum			*Rate of tax per annum*
	Rs	Rs	Rs
1.	Exceeding 400	but not exceeding 1200	5
2.	„ 1200	„ „ „ 1500	8
3.	„ 1500	„ „ „ 1800	12
4.	„ 1800	„ „ „ 2100	17
5.	„ 2100	„ „ „ 2400	23

[Home and Development Minister]

District Board, Amritsar was abolished in March, 1962, when Zila Parishad, Amritsar and Panchayat Samitis at the block level in the district were formed, under the Punjab Panchayat Samitis and Zila Parishad Act, 1961. Power to levy taxes, which were being levied by the erstwhile District Boards, was conferred on the Panchayat Samitis and not the Zila Parishad under the said Act.

Panchayat Samitis in the Amritsar District have been levying profession tax on teachers as well as others at the following rates since the year 1962 :—

SCHEDULE

					Amount of tax per annum
		Rs		Rs.	Rs.
1.	Where the annual income exceeds	400	but does not exceed		
2.	Ditto	500	Ditto	600	10
3.	Ditto	600	Ditto	700	13
4.	Ditto	700	Ditto	800	16
5.	Ditto	800	Ditto	900	20
6.	Ditto	900	Ditto	1,000	24
7.	Ditto	1,000	Ditto	1,200	28
8.	Ditto	1,200	Ditto	1,400	33
9.	Ditto	1,400	Ditto	1,600	38
10.	Ditto	1,600	Ditto	1,800	44
11.	Ditto	1,800	Ditto	2,000	50
12.	Ditto	2,000	Ditto	2,500	55
13.	Ditto	2,500	Ditto	3,000	63
14.	Ditto	3,000	Ditto	3,500	70
15.	Ditto	3,500	Ditto	4,000	80
16.	Ditto	4,000	Ditto	5,000	90
17.	Ditto	5,000	Ditto	6,000	105
18.	Ditto	6,000	Ditto	7,000	120
19.	Ditto	7,000	Ditto	8,000	140
20.	Ditto	8,000	Ditto	9,000	160
21.	Ditto	9,000	Ditto	10,000	180
22.	Ditto	10,000			200

(b) The concession in the rates of profession tax enjoyed by teachers from 1st April, 1953 to 1st June, 1958 may please be seen, by the two rates embodied above, one for teachers alone in the year 1957 and the other for all including teachers when the said concession was withdrawn in respect of teachers from 1st June, 1958, i.e , the one followed by Panchayat Samitis since the year 1962 also.

It is not a fact that this concession to teachers in the rates of profession tax was granted at the intervention of late Maulana A. K. Azad, the then Union Education Minister.

(c) The concession in the rates of profession tax granted to teachers from 1st April, 1953, was withdrawn from 1st June, 1958.

The reason for the withdrawal of this concession was that other equally low-paid employees very much resented this favourable treatment to teachers only.

(d) Yes. Government does not propose to take any steps to grant relief to teachers only in this respect, as it would again create resentment in other equally low-paid employees.

Government is, however, considering to revise the present schedule of rates of. profession tax in respect of all, by raising the exemption limit of annual income from the present limit of Rs 400. This might bring relief to teachers as well.

EXCESS STAFF POSTED IN CERTAIN SCHOOLS IN AMBALA DISTRICT

3041. Comrade Shamsher Singh Josh : Will the Minister for Education be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that JBT teachers or Masters have been posted in excess of their requirements by the Government High School, Manimajra, Government Primary Schools at Badheri, Kanthala, Burail, Kansal, Nawan Gaon, Mohali, Baterla and also in various schools of Chandigarh (Ambala District);

(b) if this reply to part (a) above be in the affirmative, the actual number of teachers or Masters posted in each of the above mentioned schools and also the actual requirement of each school, along with the additional postings, if any, made therein ?

Shri Prabodh Chandra : (a) Yes. in Government High School Manimajra, Government Middle School Burail, Government Primary Schools, Kanthala, Kansal, Nawan Gaon and Mohali only and not in other schools.

(b) A statement giving the requisite information in respect of schools mentioned in (a) above is enclosed.

[Education Minister]

Statement showing the number of master/Teachers posted, actually required and surplus in schools mentioned in part (a) of the reply of the question.

Sr. No.	Name of School	Masters/ Teachers actually required	Masters/ Teachers actually posted	Additional postings made (difference of Cols. 4 & 3)
1	2	3	4	5
1.	Government High School, Manimajra	21	27	6
2.	Government Middle School, Burail	20	21	1
3.	Government Primary School, Kanthala	2	4	2
4.	Government Primary School, Kansal	3	7	4
5.	Government Primary School, Nawan Gaon	2	3	1
6.	Government Primary School, Mohali	2	3	1

MEMORANDUM FROM PRIVATELY MANAGED SCHOOLS TEACHERS ASSOCIATION

3042. Comrade Shamsher Singh Josh : Will the Minister for Education be pleased to state whether Government received any memorandum during 1964 or 1965 from the privately managed Schools teachers Association regarding their demands for Government grades, security of service etc, if so, the details of the demands made therein and the steps taken or proposed to be taken by Government ?

Shri Prabodh Chandra : Yes. A statement giving the requisite info ation is laid on the Table of the House.

Statement showing the demands put forth by the teaching personnel of Private Schools with comments

Sr. No.	Demands	Action taken or proposed to be taken by Government
1	2	3
1.	Pay scales and D.A. of teachers working in recognised schools should be as are being paid to teachers in Government schools.	A case for the liberalization of Grant-in-aid rules is already under consideration of Government. In the revised rules, a condition is proposed to be laid down that a school will receive liberalised grant-in-aid only if it gives the same grades of pay and allowances to the staff as are admissible to their counterparts in Government Schools. With the introduction of the revised grant-in-aid rules the managements of the privately—managed schools are likely to get more financial aid so as to give their staff pay and allowances as are prevalent in Government schools.
2.	Security of service should be provided to the teachers of the recognised schools. Education Code should be replaced by an Education Act containing service condition of teachers rules for constituting the managing bodies and representation of teachers in the managing committee.	The Punjab Education Code has already been amended vide Punjab Government Education Department Notification No. 1508—Ed IV-3E)—63/9.82, dated the 21st May, 1963 to provide better security of service to the staff working in the privately managed schools. As regards the replacement of the Punjab Education Code by an Education Act, the Government of India have already set up a study group for preparing a draft Education Bill for consideration of Central Government with a view to giving a statutory basis to Edueational organisation and development. This group has been abolished and its work has been transferred to the Education Commission set up by Government of India. It is hoped that the Punjab Education Code or its existing provisions will have legal sanction on the finalisation of the Education Act in due course.
3.	Grant-in-aid should be raised as to make up the deficit of these schools.	As stated in the comments against demand No. (I) the question of liberalising grant-in-aid rules is under the consideration of Government.

[Education Minister]

1	2	3
4.	Cut in summer vacation and school timing should be restored. Teachers called to teach during summer vacation should be paid extra in lieu of that.	These demands have already been considered by Government on the representations made by the Joint Council of Government Teachers Unions, it has been decided that necessary adjustments be made within the frame work of 220 working days and 1,200 instructional hours. This matter was further discussed in the meeting of State Advisory Committee on Education held on 23th & 24th November, 1964. The school timings have been fixed as follows :— (1) Summer timings : From 1st April, to 31st August, 7.00 a.m. to 1.05 p.m. (2) Winter timings : From 1st September, to 31st March, 9.30 a.m. to 4.00 p.m. The instructional hours in schools have been reduced from 1,270 hours to 1,175.50 hrs. with effect from 1st April, 1965. A relief of 1.20 hours during summer and 1.50 hrs. during winter has been given on Saturdays. As regards vacation/other holidays it has been decided to allow the existing pattern.
5.	Triple Benefit Scheme should be enforced.	It has been decided by the State Government not to introduce the Triple Benefit Scheme for the teachers working in Government institutions as they can subscribe to the Provident Fund and are entitled to pension/gratuity as the case may be under the normal rules. Due to limited resources of the State Government in view of the national emergency it could not be possible to enforce the said scheme on privately managed schools for the benefit of the teachers employed therein.
6.	An enquiry should be conducted into the conditions of service of teachers and steps should be taken to improve their lot.	The question of liberalising the Grant-in-aid Rules which will *inter-alia* purport to require the privately managed schools to pay their staff same scales of pay and allowances and have the same conditions of service as their counterparts in Government service, is under the consideration of Government In view of this there is no necessity of constituting a committee to look into the question of service condition of teachers of privately managed schools.

7.	That free Education be introduced in privately managed which school should be compensated for loss of income. (ii) Education Department should work out the compensation which will have to be paid on this account.	Grant have provided free education in their own school. Privately Managed schools have to hold their own by keeping better standard of education and attract all those children who are proposed to pay the cost of education. A provision of Rs 6 lacs is provided annually for the payment of *ad-hoc* grants to all those schools where the enrolment has gone down on account of introduction of free education in near by Government schools causing loss in income.
8.	Free Education to Children of teachers at school and College level be provided irrespective of their salaries.	Government have already extended this concession upto Higher Secondary Classes to the children of those teachers whose basic pay is Rs 250/- P.M. This concession will be available in Government schools but the children of teachers of privately managed schools, if they are studying in Government Schools, will automatically be benefitted.
9.	Class distinction with regard to the freeship and stipends be abolished and concession be allowed on economic backwardness.	Government have already taken a decision for granting fee concession on the basis of poverty viz. economic backwardness. This concession could not be extended to privately managed schools due to limited financial resources of the state.
10.	Allegations for preaching communalism have been levelled against privately managed schools. The Department should take disciplinary action in cases where there is any indication.	All privately managed schools have not been dubbed as communal. Wherever there have been complaints about a sectarian policy, Government have taken action.
11.	Restoration of J.B.T. Classes in Privately Managed schools has been asked for. Some of the Government schools where J.B.T. Unit had been attached have no amenities for teacher's training. Privately managed Schools should not be considered a foreign element and allowed necessary facilities.	There were some serious complaints against the conduct of J.B.T. classes in privately managed schools and Government had to take severe action in this regard. Policy has been reconsidered and privately managed schools have been allowed J.B.T. Units once again but they are required to maintain certain standards and abide by the Departmental Rules.
12.	Instructions with regard to formation of Arbitration Board and implementation of its decisions are not being properly carried out by the District Education Officers.	Field staff heve been asked to be vigilant in disposing of the cases which are referred to Arbitration Board and the implementation of the decisions thereof expeditiously.
13.	Instructions regarding giving extension in service to staff working in privately managed schools after the age of superannuation are not being followed by the District Education Officers and Circle Education Officers. As a result of this the cases are unnecessarily delayed.	Necessary steps are taken by the Department whenever such cases come to their notice.

[Education Minister]

1	2	3
14.	That the teachers constituencies should not be abolished from the upper House of the State. The No. of teachers is ever increasing and it is quite undemocratic to prevent such a large majority from being represented in the State Legislature.	The matter is under the consideration of the Government of India.
15.	That the service conditions of Lady teachers is miserable. They are exploited by the Managements. The Union strongly condemns this action and urges the Department to come to their rescue.	The department takes strick action against the managements if and when such complaints are received from lady teachers concerned.
16.	That the rate of C.P.F. be raised to 10 Paise per Rupee.	The proposal to enhance the rate of standard provident fund is already under consideration and the financial implications are being worked out.
17.	That fee compensation given to schools for freeship granted to backward and Harijan Students should be released every quarter.	The following time schedule was adopted for the release of Harijan Freeships grants during the year 1964-65 :— 1st quarter 31st August, 1964 2nd quarter 30th November, 1964 3rd quarter 28th February, 1965 4th quarter 30th May, 1965
18.	Representation be given to teachers on the State Education Board and other Committees set up from time to time.	One Headmaster of a High/a Higher Secondary School and a J.B.T. Institution each has already been given representation on the Punjab Advisory Board of Education.
19.	Some set policy be adopted for the Middle School examination and the syllabus for various subjects. If some subjects are to be made compulsory this change should be introduced from 6th Class.	The Department is fully aware of the position and syllabus for various subjects is introduced after thorough consideration by the P.A.B.E. It has rightly been stressed that if some subjects are to be made compulsory the change should be introduced from the VI class. This aspect is kept in view while introducing any change in the syllabus.
20.	At least 10 percent of the total outlay of Fourth Five Year Plan should be ear marked for educational development. No state should allot less than 20 per cent of its budgeted expenditure for Education.	The Fourth Five Year Plan is yet in its formative stage. The proposed suggestion of 10 per cent will be kept in view and Government will allocate provision to General Education to the Maximum extent possible, keeping in view its resources and outlay for the Fourth Plan and its requirements for more essential schemes relating to agricultural production, multi-purpos-Projects anti floods and water logging projects, etc. As regards share in the total resources of the states the present share of General Education' comes to about 15 per cent and every year it goes on increasing. Only this much percentage could be provided by Government this year in the context of its over-all requirements.

No.	Question	Answer
21.	Education should be geared more directly to the production efforts of the nation and school and colleges should have agricultural and daily farms and industrial workshops attached to them. We, therefore, demand that another sum of Rs 2,200 crores should be ploughed back to education from Industry and Agriculture.	Every effort is being made for the strengthening of teaching of Agriculture and giving of technical bias to General Education. The subjects of Agriculture and Animal Husbandury have been introduced as elective groups in High Schools. Agriculture has also been introduced as Elective Group in 31 Higher Secondary Schools. In the Fourth Five-Year Plan it is contemplated to introduce Agriculture in large number of High and Higher Secondary Schools. Agricultural Farms are attached with 74 High Schools. Under the Scheme 'Russian Pattern of Education' Technical bias to general education has been given In three schools at Jullundur, Patiala and Jagadhri. Under the 'Practical Arts Education' 160 teachers during 1964-65 and 50 during 1965-66 have been/are being trained in the trades of Carpentry, Welding, Smithy, Turning and Electronics. These teachers after getting training will impart training in 150 Middle Schools. Technical Group has also been introduced in 22 Higher Secondary Schools as Elective Group. The Education Department is thus already doing what it can, in the matter subject to availability of funds. The demand for divertion of funds from Industry and Agriculture Departments to the Education Department is difficult to be accepted. Those Departments are also important and need to be provided adequate funds to implement their development Schemes.
22.	Target of Compulsory and Universal Education for the age-group 6-11 should be attained by the end of Fourth Five-Year Plan.	Education has been made compulsory for the children of age group 6-11 with effect from the year 1961-62, under a phased programme. During the year 1965-66 children of entire age group 6-11 are liable to compulsion. The target fixed for in the Third Plan in respect of this age.-group is 89 per cent. The actual achievement is expected to be 80 per cent. During IV Five-Year Plan cent per cent children in this age-group are expected to be brought to Schools.
23.	Education at all Stages for all boys belonging to families having an income level up to Rs 1,200 a year and for all girls belonging to families of Income level up to Rs 2,400 a year should be provided free.	Under the free Education policy the following benefits are admissible to students studying in Government Schools :— (i) Free Education up to VIII Class.

[Education Minister]

1	2	3
		(ii) In classes IX and X in High School and IX to XI in Higher Secondary Schools the fees are charged as under :— (a) Education is free in case of students belonging to Harijans whose parents'/guardian's income is up to Rs 1,800 per annum. (b) Free Education for girls whose parents'/guardian's income is less than Rs 3,000. (c) Half fee is charged from boys whose parents'/guardian's income ranges between Rs 1,000 to 3,000 excluding Harijans. (d) Boys whose parents'/guardian's income exceeds Rs 3,000 are charged fee at full rates whereas girls falling under this income-group are charged fee at half rates. No further extension is possible at this stage.
24.	For National integration of India a uniform pattern and Standard of education is most essential. A National Foundation for good teaching aids, appliances, text books and referance books should immediately be set up.	This view has also been expressed by the Sampurnanand Committee on National Integration. There can be no two opinions about this. A uniform pattern and standard of education has almost been accepted by all the States. A three years degree course after Higher Secondary Stage is now prevalent in most of the States. Similarly, Higher Secondary Pattern of Schooling for 11 years has also been accepted by most of States Governments. The pattern of elementary education for eight years is also common in the countary. For the teaching of languages all the State Governments have accepted the three languages formula. Similarly General Science and Social Studies find a place in the curricula of all the states. This gives ample evidence that the country has accepted a uniform pattern and standard of Education for the sake of national integration. The whole matter is being reviewed further by the Education Commission, India.

25.	A national and uniform pay structure and service conditions of teachers all over India should be established immediately.	This is a good idea, but as education is not yet a concurrent subject, it may not be possible to implement it at this stage.
26.	Old age pension scheme should immediately be for non-Government school employees of India.	This may not be possible unless the voluntary organisation controlling Non-Government Schools take an initiative in the matter.
27.	Teachers of India must be guaranteed security of service by having suitable legislations.	Government of India are considering the enactment of a Model Education Act. It will ensure security of Service to the Teachers. The provisions of the Punjab Education Code shall have legal sanction, after such an Act is passed by the State Legislature.
28.	The teachers who have been hit the hardest by the recent rise in prices should immediately be paid Rs 80 more as D. A. and an additional T. A. of 25 paise per point rise in the cost of Living Index taking December, 1963 as the base. No distinction be made between Govt. and non-Govt. employees.	The D.A. in the case of teachers in Government Schools has been raised along with other Government Servants. The privately managed Schools will be required to pay the same grades to their counterparts under the liberalised Grant-in-Aid rules as soon as enforced.
29.	Grants must be paid in time.	It is ensured that the grants are released in time.
30.	No ceiling on Govt. contribution.	The demand is vague.
31.	A Secondary Education Grant Commission be set up for effective control and with a view to introduce a national policy in education.	The State Government is not concerned. This concerns the Government of India. It will, however, be worthwhile waiting for the recommendations of the Education Commission, India.

COMPLAINTS AGAINST THE PRESIDENT, MARKET COMMITTEE, KURALI, DISTRICT AMBALA

3043. **Comrade Shamsher Singh Josh** : Will the Minister for Home and Development be pleased to state whether the Director, Marketing Board has received in the year 1965 any complaints against the President, Market Committee, Kurali, district Ambala, if so, the contents thereof and the details of the action, if any, taken thereon, if no action has so far been taken, the reason for the same ?

Sardar Darbara Singh : Yes. A complaint from Shri Raja Singh, Sarpanch, Gram Panchayat, Chatanli, tehsil Kharar, was received by the Director of Marketing, Punjab. The complainant had alleged that the Chairman, Market Committee, Kurali, advanced a sum of Rs 4,032.80 to Shri Khusi Ram, Brickkiln-owner and a favourite of the Chairman for the supply of Bricks to the Market Committee, Kurali. An enquiry into the matter has since been conducted, which is under examination.

SUPPLY OF BHAKRA CANAL WATERS TO CERTAIN AREAS OF RUPAR AND KHARAR SUB-DIVISIONS

3044. **Comrade Shamsher Singh Josh** : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state —

*(a) whether Government ever undertook any survey to provide Bhakra Canal Waters to any areas of Rupar and Kharar Sub-Divisions, if so, a copy of the survey report be laid on the Table of the House ;

(b) if the answer to part (a) above be in the affirmative, whether Government has prepared or intend to prepare any scheme based on the said Survey Report for providing water to the said sub-divisions or any area thereof ?

Chaudhri Rizaq Ram : (a) Bhakra Nangal project does not cover these sub-divisions. These areas cannot then be considered suitable for irrigation from the Bhakra system.

(b) Does not arise.

INCREASE IN HOUSE RENT OF PRIVATE HOUSES AT CHANDIGARH

3045. **Shri Amar Singh** : Will the Minister for Capital and Housing be pleased to state whether he is aware of the fact that the house-rent of private houses at Chandigarh is increasing and causing great difficulties to the tenants as they are being forced to vacate the houses if the rents are not increased as desired, if so, the details of the steps so far taken by the Government to check this tendency, if no steps have been taken, the reasons therefor ?

*_Note._—For revised reply given by the Irrigation and Power Minister on Unstarred Question No. 3044, please see P.V.S. debate, Vol. No. 25 dated 23rd November 1965. It is printed as Unstarred Question and Answer in that debate.

Sardar Prem Singh Prem : It is true that the house-rent of private houses at Chandigarh has increased recently. The property at Chandigarh is, however, exempted from the operation of the provisions of the East Punjab Rent Restriction Act for 25 years as per press-note issued by the Government on 22nd May, 1959. This was with a view to give fillip to the the development of Capital. Hence in view of the Government assurance it is not considered desirable to take any action to check the increase in rent.

SURVEY OF ROAD FROM CHINTPURANI TO PONG DAM

3046. Thakur Mehar Singh : Will the Minister for Public Works be pleased to state—

(a) whether it is a fact that a survey of the road between Chintpurani and Pong Dam *via* Chambian, Gular Dhar, Bhatehar, Behr (Kotla), Jol, Jamdaur and Reri Kuthehara (Teris) has been made, if so, whether it has finally been approved by the Government;

(b) if the survey has been approved finally, the tentative date by which the work on the said road is likely to be started/completed ?

Chaudhri Ranbir Singh : (a) and (b) No detailed survey of the road has been carried as yet. However, the road is included in the long-range plan for Hill areas. 4.5 miles length of this road costing Rs 6. lacs lying in the Hoshiarpur District is included in the tentative proposals for the 4th Five-Year Plan and the remaining length of 14½ miles in Kangra District costing Rs 22 lacs, is likely to be included in the 5th Five-Year Plan. Construction of the road in the due course would depend on the availability of funds.

REPRESENTATIONS FOR OPENING A HEALTH CENTRE AT KOTLA BEHAR, DISTRICT KANGRA.

3047. Thakur Mehar Singh : Will the Minister for Health be pleased to state whether Government has received any representations during the year 1965 from (i) Panchayat Kotla, (ii) Principal, Government Higher Secondary School, Kotla (iii) Kangra Sabha, Chandigarh and (iv) Arthik Sudhar Sabha, Kotla for the opening of Health Centre at Kotla Behar, Tehsil Dera district Kangra, if so, the action, if any, taken by the Government to meet the above demand of the ilaqa which has a population of 5,000 people ?

Mrs. Om Prabha Jain (Health Minister) : A representation was received only from the Panchayat Kotla for the opening of Health Centre at Kotla Behar, tehsil Dera, district Kangra. In view of the following places having already been approved for locating the Sub centres of Primary Health Centre Dadasiba in Pragpur Block under the reorganised Family Planning Programme and the Government Ayurvepic Dispensary functioning at Kotla, there is no justification to open a Sub-Centre at Kotla Behar :—

(i) Tihari ;

(ii) Jandaur; and

(iii) Bathra.

ADJOURNMENT MOTION

Deputy Speaker : There is one Adjournment Motion by Shri Balramji Dass Tandon.

(The hon. Member was not present in the House.)

CALL-ATTENTION NOTICES

Deputy Speaker : Now the House will take up Call-Attention Motions.

Call Attention Notice No. 129 by Chaudhri Inder Singh Malik.

(The hon. Member was not present in the House.)

Deputy Speaker : Next Call-Attention Notice No. 130 by Sarvshri Kulbir Singh and Satya Dev.

(None of the hon. Members was present in the House.)

Deputy Speaker : Next Call-Attention Notice No. 131 is again by Sarvshri Kulbir Singh and Satya Dev.

(None of the hon. Members was present in the House.)

Deputy Speaker : Next Call-Attention Notice No. 132 by Shri Ram Dhari Balmiki.

(Serial No. 132)

Shri Ram Dhari Balmiki : I beg to draw the attention of the Minister concerned to the fact that Shri Chand Ram, Minister for Justice and Welfare suggested on 12th August, 1965 that the sweepers should withdraw their strike unconditionally and to accept the Deputy Commissioner, Kapurthala, as arbitrator and further gave an assurance that full justice will be done in respect of the demands. On this advice the sweepers on strike and the Municipal Committee, Phagwara, accepted the arbitration. The President, Municipal Committee also assured that Resolution No. 118, dated the 10th August, 1965 will not be implemented and thus withdrew it so that congenial atmosphere may be created. Now on 27th October, 1965 the Deputy Commissioner gave the following decision :—

(1) Model Sweeper Service Rules may be enforced immediately and required number of Sweepers may be appointed in accordance with these rules.

(2) The thirty water-carriers, who had been removed previously be reinstated on the basis of their security and their period of absence be treated as leave period.

(3) The newly appointed 27 Sweepers be removed from service at once and in case more appointments have to be made after reinstating their 30 water-carriers then these appointments be made out of the said 27 Sweepers.

(4) The period of absence of all the Sweepers, who are on strike should be treated as leave without pay and that may not be treated as absence from duty.

The Punjab Government have failed to get the arbitration implemented and in contravention thereof the Committee have removed 55 more sweepers.

उपाध्यक्षा : इस को एडमिट किया गया है । गवर्नमैन्ट को इस के बारे में स्टेटमेन्ट करनी चाहिए । (It is admitted. The Government should make a statement).

मुख्य मन्त्री (श्री राम किशन) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, फगवाड़ा म्यूनिस्पल कमेटी के अन्दर जो स्वीपर्ज़ की स्ट्राइक का मामला चल रहा है इसके बारे में एक डैपूटेशन मुझे मिला है और मिनिस्टर फार लोकल गवर्नमेंट को भी एक डेपूटेशन आज शाम को मिल रहा है और ख्याल है कि एक-दो दिन में इस बात का खातर खाह फैसला हो जाएगा ।

(*Serial No. 134*)

Comrade Babu Singh Master : I beg to draw the attention of the Government to the sad and deplorable state of affairs of the Art Gallery of the Arts College, Chandigarh, as the total contents of the museum previously at Simla have not been brought here from Simla uptil-now.

At the time of emergency the exhibition of the Arts Gallery of the Arts College, Chandigarh, was closed for the visitors and even for the College students in order to safeguard the master-pieces of the well-known well-reputed Artists like Shri Sobha Singh and Shri Thaker Singh, etc.

The Principal of the Arts College, Chandigarh, took out valuable production and master-pieces from the Art Gallery to Tagore Theatre in Sector 18, Chandigarh, in order to take cheap popularity. The action of the Principal is in contravention of the laid down policy of not exhibiting the precious pieces of culture in public places even in Arts Museum during emergency. The action is highly objectionable and anti-national.

Deputy Speaker: This is admitted. Government to please make a statement.

(*Serial No. 135*)

Comrade Babu Singh Master : I beg to draw the attention of the Government regarding the appointment of a special officer in connection with organising and mobilising a campaign regarding Anti-Punjabi Suba in the State at this crucial hour. This decision of the Government is highly objectionable and will adversely affect the unity of the Punjab is resulting chaos in the country.

उपाध्यक्षा : इसको एडमिट किया जाता है। गर्वनमैंट इस के बारे में स्टेटमैन्ट दे । (It is admitted. The Government should make a statement.)

मुख्य मन्त्री: डिप्टी स्पीकर साहिबा, ऐसा मालूम होता है कि मैम्बर साहिब को कोई गलत इत्तेलाह मिली है । गवर्नमैंट ने कोई ऐसा अफसर इस काम के लिये नहीं लगाया और न ही मुकर्रर किया गया है ।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਜਨਾਬ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਕ ਅਫਸਰ ਮਿਸਟਰ ਸਰੀਨ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਕਾਲਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਵਖਰਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਂਟੀ-ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕਰੇ ?

ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ (ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਪਰਤਾਪ ਗਰਗ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਕਰਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਲਸ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।

Sardar Gurnam Singh : What is he ?

Chief Parliamentary Secretary : He is one of the Deputy Directors.

शिक्षा मन्त्री (श्री प्रबोध चन्द्र) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, जैसा कि अभी-अभी मेरे फाजल दोस्त ने बताया है मैं अर्ज कर दूं कि हमने पंजाबी सूबा की फलैपिंग के लिये कोई ऐसा अफसर नहीं रखा । जिस आफिसर को रैफर क्या गया । वह गवर्नमैंट के एक आफिस का डिप्टी डायरैक्टर है। इसके पास टैलीफोन भी हो सकता है । यह आज का नहीं सरदार प्रताप सिंह के वक्त से लगा हुआ है .....

Sardar Gurnam Singh : Madam, Deputy Speaker, the Education Minister has given us some information. It is not a question of new appointment. The question is that Mr. Sarin, Deputy Director, has been assigned the duty to carry on propaganda against the formation of a Linguistic State. He has actually briefed the Press. We have got information. Let the Government deny that.

मुख्य मन्त्री : यह बात मैं हाउस में बड़े ज़ोर से कहना चाहता हूँ कि इस मतलब के लिये हमने ऐसा कोई भी आफीसर नहीं रखा । यह एक गलत फहमी है जो जब भी चाहें आप मुझे मिल कर दूर कर सकते हैं। हमारे पास ऐसा कोई भी आफिसर एप्वायंट नहीं किया हुआ जो पंजाबी सूबा के खिलाफ किसी तरह का प्रचार करे ।

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯਾ ਇਸ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਾਪੇਗੰਡਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਉਗੇ ।

मुख्य मन्त्री: आप हैपहैजर्ड ली एक सवाल में क्यों जा रहे हैं। मैं बार-बार यह कह रहा हूँ सरकार की तरफ से बिलकुल कुछ भी नहीं हो रहा है ।

(*Serial No. 136*)

Comrade Babu Singh Master : Madam, I beg to draw the attention of the Minister concerned towards the instructions of the Government prescribing tests for promotion of Clerks to Assistants and determining their seniority on the basis of said tests, which were held illegal by the Punjab High Court in September, 1964. have not so for been withdrawn as a result of which persons who were promoted/made seniors on the basis of instructions are still deriving the benefit whereas the persons who were not promoted/made juniors on the basis of the said illegal instructions continue to suffer.

Now rules drawn by the Government are to take effect from the date of their publication and will not cover the cases of persons affected by the said illegal instructions. There should be no hitch in withdrawing the instructions since declared illegal, null and void by a court of law. In fact these instructions ought to have been withdrawn immediately after these were finally held illegal by the Punjab High Court.

In case the question of withdrawing the said illegal instructions is linked with the case regarding the finalisation of new Rules, which may take another year or more, the persons who are already suffering on the basis of illegal instructions will continue to suffer and hence calls the attention immediately in order to impart justice to the aggrieved and the victimised.

Deputy Speaker : It is admitted. Government may make a statement.

मुख्य मन्त्री : अगर आनरेबल मैंबर के पास कोई ऐसा केस हो तो वह मेरे नोटिस में लायें। गवर्नमेंट की तरफ से उस पर फौरन गौर किया जायेगा।

Deputy Speaker : Call-Attention Notice No. 137 stands in the name of Chaudhri Inder Singh Malik.

(*Chaudhri Inder Singh Malik was not present in his seat*).

श्री रामधारी वाल्मीकि : On a point of order Sir मैं यह पूछना चाहता हूँ कि मेरे सवाल के जवाब में जैसे चीफ मिनिस्टर साहिब ने जवाब दिया है कि 3–4 रोज में फैसला कर देंगे कम-अज़-कम यह तो बता दिया जाता कि इन स्वीपरों को रखना है या नहीं रखना। फगवाड़ा के उन लोगों में बड़ी बेचैनी है......

उपाध्यक्षा : आप क्यों इतनी तेज़ी दिखा रहे हैं फगवाड़ा के अग्निहोत्री जी भी बैठे हुए हैं। (Why is the hon. Member so much agitated ? Shri Agnihotri hailing from Phagwara is sitting here with composure.)

मुख्य मन्त्री : मैं यह पूछना चाहूँगा कि आया इसके मुताल्लिक आपने काल-अटैनशन मोशन एडमिट कर लिया है ?

Deputy Speaker : Yes I have admitted. अगर इसके मुताल्लिक मैंबर को कोई ऑबजैक्शन हो तो आप उस का मुनासिब जवाब दे दें। (Yes I have admitted it. But if the hon. Member has still some doubts, then the Chief Minister may satisfy him in an appropriate manner.)

मुख्य मन्त्री : आगे तो ऐसे कभी डिस्कशन होती नहीं कि अगर एडमिट भी हो जाये फिर भी डिस्कस हो। यह एक नई बात होगी।

Minister for Education : Madam, there cannot be any discussion or any question on the statement made by Government. If you will set this precedent, there will be no end to it. I would, therefore, respectfully request the Deputy Speaker to consider her ruling. The hon. Chief Minister has made a statement in reply to the Call-Attention Motion of the hon. Member and it is not for the hon. Member to put questions or cross questions or give any version of his own.

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਮੈਂ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਰੂਲਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੋਸ਼ਨ ਐਡਮਿਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਾਕਫ਼ੀਅਤ ਲੈਣੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਬੈਠ ਜਾਉ ਜੀ । (The hon. Member may resume his seat.)

PAPERS LAID ON THE TABLE

Shri Ram Partap Garg (Chief Parliamentary Secretary) : Madam, I beg to lay on the Table the Punjab Panchayat Samitis and Zila Parishads Provident Fund Rules, 1965, as required under section 115(4) of the Punjab Panchayat Samitis and Zila Parishads Act, 1961.

THE PUNJAB GENERAL SALES TAX (AMENDMENT) BILL, 1965.

(Resumption of Consideration clause by clause)

Deputy Speaker : The House will now resume consideration of the Punjab General Sales Tax (Amendment) Bill, 1965, clause by clause. Clause 11 is before the House.

All the following amendments to clause 11 given notice of by Shri Ramsaran Chand Mital will be deemed to have been read and moved, and will be discussed together.

Shri Ram Saran Chand Mital :

39. *For* the proposed section 14 (2) (a), *substitute* the following:—

"(a) maintain correct accounts of his business according to the mercantile system of his class of business prevalent in his town or village, as the case may be."

40. *For* the proposed section 14 (2) (c), *substitute* the following:—

"(c) allow his accounts—books to be authenticated in the prescribed manner at his place of business during working hours by the Assessing Authority or any other officer authorised by him in writing in this behalf"

41. In the proposed section 14 (4), line 4, *delete* "or any building or place."

42. Delate the proviso to the proposed section 14 (4).

43. In the proposed section 14 (6), line 4, delete "or any building or place".

44. In the proposed section (14) (6), line 4 between "dealer, 'and' "but" *insert* "for purposes of sale."

45. In the second proviso to the proposed section 14 (6) line 3, *delete* "one thousand rupees or".

46. In the second proviso to the proposed section 14 (6), line 4, *delete* "whichever is greater".

CLAUSE 11

श्री राम सरन चन्द मित्तल (नारनौल) : मेरी इस क्लाज़ पर 3–4 अमैंडमेंट्स हैं अगर तो इन पर वज़ीर साहिब ने गौर फरमा लिया हो और मानने को तैयार हो तो मैं स्ट्रैस नहीं करूँगा, बात यहीं खत्म हो जाती है। अगर नहीं तो मैं अपनी राये इसी तरह से देना चाहता हूँ।

पहली बात अकाउंट्स के मुताल्लिक है, वह यह कि जो अमैंडमेंट किया जा रहा है इस क्लाज़ का सम्बन्ध Section 14 of the Principal Act से है। अब इसको नया बनाया जा रहा है! इसमें जो लिखा है इसकी 3–4 बातों में संशोधन करने के लिये मैं निवेदन करना चाहता हूँ।

"(2) Every registered dealer shall—

(a) maintain day to day accounts of his business including stock accounts of each class of goods dealt in by him containing particulars of purchase or receipts, sales or deliveries and balance stock;"

इसका मतलब यह है, डिप्टी स्पीकर साहिबा, कि अगर यह नई दफा जाती नहीं है तो हर दुकानदार को अपनी रोज़ की खरीदोफरोखत का हिसाब-किताब प्रति दिवस दर्ज करना होगा। सारी चीज़ों का उसे इंदराज रखना होगा। यह ठीक है जो बड़े व्यापारी हैं वह मुनीमों के ज़रिये से अपटूडेट हिसाब-किताब रख सकते हैं। मगर छोटे दुकानदार जो मुनीम नहीं रख सकते कैसे रखेंगे। जिनके यहां मुनीम नहीं होता वह हिसाब नहीं रख सकेंगे इसलिये उनको इस रूल से हार्डशिप होगी। इसलिये मेरी अमेंडमेंट यह है कि इसे तो डिलीट होना चाहिए और अगर न हो सके डिलीट तो मैंने यह प्रपोज़ किया है —

"(a) maintain correct accounts of his business according to the mercantile system of his class of busines prevalent in his town or village, as the case may be".

जिसका मतलब यह है कि जिस लौकेलिटी के अन्दर वह डीलर रहता है, वह उसी ढंग से अकाउंट रखेगा जिस ढंग से उस लौकेलिटी में रखे जाते हों। क्योंकि यह सब को छूट कर जाता है। दूसरी मेरी अमैंडमेंट है —

(c) produce, if so required, such account books before the Assessing Authority or any officer authorised in this behalf by the Assessing Authorities for authentication in the prescribed manner"

[श्री राम सरन चन्द मित्तल]

इसका मतलब यह है कि किसी भी दुकानदार को कहा जा सकता है कि अपना रजिस्टर लाओ, हम आथेंटीकेट कर दें। जहां तक आथेंटीकेशन करने वाली बात है उसमें किसी को डिसप्यूट नहीं है लेकिन जो प्रोड्यूस करने वाली बात है उस पर ऐतराज़ है क्योंकि ए.टी.ओ कहीं भी 10 या 15 मील की दूरी पर बैठ कर यह कहलवा सकते है कि अपने अपने रजिस्टर भेजो हम आथैंटीकेट करते हैं। इसमें लोगों को जाने आने की दिक्कत होगी। हमने यह रखा है कि अगर आफीसर लोगों के रजिस्टर अथैंटीकेट करना चाहे तो खुद या अपने किसी मातहत अफसर को depute कर दें, खुद dealer की दुकान पर जाकर या किसी दीगर अफसर को भेज कर वहां dealers की दुकान पर authenticate करें।

> "(c) allow his accounts-books to be authenticated in the prescribed manner at his place of business during working hours by the Assessing Authority or any other officer authorised by him in writing in this behalf"

यह व्यापारियों की सहूलियतें के लिये है। इस तरह से उनकी बुक्स आथैंटीकेट भी हो जाएंगी और उनको दिक्कत भी नहीं होगी। मेरी यही अमैंडमैंट है कि डीलर को उसकी दुकान से बलाया न जाए वहां पर ही उसकी बुक्स अथैंटीकेट हो जाएं। क्योंकि गवर्नमेंट का आबजैक्ट तो यही है कि बुक्स अथैंटीकेट हो जाएं न कि डीलर्स को तकलीफ देना। इसलिये ही गवर्नमेंट dealer को पिनडाउन करना चाहती है कि फलां-फलां बुक्स ही बिजनेस में रहें ताकि बाद में उनमें तबदीली न की जा सके। मेरी अमैंडमेंट से परपज़ हल हो जाता है।

वित्त मन्त्री : मैं एक अमैंडमेंट मूव करवा रहा हूँ फिर इन अमैंडमैंट्स की ज़रूरत नहीं रहेगी।

उपाध्यक्षा : राम प्रताप गर्ग जी, यह क्या है ? इनकी अमैंडमेंट तो आई नहीं मेरे पास। पहले उनको इजाजत लेना चाहिए थी। (*Addressing Shri Ram Partap Garg*) (What is this? I have not received any of his amendments. He ought to have first sought my permission.)

मुख्य संसद सचिव : आपके आफिस में आ गई है। मैंने भिजवाई है कहीं देर हो गई होगी।

चौधरी देवी लाल : मैं यह पूछना चाहता हूँ डिप्टी स्पीकर साहिबा, कि क्या चीफ व्हिप चेयर को व्हिप दे सकते हैं ?

उपाध्यक्षा : चेयर व्हिप मानने वाली नहीं है। यह आपको कैसे गलतफहमी हो गई ? (The Chair is not bound by the whip. How is the hon. Member labouring under this misunderstanding ?)

श्री बलरामजी दास टंडन: डिप्टी स्पीकर साहबा, मेरा प्वायंट ग्राफ ग्रार्डर यह है कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, पोलिटीकल लाइफ छोड़ कर फिल्म लाइन में जा रहे हैं, यह कहां तक ठीक है ?

सरदार ग्रजायब सिंह संधू : ठीक है जी, यह हम सब एक हैं उस फिल्म के लिये काम करने जा रहे हैं।

उपाध्यक्षा : मित्तल साहब, ग्राप बोलिये। (Let the hon. Member, Shri Mittal make his speech.)

श्री राम सरन चन्द मित्तल : मैं तो बोल ही रहा था मगर जब फाइनेंस मिनिस्टर साहब खड़े हो गए तो मुझे बैठना पड़ गया। मेरी दूसरी ग्रमैंडमेंट यह थी कि जो प्रोपोजड सैक्शन 14 है उसका सब-सैक्शन 4 है उसमें जहां है "or any building or place" उसको डिलीट किया जाए। क्योंकि जब यह डिलीट हो जाता है तो नीचे वाला proviso भी डिलीट हो जाता है ग्रौर उसकी जगह यह हो जाता है—

> "(4) For the purposes of sub-section (2) or sub-section (3), an officer referred to in sub-section (1) may enter and search any office, shop, godown, vessel, vehicle, or any other place of business of the dealer where such officer has reason to believe that the dealer keeps or is, for the time being keeping any book, account, register, document or goods relating to his business"

हमारे फिनांस मिनिस्टर साहिब इन सारी ग्रमेंडमेंट्स को समझ लेंगे ग्रौर ग्रगर मुनासिब समझें तो एक्सैप्ट कर लेंगे। जो यहां डिस्कशन हो रही है उसकी तरफ भी कोई पूरा ध्यान नहीं दिया जा रहा। मैं फिर से दोहराता हूँ।

उपाध्यक्षा : सरदार कपूरसिंह जी, ग्रटैंटिव हों। (Let Sardar Kapoor Singh be attentive.)

ਵਿਤ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੈਂ ਦੇਖ ਏਧਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।

उपाध्यक्षा : यह भी ठीक नहीं है कि ग्राप उठ कर कह दें कि मैं यह ग्रमैंडमेंट एक्सैप्ट करता हूँ। जो ग्रमैंडमेंट ग्राप मन्ज़ूर करते हैं वह मैम्बरों को सरकुलेट होनी चाहिए। (This is also not right that the hon. Minister should rise and say that he accepts a certain amendment which has not been circulated to the Members. Whatever amendment he accepts, it should have been circulated to the Members.)

वित्त मन्त्री : मैंबरों को सरकुलेट किये 6 दिन हो गए हैं।

उपाध्यक्षा : जो ग्रमैंडमेंट ग्राप इस वक्त मंज़ूर कर रहे हैं वह पहले सरकुलेट होनी चाहिए थी। एक हफ्ते का वक्फा था। ग्राप उसमें ग्रमेन्डमेन्ट्स भिजवा सकते थे ताकि यह पता लग जाता कि ग्राप यह ग्रमेन्डमेन्ट्स मनजूर करना चाहते हैं। इससे बहस का मौज़ू भी कम हो जाता। (The amendment which the hon. Finance Minister is accepting, should have been first circulated to the Members. There was an interval of one week. He could easily get them circulated during this period

[Deputy Speaker]

so that Members could know what amendment he was going to accept. This would have reduced the subject-matter of discussion.)

मुख्य संसद सचिव : यह अमेन्डमेन्ट्स नंबर 65 और नंबर 109 पर हैं। इस का पहले यश जी और श्री चांदी राम जी वर्मा ने नोटिस दिया था।

उपाध्यक्षा : मैं बेकायदगी से कोई बात नहीं करूंगी। यह अमेन्डमेन्ट 2 बज कर 5 मिन्ट पर आई है। इसका नोटिस पहले दिया जाना चाहिए था ताकि यह मैम्बरों को सरकूलेट हो सकती। (I would not do anything irregular. This amendment was received at 5 minutes past 2 p.m. The notice should have been given earlier so that it could be circulated to the Members.)

परिवहन तथा निर्यायन मन्त्री : डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप भी बहुत देर से इस हाऊस की मैम्बर चली आ रही हैं। आफीशल अमेन्डमेंट के बारे में रूल्ज़ में रिलेक्सेशन है। यह अमेन्डमेन्ट उस वक्त भी हो सकती है जब मिनिस्टर बोल रहा हो। अफीशल अमेन्डमेन्ट उस वक्त भी एकसैप्ट हो सकती है। उसके लिये पहले ज़रूरी नहीं कि सरकूलेट हो।

श्री राम सरन चन्द मित्तल : मैं ढिल्लों साहिब के इस बात पर यह अर्ज करता हूँ यह होना चाहिए कि मिनिस्टर साहिब पहले उस अमेन्डमेन्ट को मूव करें। इस अमेन्डमेंट को कब माना जाएगा ? यह मूव तो होनी चाहिए। मिनिस्टर साहब ने इसे मूव नहीं किया। उन्होंने अपनी राए बताई है। सैक्शन 14 की जो सब-सैक्शन 4 है उसमें से "Or any building or place" उड़ा दिया जाए। डिलीशन से यह सब-क्लाज़ इस तरह हो जाएगी।

> "For the purposes of sub-section (2) or sub-section (3), an officer referred to in sub-section (1) may enter and search any office, shop, godown, vessel, vehicle or any other place of business of the dealer where such officer has reason to believe that the dealer keeps or is, for the time being keeping any book, account, register, document or goods relating to his business :"

माननीय उपाध्यक्षा महोदया, इस अमैंडमेंट का यह नतीजा है कि जहां जहां पर "ऐनी बिल्डिंग और प्लेस" आए वह उड़ा दिया जाए, वह डिलीट करना चाहिए। जब रजिस्टर्ड डीलर की बिजनेस के लिये एक बिल्डिंग certificate में दर्ज होती है और हर एक डीलर को अपने रजिस्टर और अकाउंट बुक्स कानून के मुताबिक यहां रखना है, लिस्ट की एक कापी ई.टी. ओ. को देगा और एक प्रैमिसिज़ में लगायेगा, तो गवर्नमेंट को या असैसिंग अथारिटी को पता हो जाता है कि उसकी अकाऊंट बुक्स कौन-कौन सी हैं जिनको चैक करने का आफिसर को अधिकार है। इसके इलावा खर्च करने का अधिकार होगा, जो बिल्डिगं उसमें दर्ज हो उसमें ही सर्च की जाए। मेरी अमेंडमेंट है कि "एनी बिल्डिग और प्लेस" डिलीट कर दिया जाए। प्रोविजो भी डिलीट हो जायगा। In sub-section (6) of the proposed Section 14 " or any building or place" *delete* हो जाएगा।

इसके साथ साथ मेरी यह अमेंडमेंट है । हां इन्होंने पनिशमेंट को प्रोवाइड किया है। प्रोविज़ो इस तरह है--

"Provided further that the officer ordering the confiscation shall give the person affected an option to pay, in lieu of confiscation and in addition to the tax recoverable, a sum of money not exceeding one thousand rupees or double the amount of tax recoverable, whichever is greater."

मेरी राए में डबल दी अमाउंट आफ टैक्स को रिकवर करना है वह सफीशेंट है, काफी है । 1000 रुपये की आरबिट्रेरी पावर दे देना ठीक नहीं। Double the amount of tax recoverable रहना चाहिए "one thosand rupees"......"whichever is greater" *delete* होना चाहिए। दूसरी जगह जहां भी यह लफ़्ज़ हैं डिलीट हों।

(*Transport and Elections Minister rose to speak*)

मैं थोड़ी देर के लिये बैठ जाता हूँ, पहले यह बोल लें ।

उपाध्यक्षा : ढिल्लों साहिब, आप बाद में बोल लेना । (The hon. Minister, Shri Dhillon may speak afterwards.)

श्री राम सरन चन्द मित्तल : मैं तो चाहता था कि इसे जल्दी खत्म किया जाए क्योंकि इन्हें जल्दी है। जब इंट्रप्शन होती है तो मैं नहीं बोलूंगा । मेरी यह अमेंडमेंट थी कि सैक्शन 14 के सब-सैक्शन का जो प्रोविज़ो है और जो इस तरह है---

"Provided that books, documents and accounts of a period more than five years period to the year in which assessment is made shall not be so required."

यह 5 वर्ष तक अकाउंट डाकुमेंट्स को मेन्टेन करना यह बहुत लम्बा पीरियड है। यह 3 वर्ष काफी है । मेरी यह अमेंडमेंट है । मैं फिर से दोहरा देता हूँ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਇਹ ਬਿਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਇੰਟਰਪਟ ਨਾ ਕਰੋ । (Please do not interrupt.)

श्री राम सरन चन्द मित्तल : आपको भी कुछ और सुनना है। आपकी मौजूदगी में हुआ होगा, आपके पास कागज़ होंगे । तो मेरी यह अर्ज है कि दो बातें हैं। एक इवेज़न आफ टैक्स यहां हो वहां ठीक है इवेज़न को रोकना चाहिए। इसके साथ ही बिजनेस में कोई ऐसी रुकावट पैदा नहीं करनी चाहिए जिससे बिजनेसमैन का काम ही बंद हो जाए या उसे हैरेसमेंट हो। इससे कुरप्शन बंद नहीं होती। इसलिये मैं निवेदन करूँगा कि जो मैंने अमेंडमेंट्स दी हैं अगर इनको पसंद आएं तो मान लें ।

श्री बलरामजी दास टंडन (अमृतसर शहर पश्चिम) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरी अमेन्डमेन्ट इस क्लाज़ को डिलीट करने के लिये है। वैसे तो टैक्नीकली यह क्लाज़ आगे डीवाईड हो जाती है तो इसका डिलीट होना ही बनता है । जैसा कि फिनांस मिनिस्टर साहिब ने कहा है और इशोरेंस दी है इन्टरवीन करते हुए कि वह इसके बारे में संजीदगी से गौर ही नहीं कर रहे बल्कि उन्होंने अपना मन इसके लिये बना लिया है,

[श्री बलरामजी दास टंडन]

जहां तक तलाशी लेने का सवाल है वह इसको वापिस लेने के लिये तैयार हैं। डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं इस बात को समझने से कासिर हूँ कि आखिर कौनसी ऐसी ज़रूरत इनको पड़ गई है कि यह अमैंडिंग बिल इनको आज के मौजूदा वक्त में जबकि पंजाब के लोग अभी अभी दुशमन का मुकाबिला करके हटे हैं और उनके ज़खम अभी हरे हैं, लाना पड़ा है। इतना ही नहीं पंजाब के सारे लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। इस हाउस के मैम्बर साहिबान इसे वापस लेने के लिये ज़ोर डाल रहे हैं लेकिन सरकार और यह फिनांस मिनिस्टर साहिब इस बात पर बज़िद है कि यह बिल इसी सैशन में पास कराना है चाहे कितना लम्बा सैशन चले और चाहे हफ्ता हफ्ता के लिये सैशन एडजर्न करके समन करना पड़े। मुझे समझ नहीं आती कि आखिर इसमें कौनसी गीदड़सिंगी है जो सरकार इस बिल को पास कराने के लिये अड़ी बैठी है हालांकि इस बिल के ज़रिये टैक्स कोई 6 फी सदी की बजाए 10 फी सदी नहीं हो रहा है और न ही कोई एडीशनल इन्कम इससे होने जा रही है। पता नहीं यह सरकार पंजाब के लोगों को यह बताना चाहती है कि इस ऐमरजेंसी के वक्त पंजाब के लोगों ने जो इतना काम किया है, नुकसान उठाया है और दुश्मन का मुकाबिला किया है उसके बदले में सरकार आपको चोर समझती है और व्यापारियों के घरों की तलाशी लेने के लिये और उन्हें पीनेलाइज़ करने के लिये बड़े बड़े अख्तियार ले रही है। फौज को तो शायद यह इतना आर्मर सप्लाई न कर सके हों लेकिन अपने अफसरों को इस बिल के ज़रिये आर्मर दिया जा रहा है कि जिससे वह पंजाब की व्यापारी जनता को कुचल सकें और उन पर हमला कर सकें। समझ में नहीं आता कि आखिर कौन सी ऐसी बात है जिसके लिये यह सरकार बजिद है और उनके घरों तक की तलाशी लेने के लिये तुली हुई है। इतना ही नहीं कि उनके प्राइवेट मकानों की तलाशी लेंगे बलकि अगर रिपोर्ट कर दें कि पांच साल मकान छोड़ कर आगे भी किसी और के मकान पर शक है तो उसके प्राइवेट मकान की भी तलाशी लेंगे। रैज़ीडेंस के बारे में तो वज़ीर साहिब ने कह दिया लेकिन बाकी सारी की सारी चीज़ें इस कलाज़ में उसी तरह मौजूद हैं। फिर किताबों की अथांटीकेशन की बात की जाती है उसके बारे में अगर सिम्पल प्रोसीज़र बनाने के लिये कहा जाए जिससे कि पैसा भी ज़यादा आए, सरकार का पैराफरनेलिया भी कम हो और लोगों की भी हरासमेंट कम हो तो वह बात मानने के लिये सरकार तैयार नहीं। डिप्टी स्पीकर साहिबा, वज़ीर साहिब सुन नहीं रहे और बातें कर रहे हैं अगर आप कहें तो मैं बंद कर दूं..........

वित्त मंत्री: मैं सब कुछ सुन रहा हूँ।

श्री बलरामजी दास टंडन: मैं फिनांस मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर साहिब से मुअदबाना अर्ज़ करना चाहता हूँ कि यह सही मौका नहीं था कि ऐसे सख्त और स्ट्रिंजेंट मेज़र्ज़ हाउस में लाये जाते। लोगों ने अभी अभी फाइट दी है उनके ज़खम अभी हरे हैं। आज ज़रूरत इस बात की थी कि बड़े प्यार के साथ सरकार उन लोगों की पीठ पर हाथ रखती ताकि उनको महसूस होता कि पंजाब सरकार उनके साथ है लेकिन

आप उलटा डण्डा लेकर उनके पीछे पड़ गए हैं कि तुम चोर हो आपके घरों, मकानों की तलाशी लेंगे। आखिर इसी सैशन में इन हालात के होते हुए यह बिल लाने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी। अगला सैशन भी आना था और अगर ज़रूरी होता तो सारे सोच विचार के साथ और पूरी सलाह मश्विरे के साथ कुछ बातें अगले सैशन में लाई जा सकती थीं लेकिन यह मौका सही नहीं था मुझे समझ नहीं आती कि आखिर सरकार क्यों इसी वक्त इतनी जल्दी लोगों के ताजा ज़ख्मों पर नमक डालने के लिये बज़िद है। हां अगर इस बिल से कोई आमदनी बढ़नी होती और दस बीस करोड़ रुपया आना होता तो हम भी कहते ठीक है ले लो क्योंकि पैसे की डिफैंस के कामों के लिये बड़ी जरूरत है लेकिन हालत यह है कि एक पैसा भी इस बिल के ज़रिये बढ़ने वाला नहीं है। पता नहीं सरकार लोगों को बताना चाहती है कि वह उनके साथ हमदर्द नहीं है। पंजाब के व्यापारी आगे ही पंजाब से भाग रहे हैं लेकिन यह सरकार भी डंडा लेकर उन्हें जल्दी से जल्दी भगाने के लिये तैयार बैठी है। जो व्यापारी खेमकरण से उजड़ कर आए हैं जिन का लाखों का माल वहां रह गया है सरकार उनके माल का मुआवजा देने के लिये तैयार नहीं और उसके साथ उनको और पंजाब के बाकी व्यापारियों को महसूस कराना चाहती है कि वह उनको आराम से बैठने नहीं देगी। कल को परमात्मा न करे बार्डर डिस्ट्रिक्ट्स में कुछ हो जाए तो सरकार ने एक तरफ तो यह बता दिया है कि सरकार उनके माल का कोई मुआवजा नहीं देगी और दूसरी तरफ उनको तंग करने के लिये यह बिल पेश कर दिया है। चाहिए तो यह कि सरकार बार्डर ज़िलों में व्यापारियों को प्रापर्टी टैक्स वगैरा में रियायतें देती और दूसरी सहूलितें देती जिनसे सरकार की आमदनी में फर्क भी न पड़ता और लोगों की दिक्कतें भी कम हो जातीं। लेकिन सरकार कहती है कि 16 सेर गंदम और 8–10 रुपये माहवार तो दे देंगे लेकिन जो लाखों का माल आपका रह गया उसका एक पैसा भी मुआवज़ा नहीं देंगे। इसी पर बस नहीं बल्कि व्यापारी तबका को तंग करने के लिये यह बिल लेकर भी आ गई है। मैं समझता हूं कि पंजाब सरकार के लिये यह कोई शोभा की बात नहीं है। सरकार को चाहिए कि वह सैंटर की सरकार पर ज़ोर डालती और दूसरी स्टेट सरकारों को महसूस कराती कि पंजाब के इन लोगों ने जो नुकसान उठाया है और कुर्बानियां की हैं वह सारे देश की रक्षा के लिए की हैं इसलिये सारे देश के लोगों को इन लोगों की जिन्होंने भारी नुकसान उठाया है मदद की जाए और उनका नुकसान पूरा किया जाए लेकिन ऐसा न करके इस बिल को ले कर आ गए हैं ताकि इन लोगों को बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाए। मैं नहीं समझता कि इतना स्ट्रिन्जेन्ट मैयर लाने की क्या ज़रूरत थी कि उनके घरों की तलाशी ली जाए, और भी पांच सात मकानों की जिनके बारे में इत्तलाह हो कि दूसरे के मकान में कोई बात है तलाशी ली जाए, उनकी किताबों पर दस्तखत हों, ऐफीडेविटस भी लिये जाएं वगैरा वगैरा बातें की जाएं। मैं पिछले दिन भी फिनांस मिनिस्टर साहिब से कहा था कि अगर आपको इससे 16 करोड़ रुपया आता है तो व्यापारी 20/22 करोड़ रुपया देने को तैयार हैं आप इन बातों को खत्म करें। व्यापारी लम्पसम देने के लिये तैयार हैं, इससे आपका भारी अमला फैला कम होकर कुलेक्शन में खर्च की कमी भी होती है वगैरा

[श्री बलरामजी दास टंडन]

कई बातें मैंने कही थीं। उन्होंने भी कहा कि वह गौर करेंगे लेकिन पता नहीं इनका गौर कितना लम्बा है जो खत्म होने में नहीं आता और फिर उसी बात को करने के लिये बजिद हैं। यह ऐसी बात करने के लिये तैयार नहीं जिनसे इनके आमदनी बढ़े खर्च कम हो और लोगों को भी रीलीफ मिल सके। यह ज़िद नहीं तो और क्या है? आखिर यह टैक्स तो जनता ने देना है और दुकानदारों ने उनसे वसूल करके सरकार को देना है। दुकानदार तो मुफ्त के इनके कुलैक्टर बने हुए हैं लेकिन यह सरकार फिर भी इनका मुफ्त काम करने वालों के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। कल को दुकानदार सरकार से कह सकते हैं कि हम यह मुफ्त का काम नहीं करते और कुलैक्ट करके नहीं देते और हर एक दुकानदार पर सरकार अपना कुलैक्टर बिठा दे तो फिर क्या बात बनेगी। एक तरफ तो जो लोग आपका काम करते हैं उनको आप कुछ देते नहीं दूसरी तरफ उनके पीछे डंडा लेकर पड़े हुए हैं। यह कोई इन्साफ की बात है? वह कह सकते हैं कि हम पैसा इकटट्ठा करने के लिये तैयार नहीं हैं अपने आदमी दुकानों पर बिठाओ और वह टैक्स गाहकों से इकट्ठा करें।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, सरकार को आज के हालात के मुताबिक कदम उठाने चाहिएं ताकि पंजाब की जनता यह महसूस कर सके कि सरकार उन के विचारों से भली भान्ति जानकारी रखती है। लेकिन अब यहां पर क्या हो रहा है? सरकार इस बिल को पास करने में बजिद है ताकि लोगों को इस एक्ट के बनने के बाद तंग किया जाए। मैं समझता हूँ कि सरकार यह बिल पास करके आम जनता को तोहफा दे रही है जिससे यहां की जनता चीखोपुकार करे। इस लिये मैं चीफ मिनिस्टर साहिब और फिनांस मिनिस्टर साहिब को बड़े अदब से अर्ज करना चाहता हूँ कि इस बिल को सरकार वापिस ले ले। उसके बाद सरकार व्यापारियों के रीप्रिजेंटेटिवज को और कुछ लैजिस्लेटर्ज़ को बुला कर बातचीत करे ताकि इस बिल पर माइनूटली विचार किया जा सके। अगर सरकार को किसी बिल में किसी भी एमेंडमेंट लाने की जरूरत पड़ी तो वह अगले बजट सैशन म लाई जा सकती है और उस वक्त वह एमेंडमेंट पास कराई जा सकती है। ऐसा करने से पंजाब की जनता भी सरकार का सहयोग देगी क्योंकि वह समझेगी कि सरकार उन की बात को सुन कर ऐसा कर रही है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, मुझे उम्मीद है कि सरकार मेरी एमेंडमेट को मंजूर करेगी और सरकार इस क्लाज़ को डिलीट करन के लिये मान जाएगी।

कामरेड राम प्यारा (करनाल): डिप्टी स्पीकर साहिबा, जहां तक सेल्ज़ टैक्स की इवेजन का सम्बन्ध है, इसके बारे में सरकार और ट्रेडर्ज़ भी कहते हैं कि टैक्स की इवेज़न होती है। सरकार और ट्रेडर्ज भी कहते हैं कि जब सेल्ज़ टैक्स की इवेजन होती है तो उसमें गवर्नमेंट मशीनरी भी साथ शामिल होती है। मैं इस बात से सहमत हूँ कि टैक्स की इवेजन को रोकने के लिये दुकान और मकानों की तलाशी होनी चाहिए लेकिन इसके साथ यह भी होना चाहिए कि जब कोई व्यक्ति सरकार को बताता है कि फलां आफिसर ने ट्रेडर्ज से मिल कर टैक्स की इवेज़न कराई है तो उस अफसर

की तलाशी होनी चाहिए । इसमें कोई शक नहीं है कि आफिसर ट्रेडर्ज़ से मिल जाते हैं और वह ही टैक्स की इवेज़न कराते हैं। कई दफा तो अफसर ऐसी हेरा फेरी करते हुए पकड़े गए । यहां तक हुआ कि किसी घी के दुकनदार ने अपनी किताबों में सेल्ज़ टैक्स शो नहीं किया। इसकी वजह यह निकली कि कनसर्न्ड अफसर उस दुकानदार से 4 रुपये सेर घी खरीदता था। ऐसी सैंकड़ों मिसाले हैं। मैंने ही ऐसी हेराफेरी के 10-20 केसिज सरकार के नोटिस में लाए । अगर सरकार टैक्स की इवेज़न को रोकना चाहती है और टैक्स की इवेजन तलाशी के द्वारा रोकना चाहती है तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि सरकार को ट्रेडर्ज़ के घरों और दुकान की तलाशी करने के साथ साथ अफसरों के घरों की तलाशी करने में क्या एतराज है ? जब कोई डीलर्ज़ सरकार को इत्तलाह देता है कि फलां अफसर व्यापारी के साथ मिला हुआ है और टैक्स की इवेंज़न करा रहा है तो उसके घर की तलाशी होनी ज़रूरी है और उसके घर की तलाशी होनी चाहिए । ऐसा देखा गया है कि सब-इंस्पैक्टरों की तनखाह 150 और 200 रुपये के के दरमियान होती है लेकिन उनकी बीवियां 300 रुपये की साढ़ियां पहन कर बाजारों में घूमती हैं। उनके घरों में और कई किसम का सामान होता है। उसकी तलाशी होनी निहायत ही लाजमी होगी । वह डीलर्ज़ के मुकाबले में ज़्यादा लाभ उठाता है । सरकार को देखना चाहिए कि उनकी इतनी ज़्यादा इनकम कहां से हुई और उनको इतनी ज्यादा फैसिलीटीज़ कहां से मुहैय्या हो रही हैं। मैं मानता हूँ कि सारे व्यापारी इवेज़न नहीं करते हैं। टैक्स की इवेज़न तो कुछ ही बड़े बड़े व्यापारी करते हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट का, पुलिटीकल और बड़े बड़े अफसरों का हाथ और साया होता है । वह लोग तो परेशानी से बच जाते हैं लेकिन इसके विपरीत छोटे छोटे दुकानदारों को ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनको किसी तरफ से किसी किस्म की पेट्रोनेज़ नहीं मिलती । मैं समझता हूँ कि टैक्स की इवेज़न तो रुकती नहीं बल्कि उसी तरह ही टैक्स की इवेज़न होती है । अगर सरकार वाकई टैक्स की इवेज़न को रोकना चाहती है तो सरकार को एजंसी कायम करनी चाहिए । अगर कोई भी व्यक्ति टैक्स की इवेज़न के बारे में चाहे वह ट्रेडेर हो या आफिसर हो, सरकार को इत्तलाह देता है, तो उसी वक्त सरकार को टैक्स की इवेज़न रोकने के लिये सम्बन्धित व्यक्ति के दुकान और घर तथा अफसर के घर की तलाशी लेने के लिए पार्टी भेजनी चाहिए ताकि वहां पर सामान और रिश्वत मिल सके । इसके साथ इन्फरमेशन देने वाले को कमीशन देना चाहिए । अगर वह व्यक्ति 1000 रुपये की टैक्स इवेजन सरकार के नोटिस में लाता है तो उसे कम से कम 100 रुपया मिलना चाहिए ताकि इस बारे में लोगों के दिलों में प्रोत्साहन हो सके । इसके साथ अगर कोई डीलर सरकार के के नोटिस में लाता है कि फलां अफसर ने रिश्वत ली है तो सरकार को उसी वक्त उसके घर की तलाशी लेनी चाहिए । सरकार को ऐसा काम करने में किसी भी हालत में झिझकना नहीं चाहिए। अगर सरकार अपने फर्ज़ से कोताही करती है तो यह सरकार जनता की सरकार कहलाने के मुस्तहिक नहीं हो सकती है। अगर सरकार इसको वैलफेयर स्टेट बनाना चाहती है तो ऐसे हालात को एक मिनट के लिये टालरेट नहीं करना चाहिए । मेरी सरकार से सिफारिश है कि वह इस बिल के लिये कुछ लैजिस्लेटर्ज़

[कामरेड राम प्यारा]

को और डीलर्ज़ के नुमाइंदों को बुला ले और उनसे एट लेंग्थ विचार करे कि सेल्ज़ टैक्स की वसूली ज्यादा से ज्यादा किस ढंग से की जा सकती है, किस ढंग से टैकस की इवेज़न रोकी जा सकती है, कुरप्ट एलीमेंट से किस ढंग से छुटकारा पाया जा सकता है किस ढंग से व्यापारियों से आफिश्यल मशीनरी को कुरप्शन करने से बचाया जा सकता है और किस ढंग से डीलर्ज़ को परेशानियों से बचाया जा सकता है । ऐसा भी देखा गया है कि जो व्यापारी सेल्ज़ टैक्स की इवेज़न करता है वह दूसरे व्यापारी के मुकाबले में कम कीमत पर चीज़ लोगों को बेचता है । इस तरह से दूसरे व्यापारी को नुक्सान उठाना पड़ता है जब उसको इस बात का पता चलता है तो वह पहले व्यापारी की तरह मजबूरी में टैक्स की इवेज़न करके माल बेचना शुरु कर देता है । मिसाल भी मशहूर है कि खरबूज़ा खरबूज़े को देख कर रंग पकड़ता है । चालाक व्यापारी तो किसी न किसी तरह से बच जाता है लेकिन छोटे व्यापारी को परेशानियों का सामना करना पड़ता है । डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आपके द्वारा हाउस में एक मिसाल कायम रखना चाहता हूँ। कुछ व्यक्तियों ने पानीपत में एक बोगस लाइसेंस शो करके फर्म बना ली । उस फर्म ने चार लाख रुपये के करीब सेल्ज़ टैक्स की चोरी की और वह रुपया गबन कर लिया । बाद में वह व्यक्ति वहां से भाग गए । मैं ने इस बारे में सरकार के नोटिस में लाया कि वहां पर इतनी बड़ी सेल्ज़ टैक्स के हिसाब में हेरा फेरी हुई। उसके बारे में सरकारी दफ्तर में फाइल नहीं मिली लेकिन सरकार कंसर्न्ड आफिसर को या कंसर्न्ड फाइल मेनटेन करने वाले के विरुद्ध ऐक्शन नहीं ले सकी। सरकार ने उस पर कोई ऐक्शन नहीं लिया जिसके ऊपर इतनी हेराफेरी की ज़िम्मेदारी आती है। यही नहीं जो आफिसर पकड़े जाते हैं उनको भी महीनों भर सस्पेंड नहीं करती । उनसे कोई भी जवाब तलबी नहीं की जाती । एक कानून है कि जो व्यक्ति रिश्वत लेता हुआ पकड़ा जाए वह अरैस्ट हो जाए और ज़मानत पर रिहा हो तो उस व्यक्ति को सस्पेंड कर देना चाहिए लेकिन सरकार उनको सस्पेंड नहीं करती । मैं समझता हूँ कि मेरा शक वाजिब है कि ऐसे हालत में सरकार की नीयत अच्छी नहीं है । मैं समझता हूँ कि सरकार इनके प्रैशर के आगे स्टैंड नहीं ले सकती क्योंकि इसके पीछे कई दफा खासा पुलिटीकल प्रैशर होता है और कई बार आफिश्यल प्रैशर होता है जिससे केसिज हश्अप हो जाते हैं। मैं हाउस में एक मिसाल देना चाहता हूँ कि किसी व्यक्ति ने टैक्सों में हेराफेरी की वह व्यक्ति पकड़ा गया । उस पर केस चला लेकिन बाद में रिहा किया गया । जब वह रिहा हो गया तो उससे किसी दूसरे व्यक्ति ने रिहा होने का ढंग पूछा । तो उस ने बताया कि मैंने पहले लैजिस्लेटर्ज़ की सिफारिश करायी, लेकिन काम न बना। फिर बड़े बड़े बिजनेसमैनों की सिफारिश करायी, फिर भी कुछ न बना, उसके बाद अपने रिश्तेदारों की भी सिफारिश करायी लेकिन उससे काम न बना । अन्त में केस कोर्ट में चला । बाद में दिल्ली के फाइनेंस मिनिस्टर की सिफारिश करायी । मेरे कहने का मतलब यह है कि रुपये की रिश्वत देकर रिहा हो गया । इसी तरह से मैं एक और मिसाल हाउस के सामने रखना चाहता हूँ। एक आदमी किसी केस के कारण जेल के अन्दर डाल दिया गया उस से पूछा कि कैसे पकड़ा गया, कहने लगा कि मैंने रिश्वत ली थी ।

फिर क्या हुआ, आदलत से बरी हो गया। जब वह फिर पकड़ा गया तो पूछा कि अब क्या हुआ था तो कहने लगा कि रिश्वत दी थी। हालात यह हैं कि एक दफा तो रिश्वत लेने में पकड़ा जाता है और दूसरी बार रिश्वत देने में पकड़ा जाता है। तो मैं पूछता हूँ कि आया इस मामले में गवर्नमेंट विजिलैंट है या नहीं। इससे न तो टैक्स बढ़ेगा और न ही एवेज़न रुकेगी। इस लिये मैं सख्ती वाली बात की मुखालित नहीं करता क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एवेजन न हो। लेकिन मैं यह ज़रूर चाहता हूँ कि अगर डीलर्ज़ पर सख्ती करना चाहते हैं तो आफिसर्ज पर और आफिशियल्ज़ पर ज़रूर सख्ती होनी चाहिए। अगर फाइनेंस मिनिस्टर साहिब चाहते हैं कि डीलर्ज़ की तलाशी हो तो मैं मांग करता हूँ कि अफसरों और कर्मचारियों की तलाशी ज़रूर होनी चाहिए। मैं ज़िम्मेदारी लेता हूँ कि दस बीस केस एक साल में सरकार के नोटिस में ला सकूंगा।

इसके इलावा मैं एक तजवीज और देना चाहता हूं। सरकार किसी ज़िले में यह तजरुबा कर सकती है। आज एक करोड़ रुपया सालाना सरकार को सेल्ज़ टैक्स से मिलता है। जितना अमला सरकार ने इस काम के लिये रखा हुआ है उसको हटा दें और टैंडर काल कर ले कि जो आदमी सरकार को एक करोड़ दस लाख रुपया इकट्ठा करके दे दे उसको ठेका दे दिया जाएगा। इससे सरकारी खज़ाने में बीस लाख रुपया ज़्यादा आयगा। एक तो दस लाख रुपया जो अमले पर खर्च होता है वह बच जायगा और दूसरा दस लाख रुपया वह आदमी ज्यादा इकट्ठा करके देगा मशीनरी जो कुरप्ट होती है वह भी रुक जाएगी, डीलर्ज़ की कुरप्शन भी रुक जायेगी। अगर डीलर्ज़ ईमानदारी से काम करना चाहते हों तो सरकार को उनके रास्ते में नहीं आना चाहिए। इसलिये मैं सरकार से निहायत अदब से यह गुजारिश करूँगा कि अगर वह चाहते हैं कि एवेजन रुके तो अफसरों को भी अपनी चारपाई के नीचे नज़र मारनी चाहिए कि कितने चोर बैठे हुए। डिप्टी स्पीकर साहिबा, इन शब्दों के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और इतना फिर कहता हूँ अगर डीलर्ज़ की तलाशी होनी है तो अफसरान और औफिशियल्ज़ की भी तलाशी ज़रूर होनी चाहिए।

श्री **मोहन लाल** (बटाला): डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैंने क्लाज़ 11 में अमैंडमेंट 15 से 21 दी हुई हैं। पिछले रोज़ स्पीकर साहिब ने फरमाया था कि अमैंडमैंट्स को फार्मली मूव करने की ज़रूरत नहीं है। दे शैल बी डीम्ड टू हैव बिन रैड एंड मूव्ड। अगर आपका भी यही हुक्म है तो यह अमैंडमैंट्स भी मूव्ड ही समझी जाएंगी।

Deputy Speaker : The following amendments by Shri Mohan Lal shall be deemed to have been read and moved—

In the proviso to the proposed section 14 (1), line 2, *for* 'five' *substitute* 'three.

Delete sub-section (2) (a) of the proposed section 14.

In the proposed section 14 (3) (a), line 2, for 'ten' *substitute* 'four'.

[Deputy Speaker]

In the proposed section 14 (3) (b), line 1, *for* 'sixty' *substitute* 'thirty'.

In the proposed section 14 (6), line 2, delete 'and cofiscate'.

In the proposed section 14 (6), line 6, between 'documents' and ' : ' insert 'and shall impose by way of penalty double the amount of tax recoverable on such goods.'

Delete both the provisos to the proposed section 14 (6).

Now Shri Mohan Lal may proceed with his speech.

श्री मोहन लाल : मैं मुख्तसर सी बात अर्ज़ करूँगा। मेरी अमैंडमेंट्स में से कुछ तो ऐसी हैं जिनके बारे में सरकार पहले इशारा कर चुकी है कि उनको मंज़ूर कर लिया जाएगा । उनके बारे में बहुत कुछ कहना ज़रूरी नहीं होगा । मिसाल के तौर पर सैक्शन 14 की जो सब क्लाज़ दो ए है उसको डीलीट करने के लिये मैंने अमैंडमेंट दी है। जब जेनरल डिस्कशन के समय डीबेट में चीफ मिनिस्टर साहिब ने इन्टरवेनशन की थी तो उन्होंने इशारा किया था कि इसकी डीलीशन को मंज़ूर कर लिया जाएगा । इसलिये इस पर ज्यादा विस्तार से कहना मैं मुनासिब नहीं समझूंगा । मैं समझता हूँ कि फाइनेंस मिनिस्टर साहिब इस अमैंडमेंट को मंज़ूर करते हुए सैक्शन 14 के सब सैक्शन दो ए को डीलीट करना मंज़ूर कर लेंगे । इस से पहले भी मैं सेक्शन 14 (1) की प्रोविसो में अमेंडमेंट दे चुका हूँ। मैंने यह अमेंडमेंट दी हुई है कि पांच साल की बजाए तीन साल कर दिया जाए। इस बारे में भी मैं इस वक्त लम्बी दलील नहीं देना चाहता। पहले भी इस बात का चर्चा हो चुका है कि जहां तक सरकार ने अपने पैसे वापस देने का समय रखा हुआ है वह तो तीन साल की म्याद रखी हुई है । इसलिये मनासिब होगा कि जहां तक व्यापारियों के समय का सम्बन्ध है वही म्याद रखनी चाहिए जोकि सरकार ने अपनी ओर से पैसे देने की रखी हुई है । वैसे मैं दोहरा कर अपनी तरफ से फिर कहूंगा कि तीन साल का अर्सा किताबों के रखने या उनके जांच पड़ताल करने का टैक्स लेने के लिये काफी अर्सा होना चाहिए। जहां पर सरकार ने टैक्स लेना है या वसूली करनी है वहां पर सरकार को वह अर्सा लम्बा नहीं करना चाहिए । अगर सरकार यह मांग करती है कि पांच साल तक किताबें देखी जा सकें और हर व्यापारी पांच साल तक अपनी किताबों को संभाल कर रखेगा तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टैक्स की असेसमेंट में या वसूली के बारे में कितनी देर होगी और इससे खराबी पड़ेगी । बहुत नुकसान होगा। इसलिये यह सरकार के अपने इन्ट्रेस्ट की बात है कि पांच साल का अर्सा इस काम के लिये न रखे बल्कि इसकी जगह पर जो मैंने तजवीज़ दी है तीन साल का अरसा मंज़ूर कर ले ।

आगे सैक्शन 14 (3) (ए) में मैंने दस दिन की बजाए यह तजवीज़ की है कि चार दिन कर दिए जाएं । इस वक्त सरकार ने यह प्रोपोज़ किया है कि सरकारी कर्मचारी सेल्ज़ टैक्स के व्यापारियों की किताबों को जोकि चालू हैं अपने कब्जे में दस

दिन तक रख सकता है और दस दिन के बाद वापस करेगा । मैं समझता हूँ कि यह प्रोपोज़ल करते समय सरकार ने व्यापारियों की तकलीफ को अपने सामने नहीं रखा है। जो चालू किताबें होती हैं उनमें रोज़ाना इन्दराज़ करना पड़ता है । लेने देने का हिसाब किताब हर प्रकार का उनमें रखना पड़ता है । अगर चालू किताबें दस दिन के के लिये दुकान में न हों, सरकारी तहवील में रहें तो व्यापारी के काम में रुकावट पड़ेगी । इसलिये इस काम के लिये चार दिन भी बहुत हैं । इससे भी कम दिन हों तो अच्छा है । लेकिन मेरी राए में दस दिन बहुत ज्यादा हैं। इससे काफी दिक्कत और नुकसान भी होगा । किताबें न होने की वजह से व्यापारी लोग वसूली नहीं कर सकेंगे । इसलिये मैं इस सिलसिले में अर्ज़ करूंगा कि मिनिस्टर साहिब दस दिन की बजाए चार दिन मान लें । अगला सैक्शन 14(3) (बी) में साठ दिन की बजाये तीस दिन करने में मैंने तरमीम रखी है । किसी व्यापारी की किताब सरकार अपने कब्ज़े में साठ दिन के लिये रख छोड़े यह भी गैर मुनासिब बात होगी । इससे सरकार का कोई ज्यादा काम नहीं निकलता और व्यापारियों को नुकसान होता है। जैसे मैंने अभी अभी कहा सरकार को अपने काम में सरकारी कर्मचारियों को लम्बा अरसा ढील कभी नहीं देनी चाहिए बल्कि कम से कम अरसा उनको देना चाहिए ताकि थोड़े अरसे में टैक्सेशन की असेसमेंट मुकम्मल हो जाए । इसलिये मेरी राए में साठ दिन बहुत ज्यादा हैं तीस दिन ही काफी होंगे ।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, आगे मैंने मांग की है कि सैक्शन 14(6) में से कनफिस्केट का लफ्ज़ डीलीट कर दिया जाए। इसके बारे में मिनिस्टर साहिब खुद मान चुके हैं इसलिये मैं अपनी बहस को दोहराना नहीं चाहता । मेरा ख्याल है कि इस अमैंडमेंट को भी बिना किसी बहस के वह मान लेंगे । मैंने प्रोविसो दो को डीलीट करने की भी मांग की है चूंकि इसमें रीज़नेबल अपरचुनिटीज आफ हीयरिंग देने का सवाल था। तो इस तरह से सरकारी कर्मचारियों को जो डिस्क्रीशन की पावर्ज़ रीज़नेबल अपरट्यूनिटी प्रोवाईड करने के सम्बन्ध में दी हुई है तो मैंने अपनी अमैंडमैंट के जरिए उसको लिमिट किया है । जैसा कि बार बार एतराज़ भी किया गया है, और मैं उसको दुहराना भी नहीं चाहता, ऐसी डिस्क्रीशन सरकारी कर्मचारियों को नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि उसका सही इस्तेमाल नहीं होता, गलत इस्तेमाल होता है । यह मैंने सरकार के अपने हित की बात की है कि इस डिस्क्रीशन को उड़ा दिया जाए। इसलिये, डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं अपनी अमैंडमेंट नम्बर 20 पर खास जोर देना चाहता हूँ और मिनिस्टर साहिब का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूँ । वह यह है––

> "In the proposed section 14 ( ), line 6, *between* 'documents' and ':' *insert* 'and shall impose by way of penalty double the amount of tax recoverable on such goods'."

इसमें मैंने किसी को किसी किस्म की डिस्क्रीशन नहीं दी। मतलब यह है कि अगर कोई चोरी करता हो तो उसको वह अफसर सज़ा दे सके । अगर कोई डबल बुक्स इकेड रखता है तो उस को सज़ा अवश्य मिलनी चाहिए । इसलिये मैंने अपनी यह अमेंडमेंट पेश की है ।

[श्री मोहन लाल]

इन अल्फाज़ के साथ मैं अपनी यह अमैंडमैंट्स रखता हुआ यह आशा करता हूं कि गवर्नमेंट इनको मान लेगी । कुछ वायदे भी किये थे कि इस तरह की अमैंडमैंट्स को मान लिया जाएगा । इसलिये उन्हीं वायदों की तरफ ध्यान और तवज्जो दिलाता हुआ यही कहूँगा कि इन अमैंडमैंट्स को मान लेने से सरकार के अपने ही हित की बात होगी ।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : (ਮੁਹਿੰਡਾ ਐਸ. ਸੀ.) : ਮਾਨਯੋਗ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਆਏ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸੀ—ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਪੰਜ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀਆਂ ਨੌ ਦਸ ਕਲਾਜ਼ਾਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਕਰਾ ਸਕੀ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੋ । (The hon. Member need not refer to what happened on that day. He should talk of to-day.)

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ । ਤੁਸੀਂ, ਬੀਬੀ ਜੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਥੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ । ਉਸ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮੁਖਾਲਫਤ ਵਿਚ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਡਤ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਰਿਹਾ, ਇਕ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹਨ......

ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ : ਬੜੇ ਹਰ ਦਿਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਉਹ ਬੜੇ ਹਰ ਦਿਲ ਅਜੀਜ਼ ਵਜ਼ੀਰ ਸਨ । ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਨਿਸਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ—ਯਾਨੀ ਮਿਤਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਲਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਉਤੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਰਾਏ ਪਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਬਿਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਤਾਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ । ਫੇਰ ਵੀ ਜੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਮਨਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਣੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਰਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤਰਾਹ ਤਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਟੋਕਨ ਸਟਰਾਈਕ ਵੀ ਕੀਤੀ । ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ

ਬੜੇ ਵਫ਼ਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵੀ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਔਰ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੇਗੀ । ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡਟਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੀ ਇਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਥੇ ਇਕ ਦਿਨ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਈਏ । ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਚ ਬੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ—ਚਾਹੇ ਵਿਉਪਾਰੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਉਸ ਨੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮੁਮਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਉ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਉਤੇ ਹੀ ਡਟੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਹੁਣ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਵਿਉਪਾਰੀ ਨੂੰ ਕਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਕੜਨਗੇ । ਮੈਂ ਤਾਂ, ਬੀਬੀ ਜੀ' ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਹੋਈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੂਸ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮੁੜ ਆਏ ਔਰ ਹੁਣ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕੋਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਾਊਸ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਯੰਗਰ ਐਲੀ-ਮੈਂਟ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਸੋ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੰਗੀ ਦੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਨਸੈਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਕਨਸੈਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਸਖਤੀ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਿਆ ਪਰ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਸਿਵਾਏ ਵਿਉਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗਲ ਨਹੀਂ ।

ਇਸ ਕਲਾਜ਼ ਉਤੇ ਜਿਤਨੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਪੰਡਤ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਹਨ । ਜੇ ਇਹ ਵਾਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਤਰਮੀਮਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਭਦਰ ਪੁਰਸ਼ ਔਰ ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ । ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ—ਦੇਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ—ਕਿ ਇਸ ਕਲਾਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਬੜੇ ਸਖਤ ਹਨ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਨ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਐਕਟ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ । ਸਰਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਰ ਇਕ ਐਕਟ ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਕਿਸੇ ਮਕਾਨ ਦੀ, ਸਰਚ ਕਰਨ ਜਾਵੇ ਉਥੇ ਅਗਰ ਪਰਦਾਨਸ਼ੀਂ ਔਰਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਘਰ ਦੀ ਔਰਤ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੁਲ੍ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ, ਅਸੀਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਚਲੀ ਜਾ । ਇਸ ਕਾਲਜ਼ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਜ਼ੋ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕੋਈ ਈ. ਟੀ. ਓ. ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦਾ ਅਫਸਰ ਸਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀ. ਸੀ. ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵੇਗਾ, ਸਾਂਝ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ—ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਫਸਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਕਸਾ ਮਿਲੇ

[ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ]

ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਵਿਚ ਜ਼ੇਵਰਾਤ ਹੀ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਸਕੇਗਾ । ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਤਾਂ ਡੀਸੈਂਸੀ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ । ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵੀਸੋ 5 ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ:—

'(5) The power conferred by sub-section (4) shall include the power to open and search any box or receptacle in which any books, accounts, registers or other relevant documents of the dealer may be contained'.

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਕਿਤਨੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਕਸਾ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਕਸੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਵਿਚ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ purely private and personal ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਵਿਉਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਖਲ੍ਹਾ ਹਥਿਆਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ । ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਐਨੀ ਸਖਤ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਵੀਸੋ ਨਹੀਂ ਰਖੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਘਰ ਦੀ ਬੀਬੀ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੁਲ੍ਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਚਲੀ ਜਾਵੇ । ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਸਾਂ ਵਿਚ ਦਮ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ।

ਮੇਰਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਕਰਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਰਪਟ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਈਵੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਮੇਂਵਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ । ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਇਥੋਂ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਈਵਈਅਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਤਨੇ ਚਿਰ ਤਕ ਇਸ ਮਕਸਦ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤਕ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਈਵਈਅਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ । ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦਾ ਈਵਈਅਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਈਵੇਈਅਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਕਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਹਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਈਵੇਜ਼ਨ ਵਧੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿਵਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਹ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜੇਗਾ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ

ਵਪਾਰੀ ਹਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਫਸਿਆ ਕਰਨਗੇ । ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁਟਣ ਵਾਲੀ ਕਲਾਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਐਸੇ ਅਫਸਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਔਰ ਫਿਨਾਂਸ਼ਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਮਨਿਸਟਰ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਦਾਚਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ । ਮੈਨੂੰ ਐਸੇ ਇਕ ਅਫਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਫਿਨਾਂਸ਼ਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਔਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਇਨਚਾਰਜ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਕ ਵਿਚ ਦਮ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਔਰ ਵਜ਼ੀਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਥੇ ਰਹਿਣ ਨੱਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ । ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੈਥੋਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਇਥੇ ਨਾ ਕਹਾਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪੁਛ ਲੈਣ । ਅਵਲ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਮੁਤੱਲਕਾ ਕੋਲੋਂ......

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ । ਇਸ ਕਲਾਜ਼ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ । (Why is the hon. Member discussing the Ministers ? Where have they been mentioned in the clause ?

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਈਵੇਜ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਨ ਵਾਸਤੇ ਲਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਈਵੇਯਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਗੌਰਮਿੰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕ ਐਸਾ ਭੱਦਰ ਪੁਰਸ਼ ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੜੀ ਈਵੇਯਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਥੇ ਬੜੀ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਇਕ ਮਨਿਸਟਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਔਰ ਬਦਲਣ ਵੀ ਕਿਉਂ ਜਦ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਈਵਈਅਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਔਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਖਾਂ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਸਬ-ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਮਨਿਸਟਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਚੰਦੇ ਵਜੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜੋ ਕਲਾਜ਼ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮੀਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਈਵੇਯਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਗਰੀਬ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੂੰਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੂੰਡਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸ ਨਾਲ ਜਮਨਾ ਨਗਰ ਜਾਂ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ

[ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ]

ਵਿਗੜਨਾ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਹ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਵਲ ਤਾਂ ਇਸ ਅਮੈਂਡਿੰਗ ਕਲਾਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਡੀਲੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਖਣਾ ਹੀ ਚਾਹੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਪੰਡਤ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਨੇ ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਸਰਨ ਚੰਦ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

डाक्टर बलदेव प्रकाश (अमृतसर पूर्व) : डिप्टी स्पीकर साहिबा ।

पंडित भगीरथ लाल शास्त्री : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडम। हमें भी वक्त मिलना चाहिए हमें आप वक्त नहीं दे रही और उन मैम्बर्ज़ को आप समय दे रही हैं जो इस बिल पर पहले भी कई कई बार बोल चुके हैं ।

Deputy Speaker : Order please.

डाक्टर बलदेव प्रकाश : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं इस क्लाज़ की मुखालिफत करने के लिये खड़ा हुआ हूँ और मैंने एक अमेंडमेंट भी दी हुई है उसी की रूह से मैं यह चाहता हूँ कि इस सारी की सारी क्लाज़ को डीलीट कर दिया जाए । (वित्त मंत्री : तो आपका मतलब यह है कि कोई भी व्यापारी एकाउंटस रखे ही ना) मैं यह नहीं चाहता । मैं तो यह चाहता हूँ कि इस अमैंडिंग कलाज़ को बिल्कुल उड़ा दिया जाए । और इसकी जगह पर जो उरिजनल क्लाज़ थी उसे रहने दिया जाए। डिप्टी स्पीकर साहिबा, हमारे वित्त मंत्री जी यहां पर बड़े भोले बनते हैं। मैं तो समझता हूँ कि या तो इन्होंने इस बिल को ध्यान से पड़ा ही नहीं और अगर पढ़ा है तो इन्हें इसकी समझ नहीं आई और इनके भोलेपन का फायदा इनका यह डिपार्टमेंट उठा रहा है और वह इस तरह कर के इनको बदनाम कर रहा है। इनकी एक बात की तो मुझे समझ नहीं आई । यह कहते हैं कि हमने व्यापारियों की मीटिंग बुलाई थी और उस मीटिंग में यह सारी बातें डिसकस की थीं और उन्होंने यह सारी बातें तो इस बिल में लाई गई हैं, मानी थी और उसी डिसकशन के बेसिज़ पर यह बिल बनाया गया है और यहां हाउस के सामने पेश किया गया है । इसके साथ ही यह कहते हैं कि इस बिल में जो अमेंडमेंटस व्योपारी लाना चाहते थे वह हमने सब मान ली हैं और इसके लिए हमने अफीशियल अमेंडमेंटस मूव कर दी हैं। इस तरह से इन्होंने यह कहना है कि इस बिल में कई चीज़ें व्यापारियों को तंग करने वाली थीं जिनको इन्होंने अब निकाल लिया है । तो डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं इनसे यह पूछना चाहता हूँ कि जब यह कहते हैं कि इन्होंने इस अमेंडिंग बिल के लाने से पहले व्यापारियों की मीटिंग बुला कर उनकी रज़ामन्दी से यह बिल बनवाया था और अब कुछ दिनों के बाद यह खुद मान रहे हैं। इस बिल में वाक्या ही कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो व्यापारियों को तंग करने वाली थीं और उनको हटाने के लिये अब इन्होंने मान लिया है तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि यह बिल किसने बनाया था? और जब यह बनाया गया था तो क्या उस वक्त इन्होंने इसको नहीं पढ़ा था जो वह तंग करने वाली चीज़ें इन्होंने इसमें

आने दी थीं । इससे साफ जाहिर है कि जिस वक्त बिल बनते हैं तो उस वक्त मंत्री महोदय ज़रा भी उन पर अपना माइंड एप्लाई नहीं करते। और यही वजह है कि जब यह बिल बन कर इस सदन में लाया गया तो पंजाब में इसके खिलाफ यह सारा हल्ला हुआ और एक दिन के लिये सारे पंजाब में हड़ताल हुई और काफी अनप्लेज़ेंटनेस पैदा हुई और इसकी मुखालिफत यहां हाउस में सारी तरफों से हुई तब जाकर इन्होंने कहा कि इस बिल में वाक्या ही बहुत ज्यादा गल्त और नाजायज़ चीज़ें हैं (वित्त मंत्री: मैंने गल्त और नाजायज़ नहीं कहा) मैं इस बात पर हैरान हूँ कि पहले जब इन्होंने व्यापारियों के साथ तय करके यह बिल लाने का फैसला किया था और उसके बाद यह बिल बनाया गया और यहां हाउस में पेश हुआ तो उसके दो तीन दिन बाद कहने लगे हैं कि क्योंकि इसमें कुछ गल्त चीज़ें आ गई हैं इसलिये हम उनको निकालने की सरकारी तौर पर एमेंडमेंट्स लाए हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि इस बिल के बनाते वक्त इन्होंने ज़रा भी ध्यान नहीं दिया और इनके अफसरान ने इसे जिस शक्ल में बना कर रख दिया उसको इन्होंने यहां पेश कर दिया । डिप्टी स्पीकर साहिबा जिस सरकार का यह हाल हो कि जो बिल यहा पर पेश करे और उसके मिनिस्टर इनचार्ज को उसकी धाराओं का कुछ पता ही न हो तो उस सरकार से जनता का क्या भला हो सकता है। अब यह मानते हैं कि व्यापारियों के घरों की तलाशी नहीं ली जाएगी। क्या इनको इस बात का पहले पता नहीं था? क्या इन्होंने इस बिल में इस चीज़ को पहले पढ़ा नहीं था कि यह प्रोवीज़न इस बिल में की गई हुई है अगर इनको यह बात पसंद नहीं थी कि व्यापारियों के घरों की तलाशी ली जाए तो यह इस बिल में कैसे आ गई। इसलिये मैं कहता हूँ कि यह जो बातें इस बिल में आई हैं यह तो यह इन की मरज़ी से आई हैं और अगर इनकी मरज़ी से नहीं आई तो इनको इनके डिपार्टमेंट वालों ने उल्लू बनाया है। मुझे इस बात का अफसोस है कि मुझे इस बात के लिये यह सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ा है । वैसे तो यह मुहावरा है—

ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ : On a point of order, Madam, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਜਨ ਸੰਘ ਗਰੁਪ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਲਫਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਜ਼ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁਛਣ ਹੀ ਲਗੀ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਲਫਜ਼ ਕਿਉਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ? (I was going to ask him not to use such words.)

डाक्टर बलदेव प्रकाश : डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह तो उस तरह के हिमायती हैं। कोई आदमी बाजार में से जा रहा था तो किसी ने उसकी पगड़ी उतार दी तो उसने चुपचाप अपने सिर पर रख ली मगर उसके साथ जो उसका दोस्त जा रहा था उसने हंगामा खड़ा कर दिया कि उसकी पगड़ी उतारी गई है, जिससे सारे शहर को खबर हो गई कि उसकी पगड़ी उतारी गई है। मेरी बात तो किसी ने सुनी थी और किसी ने नहीं सुनी थी..... (विघ्न) अगर आप इस शब्द का इस्तेमाल गलत समझते हैं तो मैं इसे वापस लेता हूँ ।

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ : On a point of order, Madam. ਮੈਂ ਆਪਣੀ ruling ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ 'ਉੱਲੂ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਮਨਿਸਟਰ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜੋ ਕਿ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਉਮਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਹੋਵੇ ? Is it befitting and in order to use such a word for him ?

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਲਫਜ਼ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ point of order ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ Revenue Minister ਜਿਹੇ ਮਦੱਬਰ ਆਦਮੀ ਦਾ point of order ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਲਫਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ parliamentary ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ use ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (I am sorry to say that immediately after this word was used by Dr. Baldev Parkash a point of order was raised and then another point of order has been raised by our statesman-like Revenue Minister. I say this word is unparliamentary and should not be used. It should be withdrawn.)

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਜਦ ਆਪ ਆਪਣਾ ਰੂਲਿੰਗ ਕਰ ਹਟੇ ਅਤੇ ਆਪ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਦ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : On a point of order, madam, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਹ ਰੂਲਜ਼ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਲੂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਅਨਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹੈ ਪਰ ਅਗਰ ਇਹ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ......(ਵਿਘਨ) ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਜਾਂ ਗਿਦੜ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਹਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਜਾਨਵਰ ਹੈ......

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਗਸਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਫਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ (ਵਿਘਨ) ਮੈਨੂੰ ਰੂਲ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉ। (I am sorry to see some hon. Members of this August House using such words. (Interruption) Please do not teach me the Rules.)

डाक्टर बलदेव प्रकाश : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं यह कह रहा था.....

उपाध्यक्षा : डाक्टर साहिब तो बड़े सुल्झे हुए मम्बर हैं उनकी ज़बान से ऐसे शब्द क्यों निकल रहे हैं ? (Dr. Baldev Parkash is a sober man. why is he using such words ?)

डाक्टर बलदेव प्रकाश : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैंने इस लफ्ज़ का इस्तेमाल मुहावरे के तौर पर किया था तो भी मैं इसे आपकी रूलिंग के मुताबिक विदड्रा करता हूं । जिस

सरकार का कोई महकमा वक्त की नजाकत को न समझते हुए अपनी सरकार के सामने ऐसा बिल रखे तो मैं समझता हूँ कि उस महकमे और सरकार में तालमेल नहीं है बल्कि दुश्मनी है। आज इस बिल ने इस सूबे की सरकार को यहां की जनता के सामने इतना नीचा कर के रख दिया है कि इस बात का असर इस सूबे की डिफेंस ऐफर्ट पर पड़ेगा। फिर यही एक ऐसा अकेला बिल नहीं है: ट्रकों का बिल आया, सूगरकेन पर सैस का बिल आया, आगे एक और आ रहा है। मैं दावे से कहता हूँ कि इस सरकार को इन बिलों से एक पैसे का फायदा होने वाला नहीं है क्योंक टैक्स इन्होंने बढ़ाया नहीं है, पांच से दस फी सदी नहीं किया है मगर इस वक्त यह जो बिल सरकार ने पेश किये हैं इनसे सरकार की पोजीशन जनता की नजरों में गरी है बलिक खत्म हो रही है। (विघ्न) मैं तो यह बात डिफेंस ऐफर्ट के लिये कह रहा हूँ। यह सरकार अगर कल नहीं आज ही कूएं में गिरे तो मुझे खुशी होगी मगर मैं तो इस बात को इस लिये कह रहा हूँ कि पंजाब एक सीमा प्रान्त है, इस पर दुश्मन ने हमला किया हुआ है, हम सब को इकट्ठे होकर उसका मुकाबला करना है। मैं चाहता हूँ कि इस समय जो सरकार है उसकी इज्जत लोगों में बनी रहनी चाहिए, बाकी इस की किस्मत में क्या लिखा है वह तो भगवान ही जाने। इस टैक्स के बारे में अमृतसर शहर की एक मिसाल देता हूं। अमृतसर शहर के अन्दर एक फर्म जो कि लाखों रुपये का सेल्ज़टैक्स देती है उस फर्म का एक केस था। मैंने वह सारा केस पूरे फैक्टस ऐंड फिगर्ज़ के साथ अपने वित्त मन्त्री महोदय के सामने रखा था कि इस पर यह ऐक्शन लेंगे। इनको अब शायद याद आ गया होगा। तो इनके उस अफसर ने उस फर्म को कहा कि अगर तुमने यह केस ठीक करवाना है तो मुझे इतने हजार रुपया चाहिए। वह जो फर्म है उसका काम ऐसा है कि वह एक पैसे का भी टैक्स में इवयन नहीं करती। उनका काम बड़ी बड़ी मिलों से होता है और बाकायदा कैश मीमो साथ लगे हुए होते हैं। उस फर्म ने कहा कि जहां पर आपको एतराज हो आप डेट दे दें हम आपको पूरा हिसाब किताब लाकर दिखा देंगे। उस अफसर ने उनको तारीख दे दी। उस बीच में उस फर्म के साथ रुपये के बारे में बातचीत चलती रही और उस फर्म ने इसे एक नया पैसा भी नहीं दिया। तो जिस दिन की तारीख उसको दी गई थी उस तारीख को वह अपने कैश मीमो वगैरह लेकर उनके पास पहुंचे। अब मान लो कि उनको 15 तारीख दी गई थी तो जब 15 तारीख को मैनेजर उस अफसर के पास उस तारीख को पहुंचा तो उस अफसर ने उससे कहा कि तुम्हारी तारीख तो कल थी और मैंने कल ही अपना फैसला सुना दिया था। यानी 14 तारीख डाल कर फैसला लिख दिया गया। वह केस मैंने सरकार के पास सारे डाकुमेंट्स के साथ रखा मगर वह अफसर आज तक वहीं पर दनदना रहा है और सब कुछ उसी तरह से कर रहा है। सिर्फ इतना किया गया है कि केस को रीकन्सीडर करने के लिये दोबारा भेज दिया है। उस फर्म पर टैक्स जो था उसके बारे में पूरा सबूत इनको नहीं दिया गया मगर हमारी सरकार ने इस बारे में कोई कदम नहीं उठाया। मैंने यह उदाहरण इसलिये दिया है कि यह बताऊं कि इनके महकमे में क्या हो रहा है। इन जैसा आदमी जो इतनी देर तक प्रिजाईडिग अफसर रहा हो और जिसका पार्लियामेंट्री इतिहास इतना गौरवमय रहा हो अगर वह इस बिल को एक सरसरी

[डाक्टर बलदेव प्रकाश]

निगाह से भी देख लेता तो इसको रद्दी की टोकरी में फेंक देता और उस अफसर को डिसमिस कर देता । मुझे समझ नहीं आती कि ऐसा बिल हाउस में कैसे आ गया जिसमें यह लिखा गया है कि अगर इनका अफसर व्यापारी खाते और हिसाब किताब की किताबों को उठा कर ले जाए तो वह उनके अपने दफ्तर में कम से कम 10 दिन और ज्यादा से ज्यादा 50 दिन तक रख सकता है। तो मतलब यह हुआ कि दो तीन महीने तक उस व्यापारी का कारोबार ठप रहेगा हिसाब किताब नहीं होगा, उग्राहियां नहीं होंगी, कुछ काम नहीं हो सकेगा। अब कहते हैं कि इस बिल में यह जो प्रोवियन है इसको वापिस लेते हैं । मैं कहता हूँ इस क्लाज़ को डीलीट किया जाए। बेहतर तो यह हो कि इस बिल को ही वापिस लें अगर ऐसा नहीं करते तो इस क्लाज़ को तो डीलीट करें। आज पंजाब का व्यापारी सहमा हुआ है कि का चलेगा कि नहीं चलेगा लड़ाई के बादल जो मंडला रहे हैं। ऐसे समय पर ऐसा बिल ला कर पंजाब की फिजा को खराब करना सरकार को बिलकुल शोभा नहीं देता । मैं उम्मीद करता हूँ कि यह या तो इस बिल को ही वापस लेंगे नहीं तो इस क्लाज़ को डीलीट करेंगे

ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ (ਨਕੋਦਰ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟਰਸਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੀ ਕੁਲੈਕਟਸ ਆਨ ਬੀਹਾਫ ਆਫ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਂ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਫੀ ਸਦੀ ਮੁਕਰਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ । ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਹਦ ਤਕ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਦੀ ਲਿਮਟ ਨੂੰ 50,000 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 40,000 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਿਮਟ ਨੂੰ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਮਟ ਨੂੰ ਥਲੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਿਮਟ ਦੇ ਥਲੇ ਲਿਆਣ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਅਸੈਸੀਜ਼ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਲਡ ਸਰਕਡ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚੌੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਨੰਬਰ ਆਫ ਅਸੈਸੀਜ਼ ਵਧਣ ਨਾਲ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਦਾ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਦੀ ਇਵੇਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਵੇਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਵੇਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਸਾਧਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਇਵੇਜ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਪੀ. ਡਬਲਿਯੂ. ਡੀ. ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਰਿਚਸਟ ਕਲਾਸ ਤਸਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਦ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਚਸਟ ਕਲਾਸ ਤਵਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ

ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵਿਲਜਡ ਕਲਾਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ । ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦਾਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਚਸਟ ਕਲਾਸ ਇਸ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ । ਟਨਜ਼ ਆਫ ਮਨੀ ਦੇ ਆਰ ਮੇਕਿੰਗ । ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਚੌਧਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਆਪ ਅਮੀਰ ਨਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ. ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਧਾਂਧਲੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੰਨ੍ਹੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ । ਅਤੇ ਲਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਇਵੇਜ਼ਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਫੈਲੇਗੀ ।

ਦੂਸਰੀ ਗਲ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਜ਼ 11 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਡੀਲਰ ਜਿਸ ਪਾਸ ਸਟਾਕ ਰਜਿਸਟਰ ਜਾਂ ਕੈਸ਼ ਮੀਮੋ ਜਾਂ ਸੇਲਜ਼ ਰਜਿਸ-ਟਰ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਹਨ ਵਹੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤਕ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰਖੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਡੀ. ਟੀ. ਓ. ਜਾਂ ਏ. ਟੀ. ਓ. ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਹ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਆਦ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਦੇਣੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵਹੀਆਂ ਖਾਤੇ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲਾਜ਼ 9 ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਐਕਸੈੱਸ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਰੀਫੰਡ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਕਲੇਮ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਬਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਉਸ ਐਕਸੈੱਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਫੋਰਫੀਟ ਕਰ ਲਵੇਗੀ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਾਡਰੇਜ ਦੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਐਕਸੈੱਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਈ ਹੈ ਜਿਥੇ ਨਾ ਚੂਹੇ ਦੇ ਕੁਤਰਨ ਦਾ ਡਰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਚੋਰ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਰੀਫੰਡ ਲਈ ਤਾਂ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹਰ ਕੈਸ਼ ਮੀਮੋ ਦੀ ਰੀਟਰਨ ਤਿੰਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਪਾਸ ਕੈਸ਼ ਮੀਮੋ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੂਹਾ ਵੀ ਕੁਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪਾਸ ਅਲਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੰਦੂਕ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੈਸ਼ ਮੀਮੋ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰਖੇ ਫਿਰ ਕੈਸ਼ ਮੀਮੋ ਭਾਵੇਂ 3 ਰੁਪਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀ ਰਖੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦੇ ਕੈਸ਼ ਮੀਮੋ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਰੀਟਰਨ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਨਾ ਸੰਭਾਲੇ ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ 500 ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਐਕਸੈੱਸ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਉਸ ਲਈ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦੇ ਕੈਸ਼ ਮੀਮੋ ਹੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਮਿਆਦ 5 ਸਾਲ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ।

ਫਿਰ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਸ ਅਮੈਂਡਿੰਗ ਬਿਲ ਵਿਚ ਇਕ ਕਲਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਏ.ਟੀ.ਓ. ਸਟਾਕ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਹਿਸਾਬ ਖਾਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਸੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ

[ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ]

ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਰਸੀਦ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ 60 ਦਿਨ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰਖ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਪਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਟਾਕ ਰਜਿਸਟਰ ਵਹੀਆਂ ਈ. ਟੀ. ਓ. ਲੈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਰਖ ਲਵੇ । ਪੰਡਤ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਜ਼ਰ ਦੀ ਮਿਆਦ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਿਆਦ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਲੀ ਤਾਂ ਕੀ ਵਿਦਿਨ ਸੈਵਨ ਡੇਜ਼ ਮੈਕਸੀਮਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਈ. ਟੀ. ਓ. ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਲਵੇ । ਤਾਂ ਜੋ ਵਪਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰੀਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲਵੇ । ਜੇਕਰ 60 ਦਿਨ ਰਖੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 60 ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਸਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਨਹੀਂ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ । ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕੈਸ਼ ਮੀਮੋ ਤਿੰਨ ਰੁਪਿਆਂ ਦਾ ਗੁੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰ ਗੁੰਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਸੇਲ ਟੈਕਸ 10 ਰਪਏ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਸੀਜ਼ ਕਰ ਲੈਣੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੇ 1,000 ਰਪਏ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਜਿਸਦਾ 50 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 100 ਰੁਪਿਆ ਰਖ ਲਉ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਬਣਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ 200 ਕਰ ਲਉ ਪਰ ਉਥੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਡ ਪਾਵਰਜ਼ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਰਮ-ਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਲਿਮਟ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਉਸ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥਲੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵੈਲਯੂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ 1000 ਰਪਏ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਨੂੰ ਡਬਲ ਤਕ ਹੀ ਲਿਮਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਆਪ ਪਾਸੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ।

ਸਰਦਾਰ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਦਰਦ (ਖੰਨਾ, ਐਸ. ਸੀ.) ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਕਲਾਜ਼ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ, ਇਨੋਸੈਂਟ ਅਤੇ ਹਾਰਮਲੈੱਸ ਜਿਹੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣ । ਉਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਇਹ ਹੈ—

I beg to move—

In the proposed section 14 (2) (a), lines 1—4, *delete* 'including stock accounts of each class of goods dealt in by him containing particulars of purchases or receipts, sales or deliveries and balance stock".

In the proposed section 14 (2) (b), lines 2—3, *delete* 'and furnish a copy of such list to the Assessing Authority".

For the proposed section 14 (2) (c), *substitute* the following:—

'(c) produce, if so required, account books of his business before the Assessing Authority for authentication in the prescribed manner'.

In the proposed section 14 (4), line 4, for 'or place where' *substitute* 'or place except residential house of the dealer where'.

Delete the proviso to the proposed section 14 (4).

In the proposed section 14 (6), line 2, *delete* 'and confiscate'.

Delete both the provisos of the proposed section 14 (6).

Deputy Speaker : Motion moved—

In the proposed section 14 (2) (a), lines 1—4, *delete* 'including stock accounts of each class of goods dealt in by him containing particulars of purchases or receipts, sales or deliveries and balance stock'.

In the proposed section 14 (2) (b), lines 2—3, *delete* 'and furnish a copy of such list to the Assessing Authority'.

For the proposed section 14 (2) (c), *substitute* the following:—

'(c) produce, if so required, account books of his business before the Assessing Authority for authentication in the prescribed manner'.

In the proposed section 14 (4), line 4, *for* 'or place where *substitute* 'or place except residential house of the dealer, where.

Delete the proviso to the proposed section 14 (4).

In the proposed section 14 (6), line 2, *delete* 'and confiscate'.

Delete both the provisos of the proposed section 14 (6).

पंडित भागीरथ लाल शास्त्री (पठानकोट) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, आज फिर सेल्ज़ टैक्स एक्ट की धारा 11 के ऊपर विचार चल रहा है। दो दिन पहले भी जबकि आप विदेश गई हुई थीं इस पर बहस होती रही है। आप ने पुराना रिकार्ड देखा ही होगा कि किसी एक भी सदस्य ने इस बिल की हिमायत नहीं की बल्कि सबकी यह कोशिश है कि यह बिल किसी न किसी तरीका से वापस हो जाये। इसके कारण कई हैं अभी तो मुसीबत के बादल हमारे देश पर गरज रहे हैं। कुछ पीछे बरस भी चुके हैं। इस मुसीबत में हर आदमी ने सेवा की है, ऐसे लोगों को जिन्होंने अपना सब कुछ इन दिनों कुरबान किया गवर्नमेंट को चाहिए था कि उनको रिलीफ देती, मगर बदकिस्मती की बात है कि गवर्नमेंट दूसरी तरफ पड़ गई है सीधे की बजाये इन्होंने उल्टा रास्ता पकड़ लिया है, इसका नतीजा यह हुआ कि जिन ट्रक वालों ने बड़ी बड़ी कुरबानियां कीं जिन की जगह जगह तारीफ हुई, जैसे कल नंदा जी भी वार्डर एरिया में

[पंडित भागीरथ लाल शास्त्री]
गये उन्होंने ट्रक वालों की बड़ी तारीफ की है। पीछे इस जगह पर जनरल हरबख्श सिंह जी आये थे उन्होंने भी इन ट्रक वालों की बड़ी तारीफ की है मगर इस दिलेरी का आखिर नतीजा क्या निकला कि उनको भी टैक्स लगा और व्यापारियों को इस बिल के ज़रिये से टैक्स लगाया जा रहा है। अब जमींदारों का भी नंबर आने वाला है। हम तो यह सोचते हैं कि यह चल किधर पड़े हैं। आखिर उनको अब समझाये तो कौन समझाए उनको अगर कहे तो कौन कहे। पंडित जवाहर लाल जी भी चले गये जिन्हें जाकर हम पहले कह दिया करते थे कि महाराज इनको अकल दो।

(**एक माननीय सदस्य** : कल नंदा जी से ही बात कर लेनी थी ।)

पंडित भागीरथ लाल शास्त्री : इनसे भी की है । मैं तो अब एक ही दरखास्त इनसे करूंगा कि इसकी चाहे 10 धारायें पास हो चुकी हैं 11वीं अब चल रही है, पास हुई है तो क्या है इसको वापस ही ले लेना चाहिए । इस बात में मुझे ज़रा भी शक नहीं कि गवर्नमेंट हकबजानिब है टैक्सिज़ लगाने के लिये क्योंकि इसके बग़ैर सरकार का धन्धा चलता नहीं है। इसमें भी शक नहीं कि टैक्स की चोरी भी बहुत होती है हमें ऐसे व्यापारियों से चोरी ज़रूर बरामद करनी चाहिए लेकिन जो भाई चोरी को बरामद करने वाले हैं उनको भी कुछ करैडिट तो मिलना चाहिए । अगर आप किसी को अधिकार दिलाना चाहते हैं तो जो लोग इनका दुरुयोग करते हैं उनके लिये भी कोई सज़ा की तजवीज़ इसमें होनी चाहिए थी । यह बात ठीक है कि सारे व्यापारी खराब नहीं हैं और सारे अच्छे भी नहीं हैं। नेक आदमी भी होते हैं और बद भी होते हैं लेकिन अगर कोई कानून एक के लिये बनता है तो यह दूसरे के लिये भी होना चाहिए अगर कोई किसी कानून के तहत टैक्स देता है तो ऐसी बात भी होनी चाहिए कि अगर कोई चोरी करता है वह भी पकड़ा जाये । मैं तो वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करूँगा वह बड़े समझदार हैं, बड़े दिमागदार हैं, और पुराने तजर्बाकार हैं । यह ठीक है पुरानी चीज़ पुरानी ज़रूर होती है मगर कई पुरानी हमेशा नई होती है, जैसे सूरज होता तो पुराना है मगर फिर भी हर रोज़ नया होता है । वह पुराने हैं मगर फिर भी नए हैं। (विघ्न)

ਕ ਮਰੇਂਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : On a point of Order, Madam. ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦਾ 70–72 ਤੋਂ ਮਕਸਦ ਪੁਰਾਣੇ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਹੈ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਬੈਠ ਜਾਉ ਜੀ । (The hon. Member may take his seat.)

पंडित भागीरथ लाल शास्त्री : और तो मैं कुछ कह नहीं सकता मैं तो उनके दिमाग की दाद देता हूँ उन्हें यह मालूम नहीं कि सूरज इतना पुराना होते हुए भी नित नया नज़र आता है ! मगर जिनके दिमाग़ में भूसा भरा हुआ हो उन्हें समझ कैसे आ सकता है। मैं अर्ज़ कर रहा था कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं यह एक कलंक का टीका है । जो इस तरह का यह बिल पास किया जा रहा है। काश इसको पढ़ा होता और इस पर बार बार ग़ौर किया होता । एक बात यहां पर डाक्टर बलदेव प्रकाश जी ने कही। मुझे यह सुन कर दु:ख हुआ कि यह आपके अधिकार की बात नहीं है । मैं कहता हूँ कि आपके

अधिकार बहुत बड़े अधिकार हैं, यह ठीक है कि उनके पास अक्सर ऐसे आदमी आ जाते हैं कि उनके पास टाईम नहीं है कि वह पूरी तरह इस पर विचार कर सकें। मगर अगर कोई कहे कि वह भूल जाते हैं मैं उनकी इस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ। असल ग़लती तो उन अफसरों की है जो अक्सर जब बातें चलती हैं कहते कि आपके अफसर मिनिस्टर नहीं, हम आपके अफसर हैं। मैं तो यह अर्ज़ कर रहा था कि इस सारी चीज़ को हमने सोचना और विचारना होगा। इस बिल के अंदर बहुत सी धाराएं ऐसी हैं जिनके ऊपर काफी बहस हो चुकी है मगर सोचने वाली तो बात यह है कि सेल्ज़ टैक्स के महकमे वालों ने जब भी किसी दुकानदार को तंग करना होता है तो वह उसकी बही खाता ले जाते हैं अगर कोई दस्तावेज़ हो वह ले जाते हैं और कई दिन तक वापस करने का नाम तक नहीं लेते। अगर वह 60 दिन तक वापस ना लें तो यह जो मर्ज़ी चाहें कर सकते हैं। मैं समझता हूँ यह व्यापारियों के साथ ज्यादती है। मैं समझता हूँ इसमें कोई तरमीम होनी चाहिए। मैं मानता हूँ आपने काफी दिमाग लड़ाया है और काफी सुधार करने की कोशिश भी की है मगर जो नुक्स हैं वह भी तो दूर होने चाहिए। कई दफा शरीफ आदमियों की पगड़ी खाह-मखाह उछाल दी जाती है। छापा मारने पर जब कुछ नहीं निकलता तो कह दिया जाता है कुछ नहीं निकला। मैं एक दो फरमें बता सकता हूँ जिनके छापा पड़ा मगर निकल कुछ नहीं उनकी हरैसमेंट हुई। घर वाले बाहर वाले दोस्त मित्र सभी हैरान और परेशान हुए और जो ऐसी हरकत कराने वाले लोग थे, दुश्मन थे, उनके किसी तरह की हानि ना हुई। (At this stage Shri Ram Saran Chand Mital a member of the panel of Chairmen, occupied the Chair.) मैं तो वित्त मन्त्री से कहूँगा कि आप बहुत से उपकार कर रहे हैं। आप जहां भोले भाले हैं समझदार भी हैं। व्यापारियों को अगर आपने कानफीडेंस में लिया था उनकी और तकलीफ की बातें भी पूछ ली होतीं।

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : On a point of order, Sir. ਮੈਂ ਇਹ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਜੰਡਾ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣ। ਇਹ ਕੀ ਗਲ ਹੈ ?

Mr. Chairman : This is no point of order.

पंडित भागीरथ लाल शास्त्री : ..मैं एक अर्ज़ करूँगा कि पंडित मोहन लाल जी ने जो तरमीम दी है उसको गवर्नमेंट मान ले और अगर नहीं मानती तो ऐसी कोई चीज़ इसके अन्दर कर दें जिससे व्यापारियों को हरेसमेंट न हो। चेयरमैन साहिब, जो इस धारा के अन्दर 60 दिन तक बहीखातों को रखे रहने का प्रावीज़न है, मैं समझता हूँ कि यह बहुत बेजा बात है क्योंकि दुकानदारों का बहीखाते के बिना काम नहीं चलता और न ही उन लोगों को सौदा मिलता है। इसलिये मैं दरखास्त करूँगा कि इस क्लाज़ को निकाल दिया जाना चाहिए। मैं यह भी चाहता हूँ कि इस बिल को कुछ देर के लिये अभी उठाए रखना चाहिए।

[पंडित भागीरथ लाल शास्त्री]

मैं पठानकोट का रहने वाला हूँ। मैं जब वहां गया, तो ट्रांस्पोर्ट वाले बहुत सारे लोग आए और शिकायत करने लगे कि मोर्चे पर सेवा करने का तुमने यह सिला दिलवाया है, तुम वहां असैम्बली में रहते हो, यही कुछ करते हो। जनाब चेयरमैन साहब, मैं ट्रांस्पोर्ट वाले मेजर के बारे में यही कहना चाहता हूँ कि लोगों के अन्दर बड़ी बेचैनी है और उनको बड़ी मायूसी हुई है। इसलिये इस बिल को तीन साल के लिये मुल्तवी कर देना चाहिए। इस बिल से तो उन लोगों के घावों पर नमक छिड़कने वाली बात हुई है। मैं सरकार को यही प्रार्थना करूँगा कि वह जनता की भावनाओं का भी ख्याल करे।

सरदार लछमन सिंह ने कहा है कि कीमतें तो कई गुना बढ़ गईं। 6 गुने से भी ज्यादा हो गई इसलिये जो लिमिट 40,000 की की गई है वह लाखों तक की की जानी चाहिए थी और कीमतों के बढ़ने की औसत से इस लिमिट को करना चाहिए था। जहां तक व्यापारियों को चोर समझने का सवाल है मैं कहता हूँ कि यह गलत है। वह बहुत ईमानदार हैं देश की सेवा करने वाले भी हैं—उनके ऊपर शक नहीं करना चाहिए। यह अच्छी बात नहीं है। मैं यही कहता हूँ कि इस बिल को सुगम बनाया जाए। इस बिल को वापस ही ले लिया जाये तो ज्यादा अच्छा है और यही नहीं आगे आने वाला एक और दूसरा बिल है उसे भी कुछ देर के लिये मुल्तवी किया जाए। तभी हमारा देश खुश होगा और तरक्की करेगा।

Shri Yash Paul (Jullundur city, south west) : Madam, I beg to move—

> In the proposed section 14 (2) (a), lines 1—4, *delete* 'including stock accounts of each class of goods dealt in by him containing particulars of purchases or receipts, sales or deliveries and balance stock'.

> Delete the proposed section 14 (2) (b).

> *For* the proposed section 14 (2) (c), *substitute* the following :—

> '14 (2) (c). Produce, if so required, Accounts Books of his business before the Assessing Authority for authentication in the prescribed manner.'

> In the proposed section 14 (2) (d), line 1, *for* 'such' *substitute* 'his'.

> In the proposed section 14 (4), line 4, between 'place' and 'where' insert 'except residential houses'.

> For the proviso to the proposed section 14 (4), *substitute* the following—

> 'Provided that the warrants of search have been issued by Excise and Taxation Commissioner, Deputy Commissioner, Excise and Taxation or District Excise and Taxation Officer. No person below the rank of DETO shall be authorised to enter any premises of any dealer for the purpose of search'.

In the proposed section 14 (6), line 2, *delete* 'and confiscate'.

delete both the provisos to the proposed section 14 (6).

चेयरमन साहिब, मैं कोई लम्बी चौड़ी बात तो अर्ज़ करना नहीं चाहता। 14वीं क्लाज़ में जहां यह तरमीम आई है कि रैज़ीडैंशल हाउसिज़ की तलाशी न ली जा सके वहां एक तरमीम की और ज़रूरत है और उस अमैंडमेंट का नोटिस भी मैंने दे रखा है और वह इस तरह से है कि इस के आखिर में यह प्राविज़ो लिखा जाए--

'Provided that the warrants of search have been issued by Excise and Taxation Commissioner, Deputy Commissioner Excise and Taxation or District Excise and Taxation Officer. No officer below the rank of DETO shall be authorised to enter any premises of any dealer for the purpose of search'.

यह प्राविज़ो मैं इसलिये ऐड करना चाहता हूँ कि तलाशी के अख्तियार का नाजायज़ यूज़ न हो सके। हकूमत का मकसद तलाशी लेने से यह है कि अगर कहीं पर व्यापारी हिसाब किताब नहीं रखता तो तलाशी लेकर असलियत मालूम की जा सके। इसमें बुरा तो नहीं समझता लेकिन यही बड़ी भारी हैरेसमेंट का कारण बन सकता है और कोई भी साधारण सा आदमी महकमे से सम्बन्धित तलाशी लेने के लिये चला जा सकता है। और केसिज़ में तलाशी उस वक्त ली जा सकती है जब मेजिस्ट्रेट से वारंट ले लिया जाता है लेकिन व्यापारियों के केस में क्यों यह नया तरीका इस्तेमाल किया गया है, मैं यह नहीं समझ पाया। अगर कोई ऐसा व्यापारी है, जो हिसाब किताब छिपाता है, तो बड़ी आसानी से कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट का ऐक्साइज़ एंड टैक्सेशन अफसर के पास से तलाशी वारंट लिये जा सकते हैं लेकिन वैसे ही तलाशी लेने का अगर अख्तियार महकमे वालों को दे दिया जाय तो इसके तो नताइज निकल सकते हैं, वह मिनिस्टर साहिब, अच्छी तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं। उन्होंने यह तो मान ही लिया है कि तलाशी न ली जाए लेकिन अगर लेनी है उन्हीं केसिज़ में, तो जिन अफसरान का हमने ज़िक्र किया है, उनसे इजाज़त ले कर ली जानी चाहिए।

Mr. Chairman : Motions moved—

In the proposed section 14 (2) (a), lines 1—4, delete 'including stock accounts of each class of goods dealt in by him containing particulars of purchases or receipts, sales or deliveries and balance stock'.

Delete the proposed section 14 (2) (b).

For the proposed sec ion 14 (2) (c), *sustitute* the following—

'14 (2) (c). Produce, if so required, Accounts Books of his business before the Assessing Authority for authentication in the prescribed manner'.

In the proposed section 14 (2) (d), line 1, *for* 'such' *substitute* 'his'.

[Mr. Chairman]

In the proposed section 14 (4), line 4, between 'place' and 'where' insert 'except residential houses'.

For the proviso to the proposed section 14 (4), *substitute* the following—

'Provided that the warrants of search have been issued by Excise and Taxation Commissioner, Deputy Commissioner, Excise and Taxation or District Excise and Taxation Officer. No person below the rank of DETO shall be authorised to enter any premises of any dealer for the purpose of search'.

In the proposed section 14 (6), line 2, *delete* 'and confiscate'.

Delete both the provisos to the proposed section 14(6).

श्री सीता राम बागला (सर्सा): जनाब चेयरमैन साहब, 40 हज़ार की लिमिट कर देने से बहुत से ऐसैसी बढ़ जायेंगे । और इसका नतीजा यह होगा कि बहुत सारी कुरप्शन बढ़ेगी । इवेज़न भी काफी होगी । जहां तक इवेज़न का सवाल है, जब तक सरकारी कर्मचारी न मिलें तब तक इवेज़न नहीं होती । जो लोग जमा खर्च करते रहते हैं और कहीं कुछ न लिखते हैं, न उनके पास ही कुछ माल होता है, इधर से लाए उधर दे दिया, उनके उपर किसी ने आज तक हाथ नहीं उठाया और न किसी ने उनको चैक किया—जबकि उन लोगों का किसी ने हिसाब नहीं किया यह बैंक से मिल जाते हैं, इस तरह से उनको बहुत सी हैरेसमैंट होगी लेकिन आज नज़रिया यही है कि बहुत सी जगह पर तलाशियां की जा रही हैं । हमारी तहसील में भी ऐसा हुआ । पिछले पांच सात दिनों में एमनाबाद में जो छोटी सी मण्डी है वहां पर तलाशियां की गईं। वह टैक्स इवेज़न को रोकने के लिये तलाशियां शुरू करते हैं मगर यह तलाशियां खाहमखाह की गईं। यह तलाशियां रनिया कालाबारी जगहों पर की गईं। बाकी सब जगहों का मैं ज़िक्र नहीं करता । इस पिछले हफ्ते में उन लोगों ने इस लिये किया क्योंकि कानून बन रहा था और कानून बनते बनते कहीं ऐसा न हो जाए कि उनके हाथ कुछ न आए । उन्होंने अपने हाथ साफ कर लिये । इस पिछले हफता में कम अज़ कम हमारी तहसील में जहां ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं और बहुत भोले हैं उनके साथ ऐसा किया गया । ठीक है हर कम्यूनिटी में ब्लेक शीप भी होती हैं। पिछले हफ़ता में कम से कम 20 जगहों पर छापे मारे गए और तलाशियां की गईं। पता नहीं क्या हुआ । हम यहां बैठे हैं। आज जितना टैक्स बढ़ाया जा रहा है या तो वह देंगे वरना उन्हें इन्स्पैक्टरों के रहम पर छोड़ना पड़ेगा । तलाशी के वक्त जो दुकानदार की हलात होती है वह वही जानता है। वह भी पंजाब का रहने वाला है और हिन्दुस्तान में उसने अपनी जिन्दगी बसर करनी है। सारे बेइमान नहीं होते लेकिन बेईमान पोलिटीकल आदमी या कर्मचारी कोई ऐसा अनसर घुस जाता है जो उन्हें बेइमान बनाना चाहता है । हरेक अपनी जिन्दगी आराम से बसर करना चाहता है। उनके लिये सोचा जाता है कि उनको किस तरह से हैरिस किया जाए, उनका काम बंद किया जाए । यह कानून की मन्शा जो है उनकी जिन्दगी कैसे बच सकती है । मैं अर्ज़ करूँगा कि अगर तलाशी हो तो उसके दुकान या गुदाम की हो लेकिन साथ में

उस तलाशी के वक्त उन व्योपारियों में से जिनको आप अच्छा समझते हैं उन व्यापारियों को साथ ले लिया करें। ताकि वे लोग हमें आके तो न कहें कि हमारी बेइज्जती हुई। दबवाली मंडी में जो परसों हुआ वह अखबारों में भी आया है। बहुत लंबा वाका है। काला बारी, रनिया में जो हुआ वह मैं कह चुका हूँ। एमनाबाद में भी ऐसा ही किया गया। तलाशी के वक्त लोकल व्यापारियों को साथ ले लीजिये तो किसी को यह तो गुमान न हो कि हमारी सरकार क्या कर रही है। उन लोगों को तंग करने की मनशा नहीं होनी चाहिए। उसका काम बंद न हो और सरकार का काम भी बंद न हो। अगर यह इसी तरह करेंगे तो लोगों में हैरेसमेंट होगी। हम वित्त मंत्री से यह अर्ज़ करेंगे कि जब कानून बने और जब तलाशी हो तो साथ के पड़ोसी को ले लिया जाए। इन्स्पैक्टर, इ.टी.ओ., डी. टी ओ. जो भी हो वह इस बात का ख्याल रखे कि उन आदमियों के साथ इतनी सख्ती न की जाए। और उनके साथ ऐसा स्लूक न किया जाए। आप व्योपारियों को रीलीफ दे रहे हैं, इसलिये उनके साथ ज्यादती न हो। मैंने पहले ही दूसरी बातें कही हैं जो पचास हज़ार की लिमट के बारे में 60 दिन की म्याद के बारे में और 5 साल का हिसाब रखने के बारे में है। पाँच साल तक वह दस रुपये की रसीदें और अकाउंट वा बही को कैसे रख सकता है। दो साल या तीन चार साल बाद हर व्योपारी अपनी दुकान का हिसाब रख सकता है इस अर्सा में उस का हिसाब किताब चैक कर लिया जाए। तब ही उसका और सरकार का काम ठीक चलेगा। मैं यह काम तो नहीं करता लेकिन मुझे पता है कि क्योंकि मैं उस कमूनिटी को बीलांग करता हूँ। व्योपारियों के पास इतनी देर तक हिसाब रखने के लिये जगह नहीं होती। जब इतनी देर तक उसका हिसाब चैक नहीं होता रकम एडजस्ट नहीं होती रकम कम्पेयर नहीं होती ऐसी हालत में पांच साल तक हिसाब रखना मुश्किल है। हम जनता के सामने क्या कहेंगे। मैं इतना कह कर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और अपनी जगह बैठता हूँ।

ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ (ਸਮਾਣਾ, ਐਸ. ਸੀ.): ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਗਿਆਰਵੀਂ ਕਲਾਜ਼ ਵਿਚ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰਖਣ ਬਾਰੇ ਦਸਿਆ ਹੈ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਵਪਾਰੀ ਸ਼ਾਮ ਤਕ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਐਨਾ ਸਟਾਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ 6 ਵਜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਗੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਸਟਾਕ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਬਣਾਏਗਾ ? ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਰਾਮ ਰਾਜ ਆਵੇਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਫਿਨਾਂਸ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲੂਣ ਤੇਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜੁਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਫੇਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ ਲਿਮਿਟ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 40,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਐਂਟਮ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਪਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਪਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਾ ਥਲੇ ਨੂੰ ? ਐਸਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬੈਕ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ—

"ਰਾਮ ਰਾਜ ਮੇਂ ਰਾਬੜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰਾਜ ਮੇਂ ਘੀ।
ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੇ ਰਾਜ ਮੇਂ ਤੱਤਾ ਪਾਣੀ ਪੀ॥"

[ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ]

ਇਹ ਕਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣਗੇ । ਫਿਨਾਂਸ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਦੁਧ ਪੁਤ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਰਹੇ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਬਗੈਰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ । ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਹੋ, ਇਹ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਮੈਨ ਹਨ, ਲਖਾਂ ਪਤੀ ਹਨ । ਜੋ ਬਿਲ ਪਹਿਲਾਂ ਏਥੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਜੋ ਸ਼ਕਲ ਇਸਦੀ ਹੁਣ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ । ਐਵੇਂ 15 ਦਿਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਘੇਰ ਰਖੀ, ਬਿਠਾਈ ਰਖੀ । ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਮਨਾ ਲਿਆ । ਤੁਸੀਂ ਦਸੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਨਾ ਪੈਸਾ ਬਚਾ ਲਿਆ । ਇਨਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਿਉ । ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਤਾਂ ਇਨਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਪੈਣ ਦਿਉ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਫਿਨਾਂਸ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਉ । ਅੱਜ ਛੁਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫਿਨਾਂਸ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ । ਜੋ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਿਲ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ । ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗ ਜਾਇਗਾ । ਇਹੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲਿਆ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਮੋਚੀ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ । ਜਿਹੜੇ ਹਰੀਜਨ ਜੁਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਜੁਤੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ । ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਏਥੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਵਿਚ ਦੁਧ ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਗਣਗੀਆਂ । ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ । ਚਾਹੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡਰ ਵਿਚ ਆ ਗਏ । ਚਾਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੋਖੇ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਬਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ।

श्री रूप लाल महता (पलवल): चेयरमैन साहिब इससे पहले भी जब सभा स्थगित हुई थी तो मैंने इस बिल के बारे में अपने विचार सदन में रखे थे लेकिन अब क्लाज 11 ज़ेरे बहस है। मैं इस विधेयक पर कुछ बातें कहना चाहता था लेकिन उस वक्त मौका नहीं मिला और मैं बातें जो करनी चाहता था, रह गई हैं। खैर है कि क्लाज 11 भी उससे मिलती जुलती है । इस कलाज़ को ए से लेकर एच तक जो डेढ़ सफा पर है अगर पढ़ा जाये तो इसमें सारी की सारी बातें व्यापारी का गला घूंटने वाली हैं। फिनांस मिनिस्टर साहिब, वैसे तो कहते हैं कि उन्हें व्यापारियों से बड़ी हमदर्दी है और उन्हें हमदर्दी है भी लेकिन वह खुद व्यापारी नहीं, वकील हैं । इसलिये उन्होंने हकीकत को देखा नहीं कि इसमें जो इतनी सख्त दफात रखी गई हैं कि व्यापारियों को भारी मुशकिलात का सामना करना पड़ेगा। आपकी इस कलाज के साथ इतनी कागज़ी कार्यवाही बढ़ गई है कि जो मामूली व्यापारी 40 हजार रुपये तक साल में सेल करता है उसे भी एक अच्छा खासा दफतर मेनटेन करना पड़ेगा । अगर कोई गलती हो गई तो कलाज़ 10 मौजद है जिसके तहत 500 रुपये तक जुरमाना हो सकता है । इस बारे में चाहिए तो यह था कि पहली दफा गल्ती होने पर वारनिंग देते, दूसरी दफा 50 तीसरी दफा 100 और फिर 500 रुपए जुरमाना करते या लाइसेंस ज़ब्त करते । लेकिन आपने एक दम 500 रुपये जुरमाना रख दिया । जहां तक किताबें पकड़ने और उन्हें वापस करने की बात है इस में बड़ा भारी धक्का होता है । पिछली दफा जब मित्तल साहिब

वज़ीर थे तो मैंने उन्हें बताया था कि किस तरह एक व्यापारी की किताबें काफी अर्सा तक महकमा के पास पड़ी रहीं और वापस नहीं की गई। मैंने सुझाव दिया कि जब किताबें पकड़ी जायें तो बजाये सालों तक कब्ज़ा में रखने से ऐसा किया जाय कि किताबों पर दस्तखत कर दो और दुकानदार से रसीद लेकर किताबें उसे वापस कर दो। अगर फिर किताबें पेश न करे तो उसके खिलाफ ऐक्शन लो। लेकिन यह बात ठीक नहीं कि किताबें पकड़ी जाएं और तीन तीन साल तक दफ्तरों में पड़ी रहें। मुझे पता है कि कई कई साल तक किताबें दफ्तरों में पड़ी रहती हैं जो वापस नहीं की जातीं। यह ठीक है कि कई एक दुकानदार डुप्लीकेट किताबें रखते हैं लेकिन एक दो बुरे आदमियों की वजह से सारे के सारे व्यापारी तबका की नाक में दम कर देना वाजब नहीं। इस कलाज़ 11 में पांच छः क्लाज़ें ऐसी रख दी गई हैं कि जिनकी वजह से दुकानदार की इज्ज़त महफूज़ नहीं है। बड़ी भारी ताकत और आरबिट्रेरी पावर्ज़ अफसरों के हाथ में दी जा रही है। कि जो बात उनके दिल में आ जाए वह करें और उन्हें कोई अपील दलील रोकने वाली बात न हो। अभी कल ही पलवल मंडी का वाक्या है कि डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एक्साइज़ अफसर ने एक आदमी पर टैक्स लगाना और जब उससे बात हुई तो वह यह बात मान भी गया है कि जैसा आप कहते हो टैक्स लगता तो नहीं लेकिन मैंने लगाना ज़रूर है चाहे अपील में जा कर छूट जाए। मैं वज़ीर साहिब से कहता हूँ कि वह मेरे साथ पलवल में किसी सीनियर अफसर को भेज दें जो इस बात का खुद पता कर सकता है कि उसने यह बात मंडी में मौजूद कई आदमियों के सामने कही कि टैक्स बनता तो नहीं लेकिन उसने यह लगाना ज़रूर है। अपील कर दो वहां बेशक माफ हो जाए। कितने अंधेर की बात है कि खाह मखाह उसे मजबूर किया जा रहा है कि पहले वह टैक्स के पैसे पेशगी जमा कराए फिर अपील करे और अगर हक में फैसला हो भी जाए तो रीफंड के लिये धक्के खाता फिरे। ज़िला एक्साइज़ अफसर ने 10,480 रुपये 1963-64 का टैक्स असैस किया। दुकानदार ने कहा कि मैं तेल बेचता हूँ मुझ पर टैक्स नहीं लग सकता। इस बारे में सूरज प्रकाश वर्सिज़ पंजाब स्टेट एक मुकद्दमा था जिसमें हाई कोर्ट का यह रूलिंग है कि सरसों के तेल पर टैक्स नहीं लग सकता, लेकिन फिर भी उस पर 10,430 रुपये टैक्स लगा दिया गया। अब उसने उसके खिलाफ अपील भी करनी है तो वह टैक्स के पैसे पेशगी जमा कराए तब अपील हो सकती है। उसके पास इतने पैसे हैं नहीं और उसे मंडी से भागना पड़ा। अब उसके खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी किये हुए हैं। इस तरह की बातें हो रही हैं। साफ रूलिंग है कि टैक्स सरसों के तेल पर नहीं लग सकता लेकिन उसे तंग करने के लिये उस पर टैक्स जड़ दिया गया है। अगर कोई करता है और उसके हक में फैसला भी हो जाता है तो रीफंड के लिये अपीलें करता फिरे और दफ्तरों के धक्के खाए। मैं वित्त मन्त्री महोदय से कहता हूँ कि आप बड़े फराखदिल हैं और आपने लुधियाना में व्यापारियों को विश्वास भी दिलाया था इसलिये इन सख्तियों को वापस लें। आप ऐसा करें कि पंजाब के 56 हज़ार व्यापारियों का ग्रेड ए, बी, सी वगैरा बना दें कि हर एक के लिये टैक्स की रकम इस हिसाब से जमा करानी पड़ेगी। आप मुकर्रर कर दें कि ए ग्रेड वाला इतना बी और सी ग्रेड वाला इतना इतना टैक्स अदा करें। यह रकम इस तरह अदा हो जाने से व्यापारियों को भी

[श्री रूप लाल महता]

सहूलित होगी । और उन्हें रोज़ अपनी बहियां उठाए नहीं फिरना पड़ेगा और सरकार को भी टैक्स की रकम मिल जाएगी हम इस बात के हक में हैं कि स्टेट रैवेन्यू में अज़ाफ़ा हो ताकि ज्यादा से ज्यादा डिवेलपमेंट के काम हों लेकिन इसके यह मायनी नहीं कि चंद गल्त बातों से असर अंदाज़ होकर ऐसे सख्त कानून बनाए जाएं कि जिससे लोग सरकार के खिलाफ हो जाएं और विरोधी दल वालों को आंदोलन कराने का मौका मिल जाए जब बाहर लोग नुकताचीनी करते हैं तो जैसे विरोधी दल वालों को राई का पहाड़ बनाने की आदत होती है वह बात को और बढ़ा कर कहते हैं तो हमें सरकारी पार्टी वालों को उनकी बातों का जवाब देना पड़ता है। इसलिये ऐसी बात न करें कि हमें कोई बात जवाब देने के लिये मिले ही नहीं और विरोधी दल वालों को लोगों को भड़काने का मौका मिले। ऐसे सख्त कानून बनाने में अच्छा वायु मंडल पैदा नहीं होता है। यह जो भारी अख्तियारात आप अफसरों को दे रहे हैं इनके बारे में मंत्री महोदय आप ठंडे दिल से सोचें कि उन लोगों को कितनी सख्तियों का मुकाबिला करना पड़ेगा । उनको खाह मखाह वकीलों को पैसे देने पड़ेंगे और आपके इन्स्पैक्टरों की पूजा करनी पड़ेगी । इस लिये मैं अर्ज़ करता हूँ कि यह जो आपने डेढ़ सफा पर इतनी बड़ी धारायें लिखी हैं. अगर उनको पढ़ूं तो सदन का समय नष्ट होगा इसलिये ऐसी सख्त क्लाज़ों को खत्म किया जाये। ताकि व्यापारियों को इतनी मुसीबतों का शिकार न होना पड़े । और जनता में असन्तोष न पैदा हो । अब सब साधनों से काफी बिल में सुधार हुआ है तो भी यह बिल पेचीदा बन गया है । सरकार यदि यकमुश्त टैक्स हर व्यापारी पर उसके काम के अनुसार बांध दे तो अब की आमदन की बजाय ज्यादा रुपया इकट्ठा हो सकता है और सब इन्सपैक्टरों के चगुंल से भी बच सकेंगे और सरकार को रुपया घर बैठे मिल जायेगा ।

ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿਘ) : ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਭ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਮਨੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦੀ ਈਵੇਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਇਵੇਜ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੁਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਕਿਸੇ ਡੀਲਰ ਤੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਤੇ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਹਕ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕਰੇ ।

ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇ । ਫੇਰ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਪਰਪਜ਼ ਹਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਫਿਨਾਂਸ਼ਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪਾਸ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਕੇਸ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਅਲਾਵਾ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਟ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਿਉਪਾਰੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਛਪੜ ਵਿਚ ਇਕ ਭੈਂਸ ਚਿਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਬੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਭੈਂਸ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਬੇੜਦੀ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ 1 ਪਰਸੈਂਟ ਜਾਂ 5 ਪਰਸੈਂਟ ਬਿਉਪਾਰੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਇਵੇਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬ ਇਨਸਪੈਕਟਰ, ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਅਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤਦ ਤਕ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦੀ । ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਝ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਰਿਆਂ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ । ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਰੁਪਿਆ ਹੈ, ਦੁਕਾਨ-ਦਾਰ ਕਸਟੋਮਰਜ਼ ਕੋਲੋਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਦੀ ਈਵੇਜਨ ਕਰਕੇ ਸਸਤੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਆਨਿਸਟਲੀ ਜਾਂ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਘਟ ਵਿਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਪਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਅਤੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ । ਮੇਰੇ ਇਕ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟੇਜ਼ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਪਾਸ ਪਬਲਿਕ ਮਨੀ ਜਾਂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਮਨੀ 5 ਹਜ਼ਾਰ, 10 ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਸ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈ । ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਸ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਦਾਖਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਸ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫੈਸੀਲੀਟੀਜ਼ ਹਨ । (ਵਿਘਨ) ਮੇਰੇ ਇਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲਜ਼ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਇਕ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ । (ਵਿਘਨ)

पंडित भागीरथ लाल शास्त्री: आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर, बार्डर पर रहने वाले दुकानदारों को लड़ाई के वक्त काम बन्द होने से काफी नुकसान उठाना पड़ा है । उनका सारा कारोबार ठप हो गया था ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ । ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਸੂਲੀ ਹੋਣੀ ਸੀ । ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰੁਪਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ । ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ।

ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿੰਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ । (ਵਿਘਨ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਓਨਰਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲੜਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਕ ਗਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ

[ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ]

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਦਾ ਰੁਪਿਆ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਹ ਰੁਪਿਆ ਪਬਲਿਕ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜਸਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ । ਇਥੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ।

ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰੀਪ੍ਰੀਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਭੇਜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਹਰ ਕਲਾਜ਼ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਭੇਜੇ ਹਨ । ਗੌਰਮਿੰਟ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਲ ਗਜ਼ਿਟ ਵਿਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਤਕ ਹੋ ਸਕੇ ਉਥੋਂ ਤਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਕਿ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਤਕਲੀਫ ਕਹੀ । ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਯਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ਲ ਪਲੇਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਰੇਡ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਡਬਲ ਅਕਾਊਂਟਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਗੇ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਰੀਟਰਨ ਗਲਤ ਸ਼ੋ ਕਰਨਗੇ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨ-ਦਾਰ ਡਬਲ ਬਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ ।

ਗੱਲ ਇਹ ਚਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਡਬਲ ਬਹੀ ਖਾਤੇ ਰਖਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਰਖ ਲਵੇ । ਉਹ ਆਦਮੀ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟ ਰਖ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ ਰਖੇ ਜਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਫਿਰ ਵੀ ਸਸਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ਲ ਹਾਊਸਿਜ਼ ਦੀ ਸਰਚ ਹੋਵੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਸੋਚ ਲੈਣ ਕਿ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਰਖਣਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਹੀ ਰਖ ਲੈਣ । ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਵੇਜਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਫਾਜ਼ਿਲ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬੁਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ । ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਉਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਜਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਚੂੰਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਿਖੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ । ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ । (*Interruption*) ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਟਾਕ ਚੈਕ ਕਰਨਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਠ ਵਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬੱਤੀਆਂ ਬਝ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਟਾਕ

ਚੇਕਿੰਗ ਵਿਚ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਟਾਫ ਦਾ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ unnecessarily ਹੈਰੇਸ ਕਰੇ । ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲਫਜ਼ ਸਨ:—

He will maintain day-to-day account of his business including stock accounts.

ਅਗਲੇ ਲਫਜ਼, ਜਿੱਥੇ ਸਟਾਕ ਰਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ......

ਇਕ ਆਵਾਜ਼ : ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੋਹਮਿਲ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਰੀ ਸਬ-ਕਲਾਜ਼ ਨੂੰ *Delete* ਕਰੋ ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ : ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਲਫਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ । ਉਹ ਰਹਿਣ ਦਿਉ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਲਫਜ਼ ਰਖ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

ਬਾਕੀ ਕਲਾਜ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਲਫਜ਼ ਕਨਫਿਸਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਨ-ਫਿਸਕੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ......(ਵਿਘਨ) ਸੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ । ਸੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਤੇ confiscate ਕਰਨ ਵਿਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਨਫਿਸਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਫਜ਼ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੀਜ਼ ਦਾ ਲਫਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ । ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰੇਸ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਗੌਰਮਿੰਟ ਵਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।

ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੈ । ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ representation ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਏ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੋ । ਭਈ ਲਿਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਕਰੋ ਜਲਦੀ ਕਰੋ । ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਗੁੜ ਗੁੜ ਮਿਠਾ, ਰਾਈ ਰਾਈ ਕੌੜੀ । ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ੇ ਉੜਾ ਲੈਣ ਦਿਉ । ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ । ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬੋਗਸ ਡੀਲਰਾਂ ਤੇ ਚੈਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮਿਟੀ ਆਫ ਰੇਟਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਵੇਯਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਉ । ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ । ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸਾਂ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਦੋ ਹੀ ਜ਼ਰੀਏ ਹਨ । Either increase in taxation income or check of evasion. ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ । ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਮਦਨੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਭਈ ਦਖ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ? (ਵਿਘਨ) ਹੈਰੇਸਮੈਂਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਗਲਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵੇ । ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰੁਪਿਆ ਜੇਕਰ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ ਉਹ ਰੁਪਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾ ਰਖਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ । ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ । ਮੈਂ

[ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ]

ਤਾਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗਾ ।......ਰਾਤ ਟੰਡਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਔਫਰ ਆਈ ਸੀ। ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਫਰਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ 20 ਕਰੋੜ ਲੈ ਲੋ । ਕਲ ਵੀ ਔਫਰ ਆਈ ਸੀ । ਇਹ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 24 ਕਰੋੜ ਲੈ ਲੋ । ਉਹ ਤਾਂ 20 ਕਰੋੜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਮੈਂ 4 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਵਧਾ ਲਏ । ਇਹ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ । ਉਹ ਪਹਿਲੇ 20 ਕਰੋੜ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸਨ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧਦਾ ਹੈ । ਸਾਡੇ ਘਾਟੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਤੀਂ 24 ਕਰੋੜ ਕਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਦਸਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਰੁਪਿਆ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ । ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਸਦਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਫਰ ਸਿਨਸੀਅਰ ਸੀ । 24 ਕਰੋੜ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਾੜਾ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਇਕ ਹੈ ।

ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹਰ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। (ਵਿਘਨ) ਅਗਲੀ ਸਿਮਾਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ। ਜੇ ਆਨਰੇਬਲ ਮਨਿਸਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਛੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਜਾਉ। ਅਸਲ ਗਲ ਇਹ ਹੈ । ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਟੈਕਟਿਕਸ ਬਦਲ ਲਏ ਹਨ ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮਨਿਸਟਰ ਦੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ? ਇਹ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਨਿਸਟਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ (ਹਾਸਾ) ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਟਿਕਸ ਬਦਲੇ ਹਨ । ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਇਹ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਇਹ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬਿਲ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਉ । ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈ ਕਿ ਬਿਲ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜਦ ਹੁਣ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲਉ । ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਫਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਫਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਅਖਿਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਕਟ ਅਖਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਦ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁੜ ਇਤਰਾਜ ਉਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ । ਜਿਥੋਂ ਤਕ appellate system ਦਾ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਤੁਅਲਕ ਹੈ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ there should be no interference from anybody. ਜੇ ਕੋਈ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪਾਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫੇਵਰਟਿਜ਼ਮ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਝ ਤਰਮੀਮਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਮੈਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਜ਼ ਐਜ਼ ਅਮੈਂਡਿਡ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ।

ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਨ ਲਾਲ : ਤੁਸੀਂ ਸਬ-ਕਲਾਜ਼ (2) ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਸਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਡੀਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।

(ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ)

ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਫੇਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ । ਇਹ ਜਿਹੜਾ "maintain day to-day accounts of his business ਤੁਸਾਂ retain" ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦਸੋ ਕਿ accounts ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ? ਇਹ ਤਾਂ ਇਕ ਬੜੀ ਮੁਹਮਲ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ। Accounts ਦੀ ਡੈਫੀਨੀਸ਼ਨ ਹੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਬ-ਕਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਡੀਲੀਟ ਕਰ ਦਿਉ ਵਰਨਾ this will create confusion.

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ : ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ accounts ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਖਣੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਝਮੇਲਾ ਕਿਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ?

Shri Mohan Lal : But by this you will create such a confusion and give such wide powers to your officers that they are likly to misuse them.

Finance Minister : Every registered dealer will maintain day-to-day accounts of his business.

Shri Mohan Lal : What do you mean by the term 'accounts of business ?' It has no where been clarified in the Act.

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ : ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ । ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਅੱਜ ਤਕ ਇਹੀ ਲਫਜ਼ ਐਕਟ ਵਿਚ ਚਲਿਆ ਆਂਦਾ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਲਫਜ਼ ਤਾਂ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿਤਾ ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਦਸੋ ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ : ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ—

In the proposed section 14—

(1) in sub-section (2)—

(i) in clause (a), *omit* 'including stock accounts of each class of goods dealt in by him containing particulars of purchases or receipts, sales or deliveries and balance stock';

ਅਗਲੀ ਇਹ ਹੈ:—

(ii) in clause (b), *omit* the words 'and furnish a copy of such list to the Assessing Authority';

ਯਾਨੀ ਇਹ ਵੀ ਅਸਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫਰਨਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ।

ਤੀਜੀ ਤਰਮੀਮ ਜਿਹੜੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ:—

(iii) for clause (c), *substitute*—

"(c) produce, if so required, account books of his business before the Assessing Authority for authentication in the prescribed manner.

ਸ੍ਰੀ **ਬਲਰਾਮ ਜੀ ਦਾਸ ਟੰਡਨ** : ਹੋਰ ਕੀ ਕੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ ?

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ: ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ residential house of the de.ler ਨੂੰ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, *delete* ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ । ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ "ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ਲ ਹਾਊਸ" ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਵੀਜ਼ ਹੈ "no officer......" ਵਾਲਾ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ।

ਫੇਰ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ confiscat.on ਵਾਲੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਲਾਜ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਲਫਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ that should go ਉਹ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਾਵੀਜ਼ੋ ਹਨ sub-section (6) ਇਹ ਵੀ ਚੂੰਕਿ confiscation ਨੂੰ ਡੀਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੀਲੀਟ ਕਰਨਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ । (*inte:rup ions*)

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਉਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਤਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਅਸੈਸਿੰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਰੂਲਿੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ, documents, accounts books ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ । ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰਖਿਆ ਹੈ ਤਾਕਿ ਵਿਉਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਈਵੇਜ਼ਨ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ "ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਉ, ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿਉ" ਠੀਕ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ।

ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਵਾਲੀ ਨਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ।

उपाध्यक्षा: अब हाउस के सामने पंडित मोहन लाल की एमेंडमेंट्स नं० 15 से 21 तक हैं । क्या इनको पंडित मोहनलाल विदड्रा करते हैं ? (Now amendments No. 15 to 21 given notice of by Shri Mohan lal are before the House. Does Shri Mohanlal withdraw them ?)

श्री मोहन लाल: मैं अपनी एमैंडमैंट्स नं० 15,16, 17 और 18 को विदड्रा करता हूँ। मेरी अमैंडमैंट नं. 19 जो है उसको गवर्नमेंट ने मान लिया है। इसके बाद मेरी जो अमेंडमेंट नं. 20 है उसे भी मैं विदड्रा करता हूँ । फिर जो एमेंडमेंट नं. 21 है इसको भी गवर्नमेंट ने मान लिया है।

Deputy Speaker: Has the hon. Member the leave of the House to withdraw his amendments Nos. 15 to 18 ?

(*Voices from the Opposition* : No)

Deputy Speaker: Since leave has not been granted to withdraw these amendments I will put them to the vote of the House.

Deputy Speaker : Question is—

> In the proviso to the proposed Section 14(1), line 2, *for* "five" *substitute* three",
>
> *Delete* sub-section (2) (a) of the proposed section 14.
>
> In the proposed section 14(3)(a), line 2, *for "ten" substitute* "four".
>
> In the proposed section 14(3)(b), line 1, *for* "sixty" *substitute* "thirty".

The motions were lost

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਮੈਡਮ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਅਮੰਡਮੈਂਟ ਪੁਟ ਕੀਤੀ ਸੀ.....

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਂ । ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ । (What remedy should I suggest for removal of hon. Member's misunderstanding. He may please resume his seat.)

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਇਹ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ । ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇਸ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਰਾਏ ਪੁਛੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਉਧਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯੈਸ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ । ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਰੂਲਿੰਗ ਦਿਤੀ ਹੈ ।

Deputy Speaker : Order, please.

Amendment No. 19 by Pandit Mohan Lal.

Deputy Speaker : Question is—

> In the proposed section 14 (6), line 2, *delete* "and confiscate.

The motion was carried.

Deputy Speaker: Next amendment No. 20 is also by Pandit Mohan Lal.

Pandit Mohan Lal : I withdraw it.

Deputy Speaker : Has the hon. Member the leave of the House to withdraw his amendment.

Voices : Yes.

Voices : No.

Deputy Speaker : The leave is granted and the Amendment is withdrawn.

डाक्टर बलदेव प्रकाश: डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरा कहने का मतलब यह है कि यहां पर डिगनेटी आफ दी हाउस हम सब को बरकरार रखनी चाहिए। आपने जब यह सवाल पुट किया तो हमारी तरफ से सब ने नो कहा और उनकी तरफ से कोई बोला ही नहीं तो आप ने कह दिया है कि एमेंडमैंट इज विदड्रान। आपने यह कैसे कह दिया है ?

मुख्य संसद सचिव : नहीं जी इस तरफ से सब बोले हैं।

डाक्टर बलदेव प्रकाश : नहीं, डिप्टी स्पीकर साहिबा, आपने जब यह पुट किया तो हमने सबने इधर से कहा कि नो और उधर से कोई बोला ही नहीं जिसका मतलब था कि विदड्रा करने की इजाज़त नहीं दी जाती तो आपने कैसे कह दिया है कि यह विदड्रा हो गई है। जब हमारी तरफ से नो कहा गया था तो इनकी तरफ से किसी ने इस को चैलेंज नहीं किया और किसी ने आईज़ नहीं कहा —

Deputy Speaker : All right, I put it to the vote of the House.

Deputy Speaker : Question is—

In the proposed section 14(6), line 6, between "documents" and " : " *insert* "and shall impose by way of penalty double the amount of tax recoverable on such goods".

The motion was lost.

Deputy Speaker : Next amendment No. 21 is again by Pandit Mohan Lal.

Deputy Speaker : Question is—

Delete both the provisos to the proposed section 14(6)—.

The motion was carried.

Deputy Speaker : Now the House will take up the Amendment Nos. 39 to 46 by Shri Ram Saran Chand Mital.

Shri Ram Saran Chand Mital : Madam, I withdraw these amendments.

Deputy Speaker : Has the hon. Member leave of the House to withdraw his amendments.

Voices : Yes.

Voices : No.

Deputy Speaker : Ayes have it, Ayes have it. The leave is granted and the Amendments are withdrawn.

उपाध्यक्षा: अगर हाउस काम करने के मूड में नहीं है तो आपकी मर्जी है। मगर यह तरीका नहीं है कि इस तरह से इन्टरप्शन की जाए। (If the House is not in a mood to work then it is up to them but it is not proper to interrupt like this.)

डाक्टर बलदेव प्रकाश: हाउस तो बड़े सीरियस मूड में है।

उपाध्यक्षा: मित्तल साहिब ने 39 से लेकर 46 तक अपनी अमेंडमैंट्स वापस ले ली हैं। (Shri Mital has withdrawn his amendments Nos. 39 to 46.)

डाक्टर बलदेव प्रकाश: नहीं हमने नहीं होने दी (विघ्न)।

मुख्य संसद सचिव : यह जो मुगालता इन्होंने खड़ा कर दिया है उस बारे में अर्ज करना चाहता हूँ कि सब से पहले आपने कहा कि जो विदड्राल के हक में हैं वह हां कहें तो हमने कहा हां। फिर आपने कहा कि जो इसके खिलाफ हैं वह नो कहें तो इन्होंने कहा कि नो। फिर आपने कहा कि क्लाज़ ऐक्सैप्ट की जाए या न।

एक आवाज़: क्लाज नहीं अमैंडमेंट। हां अमैंडमेंट। तो अमैंडमेंट गिर गई, यह खामखाह मगालते में डाल रहे हैं।

ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ : On a point of order, Madam. ਤੁਸੀਂ foreign ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ.....

Deputy Speaker : Please take your seat. I do not want this to be brought in.

(*Interruptions*)

ਚਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ : ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਸੁਣ ਲਉ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ......(ਵਿਘਨ)

उपाध्यक्षा : हम यह कोई अच्छी रिवायत कायम नहीं कर रहे कि इस तरह से तीसरी दफा कोई मोशन की जाए। मित्तल साहिब ने 39 से लेकर 46 तक अमैंड-मैंट्स वापस ली हैं। क्यों मित्तल साहिब? (We are not setting any healthy tradition by repeating a motion thrice. Shri Mital has withdrawn his amendments Nos. 39 to 46. Is not that so Mital Sahib ?)

श्री राम सरन चन्द मित्तल : मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि चूंकि कुछ अमैंड-मैंट्स फिनांस मिनिस्टर साहिब ने कबूल कर ली हैं तो इस तरह ग यह अमैंडमैंट्स इन्फ्रकचुअस हो जाती हैं तो इन पर ज्यादा बहस नहीं करना चाहिए (विघ्न) मैं इनको विदड्रा करता हूँ।

Deputy Speaker : Has the hon. Member leave of the House to withdraw his amendment.

Voices : Yes.

Voices : No.

उपाध्यक्षा : यश जी आपकी जो अमैंडमट्स हैं......

श्री बलरामजी दास टंडन : पहले उनका तो फैसला हो ।

श्री यशपाल : जो मेरी ग्रमैंडमेंट नम्बर 65 है वह तो इन्होंने ऐक्सैप्ट कर ली है उसे तो वापस लेने की जरूरत नहीं है..........विघ्न....

उपाध्यक्षा : फिनास मिनिस्टर साहिब, क्या ग्रापने मनजूर कर ली है ? (Has the Finance Minister accepted that amendment ?)

वित्त मन्त्री : यश जी ने जो मूव की ह वह हमने सारी ऐक्सैप्ट कर ली हैं ।

(विघ्न)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : On a point of Order, Sir, ਕੀ ਕੋਈ ਮਨਿਸਟਰ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਇਕ ਦਫਾ ਕੁਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ 65 ਨੰਬਰ ਹੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ? (ਵਿਘਨ)

श्री फतेह चन्द बिज : डिप्टी स्पीकर साहिबा, हैं चीफ पार्लियामैंट्री सैक्रेटरी साहिब बार बार फिनांस मिनिस्टर साहिब को बार बार ग्रार्डर देने ग्राते हैं इससे वह कन्फ्यूज़ हो रहे हैं । इन्हें कहें कि बार बार न ग्राएं । (विघ्न)

उपाध्यक्षा : वह चीफ पार्लियामेंट्री सैक्रेटरी हैं, वह जा सकते हैं । (He is the Chief Parliamentary Secretary. He can do so.) (*Interruption*) सरदार कपूर सिंह जी, क्या ग्रापने श्री यश की ग्रमैंडमैंट नम्बर 65 ऐक्सैप्ट कर ली है ? (Has the hon. Minister, Sardar Kapur Singh, accepted amendment No. 65 by Sh. Yash Pal ?)

वित्त मन्त्री : हां जी ।

श्री बलरामजी दास टंडन: ग्रान ए प्वायंट ग्राफ ग्रार्डर, मैडम । ग्रापने जब मित्तल साहिब की ग्रमैंडमेंट्स नम्बर 39 से लेकर 46 तक विदड्राल के लिये हाउस के लिये पुट कीं तो हमने कहा नो यानी हाउस ने उनको विदड्रा करने की इजाज़त न दी । ग्रब ग्राप बतायें कि उनका किया बना ? (विघ्न) जो डिस्पयूट होता है उसको कैसे डिसपोज़ ग्राफ किया जाता है ? (विघ्न) पहले उसको डिसपोज़ ग्राफ करें ।

उपाध्यक्षा : कोई मौका माहोल भी देखना चाहिए। (The hon. Member should see if there is any occasion for this.)

श्री बलरामजी दास टंडन : रूल्ज़ के मुताबिक सारी बात होनी चाहिए।

उपाध्यक्षा : हाउस अब आगे चला गया है पीछे नहीं जा सकता। (विघ्न) देयर शुड बी सम लिमिट। (विघ्न) [The House has gone ahead. (*Interruption*) There should be some limit.]

डाक्टर बलदेव प्रकाश : आनरेबल मैम्बर ने जो प्वायंट रेज़ किया है वह बड़ा रीज़नेबल है। जब आपकी रूलिंग को चैलेंज किया जाए तो उसको डिसपोज़ आफ करने का तरीका बड़ा क्लियर है कि या तो खड़े कराके या मैम्बरों को लाबीज़ में भेज कर हाऊस की राय जानें। इसके बिना इसको डिसपोज़ आफ नहीं किया जा सकता। यह साफ बात है। (विघ्न)

ਚੌਧਰੀ ਚਰਸ਼ਨ ਸਿਘ (ਨਕੋਦਰ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਾਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸਬ-ਕਲਾਜ਼ ਤੇ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਇਹ ਇਕ ਗਲਤ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਲਿੰਗ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਰੂਲ ਹੇਠਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਰੂਲਜ਼ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਫ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸਬ ਕਲਾਜ਼ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਕਲੀ ਇਕਲੀ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Finance Minister : We do not mind if these amendments are taken up or put to the vote of the House one by one.

Deputy Speaker : All right, I am going back and will put amendment No. 39 to the vote of the House and will then put all the amendments moved to the vote of the House one by one.

Deputy Speaker : Question is—

For the proposed section 14(2)(a), *substitute* the following :—

(a) maintain correct accounts of his business according to the mercantile system of his class of business prevalent in his town or village, as the case may be".

(After ascertaining the votes of the Members by voices, Deputy Speaker said, "I think the Noes have it". This opinion was challenged and division was claimed. Deputy Speaker after calling upon those Members who were for "Aye" and those who were for "No" respectively, to rise in their places declared that the motion was lost.)

The motion was lost.

Deputy Speaker : Question is—

For the proposed section 14(2)(c), *substitute* the following :—

"(c) allow his account-books to be authenticated in the prescribed manner at his place of business during working

[Deputy Speaker]

hours by the Assessing Authority or any other officer authorised by him in writing in this behalf.

The motion was lost.

Deputy Speaker : Question is—

In the proposed section 14(4), line 4, *delete* "or any building or place".

The motion was lost.

Deputy Speaker : Question is—

Delete the proviso to the proposed section 14(4).

The motion was lost.

Deputy Speaker : Question is—

In the proposed section 14(6), line 4, *delete* "or any building or place".

The motion was lost.

Deputy Speaker : Question is—

In the proposed section 14(6), line 4, between "dealer" and "but" *insert* "for purposes of sale."

The motion was lost.

Deputy Speaker : Question is—

In the second proviso to the proposed section 14(6), line 3, *delete* "one thousand rupees or".

The motion was lost.

Deputy Speaker : Question is—

In the second proviso to the proposed section 14(6), line 4, *delete* "whichever is greater".

The motion was lost.

Deputy Speaker : Question is—

In the proposed section 14(2)(a) lines 1—4, *delete* "including stock accounts of each class of goods dealt in by him containing particulars of purchases or receipts, sales or deliveries and balance stock".

The motion was carried.

Shri Yash Pal : I beg to seek leave of the House to withdraw my amendment No. 66.

Deputy Speaker : Has the hon. Member the leave of the House to withdraw his amendment ?

Voices : Yes.

Voices : No.

Deputy Speaker : Since leave to withdraw the amendment has been refused, I will put the amendment to the vote of the House.

Deputy Speaker : Question is—

Delete the propósed section 14(2)(b).

The motion was lost.

Deputy Speaker : Question is—

For the proposed section 14(2)(c), substitute the following—

"14(2)(c). Produce, if so required, Accounts Books of his business before the Assessing Authority for authentication in the prescribed manner."

The motion was carried.

Deputy Speaker : Question is—

In the proposed section 14(2)(d), line 1, *for* "such" *substitute* "his".

The motion was carried.

श्री बलरामजी दास टंडन: मेरा प्वायंट आफ आर्डर यह है कि आपने 'आएज़' भी करवा लिये 'नोज़' भी करवा लिये मगर अभी तक फैसला नहीं दिया, टरैज़री बैंचिज़ से पूछा जा रहा है।

उपाध्यक्षा: आप मुझे क्या ऐसे ही समझ रहे हैं। मैं पहले ही फैसला दे चुकी हूँ। (What does the hon. Member think about me ? I have already given my decision in this connection.)

मुख्य मंत्री: डिप्टी स्पीकर साहिबा, जब आप मोशन मूव करें तो इस का नंबर बोल दिया करें। (*Interruptions*)

उपाध्यक्षा: मुझे अफसोस है वह मुझे सुनते ही नहीं। (I am sorry the hon. Chief Minister does not hear me.)

Deputy Speaker : Now I am putting amendment No. 69 by Shri Yash Pal to the vote of the House. This amendment reads—

In the proposed section 14(4), line 4 *between* "place" and "where" *insert* "except residential houses".

The motion was carried.

Deputy Speaker : Now I will put amendment No. 70 by Shri Yash Pal to the vote of the House.

Shri Yash Pal : Madam, I withdraw it.

Deputy Speaker : Has the hon. Member the leave of the House to withdraw his amendment ?

(*Voices from the Opposition* : No.)

Deputy Speaker : Since leave has not been granted to withdraw the amendment I will put it to the vote of the House.

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ : On a point of order, Madam, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿਆਂ ਮੈਂ ਇਕ ਬਹੁਤ ਜੂਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਊਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ । ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਨਬਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ every body may understand. (*Interruptions*)

Deputy Speaker : I am putting amendment No. 70 by Shri Yash Paul to the vote of the House.

Question is—

For the proviso to the proposed section 14(4), *substitute* the following :—

"Provided that the warrants of search have been issued by Excise and Taxation Commissioner, Deputy Commissioner, Excise and Taxation or District Exise and Taxation Officer. No person below the rank of DETO shall be authorised to enter any premises of any dealer for the purpose of search."

The motion was lost.

Deputy Speaker : Now I will put amendment No. 71 by Shri Yash Paul to the vote of the House.

Shri Yash Paul : Madam, this amendment has already been accepted by the House because it is identical to the one given by Shri Mohan Lal i. e. No. 19 and that has been accepted.

Finance Minister : Yes, it is similar to the one already accepted and need not be put to the vote of the House.

डाक्टर बलदेव प्रकाश : ग्रान ए प्वायंट ग्राफ ग्रार्डर मैडम, डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरा प्वायंट ग्रार्डर यह है कि जो ग्राप पास करते जा रहे हैं ट्रेज़री बैंचिज़ वाले लोग क्लियर नहीं हैं। ग्राप गर्ग साहिब से यही पूछ लें कि वह कौन-कौन सी मोशन के हक में हैं। मैं समझता हूँ कि यह बिल पोस्टपोन करके किसी ग्रौर मामले पर डिस्कशन जारी रखी जाये।

उपाध्यक्षा : ग्राप यह बात कह सकते हैं मगर मैं ऐसा नहीं कह सकती। (The hon. Member can so make such a suggestion but I cannot.)

चौधरी नेत राम : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं ग्रापके द्वारा ग्रानरेबल मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि यह जो तरमीमें मंज़ूर हुई हैं, उनमें से कितनी नामंज़ूर की हैं ग्रौर कितनी मंज़ूर की हैं ? (हंसी)

श्री बलरामजी दास टंडन : जनाब 71 अमैंडमैंट जो पंडित मोहन लाल जी की थी, वह इसके आइडेंटीकल थी, वह मंजूर हो चुकी है, और इसको हाउस ने रिजैक्ट किया है तो इसकी पोजीशन क्या होगी ?

उपाध्यक्षा : 71 तो पुट ही नहीं हुई। आप बैठ जाइये ।

वित्त मंत्री : एक अमैंडमैंट और है, प्रोवाइजो सब-क्लाज़ ४ बि डिलीटिड ।

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਹਾਲੇ 212 ਸ੍ਰੀ ਜਾਗੀਰ ਸਿੰਘ ਦਰਦ ਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਇਹ 220 ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ।

उपाध्यक्षा : बाबू अजीत कुमार, बैठ जाओ, जिस चीज को आपने देखा नहीं, उसके बारे में क्यों हाउस का वक्त ज़ाया करते हो ? (The hon. Member Babu Ajit Kumar may resume his seat. Why should he waste the time of the House about a matter of which he has no knowledge ?)

श्री जगन्नाथ : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडम । अगर पंजाबी सूबा बन जाता है तो उसके बनने के बाद आप स्पीकर या डिप्टी स्पीकर रहेंगी ?

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਆਨ ਏ ਪਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਮੈਡਮ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । 212 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 234 ਤਕ ਸਾਰੀਆਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹਨ । 212 ਨੰਬਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਅਜੇ ਪੁਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਨੰਬਰ 235 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਪੁਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਦੱਸਾਂ । ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨੰਬਰ 212 ਤੋਂ 234 ਤਕ ਕੈਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਨੰਬਰ 235 ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । (Let the hon. Member try to listen to me. The House has already voted upon amendments from Nos. 212 to 234. Now amendment No. 235 is being put to the House.)

Deputy Speaker : Question is—

Delete the proviso to the proposed section 14(4).

The motion was carried.

Deputy Speaker : Question is—

That Clause 11 as amended stand part of the Bill.

The motion was carrried.

ਕਲਾਜ਼ 12

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਕਲਾਜ਼ 12 ਵਿਚ ਜਿਥੇ 'ਐਂਡ ਕਨਫਿਸਕੇਟ' ਦੇ ਲਫਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ । ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ 14-ਬੀ (6) ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 14-ਬੀ (8) ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ।

[ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ]

Further, first proviso to the proposed section 14b(8) will be deleted and in the second proviso to this section, lines 2 and 4, the words "or confiscation", will be deleted.

Deputy Speaker : The following amendments given notice of by **Principal Rala Ram, will be deemed to have been read and moved and discussed together** :—

92. In the proposed section 14-B(6), line 3, *delete* " and confiscate".

94. In the proposed section 14-B(8), line 5, *delete* "and confiscate. "

96. *Delete* the first proviso to the proposed section 14-B(8).

98. In the second proviso to the proposed section 14-B(8), lines 2 and 4, *delete* "or confiscation".

प्रिंसीपल रलाराम (मकेरियां) : उपाध्यक्षा महोदय, क्लाज़ 12 में जहां कानफिसकेट का शब्द आता है उसे उड़ा दिया जाए। यह बात हर एक स्वीकार करता है कि व्यापारियों की तरफ से जो टैक्स की इवेज़न होती है उसे रोका जाए लेकिन इस बारे में भी इस सदन में तकरीबन सब की एक राए है कि उनको किसी तरह से हैरिसमेंट नहीं होनी चाहिए क्योंकि यह सब मानते हैं कि जहां तक इन्स्पैक्टर्ज़ का ताल्लुक है उनकी तरफ से नाजायज़ बातें और नाजायज़ स्लूक अक्सर व्यापारियों के साथ होता है और वह इसी गर्ज़ से होता है कि उन से रुपया ऐन्ठा जाए । इसको रोकने के लिये यह ज़रूरी है कि जो तरमीम हमारे सामने है उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिससे कि व्यापारियों में हैरिसमेंट बढ़े या उन्हें किसी तरह से तंग किया जाए। उसके लिये ज़रूरी है कि क्लाज़ 12 में जहा कहीं भी यह प्रोवीज़न किया गया है कि अगर कोई व्यापारी इवेज़न करता हो और इन आफीसर्ज़ साहिबान को जो यहां जिनके दर्जे भी बताए गए हैं यह निश्चय हो जाए कि व्यापारी वाकेई बदनियती से काम कर रहा है तो उनके गुड्ज़ को सीज़ करना या उस माल को पकड़ने का हक्क तो आगे भी हासिल है यह क्लाज़ 12 में यह चीज़ कही गई है कि वह अफसर साहिबान जिनके दर्जे उसमें बताये गए हैं उस माल को ज़ब्त भी कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि यह व्यापारियों के साथ बड़ी भारी ज़बरदस्ती होगी और उनसे रुपया ऐन्ठने के लिये ऐसा किया जाएगा।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਮੈਡਮ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਦੁਖ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਲਿੰਗ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ । ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਜਨਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਕੀ ਇਹ ਰਿਜਨਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ?

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਉਹ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਨ । (He can speak in Hindi.)

प्रिंसीपल रलाराम : डिप्टी स्पीकर साहिबा मैं यह कह रहा था कि कोई ऐसे मौके पैदा नहीं करने चाहिएं जिनसे कि इन्स्पैक्टर साहिबान को ज्यादा रुपया ऐन्ठने का मौका मिले। क्लाज़ 12 में जहां उनको गुड्ज़ को कनफिस्केट करने का इख्त्यार दिया है या गवर्नमैंट ने लिया है मैं यह समझता हूँ कि गुड्ज़ को सीज़ करने का, अपने कब्जा में

लेने का इख्त्यार ही काफी है, महकमा व्यापारी पर पैनल्टी भी लगा सकता है तो कोई वजह नहीं कि अगर वह माल को पकड़ भी सकते हैं; पेनल्टी भी लगा सकते हैं तो फिर ज़ब्त करने का भी उन्हें इख्त्यार दिया जाए । यह इतना वसीह इख्त्यार होगा कि इससे व्यापारियों को बड़ी भारी परेशानी पैदा होगी । इस परेशानी को रोकना निहायत जरूरी है । इसलिये जो अमेन्डमैन्ट्स मैंने दी हैं उन तरमीमों में यह मांग की गई है कि सैक्शन 14 बी (6) में से (एन्ड कनफिसकैट) के शब्द डीलीट कर देने चाहिएं । इसी तरह सैक्शन 14 बी (8) में से यह शब्द निकाल देने चाहिएं । इसी तरह सैक्शन 14 बी (8) का जो फस्ट प्रोवाइज़ो है उसे डीलीट कर देना चाहिए । इसलिये मैं यह समझता हूँ कि यहां हम टैक्स की इवेज़न को रोकना चाहते हैं उसके मुकाबिला में हम अफसरों को इतने अधिकार देकर खड़ा न करें । और वह है रुपया ऐन्ठने की तरकीबें जो इन्स्पैक्टर साहिबान के पास रहती हैं जिनका समय-समय पर नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं । इस बात की तरफ वित्त मन्त्री महोदय की तवज्जोह दिलाई जा चुकी है और मैं भी उनको बताना चाहता हूँ कि यह बात बिल्कुल शक शुबह से दूर है कि यह इन्सपैक्टर इन तरकीबों से इतना रुपया पैदा कर लेते हैं कि उनका स्टैंडर्ड आई. ए. एस. और आई. सी ऐस. अफसरों से भी बढ़ कर रहता है । उनके बच्चे योरोपियन कन्वैंट स्कूलों में पढ़ते हैं जो इतने महिंगे हैं कि वहां अमीर लोग और अच्छी खासी आमदनी वाले लोग ही बच्चे पढ़ा सकते हैं । मैं चाहता हूँ कि सरकार यह पड़ताल करे कि वह इतनी थोड़ी आमदनी और तन्खाह के होते हुए किस तरह ऐसा स्टैंडर्ड मेनटेन किये हुए हैं । तो मैं अर्ज़ करता हूँ कि यह जो रुपया ऐंठने की तरकीबें हैं इनको बढ़ाना नहीं चाहिए बल्कि कम करना चाहिए और जो इतने भारी अख्तियारात इन लोगों को दे रहे हैं कि वह माल ज़बत कर सकते हैं । इससे बड़ी भारी बददयानती फैलेगी । इसलिये आप पैनलटी लगाने तक ही बात रखें और जो confiscation का जो प्रोविज़न रखा है उसे उड़ा दें । आशा है वित्त मन्त्री महोदय मेरी इस बात को स्वीकार करते हुए क्लाज़ 12 में जहां जहां confiscation का लफ्ज़ आता है उसे उड़ा देंगे । इस तरह करने से उनका मकसद भी पूरा हो जाएगा और व्यापारियों की परेशानी भी कम हो जाएगी ।

श्री मोहन लाल (बटाला) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आपका सिर्फ इतना ही ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि क्लाज़ 12 पर सब से पहले मेरी अमैंडमैंट्स नम्बर 22 और 23 हैं जोकि इन से आइडैंटीकल हैं और मैंने भी वही मांग की है कि 14 B (6) और 14B (8) में जहां confiscation के लफ्ज़ आते हैं उन्हें उड़ा दिया जाए और गवर्नमट इस बात को मान गई है। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि मेरी यह अमैंडमैंट्स सब से पहले आती हैं इसलिये यह पहले पुट होनी चाहिएं ।

शिक्षा मन्त्री (श्री प्रबोध चन्द्र) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, तीन-चार दिन से इस बिल पर बहस होती आ रही है और मेरे सामने बैठे हुए और दूसरे कुछ इधर बैठे भाईयों ने जनता के नाम पर और कुरप्शन को दूर करने के नाम पर सरकार को कोसा है कि वह व्यापारियों को मारना चाहती है और कुरप्शन को बढ़ावा देना चाहती है। मैं चंद अल्फाज़ में सिर्फ इतना अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आखिर इस बिल को लाने की क्यों

[शिक्षा मंत्री]

ज़रूरत पड़ी । यह ज़रूरत इसलिये महसूस हुई कि बड़ी मुद्दत से व्यापारी यह मुतालबा करते आ रहे थे कि यह टैक्स पहली स्टेज पर लगना चाहिए ताकि बीच वाला व्यापारी न फंसे और जहां से माल आता है वहां ही उस पर टैक्स लगाया जाए ताकि न गवर्नमैंट को और न ही व्यापारियों को परेशानी हो । उनकी इस मांग को पूरा करने के लिये ही यह अमैंडिंग बिल लाया गया है । किताबें लेने के बारे में कहा गया कि ऐसा क्यों किया गया । यह चीज़ इसलिये करनी पड़ी कि पंजाब हाई कोर्ट के जस्टिस हरबंस सिंह जी का रूलिंग है कि अगर कोई ई. टी. ओ. किसी दुकानदार के पास जाकर किताबें मांगता है और अगर वह किताबें नहीं देता तो गवर्नमैंट के पास कोई ऐसा कानून नहीं कि वह उसे किताबें देने पर मजबूर कर सके । उन्होंने बल्कि यहां तक कहा कि that officer will be guilty of tresspass अगर वह किसी दुकानदार के पास जाकर उसकी किताबें मांगता है । इसी तरह कुछ और चीज़ें थी जिनको कानूनी तौर पर पूरा करने के लिये कुछ और क्लाज़ें लानी पड़ीं । मुझे यह कहने में खुशी है कि पहली बार है जो इस गवर्नमैंट ने एक दफा नहीं दो दफा नहीं बल्कि कई दफा व्यापारियों को सामने बिठा कर उनसे सारी बातचीत करके जिस बात को उन्होंने परेशानी बताया उसे हमने हटा दिया । यह काम इस गवर्नमैंट ने ही पहली दफा किया है । डाक्टर बलदेव प्रकाश जी ने कह दिया कि यह गवर्नमैंट ही क्या हुई जिसे पहले समझ न आया कि व्यापारियों से पहले बात करके बिल लाती । उनसे पहले बहस करके सारी बात करती । अगर हम ऐसा करते तो कल को प्रिविलेज मोशन आ जाती कि बिल गज़ट करने से पहले ही.....

डाक्टर बलदेव प्रकाश : आन ए प्वायंट आफ आर्डर । यह क्लाज़ 12 चल रही है जो चैक बैरियर्ज़ के बारे में है लेकिन यह बातें किताबों की कर रहे हैं ।

शिक्षा मन्त्री : तो यह जो प्रिविलेज मोशन की तलवार थी उससे बचने के लिए जब तक गज़ट नहीं हो गया किसी व्यापारी से डिस्कस नहीं किया । गज़ट हो जाने के बाद व्यापारियों को हम मिले । मुझे खुशी होती है कि यह पहली गवर्नमेंट है जिसने 99 फीसदी मांगें उनकी पूरी कर दी हैं। यह तवक्कुह किसी को नहीं करनी चाहिए कि कोई गवर्नमेंट जो जनता से वोट लेकर आती है वह कोई ऐसी बात करेगी जिससे जनता नाराज हो जाए । मैं हाउस को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि यह कुछ कानूनी उलझनें थीं जिनको दूर करने के लिये यह बिल लाना पड़ा है । जहां तक confiscation की बात है उसे उड़ाने के लिये वज़ीर खज़ाना मान चुके हैं । मैं अब हाउस से अपील करूँगा कि काफी दिनों से इस बिल पर बहस करते आ रहे हैं और थोड़ी सी बात थी जिसे अफसाना कर दिया है इसे अब जल्दी वापस किया जाए क्योंकि हम सब थके हुए हैं ।

Deputy Speaker : All the following amendments given notice of by Shri Ram Saran Chand Mital, to Clause 12 will be deemed to have been read and moved :—

> In the second proviso of the proposed section 14-B(8), line 1, between "that" and "the" *insert* "when the omission is found to be *mala fide* or dishonest".

In the second proviso of the proposed section 14-B(8), line 5, *delete* "one thousand rupees or".

In the second proviso of the proposed section 14-B(8), line 6, *delete* "whichever is greater".

श्री रामसरन चन्द मित्तल (नारनौल): डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस वक्त हाउस के सामने कलाज़ 12 है और जैसा कि अभी डाक्टर साहिब ने भी प्वायंट आउट किया कि यह किसी दुकान से या किताबों से सम्बंध नहीं रखती बल्कि जो माल बाहर के सूबों से आए उस के बारे में चैक पोस्टस वगैरा होंगी उनके बारे में यह क्लाज़ है। इस सम्बंध में मेरी अमैंडमेंट यह है कि मैं प्रोपोज़ड सैक्शन 14B(8) को जो पहला प्रोवाइज़ो उसे डीलीट कराना चाहता हूँ। वह इस तरह से है कि—

"Provided that, before taking any action for confiscation of goods, the officer shall give the person concerned a reasonable opportunity of being heard and allow him to rectify any bonafide omissions in the declaration mentioned in this section."

अगर सरकार ने कंफिसकेट का लफ्ज क्लाज़ में से निकाल दिया है तो बहुत अच्छी बात हुई। सरकार ने ठीक किया है। अगर किसी व्यक्ति से बोनाफाइड मिस्टेक हो जाए तो उसकी दरुस्ती चैकिंग-पोस्ट पर करने की इजाज़त होनी चाहिए क्योंकि यह तो केवल क्लैरीकल मिस्टेक है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने दूसरी जगह से 1 हजार रुपये का माल लाया और उसको रास्ते में चैकिंग-पोस्ट पर चैकिंग करानी पड़ जाती है। वह सारा हिसाब वहां पर शो कर देता है। उसका मन्शा कभी भी टैक्स की इवेज़न करने का नहीं। लेकिन बीजक में 50 रुपये का सामान गलती से शो नहीं हो सका क्योंकि उसने सामान लेकर जल्दी से घर को लौटाना है। अगर वह गलती चैकिंग-पोस्ट पर पता चल जाए कि वाकई यह गलती क्लैरीकल मिस्टेक है तो उसे वह मिस्टेक दुरुस्त करने की इजाज़त दे देनी चाहिए। उससे एक हज़ार रुपये का जुर्माना या दुगना टैक्स वसूल नहीं करना चाहिए। कंफिसकेट का लफ्ज़ निकाल देने से सामान को सीज की प्रोविज़न तो रह गई है। मैं इसके बारे में एमैंडमैंट suggest करता हूं कि वहां पर यह प्रोविज़ो लगा देना चाहिए। वह प्रोविज़ो यह है कि :—

Provided that, before taking any action for seizure of goods, the officer shall give the person concerned a reasonable opportunity of being heard and allow him to rectify any bonafide omissions in the declaration mentioned in this section :

अगर यह गलती वाकई क्लैरीकल मिस्टेक है तो उस व्यक्ति के ऊपर किसी तरह की कोई भी पैनल्टी नहीं लगानी चाहिए। मैं इसके बारे में हाउस में ज्यादा डिटेल्ज़ में क्लीयर कर देना चाहता हूँ। मान लीजिये किसी व्यक्ति ने दिल्ली से 1,000 रुपये का सामान खरीदा है और उसने वह सामान अमृतसर ले जाना है। जहां से वह व्यक्ति सामान खरीदता है वहां से जल्दी में बीचक तैयार करके अमृतसर को चल देता है। रास्ते में उसके माल की चैकिंग बैरियर पर हो जाती है। वहां पर चैकिंग करते समय पता चलता है कि उसका 50 रुपये का सामान क्लैरीकल मिस्टेक की वजह से

[श्री रामसरन चन्द मित्तल]

बीचक में दर्ज नहीं हुआ । वह गलती चैकिंग-पोस्ट पर ठीक हो जानी चाहिए क्योंकि उसका मंशा तो टैक्स की चोरी करने की नहीं । अगर यह बात साबित हो जाए कि उसकी मंशा टैक्स की इवेज़न करने की नहीं तो उसे एक हज़ार रुपये या डब्ल टैक्स की पैनिल्टी नहीं लगनी चाहिए । इसके लिये मैंने एमेंडमेंट दे रखी है । वह यह है कि —

In the second proviso of the proposed section 14-B (8), line 1, *between* "that" and "the" *insert* "when the omission is found to be *mala fied* or dishonest."

With this amendment the proviso will read like this—

"Provided further that when the omission is found to be *mala fied* or dishonest the officer acting under sub-section (6) or sub-section (8) may . . . . . . whichever is greater."

मैं पहले से ही इस हक में हूँ कि जहां पर बोनाफाइड मिस्टेक हो वहां पर किसी भी दुकानदार को पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए और उनको किसी तरह की हरास्मेंट नहीं होनी चाहिए । मैंने इसके बारे में अमेंडमेंट दी हुई है । मैं आशा रखता हूँ कि माननीय वित्त मन्त्री जी इनको संजीदगी से विचार करेंगे और इनको स्वीकार कर लेंगे । इसके बारे में मेरी एमेंडमेंट यह है कि —

"Provided that, before taking any action for confiscation of goods, the officer shall give the person concerned a reasonable opportunity of being heard and allow him to rectify and *bona fide* omissions in the declaration mentioned in this section;"

उपाध्यक्षा महोदया, मैं चाहता हूँ कि अगर किसी दुकानदार से कोई ओमिशन गलती से हो गई हो तो उसे चैकिंग-पोस्ट पर दरुस्त करने की इजाज़त होनी चाहिए । उसको किसी तरह की पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए । उसको किसी तरह से परेशान नहीं करना चाहिए । हां अगर किसी दुकानदार ने जानबूझ कर टैक्स की इवेज़न करने की शरारत की हो तो उसको जुर्माना होना चाहिए । उसको डब्ल टेक्स की पनिशमेंट मिलनी चाहिए । मान लीजिये कि किसी दुकानदार ने 10 हज़ार रुपये का माल खरीदा है और उस बीजक में एक हज़ार रुपये का सामान शो करता है और नौ हज़ार रुपये के माल की हेराफेरी करके अपनी दुकान पर लाना चाहता है । अगर वह गलती चैकिंग-पोस्ट पर पकड़ी जाए तो उसके बरखलाफ ज़रूर ऐक्शन लेना चाहिए । उससे एक हज़ार रुपये जुर्माना या डब्ल टैक्स रिकवर करने की प्रोविजन होनी चाहिए लेकिन जिस व्यक्ति से जल्दी में गलती हो गई हो तो उसके ऊपर सखती नहीं करनी चाहिये । मैं आशा रखता हूँ कि माननीय मन्त्री जी मेरी बात को समझ गये होंगे और मेरी बात पर ज़रूर गौर करेंगे । आशा है कि इसके बारे में मैंने जो एमेंडमेंटस दी हैं, वह स्वीकार कर लेंगे ।

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ (ਸਿਧਵਾਂ ਬੇਟ—ਐਸ. ਸੀ.) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਮਨਿਸਟਰ ਸਿਆਣੇ ਲਗਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ । ਮਨਿਸਟਰਜ਼ ਪਬਲਿਕ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਗਲਬਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲਾਜ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਕੰਨਫਿਸਕੇਟ ਦੇ ਲਫਜ਼ ਨੂੰ ਡੀਲੀਟ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਉਥੇ ਹੁਣ ਸੀਜ਼ ਦਾ ਲਫਜ਼ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲ ਕਿਨੀ ਦੇਰ ਲਈ ਸੀਜ਼ਡ ਰਹੇਗਾ । ਉਸ ਮਾਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ । ਕੰਫਿਸਕੇਟ ਲਫਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਈਫੈਕਟ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸ ਵਲ ਫਿਨਾਂਸ ਮਨਿਸਟਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਐਮ. ਐਲ. ਏਜ਼. ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੇਰ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਕਲਾਜ਼ 11 ਉਤੇ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਬਿਉਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਛਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਉਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ । ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਉਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੀਪਰੀਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਮਿਲੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਗੱਲ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਟੈਕਸ ਦੀ ਇਵੇਯਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚੈਕ-ਪੋਸਟਾਂ ਸਨ ਉਹ ਹਟਾ ਦਿਤੀਆਂ ਸਨ । ਮੈਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਫਿਰ ਰੀਵਾਈਵ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਵੇਜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਕੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਵੇਗਾ । [* * *]

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੀ ਹੇਰਫੇਰ ਹੈ ? ਇਹ ਡਿਸਆਨੈਸਟ ਲੋਕ ਗੌਰਮਿੰਟ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਉਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦਬਾਉ ਡਾਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਫੰਡਜ਼ ਲੈਣੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਬਿਜ਼ਨੈਸਮੈਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਚੰਦੇ ਲੈਣੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਕ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦੀ......

मुख्य मन्त्री : डिप्टी स्पीकर साहिबा, माननीय सदस्य जिस क्लाज़ पर बोल रहे हैं, उसका यूनियन होम मिनिस्टर साहिब से क्या सम्बन्ध है। इन शब्दों का होम मिनिस्टर साहिब के साथ दूर का भी कोई सम्बन्ध नहीं है। माननीय सदस्य ने लुधयाना के लंच की बाबत कहा है । मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि श्री गुलजारी लाल नन्दा जी

---

*Note.—Expunged as ordered by the Chair.

[मुख्य मंत्री]

भ्रष्टाचार करने वाले आदमियों को कभी भी और किसी शक्ल में बरदाश्त नहीं करते हैं। इसलिये मेरी आपके सामने बड़े अदब से दरखास्त है कि माननीय सदस्य ने जो लफ़ज़ कहे हैं, वह लफ्ज़ प्रोसीडिंग्ज से हज़फ कर दिये जाएं।

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਯੂਨੀਅਨ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਕੋਈ ਲਫਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ.....

उपाध्यक्षा : हां, यूनियन होम मिनिस्टर के बारे में जो शब्द कहे गये हैं वह एक्सपंज कर दिये जाएं। (The words used in connection with the Union Home Minister are expunged.)

श्री सुरेन्द्र नाथ गौतम : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडम। चीफ मिनिस्टर साहिब ने जो प्वायंट रेज़ किया है, उसका आपने कोई जवाब नहीं दिया कि आया वह लफ्ज़ एक्सपंज कर दिये हैं या नहीं। इसके बारे में मैं आपकी रूलिंग चाहता हूँ।

उपाध्यक्षा : आप हमेशा बात को सुनते नहीं और खड़े होकर प्वायंट आफ आर्डर रेज़ कर देते हैं। मैंने वह लफ्ज पहले ही एक्सपंज करवा दिये हैं। (The hon. Member never listens attent tively to the ruling of the Chair and unnessarily raises points of orders. I have already ruled that the words used in connection with the Home Minister are to be expunged.)

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : On a point of order. ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜੋ ਭੀ ਸ਼ਬਦ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਨੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲੌ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Deputy Speaker : I have heard your point of order. I have already ruled that the words regarding the Home Minister will be expunged.

(*Interruption*)

Order, please. The Home Minister is not under discussion.

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਆਨਸਟ ਅੰਡਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਧੂਲ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਲਖਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਦੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹੜਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਵੇਜਨ ਰੋਕਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰੋ। ਸਰਕਾਰ ਵੇਖੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਪਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਨਫਿਸਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਫਜ਼ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਜ਼ ਦਾ ਲਫਜ਼ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਸੈਂਸ ਹੈ ? ਸੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਫਸਰ ਉਸ ਮਾਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਗੁਡਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹ ਕਿਥੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਢੰਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਲਾਇਲਪੁਰੀ : On a point of order, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਇਕ ਕਾਲ-ਅਟੈਨਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ.....

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲ ਕਾਲ-ਅਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਠਾਉਣਾ । ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਭੇਜ ਦਿਉ । (The hon. Member may raise this point tomorrow. Call-Attention Notices would be taken up. tomorrow. He may send that letter to me.)

ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਲਾਇਲਪੁਰੀ : ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਹੈ.....

Deputy Speaker : Please resume your seat.

ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਲਾਇਲਪੁਰੀ : ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ.....

Deputy Speaker : The hon. Member may come to my Chamber and I will listen to his view-point.

ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਲਾਇਲਪੁਰੀ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਿਊਬਵੈਲਜ਼ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਬੰਦਸ਼ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । (There should be some limit to interruptions.)

ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਲਾਇਲਪੁਰੀ : ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕਾਲ-ਅਟੈਨਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨ ਡਿਸ ਅਲਾਉ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ?

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। (I will have to name the hon. Member.)

ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਲਾਇਲਪੁਰੀ : ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲੈਣ ਦਿਉ, ਮੈਂ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗਾ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਕਲ ਕਾਲ-ਅਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ । (The hon. Member may state his point tomorrow at the time when-Call-Attention Notices would be dealt with.)

ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਲਾਇਲਪੁਰੀ : ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੌ ਕਿ ਕਲ ਇਸ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਿਊਬ-ਵੈਲਜ਼ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ......

Deputy Speaker : Order, please order. Will you please take your seat?

श्री कहेह चन्द विज (पानीपत): डिप्टी स्पीकर साहिबा, हमारे फाईनेंस मिनिस्टर साहिब ने बड़े मासूमाना अंदाज से यह कह कर बिल को हाउस में पेश किया था कि यह तो सिर्फ इवैजन को रोकने के लिये अमैंडिंग बिल लाया जा रहा है। क्लाज़ 12 के तहत

[श्री फतेह चन्द विज]

जो नये अख्त्यारात सरकार लेने जा रही है हम ने पिछले सैशन में भी इन के बारे में कहा था कि सरकार ने यह जो चैक लगा रखे ह यह इसने भ्रष्टाचार के अड्डे खोल रखे हैं। इन अड्डों के द्वारा सालाना जो लाखों रुपयों की इवेज़न होती है उसकी ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया था। इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिये सरकार से प्रार्थना की गई थी (*Interruptions*) वित्त मन्त्री महोदय के ध्यान में यह बात लाई गई थी कि ट्रांस्पोर्ट का इन्टर-स्टेट काम शुरू हुआ है। ट्रक्क वाले बम्बई से और मद्रास से माल लाद कर लाते हैं। वह ट्रक्क वाले 1000, 1500 मील का सफर करके पंजाब में दाखल होते वक्त चैक-बैरियर पर पहुंचते हैं तो चैक-बैरियर वाले उनकी बिल्टी आदि देख कर चाहे कोई भी नुक्स न हो, कोई न कोई एतराज सेल्ज़ टैक्स के बारे में कर देते हैं और उनसे कहते हैं कि ट्रक्क को एक तरफ खड़ा कर दो और अपने कागजात अगर माल बम्बई का है तो बम्बई से जा कर ठीक करवाओ और अगर माल मद्रास का लदा हुआ है तो मद्रास से जाकर अपने कागजात दरुस्त करवा के लाओ। पिछले साल यह बात फाईनेंस मिनिस्टर साहिब से अर्ज़ की गई थी। जब वह ट्रक्क खड़ा हो जाता है तो बैरियर वालों के टाउट्स आकर उससे कहते हैं कि या तो मद्रास और बम्बई जाकर अपने कागजात दरुस्त करवा के लाओ और अगर सफर जारी रखना है तो हमारे साथ बात करो। इस तरह उनसे सौ सौ और दो-दो सौ रुपया तलब किया जाता है। अब आप बतायें कि ट्रक्क वाले क्या करें ? अगर कागज़ात दरुस्त करने के लिये मद्रास और बम्बई जाते हैं तो 5, 7 दिन तो ट्रक वहीं पर खड़ा रखना पड़ता है और सौ 50 रुपये जेब से खर्च करने पड़ते हैं। मजबूर होकर सौ रुपया वहीं पर भेंट कर देते हैं। हाउस में फाइनेंस मिनिस्टर साहिब का ध्यान इस तरफ दिलाया गया था कि पहले जो टैक्सेशन कमिश्नर थे जैसे उनको पटियाले लगाया गया उसी वक्त उन्होंने एक बहुत बड़ा प्लान लेकर दिल्ली में कोठी बनानी शुरू कर दी। कहा जाता है कि उस पर 4, 5 लाख रुपया खर्च आया। उनसे कहा गया था कि आप इन्क्वायरी करवाएं। मैं फाइनेंस मिनिस्टर से पूछता हूँ कि इस सिलसिले में उन्होंने क्या कार्रवाही की है ?

आवाज़ें : क्या नाम है उसका ?

श्री फतेह चन्द विज : उसका नाम दिलजीत सिंह है। मैं नाम नहीं लेना चाहता था लेकिन मैम्बरान के मजबूर करने पर लेना पड़ा। मैंने अर्ज़ किया था कि जिस प्रकार पहले ज़माने में राजा महाराजा जिनके हाथ में सत्ता होती थी भेस बदल कर रात को अपनी जनता का हाल मालूम करते थे उसी तरह से फाईनेंस मिनिस्टर साहिब जी हमारे साथ एक दिन दिल्ली चलें और वहां से ट्रक्क में बैठ कर बैरियर पर आएं। वहां आ कर देखें कि ट्रक्क वालों से दो दो सौ रुपया तलब किया जाता है...

उपाध्यक्षा : कल हाउस 9.00 बजे मिलेगा। The House will meat tomorrow at 9.00 a. m.

(The hon. Member Shri Fateh Chand Vij was on his legs when the House adjourned.)

(The Sabha then adjourned till 9 a.m. on Tuesday, the 16th November, 1965.)

1573-P.V.S.—4-2-66—386 Copies—C.. P, and S., Pb,, Patiala.

के बारे मे
अड्डे खोल
मकी और
कार से
ान लाई
र मद्रास
पंजाब
आदि
कर
आन
स

PUNJAB VIDHAN SABHA
DEBATES

16th November, 1965

Vol. II—No. 20

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Tuesday, the 16th November, 1965.

Punjab Vidhan Sabha Secretariat, Chandigarh.

Price Rs: 5.25

ERRATA

to

Punjab Vidhan Sabha Debates, Vol. II, No. 20,

dated the 16th November, 1965.

Read	*For*	*Page*	*Line*
Bill	Bi	title	18
VIDHAN	IDHAN	(20)2	Heading
Elections	Eleetions	(20)2	3
ਮਾਈਨਜ਼ ਲੇ	ਮਾਈਂਜਲੇ ਨੇ	(20)4	15
ਹੂ	ਹੁੰ	(20)4	25
ब्रेडविनर्ज़	बैडविन्नर्ज़	(20)4	26
ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ	ਇਨ-ਰਮੰ ਨ	(20)6	last
मिनिस्टर	मिनिम्टर	(20)7	6
पहुंची	पहूंची	(20)7	15
ਦੱਸਣਗੇ	ਦਸਣਗ	(20)8	7
ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ	ਚੋਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿਘ	(20)10	14
बन्द	बंद	(20)11	24
Delete the words 'को मालूम' before the words 'है नैशनल'		(20)11	26
ਹੂੰ	ਹੁੰ	(20)14 (20)15 (20)17	2 6th from below 24
Members	Member	(20)14	19
विघ्न	विघ्त	(20)15	14
नैशनल	नेशन्ल	(20)16	5th from below
ਹੈ ਕਿ	ਹੈ । ਕਿ	(20)17	11
इकट्ठा	इकठा	(20)17	last but one
तो	ता	(20)18	6

Read	*For*	*Page*	*Line*
तमगे	तमग	(20)18	9th from below
the	th	(20)20	3rd from below
म्युनिसिपैलिटी	मन्यूनसपैलिटी	(20)21	13
होल्ड है गवर्नमेंन्ट	होलड है गवरमैंट	(20)21	14
मुआवज़ा	मावज़ा	(20)21	6th from below
Statement	5tatement	(20)23	1
Chief Minister	Chlef Minister	(20)26	1
needs	nee s	(20)36	4th from below
करना	कर	(20)38	6
मैडम	कडम	(20)39	9th from below
make	give	(20)39	5th from below
fact	faet	(20)47	21
Distributary	Distributory	(20)47 (20)50	29 23
ਮੱਘੋ	ਮੱਘੋ	(20)49	11th from below
personnel	personncl	(20)52	7th from below
persons	persens	(20)53	5
ever	eve	(20)55	9th from below
ਮੰਤਰੀ	ਮੰਤੀ	(20)66	15
ਭੌਰਾ	ਭਰਾ	(20)92	14
Madam	adam	(20)93	7
outside	outslde	(20)95	4th from below
ਮੈਂ	ਮਂ	(20)96	11
ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ	ਡਿਕਟੇਰਸਿੰਪ	(20)97	9
ਰਖਦਾ ਹੈ	ਰਖਦਾ	(20)98	16

PUNJAB VIDHAN SABHA

Tuesday, the 16th November, 1965

The Vidhan Sabha met in the Assembly Chamber, Vidhan Bhawan, Sector 1, Chandigarh at 9.00 a. m. of the Clock. Deputy Speaker (Shrimati Shanno Devi) in the Chair.

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

CIVILIANS KILLED AS A RESULT OF PAK BOMBING IN THE STATE

*8613. **Shri Balramji Dass Tandon** : Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) the total number of civilians killed in the State as a result of Pak Bombing and the names of the places bombed ;

(b) the details of the facilities or assistance provided by Government to the relatives of those killed by the said bombing ;

(c) whether any cash awards have also been given to the survivers/relatives of the deceased, by the Punjab Government, if so, the date of giving the award and the date in each case on which the person whose survivers/relatives have been given such award was killed ?

Sardar Gurdial Singh Dhillon : (Transport, Elections and Relief and Resettlement Minister) :

(a) A statement showing the total number of civilians killed and the names of places bombed is enclosed.

(b) & (c) Government have decided to give an ex-gratia grant of Rs. 1500 to each family whose bread-winner has been killed.

(ii) provide free education to the orphaned children up to Higher Secondary, and

(iii) arrange admission of orphaned children in Swaraj Bhawan, Allahabad and widows to the Gandhi Vinita Ashram, Jullundur and other similar institutions. All fees in this behalf will be paid by the Government.

An amount of Rs. 2,00,150 on account of ex-gratia grant has already been distributed to the next of kin of the bread winners killed and the injured upto 12th November, 1965. The details of the dates and the places at which the grants were distributed are being collected.

ANNEXURE 'A'

STATEMENT

(Transport and Eleetions Minister)

Places Bombed				No. of Civilian Killed
District	Tehsil	Village/Town/City		
Sangrur	Malerkotla	Kup	—	—
	Barnala	Jaladiwal	—	—
	,,	Behmania	—	—
Kangra	Kangra	Tikka Upper	—	1
	,,	Barol Dakhli	—	—
	,,	Ghaniara	—	—
	Nurpur	Lakhanpur	—	—
	,,	Ghandwal	—	—
Gurdaspur	Gurdaspur	Gurdaspur	—	1
	,,	Batala, Pathankot, Dadwan. Sunger, Dhariwal, Manepur, Babri Nangal. Lole Nangal, Kangas, Bidipur, Satkola, Bulewal, Nangal Behmanian, Kaler Khurd, Bazurgwal, Kotli Sainian, Hardowal, Fatehgarh Churian, Killa Tek Singh, Sheikhpur, Rikhia, Dera Baba Nanak, Kotli Mughlan		Nil.
Hoshiarpur	Dasuha	Sandhwal (Murala)		1
	Hoshiarpur	Khanaura		—
		Hussainpur Sahri		—
		Khanur		1
		Dhamian		—
	Una	Saloh		—
Kapurthala		Hamira Bridge		—
		Rampur Sunran		—
Patiala	Nabha	Dhanaura		—
Ambala	Ambala	Ambala City (Model Town) Ambala Cantt.		6
Jullundur		Thala, Lakhpur, Langeri, Godaipur, Dhandore. Jolowal, Kingra Cho Wala, Kandola, Kalera, Jullundur Had Bast—307.		3
Ludhiana		Baraich, Shahpur, Kadon, Jaipur, Rajgarh, Dhandran, Alamgir, Gobindgarh, Jandiali, Burj Laton, Jogiana, Sarabha.		11

Places bombed			No. of Civilian killed
District	Tehsil	Village/Town/City	
Ferozepore		Ferozepore City	38
		Ferozepore Cantt.	—
		Zira	—
	Moga	Baude	
		Ransinh	
		Malout	
Amritsar	Amritsar	Chak Mukand	1
		Ghaunpur	—
		Pandori. Warah	2
		Sultan Wind	—
		Amritsar City	1
		Kathanian	3
		Rakh Shikargah	2
		Mahal	2
		Gumtala	—
		Chhehrata	52
	Patti	Bhikhiwind	1
		Pahuwind	—
		Viram Narla	—
		Dhun, Khalra, Algon, Wan	—
		Lakhna	17
		Valtoha	20
		Kalsian Khurd	1
		Rajoke	10
		Varnala	5
		Mahmudpura	3
		Doeley	1
	Ajnala	Chhidan	1
		Shakura	2
		Vera	—
	Tarn Taran	Atari	3
		Buri	1
		Nesta	1
		Lauka	1
		Hardo Rattan	1
Hissar	Fatehabad	Bodiwali	—
		Kutabudh	—
		Haripura	—
		Harni	—
		Total	193

श्री बलरामजीदास टंडन : जैसा कि स्टेटमैंट के अन्दर बताया गया है कि बंबिग के कारण जहां तक सिविलियन पापुलेशन का सम्बन्ध है, पंजाब स्टेट के अन्दर 193 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जो उन्होंने अम्बाला जिला के मुताल्लिक बताया है कि वहां पर सिर्फ 6 आदमी माडल टाउन मे मरे हैं, क्या अम्बाला कैंट में किसी आदमी के मर जाने की रिपोर्ट उन को नहीं पहुंची ।

मन्त्री : जो भी स्टेटमैंट मेरे पास पहुंची है उस में अम्बाला सिटी और अम्बाला कैंट इक्टठा ही दिया हुआ है ।

कामरेड मੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ : ਕੀ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦਸਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾਲਤਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 193 ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਹਨ ਕੀ ਇਸ ਵਿਚ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਮਰੇ ਹਨ--ਪੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਮਰੇ ਹਨ ?

ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਬਾਕੀ ਕੈਂਪਸ ਵੀ ਵੇਖੇ ਹਨ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਾਲੀਸੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਅਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਮਾਈਂਜ਼ਲੇ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕੀ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਬਾਰੇ till further orders ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਕਲੈਰੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੀਟ ਕਰੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਐਨੀਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ।

श्री बलरामजीदास टंडन : जैसा कि मनिस्टर साहिब ने पार्ट बी. और सी. के जवाब में बताया है कि जो ब्रैडविन्नर्ज की मृत्यु हुई है उन की फैमिलीज़ को पंद्रह पंद्रह सौ रुपया दिया गया है क्या वह बताने की कृपा करेंगे कि ब्रैडविन्नर्ज के अतिरिक्त जिन दूसरे लोगों ने शहादत प्राप्त की है उन के सम्बन्धियों को भी सरकार की तरफ से कोई सहायता दी गई है ?

मुख्य मन्त्री : आनरेबल मेम्बर ने जो सवाल उठाया है, यह गवर्नमेंट के जेरे गौर है और मैं आशा रखता हुं कि अगले तीन चार रोज़ में यह भी इन्स्ट्रकशंज जारी कर देंगे कि बैडविन्नर्ज के अलावा जिन भाइयों की एयररेड या शेलिंग वगैरा से मृत्यु हुई हो उन के परिवारों की भी मदद की जाए ।

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਕੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਦਰਾਂ ਪੰਦਰਾਂ ਸੌ ਰੁਪਿਆ ਬਰੈਡਵਿਨਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਕੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਲੋਕਲ ਫੰਡਜ਼ ਵਿਚੋਂ ਜਾਂ ਰੈਡਕਰਾਸ ਸੁਸਾਈਟੀ ਦੇ ਫੰਡਜ਼ ਵਿਚੋਂ ਹਾਰਡ ਕੇਸਿਜ਼ ਵਿਚ ਸੌ ਸੌ ਸੌ ਰੁਪਿਆ ਦਿਤਾ ?

मुख्य मन्त्री: जहां जहाँ कोई एसा हार्ड केस था, डिप्टी कमिश्नर को यह हिदायत की गई थी कि वह रैड क्रास या दूसरे फंड्ज में से उन हार्ड केसिज की मदद कर सकते हैं ।

श्री बलरामजीदास टंडन : जैसा कि पार्ट सी. के जवाब में मनिस्टर साहिब ने बताया है कि विडोज और आर्फन्ज के लिए स्वराज्य भवन इलाहाबाद और वनिता आश्रम जालन्धर में इनतजाम किया गया है, क्या वह यह बता सकते हैं कि ऐसे कितने लोग इन आश्रमों में ऐडमिट किए गए हैं ?

परिवहन तथा निर्वाचन मन्त्री: अभी तक तो मुझे इस बारे में कोई इत्तलाह नहीं लेकिन उन की लिस्ट तैयार की जाएगी ज्यूं ज्यूं कोई वहां पर आएंगे । वैसे उन लोगों को कम्पैन्सेशन भी दी गई है और कई सोसाइटीज और फिलन्थराफिस्ट्स ने भी उन की मदद की है । उन के लिए वहां पर जगह रखी हुई है और जो वहां पर आएंगे उन को वहाँ एकामोडेट किया जाएगा । अगर आप चाहेंगे तो जब कोई वहां पर आएंगे तो मैं उन की बाबत इनफरमेशन कुलैक्ट करके आप को बता दूंगा ।

लैफटीनैंट भाग सिंघ : की मनिसटर साहिब इस बारे वी कोई पालीसी दस सकदे हन कि जिहड़ीआं क्रापस शैलिंग नाल खराब हो गईआं हन उन्हां बारे कंपैनसेशन देण दा वी विचार है ?

मंतरी: क्रापस दा तां बारडर डिसटरिकटस विच विदिन 10 माईलज़ काफी नुकसान होइआ है, उथे तां कर ही दिता है । लेकिन बाकी जगाह जिथे करापस डैमेज होईआं ने उथे प्रापर वैरीफीकेशन तों बाअद उन्हां दे आखिआने और लैंड रैवीनिऊ दी रिमीशन कीती जावेगी ।

बाबू अजीत कुमार : की मनिसटर साहिब दॱसणगे कि जिथे जिथे हैवी बंबिंग होण करके फसल तबाह हो गई है और उस दे नाल खेतां विच गड्डे पै गए हन जिन्हां नूं जमींदार आपणे आप ठीक करन दे काबल नहीं, उन्हा बारे वी कोई प्रबंध सरकार वलों कीते गए हन ?

मुख्य मन्त्री : जहां भी फसलों की तबाही इस कारण से हुई है वहां वहां गवर्नमेंट उस के लिए सौ फी सदी मुआवजा देगी ।

कामरेड राम चन्द्र: क्या मैं वजीर साहिब से दरियाफत कर सकता हूं कि जिन जमीनों में हैवी बाम्बिग की वजह से गढ़े पड़ गए हैं उन का भी सरकार कोई मुआवजा देना चाहती है या नहीं ?

परिवहन तथा निर्वाचन मन्त्री : गढों की बात भी सुन लो । उस के लिए वैसे जो भी कम्पैनसेशन उस जगह के लिए होती है वह काफी होती है कि उस को ठीक कर लें । लेकिन मैं आप को बताता हूं एक जगह पर मैं गढा देखने के लिए गया । वहां पर जमींदारों ने मजाक में कहा कि पाकिस्तान वाले कितने मूर्ख हैं ... हम ने यहां पर कुवां खोदना था और इस बाम्बिग से उन्होंने खुद ही कुवां खोद दिया और इस तरह से हमारा दस दस हजार रुपया बच गया (विघन) मैं ने उन के मज़ाक के बात की है कि ऐसी स्पिरिट में भी लोगों ने इस बात को लिया है । मेरा मतलब यह है कि लोगों ने इस बात का काफी मजाक भी उडाया है लेकिन हम गढों को भरने वाली बात पर भी सोचेंगें ।

श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री : क्या वजीर साहिब बताएंगे कि उन के नोटिस मे यह बात भी आई है कि पाकिस्तानी इधर से कुछ सिविलियन लोगों का भी अगवा कर ले गए हैं । ऐसी हालत में क्या उन की फैमिलीज के गुजारे के लिए उन की सहायता के लिए मदद देने की बाबत भी सरकार ने सोचा है ?

मुख्य मन्त्री : गवर्नमेंट के नोटिस में ऐसा कोई केस नहीं है कि पाकिस्तानियों ने यहां से किसी सिविलियन को अगवा किया हो । एक दो जगहों पर ऐसी अफवाहें चली थीं लेकिन बाद में उन की तरदीक नहीं हो सकी । अगर आनरेबल मेम्बर साहिब के नोटिस में कोई ऐसा वाक्या हो तो वह उसकी सूचना मुझे दें ।

बाकी जहां तक ऐसे गांव का सम्बन्ध है जिन पर पाकिस्तान ने नाजायज तौर पर कब्जा किया हुआ है, वहां पर जितने सिविलियन थे उन की बाबत गवर्नमेंट आफ इंडिया को इतलाह दी गई है । उन की बाबत सारी पूछताछ हो रही है । जहां तक उन की फैमिलीज का ताल्लुक है, उन की मदद करना सरकार का फर्ज है और डिप्टी कमिश्नर्ज को यह हिदायात है कि अपनी अपनी जगह वह उन की मदद करें और वह कर रहे हैं ।

बाबू बचन सिंह: पिछले दिनों मनिस्टर साहिब ने एक स्टेटमेंट दी थी जिसमें बताया था कि 357 सिविलियन्ज का नुकसान हुआ है लेकिन आज जो स्टेटमेंट यहां पर रखी गई है उसमें यह तादाद 193 बताई गई है । क्या मैं मनिस्टर साहिब से यह दरियाफत कर सकता हूं कि वह 357 मौतों वाला ब्यान दुरुस्त था या 193 वाला दुरुस्त है ?

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੰਤਰੀ : ਦੋਨੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਰੁਸਤ ਹਨ । ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਫਿਗਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਪਰਸਨਲ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਲੀਸੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਐਕਸਕਲੂਡ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ ਔਰ ਦੋਬਾਰਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕੁਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।

बाबू बचन सिंह : क्या वजीर साहिब बताएंगे कि जिन पुलिस के आदमियों का जानी नुकसान हुआ है उन का एग्जैक्ट कितना नम्बर है ?

मन्त्री : यह मैं नहीं बताना चाहता कि कितने हमारी पुलिस के आदमी इस लड़ाई में काम आए हैं और न ही इस बारे में इस वक्त मेरे पास इनफर्मेशन ही है।

बाबू बचन सिंह : क्या मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि जब उन के पास यह इनफर्मेशन है ही नहीं कि पुलिस के कितने आदमी मरे हैं तो उन्हों ने यह कैसे कह दिया है कि हमारे सिविलियनज जो इस लड़ाई में मारे गए हैं उन की गिनती 193 है और 357 नहीं है जैसा कि पहले बताया गया था क्योंकि उस नम्बर में से जो पुलिस के आदमी मरे थे की गिनती निकाल दी गई है तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब उन को इस बात का भी पता नहीं कि पुलिस के हमारे कितने आदमी मरे हैं तो यह 193 की फिगर कैसे ठीक हो सकती है ।

मंत्री : जो सिविलियनज के बारे में इनफर्मेशन दी गई है वह ठीक है और पुलिस वालों के बारे में बताना ठीक नहीं है ।

मुख्य मन्त्री : पुलिस वालों के बारे में जो इतलाह इस वक्त तक पहूंची है उस के मुताबिक 90 आदमी पी. ए. पी. के ऐसे हैं जो मरे हैं और इस के अलावा 50 या 55 आदमी ऐसे हैं जो मिसिंग हैं जिन के मुतलिक जांच पड़ताल हो रही है ।

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੁਲਸ ਦੇ 90 ਆਦਮੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 193 ਸਿਵੀਲਿਅਨਜ਼ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਲ 357 ਆਦਮੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਗਲ ਤੇ ਇਨਸਿਸਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਜਵਾਬ ਠੀਕ ਹਨ ।

मुख्य मन्त्री : इस बारे में आप को गल्ती लग रही है । उस वक्त तक जो इतलाह थी उस के मुताबिक 157 आदमी मरे थे, 357 तो किसी ने नहीं बताए ।

REHABILITATION OF PERSONS EVACUATED FROM VILLAGES UNDER PAK MILITARY OCCUPATION.

***8614. Shri Balramji Dass Tandon :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total number and names of villages under the occupation of the Pak Military at present, districtwise,

(b) the details of the steps the Government is taking to rehabilitate those evacuated from the said villages,

(c) whether the Government has taken any decision to compensate the inhabitants of the above mentioned villages, if so, the details of such decision ?

Sardar Gurdial Singh Dhillon (Transport, Elections and Relief and Resettlement Minister) :

(a) It is not in the public interest to disclose this information.

(b) & (c) The questions regarding the rehabilitation and the grant of compensation are being finalized in consultation with the Government of India.

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ: ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਸਾਡੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਉਜੜ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ।

ਮੰਤਰੀ: ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਆਏ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਾਲੀਸੀ ਬਣਾਉਨ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਗੌਰਮਿੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਮੈਂ ਉਥੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਰੇਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਗਰ ਹਾਲੇ ਇਹ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫਾਈਨਲ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਾਇਰ ਪਾਲੀਸੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਡੀਫੈਂਸ ਦਾ ਵੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ।

श्री बलरामजी दास टंडन : सवाल के पार्ट बी और पार्ट सी का जवाब देते हुए मिनिस्टर साहिब ने बताया है कि जो लोग पाकिस्तान के हमला से उजड़े हैं उन को रीहैबीलीटेट करने के सवाल पर गवर्नमेंट आफ इण्डिया की तरफ से गौर हो रहा है और अभी फाइनेलाईज़ नहीं हुआ तो मैं पूछना चाहता हूं कि इस के फानेलाईज़ होने में अभी और कितनी देर लगेगी जब कि पहले भी दो महीने लग चुके हैं ।

मंत्री : मैं ने अपना वियू प्वायंट उन के सामने रखा है लेकिन इस बारे में कुछ नही कह सकता कि इस मे कितनी देर और लगेगी । जब तक वह लोग हमारे कैम्पों में है उन को फीड करने की ज़िम्मेवारी हम पर है और जहां तक उन को कम्पेंनसेशन देने का सवाल है इस बारे में कुछ नहीं कह सकता कि इस के फसला होने में अभी कितनी देर और लगेगी ।

ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਲੇਜਿਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਕੂਪਾਈ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸਾਣ ਵਿਚ ਕੀ ਅੜਚਨ ਹੈ ।

मुख्य मंत्री : इस बारे में, डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आप की विसातत से हाऊस से यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि जहां तक उन इलाकों का ताल्लुक है जो पाकिस्तान के हमारे कब्ज़ा में आए हुए हैं और जो हमारे इलाके उस के कबज़ा में चले गए हैं सिक्योरेटी कौनसल के उस रेज़ौल्यूशन के मुताबिक जिस में सीज़

फ़ायर का ताल्लुक है और विदडराअल आफ फोरसिज़ का ताल्लुक है वह सारा इस बात पर मुनहसिर है कि पाकिस्तान उस रैज़ोल्यूशन पर कहां तक अमल करता है। इस लिए जो भाई उन इलाकों से यहां उजड़ कर आए हैं उन को बसाने का सवाल पाकिस्तान के रवैया पर निर्भर करता है कि आया वह अपने गांवों में वापिस जा सकेंगे या उन ज़मीनों पर बसाए जाएंगे जो पाकिस्तान की हमारे कब्ज़ा में आई हैं। जिस तरह से पाकिस्तान ने किया उसी तरह से हमें भी करना पड़ेगा। अगर तो पाकिस्तान रेज़ोल्यूशन पर अमल नहीं करता तो कुदरती तौर पर हमें भी उस के मुताबिक कदम उठाने पड़ेंगे। वैसे यह सारा मामला गवर्नमेंट आफ इंण्डिया से सम्बन्ध रखता है। इस बारे में जम्मू व काशमीर, राजस्थान और पंजाब के अफसरान की और होम मिनिस्टर आफ गवर्नमेंट आफ इण्डिया और मिनिस्टर आफ रिहैबिलीटेशन और हमारी इस बारे में बात चीत हुई है और इस मामले पर पूरी तरह से गौर किया गया है। यह सारा सवाल इस बात के साथ ताल्लुक रखता है कि किस तरह से पाकिस्तान सिक्योरेटी कौंसिल के रेज़ोलयूशन पर अमलदरामद करता है। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि यह सारे राष्ट्र का सवाल है। इस बारे में जहां तक पंजाब गवर्नमेंट का ताल्लुक है मैं यह बता देना चाहता हूं कि यह अपनी जिम्मेवारी समझती है कि जो लोग इस लड़ाई की वजह से डिस्लोकेट हो कर आए हैं उन को दौबारा बसाना हमारा फर्ज़ है।

श्री बलरामजी दास टंडन : क्या यातायात मंत्री या मुख्य मंत्री जी बताएंगे कि जो लोग अपनी जमीनें छोड़ कर आए हैं या जो लोग अपने मकान और दुकानें और उन के अन्दर अपना सामान छोड़ कर आए हैं उन को जनरल तौर पर उन के द्वारा छोड़ी गई प्रापर्टी के इवज में कुछ कम्पेनसेशन देनें के लिए क्या कोई फामूला बना लिया गया है?

मुख्य मन्त्री: गवर्नमेंट आफ इंडिया इन भाइयों को मुनासिब कम्पेनसेशन देने के सवाल पर अभी गौर कर रही है।

Deputy Speaker : Next question please.

चौधरी दर्शन सिंह : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडम। आज सवालों की तादाद इतनी थोड़ी है कि यह 15 या 20 मिन्टों में ही खतम हो जाएंगे इस लिए आप से दरखास्त है कि आप अभी और सप्लीमेंटरीज़ इस सवाल पर पूछने की इजाज़त दे दें क्योंकि यह बड़ा इम्पार्टेंट सवाल है। रूस से वापस आने पर आप में बड़ी तबदीली आई नज़र आती है।

Deputy Speaker : Will you please take your seat ?

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਮੈਡਮ। ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਣੇ ਇਕ ਗਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਬੜੀ ਤਬਦੀਲੀਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਬੜੀ

[ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ]
ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੀਫ਼ਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੁਨਾਸਿਬ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ ।

उपाध्यक्षा : यह छोटी छोटी बातें हैं इनको छोड़ो (These are small things. Ignore them) (विघ्न) (तालियां)

श्री बलरामजी दास टंडन: हम चेयर के खिलाफ ऐसे लफ़्ज़ नहीं सुन सकते ।

(विघन)

ਚੋਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ : ਰੂਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਡਰੈਸ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ : ਹਾਸਾ ।

Deputy Speaker: Please take your seat.

श्री बलराम जी दास टंडन : यह तो और भी आगे चले गए हैं, यह विदडरा करें यह आप की ही नहीं, हाऊस की तौहीन है या यह लफ़ज़ ऐक्सपंज करा दिये जाएं ।

ਚੋਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ : ਜਨਸੰਘੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ (ਵਿਘਨ) ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁਛੋ..(ਵਿਘਨ) ਜੋ ਰੂਸੀ ਮੈਂਬਰ..(ਵਿਘਨ)

Deputy Speaker : I will have to name you. (Laughter)

डा० बलदेव प्रकाश : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडम । चौधरी दर्शन सिंह जी नें अभी कहा है कि रूसी मैम्बर बैठे हुए हैं । (विघन) क्या इन में से कोई रूस का मैम्बर है या यह पंजाब के मैम्बर हैं ।

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਨ ਜੈਕਟ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲ ਜੈਕਟ ਪਹਿਨਦੇ । (ਹਾਸਾ)

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : On a point of order, Madam ਇਹ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰੂਸੀ ਮੈਂਬਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਦਿਉ । (ਵਿਘਨ)

———

NATIONAL DEFENCE FUND.

***8616. Shri Balramji Dass Tandon :** Will the Chief Minister be pleased to state the total amount so far donated towards the National Defence Fund, districtwise in the state.

Shri Ram Kishan: The information so far collected in respect of ten districts is given in the enclosed statement which is laid on the table of the House. Information in respect of the remaining districts will be supplied later on.

STATEMENT SHOWING TOTAL AMOUNT DONATED TOWARDS NATIONAL DEFENCE FUND DISTRICT-WISE IN THE STATE OF PUNJAB.

1.	Bhatinda	29,83,845.70
2.	Ferozepur	61,57,766.57
3.	Gurgaon	16,95,732.57
4.	Hoshiarpur	18,80,725.88
5.	Jullundur	35,48,886.00
6.	Hissar	58,58,384,05
7.	Kapurthala	10,14,954.98
8.	Ludhiana	44,06,440.98
9.	Mohindergarh	12,19,520.04
10.	Sangrur	46,01,082,00

श्री बलरामजी दास टंडन : यह जो चीफ मिनिस्टर साहिब ने दस ज़िलों के बारे में इस स्टेटमेंट में सूचना दी है कि इतना रुपया इक्टठा हुआ है क्या यह बताएंगे कि क्या यह लास्ट आइटम है और इस के बाद वहां पर कलैक्शन बंद हो गई है या नैशनल डीफैंस फंड के कलैकशन का काम चल रहा है ।

मुख्य मंत्री : जैसा कि आनरेबल मैम्बर को मालूम को मालूम है नैशनल फंड की कलैकशन जारी है । इन जिलों के अलावां जो ज़िले हैं उन से भी इनफरमेशन आई थी मगर इस के अन्दर नैशनल डीफैंस फंड के अलावा पंजाब सीक्युरिटी और रीलीफ फंड की कलैकशन की फिगर्ज़ भी शामिल थीं इस लिये उन को दोबारा वापस ठीक करने के लिये भेजा गया है चूंकि सवाल सिर्फ नैशनल डीफैंस फंड का था । जब वह सूचना आ जायेगी तो इन को दे दी जाएगी ।

सरदार कुलबीर सिंह : क्या मुखय मन्त्री बताएंगे कि क्या यह बात इन के नौटिस में हैं कि इस फंड की वसूली कुछ ज़िलों में अफसरान जबर से कर रहे हैं ।

मुख्य मन्त्री : जहां तक मेरी इतलाह है इस बार कोई जबर नहीं हुआ ।

ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ : ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤ੍ਰੀ ਜੀ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਗਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਜਾਂ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਰਕੁਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਸਟਰਾਂ ਆਦਿ ਤੇ ਫੰਡ ਦੇ ਕੋਟੇ ਲਾ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ?

मुख्य मन्त्री : मेरे नोटिस में ऐसी कोई बात नहीं है । जहां तक नैशनल डीफैंस फंड का सवाल है अगर यह कोई ऐसी बात मेरे नोटिस में लाएंगे तो देखूंगा ।

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤ੍ਰੀ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੀਫੈਂਸ ਫੰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੀਕਿਉਰਿਟੀ ਐਂਡ ਰੀਲੀਫ ਫੰਡ ਇਕਠੇ ਹੀ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਲਗ ਅਲਗ ?

मुख्य मन्त्री : अलग अलग ।

ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤ੍ਰੀ ਸਾਹਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਫੰਡ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ੨ ਮਹਿਕਮੇ ਇਕਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।

मुख्य मन्त्री : जैसा कि आनरेबल मैम्बर को मालूम है नैशनल डीफैंस फंड को इक्ट्ठा करने के लिए किसी महकमें का सवाल नहीं है लोग वालैंटरीली दे रहे हैं ।

श्री बलरामजी दास टंडन : यह जो स्टेटमैंट दिया गया है इस में फिरोज़पुर ज़िले से 61 लाख 57 हज़ार, हिसार ज़िले से 58 लाख 58 हज़ार रु०, लुध्याना ज़िले से 44 लाख रु०, संगरूर ज़िले से 46 लाख रु० इक्ट्ठा हुआ बताया गया है मगर बाकी जो ज़िले हैं जिन के नाम इस में हैं उन से किसी से दस लाख किसी से बारह लाख रुपया इक्ट्ठा किया बताया गया है यानी बहुत कम रुपया मिला है । इस फर्क का क्या कारण है ? क्या यह कि वहां के जिले के डिप्टी कमिश्नरों ने इस काम में इन्टरैस्ट नहीं लिया जब कि दूसरों ने लिया यह कुलैक्शन्ज़ में इतना बड़ा फर्क क्यों है ?

मुख्य मन्त्री : इन्टरैस्ट तो सब जगह लिया गया है । बाकी कहीं पर ज़िले की आबादी और इकानौमी पर भी कुलैक्शन का इनहिसार है ।

श्री बलरामजी दास टंडन : गुड़गांव ज़िले में किस चीज़ की कमी है ?

मुख्य मन्त्री : उस की नूह और झिरका जो तहसीलें हैं वह फलड स्ट्रिकन हैं इस को नज़रअन्दाज़ न करें ।

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਕੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਬ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਡੀ. ਸੀ. ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਥੇ ਐਸ. ਡੀ. ਓ. ਦੇ ਸਿਵਾਏ ਫੰਡ ਇਕਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ

ਦੇ ਬਚੇ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਕੀ ਇਹ ਉਸ ਡੀ. ਸੀ. ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ ।

मुख्य मन्त्री : डिप्टी कमिश्नर ने जो बयान दिया है वह पंजाब सरकार की पालिसी के मुताबिक दिया है हम चाहते हैं इस का जायज़ इस्तेमाल ही हो । लेकिन जहां तक ऐजुकेशन डिपार्टमैंट का ताल्लुक है उन्होंने अलग मेरे साथ इस बारे में बात की थी और उन्होंने सैपरेट फंड इकट्ठा करके गवर्नमैंट को दिया है । अगर आप के नोटिस में कोई ऐसा वाका आया है कि किसी जगह पर उन्होंने अपने इख्तयारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया है तो आप बताएं हम कार्यवाही करने के लिए तैयार हैं ।

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਬਸਾਂ ਵਿਚ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਆਮ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚੇ ਅਤੇ ਟੀਚਰਜ਼ 4, 4 ਅਤੇ 8, 8 ਆਨੇ ਇਕਠੇ ਕਰਦੇ ਵੇਖੇ ਹਨ । ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰਖੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਮਪਨਸੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।

शिक्षा मन्त्री : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं ने चीफ मिनिस्टर साहिब से खाहिश जाहिर की थी कि कालिजों और स्कूलों के तालिबेइल्म भी और टीचर्ज़ भी इस में हिस्सा डालना चाहते हैं तो उस के लिये यह जिम्मा लिया गया कि जो प्राइमरी स्कूलों के टीचर हैं वह 20 आदमियों से मिलें और उन से हर एक से आठ आठ आने फंड के लिये लें यानी प्राइमरी स्कूलों के टीचर्ज़ ने दस रुपये इकट्ठे करने थे और हाई या हायर सैकन्डरी स्कूलों के टीचर्ज़ ने 20 रुपये इकट्ठे करने का उन का जिम्मां लगाया गया था । इस बारे में मैं अर्ज़ करूं कि मैं जहां पर भी जाता हूं वहां पर पर्स लेने से पहले वहां पर जो हाउस के मैम्बर मौजूद हों तो उन से पूछता रहा हूं कि क्या कोई नाजायज़ बात उन के नोटिस में आई है जिस में कोई गलत बात की गई हो । कल परसों ही मैं लुध्याने गया था तो मैं ने बाबू जी से कहा था कि अगर कोई ऐसी बात उन के नोटिस में हो तो वह मुझे बता दें ताकि इस बारे में जरूरी ऐक्शन लिया जा सके । पटियाले गया तो सरदार जसदेव सिंघ संधू से यही बात पूछी थी । इसी तरह करनाल में भी पर्स लेने से पहले वहां पर जो मैम्बर थे चाहे कांग्रेस के हों या आपोज़ीशन के उन से पूछ कर मैं ने कोशिश की कि इस बात का यकीन कर लूं कि इस में कोई नाजायज़ बात नहीं हुई ।

दूसरी बात इस बारे में मैं ने यह कही कि मैं ने चीफ मिनिस्टर और चीफ सैक्रेटरी को यह लिखा है कि जहां तक तालिबेइल्मों द्वारा इकट्ठे किये फंड का ताल्लुक है इस का हिसाब मैं चाहुंगा कि मेरे महकमे के आडिटर न आडिट करें बल्कि सरकार की तरफ से इस काम पर लगाए गए अलग आडिटर आडिट करें। अगर

[शिक्षा मन्त्री]

उस में कोई बेईमानी हुई हो तो उस का जिम्मा मैं लेता हुं। ऐसी सूरत में मैं वज़ारत से अस्तीफा दे दूंगा। (तालियां)

मगर मैं इतना जरूर कहुंगा कि बच्चों ने 40 लाख रुपया इक्ट्ठा किया है। मैं आगे भी कह चुका हूं कि यह वह रिसोरसिज़ हैं जो टैप नहीं होने थे क्योंकि बड़े बड़े आदमियों ने चंदा देना था इन्डस्ट्रीयलिस्टों ने देना था और चार चार या आठ आठ आने लेने किसी ने नहीं पहुंचना था। हो सकता है कि कहीं ओवर अन्थयूज़िअज़म में कोई किसी के पास चला गया हो लेकिन यह हदायत जारी कर दी गई थी कि बच्चों की पढ़ाई में किसी किस्म का फर्क नहीं पड़ना चाहिए और अगर दिन में कहीं पर आध घंटा इस काम में लग गया तो शाम को आधा घंटा वकत ज्यादा पढ़ाई में लगा दिया गया था।

Deputy Speaker: Next question please.

(*At this stage a number of hon. Members rose to ask supplementaries.*)

Deputy Speaker: There should be some limit for asking the supplementaries. Enough supplementaries have already been put.

(*A number of hon. Members rose on a point of order.*)

Deputy Speaker: Order Please. The hon. Member should resume their seats. There should be decorum in the House.

Shri Balramji Das Tandon: On a point of Order, Madam.

ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਸਾਨੂੰ ਇਕ ਦੋ ਗਲਾਂ ਹੋਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁਛਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ: ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਮੈਡਮ। ਜਿਹੜਾ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਵਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੁਛਿਆ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੰਦਾ ਇਕਠਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਵਕਤ ਹਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਫੀ ਮਾਸਟਰ ਲਈ ਦਸ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਲਈ ਵੀਹ ਰੁਪਏ ਚੰਦਾ ਇਕਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਨੀ ਰਕਮ ਇਕਠੀ ਕਰ ਕੇ ਦੇਵੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆਣ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।

(ਵਿਘਨ)

शिक्षा मन्त्री : वैसे तो ग्राप का ही हुक्म यहां पर चलेगा इस हाऊस में लेकिन मैं निहायत ग्रदब के साथ ग्रर्ज़ करूंगा कि इस सवाल पर ग्रपोज़ीशन वालों को ग्रौर दूसरे मैम्बर साहिबान को ग्रौर ज्यादा स्पलीमेंटरी करने की इजाज़त होनी चाहिए ताकि गवर्नमेन्ट की पोजीशन कलीयर हो सके ग्रौर सरकार के बारे में किसी को भी इस सिलसिले में किसी किस्म का शक ग्रौर शुबा बाकी न रहे कि सरकार की नियत चंदा इकटठा करने में ठीक न थी।

ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਮੈਡਮ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਤਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਠ ਵੇਰ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਟੈਪ ਮਦਰਲੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਦਰਲੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

उपाध्यक्षा : ग्रगर ग्राप इस तरह से मिसबीहेव करेंगे तो मुझे कोई ग्रौर एकशन लेना पड़ेगा। (विघ्न) (शोर) (If the hon. Member continues misbehaving I will have to take some other action.) (interruptions) (noise)

परिवहन तथा निर्वाचन मन्त्री : मैं ने तो सिरफ इतना ही कहना था कि चौधरी दरशन सिंह ने गलत लफज़ का इस्तेमाल किया है इन्हें स्टेप मदरली नहीं स्टेप डिप्टी स्पीकरली कहना चाहिए था।

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਮੈਡਮ। ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰੀਮਾਰਕਸ ਕਸੇ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਰਮੀ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਵੇਰ ਕਸੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਰਮੀ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦਾ ਡੈਕੋਰਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। (ਵਿਘਨ)

ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ : ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢੋ ਜੀ।

श्री बलरामजीदास टंडन : चीफ मिनिस्टर साहिब ने नेशनल डिफैंस फंड के बारे में बताया है इस के इलावा जवान रीलीफ फंड भी है जो पंजाब गवर्नमेन्ट ने इकटठा किया है तो मैं यह जानना चाहता हुं कि पंजाब के ग्रन्दर टोटल कुलैकशन कितनी हुई है ग्रौर नेशन्ल डिफैंस फंड की ग्रप-टू-डेट कुलैकशन के बारे में कब तक मैम्बरान को पता लग जाएगा ?

मुख्य मन्त्री : वैसे तो डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस का तग्रालुक इस सवाल से नहीं है इस के बारे में दूसरा सवाल ग्रा रहा है। पंजाब स्कयूरेटी एन्ड डिफैंस रीलीफ फन्ड से ग्रब तक 2 करोड़ 82 लाख 82 हज़ार 167 रुपया इकटठा हो

[मुख्य मन्त्री]

चुका है । यह रुपया 30-10-65 तक का है । (प्रशंसा) इस के बाद इन दिनों में भी रुपया आया है जहां तक नैशन्ल डीफैंस फंड का तअल्लुक है मैं ने पहले ही वजाहत कर दी है कि 10 ज़िलों से इतलाह आ चुकी है और बाकी के जिलों के डिप्टी कमिशन्रों को टैलीग्राफिकली कहा है कि फिगर्ज़ महय्या करें । पूरी इतलाह आने पर इस हाऊस को और आनरेबल मैम्बरान को मुहयया कर दी जाएगी ।

(*At this stage Chaudhri Darshan Singh rose to put his supplementary question*),

Deputy Speaker : Unless the hon. Member withdraws what he has already said, I will not allow him to put supplementary questions.

Chaudhri Darshan Singh : If, Madam, I have said anything unparliamentary, I withdraw that.

Deputy Speaker : He should please withdraw unconditionally.

Chaudhri Darshan Singh : I withdraw it unconditionally.

Deputy Speaker ; He may now put his supplementary question.

Chaudhri Darshan Singh : Madam, may I know from the hon. Chief Minister whether the Government has fixed district-wise targets for the collection of National Defence Fund ?

Chief Minister : No, Madam.

डा० बलदेव प्रकाश : क्या मुख्य मन्त्री महोदय बताएंगे कि जो इन्होंने पहले फिगर्ज़ दीए हैं कि नैशन्ल डिफैंस फंड में 3 करोड़ 33 लाख 10 हज़ार की रकम इकटठी हो गई है तो क्या यह उस वकत से है जब कि चीन की तरफ से हमला किया गया या उस वकत से है जब कि पाकिस्तान की तरफ से हमला किया गया और कच्छ में हमला हुआ और अब तक का टोटल क्या है ?

मुख्य मन्त्री : यह तो आनरेबल मैम्बर को मालूम है कि जहां तक नेशन्ल डिफैंस फंड का तअल्लुक है चाइनीज़ अग्रेशन के वक्त से शुरू किया गया था इस के बारें में जो अप टू डेट इतलाह मेरे पास है इस के मुताबिक इस वकत तक 5 करोड़ 84 लाख 22 हज़ार 986 रुपया इकट्ठा हो चुका है । (प्रशंसा)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਦੇ ਇਹ ਗਲ ਇਲਮ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ ਵਧ ਅਮਾਊਂਟ ਦਿਖਾਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੋਸਟ ਅਨਡੀਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਸਲੇ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇ ਕੇ ਰੁਪਿਆ ਇਕਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੀ ਹੈ । ਇਹ ਗਲ ਉਥੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਨਡੀਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਹੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ।

मुख्य मन्त्री : जहां तक फिरोज़पुर जिला का तग्रालुक है उस का डिप्टी कमिश्नर निहायत इमानदार और एबल है और कोई ऐसी बात उस की तरफ से नहीं की गई ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਇਹ ਗਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਮੁਖਬਰੀ ਲਈ ਤਲਬ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਵਿਦਆਉਟ ਲਾਇਸੰਸ ਅਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗਲ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ । ਕਿ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਚੰਦਾ ਇਕਠਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ?

मुख्य मन्त्री : नजाइज़ असले के बारे में हमारा ध्यान वहां के डिप्टी कमिशनर साहिब ने दिलाया है और होम मिनिस्टर साहिब का भी ध्यान दिलाया है । और इस डी० सी० ने तो खुद कई जगहों पर कारवाई की है कि नाजाइज़ असले के लाइसंसों को रोका जाए । और वहां का डी० सी० अज़हद पापूलर है । ऐसी कोई चीज़ उस के खिलाफ नहीं है। (प्रसंसा)

श्री जगन्नाथ : क्या चीफ मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि ज़िला हिसार के अन्दर सब से ज्यादा कुलैक्शन हुई तो क्या लोगों ने वहां पर विलिंगली रकम दी है या इस हदायत पर रुपया इक्ट्ठा हुआ है शेश जोकि गवर्नमेन्ट ने जारी की थी कि जमीन पर से 2 रुपये किल्ले पर और 5 किल्ले की जमीन वाले से 10 रुपए वसूल किए जाएं ।

मुख्य मन्त्री : इस सवाल से इस का कोई तग्रालुक तो नहीं लेकिन इस हाउस के मैम्बरान की इतलाह के लिए कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने भी इस फंड के लिए पैसा दिया है वह सारे का सारा वालंटरी तौर पर दिया है । (प्रसंसा)

ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਗੁੜਗਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਫਸਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਨਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਫੈਂਸ ਫੰਡ ਮੰਗਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤਰਾਂ ਬਾਂਹਿੰਡੇ ਤੋਂ ਤਾਰਾਂ ਪੁਜੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਜਬਰੀ, ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਨਾਲ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਮੁਨਾਸਿਬ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ।

मुख्य मन्त्री : हम नें किसी जगह पर भी किसी सिवल सप्लाई आफीसर को फंडज़ इकठा करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया अगर आनरेबल मैंबर के पास कोई इनफरमेशन हो तो मुझे भेज दें, मैं वहां की इनकवायरी करूंगा ।

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੇਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਆਤ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ ਕੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕੇਸਿਜ਼ ਲਿਆਈਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਨਾ-ਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਢਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇਗੀ ।

मुख्य मंत्री : मैं ता कई दफा इस बात की वज़ाहत कर चुका हूं कि अगर कोई मैंबर किसी डी० सी० के खिलाफ खाह मखाह लठ लिये फिरे सिवाये इसके कि मैं उनके रवइये को कंडैम करूं मैं और कुछ कर ही नहीं सकता । डी० सी० इतने इमानदार हैं कि सब सूझ बूझ वाले हैं, मगर फिर भी किसी को जबरी चंदा इकट्ठा करने की शिकायत हो वह हमारे नोटिस में लायें मैं उसकी इन्क्वायरी करवाने को तैयार हूं ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਚੀਫ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿਚ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਸਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ ਬਰਾਮਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ, ਪੈਸਾ ਦੇਕੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਤਕ ਬਣਾ ਲਿਆ । ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਚੰਗਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਈਏ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ?

श्री जगन्नाथ : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडम। अगर हम साबत कर दें......

उपाध्यक्षा : आप तीन दफा कह चुके हैं और चीफ मिनिस्टर ने भी यह जवाब दिया है कि अगर आप कोई ऐसा केस हमारे नोटिस में लायेंगे तो इस के खिलाफ हम जरूर ऐक्शन लेंगे । (This question has been asked thrice and the Chief Minister has replied that if any specific case is brought to his notice, action will definitely be taken against that person.)

श्री जगन्नाथ : मैडम, वह तो ऐकशन लेने की बजाये उनकी तारीफ करने लगे हैं और उन को बड़े बड़े तमग देने लगे हैं, सरटींफीकेट देने लगे हैं ।

मुख्य मंत्री : अभी तक 5,84,00,000 रुपये नैशनल डिफैंस फंड का इकट्ठा हुआ है और 2,08,00,000 रुपए डीफैंस फंड ऐंड सिक्योरिटी आफ पंजाब का इकट्ठा हुआ है । यह फंड्ज जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया वालैंटैरेली पंजाब के लोगों ने दिये हमें इस बात पर खुश होना चाहिये कि उन्होंने बड़ी भारी हिम्मत का सबूत दिया है ।

बाबू बचन सिंह : मैं यह पूछना चाहता हूं कि सितंबर और अकतूबर में जितना भी डिफैंस फंड इकट्ठा किया गया क्या इस अरसा में इतना इकट्ठा करना जरूरी था ?

मुख्य मंत्री : मैंने अर्ज़ किया है कि फंड्ज लगातार आ रहे हैं, गवर्नमैंट आफ इंडिया के नैशनल फंड्ज में भी जा रहे हैं और पंजाब के सैक्योरिटी ऐंड डिफैंस फंड में भी आ रहे हैं।

COLLECTIONS MADE TOWARDS NATIONAL DEFENCE FUND FROM DISTRICT HISSAR

*8760. **Shri Jagan Nath, M.L.A.** : Will the Chief Minister be pleased to state the details of the amounts in cash, gold, silver and clothes collected during September and October, 1965, from district Hissar tehsil-wise, towards the National Defence Fund ?

Subject : Vidhan Sabha Starred Question No. 8760 by Shri Jagan Nath, M. L. A. regarding National Defence Fund collections in District Hissar.

The answer to Assembly Starred Question No. 8760 appearing in the list of questions for the 16th November, 1965 in the name of the Chief Minister, Punjab, is not ready. This intimation is sent to the Speaker who is requested to extend the time limit for answering that question under proviso (2) of the rule 31 (ii) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Vidhan Sabha, 1950. This question may be included in the list of questions on any date after 1st December, 1965.

Sd/- RAM KISHAN,
Chief Minister, Punjab.

15th November, 1965.

To

The Secretary,
Punjab Vidhan Sabha,
Chandigarh.

U. O. NO. 101—A. Q—IEW—65, dated Chandigarh, the 15th November, 1965.

STARRED QUESTION No. 8760 (Postponed)

Deputy Speaker : It is postponed.

श्री जगन्नाथ : आखिर हमारे साथ ऐसा सलूक क्यों किया जा रहा है। इस तरह का एक सवाल जिस के ज़रिए सारे पंजाब को इनफरमेशन कन्सरन करती थी उसका तो जवाब दे दिया गया मगर महिज़ हिसार ज़िले की अगर इनफरमेशन मांगी गई उसका कोई जवाब नहीं दे सके। यह बतायें क्या यह कोई इस तरह की इनफरमेशन देना नहीं चाहते ?

उपाध्यक्षा : मैं तो कामरेड जी से कह दिया है कि आप इसी सैशन में इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करें (I have requested the Chief Minister to try to answer this question during the current Session).

DAMAGE TO LIFE AND PROPERTY DUE TO PAKISTANI AGGRESSION/BOMBING

*8642. **Comrade Shamsher Singh Josh** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total loss of property and life district-wise, in the State on account of the recent Pakistani aggression/bombing ;

(b) whether any compensation has been paid to the civilian population in lieu of the damage caused to their movable or immovable property, if so, the details thereof ;

(c) the details of the compensation paid by the Government to the survivors/relatives of those who died or to those who were injured as a result of the said aggression/ bombing ?

Sardar Gurdial Singh Dhillon (Transport and Elections Minister) : (a) The loss of civilians life (excluding P.A.P. killed and missing) is as below :—

District	*No. of civilian killed*
Amritsar	131
Ferozepore	38
Gurdaspur	1
Kangra	1
Jullundur	3
Hoshiarpur	2
Ludhiana	11
Ambala	6
	193

As for the loss of property the assessement is still being made by the Deputy Commissioners concerned ;

(b) The matter is under consideration of the State Government in consultation with the Government of India.

(c) A sum of Rs. 2,09,150 has been paid as ex-gratia grant to th next of kin of the bread winners killed or to those who were injured.

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਡੈਮੇਜਡ ਪਰਾਪਰਟੀ ਦੀਆਂ ਅਜੇ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਪੈਨਸੇਸ਼ਨ ਪੇ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਊਸਿਜ਼ ਡੈਮੇਜ਼ ਹੋਏ ਹਨ । ਪਰ ਇਹ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੈਨਸੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਵੀ ਜੋ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਇਮਦਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ।

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਛੇਹਰਟੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਕਿਤਨਾ ਫਰਕ ਹੈ । ਇਮੂਵਏਬਲ ਪਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ।

मुख्य मंत्री : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आपके जरिये इस हाउस को इतलाह देना चाहता हूं कि हम ने जितनी जल्दी हो सका वहां लोगों को रिलीफ देने की कोशिश की है । यहां तक कि वहां की मम्यूनसपैलिटी ने जिस पर कमियूनिस्ट पार्टी का होलड है गवरमैंट को मुबारिकबाद का प्रस्ताव भी पास किया कि हम इतनी जल्दी उन की इमदाद कर पाये हैं ।

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੰਬਾਰਡਮੈਂਟ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤਾਈ ਅਪਰੋਚ ਰੋਡਜ਼ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ?

मंत्री : सवाल नहीं पैदा होता।

ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ : ਜੋ ਸਿਵੀਲੀਅਨ ਬੰਬ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਪੈਰਾਟਰੂਪਰਜ਼ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਰਿਲੀਫ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ?

मुख्य मंत्री : 1500 रुपया बंब द्वारा मरने वालों को और 500 रुपया पैराटरुपर्स के साथ हुई मुठ भेड़ में मरने वालों को दिया गया है ।

श्री फतेह चन्द विज : जो ट्रक बार्डर पर या फरंट पर डिस्ट्राय हुए हैं, खास तौर से उस वक्त जब कि वह सेवा कर रहे थे, उनको कितना मावज़ा दिया गया ?

मंत्री : जब आपका सवाल आएगा तो जवाब दिया जाएगा । आपका सवाल आ तो रहा है ।

ਕਾਮਰੇਡ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ : ਕੀ ਗੌਰਮਿੰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਆ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਬੇਟ ਦੇ ਏਰੀਆ ਵਿਚ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

श्री फतेह चंद विज : इस सवाल का जवाब नहीं आया जो मैंने पूछा था ?

मंत्री : इसमें तो सिविल लाइफ का सवाल है, ट्रक्स बारे तो अगला सवाल है, उसमें आपको जवाब मिल जाएगा।

ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਲਾਇਲਪੁਰੀ : ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿਚ ਕਿਤਨੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ ?

मंत्री : 131 ज़िला अमृतसर में। अगर और कोई आपकी नालिज में हो तो लिस्ट में इनक्लूड कर लिया जाएगा।

ਸਰਦਾਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿੰਧੂ : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੰਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਿਆ ਔਰ ਪੈਰਾਟਰੂਪਸ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਿਆ ਇਹ ਕਿਉਂ ਤਮੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕੀ ਉਹ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਮਰੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਰਿਲੀਫ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ?

मुख्य मंत्री : यह सवाल आपका मौजूं है उनको सिर्फ 500 रुपया तो फौरी रिलीफ के तौर पर उनके परिवारों को दिया गया है लेकिन मामला ज़ेरे गौर है, उनके परिवारों को मजीद इम्दाद दी जाएगी।

श्री बलरामजी दास टंडन : ट्रक्स वगैरह जो मूवेबिल प्रापर्टी है, उसके एवज़ में कोई कम्पैनसेशन दिया गया है या अभी तजवीज़ हो रहा है ?

परिवहन तथा निर्वाचन मंत्री : मैं पहले इसके बारे सारे क्राइटेरिया बता चुका हूं लेकिन अगर स्पैसिफिकली कोई सवाल पूछो तो फिर बतला दूंगा।

TOURS UNDERTAKEN BY THE CHIEF MINISTER FROM CHANDIGARH TO DELHI

***8687. Comrade Shamsher Singh Josh :** Will the Chief Minister be pleased to state the total number of tours undertaken by him from Chandigarh to Delhi during the last six months alongwith the purpose of each tour ?

Shri Ram Kishan : The requisite information is laid on the Table of the House.

Statement showing total number of tours undertaken by the Chief Minister, Punjab from Chandigarh to Delhi during the last six months alongwith the purpose of each tour.

Serial No.	Tours undertaken	Purpose
1	2	3
1.	10-4-65 to 12-4-65	Met the Prime Minister, Union Home Minister and discussed the law and order situation—Met various deputations and heard their complaints.
2.	23-4-65 to 26-4-65	Attended National Development Council Committee meeting—Meeting regarding labour dispute at Jagadhri between the workers and employers of Shri Gopal Paper Mills. Met various deputations and local people and heard their complaints.
3.	7-5-65 to 10-5-65	Attended meeting of State Ministers of Information and Broad casting—Meeting of Rajasthan Canal Oustees—National Defence Council meeting—Citizens Central Council Meeting—National Savings Adv. Board.
4.	1-6-65 to 4-6-65	Attended the meeting regarding the Language policy called by P. M.—2-6-65 attended Food Ministers meeting—Met P. M. and H. M.
5.	6-6-65 to 7-6-65	Meeting of Committee of Directions of Rajasthan.
6.	8-6-65 to 9-6-65	Met Prime Minister and Home Minister.
7.	11-6-65 to 12-6-65	Met All India Gujar Conference.
8.	29-6-65	Met Prime Minister and Home Minister.
9.	13-7-65	Discussions with the Planning Commission.
10.	5-8-65 to 9-8-65	Meeting of Chief Ministers regarding Food—Me[t] National Defence Council—Met Prime Minister an[d] Minister.
1.	15-8-65 to 16-8-65	Met Prime Minister and Union Home Minister.
2.	21-8-65 to 23-8-65	-do-
3.	27-8-65 to 28-8-65	-do-
4.	5-9-65 to 7-9-65	Meeting of National Development Coun Minister's Conference with Prime Ministe Minister.
.	25-9-65	Met Prime Minister and Home Minister
	1-10-65 to 2-10-65	Attend meeting of Beas Control Board.

PUNJAB DEFENCE AND SECURITY RELIEF FUND.

*8703. **Comrade Shamsher Singh Josh** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total amount of Punjab Defence and Security Relief Fund collected all over the State by the end of September, 1965 district-wise ;

(b) a statement showing the details regarding the said collections made from the people, the total contribution received from the consolidated funds of the Block Samitis Market Committees and Municipal Committees and the total contribution from various other associations be laid on the Table of the House ?

Shri Ram Kishan : (a) & (b) A statement containing the requisite information is laid on the Table of the House.

Statement showing the details regarding the Punjab Defence and Security Relief Fund collections made from the people, the total contributions received from the consolidated funds of the Block Samitis, Market Committees and Municipal Committees and the total contribution from various other associations.

Serial No.	District	Total amount of Punjab Defence and Security Relief Fund collected by 30th September, 1965	Amount collected from Block Samitis	Amount collected from Market Committees	Amount collected from Municipal Committees	Amount collected from various other associations.	Amount collected from People and Miscellaneous
1	2	3	4	5	6	7	8
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
1.	Amritsar ..	95,975	28,010	—	16,500	6,976	44,489
2.	Ambala ..	3,71,523.69	54,700	20,000	73,000	—	2,23,823.69
3.	Bhatinda ..	1,91,892.73	1,03,576.00	—	25,500	7,309.81	55,506.92
4.	Ferozepore ..	10,05,648.86	2,36,900	3,60,200	3,32,000	—	76,548.86
5.	Gurgaon ..	15,01,881.00	2,11,000	55,600	1,17,100	1,40,000.00	9,78,181.00
6.	Gurdaspur ..	59,207.29	20,000	—	501	—	38,706.29
7.	Hoshiarpur ..	2,52,597.57	1,31,692.46	5,000	24,001	22,870.82	69,033.29
8.	Jullundur ..	9,47,940.15	2,23,687.50	60,000	43,687.55	14,695.00	6,05,870.10
9.	Karnal ..	8,09,613.72	53,600.00	42,000	78,500	9,314.00	6,26,199.72
10.	Kapurthala ..	1,04,445.00	10,000.00	7,500	11,000.00	7,601.00	68,344.00
11.	Kangra ..	9272.51	4,000.00	—	—	1,362.00	3,910.51
12	Kulu ..	3134.41	—	—	—	—	3,134.41

[Chief Minister]

13.	Keylong	..	2722.50	—	—	—	—	2,722.50
14.	Ludhiana	..	9,06,411.88	1,92,190.00	15,000	1,20,000.00	46,455.35	5,32,766.53
15.	Mahendragarh	..	5,95,628.00	3,44,000.00 35,950.00	34,700	26,211.00	19,716.00 11,111.00	1,23,940.00
16.	Patiala	..	8,03,831.19	1,32,000.00 20,000.00	89,100	1,23,311.00	—	4,39,420.19
17.	Rohtak	..	8,92,258.87	3,52,200.00	1,45,000	66,000.00	64,366.96	2,64,691.91
18.	Sangrur	..	16,97,003.04	3,21,051.00	1,31,100	1,06,000.00	22,923.75	11,15,928.29
19.	Simla	..	19,827.65	9,111.04	—	—	—	10,716.65
20.	Hissar	..	13,74,078.66	3,65,957.00	47,000	1,18,000.00	8,43,121.66	
21.	Chief Minister's Secretariat	..	3.70,483.44	5,000.00	60,500	1,40,300.00	38,126.00	1,26,557,44
22.	Estate Officer, Chandigarh	..	46,164.00	—	—	—	—	46,164.00
	Total	..	1,20,61,541.16	28,54,624.96	10,72,700.00	14,21,611.55	12,55,949.35	54,56,655.30

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਡਿਫੈਂਸ ਫੰਡਜ਼ ਐਂਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਵਿਚ 1 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ 61 ਹਜ਼ਾਰ 5 ਸੌ 41 ਰੁਪਿਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਰੁਪਿਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਐਂਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਪਜ਼ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਨੰਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਕੀ, ਉਹ ਇਸ ਰੁਪੈ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ?

मुख्य मंत्री : इस फंड की डिस्बर्समैंट करने के लिए एक कमेटी बनाई है, जो रूलज़ मुर्तब कर रही है । अगर ऐसा पैसा दिया गया है तो वह आर्म्ड फोर्सिज़ के पर्सोनलज़ के बच्चों के लिए वरता जा सकता है ।

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਇਸ ਫੰਡ ਵਿਚ 66 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੁਪਿਆ ਬਲਾਕ ਸਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਰੁਪਿਆ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ?

मुख्य मंत्री : इसका सही और जायज़ इस्तेमाल होगा । जहां तक इस कंट्रीब्यूशन का सवाल है यह वालंट्री कंट्रीब्यूशन है ।

बाबू अजीत कुमार : यह क्यों दी।

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਇਹ ਕਿਥੋਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਡਜ਼ ਵਿਚੋਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਕੇ ਰੁਪਿਆ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੱਢ ਦੇਈਏ । ਬਲਾਕ ਸਮਤੀਆਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦਾ ਰੁਪਿਆ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਇਸ ਰੁਪਏ ਵਿਚੋਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਉਗੇ ?

मुख्य मंत्री : इस रुपए में से एक भी बुक एंट्री नहीं हुई है और न कोई ट्रांस्फर हुई है।

ਕਾਮਰੇਡ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਿਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 30 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ?

शिक्षा मंत्री : जो चीफ मिनिस्टर का सिक्योरिटी और डिफैंस फंड है उसी में यह रुपया इकट्ठा किया गया है। बाकी जो 25 हज़ार रुपए का हाउस में ज़िक्र हुआ है, वह यह रुपया है जो बच्चों ने एक एक दो दो आने करके इकट्ठा किया है । इंटैग्रेशन की स्प्रिट का इज़हार करने के लिए यह रुपया काश्मीर के चीफ मिनिस्टर, और श्री नंदा जी को इस लिए दिया गया कि वह आर्मी के पर्सोनल के बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जा सके । जैसा कि मैंने कहा है, यह एक ही फंड है डिफैंस और सिक्योरिटी फंड जिसके तहत यह रुपया जमा कराया गया।

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE UNDER RULE 45

DEFENCE/RELIEF FUND

***8800. Comrade Jangir Singh Joga :** Will the Chief Minister be pleased to state whether the State Government is at present collecting any Defence/Relief Fund; if so, the names of the agencies through which it is being collected ?

Shri Ram Kishan : Yes. The Punjab Defence and Security Relief Fund is being collected through Deputy Commissioners, Sub-Divisional Officers (Civil) within their respective jurisdiction and the Estate Officer in the Chandigarh Capital. At the State Headquarters, such contributions are being received by the Special Secretary to Chief Minister, Punjab.

2. Education Institutions in the State have also been authorised to collect contributions to this Fund.

QUOTA OF WOOLLEN YARN ISSUED TO MANUFACTURERS OF HOSIERY GOODS IN LUDHIANA

***8423. Comrade Ram Chandra :** Will the Chief Minister be pleased to state whether the Government have taken any steps to find out if the quota of woollen yarn issued to the manufacturers of Hosiery Goods in Ludhiana is properly utilised by each concern and not sold in the black market, if so, the details thereof ?

Shri Ram Kishan : Two Additional Deputy Wool Controllers have been appointed to ensure proper utilization of woollen hosiery yarn by the quota holders.

STARTING INDUSTRIES IN KANGRA DISTRICT

***8424. Comrade Ram Chandra :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the details of the industries which were proposed to be started in the Kangra District during the First, Second and Third Five Year Plans respectively together with the amount allotted for the purpose, Plan-wise;

(b) the names of the industries referred to in part (a) above which were actually started together with the amount utilised, Plan-wise ?

Shri Ram Kishan : (a) & (b) The requisite information is laid on the Table of the House.

Statement regarding starting Industries in Kangra District

(a) & (b). No provision was made during the First, Second and Third Five Year Plan respectively for setting up industries in the Public Sector in Kangra District. The Department of Industries has, however, taken several measures for the promotion of Industries in the Kangra District as per details given below :—

(i) The Government of India granted industrial licences to the following two parties for the establishment of the Projects in the Kangra District in the private sector as noted against each.

(a) M/s Shree Gopal Paper Mills .. Manufacture of newsprint.

(b) M/s Surrendra Overseas (P) Ltd. .. Manufacture of portland cement.

A provision of Rs 2 crores for State participation in the capital structure of the proposed newsprint factory and a provision of Rs 50 lakhs in the capital structure of the proposed cement factory was made in the 3rd Plan period.

M/s Surrendra Overseas (Pvt.) Ltd. has since surrendered the industrial licence granted to them for the establishment of a cement factory and the possibility of finding another suitable party for implementing the project or taking it up in the public sector is being examined.

M/s Shree Gopal Paper Mills have, however, now decided to locate the news-print mill near Nangal. It has been decided to make available to them 30 lakh cft. of soft wood. The details of the scheme are being worked out by the Forest Department.

(ii) During the Third Plan period, Government participated in the share capital of the following Co-operative Societies in the Kangra District :—

Name of the Society	*Year*	*Amount*
		Rs
1. Bir Co-operative Tea Factory	.. 1962-63	50,000
	1963-64	50,000
2. The Kangra Tea Planters Supply and Marketing Society Ltd.	.. 1963-64	1,00,000

(iii) For the intensive development of industries in the Rural Areas, the Government of India have started 45 Projects during the Third Plan. Out of these two Projects have been allocated to Punjab State; one of these is in the Kangra District, i. e., at Palampur. The following Centres were set up in the Project Area :—

1. Hooked Rugs Trg. Centres.
2. Carpentry Training Centre.
3. Blacksmithy, Agricultural Implements and Sheet Metal Training Centre.
4. Shoe Making Training Centre.
5. Glazed Pottery Training Centre.
6. Short Term Poultry Training Centre.
7. Training in different trades.
8. Wool Weaving Training Centre.
9. Development of Sericulture industry.
10. Common Facility Centre for Tea.
11. Development of Khadi and Village Industries.
12. Poultry Extension Wing.
13. Model Tannery.
14. Best Model Units set up by the trainees.
15. Opening of Pharmaceutical Laboratory.
16. Subsidy.
17. Loans to Industrial Units.

[Chief Minister]

(iv) **Handicrafts**

The following centres in Handicarafts were set up in Kangra District to encourage the development of Handicrafts :—

II PLAN

1. Pashmina Weeving Training Centre, Nurpur.
2. Hooked Rugs Training Centre, Dharmsala.
3. Namda Felting Training Centre, Kulu.
4. Carpet Weaving Training Centre, Palampur.
5. Chain Stitch Embroidery Centre, Kulu.
6. Training Centre for Bamboo Works, Kangra.
7. Walnut Wood Carving Training Centre, Kulu.
8. Papier Machie Training Centre, Shahpur.
9. Tapestry Training Centre Dharmsala.
10. Training Centres for Bamboo Works, Dehra Gopipur.
11. Wooden Toy Making Training Centre, Palampur.
12. Central Organisation and Designing Centre, Dharmsala.
13. Pashmina Shawl Improvement Centre, Kulu.

III PLAN

1. Potters' Training Centre at Jawali.
2. Cane and Bamboo articles Wooden Toy Making Training Centre, Hamirpur.
3. Carpet Making Wool Spinning and Weaving Training Centre at Multhan.
4. Introcution of Production in Handicrafts Training Centre in Kangra District.

(v) **Handloom Schemes**

The following common facility centres were started for the development of Handloom Industry in the district :—

III PLAN

(i) Co-operative Dye House, Kulu.

(ii) Carding Plant at Baijnath.

(vi) **Industrial Estates**

There was no programme for setting up Industrial Estates during the I and II Five-Year Plan. During the III Five-Year Plan, it was proposed to set up one Urban Industrial Estate at Kangra and 3 Rural Industrial Estates at Jawali, Dehra Gopipur and Rajpur.

Urban Industrial Estate at Kangra has since been completed at a cost of Rs 5,29,495. The Rural Industrial Estates at Jawali and Dehra Gopipur have also been completed at a cost of Rs 1,83,409 and Rs 1,68,919 respectively. The proposal for Rural Industrial Estate, Rajpur has, however, been dropped.

(vii) **Rural Industrial Development Centres/Rural Artisans Training Centres.**

In the III Five Year Plan, three Rural Industrial Development Centres, each at Jawali, Dehra Gopipur and Rajpur in Kangra District. have deen established. The Rural Industrial Development Centres at Jawali and Rajpur are run in Silk Weaving Trades and the centre at Dehra Gopipur in Carpentry.

(viii) **Sericulture**

In order to develop Sericulture, the following Centres were established in Kangra District :—

S. No.	Name of Centre	Location
	II PLAN	
1.	Plantation-cum-Demonstration Farm ..	Nagrota
2.	Government Sericulture Farm ..	Mangwal.
3.	Foreign Race Silk Seed Station ..	Nagrota.
4.	2 Chawki Reering Centres ..	1. Mangwal 2. Nadaun.
	III PLAN	
1.	4 Chawki Rearing Centres ..	1. Bharmar. 2. Shahpur. 3. Thural. 4. Pragpur.
2.	Silk Filature ..	V. Bohar, Tehsil Nurpur.
3.	Silk Seed Grainage ..	Palampur
4.	Basic Mulberry Nursery-cum-Demonstration Farm	Nadaun
5.	Panchayats' Plantations established with the aid of State Government ..	1. Muhal. 2. Bhumpal 3. Machhali. 4. Tharu 5. Daulatpur. 6. Dhagwar. 7. Bundla. 8. Kamnala. 9. Kodana. 10. Bharmar.

(ix) Financial Assistance

Besides, the Department provides financial assistancc to the private entrepreneurs in Kangra District under the Punjab State Aid to Industrics Act, 1935. The following amounts were disbursed as loans and subsidies for the development of small Scale, cottage and village industries during the first Three Plan Periods :—

LOANS

S. No.	Plan	No. of parties benefited	Amount
			Re
1.	1st Plan ..	75	2,04,400
2.	2nd Plan ..	445	5,80,200
3.	3rd Plan (up to 31st March, 1965) ..	574	6,65,400
	SUBSIDIES		
1.	1st Plan ...	78	50,440
2.	2nd Plan ..	42	28,570
3.	3rd Plan (upto 31st March, 1965) ..	87	67,653

SETTING UP NEW FERTILIZER PLANT IN THE STATE

***8701. Comrade Shamsher Singh Josh** : Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under the consideration of Government to set up a new Fertilizer Plant in the State, if so, the proposed site selected for its location?

Shri Ram Kishan : No, Sir. Does not arise.

BUSES PLYING ON PATHANKOT-JASSUR ETC. ROUTES

***8462. Comrade Ram Chandra** : Will the Minister for Transport and Elections be pleased to state —

(a) the names of the Transport Companies plying buses at present on the Pathankot-Jassur, Rehan-Dhamete and Nurpur-Rehan-Dhamete routes:—

(b) the dates on which the above mentioned companies plied their buses on the said routes during the months of July, August and September, 1965?

Sardar Gurdial Singh Dhillon : (a) Pathankot-Jassur, Rehan-Dhamete and Nurpur-Rehan-Dhamete are not any independent routes. They are portions of other routes. As such, no companies are plying services strictly on these portions.

(b) Does not arise.

COMPENSATION FOR TRUCK OWNERS

***8804. Shri Fateh Chand Vij** : Will the Chief Minister be pleased to state the name, designation and the location of the office of the authority, if any, appointed to receive claims for compensation for trucks destroyed while on duty with the military authorities during the recent conflict with Pakistan.

Sardar Gurdial Singh Dhillon (Transport and Elections Minister) : The Deputy Commissioners in the State have been directed to set up Committees, to assess the compensation to be paid to the owners of the trucks/buses etc., damaged during military operations, while in the service of Army, consisting of the following :—

1. Deputy Commissioner .. Chairman
2. One Army Officer .. To be appointed by the General of the Army.
3. General Manager of the Punjab Roadways concerned.
4. District Transport Officer.

The compensation in such cases will be paid by the Army Authorities.

PATUADI-HODEL ROAD IN GURGAON DISTRICT

***8802. Chaudhri Tayyab Hussain Khan** : Will the Minister for Public Works be pleased to state —

(a) whether the Construction of Road from Patuadi to Hodel in Gurgaon District has been completed ; if not, the approximate time by which it is likely to be completed ;

(b) whether the said road was included in any Five-Year Plan, if so, which one ?

Chaudhri Ranbir Singh: (a) & (b) 43 miles of 52 miles Hodel-Pataudi Road was provided in the 2nd Plan, which has since been completed, the rest of the portion of 9 miles of the road from Nuh to Tauru was provided in the 3rd Five-Year Plan, which is likely to be completed during the 4th plan subject to availability of Funds.

Deputy Speaker : The Question Hour is over.

10.00 a. m.

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਮੈਡਮ ——

उपाध्यक्षा : बाबू अजीत कुमार, मैंने आपको पिछले सेशन में भी कहा था कि आप अपना एटीच्यूड बदलें, जो प्वायंट आफ आर्डर हो सिर्फ उसी पर उठें। (Addressing Babu Ajit Kamar) (I had requested the hon. Member during the last session also that he should change his attitude towards the Chair. He should rise only on a proper point of order.)

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਮੈਡਮ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀਆਂ ਜਾਂ ਮਿਊਨਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅਲਹਿਦਾ ਹੈਡ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ । ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਈਵੇਟ ਏਜੈਂਸੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਪਿਆ ਇਕਠਾ ਕਰਕੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਿਊਨਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਮਾਰਕਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸਮਤੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਪਿਆ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਹੈਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾਂ ਹੈ । ਉਸ ਹੈਡ ਵਿਚੋਂ ਰੁਪਿਆ ਕਢ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਹੈਡ ਵਿਚੋਂ ਦੂਜੇ ਹੈਡ ਵਿਚ ਰੁਪਿਆ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ । ਲੁਧਿਆਣਾ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਮਿਊਨਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਚੈਕ ਕਟ ਕੇ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ?

उपाध्यक्षा : सप्लिमैंटरी पहले कर लेतें। क्वेश्चन आवर खत्म हो गया है । अब आपनें उसी पर प्वायंट आफ आर्डर कर दिया । (He should have put a supplementery question earlier. Now when the question Hour is over, he has put it in the form of a point of order),

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ; ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੇ ਕਲ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ।

Deputy Speaker : No.

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਇਸ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਓਧਰ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ।

Deputy Speaker : Sardar Gian Singh Rarewala.

ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ : On a Point of Order, Madam. ਕਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਲਾਊ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

Deputy Speaker : No please. I allowed the point of order to be raised. I cannot go back.

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹੋਣ।

Deputy Speaker : Comrade Gurbakhsh Singh to please resume his seat. That question is over now. I have called the Short Notice Question. No more supplementaries on that question can be allowed.

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਮੈਡਮ। ਬੀਬੀ ਜੀ, ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਤ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਇੰਪਾਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਔਖੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਲ ਇਸ ਤੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਲਾਊ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੀਕਨਸਿਡਰ ਕਰ ਲਓ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੀ। (ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ) (I know my powers. I am not asking for powers from the hon. Member.) (Cheers)

SHORT NOTICE QUESTION AND ANSWER

SECURITY FOR PEOPLE OF BORDER DISTRICT IN THE STATE

***8728. Sardar Gian Singh Rarewala** : Will the Chief Minister be pleased to state the details of the steps taken by the Government to provide security to the people of the border districts in the Punjab ?

Shri Ram Kishan : It is not in public interest to disclose the details of the steps taken to provide security to the people of the border districts in the Punjab.

Sardar Gian Singh Rarewala : May I ask the hon. Chief Minister if any action has been taken to give security to the industries in the border districts ?

मुख्य मन्त्री : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं ग्रानरेबल मेंबर के उन जज़बात की पूरी कदर करता हूं जिस प्वायंट ग्राफ व्यू से उन्होंने यह शार्ट नोटिस क्वैस्चन दिया है। मैं इतनी ग्रर्ज़ करना चाहता हूं कि इस बारे जो भी मुनासिब इकदाम हैं वह गवर्नमेंट ग्राफ इंडिया का डीफेंस डिपार्टमेंट ले रहा है ग्रौर उसमें कोई तफसील में जाने की जरूरत नहीं। पंजाब गवर्नमेंट के ग्राफीसर्ज़ के साथ डीफेंस डिपार्टमेंट वालों की भी कुछ मीटिंगें हुई हैं। इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर या रोड्ज़ इन तमाम चीज़ों पर उन्होंने गौर किया है। मैं ग्राशा रखता हूं कि जो भी जरूरी इकदाम हैं किये जाने हैं वह कर रहे हैं।

सरदार ज्ञान सिंह राड़ेवाला : यह चीफ मिनिस्टर साहिव के नोटिस में होगा कि ग्रखबारों में ग्राया था कि छहरटे से सारी इन्डस्ट्री बाहिर ले जा रहे हैं। कम-ग्रज़-कम इन्डस्ट्री जहां इस वक्त वाक्या है वहां से न हिलाई जाये। इस बारे में क्या किया जा रहा है ?

मुख्य मन्त्री : इस बारे में कुछ इकदाम उठाए गए हैं, कुछ ग्रौर लिये जा रहे हैं।

श्री बलरामजी दास टंडन : क्या चीफ मनिस्टर साहिब बताएंगे कि जो सिक्योरिटी मेजर्ज़ लिए हैं उन्हों ने एसा कहा है कि यह पब्लिक इंट्रेस्ट में नहीं कि यहां पर डिसक्लोज़ किया जाए। ऐसे जो सिक्योरिटी मेजर्ज़ पंजाब सरकार ले रही है या सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ इन कन्सलटेशन विद डीफेंस मिनिस्ट्री लिए जा रहे हैं जो इस हाउस में बताना मुनासिब नहीं समझते डिफरेंट ग्रुप्स के साथ बैठ कर, उन्हें इन कानफिडैंस ले कर बात चीत की जा सकती है जिस से पता चले कि क्या हो रहा है।

मुख्य मन्त्री : हाउस को यह विश्वास रखना चाहिए कि जो जरूरी इकदाम हैं वह डीफेंस ग्रथारिटी ले रही हैं।

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪਸ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੈਣੇ ਹਨ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਲਭਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਲਾਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਆਂਗੇ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਠੀਕ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਰੋ (The hon. Member may put a relevant supplementary.)

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਮੈਡਮ। ਕਈ ਦਫਾ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਖੁਫੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਫਲਾਂ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਇਤਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਉਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਗੌਰਮਿੰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਗਲ ਪੁਛਣੀ ਕਿ ਆਇਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਹ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਹਕ ਤਾਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਛ ਲਓ, ਬਾਬੂ ਜੀ । (The hon. Members have a right. Baboo Bachan Singh may please ask.)

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਕੀ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟਸ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਸਰਕਾਰ ਲੋਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ?

मुख्य मन्त्री : सरकार इंडस्ट्रीलिस्ट्स को इस बात के लिए इन्करेज कर रही है कि वह इंडस्ट्री वहीं रहे और सरकार इन्सेंटिव दे रही है ।

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇਹ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਸਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਵਿਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਉਥੇ ਕੰਮ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਕਿਓਰਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਰਾਖੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ੨ ਕਦਮ ਚੁਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਚੁਕੇ ਹਨ । ਇਹ ਦਸਣ ਵਿਚ ਕੀ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਹੈ ?

मुख्य मन्त्री : जहां तक इंडस्ट्री का ताल्लुक है जैसा कि मेंबर साहिबान को मालूम है कुछ कदम पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से उठाए गए हैं और कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उठाए जाने हैं । जहाँ तक इंडस्ट्री की रुपये से मदद करनी है या रा मैटीरीयल से उस के बारे कुछ इफेक्टिव स्टेप्स उठाए हैं । कुछ लेबर पिछले दिनों बेकार हो गई है, उन्हें वेजिज़ नहीं मिले । पंजाब गवर्नमेंट ने उस लेबर की मदद करने के लिए, कुछ लोन देने के लिए उस के मुताबिक हिदायत जारी की है ।

मुझे अफसोस है कि अभी तक लेबर को लोनज़ डिस्बर्स नहीं हो सके हैं । कल ही हमारी इस संबंध में एक मीटिंग हुई थी और उस संबंध में कुछ स्टैप्स लिए गए हैं ताकि लेबर को बराहे रास्त पूरी तरह फायदा पहुंच सके और वह अपने काम पर आ सके ।

Comrade Ram Piara : Madam, will the hon. Chief Minister be pleased to state whether the measures adopted by Government for security purposes are sufficient to meet the nee s ?

Chief Minister : Yes, Madam.

श्री जगन्नाथ : मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ऐग्रीकल्चर के लिए भी पंजाब गवर्नमेंट कुछ कर रही है या नहीं ?

मुख्य मन्त्री : एग्रीकलचर के लिए आप सब को मालूम ही है कि इन तीन बारडर के ज़िलों अमृतसर और फिरोजपुर में 10 मील तक आब्याना और मालिया माफ कर दिया गया है और गुरदासपुर में 5 मील तक माफ कर दिया गया है। जहां तक लांग स्टैप्स का संबंध है वह गवर्नमेंट के ज़ेरे गौर है।

ਸਰਦਾਰ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ : ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਬ ਤੋਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਪਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਤਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਾਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ?

मुख्य मन्त्री : ऐसे भाई जो अपने खेतों में नहीं जा सकते उनकी मदद करना सरकार का फर्ज़ और इसके लिए स्टैप्स उठाए जा रहे हैं।

ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਬਲਕ ਇਨਟਰੈਸਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਿਤਨਾ ਅਰਸਾ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪਸ ਨਹੀਂ ਦਸੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਉਹ ਉਥੇ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ?

मुख्य मन्त्री : वहां लोगों को जो २ इतलाह देनी ज़रूरी है वह दी जाएगी और उनको confidence में लिया जाएगा।

ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਜੋ ਗਲ ਬਾਹਰ ਜਾਕੇ ਦਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਥੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ?

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਕਈ ਗਲਾਂ ਗੁਪਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦਸੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ (Certain things are secret which are not disclosed in the House.)

ਸਰਦਾਰ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਣ ਲਈ ਕੀ ਸਟੈਪਸ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਤਾਂ ਦਸ ਦਿਓ ?

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੰਤਰੀ : ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਅਪਰੂਟ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਹਨ। ਏ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿਚ ਉਹ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੀ ਵਿਚ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਟਰੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਜਿਥੇ ਮਾਈਨਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਲਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕ ਉਥੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਸੁਬਹ ਨੂੰ ਆਕੇ ਖੇਤ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੀ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਏ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪ ਰੂਟਡ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਲਾਇਲਪੁਰੀ : ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਦ ਤਕ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ?

मुख्य मन्त्री : पंजाब गवर्नमेंट की यह ज़बरदस्त खाहिश है कि सारे पंजाब में ही क्राप इन्शोरैंस सकीम लागू की जाए लेकिन ऐसा कानून पारलीमैंट ने ही पास कर है पंजाब गवर्नमेंट के अख्तियार की यह बात नहीं है । पंजाब गवर्नमैंट ने गवर्नमैंट आफ इंडिया को लिखा है कि पंजाब में क्राप इंश्योरैंस की जाए और बारडर के जिलों को ज्यादा से ज्यादा प्रैफरैंस मिलनी चाहिए ।

चौधरी देवी लाल : क्या यह बात गवर्नमैंट के इलम में है कि जो गांव पाकिस्तान की तरफ चले गए हैं वहां के कंसालीडेशन के केसों की अभी तक लोगों को तारीखें मिल रही है और इसी तरह 10 मील और पांच मील के एरिया में जो लोग हैं उन्हें भी तारीखें दी जाती हैं हालांकि वह वहां सैटल नहीं हुए इसके बारे में सरकार यह फैसला करेगी कि इस किस्म के केसों को पोस्टपोन किया जाए ?

मुख्य मन्त्री : यह तजवीज़ बड़ी माकूल है और इस पर ज़रूर गौर किया जाना चाहिए । अगर मैम्बर साहिब के पास ऐसी इतलाह हो तो दें ताकि मुनासब कार्यवाई की जा सके ।

ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ?

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਇਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੈ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਵੀ ਦਸ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵਾਰ ਅਫੈਕਟਡ ਜ਼ਿਲੇ ਹਨ ਉਥੇ ਦੇ ਜੋ ਪਿੰਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਪਿੰਡ ਜਿਸ ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਉਥੇ ਦੇ ਸਰਕਰਦਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮੀਨੇਟ ਹੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਥੇ ਦਾ ਡੀ.ਸੀ. ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾਮੀਨੇਟ ਕਰੇ ਇਸ ਕਮਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਵੇਗਾ । ਬਾਕੀ ਜੋ ਨਾਨਅਫ਼ੈਕਟਿਡ ਪਿੰਡ ਹਨ ਉਥੇ ਲਈ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏਜ਼. ਤੇ ਐਮ.ਐਲ.ਸੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਡੀ. ਸੀ. ਉਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਭੇਜੋ । ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਕ ਸਜੈਸ਼ਨ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿਓ । ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਜੋ ਆਦਮੀ ਲਏ ਜਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਣਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਲੇਕਨ ਅਜੇ ਤਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਹੈ ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਵਸਾਣ ਲਈ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਨ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ ।

CALL ATTENTION NOTICES

Deputy Speaker : We now pass on to Call Attention Motions.

Call Attention Notice No. 139 stands in the name of Comrade Shamsher Singh Josh.

Comrade Bhan Singh Bhaura : Madam, I may be permitted to read out this motion as well as other of Comrade Shamsher Singh Josh on his behalf as he cannot speak due to bad throat.

Deputy Speaker : Yes.

Comrade Shamsher Singh Josh, M.L.A. : (read by Comrade Bhan Singh Bhaura) : Madam, I beg to draw the attention of the Government to the hardship to be caused by the proposed cut in the use of electricity from 16th November, 1965. As a result of the new policy, all commercial and business shops will be closed after 6.00 P. M. which is bound to dislocate civil and business life of the State. The Government is, therefore, asked to restore normalcy in the State and apply all these cuts to electricity supplied by one State to other States.

उपाध्यक्ष : गवर्नमैंट इस बारे में स्टेटमैंट दे । (Government may make a statement in this connection.)

श्री जगन्नाथ : ग्रान ए प्वायंट ग्राफ ग्रार्डर, मडम । डिप्टी स्पीकर साहिबा, हिन्दुस्तान में तो गंगा बहती है । ग्राप जिस देश का दौरा करके ग्राई हैं वहां पर क्या बहता है ? इस के बारे में भी ग्राप रौशनी डालें (हंसी)

उपाध्यक्षा : चीफ मनिस्टर साहिब, ग्रब काल एटेंशन मोशन नम्बर 139 के बारे में स्टेटमैंट देना चाहते हैं । (The Chief Minister wants to give a statement in connection with Call Attention Motion No. 139)

मुख्य मन्त्री : डिप्टी स्पीकर साहिबा, जैसा कि सारे ग्रानरेबल मेम्बरों को मालूम है कि इस साल मानसून फेल हो जाने की वजह से पानी की कमी काफी हुई है । इस वर्श पानी रिज़र्वायर के ग्रन्दर भी कम इकट्ठा हुग्रा है । इस का ग्रसर पावजं

[मुख्य मन्त्री]

पर भी पड़ा है। पंजाब के अन्दर जहां तक पावर्ज़ का ताल्लुक है उस में 80 मीगा वाटस की कमी हुई है। इस लिए सरकार ने इस चीज़ को देखते हुए कुछ स्टैप्स उठाए हैं। अगर इस वक्त सरकार इस चीज़ को देखते हुए कट न लगाती तो हो सकता है कि किसानों को दिसम्बर और जनवरी, 1966 में खेती के लिए पानी की किल्लत महसूस हो। इस कमी को पहले ही सरकार ने महसूस किया है कि अगर ऐसे कदम न उठाए जाएं तो किसी भी समय पानी की सप्लाई में डिसलोकेशन हो सकती है। इसी वजह से सरकार ने कदम उठाए हैं। आज अखबारों में इस के बारे में पूरी तरह से डिटेल्ज़ आ गई है। सरकार का फर्ज़ है कि किसी तरह से लोगों के कारोबार में धक्का न पहुंचे। इस सिलसिले में सरकार के लिए जो कदम उठाने चाहिए वह कदम सरकार उठा रही है। इस सिलसिले में सरकार ने दुकानों के टाइम 8 बजे से लेकर साढे छः बजे तक कर दिए गए हैं। मैं समझता हूं कि जनता इस चीज़ की अहमीयत को समझेंगे। इस के इलावा सरकार ने पंजाब के दफतरों का टाईम भी साढ़े नो बजे से लेकर साढ़े चार बजें तक कर दिया है। पांच बजे से लेंकर रात के 10 बजे तक बिजली की काफी कंज़म्प्शन होती है। इस तरह से स्टेप्स उठाने के पश्चात कंज़म्प्शन पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ सकेगा। जहां तक बार्डर डिस्ट्रिक्स का सम्बन्ध है, वहां पर कारखानें और इंडस्ट्रीज़ की पावर्ज़ में कोई कमी नहीं की है। सरकार ने म्यूनिसिपल कमेटियों के हदों में स्टरीट्स लाईट में 25 प्रतिशत की कमी की है। इस तरह से बिजली की कमी को पूरा किया जाएगा। सरकार ने नंगल फर्टेलाइज़र कार्पोरेशन को बिजली सप्लाई करने में भी कमी की है। पहले 50 एम. डब्ल्यू की कमी करने का विचार था और अब 30 एम. डब्ल्यू की कमी की गई है। इस के अलावा सरकार ने सिनमा शौ के बारे मे बिजली की कमी नहीं की लेकिन सिनमा मालिकों को कहा गया है कि वह बिजली की सारी कंज़म्शन में 25 प्रतिशत की कमी करें। सरकार के इस मसले के बारे में 15 दिन के बाद सारे हालात पर गौर किया करेगी। जैसे २ हालात में सुधार होता जाएगा, वैसे २ बिजली की रिस्टिक्शन को हटाया जाएगा। मैं आशा रखता हूं कि माननीय सदस्य आज के हालात को देखते हुए सरकार के साथ पूरा सहयोग करेंगे। मुझे आशा है, कि सरकार के इस बारे में शीघर ही कदम उठाने से पंजाब के लोगों के कारोबार में कोई रुकावट नहीं आएगी।

चौधरी देवी लाल : आन ए प्वायंट आफ क्लैरीफिकेशन, मैडम। क्या चीफ मनिस्टर साहिब दूसरों को ही नसीहतें देते हैं या अपने ऊपर भी कोई बात लागू करते हैं। अगर सरकार ने स्टैप्स उठाने ही हैं तो चण्डीगढ़ से ही अमल होना चाहिए। इस हाउस के ऊपर बिजली जलाने का क्या लाभ है। यहां पर सटरीट लाईट का क्या लाभ है। इस लिए अगर सरकार ने बिजली की कमी को

देखते हुए कदम उठाने ही हैं तो सब से पहले अपनी टोपी अर्थात हाउस के ऊपर वाली बिजली को बन्द करना चाहिए ।

(Serial No. *140)

उपाध्यक्षा : गवर्नमेंट ने कल हाउस में कह दिया कि पब्लिक रिलेशन्ज़ डिपार्टमेंट में डिप्टी डायरक्टर अपनी ही डियूटीज़ परफार्म कर रहा है । उस को सरकार ने किसी दूसरे काम के लिए नियुक्त नहीं किया । सरकार ने इस का जवाब पहले दे दिया है । अब इस का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है । (The Government had stated in the House yesterday that the Deputy Director was performing his own duties connected with the Public Relations Department. He has not been deputed there for any other work. Government has already replied to this point and there is no need to repeat it.)

(Serial No. 141)

Sardar Gurbakhsh Singh Gurdaspuri : Madam I beg to draw the attention of the Minister concerned to the fact that the Punjab Government has fixed Rs. 35 and Rs. 44 per quintal the minimum price of Paddy and Basmati respectively but the growers are being given even less than this fixed minimum price. The Punjab Government have not taken any concrete step to save the interests of the growers. The State Government has not entered so far in the market to purchase paddy and Basmati for keeping the price level. The State Government has not allowed the Food Corporation to enter the markets for purchasing paddy and Basmati. The growers are not allowed to have their paddy and Basmati husked from the Jhona Machines situated in the rural areas which are sealed and are not allowed to function. The State Government has not allowed the growers to sell the rice at controlled rates from their paddy and Basmati after husking it. This attitude of the State Government has discouraged the growers and there will be a huge set back to the 'GROW MORE FOOD CAMPAIGN' of the State Government if this situation is allowed to prevail any longer.

मुख्य मन्त्री : डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप के जरिए हाउस को यकीन दिलाना चाहता हूं कि जहां तक प्रोडयूसर्ज़ और ग्रोअर्ज़ का सम्बन्ध है, उन को मुफाद का पूरी तरह से ख्याल रखा जाता है । इस के लिए सरकार ने पहले ही कदम उठाए हुए हैं । इस वक्त संगरूर, पटियाला, अमृतसर, गुरदासपुर तथा फिरोज़पुर डिस्ट्रिक्टस के अन्दर गवर्नमेंट मार्किट के अन्दर पैडी की खरीद कर रही है । माननीय सदस्यों ने कल ही अखबारों में पढ़ा होगा कि सरकार ने काफी मात्रा में

---

*Note: For previous reference please See P.V.S. Debates Vol. II No. 19 dated the 15th November, 1965 (Call Attention Notice No. 135)

[मुख्य मन्त्री]

पैडी खरीदी है । सरकार ने चावल भी काफी मात्रा में खरीदा है । हमारी फूड कार्पोरेशन के साथ खतोकिताबत जारी है । में माननीय सदस्यों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वह हमारे नोटिस में लाएं कि फलां जगह पर पैडी और चावल पड़े हुए हैं और हमारे कंसर्नंड आफिसर्ज़ वहां पर जा कर मार्किट में माल खरीदेंगे । हम पैडी और चावल खरीदने के लिए तैयार हैं। सरकार ने इस के लिए पिछले साल जो रेटस मुकर्रर किए थे, उसी भाव पर सरकार माल खरीदने के लिए तैयार है। सरकार भाव में किसी तरह से कभी नहीं आने देना चाहती है ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਵਲ ਮੈਂ ਕਾਲ ਅਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਦਾ ਧਿਆਨ 'ਦਿਲਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ।

मुख्य संसत् सचिव : जब गवर्नमैंट की तरफ से स्टेटमैंट दी जाए क्या उस के बाद भी कोई डिस्कशन हो सकती है ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ : ਮੈਂ ਇਸਤੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾਂ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾਂ ਹਾਂ ਕਿ ਚੀਫ ਮਨਿਸ਼ਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੂਰਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪੈਡੀ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚਾਵਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਮੀਂ-ਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ......।

Deputy Speaker : Order please. Please take your seat. It is not proper for the hon. Member to raise this issue unnecessarily.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ : ਇਸ ਗਲ ਉਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਅਜ ਹੀ ਸ਼ਟੇਟ-ਮੈਂਟ ਦੇ ਦੇਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇ ਦੇਣ ।

मुख्य मंत्री : हम मार्किट में बराहे रास्त जमींदार से पैडी और चावल खरीदने के लिये तैयार हैं ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ : ਪੈਡੀ ਅਤੇ ਰਾਈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਫਰਕ ਹੈ ....

उपाध्यक्षा : सरदार गुरबख्श सिंह जी आप इतने सयाने आदमी हैं। चीफ मिनिस्टर साहिब के कमरे में जा कर बात कर लें। (The hon. Member Sardar Gurbakhsh Singh is quite a wise man. He may discuss the matter with the Chief Minister in his room.)

मुख्य मंत्री : आनरेबल मेंम्बर जो कि खुद ज़मींदार हैं बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझते हैं। आखिर पैडी और चावलों की कीमत का फर्क क्यों नहीं होगा। पैडी में से दो तिहाई के करीब चावल निकलते हैं और एक तिहाई के करीब छिलका निकल जाता है। इस लिये कीमतों का फर्क तो अवश्य होगा। (विघ्न) (शोर)

उपाध्यक्षा : आप इन्ट्रप्ट करते हैं। मैं इस बात को ना पसंद करती हूं। (The hon. Members cause interruptions. I do not like this.)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ : ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰਨ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਜਦੋਂ ਇਕ ਆਦਮੀ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਵਿਚ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਬੋਲ ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (I do not relish a Member interrupting another when the latter is already in possession of the house.)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ : ਤੁਹਾਡੀ ਗਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਗ੍ਰੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਫਰਕ ਹੈ ਤਾਂ ਜੱਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਾਵਲ ਬਣਾਕੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ?

चोधरी इन्द्र सिंह मलिक : आन ए प्वांयट आफ आर्डर, मैडम। सरदार गुरबख्श सिंह ने जो सवाल उठाया है वह बड़ा ज़रूरी है। सवाल यह है कि आया जो ज़मींदार खुद पैडी में से चावल निकाल कर बेचना चाहे तो उस को इजाज़त है ? इजाज़त नहीं है। देहात में शैलर लगे हुए हैं वहां पर जमींदार लोग पैडी में से चावल निकाल कर नहीं बेच सकते। डीलर पैडी को खरीदता है। इस से बड़ा भारी नुकसान हो रहा है। यह बड़ा अहम मसला है।......... (विघ्न)

उपाध्यक्षा : अगर आप चेयर को इगनोर करेंगे और उस की बात को नहीं सुनेंगे तो चेयर को भी सोचना पड़ेगा। (विघन) (If the hon. Member ignores the Chair and pays no heed to its directions, then the Chair, too, will have to think over it.) (Interruption)

चोधरी इन्द्र सिंह मलिक : डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह जमींदारों का सवाल है लेकिन आप इस को सुनने के लिये भी तैयार नहीं है

उपाध्यक्षा : सरदार गुरबख्श सिंह लाय्यर है, उस ने अपनी बात कह दी है। समझा दी है। लेकिन आप दोबारा उन की बात को दोहराने के लिये खड़े हो गए।
(विघ्न)

(Sardar Gurbakhsh Singh is lawyer. He has clearly stated his point but the hon. Member (Chaudhri Inder Singh Malik) has stood up again to repeat his words.)

(Interruption)

मुख्य मन्त्री (श्री राम किशन) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, गवर्नमैंट आफ इंडिया के मश्विरे से पंजाब गवर्नमैंट ने पिछले साल पैडी की मुख्तलिफ किस्मों और चावलों की मुख्तलिफ किस्मों की मुख्तलिफ कीमतें मुकर्रर की थीं। इस के बारे में गवर्नमेंट आफ इंडिया का नोटीफिकेशन भी हो चुका है और पंजाब गवर्नमेंट का भी नोटीफिकेशन हो चुका है। चावलों की जितनी भी किस्में हैं, खाह बेगमी है, खाह बास्मती है, खाह परमल है इन सब की बकायदा कीमतें मुकर्रर हो चुकी हैं। पिछले साल हम ने 66 परसेंट के करीब चावल प्रोक्योर किया था। अब के साल 66 परसेंट की वजाए 75 परसेंट चावल प्रोक्योर करने का फैसला किया है। सरकार इस से आगे भी जाएगी। हम 85 परसेंट लेने को तैयार हैं। जो कीमतें चावलों और धान की मुकर्रर हैं उन्हीं कीमतों पर खरीदे जा रहे हैं। बल्कि उन्हें भी ज्यादा कीमतों पर खरीदे गए हैं। सरकार नें किसी जगह पर भी एक पैसा कम नहीं किया है। जहां तक ज़मींदार भाइयों का ताल्लुक है मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हुं फिर उस को पूरी तरह से दुहरा देता हुं कि अगर कोई ज़मींदार भाई डायरेक्ट गवर्नमेंट को मंडी में चावल या धान देना चाहता है गर्वनमेंट खरीद करने को तैयार है। इस सिलसिले में जो सहुलतें वे लोग चाहते हैं वह देने को तैयार है।

बाबू बचन सिंघ : ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਇਆ ਗੌਰਮਿੰਟ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਧਾਨ ਛੜਵਾ ਕੇ ਚਾਵਲ ਬਣਾਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਵੇਚ ਲਵੇ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਇੱਟਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬ ਪੱਥਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨ ਹੀ ਠੀਕ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਠੀਕ ਜਵਾਬ ਦਿਲਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।

उपाध्यक्षा : (मुख्य मंत्री से) बाबू बचन सिंह के प्वांयट आफ आर्डर का जवाब दें। अगर आनरेबल मेम्बर साहिबान पहले से ही अटेनटिव हों तो इस

से आधा वक्त लगे। जब वे कहते हैं तो आप सुनते नहीं हैं। (Addressing the Chief Minister) He may kindly reply to the point raised by Baboo Bachan Singh. If the hon. Members only try to be attentive then I think the Chief Minister would take half the time to explain the matter. The difficulty is that when he speaks, the Members pay no attention.)

मुख्य संसत् सचिव : उन के प्वांयट आफ आर्डर पर आप रूलिंग दें। हम क्यों जवाब दें ?

उपाध्यक्षा : बाबू बचन सिंह के प्वांयट आफ आर्डर का डैफिनिट जवाब गवर्नमेंट ही दे सकती है कि आया उन को अपनी मशीन पर चावल छड़वा कर बेचने की इजाज़त है कि नहीं। (It is only the Government which can give a definite reply to the point of order raised by Baboo Bachan Singh, namely, whether or not the growers are permitted to have their paddy husked from their own machines and sell it.)

मुख्य मन्त्री : मैं यह बात बड़ी वज़ाहत से कह चुका हूं। जहां तक हैलर और शैलर लगाने का ताल्लुक है इन के कोआप्रेटिव केसिज़ पर लगाने की इजाज़त है। जहां तक नए लाइसेंस देने का ताल्लुक है हमारे बस की बात नहीं है। गवर्नमेंट आफ इंडिया सारे हिन्दोस्तान पर एक ही एक्सपैरीमेंट लागू किया हुआ है। इस के बारे में आल इंडिया नें खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ बोर्ड के साथ फैसला किया है। इस बात का तो बाबू बचन सिंह जी रोज़ाना प्रचार करते हैं। गवर्नमेंट को कोई एतराज़ कोई नहीं है कोआप्रेटिव केसिज़ पर जितने भी हैलर और शैलर लगाने हों, गवर्नमेंट देने के लिये तैयार है।

उपाध्यक्षा : अगर किसी इंडीविजुअल के पास मशीन हो तो आप इस बात की इजाज़त देंगे या नहीं ? (If an individual possesses his own husking machine, will he be permitted to do so or not?)

मुख्य मन्त्री : नहीं देंगे, यह हमारे बस की बात नहीं है।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ : ਮੈਂ ਇਹ ਗਲ ਡੈਫਨਿਟਲੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ :—

"...... :........The growers are not allowed to have their paddy and basmatti husked from the Jhona machines situated in the rural areas which are sealed and are not allowed to function............."

[ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ]

ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ । ਗੌਰਮਿੰਟ ਚਾਵਲ ਕਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ । ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡਵਿਜੂਅਲਜ਼ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਚਾਵਲ ਕਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ।

उपाध्यक्षा : उन्होंने बताया है कि वह इजाज़त नहीं दे सकते । यह उन के बस की बात नहीं है । (The Chief Minister has stated that the Government cannot permit individuals to use their shellers. It does not lie in their power.)

Comrade Ram Chandra : On a point of Order, Madam. I want to know if there is any provision in the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly whereby hon. Members can be allowed to ask questions, make comments and/or speeches after a statemeut has been made by an hon. Minister in conection with a Call Attention Notice.

उपाध्यक्षा : काश ! कि हाउस के मेम्बर साहिबान रूल्ज़ और रैगुलेशंज़ का पालन करना सीख जाएं । (I wish that the hon. Members of this House learn to follow the Rules and Regulations.)

(*At this stage the Deputy Speaker called upon Sardar Tara Singh Lyallpuri to read his Call Attention Motion.*)

चौधरी देवी लाल : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडम । डिप्टी स्पीकर साहिबा, काल अटैंशन मोशन का नोटिस इस लिए दिया जाता है ताकि आप की मार्फत गवर्नमेंट की अटैन्शन को खास खास मामलात की तरफ इन्वाइट कर सकें लेकिन जैसा कि आप ने बजा तौर पर चौधरी रिज़क राम की बाबत कहा इन की तरह से घुसपैठिए अपनी सीट को छोड़कर दूसरों की सीट्स पर चले जाते हैं ।

उपाध्यक्षा : मैंने सरदार तारा सिंह को काल अपान कर लिया था और आप बिना मेरी इज़ाजत लिए खड़े हो गए और बिना इज़ाजत बोलना शुरू कर दिया । यह मुनासिब नहीं । (I had already called upon Sardar Tara Singh but the hon. Member took the floor without my permission and started speaking This is not proper.)

चौधरी देवी लाल : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं तो प्वायंट आफ आर्डर पर खड़ा हुआ हूं । मैं आप को रूलिंग इस बात पर चाहूंगा कि क्या यहां पर हाउस में जब कार्यवाही चल रही हो तो उस के दौरान में भी कैबिनेट की मीटिंग हो सकती है ? आखिर जब काल अटेंशन मोशन पढ़ी जा रही तो हर एक वजीर की तवज्जो इस तरफ होनी चाहिए वहां पर वज़ीर अपनी सीट को छोड़कर दूसरों की सीटों पर जा बैठते हैं । मैं इस बात पर आप की रूलिंग चाहता हूं ।

उपाध्यक्षा : यह हरियाणा प्रान्त का मामला है (This is an affair of Haryana Prant.) (Laughter)

(Serial No. 142)

Sardar Tara Singh Lyallpuri, : I beg to draw the attention of the Minister concerned towards the fact that the Government is laying more emphasis on the industrial and food production. In view of this, the Govenment has removed all restriction on the minimum charges of electricity whereas this restriction has not been removed in respect of tube-wells whereby food production is obtained. It is, therefore, requested that such like restrictions may also be removed in the case of tube-wells as well.

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ : ਮੈਡਮ, ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਨਰਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਲ ਅਟੈਨਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨ ਕਿਸ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ?

ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੰਤਰੀ : ਜ਼ਬਾਨ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਇਥੇ ਸ਼ਾਹ ਈਰਾਨ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਇਕ ਨਜ਼ਮ ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕੋਲੋਂ ਫਾਰਸੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹ ਪੁਛੱਣ ਲਗੇ ਕਿ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ । ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ । (ਹਾਸਾ)

उपाध्यक्षा : सरदार तारा सिंह वाली मोशन एडमिट की जाती है । गवर्नमेंट इस पर स्टेटमेंट देगी (The motion moved by Sardar Tara Singh is admitted. The Government will make a statement)

(Serial No. 143)

Chaudhri Inder Singh Malik : I beg to draw the attention of the Minister concerned towards the faet that there is a great scarcity of water at the tail of Jind Distributary No. 4 and on account of that the poor zamindars of villages Kinana, Anupgarh and Biroli have sufferred badly. Their Kharif crops are withering and Rabi sowing is being delayed. As a result of this shortage of water, at tail of Jind Distributary No. 4 not a single bigha of land of these villages has been irrigated for Rabi sowing. People of these villages will starve to death, if the early restoration of water supply at tail of said Distributory is not allowed. There will be a great famine which will cause great ruination of the public of these villages.

It is, therefore, requested that the full supply of water at the tail of Jind Distributary No. 4 be Kindly restored at an early date in order to save the poor famine stricken people of these villages. It is further requested that at least the arrangements of their Rabi sowing be kindly made with immediate effect.

उपाध्यक्षा : यह भी एडमिटिड है । गवर्नमेंट स्टेटमेंट देगी । (This is also admitted. Government will make a statemen.t)

(Serial No. 144)

Chaudhri Inder Singh Malik : I beg to draw the attention of the Minister concerned towards the fact that there is a great scarcity of water in Jind Distributray No. 3 at the tail and on account of that shortage, the people of villages Dighana, Shamlo-Kalan and Khurd, Lalit Khera, Nidana and Bhaironkhera have suffered badly. Their

[Chaudhri Inder Singh Malik]

kharif crops are withering and the sowing of Rabi crops is being delayed. The Zamindars of the above mentioned villages will starve to death if the arrangements of water supply at the tail of Jind Distributary No. 3, are not made immediately for sowing of their Rabi crops. It is, therefore, requested that the supply of water, be kindly restored immediately at the tail of Jind Distributary No. 3, in order to save the villagers from ruination. The canal authorities be directed for the immediate restoration of water at the tail.

उपाध्यक्षा : यह एडमिट की जाती है । गवर्नमेंट स्टेटमेंट करेगी । (It is admitted. The Government will make a statement).

(Serial No. 145)

उपाध्यक्षा : अगली काल अटेंशन मोशन न० 145 श्री फतेह चन्द विज के नाम है (The next Call Attention Motion No. 145 stands in the name of Shri Fateh Chand Vij.)

श्री फतेह चन्द विज : मेरे पास कापी नहीं पहुंची । आप ही पढ़ दें ।

उपाध्यक्षा : यह एक्शन के लिए एक रिक्वैस्ट है । गवर्नमेंट इस बारे ऐक्शन लेगी । (This is a request for action. The Government will take necessary action on it.)

कुछ माननीय सदस्य : है क्या ?

श्री फतेह चन्द विज : यह आई. टी. आईज़ में आपोजीशन के मेम्बरों की रिप्रिज़ैंटेशन की बाबत है कि उनमें आपोंजीशन के मेम्बरों को नहीं लिया गया ।

मुख्य मन्त्री : डिप्टी स्पीकर साहिबा, जहाँ तक आई. टी. आई. के इन्स्टीच्यूशंज़ का सम्बन्ध है उन के लिए जो सिलैक्शन कमेटीज़ बनाई गई हैं उनके अन्दर आपोजीशन के ऐम. ऐल. एज़ को भी रखा गया है ।

चौधरी इन्द्र सिंह मलिक : नहीं रखा गया ।

श्री फतेह चन्द विज : पानीपत के मुताल्लिक आप बताइए कि किस किस को लिया गया है ।

मुख्य मन्त्री : इस वक्त तो इन सभी डिटेल्ज़ में मैं नहीं जा सकता और एक एक की बाबत नहीं बता सकता । लेकिन ऐसी इन्स्टीच्यूशंज़ में आपोजीशन के मेम्बर साहिबान को भी लिया गया है ।

चौधरी इन्द्र सिंह मलिक : यह गलत बयान है। हर जगह पर नहीं लिया गया।

कुछ आवाज़ें : तो फिर यह भी बताइए कि किन किन को लिया गया है।

मुख्य मन्त्री : मुझे मालूम है कि डाक्टर बलदेव प्रकाश को भी लिया गया है, सरदार जगीर सिंह जोगा को लिया हुआ है। मुझे पूरी तरह पता है कि वहां पर बाकायदा आपोज़ीशन के मेम्बरान को रखा गया है।

सरदार गुरचरन सिंह : फिरोज़पुर के किसी लोकल एम. एल. ए. को नहीं रखा गया।

(Serial No. 147)

Comrade Bhan Singh Bhaura : To draw the attention of the Minister concerned towards a matter, namely 75 diesel engines lying unused with the XEN Drainage Malerkotla at this time when the Agriculture Department is in a dire need of Diesel Engines for agriculturists in this area. It is reported that the XEN (Drainage) Malerkotla, desired to pass on these engines to Agriculture Department even on daily rent. The Minister should intervene in this so that the engines may be useful for providing water to the farmers.

उपाध्यक्षा : यह एडमिट की जाती है। गवर्नमेंट इस पर स्टेटमेंट देगी। अगली काल अटेंशन मोशन नं० 148 सरदार सम्पूर्ण सिंह धौला के नाम है।

(It is admitted. The Government will make a statement on this. The next Call Attention Motion No. 148 stands in the name of Sardar Sampuran Singh Dhaula.)

(Serial No. 148)

ਸਰਦਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਧੌਲਾ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਜਵਾਹਾ ਧਨੌਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ ਰੀਮਾਡਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਵੱਲ ਦਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ 2. 5 ਪਰਤੀ 1000 ਏਕੜ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਘਟਾਕੇ ਕੇਵਲ 2.04 ਪਰਤੀ 1000 ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਰਜਵਾਹੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਦੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਘੇ ਨਵੇਂ ਡੀਜ਼ਾਇਨ ਦੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਲੀਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਘਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ ਅੱਧਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਜਵਾਹੇ ਵਿਚ ਕੱਟ ਤੇ ਕੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਨਾਲ ਫਸਲ ਦਾ ਬੀਜਣਾ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸੇ ਅਮਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰਤ ਇਸ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰੇ।

(Sardar Sampuran Singh Dhaula M. L. A. To draw the attention of the Government to the Remodelling Scheme of Dhanaula Distributary District Sangrur. Previously the quantity of water per 1000 acres was 2.5 but now it has been reduced to 2.04 per 1000 acres although

[Sardar Sampuran Singh Dhaula]

no change has been effected in the Distributary. The trouble is that the outlets of new design have been constructed. As a result of this new policy the discharge of water from the outlets has been reduced by 50% which has badly affected the sowing of Rabi crops. There is great resentment and unrest among the farmers of the area. Cuts after cuts are being made in the Distributary which has not only adversely affected the sowing Rabi crops but is also posing a danger to law and order situation. Therefore, Government should pay immediate attention towards this matter and after careful consideration bring the supply of water in line with other canals.)

उपाध्यक्षा : यह भी एडमिटिड है । गवर्नमेंट इस पर स्टेटमेंट देगी । अगली मोशन नम्बर 149 कामरेड बाबू सिंह के नाम पर है । (This is also admitted. The Government will make a statement. Next Motion No. 149 is in the name of Comrade Babu Singh).

(Serial No. 149)

Comrade Babu Singh Master : I beg to draw the attention of Minister concerned towards the failure of the Government in providing full quantum of water for sowing Rabi crops and for ripening Kharif crops.

The policy of the Government regarding remodelling of Rajbaha Dhanoula and Maudi Kalan Distributory and installing new 'Moghas' has caused a sensation and resentment in the farmers of the area. The cultivators are on the verge of making breach of peace which is obvious from the day to day breaches of the Rajbaha with the connivance of the S. D. O. Harigarh, District Sagnrur. The matter is of great public importance and concerns the food self sufficiency in the State hence the immediate steps are necessary in facing the newly created problem of the reduction of water to 2.04 cusecs per thousand acres from 2.5 cusecs per thousand acres at this crucial hour.

उपाध्यक्षा : यह एडमिट किया जाता है । गवर्नमेंट इस पर स्टेटमेंट करेगी (It is admitted. The Government will make a statement on this).

STATEMENTS LAID ON THE TABLE BY SHRI RAM PARTAP GARG, CHIEF PARLIAMENTARY SECRETARY

Chief Parliamentary Secretary (Shri Ram Partap Garg) : Madam, I beg to lay on the Table of the House Statements in reply to Call Attention Motions Nos.—

(1) 70, 75 and 83 regarding alleged charging of black market/ excess fares by certain Transport Companies of Ferozepore District,

(2) 85 regarding Sports Department,

(3) 104 regarding alleged delay by the Local Government Department to notify in the Official Gazette the revised rates of Professional Tax decided upon by the Municipal Committee, Chheharta (Amritsar),

(4) 108 regarding the position relating to classification of detenus including Communist detenus in different Jails,

(5) 109 regarding assessment of Property Tax in the border towns of Ferozepore District,

(6) 112 regarding the alleged brutal beating of a poor Harijan named Sucha Singh in village Chaprauda in Police Station Amargarh (District Sangrur),

(7) 114 regarding acquisition of nearly two thousand acres of cultivated evacuee land of village Fatehpur Bhagalan, Tehsil Rupar, District Ambala by the Forest Department, and

(8) 124 regarding termination of 55 sweepers by the Municipal Committee, Phagwara.

REPLY TO CALL ATTENTION NOTICES NOS. 70, 75 & 83 BY SARDAR GURCHARAN SINGH & COMRADE GURBAKSH SINGH, M. L. A.S

Minister-in-charge

Gurdial Singh Dhillon,
Transport & Election Minister,
Punjab.

No cases of charging black market fares by the New Samundri Transport Company Private Ltd., Ferozepur and the Ferozepur Co-operative Goods Transport Seciety, Ferozepur have come to the notice of the Government.

2. The Deputy Commissioner, Ferozepur has reported that he did not issue any certificate to any Transport Co. for rendering any best services during the emergency. He has further reported that a complaint was received from one Shri Raja Ram Setia regarding charging excess fares by the Fazilka-Dabwali Transport Co., Abohar. The Deputy Commissioner, Hissar also complained about it to Deputy Commissioner, Ferozepur on telephone. He has entrusted these complaints to the Sub-Divisional Officer (Civil), Fazilka for enquiry and report.

CALL ATTENTION MOTION S. NOS. 85 BY SHRI AJAIB SINGH SANDHU, M. L. A.

S. Ajmer Singh. Planning and Local Government Minister.

The Sports Department was created as an independent Department in 1961. In October same year, it was reorganized and besides the post of Director, posts of one Deputy Director, 3 Divisional Sports Officers, 18 District Sports Officers, and 24 Coaches were sanctioned. It was decided to take these posts out of the purview of the Punjab Public Service Commission under the orders of the Council of Ministers. The selection against these posts and subsequent selection of some District Sports Officers in 1963 were made through the Departmental Selection Committees, and it is presumed that the Departmental Selection Committees could not find any suitable candidates belonging to scheduled castes/tribes and Backward Classes, since the selection was intended to be confined to persons with distinguished career as sportsmen. In June, 1964, when one post of District

[Chief Parliamentary Secretary]

Sports Officer and 4 posts of Coaches had to be filled again through the Departmental Selection Committee, the following qualifications were prescribed for the post of District Sports Officer.

(a) Matriculation with outstanding sports achievements.

(b) Organizational and Administrative experience in sports.

(c) Physical fitness and willingness to tour country-side.

(d) Preference to be given to Graduates/D. P. E.s/or those trained from the National Institute of Sports, Patiala.

1. All these posts were reserved for Scheduled Castes/Tribes and persons from Backward Classes.

2. With further experience, it was realized that it would be desirable to have persons with higher educational qualifications i. e. Graduation, to man the posts of District Sports Officers in view of the nature of duties involved including contact with the various Schools and Colleges, and, therefore, the educational qualification was raised to Graduation. In 1964, the Government also decided that all newly created posts would be filled through the Public Service Commission. When, therefore, in the later part of 1964, 2 posts of District Sports Officers had to be filled, the following minimum qualifications were intimated to the Public Service Commission

(a) Graduate

(b) N. I. S. trained or D. P. E.

(c) Outstanding sportsman of at least University level.

3. These posts were also reserved for Scheduled Castes/Tribes and Backward Classes, but could be filled from other categories if suitable candidates from Scheduled Castes/Tribes and Backward Classes were not available.

4. As far as the selection by the Public Service Commission is concerned, the Commission intimated that only one candidate belonging to scheduled caste was summoned for interview, but he was found ineligible and the Commission had, to, therefore, recommend candidates belonging to other categories for the posts.

5. The same happened with selection by the Departmental Selection Committee. All the applicants belonging to Scheduled Castes/Tribes and Backward Classes were summoned for interview, but the Departmental Seleetion Committee which interviewed the candidates on 11th January, 1965, did not consider any such candidate suitable for the post, so much so that it did not give any marks to such candidates for personality and suitability to the post. It is incorrect that the Departmental Selection Committee obliged one of the members of the Committee in the matter of selection. On the other hand, candidates were selected only on the basis of merit.

6. It has been clearly laid down in the Punjab Government letter No. 8352-WG-2-61/24227 dated 6th October, 1961, that the Punjab Public Service Commission/Subordinate Services Selection Board are not debarred from adjudging the suitability of candidates belonging to Scheduled Castes/Tribes and Backward Classes even though they may be possessing the prescribed qualifications and that, in fact, it would not be suitable for the Government to accept the practice of appointing Scheduled Castes/Tribes personnel merely on the evidence that they have the requisite qualifications without going into the question as to whether they have the necessary intelligence and calibre be able to do the job to which appointments are being made. It was presumed that the Departmental Selection Committee had the same powers as were stipulated in the above letter to be exercised by the P. P. S. C./S. S. S. Board in adjudging the suitability of the candidates belonging to Scheduled Castes/Tribes and Back-

ward Classes, while making the selection. These selections were quite in order, in accordance with the instructions of the Punjab Government and there is no question of cancelling these selections. If the required percentage of Scheduled Castes/Tribes and Backward Classes does not exist in this Department, it is because such persens possessing the right calibre and suitability have not been available. Even at present some posts of D. S. O.s and Coaches are lying vacant and are proposed to be filled shortly. These again are being reserved for members of the Scheduled Castes/Tribes and Backward Classes and would be filled from other categories only if suitable candidates from former categories are not available.

STATEMENT BY S. AJMER SINGH, MINISTER FOR PLANNING AND LOCAL GOVERNMENT DEPARTMENTS IN RESPECT OF CALL ATTENTION NOTICE (SERIAL NO. 104) RECEIVED FROM COMRADES GURBAKSH SINGH AND BABU SINGH, ON THE 2ND NOVEMBER, 1965.

The Hon'ble members have alleged delay by the Local Government Department to notify in the official Gazette, the revised rates of Professional Tax decided upon by the Municipal Committee, Chheharta, District Amritsar, on the plea that such a proposal does not require the sanction of the Government which is duty bound, as a matter of routine, to issue notification on behalf of the Committee. On this ground, it has further been urged that the notification regarding the proposal of the Municipal Committee Chheharta, for amending its schedule of Profession Tax should be issued forthwith.

2. The plea taken by the Hon'ble members ignores the fact that the power of the Municipal Committees to impose the taxes enumerated in sub-section (1) of section 61 of the Punjab Municipal Act, 1911, are subject inter-alia, to any general or special orders made by the State Government in this behalf and that power vests in the Government under the- provisions of sections 232 and 236 of the Punjab Municipal Act, 1911, to annul or modify any proceedings which it may consider not to be in conformity with law or in the interest of the public or likely to cause waste or damage of municipal funds or property. The proposal under reference, received on 24th August, 1965. through the Commissioner, Jullundur Division, was scrutinised promptly but it was considered that some revision thereof was necessary not only with a view to removing some obvious anomalies in the rates proposed for various categories of the assessees but also to secure a uniform pattern comparable with that adopted by other municipal committees in regard to the levy of Professional Tax particularly in respect of the general exemption limit. it was, therefore, considered desirable to explain the above mentioned defects noticed in the proposal to the President of the Municipal Committee who was requested to meet the Local Government Minister on the 29th September, 1965. The proposed meeting could not be held as the President of the Committee had sought its postponement to some other date which would be fixed after the current Session is over. Efforts are, however, being made to finalise the matter with the least possible delay.

STATEMENT BY SHRI CHAND RAM, WELFARE AND JUSTICE MINISTER, PUNJAB REGARDING CALL ATTENTION NOTICE No. 108 BY COMRADE MAKHAN SINGH TARSIKA, M. L. A., PANDIT MOHAN LAL DATTA, M. L. A., SHRI OM PARKASH AGNIHOTRI, M. L. A., DR. BALDEV PARKASH, M. L. A., SHRI BALRAMJIDASS TANDON, M. L. A., SARDAR GURBAKSH SINGH GURDASPURI, M. L. A., CHAUDHRI TEK RAM, M. L. A., SARDAR MAKHAN SINGH HARRUWAL, M. L. A., SARDAR SURJIT SINGH THERI, M. L. A., SARDAR TEJA SINGH, M. L. A. SARDAR AJAIB SINGH SANDHU, M. L. A., SARDAR SHAMSHER SINGH DHANDERI, M. L. A., SARDAR GURCHARAN SINGH, M. L. A., SHRI SATYA DEV, M. L. A., BABOO AJIT KUMAR, M. L. A., SARDAR JAGJIT SINGH GOGOANI, M. L. A., SARDAR KULTAR SINGH, M. L. A.

The position regarding classification of detenus including Communist detenus in different jails is summarised below:—

(I) The first rules in vogue were the East Punjab Detenus Rules, 1946 under the East Punjab Public Safety Act, 1947.
Under these rules there were three classes namely A, B and C.

[Chief Parliamentary Secretary]

(II) The above rules were superseded by the East Punjab Detenus Rules, 1949. According to these as well, there were three classes of detenus namely A, B and C.

(III) In 1949 seperate rules were framed for the Communist detenus. These were called the East Punjab Communist Detenus Rules, 1949 under the East Punjab Public Safety Act, 1949.
The classification as 'Communist Detenus' was to be done by the District Magistrate subject to the confirmation by the Government. There was only one class under these rules.

(IV) East Punjab Detenus Rules, 1949 were replaced by Punjab Detenus Rules, 1950 under the Preventive Detention Act, 1950. These rules again Provided three classes of detenus namely A, B and C,

(V) The East Punjab Communist Detenus Rules, 1949 were also replaced by Communist Detenus Rules, 1950 under the Preventive Detention Act, 1950. As in the case of East Punjab Detenus Rules, 1949, under these rules also there was one class and the classification was to be made by the District Magistrate/Sub Divisional Magistrate concerned.

The Communist Detenus Rules, 1950 were, however rescinded in June, 1953 from which date all detenus are being governed under the Punjab Detenus Rules, 1950 as modified from time to time.

2. It is obvious that now there is no separate class as Communist Detenus and all detenus are being classified as A, B and C as the case may be, in accordance with the aforesaid rules. The classifying authority is the District Magistrate or the Sub Divisional Magistrate concerned subject to confirmation by the State Government.

3. During the period 1949 to 1953 the communist detenus were treated by separate Rules. They were classified as Communist Detenus by the District Magistrate/Sub Divisional Magistrate concerned subject to confirmation by the State Government. They were given diet allowance of Rs. 2.50 paise per day (Rs. 2-8-0) and a lumpsum sundry allowance for the purchase of clothing toilet articles, newspapers, periodicals and shaving sets. etc. @Rs. 16/- per mensem was given. They were further allowed to receive from their relatives or friends at intervals of not less than a month, funds (not exceeding in the aggregate Rs. 20/- per mensem) to enable them to supplement amenities of life.

Family allowance was sanctioned in individual deserving cases by Government, on the representations of communist detenus.

4. Thus between 1949 and 2-6- 1953, the Communist Detenus detained under the Punjab Public Safety Act, 1949 and Preventive Detention Act, 1950 were being accorded uniform treatment as provided in the respective detenu rules. The present change is due to the Communist Detenu Rules, 1950 having been rescinded.

5. So far as the treatment of C Class detenus in the Jails is concerned, they are allowed bedding and clothing according to the scale allowed for civil prisoners in accordance with the rules and diet according to the scale fixed for Criminal 'C' class prisoners.

6. They are also being allowed to receive Rs. 5/- p. m. from their relations or friends to supplement the amenities of life. They are being supplied one cake of soap per month, 2 chhatanks of oil per week and one datan per day at Government expenses. In addition, sikh C class detenus and those who are keeping long hair are being allowed 1/2 chhataniks of soap and 1/4 chhatanks of mustard oil per head per week.

7. All the communist detenus detained in various jails of this State have been classified as A, B and C class detenus in accordance with rule 3 of the Punjab Detenus Rules, 1950 and instructions issued by the State Government from time to time which inter-alia are :—

(1) All existing M. L. A./M. L.C./M.P. detenus are classified as 'A' class detenus;

(2) All detenus are classified as B class if they fulfil either of the following conditions—

(a) The detenu is a Matriculate;

(b) Monthly income of the detenu is at least Rs. 500/-;

(c) Pays annual land revenue of Rs. 500/-;

(d) The detenu is a Political Sufferer as defined by Punjab Government from time to time;

(e) Ex- M. L. A./M. L. C./M. P. detenus are classified as 'B' class detenus.

Out of 59 Communist detenus 2 have been given 'A' class, 49 'B' class and 8 'C' class treatment. The Municipal Commissioners and Panchayat Samiti members who do not fulfil any of the above mentioned qualifications are classified as 'C' class detenus.

As regards the grant of family allowance to the detenus detained under rule 30 (1) (b) of the Defence of India Rules, 1962, it may be stated that family allowance to the detenus is granted in accordance with the instructions issued by the Government of India. According to these instructions, family allowance is granted by the State Government on an ex-gratia basis in cases where it is satisfactorily proved that the detenu was the sole bread-winner of the family and his detention had affected the means of subsistance of his family. The cases of detenus have been considered by the State Government in the light of these instructions after proper and due verification of the facts from the District authorities.

8. 30 representations for grant of family allowance were received from the communist detenus. As the condition, referred to above was not fulfilled in 24 cases, their representations for the grant of family allowance were rejected. The remaining 6 cases are still under consideration.

Subject :—CALL ATTENTION NOTICE NO. 109 REGARDING ASSESSMENT OF PROPERTY TAX IN THE BORDER TOWNS OF FEROZEPUR DISTRICT.

Out of four rating areas mentioned in the Call Attention Notice above, re-assessment of property tax is being framed in the following rating areas :—

Ferozepur City and

(ii) Ferozepur Cantt.

The Draft Valuation List in respect of the aforesaid two rating areas has since been completed and published for inviting objections. Therefore, the question of cancellation of the assessment in these cases does not arise at this stage. If the Lists are cancelled as they are, Government will have to incur extra expenditure for framing new valuation lists from some later date, if so desired.

2. As regards the proposal to abolish property tax in respect of the four rating areas viz. Ferozepur City, Ferozepur Cantt., Guru Harsahai and Fazilka, the Department is not in favour of it as the present emergency is not going to last for eve. If, however, Government abolishes the tax in these rating areas, the State Government will have to lose property tax which may run into 38 lakhs of rupees (the annual demand for these four rating areas is over Rs. 3 lakhs). The State Government can ill-afford to forego any portion of their revenue from this source as our country is badly in need of every paisa for its defence etc. Moreover, the abolition of tax in these rating areas will create heart burning among the residents of other such rating areas, who will come forward with similar claim and it would be very difficult for Government to resist their demand.

[Chief Parliamentary Secretary]

(Serial No. 110)

By Comrade Bhan Singh Bhaura, regarding alleged the brutal beating of a poor Harijan named Sucha Singh in village Chaprauda in Police Station Amargarh (District Sangrur).

Sardar Darbara Singh, (Home and Develoment Minister) : No such incident took place on 8th October 1965. Howevers, Shri Sucha Singh s/o Sh. Sawan Singh, a resident of village Chaproda reported at Police Station Amargarh, district Sangrur that while he was in front of his house on 11st October, 1965, Shri Ravindar Singh s/o Shri Labh Singh abused him, saying that since he had purchased in auction, the evacuee land allotted to him; he would teach him a lesson. Shri Sucha Singh further reported that Shri Ravindar Singh also belaboured him with a lathi as a result of which he received some injuries on his back and shoulders etc. The report of Sh. Sucha Singh was recorded in the Daily Diary of the Police Station and was read over to him. He put his signatures on it, after admitting it to be correct. Thereafter, he was sent for medical examination in the Primary Health Centre, Amargarh, by the Police. According to the Medical Report, received from the Doctor-in-Charge, Primary Health Centre, all the injuries on the person of Sucha Singh were of simple nature, caused with a blunt weapon. No cognizable offence was made out from the report of Shri Sucha Singh and the medical examination report. Shri Ravinder Singh was, however, arrested u/s 107/151 Cr. P. C. in order to maintain peace between the parties and is at present on interim bail. It is incorrect that Shri Sucha Singh was not allowed to move out of his house for 3 days by Shri Ravindar Singh or his men. The land in question was not under the illegal possession of Shri Ravindar Singh or his father. It was evacuee land allotted to them and was auctioned for non-payment of loan obtained by them from the Goverment. There is no unrest or terror among the Harijans of the ilaqa.

CALL—ATTENTION NOTICE

(Serial No. 114)

Sarvshri Ajaib Singh Sandhu and Shamsher Singh Josh, regarding acquisition of nearly two thousand cultivated evacuee land of village Fatehpur Bhagalan, Tehsil Rupar, district Ambala, by the Forest Department.

An evacuee area of 871 and 461 acres of village Fatehpur and Bhaglan respectively has been transferred on payment by the Rehabilitation Department to the Forest Department in the year 1961 for raising of economic plantation thereon. Out of this area an area of about 286 acres is under cultivation in village Fatehpur and this area is under illegal possession of the Harijans. They are likely to be ejected after the mutation regarding transfer of ownership in their revenue records from the Rehabilitation Department to the Forest Department is sanctioned. As the area in question has been purchased by the Forest Department for a specific purpose i. e. for raising economic plantation, it cannot be transferred to the Harijans.

Statement in respect of Call Attention Notice No. 124 moved by Sarvshri Ajit Kumar and Net Ram, M. L. A.s regarding termination of 55 Sweepers by Municipal Committee, Phagwara.

The Divisional Inspector Local Bodies, Jullundur, who visited the Municipal Committee, Phagwara for making an inspection in April, 1965, observed that in spite of the increased expenditure on establishment, there had been no planning in the matter of creation of posts, and that while statutory posts of Municipal Engineer, Secretary, Health Officer and Octroi Inspectors had been eliminated, highly excessive expenditure was being incurred on conservancy staff. He further added that there was an army of Bhishties and recommended that 75% of the posts of the water carriers could be safely retrenched. He also advised, that the strength of Sweepers should also be suitably reduced. He also suggested to the Government that the Deputy Commissioner may be asked to invoke the provision of Section 42 of the Punjab Municipal Act, 1911, for the reduction of

extra conservancy staff as the Committee might be reluctant to do so due to fear of agitation. The State Government advised the Deputy Commissioner to take suitable steps for complying with the recommendations of the Divisional Inspector Local Bodies.

2. The Municipal Committee, Phagwara, in order to implement the recommendations of the Divisional Inspector, Local Bodies decided vide its resolution No. 55 dated 28th June, 1965 to abolish 30 posts of water carriers and in compliance thereof issued one month's notice to 29 junior-most water carriers (one post being vacant). The Municipal Committee, Phagwara, received a copy of the proceedings of the meeting of Sweepers Union held on 26th July, 1965, in which the Union, inter alia demanded that the notices issued to 30 water carriers for retrenchment be withdrawn.

3. The Sweepers of Municipal Committee, Phagwara, proceeded on strike with effect from 3rd August, 1965 which was held to be illegal by the Labour Department as the Union did not give 14 days notice, before proceeding on strike, as required by Section 22 of the Industrial Disputes Act, 1947. In order to prevent any deterioration of the cleanliness of the town, the President of the Committee vide his order dated 3rd August, 1965 engaged 27 new Sweepers for a period of six months. During the period of strike, the Municipal Committee, Phagwara, asked 55 'Striking' sweepers specifically and others in general, to resume duty failing which action would be taken against them under Section 45(2) and 45(3) of the Punjab Municipal Act, 1911. As the Sweepers did not resume duty, in spite of the notice given by the Committee, it decided vide resolution No. 118 dated 10th August, 1965 to terminate the services of 55 sweepers for absenting themselves from duty without reasonable cause and also decided to prosecute them under Section 45(3) of the Punjab Municipal Act.

4. On the 12th of August, 1965, Shri Chand Ram, Minister for Justice and Welfare visited Phagwara. On his advice, the Sweepers agreed to withdraw the strike unconditionally. It was also decided that the outstanding issues shall be decided by the Deputy Commissioner, Kapurthala, who would act as arbitrator. The Municipal Committee, Phagwara, on the suggestion of Deputy Commissioner, Kapurthala resolved vide its resolution No. 121 dated 16th August 1965, to keep in abeyance the execution of resolution No. 118 dated 10th August, 1965 regarding termination of services of 55 sweepers as the matter was under arbitration by the Deputy Commissioner, Kapurthala.

5. The Municipal Committee, Phagwara, vide its resolution No. 163 dated 18th October, 1965 apprehending that the Deputy Commissioner, Kapurthala, was not going to allow the Municipal Committee to retain 27 sweepers employed by them during the strike, decided to withdraw from the commitment made in resolution No. 121 dated 16th August 1965 regarding keeping in abeyance of resolution No. 118 dated 10th August, 1965 in regard to the termination of services of 55 sweepers and also decided that resolution No. 118 dated 10th August, 1965 terminating the services of 35 sweepers be implemented with effect from 27th October, 1965. In view of this resolution, the Municipal Committee, Phagwara, issued notices to 55 sweepers intimating them that their services would be treminated with effect from 27th October, 1965, and one month's wages in lieu of one-month notice would be adjusted. The Deputy Commissioner, Kapurthala, vide his order dated 26th October, 1965 passed u/s 232 of Puujab Municipal Act, 1911, suspended the execution of Resolution No. 163 dated 18th October, 1965, consindering it to be contrary to the interests of the public and likely to endanger peace and incur lawlessness. When it came to the notice of Government that the Municipal Committee, Phagwara, without awaiting the award of arbitration had decided to terminate the services of 55 sweepers, it advised the President, Municipal Committee, Phagwara on 26th October, 1965 to defer implementation of Resolution No. 118 dated 10th August, 1965 read with resolution No. 163 of 18th October, 1965. Later when it came to the notice of Government that the Deputy Commissioner, Kapurthala had announced the award of arbitration on 27th October, 1965 in favour of sweepers, Government on 29th October, 1965 withdrew the aforementioned stay orders, thus leaving the parties to act in accordance with the award.

6. When it came to the notice of Government that the Committee did not inted to comply with the terms of the award and that, instead, they had decided to terminate the services of 55 sweepers, the Sub-Divisional Officer (Civil)

[Chief Parliamentary Secretary]

Phagwara was asked to send the explanation of the Municipal Committee, Phagwara, with his comments thereon. The Municipal Committee, in their explanation has stated as under—

(i) that the Sweepers Union should not have gone on strike when they specifically stated that they would not make any demand for a pariod of 5 years; when their emoluments were raised to Rs. 50 in 1962;

(ii) that the committee did not initiate any action at its own will for the reduction of Saffair staff but merely acted on the advice of the Divisional Inspector Local Bodies and the Government ;

(iii) that the strike staged by the Sweepers Union had been held illegal by the Labour Department as the sweepers went on strike without giving any notice of 14 days before proceeding on strike as required by Section 22 of the Industrial Disputes Act, 1947 ;

(iv) that the committee was bound to keep in service 27 sweepers engaged in place of 55 sweepers who had gone on strike and absented themselves from duty without reasonable cause ;

(v) that the committee did not annul or rescind its resolution No. 118 dated 10th August, 1965 but as a gesture of good will had only kept the decision of terminating the services of 55 sweepers, in abeyance ;

(vi) that the committee accepted the arbitration of Deputy Commissioner, Kapurthala on the pre-condition that it would have no repurcussion on the appointment of newly engaged 27 sweepers ;

(vii) that the committee reviewed its decision as the Deputy Commissioner Kapurthala was not appointed as arbitrator and no agreement containing reference was executed under any of the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, or arbitration and no ragular proceedings were held till 18th October, 1965;

(viii) that the arbitrator has left the parties to accept or reject the decisions contained in his award of 27th October, 1965;

(ix) that the emoluments of the sweepers and water carriers were raised to Rs. 100 i. e. Rs. 97½ as pay plus Rs 2.50 N.P. as broom allowance from Rs 50 as in 1962.

7. The Sub-Divisional Officer (Civil) Phagwara, is of the view that if the Sweepers Service Rules are adopted, the maximum strength of sweepers would be 92 for the Committee, and that this number can at best be increased to 100, keeping in view the leave reserve quota. He is of the confirmed view that reduction of superfluous staff will have to be made from the existing strength of 155, besides 27 sweepers employed recently; and he has suggested that it should be carried out by stages i. e. elimination by medical test, elimination by natural process of death and retirements, and elimination by resignations and removals. The Sub Divisional Officer (Civil) has further stated as a result of Pakistani aggression the financial position of the committee has deteriorated and its income from octroi source has practically come down to zero and so is the case in other taxes and he apprehends that if steps are not taken to curtail the establishment expenditure, it would not be possible for the committee to meet its liabilities.

8. The Deputy Commissioner, Kapurthala, has, however, suggested that the committee may be superseded as it is not willing to accept the award given by him.

9. It will be seen that the Municipal Committee are contesting the validity of the award given by the Deputy Commissioner, which, inter alia, provides for retrenchment of the aforementioned 27 sweepers, for whose retention the Municipal Committee considers itself honour-bond for the reasons that they had come to the rescue of the town when its sanitation was suffering as a result of the strike by the sweepers, which strike was held to be illegal. The Deputy Commissioner in the concluding para 6 of his award dated 27 October, 1965 has said as under :—

"6. To conclude, I want to make it clear that I give the above decisions purely in the capacity of an Arbitrator and not in my capacity of the Deputy Commissioner, Kapurthala, exercising any of the powers enjoyed by me or delegated to me by Government under the Punjab Municipal Act, 1911. It is, therefore, up to the two disputing parties, namely, the Municipal Committee, Phagwara, on the one side and the Sweepers Union Phagwara on the other, to accept them or to reject them and I do not commit myself to implement any of those decisions in my capacity of the Deputy Commissioner according to the provisions of the Punjab Municipal Act, 1911. I, however, sincerely believe that in the public interest both the parties would accept these decisions with the same grace with which they had accepted the advice of Shri Chand Ram, Minister, Welfare and Justice Department, Punjab, on the 12th August, 1965". Though the Deputy Commissioner is not sure of the bounding nature of this award, yet the Government expect and propose to ask the Municipal Committee to act according to the terms of the award. In fact, the Government has already expressed them themselves on these lines in their recent communication to the Municipal Committee. It has also come to the notice of the Government that the 27 sweepers, mentioned above, have filed a civil suit in the court of Sub Judge, Phagwara against the Municipal Committee, Phagwara, wherefrom they have obtained an interim injunction against the Municipal Committee for not removing them from service in accordance with the terms of the award. The legal aspect of the question will be got examined by the Government from the Legal Remembrancer.

AJMER SINGH,

Local Government Minister,
Punjab.

FIFTH REPORT OF THE BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

Deputy Speaker : I have to report the time table fixed by the Business Advisory Committee in regard to the business for the House. The Fifth Report of the Committee reads—

The Committee, after some discussion, recommended that—

(i) on Thursday, the 18th November, 1965, instead of non-official business, the following motions shall be taken up—

(a) Motion regarding discussion of the Eleventh Annual Report and Accounts of the Punjab Financial Corporation for the year ended the 31st March, 1964,

(b) Motion regarding discussion of the First Annual Report and Accounts of the Punjab Export Corporation Ltd., for the year 1963-64 [Two hours for (a) and (b)], and

(c) Motion under Rule 84 regarding discussion of the leasing of land at Rupar to Birla Brothers (Two hours), and

(ii) on Friday, the 19th November, 1965, instead of Government business, non-official business, as already allotted for Thursday, the 18th November, 1965, shall be taken up.

Chief Parliamentary Secretary (Shri Ram Partap Garg) : Madam, I beg to move—

That this House agrees with the recommendations contained in the Fifth Report of the Business Advisory Committee.

Deputy Speaker : Motion moved—

That this House agrees with the recommendations contained in the Fifth Report of the Business Advisory Committee.

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ (ਲੁਧਿਆਣਾ ਉੱਤਰ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਦੁਖ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਨੂੰ ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ । ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਦਫਾ ਇਸ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਹੀ ਚਲਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਗਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਕਲ੍ਹ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਕਲਾਜ਼ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ ਔਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਿਨਾਂਸ ਮਨਿਸਟਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਹਾਉਸ ਨਾਲ ਮਖੌਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਮਖੌਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ । (It is not proper on the part of the hon. Member Babu Bachan Singh, to oppose this motion since he himself is a member of the Business Advisory Committee and, therefore, a party to the decision taken by that Committee.)

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਲ੍ਹ ਉਥੇ ਸੀ । ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਇਕ ਇਨਵਾਈਟੀ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ । ਜੇਕਰ ਕਲ੍ਹ ਮੈਂ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਤਨੀ ਡੀਫੈਕਟਿਵ ਰੀਪੋਰਟ ਕਿਦੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰਦੇ । ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿਲ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੀ ਮਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ........

ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਰੇਟਰੀ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ । ਬਾਬੂ ਜੀ ਕੀ ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ ਕਲ੍ਹ ਦੀ ਕਾਰਵਾਹੀ ਹੈ ਜੋ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ?

उपाध्यक्षा : यह रिपोर्ट पर बोल रहे हैं। (He is speaking on the report.)

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤਕ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਨਾ ਕਰ ਲਵਾਂ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ।

उपाध्यक्षा : कल जब बिज़निस एडवाईज़री कमेटी की मीटिंग का नोटिस दिया गया था तो मुझे यह अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आपोजीशन के मेम्बर ए से लेकर जैड तक कोई भी यहां मौजूद नहीं था और दफतर वाले सब को ढूंढते रहे और कोई भी न मिला । (I am constrained to tell the House that yesterday when notice for the meeting of the Business Advisory Committee was to be circulated, none of the Opposition Members was present here and the office could not contact any one of them inspite of their best efforts.)

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ behind the scene ਗਲਾਂ ਹਨ ਉਹ ਮੈਂ ਇਥੇ ਲਿਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ । ਲੇਕਨ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਕਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਅਜ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ । ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੌਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰੀਪੋਰਟ ਨੈਚੁਰਲ ਸੀ । ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ ।

उपाध्यक्षा : मेरे नोटिस में यह बात नहीं आई थी । (This had not come to my notice.)

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਕਲ੍ਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਹਿਰੀਕ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬਿਲ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਘਟੋ ਘਟ ਇਕ ਹਫਤਾ ਹੋਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਇਕ ਹਫਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਡਿਕਟੇਟਰ-ਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਥੇ ਵੀ ਡਿਕਟੇਟਰ ਸ਼ਿਪ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਥੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਿਲ ਤੇ ਖੁਲ੍ਹੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚਲਣ ਦੇਣ । ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੜਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸਿਅਲ ਬਿਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੇ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਲਗੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਕਲਾਜ਼ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਹੈ । ਕਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਵਿਚ ਇਕ ਕਲਾਜ਼ ਪਾਸ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ਿਆਲ ਸੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਉਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕਲਾਜ਼ਾਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀਆ ਕਨਟ੍ਰੋਵਰਸ਼ਿਅਲ ਹਨ । ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਮਰਸ਼ਿਅਲ ਕਰਾਪਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਾਊਸ ਮੁਖਾਲਫ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ । ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਬਜ਼ਿਦ ਹਨ ਔਰ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਮੇਈਅਰ ਲੈ ਆਈ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ।

[ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ]

ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਅਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਚੌਧਰੀ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਜ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਲ ਅਟੈਨਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਹਾਊਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਡਿਤ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ 14 ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਸਖਤ ਕਰ ਕੇ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਦਫਾ 84 ਥਲੇ ਇਕ ਦਿਨ ਲਈ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਤਰਲੇ ਕਰਣ ਦੇ ਗੌਰਨਮੈਂਟ ਚੌਥੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਪਲਾਨ ਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ..

मुख्य मंत्री : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मेडम। मेरी अर्ज़ यह है कि इस वक्त जनरल सेल्ज़ टैक्स एमेंडमेंट बिल पर बहस हो रही है और इस में चौथी पांच साला प्लान और नहरी पानी कहां से आ जाते हैं। जिन के बारे में बाबू जी बोल रहे हैं। इस लिए मैं आप से दरखास्त करता हूं कि आप इस बारे में रूलिंग दें और इस बहस को खत्म करें जो यह गैर मुतल्लिका कर रहे हैं।

चौधरी देवी लाल : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मेडम मुझे इस में बड़ा अफसोस है और मैं आप की रूलिंग चाह रहा हूं कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहिब को यह भी पता नहीं कि इस वक्त बाबू बचन सिंह बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी की रिपोर्ट पर बोल रहे हैं। और सेल्ज़ टैक्स का यहां पर कोई सवाल ही नहीं है। इस वक्त हाउस के सामने बिज़नेस ऐडवाईज़री कमेटी की रिपोर्ट है हाउस के सामने। बाबू जी उस की मुखालिफत कर रहे हैं और चीफ मिनिस्टर साहिब फरमा रहे हैं कि वह बोल काहे पर रहे हैं। वह चीफ मिनिस्टर हैं, लीडर आफ दी हाउस हैं अगर इनको इतना भी पता नहीं तो यह लीडर रहने के कैसे फिर हो सकते हैं इस बारे में मैं आपकी रूलिंग चाहता हूं ?

11 a. m.

उपाध्यक्षा : बाबू जी वाइंड अप करें। बस अब यही बात ठीक है। (The hon. Member Baboo Bachan Singh may please wind up his speech.)

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਦਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਕੋਈ ਹੀਰ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਵਰਗਾ ਸੁੱਤਾ ਸੁੱਤਾ ਜਾਗ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਇਕ ਹੀਰ ਦੀ ਵੀ ਲਾਦੇ। (ਹਾਸਾ)

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜ੍ਹੇ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੋ (The hon. Member is a very wise person.) (ਵਿਘਨ)

ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ : ਇਹ ਸਤਰਿਆਂ ਬਹਤਰਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗਲਾਂ ਕਰਨ ਲਗ ਪਏ ਹਨ। (ਵਿਘਨ)

ਪੀਲੀ ਭੀਤ ਇਹ ਹੀਰ ਸੁਣਨ ਹੀ ਗਏ ਸਨ ?

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਤੂੰ ਵੀ ਚਲ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਊਂਗਾ ।

(ਵਿਘਨ)

ਤੇ ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਬਾ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਾਊਸ ਪਾਸੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਲ ਹੈ । ਉਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਲਿਆਵਣਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ । ਫਿਰ ਜੋ ਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਰੁਪਿਆ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਡੈਫਰ ਕਰਾ ਲਈ । ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੈ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ । ਇਹ ਜੋ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬਿਲ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਘਟੋ ਘਟ 7 ਦਿਨ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਅਗਰ ਕੈਸ਼ ਕਰਾਪਸ ਦੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ । ਡੈਫਰਡ ਬਿਲ ਨਾ ਆਉਣ । ਚੌਥੀ ਪਲੈਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਫਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਹਾਉਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ । ਤਿੰਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ !

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਰੂਲ ਤਾ ਪੜ੍ਹ ਲਉ । ਕਿਸੇ ਮੋਸ਼ਨ ਤੇ 5 ਮਿਨਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੋਲਣ ਤੇ (Let the hon. Member may read rule 37. No Member can speak for more than five minutes on such a motion. After all there is some limit to his speech.)

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਮਿਨਟ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਉ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਪੰਡਤ ਮੋਹਨ ਲਾਲ

श्री मोहन लाल (बटाला) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं इस कन्वैनशन को जानता हूं कि बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी की युनानीमस रिपोर्ट पर बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता । अगर यह रिपोर्ट बाज़या होती तो मैं इस पर कुछ भी न कहता यह पांचवीं रिपोर्ट है और यह भी उतनी ही मोमल है जितनी कि पहली हमारे सामने आती रही है । इस में दो बातें कहीं गई हैं । एक तो यह कि 18 तारीख को नान-आफिश्यल बिजनैस की जगह पर आफिश्यल बिजनेस होगा और 19 तारीख को नान आफिश्यल डे होगा । इस से कुछ पता नहीं चलता कि सरकार के माइंड में क्या है और बिजनैस ऐडविजरी कमेटी ने क्या फैसला किया है । अभी सेल्ज टैक्स के बिल पर अमैंडमैंटस की बहस जारी हैं । एक बिल और आने वाला है । मैं नहीं जानता कि वह आज खत्म होंगे या नहीं । अगर नहीं होंगे तो उनके बारे में क्या पोजीशन होगी । आपने 18 तारीख को कुछ रिपोर्टस पर बहस रखी है, 19 को नान आफिश्यल बिजनेस रखा है । मगर जो बिजनेस बाकी रह जायगा उस का क्या बनेगा । यह बात साफ नहीं है । जब ऐडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट हाउस के सामने आए तो मैम्बरान को पता लगना चाहिए कि किस दिन को सैशन खत्म होगा । पहले भी चार दफा हाउस के ऐडजर्न होने

[श्री मोहन लाल]

की बात होती रही है तो कुदरती तौर पर मैम्बरान के दिल में यह बात उठती है। उन की कुछ मुश्कलात हैं, कुछ ऐंगेजमैंट्स होती हैं। इस लिये इस बात की आखिरी तौर पर वज़ाहत होनी चाहिए कि यह सैशन कब तक चलेगा, किस दिन खत्म होगा और अगर आज कोई बिल रह जाता है तो क्या उस को छोड़ दिया जायगा या फिर हाउस में लाया जायगा। अगर लाया जायगा तो किस दिन। यह बहुत बड़ा लैकुना है इस रिपोर्ट में। मैंने यह बात इस लिये आप के सामने रखी है ताकि यह साफ हो जाए। इस को एडाप्ट करने में मुझे रत्ती भर भी एतराज़ न होता अगर यह लैकुना इस में न होता।

चौधरी राम सरुप : आप इस को पढ़ लें इस में कहीं नहीं लिखा है कि 17 तारीख को क्या होगा या छुट्टी होगी।

उपाध्यक्षा : यह पहले तय हो चुका है। (This has already been decided.)

चौधरी राम सरुप : कुछ तय नहीं हुआ, हमें कुछ नहीं पता।

परिवहन तथा निर्वाचन मन्त्री (सरदार गुरदयाल सिंह ढिल्लों) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, बिजनेस ऐडवाइज़री कमेटी की रिपोर्ट हाउस के सामने है जैसे कि यह पहले आती रही है। उसने कुछ सजैशन्ज़ दी हैं। जब यह सैशन शुरू हुआ तो 22 सितम्बर तक इस को आपोज़ीशन की मर्जी से रखा गया। उस के बाद जब कहा गया तो दो दिन और दिये गए....

बाबू बचन सिंह : हम ने नहीं कहा।

परिवहन तथा निर्वाचन मन्त्री : बाबू जी जब आप बोलते हैं तो मैंने कभी दखल नहीं दिया। उस के बाद 25, 26 तारीख के दो दिन और रखे गए, फिर काम न खत्म हुआ तो तीन दिन और रखे मगर तब भी नहीं खत्म हुआ तो इस महीने के पहले हफ्ते में फिर रखा मगर फिर भी काम न खत्म हुआ तो 15, 16 तारीख को रखा। आप को मालूम है कि दो दिन की बात थी। मगर इस बिल पर इतने दिन लगे हैं। इसी तरह से दूसरे बिल पर भी लगे थे। जब देश में एमरजैंसी हो, पैसे को बचाने की जरूरत होती है क्योंकि यह प्लैन और एमरजैंसी के लिये निकालना पड़ता है। यह डिफीकल्ट टाइम होता है तो सब की कोआप्रेशन की जरूरत होती है। यह बात गलत कही गई है कि यह बिल सरदार प्रताप सिंह के वक्त का था। यह हो या वह मिनिस्टरी कांग्रेस की ही मिनिस्टरी है, कोई फरक नहीं है। (हंसी) (विघन) जो कुछ वह छोड़ गए हैं वह हमने इनहैरिट किया है। फिर यह व्यापारियों के साथ पूरी तरह बातचीत कर के उनकी तसल्ली करा के लाए हैं। जिन पर इस ने लागू होना है उन की

तसल्ली है तो फिर इस में देर क्यों लगे । इस लिये इस के लिये तीन दिन रखे । कल जस्टिस गुरनाम सिंह जी वहां मीटिंग में थे, चौधरी साहिब तो नहीं थे वहां पर यह फैसला किया गया था कि यह पास हो जाना चाहिए । इसी लिये थरसडे को नान ग्राफिश्यल काम की बजाए इस को रखा गया । फ्राइडे को नान-ग्राफिश्यल डे रखा गया ग्रौर रिपोर्ट थर्सडे को ग्रा जायगी । तो इस में कोई ऐसी बात नहीं है । बाकी चौथी प्लैन के मुताल्लिक बाबू-जी को हज़ार दफा समझाया है इस हाउस में भी ग्रौर बाहर भी कि चौथी प्लैन ग्रभी तैयार नहीं है (विघ्न) फिनांस कमिशन की रिपोर्ट नहीं ग्राई । गवर्नमैंट ग्राफ इंडिया ने चौथी प्लैन को डैफर कर किया है। सिर्फ पहले साल के लिये हम प्लैन बना रहे हैं । हम एक साल का प्लान बना रहे हैं 19 ग्रौर 20 तारीख को इस के बारे में सैंटर से बातचीत होनी है । इस को इन मैम्बरान की खाहिश को सामने रखते हुए तीन बार डैफर करना पड़ा । इस लिए ग्रभी तक फोर्थ प्लान तैयार ही नहीं हुई तो इस को इस हाउस में डिसक्शन के लिए कैसे लाया जा सकता है ? ग्रगर प्लान तैयार होती तो ग्राप सब से इसे छुपाने की सरकार को क्या ज़रूरत थी । इतने दिन यहां पर इस बिल पर ही लग गए हैं इस लिए हमें इस प्लान के बारे में डिस्कशन करने में तारीखों को बदलना पड़ा । ग्रब सिर्फ एक साल के लिए तैयार की जा रही है ग्रौर इस में देखने वाली बात है कि इतना रुपया सैंटर से ग्राना है ग्रौर इतने रुपये के लिए हमने सोरसिज़ पैदा करने हैं । यह तो हम सब के हित की बात है । पंडित मोहन लाल जी ने जैसा कहा है मैं उस से ऐग्री करता हूं कि इस बिल को कब पास करना है । ग्राम तौर पर बिल जब पास किए जाते हैं तो पार्टी ग्रपने तौर पर उस के बारे में फैसला कर लेती है इस के लिए बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी में किसी किस्म की टाइम लिमिट की ज़रूरत नहीं होती । ग्राप तो जानते ही हैं कि एक सिटिंग पर कोई 10 हज़ार के करीब रुपया खर्च ग्राता है ग्रौर ग्रगर ग्राप ग्रौर दो दिन इस बिल पर लगा लेंगे तो 20 हज़ार रुपया ग्रौर खर्च ग्रा जाएगा । इस के बारे में ग्राप सब को सोचना चाहिए कि ग्राज कल एमरजैंसी का ज़माना है ग्रौर फिर इस के को साथ ही फिनांस मिनिटर साहिब ने हाउस में एक्सपलेन भी किया है कि इस बिल को पास करना है । ग्रौर वाज़ह किया है वैदर विदिन दी पार्टी ग्रौर ग्राऊटसाइड। तो इस लिए इस रिपोर्ट को ग्रडाप्ट कर लेना चाहिए ।

ਕਾਮਰੇਡ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ (ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਬਿਲ ਲਿਆਣ ਦਾ ਸੀ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਿਲ ਲਿਆਣ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ । ਪਰ ਇਥੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਥਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਆਪ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ । ਮੈਂ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਲ ਲਿਆਣ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਰਖੀ ਗਈ ਸੀ । ਮਗਰੋਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਨੇ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਤੇ ਸੈਸ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਤੇ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ

[ਕਾਮਰੇਡ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ]

ਜਿਨੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਿਆਣ ਇਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਿਲ ਚਾਹੁਣ ਲਿਆਣ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹਕ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਠੋਸ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਹੀਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਖਿਆ ਜਾਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ ਆਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗਲ ਵਲ ਦਿਵਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੁਤਫਿਕਾ ਤੌਰ ਤੇ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਸ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਗਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਦ ਪਿਛਲੀ ਵੇਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਬਾਰੇ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਕ ਇਸ ਹਾਊਸ ਨੇ ਚਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਸਾਫ ਦਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੰਤੀ : ਜੋਗਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਲਿਆਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਕਈ ਦਿਨ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਰਖੇ ਗਏ ਸਨ।

चौधरी देवी लाल (फतेहाबाद) : डिप्टी स्पीकर साहिबा मैं बिजनंस एडवाइज़री कमेटी का मैम्बर होते भी इस बात को कहना चाहता हूं कि वाकई यह एक मुतफिका फैसला है इस लिए इसे हम मानेंगे लेकिन सवाल यह है कि ढिल्लों साहिब ने कहा है कि इस में लकूना है और इस लिए सेल्ज़ टैक्स के बिल पर वक्त लग गया है इस लिए इसे जल्दी पास कर लेना चाहिए ताकि जो और काम हैं वह भी किए जा सकें। मैं इतना कहूंगा कि कैरों साहिब के वक्त का यह बिल इन के कहने के मुताबिक है तो क्या सरकार चाहे उस वक्त भी इन के कहने के मुताबिक कांग्रेस की थी उस को बदलने में यह हमारे साथ थे अब अगर समय बदल गया है तो क्या कुरसियों के बदलने से हम किसी लाकूना को नहीं बदल सकते या दूर नहीं कर सकते। जैसा कि जोगा साहिब ने कहा है शुरू में बिजनंस एडवाइज़री कमेटी के पास इस तरह का कोई बिज़नंस नहीं था। और मैंने तो कमेटी में मज़ाक में यह भी कहा था कि बिजनैस तो कोई है नहीं तो फिर चौधरी नेत राम का पवायंट आफ आर्डर ही चलता रहेगा। आप तो जानती हैं कि सेल्ज़ टैक्स का बिल एक कण्ट्रोवर्शियल बिल है इस के बारे में ब्योपारियों ने धरना भी दिया था और सरकार से उन की बातचीत भी हुई थी फिर पता नहीं किस ढंग से यह काम को चलाना चाहते हैं। जहां तक फोर्थ फाइव ईयर प्लान का तअल्लुक है इस को जरूरी तौर पर डिस्कस करना चाहिए। इन की बात सैंट्रल गवर्नमैंट से हो चुकी है और प्लान फाइनल हो चुका है अगर अब

हाउस के सामने ग्रा जाए तो मैम्बरान की राए का इज़हार उस में हो सकेगा। यह ठीक है कि जो फैसला बिज़नस एडवाइज़री कमेटी में हो चुका है उस की मैं मुखालफित नहीं करता लेकिन यह जो गवर्नमैंट तरीका इख्तयार कर रही है इसको बदलना चाहिए ग्रौर हाउस के सामने हर बात साफ ग्रा जानी चाहिए।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ (ਮੁਰਿੰਡਾ—ਐਸ. ਸੀ.) ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜ ਤਕ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਕਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਇਕ ਕਲਾਜ਼ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀਆਂ 8 ਕਲਾਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੰਗਾ ਐਨੀ ਗਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈ ਫਿਰ ਇਸਤੇ ਤੀਜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਕਮਰਸ਼ਲ ਕਰਾਪ ਸੈਸ ਬਿਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਰੀਡਿੰਗਜ਼ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਕ ਹੈ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿਉਗੇ ਕਿ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਬੋਲੋ ਜਾਂ ਦੋ ਮਿੰਟ ਬੋਲੋ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਲੇਜਿਸਲੇਟਿਵ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਗਿਆ।

उपाध्यक्षा : 16 तारीख को जो बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी की मीटिंग हुई उस में मैं हाज़िर थी ग्रौर तीन दिन बाद 19 तारीख को मैं मासको चली गई उस वक्त यह ख्याल था कि सभा 22 तारीख के करीब उठ जाएगी पर मेरे रूस वापिस ग्रानें पर मुझे यह देख कर हैरानी हुई कि सभा ग्रभी तक जारी है। इस को एक महीना ग्रौर हो गया है कि सभा चल रही है। मैं ढिल्लों साहिब से एग्री करती हूं कि हम क्योंकि इस ग्रागस्ट हाउस के मैम्बर हैं हमें एक मुनासिब ढंग में कार्रवाई करनी चाहिए। (I attended the meeting of the Business Advisory Committee on the 16th October, 1965 and three days thereafter I left for Moscow. It was then expected that the House would adjourn near about 22nd of that month. However, I was surprised to learn on my return from Russia that the Sabha still continued to be in Session. It is almost another month that the Sabha has been sitting. I quite agree with Mr. Dhillon that we being Members of an august House should conduct ourselves in a reasonable manner.)

मुख्य मंत्री (श्री राम किशन) डिप्टी स्पीकर साहिबा, पार्लियामेंटरी रवायात यह हैं कि जो बिज़नस एडवाइज़री कमेटी का फैसला हो हाउस उसे विद गुड ग्रेस मनज़ूर करता है। कल की जो बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी की मीटंग हुई उस में ग्रपोज़ीशन के मेम्बर थे ग्रौर जहां तक ट्रेज़री बैंचों का तग्रालुक है हमारा सिर्फ

[मुख्य मंत्री]

एक भाई वहां पर था । और फैसले यूनानीमसली थे फिर हाउस में आ कर वही मेम्बर जो फैसला करके आए हों इस की मुखालिफत करें तो इस के बारे में बाकी के प्राविन्सों में और यहां पर लोगों की क्या राए हमारे बारे में बनेगी । मैं आप के ज़रिया इस हाउस के मैम्बरों को बिलखसूस और उन मैम्बरान को जो बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी के मेम्बर हैं कहना चाहता हूं कि वह वहां पर इंडिविजुअल तौर पर नहीं थे किसी पार्टी या गुरुप को रिप्रेज़ण्ट करते थे इस पर एतराज़ नहीं करना चाहिए और इस को अडाप्ट करना चाहिए ।

दूसरी बात डिप्टी स्पीकर साहिबा मैं फोर्थ फाइव ईअर प्लान के बारे में कहना चाहता हूं कि हम इस के बारे में सैंटर से डिस्कशन्ज़ कर रहे हैं और इस को हाउस के सामने रखने में शर्म नहीं करते हैं लेकिन जैसा कि आप जानते हैं सैंटर की तरफ से भी एलोकेशन की जाती है और पहली जो प्लान बनाई गई थी 500 करोड़ रुपया की थी । अभी तो मैं कह नहीं सकता कि सैंटर से हमें चौथे पांच साला प्लान के लिये कितना रुपया मिले । बदले हुए हालात के मुताबिक हमें जो फंडज़ मिलेंगे हमें इस बजट के अंदर प्रोविज़न करनी होगी । इस के मुताल्लिक अभी 19 और 20 तारीख को मीटिंग हो रही है जिस में सारी प्लैन का ड्राफट चाक आऊट किया जायेगा । इस लिये मैं आप को यकीन दिलाता हूं कि जब भी अगला सैशन होगा चाहे इस के लिये एक दिन रखा जाये या दूसरा दिन रखा जाये हम सब मैम्बर साहिबान को इसे डिसकस करने का मौका देंगे । हम चाहते हैं कि इस से पहले हम इसे अमल में लायें । हम चाहते हैं कि हर ग्रुप की राये आनी चाहिये ताकि तमाम भाइयों के सुझाव से पंजाब का सही नकशा बन सके । मैं इस हाउस से बड़े अदब से कहूंगा कि आप इतमीनान रखें हम जो काम करना चाहते हैं वह सब की राये कायम करके ही करना चाहते हैं ।

बाबू बचन सिंह : आन ए पांयट आफ परसनल ऐकस्पलेनेशन, मैडम । मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस मीटिंग के मुताल्लिक मुख्य मंत्री जी ने रैफर किया है इस में मैं और चौधरी देवी लाल है नहीं थे, इस लिए उन को इस मामले पर गलत फहमी हुई है ।

Deputy Speaker : Question is—

that this House agrees with the recommendations contained in the Fifth Report of the Business Advisory Committee.

The motion was carried and the Report adopted.

ANNOUNCEMENT BY SECRETARY

Secretary :

Under rule 2 of the Punjab State Legislature (Communications) Rules, 1959, I have to inform the House that the Punjab Motor Vehicles Taxation (Amendment) Bill, 1965, and the Punjab State Legislature Officers, Ministers and Members (Medical Facilities) Bill,

1965, passed by the Punjab Vidhan Sabha on the 26th October, 1965 and 3rd November, 1965, respectively and transmitted to the Punjab Vidhan Parishad have been agreed to by the said Parishad without any recommendation on the 5th November, 1965.

BILL

THE PUNJAB GENERAL SALES TAX (AMENDMENT) BILL, 1965. (RESUMPTION OF CONSIDERATION CLAUSE BY CLAUSE)

Deputy Speaker : The House will now resume discussion on the Punjab General Sales Tax (Amendment) Bill, clause by clause. Shri Fateh Chand Vij was discussing clause 12.

CLAUSE 12

श्री फतेह चन्द विज (पानीपत) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, कल मैं आप के द्वारा टैक्सेशन मिनिस्टर साहिब से यह अर्ज़ कर रहा था कि इस कलाज़ नंबर 12 की रू से हिटलराना अखत्यारात दिये जा रहे हैं । अगर आप इस मसला को सही ढंग से हल करना चाहते हैं तो इसका एक ही इलाज है कि आप इसको वापस ले लें सवर्गीय सरदार प्रताप सिंह कैरों के वक्त मैंने उन चैक पोस्ट बैरियर्ज़ की तरफ सरकार का ध्यान दिलाया था, जब कि यह बैरियर्ज़ कुरप्शन के अड्डे बने हुये थे । उन्होंने खुद दो तीन दफा दिल्ली आते जाते इन बैरियर्ज़ को चैक किया । उन्होंने खुद जाकर देखा कि वहां पर दो चार घंटे तक ट्रकों वाले खड़े रहते थे । और सिर्फ उनको आगे जाने दिया जाता था जो सौ पचास दे देते थे । इन सारे हालात को देख कर कैबनिट मीटिंग में फैसला किया गया कि यह चैक पोस्ट बैरियर्ज़ बंद कर दिये जायें । मगर आज हाउस को यह सुन कर हैरानी होगी कि इन बैरियर्ज़ को दोबारा कायम करने के लिये कैबनिट की कोई मीटिंग नहीं हुई । टैक्सेशन डिपार्टमैंट के चंद अफसरान मिनिस्टर कनसरनड को मिले और उन को अपने ढंग से समझा कर मनवा लिया और बगैर कैबनिट मीटिंग के दोबारा चैक पोस्ट बैरियर्ज़ कायम कर लिये गये । जब एक चीज़ हटाने के लिये कैबनिट लैवल तक फैसला किया गया था तो मेरी समझ में नहीं आता दुबारा इसे कैबनिट लैवल पर विचार करने की जरूरत महसूस क्यों न की गई । इस लिए मैं यह कहूंगा अगर यह कलाज़ ही वापस ले ली जाये तो अच्छा है, क्योंकि इस से नये इखत्यारात लिये जा रहे हैं ।

श्री मोहन लाल (बटाला) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं इस कलाज़ पर ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहता । मेरी नंबर 22 और 23 पर दो एमैंडमैंट्स हैं जिन को वज़ीर साहिब ने भी मान लिया है । इस लिये मैं इस पर ज्यादा सट्रैस न करता हुआ इतना ही कहूंगा कि 14-B(6) और 14-B(8) में से अगर लफज़ "and confiscate" निकाल दिये जायें तो ठीक होगा मेरे खयाल में मिनिस्टर साहिब को इस पर कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए वह ऐसा मान भी चुके हैं कि :

"In this proposed section 14—B(6), line 3, *delete* "and confiscate".

In the proposed section 14—B(8), line 5, *delete* "and confiscate".

Deputy Speaker : Motions moved—

In the proposed section 14—B (6), line 3, delete "and confiscate".

In the proposed section 14—B(8), line 5, delete "and confiscate'i.

ਵਿਤ ਮੰਤ੍ਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ) : ਜਿਹੜੀਆਂ 22 ਔਰ 23 ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਪੰਡਤ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ।

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ (ਲੁਧਿਆਣਾ ਉੱਤਰ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਅਮੈਂਡਿੰਗ ਬਿਲ ਦੀ ਦਫਾ 12 ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਰੋਜ਼ ਦਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਉਪਾਰੀ ਭਰਿਸ਼ਟਾ ਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਇਹ ਆਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇਕ ਅਡਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਹ ਬੈਰੀਅਰਜ਼ ਦੇ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੈਰੀਅਰ ਦਾ ਇਨਚਾਰਜ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਇਖਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਉਪਾਰੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਉਤਰਾ ਲਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਬਕਸਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਖਾ । ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੌਕੇ ਦਾ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਬਿਉਪਾਰੀ ਦਾ ਆਦਮੀ, ਟਰਕ ਡਰਾਈਵਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਖਜਾਲਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਕੋ ਇਕ ਸਵਾਲ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਇਹਦਾ ਮੂਹ ਮੱਥਾ ਝੁਲਸਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੀ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ । ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਮਸਾਲਾਂ ਹਨ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੀਅਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਥੇ ਜਿਸ ਮਤਲਬ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਨਚਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ੨ ਸਾਲ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਵੀਜ਼ਨ ਰਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਰਾਹੀਂ ਸਾਮਾਨ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਸਲ ਮੰਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਵਾਲਾ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਟਰਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਆਫਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

ਗਵਰਮੈਂਟ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਉਪਾਰੀ ਇਵੇਜ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਿਉਪਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਵਰਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਅਨਡਿਊ ਹੈਰੈਸ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ । ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਛੋਟੇ ਬਿਉਪਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਅਲਗ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗਵਰਮੈਂਟ ਇਕ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਵਿਚ ਦਰੁਸਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ।

ਮੈਨੂੰ ਦੁਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਤਿਆਰ ਸ਼ੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਆਪ ਮੰਨਿਆਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੇ ਵਕਤ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੂੰ ਕੁਰਪਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਉਸੇ ਵਕਤ ਦਾ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹੋ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਗੌਰਮਿੰਟ ਵਰਤਦੀ ਸੀ।

ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੰਤਰੀ : ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਮੈਂ ਪੁਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਉਹ ਆਪੋਜ਼ੀਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ? ਜਨਾਬ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ 12 ਦਫਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਫਾ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪਲੇਗਾ। ਹਰ ਇਕ ਆਦਮੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਕਲੀਨ ਐਡਮਿਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀ ਐਡਮਿਨਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਤਨੀ ਹੀ ਕੁਰਪਟ ਹੈ, ਜਿਤਨੀ ਕਿ ਪੁਰਾਨੀ ਗੌਰਮਿੰਟ ਸੀ

ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੈਰੀਅਰਜ਼ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਪੁਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਨਜ਼ਿਊਮਰ ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਬਿਉਪਾਰੀ ਤਾਂ ਕੁਲੈਕਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲੈਕਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਨਰੇਬਲ ਸਲੂਕ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਉਹ ਚੋਰ ਹਨ ਤਾਂ ਕੁਲੈਕਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਕਿਉਂ ਰਖਿਆ ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚ ਫਿਤਰਤਨ ਆਦਮੀ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੈਯਰਜ਼ ਲਿਆਕੇ ਚੋਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਸੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਆਏ, ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਕੀਤੀ ਮਗਰ ਜਿਸ ਮਾਰਕੇਟ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਉਥੇ ਸਿਰਫ ਦਸ ਦੁਕਾਨਾ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਕੇਟ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗਿਆ ? ਕਿ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਲਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਮਸਾਂ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੁਣ 66 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਕੇ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ, ਕਿ ਤੁਸੀ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਔਰ ਇਕ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਤਨੀ ਵੱਡੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਰੇਬਾਨ ਵਿਚ ਮੂੰਹ ਡਾਲ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਦੇ ਕਲੀਨ ਤਰੀਕੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੋ 12 ਵੀਂ ਕਲਾਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਸਵਾਏ ਨਾਕਾ ਬੰਦੀ ਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੋਰਾਂ ਦੀ, ਡਾਕੂਆਂ ਦੀ. ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰੀਫ ਬਿਉਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਲਖਪਤੀ ਹਨ ਈਮਾਨਦਾਰ ਹਨ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਕਿ ਇਹ

(ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ)

ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਜਿਤਨੀ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ । 12 ਦਫਾ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਬਿਉਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਰਾਉਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ, ਵਿਊਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਊਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਬਿਉਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਐਪ੍ਰਿਸ਼ਿਏਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦਸ ਸਕਦਾ ਮਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀਤਾ । ਕੀ ? ਇਕਰਾਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇਨਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ । ਔਰ ਉਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦਫਾ 12 ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿਕੰਜੇ ਪਰ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਿਆ ਹੈ । ਔਰ ਬਿਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਜਗਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ।

ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਉ ਫੇਰ ਕਦੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ । ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ, ਔਰ ਇਕ ਰਾਉਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬਿਉਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਫੇਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੰਗਾ ਬਿਲ ਲਿਆਉ, ਤਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਾਹਵਾ ਹੋਵੇ, ਵਰਨਾ ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਰੀ ਵਧੇਗੀ, ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਵਧੇਗੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਇਸ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਮੈਂ ਫੇਰ ਇਲਤਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ ।

ਸ੍ਰੀ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਅਗਰਵਾਲ (ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ. ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਜੋ ਲੂਪਹੋਲ ਲਭਦੇ ਹਨ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਕਈ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਲੂਪਹੋਲ ਨੂੰ ਪਲੱਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪਲੱਗ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਥੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਈਵੇਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਗੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਨਾਈਵੈਂਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਕਲਾ ਵਪਾਰੀ ਈਵੇਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਕ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਸ ਨਾਲ ਨਾ ਰਲਿਆ ਹੋਵੇ । ਅਸੀਂ ਉਸ ਈਵੇਜ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਥੇ ਇਕਲੇ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਛਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ । ਜੇ ਇਸ ਈਵੇਜ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ 100 ਛਾਪੇ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤਾਂ 10 ਛਾਪੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣ । ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦੀ ਈਵੇਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਮਾਲ ਨੂੰ ਸੀਜ਼ ਜਾਂ ਕਨਫਿਸਕੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ 1,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲ ਕਨਫਿਸਕੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਰ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ 500 ਰੁਪਿਆ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮਾਲ ਨੂੰ ਪਰਾਪਰਲੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਰਾਪਰਲੀ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਥ ਵਿਚ ਨਹੀਂ । ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਾਈਡ ਪਾਵਰਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਓਨੀ

ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਵਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨੇ ਇਹ ਗਲ ਇਟਸੈਲਫ ਸਪੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਨਐਫੀਸ਼ੈਂਟ ਹੈ । ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਮੈਈਰਜ਼ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਜਿੰਨੇ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਵਧਾਈ ਜਾਓਗੇ. ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਪੈਂਤਮੈਂਟਸ ਵਧਾਈ ਜਾਓਗੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾਵਰਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਈਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗੀ । ਕੁਛ ਰੈਵਿਨਿਊ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਕਿਟ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ । ਕੁਛ ਲੋਕ ਇਸ ਗਲ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਏਥੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਾਹਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ । ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਲੁਕੀ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਵਾਰ ਨੇ ਪਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ । ਜੋ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਏਥੇ ਧੱਕਾ ਲਗਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ । ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ੋਨ, ਖਾਸ ਕਰ ਬਾਰਡਰ ਜ਼ੋਨ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ । ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਪਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਤਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੋਰ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਫਲੋ ਲਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਹੋਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੇਗਾ । ਕਈ ਦਫਾ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਨੀ ਸਖਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੈਵਿਨਿਊ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿ ਰੈਵਿਨਿਊ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹੀ ਬਾਗ ਡੋਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਇਕ ਇੰਚ ਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰਨਾ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਘਟ ਜਾਏਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੈਵਿਨਿਊ ਘਟ ਜਾਏਗਾ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹੋਵੇ ਉਲਟਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ । ਮਾਲ ਨੂੰ ਸੀਜ ਜਾਂ ਕਨਫਿਸਕੇਟ ਕਰਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲ ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ । ਨਾ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਕਈ ਦਫਾ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਵਿਚ ਦੇਰ ਲਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਮਾਲ ਸੀਜ਼ ਜਾਂ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਮਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਬੋਰੀਆਂ ਫਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪੇਟੀਆਂ ਟੁਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ । ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਣ ਕਣਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਭਿਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਇੰਨਟੈਲੀਜੈਂਸ ਚੈਕ ਕਰੇ । ਮਾਲ ਸੀਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਧ ਜਾਏਗੀ । ਜਦੋਂ ਡੇਢ ਜਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਕਲੇਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲ ਤਾਂ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰਾਪਰ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਲ ਦੀ ਪਰਾਪਰ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਪੜਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਹ ਸੀ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਧੇਗੀ ਕਿ ਮਾਲ ਨੂੰ ਸਿਉਂਕ ਲਗ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਡੈਮੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਧੇਗੀ, ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਉਲਟਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ । ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਛੀ ਗੱਲ ਹੈ । ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂਫਕਚਰ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਪਰਾਵਿੰਸ ਵਿਚ ਇੰਟਰ ਹੋਵੇ ਐਸੀ ਫਰਸਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ । ਜਿਥੇ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਓਥੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਲਗੇ ਹਾਲੇ ਤਕ ਫਰਸਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜੋ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਲਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸੂਗਰ ਅਤੇ ਕਪੜੇ ਤੇ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਫਰੀ ਫਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ

[ਸ੍ਰੀ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਅਗਰਵਾਲ]

ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਜਿਥੇ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਓਥੇ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਐਡ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਹ ਗਲ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਸਾਰਾ ਪਰੋਸੈਸ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਐਲਿਮੀਨੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਨਿਹਮਤ ਹੈ ਜੇਕਰ ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਿਥੇ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਨਾਲ ਫਰੀ ਟਰੇਡ ਚਲੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਟੈਪ ਨਾ ਲਈਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਏਥੋਂ ਦੀ ਟਰੇਡ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਥੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਹਵੇ ਉਸ ਤੇ ਉਥੇ ਹੀ ਟੈਕਸ ਲਗ ਜਾਵੇ (ਵਿਘਨ) ਵਿਦਡਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਓਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ । ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਪਰ ਤੇ ਟੈਕਸ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗੇਗਾ । ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿਲੀ ਵਿਚ ਕਾਪੀਆਂ ਬਨਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ । ਪੇਪਰ ਦੀ ਟਰੇਡ ਏਥੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਈ। ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਪੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨੈਸ, ਦਿਲੀ ਯੂ. ਪੀ ਜਾਂ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਵੇ । ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫਿਨਾਂਸ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਖਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ । ਸਖਤੀ ਘਟਣ ਨਾਲ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ । ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਕਨਾਈਵੈਂਸ ਨਾਲ ਈਵੇਜ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈਕ ਕਰਨ । ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਲੇਮੈਨ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਲਓ ਅਤੇ ਅਗਰ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਬਣੈਣਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਉਸ ਨੇ ਕਲ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਸ ਸਕੇਗਾ । ਜਿਹੜਾ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਹੈਰਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏ ਉਹ ਇਕਦਮ ਹੈਰਿਸਡ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਛਾਪਾ ਮਾਰਨਾ ਇਟਸੈਲਫ ਗਰੇਟ ਹੈਰਸਿੰਗ ਹੈ । ਉਹ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਪਰਾਪਰਲੀ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਸਹੀ ਗਲ ਗਲਤ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਫੇਰ ਨਾਲ ਐਨੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਲੈ ਜਾਣਾ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਸਿੰਗ ਹੈ । ਵੈਸੇ ਇਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਡਿਸਟਰਿਕਟ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਜਾਏਗਾ । ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਸੋਚਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਖਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ, ਮਹਿਕਮੇਂ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬਦਨਾਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਣਾਓ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੇ ਪਰਾਪਰਲੀ ਅਮਲ ਹੋਵੇ । ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਮੇਰੀ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵਕਤ ਦਿਤਾ ।

ਸ੍ਰੀ ਚਾਂਦੀ ਰਾਮ ਵਰਮਾ (ਅਬੋਹਰ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਕਲਾਜ਼ ਨੰ: 12 ਵਿਚ ਮੇਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਦੋ–ਤਿੰਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਹਨ । ਕਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਲਾ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਸਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਖਤੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਅਗਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੰਨ

ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਕਲਾਜ਼ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਖਤੀ ਵਾਲੀ ਗਲ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ । ਮੇਰੀਆਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਇਹ ਹਨ—

"In the proposed section 14—B(6), lines 3, *delete* "and confiscate".

In the proposed section 14—B(8), line 5 delete "and confiscate.

Delete the first proviso to the proposed section 14—B(8), and

In the second proviso to the proposed section 14—B(8), lines 2 and 4, *Delete* "or confiscation.'

इन चीज़ों को डीलीट कर दिया जाए तो इस क्लाज में जो भी सख्ती है वह खत्म हो जाती है । मेरा खयाल है इसे मानने का इशारा भी कुछ हुआ है ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਗਰਲੀਆਂ ਦੋ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਕਸੈਪਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ।

चौधरी इन्द्र सिंह मलिक (सफीदों) डिप्टी सपीकर साहिबा, मैं यह कहना चाहता हूं कि आज ही गवर्नमैंट का स्टेटमैंट आया है कि इन दिनों गवर्नमेंट को दो करोड़ रुपए का सेलज़ टैक्स की इवेज़न का नुकसान हुआ है ।यह नुकसान उन दिनों हुआ है जब कि सख्ती कम है लेकिन अब आप और सख्ती करने लगे हो और व्यापारी सोने के अंडे देने वाली मुरग़ी है उन्हें खत्म करने लग पड़े हो । अज जो आप सख्ती करने जा रहे हो इन से कहीं ज़्यादा नुकसान होगा अभी तो सिर्फ दो करोड़ का ही नुकसान हुआ है । इन लिए इन सख्ती के पैराज को डीलीट कर देना चाहिए बल्कि मैं तो कहूंगा कि इस बिल को ही वापस ले लेना चाहिए ।

इस सब क्लाज़ 2 में कहते हैं कि हर व्यापारी जो किसी वैसल या वैहीकल का इन्चार्ज है और जो उनका डराइवर है वह माल की तीन तीन लिस्टें तैयार करे गा और हर चैक पोस्ट पर उसे जो उस चैक पोस्ट का कांस्टेबल या हैड कांस्टेबल होगा उसे लिस्ट दे कर माल चैक कराना होगा और इसके साथ ही महकमा का नाट बीलो दी रैंक आफ एक्साइज़ ऐंड टैकसेशन अफसर होगा । उसे भी अखितयार होगा कि माल देखे । कितनी हैरानी की बात है कि अफसर माल चैक करे तो करे लेकिन कांस्टेबल और हैड लांस्टेबल जो आम तौर पर इन पोस्टों के इन्चार्ज होते हैं उनको भी अख्तियार है कि वह ट्रक रोक कर माल चैक कर सकता है और जितना अरसा चाहे वैहीकल रोक सकता है । अगर लिस्ट में कोई गलती निकल आती है तो जितना अरसा चाहे माल को रोकं रख सकता है । अब यह इतनी भारी पावर इन कांस्टेबल और हैड कांस्टे-बल साहिबान को दे दी है कि आप देख लेना चैक पोस्टों पर लाइनों की लाइनें ट्रकों की लग जाएंगी और खूब रिश्वत का बाज़ार गर्म होगा । जो पैसे दे देगा उन को ट्रक तो बगैर चैक हुए भी निकल जाएगा और उसकी

[चौधरी इन्द्र सिंह मलिक]

गलती भी सही हो जाएगी लेकिन जो रिश्वत नहीं देगा उसका ट्रक वहां खड़ा रहेगा । इस सब कलाज़ 4 में लिखा है—

"(4) At every check-post or barrier or at any other place when so required by any other officer referred to in sub-section (2) in this behalf, the driver or any other person incharge of the goods vehicle or vessel shall stop the vehicle or vessel, as the case may be, and keep it stationary as long as may reasonably be necessary.."
....

इसका मतलब क्या है ? यही कि जो पैसे नहीं देगा उसे तंग किया जाएगा और उनके वैहीकल्ज़ को रोके रखा जाएगा । अफसर भी रिश्वत लें गे दूसरे कांसटेबल और हैड-कांस्टेबल भी हाथ रंगेगा और व्यापारी भी अपनी जान छुड़ाने के लिए रिश्वत देने पर मजबूर. होंगे । वहां पहले आते ही उनको जज़िया दे देगा । और ट्रक आगे लें जाएगा । इस लिए अगर आप चाहते हैं कि रिश्वत न चले तो आप इस चीज को वैसे ही रहने दें जैसे पहले था । आगे सब कलाज़ 5 आती है उसमें लिखते हैं—

"(5) At every station of transport of goods, bus-stand or any other station or place of loading or unloading of goods........"

इस का मतलब यह है कि यही नहीं कि चैक-पोस्ट पर रोकेंगे बल्कि जहां जिस जगह चाहें बस-स्टैंड पर लोडिंग अन लेडिंग स्टेशन पर सिपाही वैहीकल रोक लेगा । इस से तो और भी ज़्यादा रिश्वत चलेगी । इस सें तो व्यापारी बहुत हैरान होंगे और वह इतनें तंग होंगे कि या तो व्यापार छोड़ देंगे या फिर पंजाब छोड़ कर भागने पर मजबूर होंगे । फिर आगे नम्बर 6 आती है । यह तो इन्हों ने मान लिया कि कन्फिसकेशन का लफज़ डीलीट कर देंगे लेकिन आप देखें इन में क्या लिखा है—

"(6) Any officer not below the rank of an Assistant Excise and Tanation Officer while acting under this section shall have the power to seize........"

अब सीज़ करने की बात तो लिख दी लेकिन आगे यह कुछ नहीं बताया कि सीज़ करने के बाद वह माल कहां जाएगा, उस माल को कहां किस गोदाम में रखेंगा, उसकी रसीद देगा या नहीं और या क्या वह उस माल को खुद हजम कर लेगा । सीज़ की कोई आगे ऐकस्पलानेशन नहीं दी कि सीज़ करने के बाद माल का क्या बनेगा । फर्ज करो 50 हज़ार रुपए का माल सीज़ हो जाता है तो वह माल कहां रखा जाएगा, उसकी रसीद कौन

देगा या नहीं देगा और क्या वह खुद हज़म करेगा । यह जो सीज़ का लफ्ज़ है यह उड़ा देना चाहिए । फिर नम्बर 8 में लिखा है—

> "(8) Where the declaration made under sub-section (3) is false in respect of any particulars furnished therein, the officer-in-charge of the check-post or barrier or any other officer not below the rank of an Assistant Excise and Taxation Officer shall have the powers to seize "..........."

इन में भी सीज़ की बात लिख दी कि अगर लिस्ट में कोई माल इन्कलूड नहीं हो सका और चैकिंग के वक्त निकल आया या और कोई गलती निकल आई तो माल को सीज़ कर लिया जाएगा अब सीज़ करने के बाद कोई ऐक्स्पलानेशन नहीं कि सीज़ करने के बाद माल का क्या बनेगा और वह कहां जाएगा, उसकी रसीद दी जाएगी या नहीं या उस माल को खुद बेच लेगा । मैं कहता हूं कि व्यापारियों के साथ जितनी सख्ती करोगे उतनी ही ज्यादा बेइमानी होगी उतने ही ज्यादा अफ़सर बेईमान और कुरप्ट होंगे क्यों कि जहां चोरी है वहां मोरी है और जहां मोरी है वहां चोरी है । अगर ढ़ील करोगे तो थोड़ा मुनाफ़ा लेंगे नहीं तो जो रिश्वत का पैसा देंगे वह गाहकों के सिर से निकालेंगे और लूट मचेगी । फिर अगर व्यापारियों को सहूलित देंगे तो चंदे वगैरा लेने में भी आपको सहूलित रहेगी (घंटी) एक बात मैं आखिर में यह करना चाहता हूं कि आप देखलें कि यह जो जनसंघी भाई व्यपारियों का दम भरते हैं और उनका गम में रोते हैं आज कोई सीट पर नहीं बैठा है जमींदार भाई ही बैठे हैं । जो व्यपारितों के लिए भी लड़ते हैं और ज़मीदारों के लिए भी लड़ते हैं । तो मैं यही कहना चाहता हूं कि यह बिल ठीक नहीं इसे वापस ले लें तो अच्छा होगा ।

ਸਰਦਾਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ (ਬੰਗਾ): ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਗੌਰਮਿੰਟ ਕਲਾਜ਼ 12 ਦੇ

12.00 noon

ਅੰਦਰ ਵਾਸਟ ਪਾਵਰਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕੇ । ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਜਰਬੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ । ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟਰੱਕਸ ਸਾਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਰੀਅਰ ਦੇ ਪਾਸ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਚਾਲਾਨ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਉਥੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਡਿਸਟਰਿਕਟ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ੀਸਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਪਲੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸਨ । ਉਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ । ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕਿ ਡਿਸਟਰਿਕਟ ਹੈਡ ਕੁਆਟਰਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । ਇਹ ਬੰਡਲਾਂ ਦੇ ਬੰਡਲ ਬੋਰੀਆਂ ਵਿਚ ਪਏ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਵੇਖੇ ਹੀ ਪਏ ਰਹੇ । ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਟੇਕ ਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ । ਇਕ ਅਫਸਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ

[ਸਰਦਾਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ]

ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ । ਉਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗਾ । ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਦੋਂ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਈ ਕਾਰੀਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਵਧਦੀ ਗਈ । ਕੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਪਾਵਰਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿਤੀ ਸੀ ਉਸ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ । ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਲੈਕ ਬਿਲਟੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ । ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿਚ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਘਾਟਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਡਿਸਟਰਿਕਟ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਮਹਿਸੂਲ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਆਦਮੀ ਬਿਠਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਉਥੇ ਹੀ ਮਾਲ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਾਡੀ ਦੂਜੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿਉਪਾਰੀ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਛੁੜਾਉਣ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਜਾ ਰੇਲਵੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਲ ਛੁੜਾਉਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਬਿਲਟੀ ਰਲੀਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਰ ਲਗਵਾਏ । ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕੁਝ ਦੇਰ ਤਕ ਲਾਗੂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਉਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤਕਲੀਫਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਬਿਉਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਬਲਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ । ਟਰੱਕਸ ਬੈਕਰੀਅਰਜ਼ ਉਤੇ 2, ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਤਕਲੀਫ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ । ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਟਰੈਫਿਕ ਲਈ ਅਲਹਿਦਾ ਬੈਰੀਅਰ ਹੈ, ਫੂਡਗਰੇਨਜ਼ ਦੀ ਰੋਕ ਥਾਮ ਲਈ ਅਲਹਿਦਾ ਬੈਰੀਅਰ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਲਈ ਅਲਹਿਦਾ ਬੈਰੀਅਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਗੁੜਗਾਵਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਸ਼ਿਕਾਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੈਰੀਅਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਅਗਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਐਡਜੁਆਨਿੰਗ ਸਟੇਟਸ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬੈਰੀਅਰਜ਼ ਕਾਇਮ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੇਟ ਵਿਚ 5 ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੈਰੀਅਰਜ਼ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗੀ ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਈਵੇਜ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਫੈਲੇਗੀ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । (ਘੰਟੀ) ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਰੇਲਵੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕਰਾਸਿੰਗ ਪਲੇਸਿਜ਼ ਉਤੇ ਪੁਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ ਤਾਕਿ ਟਰੈਫਿਕ ਨਾ ਰੁਕੇ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੈਰੀਅਰਜ਼ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਆਣ ਜਾਣ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹੀ ਪਾਈਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਸੂਲ ਚੁੰਗੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ

ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚੋਰੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਥੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਉਥੇ ਮਾਲ ਦੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿਜ਼ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦਮੀ ਮੁਕਰੱਰ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ । ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਈਵੇਜ਼ਨ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨਜ਼ ਉਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨਗੇ ।

Deputy Speaker : Sardar Kapoor Singh, Finance Minister.

Finance Minister (Sardar Kapoor Singh) : Madam, I will speak on the third reading. Now the amendments to this Clause may be put.

Deputy Speaker : Amendment No. 22 by Pandit Mohan Lal.

Question is—

In the proposed section 14-B (6), line 3, *delete* "and conficate."

The motion was carried.

Deputy Speaker: Amendment No. 23 is again by Pandit Mohan Lal.

Question is—

In the proposed section 14-B (8), line 5, *delete* "and confiscate".

The motion was carried.

Deputy Speaker : Question is—

In the proposed section 14-B (8), line 6, between 'false' and ' : ' *insert* 'and impose by way of penalty double the amount of tax recoverable on such goods".

The motion was lost.

Deputy Speaker : Question is—

Delete both the provisos to the proposed section 14-B (8).

The motion was lost.

Deputy Speaker : Question is—

In the second proviso of the proposed section 14-B (8), line 1 between 'that' and 'the', *insert* 'when the omission is found to be *mala fide* or dishonest'.

The motion was lost.

Deputy Speaker : Question is—

In the second proviso of the proposed section 14-B (8), line 5, *delete* 'one thousand rupees or'.

The motion was lost.

(*Interruptions*)

Minister for Education: Madam, Deputy Speaker, I have to make a submission. Amendments Nos. 22 and 23 have been carried and the other amendments which are in accord with these, cannot be put to the vote of the House. Identical amendments become redundant.

उपाध्यक्षा । मेरे पास गवर्नमेंट की तरफ़ से कोई इतलाह नहीं आई कि फलां अमैंडमैंट एक्सेप्ट की गई है और फलां नहीं की गई । (I have received no information from the Government that such and such amendment has or has not been accepted by the Government.)

Minister for Finance : The hon. Member Shri Mohan Lal moved his amendments Nos. 22 and 23 only. When his other amendments were not moved by him, how can these be put to the vote of the House ?

उपाध्यक्षा । रूलिंग पार्टी की तरफ से काफी मुश्किलात पैदा की जा रहीं हैं । (A lot of difficulties are being created by the ruling Party.)

Deputy Speaker : Question is—

In the second proviso of the proposed section 14-B (8), line 6, *delete* 'whichever is greater'.

The motion was lost.

Deputy Speaker : Question is—

Delete the proposed section 14-B (4).

The motion was lost.

Deputy Speaker : Question is—

In the second proviso to the proposed section 14-B (8), line 2, *delete* 'or confiscation'.

The motion was lost.

Deputy Speaker : Question is—

Delete the proposed section 14-C.

The motion was lost.

Deputy Speaker : Question is—

Delete the first proviso to the proposed section 14-B (8).

The motion was carried.

Deputy Speaker : Question is—

In the second proviso to the proposed section 14-B (8), lines 2 and 4, *delete* 'or confiscation'.

The motion was carried.

Deputy Speaker : Question is—

That clause 12, as amended, stand part of the Bill.

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ਼ ਆਰਡਰ, ਮੈਡਮ । ਜਦੋਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸਾਂ ਫ਼ਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ amendments ਮੂਵ ਹੋਈਆਂ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ । ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਮੂਵ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ । ਗੌਰਮਿੰਟ ਗਲਤ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ।

उपाध्यक्षा । मैं ने खुद कहा था कि जो कुछ कहना है इन पर इकट्ठा ही कह लो । (I had myself said that all these amendments be discussed together.)

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ਼ ਆਰਡਰ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਲ੍ਹ ਦਾ ਰੀਕਾਰਡ ਵੇਖੋ ਕਿ ਆਇਆ ਤੁਸਾਂ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਭ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਮੂਵਡ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਣ......

Deputy Speaker : I remember having said that all the amendments should be deemed to have been read and moved.

(After ascertaining the votes of the Members by voices, the Deputy Speaker said "I think the Ayes have it". This opinion was challenged and division was claimed. The Deputy Speaker after calling upon those Members who were for "Aye" and those who were for "No", respectively, to rise in their places and on a count having been taken, declared that the motion was carried).

The motion was declared carried.

(CLAUSE NO. 13)

उपाध्यक्षा । मैं लीडर आफ दी आपोज़ीशन और कामरेड साहिब से यह पूछना चाहती हूं कि क्या यह मुनासिब नहीं होगा कि चूंकि आगे ही इस बिल पर और क्लाज़ बाई क्लाज़ स्टेज, जो चल रही है, उस पर काफी बहस हो चुकी है इसलिए छोटी छोटी बातों पर और ज्यादा बहस न की जाए और कोई टाईम लिमिट फिक्स कर ली जाए। थोड़ी थोड़ी बात कह कर ही जो मैम्बर साहिबान बोलना चाहते हैं, अपनी अपनी बात कह लें और थर्ड रीडिंग स्टेज पर स्पीचिज़ कर ली जाएं । कोई टाईम लिमिट जरूर फिक्स कर लेनी चाहिए ताकि आगे ही इतने दिन बहस हो चुकी है और इस बिल को खत्म किया जा सके । (I would like to seek the adivce of the Leader of the Opposition and Leader of the House whether it would not be desirable to fix some time-limit for speeches and put a restraint on long speeches on clauses as already sufficient discussion has taken place on the Bill during the consideration Motion. Now the Bill is being discussed clause by clause, those Members who wish to speak on clauses may make short speeches to convey their view point and long speeches may be made during the third reading of the Bill. Since lot of discussion has already taken place for a number of days, time-limit for speeches must be fixed so that the Bill may be passed.)

सरदार गुरनाम सिंह । आप यह बात लीडर आफ दी हाऊस को कहें क्योंकि उधर से ही ज्यादा वक्त जाया होता है ।

उपाध्यक्षा : मैं ने लीडर आफ दी हाऊस और लीडर आफ दी आपोज़ीशन दोनों को ही कहा है । मुनासिब होगा अगर कोई टाईम लिमिट फिक्स कर ली जाए । (I have requested both the Leader of the House and the Leader of the Opposition for advice. It would be proper to fix some time-limit of speeches.)

मुख्य मन्त्री : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आप के साथ इस बात में मुतफिक हूं कि जहां तक बिल पर जनरल डिस्कशन का ताल्लुक है यह काफी हो चुकी हुई है और क्लाज़ बाई कलाज़ पर बोलते हुए भी काफी बहस हो रही है । आज तक किसी बिल पर इतनी लम्बी बहस नहीं हुई जितनी इस पर हुई है । इसलिए अब ज्यादा बहस न की जाए और जिन मैंम्बर साहिबान ने बोलना हो वह थर्ड रीडिंग स्टेज पर बोल लें ताकि बिल को आज पास कर दिया जाए।

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ਼ ਆਰਡਰ, ਮੈਡਮ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਚੀਫ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਥਰਡ ਰੀਡਿੰਗ ਸਟੇਜ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ । ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੋਈ ਮੀਮੋਰੈਂਡਮ ਹੀ ਇਸ ਬਿਲ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ?

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸਾਂ ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ । ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਇਸ ਕਲਾਜ਼ ਬਾਈ ਕਲਾਜ਼ ਦੀ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਸਟੇਜ ਉਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰ ਲੈਣ । (He has not heard my submission. I had enquired whether it would not be desirable that this clause by clause stage be gone through quickly and the hon. Members desirous of making speeches might do so at the third reading stage of the Bill)

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਕ ਮਿਨਟ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ।

ਚੀਫ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ।

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਗੌਰਮੈਂਟ ਹਰ ਕਲਾਜ਼ ਉਤੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕਬੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਥਰਡ ਰੀਡਿੰਗ ਸਟੇਜ ਉਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਦੇ ਮਨਣ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਕਲਾਜ਼ ਬਾਈ ਕਲਾਜ਼ ਦੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਕਲਾਜ਼ ਉਤੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਮੰਨਣ (It is not necessary that they should accept amendments on each clause).

(*At this stage there were interruptions and noise*)

ਜੇਕਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਨਾ ਮੰਨਣ ਤਦ ਵੀ ਮਾੜੀ ਔਰ ਜੇ ਮੰਨਣ ਤਦ ਵੀ ਮਾੜੀ। ਤਾਂ ਫੇਰ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ? (The Government is condemned both ways whether it accepts or rejects the amendments. Then how can it win approbation of the Opposition?)

श्री चान्दी राम वर्मा (अबोहर) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस क्लाज़ पर मेरी एक छोटी सी अमैंडमैंट है । इस में एक ही लफज़ ऐसा है जिसको अगर ठीक कर दिया जाए तो यह क्लाज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगी । वह अमैंडमैंट यह है :

In the second proviso, line 2, for "the penalty" substitute "or the penalty."

इस अमैंडमैंट को मान लेने से यह कलाज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी । मेरा ख्याल है कि मिनिस्टर साहिब इस को मान लेंगे । ज्यादा कुछ न कहता हुआ मैं अपनी यह अमैंडमैंट हाउस के सामने पेश करता हुं ।

Deputy Speaker : Motion moved—

In the second proviso, line 2, *for* "the penalty" *substitute* "or the penalty".

Finance Minister (Sardar Kapoor Singh) : I accept the amendment. Now, the Clause, as amended, may be passed.

उपाध्यक्षा : अमैंडमैंट्स का पुलन्दा तो मेरे पास है । इन को पुट तो मैंने ही करना है । आई मस्ट पुट दैम टू दी वोट आफ दी हाउस । आप के पास तो वही है जो कि आप ने मंजूर कर ली है । इस के अलावा दूसरी और भी अमैंडमैंट्स हैं । (The bundle of amendments is lying with me. I have to put them to the vote of the House and I must put them to the House. The hon. Minister has got only that amendment which he has accepted. Besides that, there are other amendments also.)

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ (ਲੁਧਿਆਣਾ ਉੱਤਰ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਲੈ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਰੀਜਨਲ ਬਿਲ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਕ ਲਫਜ਼ "ਪੈਨਲਟੀ" ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੈਸਿੰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੇ

[ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ]

ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ, ਅਪੀਲ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਛੋੜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪਰਪਜ਼ ਸਰਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ? ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਲਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਇਹ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਹੀਲਾ ਸਰਕਾਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਨਲਟੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਵਿਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਭੇਂਟ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿਉਗੇ ਤਾਂ ਪੈਨਲਟੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਹੜਾ ਉਰਿਜਨਲ ਐਕਟ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 20 ਵਿਚ ਕੀ ਡਿਫੈਕਟ ਸੀ ? ਇਸ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੀ ਪਰਪਜ਼ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਤਨੀ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਪਾਸ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਰਵਾਜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਕਲਾਜ਼ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ—ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਰਪੋਜ਼ਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ; ਉਸ ਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਚਾਰਜ ਲਈ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। (*Interruption*)

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ: ਬਾਬੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਟਰਪਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਾਬੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬੋਲ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰੋ (Please do not interrupt Baboo Jee. I would request the hon. Member also to be brief and wind up).

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਅਮੈਂਡਿੰਗ ਬਿਲ ਉਤੇ ਜਦ ਕਲਾਜ਼ ਬਾਈ ਕਲਾਜ਼ ਡਿਸਕੱਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਨਚਾਰਜ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਰਿਜਨਲ ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟ ਐਕਟ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਅਗਰਾਜ਼ੋ ਮਕਾਸਦ ਦੱਸਣ, ਉਸ ਦੀ ਵਜਾਹ ਦੱਸਣ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਥੇ ਕੋਈ ਵਜਾਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਦ ਰੌਲੈਟ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਪੰਡਿਤ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਫੇਅਰਜ਼ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੁਰੰਦਰ ਪੰਡਿਤ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਕੀ ਹੈ ? ਨਾ ਇਥੇ ਦਲੀਲ, ਨਾ ਵਕੀਲ ਔਰ ਨਾ ਅਪੀਲ। ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਸਣਾ ਪਰ ਪਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਨਾ ਦਲੀਲ ਹੋਵੇ ਔਰ ਨਾ ਵਕੀਲ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਇਹ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬਣੇ, ਫਿਰ ਸਪੀਕਰ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਤਕ ਰਹੇ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕਦੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਬਿਲ ਜਾਂ ਕਲਾਜ਼ ਲੈ ਆਵੇ ਔਰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ

ਨੂੰ ਇਸ ਕਲਾਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਲਾਜ਼ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਨਲਟੀ ਕਿਉਂ ਰਖੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਰਖਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਨੈਲਟੀ ਲਗਾਣ ਦਾ ਵਧੇਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਗੈਰ ਦੇਖੇ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਫਿਰ ਤਰਮੀਮਾਂ ਹਰ ਕਲਾਜ਼ ਵਿਚ ਮੰਨਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲਾਜ਼ ਬਾਈ ਕਲਾਜ਼ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲਈਏ ਔਰ ਸਿਰਫ਼ ਥਰਡ ਰੀਡਿੰਗ ਤੇ ਹੀ ਬੋਲੀਏ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ।

ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਲਾਜ਼ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਅਮੈਂਡਿੰਗ ਕਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ।

श्री बलरामजी दास टन्डन (अमृतसर शहर–पश्चिम) । डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह जो कलाज़ 13 है यह इस बात के लिए है कि जो एपेलेंट एथारेटी है उस के पास अपील के लिए कोई किस सूरत में जा सकता है । इस मतलब के लिए गवर्नमेंट ने यह एक नई प्रोवीज़न इस बिल में इनट्रोडियूस की है । इस के मुताबिक कोई भी आदमी तब तक अपील दायर नहीं कर सकता जब तक जो उस टैकस की एसेसमैंट हो चुकी है और उस के साथ ही साथ अगर कोई पैनेल्टी उस पर लगाई जा चुकी है वह दोनों जब तक सरकारी खज़ाने में जमा नहीं करवा देता तब तक वह अपील दायर नहीं कर सकेगा । इस के साथ ही एक और प्रोवाइज़ो सरकार ने लगा दी है कि एपेलेंट एथारेटी अगर सेटिसफाइड हो जाती है कि अपील करने वाला टैकस या उस पर लगाई गई पैनेल्टी पे नहीं कर सकता तो उस की वह अपील एनटर्टेन कर सकता है । डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं समझता हूं कि सरकार ने यह जो कलाज़ इस बिल में इनटोडियूस की है यह आम व्योपारियों के साथ एक बड़ी हार्डशिप होगी । वैसे तो चाहिए यह कि हरेक आदमी को इनसाफ मिले और जैसे कि दूसरी स्टेटस में है इन से भी यही उम्मीद की जाती थी और जैसा कि मिनिस्टर साहब ने व्योपारियों को एश्योरेंस भी दी थी कि एपेलेंट एथारेटी और होगी और एसेसिंग एथारेटी कोई और होगी । यानी जिस तरह से इस वक्त डिपार्टमेंट में अमल दरामद हो रहा है उस को दूर करने की कोशिश करेंगे जैसा कि अब कोर्टस में होता है । लेकिन इन्होंने यह बात तो खत्म कर दी है और उसी डिपार्टमेंट में से ही एपेलेट एथारेटी मुकर्र करने की कोशिश की है लेकिन इस के साथ ही इन्हों ने इस कलाज के जरिए यह किया है कि अगर कोई अपील करे तो वह पहले टैक्स के पैसे जमा कराए और अगर उस पर कोई पैनल्टी लगाई गई हुई है उस के पैसे जमा कराए और उस तरह से नहीं किया गया जिस तरह से दूसरे सूबों में होता है । यहां पर तो इन्होंनें यह कर रखा है कि एकसाईज़ एन्ड टैक्सेशन कमिशनर के महकमा के आदमी ही एसेसिंग एथारेटी होंगे और उस

[श्री बलरामजीदास टण्डन]

के महकमा की ही एपेलेट एथारेटी होगी । इस का नतीजा हम क्या उम्मीद कर सकते हैं । जब कि इस महकमा में वही अफसर अच्छा समझा जाता है जो ज्यादा से ज्यादा पैसे टैक्स के तौर पर अकट्ठे कर देता है । इस लिए जब एसेसिंग एथारेटी किसी का टैकस एसेस करेगी तो जो एपेलेंट एथारेटी होंगी वह भी क्योंकि उसी महकमा की होगी उस की कोशिश भी यही होगी कि टैकस का रुपया ज्यादा से ज्यादा हो क्योंकि उस को इस बात का इलम होगा कि उस की प्रमोशन, तबदीली या और कोई बात इसी बात पर निर्भर करती है कि वह टैक्स कितना इक्टठा कर देता है । वह इस लिए एसेसिंग एथारेटी के इनफलूएंस में आ कर अपील करने वाले को इनसाफ कभी नहीं दे सकेगा । चाहिए तो यह था कि उस को एसेसिंग एथारेटी के इनफलूएंस से निकाला जाता जिस तरह से कोर्टस को एग्ज़ैक्टिव के इनफलूएंस से हटाने के लिए उस को उस से अलग किया गया है । और अब वह पुलिस और डिप्टी कमिशनर के हुकम से बाहर कर दी गई है । उसी तरीका से यहां भी करना चाहिए था । लेकिन सरकार ने इस के उल्ट यह प्रोवीज़न इस में कर दी है । डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस से और भी कुर्पशन फैलेगी क्योंकि एक ही महकमा के आदमियों के पास दोनों पावरज़ यानी टैक्स की एसेसमैंट करना और उस के खिलाफ़ अपीलें सुनना दी गई हैं । इस के साथ ही यह जो और प्रोवाइज़ो लगा दी गई है कि अगर एपैलेट एथारेटी सेटिसफाईड हो जाए कि फलां दुकानदार टैक्स देने की या पैंनलटी देने की अपने में क्षमता नहीं रखता तो भी उस की वह अपील एनटर्टेन कर सकेगा इस से यह होगा कि अगर किसी व्योपारी को अपील करने से पहले एक लाख रुपया टैकस का या पैनेल्टी का जमा कराना होगा तो वह यही बेहतर समझेगा कि एक या दो हज़ार रुपए उस एपेलेंट एथारेटी को रिश्वत के तौर पर यह करा लें कि उस की अपील वह रकम देनें के बगैर एन्टर्टेन कर ली जाएगी क्योंकि वह इस हालत में नहीं है कि वह इतनी बड़ी रकम जमा करवा सके । क्योंकि उस व्योपारी को यह पता होगा कि जो रकम वह रिश्वत में देगा उतना रुपया तो वह इंनट्रैस्ट के रूप में ही बचा लेगा । इस लिए मैं यह समझता हूं कि यह जो पावर सरकार ले रही है और अपने अफसरों को दे रही है यह बिल्कुल गलत है । इसे इस प्रोवाइज़ो को वापस ले लेना चाहिए और जिस सपिरट से इन्होंने व्योपारियों को एश्योरेंस दी थी उस के मुताबिक इसे चल कर एपेलेंट एथारेटी उसी महकमा की मुकर्रर नहीं करनी चाहिए ।

डिप्टी स्पीकर : सरदार कपूर सिंह ।

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਲਾਜ਼ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਹੈ ......

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸੀਂ ਥਰਡ ਰੀਡਿੰਗ ਤੇ ਬੋਲ ਲੈਣਾ । (The hon. Member may speak on the 3rd reading of the Bill.)

श्री रूप लाल महता: इस कलाज़ पर मेरी भी एक एमेंडमेंट है मैं ने उस पर बोलना है ।

उपाध्यक्षा : लेकिन महता जी मेरे पास आप की पार्टी की तरफ से यह लिखा आया है कि आप की जितनी भी एमैंडमैंटस हैं वह सब विदड्रा कर ली गई हैं । (I may tell the hon. Member Shri Rup Lal Mehta that I have received this intimation from his party that all the amendments given notice of by its members stand withdrawn.)

श्री रूप लाल महता : पर मेरी एमेंडमेंट तो अलग है ।

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਆਨੇ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ਼ ਆਰਡਰ, ਮੈਡਮ । ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਲਿੰਗ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਇਸ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਤੌਰ ਇਕ ਨਾਨ ਪਾਰਟੀ ਮੈਨ ਦੇ ਇਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਇਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ । ਹੁਣ ਹੀ ਮਹਿਤਾ ਰੂਪ ਲਾਲ ਆਪਣੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਡੀਸੀਅਨ ਦਸ ਕੇ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ।

Deputy Speaker : The hon. Member should mind his own business. Mehta Rup Sal can himself plead his case. To allow or not to allow any Member to speak is my responsibility.

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ....

Deputy Speaker : Order, please.

श्री फतेह चंद विज: आन ए प्वांयट आफ आर्डर, मैडम । डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह तो बड़ी अच्छी बात है कि आप रूस से हो कर आए हैं । लेकिन जो वहां कायदा है कि किसी को बोलने नहीं दिया जाता और अगर कोई बोलने की कोशिश करे तो उस का गला घूंट दिया जाता है । पर आप वहां का रिवाज यहां भी लागू कर रही हैं......

उपाध्यक्षा : आप अपने लफज़ वापस लें । आज आप को क्या हो गया है जो इस तरह की बातें करने लगे हैं । आपने तो अभी बड़ी अच्छी तकरीर की थी । (The hon. Member should withdraw these words. I fail to understand what has gone wrong with him. He has just made a very good speech.)

ਵਿਤ ਮੰਤ੍ਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ) : ਇਹ ਇਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜਹੀ ਕਲਾਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਔਰ ਇਸ ਅਮੈਂਡਿੰਗ ਕਲਾਜ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਪਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਲਫਜ਼ ਹਨ assessment and penalty ਔਰ ਦੂਜੀ ਵਿਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ assessment or penalty । ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਿਆਇਤ ਰਹੇ । ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੀਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇ । ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਦਿਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਲਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।

Deputy Speaker : Amendment No. 296 by Shri Chandi Ram Verma. Question is—

In the second proviso, line 2, for "the penalty" substitute "or the penalty".

The motion was carried.

Deputy Speaker : Question is—

That clause 13, as amended, stand part of the Bill.

The motion was carried.

श्री बलराम जी दास टंडन : आन ए प्वांयट आफ आर्डर, मैडम । हमारी अमैंडमैंटस कहां गईं ?

उपाध्यक्षा : आप की अमैंडमैंटस आउट आफ आर्डर हैं तो भी मैं ने कर्टसी के तौर पर आप को बोलने की इजाज़त दी । (The hon. Member's amendments are out of order. However, out of courtesy I permitted him to have his say.)

CLAUSE 14

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਬਾਬੂ ਜੀ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਹਿ ਲਉ । (The hon. Member may finish within five minutes.)

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ (ਲੁਧਿਆਣਾ ਉੱਤਰ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ ।

ਇਹ ਜੋ ਦਫ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਦਫਾ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਿਸਦ ਵਪਾਰੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਉਹ ਮੰਗ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੈਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਐਪੀਲੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਅਡ ਅਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਸੀ । ਫਿਰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ । ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਐਪੀਲੇਟ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਅਡ ਅਡ ਹੋਣਗੀਆਂ । ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਤਾਂ ਮੰਗ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਅਡ ਅਡ ਹੋਣ ।

ਵਿਤ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਉ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਇਹ ਪਰੋਵਿਯਨ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹੀ ਰੀਵੀਯਨ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਸਨ । ਹੁਣ ਉਸ ਵਿਚ ਇਹ ਲਫਜ਼ ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ:—

"Commissioner or the officer on whom Powers of the Commissioner under sub-section (1) have been conferred by the State Government".

ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਵਰ ਸੀ ਉਹ ਪਾਵਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਫਿਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦਿਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਐਪੀਲੇਟ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਅਲਗ ਅਲਗ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਿਲ ਵਿਚ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਅਰਸਾ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੁਰੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਗਜ਼ੇਕਟਿਵ ਅਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਬੀ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿਉ । (Please send Chaudhri Darshan Singh to the lobby.)

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਤਾਲਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਕ ਬਜਾਨਬ ਮਤਾਲਬਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਐਪੈਲੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਅਡ ਅਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ... ....

ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ਼ ਆਰਡਰ, ਮੈਡਮ । ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਥੋਂ ਉਠਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ।

(ਹਾਸਾ)

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਜੇ ਉਹ ਸ਼ੋਰ ਪਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਠਾ ਦਿਆਂਗੀ । (If he makes noise, then he, too, will be asked to move out.)

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਰਸਰੇ ਇਕਤਦਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ੇਕਟਿਵ ਨੂੰ ਅਡ ਅਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ । ਉਸ ਦੀ ਬਿਨਾ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਡੀਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਕ ਬਜਾਨਬ ਡੀਮਾਂਡ

[ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ]

ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉ ਕਿ ਅਸੈਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਪਨੈਲਟੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਅਸੈਸ ਕਰੇ ਪਰ ਅਪੀਲ ਸੁਣੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀ ਜੋ ਇਹ ਦੇਖੇ ਕਿ ਡੀਲਰ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਪਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਸ ਦੇਣ। ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਖਤਿਆਰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਨਵਿਲਿੰਗ ਹਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਖੋਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਫ ਰਾਏ ਰਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮੈਂਡ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁਨਹਰਫ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਟ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਇਸ ਗਲ ਤੇ ਸਿਨਸੀਅਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਲਿਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਐਪੀਲੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਵਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਗ-ਜ਼ੈਕਟਿਵ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਬਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਐਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੈਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਐਪੀਲਾਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਖ ਵਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਵਿਘਨ)

Deputy Speaker : Question is—

That clause 14 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 15

Deputy Speaker : Now Clause 15 is before the House.

(*At this stage Shri Ram Saran Chand Mital rose to speak*).

Voices : ਬੈਠ ਜਾਓ ਬੈਠ ਜਾਓ ਮਿਤਲ ਸਾਹਿਬ।

ਸ੍ਰੀ ਬਲਰਾਮ ਜੀ ਦਾਸ ਟੰਡਨ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਮੈਡਮ। ਕੀ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਮਿਤਲ ਸਾਹਿਬ ਤਰਮੀਮ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਨਫੇਅਰ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ।

श्री राम सरन चंद मितल (नारनौल) : मैं भी इतनी सी बात फिनाँस मिनिसटर साहिब के ध्यांन में लाना चाहता हूं कि यह जो क्लाज़ 15 है इस के सामने जो मोजूदा सेक्शन 23 है उस में पावर्ज कोर्टस को हैं और अब एग्ज़ैक्टिव और एडमिनिस्टेटिव आफीसर्ज़ को दी जा रही हैं। तो जो इस सरकार की वाज़ह पालेसी है एग्ज़ैकटिव को जूडीशश्री से अलग रखने की उस के खिलाफ में है इस का ख्याल फिनाँस मिनिस्टर साहिब कर लें तो बेहतर होगा। इस के इलावा लो पावर्ज़ दी जा रही हैं वह एक्सट्रीम हैं। जिस पर्पज़ के लिए है यह बिल लाया जा रहा है यानी इवैज़न को रोकने के लिए वह खत्म हो जाएगा इस बात को भी अगर सरकार देख ले तो ठीक रहेगा।

(विघन)

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ਼ ਆਰਡਰ, ਮੈਡਮ । ਜਦ ਯੂਨੀਨਿਸਟ ਵਜ਼ਾਰਤ ਸੀ ਤੇ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬਿਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੋਲਣ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਇਹ ਆਪ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸ ਦੇਣ ।

ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਜੋ ਡੀਮਾਂਡਜ਼ ਜਦ ਸਨ ਉਹ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੀਮਾਂਡਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਖੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਮਨ ਲਈਆਂ ਹਨ । ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਥੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ।

(ਵਿਘਨ)

ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਫ਼ੀਰੋਜ਼ਪੁਰ) **:** ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਜ਼ 15 ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ । ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜਿਨੇ ਵੀ ਕਸੂਰ ਸਾਰੇ ਬਿਲ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਕਲਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਰਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਆਰਬਿਟਰੇਰੀ ਕਲਾਜ਼ ਹੈ ਇਕ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਅਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਡੀਟੇਲਜ਼ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਰਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਗਿਦੜ ਕੁਟ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਿਦੜ ਤੇ ਝੁਮ ਪਾ ਕੇ ਕੁਟ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਾ ਲਗੇ ਕਿ ਮਾਰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਲਾਜ਼ ਕੰਬਲ ਕੁਟ ਵਾਂਙ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ ਪਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਰਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ।

ਫ਼ਿਰ ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਜ਼ ਦੀ ਸਬ-ਕਲਾਜ਼ 2 ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ—

> "Any officer of the rank of a Deputv Excise and Taxation Commissioner appointed under sub-section (1) of section 3 may, after affording to a dealer a reasonable opportunity of being heard, impose the penalty mentioned in sub-section (1)."

ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਬਿਨਾ ਉਸ ਦਾ ਕਸੂਰ ਡੀਫਾਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਕ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜ਼ੁਰਮ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਰਖ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਹ ਇਕ ਵਡੀ ਅਨਾਮੋਲੀ ਇਸ ਵਿਚ ਹੈ ।

ਫ਼ਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਬ-ਕਲਾਜ਼ (3) ਵਿਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ—

> "(3) Any person aggrieved by an order passed by an officer under sub-section (2) may, within a period of sixty days from the date of such order, appeal to the Commissioner or an officer not below the rank of Joint Excise and Taxation Commissioner, appointed under sub-section (1) of section 3 and authorised in this behalf by the Commissioner."

ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡੀਲਰ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਬਹੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲਈ । ਪਰ ਜੇਕਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੈ ? ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ

[ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ]

ਤੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਾਂ 60 ਦਿਨ ਰਖ ਦਿਤੀ ਪਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਮਿਆਦ ਨਹੀਂ ਰਖੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤਕ ਜ਼ਰੂਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਲ ਵੀ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਵੀ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੈਫੀਨੇਟ ਅਰਸਾ ਰਖ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਡੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਥ ਪਾ ਲਉ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਨਾ ਰਹੇ? ਫਿਰ ਇਨਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਵਾਜਬ ਹੱਦ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਲਖਪਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਠੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨੇ ਵਸੀਹ ਇਖਤਿਆਰ ਇਨਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ, ਸਜ਼ਾ ਦਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਲਾਜ਼ ਡੀਲੀਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭਰਾ (ਧੂਰੀ, ਐਸ. ਸੀ.): ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਜ਼ 15 ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਫਿਨਾਂਸ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ ਵੇਰ ਇਕ ਸੇਠ ਤੇ ਜੱਟ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਸੇਠ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਜਟ ਨੇ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਐਨੀ ਛੇਤੀ ਅਮੀਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੇਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਧਰ ਓਧਰ ਡੰਡੀ ਫੇਰਨ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਜੱਟ ਨੇ ਵੀ ਤਕੜੀ ਫੜ ਲਈ ਤੇ ਹਟੀ ਕਰਨ ਲਗ ਪਿਆ। ਇਕ ਬੁੱਢੀ ਦਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤਾਂ ਜੱਟ ਨੇ ਤਕੜੀ ਤੇ ਪਾ ਲਏ ਕਦੇ ਇਧਰ ਵੇਖੇ ਕਦੇ ਉਧਰ ਵੇਖੇ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਪੁਛਣ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਾਸਕੂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸਕੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਣਾ ਹੈ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

Deputy Speaker : Question is—

That clause 15 stand part of the Bill.

The motion was carried.

(CLAUSE 16)

Shri Chandi Ram Verma: Madam, I beg to move—

In the marginal heading *for* '27' *substitute* '24'.

Deputy Speaker: Motion moved—

In the marginal heading, *for* '27' subsitute '24'.

Deputy Speaker: Question is —

In the marginal heading *for* '27' substitute '24'.

The motion was carried.

Deputy Speaker: Question is—

That Clause 16, as amended, stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 17

(*Principal Rala Ram started to speak on clause 17*)

1.00 p.m.

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : On a point of order, adam. ਜਦੋਂ Clause No. 17 ਅਜੇ ਮੂਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ?

उपाध्यक्षा : कलाज 17 जो है वह पास हो चुकी है, क्लाज 17 अंडर डिसकशन है,) clau e 16 has been passed and cla e 16 is under discussion.)

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਲਾ ਰਾਮ (ਮੁਕੇਰੀਆਂ) : ਉਪਾਧਯਕਸ਼ ਮਹੋਦਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਾਵਰਜ਼ ਇਸ ਕਲਾਜ਼ ਵਿਚ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਕੁਝ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨੇਬਲ ਹਨ ਅਨਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਅਤੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਡੰਡੈਂਟ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਫਜ਼ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਤਰਮੀਮਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਕਲਾਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਇਹ ਹਨ :—

Delete sub-clause (1);

In sub-clause (2), lines 1-2, *delete* "for the words 'granting of certificates' the words 'granting or renewal of certificates' shall be substituted, and";

In sub-clause (3), lines 1-2 *for* '(i)' *substitute* '(1)'.

In sub-clause (3), lines 3-4, delete "and the manner of making an enquiry under the first proviso to sub-section (6) of that section";

In sub-clause (3), line 5, *for* '(ii)' substitute '(11)'.

Deputy Speaker: Motions moved—

Delete sub-clause (1);

In sub-clause (2), lines 1-2, *delete* "for the words 'granting of certificates', the words 'granting or renewal of certificates' shall be substituted, and";

In sub-clause (3), lines 1-2, *for* '(i)' *substitute* '(1)';

In sub-clause (3), lines 3-4, *delete* "and the manner of making an enquiry under the first proviso to sub-section (6) of that section";

In sub-clause (3), line 5, *for* '(ii)' *substitute* '(11)'.

ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ) : ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਫਾਰਮਲ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ । ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ।

Sardar Ranjit Singh Nainewala: Madam, I beg to move—

Delete sub-clause (1);

In Sub-clause (2), lines 1-2 *delete* "for the words 'granting of certificates' the words 'granting or renewal of certificates' shall be *substituted*, and"

Deputy Speaker: Motions moved—

Delete sub-clause (1),

In sub-clause (2), lines 1-2 *delete* 'for the words "granting of certificates' the words 'granting or renewal of certificates'. shall be substituted, and"

Finance Minister: I accept these amendments.

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਕਲਾਜ਼ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ।

ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਰੇਟਰੀ : ਬਾਬੂ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ।

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਮਝ ਲਵਾਂਗੇ । ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਅਕਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਅਕਲ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਰੇਟਰੀ : ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ਼ ਆਰਡਰ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਬਾਬੂ ਜੀ ਨੂੰ ਏਥੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਬੇਅਕਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ਖਸ ਦਰੂ ਨਾਉਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬੇਅਕਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ । ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ?

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਕ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਕਰੇ ਮੈਂ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਅਕਲ ਤੋਂ ਵਡਾ ਅਤੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ।

ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੇਟਰੀ : ਚੰਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ।

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਟਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਗਾਉਣ ਲਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ । ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਫ਼ਾ 17 ਦੇ ਸਬਧ ਵਿਚ ਕੁਝ ਤਰਮੀਮਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈਡੈਂਟੀਕਲ ਤਰਮੀਮਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਮੰਨ ਲਈਆਂ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕਲਾਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ । ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਅਗਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਜੇ ਰਿਨਿਉਅਲ ਵਾਲੀ ਮੋਸ਼ਨ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ 17 ਕਲਾਜ਼ ਬੇਮਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

Deputy Speaker: Question is—

In sub-clause (3), lines 1-2, *for* '(i)', *substitute* '(1)'.

The motion was carried.

Deputy Speaker: Question is—

In sub-clause (3), lines 3-4, *delete* "and the manner of making an enquiry under the first proviso to sub-section (6) of that section".

The motion was carried.

Deputy Speaker: Question is—

In sub-clausc (3), line 5, for "(ii)" *substitute* "(11)".

The motion was carried.

Deputy Speaker: Question is—

Delete sub-clause (1).

The motion was carried.

Deputy Speaker: Question is—

In sub-clause (2), lines 1-2, *delete* "for the words 'granting of certificates' the words 'granting or renewal of certificates' shall be substituted, and".

The motion was carried.

Deputy Speaker: Question is—

That Clause 17, as amended, stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 18

Deputy Speaker: Now, clause 18 is before the House.

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ (ਸਿਧਵਾਂ ਬੇਟ, ਐਸ. ਸੀ.) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਜ਼ 18 ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ power to amend schedule 'C' ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਯਾਨੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਸ਼ਿਡੂਲ ਸੀ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਰਟੀਕਲਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਡੂਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਨਰਲ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਦੀ ਜ਼ਦ ਵਿਚੋਂ ਐਗਜ਼ੇਂਪਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 1948 ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਿਡੂਲ ਦੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਟੀਕਲਜ਼ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਅਖਤਿਆਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਥ ਵਿਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ।

> "The State Government, after giving by notification not less than three months notice of its intention so to do, may by notification add to, or delete from, Schedule C any goods, and thereupon Schedule C shall be deemed to be amended accordingly".

ਇਹ ਇਸ ਸ਼ਿਡੂਲ ਵਿਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਔਰ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨਜ਼ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਰਵੋਦਯ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮੋਦਿਉਗ ਸੰਘ ਭੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਕਾਟੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਗਾਉ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ । ਮੇਰੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸੀ ਸ਼ੂ ਦੀ ਕਾਟੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ੇਮਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਇਹ ਆਈਟਮ ਇਸ ਸ਼ਿਡੂਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ । 59 ਆਈਟਮ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੇਮਪਟ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਗਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਲਾ ਦਿਤੀ ਹੈ—

> "when sold by the maker of such shoes himself or by any other member or his family, provided that the maker does not employ any outslde labour or use power at any stage for making shoes".

ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨੀ ਕਿ ਇਹ ਹੱਥ ਦਾ ਕਾਮ ਹੈ, ਮਗਰ ਜੇ ਉਹ ਪਾਵਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਿਡੂਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲ ਤੋਂ

[ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ]

ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਿਜ਼ੋ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਿਡੂਲ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਅਨਕਾਂਸਟੀਚੂਸ਼ਨਲ ਹੈ । ਹੈਂਡਮੇਡ ਸ਼ੂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਐਗਜ਼ੇਮਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ (ਲੁਧਿਆਣਾ ਉੱਤਰ): ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਕਿਤੇਂ ਤਕ ਇਹ ਐਡੀਸ਼ਨ ਔਰ ਡਿਲੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਤੁਅੱਲਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੀ ਖਰਾਬੀ ਦਾ ਬਾਇਸ ਹੈ । ਇਹ ਨੰਗੀ ਤਲਵਾਰ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲਟਕਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਚਲੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਡਿਲੀਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਇਕ ਜੁਆਇੰਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਗੌਰ ਖੋਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ 10 ਜਾਂ 15 ਦਿਨ ਸੀਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਐਡੀਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਲੀਸ਼ਨਜ਼ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰਦੀ । ਹੁਣ ਇਸ ਅਨੇਬਲਿੰਗ ਕਲਾਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਫਿਨਾਂਸ ਮਨਿਸਟਰ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਹਟਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵਧਾ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ । ਜੇ ਡੈਮੋਕਰੈਸੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਤੁਅਲੁਕ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਡੈਲੀਗੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਆਮਲੇ ਵਿਚ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਕਤੱਈ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਵਧਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਘਟਾ ਦੇਵੇ । ਇਸ ਕਲਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਝੋਂਕਣ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।

ਇਕ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ : ਚਸ਼ਮੇ ਲਾ ਲਉ ।

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਚਸ਼ਮੇ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਸਾਡੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹਥ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਅਖਤਿਆਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ । ਅਗਰ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਖਾਹਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ..........(ਵਿਘਨ) ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿਉ । ਇਹ ਬੋਲਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਅਤੇ ਮਨਿਸਟਰ ਵੀ ਵਿਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ।

उपाध्यक्षा : चौधरी रणबीर सिंह, आप क्यों काम लंबा करते हैं ।' यहां अनयूयुअल मीटिंग्ज़ हो रही हैं । यहां मिनिसटर कई २ जगा बैठे हैं । Kindly wind up. (Why does the hon. Minister Chaudhri Ranbir Singh make the matter lenghty ? Unusual meetings are going on here. The Ministers are occupying other seats than their own. Kindly wind up.)

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਖਾਹਸ਼ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਢਾ ਲਏ ਦਫ਼ਾ 18 ਪਾਸ ਕਰਕੇ । ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਨੂੰ ਉੜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਅਗਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਹਸ਼ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਕਰ ਦੇਣ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਬਿਟਰੇਰੀ ਪਾਵਰਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ । ਜ਼ਰਾ ਹਾਊਸ ਇਸ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇ । ਮੈਂ ਫਿਨਾਂਸ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਇਆ ਆਰਬਿਟਰੇਰੀ ਪਾਵਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਅਗੇ ਨੂੰ ਐਸਾ ਪਰੈਸੀਡੈਂਟ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਅਗੇ ਨੂੰ ਜੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਏਗਾ, ਏਥੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਖੁਦ ਡਿਕਟੇਰਸਿੰਪ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਥ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਰਖੋ । ਟੈਕਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਸਾਵਰਿਨ ਬਾਡੀ ਹੈ । ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਹਾਊਸਿਜ਼ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਵਧਾਉਣ । ਪਰ ਇਹ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਹ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ । ਇਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ । ਜਿਸ ਦੀ ਚਾਹੁਣ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਣ । ਇਹ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਅਮੈਂਡ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਡੀਸੈਂਸੀ ਦੇ ਨਾਉਂ ਤੇ, ਗੁਡ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਉਂ ਤੇ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਡੈਮੋਕਰੈਸੀ ਵਰਤੋ. ਇਹ ਅਖਤਿਆਰ ਨਾ ਲਉ । ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣ । ਮੈਂ ਐਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਹਾਂ ।

Deputy Speaker: Question is—

That clause 18 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 19

ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਫਿਰੋਜਪੁਰ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਕਲਾਜ 19 ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਵਿਚ ਮਿਰਚਾਂ ਅਤੇ ਫੂਡਗਰੇਨਜ਼ ਐਡ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲਉ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ ਕਿ ਫੂਡਗਰੇਨਜ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ । ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਭੁਖ ਨਾਲ ਮਰੇ, ਕਿਤੇ ਕਾਨ੍ਹਪੁਰ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੁਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ । ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰ ਲਉ । (I think the hon. Member Sardar Kulbir Singh is not feeling well. Why does he make a long speech ? He may take rest.)

ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸਕਰੂਟੇਨਾਈਜ਼ ਕਰੋ । ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਬਗ਼ਾਵਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਗਰਚਿ ਉਹ ਮਸੱਲਾਹ ਬਗਾਵਤ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ । ਜੇ

[ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ]

ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜੋ ਅਜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ । ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਸਨ । ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ) : ਇਹ ਕਲਾਜ਼ ਰਿਡੰਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ in view of the fact ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਜ਼ 18 ਵਿਚ ਅਖਤਿਆਰ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ਼ ਨਾ ਕਰੋ । ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ..ਾ ਇਸ ਕਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ਕ ਹਟਾ ਦਿਉ । ਬੱਸ ਐਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ । ਲਉ ਜੀ, ਬਸ ।

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ਼ ਆਰਡਰ, ਮੈਡਮ——

Deputy Speaker : When Clause 19 is going to be deleted then what is ...se of raising a Point of Order in that behalf.

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ਼ ਆਰਡਰ ।

...puty Speaker : Your amendment is out of order. Please take your

... ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ਼ ਆਰਡਰ ਰੂਲਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਅਲਕ ਰਖਦਾ

...Speaker : The hon. Finance Minister is saying that this clause ... There is no need of this clause. When there is no clause ... the amendment of the hon. Member is?

...ਕੁਮਾਰ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ਼ ਆਰਡਰ, ਮੈਡਮ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ... there is no amendment for the deletion of this ...ੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ । ਨਾ ਹੀ ਹਾਊਸ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

...entary Secretary (Shri Ram Partap Garg) : Madam, I ...he sitting of the House be extended by one hour.

(*Voices from the Opposition* : *No. No.*)

... : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ,..........

...ਆਪ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ । ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ । ਇਹ ਦੇਖੋ ... hon. Member is very learned. He ...is seat. Here is the amendment.)

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਇਸ ਵਕਤ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਲੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ । ਕੋਈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ।.......

Deputy Speaker : The House stands adjourned till 9.00 a. m. tomorrow.

The Sabha then adjourned till 9 a.m. on Wednesday, the 17th Navember, 1965.

1569 PVS—386—31-1-66—C., P., & S., Pb., Patiala.

Punjab Vidhan Sabha Debates

17th November, 1965

Vol. II—No. 21

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Wednesday, the 17th November, 1965

ERRATA

TO

PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATES, VOL. II, NO 21, DATED THE 17TH NOVEMBER, 1965.

Read	*For*	*On page*	*Line*
ਇੰਜਣਾਂ	ਇਨਜਨਾ	(21)3	19
बात	बांत	(21)3	25
सोसायटीज़	सोसययटीज़	(21)5	8
तो	ो	(21)5	9
ਨਜ਼ੂਲ	ਨਜ਼ਲ	(21)5	12
ਲਿਸਟ	ਲਿਮਟ	(21)5	15th from below
about	abou	(21)5	12th from below
of	ot	(21)5	11th from below
NOVEMBER	NOVFMBFR	(21)6	Heading
no	uo	(21)7	11
ਜਿਹੜੀਆਂ	ਜਿਹਿੜਆਂ	(21)7	15
Kashmir	Kashmirs	(21)11	21
डिफरेंट	डिफरेंस	(21)15	Last but one
लगाया	लगाय	(21)16	6th from below
एडमिनिस्टर्ड	एमिनिस्टर्ड	(21)17	11th from below
ਹੈ ।	। ਹੈ	(21)19	15th from below
Jhajjar	Jhajiar	(21)22	23
उपाध्यक्षा	उपाध्गक्षा	(21)31	5th from below
श्री बलराम जी दास टंडन	श्री बलारम जी दास टंड्न	(21)54	13
ਲੁਧਿਆਣਾ	ਲਧਿਆਣਾ	(21)67	9th from below

.m. (

o sta

S
) Fi

econ
(

1.
2.
3.
4.
5.
aya,
ly).
6.
jri a
7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
laga

7.
8.
9.
10.
11.
12.
, S
cks)

13.
14.
15.
16.

PUNJAB VIDHAN SABHA

Wednesday, the 17th November, 1965

The Sabha met in the Vidhan Bhawan, Sector 1, *Chandigarh, at* 9.00 *a.m. of the Clock. Deputy Speaker (Shrimati Shanno Devi) in the Chair.*

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

POSTPONED STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

Subsidy for purpose of 'Wat Bandi'

*8739. **Shri Banwari Lal** : Will the Minister for Revenue be pleased o state:

(a) whether it is a fact that a subsidy to the extent of 50 per cent is allowed for the purpose of 'Wat Bandi, to farmers in the State except in the Mahendergarh District, if so, the reasons for not allowing it in Mahendergarh District ;

(b) a detailed list showing the rate of subsidy allowed for the purpose districtwise, be laid on the table of the House ?

Sardar Darbara Singh (Home and Development Minister) :

ι) First Part No. Subsidy is allowed at the rate of 50 per cent in hilly areas and at the rate of 25 per cent in the Plains.

Second Part Does not arise.

(b) A statement is laid on the table.

Districts in which subsidy is allowed at the rate of 50%

1. Kangra.
2. Kulu.
3. Simla.
4. Gurdaspur (Dhar Kalan Block only) .
5. Hoshiarpur (Balachaur, Mahilpur, Nurpur Bedi, Amb, Dasuya, Hajipur, Una, ›raya, Bhunga, Hoshiarpur-I, Hoshiarpur-II, Anandpur Sahib and Gagret C.D. Blocks ıly).
6. Ambala (Naraingarh, Manimajra, Rupar, Raipur Rani, Chhachhrauli, Nalagarh, ajri and Bilaspur C.D. Blocks only).
7. Lahaul and Spiti.

(ii) Districts in which subsidy is allowed at the rate of 25 per cent

1. Gurgaon.
2. Hissar.
3. Rohtak.
4. Karnal.
5. Mohindergarh.
6. Ambala (except Naraingarh, Manimajra, Rupar, Raipur Rani, Chhachhrauli, lagarh, Majri and Bilaspur C.D. Blocks).
7. Ludhiana.
8. Jullundur.
9. Ferozepur.
10. Amritsar.
11. Gurdaspur (except Dhar Kalan Block).
12. Hoshiarpur (except Balachaur, Mahilpur, Nurpur Bedi, Amb, Dasuya, Hajipur, ι, Saroya, Bhunga, Hoshiarpur-I, Hoshiarpur-II, Anandpur Sahib and Gagret C.D. :ks).
13. Bhatinda.
14. Patiala.
15. Kapurthala.
16. Sangrur.

श्री बनवारी लाल क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि ज़िला महेन्द्रगढ़ की बैकवर्डनैस और खुश्क ज़मीन को ध्यान में रखते हुए वहां पर 50 फीसदी सबसिडी देने की कृपा करेंगे ?

ਮੰਤਰੀ : ਜੋ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਪੈਟਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸਦੇ ਹਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਤਨੀ ਰਕਮ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਸ ਲਈ ਸੈਪੇਰੇਟ ਨੋਟਿਸ ਦਿਉ।

ਕਾਮਰੇਡ ਮਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ: ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜੋ ਟਿਊਬਵੈਲਜ਼ ਲਗੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਪਰਾਇਰਟੀ ਦੇਵੇਗੀ ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਸ ਲਈ ਜੁਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰੋ।

Applications for Loans for Tube-wells, etc., in Gurgaon District

***8794. Rao Nihal Singh ;** Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

(a) the total number of applications pending as on 30th September, 1965 for the grant of loans for tube-wells, pumping sets and wells, blockwise in Gurgaon District ;

(b) whether the case of granting subsidy to the persons who instal tube-wells with diesel engine at their own expense has been decided or not, if not, the time by which a decision is likely to be taken in this regard. ?

Sardar Darbara Singh :

Tube-wells	.. 15	Blockwise break-up is awaited from the Deputy Commissioner, Gurgaon, and will be supplied in due course.
Pumping sets	.. 61	
Percolation wells	..270	

(b) No. No time-limit can be indciated.

ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੋਨਜ਼ ਲੈਕੇ ਟਿਊਬਵੈਲਜ਼ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਰਮੈਲਟੀਜ਼ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਦੋ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਨਜ਼ ਤੇ ਸੂਦ ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਜਿਲਾ ਗੁੜਗਾਉਂ ਬਾਰੇ ਹੈ।

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ। ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਇਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਫ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਜ਼ਿਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲਾ ਗੁੜਗਾਉਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਦਸ ਦੇਣ ਕਿ ਉਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਰਮੈਲਟੀਜ਼ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੋਨ ਤੇ ਸੂਦ ਚਾਰਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ?

ਮੰਤਰੀ : ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਰਜ ਕਰੇਗੀ।

राम्रो निहाल सिंह : क्या वजीर साहिब बताएंगे कि जिन लोगों ने कर्जा नहीं लिया और अपने पास से पैसे खर्च करके डीजल टयूबवैलज लगाए हैं वह सबसिडी लेने के लिए किस को एपलाई करें ?

ਮੰਤਰੀ : ਉਹ ਉਥੋ ਦੇ ਡੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਐਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਾਕੇ ਟਿਊਬਵੈਲਜ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੇਸ ਫਿਨਾਂਸ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਪੈਸੇ ਲਾਕੇ ਟਿਊਬਵੈਲਜ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਰੇਟ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ : ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਟਿਊਬਵੈਲਜ਼ ਲਈ 750 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਡੀਲਰਜ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇੰਜਣਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਣ ਲਗ ਪਏ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮਾਲਪਰੈਕਟਸ ਜਿਹੀ ਚਲ ਪਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਫਾਈਲ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਖਿਆਲ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਜਣ ਲਗਾਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਰੇਟ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਹੈ (ਸ਼ੋਰ)

ਕੈਪਟਨ ਰਤਨ ਸਿੰਘ : ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਖਾਸ ਡੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਡੇਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। (ਸ਼ੋਰ)

ਆਵਾਜ਼ਾਂ : ਉਹ ਡੇਟ ਵੀ ਦਸ ਦਿਓ...... ਸ਼ੋਰ......

ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਕੁਝ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ੂਲ ਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਕੁਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਈਟੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਜਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ?

श्री ग्रोम प्रकाश अग्निहोत्री : ग्रान ए प्वाइंट ग्राफ ग्रार्डर । वजीर खजाना कहते है कि अभी फैसला नही हुग्रा है लेकिन स्टेट मिनिस्टर कहते है कि फैसला हो गया है। मैं आपका रूलिंग चाहता हूं कि हम कौनसा जबाब सही मानें ।

ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ : ਇਸ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਤਨੀ ਕਿਸ ਰੇਟ ਤੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਡੇਟ ਤੋਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ....ਸ਼ੋਰ......

गृह तथा विकास मन्त्री : मैं इस के बारे में बांत क्लीयर कर देना चाहता हूं । सरकार ने पहले जो एलान किए हैं, उस पर सरकार पूरी तरह से पाबन्द है इस वक्त मामला सिर्फ डेट के बारे में हो सकता है कि किस डेट से सबसिडी देनी है । जहां तक नजूल लैंडज का ताल्लुक है, उस के बारे में अर्ज करना चाहता हूं कि अगर किसी व्यक्ति के पास नजूल लैंड 10, 15 साल रहनी है वहां पर सरकार को रुपये देने में भी फायदा है और जिस व्यक्ति ने पम्पिग सैट भी लगाना है, उस को भी लाभ हो सकता है लेकिन जहां नजूल लैंड किसी व्यक्ति के पास एक दो साल ही रहनी है वहां पर उसे पम्पिग सैट्स लगाने से कोई लाभ नहीं होगा । इस विषय में जहां पर कोग्राप्रेटिव सोसायटीज बनी हुई हैं, वहां पर वैसे ही अपने शेयर से 5 गुना लोन मिल सकता है । यह लोन कोग्राप्रेटिव डिपार्टमैंट से मिलेगा । जो भी हो सकेगा, उस को सहूलत दी जाएगी ।

श्री रूप लाल मेहता : क्या मुख्य मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या सरकार उन एलानों पर कायम है जोकि मुख्य मंत्री ने बजट सैशन में यहां पर दिए थे । हम ने इन्हीं आश्वासनों के कारण लोगों को डीज़ल पम्पिग सैट्स लगाने के बारे में कहा । क्या सरकार अब सबसिडी में कमी करने के बारे में सोच रही है जिस की वजह से केस को डिसाइड करने में डिले की जा रही है ।

मुख्य मन्त्री : सरकार ने पहले जो वायदे किए, उन पर उसी तरह से कायम है । जैसा कि सरदार कपूर सिंह ने कहा है कि अभी तक तारीख के बारे में विचार किया जा रहा है । बाकी सारी चीज़ों के बारे में फैसला हो चुका है । मैं हाउस को बताना चाहता हूं कि शायद हम ज़मींदारों को और भी सहूलतें दे सकें । आज यहां पर गवर्नमैंट आफ इंडिया के एग्रीकल्चर मिनिस्टरी के एडवाइज़र श्री एम० एस० रंधावा तशरीफ ला रहे हैं । उन के साथ मुख्तलिफ ईशूज पर बातचीत हो रही है जैसे कि डीजल इंजन, डीजल आयल वगैरा डीलर्ज़ ने पम्पिग सैट्स की जो कीमतें भी बढ़ा दी हैं, उस के बारे में भी विचार किया जाएगा । हम कोशिश करेंगे कि केन्द्रीय सरकार के द्वारा रीज़नेबल रेट्स पर लोगों को पम्पिग सैट्स मुहय्या कर सकें ।

कामरेड बाबू सिंघ मासटर : आन ए पुआइंट आफ आरडर, मैडम, इस सवाल दे बारे चीफ मनिसटर साहिब ने, होम मनिसटर साहिब ने, फिनांस मनिसटर साहिब अते सटेट मनिसटर फार ऐनीमल हसबैंडरी ऐंड ऐगरीकलचर ने वखरे वखरे जवाब दित्ते हन। मैं पुछणा चाहुंदा हां कि असीं किस मनिसटर दे जवाब नूं ठीक समझीए ?

उपाध्यक्षा : चीफ मिनिस्टर साहिब की बात को ठीक मान लीजिए । (The reply given by the Chief Minister may be accepted as correct.)

डाक्टर बलदेव प्रकाश : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडम । जब आप रूस गई हुई थीं तो स्पीकर साहिब ने एक रूलिंग दिया था कि सवाल के सप्लीमैंटरीज का जवाब मिनिस्टर इंचार्ज दे ताकि माननीय सदस्यों को कोई कंफ्यूजन न हो और कंसर्ड मिनिस्टर की ज़िम्मेदारी भी आयद हो सके । आप को पता ही है कि इस सवाल के जवाब में मोस्टली सब मिनिस्टरों ने अपना २ जवाब दिया है जो कि एक दूसरे से भिन्न है । फिनांस मिनिस्टर साहिब ने बताया कि अभी तक सबसिडी देने के बारे में डेट का फैसला नहीं किया जा सका । इस महकमे के स्टेट मिनिस्टर साहिब ने फरमाया कि डेट का फैसला हो चुका है लेकिन वह डेट को हाउस में बताना नहीं चाहते हैं । इसी तरह से सरदार दरबारा सिंह ने जवाब देते हुए बताया कि लगभग केस डिसाइड हो चुका है । चीफ मिनिस्टर साहिब ने और जवाब दिया है । हमें आप बताएं कि हम किस मिनिस्टर के जवाब को ठीक समझें ताकि कंफ्यूजन पैदा न हो ।

गृह तथा विकास मन्त्री : इस में कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है । सवाल तो यह था कि आया जिन लोगों ने डीजल के पंम्पिग सैट्स खुद लगवाए हैं, क्या उन को सबसिडी दी जाएगी ? अगर दी जाएगी तो कब से दी जाएगी ? इस के बारे में फैसला किया गया कि अगस्त, 1964 से सबसिडी दी जाएगी और सबसिडी भी उसी रेट्स पर दी जाएगी जिस रेट पर लोनी को दी जाती है । इस में किसी की दो राए नहीं हैं । चीफ मिनिस्टर साहिब ने कहा है कि आज केन्द्रीय सरकार के उच्च अधिकारी के साथ मीटिंग हो रही है और हो सकता है कि इस मीटिंग में ज़मींदारों को और सहूलतें देने में कामयाब हो सकें ।

इस में कंफ्यूजन की कोई बात हमारी तरफ से नहीं हुई । अगर माननीय सदस्य समझते हैं कि कोई कंफ्यूजन हुई तो मैं समझता हूं कि उन की तरफ से ही कंफ्यूजन हुई होगी । हम ने तो क्लीयर बात की है (हंसी) ।

श्री बनवारी लाल : क्या मंत्री महोदय कृपया बताएंगे कि जिन नजूल लैंड्ज पर हरिजन कोआप्रेटिव सोसायटीज़ के द्वारा काश्त कर रहे हैं, अगर वह वहां पर पम्पिंग सैट्स लगाना चाहें तो क्या सरकार उन को पम्पिंग सैट्स के बारे में सबसिडी देने के लिये विचार करेगी या नहीं ?

मन्त्री : इस के विषय में जितनी भी कोआप्रेटिव सोसयटीज़ बनी हुई हैं, उन के केसिज को देख कर अगर उन को कोई लाभ हो सकता है तो उन को सबसिडी देने से महरूम नहीं किया जाएगा ।

ਲਫਟੀਨੈਂਟ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਮੈਡਮ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ੂਲ ਲੈਂਡਜ਼ ਤੇ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਈਟੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਐਸ. ਸੀ. ਐਲ. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਣ ਕਾਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਭਾਵੇਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਉਹ ਅਪਣੇ ਕੈਪੀਟਲ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ੫ ਗੁਣਾ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਈਟੀਜ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਭੇਜ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਕਨਸਰਨਡ ਮਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਆਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤਾਕਿ ਉਥੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕੇ।

ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਮੈਡਮ। ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ, ੧੯੬੫ ਵਿਚ ਪੰਪਿੰਗ ਸੈਟਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਕਾਇਮ ਹਾਂ। ਇਕ ਪੰਪਿੰਗ ਸੈਟ ਉਤੇ ੭੫੦ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ੭੫੦ ਰੁਪਿਆ ਵਿਚੋਂ ੩੭੫ ਰੁਪਏ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਪੇ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੇਸ ਕੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਪੰਪਿੰਗ ਸੈਟ ਉਤੇ ੭੫੦ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਹੋਵੇ ?

ਮੰਤਰੀ : ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਮਨਿਸਟਰ ਦੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਅਗਰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸੈਪੇਰੇਟ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਮਟ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Headquarters of Khol Block in Gurgaon District

***8796. Rao Nihal Singh ;** Will the Minister for Home and Development be pleased to state whether the case abou the location of the headquarters of Khol block in Gurgaon District has been finalised ; if so, the name ot the place selected for the purpose of locating the office of the B.D.P.O. Khol. and the time by which the building of the said office is likely to be completed

Sardar Darbara Singh : (a) No.

(b) and (c) In view of (a) above, question does not arise as yet.

Diversion Drain of Drain No. 8

***8697. Shri Mangal Sein :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state —

(a) the progress of construction work done on the diversion drain of drain No. 8 ;

[Shri Mangal Sein]

(b) the total expenditure incurred in district Rohtak during the year 1965 on various drains giving the amount separately for each drain ?

Chaudhri Rizaq Ram :

(a) (i) Earthwork done is .. 176,96 lacs cft.
(ii) Suspension bridges 4 Nos.

			Rs.
(b)	(1)	Remodelling drain No. 6 ..	2,73,269
	(2)	Constructing Dobeta Drain ..	40,208
	(3)	Constructing Larsauli Drain ..	36,655
	(4)	Constructing Bhola Drain ..	13,054
	(5)	Checking overflow of drain No. 8 ..	1,11,969
	(6)	Constructing link drain of outfall ..	235
	(7)	Remodelling Nai Nalla Drain ..	20,872
	(8)	Constructing Isapur Kheri Drain ..	34,109
	(9)	Constructing Chhapra Drain ..	43,263
	(10)	Constructing 2nd defence of Gohana Protection bund ..	14,018
	(11)	Constructing Jassia Drain ..	5,743
	(12)	Constructing Rithal Drain ..	491
	(13)	Constructing Hansi Anti-waterlogging Scheme ..	2,270
	(14)	Diversion Drain No. 8 ..	11,30,661
		GRAND TOTAL ..	17,26,817

श्री सागर राम गुप्ता : ड्रेन नम्बर Eight के बारे में सवाल है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा रीप्रेज़ेंटेशन गवर्नमैंट के पास आया है कि इस ड्रेन को भवानी की तहसील में लोहारू की सब-तहसील की तरफ एसवटैंड कर दिया जाए ताकि कुछ सिंचाई हो सके, अगर हुआ है तो इस के बारे में गवर्नमैंट ने क्या कार्यवाही की है ?

मन्त्री : नम्बर एक के बारे में नहीं बल्कि नम्बर 8 दादरी के बारे में रीप्रेजेंटेशन आया है। लोहारू की तरफ से एक्सटेंड करने की फीज़ीबिलिटी नहीं है। गोहाना की तरफ से लोहारू में पानी आ सकता है। उस को ऐग्ज़ामिन करेंगे।

श्री बनवारी लाल : मिनिस्टर साहिब ने फरमाया है कि दादरी की तरफ से नम्बर 8 ड्रेन को डाईवर्ट किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि उस में पानी कब तक छोड़ दिया जाएगा और उस के द्वारा सिंचाई कब तक हो जाएगी ?

मन्त्री : अगर इस साल बारिश ज्यादा होती तो इसी साल छोड़ दिया जाता। अगले साल पानी छोड़ दिया जाएगा।

श्री अमर सिंह : मिनिस्टर साहिब ने फरमाया है कि हांसी एंटी-वाटरलागिंग स्कीम पर 2,270 रुपये खर्च करने हैं। उस पर तो 22 लाख रुपया खर्च करने के बाद भी 8 गांव तबाह हो गए थे। अब भी 34 गांव तबाह होने लगे हैं। इन हालात में क्या मैं जान सकता हूं कि इस थोड़ी सी रकम के खर्च करने से वहां क्या फायदा होगा ?

मन्त्री : यह रकम खर्च करनी नहीं है बल्कि यह वह रकम है जो कि पहले वहां पर खर्च हो चुकी है। जो खर्च होगा वह नहीं पूछा गया।

श्री रामधारी बाल्मीकि : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि रियाल और छपरा के अन्दर पानी कब तक छोड़ दिया जाएगा ?

मन्त्री : छपरा ड्रेन तो मुकम्मल हो चुकी है। रियाल के बारे में ऐग्ज़ामिन कर रहे हैं। जहां तक रिन्धाना गांव का सवाल है वहां पर डिप्रेशन ज्यादा है उस का पानी छपरा ड्रेन में नहीं आ सकता।

Darbara Singh Committee Report

***8683. Comrade Shamsher Singh Josh :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether any steps have so far been taken by the Government to implement the recommendations contained in the Report submitted by the Betterment Committee headed by S. Darbara Singh ; if uo steps have been taken, the reasons for the same ?

Chaudhri Rizaq Ram ; Yes. The later part of the question does not arise.

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਿਆਂ ਸਫਾਰਸ਼ਾਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਹਨ ?

मन्त्री : कुछ सिफारिशात तो गवर्नमैंट आफ इंडिया से ताल्लुक रखती थीं उन को उसी लेवल पर टेक अप किया जा रहा है। कुछ ऐसी थीं जिन पर बिजली बोर्ड और इरीगेशन डिपार्टमैंट के दरम्यान एलोकेशन होनी थी। उन को एग्ज़ामिन किया गया है। कुछ सिफारिशात थीं जो कि बैटरमैंट लैवी और फिशरीज़ से जो आमदनी होती है इन से ताल्लुक रखती थीं। उन को भी एग्ज़ामिन किया जा रहा है।

ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

मन्त्री : रिपोर्ट को पब्लिश करने की ज़रूरत नहीं समझी गई। लेकिन कमेटी की सिफारिशात पर कार्यवाही की जा रही है।

सरदार कुलबीर सिंह : क्या वज़ीर साहिब उस रिपोर्ट की कापी हाउस की मेज़ पर रखने की कृपा करेंगे ?

मन्त्री : इस में कोई एतराज़ की बात नहीं है। जब फैसला हो जाएगा तो हम हाउस को कान्फीडैंस में ले लेंगे।

ਕਾਮਰੇਡ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ : ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ੪-੫ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਰਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ?

मन्त्री : इस में टेबल पर रखने की बात नहीं है। डिपार्टमैंट रिकमैंडेशन्ज पर कार्यवाही कर रहा है।

ਕਾਮਰੇਡ ਮਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਮ ਵਿਚ ਇਹ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

मन्त्री ; अब भी आप आएं तो रिपोर्ट आप को पढ़ा देंगे।

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰੀਪੋਰਟ ਛਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ।

मन्त्री : इस रिपोर्ट को छापने से कोई मुफ़ीद परपज़ सर्व नहीं होगा गवर्नमैंट आफ इंडिया से कुछ मुराआत लेनी थीं । इसलिये उस लैवल पर टेकअप कर रहे हैं । कुछ बातों के डीसीज़न स्टेट लेवल पर लेने थे इस लिये उन को स्टेट लेवल पर ऐगज़ामिन कर रहे हैं । उस में टाईम लगता है । अगर कोई मैम्बर साहिब देखना चाहें तो देख सकते हैं ।

सरदार बलवन्त सिंह : क्या मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि अगर बैटरमैंट लैवी के बारे में जो सरदार दरबारा सिंह कमेटी ने सिफारिशात की हैं इन को स्टेट में लागू कर दिया जाएगा तो स्टेट की इकौनिमी पर अच्छा असर पड़ेगा या बुरा पड़ेगा ?

मन्त्री : यह तो आप अन्दाजा ही लगा सकते हैं कि सरदार दरबारा सिंह जो रिकमैंडेशन्ज़ करेंगे उन से बुरा असर कैसे पड़ सकता है ?

कंवर राम पाल सिंह : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इसी तरह से एक मरला टैक्स कमेटी बनी थी । वह इस कमेटी के बाद बनी थी । उस पर डिसीज़न ले कर गवर्नमैंट ने इम्पलीमैंटेशन भी कर दी है लेकिन यह कमेटी उस से पहले की बनी हुई है और इस पर अभी तक फैसला नहीं हो सका, इस का क्या कारण है ?

मन्त्री : मरला टैक्स कमेटी की रिपोर्ट के बारे में तो मुझे मालूम नहीं है लेकिन इस रिपोर्ट को एग्ज़ामिन कर रहे हैं । इस के लिये टाईम दरकार है । जब डिसीजन्ज़ ले लिये जाएंगे उन को इम्पलीमैंट कर दिया जाएगा । जहां तक डिसीज़न्ज़ ले लिये हैं उन की इम्पलीमैंटेशन हो चुकी है ।

सरदार दरशन सिंह चौधरी : क्या मिनिस्टर साहिब बताने की कृपा करेंगे कि सरकार को इस रिपोर्ट पर गौर करते हुए कितने साल हो गए हैं और कितने साल और गौर करने पर लगेंगे ?

मन्त्री : यह रिकमैंडेशन्ज तो चलती रहेंगी ।

ਕਾਮਰੇਡ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ ; ਕੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦਸਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਲੈਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਰੀਏਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਲਾ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਐਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰਖਦੀ ਹੈ ?

मन्त्री : ऐसी कोई रिकमैंडेशन नहीं थी : (विघ्न) ऐसी कोई रिकमैंडेशन नहीं थी कि इसको रिएलाईज़ेशन को ही सस्पैंड कर दिया जाए । कुछ ऐसी रिकमैंनडेशन्ज की थी कि इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड और इरीगेशन डिपार्टमैंट की जो ऐलोकेशन है वह रिवाईज़ होनी चाहिएं । इस के अलावा कुछ सैंट्रल गवर्नमैंट के इन्ट्रैस्ट की और दूसरी बातें थीं । उन की बाबत अभी तक फैसला नहीं हो सका । सैंट्रल गवर्नमैंट से कारस्पांडैंस जारी है । कुछ और भी छोटी मोटी रिकमैंडेशन्ज़ थीं जिन्हें अगर मैम्बर साहिबान चाहें तो मेरे पास आकर देख सकते हैं ।

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਕੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦਸਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਮਰਜੇਂਸੀ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਉਗਰਾਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਉਨਾ ਨੂੰ ਇਹ ਰੀਪੋਰਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਗਰੁਪ ਲੀਡਰਜ਼ ਵਿਚ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ?

मन्त्री : जैसा कि मैं ने पहले भी बताया है, कोई एतराज़ नहीं लेकिन इसकी यूटिलिटी कोई नहीं होगी जब तक कि फाईनल डिसीज़न नहीं कर लेते । वैसे हाउस के आनरेबल मैम्बरान को कान्फीडैन्स में लेने में कोई एतराज़ नहीं है । उन रिकमैंडैशन्ज़ को मैम्बर साहिबान से छुपाने का कोई सवाल नहीं है और अगर डिप्टी स्पीकर साहिबा इजाज़त दें तो मैं उन रिकमैंडेशंज को अभी यहां पर पढ़ सकता हूं ।

Cost of rewinding of electric Motors etc. recovered from certain landowners in Kapurthala District

***8810. Sardar Lakhi Singh Chaudhri ;** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state :

(a) whether any cases occurred during the last one year in Kapurthala District in which the cost of rewinding of electric motors or meters etc, of Government Tube-wells was recovered from the landowners but the amount was credited to Government as if it was deposited by the S.D.O., Tube-wells.

(b) if the reply to part (a) above be in the affirmative, the reasons for the said recovery and for misrepresentation of credits into the Government accounts Deposits made by landowners but booked as if deposited by the S.D.O., Tube-wells;

(c) the total amount realised in each case in Bholath Block in Kapurthala as well as the number of tube-wells in respect of which the amount was realised ?

Chaudhri Rizaq Ram ; (a) Yes, the cost of rewinding of motors was recovered from the cultivators in five cases in Kapurthala Sub-Division, and the amount was credited to Government as received from the cultivators and not as if it was deposited by the S.D.O., Tube-wells.

(b) The recovery was effected as the cultivators were responsible for mis-handling the machinery resulteing in burning of motors. In view of reply given in part (a) above, the question of misrepresentation of credits does not arise.

(c) A statement is laid on the table of the House.

Statement

1. Rs 200 from Shri Hari Singh, son of S. Sham Singh of village Kanswal—Tube-well No. 32-B;

2. Rs 200 from Shri Balwant Singh, son of S. Darbara Singh of village Hamira—Tubewell No. 54;

3. Rs 200 from Shri Jagar Singh, Member Panchayat of village Bahur—Tubewell No. 66;

4. Rs 200 from Shri Amar Singh Sarpanch of village Basi—Tubewell No. 42; and

5. Rs 255 from Shri Piara Singh, son of S. Bur Singh of village Bholar Khurd—Tubewell No. 42.

ਸਰਦਾਰ ਲੱਖੀ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਕਰਨੈਲਗੰਜ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਮਿਸਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ?

मन्त्री : जिन जिन टयूबवैल्ज़ की बाबत मालूम हुआ है पैसे वसूल किए गए हैं उन की बाबत स्टेटमैंट में बता दिया गया है । इस के अलावा अगर आनरेबल मैम्बर साहिब किसी खास गांव की बाबत पूछना चाहें, जिनका उन्हें इल्म हो, तो उस के लिये अलग नोटिस दे दें । पता करके बता दिया जाएगा कि वसूल किए हैं या नहीं किए हैं ।

श्री रुलिया राम : जैसा कि चौधरी लक्खी सिंह ने करनैलगंज की बाबत पूछा है, मेरा ख्याल है कि अगर गवर्नमैंट खुद वहां पैसे वसूल नहीं कर सकती तो वह आनरेबल मैम्बर साहिब के जिम्मे लगा दे कि वह वसूल करादें ।

ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਜਿਤਨੇ ਟਿਊਬਵੈਲਜ਼ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਪਰੇਟਰਜ ਰਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਿਸਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ?

मन्त्री : डिटेल्ज़ तो मेरे पास नहीं है कि किस तरह से यह हालत पैदा हुई लेकिन जो सवाल किया गया कि किन किन से वसूली हुई वह मैं ने बता दिया । वहां इतना ज़रूर है कि पुलिस में उन की रिपोर्ट हुई कि इन इन आदमियों ने उन ट्यूबवैल्ज़ को मिसहैंडल किया है—

Electricity supplied to other States/Territories

***8413. Comrade Ram Chandra :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state —

(a) the names of the States and Territories to which electricity is supplied by the Punjab Government/Punjab State Electricity Board and the rates at which it is being supplied;

(b) the rates at which the other States mentioned in part (a) above are supplying electricity to their own consumers ;

(c) the rates at which electricity is supplied to the consumers in the Punjab State ?

Chaudhri Rizaq Ram ; (a) Electricity is supplied to the States of Jammu and Kashmir, Uttar Pradesh and Union Territories of Delhi and Himachal Pradesh. The rates are given in the Statement attached (Annexure 'A,).

(b) and (c) As in the statement at Annexure 'B'. . .

ANNEXURE 'A'

Schedule of rates for Supply of Bhakra Nangal Power to various States

(i) *Rajasthan and Punjab.* (Partners in Bhakra Nangal Project).—

Demand Charge at Rs 5 per kVA per month.
Plus
Energy Charges at—

2.81 paise per kWh for the first 500,000 kWh/month.

2.66 paise per kWh for the next 1,500,000 kWh/month.

2.50 paise per kWh for all above 2,000,000 kWh/month.

(ii) *Delhi (Delhi Electric Supply Undertaking)*—

(1) Up to 31st March, 1965—As per rates prescribed under item (i) above.

(2) From 1st April, 1965 onwards —

Demand Charge at Rs 5.50 per kVa/per month
Plus
Energy charges at—
3.25 paise per kWh for the first 500,000 kWh/month.

3.00 paise per kWh for the next 1,500,000 kWh/month.

2.75 paise per kWh for the all above 2,000,000 kWh/month.

(iii) *Himachal Pradesh*—

(1) Free suppliy upto 500 k.W. under old Mandi Darbar agreement.

(2) For supplies drawn from Grid Substations —

Rates as prescribed under item (i) above.

(3) For supplies drawn from other non-grid sub stations —

Demand charge at Rs 5.50 per kVA per month
Plus
Energy charges at—

4.38 paise per kWh for the first 10,000 kWh per month.

4.06 paise per kWh for the next 20,000 kWh per month.

3.75 paise per kWh for the all above 30,000 kWh per month.

(iv) *Jammu and Kashmir* s—

(1) for supply dran from Pathankot :

Demand Charges at Rs 5.00 KVA per month
plus
Energy charge at—

3.50 paise per kWh for the first 500,000 kWh/month.

3.25 paise per kWh for the next 1,500,000 kWh/month .

3.00 paise per kWh for the all above 2,000,000 kWh/month.

(2) For supply drawn from Dhar Sub station for electrification of Basohli Town —

As per rates mentioned under item (iii) (3) above..

(v) *Uttar Pradesh* :

As per rates mentioned under item (iii) (e) above (Himachal Pradesh).

ANNEXURE 'B'

Name of State		Domestic Supply		Urban	Rural
1. Himachal	..	1st 15 units/month	..	32 P/unit.	10 P/unit.
	..	Next 25 units/month		13 P/unit	20 P/unit
	..	Above 40 units/month		6 P/unit	6 P/unit.

[Minister for Irrigation & Power]

2. Delhi .. Lights/Fans — Power
17 P/unit — 10 P/unit.
Subject to a minimum charge of—

Rs 2.50 per month below 5 kW.
Rs 3.00 per month per kW thereafter.

3. U.P. .. *Lights/Fans* — *Power*
35 P/unit. — 19 P/unit.
Subject to a minimum carrge of Re 1 to Rs 5 depending upon the load up to 3 kW and Rs 2 per kW thereafter.

4. J&K .. 1st 20 units/month — 25 P/unit.
Next 30 units/month — 19 P/unit.
Next 50 units/month — 12 P/unit.
Above 100 units/month — 9 P/unit.
Subject to a monthly minimum charge of Rs 1.5 and Rs 8.00 for Metre Power.

5. Punjab .. 1st 15 units/month — 31.25 P/unit.
Next 25 units/month — 12.50 P/unit.
Above 40 units/month — 6·25 P/unit.

Name of State	Commercial Supply	Small Power (up to 20 qW)
1. Himachal	1st 30 units/month 34 P/unit Next 50 units/month 12 P/unit Above 20 units/month 70 P/nnit	1st 500 unit/month. 16 P/unit. Abov 200 unit/month 70 P/unit
2. Delhi	*Light Fans* 20 P/unit 14 P/unit Subject to a minimum charge of Rs 3.00 for load below 5 kW Rs 3.50 per kW thereafter.	*Powers up to 10 kw* 1st 50 unit/month 16P/unit above 50 unit/month 10 P/unit
3. U.P.	As per Domesctic	1st 150 units/BHP/ month 12 P/unit Remaining 9 P/unit Subject to minimum charge of Rs 66 per BHP per year.
4. J&K	1st 200 units/month 25 P/unit Next 200 units/month 19 P/unit Next 600 units/month 12 P/unit Above 1,000 unit/ month 9 P/unit Subject to a monthly minimum charge of Rs 2.00 and Rs 10.00 for Metric power	(*Up to* 50 *H.P.*) Demand charge 4 per BHP/month plus Energy charge 4P/unit for Kashmir. 6P/unit for Jammu.
5. Punjab	1st 30 units/month 31.25 P/unit Next 50 units/month 12.50 P unit Above 80 units/ month 9.38 P/unit	1st 500 units/month 10.94P/ per unit Next 1000,units, month 9.38 per unit Above 1500 units/ month 7.81 P/ unit.

Name of State	*Medium Power*
	(21—100 KW)
1. Punjab ..	Demand charges Rs 6.50 per KW/month *Plus* Energy Charges 6.50 P/Unit for 1st 5,000 units/month.
	6.00 P/Unit for above 5,000 units/month
	Subject to a maximum of 10.P/Unit.
2; Delhi	(*Above* 10 *Kw upto* 100 *Kw*) 1st 100 units/month 16 paise/Unit.
	Above 100 unit/month 11 paise /Uni Subject to a minimum guarantees of 40 uni s per KW of load above 25 K.W.
3. U.P.	(*21—Kw* to 85 *Kw*) 1st 200 units per KW/month 11 P/unit. Remaining 9 paise per unit.
	Subject to a minimum charge of Rs 80 per KW per year.
4. J.&K	(Exceeding 50 HP at Medium *Pressure*).
	As per small Power Tariff.
5. Punjab	Demand charges Rs 6.00 per KW/month *plus* Energy charges
	5.31 P/unit for 1st 5,000 units/month.
	4.69 P/unit for next 10,000 units/month
	4.38 P/unit for above 15,000 units/month
	Subject to a maximum rate of 9.38 Paise per unit.

Large Supply
(above 100 Kw)

5

1. Himachal ..	Demand Charges Rs 5.50 per KVA/month plus Energy Charges 5.50 P/Unit for 1st 100,000 units per month
	5.25 P/Unit for next 200,000 units/ month
	5.00 P/Unit for above 300,000 units/month
	Subject to a maximum of 8P/unit.
2. Delhi ..	Demand charges Rs 9.00 to Rs 5 per KW/KVA depending upon the load *plus* Energy Charges
	8.5P/Unit for 1st 50,0000 units/months.
	8.0 P/Uit for next 500,000 units/month

[Minister for Irrigation and Power]

Name of State	Large Supply above 100 Kw
	5
	7.5 P/Unit for next 10,00,000 units/month
	7.00 P/Unit for above 20,00,000 units/month subject to a maximum rate of 13.5 P. per unit without prejudice to the minimum payment as per demand charges.
	a surcharge of 25 percent is leviable if the supply is used during restricted hours without permission.
3. U.P.	*(100 KVA to 500 KVA)* Demand charges Rs 8.00 per KV *plus* Energy Charges 1st 170 units per KVA/month 4.5 P/Unit. Next 170 units per KVA/month 3.5 P/Unit. Remaining units per KVA/month 3.0 P/Unit.
	(More than 500 *KVA)* Demand Charges Rs 8 to Rs 6 depending upon the load plus Energy Charges— 1st 170 units per KVA/month 4P/Unit Next 170 units per KVA/month 3 P/Unit Remaining units per KVA/month 2 P/Unit
4. J&K ..	*(Exceeding 50 H.P. at High pressure)* Demand Charges Rs 4.00 per BHP/month plus Energy Charges 2.5 P/Unit for Kashmir 4 P/unit for Jammu.
5. Punjab	Demand Charges Rs 5.00 per KVA/month plus Energy Charges 4.06 P/Unit for 1st 100,000 units/month 3.75 P/Unit for next 200,000 units/month. 3.44 P/Unit for above 300,000 unit/smonth Subject to (i) rebate of 0.94 P/unit for all units in excess of 360 units per KVA. (ii) a maximum rate of 5.63 P/Unit.

Name of State	Agricultural Supply		Bulk Supply to Licensee	Street Lighting
1. Himachal	1st 1,500 units/month	9 P/Unit	Demand Charge 6.87 KW per month plus Energy Charges 4.38 P/Unit for 1st 1,00,000 U/Month 4.06 P/Unit for next 2,00,000 U/Month	14 Paise per unit
	Above 1,500 units / month	8 P/Unit		

Name of State	Agricultural Supply	Bulk Supply to Licensee	Street Lighting
		3.75 P/Unit for above 3,00,000 U/month Subject to a maximum rate of 3.54P/ month without prejudice to the monthly minimum payment as per demand charges.	
2. Delhi	..	..	..
3. U.P.	Fix charges Rs 150 per BHP/year plus 5P/Unit Energy Charges 5.5P/Unit. subject to a minimum charge of one twelth of fixed charge plus energy charges	Demand charges Rs 12.75 to Rs 8.50 per KVA/ month depending upon the load *plus* 1st 170 units per KVA/ monthP/month Next 170 units per KVA/ month 4P/months Remaing units per KVA/ month 3 P/month	35 per unit
4. J&K	9.38P/Unit for 1st 1500 unit/ month 7.81 P/unit for above 1500 unit/ month	Demand Charge Rs 5.50 per KVA/month plus Energy Charges 4.38 P/unit for 1st 100 units/month 4.06 P/unit for next 20,000 units/months 3.75 P/Unit for above 30,000 units/month subject to a maximum rate of 7.81 P/unit without prejudicetothemonthly minimum payments as per demand charges	14006 P/ unit a rebate of 25 is allowed for street Light, in village Panchayats
5. Punjab	..	..	..

श्री बलरामजी दास टंडन : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जो रेट्स दूसरी स्टट्स से चार्ज किए जाते हैं उन में और जो रेटस शिमला और अमृतसर म्युनिसिपल कमेटियों से बिजली के सम्बन्ध में चार्ज किए जाते हैं उन में इतना ज्यादा फर्क क्यों है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री : अर्ज यह है कि इस सम्बन्ध में पांच छः पेजिज़ की एक बड़ी लम्बी चौड़ी स्टेटमैंट हैं जिसमें उन सभी के रेट्स दिए हुए हैं। जिन स्टेट्स को बिजली दी जाती है उन में राजस्थान है, देहली है, हिमाचल प्रदेश और जम्मू काश्मीर है। इस स्टेटमेंट के अन्दर कन्जयूमर, डोमैस्टिक, कमरशियल वगैरा के सब के अलग अलग रेट्स दिए हुए हैं और उन का डिफरेंस भी दिया है।

कामरेड राम चन्द्र : क्या मैं विद्युत मंत्री महोदय से यह दरियाफत कर सकता हूं कि जो बिजली राजस्थान को 2.8 पैसे पर यूनिट, देहली को 3.25 पैसे पर यूनिट, हिमाचल प्रदेश को 4.38 पैसे पर यूनिट और जम्मू काश्मीर को 3.50 पैसे पर यूनिट दी जाती है पंजाब के अन्दर वही बिजली 32 पैसे पर यूनिट क्यों दी जाती है ?

मन्त्री : अगर आप मुलाहिज़ा फरमाएं तो हर एक स्टेट के अन्दर अलग अलग रेट्स हैं। हमारे यहां भी डिफरेंस रेट्स हैं जैसे डोमैस्टिक सप्लाई के लिये पहले 15 यूनिटस का रेट 31.25 है, उस से आगे 25 के लियें 12.50 पैसे हैं और 40 से ऊपर 6.25 पैसे

[सिंचाई तथा विद्युत मंत्री]

पर यूनिट है। पंजाब में इस तरह से है। जहां तक राजस्थान का ताल्लुक है, वह इसमें एक पार्टनर है और जो देहली को सप्लाई करते हैं उसकी बाबत जो रेट्स हैं वह भी अप्रैल, 1965 से रिवाइज़ किए गए हैं और उसके मुताबिक अब रेट्स में फर्क है।

कामरेड राम चन्द्र : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं ने जो सवाल किया था वह दूसरा था। मैं ने यह पूछा था कि जो बिजली हमारे पंजाब से दूसरी स्टेट्स को इतनी सस्ती दी जाती है पंजाब में वही क्यों इस कदर महंगी दी जाती है। सवाल यह है कि यहां से लेकर जब दूसरी स्टेट्स मुनाफे पर बिजली को बेचती हैं और फिर भी वहां पंजाब से सस्ती बिजली लोगों को मिलती है तो क्या कारण है कि यहां पंजाब के अन्दर बिजली महंगी दी जाती है ?

मन्त्री : जो हम उन गवर्नमैंट्स को बिजली देते हैं उस के रेट्स में और आगे जो वह कन्ज्यूमर्ज़ को देते हैं उन रेट्स में भी फर्क है। हम उन को बल्क सप्लाई देते हैं। राजस्थान को, जम्मू और काश्मीर को, देहली को और हिमाचल प्रदेश को जो बिजली दी जाती है वह बल्क सप्लाई है। राजस्थान इस में हमारा पार्टनर भी है। बल्क सप्लाई का रेट डिफरेंट है और जो आगे वह कन्ज्यूमर को देते हैं उसका रेट अलग है।

श्री बलरामजी दास टंडन : फिर भी पंजाब की निस्बत वह अपनी अपनी स्टेट्स में कन्ज्यूमर्ज़ को सस्ती बिजली देते हैं।

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਕੀ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੋੜ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਬਾਰੇ 24 ਫੀਸਦੀ ਕਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਬਲਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਘਟ ਰੇਟਸ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੇਟਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੇਟਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ?

मन्त्री : जहां तक कट्स का ताल्लुक है, जो बिजली हम राजस्थान को देते हैं उसमें कट लगाने का सवाल नहीं और इस तरह से जम्मू और काश्मीर की सप्लाई पर भी कट नहीं लगाया। उस से कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता था। राजस्थान को जो बिजली सप्लाई कर रहे हैं असल में उन को जितनी बिजली की ज़रूरत है, जितनी मिलनी चाहिये उस से भी कम मिल रही है। इसलिये कोई कट नहीं लगाया।

देहली को 80 मैगावाट सप्लाई में से 20 मैगावाट का कट लगाया है। बाकी अपनी स्टेट में भी फरटेलाईज़र फैक्टरी पर 18 परसैंट का कट लगाया है। जो बार्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं यानी गुरदासपुर, अमृतसर और फिरोज़पुर वहां पर पहले ही 20 परसैंट कम कन्ज़म्पशन थी और इंडस्ट्री को काफी नुक्सान हुआ है, इंडस्ट्री काफी अफैक्ट हुई है। इस बात को ध्यान में रखते हुए इन तीनों ज़िलों में कोई कट नहीं लगाया है। बाकी सारी स्टेट में एक लेवल पर यह कट लगाया गया है और जो मिनीमम कट लगाया गया है वह फर्टेलाईज़र फैक्टरी पर लगाया गया है।

श्री बलरामजी दास टंडन : क्या सिंचाई मंत्री जी बताएंगे कि जिस रेट पर दिल्ली, राजस्थान और जम्मू काश्मीर को बिजली की बल्क सप्लाई की जा रही है क्या उसी रेट पर यह अमृतसर और शिमला कमेटियों को भी सप्लाई करने के लिये तैयार हैं ? अगर नहीं है तो इस की वजह क्या है ?

मन्त्री : दिल्ली और जम्मू काश्मीर और राजस्थान के साथ रेट का एग्रीमेंट हुआ है जिस को हम रिवाईज़ नहीं कर सकते। बल्कि राजस्थान का तो भाखड़ा पावर प्लांट में अपना शेयर भी है।

ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਰੇਟ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਰਚੇਜਿਜ ਵਾਸਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਿੱਲੀ, ਹਮ ਚਲ ਪਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਸੇ ਰੇਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।

मन्त्री : उन को कमरशियल परपज़िज़ के लिये किसी अलग रेट पर बिजली सप्लाई नहीं करते बल्कि हम उन्हें बिजली की बल्क सप्लाई करते हैं। दिल्ली को हम जो 31 मार्च 1965 तक बिजली सप्लाई करते रहे हैं वह पहले 500,000 के डबलियो. एच. 2.18 पैसे फी किलो वाट के हिसाब से और उस से आगे 2.60 और उस से आगे 2.50 पैसे फी किलो वाट के रेट पर सप्लाई करते थे लेकिन अब 1 अप्रैल, 1965 से यह रेट बढ़ा कर 3.24 पैसे कर दिया गया हुआ है। इस तरह से हम उन्हें बल्क सप्लाई करते हैं और यह बाकायदा सर्टन एग्रीमेंट के तहत सप्लाई की जाती है जिन के मुताबिक हम यूनीलेटरेली रेट्स को तब्दील नहीं कर सकते।

ਕਾਮਰੇਡ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ : ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਭਾ ਤੇ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਭਾ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਦੁਗਣੇ ਭਾ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ?

मन्त्री : आहिस्ता २ सब जगह पर एक ही रेट लागू कर रहे हैं। वहां भी वही रेट हो जाएगा। जब तक के लिये उस ठेकेदार का लाईसेंस बना हुआ है उस वक्त तक हम इस में कोई तबदीली नहीं ला सकते।

डाक्टर बलदेव प्रकाश : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि दिल्ली, राजस्थान, और जम्मू काश्मीर को पंजाब सरकार बल्क सप्लाई में बिजली सस्ती दे रही है और वहां की सरकारें आगे अपने उस पर टैक्स लगा कर भी वहां के लोगों को चाहे कमरशियल परपज़िज़ के लिये हों चाहे डोमेस्टिक परपज़िज़ के लिये हों और चाहे किसी मतलब के लिये हो, पंजाब से सस्ती रेट्स पर दे रही है इस की क्या वजह है ?

मन्त्री : राजस्थान में बिजली का रेट पंजाब से महंगा है और हम अगर इस पर लगी डियूटी को एक्सक्लूड कर दें तो दिल्ली के रेट्स और हमारे रेट्स में कोई खास फर्क नहीं रह जाता फिर दिल्ली एक सेंटरली एमिनिस्टर्ड स्टेट है और वह टैक्स न लगाना एफोर्ड कर सकती है लेकिन हम ने तो अपने ही रिसोरसिज़ पर डिपैंड करना होता है इस लिये हमें यह डियूटी लगानी पड़ती है।

उपाध्यक्षा : चौधरी साहिब, अगर आप अपनी मजबूरी बता दें कि आप बाहर के लोगों से क्यों रेट कम लेते हैं और अपने घर वालों से क्यों आप को ज्यादा रेट लेना पड़ता है तो इतने सप्लीमेंटरीज़ इस बारे में नहीं पूछे जाएंगे। (The number of supplementaries which are likely to be asked on this question will fall considerably if the hon. Minister explains the circumstances under which the State Government has been obliged to charge lower rates for supply of power to out siders and higher rates for supply to the people of this State.)

मन्त्री : कुछ स्टेट्स को हम सस्ते रेट्स पर इस लिये सप्लाई करते हैं क्योंकि उन का ट्रांसमिशन लाईन्ज और जनरेटरज़ में भी हिस्सा है जैसा कि राजस्थान स्टेट है। इस के अलावा हम दिल्ली को क्योंकि बल्क सप्लाई करते हैं इस लिये हमें उसे सस्ती बिजली देनी पड़ती है।

श्री बलराम जी दास टंडन : डिप्टी स्पीकर साहिबा, सवाल कुछ होता है और यह जवाब कुछ और दे रहे हैं इस तरह से यह हर सवाल को बाई पास करने की कोशिश कर रहे हैं।

उपाध्यक्षा : आर्डर प्लीज़ : मैं पसंद नहीं करती इस तरह से जो आप इन्ट्रप्ट करते हैं। (Order please. I do not like such interruptions by the hon. members.)

मन्त्री : तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि दिल्ली को और जम्मू काश्मीर को हमें सर्टेन एग्रीमेंटस के तहत बिजली सप्लाई करनी पड़ती है इस लिये हम युनीलेटरली रेट्स रिवाईज़ नहीं कर सकते। यह ऐग्रीमेंटस उस वक्त किए गए थे जिस वक्त हमारे पास बिजली बड़ी मात्रा में सरपलस थी और हम इस बात का अन्दाजा भी नहीं लगा सकते थे कि हमइस सरपलस बिजली को कैसे युटेलाइज़ कर सकेंगे। दिल्ली के रेट को हम ने बड़ी मुश्किल के साथ रिवाईज़ किया है। हमारा इस चीज़ के साथ कोई वास्ता नहीं कि वह अपने कनज्यूमर्ज़ को किस रेट पर आगे सप्लाई करती है। हम ने तो अपने कन्ज्यूमर्ज़ को उस रेट पर देनी है जो टैरिफ हम ने फिक्स कर रखा हुआ है इस के अलावा इस पर हमारी डियूटी है। इस लिये अगर इस रेट से अगर हम डियूटी को अलग कर दें तो दिल्ली के रेट में और यहां के रेट में कोई खास फर्क नहीं रह जाता।

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਯੂ. ਪੀ. ਦਿਲੀ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਔਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟਸ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਲਕ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਖ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨੇ। ਇਸਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ?

मन्त्री : वह चाहे कोई रेट अपने कनज्यूमरज से चार्ज करें हमारा इस से वास्ता नहीं है। (शोर)

डाक्टर बलदेव प्रकाश : मैं मिनिस्टर साहिब से यह पूछना चाहता हूं कि जिस रेट पर बिजली की बल्क सप्लाई जम्मू काश्मीर, राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल को की जा रही है क्या वह रेट इस की कास्ट आफ प्रोडक्शन से कम है या ज्यादा है ? अगर यह कम है तो इस से जो लास गवर्नमेंट को पड़ता है क्या इस को क्वर करने के लिये पंजाब के लोगों को जो बिजली सप्लाई की जाती है क्या उस पर डियूटी लगा रखी है ?

मन्त्री : जो बिजली उन स्टेट्स को दी जाती है उस पर ट्रांसमिशन लाईन्ज का खर्च जो है वह कम है और उस के मुकाबिले में हमारा खर्च ज्यादा होता है क्योंकि उन्हें हम बल्क सप्लाई करते हैं।

श्री फतेह चन्द विज : क्या वजीर साहिब बताएंगे कि क्या वह ठीक है कि पंजाब गवर्नमेंट ने स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड को बिजली के रेट कम करने के लिये लिखा था और बोर्ड ने इस की बात को नहीं माना ?

मन्त्री : नहीं, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि बिजली बोर्ड ने 1960 में फैसला किया था टेरिफ को बढ़ाने का। उस के बाद उस ने 1964 में यह दोबारा फैसला किया था कि टेरिफ 1965 से बढ़ा दिया जाए लेकिन गवर्नमैंट ने उस की बात मानने से इन्कार कर दिया है। और उसे ऐसे करने से रोका है।

पंडित मोहन लाल दत्त : क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि हिल्ली एरियाज़ में लोगों की माली हालत बड़ी कमज़ोर है और उस वजह से वह बिजली के इतने हाई रेट नहीं दे सकते क्या सरकार उन के लिये बिजली के रेट में कोई कमी ला रही है और अगर नहीं ला रही तो क्या वह इस बारे में सोच कर इस में कमी लाएगी ?

मन्त्री : अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं की जा रही क्योंकि हिल्ली एरियाज़ के अलावा भी तो पंजाब में और कई स्थान ऐसे हैं जहां के लोगों की वहां जैसी ही हालत है।

उपाध्यक्षा : इस के लिये कोई जस्टीफिकेशन होनी चाहिए। अगर वह आप दे दें तो इस बारे में काफी हद तक सपलीमेंटरीज़ खत्म हो जाएंगे। (The hon. Minister should justify this action. If that is done the number of supplementaries will come down to a considerable extent.)

कामरेड भान सिंघ भौरा : ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਕਿਉਂ ਰਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ? ਕੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪੈਨਸੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ?

मन्त्री : यह सवाल तो और है। इस की डीटेल्ज़ जानने के लिए सैपेरेट नोटिस दें।

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਮੈਂ ਤਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਵਜੁਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗਲ ਵਲ ਦਿਵਾਉਣੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਅਗੇ ਵੀ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਵਾਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੇਕ ਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਬਾਕੀ ਜਿਥੇ ਤਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਤਅੱਲੁਕ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਰਿਜ਼ਕ ਰਾਮ ਜੀ ਤਾਂ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਚੌਧਰੀ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੈ ਇਹ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਕੇ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। (ਹਾਸਾ)

डाक्टर बलदेव प्रकाश : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि बिजली के रेट्स में जो बड़ी बढ़ोत्री हुई है उस की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि पंजाब के बिजली बोर्ड के अन्दर मिसमैनेजमैंट, इर्रेगुलेरिटीज़ और बंगलिंग है जिस की वजह से खर्च बहुत बढ़ा हुआ है और क्या इस के लिये सरकार के पास कोई अपील आई है कि इस बोर्ड की अटौनोमी को खत्म किया जाए और इस काम को सरकार अपने हाथ में ले ले ? क्या सरकार इस पर गौर कर रही है ?

मन्त्री : मैनेजमैंट के मुताल्लिक आप ने बड़ा जेनरल सा सवाल कर दिया है। शिकायतें तो किस्म २ की आती रहती हैं और यह भी ठीक है कि कुछ लैजिसलेटर्ज़ ने भी लिख कर दिया है कि बोर्ड को हटा दिया जाए। मगर इस में एक बात वाज़ेह होनी चाहिये कि इस बोर्ड को बनाने या खत्म करने में पंजाब सरकार की मर्ज़ी की ही बात नहीं है, यह बोर्ड ज़ तो सारी स्टेट्स में सैंट्रल ऐक्ट के तहत बनाए गए हैं। बाकी इस के मैनेजमेंट के मुताल्लिक मैम्बरान और चेयरमैन से बार २ मीटिंग करके इस को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। आप साहिबान भी जो सजैशन्ज़ देंगे उन पर भी गौर करेंगे।

उपाध्यक्षा : चौधरी साहिब मेरी वाकफियत के लिये आप बताएं कि क्या आप को तसल्ली है उस काम से जो कि बोर्ड में हो रहा है। अगर आप की इस काम से तसल्ली नहीं है तो इस का इन्तजाम हो सकता है। (The hon. Minister Chaudhri Sahib, may kindly state for my information whether he is fully satisfied with the work being done by the Electricity Board. If not then some proper steps could be taken.)

मन्त्री : इस के काम से कहीं पर तसल्ली है और कहीं पर नहीं भी है। (हंसी) हम इस को इम्प्रव करने की कोशिश कर रहे हैं।

Collections made under the Punjab Temporary Taxation Act, 1962

***8684. Comrade Shamsher Singh Josh** : Will the Minister for Welfare and Justice be pleased to state—

(a) the actual amount so far utilised from the fund collected for the betterment of Harijans under the Punjab Temporary Taxation Act, 1962 ;

(b) the details of the plans/schemes, if any, formulated for utilizing the "remaining amount" and the probable time within which these are expected to be implemented ?

Shri Chand Ram : (a) An expenditure of Rs 1.95 crores (approximately) was incurred out of the Temporary Taxation proceeds till June, 1965, for advancing loans to Harijans for purchase of Evacuee land in restricted auctions.

(b) The remaining amount is proposed to be utilised on schemes for purchasing agricultural land for Harijans/setting up of tannaries/Housing Colonies for sweepers/Cattle Breeding Colonies, advancing interest-free loan, etc. These schemes of which details are being worked out, are proposed to be implemented during the current financial year 1965-66, as far as practicable.

ਕਾਮਰੇਡ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ : On a point of order, Madam. (ਵਿਘਨ) ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਥੇ ਇਕ ਹੋਰ ਹਾਊਸ ਲਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। (ਵਿਘਨ)

Deputy Speaker : I have called the next question.

ਕਾਮਰੇਡ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ : On a point of order. (ਵਿਘਨ)

Deputy Speaker I cannot allow you this latitude.

ਕਾਮਰੇਡ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ : ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। (ਵਿਘਨ)

उपाध्यक्षा : गर्ग साहिब, ज़रा हटाओ न उनको। बार बार इन्टरप्शन हो रही है। (Shri Garg may please ask members of his party to refrain from making interruptions).

ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ : ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ 3 ਲਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ 96 ਲਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਹੈ ?

Irrigation and Power Minister : Madam, the position is that Rs 2.03 lakhs were placed at the disposal of the Rehabilitation Department for advancing loans to Harijans for the purchase of evacuee land in restricted auction, and out of this Rs 1.95 lakhs have been accounted for so far. It may be that the remainng amount may also have been distributed but that has not been accounted for.

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਖਬਰ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਫਿਲਮ ਬਣੇਗੀ, 'ਹਮ ਸਭ ਏਕ ਹੈਂ' ਉਸ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀਰੋ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਮਿਲਕੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਸੰਨੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਹੀਰੋਇਨ ਬਨਣ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ? (ਹਾਸਾ)

Sardar Gurnam Singh : Is the Government prepared to set up some industry with this money for the benefit of Harijans instead of wasting the money by giving small doles ?

मन्त्री : यह बात भी under consideration है कि कोई इन्डस्ट्री सैंट अप की जाए।

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵਾਜ਼ੇ ਪਾਲਸੀ ਲੇ ਡਾਊਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲੋਨਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਰੁਪਿਆ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਰਟ ਵਿਚ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਪਰਸੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਪਾਲਸੀ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਐਲਾਉ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ?

मंत्री : अब तक दो करोड़ तीन लाख रुपया इवैक्वी प्रापर्टी खरीदने के लिये लोन दिया गया है इस फंड में से। इस सारे मामले पर सरकार ने दोबारा गौर किया और इस नतीजे पर पहुंची कि इस में कैश देने की जरूरत नहीं है। जो हरिजन भाई बिड करें वह रकम दस साल में किश्तों में अदा करें पहली किश्त उस से एक साल बाद या उस से भी बाद जब प्रोडक्शन होने लगे तब ली जाए। इस लिये इवैक्वी लैन्ड्ज़ को खरीदने के लिये लोन्ज़ देने की जरूरत नहीं है मगर वैसे उन को लोन्ज़ देने का प्रोवियन है। बाकी जहां तक इस से होने वाले बैनीफिट्स का ताल्लुक है तो इस का जायज़ा लेने के लिये एक इवेल्यूएशन कमेटी बनाई जा रही है।

चौधरी रण सिंह : वजीर साहिब ने बताया है कि इस फंड में से एक करोड़ 96 लाख रुपया इनफीरियर इवैक्वी लैंड खरीदने पर खर्च किया गया है। क्या सरकार यह महसूस करती है कि यह रुपया फजूल ही खर्च किया गया और अब वही रुपया इस फंड में वापिस डाल कर दूसरी फायदामन्द स्कीमों पर खर्च किया जाना चाहिये। क्या सरकार ने ऐसा अनुभव किया है ?

मंत्री : यह तो नहीं कहा जा सकता कि जो खर्च जमीन खरीदने पर हुआ है वह फजूल है। फिर भी इस सवाल को कैबिनट की एक सबकमेटी ने देखा है और सिफारिश की है कि यह जो दो करोड़ तीन लाख रुपया है यह वापिस हरिजन कल्याण फंड में डाला जाए और जो लोन्ज़ दिये गए हैं वह सरकार अपने कनसौलीडेटिड फंड में वसूल करे। मगर इस बारे में आखिरी फैसला नहीं हुआ।

श्री अमर सिंह : क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि पिछले दिनों सैशन में यह फैसला किया गया था कि दो करोड़ तीन लाख रुपया हरिजनों के वैलफेयर रिवाल्विंग

[श्री अमर सिंह]

फंड में जमा कर दिया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसा कर दिया गया है या इस बारे में गौर हो रहा है और क्या वह यह भी बताएंगे कि यह पांच करोड़ रुपया कब तक हरिजनों के कल्याण की स्कीमों पर खर्च कर दिया जाएगा ?

मंत्री : यह तो अन्डर कनसिड्रेशन है कि कब जमा किया जाए या न किया जाए। एक सब-कमेटी बनाई हुई है और वह सिफारश करेंगी कि रुपया कब जमा किया जाये। आजकल वैसे भी फाइनेंशल पोजीशन टाइट है....

Deputy Speaker : The Question Hour is over now but supplementaries on this question will continue tomorrow.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE UNDER RULE 45

Recovery of Jeep seized by culprits from Pt. Siri Ram Sharma, Ex-Minister

*8409. **Comrade Ram Chandra** : Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

(a) the circumstances in which Pt. Siri Ram Sharma, an Ex-Minister of the State while travelling with some officers in a Jeep was relieved of the Jeep some time in July, 1965 ;

(b) the action so far taken by the Government to apprehend the culprits and recover the jeep ?

Sardar Darbara Singh : (a) Pt. Siri Ram Sharma, Chairman, Flood Relief Committee, Rohtak accompanied by Sarvshri Ajit Singh Nagpal, PCS., Rao Chander Bhan, Tehsildar, Jhajiar, Ram Narain, Advocate, Mangli Ram Vaid, Ajudhya Parshad Vaid and Gurcharan Singh, Section Officer, went in Jeep No. PNR-1144 to inspect drain on 26th July, 1965. Near Villages Yakubpur the road was muddy and the Jeep could not move further. The party left the Jeep there and went ahead. On return they found a stranger aged 28/30 years talking to the Driver. The Stranger challenged the party and at the point of revolver asked them to surrender whatever they had. He fired a shot from the revolver to terrify them. He obtained Rs 4.70 and a bush-shirt from Shri Gurcharan Singh, Rs 9 from Shri Chander Bhan and Rs 4 from Shri Mangli Ram. He also snatched wrist watches of Shri Ajit Singh, G.A., and Shri Chander Bhan Tahsildar He forced the Driver to give him a lift and directed him to drive on the Farrukhnagar-Jhajjar Road. When they were about 1½ miles from Rewari, he asked the Driver to put the Jeep on the Katcha Path. The Jeep got stuck up at a distance of about 3 miles away. The culprits gave Rs 1 to the Driver and then leaving the jeep and the Driver there, himself set out for the sub-mountaineous region. The Jeep was brought back by the Driver.

(b) The accused was caught at village Sanghwar, Police Station Kattu, district Sikar, Rajasthan. The Rajasthan Government was requested to hand over the accused for investigation of this case registered at Police Station, Jhajjar. The two wrist watches and one bush-shirt have been taken into possession. The accused was duly identified by the P.Ws. in an identification parade held at Sikar. The case is still under investigation. The accused is expected to be handed over to Punjab Police shortly.

Case against S. Surinder Singh Kairon

***8410. Comrade Ram Chandra :** Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

(a) whether any case has been filed or is intended to be filed against S. Surinder Singh Kairon in connection with the Siswan Super Passage Project ;

(b) whether any Officers of the Government are also involved in the said case and whether any action has been initiated or is proposed to be initiated against them ?

Sardar Darbara Singh : (a) Yes.

(b) Yes.

Security Force in the State

***8695. Shri Mangal Sein :** Will the Minister for Home and Development be pleased to state :

(a) whether there is any proposal under the consideration of the Government to set up a Security Force in the State, if so, whether it would be in addition to the existing Home Guards ;

(b) the qualifications prescribed for persons likely to be recruited in the said force ?

Sardar Darbara Singh : (a) No.

(b) Does not arise in view of (a) above.

Alleged beating by the Proprietors of Atlas Cycle Industries, Sonepat

***8744. Shri Mangal Sein :** Will the Minister for Home and Development be pleased to state whether any report regarding beating was lodged by Sarvshri Ram Parkash and Raj Kumar with the Police Station Sonepat against the proprietors of the Atlas Cycle Industries, Sonepat during the year 1964 or 1965, if so, the action taken by the Government thereon ?

Sardar Darbara Singh : The report of Shri Ram Parkash was recorded in the Daily Diary. Since no cognizable offence was made out, no further action was taken by the Police. However Shri Ram Parkash did not sign the report as he was advised by his supporters to file a suit in the Court.

Pakistani Informers and Suspects arrested in Bhatinda District

***8801. Comrade Jangir Singh Joga :** Will the Minister for Home and Development be pleased to state the total number of Pakistani informers and suspects arrested in Bhatinda District during the recent Pakistani aggression.

Sardar Darbara Singh : It is not in public interest to disclose the information.

Agricultural Production Development Programme

***8682. Comrade Shamsher Singh Josh :** Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

(a) the details of the concrete steps being taken or proposed to be taken by the Government in the immediate future in connection with the implementation of the Agricultural Production Development Programme in the State ;

[Comrade Shamsher Singh Josh]

(b) whether any funds have been allocated for the said purpose, if so, their break-up district-wise.

Sardar Darbara Singh : (a) A statement is laid on the Table of the House.

(b) Proposals for the allocation of funds are being finalized in consultation with the Government of India and as such it is not possible to provide the break-up of the targets.

STATEMENT

The Planning Commission has suggested the following additional prod uction in Punjab during the Fourth Plan :—

Commodity	Unit		*Fourth Plan Targets*		
			Base	Additional	Total
Foodgrains	Lakh tons	..	67.50	22.00	89.00
Sugarcane	Lakh tons	..	9.00	3.00	12.00
Oilseeds	Lakh tons	..	3.00	1.50	4.50
Cotton	Lakh bales	..	12.00	3.00	15.00

The suggested additional production for foodgrains, Sugarcane, Oilseeds and Cotton has been accepted by the State Government and in the case of Sugarcane (Gur) the base level has been raised from 9.00 lakh tons to 11.50 lakh tons as the production has already exceeded the Third Plan target of 9.00 lakh tons. Thus the Fourth Plan target has been fixed at 14.50 lakh tons.

The following tentative outlays have been proposed for the Fourth Plan to achieve the additional production as suggested by the Planning Commission :—

		(Rs in crores)
Agricultural Production	..	19.5
Minor Irrigation	...	20.0
Soil Conservation	...	9.38
Agricultural University (for teaching, research and extension education.)		8.5

Under the provisional allocation made for the Agricultural production, i.e., 19.50 crores, the production potential envisaged to be achieved by the end of Fourth Plan will broadly cover the following important programmes :—

I. *Improved Seeds* (Rs, 2.08 Crores)

The object of the Seed Progmme is (a) to produce foundation seed at the seed farms (b) multiply the seed through the registered growers, and (c) procure the registered seed

from the registered growers, grade it, certify it, and distribute the same to the growers. It is proposed to distribute good quality seed and cover 42 lakh acres under wheat, 10.8 lakh acres under rice, 24 lakh acres under gram, 11 lakh acres under bajra, 4 lakh acres under maize, etc. The entire area under American Cotton will be covered with improved seeds. As a result of these operations, it is expected that 4.05 lakh tons additional food will be produced.

At present, the block Seed Farms are being cultivated through tenants. In order to improve their working as also to ensure quality of the seed, it has been decided to start direct cultivation in the Fourth Plan for which an outlay of Rs. 0.49 crores has been proposed. Seed Farms, which have 45 acres or more area will be covered under this scheme. Under the advance action for the Fourth Plan necessary provision has been made for the purchase of machinery, construction of sheds, thrashing floors, etc.

The outlay of Rs 1.0 crores is proposed for Seed multiplication through registered growers. Under this scheme it is proposed to give a premium of Rs. 5 per quintal to the registered growers on the seed to be supplied by them to the Department for general distribution. For effectively manning this programme of production of foundation seed at the Seed Farms, its multiplication, processing and distribution, it is proposed to strengthen the existing field staff with a total cost of Rs. 0.22 crores. The entire seed to be distributed during the Fourth Plan will be certified. Necessary provision for the staff and other facilities needed for this purpose have been made. For this Scheme a provision of Rs 0.14 crores has been proposed.

II. Fertilizers and Manures (Rs 3.28 crores)

Application of fertilizer to crops is the quickest mean of increasing agricultural production. The State has made rapid progress in the utilization of chemical fertilizers during the Third Plan, raising the level of annual consumption from 37,000 tons during the year 1960-61 to about 3 lakh tons during the year 1964-65. The consumption during 1965-66 will be about 3.5 lakh tons. It could be higher if the supplies can be arranged. The consumption of phosphatic fertilizers has made appreciable progress during this period, but it is felt that for pushing its sale it will be necessary to subsidize this fertilizer to the extent of 25 per cent at least during the first three years of the Fourth Plan. It is proposed to distribute 0.7 lac tons, 1.0 lac tons, and 1.3 lac tons of phosphatic fertilisers during the first three years of the Fourth Plan against the expected consumption level of about 28,000 tons during the year 1965-66.

Consumption of potassic fertilisers is still very low and for popularising the same it, is necessary to subsidize the same. The target of distribution of potassic fertilizers during the Plan are 0.7 lac tons, 0.15 lac tons, 0.25 lac tons, 0.35 lac tons and 0.45 lakh tons for the 5 years of the Plan respectively. It is proposed that the subsidy will be given during the first four years only which time it is expected that the farmers will have appreciated the utility of this fertiliser and the programme will not need any subsidy for its popularization.

The preparation of town compost will be extended to all the municipalities centres in the State. At present out of 173 Municipalities, compost is being prepared in 137 centres and the production is liekly to be 71 per cent of present potential. The present

[Home and Development Minister]

production of 2.5 lac tons of compost will be revised to 4.0 lac tons by in, tensifying the work at the existing centres and to start work at the non-working centres. For improving the quality of the compost, it is proposed to provide subsidy for the purchase of both mechanical and hand operated sieves to the municipalities. Under the rural compost programme the cultivators will be advised about proper conservation of manure and preparation of its compost so as to improve the quality including nitrogen content. It is proposed to increase the production of rural compost by 11.lakh tons.

The programme of green manuring will be pushed as far as possible. No additional targets are being proposed for the Fourth Plan. Because of limitations of canal water supply at the desired time and be cause of its competition with intensive cropping, it may not be possible to increase th area appreciably under green manuring more than the level attained during the Third Plan. In a salinity affected areas, how ever, cultivation of green manure crops will be recommended as a part of the reclamation progress.

III. *Plant Protection* (Rs.3.00 Crores)

Insect posts and diseases cause atleast 10 percent damage to the crops in the fields and similar damage to strored products. It is proposed to strengthen the plan protection organisation in the State and 160 Blocks, which are important from the plant protection point of view, will be covered during the Fourth Plan. It has been proposed to progressively in crease the area to be covered against pests and by the end of the Plan, it is planned to treat 6 lakh acres under cotton, 3.3 lakh acres under oilseeds, 40,000 acres under fruit trees and about 1 lakh acres under vegetables.

Besides rendering technical advice and demonstrating the effecacy to various plant protection operations this scheme envisages the grant of 50 percent subsidyon the manually operated protection equipment and pesticides.

IV. *Improved Implements* (Rs 1.0 crores)

Under this programme it is envisaged to (a) popularize the implements ,(b) produce improved agricultural implements like ploughs, cultivators, seed drills, disc harrows, (c), quality mark these implements, (d) supply the implements at subsidized rates and (e) set up agricultural service stations.

V. *Intensive Agricultural Area Programme for Wheat, Cotton, Sugarcane, Oilseeds Maize and Rice* (Rs 2.9 crores)

The Intensive Agricultural Area Programme was devised to (a) impart agricultural know-how to the farmers through enlarged extension agency (b) ensure adequate credit (through Co-operative and Government taccavi sources), (c) ensure adequate irrigation facilities through major and medium canals,and minor irrigation works set up by private efforts aided by Government assistance (d) ensure regular supplies of various agricultural inputs like fertilizers, seeds, pesticides etc., (e) ensure industrial supplies like electricity, cement, improved implements and plant protection machinery etc., (f) provide adequate marketing arrangements, and (g) fix minimum price of farm products. This approach was adopted, to start with, in the case of cotton and rice areas. As it proved very successful, this approach has been extended to other crops also. It is proposed to cover in the Fourth Plan 60 per cent area under American Cotton, 33 percent area under sugarcane, 30 percent area under oilseeds, 7 per cent area under maize, 50 per cent area under wheat, 32 per cent area under bajra and 66 per cent area under rice. The outlay provided for under this scheme excludes the necessary provision made for the subsidy in respect of agricultural implements, plant protection equipment and pesticides and fertilizers which have been provided for under the respective programmes.

VI. *Extension of Agricultural District Programme, Package Programme*

The intensive agricultural district programme was started in Ludhiana district with the idea of having an area where the agricultural development should be one plan ahead of the rest of the State so as to study the problems and find solutions for future programming policy in other areas. The experiment in Ludhiana district has been of immense value and it is proposed to continue it in the Fourth Plan also.

VII. ***Horticulture*** **(Rs 3.02 Crores)**

Development of horticulture is of particular importance in the hill areas. It is expected that by the end of the Third Plan an area of about 29.5 thousand acres would have been covered under fruit plants in these areas, and it is proposed to cover 40,000 acres in the Fourth Plan with an outlay of Rs. 1.21 crores (This excludes the provision for subsidy for plant protection equipment and pesticides, agricultural implements and fertilizers which provision has been made under the respective programmes).

In the plains, by the end of the Third Plan, an area of 0.79 lakh acres (including about 13,000 acres under mango etc. in the hill areas of Hoshiarpur and Ambala) will be/covered under the fruit plants and it is proposed to cover an additional area of 40,000 acres in the Fourth Plan with an outlay of Rs. 1 crore.

The grape cultivation has been introduced in Punjab in the last couple of years and about 850 acres have been planted with various varieties of grapes. In some of the areas the grapes came into bearing and it is felt that it will be possible to cultivate grapes in Punjab successfully. It is planned to extend grape cultivation over an area of 5,000 acres during the Fourth Plan alone. As the cultivation of grapes involves heavy investment by way of construction of "Bowers", etc., it has been proposed to advance Rs. 3,000 per acre as loans to the intending orchardists and a sum of Rs. 60 lakhs has been provided for this purpose.

VIII. *Vegetables* (Rs 0.50 crores)

This scheme is mainly concerned with the production of disease free potato seeds in the hill areas and intensification of the production of vegetables around big cities. It is planned to produce 8,000 maunds of foundation seed of potatoes annually, multiply it through A and B class Registered Growers for further distribution, in the plains. The total demand of potato seed is assessed, at present, at about 3 lakh maunds.

Soil Conservation

The State of Punjab is faced with a serious problem of soil erosion. Mis-management of land in the outer Shivalik has been responsible for dis-integration of soft soil in the hills. These areas need bench terracing, diversion of channels suitable follow of practices and torrent control. In the Sub-montaneous districts contour bunding, diversion of channels, construction of vegetable water ways, check dams etc. are required. In the plains comprising the districts of Gurgaon, Mohindergarh and Hissar where rainfall varies from 15—25 inches the practices recommended are contour bunding and other dry farming practices.

In the Third Five-Year Plan, it is hoped to cover an area of about 1.25 lakh acres involving an approximate cost of Rs. 1 crore. During the 4th Plan, it is proposed to cover about 8.6 lakh acres with a total cost of Rs. 9.38 crores.

Minor Irrigation.

This programme plays an important role in stepping up agricultural production. During the Third Plan about 5.32 lakh acres are expected to be brought under irrigation. In the agricultural sector alone loans for sinking of percolation wells and installation of pumping sets and tubewells amounting to about Rs. 7 crores will be advanced to the cultivators. This programme will be stepped up during the 4th Plan and tentatively Rs. 20 crores have been provided. With the aid of these loans, it is proposed to sink about 16,500 percolation wells, instal about 50,000 tubewells and pumping sets. The State Electricity Board hav prerepared a plan to energise about 40,000 tubewells during the 4th Plan. The remaining tubewells will be run with diesel engines. With this programme an area of about 10 lakhs acres is expected to be brought under irrigation.

Agricultural Operations in Border Areas

***8729. Sardar Gian Singh Rarewala :** Will the Minister for Home and Deve opment be pleased to state the details of the steps, if any, taken by Governme nt to ensure that agricultural operations do not suffer in the border areas of the State in view of the recent Indo-Pak conflict ?

Sardar Darbara Singh : A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

Sufficient quantities of improved seeds of wheat and gram have been stocked in the following border districts as detailed below :—

Name of District		Quantity of seed stocked (quintals)	
		Wheat	Gram
Gurdaspur	..	6,794	..
Amritsar	..	8,065	..
Ferozepur	..	20,600	1,200

Large quantities of seed are available with private growers as well as traders and there will not be any shortage of seed anywhere in the border areas.

Provision for the distribution of seed on taccavi basis in kind has also been made. The amount allotted for this purpose is as under:—

Name of District		*Amount of Taccavi*
		Rs.
Gurdaspur	..	2,00,000
Amritsar	..	3,00,000
Ferozepur	..	4,50,000

(ii) Fertilizers are being issued to the farmers on taccavi as usual. Special attention is being paid to these areas in the allotment of fertilizers.

(iii) Action is being taken in consultation with the Irrigation Department to keep the canals running during the sowing seasons in these areas.

(iv) The field staff of the Agriculture Department has been instructed to do intensive touring of these districts and provide technical guidance as well as any other help that may be needed by farmers.

UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS

Connections for Tubewels in Guhla Block, District Karnal

3048. Sardar Piara Singh : Will the Minister for Transport and Elections be pleased to state the number of connections for tubewells given in the Guhla Block, district Karnal during the period from 1st January, 1965 to 30th September, 1965, together with the full details thereof ?

Sardar Gurdial Singh Dhillon : None

Connections for Tubewells given in Pehowa Sub-Division

3049. Sardar Piara Singh : Will the Minister for Transport and Elections be pleased to state the number of connections for tubewells given in Pehowa Sub-Division during the period from 1st January, 1965 to 30th September, 1965 ?

Sardar Gurdial Singh Dhillon : 187.

Government amount kept by Shri Bhargava Tahsildar, now Naib-Tahsildar, Thanesar

3050. Sardar Piara Singh : Will the Minister for Revenue be pleased to state whether it is a fact that an amount of Rs 30,000 which was withdrawn from the Government treasury for disbursing among the residents of Karhera New Colony, remained for six months with the Tahsildar, Shri Bhargava, at present Naib-Tahsildar, Thanesar, if so, the reasons why it was not refunded when it was not distributed although there is a treasury at the tahsil Headquarters ?

Sardar Harinder Singh Major : No.

ADJOURNMENT MOTION

ਕਾਮਰੇਡ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੇਰੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਰੋਸ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਬੇਟ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਰ ਰਿਸਕ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ (ਵਿਘਨ)

Deputy Speaker : Comrade Tarsikka, please take your seat.

ਕਾਮਰੇਡ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ : ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਲੇ ਤੋਂ ਬਾਦ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ....

Deputy Speaker : Comrade Tarsikka, please resume your seat.

ਕਾਮਰੇਡ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚ ਹੈ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਟ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜ ਕਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਰੋਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਦਰ ਦਰ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਲੋ ਕੇ ਸਮਝਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਅਜ 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਆਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਊਟ ਆਫ ਕਰਟਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਮਿੰਟ ਲਈ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ। (I have always to rise to make you understand things. I cannot admit your adjournment motion because firstly it deals with more than one subject and secondly the house has been in session for the last 20 days. If the matter was really of vital importance then it should have been brought before the house earlier. I gave you only two minutes out of courtesy to speak about it.)

श्री जगन्नाथ : ग्रान ए प्वायंट ग्राफ ग्रार्डर, मैडम : कामरेड तरसिक्का ग्राप को हर बार ऐड्रैस करते समय 'सर' ग्रौर 'साहिब' बोलते हैं तो क्या ग्राप के रूस से लौटने पर ग्राप में परिवर्तन ग्रा गया है जो वह इस तरह से ग्रापको ऐडरैस करते हैं ? (हंसी)

उपाध्यक्षा : ग्राप तो ग्राज कल ला पढ़ रहे हैं चेयर को जैसे भी चाहें ऐडरैस किया जा सकता है। Chair is Chair. (The hon. Member is studying Law in these days. The Chair can be addressed in any way. Chair is Chair after all) (*Laughter*)

ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਤਬਾਹ ਔਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਰੋ ਮੋਰ ਫੂਡ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਕੂਪੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਖੁਸ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿ ਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪਾਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ; ਜੇਕਰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਇਮਪਾਰਟੈਂਟ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਜ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਆਣਾ ਸੀ (If this matter was so urgent it should have been brought before the House earlier. The session is going on for the last 20 days, I cannot admit it)

ਸ੍ਰੀ ਬਲਰਾਮਜੀ ਦਾਸ ਟੰਡਨ : ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਬਿਰਲੇ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਿਰਲੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੁਸ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚ ਆਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਲਾਟ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ....

Deputy Speaker : Order please. Dr. Baldev Parkash. cannot you control your party men?

डाक्टर बलदेव प्रकाश : यहां पर डाक्टर बलदेव प्रकाश क्या करें। यह मामला बहुत जरूरी है ग्रौर फिर ग्राप ने तो कामरेड तरस्सिका को बोलने की इजाज़त दे दी ग्रौर ग्रगर ग्राप इस मामले को जरूरी नहीं समझती थीं तो ग्राप उसे इजाज़त न देतीं तो फिर बाकी के मैम्बरान भी न बोलते। ग्रगर ग्राप समझतीं हैं कि यह मामला ज़रूरी है तो ग्राप इस पर बोलने की इजाजत दे दें।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਮੈਡਮ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਇਹ ਗਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਐਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਲੀਅਰ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗਲ ਬਾਰੇ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਖਿਰ ਸੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੋਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ

ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਐਗਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਉਜੜ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਸ਼ਨ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਉਜੜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾਂ ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

CALL ATTENTION NOTICES

Deputy Speaker : Order please. Now we take up, Call Attention Notices.

Serial No. 151

Comrade Makhan Singh Tarsikka, M.L.A. : I beg to draw the attention of the Minister concerned towards the situation created by the act of the State Government by not suspending the realisation of rents from the Labourers of Amritsar, (1) Shiv Nagar Labour Colony, Amritsar, (2) and Chheharta Labour Colony. About 500 quarters in both colonies. Just as this concession was given to the mill owners of Amritsar by suspending their realisation of Excise and other duties and loans.

Today about 50 thousand workers of different categories are unemployed due to the situation created by the Pakistan aggression, so the workers are not in position to pay their house rent. There is much resentment. Therefore this must be discussed.

उपाध्यक्षा : इस को ऐडमिट किया जाता है। सरकार इस पर स्टेटमैंट करे। (This is admitted. The Government shouldmake a statement.)

Chief Minister : The Government will consider this sympathetically.

Serial No. 152

Comrade Makhan Singh Tarsikka, M.L.A. : I beg to draw the attention of the Minister concerned towards situation created by the State Government by not giving any help to rehabilitate our border villages, which are under military operation :—

(1) Asal Utar
(2) Chak Walian
(3) Bhooreboth.
(4) Chima Khurd
(5) Kulangar
(6) Manawan
(7) Dholan
(8) Jhathi
(9) Dul Kona

just as they helping to the peoples under Pakistan possession (Khem Karan' Ramuwal, Ratoke, Machhike. Mehdipur, Mastgarh, Kalia Sankatera, Dul Nau and Kalse). Due this there is much resentment. Therefore, this must be discussed.

उपाध्यक्षा : इस को ऐडमिट किया जाता है। सरकार इस पर स्टेटमैंट दे। (This is admitted. The Government may make the statement.)

मुख्य मंत्री : डिपटी स्पीकर साहिबा इन तमाम विलेजिज से जो भी भाई आए हैं उन को रीलीफ देने के बारे में कारवाई की जा चुकी है और इन्हें मजीद रीलीफ देने के बारे में कारवाई करने पर विचार किया जा रहा है।

Serial No. 153

Principal Rala Ram, M.L.A. . I beg to draw the attention of the Government to the large-scale demotions of Sectional Officers under the Irrigation Department in Beas Project Establishment during the last one year, a fact which has led to wide-spread panic and frustration among Sectional Officers. It is highly desirable to allay this panic and unrest among these Sectional Officers of long standing and valuable experience as the continuance of demotions is sure to militate against efficiency and smooth work.

उपाध्यक्षा ; इस को ऐडमिट किया जाता है। सरकार इस पर स्टेटमैंट दे।
(This is admitted. The Government may make a statement).

मुख्य मंत्री इस सारे कोस्चन को ऐगज़ामिन कर के मुनासिब कार्रवाई की जाएगी।

Serial No. 154

Sarvshri Ajit Kumar and Ajaib Singh Sandhu, M.L.A. : I beg to draw the attention of the Government to a matter, namely, the non-payment of salary to Deputy Registrars and Assistant Registrars of the Industrial Co-operative in the State for the last four months.
Thus calling attention.

उपाध्यक्षा : इस को ऐडमिट किया जाता है। इस के बार में सरकार स्टेटमैंट करे।
(This is admitted. The Government may make a statement).

मुख्य मंत्री : इस के बरे में इन्क्वाईरी कर के मुनासिब कार्रवाई की जाएगी।

श्री बलरामजी दास टंडन : On a point of order, Madam. डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरा पवायंट आफ आर्डर यह है कि जब कोई मैंम्बर किसी काल अटैनशन मोशन का नोटिस दे देता है तो उस पर चीफ मिनिस्टर साहिब को चाहिए कि वह इस के सारे पहलुओं पर पहले गौर करे फिर कोई जबाब दे। मगर हम देख रहे हैं कि एक नया ही प्रोसीजर ऐडाप्ट किया गया है और दो लफज़ों में जबाब दे दिया जाता है कि हम गौर करेंगे, देखेंगे, विचार किया जा रहा है ... ...

Deputy Speaker: I call upon Sardar Tara Singh to read his Call Atttention Motion.

Serial No. 155

Sardar Tara Singh Lyallpuri : Madam, I beg to draw the attention of the Minister concerned to the fact that the Government has given safeguards to the members of the Scheduled Castes and backward Classes in services through a letter according to which no qualified Government Employee belonging to backward Classes can be reverted but, in spite of the safeguards provided in the said letter, qualified Kanungoes belonging to backward Classes have been reverted in Amritsar District while at the same time the unqualified Kanungoes are serving in the same District in contravention of the Government policy.

डा० बलदेव प्रकाश : On a point of order, Madam. मैं यह कहना चाहता हूं कि जो Call Attention Notice आप ऐडमिट करें गवर्नमैंट को उसका

बाकायदा जवाब टेबल पर ले कर करना चाहिये ताकि मैम्बरान को पता लग सके कि ऐसा स्टेटमेंट आने वाला है। मगर यह कहना कि देख लेंगे, बात करेंगे यह कोई मुनासिब जवाब नहीं है।

उपाध्यक्षा : मैं कहती हूं कि अगर काल एटेंशन मोशन मूव करने के बाद ही मिनिस्टर की तरफ से मौका पर ही जवाब आ जाता है तो इस में क्या हर्ज है। (I say, what is the harm if the hon. Minister makes a statement just after the Call Attention Notice has been read out by the Members?)

श्री बलरामजी दास टंडन : मैं चाहता हूं कि मिनिस्टर का जवाब, पहले डिपार्टमेंट की रिपोर्ट लेकर, फिर आना चाहिये।

Deputy Speaker : Mr. Tandon on what point are you speaking ?

Shri Balramji Dass Tandon : Madam, I am speaking on a point of Order.

Deputy Speaker : This is not proper. I never allowed you. You can speak only when I permit you.

श्री फतेह चन्द विज : On a point of order. मेरा प्वायंट आफ आर्डर यह है कि जब टंडन साहिब ने इस मुआमले पर बोलना ही शुरू किया था तो आपको उसी वक्त उन को रोक देना चाहिये था। सारे केस को सुनने के बाद कुछ कहना, यह आपके लिये मुनासिब नहीं है।

उपाध्यक्षा : फतेह चन्द जी, यह point of order आपने कहां से सीखा है? (Where did the hon. Member learn to raise such a point of order ?)

चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी : डिप्टी स्पीकर साहिबा, काल एटेंनशन मोशन लाने का मतलब ही यह होता है कि उस ने गवर्नमैंट की अटैनशन को किसी स्पैसेफिक मुआमला पर लाना होता है। जब चीफ मिनिस्टर ने जवाब दे दिया तो उनका मतलब हल हो जाता है.

Deputy Speaker : Mr. Garg, on what point are you speaking?

चौधरी देवी लाल : On a point of order, Madam. मेरा प्वायंट आफ आर्डर यह है कि यह जो झगड़ा काल अटैन्शन मोशन्ज़ के मुताल्लिक चला था इस का जवाब चेयर की तरफ से आना चाहिये था मगर जवाब Chief Parliamentary Secretary की तरफ से दिया जा रहा है। मैं इस पर आप का रूलिंग चाहूंगा कि आया चेयर की बजाये रूलिंग देने का चीफ ह्विप हकदार भी है या नहीं ?

उपाध्यक्षा : आप ने सुना नहीं, मैं जैसे हाउस को चलाना चाहती हूं रूलिंग देती हूं आपने सुना नहीं रूलिंग मेरा अपना है आपका नहीं। आपको बलरामजी दास की वकालत करने का भी हक नहीं वह खुद बोल सकते हैं। (The hon. Member did not here me properly. I give my ruling in a manner I like to run the House. The ruling is mine and not his. He has no right to hold brief for Shri Balramji Das Tandon. He can speak for himself.)

ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਤਰਜਮਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ।

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੰਤਰੀ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਇਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਇਹ ਪਤਾ ਨਾ ਲਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਲ੍ਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ। (ਹਾਸਾ)

ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਗੋਆਣੀ : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹੀ ਇਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਕੋ ਇਕ ਮਨਿਸਟਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ।

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ: ਮੈਂ ਅਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਮੈਂ ਚੂੰਕਿ ਆਪਣੇ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਮਝਣੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਇਹ ਦਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਰਖੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇ।

ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਖਿਲਾੜੀ ਲੰਗੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਕਵਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਇੰਟਰਪਰੇਟਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। (ਹਾਸਾ)

उपाध्यक्षा : अगर कोई मैंबर अंग्रेजी बोल न सकता हो और उसे अंगरेज़ी बोलने का शौक हो तो आप उसकों बोलने नहीं देंगे । If a Member cannot speak english but is fond of speaking english, will they not allow him to speak in english.)

माल मन्त्री : मैं ने तो एक अर्ज़ की थी मगर इजाज़त तो आप ने देनी है ।

श्री जगन्नाथ : मैं पूछना चाहता हूं, डिप्टी स्पीकर साहिबा कि जब मेजर साहिब को इन की अपनी पंजाबी बोली ही समझ में नहीं आती तो इन में और एक पैंटन टैंक में क्या फर्क है ।

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ : On a point of personal explanation, Madam. ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੈਟਨ ਟੈਂਕ ਦਾ ਖਤਾਬ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਹ ਖਤਾਬ ਗੱਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਗਨ ਨਾਥ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਪੈਟਨ ਟੈਂਕ ਚਲਿਆ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਥੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੈਂਕ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਪੈਟਨ ਟੈਂਕ ਹੈ।

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁਖ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਅਟੈਨਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ Chief Parliamentary Secretary ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨਿਸਟਰ ਕਨਸਰਨਡ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਕੇ ਇਤਨਾ ਵਕਤ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ........

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਦਿਉ। (Let him read it in the Punjabi language.)

ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਲਾਇਲਪੁਰ : ਸ੍ਰੀ ਮਤੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗਲ ਵਲ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਅਨੁਸੂਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਸੁਰਖਿਆਵਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਣ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੁਆਇਲੀਫਾਈਡ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਰੀਵਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਉਕਤ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੁਰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਲਸੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਕਾਨੂੰਗੋਆਂ ਨੂੰ ਰੀਵਰਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੀ ਅਨਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਕਾਨੂੰਗੋਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲਗੇ ਰਹਿਣ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਊਸ ਦੀ ਸੈਂਕਟਿਟੀ ਨੂੰ ਸੁਪਆਇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇਤਕਾਦ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਿਆ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਮਝ ਵਿਚ ਨਾ ਆਏ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੇਸ਼ਕ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝਾਉ, ਪਰ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, I don't believe saying in a round about manner. ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਦਿ।

श्री बलरामजी दास टण्डन : बात तो यह थी कि काल अटैंशन मोशन के बारे जवाब सैटिसफैक्टरी नहीं आ रहा ।

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ : ਟੰਡਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਸਿਪਰਿਟ ਵਿਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਵਕਤ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਇਥੇ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਸਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਜ ਇਕ ਸ਼ਰੀਫ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ : ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੁਸਕਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਸ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਸਕ ਸਕਦਾ ਸੀ ?

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਧਰੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਵੋਟ ਆਫ ਨੋ ਕਾਨਫਿਡੈਂਸ ਲਿਆਏ ਸੀ ਔਰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾ ਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਢਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੋਲੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ : ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੇ ਦੁਖ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਫ ਹਾਂ ..... *(Interruption)*

ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼: ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੂਥ ਐਂਡ ਨੇਲ ਫਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਕਾਮਰੇਡ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਡਟ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਨਿਭਾਂਦੇ ਹਾਂ।

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ: ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ।

उपाध्यक्षा : इस को ऐडमिट किया जाता है, गवर्नमैंट इस पर स्टेटमैंट दे. (This is admitted. The Government may make a statement.)

(Serial No. 157)

Sardar Tara Singh Lyallpuri : Madam, I beg to draw the attention of the Minister concerned to the fact that previously the Sarpanches used to verify the applications of the villagers for obtaining sugar in connection with marriages and other occasions. But now the Government has decided that the Oath Commissioners should verify the applications of the villagers for obtaining sugar whereby it takes many days before the poor villagers get sugar and thus they cannot get that in time. In view of this difficulty I want to request the Government to authorize the Sarpanches to verify the applications of the villagers for obtaining sugar in connection with marriage ceremonies, etc.

Deputy Speaker : This is admitted.

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ: ਗੌਰਮਿੰਟ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ: ਇਹ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਕਿ ਓਥ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ: ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਲੀਫ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ।

(Serial No. 158)

Sarvshri Kulbir Singh and Satya Dev : Madam, I beg to draw the attention of the Minister concerned towards a matter, namely, that Deputy Commissioner, Ferozepur, was good enough to suspend most of the police staff of Fazilka City Police on finding them absent from their duties on the Pak invasion time on the 6th of September, 1965. It is very necessary to take stern action for negligence, cowardice and shirking at the time when National Security was in danger.

It is really surprising to note why S.D.O., S.P., Magistrates, the heads of other Departments, Hospital Incharge, Chief of State Bank, Station Master (Railways) along with his staff, Telephone Exchange People, N.C.C. Home Guard and Red Cross Chief are considered immune of failure in their duties and absence continuously for days at a stretch. No body catches of them, asks them of explanation and suspends them. It is the heads who should be taken to task for the cowardness and absence from their duty. Attention of the Government is drawn towards this anomally of encouraging the real guilty heads who are at fault and grinding others whose only fault is that they have tread the way of their superiors to save themselves first instead of sticking to their duty towards their country and countrymen.

Deputy Speaker : This is admitted. Government may make a statement.

(Serial No. 159)

Shri Balramji Dass Tandon : Madam, I beg to draw the attention of the Government towards a situation that the land lying waste for the last so many years, acquired by the fertilizers factory, Nangal. Recently they have returned a lot of land lying vacant to the ex-owners of the land. In some cases, due to shortage of money, people are not in a position to buy back the land as such they have leased it out to the old landowners. But still no action has been taken for about 60 per cent of such waste land. Due to emergency a call has been given by the Government for grow-more food. Under the circumstances, it is requested that the Government should take up the matter for leasing the waste land to the ex-owners in order to promote grow-more-food campaign.

Deputy Speaker : It is admitted. Government may make a statement.

(Serial No. 160)

Dr. Baldev Parkash : Madam, I beg to draw the attention of the Government for not holding proper enquiry against the Sarpanch and Secretary of the Panchayat named Rajipura (Jhagre), tehsil Kharar, district Ambala, for charges of misappropriation and embezzlement. It is strange that in this case complainants have never been called, or taken in onfidence regarding their complaint. In this connection many panches of the Panchayat have decided to go on hunger strike from 22nd November, 1965. It is hereby requested that the Government should take proper action to hold enquiry into the charges of embezzlement and misappropriation against the Sarpanch and Secretary of the Panchayat, while taking complainants into confidence.

Deputy Speaker : It is admitted. Government may make a statement.

(Serial No. 161)

Chaudhri Harkishan : Madam, I beg to draw the attenion of the Minister concerned towards the matter, namely, the sending back by the Jullundur Training Centre of 42 duly approved new recruits to P.A.P. from Gurgaon District, who had been medically examined and considered fit in all respects. Since Gurgaon District is adversely affected by this arbitrary action on the part of the Jullundur Training Centre, it is, therefore, a matter of extremely urgent importance.

Deputy Speaker : This is also admitted. Government may make a statement.

ਸਰਦਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਧੌਲਾ: ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਕਲ ਇਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਲ ਅਟੈਨਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਔਰ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਅਲਾਉ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ: ਧੌਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਇੰਟਰੱਪਟ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। (It is a pity that Shri Dhaula does not hear the Chair at the proper time. What I said was that the Government would make a statement. He may please refrain from making an interruption when some other subject is under discussion.)

STATEMENTS LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE BY THE CHIEF PARLIAMENTARY SECRETARY

Chief Parliamentary Secretary (Shri Ram Partap Garg) : Madam, I beg to lay on the Table of the House statements in respect of—

(i) Call Attention Notice No. 121 by Sardar Gurnam Singh, *re*, "leading article of daily 'Pardeep' of 3rd November, 1965, in which it has been stated that if the Punjabi Suba is formed Indian Government will have to keep its armies in Punjab...........".

(ii) Call Attention Notice No. 123 by Comrade Bhan Singh Bhaura, *re* leasing out of land to 50 Harijan families in Village Bir Dhano, tehsil Malerkotla

Statement on Call Attention Notice No 121 given by Sardar Gurnam Singh

(Sardar Darbara Singh, Home and Development Minister)

The M.L.A. has drawn the attention of the Government towards an article captioned, "Punjab Ekta Samiti Ka Memorandum" wherein the 'Pradeep' Jullundur dated 3rd November, 1965, comments on a Memorandum alleged to have been submitted by Punjab Ekta Samiti to the Government enumerating 21 points against the formation of Punjabi Suba, reproducing *inter-alia* from the said Memorandum the words to which the Hon'ble Member has taken exception. This editorial was duly noticed in the aforesaid newspaper, but since in respect of the original Memorandum as published by the *Hind Samachar* and the *Pradeep*, the Legal Remembrancer had already advised that the said Memorandum was not actionable, it has not been considered necessary to obtain Legal Remembrancer's advice again.

In the course of discussion on an adjournment Motion on the subject raised in the Vidhan Sabha on 2nd November, 1965, the Chief Minister, Punjab, is reported by the Tribune, to have said that the Government had no relation direct and indirect with the view as expressed in the Newspapers under discussion. Nevertheless, he added, that the Press Consultative Committee would meet shortly and discuss the press behaviour.

Statement on Call Attention Notice No. 123, given by Comrade Bhan Singh Bhaura

The land in question is in Bir Amamgarh and not in Bir Dhano as mentioned in the Call Attention Notice. Previously, this land was on lease with Shri Siri Ram, etc. for a period of 15 years, who had installed two tubewells in this land. After the expiry of the lease period in December, 1962, the land was leased out to 50 Harijan Families by Government (in the Welfare Department). According to the terms of the lease, the previous lessees were to be paid the capital cost, at the market price of the tubewells etc., installed by them during the lease period, after due deductions on account of depreciation. This amount has not been assessed so far finally and a case is pending in the court of Sub-Judge, 1st Class, Barnala.

2. Some of the area on lease with the Harijans, is also being irrigated by the Government tubewell No. 74. The Harijans have also fitted a 5 H.P. engine on an existing bore to augment irrigation facilities. The land under the command of Government tubewell No. 74 is receiving irrigation according to 'Warabandi.'.

3. The Harijan lessees approached the district authorities. At this, efforts to get the Harijans additional irrigation facilities out of turn were made which have not proved successful as the Irrigation Department have expressed their inability to change 'Warabandi' as the neighbourers of this land were not willing to agree to any change in the existing 'Warabandi'. The tubewell is working to its maximum capacity and it cannot irrigate any more area except at the cost of the neighbouring cultivators, which is not possible under the existing circumstances.

4. As regards the other tubewells owned by the previous lessees, Shri Siri Ram, etc., it may be stated that they were approached in the matter by the district authorities but without any success. The matter being *subjudice*, they could do nothing in the matter.

MOTION UNDER RULE 15

Chief Parliamentary Secretary (Shri Ram Partap Garg) : Madam, I beg to move—

That the proceedings on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provision of the Rule "Sittings of the Assembly" indefinitely.

Deputy Speaker : Motion moved—

That the proceedings on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule "Sittings of the Assembly" indefinitely.

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ (ਲੁਧਿਆਣਾ ਉੱਤਰ): ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੋਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਲ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਜ ਸਿਟਿੰਗ ਨਾਨਸਟਾਪ ਚਲੇਗੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤਕ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਚਲੇਗੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵਰ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਹਾਊਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿਚ ਕੀ ਭਾਜੜ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਏਥੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਐਬਨਾਰਮਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਏਥੇ ਹਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਐਬਨਾਰਮਲ ਗਲ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ ਔਰ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਕਿ **Punjab is an abnormal State.** ਪਹਿਲੀ ਮਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਕਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਠੀਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਲਦੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਨਿਸਟਰੀ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਕਦਰ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਸ਼ਥਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕੁਝ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਔਰ ਐਸੇ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਏਥੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਐਬਨਾਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਥੇ ਹਾਊਸ ਅਰੈਸਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਅਜ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਥੇ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੈਦ ਦੀ ਗਲ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਬਿਲ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸ਼ਥਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਪਾਰਟੈਂਸ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਕ ਬਿਲ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲੁੱਕ ਰਖਦਾ ਹੈ। 90 ਫੀ ਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਸ਼ਥਰੂ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੋਸ਼ਨ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਕਮਰੇਡ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ (ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀਆ ਹਨ । ਅਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾਬਸਤਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ । ਜਦੋਂ ਏਥੇ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬਿਲ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਫੁਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰ ਇਕ ਇਕ ਘੰਟਾ ਬੋਲੇ ਸਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਚ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨਹੀਂ ਰਖ ਸਕਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਅਹਿਮ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰੇ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਕ ਮਨਿਸਟਰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜ ਏਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਿਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਹੈ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਹਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਵੇ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੋਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ।

श्री मोहन लाल (बटाला) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं अपने अन्दाजे से कहता हूं कि चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी साहिब ने जब मोशन दिया था शायद उस वक्त उन के ध्यान में यह बात नहीं थी कि आज पंजाब में लाला लाजपत राए डे है और मैं अगर इस वक्त खड़ा हुआ हूं इस मोशन पर कुछ कहने के लिये तो मेरे सामने सब से बड़ी बात यही है । मुझे सिटिंग के बढाने में कुछ एतराज न होता अगर आज पंजाब केसरी लाला लाजपत राए की ऐनीवरसरी न होती । मैं तो ऐसा ख्याल करता था कि शायद आज सिटिंग ही नहीं होगी ।

उपाध्यक्षा : आप ने प्रोपोजल नहीं भेजी थी । (The hon. Member did not send a proposal in this connection.)

श्री मोहन लाल : डिप्टी स्पीकर साहिबा, कल जब बिज़नेस ऐडवाईज़री कमेटी की रिपोर्ट आई थी तो उस में कोई ऐसा रैफ्रैंस नहीं था कि आज कोई बिज़नेस होगा इस लिये हम ने समझा था कि आज कोई सिटिंग नहीं होगी । मैंने कल वाज़ा तौर पर कहा था कि कल के जो बिल रह गए हैं उन का क्या होगा लेकिन उसका कोई जवाब नहीं दिया गया था, इस लिये मेरा कल रात तक ख्याल था कि सिटिंग नहीं हो रही । कल मित्तल साहिब ने मुझे बताया था कि आज सिटिंग हो रही है, खैर इस पर मुझे एतराज़ नहीं कि क्यों आज मीटिंग बुला ली है लेकिन मुझे इस बात पर सख्त एतराज़ है कि आज लाला लाजपत राए डे पर यह कहा जाए कि जब तक बिल पास न हो हाउस बैठा रहे । अब पता नहीं हाउस किस वक्त तक बैठे क्योंकि बड़ा अहिम बिल है हर एक मैम्बर अपने ख्यालात का इज़हार करना चाहेगा और नान स्टाप सिटिंग का मतलब है कि बिल को डिसपोज़ आफ करने के लिये अगर रात के 12 बजे तक भी बैठना पड़े तो बैठना होगा । आज के दिन खास तौर पर यह बात करना मुनासिब नहीं । मुझे कोई एतराज़ नहीं और मैं तैयार हूं कि कल और परसों एक की बजाए दो सिटिंग्ज़ कर ली

जाएं और परसों चाहे नान-स्टाप सिटिंग कर लें लेकिन आज पंजाब केसरी लाला लाजपत राए की बरसी वाले दिन यह कहना कि हाउस नान-स्टाप बैठे मुनासिब नहीं क्योंकि कई मैम्बर साहिबान ने उस सिलसिले में फंक्शन्ज में शामिल होना होगा ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ (ਰਾਏਕੋਟ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਹ ਜੋ ਮੋਸ਼ਨ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ । ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜ ਤਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਕਿ ਕਿਤਨੀ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ । 22 ਅਕਤੂਬਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਰਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਜ 17 ਨਵੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੋਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਜਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾਨ-ਸਟਾਪ ਸਿਟਿੰਗ ਹੋਵੇ । ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਥੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਪਰੈਸ਼ਨ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਜਿਤਨਾ ਅਰਸਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੈਸ਼ਨ ਚਲੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਗਿਰਗਿਟ ਵਾਂਗ ਰੰਗ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ (ਹਾਸਾ)।

ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ : ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦਸ ਦਿਓ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਉਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਕਲ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ । ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਬਿਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਸਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ । ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵ੍ਹਿਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਖਤ ਹਨ......(ਵਿਘਨ) ਇਸਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਲਾਉਂਜ ਵਿਚ ਰੁਲਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵ੍ਹਿਪ ਨੂੰ ਡਿਸਆਨਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਬਿਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਜਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਖ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਮੁਹਾਰੇ ਛਡ ਦਿਤਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ । ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਬੜੇ ਵੋਕਲ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹਨ । ਇਹ ਜਟ ਤਬਕਾ ਚੂੰਕਿ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਵੋਕਲ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰੈਸ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸੈਸ ਦੇ ਬਿਲ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਗੜ ਦਿਓ । ਜਿਸ ਵਕਤ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚਲਦੇ ਰਹੋ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ । ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਖਾਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਤੇ ਠੀਕ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜੋ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਆਈਆਂ ਉਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਲੇਕਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਫਰਕ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬਿਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਇੰਡੈਫਨਿਟਲੀ ਚਲੇਗਾ ਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਥਕ ਥਕਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਚੂੰਕਿ ਵੋਕਲ ਹਨ, ਤਾਕਤਵਰ ਤੇ ਪਰੈਸ ਵਾਲੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚਲਦੇ ਰਹੋ ਜਿਤਨੇ ਦਿਨ ਚਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਹਫਤੇ ਹਫਤੇ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਬਰੇਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ । ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਤਬਕੇ ਨੂੰ

[ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ]
ਰੀਪਰੇਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਇਲਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਇਸ ਸੈਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੇਤੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ । ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਗਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੀਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਸ ਬਿਲ ਤੇ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਇਨ ਡੈਫਨਿਟਲੀ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ । ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲਗੀ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਜੇ ਟੈਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾ ਲਓ ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਇਦੇ ਦੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਂ । ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮੀਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ । ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਓ ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਹੈ । ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜੇਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਥੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਉਸਦੇ ਪਾਸ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਤੁਸੀਂ ਉਸਤੇ ਬਹਿਸ ਰਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ ਤਾਕਿ ਤਹਾਨੂੰ ਵਧ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਸਕਣ । ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਜਦ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੁਰੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਣ। ਉਥੇ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਸ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਾਕੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਥੇ ਆਕੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੇ ਰੁਹਬ ਪਾਂਦੇ ਹਨ......(ਵਿਘਨ) ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੁਪ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜੁਰੱਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਉਜੜ ਗਿਆ ਹੈ.........

ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ । ਕੀ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਬ ਕਿਸੇ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਿੱਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ? (ਹਾਸਾ)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਚਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਸ਼ੇਰ ਬੈਠਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਬੈਠਣਾ ਹੈ । ਇਥੇ ਸ਼ੇਰ ਬੈਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਵਿਚ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਗਈ ਹੈ (ਹਾਸਾ)। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤਾਕਿ ਅਗਲੀ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਆਵੇ । ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੋ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਢ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟ ਸਿਟਿੰਗਜ਼ ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਜਦ ਵੀ ਮੌਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਭਜਦੀ ਹੈ । ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਬਿਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਪ ਕਰਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਾ ਲਊ ਲੇਕਨ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੈਸ ਟੈਕਸ ਬਿਲ ਤੇ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਸੈਸ ਬੇਜਾ ਤੇ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਤੇ ਮਬਨੀ ਹੈ । ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ।

ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ) : ਫੈਸਲਾ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਗਲ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਦ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੁਪ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਾਂ ਮੰਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ , ਉਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇ ਇਥੇ ਆਕੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਂਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਰੀਬ ਦੀ ਡੈਫੀਨੀਸ਼ਨ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗ਼ਰੀਬ ਹਾਂ (ਵਿਘਨ) ।

ਗਰੀਬ ਕਮਯੂਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੀਪ੍ਰੀਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ । ਜਜ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਮਯੂਨਿਟੀ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰੀਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋਣ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨਾਮਿਕ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੇ

ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਰ ਜ਼ੋਰ ਲਫਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਲਿਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੰਬਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਲੜਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤਕ ਇਕਨਾਮਿਕ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੱਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਲੜਾਈ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਿਆ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਛਡਿਆ ਜਿਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪਰਜ਼ੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੀਡ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ । ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਅਸੀਂ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਾਉ । ਅਗਰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਬਹਿਸ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਗਲ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਦਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਦਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ । ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ । ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ । ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

डाक्टर बलदेव प्रकाश (अमृतसर शहर पूर्व): डिप्टी स्पीकर साहिबा, बिज़नेस ऐडवाइज़री कमेटी के अन्दर ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ था कि हाउस आज नान-स्टाप चलेगा । अगर कल बिल पास नहीं हुआ तो उस के बारे में बिज़नेस ऐडवाइज़री कमेटी ज़िम्मेवार नहीं है । बिज़नैस ऐडवाइज़री कमेटी में फैसला हुआ था कि हर एक अमैंडमेंट पर मैम्बर को 5 मिनट दिए जाएं । किसी भी मैम्बर ने अमेंडमेंट पर 2 या 3 मिनट से ज्यादा नहीं लिए । सैल्ज़ टैक्स बिल पर ज्यादा अमैंडमेंट थीं, इस लिये उस पर ज्यादा वक्त लगना लाज़मी ही था । मैम्बरों ने सरकार को बिल पास करते वक्त पूरी तरह से सहयोग दिया । अगर फिर भी ज्यादा वक्त लग गया तो उस के लिये मैम्बर दोषी कहे नहीं जा सकते । अगर सैल्ज़ टैक्स बिल पर ज्यादा वक्त लग गया है तो इस का मतलब यह नहीं कि पंजाब कमर्शियल क्राप्स सैस बिल को आपोज़ीशन की बात सुने बिना ही पास कर दिया जाए । सरकार टैक्सेशन बिल हाउस में पास कराना चाहती है और हम उस की मुखालिफत करना चाहते हैं । हम सरकार को सुझाव देंगे कि इस बिल को विदड्रा कर लिया जाए और इस के इवज़ में फलां २ इंतज़ामात किए जाएं । सैंटर से ज्यादा एड हासल करने के लिये कदम उठाए जाएं । इन सजैशन्ज़ को देने के लिये हमें वक्त की ज़रूरत है और ऐसे हालात में माननीय सदस्यों को वक्त मिलना ही चाहिये । मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वह नान स्टाप वाली मोशन को वापिस ले लें अगर सरकार इस बिल को पोस्टपोन कर सकती है तो पोस्टपोन कर दे । अगर इस बिल को पोस्टपोन नहीं कर सकती तो इस को अगले हफ्ते में टेक अप किया जाए । नान-स्टाप सिटिंग करने के बारे में बिज़नेस ऐडवाइज़री कमेटी को अधिकार है । इस के बारे में सरकार को किसी तरह का अधिकार नहीं है । अगर सरकार ने नान स्टाप सिटिंग करनी ही है तो यह मामला पहले बिज़नेस ऐडवाइज़री कमेटी में डिस्कस किया जाना चाहिए । मैं समझता हूं कि सरकार अनडैमोक्रेटिक काम करना चाहती है जो कि सरकार के लिये शोभा नहीं देता । इस लिये सरकार नान-स्टाप वाली मोशन को विदड्रा करे ।

चौधरी देवी लाल : आन ए प्वायंट आफ आडर, मैडम । डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं नान-स्टाप वाली मोशन की मुखालफत करने के लिये खड़ा हुआ हूं । कल लाला लाजपत राए की शताब्दी मनाने के लिए 22 सैक्टर, चंडीगढ़ में जलसा हुआ । वहां पर मैं भी गया हुआ था । इस जलसे की प्रधानगी चौधरी रिज़क राम, सिंचाई तथा बिजली मन्त्री कर रहे थे । वहां पर और भी राजदुलारे गए हुए थे । वहां पर किसी राज दुलारे ने कहा कि क्या कल सैशन हो रहा है ? चौधरी रिज़क राम ने कहा कि कल सैशन नहीं हो रहा है । मैं ने आज बाहिर किसी काम के लिए जाना था । आज मेरी कार सर्विस और कलीनिंग के लिए वर्कशाप में जानी थी । इस लिए मैं ने चौधरी हरद्वारी लाल जी को जा कर कहा कि मुझे बाहिर जाने के लिए कार दे दें । चौधरी रिज़क राम ने चौधरी हरद्वारी लाल को आज प्रातः टेलीफोन किया कि मैंने जो बात कल की थी, वह गलत निकली । आज सैशन हो रहा है । बिजनेस ऐडवाईजरी कमेटी की रिपोर्ट में भी आज सैशन होने के लिए लिखा हुआ था । लेकिन चौधरी रिज़क राम कहते हैं कि 18 नवम्बर, 1965 को सैशन नहीं हो रहा है । जब वज़ीरों को इतनी बात का पता नहीं तो यह किस तरह से सरकार के काम चलाएंगे । नान स्टाप सिटिंग को डिसाइड करना बिज़नेस ऐडवाईज़री कमेटी का काम है । लेकिन सरकार बेमुहारे चल रही है । इन की कोई प्लैनिंग नहीं है । इन्हें कोई पता नहीं कि कितनी देर में बिज़नेस खत्म होगा । डाक्टर बलदेव प्रकाश जी ने जो बातें कही हैं, मैं उन का पूरी तरह से समर्थन करता हूं । मैं नान-स्टाप वाली मोशन की सख्त मुखालफत करता हूं । मैं चाहता हूं कि सरकार इस मोशन को वापस ले ले ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਮੈਡਮ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਮੋਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਸਖਤ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕਰਾਪਸ ਸੈਸ ਬਿਲ ਦੀ ਸਖਤ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਮੁਖਾਲਫਤ ਪਾਸ ਕਰਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਅਗਰ ਇਹ ਬਿਲ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਨਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਹੋਵੇ-ਗਾ। ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਬਿਲ ਉਤੇ 7 ਦਿਨ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਿਲ ਉਤੇ 7 ਦਿਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 14 ਦਿਨ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵਾਜਿਬ ਸੀ। ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਬਿਲ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਕਰਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਬੂਲ ਵੀ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਮਰਸ਼ਲ ਕਰਾਪਸ ਸੈਸ (ਐਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਬਿਲ ਨੂੰ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਮਯੂਨਿਟੀ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰੀਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਿਲ ਉਤੇ ਖਰੋਲੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮੌਕਾ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਰੈਸ਼ਲੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਸਖਤ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

परिवहन तथा निर्वाचन मंत्री (सरदार गुरदयाल सिंह ढिल्लों) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, आपोज़ीशन की तरफ से जो ख्यालात जाहिर किये गए हैं हम तो हमेशा ही उन की खाहिशात का एहतराम करते आए हैं और यह कभी हमारे दिल में ख्याल नहीं आया ....

ਇਕ ਆਵਾਜ਼ : ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ।

परिवहन तथा निर्वाचन मन्त्री : जो मैं बोल रहा हूं यह भी एक लैंगुएज है । बोलना ठीक चाहिये । आप की तरह नहीं बोलना चाहिए ....।

उपाध्यक्षा : आर्डर प्लीज़ । (Order please.)

परिवहन तथा निर्वाचन मन्त्री : मैं अर्ज़ कर रहा था कि हम तो हमेशा ही उन की खाहिशात का एहतराम करते आए हैं । और कभी भी सरकार की खाहिश नहीं हुई कि उन के ख्यालात और उन के जज़बात को किसी तरह से भी नजर अंदाज किया जाए । मैं आप से दरखास्त करता हूं कि इस मोशन को अभी थोड़ी देर के लिए इल्तवा में रखें . . . (विघ्न)

आवाजें : वापस लो । (विघ्न)

परिवहन तथा निर्वाचन मन्त्री : वापस नहीं हो सकती । हम बिज़नेस ऐडवाईज़री कमेटी के पास जाने के लिये तैयार हैं । उस के बाद देख लेंगे कि क्या फैसला होता है.... (विघ्न)........ अगर यह बात आप को मंजूर नहीं है तो मोशन को चलने दो । मैं बैठ जाता हूं ।

उपाध्यक्षा : आर्डर प्लीज़ । साढ़े ग्याहर बजे बिज़नेस ऐडवाईज़री कमेटी की मीटिंग रखी है । इस मोशन को अभी विदहोल्ड किया जाता है (विघ्न) । (Order please. The Business Advisory Committee is meeting at 11.30 a.m. Further discussion on the Motion is therefore withheld).

चौधरी नेत राम : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडम । मैं सरदार गुरदयाल सिंह के सुझाव को सुन कर बहुत परेशान हुआ हूं । आप ने भी उन की बात पर हाउस में कह दिया कि बिज़नेस ऐडवाईज़री कमेटी की मीटिंग में यह बात होगी । मैं आप की रूलिंग इस बात पर चाहता हूं कि क्या वह कमेटी हाउस से भी ज्यादा सुप्रीम है । जब बात हाउस में आ चुकी है तो बिज़नेस ऐडवाईज़री कमेटी में जाने का क्या मतलब है । क्या वह कमेटी हाउस से भी ज्यादा सुप्रीम है, मैं आप का रूलिंग इस बात पर चाहता हूं ।

उपाध्यक्षा : आप को इस बात पर कुछ मुग़ालता लगा है । बिज़नेस ऐडवाईज़री कमेटी में बात हर वक्त आ सकती है और आएगी । (The hon. Member is labouring under some misunderstanding. This matter can come before the Business Advisory Committee any time and will come before it.)

चौधरी नेत राम : आप ने जो रूलिंग दिया है उस पर पाबन्द रहिये और मुख्य मन्त्री इस तरफ बैठाइये ।

ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ : On a point of order Madam. ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਸ ਉਪਰ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪੋਜ਼ਲ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਰਖੀ ਹੈ ਜੇ ਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਮੈਂਡ ਕਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ

[ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ]

ਲੈਣ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰਖਦੀ......

उपाध्यक्षा : मुझे अफसोस है कि आप को पहले मौका नहीं मिल सका। जब एक प्रोपोज़ल आ गई है तो इस पर न बोलें। (विघ्न)

(I am sorry the hon. Member could not get an opportunity earlier. When an other proposal has come he should not speak on the previous one)

चौधरी नेत राम : डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। हाउस सुप्रीम बाडी है या कमेटी..............

Deputy Speaker: Please take your seat. I am going to give my ruling on your point of order.

ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ : ਇਹ ਮੋਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਦਹੋਲਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਮੰਜ਼ੂਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰੋ।......

उपाध्यक्षा : चौधरी नेत राम के प्वायंट आफ आर्डर पर मैं रूलिंग देने लगी हूं। बिज़नेस ऐडवाईज़री कमेटी की रिपोर्ट हाउस में आती है। हाउस सब से ज्यादा सुप्रीम है, कमेटी से भी, दूसरे तमाम आनरेबल मैंबरान हाउस के मातहत हैं। हाउस सब से बड़ा है। (विघ्न)

(I am going to give my ruling on Chaudhry Net Ram's point of Order. The report of the Business Advisory Committee is presented to the House for adoption The House is supreme and more powerful than the Business Advisory Committee even. All the hon. Members are subservient to the House, which as I have already stated is all supreme.)

ਸਰਦਾਰ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ : On a point of order. ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਐਡਵਿਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਇਹ ਗਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਉਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਗਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਲਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਇਆ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ? (ਵਿਘਨ)

(Deputy Speaker called upon the Chief Minister to Speak.)

ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਗੋਆਣੀ: On a point of order. ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਨੇਮ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਉ।

उपाध्यक्षा : नेम करने का मतलब तो बाहर निकालना होता है मैं ने उन को बाहर नही निकाला। (Naming means turning out a Member from the House. I have not asked Giani Ji to withdraw from the House.)

ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ (ਫਰੀਦਕੋਟ) : ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦਹੋਲਡ ਕਰਨਾ, ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ, ਹਾਊਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੀ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਪਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ

ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਐਮ. ਐਲ. ਏਜ਼. ਨੂੰ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਂਦਾਰ ਨਾ ਸਮਝੋ ਫਜ਼ੂਲ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਐਂਗੇਜਮੈਂਟਸ ਹਨ, ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨ ਵਧਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਸਕਰੂ ਢਿੱਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰਕੇਨ ਸੈਸ ਬਿਲ ਤੇ ਇਕ ਦਿਨ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਇਕ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਿਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਥਰੈਸ਼ ਆਊਟ ਕਰ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਸ਼ਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਨੇਕ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੰਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੈਨਰਲ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ਲ ਕ੍ਰਾਪਸ ਸੈਸ ਬਿਲ ਦਾ ਤਅੱਲੁਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਠੰਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਤਾਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਪਰ ਕੱਲ ਅਜ਼ ਕੱਲ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਆਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ—ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਹੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਤਾਂ ਇਹ ਰਵਾਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਮੰਗ ਕਰੇ ਕਿ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉ, ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਕਹੇ ਕਿ ਬਹਿਸ ਲਈ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਦਿਉ ਪਰ ਅਜ ਇਥੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਖੋ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਲਿੰਗ ਦੀ ਬੜੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੋਸ਼ਨ ਪੰਜ ਮਿਨਟਾਂ ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਕ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਸੇ ਗਲ ਉਤੇ ਲਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਸ਼ਨ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ—ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਪਾਰਟੈਂਸ ਘਟ ਹੈ—ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰਖੋ ਕਿ ਜੋ ਐਮ. ਐਲ. ਏਜ਼. ਹਨ ਉਹ ਇਕ ਇਕ ਡੇਢ੍ਹ ਡੇਢ੍ਹ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੀਪਰੀਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਔਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿਉ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬੇਇਤਬਾਰੀ ਨਾ ਕਰੋ।

ਦੂਜੀ ਇਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡੀਬੇਟ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬੋਲਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਜ਼ ਉਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਢ ਲਓ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਉ। ਪਰ ਉਹ ਲਿਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਅਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਬਾਰ ਬਾਰ ਉੱਠਕ ਬੈਠਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇ ਕਿ "ਬੈਠ ਜਾਉ, ਬੈਠ ਜਾਉ"। ਸ਼ਰਮ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਇਕੋ ਵਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕੈਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰਖੋ।

श्री मोहन लाल : ग्रान ए प्वायंट ग्राफ ग्रार्डर, मैडम। डिप्टी स्पीकर साहिबा, जो प्वायंट ग्राफ ग्रार्डर सरदार नारायण सिंह ग्रौर ज्ञानी जी ने उठाए, यह प्रोसीजर का एक [illegible]

[श्री मोहन लाल]

अहम मसला है और मैं इस लिए उन को स्पोर्ट करता हूं कि अगर कोई गलत प्रैसीडैंट सैट अप हो गया तो अच्छा नहीं होगा। मैं जो कुछ अपने तजरुबे की बिना पर जानता हूं, कह सकता हूं कि कोई मोशन जो कि हाउस में बाकायदा मूव की गई हो वह हाउस की प्रापरटी बन जाती है और जब वह हाउस की प्रापरटी बन चुकी हो तो वह सस्पैंड नहीं की जा सकती इस के लिए कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं है, जहां तक मैं जानता हूं। या तो वह ऐक्सैप्ट की जा सकती है, या रीजैक्ट की जा सकती है, कन्सिडरेशन के प्वायंट पर वह सस्पैंड नहीं की जा सकती। ऐसा करना मैं बिल्कुल नामुनासिब समझता हूं। जो रीजन दिया गया है इस को सस्पैंड करने का वह बहुत नामुनासिब है। चौधरी नेत राम की बाकी बातों से दुनियां इत्तफाक करे या न करे लेकिन जो बात इस वक्त उन्होंने उठाई उसमें वजन है कि हाउस सुप्रीम है। हाउस के अन्दर जो मोशन आ चुकी है उसको कंसिडर करना हाउस का काम है। बिजनेस ऐडवाईज़री कमेटी में भेजना बिल्कुल नामुनासिब बात है क्योंकि उसकी रिपोर्ट की भी तो कंसिडर करने की मोशन होती है। इस लिए मैं आप से प्रार्थना करूंगा कि इस मोशन को, जो इस वक्त हाउस के सामने है, कंसिडर किया जाए और इसकी कंसिडरेशन को सस्पैंड न किया जाए। मैं सरकार से भी यही प्रार्थना करूंगा कि इस वक्त जो इस मोशन पर हाउस की फीलिंग्ज़ हैं उन को ध्यान में रखते हुए वह इस को विदड्रा कर लें।

डाक्टर बलदेव प्रकाश : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडम।

उपाध्यक्षा : कामरेड राम किशन तीन दफा बोलने के लिए खड़े हुए हैं ? क्या यह नामुनासिब नहीं मालूम होगा कि उन की बातों को न सुना जाए ? क्या आप यह समझते हैं कि ही हैज़ नो राईट? (Comrade Ram Kishan has risen thrice to speak. Is it not improper to deny him to speak? Do they think that he has no right to speak?)

डाक्टर बलदेव प्रकाश : मेरा प्वायंट आफ आर्डर भी तो, डिप्टी स्पीकर साहिबा, प्रोसीजरल मामले से ताल्लुक रखता है और इसी सम्बन्ध में है। वह यह है कि यह जो मोशन गर्ग साहिब ने यहां हाउस के सामने रखी है, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो एजंडा होता है उस में अगर कोई चेंज लानी हो और उसमें ऐसे रीज़न्ज़ हों कि स्पीकर उसमें चेंज लानी ज़रूरी समझे, किसी आइटम को चेंज या सस्पेंड करना चाहे, तो कर सकता है और उसके बाद दूसरी आइटम को लिया जा सकता है। यह बात रूल्ज़ के अन्दर है और जो मुताल्लिका रूल है वह मैं आप को पढ़कर सुनाता हूं वह यह है :

Rule 29

"On days allotted for the transaction of Government business such business shall have precedence and the Secretary shall arrange that business in such order and on such days as the Speaker after consultation with the Leader of the House may determine ;

Provided that such order of business shall not be varied on the day that business is set down for disposal unless the Speaker is satisfied that there is sufficient ground for such variation."

जो मैं ने सिर्फ गुजारिश करनी है कि यह अब बिल्कुल अननेसेसरी कंट्रोवरसी शुरू हो गई है कि हाउस सुप्रीम है या बिजनेस ऐडवाईज़री कमेटी। हाउस बिजनेस ऐडवाईज़री कमेटी की रिपोर्ट को रीजैक्ट भी कर सकता है अगर वह ठीक न समझे। आखिर यह कोई नई बात नहीं है। हमेशा बिज़नेस ऐडवाईज़री कमेटी बैठ कर बिज़नेस को सैट करती है, बनाती है और आप के पास यह अख्तियार है कि आप एक आईटम को पीछे रख सकते हैं, उसको सस्पैंड कर सकते हैं। तो फिर मैं हैरान हूं कि यह अनड्यू कंट्रोवरसी किस लिए हो रही है? आप ने साढ़े ग्यारह बजे बिजनेस ऐडवाईज़री कमेटी की मीटिंग रखी है। अगर उस की रिकमैंडेशन के साथ हाउस ऐसी नहीं करेगा तो वोट हो जाएंगे।

उपाध्यक्षा : कामरेड राम किशन।

चौधरी नेत राम : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है।

उपाध्यक्षा : चौधरी नेत राम, मैंने कामरेड राम किशन को काल अपान कर लिया है। मैं आप से दरखास्त करती हूं कि आप बैठ जाएये। (Chaudhri Net Ram, I have already called upon the Chief Minister. I request you to please take your seat.)

चौधरी नेत राम : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरे प्वायंट आफ आर्डर का जो जवाब आप ने दिया है वह मेरी समझ में नहीं आया। मेरी उस से तसल्ली नहीं हुई .....

उपाध्यक्षा : चौधरी नेत राम, आप तशरीफ रखिए। (Chaudhri Net Ram, please take your seat.)

चौधरी नेत राम : मेरा भी तो प्वायंट आफ आर्डर है।

उपाध्यक्षा : चौधरी नेत राम, अगर हमेशा नहीं तो कभी कभी तो आप चेयर की बात को मान लिया करें। (If not always the hon. Member should, at times obey the ruling of the Chair.)

चौधरी नेत राम : मैं जो प्वायंट आफ आर्डर करने वाला हूं उस को सुन कर आप इकट्ठा जवाब दे दें। जो रूलिंग पहले आप ने दी है उस से मैं मुतमईयन नहीं हुआ हूं ....

उपाध्यक्षा : चौधरी नेत राम, मैं आप की बड़ी रैस्पैक्ट करती हूं और आप ऐसी बात न करें कि उस में कमी आए। कभी कभी तो किसी की बात को समझा करें। मैं ने कामरेड राम किशन को काल अपान किया हुआ है। उन्हें बोल लेने दें। (I hold Chaudhri Net Ram in great esteem. He should not do any thing which may lower him in estimation. He should some time try to understand other's view. I have already called upon Comrade ram Kishan. Let him speak.)

मुख्य मन्त्री (श्री राम किशन) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, जो कुछ भी इस हाऊस के अन्दर इस सवाल पर बहस हुई है उस को सुन कर मुझे काफी दुख हुआ हैं खास तौर पर इस लिए कि कुछ ऐसे भाइयों ने इस सवाल पर डैमाक्रेसी की तरफ सरकार की तवज्जो दिलाई जिन्हें शायद इस बात का ख्याल नहीं रहा कि जब वह इस हाउस के अन्दर एक बड़ी इम्पार्टैंट

[मुख्य मंत्री]

कैबिनेट के मिनिस्टर थे तो किस तरह से उन दिनों मैंबरान का हाउस के अन्दर गला घोटा जाता था और किस तरह से मैंबरान को यहां पर बोलने की इजाज़त दी जाती थी। मैं इस वक्त उन बातों पर ज्यादा नहीं जाना चाहता लेकिन जहां तक इस गवर्नमैंट का ताल्लुक है मैं आप की सेवा में यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि जो पालिसी इस सरकार ने शुरू में बनाई थी, जो पालिसी आप के सामने रखी थी उसके मुताबिक मैंबरान को, जहां तक लैजिस्लेशन का ताल्लुक है और हाउस के काम में हिस्सा लेने का ताल्लुक है, इस में पूरी तरह से खुली इजाजत होगी और हमारी खाहिश है कि ऐसे मामलात पर जितनी भी ज्यादा डिस्कशन हो सकती है वह उसके मुताबिक बड़ी खुशी से करें। उसी के मुताबिक आप ने देखा कि जहां तक इस सेलज़ टैक्स बिल का ताल्लुक है, डिप्टी स्पीकर साहिबा, उस पर आज तक पूरे छः दिन लग चुके हैं और इस पर आप की इजाज़त से पूरी और पर खुले तौर पर बहस हुई है। जहां तक गवर्नमैंट का तालुक है, हम किसी चीज़ को भी दबाना नहीं चाहते। अगर हाउस चाहेगा, तो आप हाउस को जितना लम्बा करना चाहेंगे, हम उसके मुताबिक बैठने को तैयार होंगे। लेकिन इसी के साथ ही साथ, डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आप के ज़रिए हाउस को बताना चाहता हूं कि पिछली गवर्नमैंट के ज़माने में कितनी नान स्टाप सिटिंग्ज़ हुई, किस कदर मैंबरान को बहस में हिस्सा लेने की इजाज़त थी--इस में मैं नहीं जाना चाहता--और किस तरह से सभी बातें हुआ करती थीं। मगर इस बात की नसीहत देने के लिए आज वही साहिब खड़े हुए हैं जो उस जमाने में एक इम्पारटेंट मैंबर थे। मैं, डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप को इस बात का यकीन दिलाता हूं कि जहां तक इस गवर्नमैंट का ताल्लुक है, जहां तक आप के इस प्रथम सेवक का सम्बन्ध है, पार्लियामैंटरी डैमाक्रेसी की एक एक धारा की हम पूरी कदर करते हैं और उसी पार्लियामेंटरी सिस्टम के मुताबिक आप ने, स्पीकर साहिब ने बिजनैस ऐडवाईज़री कमेटी बनाई और वह कमेटी जैसा कि प्रोग्राम बनाती है उसी के मुताबिक हाउस को चलाया जाता है। यह काम सारे ग्रुप लीडर्ज़ के मशविरे से होता है। वही कमेटी इस हाउस का सारा बिजनैस और प्रोग्राम तै करती है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, बिजनैस ऐडवाइज़री कमेटी की जो रीसेंट मीटिंग हुई उस में इनफारमली यह बात तै हुई थी कि जहां तक लैजिस्लेशन का ताल्लुक है, आज के दिन वह सारा काम पूरा हो जाएगा। यह फैसला इनफारमली हुआ था। लेकिन इस बात को देखते हुए कि शायद आज भी यह काम खत्म न हो, इस मोशन को मूव किया गया था तो अब जब फिर इस हाउस के अन्दर सवाल उठा तो लीडर आफ दी आपोज़ीशन से बातचीत की गई। अब फिर इस सवाल पर बातचीत की है और बिजनैस एडवाईज़री कमेटी की मीटिंग को दोबारा बुला रहे हैं जिस में इस बात का फैसला किया जाएगा कि आया जो इस कमेटी ने नान-अफीशियल डे रखा है उस को डिसपेंस विद कर देती है या इस सेशन को दो चार दिनों के लिए बढ़ाती है या एक दिन में दो सिटिंगज़ करके काम को खत्म करना चाहती है, वह कमेटी इन सारी चीज़ों को देख कर फिर इस हाउस के अन्दर ले आए। यही बात कही गई है और कोई हम मेजारेटी वोट के ज़ोर पर कोई इंशु तय तो नहीं करवा रहे बल्कि हम तो इस मामले को बिज़नैस ऐडवाईज़री कमेटी के सुपुर्द कर रहे हैं जिस में हमारी पार्टी के भी मैंबर हैं और इस हाउस की दूसरी सारी पार्टियों के भी मैंबर हैं। हम यह चाहते हैं कि वही डिसाईड करे कि इस बारे में क्या प्रोग्राम बनाना है। वह चाहे तो दो चार दिनों के लिए सेशन को बढ़ा सकती है, वह चाहे तो

किसी दिन दो सिटिंगज़ रख सकती है और यदि वह चाहे तो नान-अफीशियल डे को यह काम रख सकती है और चाहे तो नान-स्टाप सिटिंग रख दे। लेकिन पंडित मोहन लाल जी ने मोशन को सस्पेंड करने का ज़िक्र किया। लेकिन सरदार गुदयाल सिंह ने इस को सस्पेंड करने की बात नहीं कही बल्कि उन्होंने तो इस को होल्ड ओवर करने के लिये कहा था। उन्होंने यह तो नहीं कहा कि इस को सस्पेंड किया जाए।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आप के ज़रिए बड़ी नम्रता से यह अर्ज़ करनी चाहता हूं कि डैमोक्रेसी की जो आप ने यहां रवायतें कायम की हुई हैं हम उन्हीं के मुताबिक चल रहे हैं और उन्हीं रवायतों के मुताबिक ही यह बिज़नेस एडवाईज़री कमेटी बनी हुई है जिस को स्पीकर साहिब ने हाउस की राए से कायम किया हुआ है और उसी के फैसलों के तहत यहां यह सारा काम चल रहा है।

मेरे एक बड़े ज़िम्मेवार दोस्त बाबू बचन सिंह ने इस सिलसिले में एक बात कही है। मैं उन को एक पुरानी बात की याद दिलाना चाहता हूं। जब वह पहले इस सदन के मैंबर हुआ करते थे। जब इस पंजाब असैम्बली के सामने एक बहुत इम्पार्टेंट मैयर पेश था और उस को पास करने के लिये यह हाउस रात के दो बजे तक बैठा रहा था। डिप्टी स्पीकर साहिबा, अगर मैं गल्ती नहीं करता तो उस दिन आप ही थीं जो इस हाउस को प्रीज़ाइड कर रहीं थीं। रात के दो बजे तक आप ने ही इस हाउस की कार्यवाई चलाई थी और वह जो मैयर था वह पंजाब की गरीब जनता के साथ ताल्लुक रखता था, और पंजाब के गरीब टैनेंट्स के साथ सम्बन्ध रखता था और उस वक्त नान स्टाप सिटिंग कर के उस बिल को पास किया गया था। सिर्फ यहीं पर बस नहीं। सरदार प्रताप सिंह कैरों की केबीनिट के वक्त जिस में पंडित मोहन लाल जी होम मिनिस्टर थे यहां पर लेजिसलेशन के बारे में क्या कुछ नहीं होता रहा, जो अब यह इस तरह की बातें बनाने लगे हैं। इस बात को सारी दुनिया जानती है कि किस तरह से मैंबरों को बिलों पर बोलने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। जहां तक इस गवर्नमैंट का ताल्लुक है इस बात से कोई भी इन्कार नहीं कर सकता कि इस ने पूरी तरह से मैंबर साहिबान को बिल्ज़ पर बोलने की खुली छुटी दे रखी हुई है और यह गवर्नमैंट जितनी भी आपोज़ीशन की जायज़ चीज़ें होती हैं उन की कदर करती है और आगे भी कदर करेगी (प्रशंसा) और इस तरह से कर के हम यहां जो पार्लियामेंटरी रवायात हैं उन पर चल कर डैमोक्रेसी को मज़बूत करने की कोशिश करेंगे और ऐसा करने में कामयाब हो सकेंगे।

जहां तक इस पार्टी के मैंबरान का ताल्लुक है इस हाउस में जितने भी दूसरे मैंबरान बैठे हुए हैं, मैं उन के बारे में यह कह सकता हूं कि हमारी पार्टी के मैंबरों के दिलों में गरीब किसानों और गरीब अवाम के लिए जितना दर्द है वह किसी दूसरी पार्टी के मैंबरों के दिलों में नहीं है और यही वजह है कि वह दिन और रात लगातार उन की बेहतरी के लिए काम करते रहते हैं।

इस लिए, डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आप के ज़रिए इस हाउस से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि वह इस सवाल को बिज़नेस एडवाईज़री कमेटी के फैसले पर छोड़ दे और जिस तरह से भी वह इस बारे में फैसला करे यह उस के मुताबिक चले। मैं ने यही आप से है निवेदन करना है।

(*Noise and Interruptions in the House*)
(*Khan Abdul Ghaffar Khan Rose to speak*)

Deputy Speaker : On what the hon. Member is going to speak ?
Khan Abdul Ghaffar Khan : Madam, I am on a point of Order.

मैं आप की खिदमत में इस लिए खड़ा हुआ हूं क्योंकि मुझे अपने मुअज़िज़ चीफ मिनिस्टर की तकरीर सुनने के बाद इतना रंज और सदमा पहुंचा है जितना कि मैं समझता हूं कि कभी नहीं पहुंचा। वैसे हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहिब हैं वह बड़े नेक हैं और बड़े भले आदमी हैं लेकिन उन की तरफ से यहां पर यह बात बार बार कहना कि पिछली गवर्नमैंट के वक्त..

Chief Minister : Madam, I rise on a point of Order. Is the Chief Minister under discussion ?

खान अब्दुल गफ्फार खां : मैं तो इन को इतना याद दिलाना चाहता हूं कि सरदार प्रताप सिंह के वक्त यह भी पहले डिप्टी मिनिस्टर रहे हैं और बाद में बतौर स्टेट मिनिस्टर के भी काम करते रहे हैं ......

उपाध्यक्षा : बेहतर होता अगर आप पहले मुझे कहने देते जो कुछ मैं इस बारे में कहना चाहती थी। अगर मुझे कहने दिया होता तो इस बारे में इतना कुछ कहने की ज़रूरत भी महसूस न होती। पूरा एक घंटा इस मोशन पर लग गया है। यह बात ठीक होती अगर यह मामला पहले ही बिज़नैस एडवाईज़री कमेटी के पास से हो कर यहां आता। खैर अब साढ़े ग्यारह बजे बिज़नेस एडवाईज़री कमेटी की मीटिंग होगी आप उस के फैसले की इंतज़ार करें। (It would have been better if I had been heard before. No need would have then been felt for all this discussion. It has taken full one hour. It would have been proper, if this motion had first been decided upon by the Business Advisory Committee. Anyhow, let the hon. Members wait for the decision of that Committee which is meeting at 11-30 a. m.)

BILL

The Punjab General Sales Tax (Amendment) Bill, 1965

(*Resumption of discussion Clause By Clause*)

CLAUSE 19

Deputy Speaker : The House will resume consideration of the Bill clause by clause. Clause 19 is before the House.

Comrade Ram Piara : On a point of Order, Madam. The hon. Chief Minister during the course of his speech has used the words "Leader of 'Opposition", Madam, I would like to know whether there is any Leader of the Opposition in this House ?

उपाध्यक्षा : लीडर आफ दी आपोज़ीशन तो सरदार गुरनाम सिंह जी हैं।

(Sardar Gurnam Singh is the Leader of the Opposition).

Comrade Ram Piara : Madam, is he Leader of the Opposition or Leader of the Akali party ?

Deputy Speaker : He is Leader of the Akali party.

Comrade Ram Piara : Then I should presume that there is no Leader of the Opposition in this House.

उपाध्यक्षा : वह अपनी पार्टी के लीडर हैं। (He is the Leader of his own party).

चौधरी नेत राम : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मेडम। डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं ने इस मोशन के सिलसिले में अपना एक प्वायंट आफ आर्डर उठाया था। उस पर आप ने फरमाया था कि बिज़नेस एडवाईज़री कमेटी के पास इस मामले को भेजने की मोशन पेश है मैंने कहा था कि पहले क्यों इसे बिज़नेस एडवाईज़री कमेटी के पास भेजा गया था। तो मैं आप से यह जानना चाहता हूं कि क्या चीफ पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी बगैर बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी के सामने इस मामले के पेश किए के इसे यहां पर ला सकते हैं और क्या यह दोबारा इस तरह से उस के सामने भेजा जा सकता है ?

उपाध्यक्षा : आप ने मेरी बात को ध्यान से सुना नहीं। मैंने कहा था क मुनासिब यही था कि यह उस कमेटी के पास से हो कर यहां आता। खैर अब चला गया है और इस बारे में जो हाउस की ओपीनियन है उस का उस कमेटी को पता लग गया है। अब इस बारे में वह इस ओपीनियन को सामने रख कर फैसला करेगी। (The hon. Member did not hear me attentively. I had stated that it would have been proper if the matter had come before the House after receiving due consideration by that Committee. Any how, it has gone before that Committee which is fully aware of the strong feelings of the House about it. Now the Committee would give its decision duly keeping in view the opinion in the House about it.)

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ : ਕਲਾਜ਼ ਨੰ. 19 ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ......

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਇਸ ਕਲਾਜ਼ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲਣ ਤਾਂ ਦਿਉ ਤੁਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ......

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਸ੍ਰੀ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। Order please. (I do not like the way in which the hon. Member Baboo Ajit Kumar interrupts, Order please.)

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ: ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਿਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ......

Deputy Speaker : You must withdraw these words.

Baboo Ajit Kumar ; I withdraw these words, Madam.

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ: ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਇਹ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮਝਣ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ਕ ਕਹਿ ਲੈਣ।

ਕਲਾਜ਼ 19 ਦੇ ਸ਼ੈਡਿਊਲ 'ਸੀ' ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਮਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਇਹ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਟੈਕਸ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਐਂਟਰੀ ਵਧਾਈ ਜਾਂ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਚਿਲੀਜ਼ ਜਾਂ ਫੂਡਗਰੇਨਜ਼ ਹਨ। ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਟੈਕਸ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸ਼ੈਡਿਊਲ 'ਸੀ' ਵਿਚ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਾਵਰ ਕਲਾਜ਼ 18 ਵਿਚ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੈਡਿਊਲ 'ਸੀ' ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ

[ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ]

ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ 19 ਕਲਾਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਇਕ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਸੀ ਕਿ 'ਜੁਤੀਆਂ' ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਉ। ਮਾਲੂਮ ਇਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ੈਡਿਊਲ 'ਸੀ' ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਮੰਨ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਗੇ, ਪਰਚੇਜ਼ ਟੈਕਸ ਲਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਰਨਾ ਮੁਨਾਸਬ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਜ 19 ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।

श्री बलराम जी दास टंडन : मैं इस बारे में कुछ कहना चाहता हूं . . .

उपाध्यक्षा : जब वह क्लाज़ को ही वापस लेना चाहते हैं तो फिर आप ने क्या कहना है। (विघ्न) (What will the hon. Member say when he is going to withdraw the clause itself). (*Interruption*)

श्री बलराम जी दास टंडन : ग्रान ए प्वायंट ग्राफ ग्रार्डर, मेडम। ग्रभी तो, डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह क्लाज़ बिल में स्टेंड करती है, वोटिंग के बाद क्या पोज़ीशन होगी वह तो बाद में ग्रायेगी। ग्रभी तो इन्होंने ग्रपनी राय दी है जब तक पोज़ीशन फाइनल नहीं हो जाती तब तक इस पर बहस हो सकती है।

उपाध्यक्षा : वह कह रहे हैं कि इस क्लाज की ग्रब ज़रूरत नहीं रही तो वह इस बात को पास करवाना उन की ज़िम्मेदारी है। (He says that this clause has now become redundant. He will see that this is approved by the House).

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : On a point of order, Madam. ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।

ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿੰਟ ਦੋ ਮਿੰਟ ਇਸ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਉ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੋਟ ਪਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ (ਵਿਘਨ) ਲੈ ਸਕਦੇ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ : ਪਰੋਸੀਜਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਕੋਈ ਕਲਾਜ਼ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਡੀਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੋਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। (ਵਿਘਨ)

ਕੁਝ ਆਵਾਜ਼ੇਂ : ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।

श्री बलरामजी दास टंडन : डिप्टी स्पीकर साहिबा, जिस बेतरतीबी ग्रौर बिना सोचे समझे इस बिल की ड्राफटिंग को वज़ीर साहिब ग्रौर कैबिनेट ने मन्ज़ूरी दी है उस का इस से बड़ा सबूत ग्रौर क्या हो सकता है कि इस बिल में जिस तरह से सब क्लाज़ 18 है वह भी

इस में थी और, जैसे इस वक्त क्लाज़ 19 है वह भी इस बिल में थी। इस तरह से बिल बना कर यह हाउस के सामने लाए। अब फरमाते हैं कि क्लाज 18 के होते हुए क्लाज 19 की ज़रूरत नहीं है। हम ने क्लाज़ 18 के ज़रिये यह पावर ले ली है कि नोटीफिकेशन के ज़रिये किसी आर्टीकल की शैड्यूल "सी" में ऐडीशन करा लें या उस में से निकाल लें। उस क्लाज़ से यह पावर सरकार में इन्हैरेंट हो जाती है। इस लिये अब क्लाज 19 को ड्राप करना चाहते हैं। तो इस का साफ मतलब और यह है जैसे कि पहले भी कई क्लाज़ों के केस में हुआ है और उस से भी यह साफ है कि सरकार ने बिला सोचे समझे इस बिल को ड्राफ्ट किया है। मैं यह नहीं कहता कि जो नामुनासिब बात इस में है उस को यह वापिस क्यों लेते हैं, उसे वापस लें मगर इस से यह बात जाहर होती है कि सरकार इस बिल को एक अन्धाधुन्ध तरीके से बिना विचारे कि इस में क्या रख रही है, यहां पर लाई है। मतलब सिर्फ इस का यह था कि यह किसी न किसी तरीके से व्यापारियों को तंग कर सकें। अब नतीजा यह है कि इस ने यहां पर बैठ बैठ कर एक एक क्लाज़ की सब-क्लाजों को भी विदड्रा किया है। हम सरकार की इस सारी जहनियत को कन्डेम करना चाहते हैं।

बाबू बचन सिंह : मैं एक बात से तो बहुत खुश हूं कि वज़ीर साहिब ने इस क्लाज़ को पेश करते वक्त कुछ लफज़ कहने मुनासिब समझे ...

वित्त मन्त्री : जहां ज़रूरत होती है वहां कहता हूं।

बाबू बचन सिंह : चेयरमैन साहिब, अगर सरदार कपूर सिंह ने इस बिल को एक बार भी पढ़ा होता तो वह यह दफा 19 किसी तरह से भी इस में न लाते। मालूम यह देता है कि इन्होंने आंखें बन्द कर के इस बिल पर दस्तखत किये हैं। और जो कुछ इन के महकमे ने लिख दिया वह इन्होंने कलामे इलाही समझ लिया। अब देखना यह है कि इन के महकमे के जिन अफसरों ने यह बिल तैयार किया है उन को कोई सज़ा मिलनी चाहिए या नहीं कि उन्होंने इस किस्म की बेवकूफी की है और इस का मतलब यह है कि वह ऐसी ही हज़ारों बेवकूफियां रोज़ाना करते हैं।

दफा 18 क्लीयर है कि जो शैडयूल "सी" है उस में आप जितना चाहें ऐड कर लें और जितनी चाहें डिलीशन कर लें। जब इस किस्म के फुल राइट हैं तो दफा 19 को रखने की क्या ज़रूरत थी। मुझे तो इस बात के लिए खुशी है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं मानना चाहिए। आखिरकार इस बात की अक्ल तो आ गई कि इन्होंने बेवकूफी की है। यह जो इन्होंने कहा है कि इस बात का सही सबूत है कि जब बिल पेश किया जाता है तो वज़ीर साहिब इस को पढ़ते नहीं और इस का गौर से मुताला नहीं करते और इस को क्रिटीक्ल तौर से नहीं देखते। अगर इन्होंने इस बिल को यहां पर पेश करने से पहले एक बार भी अच्छी तरह से देखा होता तो इन्हें पता चल जाता कि फलां क्लाज़ की इस में ज़रूरत रह जाती है या नहीं इसी तरह से पंजाब गवर्नमैंट कानून पास करवा लेती है और जब हाई कोर्ट में केस जाते हैं तो वहां पर एक बार नहीं, दो बार नहीं, दस बार फैसला दिया जा चुका है कि कानून में फलां खला था, खामी थी। इन बातों को देख कर कम से कम मेरा सर तो नदामत से झुक जाता है कि किस तरह से गवर्नमैंट बिलों को पास करवा कर ऐक्ट बनाती है। (विघ्न)

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ ਮੇਰਾ ਮਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਬਾਬੂ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਦੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ । ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲ ਬਾਬੂ ਜੀ ਕਿਸ ਗਲ ਤੇ (Shri Roop Singh Phul, a Member of the Panel of Chairmen, occupied the hair) ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾ ਦਾ ਸ਼ੈਡਿਊਲ 'ਸੀ' ਕਿਸੇ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੀਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਰਟ ਵਿਚ ਬਾਬੂ ਜੀ ਉਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੇਮਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਫਲਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਵਿਚ ਹਸਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨਜਾਣਪੁਣੇ ਦੀ ਦੀ ਦਾਦ ਦਿਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਕਰ ਹਹੇ ਹਨ । ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਸ਼ਡੂਲ 'ਸੀ' ਕੇਵਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਰੀਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ । ਮੈਨੂੰ ਇਥੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਪਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੁਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬੂ ਜੀ ਕੀ ਗਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ । ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਸਦਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਵਾਕਫੀਅਤ ਬਾਰੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬੂ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਿਆ । ਅਮੈਂਡਿੰਗ ਬਿਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਮੈਂਡਿੰਗ ਬਿਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿਚ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ । ਅਤੇ ਜਦ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਰਿਜਨਲ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ । (ਵਿਘਨ) ਮੈਂ ਇਸ ਅਮੈਂਡਿੰਗ ਬਿਲ ਦੇ ਇਕ ਇਕ ਲਫਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ । ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਗਲ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਇਕ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵਾਂ । ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਨ ਵਿਚ ਮਿਥ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਰਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ।

ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਕਲਾਜ਼ 19 ਦਾ ਤਅੱਲੁਕ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਅਸਲ ਵਿਚ ਗਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਇਨ ਇਟਸ ਉਰਿਜਨਲ ਫਾਰਮ, ਜਦ ਪਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਕਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਚੋਂ ਕਢ ਕੇ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਦੂਜੇ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲਿਆਉ । ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਇਵੇਜ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਫਾਜ਼ਲ ਦੋਸਤ ਅਜ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਗਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਲ ਵਿਚੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੀਲੀਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂ (ਵਿਘਨ) ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਇਸ ਕਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰਖਿਆ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਡੀਲੀਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ । ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦਸ ਦਿਤੀ ਹੈ । ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮੈਂਡਿੰਗ ਬਿਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ । ਇਸ ਕਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮਝੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਲਾਜ਼ ਦੀ ਨੈਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡੀਲੀਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਮੋਸ਼ਨ ਪੁਟ ਕਰਕੇ।

Mr. Chairman . . Question is—

That Clause 19 stand part of the Bill.

The motion was lost.

SUB-CLAUSE (1) OF CLAUSE 1.

Mr. Chairman ; Question is—

That Sub-Clause (1) of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

Mr. Chairman : Question is—

That title be the title of the Bill.

The motion was carried.

Finance Minister (Sardar Kapoor Singh) : Sir, I beg to move—

That the Punjab General Sales Tax (Amendment) Bill, as amended, be passed.

Mr. Chairman ; Motion moved—

That the Punjab General Sales Tax (Amendment) Bill, as amended, be passed.

चौधरी नेत राम : ग्रान ए प्वायंट ग्राफ ग्रार्डर, सर। मैं यह जानना चाहता हूं कि ग्राज की कारवाई किस तरह से चलाई जा रही है क्यों कि बिज़नेस ऐडवाईज़री कमेटी में इस बात का कोई एजन्डा नहीं था ग्रौर पहले जो मोशन रखी गई थी वह तो ग्रकसैप्ट नहीं हुई। एडवाईज़री कमेटी चल रही है तो इस बात के होते मेरी समझ में नहीं ग्राया कि यह हाउस की कारवाई किस ढंग से ग्रौर कैसे चल रही है। ग्राज की वैसे लाला लाजपत राए की बर्सी के संबंध में छुट्टी भी है। इस के बारे में मैं ग्राप का रूलिंग चाहता हूं।

श्री बलरामजी दास टंडन (ग्रमृतसर शहर पश्चिम) : चेयरमैन साहिबा, यह जो बिल पास करने का मोशन मिनिस्टर साहिब ने पेश किया है, मैं इस की मुखालफित करने के लिये खड़ा हुग्रा हूं। जहां तक सेल्ज टैक्स का ताल्लुक है जैसा कि मैं ने इस बिल की पहली रीडिंग के समय कहा था, वज़ीर साहिब इस महकमे की कारगुजारी को देखने की कोशिश करें। ग्रब जब कि यह बिल तीसरी रीडिंग स्टेज पर है, मैं फिर यह बात कहना चाहता हूं कि जहां तक सेल्ज टैक्स ताल्लक है यह ठीक ढंग से ग्रगर वसूल किया जाये तो इस सरकार का रैवेन्यू बढ़ेगा, किसी को तकलीफ भी नहीं होगी। मगर होता क्या है कि जिस ढंग से सेल्ज टैक्स वसूल होना चाहिये, उस तरह नहीं हो रहा ग्रौर जिस ढंग से इस के डिपार्टमैंट को वसूली के लिये काम करना चाहिये, वह नहीं किया जा रहा। ग्रसल कारण की तरफ यह सरकार ध्यान देना नहीं चाहती ग्रौर इस बात को ग्रपने प्रिविलेज की ब्रीच समझ कर यह ग्रवायड करना चाहती है। जहां तक इस बिल के एम्ज़ ऐंड ग्रौबजैक्ट्स का जो मनशा है उस के मुताल्लिक दो रायें नहीं हो सकतीं कि सरकार को ग्रपना कारोबार चलाने के लिये, डिवैलपमैन्ट के कामों के लिये, रैवेन्यू हासिल करने के लिये साधन ग्रकसर ग्रपनाने पड़ते हैं। यहां पर एक बात ग्रौर यह भी कही गई कि हम ने दो-तीन चीज़ों के मुताल्लिक युनियन सरकार से सलाह करके ऐक्साइज़ डियूटी को तबदील कर दिया है। ग्रब भी यही वादा किया गया कि यह सरकार कुछ ग्राईटम्ज़ के केस में ऐसी बात करेगी कि वह सेल्ज़ टैक्स को भी ऐक्साईज ड्यूटी के ग्रन्दर

[श्री बलरामजी दास टंडन]

शामिल करने की कोशिश करेगी। मगर, चेयरमैन साहिब, ऐसा दिखाई देता है कि सरकार का जो नज़रिया इस सिलसिला में है वह, मुनासिब नहीं है। पहले भी यह बात इस हाउस के अन्दर कही गई है कि टैक्स देने से कोई भी आदमी कतराता नहीं है क्योंकि मुल्क के अन्दर कोई भी काम अगर डिवैल्पमैन्ट का हो सकता है तो वह सरकार के ज़रिये से ही हो सकता है। मगर ज़राये इसके लिये जो चाहियें वह इस देश के लोगों से ही पूरे होने हैं। हर चीज़ की कोई न कोई सीमा होती है। अगर कोई चीज़ हद से तजावज़ कर जाती है तो ज़रूरी है कि वह चीज कोई और सूरत इख्तयार कर ले। जब सेल्ज़ टैक्स पहले लगाया गया था तो उस वक्त कोई और तरीका चल रहा था। अन्ग्रेज़ों ने जब सेल्ज टैक्स लगाया था तो यह कह कर लगाया था कि आज कल चूंकि जंग का जमाना है हम यह टैक्स लगाना चाहते हैं, जंग के बाद इस को खत्म कर देंगे। मगर इस के बाद भी लोगों को नये नये तरीकों से टैक्स देने पर मजबूर किया गया। आज मुझे यह देख कर हैरानी होती है कि यह टैक्स पहले की निस्बत कई गुना बढ़ गया है। कहीं पर सैंट्रल टैक्सिज़ हैं और कहीं पर प्राविनशयल टैक्सिज़ हैं जिन चीज़ों पर पहले 2 प्रतिशत टैक्स था आज उन पर 6 प्रति शत टैक्स है। आज किसी पर अगर पहले हम 12 प्रतिशत दे रहे हैं तो यह 14 प्रतिशत हो जायेगा। एक तरफ चार आने पर हंडरड रुपीज़ था और दूसरी तरफ 14 प्रतिशत है। अब आप ही हिसाब लगा लें कि किस प्रोपोरशन से टैकिसिज बढ़े हैं। जो रकम सेल्ज टैक्सिज से वसूल होती है यह 16–17 करोड़ रुपये के करीब है। इस बात के लिये व्यापारियों ने एक बार नहीं बल्कि कई बार अर्ज़दाशत की कि आप को कितने टैक्सिज़ अब मिलते हैं आप इस से कई गुना ज़्यादा टैक्स हम से ले लें मगर यह नौकरशाही जिस को आपने हम पर खुला छोड़ा हुआ है इस से छुटकारा तो दिलायें। यह ऐसे कुरप्ट अफसरान हैं जिस को सुधारने के लिये, टैकल करने के लिये इस सरकार के पास कोई ताकत नहीं है, कोई ज़राये नहीं है। सरकार को पहले इन लोगों को जकड़ने के लिये अपने हाथों को मज़बूत करना होगा

(Quorum bells were rung for quorum)

चेयरमैन साहिब, मैं ने उस दिन फस्ट रीडिंग पर भी कहा था कि अगर आप इस बिल में कोई तरमीम करना चाहते हैं तो इस ढंग से करें जो सब को मुनासिब मालूम दे। जायज़ टैक्स के लिये किसी भी व्यापारी को कोई गिला नहीं हो सकता मगर कोई भी खुददार व्यापारी यह बरदाशत नहीं करेगा कि अगर उस ने एक कापी पर किसी अफसर की मोहर लगवानी हो तो वह पहले ऐफीडैविट दे कर जाये। जगह जगह पर बैरियर इसके लिये कायम किये जायें जैसे कभी पुराने ज़माने में हुआ करता था। अगर पहले कटहड़े के अन्दर जाये तो वहां टैक्स दे, पहले से दूसरे के अन्दर जायें तो वहां टैक्स दे और इस तरह से टैक्स देता ही चला जाये। आज इसी तरह से टैक्सिज की वसूली के लिये यह चैक बैरियर्ज़ कायम करना चाहते हैं। मगर इनको याद होना चाहिये कि कुछ अर्सा पहले देहली और पंजाब की सरहद पर जो चैक बैरियर तोड़ा गया था वह इस वजह से तोड़ा गया था कि जब ऐक्स चीफ मिनिस्टर ने खुद जाकर देखा था कि सैंकड़ों की तादाद में व्यापारियों को रोका हुआ था, ट्रकों के ट्रक खड़े हुए थे, किसी को कहा जा रहा था कि तुम अपना वाउचर मद्रास से ठीक करवा कर लाओ और किसी को यह कहा जा रहा था कि तुम अपना बीचक बम्बई से दुरुस्त करवाओ। जो पैसे दे जाता उससे आगे

जाने दिया जाता इस तरह जो लोग इन चैक बैरियर्ज़ पर लगे होते थे सैंकड़ों नहीं, हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपये की कमाई कर रहे थे। इनके चपड़ासियों से ले कर कलर्क लोग सभी कमा रहे थे। यह बैरियर मजबूर होकर उस वक्त सरकार को बन्द करना पड़ा था। आखिर इस कुरप्शन को फैलाने वाले हैं कौन लोग ? यह वही अफसरान हैं जिन को सरकार ने इतनी पावर दी हुई है। अगर किसी व्यापारी से 5 रु. का अन्दराज रह जाता है तो यह उस की सारी दुकान तक कुर्क करने को जाते हैं। उस का पीछा उस वक्त तक नहीं छूटता जब तक वह 10,000 रु. की ज़मानत न दे। ऐसे ऐसे तरीके सरकारी मशीनरी की तरफ से अपनाये जाते हैं कि अगर किसी को एक पैसे का भी मुनाफा होता हो तो यह इस बात का समझौता करने पर आमादा हो जाते हैं कि इस एक पैसे में से धेला हमें बचा कर दो और धेला तुम रखो। अगर किसी को 10,000 रुपए का फायदा हो तो यह कहते हैं कि दो हज़ार इधर रखो। मैं पूछता हूं कि ऐसे अफसरान पर इस सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। कभी कहते हैं कि किताबों को चैक कराओ, कभी कुछ और कभी कुछ। मगर बीमारी की जड़ तो वह खुद हैं तो क्यों न सरकार इन लोगों पर अपनी विजीलैंस बढ़ान की कोशिश करे। यहां पर ऐसे कई केसिज़ मैम्बरान ने इस सरकार के नोटिस में लाये हैं। क्या इन्हों ने कभी कोई ऐक्शन लेने की कोशिश की है ? खुद डाक्टर साहिब एक डैफिनिट केस आप के नोटिस में लाये थे। क्या सरकार ने किसी आदमी पर कोई ऐक्शन लेने की कोशिश की ? मगर इन के अफसरान इन के क्लर्क, यहां तक कि अगर इनका चपड़ासी भी बाहर जाकर सेल्ज़ टैक्स की चैकिंग के नाम पर महीना भर तक बुलाता रहता है तो चाहे व्यापारी के कोई भी मजबूरी क्यों न हो उसे सब काम छोड़ कर एक 100–125 रुपए माहवार तनखाह पाने वाले कलर्क की खिदमत में हाज़िर होना पड़ता है। उस का कोई काम बिना पैसे दिये नहीं हो पाता। अगर एक चपड़ासी, जिसको किसी की फाइल उठा कर आगे देनी होती है, वह भी जब तक उसे पैसे न मिल जाएं न जाने कितने चक्कर कटवाता है और पूछने पर कहता है कि अगर आप पहले ही दे देते तो आपको इतनी तरद्दद और खर्च तोन उठाना पड़ता। और जो आदमी आफिसों में जाते हैं, उनको न बैठने के लिये कोई जगह है, न ही और कोई सुविधा है इनकम टैक्स वालों न तो फिर कुछ सहूलियत दी है लेकिन इकसाइज के महकमे वालों ने तो लोगों को तंग कर रखा है। न तो उनके साथ सलूक अच्छा होता है, न ही उनकी सुनवाई होती है। असैम्बली में अमेंडमेंट देने और बोलने से ही यह साबित नहीं हो जाता कि डैमोक्रेसी ठीक तरह से चल रही है। बल्कि जनता को अफसरों के हाथों ट्रीटमेंट भी डैमोक्रेसी वाला मिलना चाहिये। एक अफसर किसी भी व्यापारी को एक डेट मुकर्रर कर देता है, लेकिन जब वह दफतर में पहुंचता है तो दिन भर तो बैठा रहता है कोई नहीं पूछता, लेकिन जैसे ही दफतर का टाइम खत्म हुआ, अफसर उठ कर चला जाता है और कहलवा देता है कि अब वह व्यापारी किसी और डेट को आए। इस तरह डेट पर डेट पड़ती चली जाती है और लोगों का बिज़नेस खराब होता रहता है।

मैं सरकार को यही कहना चाहता हूं कि व्यापारियों की आफर सरकार स्वीकार करे क्योंकि वह 20 तो क्या 24 करोड़ रुपया तक सरकार को देने के लिये तैयार हैं। अगर सरकार

[श्री बलरामजी दास टण्डन]

उनकी बात को स्वीकार करती है तो जो 2–3 करोड़ रुपया कुलैक्टिंग एजंसी पर खर्च कर रही है वह बच जाएगा और 12 या 13 करोड़ की जगह दुगना रुपया सरकार को मिल जाएगा। लकिन मालूम तो यह होता है कि सरकार का ढंग यह है कि लाखों लोग सरकार के इशारे पर चलें वही ढंग यह अख्तियार कर रही है। इसीलिये ऐसी ताकत यह अफसरों को दे रही है। मैं फाइनैंस मिनिस्टर साहिब को यह कहता हूं कि व्यापारियों की आफर स्वीकार कर, फिर अगर व्यापारी अपनी बात से भागते है तो भाग जाएं। आपने जंग के बाद जो यह तोहफा देने का काम किया है इससे जनता आपके खिलाफ हो जाएगी, क्योंकि यह बिल्कुल गलत मैयर है, ना मुनासिब है, इसको रद्द करना चाहिये और इसको विदड्रा कर लेना चाहिए।

श्री रामसरनचन्द मित्तल (नारनौल) : चेयरमैन साहिब, मैं दो चार बातें ही रखूंगा। दरअसल इस बिल के द्वारा रेट्स आफ टैक्सेशन नहीं बढ़ाए जा रहे हैं। इसके अन्दर इवैयन रोकने के लिये प्रोवीयन्स हैं या कुलैक्शन करने के बारे में हैं। इस बिल के बारे में कुछ गलत प्रजिडुसिज़ हो गए हैं और यह कहा जा रहा है कि चूंकि इससे किसी खास कम्युनिटी पर बोझ पड़ता है इसलिए कुछ लोग उस कम्युनिटी को डिफैंड करना चाहते हैं या उनके लिए बहुत बोलते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि इसका बोझ किसी खास कम्यूनिटी पर ही नहीं बल्कि सभी कंज्यूमर्स पर पड़ता है। एपैरेंटली चूंकि इस टैक्स को कामर्शियल कम्यूनिटी कुलैक्ट करती है इसलिये ऐसा कहने की गुंजायश बन जाती है। और उसी लाइट में सरदार गुरनाम सिंह जी ने भी कहा है कि लोगों को इस कम्युनिटी के साथ ज्यादा सिम्पैथी है, और किसानों के साथ कम है। ऐसी बात नहीं है। किसानों के साथ सबको सिम्पथी है। मैं समझता हूं कि जिस डिपार्टमैंट ने ऐडमिनस्टर करनाहै अगर उसके अन्दर यह बात रहेगी कि यह शहरी हैं और इनको कुचलना है, तब तक ऐडमिनस्ट्रेशन ठीक नहीं रहेगी। ओपन माइंड से बात अगर देखी जाए तो ही अच्छा ऐडमिनस्ट्रेशन चल सकता है।

यहां पर एक माननीय मंत्री ने यह कहा कि मित्तल साहिब ने पद छोड़ने के बाद अपनी राय बदल ली पहले कुछ और थी। मैं उन्हें कहना चाहूंगा कि ऐसी बिल्कुल बात नहीं है, जो मेरी राय अब है वही पहले भी थी। कामरेड साहिब को अच्छी तरह याद है जब वे केवल एम. एल. ए. थे तब उन्होंने इस महकमे की नुक्ताचीनी की थी, उस समय के मुख्य मंत्री ने मुझे उनकी कम्पलेंटस की जांच करने के लिये कहा था। मैंने उन केसिज़ को स्वंय देखा और पाया कि जितनी उनकी शिकायतें थी वह दुरुस्त थीं और मैंने बावजूद महकमें के एडवर्स रिपोर्टस होने के उन्हें कहा कि मैं ने आपकी शिकायतों को दुरुस्त पाया। वही व्यूज, और attitude अभी भी हैं जो आज मैंने फर्स्ट रीडिंग पर बातें कहीं और अब जो कह रहा हूं और उस से पहले भी जब कभी मैं अमैंडमेंट पर बोला हूं मेरे व्यूज़ और एटिचूयूड शुरू से यही रहे हैं। अगर मेरी इन्डीविजूअल राए पेश करने के बावजूद कोई तरमीम पास नहीं होती तो उस का यह मतलब नहीं लिया जाना चाहिये कि उस चीज़ की जिम्मेदारी मेरे ऊपर लगा दी जाए। यह जो बिल है जब पास होकर एक्ट बन जाएगी तो फिर यह इस हाउस का एक्ट समझा जाएगा, यह नहीं समझा जाएगा कि फलां मैम्बर ने क्या राए दी थी या क्या नहीं दी थी। जो डीसीयन्ज उस वक्त हुए थे उन के बारे में मेरा ऐटीच्यूड यही रहा था जो आज है लेकिन जो मेजारिटी का फैसला होगा वह सब को मानना पड़ेगा। इस लिये मेरे मुताल्लिक

जो बार बार कहा गया, एक दो मन्त्रियों ने भी ऐसा कहा था वह बात दुरुस्त नहीं। मैं कैबिनेट सीक्रेट्स में नहीं जाना चाहता सिर्फ इतना ही कहता हूं कि मेरे जो परसनल व्यूज़ हैं उन में कोई चेंज नहीं हुई है जो पहले थे अब भी वही हैं। आप जानते हैं कि जब व्हिप जारी होती है कि फलां तरमीम माननी है तो हम को मानना होता है लेकिन अपने इन्डीविजूअल व्यूज़ जो हैं वह तो जो हैं वही रहेंगे। इसी लिये मैं ने कामरेड साहिब के वाके का यहां पर ज़िक्र किया है। मैं ने उन की शिकायत पर विदाउट ऐनी आफिश्यल असिसटैंस वहां परसनली जा कर इन्क्वायरी करके जो बातें सही थीं उन की रिपोर्ट की थी। वह फाईलें अब इन के पास कहीं होंगी। मैं वित्त मंत्री साहिब से सिर्फ इतना अर्ज़ करना चाहता हूं कि यह जो 2/4 प्रोवियन्ज़ हैं उन के बारे में ज़रा एहतियात की जाए। जैसे रिफन्ड का प्रोवियन है। इसके बारे में मैं बहुत पार्टीकुलर था कि क्यों डिले हो जाती है। मैं ने ला को स्टडी किया था। तीन साल ज़रूरी नहीं था उस से ज्यादा भी हो सकता था। खैर मैं सिर्फ इतना ही अर्ज़ करता हूं कि रिफन्ड के लिये जब कोई एप्लीकेशन दे तो वह बाकायदा रीसीट होनी चाहिए। और डीलर को रसीद देनी चाहिये और रजिस्टर में दर्ज होनी चाहिए नहीं तो तीन साल के बाद अगर फाईल कहीं खो गई तो महकमें वाले कह देंगे कि साहिब इन्होंने तो रिफंड के वास्ते एप्लाई ही नहीं किया और अब टाईम बार्ड एप्लीकेशन हम नहीं लेते। इसलिये मैं कहूंगा कि रिफंड के लिये जो एप्लीकेशन हो वह बाकायदा रिसीट की जानी चाहिये। जब एरियर्ज़ सरकार लैंड रैविन्यू के तौर पर रिकवर करती है तो फिर रिफन्ड के बारे में भी पर्टीकुलर होना चाहिए। बस मैं इतना ही कहना चाहता था।

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ (ਸਿਧਵਾਂ ਬੇਟ, ਐਸ. ਸੀ.) : ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣ ਬਰੂਟ ਮੈਜਾਰੀਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਰੀਡਿੰਗ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਤਕੜੇ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਜਦ ਧੱਕੇ ਜ਼ੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਜ ਅਸੀਂ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਕਤ ਦੇ ਬਲਬੋਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੰਮ ਦਾ ਅਸਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਿਚ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਸਣ ਲਈ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਇਨਸਾਨੀ ਕਦਰਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀ ਏਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਲਖਾਂ ਰੁਪਿਆ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰੈਸਟੀਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਚੌਥੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕੁਝ ਰੁਪਿਆ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮੂੰਹ ਦਖ਼ਾਲਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਕ ਅਸੂਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਔਰ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਏਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਾਵਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੇ

[ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ]

ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੰਗੀ ਗਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਿਸਿਪਲਨ ਦੇ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤੀ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਆਮ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਡਾਕੂ ਤੋਂ ਘਟ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਕ ਵਾਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਝਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਪੜਾਸੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ, ਸਾਹਿਬ ਬਹਾਦਰ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਚੁਪ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਕੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਗਰਿਟ ਦੀ ਡਬੀ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਚਾਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਡਾਂ ਬਕਰੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਟਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਅਗੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡੀਲਰਜ਼ ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਨਰਜਿਸਟਰਡ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਡੀਲਰ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸੇਲ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਬਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਨੇ ਅਖਤਿਆਰ ਲਏ ਹਨ ਤਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੀਅਤ ਕਰੇ ਤਾਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਉਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਡੀਲਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਚੋਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਲਈ ਸੋਫੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੋਹਫੇ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਨਾ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣ ਤਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਲੇ ਹਨ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਬੰਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਗਲ ਵਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਅਮੀਰ ਘਰਾਨੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰਖਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ।

ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਗਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਕਤਾਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਖਰ ਤਕ ਰੂਰਲ ਆਉਟ ਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜੋ ਦਿਲ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਬਿਲ ਡਰਾਫਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇਨਾਂ ਗਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ। ਇਕ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਟੈਕਸੇਬਲ ਲਿਮਿਟ ਘਟਾ ਕੇ ੪੦ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਲਾਈਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੈਂ ਕਲ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਦਸਤਕਾਰੀ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਕਿ ਜੁੱਤੀ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ੈਮਪਟ ਕਰ ਦਿਓ ਪਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਟੈਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਮੜਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸੀ ਜੱਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਤੋਂ

ਇਮਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਥੇ ਹੀ ਲੋਕ ਹੀ ਚਮੜਾ ਟੈਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਉਸ ਚਮੜੇ ਨਾਲ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੀ ਵਿਕ ਜਾਣ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਕ ਦੋ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਥੋਕ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਇਕ ਵਡੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਜਲੰਧਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਥੇ ਉਹ ਦਸ ਵੀਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲੈਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਡੇ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਗਰੀਬ ਤੇ ਅਣਪੜ੍ਹ ਆਦਮੀ ਹਨ ਜੋ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਪੇਟ ਪਾਲਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਛੋਟੇ ਖੋਖੇ ਲਗਾਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿਤੀ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਲਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬ ਅਣਪੜ੍ਹ ਆਦਮੀ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਇਕਠੇ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਚਾਰ ਇਤਵਾਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਤੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾਂਦੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਪਾਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਹ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Mr. Chairman : Please Wind up now.

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਨਾ ਕਰੋ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਣਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਐਨੇ ਰਜਿਸਟਰ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਦਫਾ ਹੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਇਕ ਫਿਕਸਡ ਰਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਲਗਾ ਦਿਓ (ਘੰਟੀ) ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗਲ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ।

श्री मोहन लाल (बटाला) : चेयरमैन साहिब, इस बिल पर काफी बहस हुई है और मैं अपने फिनांस मिनिस्टर साहिब की दाद देता हूं कि उन्होंने बड़े सबर पेशेंस के साथ इस बिल को पायलट किया है और वह इस बात के भी हकदार हैं कि उनका धन्यवाद किया जाए कि उन्होंने इस हाउस की सैंटी मैंटस को सामने रखते हुए बहुत सी अमेंडमैंट को माना है और इस बिल में जो सख्तियां नज़र आती थीं उनको दूर करना उन्हों ने मन्जूर किया है। हकीकत में उनकी पेशैंस और रिस्पांस की कदर करता हूं। जिस गर्ज़ के लिये वह बिल लाए थे अगर वह अब पूरा हो जाए तो इससे ज्यादा खुशी इस हाउस के मैम्बर साहिबान को नहीं हो सकती। उन्होंने कहा था कि टैक्स को इवेड करने के लिये जो तदाबीर व्यापारियों की तरफ से की जाती है उनको रोकने के लिये बिल के यह प्रोविज़न लाने ज़रूरी थे। इस बिल के जरिए अगर इवेज़न को रोक सकें और सरकार की आमदनी में अगर बढ़ौतरी हो जाए तो इस से हर एक को बहुत खुशी होगी। लेकिन मैं भी और मैम्बर साहिबान के साथ शामिल होता हुआ वज़ीर साहिब का खास ध्यान फिर इस तरह दिलाना चाहूंगा कि जहां उन्हों ने हाउस से यह बिल पास कराया है ताकि व्यापारियों की इवेज़न के लिये अकदामात किए हैं वहां वह अपनी सरकारी मशीनरी पर भी मुनासिब और कड़ी निगाह रखें। टैक्स की इवेज़न जैसा कि बार बार कहा गया अकेला व्यापारी नहीं कर सकता। जब तक सरकारी कर्मचारी उसका सांझीदार न बने इवेज़न नहीं हो सकती। वह सांझीदार बनता है तो इवेजन होती है और मेरा ख्याल है कि खुद वजीर साहिब भी इस बात से इन्कार नहीं करेंगे

[श्री मोहन लाल]

इस लिये वह अपनी मशीनरी पर भी कड़ी निगाह रखेंगे यह हमें उनसे आशा रखनी चाहिये। एक बात अब मुझे ज़रूर ज़िक्र करना है। मैं नहीं चाहता था कि मैं उसका तज़करा करूं लेकिन जहां पर बार बार कुछ मिनिस्टर साहिबान ने एक बात को दोहराया जिसका अभी 2 मित्तल साहिब ने भी ज़िक्र किया था कि यह बिल ऐन वही है जो पुरानी मिनिस्टरी ने 1962–63 में मन्जूर किया था। मैं समझ नहीं सका इस मन्तक को यह कौनसा रीज़न और सहारा है जो चंद वुज़रा ने लेने की कोशिश की है। एक बात का जवाब देने में शायद वह दिक्कत महसूस करेंगे कि जो बिल 1962 या 1963 में पुरानी मिनिस्टरी ने मन्जूर करने के बाद भी पेश करना मुनासिब नहीं समझा वह उन्हों ने खुद क्यों पेश किया। वह पुरानी वज़ारत जिसने यह कहते हैं 1962–63 में यह बिल पेश करना मन्जूर किया 1964 तक रही बजट सैशन उसी मिनिस्टरी के अहिद में गुज़रा था। अगर वह मिनस्टरी मुनासिब समझती तो 1964 के बजट सैशन में भी इस बिल को हाउस के सामने पेश कर सकती थी लेकिन उस मिनिस्टरी ने इस बिल को पेश नहीं किया क्योंकि उसने इसे मुनासिब नहीं समझा। आज यह भाई इस बिल को यह सहारा ले कर पेश करते हैं कि यह पुरानी मिनिस्टरी का मन्जूर शुदा है। मुझे इनकी यह मन्तक समझ में नहीं आई कि जो बात उन्हों ने मुनासिब नहीं समझी अब इनके लिये कैसे मुनासिब हो गई और सहारा फिर किस बात का? मैं समझ नहीं सका कि क्या यह बिल मिनिस्टर इन्चार्ज ने बगैर पढ़े और बगैर कबिनेट की मन्जूरी लिये ही पेश कर दिया। यकीन कबिनट ने दुबारा इस पर गौर किया होगा और फिर इस की मन्जूरी दी होगी। फिर बार बार यह कहना कि यह पुरानी मिनिस्टरी का बिल है मुझे यह सिवाए ओछापन के और कुछ मालूम नहीं होता। फिर यही नहीं उस वक्त के मिनिस्टर साहिब क कागज़ फाइल से निकाल निकाल कर इस सदन में पेश किए जाएं इस से ज्यादा गल्त बात कोई ज़िम्मेदार मिनिस्टर हाउस में नहीं कर सकता। यहां पर एक फाइल के नोट को दिखाया गया। वज़ीर बनने पर सीक्रेसी की ओथ ली जाती है। कैबिनेट के फैसले को यहां पर दिखाया नहीं जाता। उसको बहस में नहीं लाया जा सकता है।

बाबू बचन सिंह : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर। चेयरमैन साहिब, क्या कोई आनरेबल मैम्बर कैबिनेट के डिसीजन को यहां पर डिसक्लोज कर सकता है?

श्री मोहन लाल : मैं भी यही कह रहा था कि उन्हें ने गल्त बात की। मैं इस पर ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं लेकिन इतनी अर्ज जरूर करना चाहता हूं/कि कैबनिट के डिसीजन के सम्बन्धित नोट आदि कंफीडैंशल होते हैं। उन को यहां पर दिखाना नहीं चाहिए था। आज यह दोहराना कि यह बिल पुरानी मिनिस्टरी ने पास,किया था, उस मिनिस्टरी का बार बार नाम लेना मुनासिब और गैर वाजिब बात है। यह बात मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ सकी कि इस तरह की बातें, हउस में जिम्मेदार बैंचों पर बैठने वाले लोगों की तरफ से हो या यह कहा जाए कि उस वक्त के चीफ मिनिस्टर साहिब की वजह से डैमोक्रेसी का और मैम्बरों का गला घुटा हुआ था। और यह कहा जाए कि वह तो मैम्बरों को बोलने की इजाज़त नहीं देते थे। यह शोभा नहीं देता कि जिम्मेदार आदिमियों की तरफ से कहा जाए कि यह बिल पिछली मिनिस्टरी ने बनाया था। ऐसा कह कर भी बिल एडाप्ट करते हैं।

ज़रा इन से कोई पूछे कि अगर उस,मिनिस्टरी के वक्त ऐसी ही बात थी, उस वक्त जब्र होत थे तो इस सरकार ने उस मिनिस्टरी के बिल को उसी शक्ल में क्यों पेश कर दिया। मुझे बहुत अफ़सोस हुआ जब जिम्मेदार व्यक्तियों ने बिना किसी वजह से पुरानी मिनिस्टरी और पुराने चीफ मिनिस्टर साहिब को बहस में खींचा। इनके लिये ऐसी बातें करने के लिये कोई भी वजह जवाज़ नहीं थीं। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि यही लोग उस चीफ मिनिस्टर साहिब डिप्टी मिनिस्टरी, स्टेट मिनिस्टरी हासिल करने के लिये दिन रात दौड़ा करते थे। यह उस वक्त इस बात की खुशी और फख र महसूस करते थे कि उन्हें उस चीफ मिनिस्टर साहिब से कुछ देर के लिये बातें करने का मौका मिला। यहां पर अब उस चीफ मिनिस्टर साहिब के बारे में बातें करना, कहां तक वाजिब है। आज वह लोग बार बार पुराने चीफ मिनिस्टर साहिब का नाम लेते हैं जोकि आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है। उस के लिये कुछ तो ग्रेस होनी चाहिए। जिन हालात में वह इस दुनिया से गया, उन को मैं आज यहां पर दोहराना नहीं चाहता हूं। लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहता हूं कि उस के नाम को यहां पर बार, बार लेकर कोसा न जाए। वही लोग उस को कोस रहे हैं जो उस से डिप्टी मिनिस्टरी या स्टेट मिनिस्टरी के लिये यत्न किया करते थे। आज उस के बारे में ऐसी बात कर रहे हैं जो कि इन्हें नहीं करनी चाहिएं। मैं ने तो आज केवल प्रोसीजरल बातों का ज़िक्र किया। मैं ने किसी के विरूद्ध, ज़ाती बात नहीं की। लेकिन जिम्मेदार व्यक्तियों की तरफ से पिछली मिनिस्टरी का बार बार नाम लिया गया। इस से अफसोसनाक बात और क्या हो सकती है? मैं अर्ज़ कर रहा था कि मैंने किसी के बरखलाफ बात नहीं की। मैं ने तो प्रोसीजर की बात की। मैं ने किसी डैमोक्रेसी का हवाला नहीं दिया। इन्होंने ही खुद डैमोक्रेर्स की बातों का हवाला दिया। इन्होंने मेरे नाम को खामखाह बिला वजह बहिस मैं दाखिल किया। चेयरमैन साहिब, यह बहुत ही अफसोस की बात है। इन्हे गुस्सा किसी और पर था और वह गुस्सा किसी और पर निकाल दिया। मैं समझता हूं कि मेरे नाम को बहिस में,खाहमुखाह लाने की कोशिश की गई। यह बहुत ही अफसोस की बात है। मैं उन को नम्रतापूर्वक कहूंगा कि ऐसा करने से कोई अच्छी बात नहीं होगी। पिछले पुराने चीफ मिनिस्टर साहिब को सब जानते थे कि उस में क्या क्या खूबियां थीं। उन की खूबियां किसी से छुपी हुई नहीं थी। आज ही जस्टिस गुरनाम सिंह ने अपनी स्पीच में शेर के नाम से उसे पुकारा। उन्होंने कहा कि पहली सीट पर शेर बैठा हुआ था। मैं इस बात को ज्यादा तफसीस में जाकर कहना नहीं चाहता हूं लेकिन गुज़ारिश करूंगा कि उस में इतनी खूबियां थीं कि लोग आज उन को स्मर्ण कर कर के उस को रो रहे हैं। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि यहां पर पुराने चीफ मिनिस्टर साहिब का नाम ले ले कर इल्जामतराशी न करें। अब वह इस दुनियां में मौबजूद नहीं हैं। उस के लिये ग्रेस दिखानी चाहिये। मैं आशा रखता हूं कि वह पुराने चीफ मिनिस्टर साहिब के तई आयंदा के लिये ग्रेस दिखाएंगे। हां हम जिन्दा हैं। हम यहां पर बैठे हुए हैं। मुझे कोई अफसोस नहीं कि हमारा यहां पर नाम ले कर बात की जाए लेकिन स्वर्गीर प्रताप सिंह कैरों का नाम यहां पर बार 2 लेना किसी के लिये मुनासिब बात नहीं है। उन को ऐसी बातें बन्द करनी चाहियें। यह कहना कि यह बिल पुरानी मिनिस्टरी ने तैयार किया था और उस मिनिस्टरी को लोगो को इतनी हिकारत की निगाह से दिखाने की कोशिश करना है, यह

[श्री मोहन लाल]

वाजिव बात नहीं है। मैं फिनांस मिनिस्टर साहिब को दाद दूंगा जिन्होंने बड़ी पेशेंटली से, तहम्मल के साथ रिस्पौंसिव ढंग से इस बिल को पाल`ट किया है

(*Deputy Speaker in the Chair*)

डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। यह सरकार टैकसेशन मीयर्ज़ ला रही है। इस बिल के बाद भी एक आध बिल और आ रहा है। मैं सरकार को फिर कहूंगा कि जहां पर नए टैक्सों के जरिये और पिछले टैक्स को और बढ़ा कर टैक्सिज कुलैक्ट करना चाहते हैं; उस के साथ ही सरकार को बचत की तरफ ध्यान देना चाहिये। यहां पर किसी भी तरफ से जो कांस्ट्रक्टिव बातें की जाती हैं उन को संजीदगी से सोचना चाहिये उन पर प्रैजूडिसड मन से विचार नहीं करना चाहिये कि यह सजैशन फलां व्यक्ति की तरफ से आई है। इस में उस व्यक्ति का ज़रूर कोई मोटिव होगा। उस की बात न मानी जाए। मैं ने पहले एक बात कही थी कि एडमिनिस्ट्रेशन के खर्च में कमी करने की गुंजाइश है। आज कल टाप हैवी एडमिनिस्ट्रेशन है। यहां पर मेरी बात को कंट्राडिक्ट करने के लिये धूआधार स्पीच हुई। डिप्टी स्पीकर साहिबा, इसी विष्य पर 1 नवम्बर, 1965 को ट्रिब्यून अखबार में आई ए. ऐस. आफिसर्ज़ एसोसिएशन के कुछ मैम्बरों की तरफ से रिपोर्ट शाया हुई थी। यह बहुत ही ज़रूरी है। आप इस का मलाहज़ा फरमाएं। वह यह है कि ——

> "About a dozen I.A·S. Officers have initiated a move that the I.C.S· and I.A.S. Association should demand, in national interest, an immediate reduction in the top heavy administration ...."

लोक कार्य मन्त्री : उपाध्यक्षा महोदया, मेरा व्यवस्था प्रश्न यह है कि पंडित मोहन लाल जी जो कुछ पढ़ रहे हैं, उस का इस बिल के साथ कोई भी वास्ता नहीं है। मैं आप के द्वारा पंडित मोहन लाल जी को कहूंगा कि वह सिर्फ बिल पर ही बहिस करें।

श्री मोहन लाल : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं अपने साथी का बहुत मश्कूर हूं जिन्होंने मेरा ध्यान इस तरफ दिलाया है। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि जहां सरकार टैक्स इकटठा करने की कोशिश करती है, वहां पर उसे टाप हैवी एडमिनिस्ट्रेशन के ऐक्सपेंडीचर में भी बचत करनी चाहिये। उस में एक्पैंडीचर में रिडक्शन हो सकती है। मैं आपके आफिसर्ज़ की एसोसिएशन की राए बतला रहा हूं। This is relevant.

मैं आई. ए. एस. अफसरान की रिपोर्ट पढ़ रहा था। ....मैं टाप हैवी एडमिनिस्ट्रेशन का लफज़ पहले पढ़ चुका हूं। आगे उन्हों ने कहा ...

> "They feel that the Secretariat in particular has expanded in recent years beyond 'reasonable proportions' and have circulated the draft of a resoultion which the Association should adopt."

उन्होंने बाकायदा एक ड्राफ्ट रेज़ोल्यूशन बना कर अपनी एसोसिएशन में डिस्कशन के लिये भेजा है। अब आगे :

> "It seeks to recommend to the Government that as a first step, the number of posts in the Secretariat be reduced by one-third and that the process of reduction be completed in three months.
>
> In addition, it recommends the establishment of a Committee at the highest level to find out the scope of further reduction both in the Secretariat and in the field.
>
> For sucessful implementation of this recommendations, the draft resolution has also suggested several measures, including introduction of more economical and simpler ways of working in the Secretariat and delegation of more powers to the filed officers.

It has also suggested that the methods of disposal of work should be reveiwed so as to devise suitable devices for reduction of work-load in the Secretariat.

The staff rendered surplus in the Secretariat as a result of the acceptance of these recommendations should be usefully employed in the field, according to the resolution."

Madam, now I am coming to the important point in that report in the Press, which deserves your attention. It is—

"In support of this move, the initiators have pointed out that the number of Secretaries have increased from seven in 1948 to 17 in 1965 and that of Additional Joint, Deputy and Under Secretaries from 1, 1, 3 and 13 to 4, 5, 45 and 22 respectively."

आप एक मिसाल देख लीजिए कि डिप्टी सेक्रेटरीज़ की पोस्टस तीन के मुकाबले में आज 45 हैं। पहले तीन थीं लेकिन आज 45 हैं। फिर कहते हैं कि टाप हैवी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। हमें मानना चाहिये कि है। आगे देखिये :

"Similarly, during this period the number of Assistant Secretaries, Superintendents, Deputy Superintendents, Assistants and Clerks have gone up from 2, 29, 2, 102, and 167 to 13, 123, 56, 687 and 903 respectively."

(*Interruption*)

मैं क्लियर करता हूं। वे कहते हैं कि असिसटेंट सेक्रेटरीज़ की पोस्टस पहले दो थीं आज 13 हैं। इसी तरह से पहले सुप्रिंटेंडेंटस की पोस्टस थीं 29 और आज 123 हैं लास्ट देख लीजिये, क्लर्कस की पोस्टस पहले 167 थीं और आज उस के मुकाबिले में 903 हैं। कई गुना बढ़ौतरी हैं।

"The total staff in the Secretariat has increased from 320 in 1948 to 2,226 this year."

यानी 320 की जगह पर 2,226 पोस्टस हो गई हैं। मैं इस की जस्टीफिकेशन या नान-जस्टीफिकेशन में इस वक्त नहीं जाता। यह आप के सीनियर मोस्ट आई०ए०एस० और आई० सी० एस० आफिसर्ज़ की राए है। जब आप को वे यह राए दें तो इस का मतलब है There is a case for examination and implementation of their proposals इस लिये मैं फाईनेंस मिनिस्टर साहिब से दुहरा कर यह बात कहूंगा कि इस से सैंसटिव होने वाली कोई बात नहीं है। सीनियर आफिसर्ज की तरफ से मांग आई है। उस दिन मैंने टाप हैवी पोस्टस का भी हवाला दिया था। इस में जो उन की रिकुमेंडेशन्ज हैं उन पर संजीदगी से विचार करके जहां जहां पर रीडक्शन हो सकती हैं वहां पर करनी चाहिये ताकि खर्च बच सके। डिप्टी स्पीकर साहिबा आप का शुक्रिया।

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ (ਲੁਧਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਗੌਰਮਿੰਟ ਵਲੋਂ ਇਕ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਇਵੇਯਨ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਜਿੰਨਾ ਇਵੇਯਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਇਵੇਯਨ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਗਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਸਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਲਗੇਗਾ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨੇਬਲਿੰਗ ਕਲਾਜ਼ ਤਾਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਜਿਥੇ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝਣਗੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦੇਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ, ਨਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ

[ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ]
ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਿਥੇ ਟੈਕਸ ਲਗੇਗਾ। ਹੁਣ ਕੰਮ ਸੇ ਕੰਮ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਹ ਗਲ ਦਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗੇਗਾ। ਪੀਸ ਮੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਕਲਖਤ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲਗੇਗਾ

ਇਕ ਹੋਰ ਵਾਇਦਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਉਡੀਸ਼ੀਅਰੀ ਅਤੇ ਅਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਅਡ ਅਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ assessing authority ਹੋਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ appellate authority ਹੋਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨੇਬਲਿੰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ ਲਈ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮਿੰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਵੇਯਨ ਵਿਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ assessing authority ਹੋਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਐਪੀਲੇਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਹੋਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟੋਰੇਟ ਰਾਜ ਦਾ ਦੌਰ ਦੌਰਾ ਘਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਗਲਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ amendments ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪੰਡਤ ਮੋਹਣ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਹਕੀਕਤ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਈਲੈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਹੈਪਹੈਜ਼ਰਡ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ amendments ਮੰਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡੰਗ ਕੁਝ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਾ ਧਨ ਜਾਂਦਾ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਦਈਏ ਵੰਡ। ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਰ ਲੌ। ਮੈਂ ਇਸ ਰਾਏ ਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਹੋ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੁਹਰ ਵੀ ਲਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗਲ ਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗਲ ਬਾਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਉਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਗਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲ ਭਾਵੇਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏ ਲੇਕਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਵਿਊ ਔਰ ਵਿਉਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਊ ਕੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਘਟ ਤੋਂ ਘਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਗਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਉਪਾਰੀ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਜ਼ਿਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਟੈਕਸ ਘਟਾਇਆ ਜਾਏ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਜਾਏ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਉਤੇ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਐਪੀਲੇਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੁਐਂਟਮ ਦਾ ਨਹੀਂ

ਬਲਕਿ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦਾ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਡਿਫਰੈਂਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਖਤਰਾਤ ਮੁਲਕ ਉਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ—ਮੈਂ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਗਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਜ ਮੈਂ ਵਿਉਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਲ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਪਵੇ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦਸਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ—ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਚੀਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਕਜਹਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਨੋ-ਅਮਾਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ ਉਤਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਮੈਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਇਸਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬਾ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਨ 1947 ਦੀ ਸੱਟ ਪਈ ਔਰ ਹੁਣ ਫੇਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਸੱਟ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਉ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜਾਹ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਡਿਸਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਫੈਲੇ । ਇਹ ਬਿਲ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪਾਇਲਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਬਾਬਤ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਕਲ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ । ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਪਏ ਹੋਵੋ ਕਿ ਬਿਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਐਸੀ ਬਿਗਾੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਸ, ਜਿਤਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਥੋੜਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਵਿਉਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗਲ ਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਏ ਡਿਫਰੈਂਸਿਜ਼ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਰੋ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਐਸਾ ਅਮੈਂਡਿੰਗ ਬਿਲ ਲਿਆਓ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਏ, ਟੈਕਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸੂਲ ਹੋਣ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਘਟ ਤੋਂ ਘਟ ਹੋਵੇ । ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਉਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋਗੇ । ਇਕ ਗਲ ਹੋਰ ਕਹਿ ਕੇ, ਮੈਡਮ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ, ਮੈਂ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗਾ । ਮੈਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਤੁਸਾਂ ਇਥੇ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਹੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੌਂਸਿਲ ਵਿਚ ਵੀ ਵਖਾਉਣਾ । ਉਥੇ ਜਾਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤਾਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤਲਖੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ।

उपाध्यक्षा : पेशतर इसके कि मैं किसी और आनरेबल मैम्बर को काल आपान करूं मैं अर्ज करूंगी कि जैसा कि बाबु जी ने भी फरमाया कि मुक्के मार मार के इस को पास किया है, इस पर काफी बहस हो चुकी है । इस लिए इस पर टाईम लिमिट फिक्स कर लीजिए ताकि आज बिल को पास कर दिया जाए । मेरा ख्याल है कि पांच-पांच मिन्ट अब हर बोलने वाला मैम्बर ले । हाउस की क्या राए है ? (Before

[उपाध्यक्षा]

I call upon any other Member to speak, I would like to suggest that since according to Baboo Bachan Singh, the Bill has under gone a severe thrashing during its passage and has been thoroughly discussed, a time limit for speeches should be fixed so that it may be passed today. I think every member who wishes to participate, may speak for five minutes. What is the consensur us of the House?)

आवाजें : ठीक है ।

ਪੰਡਤ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਦੱਤ (ਅੰਬ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੇਰੀ ਬਿਉਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਕੋਈ ਗਹਿਰੀ ਸਟਡੀ ਨਹੀਂ; ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗਲ ਉਤੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਵਕਤ ਇਤਨੀ ਗ਼ਲਤੀ, ਕੋਤਾਹੀ ਔਰ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਗਫਲਤ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇਕ ਨਿਕੰਮਾ ਜਿਹਾ ਬਿਲ ਲੈ ਆਂਦਾ; ਫੇਰ ਇਹ ਕਈ ਦਿਨ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ । ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰੁਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਆਈਆਂ ਔਰ ਕਿਤਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਿਆ ਇਸ ਇਕ ਸਿਟਿੰਗ ਦਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਪਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ । ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ । ਮਸਲਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇਕ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਮਸਲਾ ਹੈ । ਕਿਤਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਥੇ ਇਕ ਮੋਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ: ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ ਔਰ ਅਜ ਤਕ ਇਸੇ ਬਿਲ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਚਲਦੀ ਰਹੀ । ਕਾਨੂੰਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਨਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਅਕਲ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ ਤਾਕਿ ਇਥੇ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਿਹੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ਉਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ । ਐਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਤੇ ਲਈ ਲੀਵ ਮੰਗੀ ਪਰ ਉਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ । ਪਰ ਅਜ ਇਕ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ । ਮੈਂ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਇਤਨੀ ਅਕਲ, ਇਤਨੀ ਹੋਸ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀ ਗਲ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋ ਔਰ ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਬਿਲ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਬਿਲ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ । ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵਿਉਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਫੇਰ ਚੁਪ ਬੈਠ ਗਏ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨਾ ਔਰ ਅਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ।

ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਕੇ ਤੁਸਾਂ ਇਹ ਬਿਲ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸਾ ਆਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ । ਹਨੇਰ ਗਰਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਜੇ । ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀਤਾ । ਪਰ ਇਕ ਗਲ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦ ਚੀਨ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਪਣੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਘਟਾ ਕੇ ਛੇ ਸਤ ਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ । ਹੁਣ ਵੀ ਚੀਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਬੜਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੌਜ ਘਟਾਉ ਅਤੇ ਘਟਾ ਕੇ ਉਤਨੀ ਹੀ ਕਰ ਦਿਉ ਜਿਤਨੀ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਡਿਪਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ । ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗਲ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ

ਸਾਡੇ ਅਖਤਿਆਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ । ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਹੋਰ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ, ਪਾਲੇਟਿਕਸ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਪਣੀਆਂ ਗੱਦੀਆਂ ਔਰ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿਚ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ । ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਡੀ ਵਡੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਦ ਅਖਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਫੌਜ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੌਜ ਉਹ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਖੇਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਫੌਜ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਨਾਉ । ਉਸ ਫੌਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰੋ । ਔਰ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀ ਪਾਲੇਟੀਸ਼ਿੰਜ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਘਟਾਉ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਖਰਚ ਕਰੋ ।

कामरेड राम चन्द्र (नूरपुर) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई है कि हमारे फाईनेंस मिनिस्टर साहिब ने जिस फराखदिली से मैम्बरान की तरफ से ग्राई हुई तरामीम को मन्जूर किया है, उसकी इधर से पंडित मोहन लाल जी ने ताईद ग्रौर तारीफ की है ग्रौर इधर ग्रापोजीशन से भी पंडित मोहन लाल जी ने तारीफ की है। मैं भी इस तारीफ में शामिल होना चाहता हूं ।

मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी वजारत ने बार बार व्यापारियों से बातचीत की ग्रौर उन की कई बातों के फैसले हुए। लेकिन व्यापारी लोग भी कई बातें भूल गए। मुझे खुशी है कि जो बातें ग्रपने मुफाद के मुताल्लिक भी वह भूल गए, वह नहीं सोच सके, मेरे दोस्त पंडित मोहन लाल ग्रौर कांग्रेस के दूसरे सदस्यों ने इस बिल के ग्रन्दर वह वह बातें भी ठीक करा दीं जो कि व्यापारी खुद भूल गए थे ग्रौर उन की राए में उन के हित में दुरुस्त थीं। इस से व्यापारियों को यकीन हो जाएगा कि हमारी वजारत तो उन का ख्याल करती ही है लेकिन मैम्बर व्यापारयों से भी ज्यादा उन के मफाद का ख्याल करते हैं।

इस बात में भी मैं पंडित मोहन लाल जी की ताईद करना चाहता हूं जो उन्होंने कहा कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन टाप हैवी है ग्रौर टैक्स लगाने की बजाय गवर्नमैंट को इस ऐडमिनिस्ट्रेशन को भी ठीक करना चाहिये। इस सम्बन्ध में ज्यादा न कहता हुग्रा मैं सिर्फ एक शेर ही पढ़ना चाहता हूं :

की मेरे कत्ल के बाद उसने जफ़ा से तौबा।
हाय, उस ज़ूद पशेमां का पशेमां होना ।।

लेकिन सुबह का भूला हुग्रा ग्रगर शाम को घर ग्रा जाए तो उस को भूला हुग्रा नहीं समझा जाता। पंडित जी ग्राठ साल मन्त्री—वित्त मंत्री भी रहे मगर उस समय उन्हें ध्यान न ग्राया कि स्टाफ कई गुणा बढ़ गया है। शुक्र है कि ग्रब उन्हें पता लग गया। इसलिये ग्रगर वह ग्रपने ज़माना में बहुता खर्च न रोक सके तो भी इन का इस तरह से ग्रब कहना ग्रौर सोचना मैं समझता हूं कि यह एक ग्रच्छी चीज़ है। इस लिये मैं इन की ताईद करते हुए ग्रपने वज़ीर साहिब से यह कहना चाहता हूं कि वह एडमिनिस्ट्रेशन के खर्च में कमी करें ताकि लोगों को सेटिस्फेक्शन हो कि यह गवर्नमैंट जो टैक्स लगा कर रुपया वसूल करती है वह ज़ाया नहीं होता। इस के साथ ही मैं उन का ध्यान इस बात की तरफ भी लाना चाहता हूं कि इस वक्त भी गवर्नमैंट के कई महकमों में बड़ी कुरप्शन की है ग्रौर यह इस को हटा नहीं सके। मिसाल के तौर पर पी० डब्लियू० डी० में बड़ी कुरप्शन है, इसी तरह से इरीगेशन के महकमा में बड़ी कुरप्शन है ग्रौर फूड एण्ड सप्लाइज के महकमा में बड़ी कुरप्शन है।

सरदार गुरनाम सिंह : ऐजुकेशन के महकमा में भी बड़ी कुरप्शन है।

कामरेड राम चन्द्र : मैं कहता हूं कि यह जो इतनी कुरप्शन हो रही है और इस तरह से लोगों पर जो ज़ुल्म होता है इस को दूर करना चाहिए। सरकार ने खुद माना है कि कुरप्शन हैं और यह पूरी तरह से इसे दूर नहीं कर सकी। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर कुरप्शन हो और गवर्नमैंट उसे दूर न कर सके तो वह अपनी नाअहलियत का सबूत देती है। जब हम ऐसी चीज़ देखें तो यह हमारा फर्ज़ हो जाता है कि हम इसे गवर्नमैंट के नोटिस में ले जाए। तो डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं इस गवर्नमैंट से आशा करता हूं कि यह इस कुरप्शन को दूर करने की कोशिश करेगी और इस तरह से खर्च में भी कमी कर के बचत करने की कोशिश करेगी ताकि इसे इस तरह और ऐडीशनल टैक्स न लगाने पड़ें। इस के लिये यह ज़रूरी है कि इस वक्त जो भी एडीशनल पोस्ट्स है यानी एडीशनल आई. जी., एडीशन्ल सेक्रेटरीज़ वगैरा २ इन पोस्ट्स को हटा देने की कोशिश करनी चाहिये। मैं तो यह चाहता हूं कि जितने भी अफसर कोई स्पैशल सेलेरीज़ ड्रा कर रहे हैं उन की वह ऐडीशन्ल पे बन्द हो जानी चाहिये और इन मौजूदा हालात में यह पट्राटिज़म का तकाजा भी यही है। ताकि अवाम की पीठ पर टैक्सों का और ज्यादा बोझ न पड़े।

कामरेड राम प्यारा (करनाल) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि जो अमेंडमेंट सरकार ने इस बिल में मंजूर की है मैं इस के लिये इस का शुक्रिया अदा करता हूं लेकिन इस के साथ एक बात यह भी कहता हूं कि इस ने इन के मंजूर करने में ग्रेस नहीं दिखाई और अगर यह ग्रेस दिखा कर इन को मंजूर कर लेती तो इस हाउस का बहुत सारा वक्त बच सकता था और साथ ही बहुत सारा रुपया जो खर्च हुआ है वह भी बच सकता था। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आयंदा के लिये सरकार इस बात की तरफ ध्यान देगी।

इस के अलावा मैं गवर्नमैंट को एक तजवीज़ देता हूं कि और मैं समझता हूं कि अगर इस पर ठीक तरह से अमल किया जाए तो बहुत हद तक इस महकमा से कुरप्शन भी दूर हो जाएगी और इस के साथ ही साथ लोगों को सहूलत भी हो जाएगी। मेरी तजवीज़ यह है कि जब भी कोई व्यापारी किसी सिलसिले में भी कोई दरखास्त दे तो उस को दर्ज करने के लिये एक्साईज एण्ड टैक्सेशन कमिश्नर के दफतर में एक रजिस्टर रखा हुआ होना चाहिये जिस में वह दर्ज हो जाए जिस से पता चल जाएगा कि उस व्योपारी ने इन टाईम अपनी दरखास्त दी है या इन टाईम नहीं दी। अब इस तरह का रजिस्टर मौजूद न होने की वजह से लोगों को बड़ी इनकनवीनियेंस होती है क्योंकि उन की दरखास्तें गुम हो जाती हैं। दरखास्त देते वक्त वह उन के डर से उस की रसीद तो मांग नहीं सकते। इस तरह से जो अनप्लेज़ेंटस और इकनवीनियेंस होती है वह दूर की जा सकती है।

इस के अलावा एक बात मैं चेक बरियर्ज़ के मुताल्लिक कहना चाहता हूं। गवर्नमैंट ने यह बात इस बिल में लाई है कि जो माल वहां पकड़ा जाएगा उस में से जितने माल पर टैक्स की इवेयन की गई होगी उस पर उस के मालिक को एक हज़ार रुपए तक जुरमाना किया जा सकेगा। इस बारे में मेरी अर्ज़ यह है कि अगर किसी केस में 10 या 15 रुपये की टैक्स इवेयन होगी और चाहे वह व्योपारी की गल्ती इरादतन से हो या सहवन हो जाए और उस पर अगर एक हज़ार जुरमाना लगाया जाए तो यह एक उस के साथ ज्यादती होगी और दूसरा इस से कुरप्शन को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि वह चाहेगा कि एक हज़ार जुरमाना देने की बजाए

वह क्यों न एक सौ या दो सौ रुपया रिश्वत में देकर अपनी जान छुड़वा ले। इस से उस के दिल में बड़ी रिज़ेंटमेंट होगी अगर उस को थोड़ी सी गल्ती की वजह से एक हज़ार जुरमाना कर दिया जाए। मैं यह नहीं चाहता कि कोई व्योपारी अगर बोनाफाईड मिस्टेक भी करे तो उस को एक हज़ार रुपया जुरमाना की सज़ा दी जाए। इस की बजाए जितने टैक्स की इवेयन उस गल्ती की वजह से होती है उस से डबल पेनेलटी ले ली जाए। गल्ती चाहे बोनाफाईड हो चाहे मैलाफाईडी हो इस के लिये अगर हम सज़ा एक हजार रुपया रखेंगे तो इस से सरकार को कोई फायदा नहीं होने वाला क्योंकि इस से तो डीलर जो होंगे वह बजाए इतना जुर्मना भरने के चाहेंगे कि कुछ रुपया अफसरों की जेब में डाल कर अपनी जान छुड़ाएं। इस से तो सिर्फ अफसरों के ही जेब भरेंगे। इस जुरमाने की बजाए अगर यह कर दिया जाए कि जितना माल पकड़ा जाएगा उस पर उस से दुगनी कीमत की पेनेल्टी होगी तो इस तरीके से कुछ न कुछ पैसा तो व गवर्नमैंट के घर जाएगा।

दूसरी बात इस बिल में सिक्योरिटी के बारे में कही गई है। मैं कहता हूं कि सिक्योरिटी ज़रूर लेनी चाहिये ताकि कोई लाईसेंसी टैक्स का रुपया ले कर भाग न जाए लेकिन इस के साथ मैं यह कहता हू कि सिक्योरिटी बजाए कैश में लेने के उसी तरीका से दूसरे एक दो डीलर्ज़ से ले ली जाए जो पुराने लाइसेंसी हैं और जिन का पिछला रिकार्ड अच्छा है, जैसा कि बैंकस में किया जाता है। इस तरह से अगर कोई टैक्स में गड़बड़ी करे तो जो डिफाल्टरज़ हों जहां उन को रगड़ा दिया जाए वहां सिक्योरिटी देने वालों को भी दिया जाए। जहां तक फेक्टरी वालों का ताल्लुक है उन की सारे पंजाब की एसोसिएशन है। उस ने ऐश्योरेंस दी है कि अगर ऐट फस्ट स्टेज ही टैक्स की वसूली कर ली जाए तो टैक्स में इवेयन के चांसिज़ कम हो जाएंगे। अगर गवर्नमैंट उन की यह बात मान जाए तो इस तरह से टैक्स की ज्यादा वसूली हो सकती है। इस के अलावा एक बात हैवी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कही गई है और इस बारे में साबिक होम मिनिस्टर साहिब की तरफ से एक सवाल भी उठाया गया था जिस में उन्होंने पूछा था कि 1947 से लेकर 1965 तक कितना अज़ाफा एडमिनिस्ट्रेशन में हुआ है। बेहतर होता अगर वह इस की बजाए यह पूछते कि 1947 से लेकर 1964 तक कितनी एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ी है और 1964 से लेकर 1965 तक के अरसा में कितनी बढ़ी है। तब तो इन की सही तसबीर हाउस के सामने आ सकती थी कि कितनी एडमिनिस्ट्रेशन उन के वक्त में बढ़ी है और कितनी मौजूदा गवर्नमैंट के वक्त में बढ़ी है। इस बात में कोई शक नहीं कि एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बढ़ गई है और इस में सरदार दिलजीत सिंह पिछले एक्साईज़ एण्ड टैक्सेशन कमिश्नर जैसे कुरप्ट अफसर भी मौजूद हैं जिन के बारे में हम इतनी आवाज़ जहां उठाते रहे है।

उपाध्यक्षा : यह मुनासिब बात नहीं कि आप किसी ऐसे आदमी का नाम लें जो यहां पर मौजूद न हो।

(It is improper to refer to a person who is not present here.)

कामरेड राम प्यारा : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं ने तो साबिका होम मिनिस्टर का ही कहा है और पंडित मोहन लाल का नाम नहीं लिया और फिर वह तो यहां पर मौजूद भी हैं।

उपाध्यक्षा : आप ने सरदार दलजीत सिंह का नाम लिया है वह यहां पर मौजूद नहीं हैं उन का नाम आप को नहीं लेना चाहिए था। (The hon. Member mentioned the name of Sardar Daljeet Singh. He is not present in the House. He should not have mentioned him by name.)

कामरेड राम प्यारा : इस के लिये मैं मुग्राफी मांगता हूं और आयंदा नहीं लूंगा। पंडित मोहन लाल ने अपनी तकरीर में एक फिकरा इस्तेमाल किया था कि जब दोनों सेक्रेटेरियेट थे यानी पुराना सेक्रेटेरियेट था और दूसरा नया क्रेटेरियेट था तो उस वक्त अगर हम नए सेक्रेटेरियेट में चले जाते थे तो वहां पर हम देखते थे कि बोर्ड लगे होते थे सेक्रेटेरीज़, एडीशनल सेक्रेटरीज़, डिप्टी सक्रेटरीज़ और असिस्टेंट सेक्रेटरीज़ और ज्वायंट सेक्रेटरीज़ के और अगर पुराने में चले जाते थे तो वहां पर डाइरेक्टर्ज़, ज्वायंट डाईरेक्टर्ज़, ऐडीशनल डायरक्टर्ज़ और डिप्टी डाइरैक्टर्ज़ के बोर्ड नज़र आते थे और यह सब तब था जब यह होम मिनिस्टर थे। खैर मैं इन की बात मानता हूं कि इस वक्त ऐडमिनिस्ट्रेशन बड़ी हैवी है। लेकिन वह अपने वक्त की बात को क्यों भूल जाते हैं। यह तो वही बात हुई जिस तरह से उस दिन सरदार कपूर सिंह ने कहा था कि वह जब चेयरमैन थे उस वक्त की बातें यहां इस कुर्सी पर आ कर भूल गए हैं इसी तरह से यह इधर इस कुर्सी पर आ कर अपने वक्त की बातें भूल गए है। मैं कहता हूं कि जो बुराई उस केबेनिट ने की है वह भी बुराई है और जो इस केबनिट ने की है वह भी बुराई है। गुना गुनाह ही होता है और जनता का और लेजिस्लेटर्ज़ का इस बात के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता कि वह गुनाह आया इस कैबिनेट ने किया है या कि पुरानी ने किया है। गुनाह जो है वह गुनाह ही रहे गा और उस की मुग्राफी नहीं मिलती।

इस के अलावा यहां पर इस बात का भी ज़िक्र आया है कि कुछ महकमों मे कुरप्शन है और सरदार गुरनाम सिंह नें कहा कि ऐजुकेशन के महकमें में खास तौर पर है। मैं कहता हूं कि यह सब महकमों में है और बहुत कुरप्शन ज्यादा है और जस्टिस गुरनाम सिंह कुरप्ट अफसरों को शील्ड करने वालों में से एक हैं और जहां उन को शील्ड करने के लिये खड़े हो जाते हैं। हम ने इस कुरप्शन का मुकाबिला मिल कर करना है।

चीफ पारलियामैंट्री सेक्रेटरी : डिप्टी स्पीकर साहिबा, वह जो मोशन मैं ने मूव की थी वह तो बिजनैस ऐडवाईजरी कमेटी के सामने नहीं थी, वह तो इस का ऐक्सैप्ट करने के बाद मुझे विदडरा करनी थी। चलो खैर।

SIXTH REPORT OF THE BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

Deputy Speaker ; I have to report the time table fixed by the Business Advisory Committee in regard to various business. The Sixth Report of the Committee reads—

The Committee after some discussion, recommended that—

(1) (i) the Motion regarding non-stop sitting moved by Chief Parliamentary Secretary, shall be withdrawn ; and

(ii) the Punjab General Sales Tax (Amendment) Bill, 1965, shall be disposed of on Wednesday, the 17th November, 1965.

(2) The Agenda already notified for Thursday the 18th and Friday the 19th November, 1965, shall remain unchanged.

(3) The House shall also meet on Monday, the 22nd and Tuesday, the 23rd November, 1965 to dispose of the Punjab Commercial Crops-Cess (Amendment) Bill, 1965, and if necessary, the sitting on Tuesday, the 23rd November, shall be extended by an hour or so.

Chief Parliamentary Secretary ; Sir, I beg to move—

That this House agrees with the recommendations contained in the sixth report of the Business Advisory Committee.

Deputy Speaker : Motion moved—

That this House agrees with the recommendations contained in the sixth report of the Business Advisory Committee.

(Interruptions by Pandit Bhagirath Lal and Shri Balramjii Das Tandon)

Deputy Speaker : Question is—

That this House agrees with the recommendations contained in the sixth report of the Business Advisory Committee.

(Noise in the House)

The motion was carried.

पंडित भागीरथ लाल: डिप्टी स्पीकर साहिबा, 23 तारीख को सूर्य ग्रहण है सारी दुनिया को छुट्टी है और लोग कुरुक्षेत्र जा रहे हैं . . .

उपाध्यक्षा : बार 2 फैसला तो नहीं बदला जा सकता। (विघ्न)। (The decision cannot be changed time and again.)

श्री बलरामजीदास टंडन : आन ए प्वायेंट आफ आर्डर, मैडम। आप ने यह रैजोल्यूशन इस तरह से पेश कर के एक दम ही अपने आप आयज़ और नोज़ कहकर के पास कर दिया है हमारी बात ही नहीं सुनी हम इस में अमेंडमेंट करने के लिये खड़े हैं . . .

उपाध्यक्षा : आज तक कभी इस रिपोर्ट में अमेंडमैंट नहीं हुई। (This report has not been amended before.)

श्री बलरामजीदास टंडन : तो क्या इसका मतलब यह है कि पेश की ही नहीं जा सकती? तब फिर यह हाउस के सामने भी क्यों आती है। हम आप का हुक्म मानेंगे मगर इस तरह से इसे रश थ्रू न करें। (विघ्न) हम आप के नोटिस में लाए हैं कि उस दिन सूर्य-ग्रहण की छुट्टी है, इस के लिये इस में हम अमैंडमेंट देना चाहते हैं, आप सुनते ही नहीं।

(विघ्न)

पंडित भागीरथ लाल : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडम। यह हमारे जज़बात की बात है। सारा हिन्दुस्तान तो उस दिन कुरुक्षेत्र इकट्ठा हो रहा है और हमारी बात तक नहीं सुनी जा रही (विघ्न) उस दिन सैशन नहीं होना चाहिए।

श्री बलरामजीदास टंडन : बिज़नैस ऐडवाइज़री कमेटी की रिपोर्ट में अमैंडमेंट हो सकती हैं, सैशन 24 और 25 को कर लें।

THE PUNJAB GENERAL SALES TAX (AMENDMENT) BILL, 1965 (RESUMPTION OF DISCUSSION) *(concld.)*

चौधरी नेत राम (हिसार सदर) : डिप्टी स्पीकर साहिबा इस बिकरी कर संशोधन बिल पर कहने से पहले मैं यह कहूंगा कि यह सरकार हर उस हरबे का इस्तेमाल कर रही है जिस से कि यह जनता को अपने कानून के डंडे से दबाकर अपनी हुकूमत को चला सके।

[चौधरी नेत राम]

डिप्टी स्पीकर साहिबा, कुछ मैम्बरान यहां पर खड़े हो कर कहते हैं कि पहली मिनिस्टरी ने गल्ती की और यह बिल रखा दूसरे सदस्य कहते हैं कि नई मिनिस्टरी ने गल्ती की और यह बिल लाई। इस बिल का कोई वारिस नहीं बन रहा है मगर मैं अर्ज करूं कि एक लाला जी थे वह मर गए तो उन के श्राध में एक पंडित के छोकरे को जीमा तो घर वालों ने सोचा कि यह तो ज्यादा खा गया तो अगली बार जब श्राध किया तो दूसरे लड़के को न्योता दिया तो पंडितयान ने कहा कि दोनों लड़कों में से किसी को ही न्योता दे दो दोनों ही होश्यार हैं। तो नुक्स इस नई या पुरानी मिनिस्टरी का नहीं यह तो कांग्रेस का ही है जिस की यह दोनों मिनिस्ट्रयां हैं। (हंसी): कांग्रेस की ही गल्त नीति चलती है चाहे यह राम किशन की मार्फित चले या कैरों की मार्फित, भीम सैन सच्चर की हो या गोपी चन्द भार्गव की। पिछले 17, 18 साल से कांग्रेस सरकार की दमन नीति चल रही है.....

उपाध्यक्षा: बिल पर बोलें। उन को छोड़ें। (The hon. Member may please leave him and speak on the Bill only).

चौधरी नेत राम: मैं तो मिसाल दे रहा था। इस सरकार की नीति है कि किसी तरह भी जनता को दबा कर हकूमत की जाए। लेकिन इन को पता नहीं कि वह दिन दूर नहीं जब जनता मस्त हाथी की तरह अंगड़ाई लेकर इन शेर के बच्चों को पांव तले रोंद डालेगी। सरकार ईमानदार होती तो इस तरह से बिल लाके यह दावे न करती कि इस से सेल्ज टैक्स की चोरी को रोकेंगें। टैक्स की चोरी से व्यापारियों को बाज़ रखेंगे। यह गल्त बात है, इस बिल से चोरी खत्म नहीं हो सकती (घंटी) सेल्ज टैक्स की चोरी तब रुक सकती है अगर यह उस वक्त ले लिया जावे जब कि कोई चीज़ जहां पर तैयार होती है, कारखाने से, फैक्टरी से या मिल में वहीं पर उस चीज़ का सेल्ज़ टैक्स वसूल कर लिया जावे। अगर इन की नियत साफ होती तो यह बार 2 तरमीमी बिल न लाते। ये तो तरीके हैं व्यापारियों से चन्दे वसूल करने के, वोटें लेने के। इस के सिवा इस बिल का और कोई किसी को फायदा न होगा। (घंटी) अभी तो तीन ही मिनट हुए हैं। यह सरकार ऐसी बातों से अपना रोज़ का खर्चा बढ़ा रही है और दूसरी तरफ जनता पा नए नए टैक्सों का बोझ लाद रही है जैसे कि कमरशल सैस का बिल आ रहा है जिस से किसानों पर नए बोझ लादे जाएंगे। इसलिये मैं इन से प्रार्थना करूंगा कि इन नीतियों का सुधार कर के, इमानदारी से काम कर के नए टैक्सों को न लगा कर के, पुराने टैकस में कमी कर के, जो अफसर रिश्वत लेते हैं उन को हटा कर के, गल्त महकमों को तोड़ कर के जनता को टैक्सों के बोझ से नजात दिलाई जाए और देश को खुशहाल बनाया जाए वरना इस किस्म से जनता को कोई फायदा न होगा।।

ਕਾਮਰਡ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ (ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ): ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ ਮੈਂ ਇਕ ਮਿਨਟ ਹੀ ਲਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਫਿਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ੍ਰੀ ਤਜਰੁਬੇ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਉਸ ਵਿਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਕਹੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੈਪਸੂ ਵਿਚ ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਆਪ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਥੇ ਹੁਣ ਅਜ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ

ਫਿਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਅਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਨਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਪੰਡਤ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਨੇ ਇਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਇਕਾਨੋਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟਾਪ ਹੈਵੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗਲਾਂ ਤਦ ਨਹੀਂ ਕਹੀਆਂ ਜਦ ਕਿ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਨ ਅਤੇ 34 ਮਨਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ । ਅਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਸਲਾ ਕਰ ਕੇ ਗਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਡਾ ਹਥ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਸਰਿਵਿਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗੇ ਸਬੰਧਤ ਇਸ਼ੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ । ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਯਕੇ ਬਾਦ ਦੀਗਹੇ ਪੋਸਟਾਂ ਵਧਾਈ ਗਏ । ਉਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਲੇਰੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਅਜ ਗਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਇਥੇ ਫਿਨਾਂਸ ਮਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਦਲੇਰੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤ ਦੀਆ ਤਰਮੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਨਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਇਹ ਕਮਰਸ਼ਲ ਕਰਾਪ ਸੱਸ ਦੇ ਬਿਲ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣਗੇ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਬਨਾਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਅਤੇ ਇਹ ਚੰਗੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਹ ਖਿਆਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਦਾ ਫਿਨਾਂਸ ਮਨਿਸਟਰ । ਇਹ ਅਜ ਦਾ ਫਿਨਾਂਸ ਮਨਿਸਟਰ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ 1942 ਵਿਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਫਿਰ ਇਹ ਫਿਨਾਂਸ ਮਨਿਸਟਰ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ 1948 ਵਿਚ ਜਦ ਇਹ ਬਿਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆਂ ਤਾਂ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕ ਪ੍ਰਿਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਆਫੀਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਜ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਵੇਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 1960 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਦ ਲੁਧਿਆਨੇ ਵਿਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਾਕਿਆਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਵਕਤ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ । ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਇਵੇਜ਼ਨ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ । ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਗਰੇਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਯਸ਼ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ । ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਵਕਤ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲ ਅਜਿਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਇਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ । ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮਾਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਨਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਸ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਇਮਪਲੀਮੈਂਨਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਇਵੇਜ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇ ਜਿਸ ਇਵੇਜ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਕ ਅਵਾਜ਼ ਹਨ । ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰੀਆਂ

[ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ]

ਦੀ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਵੇਜ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ । ਟੰਡਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀ 24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ । ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਫਰ ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ । ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ ਖੁਸ਼ੀ ਕਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ 24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ! ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਣ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋੜ ਨਾ ਪਏ । ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਘਾਪਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ।

उपाध्यक्षा : मैं उस हाउस की इस सिटिंग को दस मिन्ट के लिए एक्सटैंड कर रही हूं ।
(I am extending the sitting of the House for ten minutes).

Chief Parliamentary Secretary ; Madam, I seek the leave of the House to withdraw my motion for a non-stop sitting today.

Deputy Speaker : Has the hon. Chief Parliamentary Secretary leave of the House to withdraw his motion ?

Voices : Yes.

The motion was by leave withdrawn.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਆਨ ਏ ਪਵਾਇੰਟ ਆਫ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਮੈਡਮ । ਇਥੇ ਮੇਰੀ ਐਬਸੈਂਸ ਵਿਚ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਰੱਪਟ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਔਰ ਗ਼ਲਤ ਬਾਤ ਹੈ । ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਇਕ ਕਾਨਸਪਰੇਸੀ ਕਰ ਕੇ ਮੁਹਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਹ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਮੁਹਾਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਜਿਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂ ਤਾਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।

ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ : ਆਨ ਏ ਪੁਵਾਇੰਟ ਆਫ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ......(ਵਿਘਨ)

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਉ । (Please resume your seat.)

ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ : ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਦੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ?

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲ ਕਹਿ ਲਈ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਲ ਕਹਿ ਲਈ ਹੈ ਹੁਣ ਬੈਠ ਜਾਉ । (The hon. member has said something and Sardar Gurnam Singh has also said something. Now he sould resume his seat.)

ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨਸਿਨੂਏਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਮਯੂਨਲ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਫਸਰ ਕੁਰੱਪਟ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿਖ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਰਗੜਾ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਈ. ਜੀ. ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਹ ਅਫਸਰ ਕੁਰੱਪਟ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਇਹ ਗਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਇਸ ਗਲ ਲਈ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਕਰਰ ਕਰਵਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਚੈਲਿੰਜ ਨੂੰ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲੈਣ । ਮੈਂ ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ।

Deputy Speaker ; Question is—

That the Punjab General Sales Tax (Amendment) Bill, as amended, be passed.

After ascertaining the votes of the Members present by voices, Deputy Speaker said "I think the Ayes have it". This opinion was challenged. Bells were sounded. The motion was put again and carried by a voice vote.

The motion was declared carried.

1-31 p.m. **Deputy Speaker:** The House stands adjourned till 9.A.M. tomorrow

(*The Sabha then adjourned till* 9.00 *a.m. on Thursday, the* 18*th November,* 1965).
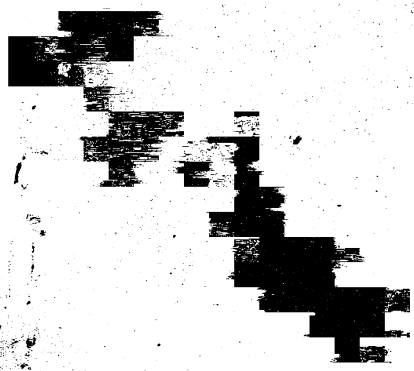
7243 PVS—384—28-5-66—C., P. and S. Pb., Chandigarh.

PUNJAB VIDHAN SABHA

DEBATES

18th November, 1965

Vol. II No. 22

CONTENTS

Thursday, the 18th November, 1965

Punjab Vidhan Sabha Secretariat Chandigarh

Price Rs 4.85

ERRATA

to

Punjab Vidhan Sabha Debates, Vol. II, No. 22, dated the 18th November, 1965

Read	*For*	*Page*	*Line*
Sardar	Sarda	(22)10	28
ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ	ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮ ਰ	(22)15	18
unduly	undully	(22)16	18
डा. बलदेव प्रकाश	डा. बलदेन प्रकाश	(22)30	1
ਸ੍ਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ	ਸ੍ਰੀ ਚੇਅਰਮਨ	(22)45	12
Member	ember	(22)49;53	17; 6
यह	पह	(22)50	30
this	his	(22)52	17
ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼	ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿਘ ਜੋਸ਼	(22)53 (22)82	4 from below 3 from below
ਸਰਾਸਰ	ਸਰਸਰ	(22)65	Last
चौधरी इन्द्र सिंह मलिक	चौधरी इद्र सिंह मलिक	(22)66	5 from below
Delete the word 'ਜੋ'	before the words 'ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ'	(22)68	16 from below
ਭਗਤ ਗੁਰਾਂ ਦਾਸ ਹੰਸ	ਭਗਤ ਗੁਰਾਂ ਦਾਂਸ ਹਸ	(22)70	1
ਪੰਜਾਬ	ਪਜਾਬ	(22)55 (22)78	11 6 from below
ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼	ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿਘ ਜੋਸ਼	(22)82	7
ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ	ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੈਜ ਸਿੰਘ	(22)84	3 from below
BROTHERS	BRNTHERS	(22)86	13 from below
ਰੀਪਲੇਸਮੈਂਟ	ਰਿਪਲੇਸਮਂਟ	(22)89	12

PUNJAB VIDHAN SABHA

Thursday, the 18th November, 1965

The Sabha met in the Vidhan Bhawan, Sector 1, Chandigarh, at 9.00 a.m. of the Clock. Deputy Speaker (Shrimati Shanno Devi) in the Chair.

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

*Supplementaries on Starred Question No. 8684**

श्री अमर सिंह: On a point of order, Madam. कल आपने एक पोस्टपोण्ड सवाल के बारे में चंद सप्लीमैंटरीज़ अलाऊ किये थे मगर यह आज क्यों पूछे नहीं जा रहे ? इस पर मैं आपका रूलिंग चाहता हूँ ।

उपाध्यक्षा : यह कल हो जायेंगे । (These will be asked tomorrow.)

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री: अगर आप चाहते हैं तो आज आप पूछ सकते हैं। मुझे तो कोई एतराज़ नहीं ।

Deputy Speaker : I allow supplementary questions.

ਸਰਦਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਧੌਲਾ: ਕੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀਜਨ ਕਲਿਆਨ-ਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸੀ ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री : वह सब पर था, प्रापर्टी वालों पर था और दूसरे लोगों पर भी था।

ਸਰਦਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਧੌਲਾ : ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸੀ।

मन्त्री: यह तो सभी पर था। किसी पर किसी शकल में, और किसी पर किसी और शकल में ।

---

*NOTE: Starred Question No. 8684 alongwith its reply appears in the P.V.S. debates Vol. II, No. 21, dated 17-11-1965.

ਸਰਦਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਧੌਲਾ : ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?

(*No reply was given*)

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀਜਨ ਕਲਿਆਨਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕੀ ਉਹ ਹਰੀਜਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ?

कल्याण तथा न्याय मन्त्री : इसके लिये सैपेरेट नोटिस दें तो बताया जा सकता है।

श्री फतेह चंद विज : क्या यह दरुस्त है कि हरिजन कल्याणकारी टैक्स इस ग़रज़ के लिये लगाया गया था कि यह पैसा 1967 की इलैक्शन के लिये खर्च किया जायेगा ?

उपाध्यक्षा : यह क्या सप्लीमेंटरी है, जरा सोच कर तो करें। (What a supplementary ? Please put it intelligently.)

श्री जगन्नाथ : क्या बज़ीर साहिब बतायेंगे कि जो कैरों साहिब ने टैक्सिज़ लगाये थे..............

उपाध्यक्षा : जो इनसान है नहीं आप उसका बार बार क्यों नाम लेते हैं। (Why does the hon. Member mention the name of a person who is no longer alive.)

श्री जगन्नाथ : आप रोज़ श्री राम चंद्र और कृष्ण जी का नाम लेते हैं क्या वह हैं ? मैं तो यह अर्ज़ कर रहा था कि स्वर्गीय सरदार प्रताप सिंह के वक्त यह टैक्स महज़ इस लिये लगाया गया था कि इससे लोगों को पक्के मकान बना कर दिये जायेंगे। आप मकान छोड़ कर कहते हैं कि उनको ज़मीन दी जायेगी मगर ज़मीन भी नहीं मिल रही। आखिर यह हरिजन के लिये किस परपज़ पर लगेगा ?

मन्त्री : यह कर हरिजनों की आर्थिक हालत को बेहतर बनाने पर सरफ किया जायेगा। इसमें उनके पक्के मकान और जमीन वगैरा सब आ गई हैं।

श्री अमर सिंह : इन लोगों की बेहतरी के लिये सरकार की तरफ से 2,03,00,000 रुपये देने का फैसला किया था, जिसके लिये एक सब कमेटी भी बनाई गई थी। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि जैसे टर्म्ज़ आफ रैफरेंस के अंदर हरिजनों को 2 करोड़ और 3 लाख रुपया देना था क्या वह खर्च होगा या अभी यह मामला सरकार के अंडर कंसिडरेशन है ?

मन्त्री : टर्म्ज़ आफ रैफरेंस का तो मुझे पता नहीं कि क्या मतलब हैं मगर जहां तक स्कीम्ज़ का ताल्लुक है यह करीब करीब बन गई हैं। सैंट्रल सरकार की इस सिलसिले में बात हो गई है। यह हरिजनों की बेहतरी पर ही खर्च होना है और यह रकम 2,03,00,000 रुपये नहीं है यह 1,95,00,000 रुपये है।

ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ : ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰੁਪਿਆ 20 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕੀ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੁਣ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ?

मन्त्री : मैंने एक काल अटैनशन मोशन के सिलसिले में यह जवाब साफ तौर पर detailed दे दिया था । आप की इत्तलाह के लिये फिर अर्ज़ कर दूं कि यह रुपया date of confirmation of the auction से एक साल बाद 20 किश्तों में वसूल किया जायेगा ।

ਕਾਮਰੇਡ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 52 ਲਖ ਦੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਤਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁਣ ਤਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ?

मन्त्री : इनके मुताल्लिक मैंने जब शेड्यूल्ड कास्ट्स के मुताल्लिक एक रिपोर्ट पेश हुई थी तो बड़े विस्तार से बताया था । ऐक्चुअल तो मैं बता नहीं सकता, जहां तक मेरा अपना विचार है यह कोई 3200 के करीब ऐसे हरिजन हैं जिनको जमीन दी गई है इसके इलावा नजूल ज़मीनें हैं। कुछ मुज़ारों के मसले हैं जो अपने आप कानूनी शकल ले रहे हैं।

ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1,95,00,000 रुपये ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਖਿਆ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਨਸਾਲੀਡੇਟਿਡ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਪੈਸੇ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 20 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ?

मन्त्री : पहले जो कर्ज़ा दिया गया उसकी शरायत और हैं, अब जो दिया गया है इसके लिये शरायत और हैं, दोनों को कैसे मिला सकते हैं ?

पंडित मोहन लाल दत्त : मैं यह बात मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि रूल्ज़ यह है कि हरिजनों के लिये 5 एकड़ ज़मीन खरीदी जाये और खास रेट पर खरीदी जाये, मगर अगर किसी इलाके में ज़मीन ही नहीं है तो क्या 5 एकड़ के रूल को नर्म किया जायेगा ?

मन्त्री : यह मामला इस सरकार अभी ज़ेरे गौर है क्योंकि जो अब सबसिडी दी जाती है इसमें 5 एकड़ ज़मीन खरीदी नहीं जा सकती ।

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 3,200 ਹਰੀਜਨਾਂ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਹਰੀਜਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ?

मन्त्री : कहीं निकासी ज़मीन के बारे में कोई ऐसी बात होगी । आफिस की खबर यही है कि सबको कब्ज़ा मिल चुका है।

श्री सत्य देव : जो पैसे ज़मीन खरीदने के लिये या मकान बनाने के लिये हरिजनों को देने थे लेकिन वह नहीं दिये जा सके तो क्या गवर्नमेंट अब देने के लिये तैयार है ?

मन्त्री : जो एक करोड़ पैंतीस लाख रुपये का लोन दिया गया है, उसमें यह भी अपेक्षित था कि हरिजनों को दिया जाता। अगर कहीं रह गया है तो उसका फायदा दिया जाएगा। इसकी वापसी पर गवर्नमेंट की यह कोशिश होगी।

श्री बनवारी लाल: हरिजनों को जो कर्ज़ा दिया जाता है और उस पर इंट्रेस्ट चार्ज किया जाता है क्या गवर्नमेंट इंट्रेस्ट को माफ करने के लिये कोई कदम उठा रही है ?

मन्त्री : यह तो जी फर्ज़ी सवाल है।

ਸਰਦਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਧੌਲਾ : ਕੀ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭੱਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ?

मन्त्री : मैंने तो यह कहा है कि यह प्रिज़म्पशन के तौर पर पूछा गया सवाल है। इसमें भद्दा कहां से आ गया ?

उपाध्यक्षा: अगर भद्दा कहा गया है तो वापस ले लो। (If the word "Bhadda" (absurd) has been used, then it may be withdrawn.)

डाक्टर बलदेव प्रकाश : क्या एक मिनिस्टर किसी आनरेबल मैंबर के सवाल को यह कह सकता है कि यह हाईपोथैटिकल है, फर्ज़ी है, भद्दा है, या बनावटी है ?

उपाध्यक्षा : नहीं कह सकता। (He cannot call it as such.)

GOVERNMENT COLLEGES WITH M.A., M.SC. AND B.SC. GEOLOGY CLASSES

*8809. **Chaudhri Hari Ram** : Will the Minister for Education be pleased to state :

(a) the number of Government Colleges that have M.A. M.Sc. and B. Sc., Geology classes in the State, district-wise, at present and the year in which these classes were started in each case;

(b) whether there are any such classes in the Government College, Dharamsala, if not the reasons therefor;

(c) whether the Government intend to start M.A., M. Sc., classes in the Government College, Dharamsala.

Chaudhri Ranbir Singh (Public Works Minister) :

A statement giving the requisite information has been laid on the Table of the House.

(a)

The District-wise details of colleges where M.A, and B. Sc., (Geology) classes exist are given below :—

District	Name of the College	Subject	Year of affiliation
Patiala	Mahendra College, Patiala	M.A. (Hindi)	1949
		M.A. (History	1955
		M.A. (Pol. Sc.)	1954
		M.A. (Philosophy)	1955

District	Name of the college	Subject	Year of affiliation
Rohtak	Government College, Rohtak	M.A. (Economics)	1962
		M.A. (Hindi)	1958
		M.A. (Pol. Sc.)	1958
Hoshiarpur	Government College, Hoshiarpur	M.A. (English)	1948
		M.A. (History)	1948
		M.A. (Economics)	1948
		M.A. (Pol. Sc.)	1948
		M.A. (Hindi)	1948
Ludhiana	Government College, Ludhiana	M.A. (English)	1948
		M.A.(Mathematics)	1948
		M.A. (Geography)	1948
		M.A. (Economics)	1955
		M.A. (Punjabi)	1951
		M.A. (Hindi)	1952
Ambala	Government College for Women Chandigarh	M.A. Music (Vocal and Instrumental)	1959
Kangra	Government College, Dharamsala	B. Sc.(Geology)	1953

There are no M.Sc. classes in any of the Government colleges in the State.

(b) No except B. Sc. Geology Classes. Due to tight financial position and the fact that Post-Graduate teaching should be concentrated in Universities.

(c) No.

(उपाध्यक्षा ने बख्शी प्रताप सिंह को चौधरी सुन्दर सिंह कह कर पुकारा)

श्री बलरामजी दास टंडन : यह तो जी बख्शी जी का बड़ा भारी अपमान है ?

ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਟੰਡਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ।

उपाध्यक्षा : टंडन साहब क्या फरमाया ?

ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਜੇ ਟੰਡਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ "ਫਰਮਾਉਣਾ" ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਥੋਂ ਤਕ ਠੀਕ ਹੈ ?

उपाध्यक्षा : बैठ जाओ । मुझे मालूम करने दो कि क्या कहा टंडन साहब ने। (The hon. Member may please take his seat. Let me find out what Shri Balramji Dass Tandon has said.)

श्री बलरामजी दास टंडन: बीबी जी, आपने बख्शी प्रताप सिंह को गलती से चौधरी सुन्दर सिंह कहा । मैं समझता हूँ कि बख्शी जी को चौधरी सुन्दर सिंह समझना माड़ी गल है । (*Interruption*)

बख्शी प्रताप सिंह: क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि धर्मशाला में इन ऐम. ए. क्लासिज़ को शुरू क्यों नहीं किया गया ?

लोक कार्य मन्त्री: जो सवाल इन्होंने पूछा है उसका जवाब जो उत्तर में मैंने पढ़ा है उसमें शामिल है। उपाध्यक्षा महोदया, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि 1964

[लोक कार्य मंत्री]

में डायरैक्ट्रेट ने गवर्नमेंट को लिखा था कि धर्मशाला के कालेज में 1965 में सिर्फ अंग्रेज़ी की एम.ए. क्लासिज शुरू की जाएं। उस पर जांच पड़ताल की गई। उस जांच पड़ताल के बाद पता लगा कि उसके लिये कोई गुंजाइश नहीं है।

श्री रूप सिंह फूल : क्या वज़ीर साहिब फरमायेंगे कि ज़िला कांगड़ा में इतनी देर से कालेज है और वहां की अवाम बहुत अरसा से गवर्नमेंट को कह रही है कि वहां एम.ए. की क्लासिज शुरू करनी चाहिएं इस पर क्यों गौर नहीं किया जा रहा ?

मन्त्री : मैंने अभी निवेदन किया कि दो कारणों की वजह से धर्मशाला कालेज में एम.ए. की क्लासिज शुरू नहीं की जा सकतीं। एक कारण तो यह है कि पैसा नहीं। दूसरे इस बात को भी देखा गया था कि आया वहां एम.ए. की कक्षा की आवश्यकता है भी या नहीं। जो जांच की गई उससे पता चला कि आवश्यकता नहीं है।

बख्शी प्रताप सिंह : वज़ीर साहिब ने अभी बताया है कि पैसे की कमी है। उनको पता है कि कांगड़ा में, पहाड़ी इलाका में एक ही कालेज है तो वहां सरकार की ओर से पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा ?

मन्त्री : मैंने दो तीन कारण बताये हैं पहाड़ी इलाके में लोगों की मांग के मुताबिक सरकार ने कुछ पैसा निकालने का इरादा किया था और इधर उधर से बचा कर देना चाहती थी सरकार ने वहां जांच की जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूँ। उस जांच के बाद यह पता चला कि वहां एम.ए. की कक्षा की आवश्यकता नहीं।

श्री रूप सिंह फूल : वज़ीर साहिब ने अभी फरमाया है कि वहां पर अंग्रेज़ी की एम.ए. की क्लासिज़ जारी करने में दिक्कत है तो क्या एक्नामिकस, हिस्टरी और दीगर मज़मूनों की एम.ए. क्लासिज़ जारी करेंगे ?

ਕਾਮਰੇਡ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਮੈਡਮ। ਕਲ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾ ਸੁਐਟਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਅਜ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਸੁਐਟਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ?

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। (Even all the Members of his party put together cannot convert me into a Communist.)

बख्शी प्रताप सिंह : मैं यह पूछना चाहता हूँ कि वज़ीर साहिब ने अभी बताया है कि वहां पर ऐसा कालेज नहीं है इसका क्या मतलब है ?

मन्त्री : अंग्रेज़ी के सिवाए जो दूसरे विषय हैं उनके बारे में जानकारी की गई है या नहीं, उस सिलसिले में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार का फैसला है कि एम.ए. के बाकी सबजैक्टस में जो कक्षाएं जारी की जाएं वह सिर्फ विश्वविद्यालयों

में की जाएं । जहां तक वहां पर इसकी ज़रूरत का तग्राल्लुक है वह उत्तर में पहले दे चुका हूँ।

ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਾਇੰਸ ਟੀਚਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਲਿਜ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ? ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲਾਸਿਜ਼ ਵਿਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਵਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ?

मन्त्री : यह सप्लीमेंटरी प्रश्न के जवाब से पैदा नहीं होता लेकिन मैं मानता हूँ कि वह मेरी मदद कर रहे हैं। वहां पर साइन्स की एम.ए. क्लासिज़ इसलिये नहीं खोली जा सकतीं क्योंकि साइंस पढ़ाने वालों की तादाद उतनी नहीं है जितनी ज़रूरत है इसलिये सरकार ने फैसला किया है कि विश्वविद्यालयों में ही एम.ए. की क्लासिज़ जारी की जाएं ।

ਕਾਮਰੇਡ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ : ਮੈਂ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਇਕ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚਾਰ ਕਾਲਿਜ ਹਨ। ਘਟ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਐਮ. ਏ. ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਜ਼ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਂਗੜਾ ਦੀ 10 ਲਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਕੀ ਉਥੇ ਐਮ. ਏ. ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਜ਼ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਪਛੜਾਪਨ ਜਾਰੀ ਰਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ?

मन्त्री : पटियाला, रोहतक, हुश्यारपुर, लुधियाना ग्रौर ग्रम्बाला में पांच जगह ऐसी हैं जहां एम.ए. की क्लासिज़ हैं। ये सरकारी कालिज हैं गैर सरकारी ग्रौर भी कालिज हो सकते हैं । धर्मशाला में जो कालेज है वहां एम.ए की कक्षा खोली जाए या न उस का उत्तर मैं पहले दे चुका हूँ।

उपाध्यक्षा : ग्रगर पांच जगह खोल सकते हैं तो कांगड़ा में भी खोलने की कोशिश करनी चाहिए (If the Government can open classes at five places, they may try to open it in some college in the Kangra District also.)

मन्त्री: उन्होंने यह भी पूछा है कि वहां क्लासिज़ कब जारी किये गये थे तो इस का उत्तर है कि वहां 1949, 1954 ग्रौर 1958 में क्लासिज़ शुरू की गईं । उस वक्त के हालात ग्रच्छे थे ग्रब वह हालात नहीं हैं।

बख्शी प्रताप सिंह: वज़ीर साहिब ने ग्रभी ग्रभी बताया है कि वहां एम.ए. की क्लासिज़ खोलने का स्कोप नहीं है क्योंकि स्टूडेन्ट्स कम हैं ग्रौर डिप्टी स्पीकर साहिबा ग्रापने मदद की है ग्रौर कहा है कि वहां पर यह क्लासिज़ खोली जानी चाहिएं। ग्रगर वह स्कोप पूरा हो जाए तो क्या सरकार इसको रीकन्सीडर करने के लिये तैयार है ?

मन्त्री : मैंने पहले ही निवेदन किया है कि शिक्षा विभाग ने इस बात की जानकारी की है कि ग्राया वहां पर गुंजाइश है या नहीं । इसकी जानकारी के बाद

[लोक कार्य मंत्री]

यह फैसला किया गया कि वहां पर आवश्यकता नहीं है। पैसे की भी कुछ कमी है और तीसरे यह फैसला भी है कि जो एम.ए. की क्लासिज़ हैं वह विश्वविद्यालयों में ही खोली जाएं।

श्री अमर सिंह : क्या आनरेबल मिनिस्टर साहिब यह बताने की कृपा करेंगे कि सारे पंजाब में सिर्फ धर्मशाला में ही बी.ऐस.सी. (जिग्रालोजी) की क्लासिज़ हैं तो वहां पर एम.ऐस.सी. (जिग्रालोजी) करने में क्या आपत्ति है जब वहां एक ही जगह बी.ऐस.सी. (जिग्रालोजी) की क्लासिज़ जारी हैं ?

मन्त्री : अगर उनके पास कोई और सूचना हो तो बताएं। उसको देख लिया जाएगा। जहां तक साइन्स की एम.एस.सी. की कक्षा को खोलने का ताल्लुक है उस बारे में फैसला है कि वह सिर्फ विश्वविद्यालय में ही खोली जाएं।

पंडित मोहन लाल दत्त: वजीर साहिब ने फरमाया है कि एम.ए. क्लासिज़ जारी करने में सरकार की कुछ मजबूरियां हैं। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि एम.ए. क्लासिज़ न सही, लेकिन ऊना सबडिवीज़न का इतना बड़ा पिछड़ा हुआ पहाड़ी अलाका है, उसमें बी.ए. की शिक्षा का भी कोई प्रबंध नहीं। क्या वहां डिग्री कालिज खोलने का सरकार कोई विचार रखती है।

मन्त्री: धर्मशाला पहाड़ी अलाका में ही है और वहां बी.ऐस.सी. की क्लासें चलती हैं।

UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS

SUPPLY OF QUOTA OF HIGH SPEED STEEL ETC. IN PATIALA AND SANGRUR DISTRICTS.

3051. Comrade Bhan Singh Bhaura : Will the Chief Minister be pleased to state the names of the firms in Patiala and Sangrur Districts, to which quota of the following material was allotted during the period from 1960 to 1965 alongwith the quantity allotted and the purpose for which it was allotted: (i) High speed steel, (ii) Graphite, (iii) Pig Iron, (iv) coal, (v) Zinc, (vi) Ball bearings, (vii) Copper, (viii) Rubber ?

Shri Ram Kishan : The time and labour involved in collecting the information will not be commensurate with the benefi t sought to be derive therefrom.

APPOINTMENT OF COMMITTEES TO RECOMMEND MINIMUM WAGES FOR WORKERS IN CERTAIN INDUSTRIES

3052. Comrade Bhan Singh Bhaura : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state —

(a) whether Government appointed during the years 1964 and 1965 any Committees to recommend the minimum wages

for the workers of the following industries Engineering, Public Transport, Iron and Steel Re-Rolling, Building and Construction, Flour and Dal Mills, Local Bodies; (b) if the reply to part (a) above be in the affirmative,the date when these Committees were appointed ?

Chaudhri Rizaq Ram : (a) The State Government appointed during the years 1964 and 1965 committees to hold enquiries and advise Government for fixing/revising minimum rates of wages in the employments of (i) Agricultural Implements, Machine Tools and General Engineering including Cycle and Electrical Goods Industry, (ii) Public Motor Transport and (iii) Ferrous Metal Rolling and Re-rolling Industry. The matter regarding appointment of Committees in the employments in (i) Rice,Flour and Dal Mills, (ii) local Bodies, and (iii) on the construction or maintenance of roads, or (a) in building operations; and (b) in stone breaking or stone crushing is under consideration of Government.

(b) The requisite information is given below :—

Sr. No.	Name of the employment	Date of Notification appointing the Committee
1.	Agricultural Implements, Machine Tools and General Engineering including Cycle and Electrical Goods Industry	6th August, 1964
2.	Public Motor Transport	12th March, 1965
3.	Ferrous Metal Rolling and Re-rolling Industries.	21st/24th April,1965

COMPLAINTS FROM THE UNIONS

3053. Comrade Bhan Singh Bhaura : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) Whether the Director of Industries and District Industries Officer, Patiala received any complaints from the unions in connection with the retrenchment of workers during the year, 1965;

(b) if the reply to part (a) above in the affirmative, the names of such unions, the contents of the complaints and the details of the action, if any, taken thereon?

Chaudhri Rizaq Ram : [Irrigation ond Power Minister] (a) Yes.

(b) A representation dated 26th August, 1965 was received from the General Secretary, Bhupindra Cement Karamchari Union, Surajpur by the Director of Industries, Punjab regarding retrenchment of workers consequent upon shifting of one kiln from Surajpur. The Management

[Irrigation and Power Minister]

of the said concern has, however, given an undertaking that they will try to absorb the surplus workers either at their works against permanent vacancies or in their other sister concerns. A telegraphic complaint was also, however, received from Mazdoor Union, Industrial Cables, Rajpura on 11th November, 1965 by the Labour Commissioner, Punjab regarding alleged non-payment of wages and illegal retrenchment of workmen by M/s Industrial Cables, Rajpura. The Management of this concern retrenched about 73 workers on different dates during the month of November, 1965. The Mazdoor Union has raised a regular industrial dispute in respect of retrenched workers through a demand notice, which is under investigation with the Conciliation Officer concerned.

EMBEZZLEMENT IN THE LANGUAGES DEPARTMENT

3054. **Comrade Bhan Singh Bhaura :** Will the Minister for Education be pleased to state whether any embezzlement took place in the Languages Department, during the year, 1960 to 1965, if so, the details thereof and the circumstances in which it took place ?

Shri Prabodh Chandra : Yes, one case of embezzlement took place in the Languages Department during June, 1964. The case was registered with the Police and Shri Hardyal Singh Cashier was named as an accused. The total amount found to have been embezzled has come to Rs 8750.41P. The case is subjudice.

ADJOURNMENT MOTION

उपाध्यक्षा : यह एक ऐडजर्नमेंट मोशन* सरदार जगजीत सिंह गोगोआनी और सरदार तेजा सिंह की तरफ से आई है । मैं इसे मन्जूर नहीं करती क्योंकि गवर्नमेंट के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने खुद अखबार मंगा कर देख लिया है और जो कुछ इस मोशन में तसवीर के बारे में ब्यान किया गया है वह चीज़ ठीक नहीं है।

(There is an adjournment motion given notice of by Sarda Jagjit Singh Gogoani and Sardar Teja Singh. I do not allow it because it has no connection with the Government. I have myself seen the newspaper and I find that whatever description of the picture given in the motion as printed in the paper is not correct.)

ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਗੋਆਣੀ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ । ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਚੈਂਬਰ ਵਿਚ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਵਿਖਾ ਦਿਉ । ਇਸ ਤੇ ਕਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । (The hon. Member may see me in my chamber and show me that picture. This matter would then be considered tomorrow.)

*Regarding two pictures of Guru Nanak Sahib......printed in the daily Hind Samachar, dated the 9th November, 1965......"

ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਗੋਆਣੀ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ । ਮੈਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਮੋਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ । ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਖਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਂਬਰ ਵਿਚ ਮਿਲ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਉ । ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਲ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ? (When I have said that the hon. Member may show me that picture in my chamber and if what he says is correct, the matter will be considered tomorrow, then what is the fun of raising a point of order ?)

ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਗੋਆਣੀ : ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਛਪੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ । ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਕਤ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੀ । ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੈਂਬਰ ਵਿਚ ਮਿਲ ਲਉ । ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵੈਸੀ ਗੱਲ ਹੋਈ । (I cannot be deceived by my own eyes. However, he may see me in my chamber. I cannot tolerate if there is anything derogatory against Guru Sahib.)

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ ?

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਹਾਂ । (Yes)

CALL ATTENTION NOTICES

(*Serial No, 162*)

Sardar Lakhi Singh Chaudhri: I beg to draw the attention of the Minister concerned to the fact that the Punjab Government have not appointed a Committee to revise the rates of burnt bricks in the State in spite of the assurance given to the deputation of brick kiln owners in April, 1965. The District Magistrate, Hoshiarpur, has, however, permitted the Beas Dam authorities to obtain bricks from the Departmental kilns at rate approved by the Beas Control Board which are very much high than those at which the other kiln-owners are required to sell. The kiln-owners are also required to restrict the depth of the pits for removal of earth to 3 feet in spite of the fact that the land belongs to the kiln-owner or the owner has no objection to excavate earth to any depth. The variation in rates in the same District , the unnecessary restriction on digging of pits and the failure of the Government to appoint the Committee to go into the structure of rates has hit the brick kiln industry and is creating unrest amongst the kiln-owners. The attention of the Minister concerned is, therefore, drawn to the above facts to remove the causes.

Deputy Speaker : This is admitted. Government will make a statement.

(*Serial No.* 163)

Comrade Makhan Singh Tarsikka : I beg to draw the attention of the Government to the recent occurrance i.e. I, through an adjournment motion

[Comrade Makhan Singh Tarsikka]

drew the attention of the Government to a serious situation of a law and order prevailing in the Karnal District in which I naratted the murder of five innocent persons in running bus near village Khai Ashrafali. Further I also pointed out that the assailants of that case are being helped by a local M.L.A. Though the motion was disallowed by the hon. Speaker, but I along with a member made pointed observations on the floor of the House, that life of an M.L.A. from Karnal is in danger. Then at this stage discussion was stopped.

Now on 12/13-11-65 night, house of Shri Rampal Singh, M.L.A. was attacked and brickbated by the party of those assailants. Fortunately the M.L. A. was not in his house and his servants received injuries. So far those assailants have not been traced out. This is causing great anxiety in Karnal city and in general public and among members of this House.

Therefore, Government should make thorough enquiry, trace out the assailants to restore the confidence in the public.

Deputy Speaker : This is admitted.

श्री जगन्नाथ : ग्रान ए प्वायंट ग्राफ ग्रार्डर । धमकी दी जाती है कंवर रामपाल सिंह को लेकिन मोशन लाते हैं उनके हक में कामरेड तरसिक्का । कितनी शर्म की बात है कि उनमें हिम्मत नहीं कि मोशन खुद लाते......(शोर)

Deputy Speaker : Please take your seat.

चौधरी इन्द्र सिंह मलिक : ग्रान ए प्वायंट ग्राफ ग्रार्डर । यह बड़ा ग्रहम मामला है । सड़क पर लारी रोक कर चार ग्रादमी मारे गए ....

उपाध्यक्षा : यह ऐडमिट हो गई है ग्रौर चीफ मिनिस्टर साहिब स्टेटमैंट करना चाहते हैं । (This has been admitted and the Chief Minister wants to make a statement.)

चौधरी इन्द्र सिंह मलिक : उनके मकान से टैलीफोन किया गया लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि हमारी जुरिसडिकशन में नहीं है ग्रौर सदर वाले कहते हैं हमारी जुरिसडिकशन में नहीं है ....

उपाध्यक्षा : वह कांग्रेस ग्रसैम्बली पार्टी के मैम्बर हैं। ग्राप ऐसी बातें करके उनकी मदद नहीं कर रहे । (He is a member of the Congress Assembly party. The hon. Member is not helping him by saying so.)

मुख्य मन्त्री (श्री राम किशन) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, हमारी इत्तलाह के मुताबिक वह alleged assailants गिरफ्तार किये जा चुके हैं। जहां तक कंवर रामपाल सिंह के मकान पर हमले का संबंध है, मेरे पास रिपोर्ट पहुंची थी ग्रौर उसके मुताबिक डी. ग्राई. जी ग्रम्बाला रेंज उसकी तहकीकात कर रहे हैं।

उपाध्यक्षा : ग्रगली काल ग्रटैनशन मोशन श्री बनवारी लाल के नाम पर है। (The next Call Attention motion is in the name of Shri Banwari Lal.)

(*Serial No.* 164)

Shri Banwari Lal : I beg to draw the attention of the Minister concerned towards the matter, namely, the shortage of kerosene oil and rice in Mohindergarh District particularly in Kanina Block. These two commodities are not easily available in Mohindergarh District. The people are facing great hardship on account of non-availability of kerosene oil and rice. The keroseneoil is being sold in black market at the rate of Rs. 1.25 per bottle while rice is available at Rs. 2/- per kilo which is causing great hardship to the people of the ilaqa. There is need of Government making necessary arrangements for the supply of these two commodities in adequate quantity in Mohindergarh District with a view to check the black market. It is, therefore, a matter of extremely urgent importance.

Deputy Speaker : This is admitted.

मुख्य मन्त्री (श्री राम किशन) : यहां दो बातें कैरोसीन आयल और चावल के संबंध में तवज्जुह दिलाई गई है । जैसा कि आप सब को मालूम है कैरोसीन आयल की इस वक्त कमी है लेकिन इसके बावजूद जो भी वहां तकलीफ है उसे दूर करने की कोशिश की जाएगी । चावल के बारे में अर्ज़ है कि अगर वहां फेयर प्राइस शाप नहीं तो खोलने के लिये तैयार हैं। अगर शाप पर चावल अवेलेबल नहीं तो वह भेजने के लिये तैयार हैं। इनकी हमारे पास कमी नहीं है ।

श्री बनवारी लाल: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडम। सरकार की तरफ से कहा गया कि मुहिन्द्रगढ़ ज़िले में कैरोसीन की कमी है मैं आपके द्वारा चीफ मिनिस्टर साहिब के नोटिस में लाना चाहता हूँ कि वहां पर ब्लेक में कैरोसीन मिल रहा है । सरकार ने इसकी रोक थाम के लिये कोई इन्तज़ाम नहीं किये ।——

Deputy Speaker : Please take your seat, I can not allow the hon. Member to say more on this issue.

(इस वक्त कामरेड मक्खन सिंह तरसिक्का अपनी काल एटेंशन मोशन नं0 165 पढ़ने के लिये खड़े हुए)

उपाध्यक्षा: आपकी यह काल एटेंशन मोशन क्लीयर नहीं है । आप मुझे चैंबर में मिल लें और इसके बारे में डिस्कस कर लें । (The Call Attention notice given of by the hon. Member is not clear. He may see me in my chamber and discuss it there.) Next i.e. number 166 please.

(*Serial No.* 166)

Comrade Makhan Singh Tarsikka : Madam, I beg to draw the attention of the Minister concerned towards the discontentment prevailed amongst Punjab Roadways employees, Amritsar, due to the illegal order of the General Manager, Amritsar, (Order No. 773/EA-Amritsar of 1965). Through which he has ordered to recover the amount of cash reward disbursed to different drivers, conductors, clerks, and helpers (total number 48 officials of Amritsar Roadways) etc. during the year 1962-63, as rewards to their extraordinary services done by them working day and night. Now due to personal vengeance he has ordered withdrawa

[Comrade Makhan Singh Tarsikka]

after three years. This is a great injustice. There is mucn discontentment, therefore, Government must do the needful.

Deputy Speaker : This is admitted. The Government will make the statement.

Serial No. 167

Comrade Makhan Singh Tarsikka : Madam, I beg to draw the attention of the Minister concerned towards discontentment prevailed amongst the people of Amritsar District, due to not taking any action on the report of Shri B.R. Chadha, Additional D.I.G., P.A.P. in which he has reported to the concerned authorities after proper detailed enquiry that one S.P. Border P.A.P. (Amritsar) has embezzled more than 60 thousand rupees while purchasing material for P.A.P. pickets etc. Due to this there is much discontentment amongst general public, therefore, Minister must make a statement.

Deputy Speaker: This is admitted. Government will make a Statement.

(*Serial No. 168*)

ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ : ਮੈਂ ਪੀ. ਡਬਲੀਊ. ਡੀ. ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਰਹੰਦ ਨਹਿਰ ਦੀ ਕੋਟਲਾ ਬਰਾਂਚ ਦੇ ਪੁਲ ਵਲ ਦੁਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਇਹ ਪੁਲ ਧੂਰੀ-ਸ਼ੇਰ ਪੁਰ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਲ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਹਿਕਮੇਂ ਦੇ ਰੀਕਾਰਡ ਵਿਚ ਨਾਕਸ ਪੁਲ ਵਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਪੁਲ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਬਸਾਂ ਤੇ ਟਰੱਕ ਆਦਿ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਲੋਹੇ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਪੁਲ ਤੇ ਰਖਕੇ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਧੂਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਚਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਪੁਲ ਤੋਂ ਦੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੁਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਭੀ ਵੇਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਬਧਤ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਪੁਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਲ ਸ਼ੀਘਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ।

(I beg to draw the attention of the Minister concerned to the bridge on the Kotla Branch of Sirhind Canal which is situated on the Dhuri-Sherpur road near village Jahangir. This bridge has been recorded as unserviceable in the record of the Department for the last four years. Every day buses and trucks etc. cross this bridge. Bus operators have placed several pieces of iron on the said bridge, to make the passage. Now Dhuri Sugar Mill is about to start functioning and the growers will have to carry sugarcane over this bridge. Therefore, it is necessary to pay attention to this bridge in order to avoid any loss of life. I hope the Minister concerned would consider the matter of constructing this bridge at an early date.)

Deputy Speaker : It is admitted.

लोक कार्य मन्त्री (चौधरी रणवीर सिंह) : उपाध्यक्षा महोदया, इस विषय पर मेरे पास जानकारी तो नहीं है। जो कुछ सूचना माननीय सदस्य ने दी है, अगर वह दरुस्त है तो जल्दी ही उस पुल को बनाने की कोशिश की जाएगी ।

Deputy Speaker : The Call Attention notice (No. 169) given by Shri Ajit Kumar is similar to Call Attention Motion No. 124. The reply of Call Attention Motion No. 124 has already been given by the Government. Therefore I disallow it.

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਾਲ ਅਟੈਨਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਆਪ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਮਸਾਊ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ.

उपाध्यक्षा: आप पहले अपने लफ्ज़ वापस लें क्योंकि अपने चेयर के बरखिलाफ लफ्ज़ कहे हैं। मैं अनपढ़ औरत नहीं हूँ। मैं सब कुछ पढ़ कर हाउस में आती हूँ। मैंने इनसान पढ़ाए हैं। (The hon. Member may first withdraw his words as these constitute a reflection on the Chair. I am not an uneducated woman. I come fully prepared in the House after peusing all the papers. I have been teaching people myself.)

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚੇਅਰ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।

Deputy Speaker : Kindly withdraw your words. I can not tolerate such insinuations.

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਅਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਫਗਵਾੜੇ ਦੀ ਮਿਊਂਸਪੈਲਿਟੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਥੇ ਸਵੀਪਰਜ਼ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਥੇ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ..

उपाध्यक्षा: आप मेरे चैम्बर में आए। आप को दोनों काल एटैंशन मोशन दिखा दी जायंगी। अगर इनमें कोई फर्क मालूम होगा तो आपकी मोशन एडमिट कर ली जाएगी। (The hon. Member may come to my chamber. He will be shown both the Call Attention notices. If any variation is found in them, then his motion will be admitted.)

STATEMENT LAID ON THE TABLE

Shri Ram Partap Garg (Chief Parliamentary Secretary) : Madam, I beg to lay on the Table of the House a Statement in reply to Call Attention Motion No. 120 regarding alleged imposition of restrictions on the sale of milk by Dhodis or any one else in the Punjab .

STATEMENT BY CAPTAIN RATTAN SINGH, MINISTER FOR ANIMAL HUSBANDRY AND AGRICULTURE IN REPLY TO CALL ATTENTION NOTICE (Sr. No. 120) BY COMRADE MAKHAN SINGH TARSIKKA.

It is not correct that the Government has imposed any restrictions on the *sale* of milk by *dhodis*, or any one else, in Punjab. But the use of milk for the production of cream, skimmed milk, casein, *Rubree*, *Khoa*, *Panir* and sweets of which milk or a milk product other than *ghee* may be an ingredient, and the sale of such products was banned in all districts of Punjab, except Lahaul and Spiti, under the D.I.R. Order issued on September 7, 1965.

2. The aforesaid ban was imposed to ensure that milk used for the production of these, the House will agree with me, non-essential products, was diverted for meeting the large demand from the Armed, Forces, which arose suddenly because of the national emergency. But for such action, I have no hesitation in saying , we could not have met the requirements of the Army and the price of milk too would have also spiralled up causing terrible suffering to the civil population. The expenditure of the Government, too, would have increased undully and unnecessarily because of that.

3. Before explaining the position in detail, let me, at the outset, assure Comrade Tarsikka and through you, Mr. Speaker, the House that there is no real basis for apprehensions mentioned in the Call-Attention Notice.

4. Like most other commodities, milk is sold both wholesale and reatail and, therefore, has two prices, namely, the wholesale and retail. While comparing prices, it is important to keep this point in view, for it would be fallacious to compare the wholesale price with the retail price. Shri Tarsikka seems to have erred in this regard.

5. Dhodis sell milk both wholesale and retail and, as would be expected, get a different price in each case. At the time the ban was imposed, the wholesale price milk ruling in most parts of the State was Rs. 24.25 per maund (Rs. 60-62.50 per quintal). Large quantities of milk were being bought by Government as well as by private buyers from private sellers at that price. It is, therefore, not correct to say that on or about September 7, *Dhodis* were getting Rs. 32 per maund for milk sold *wholesale*.

6. Moreover, the price of milk depends upon its quality. The price Rs. 24 per maund, is what the Government Milk Plants were paying for milk of basic quality, i.e., containing 6.2 per cent fat. Where the fat content is higher , the price is increased almost prorata. For instance, if the fat content is 7 per cent the price paid is Rs. 27.04 and for milk containing 7.5 and 8.0 percent it is increased to Rs. 28.94 and 30.84 respectively. The price which a *Dhodi* can get, therefore, depends upon the quality of milk he supplies and may actually be much higher than Rs. 24 per maund.

7. After imposing the ban, I was very anxious that it did not depress the producers' price. I had, therefore, asked the Deputy Commissioners to report to the Government if the price dropped below Rs. 24 per maund at any place, so that remedial action might be taken. The

House would be glad to know that the need for such action has not arisen anywhere.

8. The retail price was no doubt higher than Rs. 24 per maund at most places, when the ban was imposed. But that is not relevant to the point raised by Shri Tarsikka. Nor has the ban anything to do with milk sold retail for consumption as such or as products the production of which is not banned. The *Dhodis* are continuing to enjoy that market, as they did previously, and the retail price of milk has not slumped anywhere in the State. This would be clear from the following data comparing the average retail prices for September and October for 5 cities, derived from 'the Monthly Survey of Economic Conditions in Punjab published each month by the Economic and Statistical Organisation, Punjab :—

Average Retail Price of Milk (Per Kg.)

	Amritsar	Ludhiana	Jullundur	Ambala	Rohtak
September, 65	0.85	0.98	0.97	0.75	0.84
October, 65	0.83	1.00	0.90	0.75	0.87

9. The price of milk, wholesale or retail, has, thus, not changed much this year since the ban was imposed, despite the fact that, normally, at this time the price drops somewhat. This is because of the decision the Government has taken not to lower the price below Rs. 24 per maund for milk purchased by its milk plants. This has had, contrary to what Shri Tarsikka has given notice of, a great stablising effect on the milk market in the State.

10. It is also not correct that the Government Milk Plant at Verka is selling milk at Rs. 1.50 per quintal to the Army. In fact, no fresh milk has been, or is being, sold by that plant to the Army since the hostilities began. It has been manufacturing and supplying whole milk powder and diverting its surplus butter-fat to another (Privately owned) plant to enable the latter to step up its production of tinned milk for supply to the Army. But, it is understood, the army has a number of contracts with private suppliers according to which it has been buying fresh milk at prices ranging from Rs. 75—85 per quintal delivered at various stations in Punjab. The Army could not have paid almost double that price to the Verka Plant.

11. It is no doubt true that banning the production of cream and skimmed milk has affected the business of private creamery owners in the State. The Position in this regard was explained by me in detail while replying to the Vidhan Sabha Call Attention Notice by Shri Kulbir Singh.

PERSONAL EXPLANATION BY THE CHIEF MINISTER

मुख्य मन्त्री (श्री राम किशन) : ग्रान ए प्वायंट ग्राफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन, मैडम। डिप्टी स्पीकर साहिबा, कल जनरल सेल्ज़ टैक्स बिल पर डिस्कशन हो रही थी जब पंडित मोहन लाल ने जनरल सेल्ज़ टैक्स पर स्पीच की उस वक्त मैं हाउस में मौजूद नहीं था। उन्होंने कुछ मेरे ऊपर एटेक किया था। इसके बारे में ग्रखबारों में भी छपा है। ग्रखबार

में आया है कि जब तक सरदार प्रताप सिंह कैरों ने मुझे रिमूव नहीं किया था उस वक्त तक मैंने मिनिस्ट्री से अस्तीफा नहीं दिया । यह बात अखबारों में छपी, इसलिये उससे गलतफहमी होने का अन्देशा है। आपके जरिए हाउस को इस बात की अशोरेंस दिलाना चाहता हूँ और मुझे आशा है कि यह बात क्लीयर हो जाएगी । उन दिनों पंडित मोहन लाल सीनियर मिनिस्टर थे । शायद उन्हें इस बात का इल्म भी होगा कि जब 20-10-62 को देश में एमरजेंसी डिक्लेयर हुई तो मैंने 30-10-62 को कलकत्ता से अपना अस्तीफा सरदार प्रताप सिंह को भेज दिया । (ट्रेजरी बैंचों की तरफ से तालियां) उसके बाद सरदार प्रताप सिंह कैरों ने दिसम्बर के महीने में वजीरों से अस्तीफे मांगे थे । मैंने तो 30-10-62 को ही अपना अस्तीफा भेज दिया था । मैं नहीं कह सकता कि वह अस्तीफा रिकार्ड के अन्दर है या नहीं । मैं उन आदमियों में नहीं था कि जब तक उन्हें अस्तीफा देने को नहीं कहा गया उस वक्त तक अस्तीफा नहीं दिया । (श्री जगन्नाथ द्वारा विघ्न)

डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं एक और अर्ज़ करना चाहता हूँ। इन्होंने यह भी कहा कि मैं 1956 में सरदार प्रताप सिंह कैरों के पीछे डिप्टी मिनिस्टरी के लिये फिरता रहा । मैं इस बात की ज़ोर से वजाहत कर देना चाहता हूँ कि और शायद बहुत से मैम्बरों को इस बात का इल्म भी नहीं होगा कि 1956 के शुरू के अन्दर 3 और 4 महीने तक मेरे और सरदार प्रताप सिंह के सम्बन्ध अच्छे नहीं थे । हम दोनों स्पीकिंग टर्म्ज़ पर भी नहीं थे । अप्रैल, 1956 के शुरू में सैकंड फाइव इयर प्लान का पब्लिसिटी हफता मनाना था। उस वक्त मुझे सरदार प्रताप सिंह कैरों का मैसिज डिप्टी कमिश्नर, जालन्धर के द्वारा आया कि वह मुझे किसी काम के लिये मिलना चाहते हैं; वह जालन्धर में सैकंड प्लैन का पब्लिसिटी हफ्ता मनाने के लिये आए । मैं वहां पर सरदार प्रतापसिंह कैरों को मिला। मैंने पूछा कि सरदार साहिब, बताएं कि मुझे किस काम के लिये बुलाया है । उस वक्त सरदार प्रताप सिंह कैरों ने कहा कि आप चंडीगढ़ आएं वहां पर बात करेंगे । मुझे इस बात के लिये कहा गया । मास्टर गुरबन्ता सिंह और प्रोफैसर यशवन्त राए भी हमारे साथ थे, हम सब कार में बैठ गए। रास्ते में सरदार प्रतापसिंह कैरों ने मुझे कहा कि मैं आपको कैबिनिट में डिप्टी मिनिस्टर लेना चाहता हूँ। मैंने इनकार कर दिया । जब चन्डीगढ़ पहुंचे तो उन्होंने फिर मुझे वही बात कही लेकिन मैंने फिर इन्कार कर दिया । उस समय उस वक्त के कैबनिट के मैम्बरान भी मौजूद थे, रात को हवन के समय फिर उन्होंने वही बात कही और मैम्बरान ने भी ज़ोर दिया । तब मैं ने अपनी रज़ामन्दी ज़ाहर की और कहा कि अच्छा मैं आना चाहता हूँ। इस तरह से मैं कैबनिट के अन्दर आया । मुझे खुशी है कि जब मैं सन् 1956 में कैबनिट के अन्दर काम किया तो सरदार प्रतापसिंह ने कभी मेरे काम में किसी तरह की इन्टरफियरेंस नहीं की........(तालियां)

एक आवाज़ : यह बात मानी जाने वाली तो नहीं है ।

मुख्य मन्त्री: मैं 1956 की बात कर रहा हूँ। डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह भी कहा गया कि मैंने सरदार प्रताप सिंह पर किसी प्रकार के हमले किये हैं। मेरे दिल में जितनी इज्जत सरदार प्रताप सिंह की है उतनी किसी और मैम्बर के दिल में नहीं होगी (तालियां) मैं हमेशा उनकी सफात का कायल रहा हूँ और आगे के लिये भी रहूँगा। जो उनमें बुरी बात थी उसकी मैंने हमेशा ही मुखालिफत की है, आगे भी करूंगा और कभी उनको अपनाने के लिये तैयार नहीं हूँगा। उनमें जो सफात थीं उनका हमेशा ही जिक्र करता रहा हूँ और आगे भी करूंगा, यहां भी और बाहर भी। मैं आपके द्वारा मैम्बर साहिब से कहूँगा कि इस तरह की गलत बातें करना मुनासिब नहीं है कि अगर मेरी खुददारी को भी चैलेंज किया जाए तो भी मैं स्टिक करता रहूँगा। मैं आपके द्वारा यह बात कह देना चाहता हूँ कि मैं उसी वक्त तक हाउस का लीडर हूँ जब तक हाउस की मैजारिटी मेरे साथ है। हम खुददारी और इज्जत के साथ इस जिम्मेदारी को निभाना चाहते हैं, इज्जत के साथ निभाएंगे। हम खुददारी के साथ पंजाब की सेवा करना चाहते हैं (तालियां) जो रवायात मैंने पब्लिक लाईफ में democracy की खुददारी और इज्जत के साथ सेवा करने की सीखी हैं उन पर पूरी तरह से अमल करता रहूँगा खाह मुझे कितनी भी कीमत अदा करनी पड़े।

DISCUSSION OF MOTIONS

(i) RE-ELEVENTH ANNUAL REPORTAND ACCOUNTS OF THE PUNJAB FINANCIAL CORPORATION FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 1964, AND

(ii) FIRST ANNUAL REPORT AND ACCOUNTS OF THE PUNJAB EXPORT CORPORATION LIMITED FOR THE YEAR 1963-64.

उपाध्यक्षा एजेंडे पर दो आईटम्ज़ हैं। दोनों के लिये दो घंटे टाईम फिक्स किया गया है। यह दोनों आईटम्ज़ इकट्ठी ही डिस्कस कर ली जाएं। (There are two items on the Agenda and time fixed for both is two hours. Both the items may be discussed together.)

श्री **बलरामजी दास टंडन** : डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह दो अलग अलग चीज़ें हैं आपसे दरखास्त है कि दोनों की डिस्कशन अलग अलग होनी चाहिए।

उपाध्यक्षा: यह बात पहले तै हो चुकी है। इन दोनों के लिये दो घंटे समय डीसाईड हो चुका है। इससे ज्यादा समय नहीं मिल सकता। अगर हाउस इस को अलग-अलग डिस्कस करना चाहता है तो अलग अलग कर लिया जाए। हाउस की क्या राय है? (This matter has already been decided and a period of two hours has been fixed for the discussion of both the motions. No more time can be allocated for this. But if the House wants to hold seperate discussion on them, then this may be done. What is consensus in the House.)

आवाजें: इकट्ठा ही कर लो जी।

उपाध्यक्षा: दोनों आईटिम्ज़ इकट्ठी डिस्कस की जायेंगी। अगर मुनासिब हो तो टाइम लिमिट मुकर्रर कर ली जाए वरना चेयर के लिये बड़ी मुश्किल हो जाती है।
(Both the items will be discussed together. If there is no objection, some time limit for speeches may be fixed, otherwise it becomes very difficult for the chair to satisfy the Members.)

Shri Balramji Dass Tandon (Amritsar City West) : Madam, I beg to move—

> That the Eleventh Annual Report and Accounts of the Punjab Financial Corporation for the year ended the 31st March, 1964, laid on the table of the House on the 15th September, 1964, be discussed.

Deputy Speaker : The honourable Member should move his next motion also.

Shri Balramji Das Tandon : Madam, I also beg to move—

> That the First Annual Report and Accounts of the Punjab Export Corporation Limited for the year 1963-64, laid on the Table of ths House on the 25th February, 1965, be discussed.

डिप्टी स्पीकर साहिबा, जहां इस तक रिपोर्ट का ताल्लुक है यह काफी देर पहले इस हाउस के अन्दर पेश की गई थी लेकिन इस की कंसिड्रेशन काफी देर से पोस्टपोन होती चली आई। अब भी काफी तग्गोदो और काफी कहने सुनने के बाद यह रिपोर्ट इस बार हाउस में डिस्कशन के लिये आई है। अगर फाईनैंशल कार्पोरेशन की रिपोर्ट को गौर से देखा जाय और साथ ही साथ इसकी जो आखिरी बारहवीं रिपोर्ट छपी है और सरकुलेट हुई है उसको भी देखा जाए तो ऐसा महसूस होता है कि इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले कुछ समय से कार्पोरेशन ने अपने काम में तरक्की की है और कुछ मुनासिब इकदामात लिये हैं। इसमें भी कोई शक नहीं है कि 1951 में जो फाईनैंशल कार्पोरेशन ऐक्ट बना था और जिस पर अमल दरामद होते आज 14 साल के लगभग हो गए हैं, और जिस ऐक्ट के मातहत तकरीबन तमाम सूबों में फाईनैंशल कार्पोरेशन बनी थीं, उनमें जहां पर पंजाब फाईनैंशल कार्पोरेशन का ताल्लुक है उसने अपना एक नुमायां स्थान बना लिया है। इसका पेड अप कैपिटल भी अच्छा है। इसने काफी अमाउंट तक लोन्ज़ भी सैंक्शन किये हैं। इसकी डिस्बर्समेंट भी काफी हद तक तसल्ली बख्श कही जा सकती है। लेकिन जब हम इसकी वर्किंग को देखते हैं, इसके काम के तौर तरीके को देखते हैं तो हमें यह कहना पड़ेगा कि जिस आशय को लेकर और जिस भावना को लेकर फाईनैंशल कार्पोरेशन को खड़ा करने की स्कीम सैंट्रल गवर्नमेंट के एक ऐक्ट के ज़रिये चालू की थी उस आशय को प्राप्त करने की उचित कोशिश नहीं की गई। कई एक काम इस कार्पोरेशन के जिम्मे लगाये गए थे जिनमें से एक काम यह था कि लोन्ज़ और एडवांसिज देने हैं। और भी तीन चार काम इसके जिम्मे थे। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जहां तक इस कार्पोरेशन का ताल्लुक है उसने केवल एक ही काम उनमें से किया है और बाकी कामों की तरफ उसने ध्यान नहीं दिया। इसकी कई एक वजूहात हो सकती हैं

लेकिन बाकी किसी काम को जो कि पंजाब गवर्नमेंट को न करके इस कार्पोरेशन को करने चाहिए थे, इसने नहीं किये । वे काम थे, अंडर राईटिंग का काम, गारंटीइंग आफ बांड्ज़, वर्किंग आफ लोन्ज़ और गारंटीइंग आफ डेफर्ड पेमेंट का काम था । यह सब काम जो इसके जिम्मे इस एक्ट के ज़रिये लगाए गए थे, चार काम इसने करने थे । लेकिन सिरफ एक ही काम वह कर पाई है और उस सारे का भी जो वर्किंग है अगर उसको देखा जाए तो यह कहना पड़ेगा कि यह काम मुनासिब ढंग से कराने की सरकार ने कोशिश नहीं की है । जिस तरह से फाईनैंसिज़ कारपोरेशन की डिस्पोज़ल के ऊपर होने चाहिए थे वह फाइनैंसिज़ उसकी डिस्पोज़ल के ऊपर नहीं दिये जिसका नतीजा यह हुआ है कि वह काम जो कि कारपोरेशन को करना चाहिए था जैसे ऐल. आई. सी. है उससे कोई म्युनिसिपल कमेटी, ज़िला परिषद् या दूसरे सरकारी या नीम सरकारी अदारे उससे एडवांस या लोन्ज़ वगैरह लेते हैं तो उसकी गारंटी देने का काम कारपोरेशन के ज़िम्मे लगाया गया था लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि सरकार को जो उसे सहायता देनी चाहिए थी, म्युनिसिपल कमेटियों ज़िला परिषदों, इम्प्रूवमेंट ट्रस्टस और ऐसे जो सैमी गवर्नमेंट अदारे हैं उनके लिए ज़रूर सरकार को चाहिए था कि कारपोरेशन के लिये खुला रखती कारपोरेशन उनकी सहायता के लिये काम करती लेकिन सरकार ने उसकी डिस्पोज़ल पर न तो इतने साधन दिये, न पैसा दिया और न ऐसे ढंग पैदा किए । जिसका नतीजा यह निकला कि इस काम को कारपोरेशन मुनासिब तरीके के साथ निभा नहीं सकी और वह काम हो नहीं पाया। इसके कारण हुआ क्या ? इसके साथ जो सीधा सवाल जुड़ता है वह है कारपोरेशन की वर्किंग का कि किस ढंग से उसका वर्किंग रहा । डिप्टी स्पीकर साहिबा, मुझे बड़े अफसोस के साथ यह बात कहनी पड़ती है कि जहां तक कारपोरेशन की वर्किंग का ताल्लुक है, जहां तक कारपोरेशन के काम करने का ताल्लुक है, इसका बहुत बड़ा पहलू पंजाब को इंडस्ट्रियलाईज़ करना है और वह इसमें बुरी तरह से फेल हुई है । इसके अन्दर देहली की एडमिनिस्ट्रेशन भी आत है, हिमाचल प्रदेश की एडमिनिस्टट्रेशन भी आती है । मैं इस वक्त उनकी तरफ, डिप्टी स्पीकर साहिबा, कोई ज्यादा ध्यान आपका नहीं दिलाना चाहता लेकिन जहां तक पंजाब की वर्किंग का ताल्लुक है उसकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। जो काम एक छोटे स्केल के ऊपर पंजाब का इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट करता है, छोटे लोन्ज़ देने का काम वह करता है जिसकी लिमिट पहले 25,000 रुपये थी उसी लोन्ज़ की बावत ज्यादा बड़े पैमाने पर जो काम है वह यह फाईनैंशल कारपोरेशन करता है । जिस मकसद के लिये ये लोन्ज़ देने का काम पंजाब गवर्नमेंट अपने इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट से कराती है उसी काम को बड़े पहलू पर करने की ज़िम्मेवारी फाइनैंशल कारपोरेशन की है। लेकिन जब हम देखते हैं तो दुख इस बात का होता है कि जिस कदर कम्बरसम प्रोसीजर इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट ने लोन्ज़ देने का रखा हुआ है उससे भी ज्यादा कम्बरसम प्रोसीजर कारपोरेशन ने रखा हुआ है । डिप्टी स्पीकर साहिबा, अगर किसी व्यक्ति ने किसी काम के लिये लोन लेना है, अगर किसी इन्डस्ट्री ने अपने तरक्की के लिये ज़राय बनाने हैं तो यह एक मानी हुई बात है कि हर एक इन्डस्ट्री हर वक्त तरक्की नहीं कर सकती, किसी भी इण्डस्ट्री के लिये तरक्की करने का मौका किसी खास वक्त पर, खास समय

[श्री बलरामजी दास टंडन]
पर आता है। उसके लिये उसको रनिंग कैपीटल की ज़रूरत होती है, मशीनरी की आवश्यकता होती है या दूसरी चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो ऐसे समय में उसे फंड्ज़ दरकार होते हैं। लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी इन्डस्ट्रियल यूनिट ने पंजाब के इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट से कोई लोन लेना है, इस फाइनेंशल कारपोरेशन से लोन लेना है तो डिप्टी स्पीकर साहिबा, इसके लिये इतना कम्बरसम प्रोसीज़र है कि जिसे कोई व्यक्ति देख कर हैरान हो जाता है। उसके लिये उसे पूरा करना ही कठिन है, एक समस्या है। पूरा कर पाना तो अलग बात है अगर वह उसे पूरा करने का सामर्थ्य भी रखता हो तो भी कई महीने उसके लिये लग जाते हैं, उसे पूरा करने के रास्ते में कई मुश्किलात, कई अड़चनें, कई प्रकार के संकट आते हैं। उसके लिये जहां पर डिपार्टमेंट के साथ ताल्लुक रहता है वहां कारपोरेशन के आदमियों के साथ भी वास्ता पड़ता है और मुझे यह बात बड़े अफसोस के साथ कहनी पड़ती है कि कारपोरेशन के आदमी कोई एबव ससपिशन होकर अपना कान्डक्ट शो करने की कोशिश नहीं करते इतना ही नहीं कुछ और बातें हैं जोकि गौर तलब हैं।

सब से बड़ी अहम बात यह है कि कारपोरेशन ने लोन्ज़ एडवांस करने के लिये 9 प्रतिशत इन्ट्रैस्ट रखा हुआ है। अब सवाल यह पैदा होता है कि जहां तक लोन्ज़ लेने का सम्बन्ध है अगर इन दोनों महकमों का यानी इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट और फाईनैंशल कारपोरेशन का आधार इंडस्ट्री को तरक्की देना है तो सोचना पड़ेगा कि बैंक जो काम कमरशियल बेसिज़ पर करता है, जिसका आऊटलुक कमरशियल है, उसके अन्दर और इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट तथा कारपोरेशन की वर्किंग के अन्दर लोन्ज़ की एडवांसमेंट के काम में फर्क क्या है ? जब हम इस बात पर विचार करते हैं तो डिप्टी स्पीकर साहिबा, मुझे यह बात बड़े अफसोस के साथ कहनी पड़ती है कि हर एक बैंक भी 9 परसेंट पर लोन एडवांस करती है और यह कारपोरेशन भी 9 परसेंट पर एडवांस करती है तो मैं नहीं समझता कि यह कोई मुनासिब तरीका है कि यहां पर प्रोसीजर को इस कदर कम्बरसम बनाया जाए। पंजाब की सरकार यहां पर अपने प्रान्त के अन्दर इन्डस्ट्रीज़ को तरक्की देने के लिये कौनसा बड़ा काम कर रही है ? मैं यह बात समझने से कासिर हूँ। महकमे तो बड़े बड़े बना रखे हैं....कई डिप्टी डाइरैक्टर, कई असिस्टेंट डाइरैक्टर और हर ज़िले के अन्दर इन्स्पैक्टरज़ और दूसरे कर्मचारियों का इतना बड़ा नैटवर्क फैला रखा है, इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन सवाल इस बात का है कि जहां तक इन्डस्ट्री को तरक्की देने का प्रश्न है उसके अन्दर गवर्नमेंट और सरकार के अदारे, जिनका नैटवर्क सारे पंजाब में छाया हुआ है, किस तरह से काम करते हैं अगर कोई व्यक्ति उसको देखने की कोशिश करे तो महसूस होता है कि सिवाय किसी छोटे मोटे काम के लिये इंडस्ट्री की तरक्की के लिये इनडायरैक्ट काम किया हो, अगर कोई व्यक्ति इस डिपार्टमेंट के लोगों के पास किसी प्रकार की गाईडैंस के लिये चला जाये तो उसको गाईडैंस नाम की भी नहीं मिलती। लोगों को इधर उधर भागना पड़ता है, वह लोगों को किसी तरह से समझाते नहीं। डिपार्टमेंट को तो इस कदर फैला कर रखा हुआ है जिसका स्टेट के फाईनैंसिज़ के ऊपर बड़ा भारी असर पड़ता

है लेकिन इससे किसी व्यक्ति को किसी इंडस्ट्रियल यूनिट को टोटली कोई गाईडैंस नहीं मिलती, इसमें किसी किस्म का कोई मुगालता नहीं रखा जा सकता कि किसी को इनडायरैक्टली भी कोई टैक्निकल जानकारी प्राप्त हो सकती हो । यह बात भी नहीं । कोई और फायदा लोगों को हो सकता हो, यह भी बात नहीं । डिप्टी स्पीकर साहिबा, एक ही इनडायरैक्ट तरीका इंडस्ट्री को तरक्की देने का जो है वह लोन्ज़ है। उसके लिये छोटे पैमाने पर महकमा काम करता था जिसको अब इस कारपोरेशन के द्वारा करना चाहिए था। इनको चाहिए था कि लोगों को टैक्निकल गाईडैंस देने के लिये कोई तरीका बताया जाता, अगर लोग इसके लिये कोई रास्ता ढूंढते हैं तो उनके रास्ते की रुकावटें दूर की जानी चाहिए थीं । लेकिन जैसा कि मैंने निवेदन किया, लोन्ज़ देने के लिये भी एक बड़ा काम्पलीकेटिड प्रोसीजर बनाया हुआ है जिसे अबूर करने के लिये लोगों को कई एक मुश्किलात से दो चार होना पड़ता है । उसकी तस्वीर नंगी तस्वीर है जिसे खुला रखा हुआ है और उसकी कारकरदगी पर एक आदमी को शर्म आती है । इसलिये मैं कहूँगा कि सरकार को इसके अन्दर बड़ी गौर करके, गम्भीरता के साथ विचार करके इस ढंग को तब्दील करने की ज़रूरत है । जितना कम्बरसम प्रोसीजर डिपार्टमेंट ने रखा हुआ है उतना ही बल्कि उससे भी ज्यादा कम्बरसम प्रोसीजर कारपोरेशन का है । इसे आसान बनाने की ज़रूरत है । ठीक है कि बार्डर डिस्ट्रिक्टस के लिये आपने उसे आसान बना दिया है । यह बहुत बड़ी सहूलियत है लेकिन सवाल यह है कि जब गवर्नमेंट ने लोन देने की फैसिलिटीज देनी है तो उसे उसके लिये एश्योरैंस चाहिए । गवर्नमेंट को तो यह देखना चाहिए कि उसके लिये जो सिक्योरिटी मिलती है वह कितनी सेफ है, कितनी डिपैंडेबल है । लेकिन, डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस मकसद के लिये जो फार्म बना हुआ है उसे पढ़ने की कोशिश की जाए—चाहे वह डिपार्टमेंट का है और चाहे कारपोरेशन का है—तो ऐसा लगता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सेल्ज़ टैक्स और दूसरे महकमों वाले जितनी जानकारी एक आदमी से अलग अलग तौर पर प्राप्त करते हैं उस सारी की सारी जानकारी से भी ज्यादा बातें इसमें बतानी होती हैं। शायद इनकम टैक्स और सेल्ज़ टैक्स वाले भी उन बातों को नहीं जानना चाहते जिनकी बाबत यहां पर पूछताछ की गई होती है। इसमें पूछा गया है कि फलां साल के अन्दर कितना कोयला लिया, फलां साल के अन्दर फलां चीज़ कितनी मांगी गई थी । वे सभी बातें एक आदमी को उस फार्म में दर्ज करनी पड़ती हैं जब उसने लोन के लिये एप्लीकेशन देनी हो। चाहिए तो यह था कि कारपोरेशन पंजाब के अन्दर इंडस्ट्री को तरक्की देने के लिये रास्ते आसान करती लेकिन हैरानी होती है कि आखिर किस लिये इस कदर कम्बरसम प्रोसीजर बनाया हुआ है ? यह बात तो समझ में आती है कि जब लोन लेना हो तो जो सिक्योरिटी दी जा रही हो, यह देखा जाए कि वह डिपैंडेबल है, सेफर है या नहीं । आपकी अपनी है तो और बात है और अगर किसी दूसरे आदमी ने वह सिक्योरिटी दी है तो उसकी वाकफियत पूरी तरह से लें, पूछताछ करें । यह बात तो किसी हद तक समझ में आ सकती है लेकिन पूछा यह जाता है कि आपकी प्राफिट एंड लास की क्या पोज़ीशन है, पिछले साल कितना मुनाफा हुआ, कितना नुकसान हुआ और इसी तरह से और कई फज़ूल सी बातों के चक्कर में

[श्री बलरामजी दास टंडन]

डाला जाता है । इतना बड़ा पैराफरनेलिया जानकारी प्राप्त करने के लिये रख छोड़ा हुआ है कि बजाय काम को खत्म करने के जिस मकसद के लिये लोन मांगा जा रहा है उसे जल्दी से पूरा करने के, उसके रास्ते में तरह तरह की रुकावटें डाली जाती हैं, अड़चनें पैदा की जाती हैं, जिनका कोई मतलब ही नहीं होता। इसका नतीजा यह होता है कि कई व्यक्तियों को छैः छैः महीने और बाज़ दफा तो नौ नौ महीने अपनी एप्लीकेशन्ज़ दिए हो जाते हैं और उनको लोन ही नहीं मिलता। इसके लिये मैं यह चाहूंगा कि इस कारपोरेशन के अन्दर जो भी लोन के लिये दरखास्त आए उस पर जिस दिन वह आए वह डेट दे दी जाए और जिस दिन उस पर लोन मंजूर हो वह डेट भी दी जाए ताकि इससे यह पता चल सके कि एप्लीकेशन देने वाले को कितनी देर बाद लोन मिला है और इसमें जो रास्ते में अड़चनें पड़ती हैं उनके बारे में पता चल सकेगा ।

इसके साथ ही साथ मैं अर्ज़ करनी चाहता हूँ कि इसमें लोन्ज़ पर जो 9 परसेंट के हिसाब से इनट्रेस्ट चार्ज किया जाता है वह हाइएस्ट रेट आफ इनट्रेस्ट है। इस रेट पर तो बैंकों से भी इण्डस्ट्रिलिस्टस को लोन मिल सकता है । इस कारपोरेशन के सामने यह ख्याल होना चाहिए कि इसने इण्डस्ट्रीज़ को इस प्रान्त में प्रमोशन देनी है और इसी ख्याल से इसे कम रेट आफ इनट्रेस्ट पर लोगों को लोन देने चाहिएं । इस कारपोरेशन ने पिछले साल तो 15 लाख का प्राफिट दिखाया है और उसमें से इसने साढ़े तीन लाख रिज़र्व में रख दिया और फिर साढ़े तीन लाख इसको इनकम टैक्स देना पड़ा। इस तरह से बाकी थोड़ा सा रुपया बचा है जो आज तक डिवीडेंड्ज़ में नहीं बांटा गया । डिप्टी स्पीकर साहिबा, ज़रा आप ही सोचिए कि करोड़ों रुपये की इनवैस्टमेंट करने पर भी इतनी थोड़ी रकम शेयर होल्डरज़ को देने के लिये बची है । इस कारपोरेशन को बने 14 साल हो गये हैं और यह बात देख कर पंजाब के हर शहरी का सर अफसोस के साथ झुक जाता है कि इस कारपोरेशन ने आज तक एक पैसा भी किसी शेयर होल्डर को डिवीडेंड के तौर पर नहीं दिया । इसके लिये प्राइवेट शेयरज़ वाले लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं । इसके लिये कानून भी ऐसा बना हुआ है कि उसमें यह ज़रूरी कर दिया हुआ है कि पहले पंजाब गवर्नमेंट ईक्वल रेट पर श्योरेंटीज़ जमा कराये । इस तरह से तो यह 25 साल बाद जाकर डिवीडेंड निकाल सकेंगे और यह भी कब निकलता है? देखने की बात तो यह है कि अगर कोई आदमी किसी बैंक में ही अपना रुपया जमा कराता है तो उसे सेविंग्ज़ एकाऊंट में साढ़े चार परसेंट सूद मिल जाता है और फिक्सड डिपाज़िट पर तो साढ़े पांच परसेंट से लेकर 7 परसेंट तक मिल जाता है लेकिन जिन लोगों ने इस कारपोरेशन के शेयर्ज खरीदे हुए हैं उनको आज 14 साल गुज़र जाने पर भी एक पैसा डिवीडेंड की शक्ल में नहीं मिल सका । इसकी वजह से यह हालत हो गई है कि अब इस कारपोरेशन के शेयर खरीदने वाला ही नहीं है। फिर आप देखें कि बाज़ार में प्राइवेट शेयरज़ तो लेने वाला कोई नहीं है और जब दिल्ली को शेयर देने थे तो गवर्नमेंट

ने अपने शेयर्ज़ में से उसे दिये थे और जब हिमाचल को देने का सवाल पैदा हुआ तब भी गवर्नमेंट ने अपने शेयरज़ में से ही दिये और प्राइवेट लोगों के शेयरज़ नहीं देने दिये हालांकि वह इसके लिये चीखते चिल्लाते रहे और मैं समझता हूँ कि यह इस का निहायत गलत और अत्यंत गिरा हुआ तरीका है। हालांकि चाहिए तो यह था कि यह लोगों में इसके लिये कानफीडेंस क्रीएट किया जाता और इस के लिये लोगों को बताया जाता कि इस कारपोरेशन के शेयर बड़े सेफ हैं क्योंकि इस कारपोरेशन की पीछे गवर्नमेंट के रिसोरसिज़ हैं और इनका कोई खतरा नहीं है लेकिन अगर इस बारे में इस गवर्नमेंट की सारी कारकरदगी देखें तो कोई भी नहीं कह सकता कि यह शेयर अच्छे हैं जबकि इन शेयर्ज़ पर साढ़े तीन प्रसेंट डिवीडेंड निकलने की आश है और जब इसके मुकाबिला में बैंक्स में इंवेस्टमेंट ज्यादा सेफ है और वहां पर सेविंग्ज़ एकाऊंट में साढ़े चार परसेंट इनट्रेस्ट मिल सकता है और फिक्सड में तो पांच से सात परसेंट तक मिल सकता है और बैंक्स में से जब भी चाहें अपना रुपया निकलवा लें और इस कारपोरेशन के शेयर्ज़ की यह हालत है कि इसके शेयर बाजार में लेने वाला नहीं। इसलिये मैं अर्ज़ करता हूँ कि इस बारे में ऐक्ट में मुनासिब तब्दीली करने की ज़रूरत है और पंजाब गवर्नमेंट को चाहिए कि वह इसको अच्छी तरह से देख कर जहां ज़रूरी समझे तब्दीली करने के लिये सैंट्रल गवर्नमेंट को लिखे और रिकमेण्ड करे कि वह इस ऐक्ट में एमेण्डमेंट ले आए। यह ऐक्ट 1952 का बना हुआ ऐक्ट है। वैसे भी हालात के बदल जाने से इसके अन्दर तब्दीली की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि इसी तरह की जो कारपोरेशन्ज़ दूसरी स्टेट्स में भी बनी हुई हैं क्योंकि उन सब के लिये ऐक्ट एक ही है। पंजाब गवर्नमेंट इसमें तब्दीली लाने के लिये उन स्टेट्स को भी कह सकती है कि वह भी इसी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्रोच करें।

उपाध्यक्षा : आप 17 मिनट बोल चुके हैं। और कितना समय आप लेना चाहेंगे ? (The hon. Member has spoken for seventeen minutes. How long more will he take to complete his speech ?)

श्री **बलरामजी दास टंडन** : मैं कोई 13 या 14 मिनटों में खत्म कर दूंगा।

उपाध्यक्षा: अगर आप इतना वक्त ले लेंगे तो इसका मतलब यह हुआ कि बाकी के मैम्बरों के लिये बहुत थोड़ा वक्त बचेगा। आप जल्दी खत्म कर दें। (If he will take so much time, then this means that much less time will be left for the Members intending to participate in the discussion. He may please immediatly wind up.)

श्री **बलरामजी दास टंडन**: मैं जल्दी खत्म करने की कोशिश करूँगा। तो डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं पंजाब गवर्नमेंट से मुअदबाना गुज़ारिश करनी चाहता हूँ कि स्टेट में इण्डस्ट्रीज़ को फरोग देने के लिये यह और तो कोई खास काम कर नहीं रही या सिवाए इसके कि यह उन को थोड़े बहुत लोन देकर उनकी सहायता करती है। इसलिये इसको चाहिए कि यह सैंट्रल गवर्नमेंट को कहे कि इण्डस्ट्रीज़ को ज्यादा से ज्यादा लोन

[श्री बलरामजी दास टंडन]

देने के लिये इस कारपोरेशन की फाईनेंशल पोज़ीशन को स्ट्रांग बनाए और इसके लिये ज़रूरी है कि इसके शेयरहोल्डर्ज़ को इम्पीटस दे और इसके लिये यह कर दे कि जो इनकम उनको इस शेयर्ज़ से होने वाली होगी उस पर इनकम टेक्स नहीं लगेगा। इस तरह से लोग इसके शेयर्ज़ खरीदने में ज्यादा से ज्यादा इनवैस्ट करेंगे क्योंकि उनको पता होगा कि जो इनकम उनको बैंकों में रुपया जमा कराने से सूद से होगी उस पर तो उन्हें इनकम टैक्स देना पड़ेगा और यहीं पर उनकी जो इनवेस्टमेंट से इनकम होगी वह इनकम टैक्स फरी होगी। इण्डस्ट्रीज़ को फरोग देने के लिये यह बहुत ज़रूरी है कि इन अदारों के पास जो उनके लिये लोन्ज़ देते हैं, बहुत ज्यादा रुपये हों। इसलिये मैं समझता हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट आफ इण्डिया के पास यह सवाल टेक अप करे।

जहां तक इस कारपोरेशन के सबवेनशन्ज़ का ताल्लुक है वह इसने जहां सवा दस लाख के लिये हुए हैं वहां इसने सवा तीन लाख वापस कर दिये हैं। मैं समझता हूँ कि इस बात के अन्दर इसको क्रेडिट जाता है। लेकिन इस पर इसको फूल नहीं जाना चाहिए यह ठीक है कि इसको इसका क्रेडिट ज़रूर है क्योंकि हिन्दुस्तान की जो बाकी इस तरह की कारपोरेशन्ज़ बनी हुई हैं, उनमें से अभी तक किसी एक ने भी यह वापिस नहीं किये। इस बात का इसको क्रैडिट जाता है कि इसने कुछ तो वापस कर दिए हैं। यह इसकी क्रेडिटवर्दीनेस है। लेकिन इस बारे में मैं यह ज़रूर कहूँगा कि यह इसे बाकी भी जल्दी से जल्दी वापस कर देने चाहिए क्योंकि जब यह सारे के सारे वापस हो जायेंगे तब ही यह प्राइवेट शेयर होल्डर्ज़ का डिवीडैंड निकाल सकेगी। इसलिये इसे यह वापस करके जल्दी से जल्दी लोगों को उनके शेयर्ज़ पर जो डिवीडैंड बनने देना चाहिए। अगर यह नहीं देगी तो प्राइवेट इंडिविजुअल्ज़ को इसमें इनवेस्ट करने के लिये इनकरेजमेंट नहीं मिल सकती। अगर यह उन को दिया जायेगा तो उनमें इसके प्रति कानफीडेंस पैदा होगा।

एक बात मैं आपके ज़रिए हाउस के नोटिस में और लाना चाहता हूँ और वह यह है कि इसका जो कानून बना हुआ है उसका मुद्दा तो यह है कि हर आदमी को बिला किसी तमीज़ के जो भी इण्डस्ट्रियल परपज़िज़ के लिये लोन लेना चाहे उसे मिल सके लेकिन हो यह रहा है कि यहां पर चन्द आदमियों की या चन्द फर्मों की मनापलीज़ बन गई हैं। आप सुन कर हैरान होंगे कि एक ही साल में एक ही पार्टी को डिफरेंट नामों पर 95 लाख रुपये तक कर्ज़ा दिया गया है। आर. के. ब्रदर्ज़ की एक फर्म है उसके तीन चार युनिट्स हैं। उन सब को पांच पांच सात सात लाख करके 95 लाख रुपये एक ही साल में कर्ज़ा दिया गया है। तो इसका मतलब यह हो जाता है कि थोड़े से आदमियों के लिये रुपये इकट्ठे करने का यह अदारा बन गया है। वैसा कानून के मुताबिक यह कारपोरेशन तो इसलिये बनाई गई थी ताकि स्टेट के सैंकड़ों लोगों को जो अपनी अपनी इण्डस्ट्रीज़ के लिये लोन लेना चाहें उन सब को उनकी ज़रूरत के मुताबिक लोन मिल सके। इस लिये गवर्नमेंट को इस मनाप्ली को खतम करने की कोशिश

करनी चाहिए । जब यह कारपोरेशन लोन सैंक्शन करती है तो उसमें इसके डाइरैक्टर आफ इण्डस्ट्रीज़ और फाईनेंस सैक्रेटरी भी होते हैं। उनको चाहिए कि वह इस चीज़ का खास तौर पर ख्याल रखें कि इस कारपोरेशन से सिर्फ चन्द बड़े बड़े सरमाएदारों ने ही फायदा नहीं उठाना बल्कि बाकी के गरीब लोगों ने भी फायदा उठाना है। अगर इस तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा तो इस कारपोरेशन को बनाने का जो मक्सद है वह खत्म हो जाएगा ।

फिर इस बात को भी देखने की ज़रूरत है कि इस कारपोरेशन का जो ढांचा है, वह किस हद तक मौजूं है। इस बारे में आप देखेंगे कि इसकी जो ऐडमिनिस्ट्रेशन है वह टाप हैवी है और इस में जो अफसरान काम कर रहे हैं वह बड़ी बड़ी तनखाहें ले रहे हैं और इसके साथ ही वह हज़ारों रुपये बोनस की शक्ल में भी ले लेते हैं और इस तरह से मुनाफे से हुई रकम को काफी हद तक खत्म कर देते हैं । जो अफसरान दो दो या इससे भी ज्यादा तनखाहें लेते हैं उनके बोनस लेने में कोई जस्टीफिकेशन नहीं है। बोनस तो छोटे कर्मचारियों को ही मिलना चाहिए । अगर वह इस तरह से बोनिस लेते रहे तो मैं नहीं समझता कि किसी तरीका से इसके इखराजात में कमी की जा सकती है। सरकार को इस बारे में ज़रूर देखना चाहिए कि इसके इखराजात में कैसे कमी की जा सकती है । अगर इखराजात में कमी की जायेगी तो मुमाफा ज्यादा निकाला जा सकेगा और लोगों को उनके शेयर्ज़ पर ठीक डिवीडेंड मिल सकेगा। (घंटी की आवाज़) एक बात आखिर में कह कर मैं समाप्त करूँगा और वह यह है कि गवर्नमेंट को इस सारे के सारे कानून को देखना चाहिए और इसे नए सिरे से नई शक्ल देनी चाहिए। इसमें उन लोगों को जिनकी इण्डस्टरी की तरफ रुचि है उनकी राय लेनी चाहिए और उनको कानफीडेंस में लेकर जो इसकी वर्किंग की जानकारी रखते हैं, उनसे फायदा उठाना चाहिए। आज इस कानून में काफी तबदीली लाने की ज़रूरत है । किस तरह से डिसवर्समेंट आफ लोन्ज़ हो और किस तरह से इसकी वर्किंग हो इस बारे में सोचना चाहिए ।

उनको भी कहें और फिनांस कारपोरेशन, जिसके जिम्मे यह काम है, उसको भी ऐप्रोच करें ताकि ऐसी मनौपलीज़ क्रियेट न हों और इसके वर्किंग में सुधार होकर पंजाब की तरक्की हो सके और वह अपने पांव पर खड़ा हो सके । इसका डिवीडेंड मुनासिब हो और इनकम टैक्स फ्री हो। दूसरी सरकारों को भी ऐप्रोच करें और इसमें तरमीम कराएं। लोगों को लोन्ज़ मुनासिब तरीके से मिलें । इन सारी बातों का ख्याल करने से यह कारपोरेशन काफी यूज़फुल साबित हो सकती है और हो भी रही है। इसकी कमियों को अगर दूर कर दिया गया तो यह और भी ज्याद यूज़फुल साबित होगी ।

Deputy Speaker : Motions moved :

That the Eleventh Annual Report and Accounts of the Punjab Financial Corporation for the year ended 31st March, 1964, laid on the Table of the House on the 15th September, 1964, be discussed.

That the First Annual Report and Accounts of the Punjab Export Corporation Limited for the year 1963-64 laid on the Table of the House on the 25th February, 1965, be discussed.

उपाध्यक्षा: अब देखिए 25 मिनट अकेले टंडन साहिब ने ले लिये हैं, इस सारी डिसकशन को दो घंटे के अन्दर खत्म करना है। यह ख्याल रखें। (Shri Tandon alone has taken 25 minutes. The hon. Members may please bear this fact in mind that this discussion is to last two hours only.)

सरदार बलवंत सिंह: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडम। क्या दोनों रैजोल्यूशन इकट्ठे ही चल रहे हैं?

उपाध्यक्षा: आप इस आगस्ट हाउस के मैम्बर हैं, आपको यहां पर अटैंटिव होकर बैठना चाहिए और जो कुछ मैं कहती हूँ वह सुनना चाहिए। (The hon. Members of this august House should be attentive and should listen to the Chair.)

डा. बलदेव प्रकाश (अमृतसर शहर पूर्व): डिप्टी स्पीकर साहिबा, यहां पर हाउस में ऐक्सपोर्ट कारपोरेशन की नौ महीने के काम की रिपोर्ट ले डाउन की गई है। इस बारे में मैं आपके द्वारा कुछ सदन को बताना चाहता हूँ। इसमें कोई शक नहीं है कि ऐक्सपोर्ट का जो काम है यह सूबे और देश के लिये निहायत ज़रूरी है और जो हमारे तीसरी प्लेन के ऐक्सपोर्ट के टार्जेट्स थे उनसे बहुत कम ऐक्स्पोर्ट हो पाई है और जो चौथी प्लेन के टार्जेट्स थे 7,800 करोड़ रुपये के और जो पहले 5,100 करोड़ रुपये के थे उन दोनों में बहुत गैप है जो शायद पूरा न हो सके। इस कार्पोरेशन के काम को देख कर निराशा होती है। अगर इसी ढंग से यह कारपोरेशन काम करती रही तो चाहे यह सौ साल भी काम करती रहे तो भी यह अपने टार्जेट्स को पूरा नहीं कर सकेगी। डिप्टी स्पीकर साहिबा, इसकी जो नौ महीने की रिपोर्ट है वह मैं आपको बताता हूँ कि क्या है।

इसके मुताबिक कुछ माल विदेशों के अन्दर गया है मुख्यत: यह जो तीन चीज़ ही हैं जैसे आयरन शीट्स, कुछ बड शीट्स, कुछ हैंडलूम इन्डस्ट्री की चीजें हैं कुछ और हैंडी क्रैफ्टस या खिलौनों की हैं चीजें जो बाहर भेजी गई। डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह काम जिस ढंग से ऐक्सपोर्ट कार्पोरेशन ने चलाया है वह बहुत ही काबिले एतराज़ है। इस कारपोरेशन का आथोराइज्ड कैपीटल 50 लाख रुपये का है। इसमें से 20 लाख रुपया हमारी सरकार ने इस कारपोरशन को दिया। इस रकम में से 7 लाख 48 हजार 675 रुपये के शेयर्ज़ के रूप में सरकार ने कनवर्ट करा दिया है, 10 लाख 760 हजार और एक सौ रुपया हमारी सरकार का इस कारपोरेशन के पास बैंक में जमा पड़ा है। इसका किसी को कोई फायदा नहीं है न सरकार को और न ही कारपोरेशन को। इसके अलावा अगर कारपोरेशन ने कोई फंड रेज़ किये हों तो उनका इस रिपोर्ट में तो जिक्र नहीं है, जितने शेयर्ज़ बेचे हैं वह सरकार को बेचे हैं और जो रुपया लिया है वह भी सरकार से ही लिया है। मैं तो कहता हूँ कि सरकार ने अपना 20 लाख रुपया देकर इसको शुरू करवाया है। बाकी यह काम किस ढंग से कर रही है यह मैं आप के सामने रखता हूँ। डिप्टी स्पीकर साहिबा, जो आयरन शीटस इसने भेजी उसमें कुछ मुनाफा हुआ। उसके साथ ही बम्बई की एक फर्म के साथ यू. एस. ए. को शीट्स

भेजने का सौदा हुआ था । वह माल गया तो उस फर्म ने माल लेने से इनकार कर दिया, नतीजा यह हुआ कि यू. ऐस. ए. में नुकसान उठा कर वह माल बेचना पड़ा। यही नहीं । फिर जो अमरीका में इण्डस्ट्रियल फेयर हुआ तो उसमें इन्होंने एक पैवीलियन लगाया। उसमें भी बंगलिंग की गई वहां पर जो माल भेजा गया उसमें नुकसान हुआ है। वहां पर किराया पर जो जगह ली गई वह एक लाख 80 हज़ार रुपये पर ली गई और उसमें जो माल रखा गया वह दो लाख कुछ हज़ार रुपये का था । इससे आप अन्दाज़ा लगा सकते हैं कि यह तो वही बात है कि एक दुकान हो जिसका किराया तो सौ रुपया हो मगर माल उसमें सवा सौ रुपये का रखा जाए । जब ऐसी हालत हो तो उससे प्राफिट की क्या उम्मीद रखी जा सकती है ? फिर वह माल बिका भी नहीं। एक लाख 12 हजार रुपये का माल वैसे ही पड़ा रहा । तो यह एंटरप्राइज़ रहा इसमें कार्पोरेशन को 87 हज़ार रुपये का नैट लास हुआ ।

उपाध्यक्षा : क्या किराया माफ नहीं हुआ ? (Was it not given rent free ?)

डा. बलदेव प्रकाश: इस रिपोर्ट में ऐसी कोई बात नहीं है उसे डायरैक्टर्ज़ खा गए या कहां वह खपत हो गया कुछ नहीं बताया गया । आप देखें कि जो कारपोरेशन एक साल के अन्दर दस लाख रुपये का तो काम करे और उसको एक लाख रुपये का नुक्सान हो जाए तो जब वह और बड़े बड़े काम करेगी तो क्या हालत होगी ? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस कारपोरेशन का क्या खर्च है और यह किस ढंग से चल रही है । वह मैं आपको बताना चाहता हूँ ।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस कारपोरेशन का जो हैडक्वार्टर है वह चंडीगढ़ में है और इस हैडक्वार्टर का नौ महीने का खर्च एक लाख 421 रुपये है । डायरैक्टर्ज़ और मैनेजिंग डायरैक्टर्ज़ का आप देखें कि दस लाख रुपये का तो इस फर्म का काम चल रहा है, मगर उसकी मैनटेनेंस पर एक लाख से ऊपर रुपया खर्च हो गया है । अभी इसमें ऐस्टेबलिशमेंट का खर्च शामिल नहीं है । उसका खर्च भी बताता हूँ। इस ऐस्टेबलिशमेंट पर 61,475 रुपये का खर्च है । इस तरह से अगर दोनों खर्च मिलाये जायें तो डायरैक्टर्ज़ और ऐस्टेबशिलमेंट पर खर्च एक लाख 61 हज़ार रुपया हुआ । उसकी डिटेल्ज़ में, डिप्टी स्पीकर साहिबा, आपके सामने रखना चाहता हूँ। 2,350 रुपये तो डायरैक्टर्ज़ ने फीस ली । 11,255 रुपये मैनेजिंग डायरेक्टर ने तनखाह ली । इसके अलावा 6,771 रुपया डायरेक्टर्ज़ का टी.ए. है । इसके अलावा 14,011 रुपये मिसलेनीअस टी. ए. है, जिस की कोई मज़ीद डीटेल नहीं दी गई क्योंकि इसमें कुछ डायरैक्टर्ज़ चंडीगढ़ के हैं और कुछ लुधियाना के हैं और यह नहीं बताया गया कि यह टी. ए. किस का है। कार की मेन्टेनैंस पर 4,577 रुपये का खर्च दिखाया गया है और यह कुल मिला कर 1 लाख 421 रुपये का खर्च है।

उपाध्यक्षा: क्या इसमें डायरैक्टर्ज़ की लिस्ट भी दी हुई है ? (Does it contain the list of Directors also ?)

डा. बलदेव प्रकाश: जी हां, इसमें डायरैक्टर्ज़ के नाम दिये हुए हैं:

श्री जगदीश लाल बहल
श्री पृथी पाल सिंह
श्री अमृत लाल बतरा
श्री डी. डी. सहगल
श्री बृज मोहन लाल

और इस के मैनेजिंग डायरैक्टर हैं श्री एल. आर मागो ।

पांच छः आदमियों को लेकर एक्सपोर्ट कारपोरेशन कायम की हुई है जिस पर इन नौ महीनके अर्सा में 1 लाख 421 रुपया खर्च किया गया है और डायरैक्टर्ज़ की फीस पर खर्च हुआ । इस कारपोरेशन ने इस अर्सा में दो मेजर काम किये हैं। एक तो यह कि अमेरिका में वर्ल्ड फेयर के लिये माल भेजना और दूसरा आयरन शीट्स तैयार करने के लिये पिग आइरन फौन्डरियों को दिया गया । इन दो कामों के इलावा कोई काम इस कारपोरेशन ने पिछले साल में नहीं किया और फिर यह किस तरह से 1 लाख और 421 रुपया एडमिनिस्ट्रेशन पर खर्च कर सकती है ? इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस स्टेट को ऐक्सपोर्ट कारपोरेशन कायम करने से क्या फायदा हो सकता है।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरा इस डिसकशन को रेज़ करने का भाव यह नहीं था कि मैं सिर्फ क्रिटिसिज़्म ही करूँ । मेरा भाव तो यह बात भी सब के ध्यान में लाने का था कि गवर्नमेंट जो भी इस तरह का अदारा बनाती है चाहे फिनांशल कारपोरेशन हो या ऐक्सपोर्ट कारपोरेशन हो और जिसमें सारे का सारा रुपया सरकार का लगता हो उसका क्या हाल होता है । किसी को उसकी बहबूदी का कोई ख्याल नहीं आता न फिकर न चिंता । न गवर्नमेंट के डायरैक्टर और न ही पब्लिक की तरफ से आए डायरैक्टर कोई काम करते हैं और इन्ट्रेस्ट नहीं लेते जिसका नतीजा क्या होता है कि धीरे धीरे पांच सात सालों में सारा सरमाया खत्म हो जाता है । यह है गवर्नमेंट एन्टरप्राइज का नकशा। मैं इसकी तरफ भी सरकार का ध्यान आपके द्वारा दिलाना चाहता था। हमारे पास इस कारपोरेशन की पिछले 9 महीनों के काम के बारे में रिपोर्ट आई है इसलिये इस पर और ज्यादा विचार हम नहीं दे सकते । यह चार सफे की तो रिपोर्ट है और सारे का सारा हिसाब किताब ही दिया हुआ है । इसके इलावा कोई लम्बा चौड़ा काम इसने नहीं किया इसलिये ज्यादा क्रिटिसिज्म नहीं हो सकती । लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ऐक्सपोर्ट के काम का जहां तक तआल्लुक है पंजाब में कितना ही काम होता है, स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज़ हैं, काटेज इन्डस्ट्रीज हैं, वूलन, टैक्सटाइल, साइकल और सिउइंग मशीन्ज़ और छोटे छोटे पुर्ज़े यहां पर तैयार होते हैं। और इनकी ऐक्सपोर्ट की जा सकती है । लेकिन इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया हालांकि फोर्थ प्लान में हमने 78 एज़ार करोड़ की ऐक्सपोर्ट करनी है और यहां पर इतनी बड़ी स्टेट से जोकि सारी की सारी इण्डस्ट्रियलाइज़्ड है सिर्फ 28 लाख का माल बाहर भेजा गया । न 100 लाख

न दो सौ लाख न एक करोड़ ना आधा करोड़ सिर्फ 24 लाख की ऐक्सपोर्ट हम कर सके हैं। तो यह हालत है इस कारपोरेशन की । फिर जो वर्ल्ड फेयर लगाया गया उसमें उसका क्या हाल है ? ऐक्सपोर्ट में भी 87 हजार का नुकसान उठाना पड़ा । अगर इसी ढंग से इस कारपोरेशन को चलाना है तो जो टारगिट है वह हम पूरा न कर पायेंगे । इसलिये इस सारी बात को देखने की ज़रूरत है कि किस ढंग से इस कारपोरेशन को चलाया जाए और इसमें कौन सा नया ऐलीमेन्ट लाया जाए, जो सरकार ने 20 लाख रुपया दिया हुआ है वह इधर उधर के इखराजात में ही खत्म न हो सके, कारपोरेशन को फायदा हो और पंजाब की इन्डस्टरी को फायदा मिले । इसकी तरफ फौरी तौर पर ध्यान देने की ज़रूरत है इतना कह कर मैं बैठता हूँ।

ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ (ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਅੱਜ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਫਾਜ਼ਲ ਦੋਸਤ ਸ੍ਰੀ ਬਲਰਾਮਜੀ ਦਾਸ ਟਡਨ ਨੇ ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਅਰੰਭਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਹੈ ਇਸਨੇ ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੈਂਡੇਬਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮਾਲ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕੀ ਆਪ ਐਕਸਪੋਰਟ ਮਾਈਂਡਿਡ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਐਪਟੀਚਿਊਟ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਲ ਹੈ ? ਇਸ ਪੱਖ ਵਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਮਾਲ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਅਰਸੇ ਵਿਚ 24 ਲਖ ਦਾ ਮਾਲ ਬਾਹਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲ-ਪਡ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਜੇ ਆਪਣੀ ਇਨਫੈਨਸੀ ਦੀ ਸਟਟ ਵਿਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਥੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਉਸਦੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧਾ ਮੁਲ ਬਾਹਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਈਕਲ ਏਥੇ 150 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁਲ 80 ਰੁਪਏ ਵਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਮੁਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਕੇ ਐਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇੰਡਸਟ੍ਰਿਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸੂਏਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਾਟੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੇ ਕੀਮਤ ਵਧ ਮਿਲਦੀ ਏ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਉਸੇ ਹੀ ਮਾਲ ਲਈ ਘਟ ਮੁਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਨੇਲਾਇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਿਫੀਕਲਟੀਜ਼ ਅ ਤੇ ਂਦੀਆਂ ਹਨ ।

ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇੰਨਡਸਟਰੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਸਟ ਆਇਰਨ ਸਾਇਲ ਪਾਇਪ ਦਾ ਆਰਡਰ ਬਾਹਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹ

[ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ]
ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਨਟ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਥੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਲ ਉਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਇਨਟ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਉਥੇ ਨਵੇਂ ਸਾਇਲ ਪਾਇਪ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭਿਜਵਾਏ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਇਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਨਾਲੇਜ ਨੂੰ ਇੰਟ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ । ਇਹ ਇਕ ਸ਼ਲਾਘਾ ਯੋਗ ਕਦਮ ਤੇ ਕੰਮ ਹੈ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਇਹ ਵਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਇਲ ਪਾਇਪ ਭੇਜਣਾ ਸੀ ਭੇਜ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਬੰਬਈ ਵਿਚ ਚਾਰ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਨਾ ਮਿਲਿਆ । ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਂਡੀ ਕੈਪਸ ਐਕਸਪਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ; ਮੀਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਜਿੱਥੇ ਤਕ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁਕਾ ਹਾਂ, ਸਾਇਲ ਪਾਇਪ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਆਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਪਿਗ ਆਇਰਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪਾਇਪਸ ਦਾ ਆਰਡਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਣ ਨਾਲ ਪਿਗ ਆਇਰਨ ਦਾ ਕੋਟਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਵਧਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਕੋਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੂਜੀ ਵਸਤੂ ਸੀ ਮਿਲਣ ਲਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਰਾ ਮਟਰੀਅਲ ਵੀ ਵਧ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਚ ਚਾਰ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਮਪਲਾਇਮੈਂਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ । ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ।

ਇਥੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਬੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਬੀਸ਼ਨਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮਾਰਕਟ ਕਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਰਲਡ ਫੇਅਰ ਵਿਚ ਸਟਾਲ ਲਾਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਨਡਸਟਰੀ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮਾਰਕਿਟ ਕਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈਂਡ ਲੂਮ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਬੀਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ 5 ਲਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ।

ਇਸ ਰਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਨੁਮਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਰਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰਸ਼ਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਉਹ ਨਵੀਂ ਲਾਈਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਤਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਖਰਚ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰਾਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰਖ ਕੇ ਕਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ

ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁਆਮਲੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਗਜ਼ੀਬੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪਰਪਜ਼ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਐਕਸਪੋਰਟ ਆਰਡਰਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗ । ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੀਬੀਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਫੇਅਰ ਦਿਲੀ ਦੇ ਵਿਚ ਲਗਾਈ ਸੀ ਉਹ ਪਰਾਪੇਗੰਡਾ ਪਰਪਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਨਾਫਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ, ਅਮਰੀਕਾ, ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿਚ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਾਰਕਿਟਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹ ਬੇਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਕੇ ਐਗਜ਼ੀਬੀਸ਼ਨਜ਼ ਰਖਦੀ ਹੈ ਆਪਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਸਬਸੀਡਾਇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਹੈਂਡ-ਲੂਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜਾਹ ਨਾਲ ਬਾਹਰਲੇ. ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਪੂਲਰ ਹੋਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਮਾਰਕਿਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਈ । ਸਾਨੂੰ ਕੁਲੰਬੂ 'ਪਲੈਨ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਪਲੈਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਮਹਿਜ਼ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ । ਜਿਥੇ ਪੈਕਿੰਗ, ਰੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਕਰਸ਼ਿੰਗ ਵਰਗੀਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਅਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਬੜੀ ਕਾਮਿਆਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੀ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਥਾਂ ਘਾਟ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਣ ਫੁਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬੜੀ ਮੈਨੇਜਏਬਲ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਏਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

श्री मोहन लाल (बटाला) : आज हम फाईनैन्शल कारपोरेशन तथा ऐक्सपोर्ट कारपोरेशन की रिपोर्टस को डिसकस कर रहे हैं। पंजाब की इंडस्टरी की डिवैल्पमैंट के साथ उनका एक बहुत ही गहरा संबंध है । इसलिये हमें इन रिपोर्टस को महज़ डिसकशन के तौर पर ही डिसकस नहीं करना चाहिए बल्कि मौजूदा स्थिति की अहमियत को मद्दे नज़र रख कर हमें इस सारे सिलसिला को देखना होगा । आप देख रहे हैं कि जंग की वजह से पंजाब की इंडस्टरी को बड़ा भारी धक्का लगा है और आगे भी लगने का इमकान है । मेरे लिये इतना समय नहीं होगा कि मैं इसकी सारी डीटेल में जा सकूं ।

आप जानते हैं कि जंग की वजह से रा मैटीरियल का कोटा जो पंजाब की इन्डस्ट्रीज़ को दिया जाता था वह बहुत कट गया। एसैंशियेलिटी सर्टीफीकेट्स पर भी

[श्री मोहन लाल]

जो कोटा दिया जाता था वह भी घट गया । बहुत कम कोटा मिल रहा है । खास तौर पर जहां तक पंजाब की इंडस्ट्रियल ग्रोथ का संबंध है, पंजाब की इंडस्टरी को बहुत ज़बरदस्त धक्का लगा है । जहां तक इंडस्ट्रियल गरोथ का सवाल है पंजाब की इंडस्टरी बहुत हद तक फरदर डिवैलपमेंट के लिये और इसकी ऐक्स्पोर्ट के लिये बहुत खतरे में है । जब ऐक्स्पोर्ट की हम बात करते हैं तो यह खतरा हमारे सामने बहुत ज्यादा आ जाता है इस से तो यह जाहिर होता है कि ऐक्स्पोर्ट के लिये हमारी प्रोडक्शन रहेगी ही नहीं । इसके इलावा फाईनैंसिज़ की बहुत ज्यादा दिक्कतें हमारे सामने पैदा हो रही हैं । इंडस्टरी के लिये रा मैटीरियल की जुदा दिक्कते हैं। और टैकनीकल लैवल पर देखें तो और भी बहुत सी दिक्कतें हैं। इसलिये मैं तो यही कहूँगा कि पंजाब सरकार को चाहिए कि वह सैंट्रल गवर्नमेंट से पंजाब की इंडस्ट्री के लिये ज्यादा से ज्यादा जितनी भी इमदाद ले सकती है वह ले । खास तौर पर पंजाब की इंडस्टरी को मौजूदा हालात में बहुत जबरदस्त धक्का लगा है । अगर स्पैशल तौर पर पंजाब की इंडस्टरी को रा मैटीरियल की या और दूसरी चीज़ों की सैंट्रल सरकार ने इमदाद न की तो मैं समझता हूँ इस इंडस्टरी को और भी जबरदस्त धक्का लगेगा ।

जहां तक इन कारपोरेशन्ज़ का संबंध है, मैंने इनकी लेटैस्ट रिपोर्ट्स को भी पढ़ा है और यह एक खुशी की बात है कि पंजाब की फाईनैनशल कारपोरेशन ने बहुत अच्छा काम किया है, बल्कि हमें ऐसा मालूम होता है कि हमारी कारपोरेशन हिन्दुस्तान की बेहतरीन रन कारपोरेशन्ज़ में से एक है।

मैंबर साहिबान की वाकफियत के लिये मैं यहां पर दो तीन बातें अर्ज़ कर देना ज़रूरी समझता हूँ ।

(*At this stage Shri Rup Singh Phul, a Member of the Panel of Chairmen, occupied the Chair*)

इस फाइनैंशल कारपोरेशन के पराफिट्स का पिछले सालों की निसबत अगर मुकाबला किया जाये तो आप देखेंगे कि यह बढ़ता ही जा रहा है । 1959-60 में यह प्राफिट्स 4,12,000/- के थे मगर 1963-64 में यह 11,50,000/-हो गए और 1964-65 में यह बढ़ कर 15,35,000/- तक पहुंच गये हैं और यह एक बड़ी प्रोग्रैसिव इन्क्रीज़ है । इसी तरह से रिज़र्व इनका 1959-60 में 50,000/- था 1964-65 में 11,96,000 हो गया सबवेंशन लायबिलिटी में इसने 1962-63 में 25,688 रुपये अदा किये और 1964-65 में 2,50,000/- जैसा कि टंडन साहिब ने ज़िक्र किया सरकार को इस फाईनेनशल कारपोरेशन की जल्दी से जल्दी इमदाद करनी चाहिए ताकि यह कारपोरेशन अपनी Subvention Liability को बहुत जल्दी वापस अदा कर सके और अपना Dividend बढ़ा सके ।

हिन्दुस्तान की दूसरी कारपोरेशंज़ ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया है । और अपनी यह liability वापस नहीं की है । जो लोन्ज़ सैंक्शन हुए हैं वह भी तसल्लीबख्श

है। 1959–60 में 66 लाख के करीब और 1964–65 में दो करोड़ 63 लाख के करीब सैंक्शन हुए । इससे अंदाज़ा लगता है कि बहुत बढ़ोतरी हुई है । हम इस तरह से पंजाब फाइनैंशल कारपोरेशन की इस दशा में सराहना कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम डिस्बर्समेंट को लें तो 1959–60 में 52 लाख के करीब थी और आज 1 करोड़ 42 लाख के करीब है यह भी अच्छा सिलसिला है । और खुशी की बात यह है कि कोई भी बैड डैट राइट आफ नहीं करना पड़ा । मैंने दूसरी स्टेट्स के टेबल भी देखे हैं और पाया है कि जहां तक प्राफिट का सम्बन्ध है वह इस साल इस कारपोरेशन का 15.36 लाख हैं जो कि सारी हिन्दुस्तान की कारपोरेशंज से बढ़ कर हैं। दूसरी स्टेट्स के कोई 12 लाख या 11 लाख के करीब और इससे भी कम हैं । सबवेन्शन रीपेमेन्ट के लिहाज़ से भी यह अव्वल दर्जे पर है । जहां तक रीज़र्वज़ का सम्बन्ध है वैस्ट बंगाल को छोड़ कर और कोई कारपोरेशन इसका मुकाबला नहीं करतीं । लोन्ज भी दूसरे दर्जे पर और डिस्बर्समेंट में भी दूसरे दर्जे पर यह आती है । एक महाराष्ट्र स्टेट है जिसने लोन्ज की डिस्बर्समेंट ज्यादा की है । टंडन साहब के सुझाव पर कारपोरेशन को ध्यान देना चाहिए। आज तक लोन्ज़ देने का ही जो काम इसने किया है वह नाकाफी है । कारपोरेशन की जिम्मेदारी सिर्फ लोन देने की ही नहीं है कि सिर्फ पैसे दे दिये और ले लिये । इसके साथ साथ अंडरराइटिंग और लोन्ज़ की अथवा deferred payments की पेमैंट की गारंटी का भी सबसे ज्यादा ज़रूरी काम है । अगर सरकार की तरफ से या कारपोरेशन की तरफ से यह कहा जाए कि फंडज़ की कमी की वजह से नहीं कर पाये, तो यह कोई जस्टीफिकेशन नहीं है । इंडस्ट्री की तरक्की को फरोग़ देने के लिये इस तरफ कदम बढ़ाया जाना ज़रूरी है । चाहे गवर्नमेंट आफ इंडिया से फंडज़ लेकर दें, मगर दें । और फाइनैंशल कारपोरेशन में जो कमी है, वह दूर करनी पड़ेगी । जो डिवीडैंड डिक्लेयर किये हैं वह 3 परसेंट हैं।

I am reading from the report itself :—

"The Board of Directors have declared a dividend at the rate of 3 per cent per annum per share as guaranteed by the State Government minus, of course, such tax deductions as are prescribed under the relevant Finance Act."

मैं समझता हूँ कि उनके रास्ते में दिक्कतें हैं। हाइएस्ट डिवीडैंड देने में और गवर्नमेंट आफ इंडिया के ऐक्ट की भी बाधा है । मैं बलरामजी दास टंडन से सहमत हूँ कि डिवीडैंड बढ़ाने के काम को ज्यादा देर तक रोकना मुनासिब नहीं है । इसलिये गवर्नमेंट आफ इंडिया से जहां भी कहने की ज़रूरत पड़े कहना चाहिए कि कानून में तरमीम करें टंडन साहब को प्राइवेट शेयर होल्डर्स के बारे में कुछ गल्ती लगी है । इसमें वह सवाल पैदा नहीं होता । इस कारपोरेशन में हिस्से पंजाब गवर्नमेंट के 24,504 दिल्ली के 12,251 हिमाचल के 4,901, Reserve Bank of India के 20 हज़ार, इसी तरह दूसरी गवर्नमेंट्स के हैं। प्राइवेट पार्टी के तो सिर्फ 3300 के करीब के हैं वह भी एक लाख हिस्सों में

[श्री मोहन लाल]
से। इसलिये प्राइवेट पार्टी के बारे में कोई यह मैटीरियल बात है, मैं नहीं समझता। जहां इन गवर्नमैंट्स के शेयर होने का ताल्लुक है, यह तो एक पब्लिक सैक्टर बन जाता है। मैं ज्यादा डिटेल में न जाता हुआ यही कहूँगा कि जहां तक इन कारपोरेशंज़ का सम्बन्ध है, इनके वर्किंग को और इफैक्टिव बनाना होगा। खास तौर से इन हालात में, जब कि पंजाब की इंडस्ट्री कमज़ोर हो रही है। इसलिये पंजाब की सरकार को सैंट्रल सरकार के पास अपना केस मजबूत बना कर पेश करना होगा वरना हमें धक्का लगेगा और बाद में पछताना होगा।

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ (ਲੁਧਿਆਣਾ ਉੱਤਰ) : ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਇਕ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਇਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਹਨ। ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਯੂਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅੌਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਯੂਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਵਿਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹਨ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਕ ਚਾਦਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰੋੜੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਧਿਮਕੇ ਥਾਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾ ਲਓ। ਇਕ ਬੰਬਈ ਦੀ ਫਰਮ ਨਾਲ ਬੈਡ ਸ਼ੀਟਸ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਚੁਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ

11.00 a.m.

ਗਏ ਸਟਾਲ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਘਾਟਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਹੈ ਟਰਾਂਸੈਕਸ਼ਨ। ਇਕ ਪਾਇਪਸ ਦੀ ਟਰਾਂਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। 35,000 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਕੁਲ ਸ਼ੀਟਸ ਸਨ। ਇਹ 3 ਸੌਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮਕਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬਾ ਇਕ ਐਸਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਟਨ ਵੀ ਲੋਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਐਸਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਕਤਰਾ ਮਿਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਐਸਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਇੰਚ ਐਲਮੀਨੀਅਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਐਸਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕਾਪਰ, ਨਾ ਜ਼ਿੰਕ ਅਤੇ ਨਾ ਕਈ ਹੋਰ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੀਮਿੰਟ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀ ਸੂਰਜਪੁਰ ਵਿਚ, ਭੂਪਿੰਦਰਾ ਸੀਮਿੰਟ ਫੈਕਟਰੀ। ਉਸ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਈ ਭੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਏਥੇ ਜੇ ਕੁਝ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡੀਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਏਥੇ ਬਿਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਿਵਾਏ ਖਿਆਲੀ ਪੁਲਾਓ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਜਿੱਥੇ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਲਗਦੇ ਹਨ ਓਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਐਲਮੀਨੀਅਮ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਓਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਰੀਫਾਈਨਰੀ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਦਾ ਹੈ ਓਥੇ ਫਰਟੈਲਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡੀਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸ੍ਰੀ ਹਮਾਯੂੰ ਕਬੀਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੂਸਰਾ ਫਰਟੇਲਾਈਜ਼ਰ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਲਗ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ। ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਖੁਦ ਇਕ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 14 ਫੀ ਸਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਲਈ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਏਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਅਤੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਗੁਨਾਹ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੁਧ, ਕਰੀਮ, ਮਿਲਕ ਪਾਊਡਰ, ਮਖਣ ਅਤੇ ਘਿਓ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਓਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਜ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚਾਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਏਥੇ ਚਾਰਾ ਬਹੁਤਾਤ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏਥੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮੱਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮੋਟਾ ਅਨਾਜ ਛੋਲੇ ਅਤੇ ਬਾਜਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੁਧ ਘਿਓ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਏਥੋਂ ਦਾ ਦੁਧ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਡੇਢ ਔਂਸ, ਦੋ ਔਂਸ ਜਾਂ ਢਾਈ ਔਂਸ ਦੁਧ ਫੀ ਕਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਏਥੇ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ ? ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਦੁਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਬਤ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਵੇਦਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿਚ ਗੀਤ ਗਾਏ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਦੁਧ ਅਤੇ ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਗਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਏਥੇ ਦੁਧ ਅਤੇ ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਗਦੀਆਂ ਸਨ, ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਲਡੇ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡਾਲਡੇ ਅਤੇ ਬਨਾਸਪਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਧ ਘਿਓ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਲਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਇਆ ਹਿੰਦੁ-ਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰਕਿਟ ਨਹੀਂ ? ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਬੰਬਈ ਵਾਲੇ, ਕਲਕਤੇ ਵਾਲੇ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਮਦਰਾਸ, ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਅਤੇ ਕਾਂਡਲੇ ਵਾਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਦੇਵੇ। ਜਿਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਓਥੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ? ਸਾਨੂੰ ਧੋਖੇ ਵਿਚ ਰਖਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਫਾਰਿਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਕਈ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਆਦਮੀ ਏਥੋਂ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਰਖ ਸਕਣ। ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਲੜਕਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਰਿਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਪਿਆ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ।

ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ : ਉਹ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ।

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਝਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇਤਲਾਹ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਉਂ

[ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ]

ਦਸਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਾਈ ਗਈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਸਟਾਲ ਵਿਚ। ਆਇਆ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਕੁਛ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਾਈ ਜਾਏ ?

ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ : ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਨ।

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੇਰ ਗਲ ਗੂਠਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਨ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਣਕ ਅਤੇ ਛੋਲੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਹਾਪੜ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਾ ਪੜ੍ਹੋ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾ ਪੜ੍ਹੋ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਗਊਆਂ ਤੇ ਬੈਨ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਝਾਂ ਤੇ ਬੈਨ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਤੇ ਬੈਨ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬੈਨ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਾਪੜ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾ ਪੜ੍ਹੋ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਏਥੋਂ ਨਾਲੋਂ ਡੂਢੇ ਜਾਂ ਪੌਣੇ ਦੋ ਗੁਣੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਏਥੋਂ ਦਾ ਇਖਲਾਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਏਥੋਂ ਦੇ ਇਖਲਾਕ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤਕ ਕਿਸੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦਾ ਨਾਉਂ ਦਸੋ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ? ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਣ।

ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਕ ਸ਼ੋ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਇਥੇ ਹੁਣ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬੜੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਪੁਚਾਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਐਕਸ-ਪੋਰਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਾਅਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਤਨਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤਨਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ? ਕੁਲ ਪੰਜ ਲਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਤਨਾ ਘਾਟਾ ਜਾਂ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ ਇਕ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1964-65 ਵਿਚ ਸਾਢੇ 44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਗਲ ਪੁਛਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਰਿਪੋਰਟ ਛਪੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੋ ਅਰਬ ਦਾ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਦੋ ਅਰਬ

ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਲਖ ਦਾ ਮਾਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਕਾਗਜ਼ ਲਗਾਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼ਾਇਆ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ । ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਰੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ । ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਬਿਲ ਲਿਆਕੇ ਗਾਈਆਂ ਮਝਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਂਦੇ ਹੋ ? ਸਿਰਫ ਇਕ ਦੋ ਲਖ ਦੀਆਂ ਬੈਡ ਸ਼ੀਟਸ ਨਿਊਯਾਰਕ ਭੇਜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਬਈ ਦੀ ਫਰਮ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਕਸ-ਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ ? ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਤਨੀ ਦੀਦਾ ਦਲੇਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸਦੇ ਆਖਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :

"Selling successfully in the competitive markets of the world is a challenging task and while consolidating its present achievements the Corporation will, during the current year, bend all its energies towards ensuring wider horizons for manufactured products of Punjab. The Japanese way of handling the export of small-scale industries produ cts is an example for the State of Punjab to follow. "

ਗੋਇਆ ਅਸੀਂ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਖਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਭੇਜਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਭੇਜਾਂਗੇ (ਹਾਸਾ) ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੋਟੋ ਹੈ । ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਚਲਨਗੀਆਂ ਦਫਤਰ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਫਰਨੀਚਰ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸੈਰਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ......

ਇਕ ਆਵਾਜ਼ : ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ।

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਹਾਂ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ । ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਐਸ਼ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।

ਸ੍ਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ: ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਗਲ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਬੂ ਜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੋ । (Leaving aside references to boys and girls the hon. Member should talk about something else.)

ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ : ਬਾਬੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।(ਹਾਸਾ)

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ: ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਸੂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ । ਮੈਨੂੰ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣ ਜਾਓਗੇ (ਹਾਸਾ)। ਅਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਾਊਂਡ ਲਾਈਨਜ਼ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਾ ਲੋਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਥੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਇਥੇ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲਗ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

[ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ]

ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹੀ, ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਤਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਦੁਧ ਘੀ ਮੱਖਣ ਤੇ ਦੂਜੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਮਾਰਕਿਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਕਾਸ਼! ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੋਸ਼ ਆਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ । ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚੇਗੀ ।

ਸ੍ਰੀ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਅਗਰਵਾਲ (ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ) : ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਾ ਲੋਹਾ ਨਾ ਕੋਲਾ ਤੇ ਨਾ ਤੇਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲਗ ਸਕਦੀ। ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ । ਇਥੇ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਛੁਰੀਆਂ ਟੋਕੇ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਹੀ ਸੀ। ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਤਰਕੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੀ ਲਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਮਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਮਾਇਆ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਜੋ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਧੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿ ਮਾਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲ ਇਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਸੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਬਾਹਰ ਮਾਲ ਐਕਸ-ਪੋਰਟ ਹੋਣ ਲਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪਰੋਮਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਕਸਪੋਰਟ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਮਹਿਕਮਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਖਦੇ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਕਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਜਿਤਨੇ ਮੁਲਕ ਹਨ ਖਾਹ ਛੋਟੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿਤਨੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਉਤਨੀ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਜ਼ੈਕੋਸਲਵਕੀਆ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਵੇਖੋ ਕਿਤਨੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਉ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਘੜੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਉਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਰਾ ਮੈਟਰੀਅਲ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਐਮੋਨੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤੇ ਵਾਰ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੈਟ (gnat) ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਇਆ ਪਰ ਇਜਨ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੈਂਕ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪਾਰਟਸ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਅਜੇ ਤਕ ਇਨਫੈਨਸੀ (infancy) ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਤਨਾ ਅਰਸਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ । ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਮਰਸ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਪੋਰਟ ਇਮਪੋਰਟ ਤੇ ਫਾਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਨੈਸ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਕਤ ਕਲਕੱਤਾ ਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਕਲਾਸਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਦ ਉਥੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਪਰਾਇਰਟੀ ਰਖੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਓਪਨ ਰਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁਛਦਾ । ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ

ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਮੁਤੱਲਿਕ ਕਲਾਸਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚਾਲੂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਮੂਨਾਂ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰ ਸਕਨ । (ਵਿਘਨ)

ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਸਰਦਾਰ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ Shan Sewing Machine ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਚ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਪਾਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਥੇ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ 4 Jobs ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਵਿਯਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਕ ਮਸ਼ੀਨ 4 ਜਾਬਜ਼ (Jobs) ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਖਰਕਾਰ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜੀ 4 ਜਾਬਜ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਛੇ ਜਾਬਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਹਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਰਰ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਭੇਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟਸ ਦੀ ਬਜਾਏ Small scale ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸ ਭੇਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਸੈਲਫ ਸ਼ਫੀਸੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਅਤੇ ਕਪੜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜ਼ਨੈਸਮੈਨ ਨੂੰ ਗੰਦਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਹਰ ਇਕ ਕਮੀਉਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਰਜੀਕਲ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਛੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਗਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਲਈ ਫਾਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਿਥੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ? ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਵਾਵਾਂਗੇ ? ਇਸ ਲਈ ਫਾਰੇਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪਰੋਮੋਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਇਤ ਹੀ ਦਾਨਸ਼ਮੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇੰਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੀ ਮੁਸਤਹਿਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਰੁਪਿਆ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਇਕ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਡਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ । ਉਸ ਨੇ ਉਥੇ ਸਕਾਰਫ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ । ਉਸ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਸਸਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ । ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਹਰ ਇਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵਿਜ਼ਡਮ (wisdom) ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਲਕੜੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਕਿਸੇ ਜਗਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਰਸਤੇ ਇਕ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਕੜੀ ਦੇ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਰਨੀਚਰ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰੀਗਰ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ

[ਸ਼੍ਰੀ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਅਗਰਵਾਲ]

ਇੰਨੇ ਟੇਬਲ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਇਕ ਦਾ ਵਖਰਾ ਵਖਰਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ; ਉਹ ਉਥੇ ਜਾਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਥੇ ਲੋਕ ਫਰੂਟਸ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਸੰਗਤਰੇ ਅਤੇ ਮਾਲਟੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਸੁਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਛਿਲਕਿਆਂ ਦਾ ਜੈਮ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛਿਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਖਾਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ in Moga Condensed Milk Factory and Nescafe Coffee ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ (production) ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਫਾਰੇਨ ਕਰੰਸੀ ਕਮਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ ਵਖਰੇ ਵਖਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇਨਸਪੈਕਟਰਜ਼ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਸਾਮਾਨ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਸਾਮਾਨ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟਸ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸਮੈਨ ਨੂੰ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਅਤੇ ਫੈਸਿਲੀਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਲਕਿ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਨਸਪੈਕਟਰਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਹੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮਿੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਮਨਾ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਬੰਬਈ ਭੇਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਬਈ ਵਿਚ ਇਕ ਲੈਬਾਰੇਟਰੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤਕ ਭਟਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਮੈਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀਜ਼ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਸੈਂਪਲਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀਜ਼ ਵਿਚ ਚੈਕ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਰਿਜਲਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟੈਕਸਟਾਈਲਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮਿੰਟ ਕਿਉਂ ਇਨਸਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਰੀਪ੍ਰੀਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰਕੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਾਏ ਤਾਕਿ ਇਥੋਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ (disadvantage) ਜਾਂ ਐਡਵਾਂਟੇਜ (advantage)

ਸਮਝੇ । ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਰੀਪ੍ਰੀਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਰੇਲਵੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਫਰੇਟ ਵਿਚ ਇੰਡਸਟਰਿਅਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲ ਬੰਬਈ ਤੋਂ ਇਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਕਪੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਪੜਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਬੰਬਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਰਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬੰਬਈ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਬਰਡਨ (burden) ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਲੀ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਰੀਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਘੰਟੀ)

ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਚੰਦ ਲਾਈਨਾਂ ਕਹਿਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ । ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਰਲੀ ਅਤੇ ਕੁਇਕਲੀ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰੈਸਟ ਕਮ ਕਰਨਾ ਚਾਈਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਾਫਿਟ ਅਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰੈਸਟ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਕਾਟਿਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਪਿਆ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਜ਼ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਵੱਡੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਲਿਮਿਟਿਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਟਿਜ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਇਡਸਟਰੀਜ਼ ਲੋਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫਿਕਸਡ ਫੰਡਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲਾ ਵਾਸਤੇ ਐਨੇ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਸਤੇ ਐਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਸਟ (exhaust) ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲ ਹੈ ਉਥੇ ਜਾਉ। ਉਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਐਨੇ ਫੰਡਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡੀਮਾਂਡਜ਼ ਕੇਟਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਕੇਵਲ ਵੱਡੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਜਦ ਤਕ ਛੋਟੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਸ ਵਕਤ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ (ਨਕੋਦਰ) ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ । ਪਹਿਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ

[ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ]

ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਟਨ ਵੀ ਲੋਹਾ ਨਹੀਂ ਪਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸੀਮਿੰਟ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਰੀਮੂਵ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਥੇ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਹਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਲੋਹਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਲ ਤਾਂ ਬਾਬੂ ਜੀ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। (ਹਾਸਾ) ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਬਾਬੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ, ਘੀ ਅਤੇ ਮਖਣ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅੰਨ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅੱਛੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਘੀ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਘੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਈਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੈਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬਾਬੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇਗੀ ?

ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਪਰਲੇ ਆਦਮੀ ਜੇਬਾਂ ਭਰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਾਫ ਹੈ। ਬਾਬੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਭੁਖ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ in writing ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੁਖ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛਡਣਾ ਪਰ ਬਾਕੀ ਵਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਿਉ (ਹਾਸਾ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬਨਾਉਣ ਦਿਉ ਤੁਸਾਂ ਆਪ ਤੇ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਕ ਆਵਾਜ਼ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਪਲਸ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੋਂ ਸੀ......

ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ; ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸਰਪਲਸ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ—

"Export is as necessary as anything . But we cannot export anything which is surplus. There is absolutely nothing surplus in India."

ਸਿਵਾਏ ਭੁਖ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਰਪਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਪਲਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਟ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਕੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਜੇਕਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਮਾਰਕੇ ਵੇਖ ਲੋ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਵਾਲੀਆ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਜੇਕਰ ਫੋਰਥ ਫਾਈਵ ਯੀਅਰ ਪਲਾਨ ਵਿਚ 7,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 7,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਟ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ।(ਵਿਘਨ) ਸਾਨੂੰ ਬੇਇੰਤਹਾ ਹੈਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਫਾਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨਗਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਟ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਵਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਾਈ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ।

ਮੈਂ ਬਾਬੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬਦ-ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਰਲੀ ਮੈਨੇਜ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ! ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਲਾਈਫ ਅਜੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਰਕਿਟ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਰਕਿਟ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਰਕਿਟ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਰਕਿਟ ਨੂੰ ਸਟਡੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਜੂਟ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ੂ ਨਟ ਦੀ ਕਦਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਦਾਮ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਕਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਸਿਕਲ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ 145 ਰੁਪੈ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿਚ 65 ਰੁਪੈ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹਰਕੂਲੀਸ ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਇਗਲੈਂਡ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਈਕਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿਚ ਰਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ......

ਸ੍ਰੀ ਚੇਅਰਮਨ (ਸ਼੍ਰੀ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਫੂਲ) : ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਐਕਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰੋ: ਇਹ ਕੋਈ ਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਊਸ ਹੈ। (ਹਾਸਾ) (The hon. Member Chaudhri Darshan Singh need not indulge in "acting" as this is the House and not a Stage.) (Laugher]

ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ : ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਸ਼ੂਨਟਸ ਅਤੇ ਰਾਈਸ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕਿਟ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰ-ਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ ਹਾਰਡਲੀ 2 ਸਾਲ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਰਕਿਟ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪਜਾਬ ਮਾਰਕਿਟ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕਿਟ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਜਨ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਗਲਤ ਮਤਲਬ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਿ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿਚ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਯੂਨਿਟ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਹਨ—ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੇਲਜ਼ ਏਜੰਟਸ ਨੂੰ ਫਾਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਮਾਲ ਦੀ ਖਰੀਦੋਫਰੋਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਿਰਲਾਸਕਰ, ਊਸ਼ਾ ਔਰ ਦੂਜੀਆਂ ਵਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਾਈਪਸ ਬਣਾਂਦੇ ਹਨ, ਬੋਲਟਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

Mr. Chairman (Shri Roop Singh Phul) : The hon. Member may please wind up. The Deputy Minister for Industries, Shri Gian Chand Toto, is to speak at 11.45 A.M. by way of reply to the debate.

Chaudhri Darshan Singh : I shall wind up within five minutes.

Mr. Chairman : Only three minutes are at the disposal of the hon. Member.

ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ : ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਾਰਪਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਲ ਯੂਨਿਟਸ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿਚ ਆਪ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਇਹ ਕਾਰ-ਪੋਰੇਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੇਲਜ਼ ਏਜੰਟ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਤਾਕਿ ਉਹ ਮਾਰਕਿਟ ਵੀ ਕਰ ਆਉਣ ਔਰ ਸੈਰ ਵੀ ਕਰ ਆਉਣ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬਾਬੂ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਘਟ ਹਨ, ਪਰਾਫਟ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਅਗੇ ਨਾ ਵਧੇ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ? ਦੋ ਚਾਰ ਸਾਲ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਢ ਸਕੇਗਾ, ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਡਿਤ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਹੋਰਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੇਸ—ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਫੋਰਥ ਫਾਈਵ ਈਅਰ ਦਾ ਪਲੈਨ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਇੰਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਹ ਦਾਵਾ ਪਈ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਕੇਸ ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਪਰਲੀ ਪੁਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਪਰ ਜੇ ਐਗਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਜਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੀ।

Mr. Chairman : Please wind up.

ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਾਪਰਲੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਹਿੱਟ ਹੋਈ ਹੈ; ਇਸ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਹ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ; ਇਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਿਗ ਆਇਰਨ ਦਾ ਕੋਟਾ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਦੂਜੇ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਦਾ ਕੋਟਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਰਾ ਮੈਟਰੀਅਲ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਭੇਜਦੀ। ਜਿਤਨੀ ਇਸ ਦੀ ਲਾਈਫ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਤਨਾ ਇਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਔਰ ਇਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕਿਟ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਡੀ ਕਰਨਗੇ ਉਤਨੀ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। (ਘੰਟੀ)

ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਕੇ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗਾ । ਸ੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ— ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਮਨੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਸਤੇ-ਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੌ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰਜ਼ ਹਨ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰੀਦਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟ ਲਾਈਸੈਂਸ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ । ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੌ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਨਣ ? ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਨਾਉਣ ਤਾਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਘਟ ਹਿੱਸੇ ਹੋਣ ।

Mr. Chairman (Shri Rup Singh Phul) **:** The hon. Deputy Minister for Industries.

(At this stage, Chaudhri Net Ram rose to speak).

Mr. Chairman : I can understand the anxiety of the hon. Member but I have called upon the honourable Deputy Minister who has to speak only for 15 minutes by way of reply to the Debate.

चौधरी नेत राम: चेयरमैन साहिब, उन्होंने तो पंद्रह बीस मिनट बोलना है, मैं तो सिर्फ पांच मिनट का समय आपसे मांग रहा हूँ।

श्री **सभापति** : आप दूसरी मोशन पर बोल लेना । (The hon. Member may speak on the next motion.)

चौधरी नेत राम: मैं इसी रिपोर्ट की बाबत अपनी पार्टी के विचार हाउस में पेश करना चाहता हूँ।

श्री **सभापति**: मैं उनको पहले ही काल अपान कर चुका हूँ। (I have already called upon him to speak.)

चौधरी नेत राम: मैं इस मोशन पर अपनी पार्टी के ख्यालात रखना चाहता हूँ। मेरा भी बोलने का पूरा हक है । मैं असैम्बली में अपनी पार्टी के विचार रखने के लिये ही यहां पर आया हूँ।

Mr. Chairman : Order please.

चौधरी नेत राम: चेयरमैन साहिब, आप मुझे थोड़ा सा ही टाईम दे दो । मैं थोड़े से टाईम में ही अपनी बात समाप्त कर दूंगा ।

Mr. Chairman : I am sorry because I have already called upon the honourable Deputy Minister.

चौधरी नेत राम: चेयरमैन साहिब, मेरी गुज़ारिश यह है कि आप चाहें मुझे दो तीन मिनट के लिये ही समय दें लेकिन बोलने जरूर दें क्योंकि मैंने अपनी पार्टी का दृष्टिकोण इस सम्बन्ध में जरूर हाउस के सामने रखना है ।

श्री सभापति : अच्छा तो आप दो मिनट में अपनी बात कह लें। (Well the hon. Member may have his say within two minutes.)

चौधरी नेत राम (हिसार सदर) : बहुत अच्छा जी, मैं दो मिनट में ही अपनी बात समाप्त कर दूंगा। चेयरमेन साहिब, इस ऐक्सपोर्ट कारपोरेशन के सम्बन्ध में जो बहस इस वक्त हाउस में चल रही है इस के अन्दर हिस्सा लेते हुए में ज्यादा, आंकड़ों में नहीं जाना चाहता। आंकड़ों की बाबत तो बाबू बचन सिंह जी ने बड़ा खोल कर बता दिया है और अगर यह कांग्रेसी सरकार ज़रा भी शर्म रखती तो इसे चाहिए कि अपनी नीति को बदले। पंजाब एक ऐसा प्रान्त है जोकि खेतीबाड़ी पर मुनहस्सर करता है। इसका इनहिसार कृषि पर है मगर बड़े दुःख और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस कांग्रेसी सरकार ने कृषि को बढ़ाने की तरफ तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया है जिससे यह प्रान्त खुशहाल हो सके। बात तो ऐसी मालूम होती है गोया इस प्रान्त को खुशहाल बनाने का इस सरकार का कोई मतलब नहीं। इस सरकार का तो एक ही रवैया, एक ही पालिसी, एक ही नीति और एक ही तरीका है कि किस तरह से अपने दलाल पाले जाएं और उनकी जेबों को भरा जाए ताकि उनकी मारफत इलैक्शनों में जीत हासिल की जा सके। चेयरमैन साहिब, आपका ध्यान मैं इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूँ कि यह कारपोरेशन बनाई तो इसलिये गई थी कि इसके द्वारा अपने मुल्क में, अपने सूबा में पैदा हुआ हुआ माल दूसरे मुल्कों में भेजा जाए और दूसरे मुल्कों का माल यहां पर लाया जाए जिससे देश के अन्दर ताकत बढ़ाई जाए, कारखानों का और दूसरा फौजी सामान बढ़ाया जाए लेकिन मैं हैरान हूँ कि जिस देश को कृषि का देश कहा जाता है, जो कृषि प्रधान देश है जिस देश में किसी समय इतना अन्न पैदा होता था कि हिसाब नहीं, आज उसी देश को यह कांग्रेस की सरकार इस लायक नहीं बना सकी कि अन्न संकट दूर हो सके और दूसरे मुल्कों—अमरीका जैसे सरमायादार मुल्कों से अन्न के लिये मांग करने पर मजबूर हुई है। इस सरकार को तो न देश की तरक्की का ख्याल है और न ही इसे मज़बूत बनाने का ख्याल है। इस सरकार को एक ही बात का ख्याल है कि यह लुटेरे किस तरह से कायम रहें और अपने अड्डों को मज़बूत करते जाएं।

श्री सभापति : आपकी बात तो आ गई। अब बैठ जाइये। (He has given his point of view. He should now resume his seat.)

चौधरी नेतराम : चेयरमैन साहिब, मेरी बात अभी नहीं आई। कहते तो यह हैं कि हम अच्छी अच्छी चीजें बना कर इस कारपोरेशन की मारफत दूसरे मुल्कों को भेजेंगे। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब पानीपत के खेस दूसरे मुल्कों में भेजे गए तो उन लोगों को उनका रंग पसन्द नहीं आया, कपड़ा पसन्द नहीं आया क्योंकि घटिया किस्म का बना था। लेकिन करते क्या हैं? किसी सरमायादार की लड़की या लड़के को बाहर के मुल्कों की सैर कराने के लिये भेज दिया। कितनी शर्म की बात है। जाहिर है कि सरकार की नीति, इसकी पालिसी और यहां तक कि इसकी

नीयत साफ नहीं । अगर सरकार सूझबूझ, इमानदारी और साफ नीयत से काम करे तो कोई वजह नहीं कि देश की तरक्की क्यों न हो ।

(उपाध्यक्षा ने इस समय कुर्सी ग्रहण की)

डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आपके द्वारा अर्ज़ करूँ कि इस सरकार की नीयत बदलनी पड़ेगी । अगर यह सरकार अपनी नीयत नहीं बदलती और इसी तरह से हरबे इस्तेमाल करती गई तो वह दिन दूर नहीं जब देश का दीवाला निकाल देगी और इस देश को रसातल में पहुंचा देगी । इसलिये मैं इस हाउस के मैम्बरान से दरखास्त करना चाहता हूँ कि कैसे इस घटिया नीति रखने वाली, गलत नीति रखने वाली सरकार को बरदाश्त किया जा सकता है ? क्यों न ऐसी सरकार के खिलाफ बगावत उठाई जाए ? (घंटी) क्यों न ऐसी सरकार को यहां से हटा दिया जाए जिस सरकार की इस कदर घटिया नीति हो कि वह पंजाब की कृषि की समस्या को तो हल न करे, पंजाब की तरक्की का तो ख्याल न करे और इस प्रकार के नीच और घटिया तरीकों से सरमायादारों की जेबों को भरती रहे ? ऐसी सरकार किस तरह से कायम रह सकती है ?

उपाध्यक्षा : चौधरी नेतराम, आपकी तो थोड़ी सी बात का सभी लोगों पर असर हो जाता है । अब खत्म करें । (Even a few words from the hon. ember have tremendous effect on all. He should now conclude his speech.)

चौधरी नेत राम: डिप्टी स्पीकर साहिबा, लेकिन मैं हैरान हूँ कि इन अठारह सालों में आप पर मेरी बातों का क्यों असर नहीं हुआ । अब मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं आपकी बड़ी इज्ज़त करता हूँ आप विदेश से अच्छे ख्यालात लेकर वापिस आई हैं, घूम कर आई हैं और आपकी अकल की बातों का इस कांग्रेसी सरकार पर भी असर होना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप उनको समझाएं। इन शब्दों के साथ मैं अपनी जगह पर बैठता हूँ।

उद्योग तथा पहाड़ी क्षेत्र उप मंत्री (श्री ज्ञान चंद): आदरणीय डिप्टी स्पीकर, साहिबा, मुझे इस बात की खुशी है कि इण्डस्ट्री को तरक्की देने के प्वायंट आफ वियू से जो यहां दो कारपोरेशन्ज़ बनी हुई हैं जोकि बड़ी इम्पार्टेंस रखती है, आज उन पर बहस हो रही है । मुझे इस बात की भी खुशी है कि पंजाब फाइनैंशल कारपोरेशन की इस हाउस में बड़ी सराहना की गई है । मुझे यह बताते हुए खुशी होती है कि जब से पंजाब फाइनैंशल कारपोरेशन बनी है, उसके जो हर साल के जो नतीजे हैं वह अच्छे होते जा रहे हैं। 1959–60 में जहां इसने 51 लाख रुपये के कर्ज़े लोगों को दिये थे वहां इसने 1963–64 में एक करोड़ और 32 लाख रुपये के कर्ज़े दिये हैं। अभी अभी पंडित मोहन लाल ने आपके सामने बताया है कि सारे हिन्दुस्तान में जो इस तरह की कारपोरेशन्ज़ हैं उन तमाम के रिज़ल्टस देखने के बाद कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि उन सब से पंजाब फाइनौनशल कारपोरेशन का रिज़ल्ट अच्छा है । लेकिन इसके साथ ही कुछ भाइयों ने इसकी वर्किंग की

[उद्योग तथा पहाड़ी क्षेत्र उप मन्त्री]

नुक्ताचीनी भी की है, जो मैं समझता हूँ कि यह उन की कुछ गलतफहमी की वजह से उन्होंने की है। मसलन यह कहा गया है कि इस कारपोरेशन ने अभी तक अण्डर राईटिंग शुरू नहीं की। दरअसल बात यह है कि इसको ऐसा करने के लिये रिज़र्व बैंक आफ इण्डिया ने पहले इजाज़त नहीं दी थी आज से दो साल पहले इसके लिये इजाजत मांगी थी। लेकिन मुझे यह बताने में खुशी होती है कि पंजाब गवर्नमेंट का इण्डस्टरी डिपार्टमेंट पिछले दो सालों से अण्डर राईटिंग कर रहा है और चौथे प्लान के लिये इसने पांच करोड़ रुपये की प्रोवीज़न की है। इस सिल-सिले में रिज़र्व बैंक आफ इण्डियां के डिप्टी इकानामिक एडवाईज़र मिस्टर रामा कृष्णन यहां आए थे उन्होंने यह काम कारपोरेशन के हवाले करने के बारे में अपनी रिपोर्ट दी है उस रिपोर्ट पर पंजाब सरकार गौर कर रही है और उम्मीद है कि चौथे पांच साला प्लान में यह काम पंजाब फाइनैंनशल कारपोरेशन के हवाले कर दिया जाए।

दूसरी बात यहां पर यह कही गई है कि लोन देने का जो प्रोसीजर है, वह बड़ा कम्बरसम है और इसकी वजह से लोगों को लोन लेने में काफी देर ग जाती है। यह बात मैं स्वीकार करता हूँ लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब इस बात को स्वीकार करेंगे कि लोन देते वक्त इस बात की एहतियात रखनी जरूरी होती है कि जो लोन दिया जाए वह कहीं बैड डैट न हो जाए और इसी मकसद को पूरा करने के लिये यह सारा प्रोसीजर बनाया हुआ है। और आप यह देखेंगे कि जिस वक्त से पंजाब कारपोरेशन लोन देने का काम कर रही है आज तक इस का एक भी कर्जा बैड डैट नहीं हुआ। अगर कोई मैम्बर साहब इस बारे में कोई बेहतर तरीकाकार बताएं तो हम उस पर गौर कर लेंगे। पंजाब सरकार इस पर अमल करने को तैयार होगी अगर वह ठीक समझेगी। लेकिन जहां तक एप्लीकेशन्ज़ फार लोन्ज़ देने की डेट का और लोन के सैंक्शन होने की डेट का सवाल है, इसमें जो ज्यादा वक्त लगता है इसके लिये न तो पंजाब गवर्नमेंट ही ज़िम्मेवार है और न ही कारपोरेशन ही ज़िम्मेवार है। इस बारे में जो एनकुआयरीज़ कारपोरेशन करती है उनका जवाब देने में एप्लीकेंट्स देरी लगा देते हैं।

इसके अलावा एक बात और कही गई है कि पंजाब फाइनैंनशल कारपोरेशन ने अभी तक कोई डिवीडैंड नहीं दिया, और यह सिर्फ तीन परसैंट ही डिवीडैंड दे रही है। इस बारे में मैं अर्ज़ करता हूँ कि इस बारे में जो गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने कानून बनाया हुआ है, उसके मुताबिक पह कारपोरेशन तीन परसेंट डिवीडैंड दे ही नहीं सकती। मैंबर साहिबान को यह जानकर खुशी होगी कि इस बारे में पंजाब सरकार ने आलरेडी गवर्नमेंट आफ इण्डिया को मूव किया हुआ है कि यह डिवीडैंड कम अज़ कम जो बैंक रेट हो उसके बराबर कर देना चाहिए यानी जहां तक बैंक रेट हो उस हद तक यह डिवीडैंड दिया जाना चाहिए। इसके अलावा सूद की शरह के बारे में भी कहा गया है। इस बारे में मैं अर्ज़ करता हूँ कि यह कारपोरेशन खुद 6 परसेंट सूद पर रुपया लेता है और यह 9 फीसदी के हिसाब से आगे सूद पर देता है। इस तरह से

यह अपना खर्चा करके इसको कोई आधा परसैंट प्राफिट होता है जो कोई ज्यादा नहीं है। मैं समझता हूँ कि यह 9 परसैंट सूद का लोन कोई ज्यादा नहीं है क्योंकि बाजार से इण्डस्ट्रियलिस्टस 12 परसेंट सूद पर भी लोन लेने को तैयार रहते हैं। अगर आप यह चाहें कि यह 9 परसेंट के हिसाब से सूद न लेकर कम रेट पर लेकर लोन लोगों को दे और घाटा खाए तो यह कोई अकलमन्दी की बात नहीं होगी। आज अगर 9 परसेंट पर भी इण्डस्टरी को लोन मिल जाए तो यह बड़ी गनीमत है।

कुछ मैम्बर साहिबान ने एक और एतराज़ किया है कि पंजाब फाईनैंशल कारपोरेशन सिर्फ चन्द कनसर्न्ज़ को या चन्द कम्बीनेशन आफ कनसर्न्ज़ को ही कर्ज़ देती है और बाकी को नहीं देती है। मैं समझता हूँ कि उनका यह एतराज़ गल्तफहमी पर मबनी है और इसमें सचाई नहीं है। इस कारपोरेशन ने आज तक 495 फर्म्ज़ को कर्ज़ा दिया है और यह बात नहीं है कि किसी सर्टेन सैट अप आफ फर्म्ज़ को दिया गया हो और दूसरे सैंट अप को इनकार किया गया हो। आजतक किसी लार्ज स्केल में रिजेक्शन नहीं की गई और सिर्फ उन्हीं के केस रिजेक्ट किये गए हैं जिनको यह देखा गया था कि अगर उनको लोन दिया गया तो वह बैड डेट हो सकता है।

Deputy Speaker : Next item on the Agenda, Please.

Comrade Shamsher Singh Josh (Rupar) : Madam, I b eg to move—
That the matter.............

श्री बलरामजी दास टण्डन: डिप्टी स्पीकर साहिबा, जो नुक्ताचीनी पंजाब एक्सपोर्ट कारपोरेशन पर की गई है उसका जवाब गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दिया गया।

उपाध्यक्षा : अगर हर चीज़ आपके कहने के मुताबिक हो तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इस बहस के लिये सिर्फ दो घंटे का टाइम मखसूस किया गया हुआ था और इसी वक्त में जितना जवाब मिनिस्टर कनसर्ड दे सकता था वह उसने दे दिया है। (If everything were to be done according to the sweet will of the hon. Member then lot of difficulties would arise. Only two hours time had been fixed for the discussion and during this period whatever reply the Minister concerned could give he has given.)

श्री बलरामजी दास टण्डन: आन ए प्वायंट आफ आडर, मैडम। मेरा प्वायंट आफ आर्डर यह है कि अगर इसी तरह से यहां तर डिस्कशन होनी है तो उसका——

Deputy Speaker : Comrade Shamsher Singh Josh is on his legs. No. Point of Order, please.

Shri Balramji Das Tandon : You must listen to me Madam. Iam on a point of Order.

Deputy Speaker : You should not waste the time of the House.

Shri Balramji Das Tandon ; Under what rule, are you disallowing my Point of Order ?

Deputy Speaker : Please take your seat.

श्री बलरामजी दास टण्डन : आप कोई ऐसी बात बतायें या कोई रूल बताएं जिसके तहत आप मेरा प्वायंट आफ आर्डर सुनने से इनकार कर रही हैं। वह कौन सा रूल है जिसके तहत आप मुझे अपना प्वायंट आफ आर्डर रखने से रोक रही हैं ?

उपाध्यक्षा: आप डंडे के जोर से मुझे अपना प्वायंट आफ आर्डर सुनाना चाहते हैं; इसकी मैं इजाज़त नहीं दे सकती । (The hon. Member wants me to hear his point of order under duress; I cannot allow that.)

Shri Balramji Das Tandon : I must be allowed to raise my Point of Order.

Deputy Speaker : No, please. I object to the way in which yon want to raise your Point of Order.

श्री बलरामजी दास टण्डन: मैंने तो अपना प्वायंट आफ आर्डर रेज़ करना है...

उपाध्यक्षा : आर्डर प्लीज़। जब मैं खड़ी हूँ तो आप क्या बैठेंगे नहीं ? आप इतने पुराने मैंबर हैं आप से तो इस बात की तवक्को नहीं की जा सकती। (Order please. When I am on may legs will the hon. Member not take his seat ? He is a Member of long standing and his behaviour is not expected of him.)

श्री बलरामजी दास टण्डन : आप खड़ी हैं तो मैं बैठ जाता हूँ लेकिन आप मुझे अपना प्वायंट आफ आर्डर रेज़ कर लेने दें ।

उपाध्यक्षा : अच्छा आप अपना प्वायंट आफ आर्डर रेज़ कर लें । (Very well. Let the hon. Member raise his point of order.)

श्री बलरामजी दास टण्डन : मेरा प्वायंट आफ आर्डर यह है कि यहां पर दो अलग अलग कारपोरेशन्ज़ पर बहस हुई है मगर एक पर हुई बहस का जवाब तो दिया गया है, लेकिन जो बातें यहां पर दूसरी कारपोरेशन के बारे में कही गई हैं, उनके जवाब में कुछ ही नहीं कहा गया तो इस बारे में मैं आपका रूलिंग चाहता हूँ कि क्या उसका जवाब गवर्नमेंट की तरफ से आना ज़रूरी नहीं है ?

उपाध्यक्षा: मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकती कि वह ज़रूर उसका रिप्लाई दे। (I cannot force any body that he must necessarily reply to a certain point.)

मुख्य संसत् सचिव (श्री राम प्रताप गर्ग) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं तो जवाब देने के लिये अपनी सीट में राईज़ हुआ था लेकिन आपने टाइम न होने की वजह से इजाज़त नहीं दी थी । मेरे अलावा चीफ मिनिस्टर साहब भी खड़े हुए थे ।

उपाध्यक्षा : टण्डन साहब, आपको यह भी ख्याल नहीं आया कि चीफ मिनिस्टर साहब, इस बहस का जवाब देने के लिये खड़े हुए थे लेकिन वह जवाब नहीं दे सके थे क्योंकि मैंने उन्हें टाइम नहीं दिया था । और मैंने इसलिये टाइम नहीं दिया था क्योंकि मैं यह नहीं चाहती थी कि किसी दूसरे के साथ बेइनसाफी हो। अच्छा आप अपनी बारी पर 25 मिनट बोले हैं। इस तरह इजाज़त नहीं दे सकती । (Addressing Shri Tandon) (The hon. Member does not appear to remember that the Chief Minister had arisen to give a reply to the discussion but he could not do so as I did not give him the time. The reason I did so was that I did not want any injustice to be done to others. The hon. Member himself spoke for 25 minutes in his own turn. Now I cannot permit him for this.)

12.00 Noon

श्री बलरामजी दास टण्डन : 5 मिनट तो तब भी थे । अब 12 बजे हैं।

MOTION UNDER RULE 84 REGARDING MATTER RELATING TO LEASING OF 1000 ACRES AGRICULTURAL FARM NEAR RUPAR TO BIRLA BROTHERS.

Comrade Shamsher Singh Josh (Ruper) : Madam, I beg to move—

that the matter relating to leasing of 1000 acres Agricultural Farm near Rupar to Birla Brothers be discussed.

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਰਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਰਮ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੀ ਕੈਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ।

(ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਾ: ਬਲਦੇਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਬਲਰਾਮ ਜੀ ਦਾਸ ਟੰਡਨ ਮਿਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਬੈਂਚਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ।)

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ । (Now other members will object that they are not being listened to.)

श्री रूप सिंह फूल : On a point of order, Madam. क्या सारे जन संघी मैंबर कांग्रेस में आ गए हैं ?

उपाध्यक्षा: अभी इरादा कर रहे हैं। (They are making up their minds.)

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿਘ ਜੋਸ਼ : ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਬਿਰਲਾ ਬਰਾਦਰਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਨ ਤਕ ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ ਕੈਨੇਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਰੀਕਲੇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕੈਰੋਂ ਮੰਤ੍ਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੀਤ

[ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼]

ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਰੀਸਰਚ ਡਿਪਾਰਟ-ਮੈਂਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਉਪਲ ਨੇ ਇਕ ਬੁਕਲੈਟ ਛਾਪੀ ਸੀ। ਇਸ ਬੁਕਲੈਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਢਾਈ ਤਿੰਨ ਲਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਕਲੇਮ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਬਨਾਉਣ ਵਿਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਾਮਰੇਡ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ : On a point of order, Madam. ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਨਚਾਰਜ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਊਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਨਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।

उपाध्यक्षा : इनकी बात मुनासिब है, मिनिस्टर इन्चार्ज ज़रूर होना चाहिए। (He has raised a reasonable point The Minister-in-charge must be present in the House.)

मुख्य संसद सचिव (श्री राम प्रताप गर्ग) : सरदार दरबारा सिंह जी कमिशन के सिलसिले में बिज़ी हैं अभी आ जायेंगे। (Sardar Darbara Singh is busy in connection with the work of a Commission. He will be here shortly.)

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : ਦੂਜੀ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਰਲਾ ਬਰਾਦਰਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਰੀਕਲੇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫਾਰਮ ਸੀ। A Development Farm was already in existence which was being run by the Irrigation and Power Research Directorate. ਉਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਪਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਲੈਂਡ ਓਨਰਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਇਵੈਕਵੀ ਲੈਂਡ। ਲੈਂਡ-ਓਨਰਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਮਤਲਬ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹਾਲੇ ਤਕ ਮਾਲੀਆ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਈ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫਾਰਮ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਬਿਰਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਮਗਰ ਮਾਲੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਲੀਗਲ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਕੀ ਹਨ, ਕੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਵੈਕ ਵੀ ਲੈਂਡ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਐਕਸਪੈਕਟ ਬਾਰੇ ਦਸਿਆ ਜਾਵੇ। (ਵਿਘਨ) ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰੀਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਇਹ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਪਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਇਵੈਕਵੀ ਲੈਂਡ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਡ-ਓਨਰਜ਼ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਰਲਾ ਬਰਾਦਰਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਮੰਸ਼ੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਲਈ, ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਮਹਿਕਮਾ ਬਣਾਇਆ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਰਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਹੁਣ ਰੀਵਰਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਿਰਲੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕ ਅਮੀਰ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਐਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ

ਦਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਬਿਰਲੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐਗਰੀਕਲ-ਚਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਿਚ ਮਾਹਰ ਸੂਬਾ ਤੇ ਇਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਖਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਥੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਫਾਰਮ ਖੋਲ੍ਹੋ ਤਾਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸੀਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੀ ਸਾਡਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਇਤਨਾ ਅਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਬਿਰਲੇ ਨੂੰ ਸਦਣਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਬਿਰਲੇ ਨੇ ਖੁਦ ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਦਿਉ ਜਿਸਨੂੰ ਮੈਂ ਉਥੇ ਮੈਨੇਜਰ ਲਗਾ ਦਿਆਂ। ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਹੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਇਕ ਰੀਟਾਇਰਡ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਉਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ?

(At this stage Shri Ram Saran Chand Mital, a member of the Panel of Chairmen, occupied the chair.)

ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਗਰ ਇਵੈਕਵੀ ਲੈਂਡ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚ ਤੇ ਉਹ ਰੀਕਲੇਮ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਖੁਦ ਹੀ ਖੂਹ ਲਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਨੂੰ ਰੀਕਲੇਮ ਕਰਨ ਤੇ 93,535 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਿਰਲੇ ਨੂੰ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਸਬਕ ਦੇਣ ਲਈ ਇਥੇ ਸਦਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇਕ ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਹੀਯੋਗ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਪੁਛਦ ਹਾਂ ਜਦ ਕਿਸੇ ਹਰੀਜਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਤੇ ਖੋਟਾ ਧੇਲਾ ਵੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਬਿਰਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਕਲੇਮ ਕਰਕੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਦੇ ਕਰਕੇ, ਬਾਰਬਡ ਵਾਇਰ ਲਾਕੇ ਅਤੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਵਿਆਹੀ ਦੁਲਹਨ ਵਾਂਗੂ ਸਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲਉ ਸਾਂਭੋ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉ।

ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋ-ਪਰਾਫਿਟ ਨੋ-ਲਾਸ ਬੇਸਿਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਜ਼ਰਾਇਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਮਣ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਹੈ ਨੋ-ਪਰਾਫਿਟ ਨੋ-ਲਾਸ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਐਗਰੀ ਕਰ ਲਿਅ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦ ਕਦੇ ਬਿਰਲੇ ਦਾ ਮਨ ਛਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਖਾੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਇਕ ਸਕੈਂਡਲਸ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ 30 ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ 25 ਸਾਲ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਵ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਇਥੇ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਬਿਰਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਆਲੂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 180 ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਰਲੇ ਨੂੰ

[ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼]

30 ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 1,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਇਹ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਕ ਲਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸਤਰ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ $17\frac{1}{2}$ ਲਖ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਏਗਾ।

For Rs. $17\frac{1}{2}$ lakhs that land has been leased out to Birla Brothers for 25 years. I suspect some doubtful deeds in the matter.

ਇਹ ਸਾਢੇ ਸਤਾਰਾਂ ਲਖ ਦਾ ਨਫਾ ਬਿਰਲੇ ਨੂੰ ਖਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਫਰਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਇਹ ਨੋਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਸਦਾ ਫਿਨਾਂਸਲ ਮਦਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਫਰਮ ਦੀ ਯਾਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉਤਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

With this background of doubtful deeds in the matter to the Congress party ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਕਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਬਿਰਲੇ ਪਾਸ ਗਏ ਸੀ। ਜਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਦਾ ਦੌਰ ਪਿਛੇ ਚਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 35 ਲਖ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਲਵਾ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਲਏ ਗਏ। ਆਖਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੰਦਾ ਦਿਉ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਨਾ ਲੋੜ ਹੈ ਲੈ ਲਉ। ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਚਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਫਾਰਮ ਬਣਾ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹਰਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ:

M/s Birla Brothers were reported to have been asked by the Central Government to assist in the production and distribution of quality seeds, particularly, wheat seeds.

ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਸਤਾਰਾਂ ਲਖ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਫਾਰਮ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ ਵਲੋਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

No tenders were invited. No negotiations were done.

ਫਿਰ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਿਨਾ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਅਤੇ ਕੁਟੇਸ਼ਨਾਂ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਟੈਂਡਰ ਕਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੇਕਰ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਟੇਸ਼ਨਾਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਥੇ ਲਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੋਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਟੈਂਡਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪਰ ਇਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸੋਦੇ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀਹ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਖਾਂ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਵੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪਟੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਲੈਂਡ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਆਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਉ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖ ਲਉਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਿਧੇ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ 1,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਆਪ ਹੀ ਹਾਂ ਕਰ ਆਏ।

ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤਿੰਨ ਰੀਜ਼ਨ ਸਨ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਟੇ ਤੇ ਦੇਣ ਦੇ। ਉਹ ਸੁਣ ਲਉ।

'Setting up of big commercial viable Farms in Sutlej area would be most conducive to the increased agricultural production. Allotment to Harijans or poor cultivators would not have permitted large-scale mechanised cultivation and production of quality foundation seeds.

ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਲੀ ਲਖ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਨਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਥੇ ਬੈਠੇ ਹਰੀਜਨ ਐਮ. ਐਲ. ਏਜ਼. ਸਾਹਿਬਾਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਰੰਟ ਇਸ ਡੀਲ ਰਾਹੀਂ ਕਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

(ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਚੌਧਰੀ ਚਾਂਦ ਰਾਮ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ।)

ਆਵਾਜ਼ : ਲਉ ਚੌਧਰੀ ਚਾਂਦ ਰਾਮ ਜੀ ਆ ਗਏ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉ।

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਕ ਵੇਰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਇਸ ਵਿਚ ਰੀਜ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ—

Setting up of big commercial vaible Farms in Sutlej area would be most conducive to the increased agricultural production. Allotment to Harijans or poor cultivators would not have permitted large scale mechanised cultivation and production of quality foundation sees.

[ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼]

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਅਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ । ਇਥੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੈਕਾਨਾਇਜ਼ਡ ਫਾਰਮ ਬਨਾਣੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਹਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ । ਨਾ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਨਾ ਟਯੂਬਵੈਲ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਮਰਸ਼ਲ ਵਾਇਬਲ ਫਾਰਮ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਣਾ ਬਿਰਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰ ਸਹੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਹੇ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਬਿਰਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਫਿਰ ਥਾਪਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਰੀ ਆ ਜਾਏਗਾ । ਮੈਂ ਇਥੇ ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਚ ਡੀ. ਸੀ. ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 20-20 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪਟੇ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਫਾਰਮ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ।

ਨਾਂ ਤੇ ਬਿਰਲੇ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡਿਆਂ-ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਕਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਜਿਨੀ ਵੀ ਆਮਦਨ ਚਾਹੇ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜ ਲਖ ਦੀ ਹੋਵੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੰਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ । ਬਿਰਲਾ, ਥਾਪਰ ਅਤੇ ਪੁਰੀ ਆਦੀ ਵਰਗੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਛੁਪਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ।

ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਜੋ ਨੀਤੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੀ, ਉਹ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫਾਰਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਟਯੂਬਵੈਲ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਮਿਡਲ ਪੈਜ਼ੈਂਟਰੀ ਮੈਕਾਨਾਇਜ਼ਡ ਫਾਰਮਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕੇ । ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਤੇ ਜੈਪੁਰ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ—

> "There is no way except to go back to the Nagpur Resolution and implement it in all earnestness. There are difficulties involved in inducing 300 million Kisans to change from old to new ways but I feel if the proposals are conveyed to them thtat they are all to their material benefit they would accept them. They are reluctant to change the *status quo* for something that has not been properly explained to them but misrepresented to them by all types of reactionary people."

ਪੰਡਤ ਜੀ ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ middle ਕਲਾਸ ਦੇ peasant ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ co-operative farms ਜੇ ਬਣਾ ਦਿਉ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਮਸਲੇ ਹਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਫਾਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ

ਇਮਦਾਦ ਦਿਉਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ । ਤੁਹਾਡੀ P.L.480 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆ ਰਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕਣਕ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ । ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਤ ਗੜ੍ਹ ਫਾਰਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ even hundred such farms cannot solve the food problem of thec ountry । ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਖਾਸ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸੁਭਰਾਮਨੀਅਮ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ—

> "*Calcutta. October, 25.* Private joint stock companies are after all, likely to be allowed to reclaim waste land for foodgrain production, Union Food Minister Subramaniam said here today in reply to a question. He said there might be leasing waste land in various States for the purpose. The proposal was being considered and a decision would be taken shortly."

ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਦਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਪਰਚਾ 28-29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਇਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਪਰੋਫੈਸਰ ਤੋਂ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ, ਛੋਟੀ ਪੈਂਜ਼ੇਂਟਰੀ ਨੂੰ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇ । ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਨੀਤੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਫਾਰਮ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਏਥੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਸਟਾਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਪੱਟੇ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਦੋਂ ਫੂਡ ਮਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਫੂਡ ਮਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਏ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬੜਾ ਸੀਰਿਅਸਲੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਜੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਰਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਬਾਇਸ ਹੋਵੇਗਾ । ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਕ ਤਾਂ ਹੈ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਨਾ ਨੀਤੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਯੋਰੋਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼—ਫਰਾਂਸ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਜਰਮਨੀ, ਵਿਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਜੁਆਇੰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਇਕ ਨੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਉਥੇ ਪਹਿਲੋਂ ਪਹਿਲ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਢਿਆ ਗਿਆ, ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਲੈਂਡ-ਲਾਰਡ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਰਮਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ । ਘਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਘਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਮਾਇਦਾਰਾਨਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੜ ਤੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ । ਉਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਸੈਕਟਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ । ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਹੀ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ।

[ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼]

ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਅਮਰੀਕਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਇਥੇ ਅਨਕਲਟੀਵੇਟਿਡ ਜੰਗਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਉਸ ਨੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਜਗਲ ਵਗਲ ਲਏ ਅਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਆਪਣੇ ਨਾਉਂ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਥੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ-ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਰਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

Reversal of Nehru's policy in Agriculture Sector.

ਤੀਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਆਪਰੇਟਿਵ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਰਮਿਆਨੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰਜ਼ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਡਰਨ ਢੰਗ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ।

Mr. Chairman (Shri Ram Saran Chand Mital) : The hon. Member should please wind up now.

Comrade Shamsher Singh Josh : I may be permitted to speak for five minutes more ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੈਕਨਾਈਜ਼ਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਫਾਰਮਜ਼ ਦੇ ਅਗੇਨਸਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜੋ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਫਾਰਮਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਡਰਨ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਨਾਲ ਵੈਲ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ਡ ਹੋਣ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੋਵੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੀਵੈਲਪ-ਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ । ਜੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੋ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੰਕਚੂਆਲਾਇਜ਼ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਇਤਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਮਣ ਹੋਰ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਉਪਜ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਇਸ ਤੇ ਉਲਟ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਰਲਿਆਂ ਟਾਟਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋਕ ਇਤਨੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਏਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ ਜੇਲ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਵੇ । ਇਹ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ

ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਬਿਰਲੇ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਤੇ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ । ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ, ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਆਮਲੇ ਤੇ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਹਰਗਿਜ਼ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ । ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਰਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਰਮਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ । (ਤਾਲੀਆਂ)

Mr. Chairman (Shri Ram Saran Chand Mital): Motion moved—

That the matter relating to leasing of 1,000 acres Agricultural Farm near Rupar to Birla Brothers be discussed.

Mr. Chairman : Sardar Gurdarshan Singh.

Sardar Gurnam Singh : Mr. Chairman, Sir, I am one of the movers of the motion.

Mr. Chairman : I have already called upon the hon. Member Sardar Gurdarshan Singh. Let him speak first.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਕੇਵਲ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 10-10 ਮਿੰਟ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਮੁਕਰਰ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ ਦੋ ਦੋ ਮਿੰਟ ਮਿਲਣਗੇ ।

चौधरी नेत राम : चेयरमैन साहिब, यह तो एक बहुत अहम मसला है, एक तरफ तो यह सरकार जागीरदारी को खत्म करती है और दूसरी तरफ इन बिरलों को जमीन देकर जागीरदारी खत्म नहीं कर रही। हम चाहते हैं कि इस मामले पर ज़्यादा से ज़्यादा बहस होनी चाहिए ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ (ਨਾਭਾ) : ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਮੁਤਲਿਕ ਇਕ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਮਤੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਲਿਆਵਾਂਗੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਭੁਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਬੇਟ ਏਰੀਆ ਦੀ ਰੀਕਲੇਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਬਿਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। (ਤਾਲੀਆਂ)

[ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ]

ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਲਈ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 16-11-64 ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਗੈਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਬੇਟ ਏਰੀਆ ਦੀ ਹੈ ਬਿਰਲੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਜਨਵਰੀ, 1965 ਤਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਲੈਵਲ ਤਕ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ। ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਐਂਡ ਤਕ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਸਪੀਡੀਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਕੇਸ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਫ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਸ ਦਾ ਹੱਥ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਥ ਗਰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਾਈਲਾਂ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਕੀ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਰੁਕੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। (ਤਾਲੀਆਂ)

ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਰਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੀਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ, ਗੌਰਮਿੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੰਨਸਰਨ ਦਾ ਇਕ ਐਡਵਰਟਿਜ਼ਮੈਂਟ* ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਵੀ ਲੇ* ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਵਿਚ ਹੈ—

"LAND FOR SEED FARMS
OFFERS INVITED.

Large blocks of land of 500 acres or more area are required for developing seed farms. The land should be fertile, levelled and well-drained, having irrigation facilities. Offers for sale or long lease would be considered. For details please contact personally or write to :—

The General Manager,
National Seeds Corporation Ltd.
(A Government of India Undertaking),
F-35, South Extension Part 1, New Delhi—3".

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਆਫਰ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੀਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਹੀ ਆਫਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ।

ਮੈਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਦੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ—

(Page 9 of the memorandum)

"Agriculture († Rs 66 lakhs)—The increase is mainly due to large provision made for (a) grants to the Agriculture University (Rs 24 lakhs) and (b) purchase of improved seeds for sale to cultivators (Rs 42 lakhs)"

---

*NOTE—Kept in n the library.

ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਿਕੰਮਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ 42 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਲਟੀਵੇਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਮਪਰੂਵਡ ਸੀਡ ਖਰੀਦੇ। ਬਿਰਲੇ ਨੂੰ ਜੇ ਸੀਡ ਫਾਰਮਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ?

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ 146 ਸੀਡ ਫਾਰਮਜ਼ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਮਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸੀਡ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਮਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਆਫਰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਮਗਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਗਰ ਬਾਹਰਲੇ ਵਡੇ-ਵਡੇ ਬਿਰਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (Thumping)

ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਰਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਹਵੇਲੀ ਕਲਾਂ, ਬੜਾ ਫੂਲ, ਛੋਟਾ ਫੂਲ, ਨਾਨੂਵਾਲ, ਛੋਟਾ ਸਤਨਾਪੁਰ, ਬੜਾ ਸਤਨਾਪੁਰ, ਵਿਚ 958.28 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸਦੇ ਵਿਚ 651 ਏਕੜ ਨਾਨ-ਇਵੇਕੂਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਰੇਟ 100 ਰੁਪੈ ਏਕੜ ਹੈ। ਮਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਬਿਰਲੇ ਨੂੰ ਕਿਤਨੇ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੈਬੀਨਿਟ ਇਕ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ 16-11-1964 ਨੂੰ, ਔਰ ਛੇਤੀ ਹੀ, ਫਸਟ ਵੀਕ ਆਫ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨਟਰੈਕਟ ਸਾਇਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤਨੀ ਐਫੀਸੇਂਟਲੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਹੋਰ ਕੇਸਿਜ਼ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਲੀਜ਼-ਡੀਡ ਦਾ ਇਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ :

> "The leased land detailed in the Schedule 'A' attached herewith to be leased out will comprise the developed Farm which has been established near Rupar by the Director, Irrigation and Power Research of which about 150 acres remain to be reclaimed and covers an area of about 1,000 acres ...."

ਯਾਨੀ 150 ਏਕੜ ਲੈਂਡ ਜਿਸਦੀ ਰਿਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਰਿਕਲੇਮਡ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਨ-ਰਿਕਲੇਮਡ ਲੈਂਡ ਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ—

> "The lessor would be responsible for the maintenance of the Budki and Sutlej bunds to prevent the flooding of the leased land and would also make arrange ments for the external drainage of the leased land by making and maintaining suitable outlets in these bunds."

ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਗ੍ਰੀਕਲਚਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਲਕਿ ਦਰਿਆ ਦੀ ਲਿਆਈ ਹੋਈ

[ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ]

ਮਿੱਟੀ ਬੜੀ ਉਪਜਾਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਥੇ ਬੰਪਰ ਕ੍ਰਾਪਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਵਸੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਹੀ ਹਨ, ਇਹ ਜੋ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲੀਟੀ ਲਈ ਹੈ ਕਿ the lessor would be responsible for the maintenance of the Budki and Sutlej bunds to prevent the flooding of the leased land and would also make arrangements for the external drainage of the leased land by making and maintaining suitable outlets in these bunds.

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਧ ਟੁਟਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੂੰ ਕੰਪੈਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਥੇ ਗਿਆ ਉਹ ਲਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪੈਨਸੇਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬੀਸੀਐਂ ਕਲਾਜ਼ਾਂ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਆਦਮੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕਲਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਚੂੰਕਿ ਉਹ ਤਗੜੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਕਮਪੈਨਸੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। (ਘੰਟੀ) ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ—

"To begin with the lessee will be supplied foundation seed by the Department of Agriculture of Punjab Government and the lessee shall grow registered seed. The lessee shall be free to either sell the registered seed to the Agriculture Department , Punjab on the usual terms (which include a premium of Rs 5 per quintal at present) or to process, bag and sell their seeds under their own lable whenever and wherever they like."

ਯਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜ ਵੀ ਮੁਹੈਯਾ ਕਰੇਗੀ, ਫੇਰ ਜਦ ਉਹ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਬੀਜ ਵੇਚਣ ਤਾਂ ਗੌਰਮਿਟ 5 ਰੁਪਏ ਪਰ ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਫੇਰ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਕਿ ਉਹ ਮੈਕਸੀਮਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਖਟਣ ਲਈ ਜਿਸਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਵੇਚਣ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਔਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਜ਼ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰਖੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੇ ਮੁਫਾਦ ਦੇ ਬਰਖਿਲਾਫ ਹਨ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸ਼ਤਬਾ ਇਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ। ਮੁਸ਼ਤਬਾ ਨੂੰ ਏਥੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗੇ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ (ਰਾਏਕੋਟ) : ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਆਤ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਬੋਲੇ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਏਤਕਾਦ ਰਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਸਲ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਸੀ,

ਹੁਣ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਸੂਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਖੁਦ ਵਾਹੇਗਾ ਭਾਵ ਟਿਲਰ ਆਫ ਦੀ ਲੈਂਡ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਹਰੀਜਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਛੋਟੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ । ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੀਜਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਉਚਾ ਲੈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਰਲੇ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲੈ ਆਈ ਹੈ । (ਵਿਰੋਧੀ ਪਖ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸੰਸਾ) ਐਨਾ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਰਲੇ ਨੂੰ ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਰਲੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।

(*Deputy Speaker in the Chair.*)

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿਉ ! ਇਸ ਨੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ! ਕੋਈ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਦੇਣਾ ਹੈ । ਕਲ੍ਹ ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗੁਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪੁਛਿਆ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਨਹੀਂ ਪਈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ—

> "Messrs Birla Brothers were reported to have been asked by the Central Government to assist in the production and distribution of quality seed, particularly wheat seed."

ਸੋ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੁਰੱਅਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਅਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਉਤੇ ਨਾ ਠੋਸੋ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਠੋਸਣ ? ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆ ਬਿਰਲਾ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮਨਿਸਟਰ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਿਰਲੇ ਦੇ ਜ਼ੇਰੇ ਬਾਰ ਨੇ । ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰੁਪਿਆ ਲੈਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਐਸਾ ਪਰੋਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਰਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ । ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਬੁਜ਼ਦਿਲੀ ਹੈ । ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦ ਬੋਲਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਕੇ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚਿਠੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਰਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਰਲੇ ਨਾਲ ਐਨੀ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਸਟਰੀ-ਬਿਊਸ਼ਨ ਦੋਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ । ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਨਾਫਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰ ਜੋ ਚਾਹੇ ਲੇਬਲ ਲਾ ਕੇ ਕਰ ਦੇਵੇ । ਮੇਰੇ ਫਾਜ਼ਲ ਦੋਸਤ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਬਿਰਲੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਤਨੀ ਨਾਕਾਰਾ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਯਾ ਬਹਾਨਾ ਹੈ, ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ? ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਭੁਖੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ । ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਕ ਇਕ ਏਕੜ ਦੇ ਕੇ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਾ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਨਾ ਹਰੀਜਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਨੂੰ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬਿਰਲੇ ਨੂੰ ਇਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰਸਰ

[ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ]

ਇਕ ਧੋਖਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਬਿਰਲੇ ਨੂੰ 1,000 ਏਕੜ ਦਾ ਕੰਪੈਕਟ ਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਇਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਥੇ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਉਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਹਿਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਉਜੜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਹ 18 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਟਬਰ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ? ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਉ ਇਹ 1,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਜੜੇ ਹਨ, ਵਾਰ ਹਿਟ ਹਨ। (ਵਿਰੋਧੀ ਪਖ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ) ਅਗਰ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਏਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਟਾ ਵੀ ਕੀੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕੰਬਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੀਲੀਫ ਨੂੰ ਛਡ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੀਹੈਬੀਲੀਟੇਟ ਕਰੋ। ਰਿਲੀਫ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਚੁਪ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਿ ਬਿਰਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਟੈਂਡਰ ਇਨਵਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਚੋਰੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਰਨੈਲ ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏਥੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਉ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹਨ, ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਕੈਪਟਲਿਸਟ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕੈਪਟਲਿਸਟ ਹੋ ਗਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੇਲੇ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨਹੀਂ। ਇਕ ਗਰੀਬ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਕਲਕਤੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰੋਪੜ ਵਿਚ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਨਾਰੇ ਤੇ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਇਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ। (ਵਿਘਨ) ਹਰੀਜਨ ਭਾਈ ਐਵੇਂ ਗੁਸੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਉ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀਏਟ ਨੇ ਕੀ ਨੋਟ ਪੁਟ ਕੀਤਾ ਮਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀਏਟ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕੈਪਟਲਿਸਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕੈਪਟਿਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸਿਰਫ ਗਲਤ ਪਰੋਫੈਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੈਪਟਲਿਸਟ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਬਿਰਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਹ ਪਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋਵੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਉ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੋਪੜ ਵਿਚ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।

चौधरी इन्द्र सिंह मलिक : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडम। गुजारिश यह है कि क्या वह नेशलिस्ट भाई जन संघ वाले बिरले से सलाह करने गए हैं उनका कोई मासिक मेंबर यहां नहीं है ?

Deputy Speaker : Please take your seat.

(Interruptions and Noise.)

ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ :ਕਾਂਗਰਸੀ ਦੋਸਤ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਜਨ ਸੰਘੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। (ਵਿਘਨ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰ)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ: ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਇਕ ਦੋ ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੋਲਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਵਕਤ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਜ਼ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਲਗਾਈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਇਬਲ ਫਾਰਮ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਵਾਇਬਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰੋਫੈਸ਼ਨ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਰਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਲਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਖੁਦ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ ? ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪਰ ਦਰਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬੇਸਕ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਗੀ ਹੈ । ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਸਕ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈਂਡ ਟੂ ਦੀ ਟਿਲਰ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਲੈਂਡ ਟੂ ਦੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫਾਰਮਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਲ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ । ਇਹੋ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਨਣ ਲਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਰੇਡ ਜੋਸ਼ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਇਕ ਮਨਿਸਟਰ ਕਾ ਇਕ ਐਲਾਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ । ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਛੋਟਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਹਰੀਜਨਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਸਰਕਾਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫਰਮਜ਼ ਤੇ ਕੈਪੀਲਿਸਟਸ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਇਹ ਇਕ ਪਰੈਕਟੀਕਲ ਸਟੈਪ ਹੈ ।

चौधरी नेत राम: आन ए प्वायंट आफ आडर। मैं सरदार गुरनाम सिंह से कहना चाहता हूँ कि सोशलिस्ट सरकार का नाम बदनाम न करें। कांग्रेस सरकार का नाम बदनाम करें । यह सोशलिस्ट नहीं कांग्रेस सरकार है । सोशलिस्ट तो मैं यहां अकेला बैठा हूँ; मेरी कोई सरकार नहीं। (हंसी)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ: ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਸਦਾ ਪਰੋਫੈਸ਼ਨ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਹੈ । ਮੈਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਹਿਸ ਮਾੜੇ ਕੇਸ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕੇਸ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਇਲਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਮਾੜਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾੜੇ ਕੇਸ ਦੀ ਬਹਿਸ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿਲਾ ਸਕਦੇ । ਇਸ ਲਈ ਬਜਾਏ ਮਾੜੇ ਕੇਸ ਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸਦਾ ਅੱਜ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿਉ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿਉ ਕਿ ਬਿਰਲੇ ਤੋਂ ਖੇੜਾ ਛੁਡਾ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਰ ਹਿਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਕਲੇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਸ ਵਿਚ ਇਹੋ ਬੇਹਤਰ ਗੱਲ ਹੈ।

ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ (ਨਕੋਦਰ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਰੀਕਲੇਮਡ ਤੇ ਫਰਟਾਈਲ ਜ਼ਮੀਨ 30 ਰੁਪਏ ਫੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 25 ਸਾਲ ਲਈ ਬਿਰਲਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੀ ਲਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਗੈਰਆਬਾਦ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਰੀ-ਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਪੁਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਬੜੀ ਰੋਜ਼ੀ ਪਿਕਚਰ ਪੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਅਮਰੀਕਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਥੇ ਮੱਕੀ, ਕਣਕ, ਬਾਜਰਾ ਤੇ ਇਸਦੇ ਬੇਟਰ ਕੁਆਲਟੀ ਦੇ ਸੀਡਜ਼ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰੇਡਿੰਗ ਤੇ ਤੈਗਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿਚ ਭੇਜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਕ ਹੋਰ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਨਸਰਨ ਨੋ-ਪਰਾਫਿਟ ਨੋ-ਲਾਸ ਤੇ ਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਜੋਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਐਵੈਕੂਈ ਲੈਂਡ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਪੰਚਾਇਤ ਲੈਂਡ ਤੇ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਲੈਂਡ-ਓਨਰਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ । ਇਸ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਰਿਸਰਚ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਪਲੇਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ 93 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਇਸਦੀ ਰਿਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿਰਲੇ ਨੂੰ ਸੀਡ ਫਾਰਮ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਦੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਈ । ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੇਟ ਵਿਚ 222 ਸੀਡ ਫਾਰਮਜ਼ ਚਲਾਏ ਜੋ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੇਲ ਹੋਏ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦਾਨਸ਼ਮੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਜਾਏ ਖੁਦ ਸੀਡ ਫਾਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਘਾਟਾ ਪਾਉਂਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅਕਲ ਨਾਲ ਬਿਰਲੇ ਦੇ ਗਲ ਮੜ ਦਿਤਾ (ਹਾਸਾ) ਤੇਲ ਹੋ ਕੇ ਕਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜੋ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਫਿਰ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਰਲੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਐਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਾਰਮ ਚਲਾਉ । ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਲਿਖਦੇ ਵਕਤ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਖਦੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਰਿਸ਼ੀ ਪੰਡਤ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਰਖਦੀ । ਇਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਬੜਾ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਹੈ । ਕੀ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨੋ-ਪਰਾਫਿਟ ਨੋ-ਲਾਸ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਜ਼ ਰਖੀ ਤੇ ਕੀ ਚੈਕ ਰਖਿਆ ਹੈ......(ਘੰਟੀ) ਅਜੇ ਤਾਂ ਦੋ ਮਿੰਟ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਇਨਸਿਸਟ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰੋ । (I will have to think over in future about the hon. Member who will insist. He should finish now.)

ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਲਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਰਲੇ ਦੀ ਬੈਲੈਂਸ-ਸ਼ੀਟ ਚੈਕ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਫਟ ਲਾਸ ਵੇਖ ਸਕੇ। ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਡਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਫਾਰਮ ਨੋ-ਪਰਾਫਟ ਨੋ-ਲਾਸ ਤੇ ਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਦਰਅਸਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨਕਮਟੈਕਸ ਲਕੋ ਲਓ ਅਤੇ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਢੰਗ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਸੀਡ ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸਦੀ ਕੀਮਤ ਮੁਕਰਰ ਕਰਨ ਵਿਚ

ਕੋਈ ਹੱਥ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਇਸ ਵਿਚ ਐਸੀ ਕੋਈ ਕਲਾਜ਼ ਹੈ । ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਟਾਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਹ ਟਾਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸੀਡ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ (ਘੰਟੀ) ਬਸ ਜੀ, ਇਹੋ ਇਕ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਥੇ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ । ਇਥੇ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਝਲਕੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਝਲਕੀ ਤਾਂ ਇਹ ਆਈ ਕਿ ਰੌਣਕ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਦੇ ਦਿਓ ਵਿਘਨ) ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਇਹ ਝਲਕੀ ਆਈ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਉ । ਤੀਜੀ ਝਲਕੀ ਕਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਰਾਪਸ ਸੈਸ ਬਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਚੌਥੀ ਝਲਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ (ਹਾਸਾ) ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਤਨੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ (ਹਾਸਾ) ਅਜੇ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਦੀ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੰਗਾ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਪਾਕ ਤੇ ਸਾਫ ਜਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ । ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕ ਤੇ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ...(ਘੰਟੀ)...

ਭਗਤ ਗੁਰਾਂ ਦਾਸ ਹੰਸ (ਹਰਿਆਣਾ—ਐਸ. ਸੀ.) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਉਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਗਰੀਬ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਬਿਰਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਉਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲੰਮਬਰਦਾਰ ਬਣਾਏ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜੋਤਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ । ਇਸ ਲਈ ਬਿਰਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਹਰੀਜਨ ਲਮਰਬਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜੋਤਰੇ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਕਿ ਉਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਉਪਜ ਕਰ ਸਕਣ । ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 4,500 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ 900 ਰੁ: ਫੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 200 ਜਾਂ 300 ਰੁਪਏ ਫੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖੂਹ ਅਤੇ ਟਿਊਬ-ਵੈਲਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਹਨ । ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਰਲੇ ਨੂੰ ਕਾਬਲੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ 30 ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਉਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।

1.00 p.m.

ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਬਿਰਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਰਿਆਇਤਾਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ । ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਬਲੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਦੇਣ । ਉਥੇ ਟਿਊਬ ਵੈਲ ਲਾ ਕੇ ਦੇਣ ਤਾਂਕਿ ਹਰੀਜਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਤੇ ਕਰ ਸਕਣ । ਹਰੀਜਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ । ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੰਡੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਬਲੇ ਕਾਸ਼ਤ ਹੈ । ਉਥੇ ਟਿਊਬ-ਵੈਲ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਲਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ

[ਭਗਤ ਗੁਰਾਂ ਦਾਂਸ ਹੰਸ]

ਕਰੇਗੀ। (ਘੰਟੀ) ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਆਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੀਚ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਮਿੰਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। (ਘੰਟੀ)

EXTENSION OF THE TIME OF THE SITTING

उपाध्यक्षा: पेशतर इसके कि मैं किसी और आनरेबल मैम्बर को काल अपौन करूँ मैं हाउस को इत्तलाह देना चाहती हूँ कि इस मोशन के लिये 2 घंटे निश्चित किये गए थे। यह मोशन 12 बजे टेक अप हुई और डेढ़ बजे तक केवल डेढ घंटा ही डिस्कशन हो सकती है। इसलिये मैं हाउस का टाइम आध घंटे के लिये एक्सटैंड करती हूँ। मैं आनरेबल मैम्बरों से प्रार्थना करूँगी कि जिस भी आनरेबल मैम्बर को काल अपौन करूँ, वह इस विषय में 5 मिनट से ज़्यादा समय न ले। समय बहुत कम है मिनिस्टर कंसर्ड को भी जवाब देने के लिये आधा घंटा का टाइम चाहिए।।

(Before I call upon any other hon. Member to speak I would like to inform the House that two hours' time was fixed for the discussion of this motion. It was taken up at 12 noon and naturally the discussion can go up to 1-30 p.m. in the normal course of time. I, therefore, extend the time of the sitting by half an hour. I would request the hon. Members that who so ever is called upon to speak, should in no case take more than five minutes to express his views on the subject. The time at our disposal is short and the Minister concerned would also need half an hour for making a reply to the debate.)

MOTION UNDER RULE 84 RE: MATTER RELATING TO LEASING OF 1,000 ACRES OF AGRICULTURAL FARM NEAR RUPAR TO BIRLA BROTHERS—(RESUMPTION OF DISCUSSION)

ਸਰਦਾਰ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ (ਖਾਲੜਾ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਜਿਸ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਅੱਜ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਭੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਟੇਕ ਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਰਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਯੁੱਧ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪੀੜਾ ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਲਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫ਼ਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਯੁਧ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰੀਜਨਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਯੁਧ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਬਿਰਲੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸਟਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਿਰਲੇ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਯੁਧ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਕਿ ਉਹ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਢਕ ਸਕਦੇ। ਯੁਧ ਪੀੜਤ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਵਸ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ

ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ // ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਣਕ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ । ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਜਾਈਆਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ । ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਰਜਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ; ਉਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰਫ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ।

ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ । ਕੈਂਪ ਵਿਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਣਕ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸਦਾ ਕੁਝ ਨਮੂਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਲਿਆਇਆ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੈਂਪ ਵਿਚ ਗਿਆ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਕ ਮਣ ਕਣਕ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਸੇਰ ਖਪਰਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਉਸ ਕਣਕ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪਰਲੋਕ ਸੁਧਾਰ ਜਾਣਗੇ । (ਵਿਘਨ) ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੁਧ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਣਕ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ । ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਰਜਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਜਾਈਆਂ ਯੁਧ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਜਾਈਆਂ ਦੀ ਰੂਈ ਬਾਹਿਰ ਅਤੇ ਕਪੜਾ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਖੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਾਈਆਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਰਦੀ ਵਿਚ ਪਾਲੇ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ।

उपाध्यक्षा : आप कनक और रज़ाई मुझे दिखा दें । अब इस बात को हाउस की डिस्कशन में न लाएं । (The hon. Member may show me the specimen of wheat and quilt and avoid bringing this matter in the discussion now going on in the House.)

ਸਰਦਾਰ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ : ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਰਜਾਈ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਇਥੇ ਹੀ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਥੇ ਹੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ......

मुख्य मन्त्री: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडम । डिप्टी स्पीकर साहिबा, जो कुछ माननीय सदस्य कह रहे हैं उसका इस मोशन के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। इस मोशन के साथ रजाई और कनक का कोई सम्बन्ध नहीं है । सरदार गुरदयाल सिंह ढिल्लों रिलीफ तथा रीकंसट्रक्शन के इंचार्ज हैं। कैम्प में जो रजाई दी गई है, वह तैयार करके यहां पर लायी गई । यहां पर माननीय सदस्यों के नोटिस में लाया गया कि उन्हें इस तरह की रजाइयां दी जा रही हैं । इस सिलसिले में किसी भी आनरेबल मैंबर की तरफ से कोई भी एतराज़ और शिकायत हमारे नोटिस में नहीं लाई गई । मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमने कनक के बारे में जांच कराई है और उसकी रिपोर्ट हमारे पास आ चुकी है और उस पर ग़ौर हो रहा है। जो कुछ सरदार नारायण सिंह शाहबाज़पुरी ने कहा है, मैं उसकी पूरी तरह से तरदीद करता हूँ कि हमें इसके बारे

[मुख्य मन्त्री,]

में किसी किस्म की शिकायत नहीं आई । इनकी कोई अपनी ज़ाती दुश्मनी है । अगर इन्होंने किसी के साथ ज़ाती अदावत निकालनी है तो हाउस में नहीं निकालनी चाहिए। यह और किसी जगह अदावत निकालें ।

उपाध्यक्षा : सरदार नारायण सिंह जी, आप दोनों चीज़ें मेरे पास भेज दें । आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं रह जाती । (The hon. Member, Sardar Narain Singh may send both the articles to me and this would obviate any necessity for his speaking any further on the subject.)

ਸਰਦਾਰ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ : ਮੇਰੇ ਉਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪਲੇਨਸ਼ਨ ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ।

उपाध्यक्षा : आप यह कहें कि बिरलें को ज़मीन क्यों दी है। रज़ाई और गंदम की बात आप न करें । (The hon. Member should ask for the reason for leasing out land to the Birlas and leave aside the matter relating to the quilt and wheat). (*Interruption*)

ਸਰਦਾਰ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ : ਮੈਂ ਕਾਮਰੇਡ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਦੇ ਦੰਦ ਹੋਰ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਖਾਣ ਦੇ ਦੰਦ ਹੋਰ ਹਨ (ਵਿਘਨ)......

Deputy Speaker : Order please.

ਸਰਦਾਰ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ : ਸਰਦਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀਂ 9 ਜੀਅ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਮੈਂ ਉਹੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹੋ ਜ਼ਮੀਨ ਯੁਧ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਆਪ ਬਣਵਾ ਲੈਂਦੇ......ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੋਬੀਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਅਦਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਮੈਂ ਯੁਧ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਅਜ ਵੀ ਹਮਦਰਦ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਖਰ ਤਕ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ।

Deputy Speaker : Order please. Please take your seat.

ਸਰਦਾਰ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ : ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੀਕਵੈਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬਿਰਲੇ ਵਾਲਾ ਲੀਜ਼ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਯੁਧ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਣ, ਕਪਾਹ ਬੀਜ ਕੇ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਭਰਵਾ ਸਕਣ । ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਧੂਆਂਧਾਰ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਿਕ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਿਕ ਪਟਰਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਪੱਥਰ ਰਖਣਗੇ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਪੱਥਰ ਕਢ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇਜ਼ਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੇ. . . .ਮੈਂ ਰਜ਼ਾਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।......

Deputy Speaker : Will you please take your seat now.

(ਵਿਘਨ)

(At this stage the hon. Member S. Narain Singh Shahbazpuri placed a Razai in the House, which was immediately taken away by S. Harchand Singh.)

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸਾਂ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਖਲਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।...

(The hon. Member has started unrolling the quilts in the House.)

(Interruptions)

श्री रूप सिंह फूल (हमीरपुर—एस. सी.) : सदरे मुहतरिमां, हकूमत की जिस पालिसी के मातहत यह ज़मीन बिरला के हवाले की गई है उस पालिसी के मुताल्लिक मुझे अल्लामा इकबाल मरहूम का एक शेर याद आ गया है :

कभी सरबसज्जदा हुआ जो मैं,
तो ज़मीन से आने लगी सदा,
तेरा दिल तो है सनम आशना,
तुझे क्या मिलेगा नमाज़ में ।

मैं यह भी नहीं कहता कि यह ज़मीन उनको क्यों दी गई है । मुझे तो यह एतराज़ यों है कि वह तो महान् इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका ज़रायत से कोई ताल्लुक नहीं है। और अगर इसको भी इंडस्टरी ट्रीट कर लिया जाए तो और स्टेट्स में भी बड़े-बड़े फार्म हैं लेकिन वह तो उन्होंने बिरला जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट को नहीं दिये । हां, जैसे आनरेबल मैम्बरान ने फरमाया है कि हकूमत ने यह एलान किया था कि जो उजड़े हुए लोग हैं, जो बेदखल शुदा मुज़ारान हैं उनको और खसुसन हरिजनों को इस किस्म की ज़मीन पर आबाद किया जायगा और अभी तक काफी तादाद मुज़ारान की ऐसी है जोकि बेघर हैं और बेघर होने वाले हैं। जब उनके मुताल्लिक किसी जामा कानून को बनाने की इस हाउस में अर्ज़दाश्त हकूमत के पास करते हैं तो हकूमत के कान पर जूं तक नहीं रेंगती । इस ज़मीन पर काफी तादाद हरिजनों की, जो कि बेदखलशुदा मुज़ारान हैं, बस सकती थी और इस तरह से देश की पैदावार में इज़ाफा किया जा सकता था। लेकिन इस तरह से ज़रई ज़मीन बिरला को दे देने का मतलब तो यह है, मुझे फिर मौलाना मरहूम का शेर याद आया है :

यह गिला मुझ को नहीं, हैं उनके खज़ाने मामूर,
जिन को महफल में नहीं बात भी करने का शऊर,
शिकवा इस बात का है, उनको मिलें हूरोकसूर,
और मुसलमां को फक्त वादाए हूर ।

किसानों और हरिजनों के साथ वादे किये जाते हैं कि हम यह करेंगे, वह करेंगे । एलान तो ऐसे किये जाते हैं लेकिन अमली तौर पर सरमायेदारों की मदद की जाती है । यह तौर हमारी गवर्नमेंट को बदलने होंगे :

सरमायदारी का यह दौर बदलना होगा,
कुछ कुछ तो बदल बैठे हो कुछ और बदलना होगा,
अब देर नहीं है अच्छी फिलफौर बदलना होगा,
"फूल" जिस तौर ज़माना बदले उस तौर बदलना होगा ।

[श्री रूप सिंह फूल]

हम यह देखते हैं कि पालिसी का एलान तो कुछ और होता है और अमल कुछ और होता है । मैं हकूमत पंजाब से यह कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी सैक्शन सोसाइटी का कमज़ोर होता है, खाह वह हरिजन हो, खाह मुज़ारा हो, वह कमज़ोर होता है तो सारा राष्ट्र कमज़ोर होता है । अगर शरीर का एक अंग भी शिथिल हो जाए तो सारा शरीर ही शिथिल हो जाता है । ठीक इसी तरह से किसी एक सैक्शन के कमज़ोर होने से सारा राष्ट्र ही कमजोर हो जाता है क्योंकि राष्ट्र भी एक शरीर की तरह ही है । किसानों, हरिजनों और मुज़ारों का मसला अभी तक हल नहीं हुआ लेकिन सरकार ने जमीन बिरला साहिब को दे दी है । मैं पूछता हूँ कि क्या बिरला साहिब का बीज पंजाबियों से ज़यादा ज़बरदस्त हो सकता है ? पंजाब सारे देश का बाज़ूए शमशीर है । मरने के लिये तो पंजाबी और हरिजन, हरिजनों ने भी लड़ाई में हिस्सा लिया है, किसानों और मुज़ारों ने लिया तो बिरला साहिब का बीज कैसे जबरदस्त हो सकता है ? (हंसी) मै यह बरदाश्त नहीं कर सकता कि पालिसी तो कुछ और हो और अमल कुछ और हो । डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं एक मिन्ट के लिये एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। भक्त कबीर मशहूर हो गुजरे हैं, वे परम भक्त थे । उनकी धर्म पत्नी का नाम लोई था । भक्त कबीर एक दिन अपनी धर्मपत्नी से कहने लगे कि हम बूढ़े हो गए हैं, सुना है कि नारी चरित्र होता है जिसे त्रिया चरित्र भी कहते हैं। हम ने कभी नहीं देखा और न ही कभी आपने दिखाया है । एक आध नारी चरित्र ज़रूर दिखा दो। लोई पतिव्रता स्त्री थी बोली कि बहुत अच्छा। दूसरे ही दिन जब भक्त जी रफाए हाजत के लिये बाहर गये तो माई लोई ने एक डंडे को जिस पर लोहा लगा हुआ था खूब गर्म करके अपने पास रख लिया । वह डंडा जिसका लोहा लाल हो रहा था उनके पास पड़ा हुआ था कि बाहर से पांच-सात महात्मा, साधु सन्त कबीर जी के दर्शन करने के लिये आ गए । उन्होंने पूछा कि यह क्या है और भक्त जी कहां गए हैं, तो माई लोई ने कहा कि वे तो बाहर गए हैं लेकिन आज वे बहुत क्रोधित हैं और उन्होंने यह डंडा लाल करवाया है, कहते हैं कि जो भी आएगा उसके जिस्म के साथ लगा देंगे और उसका बुरा हाल करेंगे । साधु महात्माओं ने जब यह सुना तो कहने लगे कि हमारी आफत आ गई और डर के मारे भाग गए । जब भक्त कबीर जी वापस आए तो पूछने लगे कि क्या कोई सन्त महात्मा मिलने के लिये आया था । माई लोई बोली कि हां आए थे लेकिन वे यह डंडा मांगते थे मैंने यह कह कर इनकार कर दिया कि यह तो एक ही डंडा घर में है और भक्त जी ने अपने इस्तेमाल के लिये रखा हुआ है । इसलिये वे नाराज़ होकर चले गये हैं। यह सुन कर कबीर जी बहुत दुखी हुए कहने लगे कि लोई यह तुमने क्या किया ? तुमने तो साधुओं को नाराज़ करके मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया । साधुओं का निरादर करने के समान तो और कोई पाप ही नहीं है । यह कह कर उन्होंने डंडा उठाया और जिधर साधु गए थे उसी तरफ पीछे पीछे भागने लगे । वह आगे आगे और भक्त जी उनके पीछे पीछे दौड़े । दूर से उनको वह डंडा भी दिखाया और ज़ोर-ज़ोर से पुकारते रहे कि इसे ले जाओ लेकिन वह मारे डर के और ज़यादा तेज़ भागते गए । भक्त जी मीलों मील उन के पीछे दौड़े

पर वह हाथ न आए। आखिर वह बेचारे वापिस आए। माई लोई ने उनके लिये गर्म गर्म पानी तैयार किया हुआ था। उन के हाथ पांव धुलाए। भक्त जी ने उनसे कहा कि लोई तुमने हमारा जन्म बेकार कर दिया है। इस पर लोई ने कहा कि मैंने तो आपकी आज्ञा का पालन किया है। क्या, कबीर जी ने पूछा। इस पर लोई ने जवाब दिया कि आप ही ने तो कहा था कि मुझे त्रिया चरित्र दिखाओ। मैंने तो आपको यह नारी चरित्र का एक ही उदाहरण दिखाया है। और आप कहेंगे तो और भी दिखा दूंगी। तो उन्होंने कहा कि न लोई, आइन्दा के लिये और कोई न खाना। इसी तरह से मैं कामरेड साहिब और सरदार दरबारा सिंह साहिब से कहूंगा कि जैसे माई लोई ने नारी चरित्र दिखाया था ऐसा और "सरकारी चरित्र" आप लोगों को न दिखाइयगा।

श्री जगन्नाथ (तोशाम): डिप्टी स्पीकर साहिबा, एक हज़ार एकड़ ज़मीन तो कामरेड जी ने और सरदार दरबारा सिंह जी ने बिरला ब्रदर्स को दी है। ज़मीन आपके पास काफी है, एक हजार एकड़ से आप को कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन सवाल यह है कि वह उन को दी क्यों है? जरूर इसमें इनका कोई स्वार्थ होगा क्योंकि स्वार्थ के लिये तो कोई भी चीज़ किसी को दी जा सकती है। स्वार्थ के लिये राजा मानसिंह ने अपनी बहन जोधा बाई शहनशाह अकबर को दे दी थी। लेकिन इन्होंने तो सिर्फ एक हज़ार एकड़ ज़मीन ही दी है।

बड़े अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि एक तरफ तो यह इस बात का दम भरते हैं कि ज़मीन हरिजनों को देंगे, मुजारों को देंगे। दूसरी तरफ कामरेड साहिब कहते हैं कि यह जमीन हरिजनों के लिये, फौजियों के लिये नहीं है, सरदार दरबारा सिंह साहिब कहते हैं कि एक हज़ार एकड़ ज़मीन दे देने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इससे कानूनी झगड़ा हो सकता है, कानून टूट सकता है क्योंकि वह लोग हाईकोर्ट में केस ले जायेंगे, सुप्रीम कोर्ट में चले जायेंगे और इस तरह से कानून को अमैंड करना पड़ेगा; इसलिये फौजियों को नहीं दे सकते बिरला ब्रदर्स को ही देंगे और, डिप्टी स्पीकर साहिबा, बिरला ब्रदर्स को वह ज़मीन इस लिये देंगे क्योंकि वह इलैक्शन के दौरान इनको पैसा देंगे। डिप्टी स्पीकर साहिबा, सिर्फ पंजाब के अन्दर ही नहीं बल्कि अगर आप राजस्थान और दूसरी स्टेट्स के अन्दर जाएं *× × × हैं। यहां पर कामरेड जी उनके एजेंट हैं। वह लोग हरेक स्टेट में कोई न कोई एजेंट रखते हैं जिस से उनका काम चलता रहे। यह तो ज़मीन ही दी है अगर स्वार्थ पूरा होता हो तो यह राजा मानसिंह की तरह उन लोगों को दूसरी चीजें भी सप्लाई करने को तैयार होंगे। इसलिये मैं यह कहूंगा कि पंजाब के साथ नहीं बल्कि कामरेड जी का लगाव देहली वालों के साथ है, बिरलों वगैरा के साथ है। जिस तरह से ग्रोह होते हैं....बनियों का ग्रोह अलग होता है, बिजनैसमैन का ग्रोह अलग होता है और चोरों का ग्रोह अलग होता है जिनकी तसल्ली देश में जगह जगह से चोरी करके ही होती है। ऐसे ही बिजनैसमैन और कामरेड साहिब हैं। कामरेड साहिब न तो मुज़ारों के बारे में सोच सकते हैं और न ही हरिजनों

Note.—Expunged as ordered by the Chair.

[श्री जगन्नाथ]

के बारे में सोच सकते हैं (घंटी) न ही जमींदारों के बारे में सोच सकते हैं। वह तो बनिया ढंग के आदमियों की ही सोचते हैं फिर वह चाहे हैदराबाद से हो, चाहे बम्बई से हो। यह तो चाहते हैं कि ऐसे आदमियों को लाकर पंजाब के अन्दर जमीन दे दो और उसको यहां पर बसा दो। हरिजनों का या ऐग्रीकल्चरिस्ट्स का भला न हो। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि सरदार प्रतापसिंह कैरों ने अपने कोल्ड स्टोरेज बना लिये थे, सिनेमाघर बना लिये थे लेकिन बिरला और टाटा वगैरा को यहां पर इन्वाईट करके उसने पंजाब की जमीन तो कभी नहीं दी थी। सरदार प्रतापसिंह के अन्दर कितनी ही बुराइयां थीं लेकिन पंजाब में उसने ऐसा नहीं होने दिया जैसा कि अब कामरेड साहिब ने किया है। इस ढंग से तो यह पंजाब का भट्ठा ही बैठा देंगे। (घंटी)

डिप्टी स्पीकर साहिबा, बस एक बात और कह कर खत्म कर रहा हूँ। पंजाब के जितने भी हिन्दू हैं हिन्दी रिजन में हरिजनों के पास जाकर वोट हासिल करते हैं। उन्हें कहते हैं कि आप यूनाइयटिड पंजाब का ही नारा लगाओ कि पंजाब यूनाइटिड रहना चाहिए, यह जो अकाली हैं यह तुम लोगों को खा जायेंगे, यह हो जाएगा वह हो जाएगा। सरदार दरबारा सिंह भी इसी तरह की बातें उनके साथ करते हैं। मैं पूछता हूँ कि अगर वाकई उनकी हमदर्दी हरिजनों के साथ होती तो यह जो एक हजार एकड़ जमीन बिरला को दी गई है यह हरिजनों को देते। मैं तो आखिर में यही कहूँगा कि पंजाबी रिजन का कोई भी हिन्दू हो उसकी नीयत खराब है चाहे वह यह कामरेड राम किशन हो या कोई दूसरा राम किशन हो।

उपाध्यक्षा: श्रीमती सरला देवी, सिर्फ चार मिनट हैं। उसी हिसाब से बोलना। (The hon. Member has only four minutes at her disposal. She should speak accordingly.)

श्रीमती सरला देवी (बड़सड़): डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह जो आज विधान सभा के अन्दर बहस चल रही है कि हमारी पंजाब गवर्नमैंट ने बिरला ब्रदर्स को एक हजार एकड़ के करीब जमीन देने का वायदा किया है या दे दी है, मैं इसका विरोध करने के लिये खड़ी हुई हूँ। मैं विरोध इसलिये करना चाहती हूँ कि इस सम्बन्ध में कहा यह जा रहा है कि बिरला ब्रदर्स को यह ज़मीन इसलिये दी है क्योंकि पंजाब को बड़े अच्छे-अच्छे बीजों की ज़रूरत है, यह लोग बड़े पैसे वाले हैं और यह दूसरे मुल्कों से अच्छे-अच्छे बीज मंगवा कर यहां पर नरसरी बनायेंगे और फिर वह बीज किसानों को सप्लाई करेंगे और तब जा कर हमारी खेतीबाड़ी बहुत आगे बढ़ सकेगी। डिप्टी स्पीकर साहिबा, हमारे प्रधान मन्त्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी तो यह कह रहे हैं कि एमरजेंसी का ज़माना है, लड़ाई का समय है और ऐसे अवसर पर हमें किसी भी दूसरे मुल्कों से खाने का सामान नहीं लेना चाहिए और अपने मुल्क में ही इस कदर अनाज पैदा करना चाहिए ताकि हम इस खुराक के मसले को स्वयं हल कर सकें लेकिन मैं हैरान हूँ कि इस एक हजार एकड़ भूमि को देने के लिये जो कारण बताये गए हैं वह क्या हैं। कब जाकर इस ज़मीन पर बीज पैदा होगा, कब यह किसानों को सप्लाई किया जायगा और कब जा कर हमारी खेतीबाड़ी अच्छी होगी ?

डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरे भाई श्री रूप सिंह फूल ने बड़े शायराना अन्दाज़ से अपने विचार हाउस के सामने रखे हैं। मैं भी आपको बताना चाहती हूँ कि यह जो ज़मीन है इसे एक ही आदमी को देकर पंजाब के अन्दर हजारों मुज़ारे, हरिजन और दूसरे छोटे-छोटे लोग हैं उनका एक प्रकार से गला घोंटा जा रहा है। आप कांगड़ा ज़िला में जाकर देख लीजिये कि जिन लोगों के पास तीस स्टैंडर्ड एकड़ ज़मीन है या इससे कम ज़मीन है वहां से कई बेगुनाह मुज़ारों को बेदखल किया जाएगा। वहां पर हाहाकार होगी और सैंकड़ो की तादाद में मुजारे कचहरियों के अन्दर मारे मारे फिरेंगे। उनके पास पैसा नहीं, अपनी झौंपड़ियों को गिरवी रख कर कई किस्म की मुसीबतों को झेल कर वकीलों को पैसे देंगे और कचहरियों के अन्दर मुकद्दमें लड़ेंगे। यह कितनी दुखद अवस्था होगी। डिप्टी स्पीकर साहिबा, महात्मा गांधी जी कहा करते थे कि हमने जो भी सुधार मुल्क में करने हैं वह गरीबों के भले और उनकी उन्नति और खुशहाली के लिये करने हैं। वह इस लिये हरिजनों की बस्ती में रहा करते थे। लेकिन कितने दुख की बात है कि आज वह ज़माना आ गया है कि जबकि हरिजन कचहरियों के अन्दर मारे मारे भटक रहे हैं और मुसीबतों के मारे तड़प रहे हैं और उनकी किस्मत का फैसला नहीं किया जाता (घंटी) डिप्टी स्पीकर साहिबा, नूरपुर के अन्दर दो-दो कनाल जमीन उनको ऐग्रीकलचर के लिये दी है लेकिन अगर वहां पर देखा जाये तो खड्डे हैं, चारों तरफ पत्थर हैं (घंटी) मैं इस सम्बन्ध में एक-दो सजैशंज देना चाहती हूँ। यह बिरला ब्रदर्स दूसरी स्टेट के रहने वाले हैं। उनके पास बहुत पैसा है। उनकी बहुत मिलें चलती हैं।

उपाध्यक्षा: आपका टाइम हो गया है। (Her time is over.)

श्रीमती सरला देवी: उनके पास क्या नहीं ? मिल मालिकों के पास क्या चीज़ नहीं होती ? सरमायादार के पास हर चीज को प्राप्त करने के अनेक ढंग होते हैं, उनकी प्रैस होती है, बिज़नैस होती है, कारोबार होता है। सब के ऊपर उसका कब्ज़ा होता है। क्या ज़मीन पर भी इस ढंग से उसका कब्ज़ा करवाना चाहते हैं ? मैं कहूँगी कि पंजाब के अन्दर बहुत छोटे-छोटे किसान हैं, सिख किसान हैं, मुज़ारे हैं, हरिजन हैं। अगर उनको जमीन दे दी जाए तो यह बिरला से भी अच्छा काम कर दिखाएंगे, ज़यादा अनाज पैदा करेंगे और आज हमारे सामने जो अनाज का मसला खड़ा हुआ है उसको हल करने में पूरी तरह से सहायता देंगे। इन सभी बातों को देखते हुए वह जमीन अपने पंजाब के किसानों में बांटी जानी चाहिए चाहे वह हरिजन हों, चाहे मुज़ारे हों और चाहे वह छोटे-छोटे किसान हों। बिरलों को यह ज़मीन हरगिज़ नहीं दी जानी चाहिए। यह जो डील उनके साथ की गई है मैं इसका सख्त विरोध करती हूँ।

उपाध्यक्षा: सरला देवी अब बैठ जाओ। (The hon. lady Member should resume her seat now.)

श्रीमती सरला देवी बस जी, दो मिनट।

उपाध्यक्षा : बस अब और नहीं । आपने कह तो दिया है कि निरलाज़ को ज़मीन नहीं दी जानी चाहिए । (No. That is all. She has opposed the leasing out of the land to the Birlas)

श्रीमती सरला देवी : इस सम्बन्ध में मैं यह सुझाव देना चाहती हूँ कि ज़मीन की बांट किस तरह से की जानी चाहिए।

उपाध्यक्षा : इस वक्त आप बांट की बात न कीजिये । पहले जमीन वापिस तो ले लो । बांट की बात बाद में कर लेना । (She need not go into the question of distribution at this stage. First get back the land. The question of distribution may be taken up later.

श्रीमती सरला देवी : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं यह कहना चाहती हूं.........

(Interruption)

आप देखेंगी कि........

Deputy Speaker : Please take your seat now.

श्रीमती सरला देवी : आप देखेंगी कि मैं एक-दो मिनटों में वाईंड अप कर देती हूँ। आप वाईंड अप तो करने दें ।

उपाध्यक्षा : प्लीज़ सरला जी ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ (ਮੋਗਾ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਪੰਜ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ।

श्री सागर राम गुप्ता : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडम । डिप्टी स्पीकर साहिबा आपसे पहले जब श्री रूपसिंह फूल चेयर में थे तो उन्होंने फरमाया था कि जो मैम्बर रिपीट नहीं करेंगे उन्हीं को टाइम दिया जाएगा । यह तो रिपीट कर रहे हैं। मैंने तो क्योंकि कुछ नई बातें कहनी हैं इसलिये आप मुझे बोलने के लिये टाईम दें ।

Deputy Speaker : No please.

श्री अमर सिंह : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडम । मैंने हरिजनों के लिये कुछ कहना है क्योंकि सरकार ने पहले कहा था कि यह जमीन हरिजनों को दी जाएगी । इसलिये आप मुझे बोलने दें ....

Deputy Speaker : Harijan Members have been given enough time.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਜੋ ਨਾਹਰਾ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪਰਾਈਮ ਮਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ "ਜੈ ਕਿਸਾਨ, ਜੈ ਜਵਾਨ" ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਹਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਖਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਵਾਹੀਵਾਣ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਹੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਤਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਟ ਕਾਮਯਾਬ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਲਾਹਨਤ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਟ ਵਾਹੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਕਲਕਤੇ ਤੋਂ

ਇਕ ਮਾਰਵਾੜੀ ਸੇਠ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ ! ਫਿਰ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗਰੋਅਰਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਡਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੋ ਰੁਪਏ ਪਰੀਮੀਅਮ ਤੇ ਇਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਫਰਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋ-ਪਰਾਫਿਟ ਨੋ-ਲਾਸ ਬੇਸਿਜ਼ ਤੇ ਉਹ ਫਰਮ ਬੀਜ ਪਰੋਡੀਉਸ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਤ ਰੁਪਏ ਪਰੀਮੀਅਮ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਮਾਰਵਾੜੀ ਸੇਠ ਨੂੰ ਕਲਕਤੇ ਵਿਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬੀਜ ਪਰੋਡੀਉਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜਦ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਹੀਵਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜੋ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਲਟੀਵੇਟਰ ਹਨ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਗੇ ਹੀ 19 ਐਸੇ ਆਦਮੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਬਲੈਕ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹੋਈ ਆਮਦਨੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਫਰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਜਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਕੋਲ 4 ਜਾਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਵਾਹੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਪਾਸ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬੈਟਰ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਸਰਪਲਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ । ਉਸ ਪਾਸ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਾਣ ਲਈ ਇਕ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫਲੀਟ ਵੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਹੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਚੰਗੇ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ? ਲੇਕਿਨ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬਿਰਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਏਜਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਬਜਾਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਹੀਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਾਲਖ ਪੋਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛਿਪੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਹੀਵਾਣ ਹੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਬਾਰਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ? ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਹੀਵਾਣ ਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰਾਈ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪੀਲੀਭੀਤ ਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਤੋੜ ਖਟਮੰਡੂ ਤਕ ਆਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਵਾਹੀ-ਵਾਣ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸੀ । ਜਿਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਹੀਵਾਣ ਨੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਫਖਰ ਕਰਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਾਲਖ ਪੋਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ।

चौधरी नेत राम: स्रान ए प्वायंट स्राफ स्रार्डर, मैडम । 6 दिन तक जनरल सेल्ज़ टैक्स पर यहां बहस होती रही है लेकिन मैं एक दिन भी नहीं बोला क्योंकि मैं चाहता था कि जिस दिन यह ज़मीन जो बिरला को दी गई है इसके ऊपर बहस होगी तब मैं बोलूंगा स्रौर स्राज वह मौका स्राया है तो स्राप मुझे बोलने के लिये मौका ही नहीं दे रहीं —

उपाध्यक्षा : आप ज़रा बैठ जाइए। (He may please resume his seat for a while.)

चौधरी नेत राम: नहीं, डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैंने इस पर ज़रूर बोलना है और अपनी पार्टी का नज़रिया इस मामले पर जो है वह सदन के सामने रखना है।

उपाध्यक्षा : चौधरी नेत राम जी, मैं आपकी बात बहुत दफा मान लेती हूँ, आज आप मेरी बात मान लें और बैठ जाएं। (Addressing Chaudhri Net Ram) (I often comply with his requests. He should now obey me and resume his seat.)

चौधरी नेत राम: मैं आपकी बातें रोज़ मानता हूँ। आज आप मेरी बात मान कर सिर्फ पांच मिनट ही दे दें।

उपाध्यक्षा : आप बैठ जाइये। (He may please take his seat.)

चौधरी नेत राम : मुझे पांच मिन्ट ज़रूर मिलने चाहिएं।

उपाध्यक्षा: आप ज़िद कर रहे हैं तो पांच मिनट के अन्दर अन्दर खत्म करना होगा। (If he insists so much, then he shall have to finish his speech within five minutes.)

चौधरी नेत राम (हिसार सदर): डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं एक मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, बिरला ब्रदर्ज़ को सरकार ने जो एक हज़ार एकड़ ज़मीन 30 रुपये फी एकड़ फी साल के हिसाब से 25 सालों के लिये देनी की है इसके बारे में मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा बेइनसाफी का काम और दुनिया भर में नहीं हो सकता। ज़रा आप देखें कि आज जो पंचायतों की ज़मीनें नीलाम होती हैं तो वह दो सौ रुपये फी एकड़ से भी ज्यादा के रेट पर ठेका पर चढ़ जाती है हालांकि वह ज़मीनें बारानी होती हैं और यह ज़मीन जो बिरला ब्रदर्ज़ को दी गई हैं यह दरयाए सतलुज के साथ की बड़ी सरसब्ज़ ज़मीन है जोकि बड़ी कीमती ज़मीन है जो उन्हें 30 रुपए फी एकड़ के हिसाब से दे दी गई है और यह ज़मीन 25 साल तक उनके कब्ज़ा में रहेगी। मैं हैरान हूँ कि ज़िला हिसार के अन्दर हज़ारों एकड़ ज़मीन गवर्नमेंट की अपनी फार्म के अन्दर पड़ी हुई है तो क्या वहां पर यह बीज पैदा नहीं करवा सकते थे?

श्री सागर राम गुप्ता: डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ की है कि आप इस मसला पर बोलने के लिये ज़रूर मुझे समय दें क्योंकि मुझे बिरला वालों का भिवानी में तजरुबा हासिल है और उस तजरुबा की बिना पर मैं यहां कुछ बातें बताना चाहता हूँ।

डिप्टी स्पीकर : आर्डर प्लीज़।

चौधरी नेत राम: डिप्टी स्पीकर साहिबा, अपनी लूट कायम करने के लिये यह बिरला को यह ज़मीन दे रहे हैं। इसके सिवाए इन का और कोई मतलब नहीं है। भला आप ही बताएं कि जिस आदमी ने कभी खेती की ही न हो और जो यह भी न जानता हो कि गंदम का पेड़ कितना बड़ा होता है —

उपाध्यक्षा: चौधरी नेतराम जी अब आप बैठ जाएं अब मिनिस्टर साहब को इसका जवाब दे लेने दें। (The hon. Member may now take his seat and let the hon. Minister make his reply.)

चौधरी नेत राम: यह उस बिरले को जमीन दे रहे हैं जिसको खेतीबाड़ी का कुछ पता नहीं है (शोर) चने का पेड़ होता है (विघ्न) या डंठल होता है (विघ्न) वह क्या बीज़ देगा आपको ? (विघ्न) हो सकता है कि आने वाले जमाने में सारी ज़मीन हड़प कर ले (विघ्न) ......

उपाध्यक्षा: बाकी के सैशन में आपको बोलने की इजाजत नहीं होगी। (He will not be allowed to speak during the rest of the Session.)

श्री [illegible] **राम गुप्ता**: मुझे पांच मिनट दिये जाएं (विघ्न) वजीर साहब को भी एतरा[illegible] [illegible]हीं है (विघ्न)

Deputy Speaker : Please take your seat.

श्री **सागर राम गुप्ता**: मैं आपको बताता कि हूँ किस तरह से ट्रस्ट बना कर यह लोग जिनको ज़मीन दी जा रही है भिवानी में इनकमटैक्स वगैरा की चोरी कर रहे हैं (विघ्न)

ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ : (ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਸ ਮਤੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ ਪਰ ਚੂੰਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਜਸਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। (ਵਿਘਨ) ਇਸ ਤੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਮੈਂ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਾਰੇ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ।

ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਕ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਿ ਇਥੇ ਬੰਨ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋ ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਦਰਿਆ ਬੁਰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵਾਹੀ ਲਈ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਤੁਗਿਆਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਕੇ ਇਹ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਤਖਮੀਨੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਫਿਗਰਜ਼ ਦਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ 2 ਲਖ ਏਕੜ ਹੈ, ਜਾਂ ਡੇਢ ਲਖ ਏਕੜ ਹਨ। ਮਗਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਹੈ। (ਵਿਘਨ) ਬਿਰਲਾ ਫਾਰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਫੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮੈਟਰਜ਼ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਰਾਂਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਕਚੂਅਲ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਦਾ ਹਾਂ। (ਵਿਘਨ) ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। (ਵਿਘਨ) ਇਥੇ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਵਿਚ ਜੋ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : On a point of order, Madam.

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਆਪ ਨੇ ਸੁਣਾਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਵੀ । ਸਿਰਫ 15 ਮਿੰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰਜ਼ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। (The hon. Member had his say, let him now hear. The hon. Minister has been given only 15 minutes and still during that period he is being interrupted by points of order.)

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿਘ ਜੋਸ਼ : ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲਈ ਕਦੋਂ ਜਾਵੇਗੀ ।

ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ : ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਉ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਦਿਆਂਗਾ ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੇਜ਼ ਸਿੰਘ: On a point of order, Madam. ਪਿਛਲੀ ਮਨਿਸਟਰੀ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਹਰੀਜਨ ਮੈਂਬਰ ਵਾਕ ਆਊਟ ਕਰ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਹੁਣ ਬਿਰਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ: ਕਾਫੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣ ਲਉ । ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ......

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਮੋੜ ਲਉ ਪਰਾਂ ਝਗੜਾ ਖਤਮ ਕਰੋ । (Let the Minister rescind this contract and put an end to this controversy.)

(ਵਿਘਨ)

ਚੌਧਰੀ ਰਾਮ ਰਤਨ : On a point of order.

Deputy Speaker : I do not allow. (*Interruption*) I will have to name you.

ਚੌਧਰੀ ਰਾਮ ਰਤਨ : ਮੇਰਾ ਹਕ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ।

Deputy Speaker : I do not allow.

ਚੌਧਰੀ ਰਾਮ ਰਤਨ : ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਾਕ ਆਊਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

(ਚੌਧਰੀ ਰਾਮ ਰਤਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਾਕ ਆਊਟ ਕਰ ਗਏ ।)

(*Interruption*)

(ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੌਧਰੀ ਨੇਤ ਰਾਮ ਵੀ ਵਾਕ ਆਊਟ ਕਰ ਗਏ।)

(ਵਿਘਨ)

ਕਾਮਰੇਡ ਜੰਗੀਰ ਸਿਘ ਜੋਗਾ : On a point of order, Madam. (ਵਿਘਨ) ਅਸੀਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੈਨਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ? (ਵਿਘਨ) ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਾਕ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

(ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਵਾਕ ਆਊਟ ਕਰ ਗਏ।)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਇਹ ਦਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਵੈਕੂਈ ਲੈਂਡ ਬਿਰਲੇ ਨੂੰ ਦੇਵੋਗੇ ਜਾਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ?

ਗ੍ਰਿਹ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਉ। ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਾਂਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਉ।

(ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵੀ ਵਾਕ ਆਊਟ ਕਰ ਗਈ।)

ਗ੍ਰਿਹ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ 565 ਏਕੜ ਸੈਲਾਬੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, 400 ਏਕੜ ਗੈਰ ਮੁਮਕਿਨ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ...(ਵਿਘਨ)

Deputy Speaker : No noise please,

ਗ੍ਰਿਹ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 55 ਲਖ ਮਣ ਬੀਜ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਯਾਨੀ ਹਰ ਸਾਲ 11 ਲਖ ਮਣ ਬੀਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ...(ਵਿਘਨ)

Shri Amar Singh : On a point of order, Madam,

उपाध्यक्षा : मैं एलाउ नहीं कर रही। (I disallow.)

श्री अमर सिंह: आप हरिजन मैम्बरों को कुछ कहने की इजाज़त तो क्या देंगे प्वायंट आफ आर्डर भी नहीं रेज करने देते। यह क्या तमाशा है? मैं वाक आउट करता हूँ। (विघ्न)

Deputy Speaker : I will have to name you.

ਗ੍ਰਿਹ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਨਟ੍ਰੈਕਟ ਹੈ।

ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਤਰਦੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭੈੜੀ ਜਾਂ ਕੋਝੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਨਾਣ ਸਮੇਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਹਰ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀ ਹੋਵੇ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ

[ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ]

ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਾਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਿਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਡੀਡ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਰਲਾ ਫਰਮ ਪਾਸ ਵੇਚਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਡੀਡ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਖਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ। (ਵਿਘਨ)

ਸ਼੍ਰੀ **ਗੁਰਮੇਲ** : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਮੈਡਮ......

Deputy Speaker : No please, I do not allow you to rise on a point of order.

ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਮੇਲ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਿਰਲੇ ਦਾ ਜਵਾਈ ਫਰੰਟ ਵਿਚ ਛੰਭ ਜਾਂ ਖੇਮ ਕਰਨ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਫਿਰ ਬਿਰਲੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਸਿਆ ਜਾਵੇ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨਾਲ ਕਮਿਟ-ਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਰੀਜਨ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਤੇ ਰੋਸ ਪਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਕ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

(*At this stage Sarvshri Gurmail, Amar Singh, Ram Dhari Balmiki and Fakirla staged a walk out*).

(ਵਿਘਨ) (ਸ਼ੋਰ) ।

ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਟਰਪਸ਼ਨਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਥਰੈਸ਼ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹਾਊਸ ਦਾ ਵਕਤ ਵਧਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

(ਵਿਘਨ) ਸ਼ੋਰ)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਮੈਡਮ ।

Deputy Speaker : I do not allow you to rise on a point of order. No interruptions please.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਮੈਡਮ । ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਮਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਕੇਵਲ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ? ਕੀ ਬਿਰਲਾ ਹਰੀਜਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ

ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਡੀਡ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਉ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਤੌਰ ਪਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਾਕ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

(ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਰੀਜਨ ਮੈਂਬਰ ਵਾਕ ਆਊਟ ਕਰ ਗਏ।)

(ਵਿਘਨ, ਸ਼ੋਰ)

ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਂ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗਾ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵਕਤ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ, ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਜਸਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਾਂਗਾ। (ਵਿਘਨ)

ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ 1000 ਏਕੜ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘੇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਬੁਰਦ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇਵੈਕੂਈ ਲੈਂਡ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚੋਂ 1,000 ਏਕੜ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹੈ ਸਾਨੂੰ 5 ਲਖ ਮਣ ਬੀਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸਾਰੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਪਲਾਨ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੀਜ ਰੀਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਅੱਜ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਵਧ ਆਵੇ, ਯੀਲਡ ਵਧ ਆਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਝਾੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇਰੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੀਜ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਕ ਤਾਂ ਸੀ 276 ਤੇ ਸੀ 253 ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਹੈ ਬੀ 18। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀ-ਵਰਿਸਟੀ ਵਿਚ ਤਜਰਬੇ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਏਕੜ ਵਿਚ 87 ਮਣ ਕਣਕ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਤਕ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਸਾਡੀ ਐਕਚੂਅਲ ਯੀਲਡ 13 ਜਾਂ 14 ਮਣ ਦੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਇਸ ਪੱਖ ਵਿਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਤਰਵੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਥੇ ਅਸੀਂ 25 ਮਣ ਫੀ ਏਕੜ ਤਾਂ ਅਜੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਬੀਜ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੀਜ ਨਾਲ ਰੀਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਢਾਈ-ਢਾਈ ਏਕੜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਿਲਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੂਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਦੀ ਤਹਿ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਮਝਿਆ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਾਲੰਧਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ ਢਾਈ ਢਾਈ ਏਕੜ ਦੇ

[ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ]

ਮਾਲਕ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਮਰਸ਼ਲ ਕਰਾਪ ਬੀਜ ਲੈਣ ਤਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਨਾ ਬੀਜਣ ਤਾਂ ਚਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੰਗੇਰੇ ਬੀਜਾਂ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਰੀਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਝਾੜ 50 ਜਾਂ 60 ਮਣ ਤਕ ਲਿਆ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਸ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰਹਿ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਵੇਚ ਵਟ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਹੋਰ ਧੰਦੇ ਚਲਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਾੜ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕਣਕ ਦਾ ਬੀਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਤਾਂ ਰਹਿਨ ਹੀ ਰਖੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੇਚੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ 'ਨੋ ਪਰਾਫਟ ਨੋ ਲਾਸ' ਬੇਸਿਜ਼ ਤੇ ਚਲਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਚਲਾਣ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨੁਕਸ ਜਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਗਰੋਅਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਬੀਜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 50 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਚਲਾਵੇਗੀ (ਵਿਘਨ)।

FURTHER EXTENSION OF THE TIME OF THE SITTING

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਨਟਰਪਸ਼ਨਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਦੀ ਸਿਟਿੰਗ ਨੂੰ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾ ਦੋ ਵਜੇ ਐਡਜਰਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

(Since due to interruptions in the House the hon. Home and Development Minister can not justify himself. I extend the sittin of the House by another fifteen minutes. Now it will adjourn at 2 . 15 p.m.)

MOTION UNDER RULE 84 REGARDING MATTER RELATING TO LEASING OF 1,000 ACROS OF AGRICULTURAL FARM NEAR RUPAR TO BIRLA BRNTHERS,

(Resumption of discussion)

ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਥੇ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਉਠਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਲਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਚੰਗੇ ਬੀਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਤਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਰਿਆ ਬੁਰਦ ਸੀ ਅਤੇ ਕਢੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੌਰ ਖੌਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਈਕੁਇਪਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਾਈਡ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨਸਪੈਕਟਰ 1, ਸਬ-ਇਨਸਪੈਕਟਰ 4 ਅਤੇ 6 ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਲਗਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਕੁਇਪਮੈਂਟ ਵੀ ਮੰਗਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਫਸਰ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਕਈ ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 7 ਟਯੂਬ ਵੈਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੰਕ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਨਾਂ ਕੁਝ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਕ ਹਦ ਤਕ ਮਾਦੂਦ ਹੈ । ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਵੇਚਣਗੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਰਫਤ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੀਮਤ ਤੇ ਹੀ ਵੇਚਣਗੇ, ਫਿਰ ਸਿਧੇ ਖੁਲੀ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਰਫਿਤ ਕੋਆਂਪਰੇਟਿਵ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਪਾਸ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਡੀ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਣ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਥੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਹਰ ਗਰੋਅਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਪੈਟਰਨ ਹੀ ਰਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਥੇ ਮੈਂ ਇਕ ਐਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਐਸਪੈਕਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਇਸ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵੀਜੁਅਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।

2-00 p.m.

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਫਾਰਮ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਆਇਆ ਉਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਕ ਖਾਸ ਪਰਪਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਸੀਡ ਬੀਜਿਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ । ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕਿਉਂਕਿ ਅਛੇ ਬੀਜ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਬੀਜ ਅਤੇ ਆਲਾ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੀਜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਾਪ ਇਸ ਫਾਰਮ ਵਿਚੋਂ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਸਿਵਾਏ ਇਸਦੇ ਕਿ ਆਲਾ ਕੁਆਲਟੀ ਦਾ ਬੀਜ ਉਹ ਪਰੀਪੇਅਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ । ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਇਸੇ ਪਰਪਜ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਾ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਬੜ੍ਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਦੀ ਅਨਇਕਨਾਮਿਕ ਹੋਲਡਿੰਗ ਹੈ । ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਅਪਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਵੇ । ਇਹ ਤਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੀਜ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਜ਼। ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਇਸ ਪਰਪਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟ ਤੋਂ ਘਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਮਦਾਦ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿਚ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਾਸਤੇ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।ਇਹ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਲੋਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਦੇ ਹਨ, ਆਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਬੋਗਸ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ? ਇਹ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਇਹ ਕਹਿਣਾ ...

[ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ]

ਕੁਝ ਰੁਪਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਅਤੇ 17-18 ਲੱਖ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਸਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ 20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਤਕ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਇਸ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਰਿਆ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹਾਓ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੜੀਆ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਸ ਆਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਏਥੇ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਏਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੈਪੀਟੇਲਿਸਟ ਇਕੋ-ਨੋਮੀ ਦੇ ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੈਪੀਟਿਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲਾਇਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਚਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ । ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਰੂ-ਰਿਆਇਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ । (ਤਾਲੀਆਂ)

ਉਧਰ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਆਦਮੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਸਿਵਾਏ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਗਠਜੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ । ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀ ਖਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਥੇ ਕੋਈ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿਨਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਏਥੇ ਦੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਵਧਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀਡ ਫਾਰਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਦ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਚ ਅੱਛੀ ਉਪਜ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਜੇ ਥੋੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੈਲ ਰਨ ਫਾਰਮ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ । ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇੰਟਰੈਸਟ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਰਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇੰਟਰੈਸਟ ਵਿਚ ਹੈ । ਏਥੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੜਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਗੱਲ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹੀ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਕਾਰਖਾਨੇ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਜ਼ਨ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵੋਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਫਾਰਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਹਰੀਜਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇੰਟਰੈਸਟ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖ ਕੇ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸ਼ਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗੋਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਗੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸੀਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਆਂਗੇ । ਮੇਰੀ ਹਰੀਜਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ, ਏਥੇ ਆਲਾ ਬੀਜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਈ ਹੈ ਇਸ

ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਾ ਕਢਿਆ ਜਾਵੇ । ਬੀਜ ਦੀ ਇਤਨੀ ਡੀਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 25-30 ਲੱਖ ਤਕ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਪਰ ਇਤਨਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਡੀਮਾਂਡ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ (ਇਕ ਮੈਂਬਰ : ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜੋ ਇਤਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ) ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੀਜ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫੇਰ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਸੀਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਡਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗੇਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਅਜੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਮਹਿਜ਼ ਆਲਾ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੀਡ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰੀਜਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ...... ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਚੰਗੇ ਬੀਜ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਗਰ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਉਸਦੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਚੰਗੇ ਬੀਜ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਬੀਜ ਮਿਲ ਸਕਣ । ਇਸ ਵਿਚ ਨਾ ਥਾਪਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੁਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੈਪੀਟ-ਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ । ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਪਰੂਵਡ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।

ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਦਿਉ, ਮਗਰ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੰਗੇ ਤੇ ਇਮਪਰੂਵਡ ਬੀਜ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ? ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਡੀਡ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੈਂਸਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗੇ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਥੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਨਜ਼ਨ ਸਪੀਚ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਬੁਜ਼-ਦਿਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਦਾ ਜੇ ਉਹ ਇਥੇ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਨਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ । ਮੈਂ ਫੇਰ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ, ਜਦ ਸਾਡਾ ਦਾਅ ਲਗੇਗਾ । ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਫੂਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਮਗਰ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਸਖਤ ਗੱਲਾ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ "ਵਾਦਾ ਏ ਹੂਰ" ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ । ਔਰ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਜਗਨ ਨਾਥ ਨੇ ਲਫਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰਾਓ । ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਤਅੱਲੁਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਲਫਜ਼ *ਜਗਨਨਾਥ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ , ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Deputy Speaker : The House now stands adjourned till 9-00 a.m. tomorrow.

2.15 .pm.

(*The Sabha then adjourned till 9 a.m. on Friday, the 19 November, 1965.*)

*Note :—In this connection please see page (22)75 omite.

1563—14-6-66—C,. P. & S,. Pb,- Patiala.

PUNJAB VIDHAN SABHA

DEBATES

19th November, 1965

Vol. II—No. 23

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Friday, the 19th November, 1965.

Punjab Vidhan Sabha Secretariat, Chandigarh.

Price : Rs. 3.20

ERRATA

to

Punjab Vidhan Sabha Debates Vol. II, No. 23, dated the 19th November, 1965

Read	*For*	*Page*	*Line*
view	vtew	Title	5 from below
ਮੈਂ	ਮਂ	(23)1	5 Ditto
ਸਿੰਘ	ਸਿਘ	(23)1 (23)50	3 Ditto 5 Ditto
चूंकि	वूंकि	(23)3	6 Ditto
रूलिंग	रुलगिं	(23)5	16
पट्टी	पट्ट्टी	(23)5	24
AND	RND	(23)7	Heading
House	Hous	(23)7	9
कांफ्रेंस	कांनफ्रेंस कांनफ्रेंस	(23)7 (23)7	3 from below last but one
खुद	खूद	(23)7	last
सिक्योरिटी	सिक्योर्ि टी	(23)9	8
against	agai st	(23)31	5
interruptions	interrupt ons	(23)37	6 from below
practice	practic	(23)40	7 Ditto
matter	Matter	(23)40	4 Ditto
दुश्मन	दूश्मन	(23)42	25
डिप्टी	डि टी	(23)44	23
ਬਾਬੂ	ਬਾਬੂ	(23)44	7 from below
up	p	(23)44	last but one
NOVEMBER	NOVEMB R	(23)45	22
Legislatures	Legislaturs	(23)46	last

Read	*For*	*Page*	*Line*
ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ	ਨਰਾਿ ਣ ਸਿੰਘ	(23)48	3
ਇਸ	ਿ ਸ	(23)49	6
ਹਾਟੀਐਸਟ	ਹਾ ਿਐਸਟ	(23)49	13 from below
Common-Wealth	Cemmonwealth	(23)54	13
RESOLUTION	REESOLUTION	(23)55	Heading
	SOLUTION	(23)57	Heading
Whatever	Whetever	(23)57	2
Add the word 'QUIT' after the word 'SHOULD'		(23)63	Heading

PUNJAB VIDHAN SABHA

Friday, the 19th November, 1965

The Vidhan Sabha met in the Vidhan Bhawan, Sector 1, at 9.00 a. m. of the Clock. Deputy Speaker (Shrimati Shanno Devi) in the Chair.

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

ELECTRIFICATION OF CERTAIN VILLAGES IN TEHSIL HANSI

***8806. Shri Amar Singh** : Will the Minister for Transport and Elections be pleased to state whether there is any proposal to provide electricity to the villages in Hansi Tehsil which are in pockets, namely, Rakhi Shahpur, Kapro, Khot Kalan, Khot Khurd, Kinar, Nara, Kheri Jalib, Lochach, Bas, Sorkhi etc., if so, the approximate date by which the same is likely to be implemented ?

Sardar Gurdial Singh Dhillon : Owing to lack of funds no programme has been drawn up yet for taking up new villages for electrification.

चौधरी अमर सिंह : गवर्नमेंट के सरकुलर के मुताबिक मैं ने अपनी सब-डिवीज़न में 10 गांव ऐसे बताए थे जो कि pocket villages हैं । क्या उन को मन्त्री महोदय इलैक्ट्रीफाई करवाने की कृपा करेंगे ?

मंत्री : 10 गांवों की पाकिट तो नहीं होती । लेकिन जब फंड्ज़ अवेलेबल होंगे तो आप का काम सब से पहले किया जाएगा ।

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਥੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਉਥੇ ਬਿਜਲੀ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ?

ਮੰਤਰੀ : ਨਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਫੰਡਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਜਿਥੇ ਕੋਈ ਵਰਕਸ ਇਨ ਹੈਂਡ ਹਨ **ਜਾਂ** ਜਿਥੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਕ ਅੱਧਾ ਪਿੰਡ ਅਨਕੁਨੈਕਟਿਡ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿਘ ਭੌਰਾ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਥੋਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਖਰਚ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ?

ਮੰਤਰੀ : ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਰੂਰਲ ਇਲੈਕਟਰੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅਧ ਮੀਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪਿੰਡ ਹੋਣ ਉਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਬਾਕੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਖਰਚਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ।

श्री सागर राम गुप्ता : क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि जिन इलाकों में ड्रिंकिंग और इरीगेशन के लिए पानी नहीं है उन के लिए भी सरकार की यही पालीसी है या उन के लिए फंड्ज़ मुहैया किए जा सकेंगे ?

मंत्री : जो रूरल इलैक्ट्रीफीकेशन का प्रोग्राम है वह प्रोग्राम के तौर पर ही है । लेकिन उन का बुनियादी असूल थोड़ा सा बदल दिया गया था । हम ने उन को कहा था कि ऐग्रीकल्चर डिपार्टमैंट की राए से जहां फूड प्रोडक्शन का सवाल हो वहां बिजली दी जाए लेकिन अभी तक पैसे ही नहीं हैं । बाकी ड्रिंकिंग वाटर के सिलसिले में मेरे पास अभी तक कोई तजवीज़ नहीं है ।

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਿਤੀ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰੂਰਲ ਇਲੈਕਟਰੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ?

ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਸੂਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਿਉ, ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਐਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਵਗੈਰਾ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਆਂਗੇ । ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ [ਉਹ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾ ਦਿਤੀ ਹੈ । ਇਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਂ ਫਲਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਜਾਵੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਥੇ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਆ ਗਏ ਹੋਣ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਪਰਾਇਆਰਿਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਮੋੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।]

लाला रुलिया राम : क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि जो खादर या बैकवर्ड एरिया है जहां पर खेती के सिवाए और कोई लोगों का साधन नहीं वहां लोगों को टयूबवैल्ज़ के लिए बिजली दी जाएगी ? उन लोगों पर कृपा करेंगे ?

मंत्री : हमने तो आप की खिदमत करनी है । कृपा करने वाला तो बोर्ड बना हुआ है । जैसे आप ने मुझ से कहा है मैं इस से भी 10 गुना ताकत से उन को कहूंगा ।

ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਲਾਇਲਪੁਰੀ : ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰਖੀ ਹੈ । ਜੇ ਕੋਈ ਉਹ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਹਿਰੂਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਇਕ ਕਮਰਸ਼ਲ ਮਹਿਕਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਅਟਾਨੋਮਸ ਬਾਡੀ ਦੇ ਥਲੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਨ । ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਏਸ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ।

श्री जगन्नाथ : मंत्री महोदय ने बताया है कि इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड अटानोमस बाडी है । इंडीपैंडैंट है । मैं पूछना चाहता हूं कि जब आप का उन के ऊपर कंट्रोल नही है तो फिर मुख्य मंत्री साहिब के हलके में या आप के ज़िले के अंदर, आप के हलके के अंदर ज्यादा गांव इलैक्ट्रीफाई होने की क्या वजह है ?

मंत्री : जब से मैं मिनिस्टर बना हूं आप को शक नहीं होना चाहिए कि वहां कुछ हुआ है । बाकी जो वहां बिजली दी गई है वह आप के हिस्से से काट कर नहीं दी गई । जो जोगिन्दर नगर से पाकिस्तान को सपलाई होती थी जब वह बन्द की गई तो फिर वहां उन गांव को मिली है ।

ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦਿਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਇਕ ਅਧ ਪਿੰਡ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਥੇ ਸਾਲਮ ਦਾ ਸਾਲਮ ਬਲਾਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਕੀ ਉਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ ?

ਮੰਤਰੀ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੰਜ ਸੱਤ ਪਿੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਬੜੀ ਆਜਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਦਸ ਦਿਤੀ ਹੈ ।

चोधरी नेत राम : मैं वज़ीर साहिब के ध्यान में लाना चाहता हूं कि 1962 के चुनाव से पहले के फतेहबाद से 12 मील भट्टू कलां में बिजली के खम्बे और तारें लगी हुई हैं लेकिन चूंकि कांग्रेस वहां हार गई इस लिए वहां बिजली नहीं दी गई और वहां जो तारें वगैरा पड़ी थीं वह भी वहां से उठा कर ले गए। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वहां बिजली देने की कृपा करेंगे ?

ਸਰਦਾਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ : ਬੋਰਡ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦੇਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗਰੀਬ ਹਨ ਤੇ ਡੀਜ਼ਰਵਿੰਗ ਹਨ ਉਹ

[ਸਰਦਾਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ]

ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ । ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਰਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਆਇਤ ਦਿਤੀ ਜਾਏ ?

ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ।

श्री अमर सिंह : वज़ीर साहिब ने फरमाया है कि 10 गांव का पाकिट नहीं बनता, तो क्या मैं पूछ सकता हुं कि जहां पांच का पाकिट हो वहां बिजली देंगे ?

मंत्री : मैं अर्ज़ करता हुं कि यह जो 24 गांव का सब प्राजैक्ट बना हुआ है इस में यह तो गांव सुरखी और मुढला कवर्ड हैं बाकी गांव का अभी प्राजैक्ट सैंक्शन होना है ।

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ । ਕਲ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪਾਵਰ ਮਨਿਸਟਰ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਕਾਰਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਜ ਫਿਰ ਰੂਰਲ ਇਲੈਕਟਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੂੰ ਐਪਰੋਚ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਲਵੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਲਵੇ ?

ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੋਰਡ ਅਟਾਨੋਮਸ ਬਾਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਟਾਨੋਮਸ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਕੀ ਅਖਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ । ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੇਟ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

श्री सागर राम गुप्ता : वज़ीर साहिब ने फरमाया है कि यह कमर्शल बाडी है और हम जानते हैं कमर्शल हाऊसिज़ किस तरह चलते हैं । यह जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं उन को इलैक्ट्रीफाई करना कभी कमर्शल प्राजैक्ट नहीं हो सकता । तो क्या मैं पूछ सकता हुं कि आखिर इन बैकवर्ड अलाकों को कैसे ऊपर उठाना है और क्या कभी इन अलाकों में और अलाकों के बराबर बिजली जा सकती है ?

मंत्री : मैं ने पहले भी पिछले दिनों सवालों का जवाब देते हुए बताया था कि गवर्नमैंट ने उन को यह पालीसी अब दी है कि जिन इलाकों में ज्यादा बिजली दी गई है और जिन में कम दी हुई है इस फर्क को निकालना है । उनको हिदायात दे दी गई हैं कि आने वाले प्रोग्राम में जो बैकवर्ड हैं उन्हें आगे बढ़े हुए अलाकों के बराबर लाया जाना है ।

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜੋ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹਨ ਉਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕੀ ਸਟੈਪਸ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ?

ਮੰਤਰੀ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ।

Chaudhri Darshan Singh : May I know from the hon. Minister as to who makes the appointment of the Members and the Chairman of the Board ? If it is the Government of India then on whose recommendation these appointments are made ? Who is competent to remove the Members and the Chairman of the Board ?

ਮੰਤਰੀ : ਜੇਕਰ ਆਪ ਹਾਊਸ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿਉ ਤਾਂ ਅਲਗ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ । ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗੌਰਮਿੰਟ ਹੀ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਵਕੀਲ ਹੋ । ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਕੋਪ ਆਫ਼ ਦੀ ਐਕਟ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

श्री सागर राम गुप्ता : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आप की रूलिंग चाहता हूं कि जब कोई बात पालिसी के बारे में हो, वह पालिसी की बात सप्लीमेंटरी सवाल के जवाब से पैदा हो जाए तो क्या किसी माननीय सदस्य को उस के बारे में सवाल करने की इजाज़त है या नहीं ?

मंत्री : मुझे कोई इतराज़ नहीं । आखिर एक चीज़ से ही दूसरी चीज़ पैदा होती है । दुनिया में ऐसा तरीका सदियों से चला आ रहा है । (हंसी)

श्री जगन्नाथ : जब सरदार गुरदयाल सिंह ढिल्लों और मैं एक जीप पर बैठ कर पट्टी के इलैक्शन में प्रापेगंडा करने के लिए जाते थे तो वहां पर हम दोनों ने देखा कि कहीं पर पोल बिजली लगाने के लिए रखे गए और कहीं पर लकड़ी के पोल बिजली लगाने के लिए रखे गए थे । वह केवल इलैक्शन प्रापेगंडा था क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्होंने उस बात मेरे साथ कहा नहीं था कि सरकार क्या हेरा फेरी कर रही है ?

मंत्री : किसी को हेरा फेरी की ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर थोंपने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। (हंसी)

श्री फकीरिया : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मुझे हाउस में बहुत ही कम बोलने के लिए समय मिलता है । इसलिये मुझे सप्लीमेंटरी सवाल करने की इजाजत दे देनी चाहिए । नरवाना तहसील में अभी तक बिजली देने का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया । यह इलाका बहुत बैकवर्ड है । इस बात को सरकार खुद मानती है । क्या वज़ीर साहिब बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस इलाके को बिजली देने की कोई स्कीम है या नहीं ?

मंत्री : इस बारे में पहले जो वज़ीर थे, वह जवाब देने के लिए बहुत उत्सुक हैं । वह पुरानी बात को कलीयर करना चाहते हैं । इसलिए वह उस के बारे में जवाब देंगे ।

लोक कार्य मंत्री : मैं तो कोई जवाब देने के लिए खड़ा नहीं हुआ । मैं तो पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं । उस वक्त कोई हेरा फेरी नहीं हुई थी । मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय को गलतफहमी है ।

श्री फकीरिया : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरे सप्लीमेंटरी का जवाब नहीं दिया गया ।

परिवहन तथा चुनाव मंत्री : इस सवाल में केवल 5 और 7 गांवों के बारे में पूछा गया है । इस सवाल के साथ सारे पंजाब का कोई सम्बन्ध नहीं है । आगे के लिए मैं सारे पंजाब के मसले के बारे में तैयार हो कर आया करूंगा । इस दफा गलती हो गई है ।

श्री राम धारी वालमीकि : दो साल पहले पानीपत और रोहतक के दरमियान बिजली के खम्बे लगे और अभी तक वहां पर बिजली की तारें लगाई नहीं गई । क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इस की वजह यह है कि सरकार गोहाना तहसील को बिजली मोहैया नहीं करना चाहती और क्या तभी वहां पर तारें नहीं लगाई गई ?

मंत्री : श्री अमर सिंह ने केवल पांच और सात गाँव जो कि तहसील हांसी में हैं, उन के बारे में सवाल पूछा है । डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं इस के बारे में जवाब लेकर हाउस में आप की खिदमत में हाजिर हो गया । अगर माननीय सदस्य किसी और गांव के बारे में या और कोई बिजली के बारे में इन्फार्मेशन चाहते हैं तो वह मेरे पास आ जाएं । मैं उन को इन्फार्मेशन दे दूंगा ।

REHABILITATION OF PUNJABIS UPROOTED AS A RESULT OF PAKISTANI AGGRESSION

*3710 Comrade Shamsher Singh Josh : Will the Minister for Transport and Elections be pleased to state;—

(a) whether the State Government has submitted any Memorandum/Note etc. to the Union Government seeking their help

in rehabilitating the Punjabis uprooted as a result of the Pakistani aggression; if so, a copy thereof be laid on the Table of the House ;

(b) the details of reply, if any, received from or commitment, if any, made by the Union Government in connection with (a) above ?

Sardar Gurdial Singh Dhillon : (a) and (b) Yes.

The matter being still under consideration of the Union Government, the stage for laying any papers on the Table of the Hous has not reached as yet.

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ (ਧਾਲੀਵਾਲ) : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ?

मंत्री : जिस ससय रिफूजी श्राए, उस के बारे में काफी देर तक मिलटरी श्रथाटीज़ ने पोज़ीशन कलीयर नहीं की कि पाकिस्तान के पास हमारे कितने गांव चले गए श्रौर हमारे पास उन के कितने गांव हैं। हम ने इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए कोशिश की । जहां तक रिफूजियों को रीलीफ देने का सम्बन्ध है, मैं श्रर्ज़ करना चाहता हूं कि रिफूजियों को बसाने के लिए, राशन देने के लिए, इंडस्ट्रीज़ को रीहैबिलीटेट करने के लिए टैक्सों में रिलीफ देने के लिए केन्द्रीय सरकार के साथ खतो किताबत होती रही । उस के बाद जिस वक्त चीफ मिनिस्टर्ज़ की कांफ्रेंस हुई उस में प्वायंट रेज़ किया गया कि जो गांव पाकिस्तान के हमारे कब्ज़े में श्रा गए, वहां पर जो फसलें खड़ी हैं, क्या वह फसलें काटी जाएं श्रौर कुलैक्ट की जाएं या नहीं । श्रगर मिलटरी श्रथार्टीज फार दी टाईम बीइंग इजाज़त दे दें तो लोग उस ज़मीन को इस्तेमाल कर सकें । इस के बाद बहुत सारी चीज़ें जैसा कि इंडस्ट्रीज़ को रीहैबीलीटेट करने का मसला है श्रौर दूसरे कंसैशन जो सरकार ने दिए हैं, उन की जानकारी माननीय सदस्यों को होगी । हमारी जबरदस्त खाहिश है कि उन के बसाने के लिए प्रान्त के श्रन्दर ज़मीन मिल सके तो दे दी जाए । हम ने सोचा कि पंचायतों के पास जो ज़मीन पड़ी है वह दे दी जाए । हमें मालूम हुश्रा कि पंजाब की बहुत सारी पंचायतों ने वह ज़मीन खुद काश्त कर रखी है । वह भी ज़मीन इन को देने में रुकावट पड़ गई । हम ने सोचा कि प्रान्त में जो वेस्ट लैंड पड़ी है, उस को सरकारी खर्च पर रीकलेम करके इन को दे दी जाए । इस के लिए गवर्नमेंट श्राफ इंडिया के साथ खतोकिताबत चल रही है । मानयोग सदस्य मेरे साथ सहमत होंगे कि इस मसले को सैटल करने के लिए समय दरकार होता है । देहली में श्रौर भी कांनफ्रेंस हुई वहां पर सारी चीज़ पर जोर दिया गया । उस कांनफ्रेंस में चीफ मिनिस्टर साहिब, होम मिनिस्टर साहिब श्रौर मैं खूद हाज़िर था ।

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਹੈ । ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਫੂਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲਗੇਗਾ ? ਮਾਨਯੋਗ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 1947 ਦੇ ਰਿਫੂਜੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਿਜ਼ ਅਜੇ ਤਕ ਸੈਟਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ । ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੈਸਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ?

मंत्री : इस के बारे में अर्ज़ करना चाहता हूं कि 1947 में जो लोग रिफूजी बन कर आए और अब जो लड़ाई की वजह से रिफूजी हुए हैं उन के रीहैबीलीटेट करने में फर्क है । माननीय सदस्यों को मालूम ही है कि इस बारे में आफिशल गाइंड किस तरह से चलता है । उस वक्त जो लोग आए थे, वह वहां पर अपनी जमीन और जायदाद छोड़ कर आए थे । उन को उस के बदले में ज़मीन दी गई । इस वक्त हमारा जो प्राबलम है वह डिफ्रेंट है । कुछ गांव 'ए' केटेगरी के पाकिस्तान के कब्ज़े में चले गए । केटेगरी 'बी' के विलेजिज़ जो पहले बार्डर के नज़दीक थे खतरनाक हैं लेकिन ज्यों ज्यों मिल्टरी कह देगी कि वह सेफ हैं तो दोबारा उन लोगों को वहां पर जाना पड़ेगा क्योंकि वह हमारे कब्जे में हैं। इस पालीसी को तय करना गवर्नमेंट आफ इंडिया का काम है । पंजाब गवर्नमेंट अकेली नहीं कर सकती । मैं समझता हूं कि पंजाब में रीलीफ और रीहैबिलीटेशन का मसला बार्डर डिस्ट्रिक्ट्स का मसला नहीं, न सिर्फ पंजाब का ही है, बल्कि सारे हिन्दोस्तान का मसला है । हम ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और इर्द गिर्द की दूसरी स्टेट्स को अपील की है कि अगर वे इन युद्ध पीड़तो को ले सकते हैं तो ले लें । लेकिन यह सारी बात गवर्नमेंट आफ इंडिया की लैवल पर होगी ।

ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਤਿਆਗੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੇ ਰੀਲੀਫ ਐਂਡ ਰੀਹੈਬੀਲੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ।

ਮੰਤਰੀ : ਤਿਆਗੀ ਜੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ । ਇਕ ਤਾਂ ਖਤੋ ਕਿਤਾਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਲਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ । ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰਿਫੀਊਜੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰੋ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਕਾਠ, ਛਕਣਾ ਛਕੌਣਾ ਅਤੇ ਪਹਿਰਾਵਾ ਸਾਰਾ ਡਿਫਰਿਟ ਹੈ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੀਲੀਫ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ । ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਡਤ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਅਤੇ ਪੰਡਤ ਭਗਵਤ ਦਿਆਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਨ । ਅਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਤੀ । ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ।

ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀਆ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ?

Deputy Speaker : It does not arise.

श्री सागर राम गुप्ता : मैं यह जानना चाहता हूं कि अमृतसर, बटाला और दूसरी जगहों से जो मज़दूर पाकिस्तान के साथ लड़ाई के कारण हज़ारों की तादाद में अपरूट हुए हैं उन के लिए पंजाब सरकार ने क्या, सहायता सैंट्रल गवर्नमेंट से मांगी है और खुद भी क्या किया है ?

मन्त्री : उन के लिए 25 लाख रुपया हम ने अलग रखा था ताकि जिस जिस फर्म में काम करते हैं उन के मालिकों के जरिये उन में वह रुपया बांटा जाए। लोन्ज़ को कुछ ऐसी कंडीशन्ज़ थीं कि [illegible] देन [illegible] थी लेकिन कुछ मुश्किलात पेश आईं। अब हम ने फैसला किया है कि दोबारा उस स्कीम को रीवाईज़ करके ऐसी शक्ल में पेश किया जाए कि वह शर्तें भी रीलैक्स हो जाएं।

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਤੇ ਔਫੀਸ਼ਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਰਵੈਈਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜੰਗ ਲੜੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਬਰਡਨ ਨੂੰ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਰਡਨ ਨੂੰ ਚੁਕਣ, ਕੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਲ ਕੀ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਹਨ ?

मुख्य मन्त्री (कामरेड राम किशन) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह सवाल कई बार हाउस में उठा है, इसकी कुछ हद तक मैं वज़ाहत भी कर चुका हूं। जहां तक हमारे डिसलोकेटिड और डिसप्लेस्ड परसन्ज़ को परमानेंटली रीहैबिलीटेट करने का सवाल है वह इंडिया और पाकिस्तान के रेज़ोल्यूशन के सेक्योरिटी कौंसल मे फैसले पर मुनहसर है। अगर फैसले के मुताबिक दोनों तरफ की फौजें विदडरा हो जाती हैं और जो जो इलाका जिस जिस कंटरी के कबज़े में आया है वह वहां से विदडरा हो जाता है तो वहां के डिसलोकेटिड और डिसप्लेस्ड परसन्ज़ को अपने इलाके में वापस जाना पड़ेगा। उस वक्त उन को रीहैबिलीटेट करने का और तरीका होगा। जो ज़मीन या मकानात वह वहां पर छोड़ कर आए हैं वह उनको मिलेंगे लेकिन उनकी रीहैबिलीटेशन के लिये उनके मकानात की नए सिरे से तामीर करने के लिये या खेती के लिये जिस जिस सामान की ज़रूरत हो वह उनको देना पड़ेगा। और अगर कोई फैसला नहीं होता है तो उनको दूसरे ढंग से आबाद करना पड़ेगा। इस सम्बन्ध में कई बार गवर्नमैंट आफ इंडिया के अफसरान से और वज़ीरों से बात चीत हुई है। इस बात का जो फैसला होगा उसी के मुताबिक प्रोग्राम बनाया जाएगा। जहां तक पंजाब गवर्नमैंट का और केंद्रीय सरकार का ताल्लुक है मैं हाउस को यकीन दिलाता हूं कि वह पूरी तरह से ऐसे डिसप्लेस्ड परसन्ज़ को बसाने की हर तरह से सहायता देगी, किसी तरह से भी गफलत

[मुख्य मंत्री]

नहीं करेंगी । यह बात सब भाई जानते हैं कि जब तक जमीन और सारी चीज़ का फैसला नहीं हो जाता तब तक किसी प्रकार का प्रोग्राम बनाना कि क्या पालिसी तय की जाए, उनको किस तरह से बसाया जाए, नामुमकिन है । लेकिन मैं फिर हाउस को यकीन दिलाना चाहता हूं कि उन भाइयों को बसाना, उनकी मदद करना, उनकी सहायता करना हमारी पवित्र और सेंक्रिड ड्यूटी है, उसको सर अंजाम देने में हम किसी तरह की ग़फलत नहीं करेंगे ।

ਸਰਦਾਰ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ : ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਪਵਿਤਰ ਧਰਮ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਿਆਦ ਮੁਕਰੱਰ ਕਰ ਦਿਉ । ਪਹਿਲੇ ਇਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਢਿਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਪਰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਹਨ । ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਿਆਦ ਮੁਕਰੱਰ ਕਰ ਦੇਣ, ਭਾਵੇਂ 6 ਮਹੀਨੇ, ਭਾਵੇਂ 3 ਮਹੀਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।

मुख्य मन्त्री : गवर्नमैंट जो भी एलान करती है सोच समझ कर करती है और पूरी तरह से उस पर अमल किया जाता है । (तालियां)

(*Interruption*)

ਸਰਦਾਰ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ......(ਵਿਘਨ) ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ....।

Deputy Speaker : No, please resume your seat.

पंडित भागीरथ लाल : डिप्टी स्पीकर साहिबा, आज सारे हिन्दुस्तान के अन्दर इस बात की चर्चा चल रही है कि 80 के करीब लड़कियों को पाकिस्तानी हमारे इलाके से अगवा करके ले गए । हम चाहते हैं कि चीफ मनिस्टर साहिब इस सम्बन्ध में पुज़ीशन किलयर करें कि गवर्नमैंट की क्या पोज़ीशन है ।

उपाध्यक्षा : आप को सप्लीमैंटरी पूछने की इजाज़त दी गई थी, काल-अटैनशन मोशन मूव करने की नहीं । इस सम्बन्ध में एक काल-अटैंशन मोशन आ रही है और उस पर मैं गवर्नमैंट को कहूंगी कि स्टेटमेंट दें । (I have permitted the hon. Member to put a supplementary question and not to move Call-Attention Motion. In this conection a call Attention Notice is coming up and I would ask the Government to make a statement on it).

श्री जगन्नाथ : ऐसे आदमियों को हाउस से बाहर करो । यह छाताधारी कहां से आ गए हैं । (विघ्न)

उपाध्यक्षा : आर्डर प्लीज़। सयानें आदमियों को इस तरह से बीहेव नहीं करना चाहिए। हाउस के डैकोरम का भी ख्याल करना चाहिए। (Order, please. Responsible persons should not behave like this. After all, maintenance of decorum of the House should not be lost sight of.)

(इस समय चौधरी नेत राम अपनी सीट पर खड़े हुए)

उपाध्यक्षा : चौधरी नेत राम, आप की सप्लीमैंटरी क्या है ? (What is your supplementary, Chaudhri Net Ram ?)

चौधरी नेत राम : मैं प्वायंट आफ़ आर्डर के लिए खड़ा हुआ हूं।

उपाध्यक्षा : मैंने आप को सप्लीमैंटरी की इजाज़त दी है। वह आप पूछ लें। (I have permitted him to put a supplementary. He may ask that.) (*Interruptions, noise*)

चौधरी नेत राम : मैं प्वायंट आफ आर्डर पर खड़ा हुआ हूं। मेरा प्वायंट आफ आर्डर यह है कि जब शाहबाज़पुरी साहिब बोल रहे थे तो आप ने उन से कहा था कि चौधरी नेत राम वाले तरीके को मत अपनाओ। डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं हैरान हूं कि आप ने यह बात कैसे कह दी। मैं तो आपोज़ीशन में हूँ और गवर्नमैंट की हर त्रुटी की, हर कमज़ोरी की आलोचना करनी हमारा फर्ज़ है, हक है.........

उपाध्यक्षा : आप बैठिए। (The hon. Member may resume his seat.)

चौधरी नेत राम : आप ने इस तरह से जो कहा अगर इस किस्म की बातें हों तो हम बरदाश्त नहीं करेंगे। क्या आप यह चाहती हैं कि मैं सरकार की पालिसी की आलोचना न करूं ? आप ने उन को कह दिया कि चौधरी नेत राम जैसा तरीका मत अपनाओ। मैं कहूंगा कि यह हज़ारों एकड़ ज़मीन यहां राजधानी में पड़ी है। यह क्या जनता के साथ मज़ाक किया जा रहा है। . . . . . . (*Noise. Nothing was audible correctly.*)

उपाध्यक्षा : चौधरी नेत राम, बैठिए। (Chaudhri Net Ram may please resume his seat.)

चौधरी नेत राम : यह सारा सरमाएदारों को फायदा पहुंचाने का काम हो रहा है। सरकार सरमायादारों के हाथों में खेल रही है।

उपाध्यक्षा : चौधरी नेत राम।

चौधरी नेत राम : यह गरीबों पर टैक्स लगाएंगे और लाखों रुपए का सरमायेदारों को फायदा पहुंचाएंगे। सरकार पंजाब की जनता का इस तरह से बुरा हाल कर रही है और आप कहती हैं कि चौधरी नेत राम वाला तरीका न अपनाना। यह ऐसी ना अहल सरकार है........

(इस समय सरदार तारा सिंह प्वायंट आफ आर्डर पर खड़े हुए।)

उपाध्यक्षा : सरदार तारा सिंह, पहिले मुझे चौधरी नेत राम के प्वायंट आफ आर्डर का तो जवाव दे लेने दो।

चौधरी नेत राम, मैं कह देना चाहती हूं कि आप का बीहेवियर मुझे पसन्द नही है। मैं इतने बुज़ुर्ग आदमी को नेम नहीं करना चाहती मगर आप का यहां पर ढंग बिल्कुल गलत है। आप खड़े हो जाते हैं और बावजूद बार बार मेरे रोकने के भी बोलते ही जाते हैं। यह बिल्कुल नामुनासिब बात है। यह मैं आप को लास्ट वार्निंग देतो हूं। वह जो मैंने उन को कहा वह बिल्कुल सही कहा कि सियाने सियाने पुराने पार्लेमैंटेरीशंज़ को आप की तरह खड़ा होकर आप को फालो नहीं करना चाहिए। मैं आप को लास्ट वार्निन्ग देती हूं कि अगर अब काम में विघ्न डाला तो मैं आप को इस बांत की हरगिज़ इजाज़त नहीं दे सकती। (*Addressing Sardar Tara Singh.*) (Please let me first answer the point of order raised by Chaudhri Net Ram). (*Addressing Chaudhri Net Ram*) I may tell the hon. Member that I do not countenance his behaviour with favour. I do not want to name a "buzurg" like him but the way in which he behaves here is not at all desirable. He gets up and continues speaking despite my stopping him time and again from doing so. This is most improper. I give him the last warning. Whatever I said to the hon. Member (Sardar Narain Singh Shahbazpuri) was perfectly correct that an intelligent and an old Parliamentarian like him should not abruptly get up and follow in the foot-steps of the hon. Member. I give him the last warning. I cannot permit him to interrupt the proceedings.)

ਸਰਦਾਰ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ (ਚੌਧਰੀ ਨੇਤ ਰਾਮ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ) ਫ਼ਾਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। (ਵਿਘਨ)

उपाध्यक्षा : ग्राप इस तरह से मत समझो कि चेयर पर कोई खिलौना बैठा हुग्रा है। (*Voices of point of order*) जो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर प्वायंट ग्राफ ग्रार्डर करेगा उसे मैं इजाज़त नही दूंगी। ग्रगर इस तरह से चिल्ला कर बोलना है तो बाहर चले जाइए। हाऊस इस तरह से बोलने के लिए नहीं है। [The hon. Members should not remain under the impression that some doll is presiding -- (*Voices of point of order*) -- I will not permit those who shout to raise points of order. If the hon. Members are to cry hoarse, they should better go out. This House is not meant for such things.]

ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਲਾਇਲਪੁਰੀ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ਼ ਆਰਡਰ, ਮੈਡਮ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਬੜੇ ਤਮਤਰਾਕ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ ਅਫੈਕਟਿਡ ਇਲਾਕੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਤਲਖ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਜਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਵਜੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈ। ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੇਮ ਕਰਨ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਜੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਢਿੱਲੇ ਰਹਿਣ ਉਤੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਕ ਆਊਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

(*At this stage Sardar Tara Singh Lyallpuri staged a walk-out.*)

श्री ग्रोम प्रकाश ग्रग्निहोत्री : क्या वज़ीर साहिब यह बताएंगे कि जैसा कि उन्होंने कहा है कि मज़दूरों के लिए पच्चीस लाख रुपए की रक्म रीज़र्व की गई है ग्रौर बताया है कि जिस मज़दूर को इंडस्ट्रियलिस्ट रिकमैंड करेगा उसी को इसमें से लोन की रक्म दी जाएगी मगर ग्राज तक किसी भी मज़दूर को कोई लोन नहीं मिला। ग्राज तक किसी मज़दूर को एक पैसा भी नहीं मिल पाया। क्या मैं यह जान सकता हूं कि सरकार ने मज़दूरों को लोन देने के ग्रपने तरीकाकार में कोई तब्दीली की है, ग्रौर ग्रगर की है, तो वह क्या है ?

(इस समय सरदार तारा सिंह लायलपूरी को, जो कि वाक-ग्राउट कर रहे थे, कांग्रेसी बैंच से किसी माननीय सदस्य ने रोका ग्रौर उधर कुछ शोर सा सुनाई दिया।)

उपाध्यक्षा : गर्ग साहिब, सरदार तारा सिंह वाक-ग्राउट करके जा रहे हैं ग्रौर उधर ग्राप के मेम्बर उन को रोक रहे हैं। ग्राखिर यह क्या मज़ाक है ? यही ग्राप की पार्टी का निज़ाम है ? (विघ्न)

[उपाध्यक्षा]

मैं इस आगस्ट हाउस के आनरेबल मेम्बर साहिबान से बड़े अदब से दरखास्त करूंगी कि मुझे शर्म आती है कि यहां पर मैं बैठी हूं और हाउस में इस किस्म का ढंग चल रहा है। डैकोरम का बिल्कुल ख्याल नहीं किया जा रहा। मै साफ़ तौर पर बड़ी नम्रता से यह वाज़ाय कर देना चाहती हूं कि मैं इस ढंग की आदी नहीं हूं। मुझें यह चीज़ बिल्कुल ना पसन्द है। जब सन् 1951 में मुझ हाउस की इसी कुर्सी पर बैठाया गया था तो उस वक्त तमाम हिन्दुस्तान के लोगों की तरफ से मुझे तारें आई थीं कि आप इस चेयर पर बैठीं हैं तो हाउस का निज़ाम अच्छा रहेगा, हाउस में डैकोरम और डिसिपलिन अच्छा रहेगा। मैं बड़े अदब से आप से यह पूछना चाहती हूं कि क्या आप मुझे नाकामयाब करना चाहते हैं या आप मुझ पर एतमाद नहीं रखते। अगर ऐसी बात है तो आप मुझे बता दीजिए। लेकिन यह बात मुझे बिल्कुल नापसंद है कि एक आदमी बगैर चेयर की इजाज़त के उठकर बोलता चला जाए, उसको चेयर की तरफ से रोका जाए और वह परवाह न करे। मैं नहीं चाहती किसी को नेम करूं। मैं नहीं चाहती कि किसी के खिलाफ कोई और ऐक्शन लूं। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि हाउस को इस तरह से फिश मार्किट बनाया जाए और हाउस को हाउस ट्रीट न किया जाए। मैं यह हरगिज पसन्द नहीं करती। मैं अब बड़े अदब से दरखास्त करती हूं कि मेम्बर साहिबान हाउस के निज़ाम को ठीक ढंग से चलने दें। [*Addressing Shri Ram Partap Garg*] (Sardar Tara Singh is going out after staging a walk-out but the Members of his party are obstructing him. What is this fun ? Is this the discipline in his party ? (*Interruption*)

I would respectfully like to submit to the hon. Members of this angust House that I feel ashamed to find this state of affairs in the House while I am occupying the Chair. I find that maintenance of decorum is being completely ignored. I would plainly but humbly make it clear that I am not accustomed to this way of doing things. This is not at all to my liking. In 1951 when I was elected to this Chair, I received telegrams from all over India that with my elevation to this Office, there would be perfect discipline and decorum in the House. I would respectfully like to enquire from the hon. Members whether they are out to prove me unsuccessful or they have no confidence in me. If that is so, then I may be informed. I treat this fact with disfavour that without the permission of the Chair, a Member should rise and go on speaking without caring to obey the Chair's direction to stop doing so. I have no intention to name anybody. I have no mind to take any action against anybody. But this does not mean that the

House be converted into a fish market and not treated as an august House. I do not like this. I would now respectfully request the hon. Members to let the House transact its business in a disciplined manner.]

लोक कार्य मन्त्री : हमें आप पर पूरा एतमाद है।

मुख्य मन्त्री : डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह जो आनरेबल मेम्बर श्री अग्निहोत्री जी ने सवाल उठाया है, सवाल बड़ा माकूल है इन मायनों के अन्दर कि जहां तक अमृतसर का ताल्लुक है वहां पर लेबर को रीहैबिलीटेट करने का सवाल भी पूरी तरह से दरपेश है। जो पच्चीस हज़ार रुपया लेबर लोन के लिए मन्ज़ूर किया गया है वह उस लोन के अलावा है जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट्स को दिया जाएगा। पच्चास लाख रुपया इंडस्ट्रिलिस्ट्स के लिए लोन के लिए मन्ज़ूर किया गया है और इस पच्चास लाख के अलावा अगर और भी ज़रूरत पड़ेगी तो, जैसा कि मैंने कौंसल में भी कहा था, पंजाब गवर्नमैंट केन्द्रीय सरकार की मदद से दो करोड़ रुपए तक लोन देने को भी तैयार रहेगी। जहां तक लेबर का ताल्लुक है इस सम्बन्ध में, डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस लोन के देने में दिक्कतें आई हैं और उस पर गवर्नमैंट की ज़बरदस्त खाहिश थी और अब भी है कि जो फैक्टरीज़ वर्क करती हैं, उन में, जो लेबर काम करती हैं उसको उन फैक्टरी ओनर्ज़ के ज़रिए हम वह तमाम रुपया दें। कुछ ओनर्ज़ ने उस सम्बन्ध में शरायत वगैरा के सिलसिले में कोई एतराज़ उठाया। मगर रीसैंटली गवर्नमैंट ने यह फ़ैसला किया है कि जो छोटी फैक्टरी का ओनर है उसको दस हज़ार रुपए तक लोन दिया जाएगा सिर्फ़ एक शोरिटी पर और उसमें यह शर्त लगाई गई है कि उसमें से पांच हज़ार रुपया तो वह इंडस्ट्रियलिस्ट अपने काम के लिए इस्तेमाल कर लेगा और पांच हज़ार रुपया अपनी लेबर को देगा जो कि उस इंडस्टरी के चलाने में काम कर रही है। हम यह समझते हैं कि जो एक ही पर्सनल शोरिटी की शर्त लगाई है इससे मसला कुछ हद तक हल हो जाएगा।

इस के साथ ही साथ जहां तक रा-मैटीरियल का ताल्लुक है, गवर्नमैंट आफ़ इंडिया ने हमारी इस रिक्वेस्ट को मन्ज़ूर कर लिया है कि जितना रा-मैटीरियल इस वक्त तक मिलता है, पिग आयरन या स्टील, अब वह ओरिजनल कोटे से हमें 10 परसैंट ज्यादा रा-मैटीरियल देंगे और शायद इस से भी और ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा।

इस के साथ ही साथ कुछ और भी फैसिलिटीज़ दी गई हैं। पहिले यह था कि 35,000 रुपए तक का लोन किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को उसकी प्रापर्टी के अगेन्स्ट दिया जा सकता था। लेकिन अब इस शर्त में भी कुछ तबदीली कर दी गई है, तरमीम कर दी गई है कि अगर वह प्रापर्टी उस की अपनी नहीं है, उस ने लीज़ पर ली हुई है और उसके ऊपर उसने मशीनरी इन्स्टाल की हुई है तो उस मशीनरी के अगेन्स्ट हम उसे 35,000 रुपया लोन देने को तैयार होंगे ताकि उस को सहूलियत हो।

[मुख्य मंत्री]

जहां तक लेबर को सहूलियत देने का सम्बन्ध है, अगर आनरेबल मेम्बर साहिबान कोई और सुजैशन हमें दे सकें जिस से गवर्नमैंट का रुपया भी महफूज़ रहे और लेबर को भी पैसा मिल सके तो गवर्नमैंट उस पर पूरी तरह से गौर करने के लिए तैयार है ।

(इस समय सरदार नारायण सिंह शाहबाज़पुरी सप्लीमैंटरी करने के लिये खड़े हुए ।)

उपाध्यक्षा : सरदार नारायण सिंह, आप मुझे एक बार ही बता दें कि आप ने कितनी और सप्लीमैंटरीज़ करनी हैं । (The hon. Member may tell me once for all as to how many supplementaries he wants to put).

ਸਰਦਾਰ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਇਕੋ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਚੀਫ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਬ ਨੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨਾ ਰੁਪਿਆ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟਸ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ । ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਤਕ ਕੁਝ ਦਿਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤਨਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ?

मुख्य मन्त्री : इस बारे में मैं अर्ज़ करता हूं कि 27 लाख रुपया इस मतलब के लिए मंजूर किया गया है जिस में से 20 लाख रुपया अमृतसर और बटाला के लिए है। 27 तारीख को फिर मीटिंग हो रही है, इस के अलावा जितने रुपए की और ज़रूरत होगी उतना और मंजूर कर दिया जाएगा। रुपए की कमी नहीं आने देंगे ।

RECONSTITUTION OF DISTRICT CITIZENS' COUNCILS

***8704. Comrade Shamsher Singh Joshi**: Will the Chief Minister be pleased to state whether the District Citizens Councils in the State have been reconstituted; if not, the reasons therefor ?

Shri Ram Kishan : Yes. Most of the District Citizens' Councils have since been reconstituted.

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : ਕੀ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜੋ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕੌਂਸਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨੀਅਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ?

मुख्य मन्त्री : बहुत दिन हुए हैं हम ने तमाम डिस्ट्रिक्ट अथारेटीज़ को हिदायतें जारी कर दी थीं कि उन के ज़िले में जितने भी एम०एल०एज़०, एम०एल०सीज़० और एम० पीज़० हों उनको बाकी मेम्बरों के साथ साथ ज़िला सिटीज़न कौन्सलों में ले लिया जाए और उन के साथ जो उन के ज़िलों में जितने भी अच्छे रिटायर्ड फौजी

अफ़सर हों, जिन्हों ने इस एमरजैंसी के वक्त बहुत काम किया है, उन में से भी इस कौंसल में ले लिए जाएं । इस के साथ ही हम ने यह भी हिदायात जारी कर दी हैं कि जो भी पोलिटीकल पार्टियों के अच्छे अच्छे वर्कर उन के ज़िलों में हैं उन में से भी कुछ को इस में शामल कर लिया जाए और उन सब को शामल कर के इन कौंसलों को अच्छी तरह से चलाओ ।

ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ : ਕੀ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਜ਼ਿਲਾ ਸੰਗੂਰਰ ਦੀ ਜੋ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ? ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ । ਕੀ ਇਸ ਲਈ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ?

मुख्य मन्त्री : ज़िला संगरूर में सिटीज़न कौंसल बाकायदा तौर पर कायम है और वहां के जो एम० एल० एज़० और एम० एल० सीज़० हैं वह उस में शामल हैं ।

(कामरेड गुरबख्श सिंह धालीवाल सप्लीमैंटरी पूछने से लिए खड़े हुए)

Deputy Speaker : No, please. Next question, please.

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਹਾਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪੁਛੇ ਗਏ ਹਨ . . . . . .

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਨੋ ਪਲੀਜ਼ । ਅਗੇ ਇਕੋ ਸਵਾਲ ਤੇ 35 ਮਿੰਟ ਲਗ ਗਏ ਹਨ । (No, please. Already 35 minutes have been spent on putting supplementaries and their replies on one single question). I cannot allow time like this.

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ; ਉਸ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ? ਉਸ ਤੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪੁਛਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ।

Deputy Speaker : No please.

श्री जगन्नाथ : अभी तो सिर्फ दो ही सप्लीमेंटरीज़ पूछे गए हैं......

Deputy Speaker : Order, please. I can not allow like that.

श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री : डिप्टी स्पीकर साहिबा, एक सवाल पर कम से कम तीन सप्लीमेंटरीज़ पूछने की इजाज़त तो होनी ही चाहिए ।

उपाध्यक्षा : यह जरूरी नहीं है कि तीन सप्लीमेंटरीज एक सवाल पर जरूर ही पूछे जाएं। मैं इस तरह से इन को आदत नहीं डालना चाहती। (It is not necessary to allow at least three supplementaries on each question. I do not want them to form this habit.)

श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री : क्या चीफ मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि क्या यह अमर वाक्या नहीं है कि उन को एक ऐसा रिप्रीजैंटेशन मिला है जिस में कहा गया है कि तमाम जिलों में जो सिटीजन कौंसलें बनी हुई हैं उन में अभी तक वहां के तमाम एम० एल० एज़० को और एम० एल० सीज़० को नहीं लिया गया ?

मुख्य मन्त्री : अगर किसी ज़िले के मुतालिलक आनरेबल मेम्बर को इलम हो तो वह मेरे नोटिस में ले आएं। मैं देख लूंगा।

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਕੌਂਸਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਕਾਮਰੇਡ ਭੌਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਧੌਲਾ ਨੂੰ ਉਸ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਬਤੌਰ ਐਕਸ ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਦੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਰੀਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਚੀਫ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਜ਼ਿਲਾ ਸੰਗਰੂਰ ਔਰ ਫੀਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀਆਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਰੀਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਔਰ ਜੇਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਐਮ. ਐਲ. ਏਜ਼. ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਰੀਵਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਮੰਗੇਗੀ ?

उपाध्यक्षा : मेरी चीफ मिनिस्टर साहिब से छोटी सी दरखास्त है कि वह सारे जिलों की सिटीजनज़ कौंसलों की लिस्टें मंगवा कर पड़ताल करवा लें और जहां जरूरत समझें उन्हें रिवाइज कर दें। (I would request the Chief Minister to send for the lists of members of Citizens Councils of all the Districts and get them scrutinised. He may get them revised where he feels necessary.)

मुख्य मन्त्री : मैंने तमाम जिलों की लिस्टें मंगवाई हैं और एक एक ज़िला करके मेरे पास वह आ रही हैं और जो जो आती जाती है उस को रिवाईज़ कर के वापस भेजता जाता हूं। जहां तक जिला संगरूर की लिस्ट का ताल्लुक है वह अभी मेरे पास आई नहीं। जब आई तो अगर उस में कोई गलती हुई तो उस को मैं ठीक कर के भेज दूंगा।

ਕਾਮਰੇਡ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ : ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਲਾ ਫੀਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ?

उपाध्यक्षा : मैं ने कामरेड राम किशन से दरखास्त की है कि वह तमाम जिलों की लिस्टें मंगवा कर देख लें । (I have already requested the Chief Minister to send for lists of members of Citizens' Councils of all the districts and scrutinise them.)

कामरेड राम प्यारा : क्या चीफ़ मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि जो उन्होंने बताया है कि बहुत सारी कौंसलज़ रीकानस्टीच्यूट कर दी गई हैं तो मैं पूछना चाहता हूं कि इस बारे में जो डिस्ट्रिक्ट अथारेटीज़ और चेयरमैन की रिकमैंडेशनज़ आई हैं क्या उन के मुताबिक सारी लिस्टों को रिवाईज़ कर के वापस भेज दिया गया है ?

मुख्य मन्त्री : कई जगह की लिस्टों को तो भेज दिया गया है और कई अभी एग्ज़ामिन हो रही हैं ।

लाला रुलिया राम : क्या चीफ मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि ज़िला करनाल की कौंसल की पहले श्रीमती ओम प्रभा जैन मेम्बर थीं वह अब क्योंकि मिनिस्टर बन गई हैं तो उन्हों ने जो जगह खाली की है उस पर किसी को मेम्बर बना लिया गया है ?

मुख्य मन्त्री : उन की जगह पर श्री मूल चन्द जैन को जो एक्स एम०ऐल०ए० हैं मेम्बर बना दिया है ।

श्री जगन्नाथ : क्या चीफ मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि क्या किसी सिटीज़न कौंसिल की मेम्बरशिप के लिए कोई मेक्सीमम नम्बर भी रखा हुआ है कि इतने नम्बर से ज्यादा उस के मेम्बर नहीं हो सकेंगे ?

मुख्य मन्त्री : मेरा ख्याल यही है कि यह 40 तक होने चाहिएं ।

Deputy Speaker : Question hour is now over.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE UNDER RULE 45

GREEN FODDER SOWN IN THE S.D.M. PALWAL'S COMPOUND

***8812. Shri Rup Lal Mehta** ; Will the Chief Minister be pleased to state whether he is aware of the fact that green fodder was sown in the S.D.M. Palwal's Compound and it was sold and money not deposited in Government revenue income account ?

Shri Ram Kishan : No green fodder was sown in the compound of the S.D.M. Palwal's residence and as such the question of the sale and the deposit of the sale-proceeds into the Government Treasury does not arise.

LETTER FROM FLIGHT LIEUTENANT A. K. DHIR, BARRACKPORE

***8608. Comrade Ram Chandra** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether he received any letter dated 26th January, 1965, from a Military Officer, namely, Flight Lieutenant A.K. Dhir, Barrackpore, complaining about forcible possession of his land in Kapurthala District by bad characters ;

(b) whether he also received another copy of the said letter from Comrade Ram Chandra, M.L.A., along with his forwarding letter dated 29th May, 1965 ;

(c) if the reply to parts (a) and (b) above be in the affirmative, copies of both the letters referred to above be laid on the Table of the House and the details of the action taken on each ?

Shri Ram Kishan : (a) Yes Sir.

(b) and (c) Yes, Sir. Copy of the letter is placed on the Table of the House.

Deputy Commissioner, Kapurthala, who was asked to look into the matter, has advised the Flight Lieutenant to seek remedy in a Court of Law.

Copy of Flight Lieutenant A. K. Dhir (5790)GD(P), No. 48 Squadron, c/o No. 6 Wing Barrackpore letter dated the 26th January, 1965, addressed to the Chief Minister, Punjab regarding land dispute.

I have the honour to state the following facts for your kind consideration.

1. That my father owns land in village Randhirpur, sub-tehsil Sultanpur Lodhi, district Kapurthala of which I am now a co-partner.

2. That one Udham Singh with the help of certain bad character of the area forcibly occupied a portion of our land and unlawfully constructed a hut on that land. In order to perpetuate religious feelings and win sympathy of the public to continue their unlawful possession and looting of our crops, the goondas converted that hut into a gurdwara which was named as Gurdwara Sant Ghat.

3. That my father filed a civil suit against the above aggressive acts of Badmash Udham Singh and when final decree was about to be passed against those people, the district authorities, namely, the then Deputy Commissioner S. Sant Partap Singh and the Magistrate S. Fauja Singh by putting their official pressure persuaded my father to donate about 3 acres of land in the name of the said Gurdwara. Mutations for the same were officially sanctioned and the possession of our surrounding lands was restored to my father in the year 1951.

4' That again after some time the same Udham Singh started trouble but he was firmly dealt with, even got arrested by Shri P. S. Rao who was the Administrator of Pepsu. Udham Singh then filed a statement on 8th September, 1953 (D.C. Kapurthala office file No. G-2nd January, 1953) copy enclosed, saying that he will abide by the earlier decision and will have no concern with our lands. Under the circumstances we continued to have the possession of our land peacefully till 1956 and when for the third time Udham Singh started trouble.

5. That subsequently in 1958 another person named Santa Singh who had more of bad characters with him made Udham Singh to leave that place and took the charge of the entire lands measuring about 30 acres adjoining to the lands donated by

us to the Gurdwara. Further to this in the next year Santa Singh accompanied with bad characters started interference in another plot of our land situated at a farther distance across the road and railway line and forcibly cultivated that piece of land measuring about 50 acres. The Deputy Commissioner and Commissioner, of the Division though agreed in their report dated the 12th February, 1963, that the cultivation has been done "BAWAJA SINA ZORI" but they took no action to remedy the default.

6. That my father applied to the Gurudwara Tribunal Board against the above-mentioned illegal incursions and that court gave a clear judgement on 29th November, 1962 and ordered that the Gurdwara owns five acres of land donated by our family and have no right to possess or own any other portion of our surrounding lands. The implementation of those orders of the court (copy of judgement enclosed) has not been done by the executive inspite of our repeated requests.

7. That the Punjab Government, since the taking over by the New ministry have made many announcements and put forth many promises to help and safeguard the interests of persons serving the Nation, at the stake of their lives by being in active armed forces. On the reliance of these encouraging commitments I have ventured to approach your honour to please help me. My father is very old aged 75 years and unable to take proper care or conduct lengthy litigations. In spite of many requests made by my father to the local police, they always refuse even to register a case and have on the other hand been pampering the goondas, in the garb of religion.

8. I therefore, request you to take necessary and immediate action to safeguard my interests.

INFORMATION/FIELD ASSISTANTS

*8807. **Shri Amar Singh** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total number and names of Information Assistants/ Field Assistants recruited by the Government, regionwise, and districtwise, during the period from 1st July, 1964 to date ;

(b) the total number and names of the journalists who appeared in the test for the posts of Information Assistants together with the names of those journalists, districtwise, who were selected for the said posts during the said period ?

Shri Ram Kishan : (a) & (b) Annexures A and B containing the requisite information are placed on the Table of the House.

ANNEXURE 'A'

Names of Field Publicity Assistants/Information Assistants Recruited Region and District-wise during the period from 1st July, 1964 to date

Sr. No.	Name	Designation	District to which the incumbent belongs
	Punjabi Region		
1.	Shri Parlok Singh	Field Publicity Assistant	Gurdaspur
2.	Shri Raj Kumar Bali	Ditto	Do
3.	Shri Puran Chand	Ditto	Do
4.	Shri Sukhpal Vir Singh Hasrat	Ditto	Do
5.	Shrimati Satya Datta Shama	Ditto	Amritsar
6.	Shri Chatter Singh	Ditto	Do
7.	Shri Piara Singh	Ditto	Do

[Chief Minister]

S. No.	Name	Designation	District to which the incumbent belongs
8.	Shri Joginder Singh Gill	Field Publicity Assistant	Amritsar
9.	Shri Kemlinder Singh	Ditto	Do
10.	Shrimati Gurdashan Kaur	Ditto	Do
11.	Shri Banwari Lal Mehra	Ditto	Do
12.	Shri S.K. Saroor	Information Assistant	Jullundur
13.	Shri Narinder Nath Sharma	Field Publicity Assistant	Hoshiarpur
14.	Shri Vinod Kumar Lakhanpal	Ditto	Do
15.	Shri Rajbir Singh Dhillon	Information Assistant	Ludhiana
16.	Shri Siri Ram Arsh	Field Publicity Assistant	Do
17.	Shrimati Joginder Kaur	Ditto	Do
18.	Shri Babu Singh	Ditto	Do
19.	Shri Natha Singh	Ditto	Ferozepore
20.	Shrimati Raman Sharma	Ditto	Do
21.	Shri Ravinder Singh	Ditto	Patiala
22.	Shrimati Vimal Kaushal	Ditto	Do
23.	Shri Basant Kumar Sharda	Ditto	Do
24.	Shri B. J. Kapoor	Ditto	Do
25.	Shri Shankar Parkash	Ditto	Sangrur
26.	Shri Nachatar Singh Shad	Ditto	Do
27.	Shri Rakesh Chander	Ditto	Bhatinda
28.	Shri Jagmohan Singh	Ditto	Do
29.	Shri Mohinder Singh Gill	Ditto	Kapurthala
		Hindi Region	
30.	Shri Jagdish Bharti	Field Publicity Assistant	Hissar
31.	Shri Pat Ram Verma	Ditto	Do
32.	Shrimati Raj Josh	Ditto	Do
33.	Shri Shankar Lal	Ditto	Do
34.	Shri Satvir Singh Rana	Ditto	Rohtak
35.	Shri Dial Chand Miglani	Ditto	Do
36.	Shrimati Shakuntla Kumari	Ditto	Do
37.	Shrimati Savitri Malik	Ditto	Do
38.	Shri Chander Bhan	Ditto	Do
39.	Shri Hari Ram Arya	Ditto	Gurgaon
40.	Shri Chatter Sain Goel	Ditto	Karnal
41.	Shri Balbir Kapoor	Ditto	Ambala
42.	Shri Gurmukh Singh Ambalvi	Ditto	Do
43.	Shri Sharda Gulati	Ditto	Do
44.	Shri Subash Narula	Information Assistant	Do

S. No.	Name	Designation	District to which the incumbent belongs
45.	Shri Sushil Chand Rattan	Field Publicity Assistant	Kangra
46.	Shri Rup Chand Misra	Ditto	Kulu
		Delhi State	
47.	Shri Sushil Chander	Field Publicity Assistant	Delhi
48.	Shri A. K. Saigal	Information Assistant	Do

ANNEXURE 'B'

List of persons claiming no realistic back-ground who appeared in the tests for the posts of Information Assistants/Field Publicity Assistants together with those selected

S. No.	Name	Home District	Whether Selected for appointment or not
1.	Shri Pat Ram Verma	Hissar	Appointed
2.	Shri Jagdish Bharti	Do	Do
3.	Shri Radha Krishan Hooda	Rohtak	
4.	Shri Shankar Lal	Do	
5.	Shri Ram Pat	Do	
6.	Shrl Surinder Pal Singh Ahlwat	Do	
7.	Shri Prem Prakash Sharma	Gurgaon	
8.	Shri Hari Ram Arya	Do	Appointed
9.	Shri Raj Pal Bhatia	Karnal	
10.	Shri Teja Singh	Do	
11.	Shri Kuldip Singh Verma	Ambala	
12.	Shri Gurcharan Singh Dev	Do	
13.	Shri Virinder Kumar Thukral	Do	
14.	Shri Sarup Singh	Do	
15.	Shrimati Satya Wati	Do	
16.	Shri Sher Singh	Do	
17.	Shri Gurcharan Dass	Do	
18.	Shri Sudershan Kumar Deep	Do	
19.	Shri Charles H. Messey	Do	
20.	Shri Antar Singh	Do	
21.	Shri Om Parkash Dhiya	Do	
22.	Shri Chander Mohan Sharma	Do	
23.	Shri Dhayan Chand	Do	
24.	Shrimati Vasu Devi	Do	
25.	Shri Chanan Singh Sohal	Do	
26.	Shri Ravinder Nath	Do	
27.	Shri Surinder Kumar	Do	
28.	Shri Balwinder Sarup Gupta	Do	

S. No.	Name	Home District	Whether selected for appointment or not
29.	Shri Manohar Lal	Ambala	
30.	Shrimati Devinder Kaur Kohli	Do	
31.	Shri Kesar Chand Jain	Do	
32.	Shri Surinder Singh	Do	
33.	Shri Man Mandir Singh	Do	
34.	Shri Pran Sharma	Simla	
35.	Shri Ravinder Parsad Randev	Do	
36.	Shri C. R. Prem	Kangra	
37.	Shri Amar Singh Rana	Do	
38.	Shri Murari Lal	Hoshiarpur	
39.	Shri Karam Singh Amar	Jullundur	
40.	Shri Surinder Nath	Do	
41.	Shri Abinash Singh	Do	
42.	Shri Raghubash Rai	Do	
43.	Shri Om Parkash	Do	
44.	Shri Girdhari Lal	Do	
45.	Shri Mohan Singh Sehgal	Do	
46.	Shri Makhan Lal Aggarwal	Do	
47.	Shri Shivdayal Bhalla	Do	
48.	Shri Raghuvir Singh	Do	
49.	Shri Ajaib Singh	Do	
50.	Shri Surinder Singh	Do	
51.	Shrimati Tripta	Do	
52.	Shri Jagjit Singh Bir	Do	
53.	Shri Surinder Kumar	Do	
54.	Shri Kirpal Singh	Do	
55.	Shri Jasbir Singh Bhullan	Do	
56.	Shri Ram Nath Azad	Ferozepore	
57.	Shri Dev Raj Puri	Do	
58.	Shri Mool Chand	Do	
59.	Shri Jagdish Chander Sharma	Do	
60.	Shri Natha Singh	Do	Appointed
61.	Shri Gurdip Singh	Ludhiana	
62.	Shri Avtar Singh	Do	
63.	Shri Tarnjit Singh	Do	
64.	Shri Yog Raj Joshi	Do	
65.	Shri Kashmir Singh	Do	
66.	Shri Rajinder Pal	Do	
67.	Shri Piare Lal Bhat	Do	
68.	Shrimati Niranjan Avtar	Do	
69.	Shri Mohinder Singh	Do	
70.	Shri Charan Singh	Do	
71.	Shri Vishwinder Mehta	Do	

S. No.	Name	Home District	Whether selected for appointment or not
72.	Shri Harbhajan Singh	Lndhiana	
73.	Shri Bidhi Chand	Do	
74.	Shri Ajit Singh	Do	
75.	Shri Kuldip Singh	Amritsar	
76.	Shri Joginder Singh Gill	Do	Appointed
77.	Shri Lekh Raj	Do	
78.	Shrimati Sukesh Kapur	Do	
79.	Shrimati Gurdev Kaur	Do	
80.	Shri Kamlinder Singh	Do	Appointed
81,	Shri Chatter Singh	Do	Appointed
82.	Shri Avtar Singh	Do	
83.	Shri Gurnam Singh	Do	
84.	Shri Pritpal Singh	Do	
85.	Shri Bhupinder Singh Paul	Do	
86.	Shri Avtar Singh	Do	
87.	Shri Niranjan Singh	Do	
88.	Shri Gian Chand Chohan	Do	
89.	Shri Parlok Singh	Gurdaspur	Appointed
90.	Shri Puran Chand	Do	
91.	Shri Jaswant Singh	Do	
92.	Shri Sudershan Dhingra	Do	
93.	Shri Supinder Singh	Patiala	
94.	Shri Swaran Singh	Do	
95.	Shri Vinay Kumar	Do	
96.	Shri Jagdish Chander	Do	
97.	Shri Kuljit Singh	Do	
98.	Shri Kuldip Singh	Do	
99.	Shri Gopal Krishan	Do	
100.	Shri Ram Sarup	Do	
101.	Shri Sohan Singh	Do	
102.	Shri Balwant Singh	Do	
103.	Shri Hari Singh	Do	
104.	Shri Kuldip Parkash	Do	
105.	Shri Shankar Parkash	Sangrur	Appointed
106.	Shri Mohinder Singh	Do	
107.	Shri Amar Nath	Do	
108.	Shri Parbhati Ram	Mohindergarh	
109.	Shri Sudershan Kumar	Do	
110.	Shri Rakesh Chander	Bhatinda	Appointed
111.	Shri Ved Parkash Gupta	Do	
112.	Shri Sant Singh	Do	

ENQUIRIES MADE BY DISTRICT OFFICER INTO VARIOUS COMPLAINTS

*8813. **Shri Roop Lal Mehta** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether it has come to the notice of the Government that the system of allowing Advocates from both sides to represent their cases before the District Officers during the course of enquiries into complaints referred to them for investigation by the Complaints Committee at district level is expensive ;

(b) if the reply to part (a) above be in the affirmative whether Government intend to simplify the procedure regarding enquiries into such complaints ?

Shri Ram Kishan : (a) No. Advocates generally do not appearin these enquiries.

(b) Does not arise.

SETTING UP OF NEW INDUSTRY IN PUBLIC SECTOR IN THE FOURTH FIVE YEAR PLAN

*8/09. **Comrade Shamsher Singh Josh** : Will the Chief Minister be pleased to state whether any new industry in the Public Sector is proposed to be set up in the State during the Fourth Five Year Plan ; if so, where and when ?

Shri Ram Kishan : A statement containing the required information is laid on the Table of the House.

STATEMENT

The Fourth Five Year Plan provides for the establishment of a Pig Iron Plant and a Coke Ovens Plant in the public sector which are proposed to be located in the Hissar District. The installation of the Pig Iron Plant. as planned at present. will be completed by 1968. As regards the Coke Ovens Plant, no definite date of its establishment can be indicated at the present preliminary stage of the project.

A few cotton spinning mills may also be set up in the public sector during the Fourth Plan. depending upon the allocation of capacity that may be made by the Government of India. It is premature to give the location of these mills or to lay down a time schedule for setting them up.

THE WEAVING AND SPINNING MILL, UKLANA IN HISSAR DISTRICT

***8808. Shri Amar Singh** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the number and names of the Directors and of the share-holders of the Weaving and Spinning Mill, Uklana in tehsil and district Hissar ;

(b) the total amount so far collected from the said share-holders together with the target fixed by the Government for the purpose ;

(c) the approximate date by which the said mill is likely to be completed in all respects ?

Shri Ram Kishan : A statement containing the requisite information is laid on the Table of the House.

STATEMENT

(a) (i) A list indicating the number and names of the Directors of the Mill is attached.

(ii) The number of share-holders of the Mill is 995. The time and labour involved in collecting their names and the preparation of a list thereof will not be commensurate with the benefit to be derived therefrom.

(b) (i) Collection from the share-holders ... Rs 95,030

(ii) Target fixed by Government .. Rs 10,00,000

(c) Normally it takes about 3-4 years to start such a mill. In the present case, however, the progress has been slow on account of non-collection of adequate share money from the members.

List of Directors of the Punjab Co-operative Spinning and Textile Mills Ltd., Uklana, District Hissar

1. Shri Meher Chand, House No. 220, Sector 18-A, Chandigarh.
2. Shri Hunna Mal, M. L. A., Hissar.
3. Shri Indraj Singh, Uklana Mandi, district Hissar.
4. Shri Gulab Singh Jain, Advocate, Hissar.
5. Shri Manphool Singh, M. L. A., Tohana, district Hissar.

[Chief Minister]

6. Shri Ran Singh Sarpanch, Daulatpur, district Hissar.

7. Shri Hazari Ram, Village Bhanda (Sangrur)

8. Administrator of the Punjab Handloom Weavers Apex Co-operative Society, Chandigarh.

9. Shri Diwan Chand Bhatia, M. C. Panipat.

10. Shri N. K. Bhandari, President, Tarn Taran Handloom Production-cum-Sale Industrial Co-operative Society Ltd., Tarn Taran, district Amritsar.

11. Shri Manohar Lal Kalra, M. C. Uklana Mandi, district Hissar.

12. Shri Gurdarshan Singh, Chairman, Block Samiti Tohana, District Hissar.

13. Shri Prithipal Singh, Joint Director, Village Industries, Chandigarh (*Chairman*).

COMPLAINT AGAINST THE PRESIDENT, LYALLPUR JOINT FARMING SOCIETY, MURTAZAPUR, DISTRICT KARNAL

***8811. Sardar Piara Singh** : Will the Chief Minister be pleased to state whether the Deputy Commissioner, Karnal/Government received from S. Manjit Singh a .y complaint on 25th January, 1965 or thereafter against the President, Layallpur Joint Farming Society, Murtazapur, tehsil Kaithal, district Karnal and one of his companions to the effect that they procured bogus permits for sugar in connection with a marriage, if so, a copy of the complaint, together with the details of the action taken thereon be laid on the Table of the House ?

The answar to Starred Assembly Question No. 8811 appearing In the list of Questions for 19th November, 1965 in the name of Sardar Piara Singh, M. L. A. is not ready. This intimation is sent to the Speaker who is requested to extend the time for answering this Question under proviso (ii) to rule 41 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly. This Question may kindly be included in the list of Questions for any date after 10th December, 1965.

Sd/-

Chief Minister, Punjab,

To

The Speaker,
Punjab Legislative Assembly,
Chandigarh.

U. O. No. 21566-SD-65, dated Chandigarh, the 18th November, 1965.

QUESTION OF PRIVILEGE

10.00 a. m.

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਪਰਿਵਿਲੇਜ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤ੍ਰੀ ਅੱਰ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇਥੇ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਉਠਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਏ ਪਰ ਸਾਡੇ ਡੀਫੈਂਸ ਮਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇਹ ਗਲ ਮੰਨੀ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਥੇ ਗ਼ਲਤ ਗਲ ਕਹੀ ਹੈ............(*Interruption*)

उपाध्यक्षा : क्या मेरी रिक्वैस्ट का यही असर हुआ है ? मैं कहती हूं कि आप असेंबली के आनरेबल मेम्बर हैं, आप हाउस का कुछ तो ध्यान रखें । (Is this the effect of my request for maintenance of decorum in the House ? I say he is an hon. Member of the Assembly. He should have at least some regard for the dignity of the House.)

परिवहन तथा निर्वाचन मंत्री : डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप की तरफ से अभी कोई हुकम नहीं आया था कि इन्हों ने बोल दिया । अब आप की तरफ से हुकम आ गया है । मैंने इस हाउस में कहा है कि हमारे पास मिसिंग लोगों की रिपोर्ट आई है । हमें किसी लड़की का पता नहीं । अगर मैंने कहा है, जैसा कि यह कहते हैं, आप प्रोसीडिंग्ज़ मंगवा कर देख लें अगर मैंने यह कहा हो तो मैं उसी वक्त रिज़ाइन कर दूंगा । यह क्या है कि मेरे मुंह में गलत बात डाल दें । यह मामला कल अप्पर हाउस में भी उठा था । इस के बारे में एक एडजर्नमैंट मोशन आई थी । वहां यह फैसला हुआ कि यह एडजर्नमैंट मोशन न ली जाए । बाद में सब पार्टियों ने फैसला किया कि यह कुछ ऐसा मसला है कि चीफ मिनिस्टर के पास सब पार्टियों के अपोज़ीशन के लीडर्ज़ जाएंगे । मुझे पता नहीं कि चीफ मिनिस्टर साहिब ने क्या कहना है । जो उनकी नालिज में आएगा आपोज़ीशन पार्टीज़ से बात कर लेंगे । अगर मैं ने कहा हो तो मैं यहीं इस हाउस में बैठा हूं आप मुझे हुकम दे दें मैं अभी घर को चला जाऊंगा ।

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਮੈਂ ਪਰਿਵਿਲੇਜ ਮੋਸ਼ਨ ਦਿਤੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ । ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ । ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਉ ।

Deputy Speaker : No.

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਉ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਉ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਡਿਸਅਲਾਊਡ । ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਾਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਚੈਂਬਰ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਦਸੋ । (Disallowed. If any thing has been left, the hon. Member may tell me in my chamber.)

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਮੈਂ ਚੈਂਬਰ ਵਿਚ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ । ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਚੈਂਬਰ ਵਿਚ ਜਾਵਾਂ ? ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ । ਮੈਂ 24 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਮਾਰਦਾ ਰਹਾਂ ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੀਅਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ । ਰਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ । ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਵਜੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਆਏ ਜਦੋਂ 9 ਵਜਣ ਵਿਚ 10 ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ । ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਸੀ । ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਓ ਮੈਂ ਗਲ ਕਰਾਂਗੀ । (I am feeling unwell. For God's sake, for his own sake and for the sake of the House, the hon. Member should behave properly. I had called him at 8.30 a.m. but he turned up when it was 8.50 a.m. At that time I had to come to attend the House. So he may come to my Chamber and I will discuss the matter with him.)

ADJOURNMENT MOTIONS

Deputy Speaker : Now I take up Adjournment Motions. Adjournment Motion No. 31 stands in the name of Sardar Gurbaksh Singh Gurdaspur but since the hon. Member is not present in the House, I take up the next Adjournment Motion No. 32 standing in the name of Comrade Bhan Singh Bhaura.

ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ : 25,000 ਰੁਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਛਾਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਇਹ 25,000 ਰੁਪਿਆ ਡਾਲੀ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਚਿਆਂ ਨੇ ਇਕਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ । ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਏਥੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਥੋਂ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਕਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਸਲ੍ਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ । ਤੁਸੀਂ ਸੈਨਸਰ ਮੋਸ਼ਨ ਲੈ ਆਓ । ਤੁਸੀਂ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ।

(The hon. Member has started delivering a lecture. I may tell him that I have not admitted it. He can bring a Censure Motion against the Minister.)

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਚਿਆਂ ਨੇ ਆਨਾ ਆਨਾ ਇਕਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਛਾਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਨੰਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਤਾ। ਜੇ ਇਹ ਢੰਗ ਵਰਤਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਕਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਰੋਲਣਾ ਸੀ । ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੁਪਿਆ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਰੁਪ ਲਈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪੈਸਾ ਇਕਠਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਇਕਠਾ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ।

ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੁਪਿਆ ਇਕਠਾ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਹਿ ਲੈਣਾ । ਹੁਣੇ ਇਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ । (The hon. Member may have his say afterwards. Now a Parliamentry Delegation is coming. What impression will they carry about what we do here ?)

ਕਾਮਰੇਡ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ : ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਾ ਦਿਓ, ਅਗਰ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੁਪਿਆ ਇਕਠਾ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏ ।

ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ : ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ? ਕਿਵੇਂ ਚਲ ਰਿਹਾਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ? ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲ ਰਿਹਾ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ? ਕਿਸ ਗਲ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ? (What is he saying ? On what subject is he speaking ?)

ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਗਰੁਪ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜੋਗਾ ਜੀ ਨੇ ਸਪੀਚ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ? ਇਹ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਗਲ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ? ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ? (Is it on a point of order, that he has stood up? What is that ?)

ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ : ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ਼ ਆਰਡਰ ਹੈ ।

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ਼ ਆਰਡਰ, ਮੈਡਮ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊਸ ਦਾ ਡੈਕੋਰਮ ਕਾਇਮ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਬੀਹੇਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਹੇਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਏਥੇ ਇਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਹੋ ਕਰਤੂਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਦਸੀਏ ? ਚਾਹੇ ਫਾਰਿਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੋਣ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੁਪਿਆ ਇਕਠਾ ਕਰਕੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ।

मुख्य मंत्री (श्री राम किशन) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, जैसा कि आप को मालूम है चार दिन हुए यहां एक क्वैस्चन पंजाब सिक्यूरेटी एन्ड डिफेंस रीलीफ के बारे में पूछा गया था उस का जवाब एजूकेशन मिनिस्टर साहिब ने दिया था और साथ ही यह अर्ज़ किया था कि अगर किसी को कोई एतराज़ है तो उन से पूछ सकते हैं । उसका जवाब देने को वह तैयार हैं । यह जो दो तीन काल अटेन्शन नोटिसिज़ इस सिलसिले में दिए गए हैं इस बारे में मैं इतना ही अर्ज़ करना चाहता हूं कि जो भी रुपया एजूकेशन मिनिस्टर ने छागला साहिब, नंदा साहिब या इन्दरा गांधी जी को 25–25 हज़ार दिए हैं वह इस मतलब के लिए हैं कि जो आर्मड फोरसिज़, आर्मड पर्सानल के बच्चे हैं उनकी एजूकेशन के लिए डीज़रविंग केसिज़ के लिए दे सकें, ना कि किसी दूसरे मतलब के लिए । मैं आशा रखता हूं कि तमाम मैम्बरान इस बात को एप्रीशीएट करेंगे कि आर्मड पर्सानल के बच्चों को जहाँ भी तालीम की ज़रूरत होगी, खाह वह राज्य सरकार या केन्दरी सरकार हो उन का फर्ज़ है कि उन की मदद करें । अगर किसी और मकसद के लिए वह रुपया दिया दिया जाए तो मैम्बरान को एतराज़ हो सकता है । इस लिए, डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आप के ज़रीए तमाम मैम्बरान को कहूंगा कि जितने यह काल अटेन्शन नोटिस दिए गए हैं उन की ज़रूरत नहीं । वह सब इस बात को एप्रीशीएट करेंगे कि यह रुपया फौजी जवानों के बच्चों की तालीम के लिए

इस्तेमाल हो । अगर इस के इलावा और कोई चीज हो तो आप हमारे नोटिस में लाएं । उस को मैं चैक कर सकता हूं और आप की तसल्ली करवा सकता हूं ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਜੋ ਕੁਝ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਲੜੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ, ਮਾਲੀ ਤੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਹਨ । ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੜੀ ਗਈ, ਇਸ ਲਈ ਇਥੇ ਦਾ ਰੁਪਿਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ (ਵਿਘਨ) ਇਸ ਗਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੀਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਸ ਤਾਕ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਅਗਰਾਜ਼ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਨੂਦੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕ ਤਬਾਹ ਹੋ ਕੇ ਮਾਰੇ ਮਾਰੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੈਟਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਉਸ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰੀਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਕੀ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ? ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਪਾਸ ਅਧੀਨਗੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰਖਣ । ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੁਪਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

Chief Parliamentary Secretary : It is narrow—mindedness.

Voices from Opposition : Shame, Shame. (*Interruptions*)

मुख्य मंत्री : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैंने आगे भी इस बात की वज़ाहत की है इस संबंध में । अब सरदार गुरनाम सिंह जी ने एक सवाल उठाया है तो उनकी खिदमत में मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि यह रुपया उन आर्मड फोर्सिज़ के बच्चों के लिए है जो पंजाब के क्षेत्र में या राजिस्थान के क्षेत्र में या जम्मू और काश्मीर के क्षेत्र में लड़े हैं । और इस फन्ड में दूसरी स्टेटों ने भी अपनी अपनी जगह रुपया दिया है । अगर यह रुपया आर्मड परसानल के बच्चों के

[मुख्य मंत्री]

इलावा दूसरी जगह पर खर्च किया जाता तो कोई एतराज़ की बात हो सकती थी । यह सिर्फ उन्हीं के लिए है जो देश के लिए लड़े और आप इस बात को, डिप्टी स्पीकर साहिबा, एप्रीशीएट करेंगी कि हमें आर्मंड फोर्सिज़ की मदद करनी चाहिए । और इस बात का भी ख्याल रखना है कि इस रकम का नाजाइज़ इस्तेमाल न हो । जहां तक उस रुपया का तग्रालुक है जो पंजाब गवर्नमट के पास है उसके लिए अर्ज़ करूं कि एक सब कमेटी बना दी गई है और इस रुपया को खर्च करने के लिए कि किस ढंग से खर्च किया जाए रूल्ज़ और रेगूलेशन्ज़ यह कमेटी बनाएगी । इस में मिलटरी के जनरल और आर्मंड फोरसिज के नुमाइन्दे हैं और दूसरे लोग भी शामिल हैं और जो रूल्ज़ यह कमेटी बनाएगी उस के मुताबिक इस रुपया की डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी । मैं हाउस को, डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप के द्वारा यकीन दिलाना चाहता हूं कि मैं इन के जज़बात के साथ मुतफिक हूं कि इस रुपया का जाइज़ इस्तेमाल होना चाहिए । और इस को इस ढंग से इस्तेमाल में लाना चाहिए कि जिस से पंजाब के लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद हो सके ।

(विघ्न)

चौधरी इन्दर सिंह मलिक : आन ए पाइन्ट आर्डर मैडम

(विघ्न)

उपाध्यक्षा : कामरेड साहिब, मैं यह समझ रही हूं कि हाउस की सैंस यह है कि जो रुपया जहां पर इकट्ठा किया गया हो वहां पर ही खर्च होना चाहिए और यह ढंग जारी नहीं रहना चाहिए कि यहां का रुपया ऊपर चला जाए । पंजाब का रुपया पंजाब में ही खर्च किया जाना चाहिए । (*Addressing* Comrade Ram Kishan) : (I feel that the sense of the House is that the money which has been collected in the State should be spent within the State and the practice of sending it to the Centre should not be allowed to continue. The money which has been collected in the Punjab should be spent in the Punjab for the purpose for which it has been collected.)

ਸਰਦਾਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਸੀ. ਐਮ. ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੁਪਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਦੇ ਬਚਿਆਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੜੀਆਂ । ਜੇ ਇਹ ਰੁਪਿਆ ਇਕੋ ਕਾਜ਼ ਲਈ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਦ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਉਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ? ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਕੋ ਹੀ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ? ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਉਥੇ ਵੀ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਦੇ ਬਚਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਕੋ ਥਾਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ । (ਵਿਘਨ) (ਸ਼ੋਰ)

ਦੂਜੀ ਗਲ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਰਕਮ ਪੰਜਾਬ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਐਂਡ ਡੀਫੈਂਸ ਰੀਲੀਫ ਫੰਡ ਵਿਚ ਇਕਠੀ ਕਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ । ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਰੂਲਜ਼ ਇਕ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਅਜੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਫਿਰ ਜਦ ਤਕ ਰੂਲਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰ ਦੇਣਾਂ ਕਿਥੇ ਤਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ?

(ਵਿਘਨ) (ਸ਼ੋਰ)

उपाध्यक्षा : आप किसी कि बात भी सुना करें । मैंने तो आप से पहले ही चीफ मिनिस्टर साहिब को कहा है कि पंजाब का रुपया पंजाब में ही रहना चाहिए । (Order please. The hon. Member should please listen to the Chair. I have already requested the Chief Minister that the money collected in the Punjab should remain in the State.)

चौधरी इन्दर सिंह मलिक : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, मैडम । आप ने जो फरमाया है बिलकुल दरुस्त फरमाया है । मैं तो यह कहना चाहता था कि पंजाब में इकट्ठा किया गया रुपया पंजाब के एक वज़ीर ने सैंटर के तीन वज़ीरों को 25:25 हजार दिया, कुल 75 हज़ार रुपया दिया गया तो क्या यह बात चीफ मिनिस्टर साहिब के नोटिस में पहले थी कि इस तरह एक रकम दी जा रही है या कोई इस के बारे में कैबिनिट में फैसला किया गया था ? क्या चीफ मिनिस्टर साहिब बता सकते हैं कि आया इस बात में इन्हें रुपया देनें से पहले कानफिडैंस में लिया गया था ? (विघ्न) या इन की आवाज़ को कोई पूछने वाला नहीं ? यह बात साफ हो जानी चाहिए । (विघ्न)

Deputy Speaker : Order please.

आप ने शायद मेरी बात को सुना नहीं । मैंने पहले ही सरकार को कहा है कि पंजाब का रुपया पंजाब में ही रहना चाहिए । (The hon. Member has not perhaps heard me. I have already requested the Government that the money collected in the Punjab should not be sent out of the State.)

(interruption)

चौधरी इन्दर सिंह मलिक : आप ने जो कहा है दरुस्त है । मेरी तो गुज़ारिश यह थी कि इस बात का तो सी० एम० साहिब को पता ही नहीं दिया गया कि रुपया इस तरीके से सैंटर को दिया जा रहा है ।

(विघ्न)

मुख्य मन्त्री : मैंने पहले ही इस सम्बन्ध में अर्ज किया है कि इस के लिए सब कमेटी बना दी गई है जिस ने रूल्ज़ और रैगूलेशन्ज़ बनाने हैं कि इस रकम की डिसबर्समैंट किस तरीका से की जाए । इस सब कमेटी की दो मीटिंग्ज़ हो भी चुकी है और इस में बाई लाज़ भी बनाए जाने हैं । इस कमेटी की मीटिंग के अंदर आनरेबल मैम्बर साहिबान की नेक खाहिशात को देख लिया जाएगा और इस रकम को ज्यादा से ज्यादा पंजाब की इमदाद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा ।

चौधरी राम सरूप : आन ए पवाइन्ट आफ आर्डर, मैडम । मेरा पवाइन्ट आफ आर्डर यह है कि यहां इस हाउस की कारवाई एक ज़ाब्ता और प्रोसीजर के मुताबिक चलनी चाहिए । यह भी पता नहीं चला कि आप ने यह एडजर्नमैन्ट मोशन एडमिट कर ली है या नहीं और अगर एडमिट करली है तो हरेक मेम्बर को बोलने का हक्क होना चाहिए । यहां पर इसी मामले पर चीफ मिनिस्टर साहिब तीन बार बोल चुके हैं हालांकि प्रोसीजर यह है कि किसी को भी एक दफा से ज्यादा बोलने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए । इस लिए मेरा तो यही कहना था कि कारवाई को सैट प्रोसीजर के मुताबिक चलाना चाहिए ।

उपाध्यक्षा : शुक्रिया । (Thanks.)

श्री सागर राम गुप्ता : आन ए पवाइन्ट आफ आर्डर, मैडम । चीफ मिनिस्टर साहिब ने फरमाया है कि इस रुपया की डिसबर्समैन्ट के लिए रूल्ज़ अभी बनाए जाने हैं । तो रूल्ज़ जब तक न बन जाएं रुपया कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है और अगर कर दिया गया है तो उस मिनिस्टर के खिलाफ जिस ने ऐसा किया है क्या सरकार कोई एक्शन लेने के लिए तैयार है ?

परिवहन तथा निर्वाचन मन्त्री (सरदार गुरदयाल सिंह ढिल्लों) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, यहां पर मिनिस्टर कन्सर्न्ड नहीं हैं जो कि सारी बातों का जवाब दें । इस लिए वह सोमवार को आ जाएंगे उन से भी पूछ लेना चाहिए ताकि सही हालात का पता चल सके । यहां पर कुछ मैम्बरों ने सभी मिनिस्टरों के बारे में कहा है तो मैं अपने तरीका के बारे में उन्हें बताना चाहता हूं कि जिस ज़िला में ब्लाक समिति की तरफ से या किसी और आरगेनाइज़ेशन की तरफ से रुपया मुझे दिया जाता है मैं वहीं उसी ज़िला के डिप्टी कमिश्नर को दे देता हूं ताकि एक तो उस ज़िला का कोटा पता लग सके कि कितना कुलैक्ट किया है और दूसरा यह कि जिस तरह से सरकार की तरफ से उस को खर्च करने की हिदायत डी० सी०

के पास जाए उस का डिपारचर न हों। इस लिए मिनिस्टरों में फरक होना चाहिए। (विघन)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਤਨੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡਜ਼ ਨੂੰ ਐਜੀਟੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਕਊਰੇਟੀ ਐਂਡ ਡੀਫੈਂਸ ਰੀਲੀਫ ਫੰਡ ਲਈ ਰੁਪਿਆ ਇਕਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਅਸਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। (ਵਿਘਨ)

(Interruptions by Babu Ajit Kumar.)

उपाध्यक्षा : श्री अजीत कुमार, जब एक चीज़ बता दी है कि इस के मुताल्लक आप काल-अटैनशन मोशन ले आयें कोई अडजर्नमैंट मोशन आ ही नहीं सकती तो फिर एक बात को बार बार क्यों रीपीट करते हैं ? (*Addressing Shri Ajit Kumar*) (When he has already been asked to send a Call Attention Notice in this connection as an Adjournment Motion thereon cannot be admitted, why should he repeat the same thing again and again ?)

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ੈਡੂਲਡ ਕਾਸਟਸ ਨੂੰ 10% ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸ਼ੈਡੂਲਡ ਕਾਸਟਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰੋਮੋਸ਼ਨਜ਼ ਹੀ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਦਿਲਾਸੇ ਚੌਧਰੀ ਰਿਜ਼ਕ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਜ਼ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਈ ਦਿਤੇ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਪ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਡਿਸ਼ਕਸ਼ਨ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Deputy Speaker : I cannot admit this adjournment motion. (*interruptions*) आखर किसी डिस्कशन के लिये कोई न कोई रैलेवैंसी का होना भी तो जरूरी है, ऐसे कैसे डिसक्शन की कोई इजाज़त किसी को दी जा सकती है (I cannot admit the adjournment Motion (*interruption*) After all it is necessary that there should be some relevancy of the subject in a discussion. How can any discussion be allowed in its absence ?)

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਮੈਡਮ, ਮੇਰਾ ਇਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ਼ ਆਰਡਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਮੋਸ਼ਨ ਦਿਤੀ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸ਼ੈਡੂਲਡ ਕਾਸਟ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਵਾਕਆਊਟ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ?

Chief Minister : On a point of order, Madam.

Shri Jagan Nath : On a point of order. हम ने बीसियों दफा काल अटैनशन मोशन दिये मगर किसी ने कोई तसल्ली बखश जवाब नहीं दिया......

(Interruptions)

(S. Ajaib Singh, Sandhu, S. Harchand Singh Shri Jagan Nath and the C. M. rose on a point of order all at a time. S. Ajaib Singh Sandhu was allowed to speak.)

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਲ-ਅਟੈਨਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਉ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਲੈਕਟਰਿਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਜੋ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿਚ ਲੈ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੀਜਨ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਕੀ ਹਰੀਜਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ?

ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ : ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ਼ ਆਰਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਏਥੇ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਦਾਰ ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੀਏ ?

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਜਿਹੜਾ ਅਫ਼ਸਰ ਏਥੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। (No officer who is not present here, should be mentioned by name. Otherwise he can state the matter in a general way.)

श्री जगन् नाथ : On a point of order, Madam. जब हम काल-अटैनशन मोशन लाये थे तो आप ने कह दिया कि ऐडजर्नमैंट मोशन लाओ। अब अगर ऐडजर्नमैंट मोशन ले भी आते हैं तो आप कहते हैं काल एटैनशन लायें।

उपाध्यक्षा : मुझे हरिजनों के साथ पूरी हमदर्दी है मगर यह एक प्रोसीजर का सवाल है। हरीजनों के लिये आप मुझे जहां भी ले जाना चाहें मैं आप के साथ चलने को त्यार हूं। (I have the fullest sympathy for

Harijans. But this is a question of procedure. As for the Harijans, I am prepared to accompany the hon. Member any where he likes to take me for pleading their cause.)

Shri Jagan Nath: Will it be kept pending ?

Deputy Speaker : You may please send a call-attention notice.

श्री जगन् नाथ : यह कैसा तरीका है ? आप कोई अमरीका से नहीं आई या आप स्विटजरलैंड से नहीं आई जो हम आप को साथ लेकर चलें। हम तो आप से यह हैल्प चाहते हैं कि आप हमारी यह मोशन किसी तरह से एडमिट कर लें ताकि इस पर डिसकशन हो सके।

उपाध्यक्षा : मैं फिर कहती हूं कि ऐसे इस पर कोई डिसकशन नहीं हो सकती। (I reiterate that in this form, no discussion can be allowed.)

चौधरी नेत राम : मेरी आप से प्रार्थना है कि दफा 84 के तहत दो घंटे के लिये इस पर डिसकशन रख दें। इस से इन का मकसद भी हल हो जायेगा और हर हरिजन खुले तौर से डिसकशन भी कर सकेगा।

उपाध्यक्षा : यह 84 और 85 की आप उन को ही रायें दें। (The hon. Member may give this opinion about Rules 84 and 85 to them.)

मुख्य मंत्री : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं कोई चार बार उठा हूं मगर आपने मुझे इजाज़त नहीं दी।

उपाध्यक्षा : आप को कम अज़ कम चेयर के लिये ऐसे शब्द कहने नहीं चाहियें। (The hon. Chief Minister should atleast not have used these words for the Chair.)

मुख्य मंत्री : कम अज़ कम, मैडम, आप को भी ऐसा नहीं करना चाहिये था।

उपाध्यक्षा : आप की पार्टी का निज़ाम ही जब ठीक नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ। (When there is no discipline in his party what can I do ?

मुख्य मंत्री : इस तरफ से, मैडम, जब कोई आबजैकशनेबल बात ही नहीं हुई आप कैसे कह सकते हैं ?

उपाध्यक्षा : आप कुछ भी कहें मगर जो कुछ भी हो रहा है वह मेरे सामने है। (Whatever the Chief Minister may say, the fact is there.)

मुख्य मंत्री : डिप्टी स्पीकर साहिबा, पिछले बजट सैशन में इस हाउस के मुखतलिफ पार्टीज़ के लीडर साहिबान के मशवरे से यह तय किया गया था कि काल अटैनशन मोशन्ज़ ऐडजर्नमैंट मोशन, जिस को भी आप अलाऊ कर देती हैं उस पर किसी तरह की कोई बहस नहीं होगी । लेकिन मुझे इस बात का अफ़सोस है कि जिस दिन से सैशन हुआ है, मैं देखता हूं कि एक चीज़ तय होती है, वह अमल में नहीं आती । उसको अमल में लाना, यह चेयर का काम है । चेयर देखे कि आया एक डिसीज़न जो लिया गया है उस पर अमल हो रहा है या नहीं । लेकिन होता क्या है कि एक फ़ैसला हुआ उसको न मान कर हाउस में मैम्बर उसके विपरीत चलते हैं और चेयर उनको अमल में लाने के लिए प्रैस नहीं करती । कभी-कभी 15 या 20 मिनट तक कोई फैसला ही नहीं हो पाता। इस तरह से हाउस का वक्त जाया होता है । चूंकि हमें बोलने का मौका नहीं दिया जाता है, इस लिए उस पर हम कुछ कह नहीं सकते । बाद में अखबारों में शाया होता है कि गवर्नमैंट कुछ कह नहीं सकी या कुछ कर नहीं सकी। इस लिए मेरी यह दरखास्त है कि जो पार्लियामैंट्री प्रोसीजर है, जिस के तहत जिस रूल्ज़ और रैगुलेशन को तय किया गया है या जो फ़ैसला लिया गया है उस पर सखती से अमल होना चाहिए ।

उपाध्यक्षा : मुझे निहायत संजीदगी और अफ़सोस से कहना पड़ता है, कि 25 साल की पार्लियामैंट्री ज़िन्दगी में जो कुछ मैंने पढ़ा है और समझा है-सिर्फ कुछ देर के लिए ही इस दौरान में बाहर रही हूं-उस में मैंने यही देखा है कि अगर किसी वक्त कोई चेयर को न माने तो उसको नेम किया जाता है, मार्शल जाता है और मैम्बर को हाउस से विदड्रा करा दिया जाता है । ऐसा यहां होता रहा है । लेकिन आज जो बात मेरे लिए कही गई है कि मेरी वजह से किए गए फ़ैसलों पर अमल नहीं होता है, यह बेबुनियाद है । दरअसल बात यह है कि न इस तरफ कोई निज़ाम है, और न उस तरफ कोई निज़ाम है । अगर आपका निज़ाम ढीला हो तो मैं कुछ नहीं कर सकती ।(With all seriousness and profound regret I have to say that whatever the Parliamentary procedure I have read and understood during the 25 years of my Parliamentary life—I remained outside for a short period—I have found that if ever a member fails to obey the Chair, he is named. Then the Marshal is sent and the hon. Member is made to withdraw from the House. This has been the practic here. But the fact that has been attributed to me that because of me certain decisions taken by the House are not implemented is simply baseless The fact of the Matter is that there is no discipline on either side of this House. If they lack control over their parties, I am helpless.)

मुख्य मंत्री जहां तक इन बैंचिज़ का ताल्लुक है, यह पूरी तरह से चेयर का अहितराम करती हैं और करेंगी । लेकिन मेरी आप से दरखास्त है कि इस हाउस के डैकोरम को रखने के लिए आप लीडज़ आफ़ दी डिफरैंट गरूपस को बुलाइए और इम्प्रैस कीजिए कि रूल्ज़ आफ प्रोसीजर पर स्ट्रिक्टली अमल हो ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਿਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦਸੇਗਾ । ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸ਼ੋਅਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਇਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਚੇਅਰ ਵਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਪਾਲਨ ਕਰਾਂਗੇ ।

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਹ ਸੀਰੀਅਸ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਮੈਂ ਵੀ ਸਪੀਕਰ ਹਾਂ । ਖੂਬ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ। (I am also the Speaker and quite understand the matter.)

CALL ATTENTION NOTICES

(*Serial No. 171*)

Pandit Mohan Lall Datta : Madam, I beg to draw the attention of the Minister concerned to the grave irregularity in continuing the old Zila Parishad Hoshiarpur to function inspite of the fact that the election of new members of this Zila Parishad was notified in April last. Under the provisions of the Zila Parishad and Panchayat Samitis the old members could not function. It was a very serious irregularity in not constituting the new Zila Parishad and depriving the duly elected members from performing their duties as duly elected representatives of the people. The work carried on under the old set up was entirely *ultravires* The delay in constituting the new Zila Parishad was entirely unjustifiable. The matter is of urgent public importance and deserves immediate attention. The new Zila Parishad must be constituted immediately.

Deputy Speaker : It is admitted.

(*Serial No. 172*)

Comrade Babu Singh Master : Madam, I beg to draw the attention of the Minister concerned towards the matter regarding the retrenchment of nearly 300 Sectional Officers at Talwara and three other drain divisions.

Secondly the consolidation patwaris and clerks are being retrenched. No alternative jobs have been provided for the above-mentioned employees of the State. There is great sensation and resentment prevailing among the employees and members of their families. Hence the matter requires immediate attention of the Government to redress their genuine grievances.

Deputy Speaker : This is admitted, Next is by Shri Fateh Chand Vij, who is not in his seat. Next is by Sardar Gurnam Singh.

(*Serial No. 174*)

Sardar Gurnam Singh : Madam, I beg to draw the attention of the Government to the fact, namely, the reported kidnapping by Pakistani soldiers of 60/70 Indian girls from villages in Fazilka Sector during hostilities with Pakistan.

Deputy Speaker : This is admitted.
कामरेड साहब, जिस मोशन पर आपने फौरन स्टेटमैंट देनी हो, तो मेरे पास वह इत्तला भेज दिया करो (If the hon. Chief Minister wants to make a statement immediately after such a Motion, then he may please send necessary information to me.)

मुख्य मंत्री : डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह मामला बड़ा गंभीर है । यह जो किडनेपिंग और ऐबडक्शन की बात चल रही है, मैं यही कहना चाहता हूं कि यह बात ऐसी नहीं है । कल जो डिफैंस मिनिस्टर साहब ने लोक सभा में ब्यान दिया उस में उन्होंने कहा,

> "I am learning the details of this matter for the first time. The only information supplied by the Government to the Union Defence Ministry is that some families were missing from villages in the Fazilka Sector."

किसी जगह किडनेपिंग और ऐबडक्शन का सवाल नहीं है । मेरी तमाम भाईयों से यही दरखास्त है कि इस को बहस का मौजू न बनाएं । काऊंसिल में भी कल ऐसी ऐडजर्नमैंट मोशन आई थीं । मैंने यही कहा था कि लीडर्ज़ आफ दी पार्टीज़ को कानफिडैंस में लेकर इत्तला दी जाएगी । इस वक्त यही कहा जा सकता है कि फाज़िलका तहसील के दो गांव हैं, एक झंगर है और दूसरा चिश्ती पक्का । 6 तारीख को छम्ब पर जब अटैक हुआ तो उस वक्त इन विलेजिज़ पर दुश्मन का कब्ज़ा हो गया था । इस गांव में यानी झंगर गांव में उस वक्त 72 के करीब कुछ भाई और बहिन रह गए थे । इसी तरह चिश्ती की 1573 की अबादी में से 28 के करीब भाई और बहिन वहां रह गए थे । हमारे यहां के भाई जो पी० ए० पी० के थे वह भी कुछ मिसिंग हैं । हमारे पास जो इनफरमेशन आई थी वह यह थी कि 81 के करीब कुछ भाई और बहिन मिसंग हैं । उस के बाद 110 आदमियों के मिसिंग होने की इत्तला आई । दरअसल यह ऐसे हुआ कि दुश्मन के अटैक के कारण कुछ लोग निकल आए, कुछ रह गए जिस तरह से कि पाकिस्तान के गांव के भी कुछ लोग निकल गए और कुछ रह गए । इस लिए हम यह नहीं कहते कि किडनेपिंग हुई है या ऐबडक्शन हुई है । जो इत्तला आई थी वह मैंने गवर्नमैंट आफ इंडिया को भेज दी है । यह केस गवर्नमैंट आफ इंडिया के लैवल पर इंटरनेशनल रैडक्रास आर्मी परसोनल के ज़रिए टेक अप करना होगा । अभी मैं ने अपने डिस्ट्रिक्ट अथारिटीज़ से इनफरमेशन मांगी है कि जितनी भी इनफरमेशन मिल सके वह सप्लाई करें । यह इनफरमेशन हमें उन गांवों के लम्बरदार और सरपंच से मिली थी । इस के इलावा जो मज़ीद इनफ़रमेशन होगी वह हाउस के सामने रख दी जाएगी । जिस तरह आप को तशवीश है इस तरह गवर्नमैंट को भी पूरी तशवीश है कि हमारे एक एक भाई और बहन की इज्ज़त व माल महफूज़ होना चाहिए इस के लिए जो खातिरखाह बात है उस की तरफ पूरी तवज्जो दी जाएगी ।

Deputy Speaker : Call-Attention Notice No. 175 by Sardar Gurcharan Singh and Call-Attention Notice No. 176 by Sardar Gian Singh Rarewala are identical to Call-Attention Notice No, 174 and the Chief Minister has already made a statement on that Call-Attention.

सरदार ज्ञान सिंह राड़ेवाला : चीफ मिनिस्टर साहिब ने अपनी स्टेटमैंट में पोज़ीशन वाज़ेह नहीं की है। मैं अर्ज़ करता हूं कि हमारी इनफरमेशन के मुताबिक यह 1½ महीने की बात है कि जब मिलिटरी ओप्रेशन्ज़ हो रहे थे उस वक्त एक गार्द के तहत उन लड़कियों को वहां कपास चुनने के लिए ले जाया गया जहां से उन्हें पाकिस्तानी किडनैप करके ले गए। उस बात को छिपाया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि 1½ महीना खामोशी क्यों अख्तियार की गई थी।

ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਪ-ਮੰਤਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਚ ਉਹ ਪਿੰਡ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਪਾਹ ਚੁਗਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੈ ਗਏ ਹਨ। ਗਲ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੱਕਾ ਚੁਸ਼ਤੀ ਅਤੇ ਝੰਗਰ ਪਿੰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਉਤੇ ਜਦੋਂ ਰੇਡਰਜ਼ ਆਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅਚਾਨਕ ਬੇਖਬਰ ਘੇਰੇ ਗਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। (ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਘਨ)। ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਝੇ ਨੇਮ ਕਰਨਾ ਪੜੇਗਾ। (The hon. Members may please listen. This is not a subject for any discussion. I have, therefore, no intention to permit any discussion on it. (*Interruptions by Chaudhri Darshan Singh*) The hon. Member may refrain from doing so, otherwise I will have to name him.)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਸ ਗਲ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਉਥੇ ਖੁਦ ਕਪਾਹ ਚੁਗਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਰਾਇਮਰੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਥੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਫਰਕ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿਸਿੰਗ ਹਨ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਡਨੈਪ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਡਕਰਾਸ ਨੂੰ ਪੁਛ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਵਾਏ। ਬਸ ਏਨੀ ਹੀ ਗਲ ਹੈ।

ਉਪ ਮੰਤਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ): ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਪਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁਗਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਉਥੇ ਗਿਰਦਾਉਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਆਏ ਹਨ ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗ਼ਲਤ ਖਬਰ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਸਿਰਫ ਅਟੈਨਸ਼ਨ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

उपाध्यक्षा : चाहे वह मिसिंग हैं या ऐबडक्ट किए गए हैं इस बात पर बहस नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो गुमशुदा लोग हैं वह जरूर वापिस आने चाहिएं। (The fact whether they are missing or have been abducted should not be discussed. But what is needed is that the missing persons should be recovered without fail.)

चौधरी दर्शन सिंह : मैडम आप ने मेरे बाद सरदार गुरनाम सिंह को किस बेस पर बोलने की इजाज़त की है ?

उपाध्यक्षा : कामरेड साहिब, यह देख लें आप अपना निज़ाम। (Let the hon. Chief Minister just see their discipline in the members of the party.)

(*Serial No. 179*)

Giani Zail Singh : I beg to draw the attention of the Minister concerned to the fact, namely, the acquisition of fertile land in village Kansal Khol, tehsil Kharar, district Ambala, for the purpose of afforestation in the State. In view of serious food shortage in the country, diversion of agricultural lands for afforestation is not understandable. In view of the serious shortage in the country and the financial stringency, the Government should drop its scheme for the acquisition of agricultural lands of village Kansal Khol, for the development of forests. This is, therefore, a matter of extermely urgent importance.

Deputy Speaker : This is admitted.

चौधरी नेत राम : On a point of order, Madam. डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैंने काल-अटैनशन नोटिस दिया था कि फतहबाद के इलाका में पुलिस की नाजायज़ मदद से मुज़ारों को बेदखल किया जा रहा है। (विघ्न)

इस लिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इस बात की तरफ फौरी ध्यान दिया जाए।

उपाध्यक्षा : आप का काल-अटैनशन नोटिस मेरे पास नहीं आया। मैं आफिस से पता कर लेती हूं। (The Call attention Notice given by the hon. Member has not reached me. I will find out from the office.)

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੰਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪ ਉਥੇ ਗੋਲੀ ਚਲਵਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਣ ਇਕ ਬੰਦਾ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਗਲ ਵਲ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।

उपाध्यक्षा : मुझे आफ़िस से पता कर लेने दो। अगर आज न हुआ तो सोमवार को उसे ले लिया जाएगा। (Let me find out from the office. This matter will be taken up on Monday, if it has not been possible to take it up today.)

STATEMENTS LAID ON THE TABLE

Chief Parliamentary Secretary (Shri Ram Partap Garg): Sir, I beg to lay on the Table of the House the following four statements in regard to Call-Attention Notices Nos. 113, 115, 146 and 157 :—

(i) *re.* Call-Attention Notice No. 113 by Shri Jagan Nath, M.L.A., before the Vidhan Sabha on the 3rd November, 1965 in regard to the declaration of the result of Assistant Grade Test held in December, 1964;

(ii) *re.* Call-Attention Notice No. 115 in regard to supply of water in Kamach Khera Minor of Sunder Branch;

(iii) *re.* Call-Attention Notice No. 146 by Comrade Shamsher Singh Josh, M.L.A., in regard to initiation of legislation to nationalize the holding of Cattle Fairs in the State; and

(iv) *re.* Call-Attention Notice No. 157 by Sardar Tara Singh Lyallpuri requesting the Government to authorise the Sarpanches to verify the applications of the villagers for obtaining sugar in connection with marriage ceremonies, etc.

STATEMENT *re.* CALL-ATTENTION NOTICE NO. 113 BROUGHT BY SHRI JAGAN NATH, M.L.A., BEFORE THE PUNJAB VIDHAN SABHA ON THE 3rd NOVEMB R, 1965 IN REGARD TO THE DECLARATION OF THE RESULT OF ASSISTANT GRADE TEST HELD IN DECEMBER, 1964

In 1957, Government issued instructions whereby a test was prescribed for the promotion of a clerk to the post of an Assistant. This test was held as illegal by a court of law and that decision was upheld by the High Court. When the matter was referred to the L. R. to Government, Punjab, he advised that in order to give these instructions the force of law, it would be necessary to frame rules under Article 309 of the Constitution. These rules have been drawn and are being referred to the Government of India and the Punjab Public Service Commission for their approval under the provisions of the States Reorganisation Act, 1956 and under the provisions of the Constitution of India, respectively. After the publication of these Rules, now being framed it will become legal obligation on every clerk to pass the Assistant Grade's test before he is promoted as an Assistant. For the present this test has no legal force and any promotion made on the basis of the result of the test held by the Board might be challenged and involve Government in another complication. This complication is that the Clerks having failed and not promoted will contest their non-promotion, in view of the High Court Judgement already given on this point. The promotions ordered on the basis of the result of the test may have to be cancelled. In view of this it will be desirable to keep the result with held. So far as Government is aware this test is being held only on the basis of executive instructions and even if it be presumed for argument sake that a provision for the holding of such a test does exist in some of the Service Rules, it would not be desirable to declare a part of the result and withhold a part of it. Government is making serious efforts to settle this issue as quickly as possible.

STATEMENT IN REPLY TO CALL-ATTENTION NOTICE (S. NO. 115) REGARDING SUPPLY OF WATER IN KAMACH KHERA MINOR OF SUNDER BRANCH

Areas covered by the Western Jumna Canal depend on the free-flow in the river for irrigation supplies and in such a case it is not possible to conserve water during a particular period for utilisation later on. Efforts are made to take the maximum advantage of the free flow in the river at a particular time. During some of the summer months, the flow in the rivers is in excess of the demand. The supplies in the remaining months are, however, less than the maximum demand in the various systems. It thus becomes necessary to ensure equitable distribution in the entire system by rotational running of canals.

(Chief Parliamentary Secretary)

2. The rainfall has been extremely poor during the current year, throughout the State. This has been the position in the catchment areas of all the rivers. In particular he rainfall has deen extremely poor during the months of July and August, th rainfall was invariably much below the average rainfall in the past years. The discharge of the river Yamuna has also been unusually low, this year, which is insufficient to meet the demand. Against our requirements of 9,000 cusecs we are getting only 3,312 cusecs from this river.

3. Even with the poor availability of water, there has been no shortage in Kamach Khera Minor. In fact, the minor has been drawing more than its authorised discharge. From time to time, the outlets and minors are adjusted so as to ensure the drawal of authorised discharge Adjustments in Kamach Khera Minor have also been made. A fall at R.D. 6,700 below outlet for village Bamanwas has been built to ensure equitable distribution, which is not an obstruction, but a necessity.

4. Government have taken a number of steps to make best possible use of the existing supplies and provide facilities to the irrigators as indicated below :—

(i) 11,000 private tube-wells will be energised during the current year against 6,800 tube-wells energised during last year.

(ii) Action to connect CCA of tube-wells with watercourses has been taken vigorously and sufficient progress made. Arrangements to run the State Tube-wells for 24 hours have been made and optimum utility of tube-well water is being derived.

(iii) A number of schemes for remodelling and extending the channels have been taken up.

(iv) Minor Irrigation Schemes are also being taken up in certain area where canal irrigation cannot be made available.

(v) Strict watch is being kept on the rotational running of channels and proper regulation of Supplies has been ensured.

(vi) Decision to draw canal water from areas in the command of State Tube-wells has also been taken.

From the above, it is clear that Government is fully alive to the problem and are taking and will continue to take, all steps to ensure maximum supplies to the cultivators.

STATEMENT IN REPLY TO CALL-ATTENTION MOTION NO. 146 *re*. NON-INTERFERENCE OF GOVERNMENT IN THE MATTER OF HOLDING OF CATTLE FAIR BY PRIVATE INDIVIDUALS

Call-attention Notice No. 146 by Comrade Shamsher Singh Josh, M. L. A., to draw the attention of the Goverment to the fact that owing to non-interference by the Government in the matter of holding of Cattle Fair by private individuals which originally held only by the District Boards, the financial position of a large number of Panchayat Samitis has been gravely affected. The Government have been promising in the past to bring an enactment removing lacunae of present Zila Parishads and Panchayat Samitis Act so as to empowering only those local body institutions to hold fairs but so far no such enactment has been brought and a regular loot of the Panchayat Samiti finances is going on with the continuance of status-quo. In view of the grave consequences for these Panchayat Raj Institutions if the present situation continues, it is suggested that early steps to safeguard the financial interests of the Panchayat Raj Institution be taken.

STATEMENT BY THE HOME AND DEVELOPMENT MINISTER, PUNJAB

It has been decided by Government to initiate legislation to nationalise the holding of Cattle Fairs in Punjab. The interests of the local authorities which have been holding the cattle fairs in their respective areas will, however, be safeguarded by awarding them grants-in-aid out of the income accruing from the holding of cattle fairs in their areas. Necessary Bill for the purpose is being vetted and finalized by the Legislative Department. Government proposes to introduce the said Bill in the House during the next Budget Session of the State Legislaturs.

STATEMENT IN REPLY TO CALL-ATTENTION NOTICE NO. 157 *re.* VERIFICATION OF APPLICATIONS FOR SUGAR BY SARPANCHES

Sardar Tara Singh Lyallpuri, M.L.A. to draw the attention of the Minister concerned to the fact that previously the Sarpanches used to verify the applications of the villagers for obtaining sugar in connection with marriages and other occasions But now the Government has decided that the Oath Commissioners should verify the applications of the villagers for obtaining sugar where it takes many days before the poor villagers get sugar and thus they cannot get that in time. In view of this difficulty, I want to request the Government to authorise the Sarpanches to verify the applications of the villagers for obtaining sugar in connection with marriage ceremonies etc.

STATEMENT BY COMRADE RAM KISHAN CHIEF MINISTER.

Under the present controlled distribution scheme of sugar, in force in the Punjab State from April, 1963, the distribution of sugar in the rural areas of the State, has been entrusted to the Punjab State Co-operative Supplies and Marketing Federation under the control and supervision of the State Co-operation Department. A monthly quota of 6,000 to 7,000 tonnes out of the State quota of 14,000 tonnes per month is allotted to the Federation for distribution in the rural areas. Besides, an additional *ad hoc* quota of 1,000 tonnes obtained from the Government of India is being given for rural areas from October, 1965. Fifteen per cent of the total quantity of sugar allotted for rural areas is earmarked by the Federation for distribution to establishments and for marriages and other special occasions.

2. In the beginning, the sugar quota on special occasions, including marriages etc., in the rural areas could be drawn on applications verified by the Sarpanches. The anti-social elements, however, began to exploit the situation and complaints were received that sugar was being drawn by many applicants on false pretexts. Steps were, therefore, taken by Government through the agency of the Food and Supplies Department and the Police Department, for detection of cases where sugar had been drawn on false pretexts of marriages or any other special occasions. The checking made by the District Food and Supplies Controllers and Police Department revealed that there had been as many as 687 cases where sugar had been drawn for marriages and other special occasions on false pretexts, during the period from April, 1963 to October, 1963.

3. It was under these circumstances that with a view to curbing the anti-social elements, who exploited the tight supply position of sugar, Government decided to impose a condition of filling an affidavit about the correctness of the contents of the application for sugar permits for marriages and other special occasions along with the application.

4. It is, of course, true that some inconvenience is involved in the revised procedure, but this condition had to be imposed to keep a check on the activities of the anti-social elements. The requirement of filling an affidavit along with the application for sugar for special occasions, though not a complete check in itself, goes a long way in minimising the chances of drawal of sugar on false pretexts. The requirement of filling an affidavit has, however, been dispensed with in such cases where the applications are attested by a gazetted officer, MLA/MLC.

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ–ਅਟੈਨਸ਼ਨ ਅਜ ਹੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 22 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਟੇਕ ਅਪ ਹੋਵੇਗੀ । (*Addressing Babu Ajit Kumar*) (This call-attention notice has been received today and it will be taken up on the 22nd November, 1965.)

OBSERVATION BY THE TRANSPORT AND ELECTIONS MINISTER

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੰਤਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਕਲ ਮੇਰੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਆਪਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ ਨੇ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਖਰਾਬ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਵੀ ਨਾਲ ਇਥੇ ਰਖੇ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਕ ਦਫ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੂਸ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਇਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜੋ ਆਟਾ ਕਿਸੇ ਮਾਰਵਾੜੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਲੋਂ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅਜੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਅਜੇ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਸਨੂੰ ਇਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਆਟਾ ਡਿਸਪਲੇਸਡ ਪਰਸਨਜ਼ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਤੇ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਉਥੇ ਗਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਂਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਉਸੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁੜਮ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਲਾਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਿਸਦਾ ਹਲਕਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਇਕ ਰਜ਼ਾਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਇਸਦੀ ਸਾਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਇਕ ਖਾਸ ਥਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਪਲੇਨ ਕਪੜੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰ-ਸ਼ੁਦਾ ਹਨ। ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਰਖੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੇ ਪੱਟੀ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੱਟੀ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ, ਮੰਡਲ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਰਧਾਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਆਦਮੀ ਸਨ। ਪੱਟੀ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕ ਇਕ ਟੈਂਟ ਵਿਚ ਗਏ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਮਿਲੀ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਉਸ ਮੈਂਬਰ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਆਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਵਿਚ ਕੁਝ ਖਪਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਪਰੇ ਵਾਲੀ ਛਾਂਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਬੋਰੀ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਿਚੋਂ ਖਪਰਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਜੋ ਰਜ਼ਾਈ ਹੈ ਉਹ ਬੂਟੀਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵਲੋਂ ਰੀਲੀਫ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੌਰਮਿੰਟ ਰੀਲੀਫ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਗਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਮਿਸਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਪੰਡਤ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਵਰਗੇ ਲਾਇਕ ਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਆਦਮੀ ਸਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਸਰਨ ਚੰਦ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਨੇਕ ਸ਼ਰੀਫ ਵਜ਼ੀਰ ਸਨ ਉਥੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਦਮੀ ਵੀ ਰਖੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜੋ ਹਮਾਤੜਾਂ ਧਮਾਤੜਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਸਨ (ਹਾਸਾ) ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਥੇ ਐਸਾ ਆਟਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੀੜੇ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਐਸੀਆਂ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਚੀਥੜੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ

ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆਖਰ ਵਿਚ ਕੀੜੇ ਪੈਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਥੜਿਆ ਨਾਲ ਮਰਾਂ (ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ) ਵਰਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਬੇੜਾ ਕਰੇ । ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਗੁਰਿੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੜਕਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਹੈ । ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਵਰ ਰਖ ਲੈਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਟਲਣਾ ਸੀ । ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਈ ਵੀ, ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ । ਨਹੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਡਣਾ ਸੀ । ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੱਬ ਦਾ ਦਿਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਬਾਕੀਆ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਤਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜਸਟਿਸ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਪਾਉਣਗੇ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਕਲ ਜੋ ਗੱਲ ਇਥੇ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਗੱਲ ਹੈ । ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੈਂਬਰ ਵਿਚ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਖਾਉ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਬੁਰੀ ਗਲ ਹੈ । ਚੂੰਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਹਾਊਸ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਐਡਜਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਥੇ ਜਾਕੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ । (Whatever was said here yesterday in this respect, was of a very low order. I had stated at that time that if there was any such thing, the hon. Member should see me and show it in my Chamber and that it was not in good taste to behave like that in the House. The house is now adjourning for two days and feel it to be my responsibility to go there and see things for myself on the spot and report the true picture to the House.)

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੰਤਰੀ : ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗੌਰਮਿੰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਾਈਐਸਟ ਅਫ਼ਸਰ ਉਥੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ । ਮੈਂ ਵੀ ਉਥੇ ਸਰਪਰਾਈਜ਼ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਨੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਇਥੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਰਪ-ਰਾਈਜ਼ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਪਰਾਈਜ਼ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀ । ਮੈਂ ਆਪਨੂੰ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਰਪਰਾਈਜ਼ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੀ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੁਆਵਨ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਤੁਸੀਂ ਆਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਸ ਦੇਣਾ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਗਲਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿਤੋਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੈ ? ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਡੋ, ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਸਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ?

मुख्य मन्त्री : डिप्टी सपीकर साहिबा, गवर्नमैंट की तरफ से हम आपको हर तरह से फेसिलटीज देने को तयार हैं, आप वहां जाएं । रात मुझे खेमकरन के एक लीडिंग एडवुकेट श्री सूरज पाल जी जो बहुत पुराने कांग्रेस मैंन है मिले और तीन चार भाई और भी मिले । कोई शिकायत किसी जगह से नहीं मिली । इस वक्त

कोई 47/48 हजार भाई बहन हैं जिनकी मदद की जा रही है लेकिन किसी एक जगह से भी शिकायत नहीं पहुंची है कि कोई खराब चीज़ मिल रही है । हाउस में आकर इस किस्म की बातें करना स्वाए इसके कि एक तरह से कीचड़ उछालना है और कोई बात नहीं । मैं हाउस को यकीन दिलाना चाहता हूं कि अगर कोई भी ऐसा वाक्या हो कि वहां खराब और मिलावट की चीजें देते हों तो उसके लिए हम पूरी तरह सज़ा के मुस्तहिक हैं । न ऐसी चीज़ हुई है न हो रही है और न कभी होगी । डिस्पलेसड परसनज़ पूरी तरह से मुतमैंइन हैं और उनको कोई शिकायत नहीं लेकिन फिर भी मालूम नहीं कि वह किस तरह राई का पहाड़ बनाना चाहते हैं । गवर्नमैंट इन चीजों की अजाजत नहीं देगी ।

ਸਰਦਾਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ਼ ਆਰਡਰ, ਮੈਡਮ । ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਕਲ ਗੰਦੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਗੰਦੀ ਰਜਾਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸਮਗਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ ?

11.00 a.m.

THE PUNJAB SECURITY OF LAND TENURES (AMENDMENT) BILL, 1965

Pandit Mohan Lal Datta (Amb) **:** Madam, I beg to move for leave to introduce the Punjab Security of Land Tenures (Amendment) Bill, 1965.

डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं इस बिल के बारे में दो मिनट अर्ज़ करना चाहता हूं । इस बिल का मकसद बहुत ही साधारण है । जो टैनेंट्स 40 साल से मुतवातर जमीन पर कब्जा किए हुए हैं, उन को आकूपैंसी के राइट्स दे दिए जाने चाहिएं । इस के बारे में पहले जो कानून बने हुए हैं, उन में काफी लूपहोल्ज हैं । हमारी सरकार हर सेशन के अन्दर इन लूपहोल्ज को दूर करने के लिए लैजिसलेशन लाने का वायदा करती है लेकिन सरकार इस तरह का लेजिसलेशन लाने के लिए तैयार नहीं है । मैं समझता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान नही देना चाहती है । वैसे यह सरकार सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसायटी का नाहरा लगाती है लेकिन उन असूलों पर खुद सरकार चलती नहीं है । इस लिए मैं ने इस समस्या को हल करने के लिए एक बिल लाया हूं । मैं माननीय सदस्यों को प्रार्थना करूंगा कि टैनेंटस के हित को देखते हुए इसे पास कर दिया जाए ।

Deputy Speaker : Motion moved—

> That leave be granted to introduce the Punjab Security of Land Tenures (Amendment) Bill, 1965.

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੇਜਰ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾਂ, ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਮੋਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਪੰਡਤ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਮਾਨ ਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਜਿੰਨਾ

ਅਹਿਸਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਲੈਂਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੌਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਦੂਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਉ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਠੰਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੋਚਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ, 'ਗਰੋ ਮੋਰ ਫੂਡ' ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ, ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਿਕ ਪੈਟਰਨ ਆਫ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਪੰਡਤ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਇਕ ਨਾਉਂ ਤੋਂ ਅਲਰਜਿਕ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਐਲਰਜਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਧਿਆਨ ਰਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਟੈਨੈਂਟ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਉਠਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝੇਗੀ ਕਿ ਫਲਾਂ ਸਟੈਪਸ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਟੈਪਸ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਉਤੇ ਅਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇੰਡੋ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਨਫਲਿਕਟ ਦੇ ਕਾਰਣ ਇਮਪਾਰਟੈਂਟ, ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕੰਮ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਮ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਇੰਡੋ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਨਫਲਿਕਟ ਦੇ ਕਾਰਣ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦਰਹਮ ਬਰਹਮ ਹੋ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੁਚੀ ਉਸ ਕਨਫਲਿਕਟ ਵਿਚ ਲਗ ਗਈ। ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਐਸੀ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪੰਡਤ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਨੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਾਬਲਮ ਸਾਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਬਲਕਿ ਪੇਚੇਦਗੀਆਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬੇਜ਼ਰਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਬੇਜ਼ਰਰ ਆਤਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਭਾਵਨਾ ਬੇਜ਼ਰਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ "A" "B" ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ "B" "A" ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ ਉਹ in due course land less ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਹੁਤ ਸਾਧਾਰਨ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਤਬਕੇ ਉਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪਾਰਟੈਂਟ ਮਸਲਾ ਹੈ । ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ top priority ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਢੰਗ ਨਿਕਲ ਆਵੇਗਾ । ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਾਈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਭੀ ਦਿਤੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਆਲ ਹਨ ਅਗਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ in due course of time ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਲਿਆਵਾਂਗਾ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨਗੀਆਂ । ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਰੈਡਿਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਟਿਪਣੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਖਿਆਲਾਤ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਨੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਰਾਈਟਸ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਆਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਾਊਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਟੈਨੈਂਟ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਡਿਟੇਲਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । Punjab Tenancy Act, 1887 ਦੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 5, 6 ਅਤੇ 8 ਵਿਚ ਟੈਨੈਂਸੀ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਟੈਨੈਂਟ ਰਾਈਟਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਤੋਂ ਮਸਲਾ ਹਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ । ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕਨਾਮਿਕ ਹੋਲਡਿੰਗ ਦੀ ਡੈਫੀਨੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਪਹਿਲੂ ਹਨ । ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਦੀ ਡੈਫੀਨੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ? ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇਕਨਾਮਿਕ ਹੋਲਡਿੰਗ ਡੀਫਾਈਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿਲ ਬੇਜ਼ਰਰ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ । ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੀ ਹੈ । ਉਸ ਉਤੇ ਅਸੀਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ । ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਫਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਲਫਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ।

कामरेड राम प्यारा : ग्रान ए प्वाइंट ग्राफ ग्राडर, मैडम माल मंत्री ने फरमाया कि सरकार इस मामले पर फुरती से गौर कर रही है । मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि इस मामला पर सरकार कब से गौर करने लगी है । इस

बारे में हर सैशन में सवाल किया जाता है तो उस का जवाब आता है कि यह मामला ज़ेरे गौर है। मैं ने टैनेंट्स के मामले के बारे में सवाल किया और उस का जवाब तीन साल के बाद मिला कि——

'time and labour involved will not be commensurate with the result to be achieved.'

Deputy Speaker : The hon. Member knows the procedure that I cannot allow any other hon. Member to take part in discussion when leave to introduce a Bill is sought.

Comrade Ram Piara : Madam, I only want to elicit information from the hon. Minister in respect of or arising out of the observations made by him.

Deputy Speaker : The hon. Member may get that information from the Government in writing.

Comrade Ram Piara : I had asked this information a number of times and got the replies. In one case I got a reply to a question after three years, wherein it was stated that 'the time and labour involved will not be commensurate with the result to be achieved.' I also made some suggestions to the Government in regard to tenants' problem and the reply that I received from the Government was that 'the matter is under the consideration of the Government.'

Now, Madam, what I want to know is how long will it remain under the consideration of the Government.

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਤਾ ਕਿ the labour involved will not be commensurate with the results likely to be achieved. ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।

ਦੂਸਰੀ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ matter is under consideration of the government ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਇਹ ਮਸਲਾ ਅੰਡਰ ਕੰਸਿਡਰੇਸ਼ਨ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਕਾਮਰੇਡ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਲੈਣ, ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਦਸ ਸਕਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਲਗੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਐਨੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ

Deputy Speaker : Question is—

That leave be granted to introduce the Punjab Security of Land Tenures (Amendment) Bill 1965.

(After ascertaining the votes of the Members present by voices, Deputy Speaker gave an opinion. The opinion was challenged. The bells were sounded. The question was put again and lost by a voice vote.)

The motion was declared lost

RESOLUTION *RE. THE GENERAL FEELING AMONG THE PEOPLE OF THE STATE THAT IN VIEW OF THE ANTI-INDIAN ROLE OF THE BRITISH GOVERNMENT IN THE RECENT INDIA-PAKISTAN CONFLICT, INDIA SHOULD QUIT THE COMMONWEALTH (RESUMPTION OF DISCUSSION)

Deputy Speaker : Now the House will resume discussion on the non-official resolution moved by Comrade Shamsher Singh Josh on the 5th November, 1965.

Transport and Elections Minister (Sardar Gurdial Singh Dhillon) : Madam Deputy Speaker, it is since the last Non-official day that we are discussing and also reviewing in this House as well as in the Upper Houseour relations in the Cemmonwealth. Madam, I am one of those persons who have always been advocating the desirability of the beneficial results of our links with the Commonwealth and our great leader the late Prime Minister, Pandit Jawahar Lal Nehru taking stock of the various shades of opinion in this country, at the time when we became Republic, decided in favour of our continuing in the Commonwcalth and today when we find ourselves faced with the same problem of reviewing whether we should continue or dissociate ourselves at a stage when we are passing through a great crisis, is very painful to me.

Madam, during all these years I have had an opportunity to be one of the Presidents of the Commonwealth Organisation in the State and you know most of the Members from this side and from the Opposition side were members of the Working Committee and all this time we never differed about one thing i.e. we must continue to be a member of the commonwealth. A number of occasions arose when this question was debated but not with so much resentment as this time. I, too, now feel that men of my way of thinking should also revise their past opinion. Madam, I have gone through the various stages through which this Commonwealth concept has passed. From the Durham Report and the Belfour Declaration we came down to the London Conference of 1949. There was time when its membership was confined only to the Dominions and that too in very limited sense. Later on the authority of the Dominions was expanded and then it was treated at par with the mother country. Again later on a time came when most of the Asian countries gained their independence and some of these countries chose to remain outside the Commonwealth and India alongwith some other countries decided to join it. Then came the time when African countries started gaining their independence and some of them also joined the Commonwealth. Now, Madam, the total population of the Commonwealth is 720 millions. Out of this 560 millions is in Asia; i. e. 77% and 77 millions in Africa; i. e. 10½%. Madam, out of this population which is associated with the Commonwealth 450 million Indians alone are amongst them. After every three members of the Commonwealth we have one Indian.

Madam, during this period on one or two occasions, I had a chance to attend either in one form or the other some Parliamentary Conferences. One was held in Australia and the other in England. I came back with the genuine impression that the old Commonwealth countries—Britain, Australia, New Zealand and Canada — genuinely wanted to help us and most of the African-Asian countries genuinely wanted to be associated with the old countries. Once when I was in Australia, Lord Attlee also happened to be in that Conference.

---

*"This House recommends to the Government to draw the attention of the Union Government to the general feeling among the people of the state that in view of the anti-Indian role of the British Government in the recent India—Pakistan conflict, India should quit the Commonwealth" was discussed in the House on the 5th November, 1965.

During our trip to the various States in Australia when by chance or by an accident, the white Members were accommodated in one Hotel and the Africans and the Asians in other separate Hotels, some Members of the delegation objected to this, but Lord Attlee was able to handle the situation in a very commendable manner. But, now, I view the whole situation again on the basis of professions and actions. So far as the relations between different countries of the Commonwealth are concerned, I may say that it was in a London Conference in 1949 that the late Prime Minister of India, Shri Jawahar Lal Nehru got an agreement to the Indian Republic remaining within the Commonwealth and to India recognising the Queen as the symbolic head of the Commonwealth although not as the Queen of India. That was a big constitutional issue which was decided in that Conference. That issue arose because of the sovereign status of the Republic of India as enshrined in the Indian Constitution. In that Conference, it was admitted, rather it was agreed upon that the Queen may be the Queen of England, but she will not be the Queen of other countries and will be treated only as the Head of the Commonwealth. That vital decision provided a big solution to the other countries which later got independence and joined this Commonwealth.

Madam, you know full well what storm of controversy arose at the time the Constituent Assembly was in session over this issue. You are also well aware what our late Prime Minister, other Congress Leaders and Leaders of various other Political Parties, such as Shrimati Sucheta Kripalani, then Leader of the Praja Socialist Party in the House of People, now the Chief Minister of Uttar Pradesh, Shri H. V. Kamath, a Member of Parliament, Professor H. N. Mukerji, Deputy Leader of the Communist Party in the House of People, Dr. S. P. Mookerjee, then Leader of the Jan Sangh, said on this vital issue. Shri Jawaharlal made it clear and said ;

> "If we are completely dissociated from the Commonwealth—for the moment we are completely isolated, we cannot remain completely isolated and so inevitable by stress of circumstances, we have to incline in some direction or other".

Speaking on 'what is Commonwealth', Shri H. V. Kamath described the commonwealth as a house divided against itself; it is half slave and half free. A house divided against itself could not stand and a group of nations half slave and half free could not endure. Professor H. N. Mukerji of the Communist Party in the House of People said ;

> "We find Mr. Nehru yoking himself to the chariot wheels of the imperialist machine of Britain and America in a manner which makes us feel that the future of the world is being imperilled".

Shrimati Sucheta Kripalani, referred to India's policy of non-alignment and pointed out that being in the Commonwealth India had to work in close cooperation with the Commonwealth countries and hence could not claim that she stood absolutely impartial between the two blocks or that her position was quite distinct between the two blocs, while Dr. S. P. Mookerjee argued that India should quit the Commonwealth because it has not helped us at all even in our right and just stand. Ultimately, however, the country accepted the views of Shri Jawahar Lal Nehru. Clarifying the position, he said ;

[Transport and Elections Minister]

> "The Commonwealth does not restrict independence of judgment or action. It is only in terms of independent nations cooperating together that we can consider the problem of our association with Commonwealth. Alliances usually invole military and other commitments and they are more binding. Other forms of association which do not bind in this manner but which help in bringing together nations for the purpose of consultation and, where necessary, of cooperation are therefore a more preferable than any form of alliance which does bind".

I may tell you, Madam, that I was just going through a book "The Commonwealth Challenge" by Derek Ingram wherein it is stated..

> "The successors to Harrow-educated Mr. Nehru or Sandhurst trained President Ayub Khan will not see things in quite the same way as their predecessors. If Britain hopes to win the ideological battle she should not be afraid to encourage the natural flowering of different national personalities within the Commonwealth......In the rich variety of the Commonwealth lies its greatest promise to mankind. It is also, I think, the supreme challenge to its future."

(THE AGA KHAN AT OXFORD, 1960.)

This advice of the Aga Khan was very sound indeed to Great Britain.

Madam, during the critical times of 1962, we fought against the Red China and Britain did come up to our expectations. In fact, I think, in that hour of crisis, in that hour of misery and anxiety, U. K. and U. S. A. did come to our rescue. But, later during the Indo-Pakistan conflict, I really wondered how the attitude which Britain showed in 1962, should have changed so suddenly, when Pakistan entered into an alliance with China against India. I fail to understand the implications of that British policy so far.

Madam, you remember, during the Indo-Pakistan conflict, I was appointed like my other colleagues in the Cabinet, with my headquarters at Amritsar, as in-charge of the Border Districts of Ferozepore, Amritsar and Gurdaspur. It was then that I used to hear in the evening B. B. C. announcements that the Pakistanis had over-run all these districts. The B. B. C. told us that Pakistani forces had occupied the Hall Bazar of Amritsar; that they had taken away the clock on the front gate of Amritsar. I was really surprised to see that the B. B. C. possessing unique reputation and having most fair and impartial commentators, should have been misled by somebody like this. The heroic deeds of our soldiers were not properly depicted, rather distorted and presented in a questionable manner. The role of the B. B. C. in that turmoil and struggle and what I read in the Papers from U. K. in those days, was really shocking. What the leading Papers in London, Manchester, New York and Washington, said at that time, had no basis at all. My faith was shaken not only in the B. B. C., but also in the British as well as the United States Press as a whole. I very often wonder whether our Embassies abroad kept them properly informed. But, inspite of that we knew that our Public Relations Department and our Embassies abroad kept them well posted. Madam, when I came back from Amritsar, I received a number of letters from my friends abroad, as during my stay in America and other foreign countries, I had made a number of friends and well-wishers of India. One of them wrote to me :

> "It is a pity that such a nice city as Chandigarh should be destroyed and demolished by Pakistan. We heard that the Vidhan Sabha building, the Civil Secretariat building and the High Court building, have been razed to the ground".

Madam, I wrote back to him :

> "Whetever you say my friend is absolutely correct. They did demolish and raise all these buildings to ground, but our Government did not wish the people to know about it. What we did was that we got up the same day and reconstructed all these buildings in the early hours of the morning. When the staff came back to these buildings, they found that these had been reconstructed in the early hours of the morning. The people could not know about it".

I had expected that the B. B. C. will give this news as well that these buildings had been raised again, but I was sorry to find that nothing of it came about.

Now, I tell you, Madam, what we thought about the Commonwealth. You know how deeply prejudiced was our Prime Minister, Shri Jawahar Lal Nehru, at the time of the Congress Session at Lahore in 1930. Madam, you yourself are one of the old stalwarts of that movement. We were just children, when we used to hear your name I saw you amongst the people at the dais in the Lahore Congress Session. At that time our Prime Minister said that—

> "Independence for us means complete freedom from British domination and British Imperialism, India should never be an equal member of the Commonwealth unless imperialism and all that it implies is discarded."

The great man of the world had such deep prejudices which he had expressed in these words.

Later on, his views changed. He became a very mild man, a little wiser and a little soft man and again in March, 1937, he said—

> "It is said and I believe Gandhi Ji holds this view that if we achieved national freedom, this would mean the end of British Imperialism itself..............."

Madam, you will see from these observations that the man, who was so deadly opposed to any idea of a commonwealth etc., changes a little, and while making these observations he continued to say further that—

> ".........Under such conditions there is no reason why we should not continue our connection with Britain. There is force in the argument for our quarrel is not with British Imperialism."

He reiterated connection, and declared—

> ".........But let us repeat again that we favour no policy of isolation or aggressive nationalism as the word is understood in the Central European countries today. We shall have the closest of contacts we hope with all progressive countries including England, if she has shed her imperialism".

So see, Madam, the man who had very deep prejudices against that country, changed and gave a very clear opinion or I should say policy.

Then in March, 1946, Lord Attlee, at that time Mr. Attlee, said—

> "I hope that the Indian people may elect to remain within the British Commonwealth. I am certain that she will find great advantages in doing so, but if she does not so elect, it must be by her own free will..........."

Here you will see, Madam, that Lord Attlee, at that time Mr. Attlee changed considerably. Our leaders also changed their opinion and up to 1947, they were thinking on certain common points. These observations of Lord Attlee produced the background. Please note these words that were said by Lord Attlee—

[Transport and Elections Minister]

> "...........I am certain that she (India) will find great advantages in doing so, but if she does not so elect, it must be by her own free will. The British Commonwealth and Empire is not bound together by chains of external compulsion. If on the other hand she elects for independence in our view she has a right to do so."

After two-and-a-half years of Dominion Status we decided to become Sovereign Republic in January, 1950 and as I have told you, the Prime Minister, who was so much opposed to the Commonwealth idea, first changed a little in 1937, and after Mr. Attlee's statement, he changed considerably. So while discussing the future relations of the proposed republic with the British Commonwealth, Our Prime Minister recalled the Independence Day Pledge to which the Nation had dedicated itself year after year that India must sever her connection with Great Britain, because that connection had become an emblem of British domination, and said—

> "On the eve of this great occasion when we stand on the threshold of freedom, we do not wish to carry a train of hostility with us against any other country............."

He said there were a number of reasons for that. But as the great Leader Mahatma Gandhi said that we have no malice, the Prime Minister said that we will forget everything, viz.—

> ".............We will forget the train of hostility with us against any other country. We want to be friendly with all. We want to be friendly with the British people and the British Commonwealth of Nations."

In this way he created a ground.

Again, later on Mr. Nehru declared that—

> "India, however, desires to maintain all such links with other countries as do not come in the way of her freedom of action and independence and the Congress would welcome her free association with the independent nations of the Commonwealth for their common well and the promotion of world peace."

I may also mention, Madam, that the Jaipur decision was a clear indication to the future set-up. The Prime Minister very much preferred an association with the British Commonwealth which would not bind India to any commitments but which would help bringing nations together for the purpose of consultation and possible co-operation.

This is the background under which we joined the Commonwealth organisation. The Britain also assured us about their impartial attitude. We expected from her non-interference in our independence. During all these years that followed, i.e., after this declaration of the Prime Minister, a number of occasions came such as the organisation of NATO, CENTO, SEATO, when Pakistan became a member of these organizations, but we withstood all those occasions because we were given the assurances that all these treaties were meant more for other purposes than helping any country, inimical towards India. We have all through been working on this idea as a member of the Commonwealth, and feel very much pained when we have to speak in a different tone. I do not wish or like that and I wish we could clear up our positions with that country Britain. Sometime back, the first Secretary of British High Commission came and met me. I took him to my house and at break-fast I told him 'Let us discuss this matter in a very free and frank manner, i.e., what is wrong with us and what is wrong with you people/your Government'. I asked him, how all this has happened with the background of all our relations and

clear records. I also told him that the people of Punjab thought as if on the B, B. C. Radio, Nizam-ud-Din was speaking from the Pakistan Radio and if the masses see this attitude, it becomes very difficult for leaders and their representatives to remove the hatred/opinion against that country (Britain). Atleast I feel like this. He said, and I do not hesitate to share his views with this House because he is a nice man, that now Mr. Wilson had made the amends, he did not have the exact information at the time he denounced India; this information was incorrect and now Mr. Wilson has come up with this statement.

I told him that it is very nice of Mr. Wilson and that we are quite good people to accept what he says but when we tell to our people, when we go to the masses, when we go to the people of the border areas who were shelled, who were bombarded and to whom Mr. Wilson said that they were the aggressors and not the Pakistanis, and tell them "No, no, Mr. Wilson said this without ascertaining full facts and that Mr. Willson has now realised his mistake", they say that England is a most advanced country on whom we have based our pattern of democracy, on whose political concept and political ideologies we have based our political institutions and she should not have given her opinion on such an important matter as between India and Pakistan in such a haste. I told the First Secretary that our 450 million people refuse to believe your explanation. They report and say "What is the use of now saying by Mr. Wilson that he was not in possession of full facts when he made his first statement. He should have said this on the next day, on the next following day but not after ten days of the cease-fire. What is the use of saying this now."

Madam, if we had not taken a little care across the borders after the Pakistanis crossed our international border, I tell you—I have full information in my possession—Pakistan would have attacked us on the 7th September. I come from the district of Amritsar where the Pakistanis wanted to attack us through the Kasur Sector on the 7th. Throughout all these years we were told that these NATO and CENTO arms were not meant to be used against India but they were meant to be used against Communist China but now, Madam, everyone knows against whom these arms, ammunition, Patton Tanks and Sabre Jets have been used.

उपाध्यक्षा: क्योंकि हाउस में पैंनल आफ चेयरमैन का कोई मैम्बर नहीं है। इस लिए मैं मिस्टर खुरशेंद अहमद को कहती हूं कि वह थोड़ी देर के लिए यहां चेयर में आ जाएं। मैं थोड़ी देर के लिए जाना चाहती हुं। Is it the sense of the House?

(As no Member of the Panel of Chairmen is present in the House I request Chaudhri Khurshed Ahmed to occupy this Chair as I want to go out for some time. Is it the sense of the House ?)

VOICES: Yes.

(At this stage Chaudhri Khurshed Ahmed occupied the Chair.)

Transport and Elections Minister: Mr. Chairman, I would call upon any honest, impartial and neutral person from any country of the world to visit our border areas where our brave men have maulded

[Transport and Elections Minister]

the Pakistan's Army and destroyed hundreds of Patton Tanks and Sabre Jets and see to himself that all this armour was the part of the NATO and CENTO equipment.

Now, Mr. Chairman, as I have already stated, with the joining of the most of the African and Asian countries in the Commonwealth we have out-numbered the old members of the Commonwealth. We are greater in number, we are greater in population and now a question arises: Is there any chance or possibility of increasing our influence in the Commonwealth in the future? I think, Sir, that we stand a very little chance. I think there is no chance left now. We are larger in population, we are larger in membership but still Britain does not play her role impartially. Her leanings towards Pakistan are well understood. Pakistan is the creation of the British imperialism. She is the child of Britain and you see a child however inefficient, however imbecile and however stupid he may be, the affectionate parents do not mind. They say "No, no, after all he is our son. He will be all right in due time". That is the attitude of the British Government towards Pakistan.

Mr. Chairman, for all these years they kept on feeding us with good ideas and with all sorts of ideals but when we were face to face with Pakistan in the recent hostilities, Britain chose to go over to the side of Pakistan and its Prime Minister declared us aggressor without knowing the full facts.

कामरेड बाबू सिंह मास्टर : चेयरमेन साहिब, कोरम देख लीजिये ।

श्री सभापति : सरदार गुरयाल सिंह जी क्योंकि कोर्म की कमी है इस लिए जब कोर्म नहीं आप बंद रहें । (Since the House is not in quorum, the hon. Minister may stop speaking till the quorum is complete)

(इस समय कोर्म को घंटी बजाई गई । कोर्म पूरा हो गया ।)

Transport and Elections Minister : Now I think, Sir, that we should seriously think over our relations with the Commonwealth countries. Sir, it is high time when we should think whether it is really beneficial to live in the Commonwealth or not? I think, Sir, it needs deep consideration, it needs deep and greater discussion with the members of the Commonwealth family so that they may know that what has happened with us today can happen with them also.

Now, Sir, take the case of Rhodesia. Rhodesia was the pet child of Britain. That pet child has made a mistake and there is very mild reaction from the British Government. They are not taking any strong action against their pet child. The Rhodesian Government has cut off the telephone connection of the Governor, who is the legal authority there, and the British Government has not even protested against it and now the Governor is without any telephone. Yesterday, I also read in the newspapers that the British Government may not use force against its pet child to bring him round,

In the end I would request you, Sir, that now when we have gained experience of the attitude adopted by the old members of the Commonwealth and particularly the British Government at a time when we were passing through a critical hour we should seriously think over about our relationships with the Commonwealth.

With these words, I resume my seat. Thank you very much, Sir.

प्रिंसिपल रला राम (मुकेरियां): सभापति महोदय, ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध जब हिन्दुस्तान ने आज़ादी की मुहिम चलाई तो यह लाज़मी था कि ,कुछ हद तक कड़वापन हमारे व्यवहार और विचारों में आ जाता। वह कड़वापन काफी देर रहा और जैसे अभी हमारे मिनिस्टर साहिब ने पंडित जवाहर लाल नेहरू की स्पीचिज़ में से एक्स्ट्रेक्ट्स पढ़ कर सुनाए हैं वह हमारे इण्डिया की जो पालिसी थी उस के अन्दर भी ज़ाहिर होता था लेकिन ज्यूं ही हिन्दुस्तान को आज़ादी मिली हिन्दुस्तान का रवैय्या ग्रेट ब्रिटेन की तरफ जो था उस में तबदीली हो गई और जो कड़वापन हमारे ताल्लुकात में था उसे कम अज़ कम हिन्दुस्तान ने भूलने की कोशिश की।

कामरेड बाबू सिंह मास्टर : मिस्टर चेयरमैन, कोरम नहीं है। हाऊस कैसे चल सकता है ?

(Bells were sounded for want of quorum.)

(At this stage some hon. Members came in but the quorum was still not complete.)

ट्रांसपोरट अते चोण मंतरी : चेअरमैन साहिब, किउंकि बाहर ब्रिटिश पारली-मैंटरी डैलीगेशन आइिआ होइिआ है अते आनरेबल मैंबर साहिबान उन्हां नाल चाह पी रहे हन इस लई मेरी बेनती इह है कि हाऊस नूं अधे घंटे वासते ऐडजरन कर दिता जावे।

11.50 a.m. **Mr. Chairman** : since the House is still not in quorum, it is adjourned for half an hour.

(The Sabha then adjourned till 12.22 p.m.)

(The Sabha re-assembled at 12.22 p.m. and bells were rung, till 12.26 p.m)

(The Deputy Speaker, Shrimati Shanno Devi in the Chair)

Deputy Speaker : The House will now resume discussion on the Resolution. Principal Rala Ram, who was in possession of the House when it adjourned, may resume his speech.

प्रिंसिपल रला राम : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं यह कह रहा था कि जब हिन्दुस्तान को आज़ादी मिली तो इस ने अपने ताल्लुकात दूसरे मुल्कों से ज्यादा से ज़यादा बढ़ाने की कोशिश की, हिंदुस्तान बाहमी ताल्लुकात में इतना ज्यादा आगे आ गया कि इस ने अपने पिछले तफरकात को भुलाने तक की भी कोशिस की,

[प्रिंसिपल रला राम]

कोशिश ही नहीं की वल्कि भुला ही दिया, जिस का मतलब यह था कि हर मामले पर दूसरे मुलकों के भी सद्भावना के जज़बात पैदा हों। बेशक अंग्रेज़ हिंदुस्तान को छोड़ कर चले गये मगर इन के अंदर उस वक्त भी सद्भावना का मादा था। यही स्पिरिट यू० के० के अंदर आई।

(At this stage Shri Ram Saran Chand Mital, a Member of the Panel of Chairmen, occupied the Chair.)

यह ठीक है कि इन कंट्रीज की इंटरनेशनल पालीसी में बड़ा भारी मत भेद था मगर हिंदुस्तान ने बड़ी दयानतदारी से इन से एक हो कर रहने का प्रयत्न किया। आज तक हिंदुस्तान हमेशा कालोनियल नज़ाम के खिलाफ आवाज़ उठाता रहा है, बेशक वह कामनवैल्थ कंट्रीज़ में शामिल हो गया है मगर फिर भी अपनी सद्भावना यह मुलक दिखाता ही रहा है। (Quorum Bells were rung till there was quorum in the House) मगर पिछले दिनों जब मि० हैरल्ड विलसन ने जो कुछ हिंदुस्तान के खिलाफ कहा इस से तब इसे सही हालात का पता लगा कि किस तरह इंगलैंड ने जान बूझ कर पाकिस्तान की तरफ़दारी की और हिंदुस्तान की मुखालफत की। यह बात कौन नहीं जानता कि काश्मीर के अंदर घुसपैठिये पाकिस्तान की तरफ से सब से पहले दाखिल हुये। इनकी आँखें उस वक्त भी नहीं खुलीं जब छंभ सैक्टर में पाकिस्तानियों ने 70 टैंकों के साथ बड़ा भारी हमला किया। यह हिंदुस्तान को ही ऐग्रैसर ठहराते चले गये। इस से बड़े भारी अफसोस की और बात क्या हो सकती है? बी० बी० सी० और यू० के० के अखबारात ने यहाँ तक लिखा कि पंजाब और यू० पी० की सड़कों पर खून की नदियाँ बह रही हैं।

(Quorum Bells were rung)

उसका मतलब यह था कि पंजाब के हिन्दू और सिक्ख तथा यू० पी० के हिन्दू और मुसलमान लड़ मरें। यह यूरोपियन अखबारों ने लिखा। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से हिन्दुस्तान को नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न किया गया। बरतानिया के लोगों ने हमारे खिलाफ फिज़ा पैदा करके पाकिस्तान की मदद करने की कोशिश की। यह प्रस्ताव जो आया है वह हिन्दुस्तान की फीलिंगज़ का इज़हार है, लोगों के दिलों का इज़हार है कि किस तरह से लोगों के बरतानिया के खिलाफ जज़बात हैं। ब्रिटेन ने पाकिस्तान की मदद करके कानफलिकट को और भी संजीदा बनाने की कोशिश की, इसलिए हिन्दुस्तान के अन्दर यह मांग पैदा हुई। हिन्दुस्तान की गवर्नमैंट को हिन्दुस्तान को कामनवैलत्थ से बिदड़ा कर लेना चाहिए। ब्रिटेन ने यह साबित कर दिया इस जंग के दौरान कि आज़ादी की लड़ाई जो हमने उनके खिलाफ लड़ी उसको वे भूले नहीं हैं और उसका बदला हमसे इस वक्त लिया और माफ नहीं किया जब कि हिन्दुस्तान कामनवैलत्थ में

शामिल हो कर पुरानी बातें सब भूल गया था । जब ऐसा रवैय्या उन्होंने हमारी जिन्दगी और मौत के मरहले पर अपनाया तो स्वाभाविक था कि हमारे देश की यह भावनाएं होतीं । हम जिस दौर से गुज़र रहे, वह अभी खत्म नहीं हुआ

(Quorum Bells were rung)

इस लिए हमें बड़ी एहतियात की ज़रूरत है । लोगों के अन्दर आज यू० के० के खिलाफ बड़ी भारी नाराजगी है, क्योंकि उन्होंने हमें लैट डाऊन किया है और करारी जरब पहुंचाने की कोशिश की............

An hon. Member: Sir, the attendance in the House is very thin and it is becoming very difficult for the House to remain in quorum. I suggest that the House be adjourned. The subject under discussion is important and requires full attendance of the House.

Mr. Chairman : Is this the sense of the House ?

Voices : Yes.

(Principal Rala Ram was still in possession of the House when it adjourned.)

12.40 p.m. (The Sabha then adjourned till 2 p. m. on Monday, the 22nd November, 1965)

1570 PVS—386—16-11-65—C., P., & S., Pb., Patiala.

PUNJAB VIDHAN SABHA
DEBATES

22nd November, 1965

Vol. II—No. 24

OFFICIAL REPORT
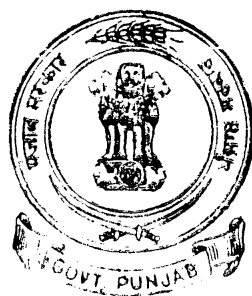
CONTENTS

Monday, the 22nd November, 1965

Punjab Vidhan Sabha Secretariat, Chandigarh.

Price Rs. 4.50

ERRATA

to

Punjab Vidhan Sabha Debates, Vol. II, No. 24, dated the 22nd November, 1965

Read	*For*	*Page*	*Line*
correct	connect	(24)4	8 from below
connection	correction	(24)4	6 from below
प्वायंट	प्यांट	(24)5	1
कैडिट्स	कैडि स्	(24)5	6
ਸੀਰੀਅਸ	ਸੀਰੀਅਜ	(24)5	14
question	questlon	(24)6	8 from below
नो	नौ	(24)6	Last but one
पूछना	पूछनन	(24)6	Last but one
ਇਸ	ਸਿ	(24)7	13
उप मन्त्री	उप मत्री	(24)9	1
ਵਥਜ਼	ਵਰਸ਼	(24)10	11 from below
vigilant	Vigilanr	(24)11	5 „
He	It	(24)11	5 „
passed	pas ed	(24)15	10
Expunged	Expunger	(24)17	Last
प्वायंट	प्यांयट	(24)19	4 from below
अर्ज़	आर्ज़	(24)20	Last
speech	speach	(24)22	8
ਖੁੜੀਆਂ	ਕੜੀਆਂ	(24)25	7
ਲੋਕ-ਸਭਾ	ਲਕ ਸਭਾ	(24)25	8

Read	*For*	*Page*	*Line*
ਨਹੀਂ	ਨਰੀ	(24)25	17
correct	correet	(24)29	Last but one
Gurdaspuri	Gusdaspuri	(24)31	7
Training	Trainjng	(24)31	5 from below
repetition	repitition	(24)34	Last
उपाध्यक्षा	उपाध्क्षा	(24)52 (24)61	6 1
withdraw	withdr w	(24)52	16
circ..lation	crculation	(24)52	Last but one
ਮੰਤਰੀ	ਮਤਰੀ	(24)58	1
ਸਬੰਧ	ਸਥੰਧ	(24)58	18
AMEND-MENT	AMENMENT	(24)59	Heading
decision	decesion	(24)61	11
ਪੰਜਾਬ	ਪਜਾਬ	(24)63	21
ਸਮੇਂ	ਸਮੈਂ	(24)63	3 from below
ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼	ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜਸ਼	(24)64	1
occasion	occassion	(24)65	4 from below
ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ	ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿਘ	(24)69	17
ਐਕਸਚੇਂਜ	ਅਕਸਚੇਂਜ	(24)75	6
ਹੂੰ	ਹੁੰ	(24)75	17
की	कि	(24)75	4 from below
ਸ਼੍ਰੀ	ਸ੍ਰੀ	(24)84	1, 20

PUNJAB VIDHAN SABHA

Monday, the 22nd November, 1965

The Sabha met in the Vidhan Bhawan, Sector 1, Chandigarh at 2.00 p.m. of the Clock. Deputy Speaker (Shrimati Shanno Devi) in the Chair.

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼; On a point of order, Madam, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ ਉਸ ਦਿਨ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜੋ ਗਲਤ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਟੇਬਲ ਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ?

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਮਨਿਸਟਰ ਇਨਚਾਰਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ । (The Minister Incharge is not present in the House now; so it will be done tomorrow.)

RIOTS BETWEEN STUDENTS AND TRANSPORT WORKERS AT JULLUNDUR

***8517. Comrade Ram Chandra ;** Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

(a) the circumstances in which riots between the Students and Transport Workers took place at Jullundur in July/August, 1965;

(b) the total number with names and designations of persons injured during the said riots;

(c) the action taken by the Government to control the said riots?

Sardar Gurmit Singh (Deputy Minister, Development, Irrigation & Power) (a) A Judicial Enquiry has been set up by Government to inquire into the causes which led to the clash between the students and Punjab Roadways Employees. The matter being sub-judice, the facts about the clash cannot be furnished.

(b) Nine persons received injuries during the clashes between the students and Punjab Roadways Employees. Their names and designations are given below:—

(i) Shri Chanchal Dass, Director, Mehr Chand Technical Institute, Jullundur.

(ii) Shri Jagdish Mitter, student, Khalsa College, Jullundur.

(iii) Shri Baldev Singh, student, Ayurvedic College, Jullundur.

(iv) Shri Surrinder Kumar, student, Mehr Chand Poly. Tech., Jullundur.

(v) Shri Ved Parkash, student, Khalsa College, Jullundur.

(vi) Shri Chaman Lal, Contractor, D. A. V. College Cycle Stand, Jullundur.

[Deputy Minister for Development, Irrigation & Power]

(vii) Shri Dhani Ram, s/o Ditu Ram, Chowkidar, D.A.V. College, Jullundur.

(viii) Shri Swarn Singh, Driver, Punjab Roadways, Jullundur.

(ix) Shri Puran Chand, s/o Hardass r/o Sial, PS Una. Now Rly. Station Nakodar.

(c) Government took extensive precautionary measures to control the situation. All the strategic points including Punjab Roadways installations and educational institutions were adequately guarded by armed police and buses of the Punjab Roadways were given armed escorts. Systematic and constant patrolling was carried. All the Deputy Commissioners and Superintendents of Police were alerted for keeping strict watch on the situation and take precautions to avoid chances of such incidents and check move if any, of Punjab Roadways Employees and Students to Jullundur and also take into confidence Principals of the Colleges.

कामरेड राम चन्द्र : क्या मैं जान सकता हूं कि स्टूडेंट्स और पंजाब रोडवेज़ के वर्कर्ज़ के दरमियान पहले किस वक्त क्लैशिज़ हुए और गवर्नमेंट ने उन को रोकने के लिए किस वक्त प्रीकाशनरी मेयर्ज़ एडाप्ट किए ?

उप मंत्री : जिस वक्त यह बात नोटिस में आई थी उसी वक्त प्रीकाशनरी मेयर्ज़ लिए गए ।

श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री : क्या मैं जान सकता हूं कि जब इन्क्वायरी अफसर अपनी इंकवायरी कंप्लीट करके रिपोर्ट सरकार को भेज चुका है और कोई एवीडेंस लेना बाकी नहीं रहा तो फिर यह मामला सबजुडिस कैसे है ?

उपमंत्री : पंजाब गवर्नमैंट ने श्री बनवारी लाल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशनज़ जज को अगस्त, 1965 को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर किया था । उस इंक्वायरी में 96 गवाहियाँ मुख्तलिफ पार्टियों की हो चुकी हैं और एडजर्नमेंट के बाद बाकी कार्यवाही अभी होने वाली है ।

डाक्टर बलदेव प्रकाश : क्या उपमंत्री साहिब बताएंगे कि जब गवर्नमेंट ने प्रीकाशनरी मेयर्ज़ लिए उस से पहले स्टूडेंट्स और रोडवेज़ के एम्प्लाइज़ के दरमियान दूसरा मेजर क्लैश हो चुका था ?

उपमंत्री : जब सरसरी तौर पर रिपोर्ट नोटिस में आई थी तो उस के मुताबिक इन्तज़ाम किया था । लेकिन उस के बाद जब लोकल बस 4-15 की बजाए 4-45 पर गई तो उस के बाद झगड़ा बहुत बढ़ गया था ।

श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री : क्या उपमंत्री साहिब बताएंगे कि झगड़े की वजह यह थी कि स्टूडेंट्स को लेजाने के लिए ट्रांस्पोर्ट का इन्तज़ाम नाकाफी था ?

उपमंत्री : मामला क्योंकि सब जुडिस है इस लिए मैं इस बात में नहीं जाना चाहता ।

श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री : क्या मैं दरियाफत कर सकता हूं कि स्टूडेंट्स और रोडवेज़ के वर्कर्ज़ के इलावा जो लोग ज़ख्मी हुए हैं उन को मुआवज़ा देने के लिए सरकार कुछ विचार कर रही है ?

उपमंत्री : रिपोर्ट आने के बाद गवर्नमेंट इस पर फैसला करेगी ।

कामरेड राम प्यारा : क्या डिप्टी मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि जो रिपोर्ट सैशन्ज़ जज की आ रही है उस के ऊपर सरकार खुद फैसला करेगी या उस रिपोर्ट को कोर्ट के पास भेज दिय जाएगा जिस ने कि फैसला करना है ?

उपमंत्री : गवर्नमैंट ने खुद इंक्वायरी कमिशन बैठाया है इस लिए सरकार खुद फैसला करेगी ।

CIVIL DEFENCE MEASURES

***8702. Comrade Shamsher Singh Josh** : Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

(a) the details of the Civil Defence Measures taken all over the State to meet any further aggression on your territory;

(b) whether there is any proposal under the consideration of Government to set up a Civil Defence Training Institute in the State, if so, when and the name of the place where it is likely to be set up?

Sardar Gurmit Singh (Deputy Minister, Development, Irrigation & Power) (a) All possible Civil Defence Measures as approved by the Government of India have been taken in the State and the same will be strengthened as would be advised by the Government of India from time to time. (Details cannot be furnished for security reasons).

(b) Yes. Details are being collected from the Central Emergency Relief Training Institute, Nagpur, on the lines of which the Civil Defence Training Institute is to be set up in the State.

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼: ਇਹ ਜੋ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਟਰੇਨਿੰਗ ਇਨਸਟੀਚਿਊਟ ਖੋਲਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਉਸ ਵਿਚ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੀ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?

ਉਪ ਮੰਤਰੀ: ਇਸ ਸਿਲਸਲੇ ਵਿਚ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

डाक्टर बलदेव प्रकाश : उन्हों ने कहा है कि सिवल डिफेंस के सभी मेयर्ज़ ले लिए हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने उसी तरह से मेयर्ज़ लिये हैं जिस तरह चीन के हमले के वक्त सब कुछ कागज़ी कार्यवाही ही की थी या अब प्रेकटीकल भी कुछ किया गया है ?

उप मन्त्री : आपके दिमाग में जो 1962 वाला वहम है वह मेरा ख्याल है इस लड़ाई के बाद दूर हो जाना चाहिए था ।

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ: ਕੀ ਪੰਜੂਆ ਡਿਪਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਬ (ਹਾਸਾ) ਇਹ ਦਸਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਬੰਧ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕਸਬਿਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੁਛ ਸੱਟਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਹਨ ?

ਉਪ ਮੰਤਰੀ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਚਾਚਾ ਚਾਉ ਵਾਲਾ ਹਮਲਾ ਭੁਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ । ਹੁਣ ਚਾਉ ਨੂੰ ਚਨੇ ਚਬਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ ।

डाक्टर बलदेव प्रकाश : डिप्टी सपीकर साहिबा, यह सवाल बड़ा अहम है इसका इवेसिव आनसर नहीं आना चाहिए । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या प्रेकटीकली भी कुछ किया गया है और किसी शहर गांव में किसी सिवल डिफैंस की ट्रेनिंग भी दी गई है या नहीं ?

ਉਪਮੰਤਰੀ : ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਿੰਗ, ਫਰਸਟ ਏਡ ਵਗੈਰਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਪਹਲੂਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਟਰੇਨਿੰਗ ਇਨਸਟੀਚੂਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਸਟਾਫ, ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੀ ਕਦਮ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਦੀਆਂ ਡਿਟੇਲਜ਼ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੀਜ਼ਨਜ ਕਰਕੇ ਦਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ । ਇਸ ਦੀ ਆਪ ਤੋਂ ਖਿਮਾਂ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ।

डाक्टर बलदेब प्रकाश : मैं अमृतसर में ही रहता हूं और मुझे पता है कि क्या मेयर्ज़ आपने लिए हैं । इस लिए ही मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या यह ठीक है कि पाकिस्तान का जो हमला हुआ है उसके बाद पंजाब में एक भी आदमी को सिवल डिफैंस की ट्रेनिंग नहीं दी गई है ?

उप मन्त्री : यह गलत है जो आप कह रहे हैं । फाइर फाइटिंग, फर्सट-एड और दूसरे मेयर्ज़ की रीहर्सल हो रही है और यह बाकायदा सारे जिलों में हो रही है ।

उपाध्यक्षा : जो बात ठीक न हो उसे इस तरह गोल मोल करके पुट नहीं करना चाहिए । मुझे जगाधरी का पता है, वहां कुछ भी नहीं हो रहा है । आप सीधे कहें कि करेंगे और करना चाहिए । (Any thing which is not connect, should not be put in a round-about way. I know about Jagadhari and nothing is being done there in this correction. He should straight away say that measures would be taken as we should take them.)

उप मन्त्री : मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि मैं भी आखिर सारे ज़िले और तहसीलों में जाता हूं और मुझे सब पता है । जो मेयर्ज़ जंग के दिनों में चलते रहे हैं वह चल रहें हैं । किसी एक आध जगह न होता हो तो पता कर लेंगे ।

डाक्टर बलदेव प्रकाश : श्रान ए प्वांट श्राफ श्रार्डर । इन्हों ने कहा है कि सब ज़िलों में रीहर्सल हो रही है। मैं कहता हूं कि यह बात गलत है, श्राप वैरीफाई कर लें श्रौर अगर पाकिस्तान के हमला के बाद एक भी रीहर्सल अमृतसर या फिरोज़पुर ज़िले में हुई हो तो मैं ज़िम्मेदार हूं।

उपमन्त्री : सिवल डिफैंस मेयर्ज़ कोई एक श्राइटम नहीं, कोई 20/30 श्राइटमज़ हैं । ऐन. सी. सी. के 3 हज़ार कैडिट्स को सिवल डिफैंस ट्रेनिंग दी जा रही है, किसी जगह फर्सट एड श्रौर किसी जगह फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है । इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले भी कुछ अपने इन्तज़ाम कर रहे हैं । यह बहुत डिटेल की बातें हैं जिन में मैं जाना नहीं चाहता । पूरी कोशिश की जा रही है । अगर किसी जगह काम में ढील है तो नोटिस में लाएं, उसे ठीक किया जाएगा ।

ਕਾਮਰੇਡ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ : ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕੋਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ?

ਉਪ ਮੰਤਰੀ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਜ ਨੋਟਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ।

ਕਾਮਰੇਡ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ : ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਹਨ ?

ਉਪਮੰਤਰੀ : ਇਸ ਲਈ ਅਲਹਿਦਾ ਨੋਟਸ ਭੇਜੋ ।

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਸਿਲਸਲੇ ਵਿਚ ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਕਤ ਕੁਛ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੱਜਨ ਵੀ ਪਕੜੇ ਗਏ ਹਨ ?

(No reply)

ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ: ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਬ ਦੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਲਮ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਲੇਰ ਕੋਟਲਾ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿਪਾਹੀ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਇਕ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਉਥੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜੋ ਆਦਮੀ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਉਸੇ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਸੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਡੀ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਕੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ?

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । (This question does not arise.)

पंडित श्रोमं प्रकाश अग्निहोत्री : इन्हों ने बताया है कि इन्सटीचयूट कायम करने के लिए सैंट्रल गवर्नमैंट से बात चीत हो रही है । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस बारे में कोई रीप्रेज़ैंटेशन वहां भेजी है श्रौर अगर भेजी है तो कब ?

उप मन्त्री : उनसे डिसकशन होती रहती है और उनकी गाइडैंस लेकर पंजाब इन्सटीचयूट कायम किया जा रहा है और सारी डिटेल्ज़ तै की जा रही हैं ।

LAND ACQUIRED ON THE BANK OF SUTLEJ FROM RUPAR TO FEROZEPUR FOR FARMING AND SHEEP-REARING PURPOSES

***8461. Comrade Ram Chandra** : Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

(a) whether Government have recently requisitioned/acquired large area of land on the Sutlej Bank from Rupar to Ferozepur for purposes of setting up farms and sheep rearing centres, etc., if so. the exact total area of such land together with the dates on which it was acquired/requisitioned;

(b) the amount, if any so far paid to the landowners concerned of the lands referred to in part (a) above;

(c) the steps taken to develop the proposed farms etc. the total amount so far spent for the purpose and the results achieved so far?

Sardar Gurmit Singh (Deputy Minister, Development, Irrigation & Power) (a) No.

(b) The question does not arise.

(c) The question does not arise.

APPOINTMENT OF DEPUTY COMMISSIONERS (AGRICULTURE) IN THE STATE

***8686. Comrade Shamsher Singh Josh**: Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under the consideration of the Government to appoint Additional Deputy Commissioners (Agriculture) in the districts in the State to assist the Deputy Commissioners in the matters relating to Agricultural Production?

Sardar Gurmit Singh (Deputy Minister, Development, Irrigation & Power) : No.

Dr. Baldev Parkash: Madam, the questlon is—

"Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under the consideration of the Government to appoint Additional Deputy Commissioners (Agriculture) in the districts in the State to assist the Deputy Commissioners in the matters relating to agricultural production."

इस का जवाब "नौ" आया है । मैं उपमंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि एडीशनल डिप्टी कमिश्नरों को क्या डियूटीज़ अलाट की गई हैं ?

उपमन्त्री : एमरजैंसी के हालात को देखने के लिए और साथ में सरकार के दूसरे फैसलों को इम्पलीमैंट करने के लिए एडीशनल डिप्टी कमिशनर लगाए गए हैं । वैसे तो एग्रीकल्चर का काम डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर आफिसर्ज़ करते हैं । डिप्टी कमिशनर तो कोआर्डीनेशन की मीटिंग काल करते हैं । अगर कहीं वह मीटिंग डिप्टी कमिशनर काल न कर सके या प्रीज़ाइड न कर सके तो यह उस मीटिंग को प्रीज़ाइड करते हैं ।

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਲਸਲੇ ਵਿਚ Additional Deputy Commissioners appoint ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮਿਸਟਰ ਏ. ਐਲ. ਫਲੈਚਰ, ਫਿਨਾਂਸ਼ਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ?

ਉਪ ਮੰਤਰੀ : ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ । ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਟੇਕ ਅਪ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ । ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ Administrative Reforms Commission ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ।

RESOLUTION PASSED BY KANGRA ZILA PARISHAD CONSULTATIVE AND PLANNING COMMITTEE

***8422. Comrade Ram Chandra:** Will the Minister for Planning and Local Government be pleased to state—

(a) whether the Chief Minister received a copy of the resolution passed by the Kangra Zila Parishad Consultative and Planning Committee in its meeting held on 7th June, 1965, demanding that funds equal to those allotted by the Union Government in the 4th Five Year Plan for Himachal Pradesh be provided in the 4th Five Year Plan of the Punjab Government for the Kangra District etc. etc. if so, a copy of the said resolution be laid on the Table of the House;

(b) whether the Government has considered the said resolution, if so, with what results?

Sardar Gurmit Singh (Deputy Minister Development, Irrigation & Power) (a) The resolution stated to have been passed by the Kangra Zila Parishad Consultative and Planning Committee in its meeting held on 7th June, 1965 has not been received.

(b) The question of the consideration of this resolution does not arise.

However, 4 M. P.s of the Punjab Hill Areas and 9 M. L. A.s of Kangra, Kulu and Simla Districts raised a similar point, as in this resolution, in their representation dated 15th April, 1965, addressed to the Governor of Punjab. This representation was examined in detail. The Punjab Government have done their best in giving weightage to the Punjab Hill Areas. In their own Third Five Year Plan, the Punjab Government have allotted a sum of Rs 22.59 crores out of the "breakable"

[Deputy Minister for Development, Irrigation & Power]

portion of the State Plan amounting to Rs 1.14 crores. This gave Hill Areas a share of 20 % as against 12½ % share on the basis of their population. This allocation more or less works out to per capita investment of Rs 130/- in Punjab Hill Areas and Rs 70/- in sub-montainous areas as against the average per capita investment of Rs 60/- in the State as a whole. As regards the 4th Five Year Plan the State Government have since decided to earmark a sum of Rs 60 crores out of the "breakable" portion of the tentative State Plan of Rs 500 crores. The question of providing funds for the Hill Areas over and above Rs. 60 crores was taken up in the 4th Five Year Plan discussions of the Punjab Government with the Planning Commission held at New Delhi on 13th-14th July, 1965. It was specifically brought to the notice of the Commission that very large allocations for the Centrally administered Himachal Pradesh were creating difficulties for the Punjab Government in as much as the Punjab Hill Areas were also clamouring for similarited allocations. However, the Commission expressed their inability in making additional allocations for the Punjab Hill Areas.

कामरेड राम चन्द्र : उपमंत्री महोदय ने जवाब देते हुए फरमाया है कि पहाड़ी इलाके की तरक्की के लिए साढ़े बाइस करोड़ रुपया रखा गया है। क्या वज़ीर साहिब फरमाएंगे कि इस में इंडस्ट्रीज़ स्थापित करने के लिए कितना रुपया रखा गया है और कौन सी स्कीमें बनाई गई हैं ?

उपमंत्री : यह रुपया सारे पहाड़ी इलाके की तरक्की के लिए रखा गया है। इस के लिए कई मुख्तलफ किस्म की स्कीमें तैयार की जा रही हैं। अगर माननीय सदस्य इस के बारे में डिटेल्ज़ में जानकारी लेना चाहते हैं तो वह किसी वक्त भी आ कर सारी इंफार्मेशन ले सकते हैं।

ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ : ਕੀ ਡਿਪਟੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ 22½ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸੀਮਿੰਟ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੁਪਿਆ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਰੁਪਿਆ ਅਲਾਟ ਕਰੇਗੀ ?

ਉਪ ਮੰਤਰੀ : ਵੈਸੇ ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਅਗਜ਼ਾਮਿਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲਜ਼ ਵਿਚ ਇਨਫ਼ਾਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ 60 ਰੁਪਏ, ਸਬ ਮਾਊਂਟੇਨੀਅਸ ਇਲਾਕੇ ਲਈ 70 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਿਲੀ ਇਲਾਕੇ ਲਈ 130 ਰੁਪਏ ਫੀ ਆਦਮੀ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

कामरेड राम चन्द्र : वैसे तो मेरे सवाल का जवाब नहीं आया है। वज़ीर साहिब की तरफ से पहाड़ी इलाके की तरक्की के लिए साढ़े 22 करोड़ रुपए खर्च करने का दावा किया जा रहा है। मैं उपमंत्री से पूछना चाहता हूं कि इस में से कितने रुपए पहाड़ी इलाके में इंडस्ट्रीज़ लगाने के लिए खर्च किए जा रहे हैं। क्या यह केवल फिगर्ज़ ही हैं या हिल्ली एरीया में खर्च भी किया गया या नहीं ?

उप मंत्री : इस के लिए माननीय सदस्य सैपेरेट नोटिस दें। सारी मुनासिब डिटेल्ज़ माननीय सदस्य को दे दी जाएगी या हाउस की मेज़ पर रख दी जाएगी ।

ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ: ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22½ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਕਿੰਨਾ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ?

ਉਪ ਮੰਤਰੀ: ਇਹ ਸਵਾਲ 4th Five Year Plan ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਨ ਸਵਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਵੈਰ ਰਖਣਾ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ।

कामरेड राम चंद्र : मैं तो द्वितीय तथा तृतीय पंच-वर्षीय योजना के बारे में पूछ रहा हूं। क्या उपमंत्री साहिब बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने द्वितीय तथा तृतीय पंच-वर्षीय योजना के अन्दर पहाड़ी इलाके में इंडस्ट्रीज़ के लिए कितना रुपया अलाट किया और रुपया अलाट करने के बाद क्या कोई रुपया खर्च हुआ भी या नहीं ? इस पर सरकार क्या अमल कर रही है ?

उपमंत्री : इस के लिए माननीय सदस्य सेपरेट नोटिस दें। जवाब दे दिया जाएगा ।

ਕਾਮਰੇਡ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰਥ ਫਾਈਵ ਈਅਰ ਪਲੈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸੀਮਿੰਟ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਡਿਪਟੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਲਈ 22½ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਐਕਸਟਰਾ ਰੁਪਿਆ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ?

ਉਪ ਮੰਤਰੀ : ਇਹ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

LAND RECLAIMED UNDER SUTLEJ CANALIZATION SCHEME

***8700. Comrade Shamsher Singh Josh:** Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

(a) the total acreage of land reclaimed under the Sutlej Canalization Scheme, district-wise;

(b) whether any decision has recently been taken by the Government to return the said land to the previous owners, if so, on what terms;

(c) the total area of such land in acres, still likely to be left with the Government for allotment, district-wise, together with the details of the scheme of allotment of such land, if any, formulated by the Government ?

Chaudhri Rizak Ram : (a) 2,000 acres of land have been reclaimed under the Sutlej Bed Reclamation Scheme. The district-wise break-up is given hereunder:—

(i) Ambala District.......... . 1,400 acres
(ii) Jullundur District.... ...... 100 acres
(iii) Ludhiana District . ... 500 acres

(b) Land of private owners will not be acquired with the exception of the area leased out to M/s Birla Brothers. No terms have been imposed.

(c) The entire evacuee land will remain with Government. Proposals for its utilization are under consideration.

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ

"Land of private owners will not be acquired with the exception of the area leased out to Messrs. Birla Brothers."

ਲੇਕਿਨ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਰਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਓਨਰਜ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰ ਕੇ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬਿਰਲੇ ਕੋਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲੇ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ?

मन्त्री : यह जवाब पहले का तैयार किया हुआ है। यह मामला कृषि विभाग से सम्बन्ध रखता है। अगर माननीय गृह तथा डिवेल्पमैंट मिनिस्टर ने इस में चेंजिज़ मान ली हैं तो वह ठीक है। यहाँ तक रीकलेमेशन के बारे में पोज़ीशन है, मैं ने उस की पोज़ीशन इस जवाब में क्लीयर कर दी है।

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : On a point of order. ਹੁਣੇ ਕਾਮਰੇਡ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਵਕਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਵਾਬ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਲਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਵਕਤ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਚੈਕ ਕਰ ਲਏ ਕਿ ਲੇਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ?

उपाध्यक्षा : जब सारे मैम्बर ऐकुरेट हो जाएंगे तो यह भी हो जाएगा (हंसी)
(When all the Members become accurate, the Ministers will become so automatically) (Laughter)

डाकटर बलदेव प्रकाश : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडम। मैं यह जानना चाहता हूं कि हाउस में जो जवाब दिये जाते हैं क्या इन में लेटैस्ट पोज़ीशन बताई जाती है या कि पहली पोज़ीशन बताई जाती है? मन्त्री महोदय ने एक सवाल के जवाब में यह कहा है कि पहला फैसला यह था, अब अगर कोई और फैसला हो गया है तो मुझे पता नहीं है। इस का मतलब हम क्या यह समझें कि जब जवाब तैयार किया गया था उस के बाद की पोज़ीशन यहां पर नहीं बताई जा सकती ?

उपाध्यक्षा : मुनासिब तो यही है कि लेटैस्ट पोज़ीशन ही हाउस में बताई जाए । अगर बाद में कोई फैसला हो जाता है तो हाउस में तो लेटैस्ट पोज़ीशन ही बताई जानी चाहिये । (It is only proper that the House be apprised of the latest position about a matter. If later on some different decision is taken by Government, the House should know the latest position.)

मन्त्री : मैं ने जो जवाब दिया है वह रीकार्ड की बेसिज़ पर दिया है। अगर उन्हों ने कोई बात दो तीन दिन पहले कही है तो वह अभी तक रीकार्ड पर नहीं आई ।

उपाध्यक्षा : चौधरी साहिब, यह जयंट रिसपांसिबिलिटी है । अगर सरदार दरबारा सिंह ने कुछ कहा था तो वह आप के इल्म में होना चाहिये था और जवाब उसी की बेसिज़ पर दिया जाना चाहिये था। (*Addressing the Irrigation and Power Minister*) (The hon. Minister must be aware, that this is the joint responsibility of the Ministers. If Sardar Darbara Singh had said something on the matter, this should have come to your knowledge and the reply should have been prepared on the basis of that statement.)

मन्त्री : रीकार्ड में कोई फैसला नहीं है । जो जवाब दिया गया है वह रीकार्ड के मुताबिक दिया गया है ।

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਰੀਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਦ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਂਡ ਲੈਸ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਏਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਮੁਕਰ ਗਈ ਹੈ ?

कामरेड राम प्यारा : इरीगेशन मिनिस्टर ने बताया है कि गवर्नमैंट के रीकार्ड पर फैसला यह है । डाक्टर बलदेव प्रकाश ने यह कहा है कि आनरेबल होम मिनिस्टर ने कुछ और कहा था । मैं आप की रूलिंग चाहता हूं कि आन दी बेसिज़ आफ दी रीकार्ड कुएस्चन का रिपलाई कुछ और है और कोई मिनिस्टर अपनी स्पीच मे हाउस में कुछ और व्यू देता है तो हमें कौनसा व्यू एक्सेप्ट करना चाहियें ?

उपाध्यक्षा : कामरेड राम प्यारा, आप तो बड़े विजिलेंट मेम्बर हैं । मैं पहले कह चकी हूं कि हाउस में लेटैस्ट पोज़ीशन आनी चाहिये । उस के बाद आप के कुछ कहने की जरुरत नहीं रह जाती । (The hon. Member Comrade Ram Piara is a very Vigilanr Member. It should know that I have already stated that the House should be apprised of the latest position in the matter. After that there appears to be no need for the Member to say any thing more on the subject.)

कामरेड राम प्यारा : मेरी सबमिशन यह है कि कुएस्चन के जवाब में तो कुछ और कहा जाता है मगर कोई और मिनिस्टर तकरीर में कुछ और कहता है..

उपाध्यक्षा : आप फिर उसी बात को रिपीट कर रहे हैं (The hon. Member is repeating the same thing again.)

कामरेड राम प्यारा : मैं तो यह पूछता हूं कि जवाब में कुछ और कहा जाता है और तकरीर में दूसरा मिनिस्टर कुछ और कहता है। दोनों बातें डिफ्रैंट हैं, तो कौन सी ठीक माननी चाहिये ?

उपाध्यक्षा : ट्राई टू लिस्न टू मी। मैं ने पहले ही कहा है कि ज्वायंट ज़िम्मेदारी है। अगर बाद में पोज़ीशन बदल गई है तो उन के इल्म में होनी चाहिये। The hon. Member should try to listen to me. I have already said that the Ministers have a Joint responsibility and that any subsequent change in the position of a matter should be in their knowledge.)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ : ਕੀ ਇਹ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਡੇਫ਼ਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੇਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਮਾਲੂਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ?

Minister : In the meeting held on the Ist September, 1965, the Council of Ministers decided that there will be no whole-sale acquisition of private lands, and that the notification already issued in this connection be withdrawn except in respect of the land on lease with Messrs Birla Brothers. This is the latest position on record. Madam, it is in accordance with that decision, that the information has been given.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ : ਲਾਸਟ ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਉਸ ਵਿਚ ਬਿਰਲਾਜ਼ ਡੀਲ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਨਰੇਬਲ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਐਸ਼ੋਰੰਸ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਰਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇਗੀ ਅਗਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਜ਼ ਹਨ, ਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਸਲਟ ਕਰ ਲੈਣ। ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀਜ਼ ਪੋਸਟ ਪੋਨ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ। ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਲ ਦੇ ਦੇਣ। (He may answer this question tomorrow.)

मन्त्री : मुझे पता नहीं है कि होम मिनिस्टर साहिब से कोई डिफ्रैंट बात कही गई होगी। उन से पूछ लेना।

Deputy Speaker : Supplementaries on this question will be put tomorrow.

PROJECT ALLOWANCE FOR EMPLOYEES OF BHAKRA DAM ADMINISTRATION

***8814. Shri Surrinder Nath Gautam** : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state —

(a) whether all the employees of the Bhakra Dam Administration stationed at Nangal are getting Project Allowance and free half rent concession, if not, the percentage of employees who have been denied these concessions and the reasons therefor;

(b) whether the concessions mentioned in part (a) above have been granted because of difficult living conditions in the locality and have no link with the Project;

(c) if the reply to part (b) above be in the affirmative, whether the Government is considering any proposal to extend the said concessions to the remaining employees of the Bhakhra Dam Administration, if not the reasons therefor ?

Chaudhri Rizaq Ram : (1) 1. No. All workmen, working on the Bhakhra Project, are either provided with rent free accomodation or house rent allowance in lieu thereof. They are not paid Project Allowance.

(2) The regular staff engaged on the construction of the right power house is allowed project allowance at five percent of pay and house rent concession at half the rate.

(3) Regular staff working on the maintenance and operation purely are not allowed any house rent concession or Project Allowance. Their parcentage is 21%

(b) No.

(c) Does not arise.

श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री : वज़ीर साहिब ने बताया है कि कुछ स्टाफ को पांच परसैंट रेंट दिया जाता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो रैगुलर स्टाफ मैन्टेनैंस पर और ओप्रेशन में काम करता है उस को क्यों नहीं दिया जाता ?

मन्त्री : जो स्टाफ प्रोजैक्ट पर काम करता है उन को कनसैशन के तौर पर कुछ रैंट दिया जाता है। जो स्टाफ प्रोजैक्ट पर काम नहीं करता उस को नहीं दिया जाता।

श्री सुरेन्द्र नाथ गौतम : मिनिस्टर साहिब ने फरमाया है कि रैगुलर स्टाफ जो मैंन्टेनेन्स में और ओप्रेशन में काम करता है और जिस की तादाद 21 परसेंट है उन को कोई अलाउंस नहीं दिया जाता। बाकी एम्पलाईज़ जो कि भाखड़ा और नंगल में काम करते हैं उन को 5 परसेंट प्रोजैक्ट अलाउंस दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि 21 परसेंट स्टाफ को क्यों इगनोर किया हुआ है, उन को क्यों अलाउंस नही मिलता ?

मन्त्री : भाखड़ा प्रोजैक्ट में जो रैगुलर स्टाफ पावर हाउस में काम करता है, नंगल डैम डीवीज़न में काम करता है, भाखड़ा रैज़रवायर डीवीजन में काम करता है, जिन का प्रोजैक्ट से सम्बन्ध है उन को दिया जाता है । जिस स्टाफ का प्रोजैक्ट से सम्बन्ध नहीं है उस को नहीं दिया जा रहा ।

श्री सुरेन्द्र नाथ गौतम : मन्त्री महोदय ने पार्ट 'बी' के जवाब में 'नो' कहा है। मैं दरियाफत करना चाहता हूं कि इतनी मंहगाई हो गई है और तहसील ऊना वैसे भी सरकार ने बैकवर्ड करार दी है इस लिये जो स्टाफ वहां पर स्टेशन्ड है उन को हिल्ली अलाउंस देने के लिये सरकार कोई गौर कर रही है ?

मन्त्री : नहीं कर रही ।

श्री सुरेन्द्र नाथ गौतम : क्या मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि जब तहसील ऊना को बैक्वर्ड हिल्ली एरीया करार दिया गया है तो अब तक वहां पर काम करने वाले तमाम मुलाजमों को क्यों हिल कम्पैन्सेटरी एलाऊंस से महरुम रखा हुआ है ?

मन्त्री : यहां पर उसकी जरुरत महसूस नहीं की गई । वैसे वहां पर जो एलाऊंस दिए गए हैं वह हिल कम्पैन्सेटरी अलाऊंस के तौर पर नहीं दिए गए। वहां पर दिया गया प्राजैक्ट एलाऊंस या प्राजैक्ट पर काम करने वालों को रैंट वगैरा की कन्सैशन दी गई थी और उस के अलावा कोई और एलाऊंस नहीं दिया गया । इसके अलावा जो प्राजैक्ट पर काम करेंगे उन को ही दिया है औरों को नहीं । इस तरह से या तो प्राजैक्ट एलाऊंस दिया गया है, या फ्री एकामोडेशन दी गई है या रैंट एलाऊंस दिया गया है ।

These are the concessions given to those workers who are actually working on the Project. Nobody, though living or working at Nangal or Bhakra, but not doing Project work, is entitled to any of these concessions.

श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जब पांग डैम और बयास डैम के वर्कर्ज़ को दोनों एलाऊंस दिए गए हैं यानि प्राजैक्ट एलाऊंस और रैंट एलाऊंस तो फिर नंगल वालों के साथ यह डिसक्रिमिनेशन क्यों की गई है ?

मन्त्री : वह तो आप सेपरेट सवाल करें तो बता दिया जाएगा । वह इस सवाल से पैदा नहीं होता । इसकी बाबत स्पैसिफ़िक तौर पर पूछेंगें तो बता दिया जाएगा ।

श्री सुरेन्द्र नाथ गौतम : जैसा कि मिनिस्टर साहिब ने फरमाया है कि जो प्राजैक्ट पर काम कर रहे हैं उन को प्राजैक्ट एलाऊंस और रैंट फ्री एकामोडेशन दी जा रही है; क्या मैं उन से पूछ सकता हूं कि तहसील ऊना में काम करने वाले जो ऐम्पलाईज़ इन दोनों कन्सेशन से महरूम हैं क्या सरकार उन को हिल कम्पेन्सेटरी एलाऊंस देने को तैयार है या नहीं ?

मन्त्री : नहीं । इस सम्बन्ध में ऐसा कोई फैसला नहीं है और उन का केस डिज़र्विंग नहीं समझा गया ।

UNSTARRED QUESTION AND ANSWER

APPEALS PREFERRED BY CONDUCTORS/DRIVERS OF PUNJAB ROADWAYS.

3055. Sardar Gurmej Singh Gumanpura : Will the Transport and Elections Minister be pleased to state —

a) the total number of appeals preferred by the conductors/drivers and members of the workshop staff and received by the Provincial Transport Controller and the Government orders passed by against the punishment the General Managers of the Punjab Roadways during the period from 1st January, 1962 to 30th September, 1965;

(b) the names of the persons with their addresses who preferred the said appeals;

(c) whether Government have taken any decision on the said appeals, if so, when and the decision taken in each case;

(d) the total number of appeals out of those mentioned above which have been accepted by the Government and the names of persons whose appeals have been accepted;

(e) whether the persons referred to in part (d) above were informed of the Government's decisions accepting their appeals, if so, when in each case;

(f) whether any delays have occurred in conveying the decisions of the Government to the officials concerned; if so, the reasons therefor and the action, if any, taken by Government in such cases;

(g) if the reply to part (a) above be in the affirmative whether the said appellats were paid their arrears etc., if so, when, if not, the time by which these are likely to be paid ?

Sardar Gurdial Singh Dhillon : (a) 453 out of which 291 have been disposed of.

(b) to (g) The time and labour involved in collecting the information will not be commensurate with any possible benefit to be obtained. Information will, however, be furnished in any specific case, if sought.

ADJOURNMENT MOTIONS

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਮੈਡਮ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਹਾਉਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 25,00,000 ਰੁਪਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੰਡੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਵਾਇਦਾ ਅਜੇ ਤਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ.... (ਵਿਘਨ)

Deputy Speaker · Comrade Gurbakhsh Singh, order please.

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : ਇਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਪੰਜ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਜ਼ ਨੇ, ਛੇਹਰਟਾ ਮਿਉਂਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਮੇਤ ਭੁਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। (ਵਿਘਨ) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਾਇਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 30,00,000 ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

उपाध्यक्षा : कामरेड गुरबख्श सिंह, क्या मैंने आप को स्पीच करने की इजाज़त दी थी ? यह बहुत नामुनासिब बात है कि आप प्वायंट आफ आर्डर पर खड़े होते हैं और इस तरह से जो मन में आए कह जाते हैं। मैं इस चीज़ को बिल्कुल पसन्द नहीं करती। प्वायंट आफ आर्डर पर खड़े होने का मतलब यह नहीं कि आप स्पीच करनी शुरू कर दें। कामरेड जोगा जी, आप इन को समझाइए कि प्वायंट आफ आर्डर का क्या मतलब होता है। (Comrade Gurbakhsh Singh, did I permit you to make a speech ? It is most undesirable that the hon. Member rises on a point of order and go on speaking on whatever point they want. I do not like this procedure at all. To rise on a point of order does not entitle one to make a speech. I would request Comrade Joga to make him understand the meaning of a point of order.)

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵ-ਪੂਰਣ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडम ......

उपाध्यक्षा : मैं खड़ी हूं। आप भी खड़े हो कर प्वायंट आफ आर्डर करने लग पड़े हैं। क्या आप जैसे सयाने मेम्बरों को भी यह बताना पड़ेगा कि जब मैं खड़ी हूं तो आप को ऐसा नहीं करना चाहिए। (I am on my legs. The hon. Member has also risen on a point of order. Does an experienced Member like him also needs to be told that he should not stand up when I am on my legs.)

श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं प्वायंट आफ आर्डर पर खड़ा हूं।

उपाध्यक्षा : क्या है आप का प्वायंट आफ आर्डर ? (What is his point of order ?)

श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री : मेरा प्वायंट आफ आर्डर यह है कि कामरेड गुरबख्श सिंह ने जो एडजर्नमेंट मोशन दी थी वह अमृतसर के मज़दूरों के सम्बन्ध में थी। जैसा कि गवर्नमैंट की तरफ से वादे किए गए थे, आज तक उन को एक पैसा भी लोन की शक्ल में नहीं दिया गया।

उपाध्यक्षा : क्या यह भी कोई प्वायंट आफ आर्डर है ? (Is this a point of Order ?

श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री : मैं प्वायंट आफ आर्डर पर आ रहा हूं। मैं आप की इस मामले पर रूलिंग चाहता हूं कि चीफ मिनिस्टर साहिब ने यहां पर हाउस के अन्दर यकीन दिलाया था कि पच्चीस लाख रुपया मज़दूरों को लोन्ज़ वगैरा की शक्ल में दिया जाएगा लेकिन वह अभी तक दिया नहीं। मैं इस बात पर आप की रूलिंग चाहता हूं कि जो एश्योरेंसिज़ यहाँ पर हाउस में मनिस्टर या चीफ मनिस्टर साहिब देते हैं, जिस तरह से इस केस में वहां पर मज़दूरों को एक पैसा भी नहीं दिया गया, जिस की वजह से उन को इतना इन्तहाई कदम उठाना पड़ा कि उन के नेताओं ने भूखहड़ताल कर दी, क्या उन वादों को इसी तरह से पूरा किया जायेगा ? क्या सरकार इसी तरह से खामोश बैठी रहेगी ? वर्कर्ज़ रिट्रैंच किए जा रहे हैं, रिट्रैंच शुदा वर्कर्ज़ को रीइन्स्टेट नहीं किया गया, उन को उन के लीगल ड्यूज़ नहीं दिए गए। क्या चेयर इस बात पर गौर करेगी या नहीं ?

उपाध्यक्षा : आगे के लिए मुझे इस बात पर गौर करना पड़ेगा कि मैं प्वायंट आफ आर्डर की इजाज़त दूं या न दूं। प्वायंट आफ आर्डर पर खड़े हो कर इस तरह से लम्बी लम्बी तकरीरें करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। यह नामुनासिब बात है। मैं इसको अच्छा नहीं समझती।(In future I shall have to think whether I should permit the raising of points of order or not. The making of such long speeches on points of order cannot be permitted. This is most undesirable. I do not like it.)

(At this stage many hon. Members including Comrade Shamsher Singh Josh and Sardar Tara Singh Layallpuri rose on points of order)

मैं श्री अग्निहोत्री के साथ बात कर रही हुं। पहले मुझे वह बात तो खत्म कर लेने दीजिए। (I am talking to Shri Agnihotri. Let me first finish it). *(Interruptions, Noise)*

ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਲਾਇਲਪੁਰੀ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਮੈਡਮ* × × × × ×
× × × × ×

(Voices of point of order.)

Lt. Bhag Singh : On a point of Order.

Comrade Shamsher Singh Josh : Madam I rise, on a point of order. *(Interruptions) (noise)*

---

*Expunger as ordered by the Chair.

उपाध्यक्षा : लैफ्टीनैंट भाग सिंह जी, आप भी इसी तरह के प्वायंट आफ आर्डर करने लगे हो ? (Does Lieut. Bhag Singh also want to raise such points of order ?) (*Interruption*)

श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आप की रूलिंग चाहता हूं . .

उपाध्यक्षा : आप बैठ जाइए (The hon. Member may resume his seat.)

ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਲਾਇਲਪੁਰੀ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ . . . .

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਇਹ ਫੌਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰਖਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ (Sardar Tara Singh Ji, this matter concerns Armed Forces. It is most undesirable if such things are reported in the Press.)

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : * × × × × ×

(ਵਿਘਨ)

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦਾ ਹੈ । ਫੌਜ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਤਅੱਲੁਕ ਨਹੀਂ । ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ! (This subject concerns the Central Government only. Nobody else has any concern with the forces. If somebody has said anything derogatory in that connection, it is bad. He should not have said so.)

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਾਉ ।

ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : × × ×

*× × × × ×

× × × × ×

(*At this stage some hon. Members from the Akali Group rose in their seats and there was noise in the House when the Deputy Speaker was also on her legs.*)

**Note* :— Expunged as ordered by the Chair,

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਔਰ ਜਦ ਮੈਂ ਖੜ੍ਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਖੜੇ ਨਾ ਹੋਣ । ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਲ ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਵਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਦਰਿਆਫਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ । ਜੋ ਇਹ ਵੈਸੇ ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਔਰ ਕੋਈ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ, ਮੈਂ ਦਰਿਆਫਤ ਕਰਾਂਗੀ । ਜੇ ਵਾਕਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀਫਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ । ਇਹ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗਲ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਵਾਲ ਉਤੇ ਐਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ (I would like Sardar Gurnam Singh Ji to tell them about maintaining discipline and also that they should not stand when I am on my legs. The matter to which Sardar Tara Singh has drawn the attention needs verification. In case it is not a general matter—if it is a specific case then he should bring it to my notice. I will make enquiries. If, at all, somebody has made this sort of reflection, then he should not have done so. This is most undesirable. But this does not become the subject-matter of an adjournment motion).

श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडम ।

Deputy Speaker: No point of order. Please resume your seat.

ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੰਤਰੀ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਪਰਸਨਲ ਅਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ, ਮੈਡਮ । .... ..

उपाध्यक्षा । जब मेरे पास लिखा हुआ आएगा तब मैं इस बारे मैं बात करूंगी । (I shall take up this matter only when I have received it in writing.)

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ....

Deputy Speaker : Please take your seat. I have not permitted you,

ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਪਮੰਤਰੀ ; ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ । ਇਹ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ।

Deputy Speaker: Order please.

डाक्टर बलदेव प्रकाश : आन ए प्यायंट आफ आर्डर, मैडम मेरा प्वायंट आफ आर्डर यह है कि कामरेड बाबू सिंह मास्टर और कामरेड गुरबख्श सिंह की एडजर्नमेंट मोशन के बारे में जो आप ने चिट्ठी लिखी है, पढ़ी है उस को डिसएलाऊ करते हुए आप ने लिखा है।

[डाक्टर बलदेव प्रकाश]

"the matter is not of recent occurrence".

Madam, I beg to disagree with you on this point.

इस बारे में मेरी आप से यह गुज़ारिश है कि जो सिच्यूएशन पाकिस्तान के हमले के बाद यहां पर पैदा हुई है अगर यह मैटर आफ रीसेंट अकरेंस नहीं है तो और क्या मैटर आफ रीसेंट अकरेंस हो सकता है और हम तो इस बारे में एक बार नहीं अनेकों बार इस सवाल को उठाते आए हैं और हम इस बारे में मोशनज़ हाउस में मूव करते आ रहे हैं। इस के बारे में आप की तरफ से जो आरग्यूमेंट दिया जाने वाला है वह मुझे पता है। आप इस बारे में यही कहेंगी कि जब इस सेशन को शुरू हुए तकरीबन डेड़ महीना होने को जा रहा है तो आप ने इस बारे में एडजर्नमेंट मोशन पहले क्यों मूव नहीं की। लेकिन मैं इस बारे में अर्ज़ करता हूं कि एक दफा नहीं कई दफा इस बारे में हाउस में एडजर्नमैंट मोशनज़ आई और इस बारे में चीफ मिनिस्टर साहब ने और कई दूसरे मिनिस्टर साहिबान ने एश्योरेंसिज़ दीं है कि वह एक एक लेबरर को और एक एक फैक्टरी को लोन दे रहे हैं। डिप्टी स्पीकर साहिबा, जो बात आप के नोटिस में लाने वाली है वह तो यह है कि इन्होंने उन लोगों को यह रकम देनी तो कर्ज़े के रूप में है कोई खरायत तो देनी नहीं लेकिन आज दो महीने हो गए हैं और आज तक उन को एक पैसा नहीं दिया गया। वह बेचारे बेकार बैठे हुए हैं, आज इस सरकार की नीतियों की वजह से वे लोग भूखे मर रहे हैं उन के बच्चों के खाने के लिए कोई राशन नहीं है और वे भूखे मर रहे हैं। उन को सरकार की तरफ से आज तक कोई सहायता नहीं दी गई। इस लिए मेरी यह गुज़ारिश है कि यह जो इडजर्नमेंट मोशन है यह यहां पर डिसकस होनी चाहिए। सिर्फ एश्योरेंसिज़ से हमारी तसल्ली नहीं हो सकती जब कि इस सम्बंध में पहले कई एश्योरेंसिज दी जा चुकी हैं लेकिन एक को भी इम्पलीमेंट नहीं किया गया.........

उपाध्यक्षा : आप ने फर्माया है कि जो एश्योरेंसिज इन्हों ने दी हैं वह इम्पलीमैंट नही की गई। इस सम्बंध में अगर आप मुझे मेरे चेम्बर में मिल लें और बताएं कि कौनसी एश्योरेंस इम्पलीमेंट नहीं हुई तो मैं इस बारे में गवर्नमैंट से लिखूंगी। (The hon. Member has said that the assurances given by the Ministers have not been implemented. If he sees me in my Chamber in this behalf and let me know about any assurance which has not been implemented, I shall write to the Government.)

डाक्टर बलदेव प्रकाश : तो, डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप तब तक इस एडजर्नमैंट मोशन को पेण्डिंग रखें।

मुख्य संसद सचिव : डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप की रूलिंग देने से पहले मैं इस बारे में कुछ अर्ज़ करनी चाहता हूं।

उपाध्यक्षा : आप को मौका मिलेगा (The hon. Member will get an opportunity.)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : * × × × ×

ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੰਤਰੀ : × × ×

Deputy Speaker : * × × × × ×

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : * × × × ×

ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੰਤਰੀ : × × ×

* × × × × × ×

ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ : × × × ×

ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੰਤਰੀ : × × ×

मुख्य संसत् सचिव : आन ए प्वायंट आफ आडर, मैडम। एडजर्नमैंट मोशन्ज के बारे में यह जरूरी होता है कि कोई स्पेसेफिक और डैफीनिट मैटर के बारे में वह हो तो इस में यह दोनों चीजें नहीं है – – –

उपाध्यक्षा : आप इस बात को मेरे पर छोड़ दीजिए। आप ने कुछ और कहना है तो कह लीजिए। (The Chief Parliamentary Secretary should leave this thing to me. He can say something else.)

मुख्य संसत् सचिव : मैं ने तो सिर्फ यही कहना है कि यह अलाऊ नहीं होनी चाहिए।

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਮੈਡਮ । ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੂਲਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ---

"..........regarding distribution of the amount of Rs. 25 lakhs as loan........"

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੜਾ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਔਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 25 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਆਂਗੇ (*Interruption*)

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਜਦ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਅਲਾਉ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ । (Why is the hon. Member raising a point that has been disallowed ?) (ਵਿਘਨ)

3-00 p.m.

*Expunged as ordered by the Chair.

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : ਇਹ ਇਕ ਡੈਫੀਨਿਟ ਮੈਟਰ ਹੈ (ਵਿਘਨ) ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ (ਵਿਘਨ) ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 25 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ (ਵਿਘਨ) (ਸ਼ੋਰ) ਮੈਂ ਇਕ ਸਪੈਸੇਫਿਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਬ ਨੇ 25 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਅਨਐਮਪਲਾਇਡ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ....

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਦੋਬਾਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਲੈਕਚਰ ਨਾ ਕਰੋ (ਵਿਘਨ) (He can plead for its reconsideration but should not make a speach)

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਖ ਦਿਉ ਅਤੇ ਹਾਉਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਉ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ। (ਵਿਘਨ)

श्री सुरेन्द्र नाथ गौतम : ग्रान ए प्वायंट ग्राफ ग्रार्डर, मैडम ।

उपाध्यक्षा : मैं बौल रही हूं। क्या ग्राप चेयर पर प्वावंट ग्राफ ग्रार्डर रेज कर रहे हैं ? (विघ्न) मैं बुला लूं ग्राप को यहां पर............... (विघ्न) (I am speaking. Is the hon. Member raising a Point of Order on the Chair ? (*Interruption*) Should I call him here (*Interruption*)

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री : डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस बारे में मैं कुछ बात कहना चाहता हूं .....

उपाध्यक्षा : पहले मुझे ग्रपनी बात खत्म कर लेने दें। ग्राप इस पर दोबारा गौर करने के लिए कह सकते हैं, लैक्चर नहीं कर सकते : (विघ्न) ग्रगर ग्राप इस तरह से करेंगे तो सब कुछ ऐक्स्पंज करा दूंगी। पर जो कुछ होता है उस के मुताल्लिक लोग चर्चा करतें हैं कि हाउस में क्या होता है। कुछ तो नज़ाम रखना चाहिए। (Let me finish first. He can ask to reconsider the matter, but cannot make a speech. (*Interruption*) If the proceedings are carried on in this way then I shall expunge the whole of the same. The people are critical about the proceedings which are carried on here. Some discipline should be maintained in this behalf.]

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री: जो लेबरर्ज के मुताल्लिक जिक्र किया गया है उस के मुताल्कि मैं कुछ ग्रर्ज करना चाहता हुं। सरकार ने रुपया मनजूर किया कि यह लेबर्ज में इन्टरेस्ट फी लोन के तौर पर तकसीम किया जाए मगर वह कर्जा स्टेट इन्डस्ड्री ऐक्ट के तहत दिया जाना था। (विघन)

उपाध्यक्षा : जिस बात से मैं ने ग्रापोजीशन वालों को मना किया वही ग्राप ने शुरू कर दी। ग्राप की बात भी ऐक्स्पंज करा दूंगी। (विघ्न) । जब कोई सवाल ही ग्राप के सामने नहीं है तो ग्राप जवाब किस बात का दे रहे हैं। (The hon. Minister has started speaking on the same

subject about which I did dot allow the Opposition. What has been said by him will also be expunged. (*Interruption*) When there is no question before him then what is he replying to?)

सिंचाई तथा विधत मन्त्री : मै आप की ही इजाजत से बोलने के लिए खड़ा हुआ था। (विघ्न) आप मेरी बात तो सुने। इन्होंने दो-तीन दफा एक प्वायंट रेज किया तो अगर आप की इजाजत हो तो में उस की कुछ कलेरौ-फिकेशन कर दूं। उस से मैम्बर्ज़ की ऐंग्जाइटी दूर हो सकती है। बाकी अलाऊ ना करने का आपका इख्तयार है, एक मिन्ट में इन की ऐंग्जाइटी दूर हो सकती है।

उपाध्यक्षा : मैं आपको एक मिनट की बजाए तीन मिनट देती हुं, इन की एंग्ज़ाइटी दूर करिये। (Instead of one minute I give three minutes to the hon. Minister to remove the anxiety of the hon. Members.)

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री : डिप्टी स्पीकर साहिबा, पोजीशन यह है कि रुपया जो हम नें कर्जे के तौर पर देना मन्ज़ूर किया था वह सरकार ने ऐम्लायर्ज की मारफत देनें के लिये फैसला किया था, स्टेट इन्डस्ट्रीज ऐक्ट के तहत हम डायरैक्टली नहीं दे सकते। मगर इस के देने के लिये ऐम्पलायर्ज तैयार नहीं हुए। इस के बाद हमने फैसला किया कि हम उन को डायरैक्टली दे दें। मगर उस में लीगल पोजीशन इन्वालवड है। यह सारी बात लीगल रीमैम्बरैसर के पास भेजी हुई है कि सारी बात देखे, आया कानून में किसी तरमीम की जरूरत है या कुछ और। एक या दो दिन मैं इस का फैसला हो जायगा। : (विघ्न) : मैं अर्ज करता हुं कि चुंकि इस बारे में गवर्नमैंट ने फैसला कर लिया है और वर्कर्ज को हम कह चुके हैं इस लिये कुछ आदमी क्रेडिट लेने के लिये भूखहड़ताल पर बैठ गए हैं, और कोई बात नहीं है। विदिन ए डे आर टू इस का फैसला हो जायगा। (विघ्न)

(कुछ मैम्बर साहिबान बोलने के लिये खड़े हुए)

उपाध्यक्षा : अब इस के बाद और कोई बात नहीं है। (विघ्न) आप फैसला चाहते हैं या झगड़ा चाहते हैं। (विघ्न) एक या दो दिन में फैसला हो जायगा, और आप कया चाहते हैं? (Now there will be no discussion on it. (*Interruption*)Do the hon. Members want a decision or a quarrel. A decision will be arrived at within a day or two; what else do they want?)

कामरेड बाबू सिंह मास्टर : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडम, आप मेरी बात सुन तो लो । (विघन)

उपाध्यक्षा : प्वायंट आफ आर्डर भी कोई हुक्म होता है ? बाहर लोग मज़ाक करते हैं । (विघन) (Is a point of order an order ? The people Outside ridicule such things.)

ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ : On a point of personal explanation, Madam. * * *

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : × × × ×

* × × × ×

* × × × ×

* × × × ×

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : On a point of order, Madam. ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਅਟੈਨਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨ ਹੀ ਟਰੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜਵਾਬ ਆ ਜਾਵੇ । ਕੁਝ ਲੋਕ ਭੁਖਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਮਸਲਾ ਹਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ———— ।

Deputy Speaker : No party propaganda here, please.

(*Interruption*)

ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ : On a point of order, Madam. ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਇਧਰੋਂ ਅਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਜੋ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਗਲਤ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਨਟਰੈਸਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਨਟਰਸਟ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।

ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਮੰਤਰੀ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਜੋ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚੋਂ ਐਕਸਪੰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਵਗੈਰਾ ਵਲੋਂ ਜੋ ਰੈਫਰੈਂਸ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ । (ਵਿਘਨ)

ਸਰਦਾਰ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ : ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਥੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ।

---

*Note : Expunged as ordered by the Chair.

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲ ਅਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦਿਉ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ । (Let me take up the Call Attention Motions first and after that the hon. Member can rise on a point of personal explanation.)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਮੈਡਮ । ਮੈਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਐਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ 60, 70 ਕੜੀਆਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਲੈ ਗਏ ਹਨ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਐਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਮੁਵ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਥੇ ਦੇ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਨੇ ਡੀਨਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ । ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਉਥੇ ਦੇ ਸਾਬਕ ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਚੁਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਜ ਤਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖ਼ਲੋਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਡਰ ਤੇ ਖੜੋ ਗਏ ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਮੋਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ । (Addressing Sardar Gurbux Singh) (You are an experienced parliamentarian and you know that points of order cannot be raised on every item and at all times. The first point has not been disposed of and you have risen on a point of order. Notice of an identical motion has already been received on this subject.)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ : ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਚੁਕੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗਲ ਨੂੰ ਇਥੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਡੀਨਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਕਾਲ-ਅਟੈਨਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਐਡਮਿਟ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ । (I would like to inform the hon. Member that notice of an identical call-attention motion has already been admitted.)

ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਮੈਡਮ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਪਹਿਲੇ ਇਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਉ । (Let the first point of order be disposed of).

ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਡਰ, ਮੈਡਮ । ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮਨਿਸਟਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਫਿਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਆਪ ਪਾਸੋਂ ਰੂਲਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ ਉਹ ਠੀਕ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਡਿਪਟੀ ਮਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਵਿਚ ਇੰਟ੍ਰੈਸਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹਨ ਜਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਗਲਤ ਸਨ । ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੂਲਿੰਗ ਦਿਉ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਗਲ ਤੇ ਉਠਕ ਬੈਠਕ ਕਰਾਉ । ਮੈਂ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਗਲ ਕਰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ਼ ਆਡਰ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਾਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ । ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਕਾ ਲੈਣ ਦਿਉ । (I am to decide this issue. You all have honoured me to take this Chair and it would be setting a rare precedent in the history of the world parliamentary conventions to make the Deputy Speaker rise in the seat a number of times. I agree that to make such references to our fighting soldiers is not good. Another point of order has already been raised here in this connection that the proceedings relating to the mention of the soldiers and the border areas should be expunged. Let me deal with that first.)

ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਮੈਡਮ ।

Deputy Speaker : I do not allow your point of order.

ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਮੈਡਮ ।* ×

× × × ×

× × × ×

Shri Surinder Nath Gautam : On a point of order, Madam.

*Expunged as ordered by the Chair.

डिप्टी स्पीकर : गर्ग साहिब आप अपनी पार्टी के मेम्बरों को कन्ट्रोल में रखिए ।
(I would request Shri Garg to keep the members of his party under control.) (*Interruptions*)

Shri Surinder Nath Gautam : On a point of Order, Madam.

Deputy Speaker : Will you please take your seat?

एक चीज़ सरदार अजमेर सिंह जी की तरफ से आई थी ..

(There was a point of order raised by Sardar Ajmer Singh......) (*Interruptions*)

Shri Surinder Nath Gautam : On a point of Order, Madam.

उपाध्यक्षा : मैं ने आपको इजाज़त नहीं दी । आप बैठिए । (I have not allowed the hon. Member to rise on a point of Order. He may please take his seat.) (*Interruptions.*)

Shri Surinder Nath Gautam : On a point of Order, Madam.

यह मेरा राइट है, आप इस की इजाज़त ज़रूर दें ।

उपाध्यक्षा : No please पहले मुझे पहले प्वाँयट आफ आर्डर का जवाब देना है जो सरदार अजमेर सिंह ने उठाया है कि जो कुछ भी यहां पर बार्डर और फौजियों के बारे में कहा गया है उसको एक्सपंज़ कर दिया जाए । ठीक है इस को एक्सपंज किया जाए । (No, please. Let me deal with the first point of order, which has been raised by Sardar Ajmer Singh that all the proceedings relating to the soldiers and the border should be expunged. Yes this should be expunged.)

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ: ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਡਰ, ਮੈਡਮ । ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ ਨੇ ਲਫਜ਼ 'ਲਾਈ' ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ।

ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ : ਮੈਂ ਇਸ ਲਫਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ।

CALL-ATTENTION NOTICES

(Serial No. 180)

Sarvshri Ajit Kumar, Jagan Nath : I beg to draw the attention of the Minister concerned towards the fact, namely, the ejectment of the tenants with the active assistance and connivance of the Police.

That on 5-11-65 one Shri Gurbaksh Singh resident of village Ayalki, Police Station Fatehabad, district Hissar, informed the Chief Minister, I. G. Police, S.P., D.C., Hissar, that D. S. P., Sirsa is forcibly ejecting from his lawful possession taking law into his own hands. But no action was taken.

[Sarvshri Ajit Kumar, Jagan Nath]

On 11th November, 1965 the party supported by D.S.P., Sirsa opened fire on the disputed land to take the possession by harassing the tenant. Local Police has not taken any action so far. One mare was killed and one man injured due to the firing.

Deputy Speaker : This is admitted. The Government to make statement.

(No. 181)

ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ : ਮੈਂ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਰਹੰਦ ਨਹਿਰ ਦੀ ਕੋਟਲਾ ਬਰਾਂਚ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਰਜਵਾਹਿਆਂ ਦੇ ਮੋਘਿਆਂ ਵਲ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਜਵਾਹਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਮੋਘੇ ਪੁੱਟ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਪੁਰਾ ਰਜਵਾਹਾ ਤੇ ਮਾਹੋਰਾਣਾ ਰਜਵਾਹੇ ਦੇ ਮੋਘੇ ਪੁਟੇ ਹੋਏ ਤੇ ਅਜ ਤਕ ਨਵੇਂ ਮੋਘੇ ਨਹੀਂ ਲਗੇ । ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤਹਿਸੀਲ, ਬਰਨਾਲਾ ਤਹਿਸੀਲ ਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਭੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਧਰਤੀ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ । ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ੀਘਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ।

(I beg to draw the attention of the Minister concerned to the outlets on distributaries of the Kotla Branch of Sirhind Canal. The outlets on these distributaries have been demolished. The outlets on the Bhagwanpura Distributary and Mahorana Distributary, which were demolished have not been reconstructed so far. Thus the sowing of Rabi crop in Malerkotla Tehsil, Barnala Tehsil and a large number of villages in Bhatinda District also has been adversely affected. If no attention is paid for some time more then on thousands of acres of land it would not be possible to sow Rabi crops. Therefore, we request the hon'ble Minister concerned to pay immediate attention in the matter.)

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਕਾਲ ਅਟੈਂਨਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਏ । (This is admitted.) Government to make a statement.

(Serial No. 184)

Pandit Mohan Lal Datta : I beg to draw the attention of the Government to the fact that owners of Kothis and big houses in Chandigarh costing a lac or more of rupees have been kept immune from payment of property tax which is being levied in all cities of the Punjab State. Such favour done to rich persons in the Capital is discriminatory and entirely unjustifiable particulary in view of the great need for huge financial resources required for defence and development. Such rich people must be made to contribute to share the burden placed on the entire nation on account of conflict with Pakistan and China.

This matter is of serious public importance and deserves clarification from the Government and immediate action.

Deputy Speaker : This is admitted. Government to make a statement.

(No. 185)

Comrade Babu Singh Master : I beg to draw the attention of the Minister concerned towards the matter regarding the misuse of public funds as well as the misuse of powers by the present Director of Animal Husbandry, Punjab Government, Chandigarh. He has given first prize at the cattle fair show, Hariana Cow Calves to his own son, Shri Ranbir Singh, Sarpanch Salika and others of the same village instead of Sardar Tara Singh, who really deserved the prize.

Secondly the same officer has given Rs 400 as subsidy to his own son for constructing Silo Tower in 1960 but nothing has been constructed so far.

The tampering with the record as is obvious from the photo attached herewith and the nepotism and favouritism shown by the head of the Department has caused sensation and resentment among the cow-breeders in particular and public in general in the State.

Hence the matter calls the immediate attention of the Government as the actions of the Director, Animal Husbandary, Punjab Government, Chandigarh, has adversely affected the motive and incentive cherished by the State Government in giving subsidies and prizes.

Deputy Speaker : This is admitted. Government to make a statement.

(No. 186)

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : ਮੈਡਮ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਕ ਬਹੁਤ ਮਹਤੱਵ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇ ਵਲ ਖਿਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਹੁਣ ਕਣਕ ਦੀ ਬਜਾਈ ਸਮੇਂ ਖਾਦ ਦੀ ਬਹੁਤ ਥੁੜ ਹੈ । ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲੇ ਨੂੰ ਖਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਖਾਦ ਦੀ ਅਸਲ ਵੰਡ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਜ਼ਿਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ । ਸਮੁਚੇ ਜ਼ਿਲਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਗਾ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਖਾਦ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਮੋਨੀਅਮ ਨਾਈਟਰੇਟ, ਸੂਪਰ ਫਾਸਫੇਟ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਖਾਦ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ । ਹੁਣ ਬਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਪਛੜੀ ਬਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਭਖਦੇ ਸਵਾਲ ਵਲ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਖਾਦ ਡਿਪੂਆਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਲ ਕਦਮ ਪੁਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਹੀ 'ਵਧ ਅੰਨ ਅਗਾਓ" ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਅਗੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

[Madam, I beg to draw the attention of the Government to the fact that there is a great shortage of fertilizers at this time, when the sowing is in progress in district Ferozepnr known for producing the best quality of wheat. Although it is correet that the Government has decided to give priority to this district in the distribution of fertilizers yet the actual

[ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ]

allocation of Fertilizers so far made to this district is too meagre and has met the requirements of the farmers to a very small extent. Calcium, ammonium nitrate, superphosphate and potash fertilizers are not available at all at this time in the whole of district Ferozepur, particularly in Moga Tehsil. The sowing season is nearing its end and the time has been left for late sowing only. Therefore, the Government should pay immediate attention to this burning question and the steps be taken to supply all kinds of fertilizers to fertilizer-depots in the district during the next few days. Only such effective steps can take the 'Grow-More Food Campaign' a long way to its achievement.]

Deputy Speaker : This is admitted. Government to make a statement.

(No. 187)

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ: ਮੈਡਮ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਲ ਖਿਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਫ਼ੀਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੀਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪਰਧਾਨ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਲਗ ਭਗ 470 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਰਤ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪਦਵੀ ਦੀ ਦੁਰ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਸੰਸਥਾ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਡੀ. ਸੀ. ਫ਼ੀਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉਜੜੇ ਲੋਕਾਂ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਮਾਯੂਸੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਡੀ. ਸੀ. ਫੀਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੜਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਕੇ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਆਪਣੀ ਪਦਵੀ ਦੀ ਦੁਰ-ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਨਾਪਾਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਰੈਡ-ਕਰਾਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਿਸ ਨੇਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਫੰਡ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।

Madam, (I beg to draw the attention of the Government to the fact, namely, recently the Deputy Commissioner of Ferozepur District, Sardar Kuldip Singh Virk, who is also President of the Red Cross Society of district Ferozepur, has utilized medicines worth about Rs 470 out of the funds of the District Red Cross Society for the treatment of his son. He has misused his authority. Red Cross Organisation has been established for helping the poor. This act of the D. C., Ferozepur has created resentment and disappointment among uprooted persons, financially poor and backward people of the district. Therefore, the Punjab Government should take serious notice of this unlawful act of the D.C., Ferozepur and take suitable action so that no officer misuses his authority in furtherance of his personal interests in future and the funds and medicines of the Red Cross Society may be utilised for the noble purposes for which it has been established.)

Deputy Speaker : This is admitted. Government to make a statement.

STATEMENTS LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE

by the Chief Parliamentary Secretary

Chief Parliamentary Secretary (Shri Ram Partap Garg) : Madam, I beg to lay on the Table of the House certain statements regarding Call-Attention Motions Nos. 116, 134, 160 and 161 as under :

(i) re: Call-Attention Notice No. 116 by Sardar Gurbakhsh Singh Gusdaspuri, suggesting action by Government against 'Hind Samachar Daily', 'Pradeep Daily', etc., for propagating communal hatred between various communities;

(ii) re : Call-Attention Notice No. 134 about the Arts Gallery of the Arts College, Chandigarh ;

(iii) re : Call-Attention Notice No. 160 by Dr. Baldev Parkash, suggesting action by Government to hold enquiry into the charges of embezzlement and misappropriation against the Sarpanch and Secretary of the Panchayat, Rajipura (Jhagre), tehsil Kharar, district Ambala; and

(iv) re : Call-Attention Notice No. 161 by Shri Harkishan regarding the sending back by the Jullundur Training Centre, of 42 duly approved new recruits to P.A.P. from Gurgaon District, who had been medically examined and considered fit ;

(i) Re. Call Attention Notice No. 116

Sardar Darbara Singh, Home and Development Minister Punjab:

It appears that the M.L.A. has probably in mind a news-item appearing in the 'Hind Samachar' and the 'Pradeep' of the 2nd November, 1965, reproducing a Memoradum alleged to have been submitted by Punjab Ekta Samiti to the Government enumerating 21 points against the formation of Punjabi Suba. This news-items was duly noticed in the aforesaid news papers. Although it is not actionable under any Law yet since it is not unlikely to produce reaction the advice of L.R. has been obtained regarding its actionability. The L. R. has opined that the aforesaid news-items is not actionable.

In the course of discussion on an Adjournment Motion on the subject raised in the Vidhan Sabha on 2-11-1965, the Chief Minister, Punjab, is reported by the Tribune, to have said that the Government had no relation direct and indirect with the views expressed in the newspapers under discussion. Nevertheless, he added that the Press Consultative Committee would meet shortly and discuss the Press behaviour.

(ii) Re-Call-Attention Notice No. 134 about Arts Gallery of the Arts College, Chandigarh.

In the building of the Government School of Arts, Punjab, at Chandigarh, two separate Institutions are functioning at present :—

(i) The Government School of Arts (and not Arts College).

(ii) Chandigarh Section of the State Museum.

Shri Sushil Sarkar is the Principal of the Government School of Arts,, Chandigarh, while administartive control over this Institution is that of the Director of Industrial Trainjng, Punjab. The Chandigarh Section of the State Museum is under the administrative control of the Education Commissioner and Secretary to Government, Punjab, Education and Languages Departments. The Principal, Government School of Arts is also Incharge of the Chandigarh Section of the State Museum. There is no

(Chief Parliamentary Secretary)

Art Gallery attached to the Arts School and so the question of the Art Gallery of the Arts College, Chandigarh, being in deplorable condition does not arise. So far as the State Museum is concerned, all the assets of the Museum at Simla were shifted in 1959 to Patiala where the State Museum was proposed to be established in the Moti Bagh Palace.

Consequent upon the sale of the Moti Bagh Palace to the National Institute af Sports of the Government of India, a part of the assests of the Museum had per-force to be shifted to Chandigarh and temporarily housed in a portion of the Government School of Arts, Chandigarh.

The present set up of the State Museum in the Government School of Arts building is apurely temporary feature and all the exhibits displayed in the limited space in the Museum are in proper order. All these exhibits will be removed and placed permanently in the new building of the State Museum which is under construction at Chandigarh.

During the recent Indo-Pakistan conflict, the requisite precautionary measures were taken to protect the fare objects in the Museum and especially paintings etc. The Museum, however, remained open to the public and no student was ever refused to enter the Museum. As stated above, there does not exist any Art Gallery of the Arts College, Chandigarh, and so the question of its being closed for the visitors and particularly the college students does not arise at all.

No instance has come to the notice of the Education Department that the Principal of the Arts College, Chandigarh, took out valuable production or master-pieces from the Museum to the Tagore Theatre in Sector 18, Chandigarh. Only on one occasion, a request was received from the Secretary, Arts Council and Director, Public Relations, Tourism, Cultural Affairs and Deputy Secretary to Government, Punjab, that the Arts Council had arranged an exhibition of contemporary art on the 29th October, 1965. He requested for a loan of 25 paintings and some pieces of sculptures which belonged to the State Museum. This request was accepted and the Principal of the Government School of Arts and Incharge, State Museum, Chandigarh was allowed to lend 25 paintings and some pieces of sculptures to the Public Relations Department for exhibition. The exhibits were loaned to the Lalit Kala Academy for exhibition in Tagore Theatre which was inaugurated by Shri M.C. Chagla, Union Education Minister on the 29th October, 1965. The Arts Council of which the Lalit Kala Academy is a Susidiary Body which sponsored this exhibition, is a Government body. The Union Minister for Education greatly commended the efforts of the Lalit Kala Academy and desired that more exhibitions of this type should be held to make people art-minded. Thus nothing was done which could be deemed to be in contravention of the Government policy or in any respect objectionable or anti-national.

Statement by the Home and Development Minister, Punjab.

(iii) It is wrong to say that no proper enquiry was held against the Sarpanch and Panchayat Secretary, Gram Panchayat Rajipur, tehsil Kharar, into the charges of misappropriation and embezzlement. A proper enquiry in this case was held by the Assistant Director of Panchayats, Ambala Division and proper opportunity was given to Shri Inder Sain, Panch (Chief complainant) along with Sarvshri Rup Chand, Jagir Singh and Amar Singh, Panches in this case to represent their case before the Assistant Director of Panchayats. The Assistant Director of Panchayats, Ambala recorded their statements. The statements were read over to them and they accepted them as correct. In view of these facts it would be quite wrong to say that the complainants were never called for taken into confidence regarding their complaints.

The findings of Assistant Director of Panchayats, Ambala Division had already been communicated to the Deputy Commissioner, Ambala on 10th February, 1965 for such action as he may deem proper in the light of the findings of the Enquiry Officer.

The Chief petitioner Shri Inder Sain, Panch, had submitted hunger his petition on 28th October, 1965, in which he has threatened to go on hunger-strike on 22nd November, 1965 if the case is not decided by that time. The Deputy Commissioner, Ambala has been asked to decide the case immediately under intimation to this office.

The matter is being pursued with the Deputy Commissioner, Ambala and there is no point in going on hunger strike by the petitioners.

It would be better if the petitioners be advised to contact the Deputy Commissioner, Ambala and get their grievances removed from him instead of using unlawfull methods.

IV Re. CALL-ATTENTION NOTICE No. 161

Sardar Darbara Singh, Home and Development Minister

All Superintendent of Police and Commaudants Border Battalions in the Punjab had been requested by the Additional Inspector-General P.A.P. to send suitable candidatcs for enlistment in P.A.P. Most of them sent more men than they were required to send and all vacancies were filled up by 28th August 1965 As a result candidates arriving on 29th September, 1965 or after had to be returned to their homes. Their names however been kept on waiting list and all such candidates are being called as and when vacancies occur.

चौधरी नेत राम : मैं ने एक काल-अटैन्शन "अक्तूबर को दी थी जिस का नंबर 2 है मगर उसका जवाब आज तक नहीं मिला । यह कहते थे कि एक हफता के अंदर दे दिया जायेगा ।

मुख्य स सत् सचिव : वह टेबल पर ले कर दिया गया है ।

उपाध्यक्षा : यह कहते हैं ले हो गया है । मेरी फिर भी सरकार से सिफार्श है कि अगर अभी तक इन्हें कापी नहीं मिली तो इनको और कापी दे दी जाये । (The Chief Parliamentary Secretary says that the reply has been laid on the Table of the House. Even then I ask the Government that if a copy of that has not been received by the hon. Member so far the same may please be supplied to him.)

चौधरी नेत राम : डिप्टी स्पीकर साहिबा, किया इस सरकार की यही नीति है कि फसलें पानी के बगैर तबाह होती चली जायें और यह महीना भर किसी मोशन का जवाब ही न दें । क्या यह उस वक्त तक सवाल हल नहीं हो सकता जब तक इन की शिकायत आपके द्वारा इस हाउस में न की जाये ।

उपाध्यक्षा : आपके सवाल का जवाब आ गया है । (The reply to his question has come.)

ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ : On a point of order. ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਏਥੇ ਇਕ ਲੱਖ ਵਾਲੇ ਇਕ ਮੁਆਮਲੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਚਲ ਰਹੀ ਸੀ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਢਿਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਲ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ । ਪਰ ਅੱਜ ਤਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲਨ ਲਗ ਪਏ ? (Why the hon. Member is speaking, when I have not allowed h.m ?)

Sardar Narain Singh Shahbazpuri: On a Point of Order Madam.

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁਛਣੀ ਚਾਹੁਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿਚ ਢਿਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਨਸੰਰੰਡ ਮਨਿਸਟਰ ਹਨ ਤਾਂ ਖੁਦ ਢਿਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਆਮਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲਣਾ ਚਾਹੁਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਚਾਹੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਨਿਸਟਰ ਯਾ ਢਿਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੁਕੀ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ ? (The previous point has not been disposed of. The hon. Member has repeated the same. How can he get a reply ?)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ : On a point of order, Madam, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਜੇ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਆਏ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਊਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਰੂਲਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਯੂ. ਪੀ. ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਉਥੋ ਦੇ ਮਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ? (ਹਾਸਾ)

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਵਰ ਮਿਲ ਗਈ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਣੀ। (The hon. Member may use such powers when he gets them.)

ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਨਾਥ ਗੌਤਮ : ਕੀ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਏਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ? ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਇਸ ਤੇ ਰੂਲਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਮੈਂ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਲਈ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਲੜਨ ਲਈ ਡੰਡੇ ਪਰੋਵਾਇਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ? ਜਦੋਂ ਇਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਢਿਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਫੇਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੀਪੀਟ ਕਰਨ ਦੀ। (I did not want to use such words for the hon. Members but would it not be proper if they are provided sticks to fight amongst themselves. When it has been admitted by Mr. Dhillon that he would reply then why there is repitition of the same thing ?)

ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਨਾਥ ਗੌਤਮ : ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਮਨਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕੀ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ? ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਰੂਲਿੰਗ ਚਾਹੁਦਾ ਹਾਂ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਪਾਵਰਜ਼ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਰਤਾਂਗੀ । (I have got ample powers and first of all I shall use them for the hon. Member.)

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੰਤਰੀ : ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਚੰਦਰ ਜੀ ਏਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ । ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ । ਕੁਛ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਕ ਦੁਬਾਰਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂਗੇ । ਸ਼ਾਇਦ ਜੋ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਕਹੀ ਜਾਏ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਬੋਧ ਚੰਦਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਲਿਆ ਦਿਉ ਕਿ ਅੱਜ ਹਾਉਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਕਲ ਏਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਅਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ । (Shri Garg may please bring to the notice of the Education Minister Shri Prabodh Chandra that he must reply the points concerning him to-day before the rising of the sitting of the House or tomorrow.)

PERSONAL EXPLANATION BY SARDAR NARAIN SINGH SHAHBAZPURI

ਸਰਦਾਰ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ (ਖਾਲੜਾ) : ਆਨ ਏ-ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪਲਾਨੇਸ਼ਨ, ਮੈਡਮ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਕਲ ਹਾਉਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਪਾਤਰ ਵੀ ਹੋ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਉਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਜ਼ਾਈ ਅਤੇ ਕਣਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨਲ ਗੁਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਮਾਲੂਮ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਉਂ ਤਾਂ ਨਹੀ ਲਿਆ ਜੁਆਇਟ ਰੈਸਪਾਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਮਨਿਸਟਰੀ ਦੀ । ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬੜਾ ਗੁਸੇ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਗੁਸਾ ਸੀ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਸਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਸਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਪਰਧਾਨ ਲੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਅਜ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਕਲ ਵਿੱਚ ਹੈ । ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ । ਉਸ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਢ ਦਿਤਾ ਤੇ ਇਹ ਇਕ ਦਿਨ ਲਈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਏ । ਇਨ੍ਹਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਢ ਦਿਤਾ, ਦੂਜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਢਿਆ । ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ 6 ਸਾਲ ਲਈ ਕਢ ਦਿੱਤਾ । ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ । ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ

(ਸਰਦਾਰ ਨਰਾਇਣ ਸਿਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ)

ਹਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁਲ ਜਾਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਕਾਇਦਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੁਰਪਟ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਉਂ ਵੀ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਏ । ਜਨਾਬ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਸਨ । ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਰਸਨਲੀ, ਆਏ ਹੇਣਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ । ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੇਲਣਾ ਮੈਂ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਢੁਕਦੀ ਹੈ ਕਿ 'ਕਿਥੇ ਰਾਜਾ ਭੋਜ ਤੇ ਕਿਥੇ ਗੰਗਾ ਤੇਲੀ' । ਤੇ ਇਹ ਗਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਉਸ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਰਖੇ ਹੋਏ ਸਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ । ਸੰਨ 1947 ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਏ......

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਮੈਂ ਰਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਕੇ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਘਰੋਗੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਲੜੋ, ਪਰਾਵਿੰਸ ਕਾਂਗਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਜਾ ਕੇ ਲੜੋ । ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਮਿਹਣੇ ਕੁਮਹਿਣੇ ਨਾ ਕਰੋ । ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੀਹੈਬੀਲੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਥੇ ਜਾਵਾਂਗੀ । ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਆਈ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿਆਂਗੀ । ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਏਥੇ ਨਾ ਕਹੋ । ਇਹ ਫਾਰਿਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਫੌਜ਼ੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ । (I would request for God's sake that if there is any internal dispute then it may be settled in the Congress Party, in the Pradesh Congress Committee. No charges or counter charges should be levelled in this House. This matter concerns the rehabilitation of the people of the border areas and providing them with quilts and wheat. I had said that I would personally go there. So I have seen the things myself by going over there. I will give a statement after showing those things to the Members of the House. Such matters should not be raised here. Their report goes to the foreign countries. On the one hand our soldiers are fighting while on the other we are saying such things.)

ਸਰਦਾਰ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ : ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗਾ । ਸੋ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਮਿਹਰ ਸਿੰਘ ਗੜਗਜ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸੀ । ਜਿਨਾ ਨੇ ਐਨੀਆ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਬਆਦ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕ ਦਮ ਭੁਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਰਗੀ ਨਾ ਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਉਹ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੋਰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪ-ਲੇਨੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਉ ਬਾਵਜੂਦ ਮੇਰੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇ । ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਉਂ ਨਾ ਦੋਸਤ ਤੇ ਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (Despite my request the hon. Member may give his personal explanation in respect of the charges levelled against him. But I may say that neither friend nor foe should mention the name of Sardar Partap Singh Kairon.)

ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਗੋਆਣੀ : ਉਹ ਸਿਰਫ ਬੰਦੇ ਮਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ।

ਸਰਦਾਰ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ : ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਉਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਾਉਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਅਜ ਉਹ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਉਸ ਦਾ ਤਅਲੁਕ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਸਿਧਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਰੁਪਿਆ ਲਿਆ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ 5 ਦਿਨ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਿਆਂ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5,000 ਰੁਪਿਆ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ । ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਅਜ ਤਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਪਏ ਹਨ । ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦਾ ਤਅੱਲੁਕ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ । ਜੋ ਰਜ਼ਾਈ ਮੈਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਲ 1,100 ਰਜ਼ਾਈ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ । ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਨੇ ਤੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਨੇ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਆਈ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਈ ਹਾਂ । ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਦਿਖਾਂਵਾਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿਆਂਗੀ । (I have already said that I have seen the things myself and have brought the same with me. I shall show them to the Members of the House and then give my statement.)

ਸਰਦਾਰ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ : ਜੋ ਰਜ਼ਾਈ ਮੈਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ । 1100 ਰਜ਼ਾਈ 52000 ਆਦਮੀਆਂ ਲਈ ਹੈ । 2200 ਰਜ਼ਾਈ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ । ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲ ਦੁਪੜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਬਾਕੀ ਗਲਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਉ । ਮੈਂ ਉਥੋਂ ਹਰ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ । ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨਫੀਡੈਂਸ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਆਦ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿਆਂਗੀ । ਇਹ ਚੀਜ਼ ਛਡ ਦਿਉ, ਹੋਰ ਗਲ ਕਹੋ । (The hon. Member can reply to the allegations levelled against him. He may leave the other matters. I have brought everything concerned from there. I will take the Members of the House into confidence and then give my statement. He should leave this matter and say something else.)

ਕਾਮਰੇਡ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ਼ ਆਰਡਰ, ਮੈਡਮ, । ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਏਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ । ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਣ, ਏਥੇ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗਲ ਦਸੀ ਹੈ । (I thank the hon. Member, he has said a good thing.)

ਸਰਦਾਰ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ : ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆਂਗਾ । ਸੋ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ । ਇਕ ਗਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸੁਰਿੰਦਰ ਤੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਪਾਉਣ । ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਐਨਾ ਤਕੜਾ ਆਦਮੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦਿਨ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਲਉ । ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਰਬ ਕਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ । (The other day when Dhillon Sahib was mentioning the names of Surrinder and Gurinder I observed not to do so. May God bless him with a son Mohinder Singh.)

ਸਰਦਾਰ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ: ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆਂਗਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦਾ ਗਲਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ।

(*interruptions and noise*)

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰੋ । ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗਲ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ । (The hon. Member may please leave this matter. I want to know from the Members of the House whether they rely upon me or not.)

ਅਵਾਜ਼ਾਂ : ਹਾਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਤਬਾਰ ਹੈ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਮੈਂ ਕਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਏਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਕ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ । (I spent the whole day yesterday to inquire into this matter and I will show everything concerned to the House.)

ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਰਾਮਜੀ ਦਾਸ ਟੰਡਨ : ਬੀਬੀ ਜੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ । ਉਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਰੀਆਂ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਹਾਊਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿਆਂਗੀ। ਹੁਣ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਫਰਦਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। (ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਦਾਰ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ ਫੇਰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਏ) ਸਰਦਾਰ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਉ। (The House has expressed confidence in me so I will give a statement in the House tomorrow. Further discussion on this matter may now be stopped. (*At this stage Sardar Narain Singh Shahbazpuri again rose to speak.*) (*Addressing Sardar Narain Singh Shahbazpuri*) I think it is not you who is speaking but you are representing views of some one else. Please resume your seat.)

ਸਰਦਾਰ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ : ਬੀਬੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗਲ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਹਿ ਲਉ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ। (The hon. Member may please confine himself to his personal explanation and finish this matter.)

ਸਰਦਾਰ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ : ਮੇਰੇ ਇਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਤੇ ਕਣਕ ਕਿਤੇ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਏਥੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ

* * * * * *

* * * * * ।

ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ : ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਲੀ ਵਗੈਰਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਹਨ ਇਹ ਐਕਸਪੰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਹਾਂ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਐਕਸਪੰਜ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ। (Yes, these words may be expunged.)

(*Sardar Narain Singh Shahbazpuri rose to speak*)

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਸਰਦਾਰ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ਼ ਰਖੋ। (Sardar Narain Singh may please resume his seat now.)

ਸਰਦਾਰ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ : ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕਹਿ ਲਵਾਂਗਾ।

---

*Expunged as ordered by the Chair.

ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਮੈਡਮ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, 17 ਤਾਰੀਖ ਦੀਆਂ ਪਰੋਸੀਡਿੰਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਹਨ । ਉਸ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਇਆ ਉਹ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਹਨ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਗੋਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ । (ਵਿਘਨ)

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਕਾਮਰੇਡ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਕਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ । (*Addressing Comrade Ram Piara*) (Since when you are in a misunderstanding that you are the only wise man ?)

ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਅਕਲਮੰਦੀ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ । ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਇਆ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹਨ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਗਰੁਪ ਹਨ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਗਰੁਪ ਹਨ । ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਉ ।(He is the Leader of the Akali Group in the House. The hon. Member may please resume his seat now.)

ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਗੋਆਣੀ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਕੀ ਮੈਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹਨ ?

* * * * * * * * * *

PERSONAL EXPLANATION BY THE MINISTER FOR TRANSPORT AND ELECTIONS

ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੰਤਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ) **:** ਬੀਬੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਮੇਰਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਿਆਣੈ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ । (I think a wise man like the hon. Minister need not speak now.)

ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੰਤਰੀ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਜਿਹੜੀ ਗਲ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਹੀ ਸੀ ਉਹ ਹੂ ਬਹੂ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਸ਼ਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਇਤਹਾਸ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਕੌਣ ਮੇਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸੀ ਔਰ ਉਥੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਏਥੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹਨ । ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਮ ਨਹੀਂ ਸਵਾਏ ਕੈਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ।

*Expunged as ordered byhe Chair.

ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਗੋਆਣੀ : * × × × × × × × ×

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਹੋ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਉ। (The hon. Member is an old man, he should not act like this. If he has used these words he should withdraw them.)

ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਗੋਆਣੀ : * × × ×

(ਸ਼ੋਰ)

डाक्टर बलदेव प्रकाश : आन ए प्वांयट आफ आर्डर । डिप्टी स्पीकर साहिबा, 2½ बजे कवैश्चन आवर खत्म हुआ और चार बजने लगे हैं ! उस वक्त से परसनल एकस्प्लेनेशन, काउंटर एकस्प्लेनेशन और प्वांयट्स आफ आर्डर का सिलसिला चला हुआ है । अगर यह सिलसिला इसी तरह चलना है और आगे एजंडा नहीं चलना है तो हम जो एजंडा के लिए बैठे हैं जा कर कोई और काम कर लेते हैं और जिन्होंने परसनल एकस्प्लेनेशन देने हैं और ज़ाती लड़ाईयां लड़नी हैं वही लगे रहें ! यह तो एक मज़ाक बना हुआ है ।....

(शोर)

ਸਰਦਾਰ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ : ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਉ........(ਸ਼ੋਰ)........ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਮਿੰਟ ਹੀ ਲੈਣੇ ਹਨ........ (ਸ਼ੋਰ)........

(ਇਸ ਵਕਤ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਰ ਸੀ)

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ I will adjourn the House. (Don't compel me. I will adjourn the House.)

(इस वक्त हाऊस में बहुत शोर था और हाऊस में कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था ।)

4.00 p.m.

कामरेड राम प्यारा : * × × × × × × × × × × ×

(शोर) विघ्न)

उपाध्यक्षा : अगर हाउस में शोर करके प्रोसीडिंग्ज़ होने नहीं देनी हैं तो मुझे मजबूर होकर हाऊस एडजर्न करना पड़ेगा । (If noise is continued and proceedings of the House are interrupted like this then I shall be compelled to adjourn the House.)

Note.—Expunged as ordered by the Chair.

कुछ आवाजें : हमें हाउस को कुछ देर के लिए एडर्जन करने में कोई एतराज नही है।

कामरेड राम प्यारा : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडम........ (शोर)

उपाध्यक्षा : आर्डर प्लीज। मैं सरदार जगजीत सिंह गोगोआनी और आप को अपने चैम्बर में काल करूंगी वहाँ पर दोनों की बातें सुनूंगी और मैं उस के बाद उसके बारे में फैसला करूंगी। There must be some limit. (Order please. I shall call Sardar Jagjit Singh Gogoani and the hon. Member Comrade Ram Piara in my Chamber. I shall hear both of them there and give my decision after that.)

(इस वक्त हाउस में बहुत शोर था। हाउस में कुछ भी सुनाई नहीं दिया).

Deputy Speaker : Order, please. No interruption and no noise please.

(इस समय राजस्व मन्त्री, कामरेड राम प्यारा और सरदार नारायण सिंह शाहबाज़पुरी कुछ कहने के लिए खड़े हुए। हाउस में बहुत शोर था। कुछ भी सुनाई नही दे रहा था।)

Deputy Speaker : Order please. No noise please.

कामरेड राम प्यारा :* × ×

(शोर) (विघ्न)

Deputy Speaker : Order please. Take your seat.

ਸਰਦਾਰ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਮੈਡਮ* × ×

(ਸ਼ੋਰ ਵਿਘਨ)

उपाध्यक्षा : जो कुछ सरदार नारायण सिंह शाहबाज़पुरी ने कहा वह एक्सपंज कर दिया जाए। (Whatever has been said by Sardar Narain Singh Shahbazpuri should be expunged.)

BILL

THE PUNJAB COMMERCIAL CROPS CESS (AMENDMENT) BILL, 1965

Minister for Revenue (Sardar Harinder Singh, Major) : Madam, I beg to move—

> That the Punjab Commercial Crops Cess (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Deputy Speaker : Motion moved—

> That the Punjab Commercial Crops Cess (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

**Note.*—Expunged as ordered by the Chair.

ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਥੇ ਆਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਵਾਏ ਕੈਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ । ਜਦੋਂ ਇਧੱਰ ਬੈਠ ਜਾਉ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗਲ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ । ਖੈਰ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੀ ਗਲ ਕਰਾਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੰਦ ਸੁਟਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਝੂਠੀ ਗਲਤ ਤੇ ਵਿੰਡਿਕਟਿਵ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ । ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਐਨਾ ਤਕੜਾ, ਲੱਠਮਾਰ, ਲੱਤਾਂ ਕਟਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਸਖਤ ਰੰਜ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ – – – –

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ? ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਉ ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ : ਇਹੋ ਕਿ ਫਲਾਨੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੈ । ਇਹ ਗਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰਾਂਗਾ ਪਰ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ । ਜੋ ਗਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਸੀ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਠੀਕ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਜੋ ਹੈ ਸੋ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਖ ਲਿਆ । ਬਾਕੀ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਉਤਨਾ ਅਰਸਾ ਹੀ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਚਿਮਟੇ ਰਹੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਟ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਫੌਰਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਥਲੇ ਚਲੇ ਗਏ (ਹਾਸਾ) । ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਅਜ ਹੀ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਸ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ।

Telephonic message from G. A. to D. C. Karnal submitted to me by Shri R. S. Kang, Relief and Rehabilitation Commissioner, read as under :—

> "825 quilts in all were donated by the public of Karnal for being given away as relief to the uprooted persons of the border districts. These were marked by the D. C. Karnal as Relief Issue Karnal."

ਉਹ ਰਜ਼ਾਈ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਤਮਤਰਾਕ ਨਾਲ ਇਥੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ । ਉਸਤੇ ਰੀਲੀਫ ਸੋਸਾਇਟੀ ਕਰਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ

> 2. G. A. is of the view that the quilts answering the description of upper and lower parts like that of the one exhibited in the Vidhan Sabha yesterday, number about 300 and all those quilts were sent by the D. C. Karnal to D. C. Amritsar."

ਬਜਾਏ ਇਸਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਥੇ ਆਕੇ ਹਾਊਸ ਦਾ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦੇ ,ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁਛ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸ਼ੋ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਾ ਰਜ਼ਾਈ ਨਾਲ ਸੀ, ਨਾਂ ਹੀ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ

[ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੰਤਰੀ]

ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਤੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਗਰੀਬ ਦੇ ਦੋ ਲੜਕੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਘੁਮ ਗਈ। ਮੈਂ ਹੁਣ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾ ਕੋਈ ਲੜਕਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਇਸੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ। ਮੇਰਾ ਹਕੀਕੀ ਭਾਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸਟੈਪ ਬਰਦਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਸਦਾ ਇਕ ਲੜਕਾ ਹੈ ਜੋ ਯੂ. ਪੀ. ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਇਥੇ ਇਕ ਬਿਘਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਦਾਰ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁਣ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਕਤ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਨਿਹਾਇਤ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਉਸਨੂੰ ਕਦੇ ਜਾਕੇ ਮਿਲ ਆਵਾਂ। ਬਾਕੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਛੇ ਸੱਤ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਲਾ ਮਿਲਾਕੇ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਬਣਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਇਕ ਦਾ ਸੌ ਸੌ ਭਤੀਜਾ ਨਿਕਲ ਆਵੇਗਾ, ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਭਤੀਜਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਿਚਾਰੇ ਮਰ ਖਪ ਗਏ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਏ ਹੋ। ਬਾਕੀ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤਨੇ ਕਾਤਲ, ਡਕੈਤ ਤੇ ਸਮਗਲਰ ਹਾਂ। ਨੈਚਰਲ ਜਸਟਸ ਹਰ ਇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸੋ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗਾ।

श्री सुरेंदर नाथ गौतम : आन ए प्वायंट आफ आर्डर। मेरा प्वायंट आफ आर्डर यह है कि जब आपने तशरीह कर दी कि सरदार गुरनाम सिंह अकाली पार्टी के नहीं, अकाली ग्रुप के लीडर हैं तो अपोज़ीशन के एक दोसत गोगोआनी साहिब उठे और कहने लगे कि कामरेड राम प्यारा* × × × उन्होंने उस मैम्बर साहिब की तौहीन की है और ये लफ़्ज़ कार्यवाही से हज़्फ किए जाएं (शोर)

उपाध्यक्षा : गोगोआनी साहिब, क्या आपने ऐसा कहा है ? (Did the hon. Member Shri Gogoani say so?)

ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਗੋਆਣੀ : ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 15 ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ। ਜੇਕਰ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਐਨੇ ਬੜੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਿਡੀਕਿਊਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਾਂ (ਸ਼ੋਰ)।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ * × × × ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲਉ। (The hon. Member is an old man and he should not compete with the younger ones. If he has used the words × × × then he should withdraw them.)

*Expunged as ordered by the Chair.

ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਉਹ ਗਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਿਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰੁਪਿਆ ਇਕਠਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਰੁਪਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੀਲੀਫ ਲਈ ਇਕਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਨਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਉਪਰ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਵਿਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਸਟੇਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੁਨਾਂਚਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਥ ਤਾਕਤ ਆਈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੱਲੀ, ਗੁੱਲੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਲਥ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਲੋਕ ਦਬੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਉਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚ ਘੁਲ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਤਨੇ ਹੀ ਤਾਕਤਵਰ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਮਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰਖਕੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਮੀਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਲਿੰਗ ਲਗਾਈ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਸੀਲਿੰਗ ਲਗਾਈ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੀਲਿੰਗ ਲਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮਦਨੀ ਤੇ ਵੀ ਸੀਲਿੰਗ ਲਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲਿਮਿਟ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਤੇ ਲਿਮਿਟ, ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇਹ ਭਾਰੀ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ। ਇਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦਾ ਤਬਕਾ ਵੀ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਕਢਿਆ। ਉਸ ਉਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬਹਿਸ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਉ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਚੁਨਾਂਚਿ ਗਰੀਬ ਬਿਰਲਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟਸ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਕੇ ਉਚਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਦਮ ਅਗੇ ਤੋਂ ਅਗੇ ਹੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੁਸਾਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਰਲਾ ਫਾਰਮ ਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਪਾਸ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਿਵਾਏ ਇਕ ਮਨਿਸਟਰ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਿਆ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਚਾ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਚਾ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਸਖਤ ਵਿਪ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਰੈਵੀਨੀਉ ਮਨਿਸਟਰ ਇਕਲੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕਲੇ ਹੀ ਸਵਾ ਲੱਖ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ : ਰਵਾਇਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰ ਹਹੇ ਹਾਂ ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਵਾਇਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਦਿਲ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਫ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ, ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਖੁਦ ਬੜੇ ਮਜਬੂਤ ਹਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਚੰਗਾ ਭਾਰੀ ਜਿਸਮ ਵੀ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥਲੇ ਦਬਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਵਰਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਵਰਟੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕਢਿਆ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠਾਂ ਦਬੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੀਲਿੰਗ ਲਗਾਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਤੇ ਸੀਲਿੰਗ ਲਗਾਈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ ਮਰੇ ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 9 ਰਤਨ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ 9 ਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਲਭਿਆ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੀਲਿੰਗ ਲਾ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਆਮਦਨ ਤੇ ਸੀਲਿੰਗ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਤਕ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ । ਫੇਰ ਇਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਇਕ ਏਕੜ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਸ ਉਤੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਸ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾਂ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਡੇ ਵਡੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਵਡੇ ਵਡੇ ਆਦਮੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸੈਸ ਲਿਆ ਜ਼ਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਤਾਂ ਗਲ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਇਹ ਕਮਰਸ਼ਲ ਕਰਾਪਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਹਨ ਗੰਨਾ ਮਿਰਚਾਂ ਅਤੇ ਕਪਾਹ । ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪਾਸ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਅਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਉਹ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ ਬੀਜੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪੁਜ ਸਕੇ । ਮਗਰ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲਿਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਸਰ ਜਿਸ ਨੇ ਹਰ ਇਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਕ ਜੈਸਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਆਦਮੀ ਉਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੰਨਾ ਮਿਰਚਾਂ ਜਾਂ ਕਪਾਹ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ।

ਫੇਰ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਖੰਡ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ । ਖੰਡ ਦੀ ਡਿਸਟਰੀ-ਬਿਊਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਦ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਆਏ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਗੰਨਾ ਬੀਜਣ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਚੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ । ਸ਼ਕਰ ਗੁੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਕੇ ਖਾਣ ਦਿੰਦੇ । ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਤਨ ਮਨਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਮਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਹਲੂਣਾਂ ਦੇ ਕੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, 70—80 ਫੀ ਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸ 80 ਫੀ ਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਵੇ-ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਆ ਨਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤੀ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜੇ ਦੇ ਹੇਠ ਦਬਾ-ਇਆ ਗਿਆ ਰੋਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਕਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਮਕਾਨ

Deputy Speaker : Sardar Gurnam Singh.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : (ਰਾਏ ਕੋਟ) ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਕਮਰਸ਼ਿਅਲ ਕਰਾਪਸ ਸੈਸ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਬਿਲ, 1965 ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਹੈ..........

(ਸ਼ੋਰ ਵਿਘਨ)

कामरेड राम प्यारा : ग्रान ए प्वायंट ग्राफ ग्रार्डर, मैडम । डिप्टी स्पीकर साहिबा, सरदार गुरनाम सिंह ने कमरशियल क्राप्स सैस बिल पर स्पीच करनी शुरू कर दी है । मैं उनकी स्पीच के खत्म होने तक इन्तजार नहीं कर सकता हूँ । मेरा प्वांयट ग्राफ ग्रार्डर रेज़ करने का ग्रधिकार है । इस लिए मुझे प्वांयट ग्राफ ग्रार्डर रेज़ करने की इजाजत होनी चाहिए........
(शोर) (विघ्न)

उपाध्यक्षा : मुझे नाखुशग्वार काम करने के लिए मजबूर न किया जाए । Please take your seat. (I may not be compelled to perform the unpleasant duty. Please resume your seat.)

कामरेड राम प्यारा : ग्रान ए प्वायंट ग्राफ ग्रार्डर, मैडम । डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं ग्रर्ज़ करना चाहता हूं कि.........(शोर)

Deputy Speaker : Please take your seat. No noise please.

कामरेड राम प्यारा : ग्रान ए प्वायंट ग्राफ ग्रार्डर, मैडम । मुझे प्वायंट ग्राफ ग्रार्डर रेज़ करने का ग्रधिकार है ।

Deputy Speaker : Comrade Ram Piara, I request you to take your seat. I will listen to you.

कामरेड राम प्यारा :* × × ×

ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਗੋਆਣੀ : * × × (ਸ਼ੋਰ) (ਵਿਘਨ)

उपाध्यक्षा : सरदार जगजीत सिंह गोगोग्रानी ग्रौर कामरेड राम प्यारा मेरे दोनों भाई हैं । मैं उनको ग्रपने चैम्बर में बुलाऊंगी । पहले उनकी बातों को सुनूंगी ग्रौर उसके बाद फैसला दूंगी । क्या दोनों का मेरे ऊपर इतबार नहीं है ? There must be some decency and decorum of the House. (Sardar Jagjit Singh Gogoani and Comrade Ram Piara both are my brothers. I shall call them in my Chamber. I shall first hear them and give my decision after that. Have both of them not confidence in me? There must be some decency and decorum of the House.)

**Note*.—Expunged as ordered by the Chair.

कामरेड राम प्यारा : * * * * *

(हाउस में काफी शोर था और कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था)

Deputy Speaker : Then I adjourn the House for 15 minutes.

(इस समय हाउस 15 मिनट के लिए एडजर्न हुआ)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਸ਼ਲ ਕ੍ਰਾਪਸ ਸੈਸ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿਲ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਬਿਲ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰਚ, 1966 ਤੋਂ ਅਗੇ ਇਹ ਸੈੱਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਹੁਣ ਵੀ ਕਮਰਸ਼ਲ ਕ੍ਰਾਪਸ ਦਾ ਸੈੱਸ ਮਾਰਚ 1966 ਤਕ ਜਾਰੀ ਹੈ । ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵਜਾ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰਥ ਫਾਈਵ ਯੀਅਰ ਪਲਾਨ ਲਈ ਰੁਪਿਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਉਪਰ ਕਾਇਮ ਰਹੇ । ਜੇ ਕਰ ਕੋਈ ਐਗ੍ਰੀਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਇਕ ਆਦਮੀ ਵਿਚ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਜਾਂ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਮੁੱਕਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਉਸ ਕਰਕੇ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਜੇ ਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਅਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਨਾਮੰਜ਼ੂਰ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਵਰਨਾ ਇਕ ਇਟਰ-ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਪ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਗੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਹਿਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਕ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਗਲ ਹੈ । ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਨਮੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ । ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੂਲ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨਸ ਕੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਉਹ ਦੇਵੇ ਉਸੇ ਉਪਰ ਅਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਅਟਾਨਮੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ । ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਫੋਰਥ ਫਾਈਵ ਯੀਅਰ ਪਲਾਨ ਵਾਸਤੇ ਰੁਪਿਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਨ-ਸਿਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਲਾਨ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਉ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲੋਂ ਰੁਪਿਆ ਲੈ ਸਕੋ । ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੜਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ? ਪਰ ਗਲ ਉਹੋ ਹੈ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ । ਇਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਗੜੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਿਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜਰੂਅਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਕਿੰਨਾ ਇਰੀਟੇਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੀਲੀਫ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਰੁਪਿਆ ਇਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿਲੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ । ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਸਾਡੀ ਇਤਲਾਹ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ

*Note : Expunged as ordered by the Chair vide ruling at page (24)52 infra

ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ 80 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਅਗਲੇ ਰੋਜ਼ ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਨੇ ਬਿਰਲਾ ਫਾਰਮ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਹਿਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਲਫਜ਼ ਕਹੇ ਉਹ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਰਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ :—

> "A vast majority of the farmers own uneconomic holdings and unless they could increase their yield, there was no chance of improving their economy."

ਇਹ ਲਫਜ਼ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕਹੇ ਜਦ ਕਿ ਬਿਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਰਾ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ " A vast majority of the farmers own uneconomic holdings" ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 80 ਫੀਸਦੀ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਲਡਿਗ ਪੰਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਏਕੜ ਤਕ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਭਾਰ ਸਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ? ਮੈਂ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਮਨਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ, ਪਬਲਿਕਲੀ ਵੀ ਇਹ ਗਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜ ਤੋਂ ਦੱਸ ਏਕੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮਰ ਇਸ ਸੈਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ ? ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਤੇ ਅਪਣੇ ਬਾਲ ਬਚਿਆ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ਲ ਕਰਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮਿਰਚਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ਲ ਕਰਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਵਿਚ ਕਿਤਨੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਉਗਦੀਆਂ ਹਨ ? ਕੀ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਏਰੀਏ ਦਾ ਅਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ? ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਇਸ ਤਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ? ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੈਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਕ ਪਥੱਰ ਨਾਲ ਦੋ ਪਰਿੰਦੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਲਿਆ ਛੋਟੇ ਜਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਲਿਆ ਔਰ ਹਰੀਜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਪਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਕਾਮਿਯਾਬੀ ਕਰ ਲਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲ ਤਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਜਮੀਨ ਉਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾ ਹੈ ਉਹ ਘਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗਲ ਸਪਸ਼ਟ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ 75 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਥਲੇ ਦਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਫਾਇਡਿੰਗ ਹੈ। 75 ਫੀਸਦੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ; ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ, ਫਾਰਮਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ 5-10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਤਸੀਂ ਇਹ ਵਾਜਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਇਹ ਸੈਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ? ਮੈਂ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੀ ਛਡਦਾ ਹਾਂ। ਕਲ ਹੀ ਇਥੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਇਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉਤੇ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਫਾਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਅਪਣਾ ਵਤੀਰਾ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਸਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮਾਂ ਵਡੀਆਂ ਵਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿਤੀ

[ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ]

ਹੈ ਕਿ ਉਥੋਂ ਦੇ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਹਮਸਾਏ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ ਛੋਟੀ ਫਾਰਮ ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਫਾਰਮ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਣੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਇਕਨਾਮਿਕ ਹੋਲਡਿੰਗ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬਿਰਲਿਆਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਇਥੇ ਅਨਇਕਨਾਮਿਕ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਹਨ ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨਇਕਨਾਮਿਕ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਸੈਸ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹਨ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਸ ਬਿਲ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨੋਟਿਸਿਜ਼ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ ਔਰ ਉਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘਟ ਦੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਉਤੇ ਇਹ ਸੈਸ ਨਾ ਲਗੇ । ਬੇਹਤਰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜ ਏਕੜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਸ ਦੀ ਛੂਟ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗਲ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜ ਏਕੜ ਵਾਲੀ ਲਿਮਿਟ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਕਿ ਹਰੀਜਨ ਵੀ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਹੈ । ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਹਰੀਜਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਇਸ ਬਿਲ ਤੇ ਰਵੀਏ ਤੋਂ ਸਾਫ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਏਗਾ ।

ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਇਸ ਬਿਲ ਉਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੋਹਾਂ ਤਰਫ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਹਨ । ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਆਦਾ ਵਕਤ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਰੈਵਿਨੀਉ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਇਸ ਸੈਸ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਤਾਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜ ਏਕੜ ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣ । ਦੂਸਰੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਮਝਾਂਗਾ ਜੇ ਇਸ ਨੇ ਪਲੈਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਇਸ ਚੀਜ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਜੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਟੈਕਸ ਜੇਕਰ ਲਗਾਣੇ ਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਲਗਾਉ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਪਲੈਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ? ਚੌਥੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਪਲੈਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਇਕ ਮਜਬੂਤ ਕੇਸ ਹੈ ਇਸ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਦਾ ਐਸਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ । ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰਖ ਸਕੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਾਲਤ ਦਾ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਗੁਜਰਿਆ ਹੈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕੇ ਮੈਂ ਨਾਜਾਇਜ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਨਿਸਟਰੀ ਵਿਚ ਉਹ ਦਲੇਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾਕੇ ਸਾਫ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕਹ ਕਿ ਲੜਾਈ ਦੀ ਵਜਾਹ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਲੈਨ ਵਿਚ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਫਰਜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਲੈਨ ਵਾਸਤੇ ਰੁਪਿਆ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ । ਇਹ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਇਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੜਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕ ਮੁਲਕ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਲੜੀ । ਇਹ ਕੋਈ

ਲੋਕਲ ਗਲ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਪੰਜਾਬ ਚੂੰਕਿ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿਸਾ ਪਾਇਆ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ । ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਮਰਦਾਂ ਔਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਬੁਢਿਆਂ ਔਰ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਉਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਦ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਉਸ ਦਾ ਮੁਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਗਏ । ਪਹਿਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿਤਾ । ਹੁਣ ਕਮਰਸ਼ਲ ਕ੍ਰਾਪਸ ਉਤੇ ਸੈਸ ਲੈ ਆਏ ਹਨ ।

ਇਕ ਆਵਾਜ਼ : ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿਤਾ ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਟੈਕਸ ਹੀ ਟੈਕਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਠੀਕ ਹੈ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਵੀ ਹੈ । ਉਹ ਵੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਤੇ ਹੀ ਲਗਦਾ ਹੈ । ਜੋ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਹੈ ਉਸ ਉਤੇ ਨਹੀ ਲਗਦਾ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਉਤੇ ਹੀ ਲਗਦਾ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬਾਬਤ ਵੀ ਇਥੇ ਸਤ ਦਿਨ ਤਕ ਕਿਤਨਾ ਝਗੜਾ ਪਿਆ । ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਗਰੀਬ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਹੈ । ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਉਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਤਬਕਾ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਦੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ । ਇਹ ਗੂੰਗੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪੁਜਦੀ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ।

ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੀਪਰੀਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੂੰਗੇ ਨੇ ਔਰ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਤਬਕੇ ਕੋਲੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਇਥੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀ-ਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਇਕ ਲਫਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਖੁਦ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੈਸ ਟੈਕਸ ਬਿਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਣਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤਬਕੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬੋਲਣਗੇ ਔਰ ਖਿਲਾਫ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ ।

ਮੈਂ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਬਕੇ ਤੇ ਇਹ ਟਕਸ ਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਤਨੇ ਟੈਕਸ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਣ ਕੇ ਦਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਔਰ ਇਹ ਗਿਣ ਕੇ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਦਾ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ । ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ 11 ਕਿਸਮ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ 11 ਕਿਸਮ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਤੱਸਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੋ ਹੁਣ ਇਹ ਸੈਸ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਨਾ ਲਗਾਉ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸੈਸ ਟੈਕਸ ਤੇ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਵਰਨਾ ਸੈਂਟਰ ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਆਬਿਆਨਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਸ਼ਕ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿਓ ਔਰ ਅਬਿਆਨਾ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿਓ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਤਾਕਿ ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਔਰ ਮੁਰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਉਠੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਔਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲ ਤਾਂ ਪੈ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਂਦੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸ ਸੈਸ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਮੈਂ ਮੇਜਰ

[ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ]

ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਟੈਸ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਨਾ ਲਗੇ । ਅਵਲ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਨਾ ਲਗਾਓ ।

उपाध्यक्षा : पेशतर इस के कि मैं किसी आनरेबल मेम्बर को काल अपौन करूँ मैं यह कहना चाहती हूं कि आज कामरेड राम प्यारा और सरदार गोगोवानी में जो वादविवाद हुआ है, उस के लिए मुनासिब तो यही था कि इस को वे दोनों वापस ले लेते लेकिन क्योंकि वह इस को वापस लेने के लिए तैयार नहीं हुए मैं इस वाद विवाद को हाउस की प्रोसीडिंज़ में से एक्सपंज कर देती हूं ।

अब जिन की एमेंडमैंट्स हैं पहले वह बोलेंगे । कामरेड गुरबख्श सिंह--
(Before I call upon any other hon. Member to speak I want to say that it would have been better if the remarks exchanged to-day between Comrade Ram Piara and Sardar Gogoani were withdrawn by both of them, but since they did not agree to withdraw them, I expunge those remarks from the proceedings of the House.

Now those hon. Members will speak first who have given notices of amendments).

ਕਾਮਰੇਡ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ : ਬੀਬੀ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੈ ।

उपाध्यक्षा : सारी एमेंडमेंटस मेरे सामने हैं । (All the amendments are before me).

ਕਾਮਰੇਡ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ : ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਟੇਕ ਅਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਉਪੀਨੀਅਨ ਲਈ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ--

उपाध्यक्षा : सब को बोलने का मौका मिलेगा । जिन की एमेंडमेंट्स हों पहले उन को बोलने दें । (All the hon. Members who would like to take part in the discussion of this Bill will be given time. Firstly those Members would be allowed who have given notices of Amendments).

चौधरी राम सरूप : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडम । मेरा प्वायंट आफ आर्डर यह है कि जिस वक्त बिल पर कलाज़ बाई कलाज डिस्कशन हो उस वक्त जिन लोगों ने एमेंडमैंट्स का नोटिस दिया हुआ होता है, उन को टाईम देना जरूरी होता है लेकिन फर्स्ट स्टेज पर तो हरेक मैम्बर को बोलने का हक हासल होता है--

उपाध्यक्षा : इस वक्त पब्लिक उपीनीअन लेने की एमेंडमेंट्स आई हुई हैं । (But there are amendments for the circulation of this Bill for eliciting public opinion.)

चौधरी राम सरूप : वह ठीक है । अगर पब्लिक उपीनियन के लिए या किसी कमेटी के सुपुर्द करने की एमेंडमेंटस हैं वह तो पहले ली जा सकती है लेकिन दूसरी एमेंडमेंटस पहली स्टेज पर नहीं ली जाती ।

उपाध्यक्षा : कामरेड गुरबख्श सिंह, आप जरा अपनी अमेंडमेंट को पढ़ दें ताकि इन को पता लग जाए । (Comrade Gurbaksh Singh may please read out his amendment so that Chaudhri Ram Sarup comes to know about it.)

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ (ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ।

I beg to move—

That the Punjab Commercial Crops Cess (Amendment) Bill, 1965, be circulated for eliciting public opinion thereon by the 31st December, 1965.

ਮੇਰੀ ਇਹ ਜੋ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰਕ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਕਰ ਲਗਾਣ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਸੋਧਨਾ ਬਿਲ ਹੈ ਜੋ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਬਿਲ ਅਜ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵਰਹੇ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅੱਜ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਇਥੇ ਸਨ ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚੀਨ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਲ ਮੰਤ੍ਰੀ ਸਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਹੋ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੀਜੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਥੁੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਨ ਲਈ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਿਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਅਜ ਫਿਰ ਮੇਜਰ ਸਾਹਬ ਨੇ ਉਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਚੌਥੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਕਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੋਧਨਾ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਅਜ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਪਤਾ ਲਗ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਮੋਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੈਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾਂ ਔਰ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖੈਰ ਖਾਹ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੀ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸੋਧਨਾ ਬਿਲ ਲੈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ । ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿਆਂਗਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਇਹ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ

(ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ)

ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਨਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਨੀ ਦੀ ਪਾਲਸੀ ਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਉਸੇ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਣ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਰ ਲਗਾਣ ਲਈ ਸਾਥੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਲਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰਾਣ ਲਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹੋ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਇਸ ਸੋਧਨਾ ਬਿਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੇ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਹ ਜੋ ਸੋਧਨਾ ਬਿਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜ ਤੋਂ 2½ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸਦੇ ਘੁਸ ਬੈਠੀਏ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਘੁਸ ਆਏ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਹਾਦਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਫੌਜ ਵਿਚ ਹਰ ਤੀਜਾ ਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਜਾਬੀ ਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ 90 ਫੀਸਦੀ ਫੌਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਜਰਨੈਲ ਹੋਵੇ (ਤਾੜੀਆਂ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਰਹਦ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡਾਂਗਾਂ ਅਤੇ ਸਲਗਾਂ ਫੜ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਛਾਤਾਬਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ। ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਫੌਜ ਵਿਚ ਬਹਾਦਰੀ ਲਈ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮ ਵੀਰ ਚਕਰ, ਮਹਾਵੀਰ ਚਕਰ ਤੇ ਵੀਰ ਚੱਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿਚ ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਸੈਸ ਦਾ ਚੱਕਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਵਡੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਗੇ ਹੈ, ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅਗੇ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਬਜਾਏ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਮੈਯਰ ਨੂੰ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬਲਬੋਤੇ ਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਹੁਣ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਬਾ ਹੇਠ ਚੌਥੀ ਪਲੈਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਸ ਸਦਨ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਖਿੰਡਾ ਪੁੜਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਹੜ ਆਏ, ਪਾਲਾ ਪਿਆ ਮਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਟ ਕਟ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਸੇਮ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਖੁਸ਼ਕ ਸਾਲੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜ ਰਖੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰਕੁਦਰਤੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅੱਤ ਭੈੜੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੈਸ ਬਿਲ ਲਿਆਕੇ ਚੌਥੀ ਪਲੈਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ। (ਘੰਟੀ) ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਸਰਕੁਲੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਅਗਰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਛੁੱਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਦੂਜੀ ਗਲ..........

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਹਨ ? (How many more points has the hon. Member to raise ?)

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : ਦੋ, ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਹਨ । ਮੈਂ ਰਿਸੋਰਸਿਜ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਦਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕਿਥੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸੈਸ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਦਸਦਾ ਹਾਂ । ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਠ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਸਟੇਟ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਇਨ ਫੂਡਗਰੇਨਜ਼ । ਇਹ ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ । ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਟੇਟ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 70-75 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ । ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇਗੀ । (ਘੰਟੀ)

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ । (The other Members of his party are also to speak.)

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : ਹੋਰ 5 ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਇਕ ਮਿਨਟ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਉ । (The hon. Member may please mention some important points in a minute.)

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : ਇਹ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰੇ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਟ ਮਾਰਨ ਤੇ ਢਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ । ਸਾਡੇ ਜਨ ਸੰਘੀ ਭਰਾ ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬੈਂਕ ਨੈਸਨਲਾਈਜ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲਗੀ 25 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਫਾਲਤੂ ਮਹਿਕਮੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਕੁਝ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ । ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਲਾਇਆ ਪੈਸਾ ਬੇਕਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ

[ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ]

ਹਾਸਪੀਟੈਲਟੀ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜਦ ਕੋਈ ਮਅਜ਼ਿਜ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਤਨੇ ਦਿਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਹਿਕਮਾ ਰਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ।

ਫਿਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਗਰ ਟੋਟਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ । (ਘੰਟੀ)

ਫਿਰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਨਾ ਕਰਕੇ ਬਚਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਮਾਈਨਰ ਲਿਫਟ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮਜ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਧਾਰਥ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ 20 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ । ਮਾਸਟਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਐਮ. ਐਲ. ਸੀ. ਦੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਜ਼ਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ । (ਘੰਟੀ) ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ।

उपाध्यक्षा : इस तरह के आनरेबल मैम्बरज़ के लिये मुझे कुछ और ढंग निकालना पड़ेगा । एक मिनट में खत्म करें । (I will have to devise some method for such hon. Members. He should finish within a minute.)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : On a point of order, Madam. ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੇ ਬਹਿਸ 7 ਦਿਨ ਚਲੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿਹਾ । ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਇਕ ਇਕ ਘੰਟਾ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਚੇਅਰ ਅਤੇ ਕੈਬਨਟ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲੋ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਮੰਨੀਆਂ । ਮੈਂਬਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ । ਤਦ ਉਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਇਸ ਬਿਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵੀ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਹੈ । ਪੰਜ ਪੰਜ ਮਿਨਟ ਦਾ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਘਟ ਹੈ.....

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ? ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਚੇਅਰ ਤੇ ਹੋਵਾਂਗੀ ਅਤੇ ਸਭ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾਂਗੀ ।

ਮੈਂ ਇਕ ਗੱਲ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ । ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ । ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 22-23 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਬੈਠੇ । ਇਥੇ ਕੁਝ ਸਜਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਲ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਕਲ ਸਭਾ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ 2 ਵਜੇ ਮਿਲੇ ਤਾਕਿ ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਣ । ਕੀ ਹਾਊਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ? (How does the hon. Member say that this Bill will not be discussed and no Member will be allowed to speak on it. Unlimited time will not

5.00 p. m.

be allowed but when I am in the chair I will do justice with every one.

I want to ask one thing from the House. I do not like that a decision should be changed time and again. The Business Advisory Committee decided that the House should also meet on the 22nd and 23rd instant as some of the hon. Members have requested that they want to have a dip in the sacred tank on account of Solar Eclipse and they want that Sabha may meet at 2 p.m. instead of 9 a.m. Is it the sense of the House?

ਆਵਾਜ਼ਾਂ : ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਜੀ ।

ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ : ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲ ਬੇਸ਼ਕ 2 ਵਜੇ ਮੀਟ ਕਰ ਲਉ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੈੱਸ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਊਸ ਕਲ ਬੇਸ਼ਕ 2 ਵਜੇ ਮੀਟ ਕਰੇ ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਮੈਡਮ । ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਬਿਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਤ ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਬਿਲ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ । ਤੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕੈਸ਼ ਕਰਾਪ ਸੈਸ ਬਿਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਕੋਈ ਟਾਇਮ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਇਹ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਬਿਲ ਹੈ (ਵਿਘਨ)

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਲੈਣਾ । ਪਰ ਇਸ ਗਲ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਲ ਅਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਮੀਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰ ਆਉਣਗੇ । ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਜਦ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ । ਕੀ ਹਾਊਸ ਦੀ ਸੈਂਸ ਹੈ ? (The hon. Member may say these points when he is given time to speak on the Bill. Now the matter before the House is that we should meet at 2 p.m. tomorrow in order to give facility to the hon. Members who want to have a dip tomorrow morning on account of the Solar Eclipse. After that I am ready to sit till the hon. Members want. Is it the sense of the House?)

ਆਵਾਜ਼ਾਂ : ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਕਲ ਹਾਊਸ 2 ਵਜੇ ਮੀਟ ਕਰੇ । ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 9 ਵਜੇ ਹੀ ਮਿਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ।

ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੰਤਰੀ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਊਸ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਥੇ ਆਮ ਰਾਏ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਾਰ ਬਾਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫਿਸਿਜ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਹਾਊਸ 9 ਵਜੇ ਹੀ ਇਸ ਦਿਨ ਵੀ ਮੀਟ ਕਰੇ ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਪਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਬਲਰਾਮਜੀ ਦਾਸ ਟੰਡਨ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਹਾਊਸ ਉਸ ਵਕਤ ਮੀਟ ਕਰ ਲਏ ਜਦ ਕਿ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਣ ਦਾ ਵਕਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇਕ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ 2 ਵਜੇ ਮੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਊਸ ਐਗਰੀ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਕਤ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਦ 10 ਵਜੇ ਮੀਟ ਕਰ ਲਉ ।

ਕਾਮਰੇਡ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਮੈਡਮ । ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਲ ਹਾਊਸ 9 ਵਜੇ ਮੀਟ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਰਖਣਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਲ 2 ਵਜੇ ਨਹੀਂ ਮੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਸਵੇਰੇ ਮੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜਦ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਬਿਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤਕ ਇਸ ਤੇ ਬਹਿਸ ਚਲਦੀ ਰਹੀ । ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਲ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਲ ਹਾਊਸ 9 ਵਜੇ ਹੀ ਮੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਲ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿਉ ਅਤੇ ਪਰਸੋਂ ਫਿਰ ਮੀਟ ਕਰ ਲਉ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਪਰ ਇਕ ਹੋਰ ਸੋਹਣੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਹੈ ਢਿਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਕਿ 10 ਵਜੇ ਮੀਟ ਕਰ ਲਉ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਕ ਚਾਹੋਗੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾਂਗੀ । ਕੀ ਹਾਊਸ ਦੀ ਇਹ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਕਲ ਹਾਊਸ 10 ਵਜੇ ਮੀਟ ਕਰੇ ? (Another good suggestion has come from Sardar Dhillon that the House may meet at 10 a.m. tomorrow. I can then sit till the hon. Members want me here. Is it the sense of the House that the House should meet at 10 a.m. tomorrow ?)

Voices : Yes, yes.

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਹਾਊਸ ਸਵੇਰੇ 10 ਬਜੇ ਮੀਟ ਕਰੇਗਾ । (The House will meet at 10 a. m. tomorrow.)

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਮੈਡਮ । ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲ ਦੀ ਬਹਿਸ ਤੇ ਇਕੋ ਵਕਤ ਬੋਲੋ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਬਿਲ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਟਾਇਮ ਲਿਮਿਟ ਕਿਸੇ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਬਿਲ ਤੇ ਕਿਉਂ ਟਾਇਮ ਲਿਮਿਟ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਦ ਤਕ ਮੈਂਬਰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

Deputy Speaker : Comrade Gurbaksh Singh, please wind up now.

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : ਮੈਂ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਹ ਅਰਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧਨਾ ਬਿਲ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਫ਼ਰੇਮ ਵਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੇ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਰਰੇਲੈਵੇਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਵਕਤ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜਬਾਤ ਨੂੰ ਇਥੇ ਪਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮੈਂ ਕਹਿਣੇ ਹਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਲੈਣ ਦਿਤੇ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ਉਹ ਨਿਰੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਪਿਉਰਲੀ ਕਿਸਾਨ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਫਾਲਤੂ ਕਹਿ ਦਿਤੀ ਜਾਂ ਰੀਪੀਟ ਕਰ ਦਿਤੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ਕ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਣਾ। (ਵਿਘਨ)

ਮੈਂ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਿਫਟ ਸਕੀਮ ਤੇ ਕਾਂਗੜੇ ਵਿਚ 30 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੋਰੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਰਾਜੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਬ ਖਰਚ ਲਈ ਲਖਾਂ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਿਵੀ ਪਰਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਂਗੜਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 1845 ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਗੀਰ ਦਿਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜਗੀਰ ਅਜੇ ਇਸ ਰਾਜੇ ਪਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਇਕ ਲੱਖ 80 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1 ਲਖ 45 ਹਜਾਰ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਜਗੀਰ ਦੀ ਬਚਤ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਗੀਰ ਵਿਚ ਫਲ ਆਦਿ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਆਪ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁਫੈਦ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਇਥੇ ਰਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਿਠ ਪੂਰੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਗੀਰਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਾਪ ਸੈਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਰਾਜੇ ਕਾਂਗੜੇ ਦੀ ਜਗੀਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੇ ਟੇਡੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਤੇ ਭਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। (ਘੰਟੀ)

ਮੈਂ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਆਪ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਛੇਤੀ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਜ ਆਪ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਹੋ। (ਵਿਘਨ)

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ: ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਫਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਉ। (The hon. Member should please withdraw this word.)

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : ਮੈਂ ਇਸ ਲਫਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ।

ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਸਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 80 ਫੀ ਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਬਹਿਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਦੋ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਰਖੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਕਿ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤ ਦਿਨ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਤੇ ਬਹਿਸ ਲਈ ਕੇਵਲ ਦੋ ਦਿਨ ਹੀ ਰਖੇ ਜਾਣ। (ਘੰਟੀ) ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸ਼ਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਹੁੱਕਮ ਮੰਨਦਾ ਹੋਇਆ ਅੰਤ ਵਿਚ ਐਨੀ ਗਲ ਹੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਧਨਾ ਬਿਲ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਠੰਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮ ਰਾਏ ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਮਰੇਡ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਇਹ ਰਾਏ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਰਲੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਹਥ ਧਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਤ ਨਹੀਂ। ਅਜ ਬਿਰਲੇ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਲ ਥਾਪਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਰਤਖ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਅਤੇ ਥਾਪਰ ਤੇ ਬਿਰਲਿਆਂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਤਰਮੀਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਉਪੀਨਅਨ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇ! ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ 1965 ਤੱਕ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਜੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

Deputy Speaker: Motion moved—

> That the Punjab Commerical Cess (Amendment) Bill, 1965, be circulated for eliciting public opinion thereon by the 31st December, 1965.

चौधरी राम सरूप : मेरा पवायंट आफ आर्डर यह है, डिप्टी स्पीकर साहिबा, कि आप हमारे से ज़्यादती ना करें। आप कहते हैं कि कल की सिटिंग के लिये बिज़ीनैस एडवाइज़री कमेटी ने फैसला किया है, मगर आप को तो पता ही है कि इसी सैशन में बिज़नैस एडवाईज़री कमेटी के फैसले तीन-तीन बार बदलने पड़े हैं। आप को हमारे जज़बात को तो समझना चाहिये था। यह हमारी ज़िंदगी और मौत का सवाल है!

उपाध्यक्षा : आप बैठिए। आपको इस बात को ऐप्रीशियेट करना चाहिये कि मेरे पास आपकी दरखास्त छुट्टी के लिये 4 दिन से आ रही है कि इस दिन हाऊस मुलतवी हो मगर यह आप फैसला उस कमेटी से करवा सकते थे, इस हाऊस में नहीं। उनहों ने 9 की बजायें 10 बजे करने को कहा मैं ने वह अनाऊंस कर दिया। (The hon. Momber may please resume his seat. He should have appreciated that request for observing an off day tomorrow has been continuously coming to me for the last four days. But this decision could have been taken by the Business Advisory Committee and not by this House . A suggestion came for changing the time of the sitting to 10 A. M. instead of 9 A. M. tomorrow. I have announced the decesion accordingly after taking the sense of the House.)

चौधरी राम सरूप : आप किस रूल के तहत मुझे बैठने को कहती है। मैं आपका हुकम मानने से इनकार तो नहीं करवा सकता मगर यह बात कहे बगैर नहीं रह सकता कि अगर इस तरह हमारे हकूक पर छापा मारा गया तो हम बरदाशत नहीं करेंगे।

Deputy Speaker : I would request the Honourable Member to take his seat.

Sardar Gurcharan Singh On a point of order, Madam.

Deputy Speaker Please take your seat. इस तरह बार बार पवायंट आफ आर्डर करने का क्या मतलब है ? (Please take your seat. What is the purpose of rising on a point of order time and again ?)

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ 2-2 ਘੰਟੇ ਤਕ ਅਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿਲ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘੰਟੀਆਂ ਵਜਣ ਲਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਇਤਨਾ ਅਹਿਮ ਬਿਲ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ: ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੌਜ਼ੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਬਹਿਸ ਨਾ ਵਧਾਉ। ਜੋਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਮੂਵ ਹੋਣ ਦਿਓ (This is not the matter under discussion now. The hon. Member should not prolong the discussion, Let comrade Josh move his amendment.)

Comrade Shamsher Singh Josh : Madam, I beg to move—

That the Punjab Commercial Crops Cess (Amendment) Bill, 1965, be circulated for eliciting public opinion thereon by the 31st December, 1965.

(ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼)

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮੈਂਡਿੰਗ ਬਿਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਗੋਚਰੇ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲ ਕੈਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੇਲੇ 1962 ਦੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨ ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੀ 6 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਟੀਚਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਦਾ ਢਾਈ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਤਾਂ 31 ਮਾਰਚ, 1966 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਪਈ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ? ਇਹ ਟੈਕਸ ਤਿੰਨ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਇਕ ਗੰਨਾ, ਇਕ ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਇਕ ਮਿਰਚ ਤੇ ਲਗੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ 14,27,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਪਾਹ ਬੀਜੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ 64 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿ ਗੰਨਾ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 66 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਜੋ ਮੰਤਵ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ :—

> "As one of the measures to find additional resources for the Fourth Five-Year Plan, it is proposed to continue for the Fourth Plan period the cess on Commereial Crops, levied under the Punjab Commercial Crops Cess Act, 1963, which is valid up to the kharif harvest of the agricultural year 1965-66. Hence this Bill".

ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਇਹ ਟੈਕਸ ਹੋਰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਯਾਨੀ 10 ਫਸਲਾਂ ਤੇ। ਕੈਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 10 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਲ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਫੌਰਥ ਫਾਈਵ-ਯੀਅਰ ਪਲੈਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਲਈ ਇਹ ਰੁਪਿਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰੁਪਿਆ ਜੋ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਲਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲ ਸ਼ੂਗਰਕੇਨ, ਗੰਨੇ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਤੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਂਪਰ ਦਾ ਕਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਗੰਨਾ ਘੱਟ ਬੀਜਣ ਲਗ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਦੂਜੀ ਫਸਲ ਬੀਜ ਲਓ ਗੰਨੇ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ

ਗੰਨਾ ਨਹੀਂ ਬੀਜੇਗਾ । ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੂਗਰ ਦੀਆਂ ਮਿਲਾਂ ਦੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਡਿਉਰੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਸੀ, ਖੰਡ ਥੋੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਗੰਨਾ ਘੱਟ ਬੀਜਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਗੰਨਾ ਕਿ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਮਿਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸੂਗਰ ਦੇ ਵਡੇ ਵਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟਸ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੂਗਰਕੇਨ, ਗੰਨੇ ਦਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਡੈਂਪਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਗਰ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ । ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਇਹ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਚੌਥੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਰਿਸੋਰਸਿਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਪਲੈਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਪਲੈਨ ਲਈ ਸਰਮਾਇਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਪਿਆ । ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਬੋਝ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਚੁਕਿਆ । ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਬਾਕੀ 46 ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 2 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਅਗਰ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਰਲਾ ਲਵੇ, ਸਾਡੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਅਤੇ ਇਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ । ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀ ਪੰਜ ਵਰਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰਾਂਟ ਮਿਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਪੰਜ ਵਰਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ । ਚੌਥੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਨੈ ਕਰੇ ਕਿ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਉਸ ਅਨੁਛੇਦ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਮਦਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਜਿਵੇਂ ਜਵਾਨ ਲੜਦਾ ਹੈ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ । This is the second battle front after the battle front on our borders, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਫੋਰਥ ਫਾਈਵ- ਯੀਅਰ ਪਲੈਨ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਤੇ ਘੱਟ ਬੋਝ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਘੱਟ ਬੋਝ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਨੇ ਬੈਟਲ ਫਰੰਟ ਦਾ ਬੋਝ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਉਗੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਟੈਕਸ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ 14 ਟੈਕਸ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵਿਨਿਊ ਐਕਟ, 1887 ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਮਾਲੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ । ਦੂਜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵਿਨਿਊ ਸਰਚਾਰਜ ਐਕਟ, 1954 । ਤੀਜਾ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵਿਨਿਊ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਐਕਟ, 1955 । ਚੌਥਾ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵਿਨਿਊ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਐਕਟ, 1958 । ਪੰਜਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵਿਨਿਊ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਐਕਟ । ਛੇਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1962, ਜੋ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਗਿਆ ਸੀ । ਸਤਵਾਂ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਲੈਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੀ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਅਠਵਾਂ ਵਾਟਰ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਪੇ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਨੌਵਾਂ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਚੁਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਦਸਵਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਚੁੰਗੀ

(ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼)

ਜੋ ਮਾਲ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਲਿਆਂਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਤੇ ਬਿਕਰੀ ਟੈਕਸ ਹੈ। 80 ਫੀ ਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 12 ਜਾਂ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਬਾਰਵ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਰਾਪ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ। ਡੀਫੈਂਸ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ 87 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਰੂਰਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਮਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਟ ਤੇ 13 ਟੈਕਸ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਜੱਟ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਭਵਿਖ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿਉਗੇ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਅਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਅੱਜ PL 480 ਦੇ ਹੇਠ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਦਾਣੇ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਣਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਨਾਉਣੀ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਰੈਲਾਇੰਟ ਸੈਲਫ ਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਅਤੇ ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੈਂਟ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰਿਸਟ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇਵੇ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਹਦ ਰਖੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਖਾਦ ਦੇਵੇ। ਉਸ ਤੇ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਕਰੇ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਸਬ ਭਾ ਦੇਵੇ। ਉਸ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਧ ਉਪਜਾਊ ਬਨਾਂਉਣ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵੇ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰਾਇਤ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਤੱਰਕੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ 14 ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਿਸੋਰਸਿਜ਼ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸੁਝਾਓ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫ਼ਾਈ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਟੈਕਸ ਲਾਉ। ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਟੈਕਸ—ਜ਼ਰਾਇਤ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 3,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤਕ ਜਿਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਵਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਲਾਵੇ। 5 ਏਕੜ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਥਲੇ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇੰਨਕਮ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ਼ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਾਲੀਆ ਨਾ ਲਵੇ, 5 ਤੋਂ 10 ਏਕੜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ 8 ਆਨੇ, 10 ਤੋਂ 20 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਤੋਂ 12 ਆਨੇ ਅਤੇ 30 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਕ ਰੁਪਿਆ ਬਿਘਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਹੁਜਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਥੋੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਟੈਕਸ ਸ਼ਰਾਹ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿਉ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ replace all these taxes on the peasantry by single agriculture income tax—ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸੋਰਸਿਜ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।

ਕਈ ਵਡੇ ਵਡੇ ਫਾਰਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਪਾਹ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਹ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੰਨਾ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਧ ਟੈਕਸ ਲਾਉ ਅਤੇ ਛੋਟਿਆਂ ਤੇ ਨਾ ਲਾਉ। 5 ਵਿਘੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਈ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਾਉ। 15 ਜਾਂ 20 ਜਾਂ 30 ਵਿਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਚੈਕ ਅਪ ਕਰੋ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਪੈਜ਼ੇਂਟ, ਥੋੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਵੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ। ਵਡੀਆਂ ਵਡੀਆਂ ਫਾਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਓ। ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਕਮ ਅਜ ਕਮ ਕੌਮਿਊਨਿਸਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੈਕ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਵਡੇ ਵਡੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਵਡੇ ਵਡੇ ਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਸੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਜ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮਿਡਲ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਲਾਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਪਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਉਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉ। ਅਜ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਅਤੇ ਵਾਟਰਰੇਟ ਨੂੰ ਦੁਗਣਾ ਕਰੋ ਔਰ ਅਗਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਲਗਾਉ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਾ ਫੜ ਲਉ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵਡੇ ਵਡੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਘਟ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪਾਰਟੈਂਟ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੋਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਰਾਏ ਜਾਨਣ ਲਈ ਪਰਕਾਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਤਕ ਤਾਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫ਼ਿਰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਜੇਕਰ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ we will resist those laws. We will fight against those laws. We will not tolerate such laws. ਅਸੀਂ ਫਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਚੁਣ ਕੇ ਏਥੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪਾਲਸੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। They will riselike one man and will fight the Government tooth and nail on every occassion if it fails to respond to the public opinion against it.

Revenue Minister : I would like to know from my hon. friend whether they are going to fight with bullets or through ballot ?

Comrade Shamsher Singh Josh : We will fight against the Government on this issue in the next general elections as also on every occasion and will even resort to direct action if the Government fails to respond to the public opinion against it.

Revenue Minister : Madam, the cat is out of the bag now.

Deputy Speaker : Motion moved—

That the Punjab Commercial Crops Cess (Amendment) Bill, 1965, be circulated for eliciting public opinion thereon by the 31st December, 1965.

Baboo Bachan Singh (Ludhiana—North) : I move—

That the Punjab Commercial Crops Cess (Amendment) Bill, 1965, be circulated for eliciting public opinion thereon up to the 31st January, 1966.

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮੂਵ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਕਤ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ । ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਵਕਤ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਉਪੀਨੀਅਨ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ਲ ਹੈ । ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਕ ਕਲਾਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਬਿਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਗੁੰਝਲ ਅਤੇ ਭੇਦ ਐਨੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਉਪੀਨੀਅਨ ਲਈ ਮੁਸ਼ਤਹਿਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਚੇ ਹਨ । ਇਕ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉਪਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾਂ ਬੋਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਰੂਲਿੰਗ ਸਰਕਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਸਰਕਲ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਟੈਕਸ ਲਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਰੈਵੀਨਿਊ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ਜਿਸ ਦੇ ਕਿ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਨਚਾਰਜ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਮੈਂ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । 30 ਸਤੰਬਰ, 1963 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰੀਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਹਲਾਂ ਹੇਠ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਇਕ ਕਰੋੜ 94 ਲਖ ਏਕੜ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 40,18,239 ਹੈ । ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਏਸੇ ਹੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਲਟੀਵੇਟਿਡ ਏਰੀਏ ਦੀ ਜਦ ਔਸਤ ਕਢਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ 4.7 ਏਕੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਐਤਕੀ ਦੇ ਬਜਟ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ 1954 ਦੇ ਫਿਗਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਸਤਾਂ ਕਢਣੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਨਿਹਾਇਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ । ਉਦੋਂ 1954 ਵਿਚ ਗੌਰਮਿੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ । ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 25 ਲਖ 84 ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਲਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 40 ਲਖ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਔਰ ਜੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਦਾ ਵੀ ਅਰਸਾ ਗਿਣੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ 45 ਲਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ

ਹੋਣ । ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਸੀ ? ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ 10 ਆਰਡੀਨਰੀ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਰਖਦੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 25 ਲਖ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ 10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ 20 ਤੋਂ 30 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਸਨ ਜਾਂ 100 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3 ਲਖ 84 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀ । ਜਿਹੜੇ 10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 69 ਲਖ 63 ਹਜਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 2.7 ਏਕੜ ਔਸਤਨ ਜ਼ਮੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਲਾਂ ਹੇਠ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਗਰ ਹਲ ਹੇਠ ਸਨ ਉਹ ਇਕ ਕਰੋੜ 92 ਲਖ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਸਨ । ਹੁਣ 1963 ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ 4.7 ਆਉਂਦੀ ਹੈ । ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ 7 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ 7 ਏਕੜ ਦੀ ਔਸਤ ਕਢਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਦਸ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ 2.7 ਏਕੜ ਆਉਂਦੀ ਸੀ । ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਿਗਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ 4.7 ਦਸਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਔਸਤ ਦੋ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਬੜਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰਹਿਣ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਰਕਬਾ 13 ਲਖ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ । ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਰਹਿਣ ਰਖਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ।

चौधरी नेत राम: On a point of order, Madam. चीफ पार्लियामैन्टरी सेक्रेटरी साहिब सो रहे हैं और वह सोए सोए ही फिगर पेश कर देते हैं जिस से बाद में आप को और हमें भी दिक्कत होती है ।

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਮਾਰਫਤ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਮੁਤਲਿਕ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆਂ ਹੈ।

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਾਂਜ਼ਹ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ।

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ : ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ, ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੀ ।

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੇਕਰ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੀ ਇਹ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤੰਬਰ, 1963 ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤਿੰਨ ਲਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ । ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਰਖਦਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਕ ਲਖ 45 ਹਜ਼ਾਰ 945 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਗਹਿਣੇ ਰਖੀ ਉਥੇ ਉਸਦੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 1962-63 ਵਿਚ, ਜਿਸ ਸਾਲ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੋ ਲਖ 74 ਹਜ਼ਾਰ 560 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਰਖਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ । ਖੈਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਹਾਊਸ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ

[ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ]

ਕਰ ਲਵੇ ਕਿ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਿਤਨੀ ਭੈੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਤਾਂ 1 ਲਖ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਰਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਹੀ ਉਹ 2 ਲਖ 74 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਰਖਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਿਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੇ 2 ਲਖ 42 ਹਜ਼ਾਰ 437 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਉਥੇ ਉਸਦੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਹੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਸਾਲ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਟ ਹੈ 3 ਲਖ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ । ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਬ ਤਕਸੀਮ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਾਸ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਮਰਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ।

ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ : ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਕਿਸ ਨੇ ਹੈ ?

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸਨੇ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ, ਵਡੇ ਵਡੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੇ ਵਡੇ ਵਡੇ ਵਪਾਰੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਤੇ ਖਰੀਦਣਗੇ ।

ਇਕ ਆਵਾਜ਼ : ਬਿਰਲਾ ਖਰੀਦੇਗਾ....(ਸ਼ੋਰ)....

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦਸਾਂਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੇ ਗਾ । ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੇਗਾ ਓਸਵਾਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੇਗਾ ਬਹਿਲ ਤੇ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸੋਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਲਵਾਂ ਤੇ ਦਸਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ (ਵਿਘਨ) । ਮੈਂ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਣ ਲਈ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਹ ਇਹ ਦਸ ਕੇ ਕਿ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨ 10 ਮਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਥੇ ਉਹ 40 ਮਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਖਾਂ ਵਿਚ ਮਿੱਟੀ ਪਾਕੇ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਵੀ ਛੁਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਵਕਤ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦ 1900 ਤਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਸੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਂਡ ਏਲੀਏਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਕ ਵਕਤ ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਮਾਏ-ਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਹੱਫਜ਼ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਵਰਨਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਵੇਗਾ ।

ਚੀਫ ਪਾਰਲਿਆਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ : ਇਹ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ।

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰ ਦਰਜਾ ਬਦਤਰ ਹੈ (ਸ਼ੋਰ) । ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀਆਂ ਸਨ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿਕਣ, ਗਹਿਣੇ ਰਖਣ ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਸਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਲ

ਵਢਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ । ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜੈਸਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਮੁਲਕ ਜਿਥੇ ਸਿਰਫ 8/9 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਰਗਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਤੇ ਸਿਰਫ 4 ਫੀਸਦੀ ਆਦਮੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਐਸੇ ਭੈੜੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਨਫਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਤੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਇਕੋ ਇਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੋਨੇ ਦਾ ਅੰਡਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੁਰਗੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਹ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ।

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ : ਮੇਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਥੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 25 ਜਾਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦਾ ਇਕ ਇਕ ਓਨਰ ਇਥੇ ਹੋਣ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਹਨ ?

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਬੈਡ ਪੁਅਇੰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਮੇਜਰ ਸਾਹਬ ਵੀ ਗੁਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਬੈਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ । (The hon. Revenue Minister also takes their good points and not bad ones.)

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿਘ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਐਨੀ ਵਡੀ ਕਤਾਰ ਮਨਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਸੈਸ ਤਿੰਨ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਿਤਨੀ ਰੂਈ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਇਮਪਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਹ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿਲਸਮ ਰਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬੜਾ ਕਪੜਾ ਤੇ ਸੂਤੀ ਧਾਗਾ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਟੁਟ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁੱਜਰ ਮਲ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਤੌਰ ਮੋਦੀ ਸਪਿਨਿੰਗ ਐਂਡ ਵੀਵਿੰਗ ਮਿਲਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਕੁਲ 54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦਾ ਮਾਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ 58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਦੀ ਰੂਈ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਮੰਗਾਈ ਹੈ । ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਸੇ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਨੀਆਂ ਬਗਲਾਂ ਵਜਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ । ਮੈਂ ਇਕ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਵਤੀਰਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ 1950-51 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਰੀ 1 ਲਖ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਗਠ ਅਮਰੀਕਨ ਰੂਈ ਦੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ । ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 6 ਲਖ 56 ਹਜ਼ਾਰ ਗੱਠ ਅਮਰੀਕਨ ਰੂਈ ਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ । ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੌਂਗ ਸਟੇਪਲ ਵਾਲੀ ਰੂਈ ਮੰਗਵਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਪਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੂਈ ਦੀ

(ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ)

ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੀ ਰੂਈ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਅਫ਼ਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੈਪ-ਮਦਰਲੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, 1950-51 ਵਿਚ 3 ਲਖ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਗੱਠ ਦੇਸੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, 1963 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 5 ਲਖ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਗੱਠ ਪੈਦਾ ਹੋਈ । ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ 1950-51 ਵਿਚ 3 ਲਖ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਗੱਠਾਂ ਰੂਈ ਦੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਨ । ਇਸ ਸਾਲ 11 ਲਖ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਗੱਠਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਨ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਕਪਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ 4 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ । ਇਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦਾ ਸੋਰਡ ਆਰਮ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਉਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਥੇ ਜੈ ਜਵਾਨ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ । ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ । ਉਸ ਦੀ ਕਮਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਟੁਟ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੰਨਾ 17 ਲਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਥੇ 5 ਲਖ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਗੰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ ? ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਸ਼ੂਗਰ ਬਾਹਿਰ ਭੇਜੀ ਗਈ । ਇਸ ਸਾਲ 3 ਲਖ ਟਨ ਸ਼ੂਗਰ ਬਾਹਿਰ ਭੇਜਣੀ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਥੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫਾਰੇਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਥੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਆਇਟਮ ਉਤੇ ਹੀ 99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਫ਼ਾਰਿਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਾਂ ਨੂੰ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਡੀ. ਡੀ. ਪੁਰੀ, ਸ੍ਰੀ ਨਾਰੰਗ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਥਾਪਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਗੇ । ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ (Voices of shame, shame from the Opposition Benches).

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ 1962-63 ਵਿਚ ਕਰਾਪ ਸੈਸ 4 ਰੁਪਏ ਫੀ ਏਕੜ ਲਾਇਆ ਸੀ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਇਰੀਗੇਟਿਡ ਏਰੀਆ ਉਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ । (ਵਿਘਨ) ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਅਨਇਰੀਗੇਟਿਡ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਕਮਰਸ਼ਲ ਕਰਾਪ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਅਗਰ ਅਜਿਹਾ ਅਨਇਰੀਗੇਟਿਡ ਏਰੀਆ ਹੋਵੇਗਾ

ਤਾਂ ਉਹ 1 ਲਖ ਜਾਂ ਦੋ ਲਖ ਏਕੜ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 17 ਲਖ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਉਤੇ ਕਪਾਹ ਅਤੇ 5 ਲਖ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਉਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ 95% ਇਰੀਗੇਟਿਡ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਕਮਰਸ਼ਲ ਕਰਾਪ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੈਪ-ਮਦਰਲੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛਪੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ । ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿਤਾਵਣੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫੈਮਿਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਅਨਾਜ ਲਈ ਹੱਥ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ । (ਘੰਟੀ) ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫੂਡ ਗਰੇਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । 1st Five-Year Plan ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 60 ਲਖ ਟਨ ਫੂਡਗਰੇਨਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਏ । 2nd Five-Year Plan ਵਿਚ 63 ਲਖ ਟਨ ਹੋਏ ਅਤੇ 3rd Five-Year Plan ਵਿਚ 66 ਲਖ ਟਨ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ।

ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 78 ਲੱਖ ਟਨ ਫੂਡਗਰੇਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰਖਿਆ ਸੀ । ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫੂਡਗਰੇਨਜ਼ ਦੀ ਡਬਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ । ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ । ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਅਤੇ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਫੂਡਗਰੇਨਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੰਡਰਡ ਪਰਸੈਂਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਬਲਕਿ 18% ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾ ਦੇਵਾਂਗੇ । ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 69 ਲੱਖ ਟਨ ਫੂਡਗਰੇਨਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਏ । ਕੀ ਇਸ ਸਾਲ 60 ਲਖ ਟਨ ਫੂਡਗਰੇਨਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ? ਮੈਂ ਦਾਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਫਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵੀ 60 ਲਖ ਟਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ । ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। 10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ 1954 ਦੇ ਸਰਵੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 2.7 ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ । 1963 ਦੇ ਸਿਤੰਬਰ ਤਕ ਕੁਲ ਦੀ ਔਸਤ 4.7 ਏਕੜ ਬਣਦੀ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ । ਹਰ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੇਹਿਸਾਬ ਕਰਜ਼ਾ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਗ਼ੌਰ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ । ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਦਫਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਲੜਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲੇ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਹਨ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਰੀਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਪਿੰਗ ਸੈਟ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਊਬ-ਵੈਲ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਪਰਕੋਲੇਸ਼ਨ ਵੈਲਜ਼ ਲਗਾਏ

6.00 p.m.

(ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ)

ਜਾਂਦੇ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦਾ ਪਰ ਉਲਟਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਉਸ ਉਤੇ ਪਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਾਲਸੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ । ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਐਨੇ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਘੁੰਙਣੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ । ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਨੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤਿ ਬਚਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸਾਂ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਲਗਾਉ । ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਕਨਾਮੀ ਕਰੋ ਫਿਰ ਜਨਤਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ । ਜੇਕਰ ਤੁਸਾਂ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਬੁਲਾਣੀ ਹੈ ਤਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ । ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚੋ, ਗੌਰ ਕਰੋ, ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਬਦਲੋ । ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਂ ।

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾ ਦੇਣ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 2.7 ਏਕੜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਬਣਦੀ ਹੈ । ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਸੱਤ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਲਗਾਏਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਕਪਾਹ ਬੀਜੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਦ ਲਗਾਏਗਾ । ਫਿਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਕੇ ਵੇਖਣ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉਪਰ ਕਿੰਨਾ ਭਾਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਕੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ?

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਸ਼ਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਵੇਨਿਊ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਜਿਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਤਰਮੀਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਉਪੀਨੀਅਨ ਇਲੀਸਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਸ਼ਤਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜ਼ਾਵੇ ਉਥੇ ਇਹ ਤਰਮੀਮ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕਨੌਮਿਕ ਹੋਲਡਿੰਗ ਤੇ ਬੇਸ਼ਕ ਲਗਾ ਦਿਉ । ਮੇਰੀ ਇਹ ਤਰਮੀਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੋਈ ਹੈ । ਉਸ ਵਿਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕਨਾਮਿਕ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿਉ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਪਰ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 1954 ਦੀ ਸਰਵੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ 2,884,000 ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 2,505,000 ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ 10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ 4,018,000 ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 3,500,000 10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਗਾਉ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ । ਜ਼ਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਹਿਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਬੇਸ਼ਕ ਟੈਕਸ ਲਵੇ । ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੈਂ ਸਖਤ ਮੁਖਾਲਫਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹਾਊਸ

ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖੇ ਹਨ ਕਿ 31 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਤਹਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਵੇ । ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਜਾਉਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਏਗਾ ।

Deputy Speaker : Motion moved—

That the Punjab Commercial Crops Cess (Amendment) Bill, 1965, be cireulated for eliciting public opinion thereon upto the 31st January, 1966.

कंवर राम पाल सिंह (पुंडरी): डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह जो कर्मशियल क्राप्स सैस बिल 1965 है यह उपर से देखने से तो बड़ा मासूम सा नज़र आता आता है । इस की वर्डिंग बड़ी मासूम है, यह कहा गया है कि 1965-66 की बजाए इस को 1970-71 तक लागू कर दिया जाए । इस से मासूमियत और क्या हो सकती है । लेकिन जब इस बिल की वर्डिंग को छोड़ कर इस के असल औरिजिनल बिल को पड़ा जाए तो पता लगता है कि यह भेड़ की शकल में भेड़िया है । इस वर्डिंग का क्या असर पड़ेगा और किस के उपर पड़ेगा वही जान सकता है जिस के दिल में दर्द होता है, जिसे ठेस लगती है, कोई तकलीफ होती है वही जान सकता है । इस मासूम बिल से कितने लोगों को तकलीफ होती है, वे लोग बरदाश्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इस बात को बिना सोचे समझे उन पर बोझ लाद दिया जाता है । जब इस बिल पर गौर करते हैं तो पता लगता है कि 80 परसेंट जनता जो देहात में रहती है, जो सिर्फ अपना गुज़र ही कर सकती है उस के ऊपर यह टैकस लगाने जा रहे हैं । गुजर भी वे कैसे करते हैं । पहनने को फटे हुए चीथड़े उन को मिलते हैं, खाने को एक वक्त रोटी नसीब हो गई तो शुक्र है । जहां तक एजुकेशन का सवाल है वह तो शायद कुल 20 परसेंट लोग ऐसे होंगे जो अपने बच्चों को एजुकेशन दिला सकते हैं । उन को तो 24 घंटे पेट भरने की फिक्र लगी रहती है एजुकेशन की वात कैसे सोची जा सकती है । जिस वक्त इस बिल को 1963 में इन्ट्रोड्यूस किया गया था, इस सदन में पेश किया गया या तो उस समय गवर्नमेंट ने एशोरेंस दी थी कि इस सेस को सिर्फ तीन साल के लिये लागू किया जा रहा है । उस समय लोगों को तकलीफ बहुत हुई, वे बहुत बेज़ार थे लेकिन उन को तसल्ली दिलाई गई कि कोई बात नहीं अगर देश के लिये तीन साल दुख के भी काटनें पड़ें तो काट लेने चाहियें । लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि जो एशोरेंस सरकार आन दी फलोर आफ दी हाउस देती है उस को पूरा क्यों नहीं करती । फिर अभी 6 महीने के लिये तो पहले बिल की म्याद ही बाकी है । क्यों इस को इतनी जलदी हाउस में पास करवाने के लिये जोर दिया जा रहा है । मुझे समझ नहीं आती कि एसी क्या कोई खास बात है कि इस को इसी सेशन में पास करवाया जा रहा है । मुझे तो उस एशोरेंस को देखते हुए और अब जो जोर इसी सैशन में पास करवाने के लिये दिया जा रहा है कुछ खदशा मालूम होता है । मुझे डर है कि कहीं इस को इसलिये तो नहीं पास करवाया जा रहा कि अगर जमींदारों पर लैंड रेवेन्यु और आबयाना बढ़ाना हो तो अगले सेशन में बढ़ा दिया जाए और कमर्शल क्राप्स सेस अब इस सेशन में पास करवा लिया जाए क्योंकि अगर दोनों बिल एक ही सेशन में लाए

[कंवर रामपाल सिंह]

जाएंगे तो हो सकता है कि मेम्बरान और भी ज्यादा रीवोल्ट करें । मुझे यह खदशा पैदा हो रहा है । गन्ना और कपास दोनों को कमर्शल क्राप्स कहा जाता है ।

मैं समझ नहीं पाया कि इन को कमर्शल क्राप्स किस ढंग से माना जाता है । बहर हाल अगर इस बात को ही थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए तो भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आज हमारे देश के उपर संकट का जमाना आया हुआ है । ऐसा संकट देश पर आया हुआ है जब कि हमें ज्यादा से ज्यादा फारेन ऐक्सचेंज की जरूरत है और उस फारेन ऐक्सचेंज को हासिल करने के लिए आप के पास कौन कौन सी क्राप्स है ? आप इस सम्बन्ध में सैंट्रल गवर्नमैंट की रिपोर्टस को पढ़ कर देखिए । उन से पता चलेगा कि काटन और शूगरकेन दोनों ही ऐसी चीजें हैं जो आप को फारेन ऐक्सचेंज लेकर देती है । अगर आप को देश के लिए फारेन ऐक्सचेंज की जरूरत नहीं है फिर तो ठीक है, जरूर यह सैंस लगाया जाए लेकिन अगर देश को फारेन ऐक्सचेंज की जरूरत है तो जरूरत इस बात की है कि इन क्राप्स को इन्सेन्टिव दिया जाए । जो टैक्स उन पर लगा हुआ है उसे हटाया जाए । इन्सैन्टिव के लिए फारमर्ज को इस सिलसिले में लोन्ज और सबसिडीज दी जानी चाहिए जिस से यह क्राप्स देश के अन्दर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पैदा हों और इस के जरिए हम अपने देश के लिए ज्यादा से जयादा फारेन एक्सचेंज हासिल कर सकें । डिपटी स्पीकर साहिबा आप देखिए कि हम हर रोज अखबारों में पढ़ते है और जानते हैं कि आज का जमाना 'फार्मज और आर्मज का है । इस के साथ ही हमारे प्रधान मन्त्री ने भी एक नया नारा दिया है और वह है "जय जवान जय किसान" जिस का यही मतलब निकलता है कि आज का जमाना फार्मज और आर्मज का ही जमाना है । हमारे देश का नौजवान देश की रक्षा के लिए बार्डर पर लड़ा है, लड़ रहा है और शायद आगे भी उसे दुश्मन के साथ लड़ना पड़े । दूसरी तरफ हम भी यहां पर रोज स्पीचिज़ देते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी यही अपील की जाती है कि देश में एक इंच ज़मीन भी एसी न रहे जिस पर काश्त न की गई हो ताकि देश को खुराक के लिए दूसरों के सामने न झुकना पड़े और हम अपनी अनाज की कमी को खुद पूरा कर सकें । लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि इस तरफ क्यों ध्यान नहीं दिया गया जब कि इस बिल को हाउस के सामने पेश किया गया है इस बात का ख्याल न करते हुए कि वह लोग यह सैस दे सकते हैं या नहीं दे सकते, उन के अन्दर इस टैक्स को देने की कैपेसिटी है या नहीं, यह बिल लाया गया है । क्या इस से आप समझते हैं कि प्रोडकशन में इन्क्रीज होगी । मैं तो इस बात को नहीं मानता । शायद गवर्नमैंट मानती हो । जो लोग इस के हक में हैं और कहते हैं कि टैकस और लगाए जायें वह तो शायद मानते हों मगर मैं तो नहीं

समझ पाया कि जब तक आप किसानों को, ज़मींदारों को इन्सैन्टिव न देंगे तब तक आप प्रोडकशन किस चीज़ की करेंगे, आप कैसे प्रोडकशन को वढ़ाएंगे ।

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਇਕ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਨਾ ਫਾਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ--ਗੰਨੇ ਤੋਂ ਚੀਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਚੀਨੀ ਬਾਹਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਾਰਨ ਅਕਸਚੇਂਜ ਅਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸੈਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਾਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਅਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ । ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵਿਚ ਫਾਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ?

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਇਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੈਰੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਮੰਗਣ ਲਗ ਪਏ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲਣਾ । ਤੁਸਾਂ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ । (If the hon. Revenue Minister wants clarification on every point then the proceedings cannot go on smoothly. Since he is to reply to debate he may cover all the points at that time.)

कंवर राम पाल सिंह: जैसा कि मेंजर साहिब ने पूछा, मैं समझता हुं कि खुराक का मसला भी हमारे सामने है और फारेन ऐक्सचेंज का मसला भी हमारे सामने है । दोनों ही बड़े अहम मसले हैं । दोनों मसले बराबर की अहमियत रखते है । डिप्टी स्पीकर साहिबा, जिस तरह की हालत आज देश मे चल रही है । उस सम्बन्ध में मै एक अमरीकन स्टेटसमैन के विचार आप के सामने रखना चाहता हूं । मिस्टर वैन्डाल विल्की (Wendall Walkie) ने रूस को विज़िट किया और फिर अमरीका वापिस आया तो उस ने कहा था:

> "Russian Farms have defeated the Nazi Armies.
>
> He meant that where the Russian Farms produced grain for the nation, they also contributed healthy soldiers to the Russian Army, who ultimately succeeded in beating back the German invasion."

इन शब्दों की तरफ आप का ध्यान दिलोते हुए मैं इस बात पर ज़ोर देना चाहता हूं कि आज हमारें देश के अन्दर फ्रन्ट के ऊपर जो नौजवान लड़ रहे हैं, जो देश की रक्षा के लिए हर कुरबानी करने को तैयार बैठे हैं, उन में मैजारिटी ऐसे नौजवानों की है जो देहातों के अन्दर फारमर और किसान तबका से सम्बन्ध रखते हैं । आज आप को फ्रन्ट पर 99 फी सदी किसान का ही बेटा मिलेगा। अगर फांरमर्ज़ को इन्सैन्टिव न दिया गया, किसानों कि हालत को मज़बूत न किया गया और अगर उन के पास अपने बाल बच्चों को पालनें की कैपेसिटी ही न रहने दी तो किस तरह से आप इस बात की उम्मीद कर सकते हैं कि वह अपने बच्चों को पाल पोस कर इस कदर बहादुर और जवान बना दे कि वह देश की रक्षा

[कंवर राम पाल सिंह]

के लिए फौज में जा सके ? तो मुझे समझ नहीं आती कि इस तरह की लैजिस्लेशन से कैसे "जय जवान जय किसान" का नारा जो कि हमें अपनें प्रधान मन्त्री जी ने दिया है, कामयाब होगा । (घंटी)

Deputy Speaker : Kindly wind up.

कंवर राम पाल सिंह : तो, डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं समझता हूं कि अगर इस वक्त जमींदार की मदद न की गई तो आप ही अन्दाज़ा लगाएं कि देश के साथ क्या गुज़रेगी । इस देश की क्या हालत होगी जिस की 80 फी सदी आबादी गांव से ताल्लुक रखने वाली है ? (घंटी)

मैं सिर्फ दो तीन ज़रूरी बातों का ही जिक्र करना चाहता हूं । पूछेंगे कि उन को क्या इन्सैन्टिव दिए जाएं । ठीक बात है, बड़ा माकूल सवाल है । मैं इस सम्बन्ध में यही कहूंगा कि आप को सब से पहले टैक्स-पेयर की कैपेसिटी को जज करना चाहिए । आप को देखना चाहिए कि इस वक्त टैक्स-पेअर की कैपेसिटी क्या है । आप देखें कि हर सैशन में इस बात को उठाया जाता है कि ज़मींदार को ज़ोनल सिस्टम ने तबाह कर दिया है । उस को हटाया जाए ताकि वह अनाज को अच्छे भाव पर बेच कर इतनी कैपेसिटी पैदा कर सके कि आप के इन टैक्सों के देने के लायक बन पाए । लेकिन गवर्नमैंट इस तरफ ध्यान नहीं देती । एक तरफ उन को अपनी प्रोडयूस की पूरी आमदनी हासिल करने की इज़ाजत नहीं दी जाती और दूसरी तरफ उन को कहा जाता है कि ज्यादा पैदा करो और इस के साथ ही साथ तीसरें टैक्स पर टैक्स लगा कर दबाया जाता है । आखिर किसी चीज़ की कोई हद होती है । वह इस कदर टैक्स कैसे दे सकते हैं जब कि उन को उन की प्रोड्यूस की इतनी आमदनी ही नहीं होती कि वह अपना गुजारा कर सकें और टैक्स दें सकें । उन की अब टैक्स अदा करने की कैपेसिटी ही नहीं रही ।

इस के साथ ही साथ दूसरी तरफ क्या होता है ? मिल मालिकों की क्या हालत है ? किसानों को तो कोई इन्सैन्टिव नहीं दिया जाता मगर जो बड़े बड़े मिल ओनर्ज़ हैं उन को बड़े बड़े इन्सैन्टिव दिए जाते हैं । अभी पिछले दिनों बिल आया कि जो मिल वाले अपनी चीनी को बाहर भेजते हैं, ऐक्सपोर्ट करते हैं उन को उस पर टैक्स की छूट देनी है । वह बिल पास किया गया । उन को टैक्स की छूट दी गई ।

उपाध्यक्षा : अब आप वाइंड अप करें । दूसरों ने भी बोलना है । (The hon. Member may now wind up. Others are also to participate in the discussion.)

कंवर राम पाल सिंह : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं सिर्फ तीन-चार मिन्ट और लूंगा और इस के बाद इस बिल पर नहीं बोलूंगा । सिर्फ इसी फस्ट रीडिंग पर ही बोलूंगा । हां तो में आप को बता रहा था कि बड़े-बड़े मिल मालिकों को किस तरह से रिलीफ दी जाती है और गरीब किसानों को बिल्कुल नजर अन्दाज़ किया जाता है । पिछले सैशन में चौबीस लाख रुपए की ऐक्स ग्रेशिया ग्रांट श्री डी. डी. पुरी को दी गई थी । उस के लिए रीजन क्या दिए गए थे ? यह कहा गया कि गन्ने का जूस कम हो गया था और उन को इस तरह से जो घाटा हुआ उस घाटे को मेक अप करने के लिए उन को चौबीस लाख रुपए की ऐक्स ग्रेशिया ग्रांट दी गई । मैं यह पूछता हूं कि जब किसानों का इस तरह कोई नुकसान हो जाता है तो क्या आप उनको भी इस तरह से कोई ऐक्स ग्रेशिया ग्रांट देते हैं ? उन का तो सिर्फ मामला ही मुआफ किया जाता है और उस की भी बाकायदा तौर पर असैस्मैंट होती है, परसैंटेज निकाली जाती है । अगर फिक्स्ड परसैंटेज नहीं बनती तो वह भी मुआफ नहीं किया जाता । में समझ नहीं पाया की इस सम्बन्ध में गवर्नमैंट की क्या पालिसी है ? क्या वह यही चाहते हैं कि जो कल्टीवेटर तबका है, जो आप को ज़िन्दा रखने के लिए खुराक पैदा कर के देता है उसे बिल्कुल खत्म ही कर दिया जाए ?

(आपोजीशन की तरफ से प्रशंसा)

बजाय इस के कि आप उन को कोई इन्सैन्टिव दें उन पर टैक्स लगाए जाते हैं । एक तरफ तो, जैसा कि मैंने अभी अभी श्री डी. डी. पुरी वाली बात बताई, गन्ने का जूस कम हो जाने पर उन के घाटे को पूरा किया जाता है और दूसरी तरफ किसानों की क्या मदद की जाती है उस की मिसाल मैं आप को बताता हूं । मैं तो आप को करनाल की बाबत ही बता सकता हूं । बाकी ज़िलों में भी इसी तरह की हालत है या नहीं इस की बाबत में नहीं कह सकता । करनाल में तो यह हालत है कि गन्दम और चने की फसलों को सोइन्ग सीज़न में इस तरह का कीड़ा लग जाता है कि वह पैदा होते ही खत्म हो जाती है । जमींदार की हालत यह है कि उसे बीज नहीं मिलता । महंगे भाव पर बीज मिलता है । और उसे वह महंगा बीज लेकर दो-दो और कई बार तीन-तीन दफा उसी फसल के लिए बीजना पड़ता है । लेकिन इस बारे में गवर्नमैंट ने कोई स्टैप नहीं लिया कि उन को कोई किसी किसम की यह सबसिडी देती या उन कीड़ों को मारने का कोई इंतजाम करती लेकिन इस के बावजूद इस का नारा यह है कि ज्यादा से ज्यादा अनाज पैदा करो । इस की यह बात मुझे तो समझ में नहीं आती ।

फिर, डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं कुछ सीलिंग के बारे में ज़रूर कुछ कहूंगा । इस ने छुटते ही यह किया कि किसानों की ज़मीनों पर सीलिंग लगा दी । मुझे इस बात में कोई इतराज़ नहीं है कि इकोनामीकल होल्डिंग सब के पास होनी चाहिए लेकिन जांचने की बात यह है कि क्या एक ही तबका पर यह

[कंवर राम पाल सिंह]

सीलिंग लागू होनी चाहिए। कोई गलत न समझे, मेरा मतलब सिर्फ किसानों से ही है ताकि कोई गलत न समझ ले। किसानों की होल्डिंग पर ज़रूर सीलिंग लगाई जाए। इस बारे में प्लेनिंग कमीशन की जो रिपोर्ट है, जो कि ट्रीब्यून अखबार में मैंने पढ़ी थी उस में कमीशन नें यह कहा था की फरेगमेंटेशन आफ होल्डिंगज़ जो हो रही है इस से प्रोडक्शन को खास धक्का पहुंच रहा है। आज के ट्रीब्यून अखबार में मैंने पढ़ा है कि हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर श्री प्रमार ने कहा है कि अगर फरैगमेंटेशन आफ होल्डिंग्ज़ को न रोका गया तो जो हम प्रोडकशन को बढ़ानें का नारा देते हैं वह कभी भी बढ़ नहीं सकेगी। अगर यह सरकार किसान की होल्डिगज़ पर सीलिंग लगाती है तो इसे दूसरों पर भी सीलिंग लगानी चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि एक के साथ तो सौतीली मां वाला सलूक किया जाए और दूसरे तबका को उस के राईट से भी ज्यादा हिस्सा दे दिया जाए; यह ठीक न होगा। इस से हर सूझ बूझ रखने वाले इन्सान के मन में यह बात पैदा होगी कि जब किसान की होल्डिंग पर सीलिंग लगाई जा रही है तो इंडस्ट्री पर सीलिंग क्यों न लगाई जाए ? इसी तरह से व्योपारियों की दौलत पर क्यों सीलिंग न लगाई जाए ? इसी तरह से कैपिटीलिस्टस की इनकम पर क्यों सीलिंग न लगाई जाए और अर्बन प्रापर्टी पर सीलिंग क्यों न हो ? क्या वहां पर इकोनामिक होल्डिग का ख्याल नहीं है ? क्या उन की भी इकोनामिक होल्डिंग को देखा गया है ? उन लोगों की इकोनामिक होल्डिग का ख्याल तो आया है और उन की होल्डिग पर इन्हों ने सीलिंग लगा दी है जिन के पास न तो अपने जीवन को कायम रखने के लिए पूरे साधन ही हैं, जिन के बच्चों की एजूकेशन का पूरा इंतज़ाम नहीं और जिन को और किसी किस्म की सहूलतें नहीं मिलतीं। अभी एक स्टेटमैंट यहां आई थी जिस से पता चलता था कि जो स्कूल शहरों में खोले जाएंगे उन की बिल्डिंग्ज़ पर 50 फी सदी रुपया तो सरकार लगाएगी और 50 फी सदी वहां की जनता को लगाना होगा लेकिन देहात के स्कूलों के लिए बिलकुल और ही बात रखी हुई है। वहां तो अगर देहात के लोग स्कूल की बिल्डिग बनवा कर दें और साथ ही कई हज़ार रुपया दें तब जा कर स्कूल खोला जाता है या किसी स्कूल को अपग्रेड किया जाता है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उन लोगों के साथ यही इनसाफ हो रहा हैं। फिर इस बिल के लगाए जाने के लिए यह रीज़न दिया गया है कि नैक्स्ट प्लान के लिए पैसे चाहिएं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जिन लोगों से पैसे लिए जाते हैं उन के लिए तो प्लान में कोई योजना होती नहीं और होती भी है तो उसको इम्पलीमैंट नहीं किया जाता। अगर प्रैक्टीकल तौर पर जो होता है उस को ध्यान से देखा जाए तो पता लगता है कि यह प्लानिंग जो होती है यह देहात के गरीब लोगों के लिए नहीं की जाती। अगर इस में किसी अर्बन एरिया के लिए स्कूल की प्रोवीज़न होती है तो उस की बिल्डिंग

भी बन जाती है और उस के लिए स्टाफ भी प्रोवाइड हो जाता है लेकिन अगर किसी देहात के लिए कोई स्कूल प्रोवाइड हो तो उस के लिए कुछ नहीं किया जाता। इस की वजह यह है कि देहात के गरीब लोगों का न तो कोई प्रेस ही है और न ही कोई प्लेटफार्म ही होता है। वह तो एक ऐसी कलास है जिस के बारे में जस्टिस गुरनाम सिंह जी ने ठीक ही कहा है कि वह तो गूंगों की कलास है। यह एक फेंसी कलास है जिस को मार भी दिया जाए तो वह उफ नहीं करेगी। और जब तक वह एक बार मर नहीं जाएगी उस वक्त तक यह ऊपर उठ भी नहीं सकेगी। इस लिए मैं गवर्नमैंट से अपील करूंगा कि वह इस कलास पर रहम करें और इस बिल को अगले सैशन तक मुलतवी कर दे। तब तक हम इस बारे में स्टडी भी कर लेंगे कि आया किसान इस टैकस को दे भी सकते हैं या नहीं दे सकते।

ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਕਿਰਤੀ : (ਜਾਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ) ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਅਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਲ ਮੇਜਰ ਸਾਹਬ ਨੇ ਇਥੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਜ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਦ ਉਸ ਬਿਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਭੁਖ-ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਲਸੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜਲੂਸ ਕਢੇ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਥੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਲੈਕਚਰ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਟੇਕ ਅਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜ ਫਿਰ ਇਹ ਬਿਲ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਨਸੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਔਰ ਇਥੇ ਖਾਲੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਹੀ ਕਰਣ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਔਰ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

उपाध्यक्षा : सरदार करम सिंह जी, ज़रा वक्त का भी ख्याल रखो। जो बिजनेस एडवाजरी कमेटी की रिपोर्ट आई हुई है उस के मुताबिक इस बिल पर 22 और 23 तारीख को बहस चलनी है और कल इस बिल को पास करना है और अगर ज़रूरत पड़ी तो इस के लिए कल नान-स्टाप सिटिंग-करनी होगी। इस लिए आप जल्दी जल्दी खतम करें। (The hon. Member Sardar Karam Singh Kirti may please keep the time also in view. According to the Report of the Business Advisory Committee this Bill is to be discussed on the 22nd and 23rd instant and it is to be passed tomorrow. If need be there may be a non-stop sitting tomorrow for the purpose. So he should finish his speech soon.)

चौधरी राम सरूप : डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस बारे में मैं यह अर्ज़ करनी चाहता हूं कि इस सिलसले में बिजनेस एडवाईज़री कमेटी की मीटिंग कोई पांच

[चौधरी राम सरूप]

दफा हुई है और हर बार उस ने अपना पहला फैसला बदला है और यह उस ने हाउस की राए को देख कर किया है। हाउस की राए यह है कि हम इस बिल पर खुले तौर पर बोलना चाहते हैं और जब हम इस पर बोलने लगते हैं तो आप हम को बीच में टोकती रहती हैं यह बड़े अफसोस की बात है....

उपाध्यक्षा : मैं यह बात तो नहीं कह रही कि कल को जरूर खतम हो। मैं तो इस बारे में हाउस की राए जानना चाहती हूं। (I am not saying that this Bill must be passed tomorrow. I want to know the sense of the House in this behalf.)

चौधरी राम सरूप : यह सवाल नहीं है। सवाल तो यह है कि इस हाउस के हरेक मैम्बर को यह हक हासल है कि वह किसी बिल पर अपनी राए का खुले तौर पर इज़हार कर सकता है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह एक तो टैक्सेशन का बिल है और दूसरी बात यह है कि यह बिल देहात के गरीब किसानों के साथ ताल्लुक रखता है। अगर आप हमें इस पर बोलने से टोकेंगी तो आप एक बहुत बड़ी ज्यादती करेंगी—

उपाध्यक्षा : मेरा तो फर्ज़ यह है कि हाउस के सामने बिज़नेस एडवाईज़री कमेटी का जो डिसियन हो रखूं इस बारे में जो हाउस की राए हो वही जानने के लिए मैं यह कह रही हूं। (My duty is to place the decision of the Business Advisory Committee before the House. I am saying this to know the sense of the House.)

चौधरी राम सरूप : डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप जब रूस गई हुई थीं हमारा यह ख्याल था कि आप बाहर के हालात को देख कर कुछ न कुछ नर्म हो कर आएंगी लेकिन आप तो वैसी की वैसी ही रही हैं। मुझे अफसोस से यह बात कहनी पड़ती है कि जिस वक्त आप रूस गई हुई थीं तो उस वक्त उन्होंने बिलों पर मैम्बर साहिबान को बोलने की खुली छुट्टी दे रखी थी और उन्हों ने किसी के साथ ज़िद नहीं की और इस तरह से पांच दफा उन्होंने बिज़नेस एडवाईजरी कमेटी की राए जानने के लिए मजबूर किया और उन्हों ने इस बारे में एक बार भी एतराज़ नहीं किया। फिर यह बिल तो ज़मींदारों के साथ सम्बंध रखता है और आप हमें कैद कर के, मजबूर कर के बोलने की इजाजत न दे कर यह बिल पास कराना चाहती हैं। यह डेमोक्रेसी के असूलों के खिलाफ है। यह सरासर गलत चीज़ हो रही है। हम ने कभी आप को डिसअप्रोव नहीं किया लेकिन हमारे बार बार आप से रिक्वेस्ट करने के बाद भी आप के दिल में जमींदारों के लिए रहम नहीं आ रहा। सब से ज्यादा अफसोस तो इस बात पर है कि अगर आप ने इस बिल को ज़रूर पास कराना है तो—

उपाध्यक्षा : चौधरी राम सरूप जी, आप इतने पुराने पालीयामेंटेरियन हैं और मेरी बात को समझ नहीं रहे। मैं तो यही पूछ रही हूं कि बिजनेस एडवाईज़री कमेटी ने जो रिपोर्ट की थी वह यह थी कि कल तक इस बिल को पास करना है। (The hon. Member Chaudhri Ram Sarup is an old Parliamentarian but he is not understanding what I say. I am asking that according to the Report of the Business Advisory Committee this Bill is to be passed by tomorrow.)

चौधरी राम सरूप : पर बिज़नेस एडवाईज़री कमेटी ने बोलने वालों पर कोई टाईम लिमिट नहीं लगाई हुई और यह नहीं कहा हुआ कि अगर कोई मैम्बर बोल रहा हो तो आप घंटी बजाती रहें।

उपाध्यक्षा : मैं हाउस की इस बेतरतीबी को देखते हुए इसे 15 मिन्ट के लिए एक्सटेण्ड करती हूं और इस बारे में इस की राए जानना चाहती हूं। (Keeping in view this disorder in the House, I extend the sitting by 15 minutes and I want to know the sense of the House in this regard.)

ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਹਾਊਸ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਤਰਫ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਿਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ। ਹਾਊਸ ਦੀ ਇਹ ਸੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਟੈਕਸ ਬਿਲ ਤੇ ਭੀ ਖੁਲ੍ਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਲੋਗ ਜੋ ਇਥੇ ਦਿਹਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਪਰੇਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਸ ਸਕਣ......

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਕੈਚ ਕੀਤਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਲ੍ਹ ਹਾਊਸ ਨਾਨ-ਸਟਾਪ ਚਲਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। (ਵਿਘਨ) (The hon. Member has not grasped the point. The question is whether the sitting to be held tomorrow is to proceed non-stop or not.)

ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਾਊਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਬੁਧਵਾਰ ਤਕ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਖਿਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 22 ਅਤੇ 23 ਤਰੀਕ ਦੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਦਿਉ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਐਡਵਿਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਥੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਆਂਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਐਪਰੂਵ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਰੀਲੈਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਆਖਿਰ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦਿਨ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਦੋਂ ਸਿਨੇਡਾਈ ਅਡਜਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅਗਰ ਇਤਨੀ ਬਾਰ ਲੈਟੀਚਯੂਡ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਲ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰਖਦੀ। ਇਕ ਚੀਜ਼ ਹਾਊਸ ਐਪਰੂਵ ਕਰੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਉਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪਾਰਟੈਂਟ ਬਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਇਰ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੇ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿਉ ... .

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊਸ ਨਾਨ-ਸਟਾਪ ਚਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ? (The question is whether the House should sit non-stop or not.)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਐਡਵਿਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਬਿਲ ਤੇ ਬਹਿਸ ਚਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਚਾਰ ਪੰਜ ਦਫਾ ਮੀਟਿੰਗਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਬਿਲ ਦੀ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਥੇ ਦੋ ਦਿਨ ਰਖੇ ਗਏ ਸਨ ਉਥੇ ਉਹ 7-8 ਦਿਨ ਚਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲ ਵੀ ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੇ 3-4 ਦਿਨ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਸੀ. ਏ. ਜਾਂ ਡੀ. ਏ. ਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਇਕ ਦਮ ਜਲਦੀ ਵਿਚ ਨਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਸੀ. ਏ. ਅਤੇ ਡੀ. ਏ ਵੀ ਛਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

(ਤਾੜੀਆਂ)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ (ਨਾਭਾ) **:** ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਐਡਵਿਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਐਡਵਿਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹਰ ਰਿਪੋਰਟ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬਿਲ ਲਿਆਈ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਉਸ ਵਿਚ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿਚ 6-7 ਦਿਨ ਦੀ ਦੇਰ ਹੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਜੋ ਬਿਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪਾਰਟੈਂਟ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਅੱਲੁਕ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਬਹਿਸ ਲਈ ਵੀ ਪੂਰਾ ਵਕਤ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾਨ-ਸਟਾਪ ਸਿਟਿੰਗ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜੋ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਐਡਵਿਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਨਾਨ-ਸਟਾਪ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਇਕ ਘੰਟੇ ਲਈ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ 24 ਤਰੀਕ ਦਾ ਦਿਨ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 24-25 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਵਕਤ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ (ਰੋਪੜ) **:** ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਹ ਜੋ ਬਿਲ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵਡੇ ਤਬਕੇ ਨਾਲ ਤਅੱਲੁਕ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਬਹਿਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਨ-ਸਟਾਪ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ

(ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼)

ਵਧਾਈ ਦਿਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਝੰਡਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਇਥੇ ਨਾਨ-ਸਟਾਪ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਤਾ ਵਰਨਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਨਾਨ-ਸਟਾਪ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਨਾਨ-ਸਟਾਪ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ (ਦਸੂਆ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਹ ਜੋ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਇਥੇ ਆਈ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬਿਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 15 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਤਅੱਲੁਕ ਰਖਦਾ ਸੀ ਮਗਰ ਇਹ ਬਿਲ ਪੌਣੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਵਸੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਪਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਬਿਠਾਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਵਾਹ ਲਾਇਆ (ਤਾੜੀਆਂ) ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਸੱਲੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬਿਲ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਲੜੇ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਲਵਾ ਦਿਤੇ। ਇਹ ਬਿਲ ਦਿਹਾਤੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਥੇ ਬੜੀ ਗਿਣਤੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਥੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸੈਂਸ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਨਾਨ-ਸਟਾਪ ਸਿਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿਉ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਚਾਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ਚਲਦਾ ਰਹੇ, ਅਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾਨ-ਸਟਾਪ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਜ ਜਾਂ ਕਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਲਾਉ ਅੰਗੂਠਾ ਇਸ ਤੇ। ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਭਾਸੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਿਥੇ ਤਕ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਇਸ ਹਾਊਸ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਬਿਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਐਡ-ਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਅਜ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦ ਉਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਸੀਹਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਐਡ-ਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੀ ਹਾਕਮ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਹਾਊਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਦਸ ਵਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ (ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ) ਇਸ ਲਈ ਅਸਾਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਐਡ-ਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਿਲ ਤੇ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪਰਗਟ ਕਰਨ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਹੀ ਗਲ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ।

ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਨ ਲਾਲ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕੀ ਸੈਂਸ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਸਾਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਯੂਨਾਨੀਮਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਤੇ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਥੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਤਕ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੈ ਇਸ ਬਿਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਦਿਨ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਬਿਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਵਕਤ ਇਕ ਘੰਟਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟ ਕਿਸੇ ਨਾਨ-ਸਟਾਪ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਉਸ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨ-ਸਟਾਪ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਲਈ।

(ਵਿਘਨ)

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੁਛਿਆ ਹੈ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਕਿ ਕੀ ਕਲ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਅਗ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। (The hon. Member has not put the correct position. I only referred to the report of the Business Advisory Committee and wanted to know the sense of the House whether we will be able to pass this Bill tomorrow or the Session is to continue further.)

ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਨ ਲਾਲ : ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾਨ-ਸਟਾਪ ਸਿਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਦੋ ਦਿਨ ਇਸ ਬਿਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ 23 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸਿਟਿੰਗ ਨੂੰ ਇਕ ਘੰਟਾ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਅਗੇ ਚਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾਨ-ਸਟਾਪ ਸਿਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਲ ਇਕ ਘੰਟਾ ਸਿਟਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਵੀ ਬਿਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਚਲੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਨਾਨ-ਸਟਾਪ ਦਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ ਆਪ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਊਸ ਦੀ ਸੈਂਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਅਗੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾਂ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਵਿਚ ਰਾਏ ਆਮਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ ਪਾਸ ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਊਸ ਦੀ ਇਸ ਸੈਂਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਲ ਤੇ ਖੁਲ੍ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਸਕਣ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਢਿਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਦੋ ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ? (Addressing the Transport and Education Minister Sardar Gurdial Singh Dhillon) (There are only two minutes left in the hour of interruption. Would you like to say something ?)

ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੰਤਰੀ : ਜੇਕਰ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਚਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਵਿਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। (ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ)

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਸਦਨ ਕਲ ਦਸ ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਮਿਲੇਗਾ। (The House will meet at 10 a.m. tomorrow.)

(*The Sabha then adjourned till 10.00 a.m. on Tuesday, the 23rd November, 1965*).

1602/24-3-66--386—C. P. and S., Pb., Patiala.

Punjab Vidhan Sabha Debates

23rd November, 1965

Vol. II—No. 25

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Tuesday, the 23rd November, 1965

Price : Rs 4.00 Paise

ERRATA

TO

PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATES VOL. II, No. 25,

DATED THE 23RD NOVEMBER, 1965

Read	*For*	*On page*	*Line*
सप्लीमैंट्रीज़	सप्लीमट्रीज़	(25) 1	last
गवर्नमेंट	गवर्नमट	(25) 2	13th from below
स्टैंप	स्टैंप	(25) 3	6
बहुत	कहुत	(25) 3	11
मन्त्री	मत्री	(25) 3	13
फैसला	फसला	(25) 5	6
ਕੀਤਾ	ਕੀਤੀ	(25) 6	5
ਪੂਰਾ	ਪਰਾ	(25) 6	10
	ਪੁਰਾ	(25) 7	12th from below
ਸ਼ਾਸਨ ਮੰਤਰੀ	ਸਾਸਨ ਮੰਤ੍ਰੀ	(25) 6	7th from below
लैंड	लैड	(25) 7	21
ਆਨਰੇਬਲ	ਅਨਰੇਬਲ	(25) 8	8
चौधरी देवी लाल	चौधरी `वी लाल	(85) 8	11
थे	थ	(25) 8	15
ਮੰਤਰੀ	ਮਤਰੀ	(25) 8	20
ਦਿਨ	ਦਿਣ	(25) 8	20
बैक्वर्ड	बैक्र्बड	(25) 10	12
ਕਾਲਜ	ਕਾਲਜੀ	(25) 10	3rd from below
मैरिट	मेंरिट	(25) 11	5
please	pleased	(25) 12	last but one
Vol.	Tol.	(25) 12	—do—
Hydel	Hedel	(25) 17	1
forecast	forcast	(25) 19	21
great	G eat	(25) 19	4th from below
decision	decisison	(25) 19	—do—
ਦੀ	ਨੀ	(25) 20	14
ਵੱਸ	ਬਸ	(25) 21	9
चौधरी	चौ धरी	(25) 21	20
आक्ट्राय	आक्टायी	(25) 21	24
ਬਾਬੂ	ਬਾਬੂ	(25) 21	8th from below

(Contd. .. .. 2)

Read	*For*	*On page*	*Line*
Aggression	Aggressions	(25)22	2
है	हैर	(25)22	13
बुंगे	बुगे	(25)22	last but one
में	मैं	(25)25	11th from below
Deputy Speaker	Deputy Speake	(25)26	7
only if	only. If	(25)33	8
please	plcase	(25)33	13
साइन	सा न	(25)35	10
ਮੇਰੀ	ਕਰੀ	(25)37	2
Sardar Trilochan Singh	Sardar Tarilochan Singh	(25)42	9—10
करूंगी	करेगी	(25)43	10
भेज	मेज	(25)43	12
Memter is	Member	(25)44	last but one
ऐसे	एसे	(25)47	11
नम्रता	नर्मता	(25)48	6th from below
ਮਹਿਕਮੇ	ਮਾਹਕਮੇ	(25)50	5th from below
Inconclusive	In conclusive	(25)53	9
ਬਰਪਾ	ਬਮਾ	(25)54	15th from below
ਬੇਸ਼ੀ	ਪੇਸ਼ੀ	(25)62	6
टैक्स	टक्स	(25)65	last but one
अमैण्डमैंट	अमण्डमैंट	(25)66	4
बार	वोट	(25)66	12
आते	आत	(25)66	14
ਵੈਲਥ	ਵਲਥ	(25)69	14
ਫਾਰਿਨ	ਫਾਇਰਨ	(25)69	5th from below
ਕਰਕੇ ਅਤੇ	ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅਤੇ	(25)70	17
कामरेड	आमरेड	(25)72	11th from below
लाइट	अलाइट	(25)73	16th from below
एक्सपर्ट्स	एेक्सपर्ट्स	(25)73	8th from below
		(25)74	12
ताज्जुब	तोज्जुब	(25)76	13
क्रास	क्रॉस	(25)76	16
कराते	कराने	(25)76	last but one
डिप्टी	य डिप्टी	(25)76	last but one
ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ	ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ	(25)80	First

———

PUNJAB VIDHAN SABHA

Tuesday, the 23rd November, 1965

The Vidhan Sabha met in the Vidhan Bhawan, Sector 1, Chandigarh, at 10 *a.m of the Clock. Deputy Speaker (Shrimati Shanno Devi) in the Chair.*

Statement Reg. Question No. 3044

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री : एक बात तो मैं इस हाऊस में यह अर्ज़ कर देनी चाहता हूं कि जिस बात की सरदार दरबारा सिंह ने बिरला ब्रादर्ज़ को ज़मीन देने के मुताल्लिक ऐशोरैंस दी थी कि हम अगर कोई ज़मीन उन्हें नहीं देंगे, उस के मुताल्लिक ऐग्रीकल्चर डिपार्टमैंट कार्यवाही कर रहा है कि और ज़मीन प्राईवेट ओनर्ज़ को न दी जाये ।

आवाज़ें :—सप्लीमैंटरी मैडम ।

उपाध्यक्षा : यह तो एक स्टेटमैंट के मुताल्लिक जवाब दे रहे हैं, कोई सप्लीमैंटरी इस सिलसिले में नहीं किया जा सकता । (He is saying this in connection with a statement. No supplementaries can be raised with regard to this).

सिंचाई मंत्री : कामरेड शमशेर सिंह जोश के एक सवाल के जवाब में मैं यह स्टेटमैंट हाऊस की टेबल पर ले करता हू ।

Statement by Chaudhri Rizaq Ram, Irrigation and Power Minister relating to Unstarred Question No. 3044

Unstarred Question No. 3044 by Comrade Shamsher Singh Josh related to survey of Rupar and Kharar Sub-Divisions for providing Bhakra Canal Waters. It is regretted that two diferent replies to the same Assembly Question were furnished. One of the replies was based on information available with the Irrigation Department. The other reply was prepared by the General Manager, Bhakra Dam.

2. Surveys for various purposes are conducted from time to time, Schemes which are considered suitable are only taken up for execution. In a very large number of cases, the surveys indicate that there is no possibility of extending canal irrigation.

3. No scheme for making irrigation supplies available from the Bhakra System have been executed in the Rupar and Kharar Sub-Divisions. A survey was, however, done covering a part of Rupar Sub-Divisison. The scheme was not executed. The reply forwarded by the General Manager, Bhakra Dam, may be deemed to be the reply to the Assembly Question.

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ੱਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : On a point of order, Madam.

उपाध्यक्षा : मैं आनरेबल मैम्बर साहिबान से यह बात फिर अर्ज़ कर देना चाहती हूं कि वह प्वायंट आफ आर्डर के नाम पर बोलने की कोशिश न करें हां जो कामरेड शमशेर सिंह जोश का प्रश्न है इस पर आप सप्लीमैंट्रीज़ कर सकते हैं ।

[उपाध्यक्षा]

(I will once again request the hon. Members not to try to speak by raising a point of order. However, they can put supplementaries regarding the question of Comrade Shamsher Singh Josh).

Starred Questions and Answers.

*Supplementary Questions to Starred Question No. 8700.

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡਲੈਸ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੇ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੀਤੀ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ?

ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ : ਇਸ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੀਕਲੇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਿਰਲਾ ਬਰਾਦਰਜ਼ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ ?

राजस्व मंत्री : ऐग्रीकलचर डिपार्टमैंट की यह कोशिश है कि जो इन्डीविजुअल ओनर्ज़ की ज़मीन है वह इस में शामल न की जाये ।

श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री : क्या यह ठीक है कि जो बिरला ब्रादर्ज़ को ज़मीन दी जा रही है, इस को रिक्लेम करने का सारा खर्चा सरकार देगी ? क्या जो ज़मीन दूसरे लोगों को दी जा रही है इस को भी रीक्लेम करने का खर्चा यह सरकार ही देगी ?

मंत्री : रीक्लेम करने का सारे का सारा खर्च सरकार का ही होगा ।

श्रीमती सरला देवी : अभी अभी जो मंत्री महोदय ने कहा कि कुछ जंगल का इलाका बिरला ब्रादर्ज़ को दिया जा रहा है तो क्या वह प्राईवेट ओनर्ज़ के कब्ज़ा में नहीं था ? उस का ओनर कौन है ?

मंत्री : यह जंगल गवर्नमैंट ने ही रीकलेम किये हैं और यह इस गवर्नमट के कब्ज़ा में हैं ।

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਈਵੇਟ ਪਰਾਪਰਟੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਕੀ ਇਵੈਕੂਈ ਪਰਾਪਰਟੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ?

मंत्री : हमारा डिपार्टमैंट सारी ज़मीन के मुताल्लिक खसरा बना रहा है । यह गवर्नमैंट ने फैसला कर ही दिया है कि जो भी इंडीविजुअल प्रापरटी होगी वह इस में इनकलूड नहीं की जायेगी ।

श्री बनवारी लाल : क्या वज़ीर साहिब यह बतायेंगे कि हरिजनों को जो इवैक्वी लैंड देने की पालिसी सरकार ने इख्तियार की थी यह सरकार उस पालीसी को चेंज कर चुकी है ?

**Note* :—Starred Question No. 8700 alongwith its reply appears in P.V.S. Debates Volume II, No. 24, dated the 22nd November, 1966.

ਕਾਮਰੇਡ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਸਹੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕੱਢੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਕ ਦਮ 1,000 ਏਕੜਾਂ ਤਾਂ ਬਿਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵੋਗੇ ?

मन्त्री : यह फैसला अब किया है कि इंडीविजुल ओनर्ज़ की ज़मीन के अलावा जो दूसरी ज़मीन रीक्लेम होगी उसी के बारे में कोई और स्टैप उठाया जायेगा ।

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ੈਡੂਲਡ ਕਾਸਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਰਲੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ?

मन्त्री : यह ज़मीन तो एक सीड फार्म के लिए इस सरकार ने दी है । अभी और बहुत सी ज़मीन है जो इन लोगों को दी जा सकेगी ।

श्री सुरेन्द्र नाथ गौतम : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि अब तक कितनी ज़मीन इस सरकार ने रीक्लेम की है ? हमारे प्रधान मन्त्री बार बार ऐलान करते हैं कि ऐसी ज़मीन हम छोटे काश्तकारों को देख कर इस मुल्क की पैदावार बढ़ाने की कोशिश करेंगे । क्या इस तरफ कोई ध्यान सरकार की तरफ से दिया गया है ।

मंत्री : हमारे पास 4 लाख एकड़ के करीब ऐसी ज़मीन है जो रीक्लेमेबल है । इस काम को हम ने फूड कारपोरेशन के हवाले किया है । वह इस सिलसिला में स्टैप्स उठा रहे हैं । पानी का इन्तजाम करने के लिये टियूब वैल लगाने के अलावा और भी बहुत से काम हैं जिन पर टाईम लगेगा ।

श्री हीरा लाल : क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि जब सरदार अजमेर सिंह पहली कैबनट में रेवेन्यू मिनिस्टर थे तो केबनट में फैसला हुआ था कि वह ज़मीन हरिजनों को दी जाएगी ?

(श्रीमती सरला देवी सप्लीमेंट्री सवाल करने के लिये उठीं)

उपाध्यक्षा : श्रीमती सरला देवी, अगर एक ही मेंबर को 10 सप्लीमेंटरी करने की इजाज़त दी जाए तो काम कैसे चलेगा ?

(How will the House proceed if each member was to put ten supplementary questions?)

कामरेड राम प्यारा : क्या इरीगेशन मिनिस्टर साहिब बतायेंगे कि जैसा कि उन्होंने फरमाया है कि लैंड रिक्लेम करके उनको दी है, तो बिरला ब्रदर्ज का एग्रीमेंट लैंड रिक्लेम करने से पहले हुआ था या यह हुआ कि रिक्लेम करने के बाद बिरला ब्रदर्ज को दी जाएगी ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री : यह ऐग्रीमेंट जब हुआ था उस वक्त लैंड आलरेडी रिक्लेम्ड थी उन के लिए रिक्लेम नहीं की बल्कि पहले से रिक्लेम की हुई थी ।

श्री बनवारी लाल : इस हाउस में अभी श्री हीरा लाल ने बताया है कि सरदार अजमेर सिंह ने इस हाउस में अनाउंस किया था और सारे हरिजन एम. एल. एज. से

[श्री बनवारी लाल]

फैसला किया था कि एवेक्वी लैंड हरिजनों को दी जाएगी। क्या गवर्नमैंट उस स्टैंड पर कायम है ?

उपाध्यक्षा : बनवारी लाल जी और हीरा लाल जी, मैं मशवरा देना चाहती हूं कि जो आप की पार्टी का मामला है उसे हाउस में क्यों बार बार लाते हैं ? (विघ्न) मेरी दरखास्त है कि सप्लीमेंटरी जितने मर्जी हैं कर लें मगर प्वायंट आफ आर्डर के बहाने सप्लीमेंटरी न करें।(I would advise the hon. members not to raise here the matters pertaining to their Party affairs (interruption). They may put any number of supplementary questions but this may not be done through a point of order.

श्री बनवारी लाल : मेरा मतलब यह है कि यह आप की रूलिंग है। उस वक्त भी आप डिप्टी स्पीकर थीं और आज भी हैं क्या वह कैबनेट का फैसला चेंज हो चुका है ? मैं आप की रूलिंग चाहता हूं।

चौधरी देवी लाल : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडम। क्या किसी सप्लीमेंटरी क्वैश्चन के सिलसिले में चेयर एडवाइज़ कर सकती है कि मामला पार्टी में उठाया जाए जब कि हाउस में सप्लीमेंटरी हो रहे हों ?

उपाध्यक्षा : जो हाउस की चीज़ है वह हाउस की है। वैसे मैंने कहा है कि अगर इनके साथ अन्याय हो रहा है तो वहां भी बात करें। (Any matter that is raised here is the property of the House. However, I told them to raise the matter in their Party also, if they felt some injustice had been done to them).

श्री बनवारी लाल : कम अज कम हमारा राईट है, आप की रूलिंग चाहता हूं।

उपाध्यक्षा : बैठ जांए (Please take your seat.)

श्री बनवारी लाल : जो हम आप से दरख्वास्त करते हैं आप उस पर रूलिंग नहीं देतीं। डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप से रिक्वैस्ट है कि इस पर रूलिंग दें।

श्रीमती सरला देवी : अभी २ मिनिस्टर साहिब ने मेरे सवाल के जवाब में कहा है कि वह गवर्नमेंट की लैंड है तो मैं मिनिस्टर साहिब से यह पूछना चाहती हूं कि जो लैंड बिरला को दी जा रही है आया वह वेस्ट लैंड थी या गवर्नमैंट उस पर कोई कल्टीवेशन करती थी ?

मन्त्री : इस ज़मीन में कल्टीवेशन जारी थी। पहले रीक्लेम करके उस पर काश्त हो रही थी गवर्नमैंट की तरफ से।

ਚੌਧਰੀ ਰਾਮ ਰਤਨ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਰੀਜਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੁਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਪਿਛੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ

ਗਿਆ। ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ ਕੈਬਨਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਗਈ ਹੈ, ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਹਰੀਜਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਚੌਧਰੀ ਰਿਜ਼ਕ ਰਾਮ ਜੀ, ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਰਿਪਲਾਈ ਦਿਓ ਜੋ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ।

मन्त्री : जहां तक गवर्नमेंट का यह फैसला है कि जो इनफीरियर इवेक्की लैंड है वह हरीजनों को अलाट हो, आक्शन की जाए। यह गवर्नमैंट का फसला है।

उपाध्यक्षा : सरदार अजमेर सिंह से सलाह कर लें। वह कुछ और कह रहे हैं आप कुछ और कह रहे हैं। मैं चाहती हूं कि सरदार अजमेर सिंह अपनी पुज़ीशन क्लीयर करें। (He should consult Sardar Ajmer Singh. He says something else. I would like Sardar Ajmer Singh to clarify his position.)

ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨਜ਼ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਿ There is finality about it. ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲੋਂ ਤਿੰਨ ਇਨਸਟਾਲਮੈਂਟਸ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਸੀ। ਇਕ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ within ten miles of the border ਸੀ। ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਵਖਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਵੀਏ। ਕੁਛ ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਕੁਛ ਰਾਏ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਸੈਕੰਡ ਇਨਸਟਾਲਮੈਂਟ ਵਿਚ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਇਵੈਕਈ ਲੈਂਡ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਡਿਸਟਰਿਕਟ ਵਿਚ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕੱਮੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਇਨਸਟਾਲਮੈਂਟ ਵਿਚ ਲਈ ਸੀ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਧੀ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਹਾਫ ਐਕਸ ਮਿਲਟਰੀ ਪਰਸਨਲ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਤੀਜੇ ਲਾਟ ਵਿਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ which was evacuee land unallotted evacuee land. ਇਸ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚੋਂ 20 ਪਰਸੈਂਟ ਲੈਂਡ for allotment to the unsatisfied claim holders ਰਖੀ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੀਲਾਮ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਮਗਰ ਫਿਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਉਸ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਨੇ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਬਜ਼ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਕਬਜ਼ਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪਰਾਈਸ ਤੇ ਦਿਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਚੁਨਾਂਚਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵੀ ਸਨ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਇਹ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹਰੀਜਨ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਓਪਨ ਆਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੀ ਆਕਸ਼ਨ ਹਰੀ-ਜਨਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਵਿਚ ਮਹਿਦੂਦ ਰਖੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਡੀਸੀਜ਼ਨ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਛ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਜ਼ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨੀਲਾਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਲਾਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ

[ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਮੰਤ੍ਰੀ]

ਪਰਾਈਸ ਤੇ ਦੇ ਦਿਤਾ ਜਾਏ। ਚੁਨਾਂਚਿ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੇਲ ਕਿਸੇ ਐਪੀਲੇਟ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸੈਟ ਐਸਾਈਡ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਤਲਿਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਹਰੀਜਨਜ਼ ਨੂੰ ਨੀਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਬਲਕਿ ਓਪਨ ਆਕ-ਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦੀ ਲੈਂਡ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਨ ਆਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਨਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। That I think is very suitable for the Harijans ਇਸ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਤਲਿਕ ਮੈਨੂੰ ਪਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇਵੈਕਵੀ ਲੈਂਡ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਇਵੈਕੁਈ ਲੈਂਡ ਹੈ ਔਰ ਆਇਆ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨਰਜ਼ ਦੀ ਹੈ, It is yet to be found out on the spot ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਐਸਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਲਾਮ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤਾਂ to that extent ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ amended, varied and altered ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ in the interest of the State to produce better seed ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁਛੇ ਜਾ ਚੁਕੇ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਛਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਕਾਫੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ, ਸਪਲੀ-ਮੈਂਟਰੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਨਰੇਬਲ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲੀਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। (There is no doubt that a lot of discussion has taken place in this matter and enough supplementary questions have been asked about it. However, I would request the hon. Minister to see that every effort is made to have the declared policy of the Government with regard to the Harijans fully implemented.)

ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਾਸਨ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

Draught conditions in Tehsil Bhiwani, District Hissar

***8759. Shri Jagan Nath** : Will the Minister for Revenue be pleased to state :

(a) whether it is a fact that tehsil Bhiwani, district Hissar is again experiencing draught conditions, if so, the nature of the

revenue report, if any, received by Government from the tehsil authorities concerned ;

(b) the details of the steps being taken by Government to give relief to the people of the said tehsil ;

(c) whether he is aware of the fact that there is no work for the labourers and they are migrating to other areas in search of work ; if so the steps proposed to be taken to keep the labourers there ?

Sardar Harinder Singh Major : (a) Yes. The S.D.O., Bhiwani reported about the shortage of fodder and seed for Rabi, 1966 sowing.

(b) (i) Rs 3 lacs for fodder taccavi and Rs 2.50 lacs for seed taccavi have been sanctioned.

(ii) Recovery of taccavi loans which fell due in Rabi, 1965, has been suspended upto 15th December, 1965.

(iii) Seed and Camel Fodder Depots are being opened at suitable places.

(iv) Fair Price Shops for food grains are being set up. Further relief measures are under consideration of Government.

(c) It is incorrect that labour class is migrating to other areas in search of work.

श्री जगन्नाथ : क्या रेवैन्यू मिनिस्टर साहिब बतायेंगे कि वहां पर लोगों का लैंड रेवेन्यू मुश्राफ किया जाएगा ।

माल मंत्री : रेवेन्यू मुग्राफ करने के लिए कन्डीशन्ज़ ले डाऊन की हुई हैं and I am sure the hon. Member is aware of that अगर वह कन्डीशन्ज वहां पर लागू होंगी तो जरूर मुश्राफ किया जाएगा ।

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ 3 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਫੌਡਰ ਲਈ ਅਤੇ 2 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਸੀਡ ਲਈ ਤਕਾਵੀ ਵਜੋਂ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਕੀ ਮੈਂ ਪੁਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਯੁਟੇਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੇਰਾ ਇੰਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਰਕਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬਾਕੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ।

ਕਾਮਰੇਡ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ : ਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਚਾਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪਸ਼ੂ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਥੇ ਚਾਰਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁਕਾ ਹਾਂ । ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਰਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਕਹਿਰ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ । ਮਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੀਸੋਰਸਿਜ਼ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਦਵਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਤੋਂ ਕੋਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ।

ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ਾਪਸ ਖੁਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਕੀ ਮੈਂ ਪੁਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਥੇ ਵਖਰੇ ਵਖਰੇ ਫੌਡਰ ਦੀ ਕੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਹਦੇ ਲਈ ਸੈਪੇਰੇਟ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ।

श्री जगन्नाथ : वजीर साहिब ने फरमाया था कि जो कनडीशन्ज़ ले डाउन कर रखी है उन के अंदर अगर वह इलाका आएगा तो मालिया छोड़ दिया जाएगा। मगर इन के जो पटवारी हैं वह तो जहां पर न भी फसल हो वहां की भी अच्छी रिपोर्ट कर देते हैं क्योंकि तहसीलदारों के पास जब कागज़ ऊपर से जाते हैं तो वह कानूनगों वा पटवारियों को लिख भेजते हैं कि फसलों की अच्छी रिपोर्ट करो। तो जब ऐसे हालात हैं तो लोगों को फायदा कैसे पहुंच सकता है?

ਮੰਤਰੀ : ਜਗਨ ਨਾਥ ਹੋਰਾ ਨੂੰ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਏਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਮੇਰੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਗੇ ਕਿ ਫਲਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ contrary to the fact report ਦਿਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰਗੜਾ ਬਨ੍ਹਿਆਂ ਜਾਵੇਗਾ।

चौधरी देवी लाल : रेवेन्यू मिनिस्टर साहिब ने फरमाया है कि कुदरत की तरफ से अगर कहत पड़ जाए तो दुनियां की कोई ताकत नहीं जो उस का मुकाबला कर सके। हमारे हिसार में हर साल कहत साली हुआ करती थी लेकिन भाखड़ा बनने के बाद वहां का नकशा बदल गया। इसी तरह कुरुक्षेत्र में ऐपीडैमिक्स फैलते थ खाने को कुछ नहीं मिलता था मगर अब वहां टयूब-वेल लगे हुए हैं और नकशा बदल गया है। उन्होंने कहा है कि भिवानी तहसील से कोई हिजरत नहीं कर रहा लेकिन वहां से लोग बाहिर जा रहे हैं क्योंकि पिछले तीन सालों से वहां पर कहत पड़ रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि यह अपनी ठंडी नजर भिवानी की ओर भी करेंगे ?

ਮੰਤਰੀ : ੪ ਦਿਣ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੈਬਨੇਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਬਜੈਕਟ ਟੂ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 75 ਲਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਵਰਕ ਲਈ ਅਤੇ ਲਿਫਟ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਏਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਜੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਣ।

Shifting of population of Solra and Baghpur to other places beyond Zahar Nala

***8792. Shri Roop Lal Mehta** : Will the Minster for Revenue be pleased to state :

(a) the details of steps Government proposed to take last year to shift the population of villages Solra and Baghpur of Khadar Area (District Gurgaon) to other places beyond Zahar Nala, which is flooded in rainy season every year ;

(b) whether any land has been acquired by the Government for the affected people of the villages mentioned in part (a) above; if so, the reasons for which the same has not so far been allotted to them ?

Sardar Harinder Singh Major : (a) It was decided to shift the abadi of village Solra to village Thanthri in Palwal Tehsil and that of village Baghpur to village Mohna in Ballabgarh Tehsil.

(b) No land has been acquired so far. The question of allotment, therefor, does not arise.

श्री रूप लाल महता : क्या वजीर साहिब बताएंगे कि पिछले दो तीन साल मे जो यह मामला इन दो गांवों को उठाने का जेरे गौर है और डी० सी० के पास भी जमीन ऐक्वायर करने के लिए हुक्म भेजे थे यह मामला कब तक फाईनेलाइज़ हो जाएगा ?

ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਤੇ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਡਿਲੇ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਨੈਸੇਸਰੀ ਡਿਲੇ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਅਵਾਇਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ. . . .
I will see that the matter is expedited and finalised at a very early date

Deputy Speaker : Next question please.

— — — —

Students admitted in Medical Colleges at Ludhiana and Amritsar

***8791. Shri Roop Lal Mehta** : Will the Minister for Health be pleased to state :

(a) the total number of students from the Hindi Region, district-wise, admitted in the Medical Colleges at Ludhiana and Amritsar for the 1964-65 and 1965-66 sessions, separately;

(b) the total number of students recommended every year by the Government for admission in the Medical Colleges at Ludhiana and Srinagar, respectively ;

(c) whether the Government propose to give weightage to the students of the backward areas for admission in the Medical Colleges ?

Sardar Ajmer Singh (Minister for planning and Local Government): (a) , (b) and (c) The information is laid on the Table of House.

	Dayanand Medical College, Ludhiana		Christian Medical College, Ludhiana		Medical College, Amritsar	
(a)(i) 1964-65	Ambala	3	Gurgaon	1	Karnal	4
	Hissar	2			Hissar	1
	Gurgaon	2			Kangra	5
	Rohtak	2			Kulu	1
					Gurgaon	92
					Ambala	4
Total	..	9		1		17
(ii) 1965-66	Ambala	3	Nil		Gurgaon	2
	Karnal	1			Kangra	4
	Hissar	3			Kulu	1
	Gurgaon	1			Hissar	4
	Kangra	1			Karnal	4
					Simla	2
					Ambala	2
Total		9		Nil		19

[Minister for Planning and Local Government]

(b) From the Session, 1965-66, Punjab Government have started nominating 2 candidates to Dayanand Medical College, Ludhiana. Prior to 1964-65 admissions, 6 candidates used to be nominated by State Government to Medical College, Srinagar. During 1964-65 session the Jammu and Kashmir Government admitted only 3 State Government nominees. During 1965-66 session, 5 candidates have been nominated to Medical College, Srinagar.

(c) Ten per cent seats are already reserved in Government Medical Colleges for the candidates belonging to Backward areas of the Punjab State.

श्री रूप लाल महता : वज़ीर साहिब ने जो 1964-65 और 1965-66 का स्टेटमेंट दिया है उसमें बताया गया है कि ज़िला गुड़गांव के बहुत कम लड़कों को दाखला मिला है । क्या इस बैक्वर्ड इलाके पर नज़रे अनायत करते हुए दाखला के मामला में वहां के लड़कों को तरजीह देने की तरफ ध्यान देंगे ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਸਵਾਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁਛੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁੜਗਾਉਂ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਐਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਸਨ ਅਤੇ ਐਨੇ ਕਿਉਂ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਏ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਇਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਲੇਫਟੀਨੈਂਟ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਇਹ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਿਸਚਿਨ ਮੈਡੀ-ਕਲ ਕਾਲਜ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਵਜਾਹ ਹੈ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਸ ਵਕਤ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਇਤਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਜਾ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਊਸ ਵਲੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਦਾਖਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫੈਕਟ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਦਾਖਲਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ।

श्री रूप लाल महता : क्या यह बात बजीर साहिब के नोटिस में है कि पिछले साल गुड़गांव जिले का एक लड़का यहां से कशमीर मैडिकल कालिज में दाखल होने के लिए भेजा गया लेकिन उसे वहां दाखला नहीं मिला और उसे फिर वापिस बुलाना पड़ा ? मैं पूछना चाहता हूं कि जब पंजाब गवर्नमेंट के फैसला के साथ वहां गया तो उसे क्यों वहां दाखिल नहीं किया गया और उसके साथ ऐसा सलूक क्यों किया गया ? उसे क्यों खामखाह खर्च के जेर बार किया गया ?

Minister : I have no information on that point with me, Madam, here.

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 6 ਸੀਟਾਂ ਨਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਨ ਲੇਕਿਨ 1964-65 ਵਿਚ ਕੇਵਲ 3 ਲੜਕੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ 6 ਸੀਟਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਨ ਤਾਂ ਕੀ ਵਜਾਹ ਹੈ ਕਿ 3 ਲੜਕੇ ਹੀ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਇਕ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਣਾ ਪਿਆ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਉਸ ਸਾਲ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਇਤਲਾਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਉਥੇ ਘਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਪਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲੜਕੇ ਘਟੇ ਹਨ।

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਹਰ ਸਾਲ ਉਸ ਕਾਲਜੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮੀਨੇਟ ਹੋਏ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ? ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਵੈਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮੀਨੇ-ਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ

डाक्टर बलदेव प्रकाश : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि कशमीर मेडीकल कालिज में जो सरकार स्टूडैंटस नामीनेट करती है या दूसरे मैडीकल कालिजों में एडमिशन होती है वह नामीनेशन मेरिट पर करते हैं या ज़िला-वार कोटा है ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਕੋਟਾ ਨਹੀਂ। ਗੌਰਮਿੰਟ ਅਤੇ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਫਰਰਜ਼ ਹੋਣ, ਗਰੀਬ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾਮੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

डाक्टर बलदेव प्रकाश : यह तो बढ़ा वेग जवाब है। मैं तो यह पूछना चाहता हूं कि अगर सरकार ने नामीनेट करने के लिए कोई क्राईटेरिया रखा है तो उसे बताने की कृपा करें।

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਸਵਾਲ ਵਿਚ ਪੁਛੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੈਪੇਰੇਟ ਨੋਟਿਸ ਦਿਓ।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰਕਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਿਜ ਲਈ ਨਾਮੀਨੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕਰ ਉਹ ਕਾਲਿਜ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੀ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਸਟੈਪਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਪਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਉਹ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।

श्री जगन्नाथ : [* * *

* * * * *

* * *]

उपाध्यक्षा : यह क्या तमाशा है कि जब आपका जी करता है खड़े हो जाते हैं और जो मन में आता है कह देते हैं। मैं आप को बाकी सैशन के लिए बोलने की इजाजत नहीं दूंगी अगर ऐसा करेंगे। श्री जगन्नाथ ने जो यह बात कही है वह ऐक्सपंज कर दी जाए।

(What a strange thing ! The hon. Member rises whenever he likes and says things whatever he wants. If he behave like that I will not allow him to speak during the remaining period of the session. Whatever has been said by Shri Jagan Nath should be expunged.)

ਕਾਮਰੇਡ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ : ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀ-ਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਮੈਰਿਟ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਮੈਰਿਟ ਨਾਲ

Note :—*Expunged as ordered by the Chair.

[ਕਾਮਰੇਡ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ]

ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਥਰਡ ਕਲਾਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ? ਕੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮੁਆਹਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਨਾਮੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਥੇ ਨਾਮੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ । ਮੈਰਿਟ ਦਾ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਰਿਟ ਤਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਭ ਇਥੇ ਹੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।

So some other considerations which are very weighty in some cases have also to be taken into account:

श्री अमर सिंह : सवाल के जबाब में जो लिस्ट दी गई उस में हरिजनों के लड़के तथा बैकवर्ड एरिया के स्टूडेंटस बहुत कम कालिजों में लिए गए हैं । क्या वजीर साहिब बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार के विचाराधीन कोई स्कीम है जिस से हरिजनों के लड़कों को तथा बैकवर्ड एरियाज़ के स्टूडेंटस को मैडिकल कालिजों में दाखिल होने की सुविधा हो सके ?

Minister : In part (c) of the question it has been asked whether the Government propose to give weightage to the students of the Backward area for admission in the Medical Colleges and in reply to this I have already stated that ten per cent seats are already reserved in Government Medical Colleges for the candidates belonging to Backward areas of the Punjab State.

ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਫਰਰਜ਼ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਿਜਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੇ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੈਪੇਰੇਟ ਨੋਟਿਸ ਦਰਕਾਰ ਹੈ ।

UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS

Supply of Bhakra Canal waters to certain areas of Rupar and Kharar Sub-Divisions

3044. Comrade Shamsher Singh Josh : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state :—

(a) whether Government ever undertook any survey to provide Bhakra Canal Waters to any areas of Rupar and Kharar Sub-Divisions, if so, a copy of the survey report be laid on the table of the House ;

(b) if the answer to part(a) above be in the affirmative, whether Government has prepared or intend to prepare any scheme based on the said Survey Report for providing a water to the said sub-divisisons or any area thereof?

Chaudhri Rizaq Ram : (a) *Yes, covering a part of Rupar Sub-Division only. A copy of the Project Survey Report is as follows:

(b) It is proposed to consider these areas as and when there is actual demand from the cutlivators.

---

*Note : Revised reply. For previous reply pleased see the P.V.S. Debate Vol. II No, 19 dated the 15th November, 1965

Subject.—Providing irrigation facilities to the area lying between Nangal Hydel Channel and river from Nangal to Rupar.

Will the Secretary to Government, Punjab, Irrigation and Power Departments, kindly refer to the correspondence ending with this office U.O. No. 1033/WG/569/56, dated 21st June, 1958, regarding assurances given by the Ministers on the floor of the Vidhan Sabha ?

2. With reference to item No. 7 of communication No. 6 referred to in para 3 of the U.O. noted above, it is stated that it has been proposed to provide irrigation facilities to the area lying between Nangal Hydel Channel and river Sutlej from Nangal to Rupar. Accordingly , a Project estimate amounting to Rs 4,68,300 has been prepared for this work, chargeable to Unit No. 6 of the Bhakra Canals and is enclosed herewith for perusal and return.

3. This scheme is to provide irrigation facilities to a gross area of 15,058 acres and C.C.A. of 13,487 acres. Revenue staff was deputed to contact the local inhabitants and find out their views in order to assess the utility of this scheme. The success or failure of any scheme depends on the fundamental principle of demand and supply. The Revenue Officer deputed for investigation in this respect has stated that there is practically no demand for canal irrigation in this area. A similar scheme for two direct outlets W.D. 7,955 and 12,770 in the head reach of Nangal Hydel Channel for 1.4 Cs were sanctioned and the experience gained from that scheme is not encouraging at all. During the year 1957-58 there has been a total irrigation of 5 acres and 4 acres respectively against a total C.C.A. of 625 acres. In case this be the measure for visualising the benefits of the new scheme, the signs are not at all encouraging. The various reasons for the same are also given as under:

(i) The rainfall in this region is substantially high and ranges on an average up to 48 inches per annum. Moreover, this is fairly evenly spread from June to October, and is most suitable for the sowing and maturing Kharif crops without depending on any canal supply. Quite often even Rabi Crops are sown Barani. As such there is no anxiety or keenness on the part of the land owners to seek canal irrigation.

(ii) Secondly chaks of this project lie between Nangal Hydel Chamnel and River Sutlej and Comprises of rocky, uneven and partly hot area. The mantenance of watercourse is difficult, expensive and unattractive in this term.

(iii) The major crop patterns of this area are Maize in Kharif and wheat in Rabi. Both are matured Barani satisfactorily. Canal Irrigation can little improve the existing pattern of crop.

(iv) The holdings of the Zamindars are very small, consolidation has not so far been done and hence lack of keenness for canal irrigation on the part of the Zaminders. They prefer to have easy barani crops rather than undergo hard labour in order to sow cash crops.

4. At present the supplies for irrigation purpose are available only as late as by and of May when almost sowing period is passed. Similarly little supply is available in Rabi. As such due to the supplies being not available at proper time, the Zamindars are not keen to get canal water. Moreover, out of 31.91 Cs discharge required to irrigate the area 22.87 Cs. are required to be taken u/s of Kotla and Ganguwal Power Houses and as such will reduce the available supply for developing power.

5. Under the circumstances it is not considered worth while to incur a huge expenditure to ths cxtent of Rs 5 lacs when there appears to be no prospect at all for the development of irrigation in this area. Moreover, we have already utilised the saving for the total area of C.C.A. of Bhakra Nangal Project for preparing the scheme of Dewa Minor which is comparatively a much better scheme will give higher return, and is already being taken up for execution. However, this scheme may be considered sometimes later during the Third Plan period by which time perennial Bhakra Supplies are expected to be available.

(Sd) . . . ,
Executive Engineer,
for Chief Engineer, Irrigation Works, Punjab, Chandigarh.

D.A.

Estimate for persual and return.

[Minister for Irrigation & Power]

To

The Secretary to Government, Punjab,
Irrigation and Power Departments, Chandigarh.

U.O. No. 1771/Project/982/50, dated 18th April, 1960

Endorsement No. 2499-2500/Project/982/50

Copy forwarded to the Executive Engineer, Planning, Irrigation Branch (Planning Section) / Superintending Engineer Nangal Circle for information with reference to his U.O. No. 3691/Planning /59, / No. 840/99-W, dated 22nd September, 1959.

9th February, 1960

(Sd) . . . ,
Executive Engineer,
for Chief Engineer, Irrigation Works, Punjab, Chandigarh.

PROJECT ESTIMATE FOR IRRIGATION OF AREAS LYING BETWEEN NANGAL HYDEL CHANNEL AND RIVER SUTLEJ FROM NANGAL TO RUPUR (CHARGEABLE TO UNIT NO. 6 BHAKRA CANALS).

REPORT

The Project Estimate amounting to Rs. 468300/-. has been framed to cover the probable cost of the above noted work.

The area proposed to be irrigated is intercepted by numerous torrent and creeks, therefore separate details for each block of area have been worked out as noted below:—

(1) Irrigation Scheme for the area lying along Nangal Hydel Channel R.D. 7000—25000 Nangal Hydel Channel.

(2) Irrigation Scheme for area lying between R. D. 25000-37000 NHC

(3) Ditto R. D. 37000-46000 „

(4) Ditto R. D. 58000-68000 „

(5) Ditto R. D. 77250-84705 „

(6) Irrigation Scheme for the area lying between Lotan and Kundlu Khad i.e. opposite R.D. 125000-131000 right of Nangal Hydel Channel.

(7) Irrigation scheme for the area of villages Awankot Kotbela, Aspur Majra i.e. between R.D. 154000-156000 of Nangal Hydel Channel.

(8) Irrigation scheme for the area lying on right side of Nangal Hydel Channel between R.D. 174000 to 179000.

(9) Irrigation scheme for the area lying on right side of Nnagal Hydel Channel between Chandpur and Laudal Khads opposite R.D. 179000-180500.

(10) Irrigation scheme for the area lying on right side Nangal Hydel Channel between Laudal and Bairampur Khads opposite R.D. 186500-191000.

The Scheme proposed to provide irrigation to these areas where the water table is more than 15 ft. below the natural surface.

Brief description of each of the scheme is noted below :—

1. Irrigation Scheme for the area lying on right side of Nangal Hydel Channel R.D. 7000-25000

Total C.C.A. to be irrigated under this scheme is only 625 acres for which two direct outlets from the Nangal Hydel Channel have been provided at R.D. 7955-R and

the other at R.D. 12720 Right. The outlets at R.D. 7955 right is a lift outlet and the other is a flow outlet. The area proposed to be irrigated and discharge required for the same are noted below :—

Site of off-take	Gross area	CCA	Dis-charge	Length of minor in ft.	No. of Bridges	No. of Rly. Crossing
1. Pump at R.D. 7955(R)	288	260	0.6	Direct lift outlet	..	..
2. Outlet R.D. 12720 (R)	405	365	0.8	Direct outlet	..	..

This scheme has been sanctioned vide Secy. No. 1941/P/982 dated 8th May, 1954 chargeable to 80-A Capital 1, Works, Bhakra Nangal Project and has been actually executed at site. Since no provision for the same exists in the Project Estimate for Nangal Hydel Channel (Unit No. IV) therefore, it is proposed to charge its cost to unit No. 6, III Distributions Bhakra Canals.

It is further proposed to bring more area under irrigationon the above noted outlets as detailed betlow :—

Existing Gross area / CCA	Now proposed gross area / CCA	Existing discharge	Proposed discharge
(i) 288/260	418/364	0.60 cus.	0.82 cus.
(ii) 405/365 (flow)	945/797	0.80 cus.	1.8 cus.

The size of flow outlet at R.D. 12720 and capacity of the Pump installed at R.D. 7955 for lift irrigation are sufficient to cope with the increased discharge, required in each case. Construction of water courses is the responsibility of share holders and as such no extra cost is involved in extending irrigation to the additional area referred to above.

2. Irrigation scheme for the area lying on Right side of Nangal Hydel Channel R.D. 25000-37000

Under this scheme it is proposed to irrigate area lying between Ajoli and Donala Khade. It is proposed to take off a channel 2½ miles long at R.D. 28000 right Nangal Hydel Channel. The alignment of the channel crosses the pucca road from Nangal to Rupar, as well as the Railway line for extending irrigation to the area lying across the Railway line. The details of the area proposed to be irrigated and the works to be constructed are noted below :—

Site of off-take	Gross Area	CCA	Dis-charge	Length of Minor in feet	No. of Bridges	No. of Railway crossing
R.D. 28000 R	3875	3488	8.50	12500	3 No.	1 No.

[Minister for Irrigation and Power]

3. Irrigation Scheme for the area lying on the Right side of the Nangal Hydel Channel R.D. 37000-46000

Under this scheme it is proposed to provide irrigation to area lying between Donala and Debitwali Khad. It is proposed to take off a channel of about 3.0 miles in length at R.D. 37400 Nangal Hydel Channel. This channel will also cross the pacca road from Rupar to Nangal and the Railway line hence, 1 No. A.R. Bridge and 1 No. Railway crossings will be provided. The details of areas proposed to be irrigated and works to be constructed are noted below :—

Site of off-take	Gross area	CCA	Dis-charge	Length of Minor in feet	No. of Bridges	No. of Railway Crossing
R.D. 37400 R.	3450	3105	7.5	13000	5 No.	1 No.

4. Irrigation Scheme for area lying between R.D. 58000-68000

It is proposed to take off a channel from R.D. 58000 right of Nangal Hydel Channel. The channel will be two miles long and will cross the canal, Railway side to Power House No. 1 as well as the Railway line from Rupar to Nangal. It will also cross the pacca road from Rupar to Nangal. The details of area included within the irrigation boundary of this channel and works to be constructed are detailed below :—

Site of off take	Gross area	CCA	Dis-charge	Length of minor in feet	No. of Bridges	No. of Railway crossing
R.D. 58000	1400	1260	3.25	11000	3 No.	2 No.

Two number water courses will also cross the pacca road as well as the Railway line from Nangal to Rupar. The area lying between the Nangal Hydel Channel and the River Sutlej from R.D. 68000-70000 is generally broken land hence no irrigation scheme is workable for this area.

5. Irrigation Scheme for the area lying on right side of Nangal Hydel Channel between the Pucca road and the Railway line from Nangal to Rupar opposite R.D. 77250 to 84705 Nangal Hydel Channel

Under this scheme it is proposed to provide irrigation to the area lying between the Pacca road and Railway line from Rupar to Nangal. Detail of the area and works proposed to be constructed are noted below :—

Site of off-take	Gross area	CCA	Dis-charge	Length of minor in feet	No. of Bridges	No. of Railway Crossing
R.D. 77250(R)	600	540	1.0	3500	..	..

Irrigation will start about 3/4 miles away from the site of off take as land from the Canal to the pacca road is very uneven and no water course can be constructed. It is therefore, proposed to lay a pipe line from Canal to road and then to dig a water course. A Masonary tank will be constructed at the head of Pipe.

The area lying on right side of the Nangal Hedel Channel from R.D. 77000 to Lotan Khad R.D. 126000 is mostly broken land or it lies very near to the river Sutlej, where it is effected from the river spills and the spring level is also high.

6. Irrigation Scheme for the area on the right of Nangal Hydel Channel between R.D. 126000 to 131000 right Nangal Hydel Channel

The area opposite R.D. 126000 to 131000 right of Nangal Hydel Channel is between Lotan and Kundlu Khada used to be irrigated by means of Kuhls prior to the constructed of the Nangal Hydel Channel but irrigation tothis area from Kuhls has been obstructed on account of construction of the Canal. Now it is proposed to irrigate the area by providing flow irrigation from the Nangal Hydel Channel for which an outlet to serve this area has been proposed at R.D. 127438 Right of Nangal Hydel Channel. The details of the scheme are as below :—

Site of off take	Gross area	CCA	Discharge	Length of W.C.	A.R. culvert.	No. of Railway crossing	No. of regulator
R.D. 127438 NHC	750 acres	675 acres	1.5 cs.	10000	1 No.	..	.

The sub-soil water level in this area is about 10 feet below N. S. since on both sides of the area. There arelying two big torrents, which will serve as drainage, therefor, there will be no likelihood of the area being water logged. The scheme has been included with a view to meet the demand of the Zamindars.

It was originally proposed to provide irrigation to this area by lift through tube-wells and irrigation proposals for the same were submitted vide this office letter No. 24189/99W. dated 3rd August, 1958. The Chief Engineer, advised that the scheme should be sent to the S.E. Project, who should look into the feasibility of providing lift irrigation by tube-wells.

The Superintending Engineer, Project vide his letter No. 4288/52—dated 2nd March 1957, to the address of the S.E. Nangal Circle, has informed that it will be un-economical to provide irrigation by tube well to isolate areas. He therefore, declared to work out lift irrigation by tubewells copy of his letter is attached for ready reference. Matter was also referred to the Chief Entineer, vide S.E. Nangal Circle, letter No. 17655/9CW, dated 10th July, 1957 but no further instructions have been received from the Chief Engineer.

Since the D.C. Ambala is writing for providing irrigation to this area the irrigation by Kuhls having been cut off, on construction of Nangal Hydel Channel copy of D.C. Ambala letter No. 1543/A, dated 2nd September, 1957 received from S.E. Project Circle vide his endst. No. 17471/52, dated 10th September, 1957, is attached for reference.

No irrigation to the area lying on right side of the Nangal Hydel Channel opposite R.D. 136000 to 156000 as the sub soil water level is high due to the area lying very near to the river Sutlej.

7. Irrigation Scheme for the area between R.D. 154000 to R.D. 156000 Right Nangal Hydel Channel

Particulars relating to this scheme are noted below :—

Site of off take	Gross area	CCA	Discharge	Length of WC
R.D. 155565 NHC	320	268	0.65	6000

[Minister for Irrigation and Power]

The other details are as per details in the estimate. The area opposite R.D. 156105 to R.D. 161000 Right of Nangal Hydel Channel lies in Sirsa bed and the area opposite R.D. 173000(R) being in depression and water logged have not been taken for flow irrigation.

6. Irrigation Scheme for the area lying between R.D. 174000 to R.D. 179000 Right of Nangal Hydel Channel

Irrigation Scheme for the area between Mansoli and Chandpur Khads. The main particulars of the scheme are noted below :—

Site of off take	Gross Area	CCA	Discharge
R.D. 176877 (R) NHC	1300 acres	1170	2.62 cs.

For other details detail of the estimates may please be referred to.

9. Irrigation Scheme for the area between R.D. 179000 to R.D. 186500 Right of Nangal Hydel Channel

Irrigation Scheme for the area between Chandpur and Laudal Khads.

The gross area is 7000 acres and C.C.A. 630 acres. Irrigation to this area can be given by providing a direct outlet at R.D. 180000 just on the U/s of the Railway bridge. A part of the area lies on the other side of Railway Line and the pacca road from Rupar to Nangal. Adequate water course crossing under the Railway line and pacca road will be provided.

Site of off take	Gross area	CCA	Discharge	A.R. Crossing	Railway Corssing
R.D. 180000(R) NHC	700 acres	630 acres	1.42 cs.	1 No.	1 No.

10. Irrigation Scheme for the area lying between Laudal and Bairampur Khads R.D. 186700-R.D. 191000 Nangal Hydel Channel

The main particulars of irrigation scheme for the area between Laudal and Barampur area below :

Site of off take	Gross area	CCA	Discharge	A.R. Crossing	Railway Crossing
R.D. 187000(R) NHC	1000 acres	900	2.0	1 No.	1 No.

11. Irrigation Scheme for the area between R.D. 19100-Tail Right Nangal Hydel Channel

The main particular of irrigation scheme for the area between Bairampur Khad and Tail of Nangal Hydel Channel are as below :—

Site of off take	Gross area	CCA	Discharge	A.R. Crossing	Railway Crossing
R.D. 191500(R) NHC	300 acres	270	0.6 × .25 : .85 cs.	..	...

The area lies just close to the Rupar tract and is already under irrigation by wells. Irrigation limit is fixed upto pacca road from Rupar to Nangal. The area is cut off by the Railway line, pacca road from Rupar to Nangal, almost into two equal parts. It is therefor necessary to provide a water course culvert under the pacca road and water course crossing under the Railway Linel The area is situated very near to the Rupar town and very fertile. The area at present under well irrigation, and provision of canal water will add to food production and country wealth. A Statement showing the S.S.W.L. for the area from R.D. 125000 to Tail is attached.

Total gross area of all these schemes comes to 15,058 acres and the C.C.A. 90 per cent of C.C.A. comes to 13,487 acres. The intensity of Irrigation in the pre—Bhakra Stage has been assumed at 35 per cent which is the same as for non-perennial, irrigation for the areas being irrigated by the Bhakra Canals. The intensity of irrigation has been adopted at 15 per cent for the first year. 25 per cent for the second year and 35 percent for the third year after commencement of irrigation. In the past Bhakra Stage the final intensity to be attained is presumed to be 45 per cent which is same as for restricted perennial irrigation for the area served by the Bhakra Canals.

Financial forecast for the Scheme is enclosed herewith. It shows that without batterment charges the schemes start giving a return of 4.7 per cent in the 3rd year after the commencement of Irrigation. If the betterment charges are taken into account the revenue return steps up to 6.6 per cent during the same year. Thus it is evident that the Project is self supporting. For working out the financial forcast the betterment charges have been accounted for from the third year onwards after the commencement of irrigation.

The establishment charges and III T and P charges have been worked out in the Project estimate at 10 per cent and 1 per cent respectively of the total cost of 1-Works.

(Sd.) .. .. ..
Superintending Engineer,
Nangal Circle, Rupar.

SHORT NOTICE QUESTION AND ANSWER

Abolition of Octroi Duty imposed on Cement Factory Charkhi Dadri, district Mahendragarh

***8819. Comrade Ram Piara** : Will the Minister for Planning and Local Government be pleased to state :

(a) whether the Government has recently decided to abolish octroi duty already imposed on the Cement Factory, Charkhi Dadri, district Mahendragrah; if so, the date when such decision was taken and the reasons therefor ;

(b) whether the Government have examined the question of loss of income to the Municipal Committee concerned on account of the abolition of the said duty, if so, the estimated loss to the said Committee on this account, if it had not been examined the reasons therefor ;

(c) whether Government have recently received any representation from the public of Charkhi Dadri requesting the Government not to abolish the said octroi duty, if so, a copy of the same be laid on the Table of the House ;

(d) the designation of the authority, if any that examined the said representatiton ?

Sardar Ajmer Singh : (a) No, the matter is yet under consideration

(b) Does not arise .

(c) Yes. A telegram dated the 15th November, 1965 from one Shri Ram Kishen has been received, a copy of which is laid on the Table of the House ;

(d) The representation is under consideration of the Government.

Copy of telegram dated the 15th November 1965 from Shri Ram Kishen Charkhi Dadri to the Local Government Minister

Geat resentment against decisison of Government abolishing Octroi duty imposed on Cement Factory, Charkhi Dadri . Please reconsider and reimpose octroi grant for interview.

Ram Kishan

कामरेड राम प्यारा : वजीर साहिब ने फरमाया है कि यह मामला जेरे गौर है । क्या वजीर साहिब बताएंगे कि क्या यह मामला लोकल सैल्फ गवर्नमेंट के वजीर के विचाराधीन है या कैबनिट के विचारधीन है ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਮੈਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਹਾਂ । ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਅੰਡਰ ਕੰਨਸੀਡਰੇਸਨ ਹੈ ।

कामरेड राम प्यारा : क्या वज़ीर साहिब बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार डालमिया की सीमिंट फैक्टरी की तरफ से रिप्रीज़ेंटेशन आने पर ही आक्टराय डियूटी को अबालिश करने के लिए सोच रही है ।

ਮੰਤਰੀ : ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲਜ਼ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਆਨਰੇਬਨਲ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ । ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਲੋਂ ਰੀਪ੍ਰੀਜੇਂਟੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ । ਉਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਡਿਫੀਕਲਟੀਜ਼ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਬਾਹਿਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਉਤੇ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ) ਹੀ ਆਕਟਰਾਏ ਡਿਯੂਟੀ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਨੀ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਉਤੇ ਆਕਟਰਾਏ ਡਿਯੂਟੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ । ਮੈਂ ਮਿਉਨੀਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਰੀਪ੍ਰੀਜੈਂਟੇਟਿਵ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ । ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅਜੇ ਆਪਣਾ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਕਨਵੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਐਕਸ ਐਮ. ਪੀ ਦੀ ਇਕ ਤਾਰ ਆ ਗਈ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੰਸਿਡਰ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਨਵੰਬਰ, 1965 ਦੀ ਡੇਟ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਉਸ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮਿਉਨੀਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਰੀਪ੍ਰੀਜੈਂਟੇਟਿਵ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ।

कामरेड राम प्यारा : क्या वज़ीर साहिब बताने की कृपा करेंगे कि जब यह आक्ट्राय डियूटी पहले लगी हुई है तो उस को बन्द क्यों किया जा रहा है ? इस मामले को अब क्यों टेक अप किया जा रहा है ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਕਟਰਾਏ ਡਿਯੂਟੀ 35, 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗੀ ਸੀ । ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਹੋਏ ਆਕਟਰਾਏ ਡਿਯੂਟੀ ਅਬਾਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ । ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਡਿਯੂਟੀ ਫਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਮਗਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਫਿਰ ਅਬਾਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ । ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ।

कामरेड राम प्यारा : क्या वजीर साहिब बताने की कृपा करेंगे कि जब फैक्टरी वालों की रीप्रीजेन्टेशन रिजैक्ट हो चुकी है तो उस मामले को दोबारा ओपन क्यों किया जा रहा है ?

ਮੰਤਰੀ : ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਰੀਪ੍ਰੀਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੇਚਰਲੀ ਉਹ ਕੰਨਸਿਡਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

It may be rejected or not. The mere fact that a hearing is being given does not mean that we are going to revive it or decide against it It is an open question and may be decided one way or the other.

कामरेड राम प्यारा : क्या वज़ीर साहिब बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार बड़े और प्रभावशाली व्यक्तियों की ही रीप्रीजेन्टेशन पर दोबारा गौर करती है ? आम जनता की कोई रीप्रीजैन्टेशन जो पहले रिजैक्ट हो गई है क्या उसको भी दोबारा कंसिडर करने की पालिसी इख्तियार करली है ?

ਮੰਤਰੀ : ਅਜਿਹੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Unless there is any legal bar in the deciding of a matter the Government can consider it as an executive action.

चौधरी नेत राम : क्या वजीर साहिब बताने की कृपया करेंगे कि क्या सरकार सरमायदारों को ही टैक्सों में छूट दिलाने में मदद करती है या क्या आम जनता को सुविधा देने की तरफ भी कोई ध्यान देती है ? क्या इस चीज़ को देखते हुए सीमेंट के रेटस में कमी की जाएगी ?

ਮੰਤਰੀ : ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਮੁਕਰਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਚੀਜ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੇ ਬਸ ਵਿਚ ਹੈ। (*Noise*)

Deputy Speaker : Order please, no noise please. Please take your seat.

श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री : क्या वज़ीर साहिब बताने की कृपया करेंगे कि जब इस के बारे में किसी माहाराजा के साथ ऐग्रीमेंट खत्म हो गया था और वह फैक्टरी म्यूनिसिपल कमेटी की हद के अन्दर आ गई तो इस के बाद अक्ट्राय ड्यिटी लगाई गई । फिर इस मामले को दोबारा क्यों टेक अप किया जा रहा है ?

Minister : It is yet to be seen whether that agreement is binding on the successor Government or not. It is a matter to be investigated. The mere fact that it is yet under consideration does not mean that allthose agreements have come to an end.

शिक्षा मंत्री : मैं आनरेबल मिनिस्टर की इजाजत से यह बात क्लीयर कर देना चाहता हूं । चौधरी नेत राम ने कहा कि यह सरकार केवल सरमायादारों की ही मदद करती है । यह गलत बात है । मैं उस वक्त इस महकमें का वजीर था । उस फैक्टरी वालों ने मेरे पास एक रीप्रेजेंटेशन भेजी थी और मैंने देखा कि the factory was in a position to pay the octroi duty. मैं ने उस वक्त देखा कि इस आक्टायी टैक्स से म्युनिसिपल कमेटी को फायदा होगा । इस लिए सीमेंट के रा मैटीरियल पर यह टैक्स लगाया गया । अब भी यही पालीसी चल रही है । इस लिए आनरेबल मैम्बर महसूस करेंगे कि यह सरकार आम जनता की भलाई को देखती है और यह सरकार अमीर लोगों को फायदा पहुंचाने की कोई कोशिश नहीं करती है ।

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਔਕਟਰਾਏ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਬਾਦ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਔਕਟਰਾਏ ਉਸ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੀ ਵਜੂਹਾਤ ਸਨ ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ in the absence of having seen the record ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੀ ਵਜੂਹਾਤ ਸਨ ?

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੈਪਰੇਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਦਫਾ ਔਕਟਰਾਏ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਵਜੂਹਾਤ ਹਨ ?

Minister : My colleague has just now stated that the Factory was in a position to pay. That was one of the reasons which weighed with him That reason is before you.

(इस समय कामरेड राम प्यारा बोलना चाहते थे परन्तु उपाध्यक्षा नें उन को **बोलने की इजाजत नहीं दी**)।

Statement by the Deputy Speaker re-supply of wheat and quilts to the persons uprooted due to Pakistani Aggressions.

उपाध्यक्षा : मैंने शुक्रवार को इस हाउस में एक जिमेदारी ली थी । वीर वार के दिन इस हाउस में कुछ गेहूं और एक रजाई दिखाई गई थी । उस पर काफी गर्मा गर्मी हुई बहुत बातें हुई चुनांचि हाउस की इजाजत से मैंनें कहा था कि मैं वहां पर जा कर मालूम कर के वापस आ कर आप को रिपोर्ट करूंगी । मैंने कम से कम 6 घंटे इस पर खर्च किए । तरन तारन में तीन कैम्पों में गई पट्टी में भी गई । जैसे मैंने कहा था कि मैं सरप्राईज विजिट करूंगी मैंने किसी को एतला नहीं दी और किसी को नहीं बुलाया । (विघन) आर्डर प्लीज । कैम्प की किसी एक कोठड़ी में जा कर मैंने पूछा कि आप के पास गेहूं कौन सा है। जो उन्होंने दिखाया उस की मैंने मुट्ठी भर ली और उस की पुड़ियां बांध कर ऊपर उस का नाम लिख दिया । इसी तरह से मैं ने पट्टी में भी किया । जहां तक रजाई का ताल्लुक है पट्टी कैम्प में टेंट लगे हुए हैं वहां किसी एक टेंट में जा कर जो रजाई मेरी समझ में आई वह मैंने उठा ली । तमाम गेहूं का नमूना जो मैं वहां से लाई हूं और रजाई मैंने अपने चेम्बर में मैम्बर साहिबान के मुलाहजे के लिए रखी हुई है । यहां वापस आ कर चन्डीगढ़ कोआप्रेटिव स्टोर्ज से जो गेहूं हमें मिलता है वह भी मैंने मंगवाया है । पता नहीं कि वह अभी तक आया है या नहीं । मैंने जो कुछ देखा है, मैं उस के बारे में कुछ कहना नहीं चाहती । वे सब चीजें आप के सामने हैं। मैं दरखास्त करूंगी कि इस के बाद आनरेबल मैम्बर साहिबान में अगर कोई परसनल बात है तो उस का आपस में फैसला कर लेना चाहिए । हाउस में ऐसी बातें नहीं होनी चाहियें। ऐसे नाजुक दौर में, ऐसे मौके पर जब कि हमारा धर्म है कि जो भाई और बहिनें अपरूट हो कर आए हैं उन की ठीक तौर पर मदद की जाए अगर कोई कमी रह गई है तो वह आपस में मिल कर दूर कर लेनी चाहिये । मेरी बड़ी तसल्ली है और आप लोगों की भी हो जाएगी । (चीयर्ज़) इसके बाद मैं इस मामले पर किसी तरह की बहस करने की इजाज़त नहीं दे सकती । आप लोग मेहरबानी कर के मेरे चैम्बर में यके बाद दीगरे आ कर हर एक चीज को देख लें । उस के बाद मैं हाउस में इजाजत नहीं दूंगी, मुझे मेरे चेम्बर में बता दें कि उस में क्या कमी है ।

(सरदार नारायण सिंह शाहबाजपुरी खड़े हो गए) Will you please take your seat ? सरदार नारायण सिंह शाहबाजपुरी ने रजाई यहां पर रखी थी । मैं नहीं चाहती थी कि उस के बारे में कुछ कहूं । लेकिन उन्होंने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं बात को कहूं । मुझे कुछ मालूम नहीं कि वह कहां से लाए । तरन तारन में एक टांक क्षत्री बुंगा है । मैं उस इलाके को अच्छी तरह से जानती हूं । (विघन) (विघ्न) मुझे देख कर बुंगे में से बीबी महिन्द्र कौर दोड़ी हुई आई । मुझ से कहने लगी कि हमारी रजाई

हमें वापस दे दो । मैंने पूछा कि किस के पास है तेरी रजाई तो वह कहने लगी कि सरदार नारायण सिंह शाहबाजपुरी ले गया है । मैंने उस से पूछा कि तुम ने क्यों रजाई दी । तो वह कहने लगी कि अगर आप मुझ से कोई चीज़ देखने के लिए मांगे और फिर साथ ले जाएं तो मैं क्या कर सकती हूं

विघ्न) (शोर) विघ्न) शोर)

बीबी महिन्द्र कौर से मैं कनक भी लाई थी । वह भी लाल पुढ़ी में बान्धी पड़ी है आप लोग वह भी देख सकते हैं । (विघ्न) मैं इस पर मजीद बहस की इजाज़त नहीं दूंगी ।

(I took over a responsibility on myself on Friday. On Thursday some wheat and a quilt were shown in the House which generated a lot of heat and discussion. So, with the permission of the House, I announced that I would visit that place, find out the facts on the spot and then on my return make a report to the House. Accordingly. I visited three Camps at Tarn Taran and also went to Patti and spent six hours on this work. I paid a surprise visit as I had said earlier. (interruptions). Order please. Entering any room of the Camp at random, I asked to be shown the wheat supplied to them Out of the wheat they showed me, I kept a small quantity of it as sample and wrote down their names on the cover of the packet The same thing I repeated in Patti also. The people of Patti Camp, are housed in tents. So entering any tent, I picked up a quilt at random. I have placed all these articles in my Chamber for inspection by the Members. On my return here, I sent for a sample of wheat sold by the Chandigarh Co-operative Store. I do not know if it has been received or not. All these articles are before the Members. I do not want to say anything about this matter. If there is anything personal between the Members, it should be decided outside and should not be raised in the House. The time is such when all of us should help in the task of resettling these uprooted persons and if there is any short-coming, it should be removed. I am quite satisfied and so will be the Members (Cheers). After this statement, I will not permit any discussion. The hon. Members may visit my Chamber one by one and inspect those things. They may point out to the defects therein but I will not allow this matter to be raised here.

(Sardar Narain Singh Shahbazpuri rose to speak). Will you please take your seat ? Sardar Narain Singh Shahbazpuri had brought the quilt here. I did not want to refer to this matter, but he has forced me to do so. I do not know where from did he bring it. There is a Tank Chhatri Bunga in Tarn Taran. I am quite familiar with that area. (interruption). On seeing me, Bibi Moninder Kaur came running and asked for the return of her quilt. On enquiry she told me that it was Sardar Narain Singh Shahbazpuri who had taken it away. When I said that she should not have given it to him. She said what could one do if after a request for inspecting such an article. it was taken away. (interruption). (noise) (interruption) (noise). I have brought a sample of wheat from Bibi Mohinder Kaur also. It is in the red packet. The Members can inspect it also. (interruption.) I will not permit discussion of this matter.

ਸਰਦਾਰ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ : On a point personal explanation..

Deputy Speaker : No please.

ਸਰਦਾਰ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ : ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ. . . .

उपाध्यक्षा ; मेरे खड़े होने के बाद भी आप खड़े रहेंगे तो मुझे छोड़ देना पड़ेगा। इस वक्त मैं इस मामले पर किसी बहस की इजाजत नहीं दूंगी। (विघ्न) (I will leave this Chair if the hon. Member remains standing even when I am on my legs. I will not allow any discussion on this matter now) (Interruption.)

ਸਰਦਾਰ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ : ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਉਸ ਵਿਚ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦੇ, ਜੇ ਤੁਸਾਂ ਨਾਂ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਉ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਗਲਾ ਨਾ ਘੁੱਟੋ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ . . . .

उपाध्यक्षा: आप चेयर को डीफाई न करें। मेरी स्टटेटमैण्ट को चैलेंज न करें। अगर कोई कमी रह गई है तो मुझे अलग बता दें।

(The hon. Member should not defy the Chair. He should not challenge my statement. If there is any shortcoming then he can tell me separately.)

EXPUNCTION OF REMARKS FROM THE PROCEEDINGS OF THE HOUSE.

ਸਰਦਾਰ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ : On a personal explanation..

Deputy Speaker : Shri Prabodh Chandra......

ਸਰਦਾਰ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ : (* *

* * * * *

* * * * *

* *) (*Interruptions*)

Deputy Speaker : Order please.

जो कुछ सरदार नारायण सिंह शाहबाज़पुरी ने कहा है वह एक्सपंज कर दिया जाए।

(Order please . . . . Whatever has been said by Sardar Narain Singh Shahbazpuri should be expunged.)

Note : Expunged as ordered by the Chair.

ਸਰਦਾਰ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ : ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰ ਦਿਉ (ਵਿਘਨ) ਅਸਲੀ ਗਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਵੇਗਾ . .

उपाध्यक्षा : आप इतने पुराने मेम्बर हैं, बार बार चेयर को **चैलेंज कर** रहे हैं । यह मुनासिब नहीं है । (The hon. Member is an old Parliamentarian, but he is challeging the Chair time and again. It is not proper.)

ਸਰਦਾਰ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ : ਤੁਸੀਂ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦਿਉ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੈਲੇਂਜ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁਟੋ, ਉਸ ਦੀ ਬਾਤ ਨਾ ਸੁਣੋ (ਵਿਘਨ) ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਲ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੁਣੋ ।————

Deputy Speaker : Sardar Narain Singh, are you not going to obey the Chair ? I give you the last warning.

ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਗੋਆਣੀ : On a point of order, Madam ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠਾਇਆ ਜਾਵੇ। (I would suggest that the hon. Member should occupy thi s Chair.)

ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਗੋਆਣੀ : ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਕ ਦੀ ਗਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਾ ਦਿਉ।

उपाध्यक्षा : इस हाउस में बहुत दिनों से बात बढ़ती जा रही है । मैं नहीं चाहती थी कि मेरी स्टेटमैंट के बाद – – – (विघ्न)

जब हाउस ने यूनैनिमसली इस बात को मन्जूर कर लिया कि मैं वहां पर जाकर असलियत को देखूं तो उस के बाद जो स्टेटमेंट मैंने हाउस में दी है, उस के बाद सरदार

11 A.M.

नारायण सिंह ने प्वायंट आफ आर्डर रेज़ किया और इस सवाल को उठाया । मैंने उन पर कोई रिफलैक्शन नहीं की है ।

(For the last so many days things are taking a new turn in this House. I did not want that after my statement. (*Interruptions*) When the House unanimously decided that I should go there and find out the facts myself I did so and have made a statement to that effect before the House. Thereafter, Sardar Narain Singh rose on a point of order and raised this point. I have not cast any reflection on him.)

NAMING OF A MEMBER

ਸਰਦਾਰ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ : ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਂ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ਕ ਹਾਊਸ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿਉ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਗਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਡੀ ਤੋਂ ਵਡੀ ਸਜ਼ਾ ਝੇਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਗਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਕ ਗਲ ਕਹਿ ਲਉ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਗਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਔਰ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।

Deputy Speaker : I name the hon. Member Sardar Narain Singh Shahbazpuri.

(*Interruptions and Noise in the House*)

उपाध्यक्षा: सरदार नारायण सिंह, मैं आप को नेम करती हूं। आप मेहरबानी करके हाउस से विदड्रा कर जाएं। मुझे इस बात का बड़ा अफसोस और दुःख है कि मैं ने आप को पहिले कई दफा वार्निंग दी है और अब मुझे आप को नेम करना पड़ रहा है। आप हाउस से विदड्रा करें। (Sardar Narain Singh, I name you. You should please withdraw from the House. I regret to say that I have already warned you several times and now I am compelled to name you. Please withdraw from the House.)

At this stage there was great noise in the House and nothing was audible.

ਸਰਦਾਰ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਲੀਗਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗਲ ਕਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। (*interruptions*)

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਸਰਦਾਰ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਊਸ ਵਿਚੋਂ ਵਿਦਡਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ? (Sardar Narain Singh, will you not withdraw from the House ?)

ਸਰਦਾਰ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ : ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਹੀ ਜਾਉ........

Deputy Speaker : Will the hon. Member Sardar Narain Singh Shahbazpuri please withdraw from the House ?

चौधरी देवी लाल : आन ए प्वायंट आफ आर्डर मैडम। मेरा प्वायंट आफ आर्डर यह है कि अगर हाउस में किसी मैम्बर के नाम पर कोई एलीगेशन आए तो उसका यह फंडामैंटल राईट बनता है कि वह परसनल ऐक्सप्लेनेशन दे। मैं इस बात पर आप की रूलिंग चाहता हूं कि क्या किसी मैम्बर को यहां पर परसनल ऐक्सप्लेनेशन देने का राईट है या नहीं ? क्या इस राईट को यहां पर सलब किया जा सकता है ?

(*Interruptions.*)

Deputy Speaker : Order please. इस तरह से बार बार क्यों इन्ट्रप्ट करते हैं ?

(Order please. Why are there such repeated interruptions) ?

Sardar Gurnam Singh : Madam, it is right that you went to Tarn Taran and Patti. You have, Madam, made certain accusations against the hon. Member Sardar Narain Singh Shahbazpuri. Those accusations may be right or wrong and I am not concerned with those. But when accusations come from the Chair against an hon. Member of the House, that hon. Member is perfectly within his rights to give his explanation in regard to those accusations. This right, Madam, I submit with all respect, cannot be curtailed by the Speaker.

उपाध्यक्षा : सरदार गुरनाम सिंह जी की बात को सुनने के बाद मुझे थोड़ा सा ताज्जुब भी हुआ है। आप को पता ही है कि जब मैं ने अभी अभी इस सम्बन्ध में स्टेटमेंट की तो उस में बीबी महेन्द्र कौर का मैंने किसी तरह से भी जिक्र नहीं किया। जब मैं बैठ गई तो उस के बाद सरदार नारायण सिंह ने प्वायंट आफ़ आर्डर करके इस बात को ताज़ा करने की कोशिश की। मेरी तरफ से अब भी उन पर किसी किस्म की कोई ऐक्युज़ेशन नहीं है। उन के इस सवाल को उठाने के बाद जो कुछ मेरे नोटिस में आया था उस का मैंने जिक्र कर दिया है। अब उन की तरफ से परसनल ऐक्स्प्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है।

इतने दिनों से मांग की जा रही थी कि ऐजूकेशन मनिस्टर साहिब बयान दें। आज वह यहां पर आ गए हैं और मैं हाउस से दरखास्त करूंगी कि अब आराम से उन को सुना जाए।

(I am somewhat surprised after hearing Sardar Gurnam Singh. The hon. Members are aware that in the statement which I gave a short-while ago in this connection I did not make mention of Bibi Mohinder Kaur in any way. When I resumed my Chair Sardar Narain Singh rising on a point of order tried to reopen the matter. However on my side even now I have no allegation of any kind to make against him. After he had raised this point, I stated the whole thing that came to my notice. Now there is no need of a personal explanation by him.

There has been a persistent demand in the House for the last so many days that the Education Minister should give a statement. He is here to-day and I would request the House that he may be heard patiently.)

(इस समय बहुत से मैम्बर प्वायंट आफ आर्डर पर खड़े हुए)

Deputy Speaker : Dr. Baldev Parkash.

ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ : ਬੀਬੀ ਜੀ, ਇਹ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦਾ ਖਾ ਗਏ ਹਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਉਤੇ ਜੂੰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਰੀਂਗੀ। ਇਸ ਗਲ ਉਤੇ ਝਟ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁਛਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਥੇ ਸੀ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ ਉਠ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਉ ? I have already called upon the hon. member Dr. Baldev Parkash (Since when the hon. member Sardar Harchand Singh has been permitted this right to stand up at his own free will and start making a speech? (I have already called upon the hon. Member Dr. Baldev Parkash.)

डाक्टर बलदेव प्रकाश : डिप्टी स्पीकर साहिबा, अब जो मामला हाउस के सामने आया है, यह बात बगैर वजह से बढ़ गई है। आप वहां पर गई। बड़ी अच्छी बात है कि आप ने वहां पर जाकर इन्क्वायरी की या और बातों की बाबत पूछताछ की। लेकिन आप ने अभी अभी यह रिमार्क्स भी किए हैं, एक आनरेबल मैम्बर की बाबत रिमार्क्स किए हैं कि कोई लेडी महेन्द्र कौर के नाम की उन से मिली, उस से उन्होंने वह रजाई ली और आप ने सुना कि अभी तक उसे वह रज़ाई वापिस नहीं की गई। जब आप ने यह बात कही तो वह मैम्बर उठ कर अपनी पोज़ीशन साफ करना चाहता है कि आया वह लेडी उन को मिली या नहीं मिली। हो सकता है कि आप को जिस महिला ने कुछ कहा हो वह टियूटर्ड हो सकता है। उसकी बाबत मैम्बर जो कि इस से कन्सर्न्ड है उसे आप इजाज़त दे देते और यह मामला एक दो मिनट में खत्म हो सकता था। मैं समझता हूं कि अगर किसी मैम्बर की बाबत कोई बात हाउस में आए तो उस मैम्बर को इस बात का राईट होना चाहिए कि वह अपनी बात कह सके। आप की बात से हाउस में कुछ ऐक्साईटमेंट पैदा हो गई। इस लिये और ज़्यादा ऐक्साईटमैंट पैदा करना मुनासिब नहीं होगा।

उपाध्यक्षा : मैं हाउस में कोई गैर ज़िम्मेदारी की बात नहीं होने देना चाहती। मैंने रिकार्ड से पता किया है। उन्होंने टांक छत्री बूंगा के लफज़ इस्तेमाल किए थे : (विघ्न) आप को पता है कि कल ही पर्सनल ऐक्स्प्लेनेशन पर खड़े हुए और क्या कुछ कह गए। अगर वह इस बात का यकीन दिलाए कि इसी सम्बन्ध में पर्सनल ऐक्स्प्लेनेशन देंगे तो मैं उन को इजाज़त दे सकती हूं। अगर कुछ और कहना हो तो मैं उस के लिये इजाज़त नहीं दे सकती। अगर सिर्फ बीबी महेन्द्र कौर की बाबत क्लेरीफिकेशन करना हो तो उन्हें इजाज़त है।

(*Loud noise in the House*)

Order. Order. I want decorum in the House.

(I do not want that some thing irresponsible should happen in the House. I have verified from the record. The hon. Member used the words' Tank Chhattari Bunga (interruption). You are aware that the hon. Member rose on a point of order Yesterday and said so much. I

can allow him if he assures that he would confine his personal explanation to this matter. If he wants to say something else then I cannot allow. However if he wants to make clarification about **Bibi Mohinder Kaur)** he may do so.)

(*Loud noise in the House*)

Order, Order, I want decorum in the House.

चौधरी नेत राम : ग्रान ए प्वायंट ग्राफ ग्रार्डर। डिप्टी स्पीकर साहिबा आप ने ग्रानरेबल मैम्बर को हाउस से बाहर निकल जाने को कहा था। जब तक उस बात का फैसला न हो जाए क्या तब तक उन को यहां पर बोलने का हक है ? मैं इस बात पर ग्राप की रूलिंग चाहता हूं।

Deputy Speaker : I would request the hon. Member Sardar Narain Singh Shahbazpuri to first withdraw from the House and then I will permit him to give his personal explanation.

(*At this stage, Sardar Narain Singh Shahbazpuri left his seat and returned after a shortwhile. He did not actually withdraw from the House*).

(*Sardar Narain Singh Shabazpuri rose to Speak*)

Deputy Speaker : No please. The hon. Member should not flout the Chair. He should first withdraw from the House.

(*At this stage, Sardar Narain Singh Shahbazpuri withdrew from the House*)

PERSONAL EXPLANATION BY THE EDUCATION MINISTER

शिक्षा मंत्री (श्री प्रबोध चन्द्र) : डिप्टी स्पीकर साहिबा. चन्द दिन हुए एक ग्रानरेबल मैम्बर ने काल ग्रटैंशन मोशन के जरिए हाउस की तवज्जो इस बात की तरफ दिलाने की कोशिश की कि कुछ रुपया जो यहां पर इकट्ठा किया गया उस में से कुछ हिस्सा मैंने सैंटर के किसी वजीर को दिया। ग्रगर बात इतने तक ही रहती तो ग्रफसोस नहीं था। हर एक मैम्बर को इस बात का हक है कि किसी भी मामले की तरफ तवज्जो दिला सकते हैं। मगर मेरे फाज़िल दोस्त सरदार गुरनाम सिंह जी ने ग्रागे कहा कि उस में शायद ग्रपनी कोई गर्ज़ थी या पुलिटिकल फायदा उठाने के लिये ऐसा किया गया। मैं इस बात को वाज़या करना चाहता हूं....... (*Interruptions*).

Sardar Ajaib Singh Sandhu : On a point of order, Madam.

Deputy Speaker : I won't allow the hon. Member Sardar Ajaib Singh Sandhu to rise on a point of Order.

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ?

शिक्षा मन्त्री ; मिस्टर ग्रजीत कुमार, मेरी स्टेटमेंट के बाद प्वांयट ग्राफ ग्रार्डर रेज़ कर लेना।

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਇਹ ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਗਲ ਹੈ।

शिक्षा मंत्री : मैं ग्राप की इजाज़त से ग्रपनी पोज़ीशन वाज़े करनी चाहता हूं कि पहली बात तो यह है कि यह रुपया जो दिया गया है यह एज्यूकेशन मिनिस्टर की तरफ से नहीं दिया गया ग्रौर न ही इस में से एक पाई भी मुझे खर्च करने का हक हासल था क्योंकि हरेक चैक पर चीफ मिनिस्टर साहब ने दस्तखत करने होते हैं ग्रौर उन के नाम ही पर यह सारा रुपया जमा हुग्रा है। जब सीज़ फायर हुग्रा था तो उस से चन्द दिन

[शिक्षा मंत्री]

पहले यह सोचा गया था कि जो हमारे तालब इल्म हैं और जो टीचरज़ हैं वह भी अपना कुछ हिस्सा डिफैंस फंड में डालें। तो चीफ मिनिस्टर साहब की इजाज़त से यह रुपया इकट्ठा किया गया था और इस के लिये यह फैसला किया गया था कि हरेक टीचर आठ 2 आने कर के अपने 20 दोस्तों से रकम इकट्ठी करे और जो कालेज के टीचर हों वह भी अपने 20, 20 दोस्तों से एक एक रुपया ले कर इकट्ठा कर के दें और इसी तरह से जो प्रायमरी स्कूलों के टीचर हों वह भी अपने बीस बीस दोस्तों से चार चार आने इकट्ठा करें। हो सकता है कि किसी ने जोश में आ कर रकम ज्यादा कर दी हो। लेकिन मैं हाउस को यह यकीन दिलाना चाहता हूं कि यह जो रुपया इकट्ठा हुआ तो जिन टीचरज़ ने या महकमे के अफसरान ने या तालब इल्मों ने यह इकट्ठा किया था उन की यह खाहिश थी कि जिन जवानों ने हमारी सरहदों पर अपनी जानें दी हैं उन के लड़के और लड़कियों को, जो उन के डिपैंडेंट्स हैं उन की मदद के लिये दिया जाए। उन की यह भी खाहिश थी कि जो जवान हमारी सरहदों पर मारे गए हैं लेकिन वह पंजाब के रहने वाले नहीं थे और देश के दूसरे सूबों के रहने वाले थे उन के साथ गुड विल दिखाने के लिये इस फंड का 5 या 10 परसेंट हिस्सा उन बच्चों की, जो स्कूलों या कालेजों में पढ़ते हैं, उन की सहायता करने के लिये दिया जाए। फिर ख्याल यह था कि यह रुपया कुल पांच दस लाख तक ही इकट्ठा हो सकेगा लेकिन यह 45 लाख जमा हो गया। यह मैं ने वाज़ेतौर पर कह दिया है कि यह इस रुपए के इकटठा करने वाले टीचरज़ और तालिबइल्मों की खाहिश थी कि जो जवान हमारे फरंटीयरज़ पर मरे हैं लेकिन वह रहने वाले दूसरे सूबों के थे उन को दिया जाए। इस लिए यह 25 हज़ार रुपये की रकम टोकन के तौर पर दी गई थी और इस में कोई किसी किस्म का पोलिटीकल फायदा उठाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे साथी चोधरी रिज़क राम जी इस बात के शाहद हैं क्योंकि मैं ने उन के सामने चीफ मिनिस्टर साहब से रिकुएस्ट की थी कि इस फण्ड में से कुछ रुपया हरेक मिनिस्टर के पास होना चाहिए ताकि जहां कहीं भी वह देखें कि किसी केस में फौरी तौर पर इमदाद देने की ज़रूरत है तो वह दे सकें यानी किसी ने यूनिवर्सिटी का दाखला देना है और उस के पास उस के लिये पैसे नहीं हैं और उस के दाखले की तारीख निकल जाने का इमकान हैं तो ऐसे केस में उस की मदद फौरी तौर पर की जा सके। या किसी ने कालेज की फीस देनी हो और वह इस मदद के बगैर न दे सकता हो और अगर वह वक्त पर नहीं देता तो उस का कालेज से नाम कटता हो तो उस को यह रकम दी जा सके। इस लिये कुछ रकम हरेक मिनिस्टर के पास होनी चाहिए। इसी तरह से हम चाहते थे कि आपोज़ीशन के जितने ग्रुप लीडर्ज़ हैं उन के पास भी कुछ न कुछ इस तरह के फण्ड होने चाहिएं ताकि उन लोगों की वक्त पर मदद की जा सके और इस का हिसाब किताब बाद में कर लिया जाए। लेकिन यह बात कहना कि मैं ने किसी पोलिटीकल मकसद को पूरा करने के लिए यह 25 हज़ार रुपया दिया है, यह गलत है। वैसे यह बात अपने मुंह से कहनी अच्छी नहीं लगती कि जब चीन के साथ हमारी लड़ाई हुई थी तो उस वक्त जो रुपया डिफंस फण्ड के लिये इकट्ठा किया गया था तो उस में जो मेरी अपनी या मेरे रिश्तेदारों की कनट्रीब्यूशन थी वह ही 40 या 50 हज़ार रुपए के लगभग हो गई थी। मेरी अपनी जो कनट्रीब्यूशन थी वह 16 तोले सोना, 25 सोने के पौण्ड थे और ढाई हज़ार रुपये

नकद थे और इस के अलावा मैं ने 22 या 23 हज़ार तो अपने रिश्तेदारों से ले कर दिया था। इसी तरह इस बार भी मेरी और मेरे दोस्तों और रिश्तेदारों की 22 या 23 हज़ार रुपए की नेशनल डिफेंस में कनट्रीब्यूशन है। इस के अलावा मेरे कई दोस्तों ने सिर्फ मेरे कहने पर इस फण्ड में कनट्रीब्यूट किया है अगर मैं ने यह रुपया दे कर कोई ज़ाती मकसद हल करना होता तो मैं क्या वही रुपया जो मैं ने या मेरे रिश्तेदारों ने या मेरे दोस्तों ने जो मेरे कहने पर दिया है वही इकट्ठा कर के जो 40 या 50 हज़ार के करीब हो जाता है नहीं दे सकता था? यह रुपया जो दिया गया है यह तो रुपया इकट्ठा करने वालों की खाहिश को पूरा करने के लिये दिया गया है। यह खाहिश उन्होंने एक जगह पर ही ज़ाहर नहीं की थी बल्कि 20 जगहों पर यह खाहिश ज़ाहर की गई थी कि जो जवान हमारे फरंटीयरज़ पर मारे गए है और वह रहने वाले दूसरे सूबों के हैं उन के बच्चों की सहायता के लिये भी इस रकम में से कुछ हिस्सा दिया जाए। इस रुपये के इकट्ठा करते वक्त यह जो फैंसला किया गया था इस फैंसले को मद्देनज़र रखते हुए पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से यह रकम दी गई है और जो चैक दिया गया है उस पर चीफ मिनिस्टर साहब के दस्तखत थे और उस पर मेरे दस्तखत नहीं हैं। इस फंड में से मैं तो पांच रुपये भी नहीं निकलवा सकता। यह रुपया तो टीचरज़ और तालिबइल्मों की खाहिश के मुताबिक दिया गया है। इस लिये इन की तरफ से यह जो कहा गया है कि यह परसनल पोलिटीकल एग्रेंडाईज़मेंट के लिये किया गया है, गलत है। वैसे आपोज़ीशन के भाई जो मर्जी आए कह सकते हैं?

(इस वक्त सरदार गुरनाम सिंह कुछ कहने के लिए खड़े हुए।)

उपाध्यक्षा : अब मिनिस्टर की स्टेटमेंट के बाद कुछ कहना ठीक नहीं। (It is not proper to say something in this connection after the Minister has made a statement.)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹਨ ਯਾਨੀ $2\frac{1}{2}$ ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਦਿ। ਖੈਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਸ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਮੇਰੀ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ without the decision of the Cabinet ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰੁਪਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। We will discuss this matter.

उपाध्यक्षा : आप इस बारे में लिख कर भेज दें। (The hon, Member may give me this thing in writing.)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਕਲੈਰੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ . . .

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਮਨਿਸਟਰ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ no clarification

is allowed. ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਲਗੇ ਹਨ, ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਾਂਗੇ। (No clarification is allowed after the Minister has made his statement. The hon. Member Sardar Gurnam Singh is going to give it in writing. We shall go by the decision that is taken in this regard.)

चौधरी देवी लाल : आन ए प्वांयट आफ आर्डर, मैडम।

Deputy Speaker : No point of order, please.

चौधरी देवी लाल : आखिर आनरेबल मेम्बर्ज़ को प्वांयट आफ आर्डर रेज़ करने का अधिकार तो है।

Deputy Speaker : What is your point of order ?

चौधरी देवी लाल : मेरा प्वांयट आफ आर्डर यह है कि जब कोई मिनिस्टर यहां स्टेटमेंट दे तो उस में से अगर कोई मैम्बर किसी प्वांयट को कलैरीफाई कराना चाहे तो क्या वह **करा सकता है** या नहीं करा सकता ?

Deputy Speaker : After a Minister has made his statement no need for clarification is left.

ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ : ਮੈਂ ਇਕ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ . . . .

Deputy Speaker : No please.

ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਐਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਸੀ ....

उपाध्यक्षा : मिस्टर भौरा, मैं अभी चौधरी देवी लाल के प्वायंट आफ आर्डर का जवाब दे रही हूं और आप खड़े हो गए हैं। मुझे अफसोस है कि कई बातें बार बार कहनी पड़ती हैं। यहां पर तीन दिनों से यह कहा जा रहा है था कि श्री प्रबोध चन्द्र नहीं आए और आज वह आए हैं और अपनी स्टेटमैंट उन्होंने दी है। अब अगर उस पर किसी ने कुछ कहना है तो जो उस के लिए प्रापर प्रोसीजर है उस के मुताबिक आप को करना चाहिए। (I am still giving my ruling on the point of order raised by Chaudhri Devi Lal and Mr. Bhaura has risen in his seat. I am really pained to point out these things again and again. For the last three days it was being complained that Shri Prabodh Chandra is not attending the Session. Today he has come and made his statement. Now if any one wants to raise some objection to that, there is a separate procedure for that). (*Interruptions*).

———

PERSONAL EXPLANATION BY SARDAR NARAIN SINGH SHAHBAZPURI

ਸਰਦਾਰ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਮੈਂ ਤਦ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਆਂਗੀ ਅਗਰ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਐਸ਼ਿਓਰੈਂਸ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਇਤਨੀ ਹੀ ਗਲ ਕਹਿਣਗੇ ਜਿਤਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਥੇ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਅਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ । (I will allow it only. If the hon. Member assures that he would confine himself to what has been said about him here and that he would not say more than that.)

ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਮੈਡਮ । ਮੇਰੀ ਐਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ. . .

Deputy Speaker : No please.

ਕਾਮਰੇਡ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੂਲਜ਼ ਨੂੰ ਇਗਨੌਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਾ ਦਿਉ . . .

Deputy Speaker : Order please. There must be some limit.

ਸਰਦਾਰ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ, ਮੈਡਮ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਜਿਤਨੇ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰ ਟੇਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਤਨੇ ਤਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। (I will not allow the hon. Member Sardar Narain Singh Shahbazpuri to offer his personal explanation unless he gives the required undertaking.)

ਸਰਦਾਰ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾਂ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਪਾਤਰ ਵੀ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਗਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਹੋ । ਇਸ ਦੇ ਅਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹੋ । (The hon. Member should explain his position only in regard to the reference that has been made here about Shrimati. Mohinder Kaur and refrain from saying anything else.)

ਸਰਦਾਰ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ : ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਟੈਂਕ ਛਤਰੀ ਬੂੰਗੇ ਵਿਚ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਹਾਂ । ...... ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ........

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਬਸ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ।

(That will do ; the hon. Member has given his personal explanation.)

ਸਰਦਾਰ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪਰੀ : ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇਣ ਦਿਉ ਆਖਿਰ ਕੁਝ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਬੁੰਗੇਦੇ ਕਣਕ ਦੀ ਗਲ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ (ਵਿਘਨ) ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਉ ਠੀਕ ਕਰ ਲਉ। ਖੈਰ ਮੈਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। (ਵਿਘਨ) ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। (ਵਿਘਨ)

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਜਦ ਤਕ ਇਹ ਹਾਊਸ ਰਹੇਗਾ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਰਹਾਂਗੀ। (ਵਿਘਨ) ਮੇਰੀ ਗਲ ਨਾ ਕਰੋ। (ਵਿਘਨ) ਜਿਤਨੀ ਗਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ, ਉਨੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ।

No speech please. (I will remain a Member of th isHouse till it is there. (interruption) Leave me alone. (interruption.) The hon. Member has stated what he wanted to. No speech please).

ਸਰਦਾਰ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ : ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ (ਵਿਘਨ) ਮਗਰ ਚੂੰਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਗਲ ਕਹੀ ਹੈ। (ਵਿਘਨ) ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦਲੇਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਗਲ ਸਹੀ ਹੋਵੇ। (ਵਿਘਨ) ਆਪ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਆਪ ਹੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੀਬੀ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਬਣਦੇ . . (ਵਿਘਨ) ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਖੂਨ ਦੇ ਆਂਸੂਆਂ ਦੀ ਗਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ . . .

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਰ ਲਈ। (ਵਿਘਨ)

(The hon. Member has made his statement about the matter he wanted to make.)

ਸਰਦਾਰ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ : ਜੋ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੀ ਗਲ ਹੈ . . .

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਪ੍ਰਾਮਿਜ਼ ਬਰੇਕ ਕਰੇ . .

Please take your seat.

(Please take your seat. I am sorry that an old gentleman of your stature should break his word).

ਸਰਦਾਰ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ : ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਹੀ ਹਾਂ. . . . . . (ਹਾਸਾ) ਭਾਵੇਂ ਕਿਡਾ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਾਂ . . . (ਹਾਸਾ) ਬਸ ਇਕੋ ਗਲ ਕਹਿ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। (ਵਿਘਨ)

Deputy Speaker : If you insist I will name you again. (interruption).

ਸਰਦਾਰ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ : ਅਸੀਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ . .

(ਵਿਘਨ)

Deputy Speaker : There should be some limit. (interruption).

शिक्षा मन्त्री : डिप्टी स्पीकर साहिबा, पहले सरदार गुरनाम सिंह जी ने कहा कि मैं ने ढाई लाख रुपये का जिक्र किया मगर मैं यह बात साफ करना चाहता हूं कि मैं ने ढाई लाख रुपया नहीं कहा था बल्कि 25 हज़ार रुपया कहा था, ढाई लाख नहीं कहा था ।

सरदार गुरनाम सिंह : इस बारे में कोई झगड़ा नहीं है ।

शिक्षा मन्त्री : दूसरी बात उन्होंने कैबनिट की सैंकशन की कही है । मैं अर्ज करता हूं कि मैं ने किसी वक्त नहीं कहा कि कैबनिट ने सैंक्शन दी । मैं ने कहा था कि जब चीफ मिनिस्टर साहिब को कहा कि जिन लोगों ने यह **कुलैक्शन** की है उन की यह खाहिश है तो उन की इजाज़त से उन के ही चैक पर सा न कराके यह किया गया इस में कैबनिट की सैंकशन की बात नहीं है ।

ADJOURNMENT MOTION

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਬਾ, ਮੈਂ ਇਕ ਐਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਦਿਤੀ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਇਮਪੋਰਟੈਂਸ ਅਤੇ ਰੀਸੈਂਟ ਅਕਰੈਂਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਸ਼ੋਰ)

Deputy Speaker : Please take you seat.

(*Interruptions*)

चौधरी देवी लाल : एक मेरी एडजर्नमैंट मोशन आप ने डिसएलाऊ की है सिर्फ इस मामले पर कि यह एक ऐडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है । कुरुक्षेत्र में....... (विघ्न) एक विशाल हरियाणा कान्फ्रेंस रखी गई थी । पहले लाउड स्पीकर की इजाज़त दी गई थी (विघ्न) मगर कल कैंसल कर दी गई (विघ्न) इस बिना पर कि रिलीजस मेले में पोलीटीकल कान्फ्रेंस की इजाज़त नहीं है.......

उपाध्यक्षा : मैं ने यह पैंडिंग रख ली है आप मेरे से चैम्बर में बात कर लें ।

(I have kept it pending, he may see me in my Chamber).

श्री जगन्नाथ: On a point of order, Madam. पहले इन्होंने इजाज़त दी वहां पर जलसे को फिर कैंसल की । (विघ्न) इसलिए कि यह पोलीटीकल कान्फ्रैंस, रिलीजस फेअर में नहीं हो सकती (विघ्न) मगर यह होती रही है मुक्तसर में हुई । (विघ्न) इस का फैसला कब होगा आज तो हाउस को एडजर्न करने जा रहे हैं । (विघ्न)

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਮੇਰੀ ਗਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਖੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੈਂਬਰ ਵਿਚ ਮਿਲ ਲਉ । (I have already said that his adjournment motion is kept pending. He may see me in my Chamber).

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ (ਵਿਘਨ) ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਹੇਠ ਚਲਦੀ ਹੈ। (ਵਿਘਨ) ਸੈਕਰੇਟੇਰੀਏਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ P. C. S. ਜਾਂ I.A.S. ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। (ਵਿਘਨ) ਕਿਸੇ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਨੂੰ S.P. ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਮੋਟ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। (ਵਿਘਨ) ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ।

Deputy Speaker : Please take your seat.

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਸਾਡੀ ਗਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ......

Deputy Speaker : Now I reject your motion because you flout the Chair. (interruption). Now there are the Call Attention Notices. There being insufficient time at our disposal, these motions, if the House approve, may be taken up tomorrow.

(Vioces : No, No.)

Deputy Speaker : All right, we take up the Call Attention Notices, now.

Sardar Ajaib Singh Sandhu : On a point of order, Madam.

Deputy Speaker : I do not allow. Please take your seat.

श्री जगन्नाथ : On a point of order, Madam. (विघ्न) हरिजन ऐम्पलाइज़ के बारे में जो मोशन आई है

Deputy Speaker : Please take your seat.

श्री जगन्नाथ : हरिजनों के हकों पर छापा मारा जा रहा है (विघ्न) उस पर रूलिंग ठीक होनी चाहिए। (विघ्न)

Deputy Speaker : There must be some limit (noise) क्या यहां ग्रुप लीडर्ज़ नहीं हैं। (शोर)

(There must be some limit (noise). Are there no group leaders here.) (noise.)

EXPUNCTION OF REMARKS FROM THE PROCEEDINGS OF THE HOUSE.

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਤਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਪਾਸ ਗਿਰਵੀ ਨਹੀਂ ਰਖੀ ...... (ਵਿਘਨ) ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ .... (ਵਿਘਨ) ਅਸੀਂ ਰਿਪਰੇਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ .... (ਵਿਘਨ) [****]

Deputy Speaker : This is the last warning. You are always reflecting on the Chair. You must withdraw these words. (*Interruption*). These words may be expunged.

Sardar Ajaib Singh Sandhu : On a point of order.

Deputy Speaker : Order please, I name Shri Ajit Kumar. (noise and interruptions.)

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ। ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲਕੇ ਸਾਰੇ ਹਰੀਜਨ ਪੀ. ਸੀ. ਐਸ. ਅਤੇ ਆਈ. ਏ. ਐਸ. ਅਫਸਰਾਂ

Note.—Expunged as ordered by the Chair

ਨੂੰ ਸੈਕਰੇਟੇਰੀਅਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢ ਕੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਗਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੇਅਰ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ . . . (ਵਿਘਨ)

Deputy Speaker : You should withdraw from the House.

ਤੁਸੀਂ ਚੇਅਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੋਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। (You should withdraw from the House. Are you not going to obey the Chair.)

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : No madam ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਮੰਨਾਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗਲ ਸੁਣ ਲਉ। (ਵਿਘਨ)

Deputy Speaker : Please withdraw from the House first. (Interruption)

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਮੈਂ ਵਿਦਡਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਉ। ਇਥੇ ਸਾਰੇ ਸੈਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ।

Deputy Speaker : Are you not going to withdraw from the House?

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਉ . . .

Deputy Speaker : No please, Please first withdraw from the House and then I will listen to you,

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ। ਇਥੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲ ਵੀ ਸੁਣਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ . . . (ਵਿਘਨ) (ਸ਼ੋਰ)

Deputy Speaker : Sardar Gurnam Singh Ji, you are his leader. I would request you to ask him to withdraw from the House.

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚੇਅਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। (He must withdraw from the House first. Does'nt he want to obey the Chair ?)

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਪਰ. . .

Deputy Speaker : Then you must withdraw first.

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਮੈਂ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. .. (ਵਿਘਨ)

(At this stage Babu Ajit Kumar withdrew from the House. Then some of the Harijan Members stood up to raise points of orders.)

(interruptions. noise)

Sardar Ajaib Singh Sandhu : On a point of Order Madam. (*interruption*).

Shri Amar Singh : On a point of Order Madam.

Deputy Speaker : Please take your seats. (*interruptions*). There must be some limit to points of orders.

Sardar Ajaib Singh Sandhu : On a point of Order, Madam.

ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਅਜੀਤ ਕਮਾਰ ਦੀ **ਐਡਜਰਨਮੈਂਟ** ਮੋਸ਼ਨ ਤੇ . . . . .

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਰੀਮਾਰਕ ਨਾ ਕਰੋ (The hon. Member need not say any thing about others)

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ । ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੀਮਾਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੁਣੋ । (ਵਿਘਨ) ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ . . . .

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਉਸ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ।(The hon. Member has again started referring to the motion)

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਉ ਫਿਰ ਰੂਲਿੰਗ ਦਿਉ ਐਵੇਂ ਨਾ ਦਬਾਈ ਜਾਉ । ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿਠੀ ਆਈ ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੀਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਇਕ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ **ਅਕਸੈਪਟ** ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੀਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਿਥੇ ਲੇ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ।

Deputy Speaker : Is it your point of order ?

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਮੈਂ ਤਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਲਿੰਗ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹਾਂ । (ਵਿਘਨ) (ਸ਼ੋਰ)

Deputy Speaker : Order please. There must be some limit.

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : [* * * * * * *](ਵਿਘਨ) (ਸ਼ੋਰ)

Deputy Speaker : Order please.

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਸੁਣ ਲਉ . . . .

Deputy Speaker ; Order please.

(*Interruptions*) (*noise.*)

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਜੋ ਕੁਝ ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਜ਼ ਵਿਚੋਂ ਐਕਸਪੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ । (Whatever has been said by Sardar Ajaib Singh Sandhu may be expunged from the proceedings of the House).

Note.—Expunged as ordered by the chair

Shri Amar Singh : On a point of order .. .. ..(*Interruption*)

डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप तो हरिजनों की हतैषी रहीं हैं और उदार दिल भी है लेकिन आज हरिजनों के बारे में जब भी बात आती है तो उस के साथ ऐसा ही सलूक किया जाता है। देहात में भी हरिजन ही पिट जाता है और यहां इस हाऊस में भी उस के साथ इसी तरह का सलूक किया जा रहा है। इस हाउस के एक मैम्बर ने एडजर्नमैंट मोशन के द्वारा हरिजनों की फीलिंग्ज़ को सरकार के सामने रखने की कोशिश की तो आपने उसे बाहर निकाल दिया। और एक काल अटैन्शन मोशन दी थी तो जवाब मिला कि सी. एम साहिब कुरुक्षेत्र से वापिस आएंगे तो जवाब दिया जाएगा। यह बहुत सीरीअस मामला है और आज पंजाब की कुल आबादी का 1/5 हिस्सा हरिजनों का है। इस को ऊपर उठाने के लिये ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देना चाहिए (विघ्न)

उपाध्यक्षा : प्वायंट आफ आर्डर का मतलब यह नहीं कि अगली पिछली बातें सब यहां पर कह दी जाए। मैं ने यह कहा है कि एडजर्नमेंट मोशन के बारे में फिर गौर किया जा सकता है और मैं ने यह भी कहा है कि इसको मैं पैंडिंग रख रही हूं। आप को पता नहीं कैसे यह ख्याल आ गया कि मैं हरिजनों की हितैषी नहीं। आप को पता है कि चेयर की रूलिंग बार बार नहीं बदली जा सकती। मैं ने श्री अजीत कुमार को कहा कि इस पर फिर विचार कर लिया जाएगा और इसको मैं पेंडिंग रख रही हूं तो इस पर वह फिर इनसिस्ट करने लगे, यह उन के लिए गैर मुनासिब बात थी।

(All the matters cannot be discussed or brought in while raising a point of order. I have said that we can reconsider the decision on the adjournment motion and I told the hon. Member that I am keeping this motion pending. I do not know how you have got the idea that I am not the well wisher of Harijans. The hon. Member knows that the ruling of the Chair cannot be altered every now and then. I told Shri Ajit Kumar that I will reconsider it and that I have kept it pending still he insisted. This was very unfair on his part.)

ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸਰਲਾ ਦੇਵੀ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਦੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਇਥੇ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਬਿਲ ਤੇ ਅਜ ਦੀ ਬਹਿਸ ਸੁਣਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੀ ਡਿਗਨਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਹਾਊਸ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਗਨਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੇਅਰ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਗਨਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਲੋਂ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕਾਇਮ ਰਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਗਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਚੇਅਰ ਦੀ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਡਿਗਨਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

(ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ।)

ਸਰਦਾਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸਰਲਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਸ ਹਾਊਸ ਤੇ, ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਅਤੇ ਚੇਅਰ ਤੇ ਐਸਪਰਸ਼ਨ ਕਾਸਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਜ਼ ਵਿਚੋਂ ਡੀਲੀਟ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ (ਵਿਘਨ) (ਸ਼ੋਰ)।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸਪਰਸ਼ਨ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਚੇਅਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਕਵੇਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵੇਸਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (I would like to inform the hon. Members that no aspersion has been cast on the hon. Members or the Chair by her. She has requested the Chair that the Bill is very important and the discussion there on may be started. I would also request the hon. Members to let the House proceed with the next item on the Agenda.)

डाक्टर बलदेव प्रकाश : मेरा आप से यह निवेदन है कि पीछे भी दो चार दफा ऐसा हुआ है कि हाऊस को 15 मिनट के लिये एडजर्न किया गया और अगर आज भी मैम्बर साहिबान का मूड ऐसा है तो इस हाऊस को इन का मूड पता करके 15 मिनट के लिए एडजर्न कर दिया जाए। अगर उन्होंने काम न करना हो तो यही एक सही रास्ता है इस तरह हाऊस का मजाक नहीं बनाना चाहिए। यह अनडिगेनेफाइड सा हो गया है कि इस तरह कारवाई को चलाया जाए। अगर मैम्बर साहिबान इस को एडजर्न करना चाहते हैं तो एडजर्न कर दिया जाए और फिर दोबारा मीट करने पर कारवाई को डिगनीफाइड ढंग से चलाया जा सके। This is an aspersion on the Chair which cannot be tolerated.

उपाध्यक्षा : मुझे हाऊस को एक्सटेंड करने में या किसी मैम्बर को वारनिंग देने में कोई तकलीफ नहीं होती अगर मैं महसूस करूं कि इस हाऊस की कारवाई को चलने नहीं दिया जाता। मैं तो आप सब से दरखास्त करूंगी कि अब हमें अगली आइटम पर आना चाहिए। (I can extend the Honse and can also administer a warning to an hon. Member if I feel that the normal conduct of the business in the House is being interrupted. I would request you all the hon. Members of the House to proceed with the next item on the Agenda.)

(Interruptions. Noise.)

ਸਰਦਾਰ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ : On a point of order, Madam. ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡੀਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ

ਸਰਹਦ ਦੇ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਝੂਠ ਅਤੇ ਸਚ ਨੂੰ ਨਿਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਕਨਸਟੀ-ਚਿਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੋਗੇ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। (The hon. Member may send his difficulties to me in writing for further consideration)

श्री जगन्नाथ : मैं, डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह बात कहने पर मजबूर हो गया हूं कि जब भी कोई हरिजनों को भलाई की बात इस हाऊस में आती है तो उसको हमेशा टालमटोल कर दिया जाता है। मैं समझता हूं कि इस तरह से इस हाऊस की कार्रवाई ठीक तरीका से नहीं चल सकेगी जब तक आप हरिजनों को संतुष्ट नहीं करते ....

उपाध्यक्षा : अगर आप की तरह सभी मैम्बर बोलने लग जायें और किसी की सुनें ही न तो हाऊस की कार्रवाई कैसे चल सकती है? (If all the Members were to start speaking like the hon. Member without listening to any one else, then how can the House proceed with its work ?)

श्री बनवारी लाल : मुझे डिप्टी स्पीकर साहिबा बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जब भी हरिजनों के मुताल्लिक कोई मसला आता है तो आप की तरफ से और हाऊस के तरफ से प्वायंट्स आफ आरडर्ज़ में ही सारा वक्त निकाल दिया जाता है: कोई सुनता तक नहीं। रूलिंग पर रूलिंग मांगने शुरू हो जाते हैं। आप ने भी तो आयंदा को हरिजनों से वोटें मांग कर आना है। अगर ऐसा ही हमारे साथ सलूक होता रहा तो हम इस हाऊस की कार्रवाई को चलने नहीं देंगे।

उपाध्यक्षा : श्री बनवारी लाल जी, आप को क्रोध में आकर जो मूंह में आये वह नहीं कहना चाहिये। (The hon. Member should not in a fit of anger say out every thing that comes to his mind.)

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਸ਼ੈਡੂਲਡ ਕਾਸਟਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝੂਠੇ ਵਾਇਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਢੋਲ ਦਾ ਪੋਲ ਖੁਲ੍ਹ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਈ. ਏ. ਐਸ. ਅਫਸਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਫਸਰ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੈਨਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਐਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੀਪੀਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ?

(The ruling has already been given thereon. What is the use of this repetition ?)

चौधरी दर्शन सिंह : डिप्टी स्पीकर साहिबा, ऐसा मालूम होता है कि मैंबर साहिबान सूर्य ग्रहण के मूड में हैं। आप इन को आधे घंटे की छुट्टी कर दें। अब यह सिटिंग एडजर्न हो जाये और आध घंटे के बाद हम फिर मिल लें (हंसी)

उपाध्यक्षा : ग्रहण तो अब हट गया है, आप भी खामोश हो जायें।
(The Solar eclipse is over by now. The hon. Member too, should now keep silent.)

ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਰਿਆਸਤੀ : * * *

* * * * *

* * * * * *

उपाध्यक्षा : जो कुछ सरदार तरलोचन सिंह ने कहा है वह प्रोसीडिंग्ज़ में से ऐक्सपंज कर दिया जाए। (Whatever has been said by Sardar Tarilochan Singh now may be expunged from the proceedings.)

ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਰਾਮਜੀ ਦਾਸ ਟੰਡਨ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗਲ ਵੱਲ ਦਿਵਾਉਂਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਊਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੀ ਚੇਅਰ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਬੜੇ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਆਦਮੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਨਰ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ 'miss a meal once in a week' ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਬਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਅਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਵਕਤ ਖਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਟੰਡਨ ਜੀ ਨੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਦੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ-ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਇਕ ਦਿਨ ਖਾਣਾ ਨਾ ਖਾਓ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਨਾ ਖਾਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬੇਸ਼ਕ ਨਾ ਖਾਣ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਲੜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ : ਮੇਰੀ ਇਕ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਟੰਡਨ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 'miss a meal in a week' ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸੋਮਵਾਰ ਲੰਘ ਚੁਕੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਏਥੇ ਮੀਟ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ? (ਹਾਸਾ)

Note.—Expunged as ordered by the Chair.

PAPER LAID ON THE TABLE

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਲਿਸਟ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਕ ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੋ ਪਿੰਡ ਦੇ 72 ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 42 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 30 ਮਰਦ ਹਨ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ 110 ਆਦਮੀ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਇਕੋ ਪਿੰਡ ਵਿਚੋਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ 72 ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲਿਸਟ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਦੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰੋ।

*(ਇਕ ਲਿਸਟ ਟੇਬਲ ਤੇ ਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ)।

सरदार नारायण सिंह शाहबाजपुरी : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडम। आप ने हुक्म दिया था कि एक कमेटी कन्स्टीच्यूट करेगी। मैं समझता हूं कि यहां पर शरणार्थियों के ज़खमों पर नमक छिड़का गया है। आप ने कहा था कि लिख कर दें, मैं ने लिख कर भेज दिया है और वह आप के मेज पर है। आप इनक्वायरी करवाएं।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਸਰਦਾਰ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ? (How does the hon. Member know that it has come to my Table ?)

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਮੈਡਮ। ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਕਾਲ ਅਟੈਨਸ਼ਨ ਨੋਟਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਤਅਲੁਕ ਹੈ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨਰੀ ਕੋਰਸ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਐਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਐਨਾ ਵਕਤ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਾਲ ਅਟੈਨਸ਼ਨ ਨੋਟਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਕਿ ਐਡਮਿਟਡ ਐਡਮਿਟਡ। ਗਲ ਮੁਕੀ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਜਿਹੜੀ ਐਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਨਾ-ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸ ਤੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਤੇ ਵਕਤ ਲੈ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕਾਲ ਅਟੈਨਸ਼ਨ ਨੋਟਿਸਿਜ਼ ਵੀ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਸਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਅਜ ਬਿਲ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਕਲ ਸਾਰੇ ਕਾਲ ਅਟੈਨਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨਜ਼ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। (There can be no discussion on the adjournment motion which is disallowed: However, if Members take some time in unnecessarily raising that issue and if there-after we were to take up the Call Attention Notices, then the hon. Members can not do justification with the Bill. Therefore, I suggest that the Bill be taken up today, the Call Attention Notices will be taken up tomorrow.)

CALL ATTENTION NOTICES

ਸਰਦਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਧੌਲਾ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਮੈਡਮ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਲ ਅਟੈਨਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਦੋਂ ਵਕਤ ਮਿਲੇਗਾ ?

*Placed in the Library.

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਕਲ ਸਾਂਰਾ ਹਾਊਸ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ । ਅਜ ਕਾਫੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ । ਕਲ ਕਾਲ ਅਟੈਨਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ । ਅਜ ਬਿਲ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲਓ । (Yesterday, the whole House was emphasising the importance of the Bill and wanted to discuss it. Already quite a lot of time has passed. Let the House take up the Bill today. The Call Attention Motions will be taken up tomorrow.)

ਸਰਦਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਧੌਲਾ : ਕੀ ਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਊਸ ਚਲੇਗਾ ?

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਕਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲੇਗਾ । (The House will meet tomorrow.)

ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੈਣੇਵਾਲੀਆ : ਬੀਬੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆ ਕਾਲ ਅਟੈਨਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨਜ਼ ਅਜ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਲ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਉਹ ਅਜ ਹੀ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਉਹ ਕਲ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ । (Those will be taken up tomorrow. The Chair can allow that.)

चौधरी नेत राम : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडम । डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आप को यकीन दिलाता हूं कि बाबू अजीत कुमार ने कोई ऐसी बात नहीं कही । अपने बाकी की काल अटैन्शन मोशनज़ और एडजर्नमैण्ट मोशन्ज़ कल के लिये पैंडिंग रख दी हैं। जो बाबू अजीत कुमार ने कहा है कि हरिजनों के साथ नाइन्साफी हुई है वह मोशन भी पैंडिंग रख लें ।

उपाध्यक्षा : बहतर यह होगा कि आप सुन लिया करें । मैं ने पहले ही कह दिया है कि पैंडिंग रखी है । फिर बार २ आप कहते हैं, तो आपका ख्याल है कि नामन्जूर कर दी जाए । (It would improve matters if the hon. Member pays heed to what I say. I have already kept it pending. By referring to it time and again, he probably wants it to be rejected.)

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਮੈਡਮ. . . ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸੀਂ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ । (The hon Member obstructing the proceedings of the House.)

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਸੁਣ ਲਓ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਬੈਠ ਜਾਓ । (Please resume your seat.)

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਕੁਛ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਲ ਅਟੈਨਸ਼ਨ ਨੋਟਿਸਿਜ਼ ਅਜ ਲੈ ਲਓ ।

Deputy Speaker : No please. Now the House will resume discussion on the Punjab Commercial Crops Cess (Amendment) Bill, 1965.

THE PUNJAB COMMERCIAL CROPS CESS (AMENDMENT) BILL 1965. (RESUMPTION OF DISCUSSION.)

ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਕਿਰਤੀ (ਜਲੰਧਰ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਇਸ ਬਿਲ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ।...(ਵਿਘਨ)

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਮੈਡਮ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ । ਇਸ ਬਿਲ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਕਿਰਤੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। (He is a wise man. Sardar Karam Singh Kirti is speaking on this Bill.)

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਜਿਥੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਪਰਿਵਿਲਿਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਥੇ ਕੋਈ ਰੂਲਿੰਗ ਨਹੀਂ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਕਾਲ ਅਟੈਨਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨਜ਼ ਕਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। (The Call Attention Motions will be taken up tomorrow.)

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਅਜ ਹੋ ਜਾਣ ।

शिक्षा मंत्री : इस बारे में यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि यह बिलकुल चेयर कीं मर्जी है कि जब वह चाहें उन पर डिस्कशन कराई जाए । No body has a right to question the ruling of the Chair. Madam, it is for you to decide which Call Attention Notice is to be taken up today and which ones are to be taken up tomorrow. I would request you, Madam, to give your ruling.

Deputy Speaker : I have already given my ruling.

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਮੈਡਮ । ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਰੂਲ ਕੋਟ ਕਰਨ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਰੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ।

उपाध्यक्षा : बाबू बचन सिंह जी, मैं निहायत अदब से और अफसोस से कहती हूं कि हाउस का जो फैसला था उस के मुताबिक आज सैशन खत्म होना था । पार्लीयामेंटरी एफेयर्ज़ के मिनिस्टर ने मान लिया था। लेकिन आज इस चीज़ पर ज्यादा वक्त लिया जा रहा है। कल तमाम की तमाम काल अटैंशन मोशन्ज़ ले ली जाएं। मैं आप से दरखास्त करूंगी कि हाउस का काम चलने दीजिए। (I am sorry to say that as per earlier decision of the House, the Session was to come to a close today. The Minister for Parliamentary Affairs had also accepted it.

[उपाध्यक्षा]

However, this matter is being unduly prolonged. All the Call Attention Motions will be taken up tomorrow. I request you to let the House proceed with its business.)

श्री जगन्नाथ : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडम।

उपाध्यक्षा : आप बैठिए। (Please resume your seat.)

ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਕਿਰਤੀ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਅਜ ਤੋਂ ਢਾਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿਲ ਆਇਆ ਸੀ । ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਹਮਦਰਦੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ...... (ਵਿਘਨ)

बाबू बचन सिंह : मैडम, मैं आप से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि श्री जगन्नाथ जो बात कहना चाहते हैं मैंने उस को गौर से देखा और पढ़ा है। वह इतनी इम्पार्टेंट चीज़ है कि अगर आप आगे चलना चाहते हैं तो हाउस चल नहीं सकता। गवर्नमैंट की तरफ से फैमिन के मुतालिक ऐसा जवाब दिया गया है कि गवर्नमैंट की कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं।

उपाध्यक्षा : बाबू बचन सिंह जी, मैं सरदार कर्म सिंह किरती की स्पीच को जारी रखना चाहती हूं। मेरे पास आ जाएं। आप को यहां सीधी बात करने की इजाज़त नहीं।

(I want Sardar Karam Singh Kirti to continue his speech. You may come to me in my Chamber. You cannot be allowed to interrupt like this.)

श्री जगन्नाथ : आप की तरफ से रूलिंग है। आप पहले बात सुन लीजिए, ज्यादा क्लेश होगा, क्या फायदा ?

उपाध्यक्षा : यह बहुत नामुनासिब बात है। मुझे क्यों मजबूर करते हो ? ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕਾਗਜ਼ ਭੇਜ ਦਿਉ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੀ।

(This is very improper. Why force my hand ? Send the paper to me. I will see if it can be taken up after the speech of Sardar Karam Singh Kirti.)

ਬਾਬੂ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ : ਤੁਹਾਡਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਉ । (Please resume your seat.)

(Noise.)

उपाध्यक्षा : मुझे इस किस्म का शोर देख कर आज इस बिल की संजीदगी पर शक हो गया है। (Seeing this disorder, I have started doubting the seriousness under-lying this Bill.)

12.00 noon

चौधरी नेत राम : डिप्टी स्पीकर साहिबा, भिवानी तहसील में कहत पड़ा हुआ है और आप हमें बात करने की भी इजाजत नहीं दे रहीं।

Deputy Speaker ; Please resume your seat.

(At this stage Baboo Bachan Singh rose on a point of order.)

बाबू जी, आप को यह बात शोभा नहीं देती। (This sort of behaviour does not become of the hon. Member.)

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਹਿਬਾ, ਸ਼ੋਭਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, I have a right to raise a point of order and I must exercise that right.

उपाध्यक्षा : बाबू बचन सिंह जी आप को right तो है लेकिन एसे House का काम किस तरह चलेगा। या तो आप यह decide कर लो कि today is the day of points of orders. आप इस point of order में अपनी बात खत्म करें। (Of course he has the right to raise a point of order but then how will the House proceed with its business.. The alternative is that the House may decide that today is the day of points of order. Let him finish this matter with this point of order.)

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਜਗਨਨਾਥ ਹੋਰਾਂ ਵਲੋਂ ਭੀਵਾਨੀ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਚ ਕਹਿਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਕ ਕਾਲ ਅਟੈਨਸ਼ਨ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਡਿਸਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਥੇ ਕਹਿਤ ਪੈਣ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਾਲ ਅਟੈਨਸ਼ਨ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦੇਣ ਮੈਂ ਕਲ ਨੂੰ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰ ਲਵਾਂਗੀ।

(The mistake, if any, can be rectified any time. Let him give me the notice, I will take it up tomorrow.)

ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਕਿਰਤੀ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਅਜ ਤੋਂ ਢਾਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਹੋ ਬਿਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਿਰ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪਰਗਟ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰਖਦੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਗਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਅਜ ਤੋਂ ਢਾਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਾਹਾਂ ਲਈ ਅਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬਿਲ ਪੇਸ਼

[ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਕਿਰਤੀ]

ਹੋਇਆ ਹੈ। ਢਾਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਬਲਕਿ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜ ਹੈ। ਅਜ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਵਜਾਹ ਕਰਕੇ ਜਿਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਜੜ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਲਈ ਅਤੇ ਡੀਫੈਂਸ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਸੈਸ ਦੀ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਉਗਾਰਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪਰੋਟੈਸਟ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਲਿਆਉਣੀਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਐਸੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਨਸ ਬੋਲਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਰਿਪਰੀਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲਾਂ ਫਲਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਏਥੇ ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਧਰ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਲਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਲਾਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਿਪਰੀਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਕੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਏਥੇ ਸਪੀਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੁਝੀ ਛਿਪੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।

(Shri Ram Saran Chand Mital, a Member of the Panel of Chairmen, in the Chair.)

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ: ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਸਰ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਅਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਦਿਹਾਤੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਵਾਂ ਤੇ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ ਔਰ ਕਿਰਤੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਰਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹਕ ਵਿਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮਖਾਲਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

श्री चेयरमैन : प्वायंट आफ आर्डर के बहाने ऐसी वैसी बातें कहना शोभा नहीं देता। मैं नम्रता पूर्वक प्रार्थना करूंगा कि हमें हाऊस की प्रोसीडिंग्ज़ डिगनिटी के साथ कन्डक्ट करनी चाहिए और जो मैम्बर साहिब स्पीच कर रहे हों उन्हें खुली अपरचूनिटी दी जानी चाहिए ताकि वह अपने विचार पेश कर सकें। (It is unbecoming to raise extraneous matters through a point of order. I would humbly submit that the proceedings of the House should proceed in a dignified

manner and the member who is in possession of the House should get full opportunity for giving expression to his views .)

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਆਪਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪਰੋਸੀਜਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਰੋਸੀਜਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜੋ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕਹੋ ਅਤੇ ਜੋ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿਉ। ਅਜ ਸੁਬਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਪਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਠੰਡੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

Mr. Chairman : The hon. Member is a Law Graduate and is a practising lawyer. He must know that it is not for anybody to control and regulate the speech of an hon. Member. He also knows that a point of Order can be raised relating to a point of Procedure in the House. So, this is no point of Order.

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ : ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕਾਲੇ ਬਿਲਿਆਂ ਦੀ ਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਫਹਮੀ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਪੜਾ ਤਕਸੀਮ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਤਕਸੀਮ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਦਰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਕਾਲੇ ਕਪੜੇ ਨਾਲ ਸੂਰਜ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਾਲਾ ਕਪੜਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਤਾਕਿ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। (ਹਾਸਾ)

ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ : ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਤਾਂ 12 ਵਜੇ ਹਟ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਗ੍ਰਹਿਣ ਜੱਟ ਤੇ ਲਗਣਾ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਉਸ ਗ੍ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲਗਾਏ ਹਨ। (ਹਾਸਾ)

चौधरी देवी लाल : ग्रान ए प्वायंट ग्राफ ग्रार्डर, मैं यह जो वजीर साहिब ने इस की वजह बताई है कि ग्रहण था उस बारे में मैं ग्रर्ज़ करता हूं कि मैं यहां 10 बज कर 5 मिन्ट पर ग्राया था। मुझे कांग्रेसी मैम्बर मिले उन के हाथों में यह काले बिल्ले थे ग्रौर एक बिल्ला उन्होंने यहां मेरे लगा दिया। ग्रपना ग्रहण उतार कर मुझ पर ग्रपना ग्रहण डाल कर खुद चले गए। ग्राखिर यह हर किसम का ग्रहण मेरे गले ही क्यों पड़ता है। कैरों वाला ग्रहण भी मेरे गले पड़ा था ग्रौर यह ग्रहण भी मेरे गले डाल दिया ग्रौर ग्रपना उतार कर चुप बैठ गए। मैं ग्रापका रूलिंग चाहता हूं कि क्या यह इस ढंग से किसी मैम्बर के साथ चार सौ बीस कर सकते हैं (हंसी) मेरे लगा कर ग्रपने जेबों में डाल कर बैठ गए हैं। स्पीच इन्होंने खिलाफ देनी है लेकिन वोट खिलाफ नहीं देना है। (शोर)

ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਕਿਰਤੀ : ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਖੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਮਖੌਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਨਸੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਫੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਗਰੀਬ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਨਸੀਅਰ ਲੀਡਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰੈਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸਟਰਾਂਗ ਵਾਇਸ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ

[ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਕਿਰਤੀ]

ਐਸ. ਪੀ. ਨੇ ਸਾਰੇ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨੌਕਰ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੰਗਾ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਅਤੇ ਐਸ. ਪੀ. ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਦਸੋ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਪੁਛਦੇ ਹੋ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਹਰੀਜਨਾਂ ਪਾਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਰਾਈਟਸ ਹਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਸ ਰਿਆਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਨਾ ਆਓ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭੁਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸਿਆਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸ ਜਾਓ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੁਟਾਪਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੁਟਾਪਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਅਧੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਆਦਮੀ ਹੀ ਐਸਾਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸਦੀ ਖਬਰ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੇ ਮਾਰ ਖਾਦੀ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਵਾਇਸ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹੋ ਵਜਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਅਜ ਐਨੀ ਭੈੜੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਸ ਲਗਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀ ਸਦਕੇ ਲਾਓ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਰੁਸਤ ਕਰੋ। ਬਿਕਰੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਇਹ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਐਨੇ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਤੇ ਹਾਕਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਅਜ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਕਿਤਨੇ ਹਾਕਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛਡਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਜਿਤਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਹਲ ਚਲਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਸਪਾਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਮਝ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ਦੀ ਲੰਘੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਚਲ ਥਾਣੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਬੀ. ਡੀ. ਓ. ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲਾ ਆ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਭਜਾਈ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮਕਿਮੇ ਤੇ ਅਫਸਰ ਉਸ ਲਈ ਬਣੇ ਹਨ ਉਹ ਬਜਾਏ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੰਗ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਰਾਮ ਸੇਵਕ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਹਾਕਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾਂ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 'ਮਰਜ਼ ਬੜ੍ਹਤਾ ਗਿਆ ਜੂੰ ਜੂੰ ਦਵਾ ਕੀ'। ਜਿਤਨੇ ਮਾਹਕਮੇ ਤੇ ਅਫਸਰ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਭੈੜੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਤੇ ਮਾਇਕ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦਰਅਸਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਚੁਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਕਿਸੇ ਇਕ ਤੇ ਹੋਲ ਟਾਈਮ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਸ ਵਜ਼ੀਰ ਪਾਸ ਵੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਉਹ ਨਥੀ ਬੋ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ

ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪਾਸ ਵਾਹੂ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਦਿਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਖਾਦ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਜ਼ੀਰ ਕੋਲ ਜਾਵੇ, ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸ ਜਾਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਪਾਸ ਜਾਵੇ, ਮੋਘਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੌਧਰੀ ਰਿਜ਼ਕ ਰਾਮ ਪਾਸ ਜਾਵੇ, ਤਕਾਵੀ ਲਈ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸ ਜਾਵੇ, ਚੰਗੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਵੇ ਗਰਜ਼ੇਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਜ਼ੀਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਧਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸੁਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਇਕ ਹੋਲ ਟਾਈਮ, ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਣੀ ਖਾਦ, ਤਕਾਵੀ, ਬਿਜਲੀ, ਬੀਜ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁਝ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਹੋਵੇ ਤਾਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਇਕ ਆਦਮੀ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਇਕ ਤਕੜਾ ਆਦਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਅਮਲੀ ਨੇ ਇਕ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਉਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਦੋ ਚਾਰ ਫਰਲਾਂਗ ਤੇ ਇਕ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਥੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਲਈ ਥਾਣੇਦਾਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਅਮਲੀਆ ਇਥੇ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਮਲੀ ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣੇਗਾ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਪਛਾਣ ਲਵਾਂਗਾ ।

ਮੈਂ ਕਤਲ ਹੋਏ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ । ਥਾਣੇਦਾਰ ਅਫੀਮੀ ਦੀ ਗਲ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ । ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸਿਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਫੀਮੀ ਨੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ । ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਬਿਨਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਚਾਹ ਪੀਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਫੂਡਗਰੇਨਜ਼ ਦੀ ਡਬਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਡਬਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਉਪਜ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਡਬਲ ਕਰਾਂਗੇ । ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਸ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਖਾਦ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦੀ ਡਬਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਿਨਾ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਲ ਹੈ । ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਬਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਗਾ । ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਲਿੱਕ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਡਿਸਟਰਿਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਗਲ ਹੋਈ । ਉਥੇ ਖਾਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ । ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 2,300 ਟਨ ਖਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 700 ਟਨ ਹੀ ਖਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਦ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਾਦ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਸਿਰ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਸੁਧਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰ ਸਕਣ। (ਵਿਘਨ)

ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਗੋਆਣੀ : ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ?

ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਕਿਰਤੀ : ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਰ ਇਕ ਦੀ ਵਖਰੀ ਵਖਰੀ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਬੇਜ਼ਰਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ (ਸਿਰਹੰਦ) : ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਦੀ ਸਦਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਅਜ ਜਿਹੜਾ ਅਮੈਂਡਿੰਗ ਬਿਲ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਉਰੀਜੀਨਲ ਬਿਲ 1963 ਵਿਚ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਗਾਲਬਨ ਮੈਂ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ 27 ਮਾਰਚ, 1963 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਨਾ ਲਾਉ । ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦਲੀਲਾਂ ਵੀ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਰਖੀਆਂ ਸਨ । ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਉਹ ਸਪੀਚ ਪਰਿੰਟ ਹੋਕੇ ਹੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਰੀਕਾਰਡ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇਗੀ । ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਮੰਨੀ ਪ੍ਰਮੰਨੀ ਰਾਏ ਵੀ ਉਹੀ ਹੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਉਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ । ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਕਮਊਨਿਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਅਗਰ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਗਰਿਤੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਾਵਾਜਿਬ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਸਕੇ । ਇਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗਲ ਨੂੰ ਰੀਪੀਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗਲਾਂ ਰੀਪੀਟ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਮੈਂ 27 ਮਾਰਚ, 1963 ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਂਡ ਰੈਵੇਨਯੂ ਸਰਚਾਰਜ ਲਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, Special Surcharge, Additional Surcharge, Temporary Taxation ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਫੇਰ Betterment Levy Tax ਲਾਇਆ ਗਿਆ । ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਫਿਰ Commercial crops Cess ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਉਤੇ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਟੈਕਸ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਚੌਥੀ ਫਾਈਵ-ਈਅਰ ਪਲੈਨ ਤਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਮਦੇਨਜ਼ਰ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 31 ਮਾਰਚ, 1966 ਤਕ ਹੈ । ਇਥੇ ਪਲੀਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ । ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਭੁਲ ਜਾਣਗੇ ? ਅਗਰ ਇਹ ਬਿਲ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਅਲਾਵਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ । ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਸਟਾਂ ਉਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਸਾਲ ਵਿਚ 2 ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੈਕ ਬੋਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ

ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਤਕ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ । ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਾਉ । ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਵੇਗੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਰਿਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨਗੇ । ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਨਾ ਲਾਉ । ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਟ੍ਰਿਬਯੂਨ ਵਿਚ under the Caption "In conclusive talks on Punjab for 1966-67 Plan" ਛਪੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ । ਜੋ ਕੁਝ ਟ੍ਰਿਬਯੂਨ ਵਿਚ ਛਪਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ।

> "The Punjab Government had agreed to raise a certain amount of additional resources for the Plan some time ago. After the Indo-Pakistan fighting which had its impact on the economy of this border State, Punjab is reported to have said that it could not expect to raise resources at that level".

ਅਗਰ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ । ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਲਗਾਉ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਕਮਯੂਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਚੇ ਫੌਜ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਰਿਜਨ ਦੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਜਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਖਿਆ ਵਿਚ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਗਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਖਿਆ ਵਿਚ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀਰ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਏ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਕਰੈਡਿਟ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਸਰ ਸਿਕੰਦਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਾ ਖੌਫੇ ਤਰਦੀਦ ਇਹ ਗਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਨੇ, ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਆਪਣੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਤੇ ਇਸ ਡੀਫੈਂਸ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪੈਜ਼ੰਟ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਵਿਚ ਦਿਤਾ ਹੋਇਆ

[ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ]

ਹੈ। ਕਲ ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ । ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡੀਟੇਲਜ਼ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੀਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਜ਼ੰਟ ਪ੍ਰੋਪ੍ਰਾਈਟਰਸ਼ਿਪ 2984 ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ 30 ਏਕੜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹਨ 2885,10 ਏਕੜ ਅਤੇ 30 ਏਕੜ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 2505 ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਹਨ .... (*Interruptions*) ਮੈਂ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਰਕਬੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, 2984 ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਾਈਜ਼ ਦੀਆਂ .... (ਵਿਘਨ) ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਏਕੜ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਵੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, 10 ਏਕੜ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ 10 ਤੋਂ 30 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਥੇ ਪੈਜ਼ੰਟ ਪ੍ਰੋਪ੍ਰਾਈਟਰਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਅਠ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ 100 ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ ....

(*Interruptions* by Babu Bachan Singh) ਮੈਂ ਇਹ ਫਿਗਰਜ਼ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਐਬਸਟ੍ਰਕਟ 1964 ਦੇ ਸਫ਼ਾ 81 ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕ੍ਰੈਕਟ ਫਿਗਰਜ਼ ਹਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਖਾਨੇ ਵਿਚ ਦਿਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਥੇ ਪੈਜ਼ੇਂਟ ਪ੍ਰੋਪ੍ਰਾਈਟਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਓਵਰਵੈਲਮਿੰਗ ਮੈਜਾਰੇਟੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਟੈਕਸ ਛੋਟੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਉਪਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਕ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਕੰਜ਼ੀਊਮਰਜ਼ ਦੇ goods ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਗਦਾ ਹੈ—ਮਸਲਨ ਮਿਲ ਕਲਾਥ, ਮੈਚਿਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਲਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬੋਝ ਦਾ ਇਕ ਬੜਾ ਹਿਸਾ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟ ਮੈਂਟ ਗੁਡਜ਼ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਮਸਲਨ, ਟ੍ਰੈਕਟਰਜ਼ ਹਨ, ਡੀਜ਼ਲ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾ ਕਾਬਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੈ। ਤੁਸਾਂ ਅਜ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਥੇ ਅਜ ਹੰਗਾਮਾ ਬਪਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਿਵਾਨੀ ਵਿਚ ਕਹਿਤ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਹਿਜ਼ ਭਿਵਾਨੀ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਹਿੰਦਰ-ਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਹਿਤ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਥੋਂ ਆਵੇਗਾ ? ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਗਿਆ ਸੀ ਉਥੇ ਕਿਸਾਨ ਲੇਟ ਵੈਰਾਇਟੀ ਕਣਕ ਦੀ ਬੀਜਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮੀਆਈ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਦਸਤਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸਾਂ ਅਜ ਹੀ ਟ੍ਰੀਬਿਊਨ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛਪੜਾਂ ਨਾਲ ਆਬਪਾਸ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਿਵਿੰਗ ਮੈਮੋਰੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਜ਼ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਪਟਿਆਲਾ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੇਸ਼ਕ ਕਹੀ ਜਾਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇਕ ਇਕ ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਕੋਈ ਵੀ ਸਜਨ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ

ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਿੱਬੇ ਵੀ ਵਾਹ ਕੇ ਬੀਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨ । ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਯੂਸੀ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਲ ਲਿਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨ। ਦੇਹਾਤ ਵਿਚ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਪਰ ਕਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਇਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਸ਼ੇਖੀਆਂ ਭਗਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤਕ ਮਾਲੀਆ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਜਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਇਨਕਮਟੈਕਸ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਬਾਤ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਾਰੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਆਇਦ ਕਰੋ । ਇਕੋ ਟੈਕਸ ਸਭ ਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਆਫਟਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਨਫਿਊਜ਼ਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਿੰਪਲੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਜੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਹਿਤ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਾਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਦੋਬਾਰਾ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰਜ਼ੇ ਇਲਤਵਾ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿਉ।

ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ

"The responsibility of the construction of the Beas Dam should be entirely of the Centre."

ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਤਕ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਅਟੈਂਪਟ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੋਸਟ ਇੰਮਪਾਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਟੀਊਬਵੈਲਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੋਨੋਂ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਲਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਆਸ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਨਾ ਘਟ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਆਸ ਡੈਮ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 15 ਤੋਂ 20 ਫੀ ਸਦੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ ਕੋਈ ਵਜਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਉਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਵਜੁਹ ਇਸ ਲਿੰਕ ਉਤੇ ਲਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਫਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ? ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਉਥੇ ਥਲੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਥੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਮਾਲੂਮ ਕਿਤਨੇ ਸਾਲ ਲਗ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਵਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ

[ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ]
ਤਕ ਅਲਤਵਾ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਦਹੋਲਡ ਕਰ ਲਉ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿਉ, ਇਹੋ ਮੇਰੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ): ਜਨਾਬ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਸ਼ਲ ਕਰਾਪਸ ਉਤੇ ਸੈਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਇੰਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਆਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਂਡ-ਰੈਵੀਨੀਊ ਹੈ—ਇਹ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਇਸ ਲੈਂਡ ਰੈਵੀਨਿਊ ਉਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਵੀ ਲਗਿਆ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਰਚਾਰਜ ਲਗਿਆ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਆਬਿਆਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਮਗਰ ਲੈਂਡ ਰੈਵੀਨੀਊ ਦੀ ਤਸ਼ਖੀਸ ਅਜ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਤਬਕਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਭੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਜਲ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ। ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜ ਤਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਸਿਡਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜ ਤਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਨਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਉਤੇ ਖਰਚ ਕਿਤਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਵੇਖ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਤਦ ਤਕ ਉਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਉਤੇ ਇਤਨਾ ਬੋਝ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅਜ ਤਕ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੈਂਡ ਰੈਵੀਨੀਊ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਮਾਨੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਲੇਕਿਨ ਅਜ ਉਸ 1/4 ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਹੀ ਮੁਨਾਫਾ ਸਮਝ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦ ਰਖ ਕੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਕ ਦੇ ਉਪਰ ਦੂਸਰਾ, ਦੂਸਰੇ ਉਪਰ ਤੀਸਰਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ, ਕੁਝ ਇਕਨਾਮਿਕ ਐਕਸਪਰਟਸ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਉਤੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਉਤੇ ਪੁਜਦੀ। ਪਰ ਇਥੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਜਲ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਲੈਵੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ। ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ

ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਬਗੈਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਟੈਕਸ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ। ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਦਰ ਅਸਲ ਇਕ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਜ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਉਤੇ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਥਲੇ ਉਹ ਚੂਰ ਚੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਜ ਜਦ ਫੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਰਤੀ ਵਾਲੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਦੋ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਆਦਮੀ ਪੁਜਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦਸ ਦਸ ਬਾਰਾਂ ਬਾਰਾਂ ਆਦਮੀ ਹੀ ਸਪੈਸਿਫੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਘਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉ ਕਿ ਜੇ ਮਾਲੀ ਔਰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਲਾਸ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਕਿਥੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ? ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ "ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ" ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲਗਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਰਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਪਰ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ—

(1) ਮਿਹਨਤ
(2) ਪਾਣੀ ਔਰ
(3) ਖਾਦ

ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਬੜੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਖਾਦ ਦਾ ਤਅਲੱਕ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਖਾਦ ਉਤੇ ਪੰਜ ਰੁਪੈ ਫੀ ਬੋਰੀ ਮੁਨਾਫਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੋ ਰੁਪੈ ਵਧਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਰੇਟਸ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਆਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਨੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ-ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਫਾਰਿਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ ਵਿਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਉਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ , ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਿਊਬਵੈਲਜ਼ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਕਾਵੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ। ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਕਾਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਟਿਊਬਵੈਲਜ਼ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਚਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤਕਾਵੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਪੁਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਲੁਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਵਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕਨਾਮਿਕ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਖੇਤੀ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਉਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਗਲ ਉਤੇ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ

[ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ]

ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਸੋਰਸ ਠੀਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਕ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿਸ ਕੰਮ ਆਏਗੀ ? ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖੁਦ ਦਾਰੀ ਨਾਲ ਔਰ ਕੌਮੀਅਤ ਨਾਲ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਭੁੱਖ ਹੀ ਭੁੱਖ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਤੀਸਰੀ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਕਾਵੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇ, ਫਸਲ ਦੇ ਬੀਜਣ ਦਾ ਔਰ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰ ਬਗੈਰ ਮੌਕਾ ਵੇਖੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੁਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਪਿਆਦੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਹਨ ਇਹ ਦਿਨ ਬਦਿਨ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਇਥੇ ਰਾੜੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਫਿਗਰਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਿਗਰਜ਼ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਦਿਨ ਬਦਿਨ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਨਇਕਨਾਮਿਕ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਿਥੇ ਇਸ ਕਦਰ ਅਨਇਕਨਾਮਿਕ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਥੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਿਵੇਂ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੇ ਵਾਇਦੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਲੈਂਡ ਰੀਫਾਰਮਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ. ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਰਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ 9 ਲਖ ਏਕੜ ਸਰਪਲਸ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਈ ਪਰ ਹੁਣ ਤਕ ਸਿਰਫ ਇਕ ਲਖ ਏਕੜ ਹੀ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਅਜ ਤਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਬਾਰ ਬਾਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲੈਂਡ ਰੀਫਾਰਮਜ਼ ਦਾ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕਿਉਂ ਲਵੇ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਿਲ ਕੀ ਹੈ ? ਅਜ ਤਕ ਕੋਈ ਮੁਸਤਕਿਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਮਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਲ ਖੁਸ਼ਕੀ ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਖੁਸ਼ਕੀ ਕਰਕੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਹੀ ਦੇ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਚਾਲੂ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਇਹ ਐਲਾਨ 30 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ 30 ਤਰੀਖ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਕ ਬਟਾ ਪੰਜ ਹਿਸਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਿਜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸਿਰਫ ਉਹੋ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਵਤਰ ਨੂੰ ਦਬ ਲਿਆ ਸੀ ਵਰਨਾ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚ ਕਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।

ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਖਾਦ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਸਰਕਾਰ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖਾਦ ਦੀ ਬੜੀ ਮੈਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀ-ਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਦ ਕਈਆਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਡਿਪੂਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬੀਊਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਉਹ ਆਦਮੀ ਅਗੇ ਉਸ ਖਾਦ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਵਿਚ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਉਹ ਅਗਾਹਾਂ ਪੰਜ ਪੰਜ ਜਾਂ ਛੇ ਛੇ ਰੁਪਏ ਮੁਨਾਫਾ ਲੈ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਖਾਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਢਣ ਵਿਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮੈਲ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ।

ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਬਕਿਆਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤਬਕਾ ਟਰਕਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਖਤਰਾ ਮੁਲ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਐਮੂਨੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਉਥੇ ਉਥੇ ਆਪਣੇ ਟਰਕ ਔਰ ਲਾਰੀਆਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਅਣਥਕ ਕੰਮ ਦੀ ਪਰਸ਼ੰਸਾ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੋਟਰ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। (ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਹਾਸਾ)

ਦੂਜਾ ਤਬਕਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਲਨਟਰੀ ਬੇਸਿਜ਼ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੀਲੀਫ ਫੰਡ ਲਈ ਲਖਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਔਰ ਖੁਦ ਚੰਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿਚ ਜਕੜ ਦਿਤਾ ਹੈ।

ਤੀਜੀ ਕਲਾਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿਚ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਗੜਾ ਇਹ ਇਸ ਸੈਸ ਬਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੰਨ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਔਰ ਇਸ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਛੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਵੇ। (ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ: ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਇਹ 70 ਲਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਵੇਗੀ) ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ 70 ਲਖ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਅਧੀ ਇਸ ਦੇ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ।

ਇਕ ਅਵਾਜ਼: ਇਸ ਦੇ ਵਸੂਲ ਹੋਣ ਤੇ ਖਰਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਸੂਲ ਹੋਣਾ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ: ਜੇਕਰ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹੀ ਵਸੂਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪੰਚੋਤਰਾ ਤਾਂ ਲੈਣਗੇ ਹੀ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਡਿਸਕਰੇਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਸ਼ਨ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਜਾਏ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗ ਦੀ ਵਜਾਹ ਕਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉਪਰ ਬੜਾ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਉਲਟਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟੈਕਸ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਖਰੀ ਗਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨ ਔਰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁ ਸੰਮਤੀ ਰਖਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਮੈਜਾਰੇਟੀ ਰਖਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਇਥੇ ਪਾਸ ਕਰਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਬਿਲ ਵੀ ਇਥੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰਾਏ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਥੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਅਜ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਲੇ ਬਿਲੇ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਵੋਟ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਇਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੋਏ ਜੇ ਇਹ ਕਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾਉਣ ਤਾਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕੇ ਔਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੌਸਲਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਲ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦੇਣ।

(इस समय बहुत सारे मैंम्बर बोलने के लिये खड़े हो गए।)

श्री सभापति : आप फिक्र न करें। सब को बोलने के लिये टाईम दिया जाएगा।

ਇਕ ਆਵਾਜ਼ : ਬੈਂਕ ਬੈਂਚਰਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਵਕਤ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ उन को भी मिलेगा।

(The hon. Members need not worry. Those who want to speak will get time. Even the back benchers will be given time to speak.)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ (ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਐਸ. ਸੀ.): ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਅਜ ਤੋਂ ਦੋ ਢਾਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਬਿਲ ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਥੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦਾਹਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੀਜਨ ਕਲਿਆਣ ਟੈਕਸ ਇਕ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੋਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਤੋੜ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈ ਆਏ ਹਨ। (ਵਿਘਨ) ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ

ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕੁਲ ਉਗਰਾਈ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤਕਰੀਬਨ 68 ਜਾਂ 70 ਲਖ ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜੇਕਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ ਯਾਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਔਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਅਗਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚੋਂ ਕਢ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਰਕਮ ਵਿਚੋਂ 22 ਜਾਂ 23 ਲਖ ਰੁਪਏ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ 40-45 ਲਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਪਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸੈਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਹਥੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਜਾੜ ਦਿਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਆਦਮਪੁਰ ਅੱਡੇ ਦੀ। ਉਥੇ ਬੰਬਾਰੀ ਹੋਣ ਲਗੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੈਰਾਟਰੂਪਰ ਉਤਰਨ ਲਗੇ । ਉਸ ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਅਡੇ ਦੀ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਕੁਝ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਕਟਣ ਲਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਕੀ, ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰ੍ਹਨ ਲਗੀਆਂ ਪੈਰਾਟਰੂਪਰਾਂ ਦੀਆਂ , ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਹਾਗੇ ਬੰਨੇ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜੋ ਹਾਲੇ ਪੱਕੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਛਾਤਾਬਰਦਾਰ ਨਾ ਛਿਪੇ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਗਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਵਾਈ ਅਡੇ ਲਈ ਦਿਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਬੰਬਾਰੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਿਆ।

One Voice : They are true nationalists

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ: ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੈਸ ਕਮਰਸ਼ਲ ਕਰਾਪਸ ਯਾਨੀ ਗੰਨੇ, ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ । ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਗੰਨਾ ਬੀਜੋ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੰਨਾ ਬੀਜਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਭਾਰਗਵ ਨਾਲ ਗਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ। ਕਮਾਦ ਬੀਜੋ ਗੁੜ ਬਣਾਉ ਤੇ ਚਾਹ ਪੀਉ। ਕਪਾਹ ਬੀਜੋ ਤੇ ਖੱਦਰ ਪਾਉ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਨਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਜਾਰਿਟੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦਸੋ ਉਹ ਕੀ ਕਮਾਦ ਬੀਜਣਗੇ ਦੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 4 ਕਨਾਲਾਂ ਜਾਂ ਹਦ ਇਕ ਏਕੜ। ਓਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੜ ਖਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਿਲ ਨੂੰ ਗੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ 2 ਆਨੇ ਮਣ ਪਿਛੇ ਕਟੌਤੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੰਡ ਤਕਸੀਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਟ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੰਨਾ ਬੀਜਦਾ ਹੈ, ਮਿਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 2 ਆਨੇ ਮਣ ਪਿਛੇ ਕਟੌਤੀ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਖੰਡ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੇ ਸੈਸ ਨੂੰ ਰੀਵਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਕਪਾਹ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘਟ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਕਪਾਹ ਬੀਜਦੇ ਹਨ। ਸੇਮ ਕਰਕੇ ਦੋ ਤਿੰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕਪਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਸੈਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਟੈਕਸ ਦਰਅਸਲ ਫੌਜੀਆਂ ਤੇ ਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਉ ਉਥੇ 100—50 ਬੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਟਰੀ ਵਿਚ ਹੋਣਗੇ ਭਾਵੇਂ ਹਰਿਆਨਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਜਨ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਟੈਕਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੈ ਜੋ ਮੁਲਕ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

[*Shri Rup Singh Phul a member of the Panel of Chairmen in the Chair*.]

ਫਿਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਮੈਂ ਦਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਲਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਲੋਡ ਘੱਟ ਤੇ ਕਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਲੋਡ ਦੀ ਇਸ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਲੂਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਘਟ ਹੋਈਆਂ। ਨਹਿਰਾਂ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਸ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਤੇ ਇਹ ਸੈਸ ਲਗੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਏਰੀਏ ਵਿਚ ਗੁੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇਣਾ, ਮਸ਼ੀਨੀ ਬੇਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਖੰਡਸਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੇ ਇਹ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਹਨ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਯੂ. ਪੀ. ਵਿਚ ਹੈ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੇ ਇਹ 40—45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰ ਪਾ ਕੇ ਭਲਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਥੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਐਸਟੀਮੇਟਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਮਿਲ ਨੂੰ ਲਕੜੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਕੜੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਘਟਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਐਸਟੀਮੇਟਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਕੀਮਤ ਕਿਉਂ ਘਟਾਈ ਹੈ।

ਇਕ ਆਵਾਜ਼ : ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਕੀਮਤ ਸਗੋਂ ਵਧੀ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ : ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁਛ ਲਉ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਸਟੀਮੇਟਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿਉ ਕਿ ਕੀਮਤ ਘਟਾਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਬਿਰਲੇ ਨੂੰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ 30 ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਤੇ ਦਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਪ ਪਾਪੂਲੈਰਿਟੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਝ ਟੈਕਸ ਛੱਡ ਦਿਤੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਆਖਿਰ ਜੋ ਆਦਮੀ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫੀਸ ਘਟਾ ਦਿਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਚੀਪ ਪਾਪੂਲੈਰਿਟੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਟੈਕਸ ਛੱਡੇ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬਿਲ ਆਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰ ਉਸ ਦਾ ਕਨਜ਼ਯੂਮਰ ਤੇ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਥੇ ਦੀਵਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਗਰ ਇਹ ਟੈਕਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਲਗਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀ ਐਜ਼ੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੋਕਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਰੀਜਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਟੈਕਸ ਲੱਗਾ। 3 ਕਰੋੜ 86 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 1 ਕਰੋੜ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਸ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਬਣਾਇਆ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ $3\frac{1}{4}$ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਖਾ ਗਈ। ਅੱਜ ਉਹ 1 ਕਰੋੜ 83 ਲੱਖ

ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ 3 ਕਰੋੜ 17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਥੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਜਦ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰੀਜਨਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਪੈਸਾ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਫਤ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚਾਲ੍ਹੀ ਪੰਤਾਲੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸ਼ਰਤ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ 5 ਏਕੜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਟਿਊਬ-ਵੈਲ ਹੋਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿੰਨੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੁਝ ਸੌਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ? ਲੋਕੀਂ ਖਾਦ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਹਨ, ਸੀਮਿੰਟ ਦੀ ਬੋਰੀ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਹਨ। ਖੈਰ ਸੀਮਿੰਟ ਦੀ ਬੋਰੀ ਤੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਖਾਦ ਦੀ ਬੋਰੀ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਕਦੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਖਾਦ ਦੀ ਬੋਰੀ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵਰਤਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਾਦ ਨਾਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਖਾਦ ਦੀ ਬੋਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਦ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਖਾਦ ਆਈ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਖਾਦ ਮਾਂਈਡਿਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰਟਿਲਾਇਜ਼ਰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। (ਵਿਘਨ) ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਗਣੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਖਾਦ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿਉ, ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਪਾਣੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਉ, ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿਉ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਿੰਨੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਥੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਰਲੇ ਦਾ ਤਾਂ ਇਕ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਰਲਾ ਬੀਜ ਚੰਗਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਯੂ. ਪੀ. ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯੂ. ਪੀ. ਵਿਚ ਫਾਰਮਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫਾਰਮਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਇਥੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਬਿਰਲਾ ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਮੋਟਾ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ? (ਹਾਸਾ) (ਵਿਘਨ) ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਅਜ ਤੁਸੀਂ ਯੂ. ਪੀ. ਦੀ ਤਰਾਈ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਾਰਮਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ

[ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ]
ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜ ਚੰਗਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਥਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲੀਟੀਜ਼ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਬੀਜ ਖੁਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਬਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਚੋਆਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਲਾਕਾ ਰੀਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਬੈਡ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਰੀਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਆਪ ਫਾਰਮਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਬਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਚੋਆਂ ਤੋਂ ਰੀਕਲੇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਕਲੇਮ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਕ ਹੋਰ ਗਲ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਖੇੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਚ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਉਥੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਕਿਲ ਵੀ ਹੈ ਚੰਗੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰੀਕਲੇਮ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਜਾਏ ਬਿਰਲੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ? ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।

ਪਰ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਦਾ ਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੋਕਲ ਨਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਗਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਹੀਂ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਉ ਫੇਰ ਇਸ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇਥੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਆਉ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਫਿਰ ਰਖ ਕੇ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸੇ ਛੁਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਰੱਖੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਛੁਟੀ ਸੀ। ਮੈਂਬਰ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਮਰੇਡ ਜੀ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਹੈ, ਕਾਮਰੇਡ ਬੜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲੈਣ। ਮੈਂ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਅਧੀਨਗੀ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਤਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਏ ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਕ ਸਾਲ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲੰਘਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤਕ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕਮ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਵਲ ਵੀ ਤੱਕੋ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਾਲੀਆ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੰਤ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਪਾਸੋਂ ਖਿਮਾਂ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ।

ठाकुर मेहर सिंह (डेहरा गोपी पुर) : चेयरमैन साहिब, यह जो कमर्शल क्राप सैस बिल आज इस हाऊस में ज़ेरे बहस है इस के बारे में मैं सरकार से यह कहूंगा कि यह जो सरकार का फैसला है इस बिल को पास करने का इस के लिए सब से बेहतर बात यह है कि इस बिल को सरकार वापिस ले ले। इस बिल से ज्यादा हमारे सूबे के किसानों को और दुख देने वाली कोई बात नहीं हो सकती। (विरोधी पक्ष की ओर से प्रशंसा) सरकार के अपने अदादोशुमार के मुताबिक चेयरमैन साहिब, यह बात कही गई है कि इस सैस से हमारे सूबे को 60, 70 लाख की आमदनी होने वाली है। इस में यह भी कहा गया है कि इस सैस को बार्डर के तीन ज़िलों में नहीं लगाया जा रहा। अमृतसर, गुरदासपुर और फिरोज़पुर के तीन ज़िलों को इस से मुस्तस्ना करार दिया गया है। इस हिसाब से और भी सैस कम हो जाएगा यानी कोई 30, 40 लाख के करीब होगा। फिर इस में से 10—15 लाख अमले पर खर्च हो जाएगा। इस लिये इस बिल से कोई ज्यादा फायदा पहुंचने वाला नहीं है। यह बात आप जानते हैं कि दिहात में मुल्क की 85 फीसदी आबादी बसती है और इस टैक्स का असर उन पर पड़ने वाला है। और वह अपना रोष सरकार के विरुद्ध प्रकट करेंगे।

फिर, चेयरमैन साहिब, सन् 1963 में यह सैस लगाया गया था और सरकार की तरफ से एलान किया गया था और हम भी अपने इलाके में गए और देखा कि एक एक कनाल पर भी जिसने गन्ना बीज रखा था टैक्स लगा दिया गया। और वसूल किया गया। हम लोगों को कहते रहे कि यह तो आर्ज़ी टैक्स है और सिर्फ तीन साल के लिये है इस के बाद नहीं लिया जाएगा। आज फिर गवर्नमैंट दोबारा नए सिरे से इस टैक्स को लगाने जा रही है। इस का नतीजा क्या होगा कि पंजाब की 85 फीसदी आबादी सरकार से नाराज़ हो जाएगी। अगर इन्हें रुपया ही चाहिए तो मैं आप के ज़रिये सरकार को कई दूसरे तरीके बता सकता हूं जिन के द्वारा रुपया वसूल हो सकता है। मिसाल के तौर पर सैरिक्लचर का महकमा है। इस पर लाखों रुपया तो खर्च किया जाता है और हज़ारों रुपया की आमदन भी नहीं। अगर इस महकमा को हटा दिया जाए तो फिर इस टैक्स के लगाने की ज़रूरत ही नहीं रह जाती। टैक्सों के मामले में भी ऐसे ही हालात हैं। जब टक्स लगता है तो यह समझ कर कि ज़मींदार अमीर हैं इस लिये उन पर टैक्स लगाया जाता है मगर कोई बोलता तक नहीं। मगर जब सरमायेदारों पर लगाने का टैक्स आता

[ठाकुर मेहर सिंह]

है तो चारों तरफ शोर मच जाता है। आप ने देखा होगा कि यहां पर बिकरी टैक्स आया तो कितनी अमैंडमैंट्स आईं और बहुत सी सरकार को माननी भी पड़ीं। इस बिल के मुताल्लिक मैं ने एक अमण्डमैंट दी थी कि 5 एकड़ से कम जमीन वालों को इस ऐक्ट से मुस्तस्ना करार दे दिया जाये मगर वह एमैंडमैंट आज तक न छपी है और न ही डिस्ट्रीब्यूट हुई है। मैं जानता हूं कि टैक्स लगा कर रुपया इकट्ठा करने का तरीका इस सरकार ने अपनाया है, मगर ऐसा यह अपनी फजूल खर्चियों को बन्द कर के कर सकती थी। मैं कहता हूं 45 प्रति शत लोग हैं जो कुरबानियां करके आगे आये हैं। आप ने इतने मिनिस्टर्ज़ बढाए मगर काम करने वाले इन में चन्द एक हैं। बहुत से तो ऐसे हैं जो हमेशा अपना डिसक्रीशनरी फंड तकसीम करने पर ही लगे रहते हैं, और कोई उन को काम नहीं। आप देखें जो वोट कैयुल्टीज़ की लिस्ट छपी है इसमें लिखा है कांगड़ा जिला के 193 जवान शहीद हुए, 296 जख्मी हुए और 60 लापता हैं। मगर फिर भी फ्रंट पर यह खिदमत करते नज़र आते हैं। खर्च को बचत पर विचार नहीं करते। इस जगह के लिये उन्हीं लोगों को आगे लिया जाता है जिन्होंने पहले कुरबानियां दी हैं। इस लिये मैं कहूंगा कि यह टैक्स हम पर लगाने की बजाये वापस लिया जाये।

PERSONAL EXPLANATION BY THE HOME AND DEVELOPMENT MINISTER

गृह मन्त्री : On a point of personal explanation, Sir. जब मैं यहां पर हाज़र नहीं था तो यह कहा गया कि मैं ने कुछ अल्फाज़ सिख लाईट इनफैंटरी के मुताल्लिक कहे हैं। डिफैंस के मुताल्लिक जो मेरी स्पीचिज़ हुई हैं, मैं ने उन सब को एक एक कर के देखा है, मैं ने यह अल्फाज़ कहे थे, "हमारी उस फौज ने जिस में यह भी शामिल है, सभी ने बड़ी बहादरी से लड़ाई लड़ी है और कोई भी किसी से पीछे नहीं रहा।" बस जी यही मैं अर्ज़ करना चाहता था।

कुंवर राम पाल सिंह : On a point of order, Sir. क्या कोई भाई माईक पर काला बिल्ला लगा कर अपने सामने रख सकता है ?

श्री सभापति : आप यह काला बिला उठा लें (The hon. Member should remove this black badge.)

ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ : ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।

ਸ੍ਰੀ ਸਭਾਪਤੀ : ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ ਤੋਂ ਉਠਾ ਲਉ ਜੀ। (The hon. Member should remove it from the mike.)

(ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿੱਲਾ ਮਾਈਕ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ)

THE PUNJAB COMMERCIAL CROPS CESS, (AMENDMENT), BILL, 1965

(Resumption of Discussion.)

ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ (ਲੁਧਿਆਣਾ, ਦੱਖਣ): ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਸਕੀਮਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਮਿਆਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਕੀਮਾਂ ਚਾਲੂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਅਵਾਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਵੈਸੀ ਦੀ ਵੈਸੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਥੇ ਲਾਵੇ ਜਿਥੇ ਕਿ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਦੀ ਕਦਰ ਇਤਨੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਅਜ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਝ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਸਰਦਾਰ ਉਜਲ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ. ਅਜੇ ਤਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। (ਇਕ ਮਾਨ ਯੋਗ ਮੈਂਬਰ:—ਨਾ ਹੋਣੇ ਹੀ ਹਨ) ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਦੀ ਗਿਆਤ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਉਜਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਦਫਾ ਗਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਗੰਦਮ 53 ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸੇ ਪਰ ਕੁਇੰਟਲ ਘਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਗੰਦਮ ਦੜਾ 48 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਫੀ ਕੁਵਿੰਟਲ ਦੇ ਭਾਓ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਉਤੇ ਇਹ ਸੈਸ ਲਾ ਦੇਣੀ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ? ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਨਾਂ ਪੁਛਣ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਡ ਫਾਰਮਾਂ ਵੇਖ ਲੈਣ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਅੰਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਤਆਲੁਕ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦਿਨ ਬਦਿਨ ਅਗੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਓ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਚਿਆਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁਟਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਪੜਾ ਵੀ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਪੂਰੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੀਣ ਨੂੰ ਦੁਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘਿਓ ਕਿਥੋਂ ਖਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਚੁਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

(Deputy Speaker in the Chair.)

ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਨਾ ਪਾਓ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸਹਾਰ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਮਦਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਘਟ ਤੋਂ ਘਟ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਜੋ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਓ ਕੁਝ ਉਚਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਹਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ ਵਧੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁਲੇਖੇ ਤੋਂ ਸਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅੰਨ੍ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਹਾਲਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਐਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਸ ਦਾ 40 ਫੀ ਸਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਓ। ਸਾਡੇ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਕ ਗੱਲ ਨਿਹਾਇਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹੀ ਹੈ "ਯੇਹ ਜੋ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਲੋਗ ਹੈਂ ਉਨ ਸੇ ਭੀ ਚੰਦਾ ਵਗੈਰਾ ਹਮ ਲੇਤੇ ਹੈਂ, ਉਨ ਕਾ ਭੀ ਮੂੰਹ ਰਖਨਾ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇ ਸਵਾਏ ਹਮੇਂ ਔਰ ਕੋਈ ਰਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਰਟ ਕਟ ਹੋ"......

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ? (Let the hon. Member proceed with his arguments, he needs not criticise the Central Minister.)

ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ, ਬੀਬੀ ਜੀ, ਕਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਉਸ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਜੇ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਲੈਕ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਇਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਲੈਕ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਹੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁਛੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤਨੇ ਕਿਤਨੇ ਵਿਚ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੈ, ਉਹ ਬਲੈਕ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਕਨਾਈਜ਼ਡ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਉੜਾ ਦਿਤੀ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਐਨੀਆਂ ਸਖ਼ਤੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਜੋ ਹੁਣ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੈਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਕਾਬਲੇ ਅਫਸੋਸ ਗਲ ਹੈ। ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਥੋਂ ਰੁਪਿਆ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਝਾ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਅਜ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ।ਜਦੋਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੁਕਸ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਭੀ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਹੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ : ਸਭ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ : ਠੀਕ ਹੈ ਸਭ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਸ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਨੀਆਂ ਗਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਗੇ ਲਈ ਲਾਉਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਹਾਇਤ ਸਖ਼ਤੀ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ (ਨਾਭਾ): ਡਿਪਟੀ ਸਨਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਦੋ ਢਾਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਕੁਛ ਮਤ ਭੇਦ ਕਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਅਤੇ ਨੌਨ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤਬਕੇ ਵਿਚ, ਕਿਸਾਨ, ਰੂਰਲ ਅਤੇ ਅਰਬਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਸਚੇ ਦਿਲੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਰਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਧਣਾ ਫੁਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ—ਰੂਰਲ ਅਤੇ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੀ ਤਰਕੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਸ਼ੰਕਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਦਿਲ ਵਿਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡੀ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰੇਜ਼ਰੀ ਬੈਂਚਿਜ਼ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੋ ਹੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਅਗੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਬਿਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲ ਛੇ ਸਤ ਦਿਨ ਡਿਸਕਸ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗਿਲੋਟੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਰਾਪ ਸੈਸ ਬਿਲ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜ ਸਦਨ ਉਠਣ

ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੇ ਸਾਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀ-ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰੈਸਟ ਨੂੰ ਨਾ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਇਹ ਜੋ ਟਰੇਜ਼ਰੀ ਬੈਂਚਜ਼ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਕਲ ਇਸ ਸਦਨ ਵਿਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਕੰਵਰ ਰਾਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਾਰਿਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਟ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ 'ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਤਾਰੀਖ, 31 ਅਕਤੂਬਰ, 1965 ਵਿਚ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਚ ਅਗਰ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਅਜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਸਾਲ ਵਿਚ ਫਾਰੈਸਟ ਲਈ 58.14 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸਾਇਲ ਕਨਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 65 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 1 ਕਰੋੜ 97 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੈਬਨਟ ਦਾ ਡਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਾਰੈਸਟ ਵਲਥ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਐਕਸਪਲਾਇਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਥਾਪਰ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ਿਅਸ ਸਰਕਲ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਗਲ ਕਟਣੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੰਗਲ ਲਾਉਣੇ ਹਨ। ਫਾਰੈਸਟ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਕਿਥੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਾਰੈਸਟ ਦੀ ਐਕਸਪਲਾਇਟੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ? ਕਿਥੇ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ? ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਇਸ ਕਮਰਸ਼ਲ ਕਰਾਪਸ ਸੈਸ ਦਾ ਤਅਲੁਕ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੋਗਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਬੋਲੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ 14 ਜਾਂ 15 ਟੈਕਸ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਹਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸੇ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚਲ ਸਕੀਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪੇਇੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਬਕਾ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਚਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਮਦੇਨਜ਼ਰ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਦੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਪਲੈਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਈਅਰ ਵਿਚ ਅਸੀਂ 1 ਕਰੋੜ 73 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਸਾਂ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਸ਼ਲ ਕਰਾਪ ਸੈਸ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਗਰਕੇਨ ਅਸੀਂ ਪਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਅਸੀਂ ਪਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਇਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਅਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋਲ ਇਕ ਕੈਸ਼ ਕਰਾਪ ਕਾਟਨ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਾਰਿਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਅਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੈਸ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਾਰਿਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਿਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਅਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹਨ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ

[ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ]

ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਇਕੋ ਹੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। 1963-64 ਵਿਚ ਕਾਟਨ ਹੇਠ ਏਰੀਆ ਟੋਟਲ 1,731,868 ਏਕੜ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ 1,634,748 ਏਕੜ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 87 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਏਰੀਆ ਕਾਟਨ ਹੇਠੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਈਫੈਕਟ ਕਾਟਨ ਦੀ ਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਫਾਰਿਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੀ ਅਰਨਿੰਗ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਚਿੱਲੀਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਕਿਰਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤਬਕੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਢਾਈ ਸਾਲ ਹੋਏ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਬੁਜ਼ਦਿਲੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤਬਕੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ 3 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਫਰਾਖਦਿਲੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਫਰਾਖਦਿਲੀ ਦਿਖਾਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਪੈਸਟੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਮ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅਤੇ ਫਾਰਿਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਟੈਕਸ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਕ ਐਸੇ ਵੇਲੇ ਜਦ ਕਿ ਹਾਲੇ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਸਦਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਮਾਰਚ, 1966 ਤਕ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਖਾਸ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਦਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕੋ ਹੀ ਤਗਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਆਦ ਅਜੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਫੇਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਅਸੀਂ ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਮੌਕਾ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜੰਗ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਾਰਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਜਾਰੀ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਬਿਲ ਲਿਆ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਖਦਸ਼ਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਆਵੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਆਬਿਆਨਾ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਏਥੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਜੋ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਸ ਵਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠਾਂ ਪੰਜ ਲਖ ਏਕੜ ਟੈਕਸੇਬਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਫੀਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਗੁੜਗਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਥੋੜਾ ਰਕਬਾ ਟੈਕਸੇਬਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਟਨ ਦਾ ਟੈਕਸੇਬਲ ਏਰੀਆ 5 ਲਖ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾਨਟੈਕਸੇਬਲ ਏਰੀਆ 3 ਲਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਸਤ ਲਖ ਏਕੜ ਪਿਛੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ

ਐਵੇਂ ਬਦਨਾਮੀ ਖੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇਹ ਸਜੈਸ਼ਨ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪੰਜ ਚਾਰ ਮਿਨਟ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਗਲ ਨਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ਕ ਜਾਉ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਵਾਂਗੀ। (The hon. Minister for Revenue may go out, I shall call him.)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਬਿਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਡਿਸਕਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਗਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਦੇਹਾਤੀ ਦਾ ਭੇਦ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। (He should not differentiate between ruralites and urbanites)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ । Certainly you are doing it.

Deputy Speaker : Please resume your seat.

Sardar Gurcharan Singh : Certainly you are doing.

Deputy Speaker : The hon. member is very wise and sensible. He should behave properly.

श्री मोहन लाल (बटाला) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं उन ख्यालात को जो मैम्बर साहिबान ने मुझ से पहले हाउस के सामने रखे हैं दोहराऊंगा नहीं। जैसा कि आप जानते हैं हाउस के सब मैम्बर साहिबान का और लोगों का भी यह ख्याल है, सही तौर पर कि कि आज इस जंग की वजह से किसान ने काफी सफर किया है और उस के साथ ही साथ जो खुशकसाली रही है उस की वजह से भी। खास तौर पर तीन ज़िलों में जो कि सीधे जंग की लपेट में आए हैं हर एक किसान ने बहुत ज्यादा सफर किया है। इस लिये सरकार का ध्यान हाउस के हर सैक्शन की तरफ से उस तरफ खींचा गया था कि वह मुनासिब मौका नहीं टैक्सिज़ का बोझ डालने का। खैर सरकार ने उस बात को मानना मुनासिब नहीं समझा। सरदार गुरदर्शन सिंह जी सरकार का ध्यान एक अशोरेंस की तरफ दिला रहे थे जो कि 1963 में जब यह बिल पेश हुआ इस सदन में, उस वक्त के रैवेन्यु मिनिस्टर सरदार अजमेर सिंह ने दी थी। उन की रिपोर्टिड स्पीच इस वक्त पर मेरे पास है। उन्होंने वाज़ा तौर पर यह कहा था कि यह टैक्स सिर्फ थर्ड फाइव इयर प्लैन के साल 1965-66

[श्री मोहन लाल]
तक होगा। वह यकीनदहानी यहां पर कराई गई थी। मगर आज सरकार ने मुनासिब समझा है कि उस के बावजूद फोर्थ फाइव इयर प्लैन के पांच सालों के लिये इस एक्ट को फिर लागू करें। जहां तक पिछली सरकार की यकीनदहानी का ताल्लुक है उस के कितने माने समझ रही है हमारी मौजूदा सरकार इस के मुताल्लिक तो मैं कहना मुनासिब नहीं समझता हालांकि पिछले बिल में इन्होंने पिछली सरकार के बनाए हुए बिल का सहारा लिया था और इन्होंने कहा था कि यह सेल्ज टैक्स बिल तो पिछली सरकार बना गई थी इस लिए हम इस बिल को पेश कर रहे हैं, परन्तु इस ऐक्ट के मुताल्लिक जो यकीनदहानी दिलाई गई थी, उस वक्त की सरकार की तरफ से कि केवल तीन साल के लिये यह एक्ट लागू रहेगा, अब उन के ध्यान में वह बात नहीं। खैर वह बात तो अलहदा रही। मैं अब जिस बात की तरफ सरकार का ध्यान खासतौर पर दिलाना चाहता हूं वह न उस वक्त की सरकार ने जो अशोरेंस दी थी वह है और न उस वक्त जो नुक्ताचीनी हुई थी वह है और न ही उस वक्त के मैम्बर साहिबान की फीलिंग्ज के मुताल्लिक है। लेकिन आज की सरकार के जो कर्णधार हैं उन की उस वक्त क्या फीलिंग्ज थीं, उन्होंने उस वक्त क्या कहा था मैं अपनी सरकार का ध्यान उस तरफ दिलाना चाहता हूं। यह हमारे आज के चीफ मिनिस्टर साहिब, उस वक्त के कामरेड राम किशन जी एम० एल० ए० की 13 मार्च, 1963 की स्पीच है। उस वक्त जब जैनरल डिस्कशन आन दी बजट हो रही थी तो इस टैक्स पर बोलते हुए उन्होंने यह अल्फाज कहे थे जो यहां पर मैं कोट कर रहा हूं उन की जो रिपोर्टिड स्पीच है वह इस तरह है।

"जो टैक्स एक्स्टरा लैंड रैवेन्यु की शक्ल में शूगरकेन, काटन और चिल्लीज़ पर लगाया जा रहा है उस का नया असर लोगों पर पड़ने वाला है। एक तरफ तो हम कहते हैं सारे हिन्दुस्तान के नेता लोग कहते हैं कि प्राइसिज़ नहीं बढ़ने देनी चाहिएं और जो प्रोडक्शन है उसे ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहिए, दूसरी तरफ हम यह टैक्स लगा कर एक तो कीमतें बढ़ा रहे हैं क्योंकि इस टैक्स से इन चीज़ों की कीमतें तो लाज़मी तौर पर बढ़ेंगी, दूसरी इस से प्रोडक्शन बढ़ने की बजाए कम हो जाएगी क्योंकि किसान का, ज़मींदार का, इन चीज़ों को काश्त करने का जो पहले इनसैंटिव था वह खत्म हो जाएगा।"

तब कामरेड राम किशन जी ने उस बिल की मुखालिफत में दो रीज़न्ज़ दिये थे एक यह कि इस से चीज़ों की कीमतें बढ़ेंगी दूसरे यह कि किसान का इन चीज़ों को पैदा करने का इनसैंटिव खत्म हो जाएगा। आगे उन्होंने इस की तफसील में कहा--

"इस सिलसिले में आप चीन की मिसाल देखें। मौजूदा चीन की जो सरकार बनी है इस से पहले वहां मार्शल च्यांग काई शेक की सरकार थी। मार्शल च्यांग काई शेक एक बड़े अच्छे ऐडमिनिस्ट्रेटर भी थे और आला दर्जे के आप जनरल भी थे और उन के पास बड़े अच्छे आर्मज़ भी थे और फौजें भी बड़ी अच्छी थीं लेकिन वह कमियोनिस्ट फौजों से हार गए और उस का कारण यह था कि वहां चीज़ों की कीमतें इन्फलेशन की वजह से बहुत बढ़ गई जिस की वजह से उस के फौजी कम्युनिस्टों के पास अपने आर्मज़ बेच आते थे और आप उधर चले जाते थे।"

इस लिये यह बहुत जरूरी चीज है कि हम पंजाब के अन्दर आम जरूरत की कमोडिटीज़ की प्राईसिज़ को कायम रखें और प्राइसिज़ बढ़ने न दें और अगर इन कमोडिटीज़ की प्राइसिज़ को कायम रखना है तो इन को हमें प्राडक्शन बढ़ानी होगी और प्राडक्शन बढ़ाने के लिये हमें जमींदारों को इन्सैंटिव देना होगा। यह तो एक जगह पर उन की स्पीच है। उस के बाद कहते हैं।

उपाध्यक्षा : पंडित जी अगर आप कामरेड जी की स्पीचें पढ़ कर सुनाएंगे तो सारा दिन इस में ही खत्म हो जाएगा। आप अपनी बात ही कहें जो कहनी है। (It will take the whole day, if the hon. Member were to quote the Chief Minister. He should confine himself to the matter he wants to raise.)

श्री मोहन लाल : मैं, डिप्टी स्पीकर साहिबा, बहुत थोड़ा वक्त लूंगा और मैं तो सिर्फ उन को याद दिहानी करा रहा हूं कि लोगों की आवाज़ की उस वक्त वह कितनी कदर करते थे और इस बारे में उन को अपनी राए क्या थी। पिछली सरकार की एशोरेंस न सही लेकिन शायद उन पर अपने ख्यालात का ही ज़रूरी असर पड़े। इस के बाद 17 मार्च की उन की यह स्पीच है जिस में उन्होंने कहा था :—

> "कहने का मतलब है कि हमें टैक्सेशन को ओवर आल पिक्चर को रीव्यू करना होगा। मैं डिटेल्ज़ में नहीं जाना चाहता लेकिन जहां तक हाई टैक्सेशन का सम्बन्ध है इस ने कभी किसी कन्टरी को पे नहीं किया क्योंकि इस से इन्वैस्टमैंट के अन्दर कमी हो जाती है और सेविंग के अन्दर कमी हो जाती है। जिस प्रकार के राज्य की हम स्थापना करना चाहते हैं और जो सामाजिक ढांचा हम कायम करने जा रहे हैं उस की राह में यह रोड़े अटकाता है–संसार के सभी देशों ने इस फंडेमैंटल असूल को माना है कि टैक्सेशन के अन्दर कमी की जानी चाहिए ताकि ज्यादा रुपया इन्वैस्ट हो।"

तो मैं उन को उन के पुराने विचार ही याद करा रहा हूं ताकि उन की अलाइट में वह इस बिल को देखें। आगे फिर उन्होंने कहा —

> "जब आप एक सोशलिस्ट स्टेट बनाने जा रहे हैं तो यह जरूरी है कि गरीब आदमियों को टैक्सों में रीलीफ दिया जाए और जो बड़े २ आदमी हैं और जो टैक्सों का जितना बोझ और बरदाश्त कर सकते हैं उन पर उतना बोझ डाला जाए।"

अब इस बिल को भी हमें देखना होगा कि यह प्रिंसीपल इस पर जो उन्होंने उस वक्त रखा था कितना लागू होता है। इस कमर्शियल क्राप्स सैस बिल, 1963 पर जब बहस हो रही थी तो उस वक्त कामरेड जी ने जो तकरीर की थी उस के ऐक्सपर्ट्स मैं आप को सुनाता हूं ताकि उन को याद दिहानी हो जाए कि . . , . .

उपाध्यक्षा : कामरेड जी को सब कुछ अच्छी तरह याद होगा। आप अपनी तरफ से जो कुछ कहना चाहते हैं, कहें। (The Chief Minister must be remembering all that quite well. The hon. Member should advance his arguments.)

Chief Minister : Madam, Deputy Speaker, I stand for every word of the speeches which I made on the Floor of this House.

श्री फतेह चन्द विज : ग्रान ए प्वायंट ग्राफ ग्रार्डर, मैडम। यह बिल जो सदन में डिस्कस हो रहा है अगर वाकई काला बिल है जैसा कि कांग्रेसी मैम्बर काले बैज लगा कर ग्राए हैं ग्रौर मुख्य मंत्री जी भी काला कोट पहन कर ग्राए हैं तो फिर वापस ले लिया जाए।

उपाध्यक्षा : ग्रापने काला बिल्ला नहीं लगाया इसी लिये वापस नहीं हो रहा है। (This is not being withdrawn because the hon. Member is not displaying a black badge.)

श्री फतेह चन्द विज : मैं भी लगा लेता हूं। फिर तो वापस लें।

श्री मोहन लाल : डिप्टी स्पीकर साहिबा, बड़ी खुशी की बात है कि चीफ मिनिस्टर साहिब ने इस वक्त कहा कि जो स्पीच उन्होंने उस वक्त की थी उस के एक-एक लफ्ज के वह ग्राज भी पाबन्द है। इस लिये मैं ग्रब ग्रौर भी ज़रूरी समझता हूं कि इस बिल पर जो उन की स्पीच थी उस के कुछ ऐक्सपर्टस उन को ग्रौर इस सदन को बता दूं ताकि उन्होंने जो कुछ उस वक्त कहा था उस की लाइट में वह इस बिल के बारे में सोचें। यह स्पीच उन्होंने 28 मार्च, 1963 को की थी ग्रौर इस में उन्होंने कहा है--

> "लेकिन इस के साथ साथ जिन सोर्सिज को हम ने टैप करना है उन को सैटिस-फाई करना भी ज़रूरी है--इस लिये पंजाब में शूगर की प्राडक्शन बढ़ाने के लिये ज़रूरी है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा गन्ना पैदा करने के लिये इंसैंटिव दिया जाए---मैं जानता हूं कि ग्राप को साधनों की ज़रूरत है लेकिन शूगर केन ग्रौर काटन की जो ग्रनइकनामिक होलडिंग्ज हैं उन के लिये ग्राप को ज़रूर छूट देनी चाहिए ग्रौर इस के साथ ही जो ग्रार्मड फोर्सिज़ के काम करते हैं उन को भी एग्ज़ैंप्शन देनी चाहिये।....हमारी जितनी नैशनल इन्कम होती है उस में तो 47 प्रतिशत किसानों की जेबों में से ग्राती है। मैं गुज़ारिश करूंगा कि किसानों को कोई न कोई इन्सैंटिव दिया जाना चाहिए ग्रौर जो ग्रनइकनामिक होल्डिंग्ज़ के मालिक हैं उन को छूट देनी चाहिए। जहां तक मिर्चों पर सैस लगाने के ताल्लुक है मैं सजैस्ट करूंगा कि जो हिल्ली एरियाज हैं वहां पर कम से कम दो कनाल तक जो मिर्चों की काश्त करे उसे छूट देनी चाहिए--लेकिन यह देखना ज़रूरी हो जाता है कि जिन लोगों से टैक्स लिया जाए उन को सैटिसफाई भी किया जाए जो इकानामिक होलडिंग्ज वाले किसान हैं उन से ग्राप बेशक सैस लें लेकिन जो ग्रनइकनामिक होलडिंग्ज वाले हैं उन को ग्राप को छूट देनी चाहिए।"

तो इस में इन्होंने दो बातें कहीं ग्रौर बड़ी खुशी की बात है कि ग्राज भी वह उन बातों पर पूरी तरह से पाबन्द हैं। एक तो उन्होंने यह कहा कि जितनी ग्रनइकनामिक होलडिंग्ज हैं उन को छूट देनी चाहिए ग्रौर दूसरे जहां तक मिर्चों का सम्बन्ध है हिल्ली एरियाज में दो कनाल तक जो बीजें उन को छूट देनी चाहिए। ग्रब वह खुद भी कहते हैं कि उन्होंने

जो कुछ उस वक्त कहा था उस के लिए एक एक लफ ज पर वह इस वक्त भी पूरी तरह से पाबन्द हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो कुछ उन्होंने उस वक्त कहा था जिस पर वह पाबन्द हैं उस की लाइट में वह इस बिल पर अपने द्वारा विचार बनाएंगे। डिप्टी स्पीकर साहिबा, इन्होंने 28 मार्च 1963 को इस बिल के बारे में स्पीच की थी।

उपाध्यक्षा : आप सीनियर मैम्बर हैं। आप को पता ही है और मुझे खुशी है कि आज आनरेबल मैम्बरों ने इस बिल के बारे में 10, 12 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं लिया। इस लिये आप वाइंड अप करें। (The hon. Member is a Senior Member. He knows it and I am happy that no Member took more than 10-12 minutes today while speaking on this Bill. He may now wind up.)

बाबू बचन सिंह : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडम। क्या किसी आनरेबल मैम्बर को किसी भी पुरानी स्पीच जो इस बिल से सम्बन्ध रखती हो, उस को हाउस में कोट करने की इजाजत नहीं है ? अगर है तो उसे वह लाइन्ज़ कोट करने की इजाज़त होनी चाहिए ताकि वह बातें इनकम्पलीट न रह जाएं।

उपाध्यक्ष : अगर कामरेड राम किशन की स्पीचों को यहां पर कोट करने की इजाजत हो जाए तो उस के लिये 3 या 4 दिन चाहिएं। इस लिये पंडित मोहन लाल अब वाइंड अप करें। (If the quoting of the Chief Minister's previous speeches were permitted it will need 3-4 days. The hon. Member may, therefore, now wind up.)

श्री मोहन लाल : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं 5 मिनट में ही अपनी स्पीच खत्म कर दूंगा। चीफ मिनिस्टर साहिब ने 28 मार्च 1963 को इस के बारे में स्पीच की थी। टाइम की कमी के कारण उन की स्पीच का कुछ ही हवाला देना चाहता हूं। वह यह है कि--

> "किसी काम को वैलप्लैंड ढंग से चलाने के लिए पहले लोगों से अपील करके उन की नुक्ता-नजर को सही ढंग पर लाना होता है। फिर इस के बाद उन को इस बात पर रजामन्द करना होता है कि आया वह प्लैनिंग के मुताबिक सरकार की तरफ से जो बोझा डाला जाए उस को सही मायनों में उठाने को तैयार भी हैं।"

मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इन्होंने उस वक्त फरमाया था कि आया लोग इस बोझ को उठाने के लिये तैयार भी हैं या नहीं। इस लिये अब वह खुद महसूस करें कि लोग इस टैक्स को पे करने के लिये कितने रज़ामन्द हैं। क्या वह लोगों को यह टैक्स पे कराने में रज़ामन्द करा सके हैं या नहीं। इस बिल के बारे में हाऊस के माननीय सदस्यों की जो फीलिंग्ज़ हैं उन को सामने रखते हुए वह खुद अन्दाजा लगा सकते हैं कि यह टैक्स लगाना किस हद तक जस्टीफाइड हो सकता है।

[श्री मोहन लाल]

वैसे तो समय ही बहुत कम है लेकिन मैं इस वक्त ज्यादा डिटेल्ज में जाना भी नहीं चाहता हूं। इस बिल के मुताल्लिक चौधरी रिजक राम ने भी उस समय स्पीच की थी। उनकी भी दो तीन लाइनें हाउस में कोट करना मुनासिब समझता हूं। मैं समझता हूं कि आप मुनासिब समझेंगी और उन को कोट करने की इजाज़त भी दे देंगी। उन्होंने 27 मार्च 1963 को स्पीच की थी। उन्होंने कहा था कि :—

"मैं समझता हूं कि किसान पर पिछले आठ दस सालों में जो टैक्स लगाए गए उन के होते हुए यह डायरैक्ट सैस बहुत मुनासिब नहीं है। पहले ही काफी टैक्स 1952, 1954, 1956, 1958 और 1960 में सरचार्ज, ऐडीशनल सरचार्ज और बैटरमेंट लैवी की शक्ल में किसानों पर लगाए जा चुके हैं। किसान आज यह महसूस करता है कि उस पर टैक्सों का बोझ बहुत ज्यादा है, अगर सारे टैक्स का हिसाब लगाया जाए जिस में मालगुज़ारी, सरचार्ज एडीशनल सरचार्ज बैटरमेंट फी, बैटरमैंट चार्जिज भी शामिल हों तो कोई तोज्जुब नहीं होगा कि चालीस रुपए फी एकड़ से भी ज्यादा टैक्स किसान को देने पड़ते हैं।"

मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि उन्होंने कैश क्रॉप्स में छूट देने के लिये कहा था। उस वक्त के हालात और आज के हालात को देखते हुए अन्दाजा लगाया जा सकता है कि अब हालात में कितना फर्क पड़ गया है।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, उस वक्त सरदार गुरदयाल सिंह ढिल्लों ने भी 28 मार्च 63 को स्पीच की थी। मैं उन की स्पीच की भी कुछ लाइन्ज़ हाउस में पढ़ना ज़रूरी समझता हूं। उस वक्त सरदार अजमेर सिंह माल मंत्री थे। सरदार गुरदयाल सिंह ढिल्लों ने माल मंत्री को कहा था कि...

"ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੈ"।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ—

" 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਫੀਚਰ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਫੀਚਰ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਫੀਚਰ ਸਿਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਸਟੇਟਿਸਟਿਕਸ ਲਉ, ਬੋਰਡ ਆਫ ਇਕਨਾਮਿਕ ਇਨਕੁਆਰੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉ"।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैंने उन की अपनी स्पीचें इस लिये कोट की हैं ताकि उन के अपनी कही हुई बातों का एहसास हो सके। इस लिये सरकार को चाहिए कि हाउस के मैम्बरों के जजबात का ख्याल रखे और इन साहिबान ने उस वक्त जो कुछ कहा था उस का भी बिल पास कराने समय ध्यान रखें (घंटी) । डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आप का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप ने मुझे अपने ख्यालात का इज़हार करने के लिये समय दिया।

ਕਾਮਰੇਡ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ (ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 85 ਫੀ ਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਉਤੇ ਭੈੜਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 85 ਫੀ ਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਘਟ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਿਲ-ਕੁਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਲੜਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹਰ ਪਾਸਿਉਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਲ ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਗਰਜ਼ ਕੋਟ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਹ ਫਿਗਰਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪੁਛਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 65 ਫੀ ਸਦੀ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, 20 ਫੀ ਸਦੀ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ 5—10 ਏਕੜ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। 12 ਫੀ ਸਦੀ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ 10—20 ਏਕੜ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਅਤੇ 3 ਫੀ ਸਦੀ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ 20 ਤੋਂ 30 ਏਕੜ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਿਗਰਜ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮੇਜਾਰਿਟੀ 5 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਂ-ਦਾਰ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਘਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ?

ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 14—15 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਲਾਮ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸਟੈਪਸ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਮਿਸਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉਥੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਇਕ ਟੈਕਸ ਲਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜ ਮਿਸਰ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ 15 ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਕ ਹੀ ਟੈਕਸ ਉਥੇ ਹੈ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਥੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇਕ ਹੀ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਬਰਮਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ। ਕੀ ਵਜਾਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ 14—15 ਟੈਕਸ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਟੇਢੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜ ਵੇਖਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਜੇ ਕਰ ਇਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗਲ ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਛੇ ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਲੜਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਅੰਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਛਿਲ ਭੇਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਛਿਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭੱਤੇ ਤੇ ਅਲਾਉਂਸ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਵੇਂ ਮਹਿਕਮੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 12 ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਟਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਰਲਾ ਖੋੜ੍ਹ ਟੱਪ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੋ ਗਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅਤੇ

[ਕਾਮਰੇਡ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ]

ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਚੂਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜੁਰਅਤ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ? ਇਸ ਲਈ ਹੋਈ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 15 ਫੀ ਸਦੀ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਐਨੀ ਘਬਰਾਈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮਰਲਾ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਛਿਲ ਲਾਹੋ। ਕਾਮਰੇਡ ਸਰਕਾਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਿਹੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ , ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਟੈਕਸ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਨਾ ਚੂੰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਚਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਘੁਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗੇ ਨੂੰ ਲੋਕੀਂ ਗੰਨਾ ਨਾ ਬੀਜਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੇਕਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 40 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਹਿਸ ਤੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਖੰਡ ਵਾਸਤੇ ਗੰਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੰਡ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਦਿਤੀ ਹੈ ਪਰ ਗੰਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਪਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਾਮਰੇਡ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲਵਾਉ, (Interruptions) ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ਰਾਏ ਢੂੰਡੋ, ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਨਵੇਂ ਬਿਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਿਲ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ : (ਫਤਿਹ ਗੜ੍ਹ) : ਇਹ ਬਿਲ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬੋਝ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਏ, ਉਹ ਮਹਾਜ਼ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਰਾ ਟਰੂਪਰਜ਼ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਡੀਫੈਂਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸਿਲਾ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਨਾਹਰਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੈ ਜਵਾਨ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਗਲ ਘੁਟ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ--

ਨਾ ਰੋਨੇ ਕੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਨਾ ਫਰਿਆਦ ਕੀ ਹੈ,
ਦਮ ਘੁਟ ਕੇ ਮਰ ਜਾਊਂ ਯਿਹ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਸੈਯਾਦ ਕੀ ਹੈ।

ਕਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਦੀ ਆਫਤ ਆਈ ਤਾਂ ਬਾਰਸ਼ ਹੋਈ ਨਾ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਨੇ ਫਸਲ ਮਾਰ ਲਈ, ਕਦੀ ਗੜੇ ਪੈ ਗਏ, ਕਦੀ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ , ਕਦੀ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਕਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਖਾਦ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਕਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਠੀਕ ਬੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ । ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਫਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਹਾਜ਼ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਫਾ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਫਾ ਦਿਤਾ , ਅਜ ਦਿਹਾਤੀਆਂ ਉਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਰ

ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੰਨੇ, ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਇਦਾਰ ਬਿਰਲੇ ਅਤੇ ਟਾਟੇ ਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ 2,3 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਕੂਮਤ ਉਸ ਦੀ ਪਿਠ ਠੋਕੇ, ਸੈਂਟਰ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਖਾਦ ਦਾ ਠੀਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਨ ਮੰਗਵਾਉਣ ਉਪਰ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਯੂ. ਪੀ. ਦੀਆਂ ਤਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਆਬਾਦ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਨਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੇਠੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਨੱਕ ਕਟਣ ਲਈ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇਵੇਗਾ ? ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰਜ਼ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਔਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ । ਖਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੰਨਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਿਲਾਂ ਤੇ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਖੰਡ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਾਰਿਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਗੰਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਖੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਕਦਰ ਕਿਉਂ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ? ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਪਣੀ ਜਗਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ।

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ: (ਪੱਟੀ) ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਹ ਬਿਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਪੁਰਾਣੀ ਗਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰੇਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਸਬੇ ਵਿਚ ਇਕ ਮੇਲਾ ਹੋਇਆ । ਉਥੇ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹਲਵਾਈ ਨੇ ਮਠਿਆਈ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ , ਕਪੜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਪੜੇ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ, ਦਰਜੀ ਨੇ ਸਵਾਈ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਯਾਨੀ ਹਰ ਇਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ। ਮੇਲੇ ਵਿਚ ਹੋ ਗਿਆ ਰਸ਼ ਔਰ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਗ ਲਾਹ ਲਈ। ਉਹ ਘਰ ਪੁਜਿਆ । ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਛਿਆ, "ਕਿਉਂ ਭਾਈ, ਮੇਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ?" ਉਹ ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪਗ ਲਵਾ ਆਏ ਹਾਂ।

ਤੁਸਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਥੇ ਕਿਧਰੇ ਤਾਂ ਬਿਉਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਕਿਧਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ, ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਨਸ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਅੰਗੂਰ ਖਾ ਖਵਾ ਕੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਂਗ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਗ ਲਵਾਉਣ ਗਏ ਸਾਂ ਪਗ ਲਵਾਕੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁਛਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ

[ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ]

ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਕਹਿ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਈ! ਟੈਕਸ ਲਗਵਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਜਿਥੇ ਅੱਗੇ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਦੇ ਸੋ ਹੁਣ ਵੀ ਮੰਨੀ ਚਲੋ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਕਤ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਿਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਹਰ-ਹਾਲ, ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆਂ ਹਾਂ ਉਥੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਬਟਾਲਾ ਮਿੱਲ ਵਾਸਤੇ ਗੰਨਾ ਬਿਜਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੜਾਈ ਛਿੜ ਗਈ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸਤ ਮੀਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਗੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਕਿਸਾਨ ਚੀਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਉਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੇਲਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ । ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਸ਼ਮਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਵੇਗਾ । ਉਹ ਵੇਲਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੰਨੇ ਔਰ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਕਰਾਪਸ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਮਾਦ ਔਰ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਤਨੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਇਕ ਗੱਲ ਦਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਉਤੇ ਇਕ ਭੂਰਾ ਕਰੀਮ ਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਨ ਦੇ ਉਥੇ ਟੈਂਕ ਆਏ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਜਦ ਕਮਾਦ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ਗਏ ਤਾਂ ਉਥੋਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਕ ਪੈਟਨ ਟੈਂਕ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਖੇਤ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਧਰੂ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਔਰ ਫੌਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਰਾਪਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।

SEVENTH REPORT OF THE BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

उपाध्यक्षा : सरदार उमराओ सिंह जी, मैंने एक ज़रूरी एनाऊंसमेंट करनी है। वह मुझे पहिले कर लेने दीजिए और उस के बाद आप अपनी तकरीर जारी कर लेना।

बिज़नैस ऐडवाईजरी कमेटी आज साढ़े बारह बजे बैठी और उस ने यह फैसला किया कि कल बुद्धवार, 24 नवम्बर, 1965 को हाउस नौ बजे मिलेगा और नान-स्टाप चलेगा जब तक कि बिज़नैस खत्म न हो जाए। उस के बाद सिने डाई एड्जर्न होगा।

इस के अलावा आज जो स्टेटमैंट मिस्टर प्रबोध चन्द्र, शिक्षा मन्त्री ने किया था उसके बारे में गवर्नमैण्ट एक स्टेटमैंट करेगी और उस के बाद इस पर कोई डिस्कशन नहीं होगी। यह बिजनैस ऐडवाईज़री कमेटी की रिपोर्ट में आप के सामने रखती हूं। (I have to make an important announcement. Let me do so. The hon. Member may continue his speech thereafter.

The Business Advisory Committee met today at 12-30 p.m. and decided that the House would meet on Wednesday, the 24th November, 1965, at 9 a.m. and would rise only after finishing the business on the agenda. Thereafter, it will adjourn *Sine-die*.

Besides, the Government will make a statement pertaining to the one made by Mr. Prabodh Chandra,

today. This will not be discussed. I place this Report of the Business Advisory Committee before the House.)

Chief Parliamentary Secretary (Shri Ram Partap Garg) : Madam, I beg to move—

> That the recommendations contained in the Seventh Report of the Business Advisory Committee be adopted.

Deputy Speaker : Motion moved—

> That the recommendations contained in the Seventh Report of the Business Advisory Committee be adopted.

Deputy Speaker : Question is—

> That the recommendations contained in the Seventh Report of the Business Advisory Committee be adopted.

The motion was carried

THE PUNJAB COMMERCIAL CROPS CESS (AMENDMENT) BILL, 1965

(Resumption of Discussion)

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ (ਪੱਟੀ): ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਰਾਪਸ ਉਪਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਲਈ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਇਸ ਵਕਤ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਡਿਫੈਂਸ ਪਰਪਜ਼ਿਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਖਾਮਖਾਹ ਦੇ ਕ੍ਰਿਟੀਸਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਗਲ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਖਿਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 40—45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੀ ਆਮਦਨੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ 40—45 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕਰਾਸਿੰਗਜ਼ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 40—45 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਮਦ ਵਿਚੋਂ ਕਢਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਫਜ਼ੂਲ ਦੇ ਕ੍ਰਿਟੀਸਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Deputy Speaker: Please wind up.

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ: ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਕੋ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਉਤੇ 3 ਫੀ ਸਦੀ ਸੂਦ ਹੈ ਮਗਰ ਜਦ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 5 ਫੀ ਸਦੀ ਸੂਦ। ਉਹ ਵੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਸਰਟਿਫਿਕੇਟ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਗਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ।

पंडित मोहन लाल दत्त (अम्ब) : श्रीमती जी, आज देश एक महान संकट में से गुज़र रहा है और मौजूदा हालात में फरदोबशर को ज्यादा से ज्यादा कुरबानी करनी चाहिए। देश के बचाव के लिए और देश को हर हालत में स्वावलम्बी बनाने के लिये जो योजनाएं

[पंडित मोहन लाल दत]

हाथ में लेनी हैं उन को कामयाब बनाने के लिये बहुत ज्यादा धन की आवश्यकता है। ऐसी हालत में हमें हर एक मसले पर बड़ी गम्भीरता के साथ और बड़ी सन्जीदगी के साथ विचार करनी चाहिए। किसी को भी अपने किसी मखसूस मफाद के हित में कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिस से देश को नुक्सान पहुंचे। जहां पर इस कदर भारी रुपए की जरूरत है वहां, उपाध्यक्षा महोदया, इस हाउस में मैंने एक खास किस्म का माहौल देखा है। जब व्यापारियों के ऊपर टैक्स लगाने का मौका आता है तो जो व्यापारियों के साथ हमदर्दी रखने वाले सदस्य हैं वह उस समय तो कहते हैं कि उन पर टैक्स लगने चाहिएं लेकिन जब जमींदारों पर....... The hon. Member was still in possession of the House when it adjourned.

उपाध्यक्षा : सदन कल नौ बजे मिलेगा।

(The House stands adjourned till 9.00 a.m. to-morrow.)

The Sabha then adjorned till 9. 00 a.m. on Wednesday, the 24th November, 1965.

2.30 p.m.

7286PVS—30-5-66—C., P. & S., Pb., Chd.

PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATES

24th November, 1965

Vol. II—No. 26

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Wednesday, the 24th November, 1965

Punjab Vidhan Sabha Secretariat, Chandigarh

Price : [illegible]

P.T.O.

ERRATA

to

Punjab Vidhan Sabha Debates, Vol. II, No. 26, dated the 24th, November, 1965.

Read	*For*	*Page*	*Line*
ਬਜਟ	ਬਜ	(26) 6	9
ਪੰਚਾਇਤ ਰੁਪਿਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦੇਵੇ	ਪੰਚਾਇਤ ਰੁਪਿਆ ਜਮਾਂ ਕਰ ਦੇਵੋ	(26) 12	8
ਦੂਸਰੇ	ਦਸਰੇ	(26) 17	13 from below
areas	ereas	(26) 17	6 from below
ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ	ਲੈਂਦਾ	(26) 20	10 from below
ਮਹਿਸੂਸ	ਮਹਿਸਸ	(26) 20	Last
Delete the words [Minister for Irrigation and Power]		(26) 21	5 from below
ਫੈਲੀ	ਫਲੀ	(26) 24	last but one
ਮੁਖ	ਮੁੱਖ	(26) 25	5
ਇਨ੍ਹਾਂ	ਇਨ	(26) 25	7
inflict	inlict	(26) 26	24
there	there ?	(26) 26	9 from below
quanungos	qanogos	(26) 28	last
221.	211.	(26) 31	37
Preliminary	Prelminary	(26) 32	7
मूव	भूव	(26) 33	43
attention	atieution	(26) 33	57

P.T.O.

Read	*For*	*Page*	*Line*
Control	Controle	(26) 33	61
transportation	transporation	(26) 33	62
Member	ember	(26) 34	8
Conflict	Conflicit	(26) 40	32
Chief	Chie	(26) 42	1
Silting-up	Siltin-up	(26) 46	49
Chief	Cbief	(26) 48	2
Privileges	Provileges	(26) 49	3
ਸੈਂਕਟਿਟੀ	ਸੈਕੱਟਿਰੀ	(26) 52	5
been	baen	(26) 55	25
ਸ਼੍ਰੀ	ੀ	(26) 56	20
desirable	deriable	(26) 58	29
afterwards	afterwords	(26) 58	32
holding	hoiding	(26) 61	13
dictated	dic ated	(26) 62	7
समापति	समापति	(26) 63	13
ਕਰਨ	ਕਰਨਾ	(26) 65	9
ਹੋਈਆਂ	ਹੋਇਆ	(26) 67	25
its	it	(26) 67	last
permanent	prrmanent	(26) 67	last
कोटा	ोटा	(26) 70	10
Principal	Prtncipal	(26) 73	9 from below
Deputy	Depnty	(26) 75	3
in	jn	(26) 75	9
Cess	eess	(26) 75	25
Opposition	opposirion	(26) 87	4 from below
ਬਲਕਿ	ਬਲਾਕ	(26) 92	3
ਮਨਜ਼ੂਰ	ਮਨਜ਼ੂ	(26) 99	8
ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ	ਚੇਅਮਨ ਸਾਹਿਬਾ	(26) 105	7
EXPLANATION	EXPANATION	(26) 111	1

Read	*for*	*Page*	*Line*
ਟੱਟਨੇ	ਟਟਨੇ	(26) 117	20
ਕੈਪੈਸਿਟੀ	ਕੈਪੈਸਿੀ	(26) 118	13
ਮਾਲ ਮੰਤ੍ਰੀ	ਮਾਲ ਮਤ੍ਰੀ	(26) 128	1
public	pnblic	(26) 131	23
ਪਿੰਡ	ਪਿਡ	(26) 139	8 from below
ਬੈਠੇ	ੈਠੇ	(26) 141	27
ਕੋਲੋਂ	ਕੋਲਂ	(26) 148	6
ਫੇਰ	ਫਰ	(26) 148	7
ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ	ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ	(26) 155	9 from below
ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ	ਮਾਲ ਮਤਰੀ	(26) 167	10 ,, ,,
enforcement	enforsement	(26) 169	8 ,, ,,
ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼	ਡਾਰਟਰ ਬਲਦੇਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼	(26) 174	6 ,, ,,
Crops cess	Crops	(26) 182	10
Jasdev Singh Sandhu	Jagdev Singh Sandhu	(26) 186	29
Teja Singh, Sardar	Tej Singh, Sardar	(26) 187	21
Delete the word Rs.		App. (i)	5 from below
sustaining	substaining	App. (ii)	3 ,, ,,
of	ef	App. (ii)	Last
head	headt	App. V	12
areas	a eas	App. VII	5
concurrence	concurrene	App. VII	29
Elections	election	App.	5
Ditto	Ditio	App. XVI	last
Scheme	Schemes	App. XiX	16
in	n	App. XX	13

P.T.O.

Read	*For*	*Page*	*Line*
Legislation	egislation	App. XX	14
disclosure	desclosure	App XXI	25
tax up	tax is up	App. XXIII	10 from below
hauled	haulled	App. XXIV	13
fictitious	frctitiously	App. XXIV	31
Prem Chand Bhardwaj	Prem Chahd Bhardwaj	App. XXV	27
Shrimati Om Prabha Jain	Shrimati Om Prakash Jain	1	10
inundated	inun-dated	3	13
hostilities	hostitilies	3	35
seized	sized	3	8 from below
employed	un-employed	5	10
Sober	Sobre	6	30

———

PUNJAB VIDHAN SABHA

Wednesday, the 24th November, 1965

The Sabha met in the Vidhan Bhavan, Sector 1, Chandigarh at 9.00 a.m. of the Clock. Deputy Speaker (Shrimati Shanno Devi) in the Chair.

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

VISITS BY MINISTERS TO SANGRUR DISTRICT

*8779. **Comrade Bhan Singh Bhaura** : Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) the names of the Ministers who visited Sangrur District in the month of September, 1965, alongwith the names of places where they addressed rallies;

(b) whether the legislators of the said district were informed, about the said tours etc.; if not, the reasons for the same?

Shri Ram Kishan : (a) The requisite information is laid on the Table of the House.

(b) Normally copies of tour programmes of Ministers are invariably forwarded to the Legislators of the districts concerned. However, due to short notice, emergency and security reasons the Legislators were not informed of the tour programmes.

STATEMENT

Name ef the Minister	Dates	Places where Defence Rallies were addressed
(1) Comrade Ram Kishan	18-9-1965	.. Sunam
(2) Shri Darbara Singh	4-9-1965	.. Sangrur
(3) Shri Ajmer Singh	11-9-1965	.. Mehal Kalan Barnala, Sangrur, Bhawanigarh.
	17-9-1965	Sangrur Malerkotla, Sherpur.
	18-9-1965	Narwana Uchana and Jind.

मुख्य मन्त्री : यह जो स्टेटमेंट ले की है इसमें संगरूर भी था लेकिन वह शायद गलती से आया नहीं ।

ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ : ਕੀ ਚੀਫ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੂਰ ਪਰੋਗਰਾਮ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਪਾਸ ਭੇਜ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਬੀ. ਡੀ. ਓਜ਼. ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਵੀ ਇਨਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਪਬਲਿਕ ਰੈਲੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ?

मुख्य मन्त्री : आम तौर पर मिनिस्टर्ज़ के टूर प्रोग्राम्ज़ की कापीज़ तमाम एम० एल० एज़० को भेजी जाती हैं । इस केस में शायद जल्दी करके नहीं जा सकी होंगी । आगे के लिये मैं यकीन दिलाता हूँ कि यह गलती नहीं होगी और तमाम लैजिस्लेटर्ज़ को यह भेजे जायेंगे ।

डाक्टर बलदेव प्रकाश : इस सवाल के जवाब में कहा गया है कि सिक्योरिटी रीज़न्ज़ करके और एमरजेंसी करके मिनिस्टर्ज़ के प्रोग्राम्ज़ की पब्लिसिटी नहीं की गई थी तो मैं पूछना चाहता हूँ कि इसकी क्या वजह है कि जिन मीटिंग्ज़ को मिनिस्टर साहिबान उन दिनों एड्रेस करते रहे हैं उनकी पब्लिसिटी तो होती रही है और आपोज़ीशन के मेम्बर्ज़ को इस बारे में इत्तलाह नहीं भेजी जाती रही, तो क्या उनको एम०एल० एज़० से ही खतरा था और पब्लिक जलसों में जाने से और उन्हें एड्रेस करने में खतरा नहीं था ?

मुख्य मन्त्री : एम० एल० एज़० से क्या खतरा हो सकता है। यह बात नहीं है, यही हो सकता है कि जल्दी में कहीं किसी एम० एल० ए० को इत्तलाह न भेजी जा सकी हो क्योंकि एमरजेंसी की वजह से उन्हें कई बार बड़ी जल्दी में आना जाना पड़ा है । मैं जब संगरूर गया था तो वहां कई एम०एल० एज तो आए हुए थे लेकिन कई नहीं आए थे । तो हो सकता है कि जल्दी में किसी को इत्तलाह वक्त पर न पहुंच सकी हो । इसकी और कोई वजह नहीं है ।

श्री ओम् प्रकाश अग्निहोत्री : क्या चीफ मिनिस्टर साहब बतायेंगे कि क्या एमरजेंसी को मूख्य रखते हुए मिनिस्टर साहिबान कम टूर रखने के लिये तैयार हैं ?

मुख्य मन्त्री : एमरजेंसी में तो आप जानते हैं कि कई बार ज्यादा टूर करने ज़रूरी हो जाते हैं ।

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : ਚੀਫ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਰਕੇ ਸੀਕਿਉਰਿਟੀ ਮਈਅਰਜ਼ ਲੈਣੇ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਮ. ਐਲ. ਏਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਟੂਰ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਇਤਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਬੀ. ਡੀ. ਓਜ਼ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੂਰ ਪਰੋ-ਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਐਮ. ਐਲ. ਏਜ਼. ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ? ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀਂ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਚਾਰ ਪੰਜ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗਏ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਗਏ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਬਲਿਕ ਜਲਸੇ ਵੀ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤੇ ਪਰ ਐਮ. ਐਲ. ਏਜ਼. ਨੂੰ ਖਬਰ ਨਾ ਦਿੱਤੀ । ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ?

उपाध्यक्षा : उन्होंने बता तो दिया है कि इस में शायद गलती हुई है । (He has already said that this was an omission.)

श्री बलरामजी दास टण्डन : डिप्टी स्पीकर साहिबा, अगर तो वाकई गलती हुई है जैसा कि बताया गया है कि यह गलती हुई है, तब तो यह कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन इसमें जो यह बताया गया है कि सिक्योरिटी के रीज़न्ज़ की वजह से एम०एल०एज़० को इत्तलाह नहीं दी गई तो यह एक बड़ी अहम बात हो जाती है क्योंकि इस सवाल में सिर्फ एम० एल०एज़० के बारे में ही पूछा गया था । तो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या मिनिस्टर साहिबान को एम०एल०एज़० से ही खतरा था ?

मुख्य मन्त्री : नहीं, ऐसी बात नहीं है । सिक्योरिटी का एक रीज़न शायद हो लेकिन असल बात यह है कि कहीं किसी ज़िले में शायद किसी को इत्तलाह न दी जा सकी हो । मैंने पहले ही अर्ज़ किया है कि अगर कहीं यह गलती हो गई है तो आयंदा यह नहीं होगी । कहीं कोई और खास बात हुई है और किसी आनरेबल मैम्बर को मालूम है तो मेरे नोटिस में लाएं, तो मैं उसकी वजह मालूम कर लूंगा और आनरेबल मैम्बर को कनविंस कराने की कोशिश करूँगा और अगर वह कनविंस न हो सके तो मैं अपनी गलती मान लूंगा ।

Deputy Speaker : Next question please.

ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ : ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪਲੀਜ਼ ।

Deputy Speaker: No please, No more supplementaries on this question.

ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ : ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹੈ ।

Deputy Speaker : No please. Please take your seat.

ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ : ਇਹ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਸਵਾਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸੀ ।

उपाध्यक्षा : यह ठीक है कि आप का सवाल है लेकिन जब मैं दूसरे मैम्बर साहिबान को सप्लीमैंटरी पूछने की इजाजत देती रही हूँ तो आप एक बार भी खड़े नहीं हुए ।(There is no doubt that this question is in his name. But he has not even stood up in his seat to catch my eye, when I have been permitting other Members to put their supplementaries. Now I cannot allow him.)

ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ : ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ।

उपाध्यक्षा : अब मैं अगला सवाल बुला चुकी हूँ ? (I have already called the next question).

श्री बलरामजी दास टंण्डन: डिप्टी स्पीकर साहिबा, जितनी देर अब हो चुकी है इतनी देर में अगर आप इजाज़त दे देतीं तो दो तीन सप्लीमेंटरीज़ पूछे गए होते ।

Deputy Speaker : Order please.

ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਮੈਡਮ ।

उपाध्यक्षा : आप अपना प्वायंट आफ आर्डर रेज़ कर सकते हैं लकिन आपको सप्लीमेंटरी पूछने की इजाज़त नहीं दूंगी । (The hon. Member can raise his point of order but I would not permit him to put supplementaries.)

ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ : ਚੀਫ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਵਿਚ ਇਤਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੀ । ਪਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਮ. ਐਲ. ਏਜ਼ ਸੀ ਪਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਤਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਆਦਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ । ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ।

ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਮੰਤਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਿਨੂਏਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰਾਂਗਲੀ ਰਿਫਿਊਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਰੀਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਇਤਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ । ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਛੇਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਰੋਗਰਾਮ ਛਾਪੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ । ਸਿਰਫ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਦਿਉ ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਹੋਵੇ ਵਰਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਇਨਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਵਾਇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । I strongly resent what my hon. Friend has said.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਮੈਡਮ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੇਅਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਰੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪੁਟ ਕਰਨਾ ਹੈ you have purposely done it. ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਲਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਤੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ?

Deputy Speaker: Please withdraw your words. ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜੀ ਆਇਆ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ । (Please withdraw your words. You have developed the habit of casting aspersions on the Chair.)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਚੇਅਰ ਤੇ ਰੀਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਤੇ ਰੀਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਰੀਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। (Reflection on the Chair is reflection on the House as well as the hon. Member himself.)

CONSTRUCTION OF ROADS IN MAHENDERGARH district

***8740. Shri Banwari Lal** : Will the Minister for Public Works be pleased to state—

(a) the names of the roads in Mahendergarh district for the construction of which amounts have recently been placed at the disposal of the Government by the respective Panchayat Samities;

(b) whether the construction of all the said roads has since been completed; if not, the reasons therefor?

Chaudhri Ranbir Singh : (a) No amount has been placed at the disposal of the Government by the Panchayat Samities for construction of any road.

(b) in view of (a) above the question does not arise.

श्री बनवारी लाल : क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जिन रोड्ज़ पर पंचायतों और पंचायत समितियों ने खर्च कर रखा है क्या उनको सरकार बनायेगी अगर बनायेगी तो कितनी देर में कोशिश करेगी ?

लोक कार्य मन्त्री : उपाध्यक्षा महोदया, सवाल यह है कि क्या किसी पंचायत समिति ने पंजाब सरकार को सड़क बनाने के लिये पैसा दिया है। जो यह अब पूछना चाहते हैं इसके लिये अलग नोटिस दे दें।

श्री अमर सिंह : क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि चूंकि महेन्द्रगढ़ बिल्कुल खुश्क इलाका है तो क्या सरकार वहां पर लोगों से एक चौथाई पैसा मांगने की बजाए वहां पर फ्री सड़क बनाने की कोशिश करेगी ?

मन्त्री : यह बात सही है कि जहां तक महेन्द्रगढ़ ज़िले का ताल्लुक है वहां पर आबपाशी बहुत कम है, वहां पर कई दफा कहत भी पड़ा है। कहत की योजनाओं के तहत जितनी भी सड़कें बनाई गईं उनके लिये लोगों से कोई पैसा नहीं लिया गया।

श्री बनवारी लाल : क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जब पंचायतें अपनी तरफ से कुछ काम कर देती हैं, मैटीरियल कुलेक्ट कर देती हैं तो क्या सरकार ऐसी सड़कों को बनायेगी या नहीं ?

मन्त्री : पंजाब के अन्दर 13 हज़ार पंचायतें हैं। वह क्या करती हैं, इसकी सूचना मेरे पास कैसे मिल सकती है ?

श्री ओम् प्रकाश अग्निहोत्री : क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि अगर कोई पंचायत समिति चौथाई हिस्सा खर्च जमा करा दे तो क्या सरकार सड़क पर आने वाला तीन चौथाई बाकी का खर्च करने के लिये तैयार होगी ?

मन्त्री : प्रश्न से यह सप्लीमेंट्री तो पैदा नहीं होता परन्तु आपकी आज्ञा से मैं निवेदन कर देता हूँ कि इस बारे में अभी सरकार गौर कर रही है और अभी फैसला नहीं कर पाई है कि जो पैसा ब्लाक समिति की तरफ से आता है वह लोगों का पैसा समझा जाए या सरकारी पैसा समझा जाए ।

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜੋ ਸੜਕਾਂ ਬਜਟ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ construction ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੱਸਣਗੇ?

मन्त्री : बहुत सारी ऐसी सड़कें जिनका बजट में रुपया लिख दिया जाता है उनके लिये कहीं एक हज़ार तो कहीं दो हज़ार रुपया रखा जाता है । इससे तो आप जानते हैं कि सड़क पांच गज़ भी नहीं बनती ।

श्री फतेह चन्द विज : वज़ीर साहिब ने बताया है कि अभी इस बात का निर्णय नहीं हो पाया कि जो रुपया ब्लाक समिति से आता है वह लोगों का पैसा होता है या सरकार का । अगर कोई पंचायत रुपया इकट्ठा करके कुल खर्च का एक चौथाई जमा करा दे तो क्या उसको सरकारी रुपया समझा जायगा या सरकार बाकी का खर्च करने के लिये तैयार होगी ?

मन्त्री : यह ज़रूरी है कि वह लोगों का रुपया समझा जायगा । और जितना पैसा हमारे पास होगा उसका हिसाब रखते हुए सड़क को जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश की जायगी ।

श्री फकीरिया : मैं मन्त्री जी से पूछना चाहता हूँ कि टोहाना को फिरोज़पुर से तो मिला दिया गया है लेकिन क्या नरवाना को टोहाना से मिलाने की कोई योजना है ?

मन्त्री : उपाध्यक्षा महोदया, सवाल तो महेन्द्रगढ़ ज़िला के बारे में है और माननीय सदस्य संगरूर ज़िले की बात कर रहे हैं ।

लाला रुलिया राम : वज़ीर साहिब ने बताया है कि पर माइल पांच हज़ार रुपया देना पड़ेगा तो क्या ऐसी कोई सड़क भी है कि जहां पर गांव में मिट्टी डाल दी गई है? ऐसी कई सड़कें देहात में हमारी तरफ हैं ।

गृह मन्त्री : मेरी अर्ज़ यह है कि यह बड़ी अच्छी बात हो कि मैम्बर साहिबान अपनी अपनी पंचायतों में लोगों से पैसा इकट्ठा करवा कर डिवैल्पमेंट के कामों के लिये खर्च कर सकें ।

कामरेड राम प्यारा : क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इस बारे में सरकार की पालिसी क्या है कि कितना रुपया पंचायत या पब्लिक इकट्ठा करके सरकार को दे तो उसके बाद सरकार किसी सड़क या ऐप्रोच रोड को बनाने के लिये तैयार होगी ?

मन्त्री : मैंने निवेदन किया है कि जो पंचायत या ग्रामवासी सड़क का 25 फीसदी खर्च इकट्ठा करके सरकार के खज़ाने में जमा कर देंगे, इस 25 फीसदी के अन्दर ज़मीन की कीमत भी शामिल है और अगर गांव वालों ने मिट्टी भी डाल दी हो तो उसकी भी कीमत उसमें शामिल होगी—तो ऐसी सड़क को सरकार जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करेगी ।

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ । ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਜੋ 66 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਵੈਂਸ ਫੰਡ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ?

मन्त्री: जहां तक उस पैसे का ताल्लुक है जोकि सरकार की तरफ से उसको अनुदान दिया जाता है वह सरकारी रुपया समझा जाता है, उसमें कोई दो राएं नहीं हो सकतीं । लेकिन पंचायत समिति भी कुछ टैक्स लगा कर या दूसरे ज़राए से जो उसकी आमदनी होती है वह पैसा किस का समझा जाए, लोगों का समझा जाए या नहीं, यह प्रश्न है । पंचायत समिति को यह ऐलान एक धारा है जो मुझे याद नहीं है कि उसका क्या नम्बर है उसके तहत सरकार ऐक्ट के तहत करना होता है कि इस बारे में जो खर्च पंचायत समिति ने करना है वह जायज़ है या नहीं । इसके बारे में अभी फैसला करना है ।

पंडित मोहन लाल दत्त : जो विलेज रोड्ज़ पहली प्लैन में ली गईं और उन पर कुछ खर्च किया गया मगर दूसरी और तीसरी प्लैन में उन पर खर्च नहीं किया गया, क्या चौथी प्लैन में उन सड़कों को तरजीह दी जायेगी ?

मन्त्री : वैसे प्रश्न तो महेन्द्रगढ़ ज़िले का है, तो भी अगर आप इजाज़त दें तो अर्ज़ करूँ कि जो गांव छोटी छोटी सड़कें बनाने के लिये पहली या दूसरी योजना के अन्दर शामिल किय गए थे और उन सड़कों पर कुछ खर्च हो चुका है, तब तो उन को पूरा करने की आवश्यकता है, और अगर कोई खर्च नहीं हुआ तब तो दूसरों के साथ उन पर भी विचार होगा । जो गांव चौथाई खर्च देने को तैयार हैं उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए ।

CONSTRUCTION OF ROADS IN DISTRICT MOHINDERGARH

***8750 Shri Banwari Lal** : Will the Minister for Public Works be pleased te state —

(a) the names of the roads which were under construction in district Mohindergarh during the year 1964-65;

(b) the amount allocated for each such road in the Budget for the said year together with the amount actually utilised;

(c) the names of the roads mentioned in parts (a) and (b) above in respect of which budgetary allotment was not fully utilised stating the amount which thus lapsed;

[Shri Banwari Lal]

(d) the names of the persons responsible for the lapse of the amount referred to in part (c) above together with the details of action, if any, taken by the Government against each such person?

Chaudhri Ranbir Singh : (a), (b) & (c) A statement is laid on the Table of the House. It will be observed that while full funds were not utilised in some cases, more funds than the allocation were utilised in others. The lapse is mainly due to the fact that land was acquired at cheaper rates than those provided in the estimate. Similarly materials for road construction were also obtained at rates lower than those provided in the estimates.

(d) Although some small proportion of the lapsed amount may be attributable to negligences of the field officers, the basic reasons are the ones explained above and such question of any action against them does not arise.

STATEMENT

The names of the roads which were under construction in district Mohindergarh during the year 1964-65	Amount allocated	Amount actually utilized	Amount lapsed
1	2	3	4
1. Dadri-Loharu Road ..	31,000	24,301	6,699
2. Mohindegarh-Kanina/Lukhi Nahar Road ..	35,000	32,750	2,250
3. Kanina-Ateli Road ..	2,11,800	2,10,120	1,680
4. Mohindergarh-Satnali-Bhadra Jui Road ..	6,70.960	6,61,833	9,127
5. Approach road from village Pathera to Mohindergarh-Kanina-Lukhi Nahar Road ..	30,000	20,866	9,194
6. Approach road to village Ghasla from Dadri-Mohindergarh road ..	15,000	9,514	5,486
7. Approach road to Rasiawas to Chhapar ..	2,200	1,165	1,035
8. Approach road from Chhapar to Ateli Kalan ..	82,700	74,537	8,163
9. Dadri-Chirya Road ..	2,28,400	1,78,078	50,322
10. Narnaul-Kultajpur Road ..	92,300	91,588	712
11. Nimriwala-Rugarh Road ..	49,000	42,505	6,495
12. Faizabad-Seema-Kanina Road ..	3,71,100	3,05,763	65,337
13. Nasibpur-Dharson Road	13,000	18,819	—5,819
14. Nizampur-Nangal Ke Choudhry Road	2,53,800	2,51,154	2,646
15. Jatwas-Delot Road	1,72,300	1,54,559	17,741

[Minister for Public Works]

1	2	3	4
16. Sanjarwas-Ranila-Achina Road	1,12,700	81,755	30,945
17. Badhra to Berla Road	10,000	—	10,000
18. Satnali-Loharu Road	2,51,700	239840	11,860
19. Bridge over Kansavati Nadi	(—) 3,470	(—) 3,461	(—) 9
20. Dadri-Bond Road	4,920	4,880	31
21. Dadri-Bhiwani Road	4,930	4,929	1
22. Approach Road from Dadri Mohindergarh road to village Joju Kalan	10,000	3,601	6,399
23. Narnaul-Nizampur Road	—	(—) 15,626	(plus) 15,526
24. Narnaul Singhana Road	—	(—) 55	(plus) 55
25. Ateli-Kheri Road	—	(plus) 38	(—) 38
26. Nangal-Chaudhary-Budhwal (Plan)	30,000	28,992	1,C08

लोक कार्य मन्त्री (चौधरी रणबीर सिंह) : उपाध्यक्षा महोदया, जब यह सदन शुरू हुआ था तो एक बैठक में मित्तल साहिब ने इस इलाके में एक रोड का ज़िक्र किया था कि नहीं बनाई गई। मुझे उसके बारे में याद नहीं पता करके बता दूंगा।

श्री बनवारी लाल : इन्होंने अपने जवाब में बताया है कि लो रेट की वजह से और मैटीरियल सस्ता देने की वजह से रुपया बच गया, तो जो रुपया बचा है इसको वहीं पर खर्च करने का अधिकार महकमा को दिया गया या नहीं और अगर नहीं दिया गया तो इसके क्या कारण हैं ?

मन्त्री : उपाध्यक्षा महोदया, जो खर्च के अंदाज़े लगाये जाते हैं वह कई तथ्यों को ध्यान में रख कर लगाए जाते हैं और यह भी ख्याल होता है कि कहीं पर 1) फीसदी कम या 10 फीसदी ज्यादा खर्च हो सकता है। जहां पर खर्च में कमी हो गई तो इसका मतलब यह नहीं कि वह रुपया उसी ज़िला में खर्च किया जाना है। वह तो सड़कों को बनाने के जो एस्टीमेंट हैं उनमें सरकार की बचत समझी जाती है।

चौधरी रण सिंह : क्या आनरेबल मिनिस्टर साहिब बतायेंगे कि जहां पर लोकल पंचायत या पंचायत समिति अपना पैसा किसी सड़क को बनाने के लिए जमा करती है तो उसके लिये यह अशोयर हो जाता है कि वह सड़क सरकार की तरफ से बनाई जाएगी और कितना अर्सा सरकार को उस पर काम शुरू करने में लगता है ?

मन्त्री : उपाध्यक्षा महोदया, दो सवाल इस प्रश्न में लाए गए हैं। एक तो यह कि पंचायत समिति या पंचायत अपना पैसा इकट्ठा करके सड़क बना सकती है उसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता। जहां तक पंचायत समिति या पंचायत वाले पैसा सरकार के पास किसी सड़क को बनाने के लिये जमा करवा देते हैं और फिर सरकार की तरफ से सड़क नहीं बनाई जाती अगर इस बात की सूचना माननीय सदस्य के पास है तो मुझे दें उसके बारे में ज़रूरी कारवाई की जाएगी।

श्री बनवारी लाल : डिप्टी स्पीकर साहिबा, इन्होंने पार्ट 'सी' में कहा है कि नैगलीजेंस की वजह से ऐसा हुआ तो फिर भी सरकार कोई ऐक्शन ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ तजवीज नहीं करती तो सरकार को यह बात ओपनली माननी चाहिए और छुपाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।

मन्त्री : मैंने तो यह बात अपने उत्तर में लिख दी है। इसमें छुपाने की कौनसी बात थी ? आप और क्या चाहते हैं ?

चौधरी रण सिंह : मैं यह जानना चाहता हूँ कि अगर कोई पंचायत समिति या पंचायत पैसा जमा कर चुकी है और सरकार की तरफ से सड़क नहीं बनाई जाती या लोकल तरीका से बना ली जाती है, तो जो रुपया सरकार के पास उन पंचायतों का जमा है, क्या सरकार उन्हें वापिस कर देगी ?

मन्त्री : उपाध्यक्षा महोदया, जो सूचना माननीय सदस्य ने दी है मेरे पास इसकी कोई इत्तलाह नहीं। अगर इनकी सूचना सही है कि जो रुपया पंचायत समिति का सरकार के पास जमा है और उससे सड़क नहीं बनाई गई और वह रुपया पंजाब सरकार का नहीं था बल्कि पंचायत ने अपने जराए से इकट्ठा किया था तो वह रुपया सरकार के पास धरोहर है और वापिस होना चाहिए। अगर कोई ऐसा केस इनके पास है तो मुझे सूचना भेज दें उस पर ज़रूरी कारवाई हो जाएगी।

ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣ ਕਿ ਕੀ ਇਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਡੇਟ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਚਾਇਤ ਰੁਪਿਆ ਜਮਾਂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਐਨੇ ਚਿਰ ਵਿਚ ਸੜਕ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ?

मन्त्री : उपाध्यक्षा महोदया, जहां तक लिखित का ताल्लुक है उसको मैं बहुत ज़रूरी नहीं मानता क्योंकि कई बार लिखित बात को भी पूरा नहीं किया जाता। अब यह फैसला किया है कि जब किसी सड़क के बारे में अंदाज़ा लग जाए कि इतना पैसा नकदी की शक्ल में और इतना मिट्टी वगैरा डाल कर दिया जा सकता है, और इन सारी बातों को अगर पंचायत पूरा कर दे तो जल्दी से जल्दी सरकार ऐसी सड़क को बनाने के काम को हाथ में ले लेगी।

श्री सुरेन्द्र नाथ गौतम : वज़ीर साहिब ने अपने जवाब में बताया है कि जो रुपया लैप्स हुआ है उसकी वजह थी नैगलीजेंस आफ फील्ड स्टाफ और इसके मुताल्लिक कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा क्योंकि ज़रूरी न था तो जो एस्टीमेंट में कमी थी या और वजूहात मिनिस्टर साहिब ने दी हैं यह अफसरान के खिलाफ एक्शन लेने के लिये काफी नहीं ?

मन्त्री : उपाध्यक्षा महोदया, कई गल्तियां ऐसी होती हैं जिनके पीछे इरादा बद होता है ऐसे सरकारी कर्मचारियों या अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है लेकिन जहां पर गल्ती सहवन हो जाए और इरादा बद न हो, और मैं मानता हूँ कि इस केस में भी ऐसा ही हुआ, ऐसी गल्तियों के बारे में किसी के खिलाफ ऐक्शन लेने की या इसका नोटिस लेने की आवश्यकता नहीं।

ਕਾਮਰੇਡ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੜਕ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਰੁਪਿਆ ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾਖਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਤਨਾ ਰੁਪਿਆ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਸੜਕ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਗਾ ਕੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਇਤਨਾ ਰੁਪਿਆ ਦਾਖਲ ਕਰੇ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਹੀ ਰੁਪਿਆ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?

मन्त्री : उपाध्यक्षा महोदया, मैं आपके द्वारा सारे माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि जो भी माननीय सदस्य छोटी छोटी सड़कों के काम को करवाना चाहते हैं वह 25 प्रतिशत पूरा करके हमें बता दें। अगर वह इस काम में कामयाब हो जाते हैं तो सरकार भी काम करवाने में कामयाब होगी, और पूरी कोशिश करेगी। (प्रशंसा)

श्री बनवारी लाल : डिप्टी स्पीकर साहिबा, एक प्वायंट आफ आर्डर के ज़रिये मैं एक बात आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ वह यह है.....

उपाध्यक्षा : आप प्वायंट आफ आर्डर को छोड़िए, अगर कोई ऐसी बात है तो आप लिख कर मेरे नोटिस में ले आएं । (He need not go into the point of order. In case there is any such matter he may bring it to my notice in writing.)

NON-OFFICIAL COMMITTEES SET UP IN 1965

***8712 Comrade Shamsher Singh Josh** (Put by Comrade Gurbakhsh Singh Dhaliwal) : Will the Chief Minister be pleased to state the total number of non-official Committees set up by the Government for different purposes in the year 1965, together with the names of official and non-official members of such Committees?

Shri Ram Kishan : The time and labour involved in collecting the information will not be commensurate with any possible benefit to be obtained.

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੀਫ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਤਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਆਫ਼ੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਂਬਰ ਹਨ । ਪਰ ਚੀਫ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ਼ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਸਟਾਫ ਦੀ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸੈਕਟਰੀ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਐਸਿਸਟੈਂਟਸ ਅਤੇ ਕਲਰਕਸ । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਔਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : ਮੇਰਾ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਐਸੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੈਸਟਿਡ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੱਸਣ, ਉਸਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਰੀ ਇਨਫਰ-ਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।

श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री : जैसे अखबारों में इंडस्ट्रियल लोन देने के लिये एक कमेटी बनाने की एनाउंसमेंट की गई है, क्या मुख्य मन्त्री साहिब यह बतायेंगे कि जब इस बात की हाउस में एशोरेंस दी गई थी कि इस कमेटी में आपोज़ीशन के मैंबरान लिये जायेंगे, इसकी क्या वजह है कि कपूरथला के लिये जो कमेटी बनाई गई है इसमें कोई आपोज़ीशन का मैंबर नहीं लिया गया ?

मुख्य मन्त्री : लुध्याना, जालंधर का तो मुझे पता है कि वहां जो कमेटियां बनी हैं उनमें आपोज़ीशन के नुमायंदे लिये गए हैं । अगर कपूरथले का न लिया गया हो इसमें क्या बात है । हम उसको भी इन्क्लूड कर लेंगे ।

ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਆ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀਪਤ ਆਈ. ਟੀ. ਆਈ. ਦੀ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਣੀਪਤ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਤਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ।

---

*Treated as Unstarred Question as per ruling of the Chair at page 14 and 15 infra.

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : ਇਹ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ । ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇਸ ਮੁਆਮਲੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਸਵਾਲ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤਨੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਐਸੀਆਂ 1965 ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੇ ਨਾਨ ਆਫ਼ੀਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਆਫ਼ੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਲਏ ਗਏ ਹਨ । ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਤੇ ਡਿਸਟਿਰਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੈਸਟਿਡ ਹੋਣ ਤਾਂ ਦੱਸਣ । ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਨਸਟਾਰਡ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਮੰਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਘਰੋ ਘਰੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ । ਇਹੋ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇਹ ਅਨਸਟਾਰਡ ਟਰੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ।(I have no objection in treating it as Unstarred Question.)

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ।

डाक्टर बलदेव प्रकाश : मैं आपके द्वारा यह पूछना चाहता हूँ कि यह चीज़ आया हर दफा हाउस के अन्दर आती रहेगी ? पिछले सैशन में भी यही बात हुई थी । अब और क्या चीज़ हम इनके नोटिस में लायें जब पानीपत का मैंबर नहीं लिया गया, और मोगा के सरदार गुरचरन सिंह नहीं लिये गये , मैं पूछता हूँ कि आखिर यह चाहते क्या हैं ? उन्होंने आन दी फलोर आफ दी हाऊस सारी बात कह दी । फिर यह और क्या चाहते हैं ?

मुख्य मन्त्री : यह एक मामूली बात है । आई. टी. आई. में चंद मैम्बरान की ऐडजस्टमैंट की बात है जो कर दी जायेगी ।

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : On a point of order, Madam. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਲਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਅਨਸਟਾਰਡ ਕਰਕੇ ਚੀਫ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇਣ।

उपाध्यक्षा : मैंने पहले भी कहा था, अब फिर कह देती हूँ कि इसे अनस्टारर्ड ट्रीट किया जाता है और मुख्य मन्त्री साहिब इसका जवाब भेज दें ।

MEAGRE ALLOTMENT OF QUOTA OF SUGAR FOR VILLAGES

***8611. Comrade Ram Chandra** (*Put by Comrade Ram Piara*) : Will the Chief Minister be pleased to state whether the District Authorities and some legislators have brought to the notice of the Government that there is great resentment in the villages on account of very meagre allotment of sugar quota which is 1/4th of that allowed in the cities, if so, the action taken or proposed to be taken by the Government to remove this grievance ?

Shri Ram Kishan : Yes. The allocation of sugar in between the urban and rural areas is made keeping in view past consumption of sugar in these areas. On our repeated requests, the Government of India have allowed an additonal *adhoc* quota of 1000 tonnes of sugar from September, 1965 allocation. It has been decided to allot this quantity in full to rural and hilly areas in the State in addition to their normal quota.

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕੋਟਾ ਦਿਹਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ । ਗੰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਖੰਡ ਦਾ ਕੋਟਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਐਸਾ ਰੂਲ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇ ?

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਟਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ।

कामरेड राम प्यारा : क्या चीफ मिनिस्टर साहिब बतायेंगे कि क्या गवर्नमेंट के नोटिस में ऐसे वाके भी आए हैं कि जो कोटा देहातों का मुकर्रर है, कई दफा उनको वह कोटा भी नहीं मिलता ?

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : ਅਗਰ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸਣ, ਚੈਕ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।

श्री ओम् प्रकाश अग्निहोत्री : जो गांव शूगर मिल के एरिया में आते हैं, एक्ट के मुताबक उन्हें गुड़ और शक्कर बनाने की इजाज़त नहीं । क्या आप उनको शहर के मुताबक शूगर का कोटा देने की कोशिश करेंगे ?

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਗੰਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਘਟ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । (They feel that the villagers, who produce sugar cane are given less quota of sugar as compared to the people living in cities. The Government should consider this matter.)

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਟਾ ਸਾਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮਿਲੇ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਹਾਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ । ਚੁਨਾਂਚਿ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 1,000 ਟਨ ਕੋਟਾ ਜੋ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਹਾਤ ਅਤੇ ਹਿਲੀ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ।

ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਾ ਹੁਣ ਪਿਆ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਹਾਤ ਵਾਸਤੇ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕਸੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਅਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ।

श्री ओम् प्रकाश अग्निहोत्री : मेरा सवाल यह था कि जो देहात मिल एरिया में आते हैं, जिन्हें एक्ट के मुताबिक गुड़ और शक्कर बनाने की इजाज़त नहीं, डिफेंस आफ इंडिया रूल्ज़ लागू होते हैं, उनको शहरों के मुताबक कोटा दिया जायगा या नहीं ? चीफ मिनिस्टर साहिब ने एक जनरल जवाब दिया है, इस बात का जवाब नहीं दिया ?

उपाध्यक्षा : तो आप यह पूछें कि अगर गवर्नमेंट उन्हें शहरों के बराबर चीनी का कोटा न दे तो क्या उन्हें गुड़ और शक्कर बनाने की इजाज़त है ? (Then he should put the question : whether the government is prepared to permit them prepare 'Gur' and 'Shakkar' in case they are not given sugar quota equal to that given in the cities.)

श्री ओम प्रकाश अग्निहोत्री : मेरा मिल एरिया के संबंध में सवाल है जहां गुड़ और शक्कर बनाने की इजाज़त नहीं ।

मुख्य मन्त्री : एग्ज़ामिन कर लेंगे ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਚੀਫ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਕੋਟਾ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘਟ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ? ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸ਼ੂਗਰ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ । ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੂੰ ਲੋ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : ਕੋਈ ਹੱਤਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ । ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਓਨੀ ਇਜ਼ਤ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ।

पंडित मोहन लाल दत्त : मैं मुख्य मन्त्री से यह दरियाफ्त करना चाहता हूँ कि हिल्ली एरिया में, जहां गन्ना कम होता है, गुड़ और शक्कर वहां खाने को इतना नहीं मिलता, वहां मिलट्री जवानों के फैमिलीज़ ज्यादा तादाद में हैं, तो उस एरिया में कुछ और कोटा बढ़ा कर यह कन्सेशन दिया जायगा ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਵਗੈਰਾ ਛੁਟੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਟਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜੀ past consumption of sugar in these areas ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਨਾਪ ਨਾਲ ਇਹ ਤੋਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਘਟ ਸ਼ੂਗਰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੱਧ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ?

(ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ)

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ।

Deputy Speaker : I cannot force the Government to reply.

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤ੍ਰੀ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਵਿਤਕਰਾ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ? ਹਿੰਦੁਸ-ਤਾਨ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਕੀ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ?

मुख्य मन्त्री : हक तो सब के एक जैसे हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं ।

ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਲਾਇਲਪੁਰੀ : ਚੀਫ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਕੋਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਕੋਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ?

Sardar Gurnam Singh : May I know from the hon. Chief Minister the reasons for giving proportionately reduced quota of sugar to the rural areas ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : ਜੈਸਾ ਕਿ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੈ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਾਰੀ ਹੈ । ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਵਾਈ ਵਗੈਰਾ ਯਾ ਹੋਰ ਦਸਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਦੇਹਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਐਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਟਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ 6 ਜਾਂ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਰੂਰਲ ਏਰੀਏ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਐਸ਼ਿਓਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਟਾ ਮਿਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਹਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ।

Sardar Gurnam Singh : Does the hon. Chief Minister assure us that the entire additional quota of sugar given to the Punjab Government, will be given to the rural ereas ?

Chief Minister : We will try our best.

ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤ੍ਰੀ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ?

(ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ)

WHEAT ETC. PROCURED BY GOVERNMENT

***8803. Comrade Shamsher Singh Josh** (*Put by Comrade Gurbaksh Singh Dhaliwal*) : Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) the total quantity of wheat piocurred by the Government during the months of March to August, 1965, monthwise ;

(b) whether any quantity out of such procured wheat has been exported to Bombay or any other State; if so, the actual quantity exported and the rate at which it was exported ?

Shri Ram Kishan

			(Tonnes)
(a)	March	..	86
	April	..	447
	May	..	88,745
	June	..	2,08,112
	July	..	22,827
	August		—
		Total	3,20,217

(b) Yes. About 1,28,000 tonnes (upto 31st August, 1965). This wheat was exported to the deficit States out of the stocks procured by the State Government on behalf of the Government of India and as such the State Government did not recover any price for this wheat from the recipient States.

ਸਰਦਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਧੌਲਾ : ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤ੍ਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਇਕ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾੜੀ ਕਣਕ ਹੈ । ਉਸ ਕਣਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੂਜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੱਧ ਮੁਲ ਤੇ ਬੇਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਦਾ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤ੍ਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ?

मुख्य मंत्री : मेरे पास ऐसी कोई इतला नहीं । अगर आनरेबल मेंबर के नोटिस में है तो वह बतलाएं, उसको एगज़ामिन कर लेंगे ।

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਪਾਰਟ 'ਬੀ' ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਲਖ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਕਣਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਜੋਂ ਭੇਜੀ । ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ । ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਭੇਜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਣਕ 'ਨੋ ਪਰਾਫਟ ਨੋ ਲਾਸ' ਬੇਸਿਜ਼ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ 52 ਰਪਏ ਤੋਂ 56 ਰਪਏ ਕਵਿੰਟਲ ਤਕ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ।

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਬੰਬਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲੋਂ ਪੀ. ਐਲ. 480 ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਲਈ ਹੈ ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : ਨਹੀਂ ਜੀ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ?

ਸ੍ਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ : ਸਰਦਾਰ ਉਜਲ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਕੀਮਤ 53 ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸੇ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 49 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 56 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਮੈਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੀਲਿੰਗ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 52 ਤੋਂ 56 ਰਪਏ ਤਕ ਖਰੀਦੀ ਹੈ।

ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ : ਜਿੰਨੀ procure ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਣਕ It is cent per cent from the middlemen.

(*Interruption*)

Deputy Speaker : I cannot force anybody to give reply.

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਣਿਆਂ ਦਾ ਭਾ 50 ਰੁਪਏ ਹੈ ਔਰ ਬੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 170 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਆਪਣਾ ਅਨਾਜ ਭੇਜ ਕੇ ਉਥੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਤੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।

REMISSION OF LAND REVENUE ETC. IN BORDER DISTRICTS OF FEROZEPORE, AMRITSAR AND GURDASPUR

***8747 Comrade Shamsher Siugh Josh** (*Put by Comrade Gurbakhsh Singh Dhaliwal*): Will the Minister for Transport and Elections be pleased to state the criteria kept in view in demarcating border areas in Ferozepore, Amritsar and Gurdaspur districts for remission of Land Revenue, water rates etc. because of damage caused by the Pakistani aggression in the recent India-Pakistan conflict ?

Sardar Gurdial Singh Dhillon : The criteria kept in view in demarcating border areas in Ferozepore, Amritsar and Gurdaspur districts for grant of relief concessions were the extent of loss/damage caused to property by enemy action or/and by our own army movement or camping.

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ: ਲੜਾਈ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਕਰਾਈਟੀਰੀਆ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 10 ਮੀਲ ਦੀ ਹਦ ਰਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ 5 ਮੀਲ ਦੀ ਹਦ ਰਖੀ ਹੈ। ਕੀ ਮੈਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਅੰਤਰ ਕਿਉਂ ਰਖਿਆ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਅਤੇ ਬੰਬਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੀਜੀਏਟ ਰੇਂਜ ਅਸੈਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹਦ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਅਤੇ ਬੰਬਿੰਗ ਨਾਲ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਮੈਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 10 ਮੀਲ ਦੀ ਹਦ ਤਕ ਮਾਲੀਆ ਮਾਫ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਫੀਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ? ਉਥੋਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ।

ਮੰਤਰੀ : ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

श्री राम सरन चन्द मितल : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि इन तीन डिस्ट्रिक्टस के इलावा बठिंडा डिस्ट्रिक्ट में फरीदकोट सब-डिवीज़न में जो लड़ाई के कारण नुकसान पहुँचा है ऐसें एरियाज़ को भी वार हिट करार दें कर रिमिशन देने के लिये कंसिडर करेंगे ?

मन्त्री : जहां तक लैंड रैविन्यू और आबियाने की रिमिशन का सवाल है उसके लिए operational villages की 10 मील तक लिमिट रखी है। लेकिन अगर उससे आगे कहीं हवाई जहाज़ से नुकसान हो गया है तो गवर्नमेंट हर सूरत में उसे पूरा करेगी।

ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ੀਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਏਕੜੇਜ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਰਕਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਿਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਸਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਅਲਹਿਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਖੈਰ, ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਭਿਜਵਾ ਦਿਆਂਗਾ।

ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਆ ਦੇਵ : ਰਿਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ੀਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੇਜਰ) : ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਕਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੁਵਾਲ ਪੁਛਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਅਤ ਮਹਿਸਸ ਹੋਈ ਹੈ।

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : ਕੀ ਫੀਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਔਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ।

(No Reply)

UNSTARRED QUESTION AND ANSWER

REGISTERED FACTORIES AND TRADE UNIONS

3056. Comrade Hardit Singh Bhathal : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state —

(a) the actual number of registered factories in the State up to date together with the number of workers employed in each ;

(b) the total number of registered Trade Unions in the State at present ;

(c) the number of Trade Unions with their numerical strength affiliated to the Central Trade Union Organisations and also the number of unaffiliated Unions ;

(d) the total number of disputes raised by the Unions affiliated to the different All India Organisations for adjudication during the period from January, 1962 to date and the result thereof in each case ?

Chaudhri Rizaq Ram : A statement containing the requisite information is laid on the Table of the House.

STATEMENT

(a) There are 5,285 registered factories in the State at present and total number of persons employed in the registered factories is about 1,70,632. The number of workers employed in each factory has not been given as the compilation/preparation of such an information will entail a lot of labour and expenditure which would not be commensurate with the advantage which may accrue therefrom.

(b) The total number of registered Trade Unions at present in the State is 754.

(c) The number of trade unions affiliated to the Central Trade Unions Organisations/Unaffiliated unions is given below :—

Name of the Central Organisation to whom affiliated		Number of Unions
I.N.T.U.C.		217
A.I.T.U.C.		60
B.M.S.		23
H.M.S.		10
Unaffiliated Unions		444
	Total	754

[Minister of Irrigation and Power]

(d) The collection/preparation of information union-wise with their affiliation and also with regard to the result in each case, involves a lot of labour and expenditure which would not be commensurate with its utility. However, the total number of disputes raised/referred/Awards given by Tribunal/Labour Courts

(Minister for Irrigation and Power)

year-wise is given as under :—

Year	Disputes Raised	Referred for Adjudication	Award given by Industrial Tribunal/ Labour Courts
1962	1227	227	301
1963	1069	145	206
1964	1570	177	226
1965 (from Jan., 65 to Sep., 65)	1500	135	164

QUESTION OF PRIVILEGE

उपाध्यक्षा : कामरेड राम प्यारा ने जो प्रिवलिज *मोशन का नोटिस दिया है, वह मोशन प्रैस गैलरी कमेटी को भेज दी है। (The Privilege Motion, given notice of by Comrade Ram Piara will be referred to the Press Gallery Committee.)

10.03 a.m.

CALL ATTENTION NOTICES
(Serial No. 188.)

डाक्टर बलदेव प्रकाश: मैं गवर्नमेंट का ध्यान इस बात की तरफ दिलाता हूँ कि पंजाब के अन्दर लाखों टन सीरियल फूडग्रेन (कोर्स) कीड़ा लगने की बजह से खराब हो रहा है क्योंकि सरकार इस फूडग्रेन को लोगों को बाहिर भेजने की इजाज़त नहीं देती और साथ ही सरकार लोगों से यह चीज़ें खरीद नहीं रही है। उदाहरणत: दो लाख टन के करीब सफ़ेद चना राज्य में पड़ा हुआ है। राज्य के अन्दर इसे खरीदने के लिये कोई ग्राहक नहीं और सरकार ने इसे निर्यात करने की आज्ञा देनें से इन्कार कर दिया है। इसमें कीड़ा लग रहा है और जल्दी ही यह लोगों के खाने के काबिल नहीं रहेगा। यह एक बड़ा भारी राष्ट्रीय नुक्सान होगा। यही हालत दूसरे सीरियल फूडग्रेन्ज़ (कोर्स) की है। सरकार खुद इस चीज़ को खरीदने के लिए शीघ्र कदम उठाए या लोगों को बाहिर भेज कर बेचने की इजाज़त दे ताकि यह चीज़ यहां पर खराब होकर ज़ाया न हो।

(I beg to draw the attention of the Government towards the fact that the lakhs of tons of coarse cerials foodgrain is getting worm infested in the State for lack of export permission and failure on the part of the Government to purchase it. For example, white gram near about 2 lakh tons is lying in the State. There is no customer in the State to purchase it and the Government has refused permission to export it. It is getting worm infested and will very soon be unfit for human consumption. It will be a tremendous national waste. So is the case with other cerial foodgrains (coarse). The Government should immediately take steps to purchase it or export it to prevent this waste.)

Deputy Speaker : This is admitted.

*Note. Regarding alleged publication of a portion of expunged proceedings of the Sabha dated the 22nd November, 1965, in the Daily Hind Samachar Jullundur.

मुख्य मन्त्री (श्री राम किशन) : मैं इसके बारे में अर्ज करना चाहता हूँ कि सरकार ने इसके लिये 26-11-65 को टेंडर काल किए हैं ।

Deputy Speaker : Call Attention Notice No. 190 is in the name of Sarvshri Gurbakhsh Singh Dhaliwal and Babu Singh Master (Comrades).

(Serial No. 109)

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : ਮੈਡਮ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਲ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਾਇੰਟ ਰਜਿਸਟਰਾਰ (ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਜ਼) ਨੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਰ, ਬਟਾਲਾ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਜ਼, ਬਟਾਲਾ, ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਮਿਲ ਦੇ 20/25 ਮੀਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗੰਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹੇ । ਇਸ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਨੂੰ ਗੰਨਾ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ । ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਟਾਲਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੰਨਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਿਲ ਦੇ ਪਰਬੰਧਕ ਯੋਗ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਿਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ 8 ਥਾਵਾਂ, ਪੱਟੀ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਰੱਈਆ, ਮਹਿਤਾ, ਵੇਰਕਾ, ਪਾਖਰ ਪੁਰ, ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੰਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਕਿ ਮਿਲ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੰਨਾ ਖਰੀਦਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਮਾਦ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਪਰ ਹੁਣ ਮਿਲ ਦੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਗੰਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ।

(I beg to draw the attention of the Punjab Government towards the fact that the Joint Registrar (Sugar Mills), Co-operation Department of the Punjab Government has issued an order whereby he has imposed restrictions on the Manager Batala Co-operative Sugar Mills, Batala that this year the Mill should open sugarcane purchase centres within the radius of only 20/25 miles of the Mill. By the imposition of this order a larger number of farmers of Amritsar district will be deprived of selling their sugarcane to the Mill and this has caused a good deal of unrest among the farmers of Amritsar District. The farmers of Amritsar District had purchased shares of the Mill in the belief that the management of the said Mill would make adequate arrangements for the purchase of sugarcane produced by them. Last year, the Mills had opened centres at various places, namely, Patti, Taran Taran, Khadoor Sahib, Rayya, Mehta, Verka, Pakharpur in Amritsar District and purchased sugarcane through those centres. The farmers of this district have produced sugarcane in great quantity with this hope that their produce would be purchased by Mill. Now at the starting of the season of the Mill, it has done a great injustice to the farmers by closing these centres. The Government should withdraw this order immediately to check this unrest prevalent amongst the farmers and open sugarcane purchase centres as was done last year.)

Deputy Speaker : This is admitted. Government will make a statement.

Next (No. 192) is also in the names of Comrades Gurbaksh Singh Dhaliwal and Babu Singh Master.

(Serial No. 192)

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਲ ਖਿਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ਬਾਰੇ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਹੁਕਮ ਅਧੀਨ ਉਸ ਗਰਾਂਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਹ ਫੀ ਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰੀਜਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿਦਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਹੋਰ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 20 % ਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਪੇਂਡੂ ਪਰਾਈ-ਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ । ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਫੀਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਗਰਾਂਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਹਰੀਜਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੀਜਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਗਰਾਂਟ ਵਿਚ ਉਕੀ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ।

(I beg to draw the attention of the Government towards the matter, namely, great unrest and anxiety has been caused in the State of Punjab by an order of the Government whereby a cut is being made in the grants of the private schools. The cut of 50 % has been imposed under this order in the said grant given to those institutions for giving fee concessions to the Harijan students. The cut of 20 % has been made in other grants too. The financial condition of the rural private schools is already very poor. The condition of these institutions in the border districts is worse than this because the income of these institutions by way of fees from the students has decreased due to the fall in the number of students.

A large number of private schools are refusing admission to the Harijan students due to the cut in grant. Therefore, the Government should pay attention to this matter and that there should be no cut at all in the grant to be given for Harijan students to the said institutions.)

Deputy Speaker : This is admitted. Government will make a statement.

Next (193) is again by Comrades Gurbakhsh Singh Dhaliwal and Babu Singh Master.

(Serial No. 193)

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਲ ਖਿਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਲ 'ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡ' ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੇਚੈਨੀ ਫਲੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਇਹ ਫੰਡ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਗਰਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦਰ ਹਰ ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੋਂ ਪੰਜ ਰੁਪਏ, ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੋਂ 4 ਰੁਪਏ,

ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੋਂ 2 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੋਂ ਇਕ ਰੁਪਿਆ ਹਨ । ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਹੈ । ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਰਖਿਆ ਫੰਡ ਬਹੁਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਉਗਰਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਦਾ ਅਸਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤਾਲੀਮੀ ਖਰਚਾ ਘਟ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਧਿਆਪਕ ਤਨਾਸਬ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 1:45 ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 1:60 ਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਪੁੱਟੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਤਰ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਪਰ ਦਸਿਆ "ਸਕੂਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡ" । ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਬਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ।

(I beg to draw the attention of the Government towards the matter, namely, Building Fund is being collected from the students by the Educational Institutions in the state these days, which has led to a great unrest amongst the parents of the students. This fund is being collected in the Government Colleges and schools at the rates of Rs 5 per student in the college, Rs 4 per student in the Higher Secondary School, Rs 2 per student in a Middle School and Rs 1 per student in the primary schools. As a result there is a great resentment amongst the parents. The Educational Institutions have already collected large amounts of money for the Defence Fund.

The burden of emergency is being put on the educational sphere more than required. In view of the emergency conditions the previous teacher-student ratio of 1 to 45 has been increased to 1 to 60 on the plea of cutting down the expenditure on education in the Punjab.

The Government should reconsider all these questions and set right the wrong steps taken by it immediatly. It must be taken into consideration whether the Government can impose a new tax, such as above mentioned 'school building fund' without the previous approval of the State Legislature ? Therefore we ask the Government to make a detailed statement in this connection.

Deputy Speaker : It is admitted. Government will make a statement.

Call Attention Motions Nos. 195 and 196 are by Comrade Shamsher Singh Josh. He is not present. Next (No. 197) is by Sardar Ranjit Singh.

(Serial No. 197)

Sardar Ranjit Singh : Madam, I beg to draw the attention of the Government to the fact that the stoppage of construction works of irrigation drainage on account of paucity of funds which has created serious situation as this stoppage of the said construction work is bound to result into floods in the state. This has resulted into un-employment amongst officers, technical staff and also labour. This does not speak well of our planned economy as by saving some funds which would have been spent on construction of irrigation drainage. The state Government have to undergo huge loss on account of floods and further therefrom including loss of crops and property.

Hence this motion.

Deputy Speaker This is admitted. Government will make a statement.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਮੈਡਮ । ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਲ ਅਟੈਨਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ 14 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?

Deputy Speaker : Call Attention Notice No. 198 stands in the name of Sardar Ajaib Singh Sandhu.

(Serial No. 198)

Sardar Ajaib Singh Sandhu : Madam, I beg to draw the attention of the Minister concerned towards complaints made by the Deputy Commissioners in Punjab against some responsible officers of the Medical Department of their districts that they were not performing their duty well and not co-operating with the authorities during the recent national emergency created by Pakistani aggression. The Deputy Commissioners further complained that those officers deserted their duty during national emergency and therefore, they should be shifted from their posts and punished. The Government did shift those officers from their posts, but no action was taken against them for deserting their duty during the recent national emergency. They should have been brought to book. But instead they were either promoted to higher posts or transferred to places convenient to them.

The names and designations of those officers must be disclosed to this Honorable House and the punishments which have been inflicted upon them or the Government propose to inlict upon those officers who have betrayed the nation during national emergency.

Deputy Speaker : This is admitted. Government will make a statement.

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : ਆਨ ਏ ਪਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਮੈਡਮ । ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ ਨੇ ਕਾਲ ਅਟੈਨਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਅਟੈਨਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ।

उपाध्यक्षा : सवालों के बारे में तो रूल्ज़ में इजाज़त है और उसकी इजाज़त मैंबरों को दे दी जाती है लेकिन जहां तक काल एटैंशन मोशन्ज का सम्बन्ध है, वहां पर रूल्ज़ में अथार्टी को मानने के बारे में नहीं लिखा हुआ । इसलिये मैं रूल्ज़ के बरखलाफ नहीं चल सकती । (It is provided in the Rules only in relation to questions and members are permitted to put questions on others behalf but so far as call Attention Motions are concerned there? is no provision of such authority in the Rules. I therefore, cannot go against the Rules)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਉਸ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇਵੋ।

उपाध्यक्षा : यह बात मेरे इल्म में नहीं है। जो कुछ मुझे मालूम है, मैंने उसके मुताबिक ही हाउस की कार्यवाही चलाने की कोशिश करनी है। I can not accept it (This is not to my knowledge. I am to conduct the bussiness of the House in accordance with what I know. I cannot accept it)

श्री फतेह चन्द विज : डिप्टी स्पीकर साहिबा, चौधरी टेकराम ने मुझे काल अटैंशन मोशन नम्बर 200 को हाउस में मूव करने के लिए अथार्टी दी हुई है। इसलिये मुझे यह काल अटैंशन मोशन मूव करने की इजाजत दी जाए।

Deputy Speaker : I cannot accept it. Please take your seat.

Deputy Speaker : The next notice (No. 202) is in the name of Shri Ajit Kumar. He is not present in the House.

The next notice (No. 203) is in the name of Sardar Ajaib Singh Sandhu.

(*Serial No. 203*)

Sardar Ajaib Singh Sandhu : Madam, I beg to draw the attention of the Minister concerned towards the fact that the candidates who have passed the P.C.S. Examination last year have not been absorbed so far and the result of the P.C.S. examination of this year is not being declared which is causing great discontentment among the candidates. The candidates who were selected in the P.C.S. last year may please be absorbed at once and the result of this year be declared without any loss of time.

Deputy Speaker : This is admitted.

मुख्य मन्त्री (कामरेड राम किशन) : इसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूँ कि जितनी भी हमारे पास वेकैन्सीज़ होंगी उनके मुताबिक उनको एबज़ार्व कर लिया जायगा।

Deputy Speaker : The next notice (No. 204) is in the name of Shri Ajit Kumar. He is not present in the House.

The next notice (No. 207) is in the name of Sarvshri Kulbir Singh and Satya Dev.

(*Serial No. 207*)

Sardar Kulbir Singh : Madam, I beg to draw the attention of the Minister concerned towards the fact, namely, that certain lady teachers said to have been kidnapped or were forcibly taken away by the Pakistani Army on 6th/7th September from the villages occupied by the enemy. Even after this the District Education Officer was not in a position to accept or deny this fact. D.E.O. was suggested to transfer all the lady teachers from all along the border of Ferozepur District which is about 80 miles even if the Fazilka event is not correct to which he agreed fully. He himself advised the local M.L.A. to bring to his notice the names of lady teachers and the schools. When the lady teacher brought to his notice alongwith the required recommendation the D.E.O. was out of his temper. He threatened them of dismissal and other dire consequences if any of them ever approached the C.M. or Home Minister who were expected to tour the War affected areas. Attention of the Government is drawn towards the fact that all along the border any action from the enemy is always expected, therefore, the request of the lady teacher be considered in the light of the past experience and they may be transferred to safer areas.

Deputy Speaker : This is admitted. The Government may please make a statement about it. Next call attention notice (No. 209) is by Sardar Sampuran Singh Dhaula.

ਸਰਦਾਰ ਸੰਪੂਰਣ ਸਿੰਘ ਧੌਲਾ : ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਖੋ ਕਲਾਂ, ਕਾਹਨੇਕੇ, ਭੈਣੀ ਜੱਸਾ, ਫਤਿਹ ਗੜ੍ਹ ਛੰਨਾ, ਢਿਲਵਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁਰਬਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਛਡੇ ਰਾਹਾਂ ਵਲ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਰਜਵਾਹਾ ਜਾਂ ਡਰੇਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਪੁਲ ਜਾਂ ਪੁਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਮਹਿਕਮਾ ਨਹਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ । ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੁਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਨ ਉਪਜਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ ।

(I beg to draw the attention of the Government to the thoroughfares left after the recent consolidation operations in villages Pakkho Kalan, Kahaneke, Bhaini Jassa, Fatehgarh Chhanna and Dhilwan. The Government has not constructed any bridge on the distributaries or drains crossing the roads of the above mentioned villages resulting in a great inconvenience to the cultivators for going from one village to the other. The Irrigation Department does not pay any heed to the applications submitted by the cultivators for construction of bridges. The Government should construct bridges in the said villages at once. This will help the grow more food campaign.

Deputy Speaker : This is admitted. Government will make a statement. Next (No. 210) please.

(Serial No. 210)

Shri Balramji Dass Tandon : I draw the attention of the Government towards the misuse of electricity being made in the Capital. It is strange that on one hand the Government is calling for economy in the use of electricity in the whole of the State and on the other misusing enormous electric energy by allowing street-light lighting for the whole of the night on the main road leading to High Court and Secretariat and on the lake road.

It is also note worthy that at the same time energy is not being supplied and rather cut being applied to printing presses for printing school books, when they are already in short supply in the market.

Deputy Speaker : This is admitted.

मुख्य मन्त्री (श्री राम किशन) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह सवाल ग्रानरेबल मैम्बर ने ठीक ही किया है, बड़ा माकूल है। लेकिन बात यह है कि अगर हम एक बत्ती को बंद करें तो उसके साथ ही सब बत्तियों को बंद करना पड़ता है। हम पहले ही सारी चीज़ को चैक कर बैठे हैं। फिर भी चैक करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितनी भी ज़यादा से ज़यादा बिजली बचाई जा सके बचायें। ग्रानरेबल मेम्बरान को मालूम होगा कि दो, तीन मेगा वाट से ज़यादा बिजली खर्च नहीं होती है। इसके बावजूद जितनी बचत हो सकती है, करने की कोशिश की जाएगी।

Deputy Speaker : Next call Attention Notice No. 211 is by Sardar Ranjit Singh.

(Serial No. 211)

Sardar Ranjit Singh : Madam, I beg to draw the attention of the Minister concerned towards the fact, namely, that the rate of land revenue realised from the cultivators of villages of Malerkotla Tehsil of District Sangrur is much more than even three times about than of adjoining area of Amargarh, Sherpur, Dhuri, Barnala and Mahal kalan qanogos of

the same districts. The land revenue has not been lowered and brought at par with the rate of adjoining area in spite of assurances given from time to time by the Government officers and ex-Ministers. It is a indiscriminate treatment and so great resentment is prevailing amongst the above mentioned cultivators since last 18 years.

Hence this motion.

Deputy Speaker : This is admitted. Government will make a statement. Next (No. 212) is by Shri Balramji Dass Tandon.

(*Serial No. 212*)

Shri Balramji Dass Tandon : I beg to draw the attention of the Government towards its promises for giving relief to the border districts. It is strange that instead of giving relief for Property Tax, its revision has been made upward, nearing double to its original amount. There is a huge hue and cry in the public of these areas. As such the attention of the Government is drawn for taking effective action in exempting these areas from these arbitrary orders. Rather it was expected that the Government would exempt these areas from the levy of the Property Tax at least for two years to come.

Deputy Speaker : This is also admitted.

मुख्य मन्त्री (श्री राम किशन) : जहां तक इसकी रिवीज़न का ताल्लुक है, इसके मुताल्लिक कई महीनों से इन्स्ट्रकशन्ज़ जारी की गई थीं । मैं ग्रानरेबल मैम्बर ग्रौर हाउस को यकीन दिलाता चाहता हूँ कि रिवाइज्ड रेट्स को फिलहाल लागू नहीं किया जायगा ।

Deputy Speaker: Next Call Attention Notice (No. 213) is by Pandit Mohan Lal Datta.

(*Serial No. 213*)

Pandit Mohan Lal Datta : I beg to draw the attention of the Government to the anti-prohibition policy of the State Government in allowing all clubs in certain districts of the State to serve wine against the excise rules which prohibited serving wine in such clubs.

Such a step is entirely against the recommendations of Tek Chand Committee Report which advised the Central and State Governments to start prohibition in a phased programme forthwith.

Such a step of the State Government is extremely improper and unjustified. This will further aggravate the drink evil endangering the health and morals of the people. Such an action called for an explanation and clarification by the Government regarding its prohibition policy.

Deputy Speaker : This is admitted.

Minister of State for Excise, Printing and Labour (Chaudhri Sunder Singh) : The recommendations contained in the report of the Tek Chand Committee on Prohibition have been broadly accepted by this State Government. It has been proposed by the State Government that gradual steps leading to total prohibition should be spread over a period of 16 years instead of 12 years as recommended by the Committee, subject of course to the other States in the country falling in line and the Central Government undertaking to reimburse the State Government to the extent of loss incurred through enforcement of total prohibition.

[Minister of State for Excise, Printing and Labour.]

These recommendations are to be discussed in a meeting of the Chief Ministers and Excise Ministers of all the States to be arranged by the Government of India and further action in regard to the enforcement of prohibition will be taken in the light of the decisions to be arrived at therein.

(*Thumping from the Treasury Benches*) (विघ्न)

पंडित मोहन लाल दत्त : ग्रान ए प्वायंट ग्राफ ग्रार्डर, मैडम । मैंने दरियाफ्त किया था क्लबों में जो वाईन सर्व करने की इजाज़त दे रखी है यह एक्साईज़ रूल्ज के विरुद्ध है। इसके बारे में ग्रापने कोई जवाब नहीं दिया । (विघ्न)

उत्पादन शुल्क, मुद्रण तथा श्रम राज्य मंत्री (चौधरी सुन्दर सिंह) : बार्डर एरिया है । ग्रौर जिन जगहों पर इजाज़त दी है वहां पर लड़ाई हो रही है । (विघ्न)

चौधरी देवी लाल : ग्रान ए प्वायंट ग्राफ ग्रार्डर मैडम । मेरा प्वायंट ग्राफ ग्रार्डर यह है कि उधर से चीफ मिनिस्टर साहिब भी, पार्लियामैंटरी एफेयर्ज़ के मिनिस्टर भी ग्रौर चौधरी सुन्दर सिंह तीन तीन वज़ीर जवाब देने के लिये खड़े होते हैं । मैं ग्रापकी रूलिंग इस बात पर चाहता हूँ कि एक मिनिस्टर जवाब नहीं दे सकता ग्रौर क्या तीनों मिनिस्टर यकदम जवाब दे सकते हैं ?

उपाध्यक्षा : मैंने कई बार कहा है कि यह उनकी जायंट रैस्पांसिबिलिटी है । (I have said it a number of times that it is their joint responsibility).

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੰਤਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ) : ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਹੋਇਆ। ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਚੌਧਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ—ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ, ਸਮਝਦਾਰ ਹਨ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਹਨ । ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਵਾਈਨ ਕਿਹਾ ਹੈ । ਵਾਈਨ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅੰਗੂਰਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ । ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਇਥੇ ਬਣਦੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 'ਵਾਈਨ' ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਲ ਵਿਸਕੀ, ਲਿੱਕਰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।

Deputy Speaker : Next Call Attention Motion is No. 214.

(Serial No. 214)

ਸਰਦਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਧੌਲਾ : ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਾਲੇਕੇ ਬਦਮ, ਅਸਪਾਲ ਕਲਾਂ, ਕੋਟ ਦੂਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਧੇਰਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਡਰੇਨ ਵਲ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੇਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਡਰੇਨ ਨੂੰ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਫਤ ਅਰਪਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ । ਜੋ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਡੀ. ਸੀ. ਅਤੇ ਡਰੇਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮੱਤੇ ਪਾਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ । ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ । ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ । ਸੋ ਇਹ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰੇਨ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ।

(I beg to draw the attention of the Government towards the drainage of the villages, namely, Kaleke Badam, Aspal Kalan, Kot Dunan and Pandhera. These villages have offered to give their lands free of cost for the sake of draining out the sem water. They have also offered their services free of charge for digging out the drain. This has been conveyed to the D.C., Sangrur and the authorities of the drainage Department in writing by adopting resolutions in the Panchayats but no action has been taken thereon. These villages ask the Government for making alignment of drain only. This matter concerns many villages, therefore, the Government should make this alignment of the drain so that this problem of waterlogging be solved.)

Deputy Speaker : This is admitted. Government will make a statement.

Next Call Attention Motion No. 215 is by Sarvshri Ajit Kumar, Jagan Nath and Tek Ram.

(*None of the hon. Members was present.*)

Deputy Speaker : Next Call Attention Motion No. 216 by Shri Jagan Nath.

(*The hon.. Member was not present in the House*).

Deputy Speaker : Call Attention Motion No. 220 is by Sarvshri Kulbir Singh and Satya Dev.

(Serial No. 220)

Sardar Kulbir Singh : Madam, I beg to draw the attention of the Government towards the matter, namely, Faridabad New Township Municipality is wholly a nominated body by the Government. The Deputy Commissioner is the Chairman of this Committee. Faridabad Township is knit with open drains. These drains have no draining out. During the previous years about 10 children have died by drowning in the drains which are wholly uncovered. On 5th October, 1965 small daughter of one Deep Singh a resident of 526, Faridabad drowned in the drain and died instantaneously. She was completely wrapped with mud. Always stagnant water is source of a danger to the lives of children as such a strong action is called for from the Government in this connection.

Deputy Speaker : This is admitted. Government will make a statement. Next (No. 221) is by Sardar Jasdev Singh Sandhu.

(Serial No. 211)

Sardar Jasdev Singh Sandhu : I beg to draw the attention of the Government to the fact that the construction of a V.R. bridge was started in the year 1961-62 near R.D. 105 opposite V. Khanpur Gandian on the Narwana Branch of the 1st Bhakra Main Line Circle. The contract for the construction of the bridge was duly sanctioned and the material was collected on the site. After a lapse of four years the construction of bridge has not yet been started and the material collected has been removed from the site. This action of the Government has created resentment in the mind of the public of this area. It is requested that early steps may be taken to start the construction of this bridge.

Deputy Speaker : This is admitted. Government will make a statement. Next (No. 222) please.

(Serial No. 222)

Sardar Jasdev Singh Sandhu : I beg to draw the attention of the Government towards the fact that the merger of the Municipal Committee, Rajpura and Notified Area Committee, Rajpura Township, has not been notified in spite of the fact that prel minary notification showing the intention of the Government to merge the two local bodies was issued a year back. The Deputy Commissioner, Patiala, has also recommended the merger of these two local bodies. The Panchayat Samitis of Tehsil Rajpura five members of Punjab Legislative Assembly of district Patiala, and a large number of social organisations of Rajpura, have demanded this merger. This delay is causing a great heart-burning among the people. The existence of two local bodies side by side is causing great inconvenience to the agriculturists who are to take their produce to the market by crossing these two local bodies and to pay for the *rahdari* at two places. It is requested that the Government should take immediate action in the matter.

Deputy Speaker : This is admitted. Government will make a statement Next (No. 223) is again in the name of Sardar Jasdev Singh Sandhu.

(Serial No. 223)

Sardar Jasdev Singh Sandhu : I beg to draw the attention of the Government towards the apathy of the Irrigation Department for not according sanction to the Panchayat Samiti, Bhunerheri (Patiala) to construct bridges on irrigation channels in view of the fact that Development Department and Secretary, Irrigation and Power, issued letters to all the Panchayat Samitis in the State during the year 1963-64 that where the Panchayat Samitis, Panchayats or Zila Parishads want to construct bridges and culverts on irrigation channels with their own funds, they are free to do the same. The Irrigation Department will supply the drawings and design of the bridge or culvert to be constructed to the concerned body on demand and sanction to construct the same will be given at the earliest. But it is strange that in spite of this clear policy laid down by the Government the Panchayat Samiti, Bhunerheri, district Patiala is not being given permission to construct four bridges with its own funds at four different places by the Irrigation Division, Devigarh, Patiala, and 1st Bhakra Main Line Circle, Patiala. The Panchayat Samiti, Bhunerheri, applied a year back to construct these bridges at its own cost to Irrigation Division, Devigarh, but the sanction has not been given uptil now. Such delay in the execution of development work is causing great resentment and is retarding the progress. The Government is requested to look into the causes of this inordinate delay and take immediate steps in the matter.

Deputy Speaker : This is admitted. Government will make a statement.

(Serial No. 130)

Sarvshri Kulbir Singh and Satya Dev, M.L.A.s to draw the attention of the Minister concerned towards the matter, namely, that S.D.O. (Civil) and Food Inspector of Faridkot are bullying the Public in order to obtain National Defence Fund. Every shopkeeper and public in general are compelled to donate in the National Defence Fund. Food Inspector has some goondas with him in order to insult whoever shows his

inability to donate according to the specifications of the Civil Supply Inspector. Country needs co-operation in order to carry on successful prosecution of War, of all classes of people voluntarily. You cannot force people to make sacrifice on the threat of a club. Over-zealous, strong, Officers in order to obtain promotion by all means are devoid of patriotism. In reality they create bad blood between the Government and the people. They are enemies of the country and need strong punishment. Attention of the Government is seriously drawn to this sort of cruelty and is demanded that action after enquiry be taken against both the Officers.

(Serial No. 131)

Sarvshri Kublir Singh and Satya Dev, M.L.A.s to draw the attention of the Minister concerned towards the matter, namely, that Government has declared to render relief to the uprooted people from enemy occupied areas. They are being given relief accordingly. There are villages adjoining the enemy occupied areas but actually are not under enemy occupation are deprived of Government relief but firing is still continuing and the result is that due to enemy firing from occupied areas our people are unable to collect cotton and unable to harvest kharif crop. Our military does not allow our people to go into those villages. Although inhabitants are ready to go to their fields even at their own risk yet they are not allowed. On the other hand civil authorities of the State Government do not consider them as war sufferers. The villagers of Karni Khera, Kairjanwali, Sabuana, Assowali, Kotha and other adjoining villages of Fazilka Tehsil are hanging in the fire. Attention of the State Government is drawn to this critical condition and is demanded that people belonging to this area be considered as war sufferers and entitled to all relief and rehabilitation or they may be allowed to collect cotton and harvest other Kharif crop and occupy their own houses.

The Government has allowed the remission to border villages in the belt of 10 miles but the local authorities of Fazilka consider the depth of 10 miles from the international border, i.e., pre-war border. For relief purposes Government should not neglect the villages of present 10 miles from now occupied area. Attention of the Government is drawn that villages of Churiwall Dhanna Nihal Khera, Ghallu, Abohar (village) etc. be considered liable for all relief of land revenue, and water-rates as they are within 10 miles of the Border.

In Hussainiwalla Sector, villages of Kundhe, Gatti Habibke, Dakhli Hussainiwalla, Alike, Dulcheke, Palla, Megha, etc., had never been occupied by the enemy but they are just on the border and had to go through enemy shellings as they were in the sheling range. Most of these villages of Ferozepore Sector named above were deserted at the instance of Military (indirectly). Most of the people were obliged to leave their places. They lost all their crops (standing). They came back at the end of hostilities. They must have been considered or they must now be considered war victims. Government attention is definitely called for proper action as already prescribed by the Government.

उपाध्यक्षा : सरदार कुलबीर सिंह, आप उस दिन गैर हाज़िर थे । आप की 130 और* 131 नम्बर की काल अटैनशन मोशन्ज़ है । अगर आप उन को मूव करना चाहते है· तो कर लें । (Sardar Kulbir Singh was not present in the House the other day. Call Attention notices Nos. 130 and 131 stand in his name. He may move them if he so desires.)

सरदार कुलबीर सिंह : मेरे पास उन की कापीज़ नहीं है । आप ही पढ़ दें ।

उपाध्यक्षा : ये एडमिट हो गई हैं । (These are admitted).

Shri Fateh Chand Vij : Madam, there is also one Call-Attention Notice No. 173*. It stands in my name but I could not move it as I was not present in the House at that time.

Deputy Speaker : That is also admitted. Government will make a statement.

(Serial No. 173)

*Shri Fateh Chand Vij M.L.A., to draw the atiention of the Government towards its failure to implement the Mahajan Committee's recommendations to provide a jeep in every Police Station or at least in Sadar Police Stations of the State to control effectively the law and Order situation. Law and Order situation is a serious problem in some of the Sadar Police Stations of the State immediate measure to controle it by providing means of transporation for the Police Officials should be taken.

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਮੈਡਮ । ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਲਿੰਗ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਿਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਡਜਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਾਲ-ਅਟੈਨਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ?

उपाध्यक्षा : अगर वह उस बात के लिए दरखास्त करें तो ज़रूर कनसिडर किया जा सकता है । आप कामरेड शमशेर सिंह जोश को कहना कि वह अपनी मोशन अगले इजलास में पेश कर दें । (It can be considered on a request from the hon. Member. The hon. Member may ask Comrade Shamsher Singh Josh to move his motion in the next session).

ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਲਾਇਲਪੁਰੀ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਮੈਡਮ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਕਾਲ-ਅਟੈਨਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸ-ਐਲਾਉ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ । ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ, ਐਸਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ । ਮੇਰੀ ਇਕ ਕਾਲ-ਅਟੈਨਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਦਾਅ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵਾਰ ਅਫੈਕਟਿਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਲੋਨ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਮਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੇਬਰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜਗਾਹ ਛਡ ਛਡ ਕੇ ਭੱਜੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਲੇਬਰ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣੇ ਪਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ—ਬੜੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੇਬਰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚੋਂ ਉਜੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਹਾਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੱਸ ਸਕਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਸਕਨ । ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

उपाध्यक्षा : सरदार तारासिंह ने जो प्वायंट उठाया है अगर चीफ मिनिस्टर उस पर कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं ।(If the Chief Minister wants to give any reply to the point raised by Sardar Tara Singh, he may do so).

मुख्य मंत्री : अगर कोई स्पैसिफिक केस हमारे नोटिस में लाएं तो उसके मुताबिक कार्यवाही की जा सकती है ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸੇਫਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਲੇਬਰ ਵਾਸਤੇ ਲੋਨਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੇਬਰ ਵਾਸਤੇ ਲੋਨਜ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਹਾਤੀ ਲੇਬਰ, ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦਿਉ ।

ਮੁਖਮੰਤਰੀ : ਖੇਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤੁਸਾਂ ਪੁਛਿਆ ਹੈ । ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਚੁਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਨਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਕਈ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਜਾਂ ਵਰਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ।

Chief Parliamentry Secretary (Shri Ram Partap Garg) : Medam, I beg to lay on the Table of the House.......

ADJOURNMENT MOTION

चोधरी देवी लाल : ग्रान ए प्वायंट ग्राफ ग्रार्डर, मैडम मेरा प्वायंट ग्राफ ग्रार्डर यह है कि मेरी एडजर्नमेंट मोशन थी । उसकी बारी ग्राई ही नहीं । कल ग्रापने कहा था कि उसे पैंडिग रखा गया है ग्रौर ग्राज चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी पहले ही रिपोर्टस पेश करने लग पड़े हैं । (विघ्न) मेरे कहने का मतलब यह है कि मैंने एक एडजर्नमेंट मोशन दी थी कि 22 तारीख को कुरुक्षेत्र में हमने विशाल हरियाणा प्रान्त की कान्फ्रेंस रखी हुई थी । उस कान्फ्रेंस को वहां पर होल्ड करने की 22 तारीख को इजाज़त दे दी गई थी । लेकिन उसके थोड़ी देर के बाद वहां पर लाउड-स्पीकर की इजाज़त को कैंसल कर दिया गया । इसी बिना पर मैंने ग्रापको यह एडजर्नमेंट मोशन दी थी ग्रौर ग्रापने कहा था कि इसे ग्रार्डिनरी ऐडमिनिस्ट्रेटिव ग्राऊंड पर रिजैक्ट किया गया है । मैं ग्रर्ज करना चाहता हूँ कि कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि ऐसी जगहों पर किसी पुलिटीकल कांफ्रेंस को होल्ड करने की इजाज़त न दी गई हो । ग्रानन्दपुर साहिब, फतेहगढ़ साहिब जैसी जगहों पर तमाम पुलिटीकल पार्टियों की कान्फ्रेंस होती है ग्रौर ऐसे रिलिजस मेलों का फायदा उठा कर ग्रामने सामने पुलिटिकल पार्टियां कान्फ्रेंस होल्ड करती रही हैं लेकिन कुरुक्षेत्र में विशाल हरियाणा प्रान्त की कान्फ्रेंस को होल्ड करने की इजाज़त देकर भी उस पर पाबन्दी लगा दी गई । तो मैं ग्रापकी मारफत यह ग्रर्ज़ करनी चाह रहा हूँ कि क्या वजह है कि हरियाणा के लोगों के साथ यह गवर्नमेंट इम्तयाजी सलूक कर रही है ? ग्रब भी ग्राप देख लें यहां हाउस में भी चीफ मिनिस्टर साहब ग्रौर श्री बलरामजीदास टण्डन पंजाबी सूबा ग्रौर हरियाणा प्रांत की डिमांड को दबाने के लिए कांस्प्रेसी कर रहे हैं ग्रौर कुरुक्षेत्र में जब कि वहां पर श्रीमती ग्रोम प्रभा जैन मौजूद थीं ग्रौर वहां पर डिप्टी कमिश्नर ग्रौर एस०डी०एम सब मौजूद थे लेकिन उन्होंने वहां हमें विशाल हरियाणा प्रान्त की कान्फ्रेंस होल्ड करने के लिये लाऊड-स्पीकर लगाने की इजाज़त नहीं दी थी ग्रौर इसके लिये उन्होंने यह कहा कि हम नहीं चाहते हैं कि रिलीजस मेलों पर पोलिटीकल कान्फ्रेंसिज की जाएं हालांकि वहां पर ग्रार्यसामाज वालों का जलसा हो रहा था ग्रौर ग्रकालियों की कान्फ्रेंस हो रही थी जिनमें से एक में पंजाबी सूबा की हमायत हो रही थी ग्रौर दूसरे में पंजाबी सूबा ग्रौर हरियाणा प्रांत दोनों की मुखालिफत हो रही थी ग्रौर इन मसलों पर लेक्चर हो रहे थे ।

उपाध्यक्षा : मैंने ग्रापसे कहा था कि ग्रापकी यह मोशन एडजर्नमेंट मोशन के रूप में एडमिट नहीं हो सकती क्योंकि इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर इवाल्वड है ग्रौर यह काल-एटेनशन मोशन के रूप में एंडमिट हो सकती है। I had told the hon. Members that his motion could not be admitted as an adjournment motion as it involved as administrative matter. This could be admitted as a Call Attention notice.)

चौधरी देवी लाल : डिप्टी स्पीकर साहिबा, काल-एटेनशन मोशन के तौर पर तो आप तब करें अगर यह एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर हो यह तो गवर्नमेंट की पालिसी का सवाल है, क्योंकि गवर्नमेंट की मौजूदा पालिसी यह है कि जहां कहीं भी हरियाणा प्रांत की फेवर में या पंजाबी सूबा की फेवर में आवाज़ उठाई जानी हो उसकी इज़ाजत न दी जाय। इस बारे में मिनिस्टीरियल लैवल पर डिसीयन लिया जा चुका है। इसलिये जिस किसी जगह पर हरियाणा प्रान्त के हक में या पंजाबी सूबा के हक में कान्फ्रेंस होगी उसमें सरकार की तरफ से रुकावटें डाली जायेंगी और इसी वजह से वहां पर हमें लाऊड-स्पीकर इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी गई हालांकि श्रीमती ओम प्रभा जैन, जो मिनिटर है, वहां पर मौजूद थी। मैंने जब इनका ध्यान इस तरफ दिलाया तो इन्होंने कहा कि वह इस बारे में वहां पर कैसे डिसीयन ले सकती है। तो मैंने कहा कि मिनिस्टर मौका पर डिसीयन ले सकता है लेकिन इन्होंने इस बारे में कोई डिसीयन नहीं लिया।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਮੈਡਮ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਅਸੀਂ ਸਹੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰੂਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਹਕ ਵਿੱਚ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਘੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮੇਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਕ ਵਿਚ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਉਸ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਾ ਪਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇਣ।

स्वास्थ्य मंत्री (श्रीमती ओम प्रभा जैन) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, कल इस बारे में यह एक एडजर्नमेंट मोशन आई थी और आज काल-एटेनशन नोटिस की शकल में यहां पर यह सवाल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। आपकी इत्तलाह के लिये मैं यह अर्ज़ करना चाहती हूँ कि कल शाम को मैंने वहां कुरुक्षेत्र के एस०डी०एम० के साथ टेलीफोन पर सारी बात की थी और उसने मुझे बताया था कि इन्होंने पहले कोई परमिशन नहीं मांगी थी और 22तारीख को सुबह साढ़े दस बजे इन्होंने इस सिलसिले में अपनी एप्लीकेशन दी थी यानी जब इन्होंने कान्फ्रेंस होल्ड करनी थी उस वक्त से सिर्फ आध घंटा पहले इनकी एप्लीकेशन आई थी इससे पहले कमिश्नर अम्बाला डिवीज़न के अंडर एक मीटिंग हुई थी तो उन्होंनें कुरुक्षेत्र मेले की जो कनवेन्शन्ज और ट्रेडीशन्ज़ थीं उन के मुताबिक यह परमिशन देने से न करदी क्योंकि वहां कभी इस मेले पर कोई पोलिटीकल कान्फ्रेंस होल्ड नहीं की गई।तो जब मैं कमिश्नर साहब से टेलीफोन पर बात की और उन से मैंने इस बारे में पूछा तो उन्होंने अपना स्टेण्ड मेरे सामने रखा। लेकिन इसके बावजूद भी मैंने इनको तीन घंटे के लिये लाऊड-स्पीकर इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। आपकी इत्तलाह के लिये मैं यह भी बता देना चाहती हूँ कि इसके बाद इन्होंने यह कान्फ्रेंस वहां पर होल्ड भी की थी जिसमें स्पीचिज़ भी की गई थीं। इस बात का मुझे इलम नहीं कि चौधरी साहब वहां पर बोलें कि नहीं बोलें, पर जिस चीज़ के लिये इन्होंने परमिशन मांगी थी वह दे दी गई थी।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਜ਼ਿਆ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਸਥਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਰੂਖੇਤਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਐਸੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ

ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਸਥਾਨ ਹਨ ਉਥੇ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਮਗਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਹੀ ਹੈ ।

चोधरी देवी लाल : आन ए प्वायंट आफ प्रसनल एक्सप्लेनेशन । मेरी बहन श्रीमती ओमप्रभा जैन ने कहा है कि इन्होंने लाऊड-स्पीकर इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी थी । इस बारे में मैं अर्ज़ करता हूँ कि मैंने इनको दो टेलीफोनज़ के नम्बर नोट करवाये थे और मैं वहां ढाई घंटों तक इनके फोन की इन्तज़ार करता रहा था और इनका कोई मैसेज इस बारे में मुझे नहीं मिला । यह बात तो इन्होंने खुद मानी है कि जो परमिशन पहले हमें मिली थी वह कैनसिल हो गई थी, हालांकि वहां पर और कई पोलिटीकल कान्फ्रेंसिज़ हो रही थीं । आर्यसमाज वालों की कान्फ्रेंस हो रही थी और इसी तरह से अकाली दल वालों की कान्फ्रेंस हो रही थी । आज भी आप वहां जा कर देखें, वहां पर उन के जल्से हो रहे हैं । जो इन्होंने यह कहा है कि हरियाणा कान्फ्रेंस वालों की वहां पर मीटिंग हुई थी, उस बारे में मैं अर्ज़ करता हूँ कि वह तो बगैर लाऊड-स्पीकर के चल रही थी, क्योंकि इन्होंने वहां लाऊड-स्पीकर लगाने की इजाज़त नहीं दी थी । तो इसका मतलब साफ है कि गवर्नमेंट ने इनस्ट्रक्शन्ज़ जारी की हुई थीं कि उनको इजाज़त नहीं देनी इस तरह से इन्होंने इमत्याजी सलूक बरता है और इसकी यही वजह है कि पंजाबी रिजन के 17 इलेक्टिड हिन्दु मैंबरों में से एक हिन्दू मैम्बर हम पर रूल कर रहा है—

उपाध्यक्षा : चौधरी देवी लाल हरियाना प्रान्त की एक ही तो देवी मिनिस्टर हैं आपने उसी से उलझना शुरू कर दिया है । I would point out to the hon. Member that there is only one lady Member from Hariana in the Cabinet and the hon. Member has started a controversy with her).

चौधरी देवी लाल : डिप्टी स्पीकर साहिबा, यही तो हम को सब से बड़ा एतराज़ है । पहले श्री अचिंतराम और श्री डी. डी. पुरी जैसे पुर्तगाली हरियाना प्रांत से खड़े कर दिये जाते थे और अब इनको यू० पी० से लाकर मिनिस्टर बना कर बैठा दिया है और हरियाना के मिनिस्टरों की गिनती बढ़ा दी गई है । पहले हरियाने से पुर्तगालियों को लाकर चुनाव लड़ाया जाता था और जब हमने मिल के इस बारे में आवाज़ उठाई तो यह चीज़ बन्द हुई अब यह कर दिया गया है । हमारे साथ तो यही कुछ अब भी किया जा रहा है कि यह पंजाब के 17 हिन्दू मैम्बरों में से एक चीफ मिनिस्टर बन कर बैठ गए हैं और हम हरियाने के 66 एलेक्टिड मैम्बरों में से कोई नहीं बनाया गया ।

स्वास्थ्य मंत्री (श्रीमती ओम प्रभा जैन) : मैं सिर्फ यह कहना चाहती हूँ कि चौधरी साहब ने बताया है कि इन्होंने मुझे दो टेलीफोनों के नम्बर दिये थे लेकिन चौधरी साहब यह बात भूल गये हैं कि जिस आदमी की तरफ से यह एप्लीकेशन आई थी, जिसको घोलू चौधरी के नाम से पुकारा जाता है, मैं उसका ठीक नाम तो नहीं जानती, वह खुद मेरे पास बैठा था और उस को मैंने खुद इजाज़त देदी थी कि जाकर कान्फ्रेंस कर लो । इसके बावजूद भी मुझे इनकी बात की समझ नहीं आई कि कैसे इन्होंने कह दिया है कि इजाज़त नहीं दी गई थी ।

चौधरी नेत राम : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडम । हरियाणा प्रांत की कान्फ्रेंस करने की मनजूरी मांगने के लिये दरखास्त दी गई थी और पहले यह मान भी गए थे लेकिन बाद में वह कैन्सल कर दी गई और कहा गया कि वहां पर पोलिटीकल कान्फ्रेंस नहीं हो सकती । मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से गुजारिश कर रहा हूँ कि इन्होंने भी तो उद्घाटन किया था (विघ्न) क्या यह भी उनके साथ फायदा नहीं उठा रहे ? कांग्रेस पार्टी के नाम का (विघ्न) हरियाणा प्रान्त के नाम से क्या दिक्कत आ गई, क्या इससे बगावत हो जाती ? (विघ्न) प्रजातन्त्र का ध्यान रखते हुए पंजाबी सूबा और हरियाणा जरूर बनना चाहिए और बनेगा (विघ्न)

उपाध्यक्षा : आखिर हर बात की कोई लिमिट भी होनी चाहिए । (After all there is some limit to every thing). Order please.

STATEMENTS LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE

Chief Parliamentary Secretary (Shri Ram Partap Garg) : Madam, I beg to lay on the Table of the House statements in reply to Call-Attention Notice Nos. 134, 192, 193, 207, 102, 155, 162, 179 and 172.

STATEMENT IN RESPECT OF CALL-ATTENTION NOTICE NO. 134 REGARDING ARTS GALLERY OF THE ARTS COLLEGE, CHANDIGARH

In the building of the Government School of Arts, Punjab, at Chandigarh, two separate Institutions are functioning at present :—

(i) The Government School of Arts (and not Arts College).

(ii) Chandigarh Section of the State Museum.

Shri Sushil Sarkar is the Principal of the Government School of Arts, Chandigarh, while administrative control over this Institution is that of the Director of Industrial Training, Punjab. The Chandigarh Section of the State Museum is under the administrative control of the Education Commissioner and Secretary to Government, Punjab, Education and Languages Departments. The Principal, Government School of Arts is also Incharge of the Chandigarh Section of the State Museum. There is no Art Gallery attached to the Arts School and so the question of the Art Gallery of the Arts College, Chandigarh, being in deplorable condition does not arise. So far the State Museum is concerned, all the assets of the Museum at Simla were shifted in 1959 to Patiala where the State Museum was proposed to be established in the Moti Bagh Palace. Consequent upon the sale of the Moti Bagh Palace to the National Institute of Sports of the Government of India, a part of the assets of the Museum had per-force to be shifted to Chandigarh and temporarily housed in a portion of the Government School of Arts, Chandigarh. The present set-up of the State Museum in the Government School of Arts building is a purely temporary feature and all the exhibits displayed in the limited space in the Museum are in proper order. All these exhibits will be removed and placed permanently in the new building of the State Museum which is under construction at Chandigarh.

During the recent Indo-Pakistan conflict, the requisite precautionary measures were taken to protect the rare objects in the Museum and especially paintings etc. The Museum, however, remained open to the public and no student was ever refused to enter the Museum. As stated above, there does not exist any Art Gallery of the Arts College, Chandigarh, and so the question of its being closed for the visitors and particularly the college students does not arise at all.

No instance has come to the notice of the Education Department that the principal of the Arts College, Chandigarh, took out valuable production or masterpieces from the Museum to the Tagore Theatre in Sector 18, Chandigarh. Only

on one occasion, a request was received from the Secretary, Arts Council and Director, Public Relations, Tourism Cultural Affairs and Deputy Secretary to Government, Punjab, that the Arts Council had arranged an exhibition of contemporary art on the 29th October, 1965. He requested for a loan of 25 paintings and some pieces of sculptures which belonged to the State Museum. This request was accepted and the Principal of the Government School of Arts and Incharge, State Museum, Chandigarh was allowed to lend 25 paintings and some pieces of sculptures to the Public Relations Department for exhibition. The exhibits were loaned to the Lalit Kala Academy for exhibition in Tagore Theatre which was inaugurated by Shri M.C. Chagla, Union Education Minister on the 29th October, 1965. The Arts Council of which the Lalit Kala Academy is a Subsidiary Body which sponsored this exhibition, is a Government body. The Union Minister for Education greatly commended the efforts of the Lalit Kala Academy and desired that more exhibitions of this type should be held to make people art-minded. Thus nothing was done which could be deemed to be in contravention of the Government policy or in any respect objectionable or anti-national.

STATEMENT IN RESPECT OF CALL-ATTENTION NOTICE NO. 192

Sarvshri Comrade Gurbakhsh Singh and Comrade Babu Singh Master, M.L.A.s have moved the motion calling the attention of the House to a matter of great importance *viz.* unrest and anxiety caused in the State by an order of the Government, whereby cut has been made on Harijan grants of the Privately-managed Schools. The following two points have been raised in the Motion:—

1. 50 per cent cut has been imposed on the grant to be given to the privately-managed institutions in lieu of fee concession to Harijan students.

2. 20 per cent cut has been imposed on other grants.

It has been mentioned that the financial condition of the rural private schools is already poor and the condition of those institutions in the border districts is worse as their income from fees from the students has decreased due to fall in enrolment. It has been further pointed out that a large number of privately-managed schools are refusing admission to Harijan students due to this cut on grants. Government have been urged to pay attention to this matter and see that no cut on grants in respect of Harijan students is applied.

No decision has so far been taken to apply a cut of 50 per cent, i. e., withholding of special grants. The privately-managed schools are allowed reimbursement of tuition fees of Harijan/Backward Classes students at the prescribed half rate under the provision of the State Harijan (Educational) welfare Scheme read with para 5, Article 121 of the Punjab Education Code.

In order to compensate the privately-managed schools for the half fee covered by them, they are allowed special grants on the basis of liberalised formula as per details given below:—

Serial No.	*Category of Schools*	*Special grant admissible*
(i)	Schools with more than 5 per cent and up to 20 per cent Harijan/ Backward Classes students	5 percent of half rate grant
(ii)	Schools with more than 20 per cent and up to 40 percent Harijan Backward Classes students	75 per cent of the half rate grants
(iii)	Schools with more than 40 per cent Harijan/Backward Classes students	100 per cent of half rate grant

It is obvious that the privately-managed schools catering for the educational advancement of Harijan students are more or less compensated fully for allowing exemption for the payment of tuition fees to Scheduled Castes/Backward Classes students. Accordingly Harijan freeship grants earned by the privately-managed schools for the first quarters have been paid to all the privately-managed schools. The grants due to these schools for the second quarter ending 30th September, 1965, are being paid without delay.

[Chief Parliamentary Secretary]

A sum of Rs 62.38 lacs was provided for meeting the current year's liabilities on account of stipends, freeships grants/refund of examination fees to Scheduled Castes/Backward Classes students. As a result of abnormal increase in the number of Harijan students, our liability for the current year has now been estimated at Rs 83.08 lacs. The question of providing additional funds to the extent of Rs 20.70 lacs to enable this Department to meet the current year's increased liabilities on account of Harijan freeship grants/stipends is receiving the attention of Government. No decision has so far been taken by the Government to apply cut of 50 per cent, i.e., with holding of special grants.

It is not true to say that other grants have been reduced by 20 per cent. The cut of 10 per cent on Maintenance and other grants to the privately-managed schools has been imposed by the Council of Ministers as a measure of economy necessitated by the Emergency arising out of Indo-Pak conflict. In fact Government has since applied 10 per cent cut on the Non-Plan expenditure as a whole on all the Departments and this has been done as a measure of economy. According to Article 84 of the Punjab Education Code, Government reserve to itself the right to refuse or with hold any grant at its entire discretion. Government has not, however, stopped the grant to the privately managed schools altogether. The cut of 10 per cent only is not too much keeping in view the abnormally heavy expenditure of an unforeseen character which has been incurred by Government in the context of the Indo-Pakistan conflict. Whereas Government is trying to effect economy in the present emergency, it expects the privately-managed schools to make a little sacrifice by meeting their requirements from their own resources to the extent of cut applied by Government. The cut of 10 per cent in Maintenance and other grants payable to privately-managed schools will bring a saving of Rs 3 lacs.

Government are aware of the difficulties of the privately-managed schools situated in border areas. Necessary steps are being taken to assess the loss which privately-managed schools have suffered on account of fall in enrolment due to migration and shifting of population from border areas. A definite and concrete proposal for compensating the privately-managed schools situated in border areas for the loss they have suffered during the recent conflicit with Pakistan is under active consideration of the Government.

STATEMENT IN RESPECT OF CALL-ATTENTION NOTICE NO. 193 BY GURBAKHSH SINGH AND BABU SINGH MASTER REGARDING COLLECTION OF BUILDING FUND FROM THE STUDENTS BY EDUCATIONAL INSTITUTIONS ETC.

Most of the school buildings are in a deplorable condition. Some of these are dilapidated and otherwise also not fit for use. The schools which do have buildings find these inadeduate to cope with the additional enrolment. The end result is that most of the students have to be exposed to the inclemencies of weather. There is no protection to them against the sun or the rain. Whenever there is a heavy rain most of the institutions have to be closed.

The plan ceilings have been very low and it has not been possible to make an adequate provision for providing additional accommodation or for effecting repairs. The following table will show the position of buildings in the various Educational Institutions:—

Sl. No.	Particulars	Total No. of Institutions	Institutions having adequate buildings	Institutions having buildings with unsatisfactory conditions
1.	Colleges ..	38	25	13
2.	Higher Secondary Schools ...	259	107	152
3.	High Schools ..	657	192	465
4.	Middle Schools ..	1,514	466	11,048
5.	Primary Schools ...	12,579	5,398	7,181

The Department has neither funds for effecting annual repairs nor for making additions and alterations in the school buildings. Government of India was also approached for the allocation of funds but no grant has been received. Something had to be done to put the school buildings in proper condition so that the students should have much-needed shelter. It is not possible for the schools to function efficiently without adequate accommodation. After careful consideration, it was decided that the school/college building maintenance fund should be created by levy of fee on the students of Government Institutions at the following rates with effect from the academic session of 1965-66 *vide.*—circular attached:—

(1) Primary (I to V Classes) .. Re 1 per annum per student

(2) Middle (VI, VII and VIII classes) Rs 2 per annum per student

(3) High and Higher Secondary (IX, X and XI Classes) Rs 4 per annum per student

(4) College students .. Rs 5 per annum per student

The fund will be used for meeting on priority basis the local needs for the repairs to school/college buildings. The levy being almost nominal is not likely to impose burden on the people.

So far as the Teacher-pupil ratio is concerned it is true it has been laid down in the Punjab Education Code that normally a class should not exceed more than 45 students but in actual practice it has not been possible to stick to this number. In 1962 at the time of Indo-Chinese conflict it was decided to give one teacher in a Primary School if the enrolment was up to 60. This was done on the presumption that the effective attendance seldom exceeds 45 to 50. After that the first slab of 60, one teacher was to be provided for a slab of 50 pupils. Thus, the purposes of calculation additional teacher was provided whenever the number exceeded 60.

In Secondary Schools, however, every effort was made to provide additional teachers to cope with additional enrolment in schools. There has been a Plan scheme for providing staff to remove congestion in schools. So under this scheme additional staff has been provided in most of the schools. So it is not correct to say that the Department is putting the burden of emergency on the education sphere. The recent Indo-Pakistan conflict has created a difficult situation. Money has to be found for allowing free education facilities to the children of war oustees. In most cases free books have to be provided also. Additional grant will have to be given to private schools which have suffered as a result of loss of enrolment. So under the circumstances the Department will have to stick to this 1 : 60 teacher-pupilratio in Primary Schools. It is also a fact that in good many cases Primary School enrolment varies between 20 to 40, but one teacher has to be provided there also.

The Department is very keen that the teacher-pupil ratio should under no circumstances exceed the one which has been laid down in the Code but in critical times every Department has to grade priorities. So this is just an interim measure and efforts will continue to be consistently made to restore normal teacher-pupil ratio as soon as times are normal and funds are available.

Copy of letter No. 245-M-Ed-IV- 65/8 (32)/17926, dated Chandigarh, the 8th September, 1965 from the Education Commissioner and Secretary to Government, Punjab, Education Department to Director of Public Instruction, Punjab.

Subject.—Creation of Building Fund in Government Schools.

1. Reference correspondence resting with your Memo. No. 8 (C)-13/102-64-Bd (6), dated the 16th February, 1965 on the subject noted above.

2. Government have decided that School/College Buildings Maintenance Fund should be created by levying a fee on the students of Government Institutions at the following rates with effect from the academic session of 1965-66 :—

(i) Primary (I to V Classes) .. Re 1 per annum per student

(ii) Middle (VI, VII and VIII Classes, Rs 2 per annum per student

[Chie Parliamentary Secretary]

(iii) High and Higher Secondary (IX, X ,XI Classes) .. Rs 4 per annum per student

(iv) College Students .. Rs 5 per annum per student

The fund will be used for meeting, on priority basis the local needs for the repairs to School/College buildings. It is requested that appropriate rules for the utilization of this Fund may be prepared and sent to Government for approval immediately.

OFFICE OF THE DIRECTOR OF PUBLIC INSTRUCTION, PUNJAB

Endst. No. 13/102-64-Bd (6), dated Chandigarh, the 23rd September, 1965

A COPY is forwarded to—

(1) All Government Arts Professional Colleges in the State

(2) All Circle and District Education Officers in the State,

for information and necessary action. The appropriate rules for the utilisation of this Fund are under examination and will be issued later on. The funds so collected should be deposited in the Personal Ledger Account of the Institution concerned. Detailed procedure for the utilization of these funds will follow.

These instructions may be brought to the notice of all Heads of Institutions/ offices under your control immediately for compliance.

The receipt of this communication may kindly be acknowledged.

Sd/-
BUDGET OFFICER,
for Director, Public Instruction, Punjab.

STATEMENT BY THE MINISTER ON CALL-ATTENTION MOTION NO. 207

Sarvshri Kulbir Singh and Satya Dev, M.L.A.s have raised the following points in the Call-Attention Motion :—

(i) Some lady teachers were said to have been kidnapped or forcibly taken away by the Pakistani Army on the 6th and 7th September from the Villages occupied by the enemy.

(ii) The District Education Officer neither accepted nor denied this fact.

(iii) The District Education Officer was asked to transfer all lady teachers from all along the border of Ferozepore District and he had agreed.

(iv) Later when again some lady teachers approached for transfer, they were threatened with dismissal and lost his temper.

(v) He threatened them of dire consequences if they approached the Chief Minister and Home Minister.

The District Education Officer was contacted on phone on the 23rd November, 1965. He said that he had contacted Mr. Quami, Sub-Divisional Magistrate, Fazilka who had informed that no lady teacher was kidnapped or taken away forcibly by the Pakistani Army on the 6th and 7th September, 1965. Therefore, the Honourable Members appear to have been informed wrongly.

So far as the suggestion to transfer lady teachers from the border areas is concerned the District Education Officer has assured that he will consider all such cases favourably. He has added that his anxiety is not to allow any lady teacher to re-remain exposed to danger from the enemy side.

He has categorically denied that he lost temper when some lady teachers approached him with a request of transfer. He has also denied to have held out any threat, in case they met the Chief Minister or Home Minister. He says that the Director of Public Instruction also visited this area and no such complaint was brought to his notice.

The members are, therefore, assured that the interest of lady teachers will be properly safe guarded, whenever the authorities are satisfied that they are in danger.

THE STATEMENT RELATING TO CALL-ATTENTION NOTICE NO. 102 GIVEN BY SARVSHRI SITA RAM BAGLA AND KESRA RAM ON THE SUBJECT OF ACUTE FAMINE, IN TEHSIL SIRSA, DISTRICT HISSAR

1. It is incorrect that Sirsa Tahsil is in the acute gripe of famine, or that there has been a general failure of crops. Due to general drought conditions and fall in the supply of canal water, the canals are running by rotation and the condition of kharif crop this year is poor compared with that of last year. There are villages in this tahsil whose lands are not served by canal or well irrigation, and in these villages, because of failure of rains, the kharif crop is practically non-existent and prospects for rabi are bleak.

2. As regards the remission of land revenue, there is no case for general remission. Total remission will be given where the damage is more than 50 per cent, and where the damage is less than 50 per cent but more than 25 per cent, there will be 75 per cent remission.

3. As regards postponement of the realisation of past dues, the policy of Government is not to realise past dues when the condition of crops is such that people are not in a position to pay.

4. For the relief of distress in the drought-affected areas of Hissar District, the following important decisions have recently been taken by the Cabinet Sub-Committee appointed for the purpose:—

(1) Thirteen lift irrigation schemes are to be started which will provide employment and also bring irrigation to a number of drought-affected villages of Bhiwani and Hansi Sub-Divisions. For these works, a sum of Rs 45 lakhs has been sanctioned.

(2) A number of roads are to be started in various drought-affected areas of Hissar District and a sum of Rs 15 lakhs has been sanctioned for the earthwork on these roads.

(3) Soil conservation works are to be undertaken in several drought-affected areas for which Rs 10 lakhs have been sanctioned.

The above works will provide gainful employment to a large number of unskilled people in the drought-affected areas of Hissar District.

5. A statement showing the particulars of the thirteen lift irrigation schemes to be undertaken is attached (Annexure).

[Chief Parliamentary Secretary]

ANNEXURE

SALIENT FEATURES

Lift Irrigation from Bhurtana Minor	Dong Minor	Khanak Minor	Gujrani Minor	Harita Minor	Haluwas Minor	Balsmand New Sub-Minor
4.37 lacs	2.62 lacs	(a) 30,400 for Jhalar Irrigation (b) 1,08,000 for pump irrigation	(a) 26.55 lacs for lined (b) 37.18 lacs for unlined	3.0 lacs	3.58 lacs	1.03 lacs
5730 acres 5160 acres Tosham, Dadam, Saral, Janauri, and Kharkai	3500 acres 3150 acres Charan, Biran, Riwasa	610 acres 550 acres Nalwa Khanak	19610 14723 Malwas, Deosar, Kasumbi, Biwasa, Bajina, Dhani, Mohu, Kairu, Sungerpur, Karia Bas, Kuhar Simli Balas, Sandhwa, Nigana Kalan, Jitwan Bas, Manashpur	2950 2655 Bura, Garampura, Chapper-Jogian	8095 acres 5077 acres Pehladgarh, Nimriwali, Haluwas Dhani Madian and Bhiwani	— 2000 acres Balsmand, Sarsana Ruhlalan and Bharian
Total 13.0 (a) 4.4 Cs. (b) 8.6 Cs.	12.4	1.5CS.	41 Cs. for lined 45 Cs. for unlined	5.3 Cs.	13.500	9.0 Cs.
For (a) 18.0 For (b) 20′	18.5	6.7′	6.37′ at 28000 of Gujrani minor 40′ at Kairu minor	20′	The lift area is insignificant which will be provided lift irrigation by the cultivators themselves	Nil
Rs. 72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	59.00	—

8 Cor.p pattern	K-Sugercane 240 Bajra 1050 R—Wheat 830 Gram 460	K—788 Bajra 360 Fodder 360 S. Cane 68 R Wheat 787 Wheat 500 Gram 287	KH Sugarcane 20 Maize 18 Wheat 112 Gram 25	K 3680 Maize 1400 Bajra 1400 S. Cane 880 R. Wheat 2500 Gram 300 S. Cane 880	K 823 Bajra 300 S. Cane 230 Fodder 293 R. Wheat 823	—	—
9. B.C. Ratio	4.51.1	4.85·1	2.35.1	1.92.1 for lined 2.05.1 for unlined	6.96.1	—	—
10. Length of channel	17,100	8,000′	9,000	85,000	34,000	38,500 ft. or 77 miles	20,000 ft.
11. Offtake	R.D. 54.47 of Bhurtana minor	R.D. 72,250 of Dong minor	R.D. 26922	Tail (R.D. 8100 of Gujrani minor	R.D. 40,000	R.D. 1,91,750 Bhiwani Disty.	R.D. 21000—L Balsmand Sub Minor
12. Annual loss	18,235	8,896	3627	2,23,000 for lined 1,97,000 for unlined	13,708	—	Rs. 2,060
13. No. of pumps	3×4 Cs.	2×4 Cs.+1 Stand-by	1×1.5 Cs.+1	Pumping station 28,000 or Gujrani minor 6—1 12,000 of Kairu minor+6+1 27,000 of Kairu minor+5+1 29,500 of Kairu minor+4+1 62,000 of Kairu minor+2+1 23+5	2—3 Cs.+1	—	—

Note:—Scheme relating to the Remodelling of Chaudhry Minor and its lining, covering the following villages, has not been included because the work on its execution has since been started out of the funds provided by the Irrigation Branch:—

1. Hindwas, 2. Nathawana, 3. Kurari, 4. Patan, 5. Wokas, 6. Kirari, 7. Dobi, 8. Sundwas, 9. Siswal, 10. Telanwali, 11. Kutari Kheri, 12. Chaudhriwali, 13. Ghursal.

[Chief Parliamentary Secsetary]

STATEMENT IN RESPECT OF CALL-ATTENTION NOTICE NO. 155, REGARDING ALLEGED REVERSION OF KANUNGOES BELONGING TO BACKWARD CLASSES IN DISTRICT AMRITSAR

Government instructions regarding reversion of Scheduled Castes and Backward classes employees were rightly followed in Amritsar District and there has been no deviation. No officiating Kanungo belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes has been reverted. However, only 5 officiating Kanungos belonging to the Backward classes have been reverted in Amritsar District as they were in excess of the quota fixed for them (Bacward Classes).

STATEMENT IN RESPECT OF CALL-ATTENTION NOTICE No. 162 REGARDING APPOINTMENT OF A COMMITTEE BY THE GOVERNMENT TO REVISE THE RATE OF BURNT BRICKS IN THE STATE

The Punjab Government has appointed a Committee to examine the question of increase in the rates of bricks. It is a fact that the District Magistrate, Hoshiarpur has permitted the Director of Inspection and Control, Beas Project to obtain bricks from the departmental brick-kilns at the rates approved by the Beas Control Board which are higher than those at which the other kiln-owners are required to sell in the Hoshiarpur District. It was urged by the Beas Project authorities that the consumption of coal for brick burning was higher in the area and varied from 29 to 53 tonnes per lac of pacca bricks and this was attributed to the location of kilns adjacent to the green hills from which there is a constant percolation. He also pointed out that the quality of coal supplied to the Project was not of a high standard and, as such, there was higher consumption of coal per lac of bricks. On these grounds, an exemption was no doubt given for the departmental kilns from the operation of the Bricks Supplies Order, 1956 in the interest of the Beas Project.

Restrictions on the removal of earth up to three feet have been imposed on the brick-kiln-owners on the ground that the water-table in the Hoshiarpur District is very high. All the same, the State Government will go into this question further at the time of the consideratipn of the report of the proposed Committee appointed to go into the question of the revision of brick prices.

STATEMENT BY SHRI CHAND RAM, WELFARE AND JUSTICE MINISTER ON CALL-ATTENTION NOTICE No. 179 GIVEN BY GIANI ZAIL SINGH REGARDING ACQUISITION OF FERTILE LAND IN VILLAGE KANSAL KHOL, TEHSIL KHARAR. DISTRICT AMBALA FOR THE PURPOSE OF AFFORESTATION IN THE STATE

The following area in village Kansal Khol have been acquired under the Land Acquisition Act, 1894:—

		Acres
Agricultural Land	..	120.65
Waste Land	..	2,035.16
Total	..	2,155.81

The entire area of village Kansal Khol forms the catchment of the Capital in the outer Hills which has been subject to accelerated erosion. The land in the hills behind Chandigarh Capital, including bits of cultivated land in village Kansal Khol, has been acquired in the interest of existence of the Capital itself by the stabilisation of the water regime in the area and reduction of the siltin-up of Sukhna Lake. No doubt an area of 120.65 acres of agricultural land is included in it but over 2000 acres is waste land which shows the magnitude of soil erosion and the urgent necessity of proper soil and water conservation management in this area. This cultivated area consists of small pockets of agricultural land and for various reasons it will not be possible to leave out these small bits. Moreover, the retention of any such cultivated pockets would involve not only erosion of cultivated land but the maintenance of cattle will damage other land also. Obviously there is a serious need for taking proper soil conservation and water preservation measures to protect the Sukhna Lake and Chandigarh. The acquisition of the land, in question, having since been made under proper process of law, it will not be advisable to release this area for agricultural purposes.

STATEMENT IN RESPECT OF CALL-ATTENTION NOTICE No. 172 REGARDING RETRENCHMENT OF NEARLY 300 SECTIONAL OFFICERS AT TALWARA AND THREE OTHER DRAIN DIVISIONS

On account of abolition of three Drainage Divisions (namely, Gurdaspur, Bhatinda and Muktsar) with effect from 10th November, 1965, 83 Sectional Officers became surplus, out of which 7 Sectional Officers were posted to other Circle against existing vacancies and the remaining 76 Sectional Officers were allocated to Beas Project Administration at Talwara for absorption against existing vacancies or by retrenchment of junior Sectional Officers. Notices of retrenchment to about 15 Sectional Officers recruited through Employment Exchange were given by the Beas Project Administration but subsequently extra posts became available and no retrenchment of any Sectional Officer at Talwara has taken place so far.

2. The following steps have been taken/will be taken to provide for alternative jobs to the retrenched/likely to be retrenched Patwaris and Clerks of the Consolidation Department:—

(a) the Clerks/Patwaris who have liens in other Departments have been sent back to those Departments on their original posts;

(b) In accordance with the instructions issued in the year 1961, 100 per cent vacancies up to the Naib-Tahsildar level have been reserved in the Revenue Department for the retrenched/likely to be retrenched staff of the Consolidation Department with effect from 3rd April, 1961;

(c) Instructions have also been issued to Heads of Departments etc. to reserve 50 per cent vacancies in their Departments for the retrenched/ likely to be retrenched staff of the Consolidation Department.

The lists of staff retrenched/likely to be retrenched have since been supplied to the S.S.S. Board/Chief Secretary, Punjab for necessary action for the absorption of these officials.

डिप्टी स्पीकर साहिबा, कुल 223 काल-अटेंनशन मोशन्ज़ आई जिन में से सिवाए 15, 16 के बाकी सबकी स्टेटमेंट्स टेबल पर ले की गई हैं ; मैम्बर साहिब को कुछ गलतफहमी थी ।

MOTION UNDER RULE 15

Chief Parliamentary Secretary (Shri Ram Partap Garg) : Madam, I beg to move—

That the proceedings on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly, indefinitely.

Deputy Speaker : Motion moved—

That the proceedings on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly, indefinitely.

Deputy Speaker : Question is—

That the proceedings on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly' indefinitely.

The motion was carried.

MOTION UNDER RULE 16

Cbief Parliamentary Secretary (Shri Ram Partap Garg) : Madam I beg to move—

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned *sine die.*

Deputy Speaker : Motion moved—

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned *sine die.*

Deputy Speaker : Question is—

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned *sine die.*

The motion was carried.

REPORT OF THE COMMITTEE OF PRIVILEGES

(*Motion for Fxtention of time*)

Shri Niranjan Singh Talib (Chairman, Committee of Privileges) : Madam, I beg to move—

That the time for the presentation of the final report of the Committee of Privileges on the question of privilege arising out of Government instructions prohibiting its employees to approach legislators be extended up to the 31st December, 1965.

Deputy Speaker : Motion moved—

That the time for the presentation of the final report of the Committee of Privileges on the question of privilege arising out of Government instructions prohibiting its employees to approach legislators be extended up to the 31st December, 1965.

श्री बलरामजी दास टंडन : क्या यह काम 31 दिसम्बर तक हो जायगा ? कहीं फिर एक्स्टैन्शन न मांगनी पड़े ।

Deputy Speaker . He is the Chairman, he knows better.

श्री बलरामजी दास टंडन : देखने में यह आया है कि काम नहीं हो पाता तो बार बार यहां पर लाना पड़ता है, अभी बेशक जनवरी तक ऐक्स्टैनशन मांग लें ......

उपाध्यक्षा : मेरी बात तो दोनों तरफ के लोग नहीं सुनते । मैं भी ऐसी मोशंज बारबार यहां लाने के खिलाफ हूँ । (Members from both the sides do not pay any heed to what I say. I am also against bringing of such motions again and again in the House).

सरदार निरंजन सिंह तालिब : 25 अक्तूबर को यह रैफर किया गया और यह पहली दफा है कि हम एक्स्टैन्शन मांग रहे हैं । '(विघ्न)

Deputy Speaker : Question is—

That the time for the presentation of the final report of the Committee of Provileges on the question of privilege arising out of Government instructions prohibiting its employees to approach legislators be extended up to the 31st December, 1965.

The motion was carried.

STATEMENT BY THE CHIEF MINISTER REGARDING PUNJAB DEFENCE AND SECURITY RELIEF FUND

Chief Minister (Shri Ram Kishan) : Madam, Deputy Speaker, the Punjab Defence and Security Relief Fund was instituted in the middle of September, 1965, with a view to enable the people of Punjab to contribute towards the Defence efforts of the State. According to the Government Notification, issued in this behalf, the Fund is intended to be utilised for the welfare of the Punjabi Jawans of the Armed Forces, Punjab Armed Police, and the Home Guards, who may sustain injuries and the families of those who may lose their lives in action besides the families of those who may die in the cause of the country.

2. For the administration of the Fund, a Committee known as the Punjab Defence and Security Relief Fund Committee has been constituted. This Committee consists of :—

Chief Minister	..	Chairman
Home & Development Minister	..	Member
Finance Minister	..	„
Education Minister	..	„
Transport and Elections Minister	..	„
Irrigation & Power Minister	..	„
Public Works Minister (to be included)	..	„
Lt.-General Kulwant Singh (Retd.)	..	„
Major General G. C. Katoch (Retd.)	..	„
Col. Kadam Singh (Retd.)	..	„
Wing Commander Chhatar Singh (Retd.)	..	„
Chief Secretary	..	„
Home Secretary	..	„
Finance Secretary	..	„
Special Secretary to Chief Minister	..	Member-cum-Secretary

3. The first meeting of the Committee was held on the 6th October, 1965. It was decided that missing persons or prisoners of war should also be included among the persons entitled to relief from the fund. Similarly, those civilians who are injured and the familles of such persons who may die of injuries, sustained while engaged in the defence of the country should also get relief from the fund. It was further decided that such civilians who have done conspicuous service in the defence of the country, should also be entitled to relief from the fund.

[Chief Minister]

4. By-laws in regard to disbursement of grants from this fund are being framed by the Committee. In the meanwhile the Committee has approved payment of grants amounting to Rs. 21,629.97 from this Fund.

5. The question of authorising educational institutions to make collections for this Fund was discussed by the Education Minister with me near about the 18th of September, 1965. Collections for the Fund on behalf of the Education Department commenced during first week of October and came to close on 10th of November.

The Education Minister then brought to my notice that the students and the teachers in various educational institutions had expressed a desire that a part of the fund, collected by them should be utilised for the welfare of the children of Army personnel of other States who laid their lives in the Defence of the country. Uptill then contributions amounting to a little above 3 crores had been received in the Punjab Defence and Security Relief Fund. This amount also includes about 50 lakhs collected by the educational institutions. In deference to the wishes of the donors and teachers of educational institutions, a sum of Rs. 25,000 each has been remitted to Chief Minister, Jammu & Kashmir State, Union Home Minister, Union Education Minister and Union Minister for Information and Broadcasting on behalf of the Punjab Government to be utilised for the benefit of the children of Army personnel of other States who laid their lives for the defence of the country. *Post facto* approval of the Committee for the administration of the fund will be obtained in respect of these disbursements.

6. I would like to assure the Hon'ble members of the House that proper accounts of this fund is being maintained, these accounts will be got audited in due course and wishes of the Members in the matter of disbursement of grants from the fund would be duly respected in future.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਕ ਦੋ ਕਲੈਰੀਫੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਦੇ ਬਚਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਚਿਲਡਰਨ ਅਤੇ ਟੀਚਰਜ਼ ਨੇ ਵਿਸ਼ਿਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ?

ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਐਡਮਨਿਸਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਡਿਸਬਰਸਮੈਂਟ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ? ਫਿਰ ਇਹ ਰਕਮ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਕ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੂਰ ਕਰਨ । ਸ਼ਕ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਨਿਸਟਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਨਟਰੈਸਟ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬੀ

ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਐਨਟੈਗੋਨਿਸਟ ਹਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਨਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਨ । ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨ ਟੈਗੇਰਿਟੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਅਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਨਿਸਟਰ ਨੇ ਰੁਪਿਆ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮਨਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫਲੂਅੰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇਨਡੀਵਿਜੂਅਲ ਮਨਿਸਟਰ ਦਾ ਤਅਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਦੇ ਬਚਿਆਂ ਲਈ ਰੁਪਿਆ ਦੇਣਾ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡੀਫੈਂਸ ਮਨਿਸਟਰ ਚਵਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਪਰਸਾਨਲ ਦੀ ਲਿਸਟ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪ ਐਡਮਨਿਸਟਰ ਕਰਦੇ । ਫਿਰ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ । ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਮਨਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਬੇਸਿਜ਼ ਤੇ ਸੀਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ?

ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ (ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ) : ਮੈਂ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਐਡਮਨਿਸਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਐਪਰੂਵਲ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ । ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਹੀਂ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਹਸ਼ਾਤ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ।

ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰਾਏ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਵੈਸਚਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਫੰਡ ਦੇ ਦੇਣ ਦਾ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਵਾਸਤਾ ਕਿਸੇ ਪਾਲੇਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨਾਲ ਹੈ । ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮਨਿਸਟਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਂਟਰਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਮੁਖਤਲਿਫ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਏਅਰਫੋਰਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ।

ਇਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫੰਡ ਸੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ 25 ਲਖ ਤਕ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ 50 ਲਖ ਤਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸਟੂਡੰਟਾਂ ਨੇ ਰੁਪਿਆ ਦੇਣ ਲਗਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਾਡੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਬਚੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁਡ ਵਿਲ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਰਕਮ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਥੇ ਦੇ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ ਦੇ ਬਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।

(ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਵਲੋਂ : ਇਹ ਬਿਲਕਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ।)

[ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ]

ਫਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਡਿਪਟੀ ਕਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਫਸਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਜੋ ਸੈਕੰਟਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਇਕ ਪੈਸਾ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇਕਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਾਈ ਲਾਜ਼ ਬਨਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਖਿਆਲ ਪਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ।

(ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਕਲੈਰੀਫੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ।)

(*Interruption*)

उपाध्यक्षा : मैं हाऊस के मैम्बरों से दरखास्त करना चाहती हूँ कि इस फण्ड के सिलसिला में पंजाबी सूबा या हरियाणा प्रांत की बातला करन पूछी जाए। और इस बात की आप क्लैरीफिकेशन आप ले सकते हैं कि यह रुपया जो पंजाब में इकट्ठा किया गया है सूबे से बाहर जाना चाहिए या नहीं ? (I would like to request the hon. Members not to refer to the formation of Punjabi Suba or Hariana Prant while seeking any clarification. They may ask for the clarification whether the funds collected in this State should be allowed to be sent out of the State or not.)

चौधरी देवी लाल : मैं डिप्टी स्पीकर साहिबा इस बात की क्लैरीफिकेशन चीफ मिनिस्टर से चाह रहा हूँ कि हिन्दुस्तान के लोगों की तरफ से इस बात पर ज़ोर दिया जा रहा है कि पंजाब की मदद करनी चाहिए क्योंकि लड़ाई पंजाब में लड़ी गई और जब कि सैंटर की कैबिनिट खुद इस बात को मान रही हो कि लड़ाई पंजाब में हुई और इसका भार पंजाब पर बहुत है तो फिर यह रुपया क्यों सैंटर को दिया गया ? लड़ाई पंजाब में लड़ी गई इन्डस्ट्री बंद हो गई और जब फौजी सामान पहुंचाना था तो इस सूबे की सारी ट्रांस्पोर्ट ने अपने आपको आफर किया और सामान पहुंचाया। इस बात की परवाह नहीं थी कि लड़ाई पंजाब की है या सारे हिन्दुस्तान की है और क्योंकि यह लड़ाई सारे हिन्दुस्तान की थी, इसलिये उन्होंने मदद की और अब सारे हिन्दुस्तान को पंजाब की इमदाद करनी चाहिए थी जिसका माल और जान का भारी नुक्सान हुआ है। लेकिन यहां पर उल्टे बांस बरेली को। क्यों हम कहां के धनाढ्य हैं, और हम कब से करोड़पति बन गये कि अपना रुपया बाहर को भेज दें ? (विघ्न)

Chief Parliamentary Secretary : Is it point of a clarification ?

Deputy Speaker : Order please. आपको अगर किसी बात पर एतराज़ हो तो आप प्वाइन्ट आफ आर्डर पर खड़े होकर कह सकते हैं। इस तरह आप बगैर इजाज़त के खड़े हो कर बोलने लग जाते हैं। (Order please. If the Chief Parliamentary Secretary has got some objection to raise he can rise on a point of order. He starts speaking without getting the permission of the Chair.)

मुख्य संसद सचिव : मैं तो यह अर्ज़ कर रहा था कि क्या यह क्लैरीफिकेशन ले रहे हैं ?... (विघ्न) (noise.)

चौधरी देवी लाल : मैं तो अर्ज़ कर रहा था कि इन्हें शायद पटियाला का डर है....।

उपाध्यक्षा : No please. गर्ग साहिब को प्वायंट आफ आर्डर रेज़ करने का उतना ही हक है जितना कि और किसी मैम्बर को। लेकिन प्वाइंट आफ आर्डर पर खड़े होकर इधर उधर की बातें नहीं की जा सकतीं। (No please. The Chief Parliamentary Secretary has got the same right to rise on a point of order as other hon. Members enjoy. But no extraneous matters can be allowed to be raised through a point of order.)

मुख्य संसद सचिव : आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, मैडम।

चौधरी देवी लाल : मैं यह पूछना चाहता हूँ और इस बात पर क्लैरिफिकेशन चाह रहा हूँ.........

Deputy Speaker: (Addressing Chaudhri Devi Lal) There is a point of Order by the Chief Parliamentary Secretary Chaudhri Sahib.

Chief parliamentary Secretary On a point of order, Madam. Madam, Deputy Speaker, there can be no discussion on a Statement.

Deputy Speaker : It is for me to decide and not for you. Mind your own business.

मुख्य संसद सचिव : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरी अर्ज़ यह है कि क्या कोई प्वाइन्ट आफ क्लैरीफिकेशन पर खड़ा हो कर पंजाबी सूबा और इस तरह की तंग दिली की बातें कर सकता है ?

Sardar Gurnam Singh: I refer to rule 112.

मुख्य संसद सचिव : मेरी अर्ज़ यह है कि इस क्लैरीफिकेशन पर खड़े होकर बोलने वाले को सावन का हरा ही हरा नज़र आता है (विघ्न) (शोर) और पंजाबी सूबा और हरियाणा प्रांत का ही खाब आता है क्या यह ठीक है ?

Sardar Gurnam Singh : This is wasting the public funds.

(*Interruptions*)

उपाध्यक्षा : अगर आपने मेरी बात को सुना होता तो यह प्वाइन्ट रेज़ न करते। मैंने पहले ही कहा है कि यहां पर पंजाबी सूबा या हरियाणा प्रांत की बातें न की जाएं, सिर्फ इतनी ही बात कहनी चाहिए कि फन्ड जो यहां पर इकट्ठा किया गया है यहां पर ही खर्च होना चाहिए या सूबे के बाहर ? (Had the hon. Member listened to what I have said earlier he would not have raised this point. I have already said that the hon. Members should not mention about the formation of Punjabi Suba or Hariana Prant. They can ask as to whether the funds collected here can be spent in the State or whether these can be sent out of State.)

(*Interruptions*,)

चोधरी देवी लाल : जहां तक इस लड़ाई का ताल्लुक है मैंने बतलाया है कि इसका सारा बोझ पंजाब पर है इस लिये हमें दूसरी स्टेटों से मदद लेनी चाहिए थी और वहां से आनी चाहिए थी और इधर पच्चीस पच्चीस हज़ार दूसरी स्टेटों के मिनिस्टरों को दे दिया इसका साफ मतलब यह है कि हमें बाहर की मदद की कोई ज़रूरत नहीं। (विघ्न)

(चौधरी देवी लाल)

जहां तक इस रकम की डिसबर्समेंट का ताल्लुक है इन्हों ने जो कमेटी बनाई है उसमें भी आफीसर्ज़ ही लिये हैं चाहे वह रिटायर्ड हैं लेकिन जो फन्डज़ इक्ट्ठे किये गए यह किसी एक पार्टी ने नहीं किये, तमाम पार्टियों ने किये हैं और हरेक आदमी का हक है कि वह इस फन्ड की डिसबर्समेन्ट में अपनी राए दे सके। फिर क्यों बाकी की पार्टियों को नहीं लिया गया ? (विघ्न)

उपाध्यक्षा : मैंने स्टेटमेंट देने के लिये इसलिये सरकार को कहा था कि सारी बात आ जायगी और आपने इस की बात को इतना लम्बा कर दिया है। अगर इस पर और वक्त ले लिया गया तो बिल पर विचार करने का समय नहीं रह जायगा। इस पर क्लैरिफिकेशन चाहने पर अब यह कहा जा रहा है कि कमेटी ने फैसला किया है या नहीं और जो कमेटी बनाई गई है इसमें आपोज़ीशन को क्यों नहीं लिया गया। यह मुनासिब नहीं। (I had requested the Government to give a Statement on this issue so that the whole matter should come before the House. But the hon. Members have stretched this matter too far. If more time is taken on this issue then little time will be left for the discussion of the Bill. While seeking clarification on this point, fresh points, viz. whether the committee has taken a decision on it or not, why the Members from the opposition have not been taken on this Committee, are being introduced. This does not seem proper.)

11-00 a.m.

चोधरी देवी लाल : मैं प्वायंट आफ क्लैरिफिकेशन पर खड़ा था। मेरे कहने का मतलब हरगिज़ यह नहीं था जैसे यह सरकार सोच रही है या जैसे चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी साहिब सोच रहे हैं। वह अपने आपको पटियाला से आकर चमका रहे हैं। उन की इंटैगरिटी पर, ठीक है, शक नहीं किया जा सकता क्योंकि 9 सिक्ख तो बैठे हैं मगर यह एक हिन्दू चमकते नज़र आ रहे हैं। (*Interruption*)

मुख्य संसद सचिव : On a point of order, Madam, मैं तो यह अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो स्टेटमेंट दिया गया है इसमें पटियाला का बिल्कुल भी कोई ज़िक्र नहीं है। यह समझ नहीं आता चौधरी साहिब क्या बात कह रहे हैं।

चौधरी देवी लाल : मैडम, मैं तो सिर्फ इस बात की क्लैरीफिकेशन चाहता हूँ कि जो प्वायंट आफ आर्डर गर्ग साहिब ने मुख्य मंत्री की स्टेटमेंट के मुताल्लिक रेज़ किया, वह भी मेरी क्लैरीफिकेशन से संबंधित है। मैं तो यह जानना चाहता हूँ कि जब फैसला हो चुका था कि आपोज़ीशन के मैम्बर्ज़ लिये जायेंगे तो फिर इन कमेटियों में आपोज़ीशन के मैम्बर्ज़ क्यों नहीं लिये गये ?

श्री रूप लाल महता: मैं यह रूलिंग चाहता हूँ कि मुख्य मंत्री के स्टेटमेंट दे देने के बाद क्या कोई बहस जारी की जा सकती है ?

उपाध्यक्षा : जैसे मैं आपको चैक नहीं कर सकती, दूसरों को भी मौका मिल जाता है। (Just as I cannot check the hon. Member, others also avail of the opportunity.)

श्री बलरामजीदास टंडन : On a point of Order, Madam, जहां पर लोग मौजूदा हालात के मुताबिक इस सरकार से रिलीफ मांगना चाहते थे, उन्होंने अपनी तकलीफात को भूल कर इस सरकार की इमदाद की। सरकार को रिलीफ फंड की जो भी कुलैक्शन हुई, वह किसी एक फिर्का के सवाल पर या किसी एक पार्टी के सवाल पर नहीं की गई। मैं समझता हूँ कि आज इस तरह की बातें करना कि किसी एक तबके का ही हक है, इस जायंटली कुलैक्टिड फंड की वही देने के हक्कदार हैं, यह मुनासिब नहीं होगा। खुद हम तकलीफ में हों और दूसरों के लिये किसी तरह की फराख दिली दिखायें, या इधर के फंड्ज़ सैंटर के लोगों को खुश करने के लिये दें यह मुनासिब नहीं होगा।................

उपाध्यक्षा : प्वायंट आफ आर्डर का यह मतलब नहीं है कि जो भी मुंह में आये वह कह दिया जाये। I would not allow that. (Point of order does not entitle one to say what ever comes in his mind. I would not allow that)

श्री बलरामजी दास टंडन : इन फंडज़ को डील करने की सारी ज़िम्मेवारी पंजाब सरकार की है या इनको आपोज़ीशन पार्टीज़ के सहयोग की भी ज़रूरत है, मैं तो सिर्फ यही बात इनसे पुछना चाहता हूँ।

Deputy Speaker : There is no question of opposition.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ : On a point of clarification, Madam.

* * * * *

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਪੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। (Whatever has been said in relation to Shri Lal Bahadur Shastri, will be expunged.)

Pandit Chiranji Lal Sharma : Madam, Deputy Speaker, I have heard the statemeht read out by the hon. Chief Minister just now, and am simply stunned to see the constitution of the committee for the disbursement of the collections that have been made. Madam, Deputy Speaker, in this holy job, I call it a holy job, no fair representation has baen given to us i.e. the Members sitting on this side of the House.

उपाध्यक्षा : सवाल तो महज़ इस वक्त यह है कि Education Minister ने 4 सैंटर के मिनिस्टर्ज़ को 25–25 हजार रुपया दिया वह मुनासिब था या कि नहीं। कमेटी की फारमेशन इस वक्त अंडर डिसकशन नहीं है। (The point at issue, at the moment is whether a sum of rupees twenty-five thousands each given to the four Central Ministers, by the Education Minister was proper or not. The formation of the Committee is not under discussion at present.)

पंडित चिरंजी लाल शर्मा : अब अगर कोई बात इस फंड के मुताल्लिक करनी हो तो किस से करें ? The House is going to adjourn to-day. जहां तक कुलैक्शन का सवाल है, we give unstinted co-operation अब अगर आज सारी पावर ही गवर्नमेंट लेकर बैठ जाये तो इसका क्या इलाज है ? आपोज़ीशन को कोई पूछता तक नहीं। अब कदमसिंह जो करे वह सही है हमारा जैसे इस कुलैक्शन से कोई वास्ता ही नहीं। हर बात में हमारे साथ सौतेली मां का सलूक किया जाता है। इस सिलसिला में अगर कोई कमेटी बनाई

Note.—Expunged as ordered by the Chair.

पंडित चिरंजी लाल]

जाती है तो हमें पूछा तक नहीं जाता । हमें totally ignore करने की कोशिश की जाती है। कुलैक्शन के लिये हमें पुकार पुकार कर कहते हैं कि हमारा साथ दो मगर डिसबर्समेंट के वक्त कोई बात नहीं पूछता ।

उपाध्यक्षा : चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट आ जाने के बाद बहस का जारी रखना वाजब नहीं है । There must be some end to it. (It is not desirable to continue this controversy after the Chief Minister has made a statement. There must be some end to it.)

ਕਾਮਰੇਡ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ: ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ: ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਫੌਜ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਰਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ । ਇਹ ਫੰਡ ਇਸ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰਲੇ ਮਨਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਨੂਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਸਾਨੂੰ ਦਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਸੀਬਤ ਜ਼ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ?

ਦੂਸਰੀ ਗਲ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਮਦਾਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਾਏ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਈਮਾਨਦਾਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ । ਕੀ ਇਹੋ ਹੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ?

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਜਦੋਂ ੍ਰੀ ਪਰਬੋਧ ਚੰਦਰ ਸਪੀਕਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਰਕਸ਼ਾਬੰਧਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਕ ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਇਸ ਦਾ ਪਰਪਜ਼ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਜਾਂ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ । ਕੀ ਸ੍ਰੀ ਪਰਬੋਧ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫੰਡ ਚੁਕਾ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ?

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਕੁਝ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਤਨਾ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ I am giving it to that gentleman, the Minister as a token of love......

Deputy Speaker : What token of love ?

Sardar Gurnam Singh : This can be explained by the hon. Minister himself. The amount there was given as a token of love to be used by the Minister to whom it was presented, wherever he liked. Today the position taken by the Government is that the amount has to be used in a limited sense. So it needs clarification from the Government.

चौधरी नेत राम : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडम । मैं आपसे रूलिंग चाहता हूं, वैसे तो मैं डिफैन्स फंड के बिल्कुल खिलाफ हूँ और डिफेंस रैली के खिलाफ हूँ जो सरकार करती है । यह कांग्रेस पार्टी के वकार को कायम रखने के लिये करती है लेकिन मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि क्या यह डिफेंस फंड एमरजेंसी में सरकारी तौर पर इकट्ठा किया जाता है जैसे कि बाकी दूसरे टैक्स जनता से लिये जाते हैं । और खजाने में जमा होते हैं और वह टैक्स सरकारी तौर पर खर्च किया जाता है तो बाकायदा हर मद पर असैंबली में बिल पेश होता है और मन्जूरी ली जाती है । तो यह फंड सरकारी तौर पर मांगा जाता है या प्राइवेट तौर पर इसकी उगराही की जाती है ? जब यह प्राईवेट तौर पर उगराहा जाता है तो कांग्रेस सरकार ने जनता से धोखा किया है, तो क्यों नहीं बाकायदा तौर पर खजाने में जमा करके मंजूरी ली जाती ? डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आपसे दरखास्त करूँ कि क्या चीफ मिनिस्टर साहिब को यह अधिकार है कि धार्मिक स्थानों पर जाकर भाषण करें ? किसी संत, चेले या गुरु को जाकर भाषण दें ?

* * *

उपाध्यक्षा : जो कुछ अभी कहा है यह एक्सपंज कर दिया जाए । (Whatever has been said just now will be expunged.)

Sardar Gian Singh Rarewala : Madam, I strongly lodge my protest against the indifference shown to me. I have risen several times to seek certain clarifications but was not given time although long speeches have been made from the other side. I want to seek clarification from the hon. Chief Minister about the statement made by him just now in the House.

उपाध्यक्षा : राड़ेवाला साहिब, आप पहले यह बता दें कि क्या यह प्रोटेस्ट चेयर के खिलाफ है ? (Addressing Sardar Gian Singh Rarewala) (The hon. Member may first clear this point whether his protest is against the Chair.)

ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ : ਮੈਂ ਪੰਜ ਛੇ ਦਫਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੜਿਆਂ ਦੇਖਿਆਂ ਨਹੀਂ । ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪੁਛਣਾ ਹੈ ਪੁਛ ਲਓ । (I have not seen you standing. You may now have your say.)

Sardar Gian Singh Rarewala : Madam, I want to know from the Hon. Chief Minister whether he had agreed to those donations or not ? The statement made by him is silent on this point. I also want to know what will be the position of the Government if *post-facto* sanction in respect of these disbursements is refused by the Committee for the administration of the fund ?

Note—Expunged as ordered by the Chair.

मुख्य मंत्री (श्री राम किशन) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरा बयान काफी जामे और वसीह था । लेकिन इस पर कुछ आनरेबल मैंबरान ने कुछ क्लैरीफिकेशन के लिये कुछ तकरीरें की हैं । इसमें एक बात जो श्री चिरंजीलाल जी ने उठाई उनकी सेवा में मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इस कमेटी को इस प्वायंट आफ व्यू से नहीं बनाया गया कि हिन्दी और पंजाबी रिजन का सवाल हो। लेकिन इसके बावजूद वह इस बात को एप्रिशियेट करेंगे कि इसमें आई.पी.एम. के सिवा पी. डब्ल्यू, मिनिस्टर भी इन्क्लूड होंगे । इसमें मेजर जनरल कटोच, विंग कमांडर छतर सिंह और कर्नल कदम सिंह भी शामिल हैं । इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं कि इसमें हरियाणा को इनक्लूड नहीं किया । हरियाणा ने बहुत कुरबानी की है । नेशन उसकी कदर करती है । सरदार गुरनाम सिंह जी ने एक सवाल उठाया था । मैंने वाज़ेह कर दिया था और अब फिर वाज़ेह करता हूँ कि जो रुपया भी वहां सेंटर के मिनिस्टरों को दिया है वह आर्मड परसनेल या ऐयर फोर्स वालों के बच्चों मदद के लिये है और उससे उन्हें एजुकेशन दी जाएगी। हाउस को इस बात को एप्रीशिएट करना चाहिए । पंजाब में दूसरी स्टेट्स के परसनल और ऐयर फोर्स वाले हैं वह पंजाब के लिये और सारे देश के लिये लड़े हैं । उन्होंने कुरबानियां की हैं । उनके बच्चों के लिये दिया है। मैंने अपनी स्टेटमेंट के आखिर में हाउस को इस बात का यकीन दिला दिया था । अब अगर मैं वह आखिरी फिकरे पढ़ूं तो पता लगेगा । वह इस तरह है :

> "I would like to assure the Hon'ble Members of the House that proper account of this fund is being maintained, these accounts will be got audited in due course and wishes of the Members in the matter of disbursement of grants from the fund would be duly respected in future."

इसके साथ मैंने यह अर्ज़ किया था कि जितना भी यह पैसा दिया है पैसे पैसे की इस कमेटी से एप्रूवल ली जायेगी । उसके मुताबक बाई-लाज़ बनेंगे और उसके मुताबिक वह एप्रूवल देंगे । इस बात को एप्रिशिएट करना चाहिए कि बजाए इसके कि चीफ मिनिस्टर दो तीन को साथ मिला लेता और इस फंड को दे देता, मैंने एक जामे कमेटी बनाई । रिटायर्ड जनरलज़ को और (*Voice* Opposition?) आफीशियल्ज़ को भी इसमें रखा है । इसका पालेटिक्स के साथ दूर या नज़दीक का कोई वास्ता नहीं । इसलिये मैं आप से बड़े अदब से कहना चाहता हूँ कि आपको.......... (विघ्न)

ਸ੍ਰੀ ਬਲਰਾਮ ਜੀ ਦਾਸ ਟੰਡਨ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਮੈਡਮ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਲੈਣ ਦਿਉ, ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। (Let him first have his say. It is not deriable to interrupt him.)

ਸ੍ਰੀ ਬਲਰਾਮਜੀ ਦਾਸ ਟੰਡਨ : ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਹਿ ਲੈਣਾ। not stand in the way of the hon. Member he may speak afterwords.)

मुख्य मंत्री : इस कमेटी को किसी भी नुक्ता निगाह से, पालिटिक्स के नुक्ता निगाह से नहीं बनाया गया और यह गवर्नमेंट तमाम भाइयों और बहनों की, जिन्होंने कि इसमें कुछ भी मदद दी है, उन सब की सर्विसिज़ को एप्रीशिएट करती हैं । उन तमाम की हम कद्र करते हैं । अच्छा

है कि बच्चों ने इस में पूरी तरह कंट्रीबयूशन किया है, इसको बच्चों के लिये इस्तेमाल करें। इसके मुताल्लिक सारे रूल्ज़ और बाई-लाज़ बनेंगे। तो मैं फिर एक बार सारे हाउस को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि किसी तरह से भी इसका एक पैसा भी नाजायज़ इस्तेमाल नहीं होगा, उसकी ठीक डिसबर्समेंट होगी। जो भाई और सजैशन देना चाहेंगे हम उसको पूरी कद्र की निगाह से देखेंगे।

श्री बलरामजी दास टंडन : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडम। मैं आपकी रूलिंग चाहता हूँ कि जब आपोज़ीशन के बारे में बात पूछी गई तो इन्होंने कहा कि मैं इसमें कोई पालिटिक्स नहीं लाना चाहता। अगर किसी कमेटी में आपोज़ीशन भी एसोशिएट हो जाए तो पालिटिक्स शुरू हो जाता है और अगर उसमें सब के सब कांग्रेस के रहें तो पालेटिक्स नहीं होता?

उपाध्यक्षा : उन्होंने कमेटी के मैंबरों के नाम दिए हैं। उस लिस्ट में सिवाए मिनिस्टरों के कोई कांग्रेस का मैंबर या कोई दूसरा असेंबली का मैंबर नहीं है। इस बात को यहीं छोड़ देना चाहिए। जो बात थी उसको साइड-ट्रैक करके इतना वक्त ले लिया। यह मुनासब नहीं। सब ने काफी कह लिया है। पहले कोई भी कमेटी नहीं थी, आगे के लिये बना दी है। (He has given the names of the Members of the Committee which includes no Congressman or any legislator except the Ministers. This matter should be dropped here. So much time has been consumed after side-tracking the real issue. Everybody has expressed himself sufficiently. Previously there was no Committee it has been constituted for future).

ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ : On a point of order, Madam. ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੋਂ Commercial Crop Cess Bill ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਾਰਾ time waste ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਪਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। (Thank you)

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : On a point of order, Madam. ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ notification ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਫਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ।

(No reply)

ANNOUNCEMENT BY THE SECRETARY

Secretary : I beg to lay on the Table of the House a statement showing the Bills which have been passed by the Punjab State Legislature during its current (Autumn) Session, 1965, and assented to by the Governor so far.

STATEMENT SHOWING THE BILLS WHICH HAVE BEEN PASSED BY THE PUNJAB STATE LEGISLATURE DURING ITS CURRENT (AUTUMN) SESSION, 1965, AND ASSENTED TO BY THE GOVERNOR SO FAR

1. The Punjab Appropriation (No. 3) Bill, 1965.
2. The Punjab Appropriation (No. 4) Bill, 1965.

BILL (S)

THE PUNJAB COMMERCIAL CROPS CESS (AMENDMENT) BILL, 1965

(Resumption of Discussion)

Deputy Speaker : Pandit Mohan Lal Datta was in possession of the House when it adjourned yesterday. He may resume his speech.

पंडित मोहन लाल दत्त (अम्ब) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, पेश करदा amending Bill पर कल मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ था लेकिन चन्द शब्द कहने के बाद ही सभा adjourn हो गई थी । मैं निवेदन कर रहा था कि हमारे देश पर पाकिस्तान के हमले के फलस्वरूप बड़ा महान् संकट आया है। उसका सामना करने के लिये देश को बहुत धनराशि की जरूरत है और उसके लिये देश-वासियों को, हरेक व्यक्ति को ज़यादा से ज़यादा कुरबानी करने के लिये तैयार होना चाहिए। इस taxation के सम्बन्ध में मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि यह जो small landowners हैं उन पर नावाजब बोझ डाला गया है। मैं इस हद तक इस बिल को support करता हूँ कि जो खुशहाल और धनी किसान हैं उन पर अगर cess लगा दिया जाए तो बुरी बात नहीं । मगर ऐसे बहुत कम अमीर आदमी हैं जिन पर इस संशोधन बिल का असर पड़ना है लेकिन इसके मुकाबले में छोटे मालिक बेशुमार हैं जिन पर बोझ डालना है। यह नामुनासिब बात है । यह जो agriculture का धंधा है इसमें दूसरे धंधों के मुकाबले में कोई ज़यादा आमदनी नहीं होती खास करके जो छोटे मालिक हैं इनकी तो हालत बहुत ही खराब है। बहुत मेहनत करने के बावजूद भी उन्हें पेट भर कर रोटी दस्तयाब नहीं होती। इसलिये वह tax अदा करने के काबल नहीं हैं (At this stage Shri Ram Saran Chand Mital, a member of the Panel of Chairmen occupied the Chair) चेयरमैन साहिब, Agriculture से सम्बन्ध रखने वालों की कई categories हैं। एक तो big landowners हैं जो 40/50 एकड़ ज़मीन रखने वाले हैं, उसके बाद large landowners हैं जिनके पास 100 एकड़ या उससे ज़यादा ज़मीन है। यह जो categories हैं यह cess अदा कर सकते हैं । इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने tenants को ज़मीन दी हुई है, हाथ से खेती नहीं करते, crop saving के तरीके से वह ज़मीन से आमदनी हासल करते हैं। यह लोग ज़मीन की income के अलावा बड़े-बड़े businessmen भी हैं, कोई हुकमरान बना बैठा है, कोई मंत्री है, कोई M. L. A. है। कहने का भाव यह है क वह बहुत खुशहाल हैं। उन पर अगर देश के संकट के समय कुछ cess लगा दिया जाए तो नावाजब बात नहीं है । मैं देख रहा हूँ आज यहां पर किसान के नाम पर उनको भी छूट दिलाने की कोशिश की जा रही है। यह सही

तरीका नहीं। सही तरीका taxation का यह है कि जो छोटे-छोटे हैं उनको छोड़ो और जो बड़े-बड़े हैं उनको मत छोड़ो। लेकिन इस policy पर अमल नहीं हो रहा। जब से देश आज़ाद हुआ है तब से जो बड़े-बड़े industrialists और धनी किसान हैं उनका गलबा इस कांग्रेस सरकार पर है। इस लिये यह तो इनके काबू आते नहीं। लेकिन बेचारे जो गरीब छोटे किसान हैं उन को रगड़ा जाता है। अगर industrialists पर tax लगें भी तो करोड़ों रुपये की evasion होती है। उनको कोई पूछने वाला नहीं। यहां कितने सुझाव दिये गए हैं। इधर से और उधर से किस तरह से defence के लिये और development के लिये करोड़ों रुपया हासिल किया जा सकता है मगर उनकी तरफ सरकार ध्यान नहीं देती। न ही हम से कोई मशविरा लिया जाता है। बल्कि Congress party वाले भी यहां protest करते हैं कि उनसे पार्टी में भी मशविरा नहीं लिया जाता। इसी लिये जब कोई बिल पेश होता था तो ज़यादा से ज़यादा उसकी विरोधता Ruling party से ही होती है तो मैं निवेदन करता हूँ कि जो lower basic holding और economic holding की categories में आते हैं उन की तादाद 90 % है। Economic hoiding वाले कौन हैं, क्या है जैसा इसकी Planning Commission ने definition की है इक्नामिक होल्डिंग की डैफीनीशन के बारे में प्लैनिंग कमीशन, और सरकार की लैंड रिफार्मज़ कमेटी के द्वारा दी गई रिपोर्ट में भी जिक्र हुआ है उन्होंने यह लिखा है कि नार्मल फैमिली के लिये इतनी जमीन दरकार होनी चाहिए जिससे वह एक हल के अन्दर काश्त कर सके। उसका स्टैंडर्ड आफ लिविंग भी एक हल के द्वारा काश्त की गई जमीन से भी मेंनटेन हो सकता है। (विघ्न)

एक आवाज़ : क्या यह डैफीनीशन पहाड़ी इलाके के बारे में है या मैदानी इलाके को भी कवर करता है ?

पंडित मोहन लाल दत्त : मैं मानता हूँ कि एक नार्मल फैमिली के लिये 15 एकड़ इरीगेटिड ज़मीन होनी चाहिए और बारानी इलाके में 30 या 40 एकड़ ज़मीन होनी चाहिए। इस तरह से वह लोग अपना स्टैंडर्ड आफ लिविंग भी मैनटेन कर सकते हैं। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि पहाड़ी इलाके के लोगों की हालत बहुत ही बदतर है। सरकार उनके ऊपर यह टैक्स लगा कर अन्याय कर रही है। पहाड़ी इलाके विशेषतया तहसील ऊना और ज़िला होशियारपुर के सब-माउन्टेनियस इलाके के बारे में डारलिंग साहिब ने किताब लिखी है। यह किताब बहुत ही मशहूर है। इस किताब का नाम पंजाब पीजेंट इन प्रासपैरिटी एंड डैट है। जैसा कि मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि इस में हिल्ली एरिया और सब-माउन्टेनियस इलाक के समाल लैंड-होल्डर की अच्छी तरह से तसवीर खींचने की कोशिश की गई है। अगर सरकार उस चीज़ को सामने रखती तो मुझे विश्वास था कि सरकार यह टैक्स लगा कर इन लोगों पर ज़ुल्म न करती। इस किताब के सफा 26 पर इस विषय में लिखा है। चेयरमैन साहिब, इसे आपकी इजाज़त से हाउस में पढ़ना चाहता हूँ। वह यह है कि—

> "Broadly it may be said that, without his second string to his bow, the Punjab peasant proprietor must always be in debt......"

[पंडित मोहन लाल दत]

It is further stated therein that—

"......In no tahsil is the average cultivated holding more than eight acres, and in every tahsil of Hoshiarpur it is no more than four or five. Now as Professor Carver points out, small holdings invariably mean small incomes, and in a backward country, where expenditure is less determined by income than dic ated by custom and necessity, small incomes sooner or later mean debt. Only cne tl ing cεn prevent this-lack of credit."

यह लोग मकरूज हैं। उनकी हालत बहुत ही खराब है। वह मुश्किल से अपना गुजारा करते हैं। उनकी टैक्स देने की कैपैसिटी नहीं है। इसलिये उनकी हालत को देखते हुए सरकार को उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाना चाहिए। सरकार को यह टैक्स उन लोगों पर लगाना वाजिब नहीं है। (घंटी) चेयरमैन साहिब, मैंने अभी अपनी तकरीर शुरू की है। मैंने अभी बहुत सी बातें सरकार के नोटिस में लानी हैं जिससे समाल लैंड-होल्डर्ज का भला हो सके। समाल लैंड होल्डर्ज की हालत बहुत ही खराब है। इसलिये सरकार को चाहिए कि कम से कम जो कम जमीन वाले किसान हैं, और यह टैक्स सरकार को दे नहीं सकते उनको इस टैक्स से मुआफ कर देना चाहिए। इसके अलावा जिन के पास 30 और 40 एकड़ जमीन है और वह यह टैक्स भी दे सकते हैं, उनसे यह टैक्स ज़रूर लिया जाना चाहिए। यह ठीक है कि देश में एमरजेंसी छायी हुई है और सरकार को डिवलपमेंट के काम के लिये और डिफेंस के काम के लिये रुपये की ज़रूरत है। इसलिये जो लोग टैक्स पे करने के काबिल हैं, उन से सरकार टैक्स ज़रूर वसूल करे।

चेयरमैन साहिब, पेरेंट बिल में सेल्फ कंज़म्शन के बारे में खामी रह गई है। उसमें है कि अगर कोई आदमी चाहे वह मैदानी इलाके में रहता हो या पहाड़ी इलाके में रहता हो, उन दोनों के लिये सैल्फ कंज़म्शन के लिए दो कनाल की छूट रखी गई है। उसमें लोगों की आर्थिक हालत का कोई ध्यान नहीं रखा गया है। आपको मालूम ही होगा कि पहाड़ी और बारानी इलाके में और मदानी तथा इरीगेटिड एरिया की उपज में कितना फर्क है। मैदानी इलाके में बारानी इलाके की निस्बत कई गुणा ज़्यादा उपज होती है। इस प्रोवीज़न से पहाड़ी इलाके और बारानी इलाके के लोग बुरी तरह से पीड़ित हैं। इसलिये सरकार को इसकी ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि अगर सरकार ने मैदानी इलाके और इरीगेटिड इलाके में दो कनाल की सैल्फ कंज़म्शन के लिये छूट दी है तो पहाड़ी इलाके के लिये 6 कनाल की छूट देनी चाहिए।

मुझे बहुत ही खेद से कहना पड़ता है कि पहाड़ी इलाके में ज़्यादा तर तादाद उन किसानों की है जो 5, 6 एकड़ ज़मीन रखते हैं। आपको मालूम ही होगा कि पहाड़ी इलाके में मैदानी इलाके की निस्बत बहुत ही कम उपज होती है। बारानी इलाके में भी कम ही उपज होती है। इसलिये पेरेंट ऐक्ट में दो कनाल के लिये जो छूट रखी गई है, वह वाजिब नहीं है। इसमें ज़रूर तरमीम लाने की ज़रूरत है। यह लोगों के साथ कोई ठीक इन्साफ नहीं है। पता नहीं लगता कि सरकार की अक्ल को क्या हो गया है। सरकार को कम से कम हिल्ली एरिया, और सबमाउंटेनियस एरिया की तरफ ज़रूर ध्यान देना चाहिए ताकि वहां के लोग 6 कनाल ज़मीन पर अपनी कंज़म्शन के लिये कपास और गन्ना की काश्त कर सकें। उस पर यह टैक्स लागू नहीं होना चाहिए। चेयरमैन साहिब, मुझे बड़े खेद से कहना पड़ता है कि पहाड़ी इलाके के अन्दर कोई भी

किसान 2 कनाल और एक मरला गन्ने या कपास की काश्त करता है तो उसे दो कनाल की भी छूट नहीं दी जाती है । कोई भी खेत दो कनाल का नहीं हो सकता है । कोई खेत सवा दो कनाल का होता है और कोई खेत अढ़ाई कनाल का होता है । किसान यह तो पता नहीं कर सकता कि दो कनाल का खेत कितनी दूरी तक हो सकता है और बाकी एक मरला या दो मरले को बिना काश्त भी छोड़ नहीं सकता है । अगर वह दो कनाल से एक मरला या दो मरले वाले खेत में कपास और गन्ना की काश्त करता है तो उसे सेल्फ कज़म्मशन में भी कोई छूट नहीं दी जाती है । सरकार को चाहिए कि वह इस ओर कदम उठा कर लोगों की तकलीफ को दूर करे । अगर सरकार से पिछले ऐक्ट में यह गलत बात हो गई हो तो उसको अब ठीक किया जा सकता है । यह लोगों की जायज़ मांग है । मैं सरकार से अर्ज़ करना चाहता हूँ कि सरकार लोगों की इस जायज़ मांग को स्वीकार करे । जो जायज़ बातें यहां पर सजैस्ट की गई हैं उन्हें सरकार को मान लेना चाहिए । चेयरमैन साहिब , मैं हाउस का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि जब व्यापारियों के साथ सम्बन्ध रखने वाला बिल यहां पर आया तो कितनी ही अमण्डमेंट्स उसमें पेश की गईं उनमें से आधी से ज़यादा सरकार ने मान लीं । धनी लोगों का पूंजीपतियों का प्रैशर चलता है उनका असरो रसूख है इसलिये सरकार उनकी बात मानती है । लेकिन मैं इनसाफ के नाम में यह आशा करता हूँ कि जहां पर सरकार ने सेल्ज़ टैक्स में अमैंडमैंट्स मानी हैं वहां पर हमारी अमेंड-मैंट्स भी मान लेगी । हिल्ली एरियाज़ जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं और जो बारानी इलाके हैं वहां पर पांच एकड़ से कम ज़मीन के मालिक से यह सेस नहीं लिया जाना चाहिए । दो कनाल से अगर एक दो मरले ज़यादा भी कोई किसान बो लेता है तो उस सूरत में उसको दो कनाल की छूट अवश्य मिलनी चाहिए, यह नहीं होना चाहिए कि अगर दो कनाल से एक दो मरले ज़यादा बो लेता है तो उसको छूट ही न दी जाए ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਉ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਕਾਂ ਨਾ ਕਢਣੀਆਂ ਪੈਣ । ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ ।

श्री सभापति : मेरे पास कोई लिस्ट नहीं आई । न ही मुझे पता है । (No list has reached me. I have no knowledge of it.)

ਸਰਦਾਰ ਜਾਗੀਰ ਸਿੰਘ ਦਰਦ (ਖੰਨਾ–ਐਸ. ਸੀ) : ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਐਗ੍ਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਭੁਟੋ ਨੇ ਸਪੀਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਤਕ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਕ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੈਟਨ ਟੈਂਕ ਛੰਭ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਝੋਂਕ ਦਿੱਤੇ । ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਲਗ ਭਗ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ । ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਚੂੰਕਿ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ । ਐਗਰੈਸਰ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਐਟਮ ਬੰਬ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਏਗਾ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਘਾਸ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖਾਣੀ ਪਵੇ । ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ । ਇਹ determination ਦੀ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਝਲਕ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ Bill ਤੇ Taxation ਤੇ ਝਗੜਦੇ ਹਾਂ । ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ

[ਸਰਦਾਰ ਜਾਗੀਰ ਸਿੰਘ ਦਰਦ]

ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਦੀ ਇਜ਼ਤ ਲਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਸ਼ੇਅਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਹੈ:—

ਉਧਰ ਤੀਰ ਔਰ ਤੋਪ ਕੀ ਸਦਾ ਕੁਛ ਔਰ ਕਹਿਤੀ ਹੈ,
ਇਧਰ ਰੰਗੀਨ ਸਾਜ਼ੋਂ ਕੀ ਅਦਾ ਕੁਛ ਔਰ ਕਹਿਤੀ ਹੈ ।

ਸਾਡੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਧਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਹਾਲਤ ਹੈ । ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਾਤਤ ਨਾਲ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਇਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 6 ਤਰੀਖ ਨੂੰ ਖੇਮ ਕਰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸਤ ਨੂੰ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ, 8 ਨੂੰ ਬਿਆਸ ਪਹੁੰਚ ਕੇ 9 ਤਰੀਖ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸੀ । ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਭੋਗ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ । ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ–ਜਾਮਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਪਹਿਨਾ ਸਕੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਸੀ । ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡੀਫੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਕ ਪਰੀਵਾਰ ਦਾ ਇਕ ਬੱਚਾ ਸੀ । ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਗਿਆ ਤਾਂ Recruiting Officer ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਭਾਈ ਹੈ । ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਵਾਏ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ 60 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

Sardar Gurcharan Singh : Madam, is he speaking on the Bill under discussion ?

Sardar Jagir Singh Dard : I am coming to the point, do not worry. ਤਾਂ Recruiting Officer ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਇਹੋ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ । ਜਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੇ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਭਰਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਰੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਤੇਰੀ ਇਹੋ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਹੈ । ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਆ । ਉਹ ਲੜਕਾ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਤਮ ਘਾਤ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਰਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਰੋੜਾ ਇਲਿਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ defend ਕਰ । ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੈਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਟ੍ਰੈਸਟ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵੀਯੂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫੌਜੀ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਿਆ ਹੈ । ਫੌਜੀ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਨੂੰ ਭੁਲ ਗਏ ਹਨ। ਜਨਰਲ ਮਾਂਟਗੁਮਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ "What is the difference between a statesman, a politician and a soldier".

ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤਕ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤਕ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲ ਸੋਚਦਾ ਹੈ about two Minor battles and ultimately how to win war. ਪੋਲੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਸਿਰਫ ਜੈਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ how to win general elections. ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ intellectual ਵੀਊ ਦੇ ਆਦਮੀ ਹਨ, ਕਿਨੇ ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਪਾਲੀਟੀਸ਼ਨ ਹਨ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੌਜੀ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਨੇ ਪਾਲੀਟੀਸ਼ਨਜ਼ ਦਾ ਪਾਰਟ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ how to win general elections। ਜੈਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੋਣਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡੀਫੈਂਡ ਕਰਨਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੋ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ defend ਕਰਨਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ।

ਬਿਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸ. ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਸ. ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਉਥੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਧਕਾ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ? 1965 ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਰਾਹੀਂ 66,47,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਆਈ। ਜਿਹੜੇ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਹਾਰਡ ਹਿਟ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਫੀਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗ ਭਗ 24,18,000 ਰੁਪਿਆ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ 42,23,000 ਰੁਪਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਉਂਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਤੇ ਖਰਚ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। Cess Bill is a minor thing ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਾਹੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸੌ ਫੀ ਸਦੀ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਪੰਡਤ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਸੌ ਫੀ ਸਦੀ ਹਿੰਦੂ ਬਚਾਣੇ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਲੈਂਡ-ਲਾਰਡਜ਼ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੋ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੋ। ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟਸ ਨੂੰ ਤੇ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੋ ਅਤੇ ਜਾਂ ਛਾਬੜੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਲਾਲੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੋ।

ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ : ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਲੈਂਡ-ਲਾਰਡਜ਼ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੋ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੋ। 5 ਏਕੜ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਜਿਹੜੇ 95% ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ? (*Interruptions*)

ਸਰਦਾਰ ਜਾਂਗੀਰ ਸਿੰਘ ਦਰਦ : ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਾਂ ਕਿ ਲੈਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਟੈਨਿਉਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬਾਗਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਾਗਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੂਲਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 87,500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਗਾਂ ਲਈ ਛੱਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਬਾਗ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਲਾਨਾ ਇਨਕਮ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪੈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2,000 ਰੁਪੈ ਤਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੌ ਰੁਪਿਆ ਪਰ ਏਕੜ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉ ਤਾਂ ਕੁਲ ਆਮਦਨੀ ਬਾਗਾਂ ਤੋਂ 87,50,000 ਰੁਪਿਆ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਰ ਸੈਸ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਜੱਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਗਾਂ ਤੇ **ਟੈਕਸ ਲਗਾ**

[ਸਰਦਾਰ ਜਾਗੀਰ ਸਿੰਘ ਦਰਦ]

ਦਿਉ । ਪਰ ਜੇ ਕਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਰਾਜੇ ਮਹਰਾਜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਨੇ ਲੈ ਲਈ, ਨਵੇਂ ਰਾਜੇ ਬਣ ਗਏ । ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ । ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਸਿਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ । ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੰਨੇ ਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਯਾਨੀ ਦੂਰ ਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ । ਉਹ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ exploit ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਰਬਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਸੀਲਿੰਗ ਲਗਾਉ । ਕਈਆਂ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਸ ਦਸ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਕਈਆਂ ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸ ਤੇ ਸੀਲਿੰਗ ਲਗਾਉ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ open auction ਵਿਚ ਵੇਚੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ । ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ Cess Bill ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ।

ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕੈਟਲ ਬ੍ਰੀਡਿੰਗ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ।

ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਲਿਮਿਟ ਕਰੋ । ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਤਨੇ ਕੈਟਲ ਬਰੀਡਿੰਗ ਫਾਰਮਜ਼ Land lords ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ ਕਿਤਨੇ ਹਨ । ਇਹ ਇਕ Loop hole ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਫਾਰਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੇਡਾਂ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭੇਡਾਂ ਹਨ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਔਰ ਜੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਉ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਰੀਫਾਰਮਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ? ਜਦ ਗਰੀਬ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਢਾਈਆਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਚਿਲਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੈਂਡ-ਲਾਰਡ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਉਸ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਸ਼ੇਅਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਹੈ—

ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਈਮਾਨ ਸੀ ਕੋਲ ਤੇਰੇ,
ਤੂੰ ਵਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਾਈਂ ।
ਰੱਬ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਂਦਾ,
ਪਰ ਨਾ ਬਖਸ਼ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਚੋਰ ਤਾਈਂ ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਹਨ । ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ, ਗਰੀਬ ਹਰੀਜਨ ਹਨ ਜਾਂ ਬੜਾ ਦਬਿਆ ਹੋਇਆ ਗਰੀਬ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਇਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਇਕ ਹੋ ਕੇ ਲੈਂਡਲਾਰਡਜ਼ ਨੂੰ, ਕੈਪੀਟਿਲਿਸਟ ਨੂੰ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਨੂੰ ਪੁਛਣਗੇ, ਕਿ ਜਿਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਐਸ਼ .ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ? ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਪਾਲੀਸੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਕਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਇਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਮਿਲਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ।

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ: On a point of information, Sir. ਮੈਂ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਪਾਸੋਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਰਲੇ ਔਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕੀਂ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਣ ।

ਸਰਦਾਰ ਜਾਗੀਰ ਸਿੰਘ ਦਰਦ : ਜਦੋਂ ਤਕ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਕ ਸੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਦ ਤਕ ਗਰੀਬ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ । ਗਰੀਬ ਦੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ । ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਰਜ਼ਾਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਕ ਹਰੀਜਨ ਮੈਂਬਰ ਲਿਆਇਆ, ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਕ ਜੱਟ ਨੇ, Is it a social equality ? ਮਗਰ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਗਰੀਬ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇਕਨਾਮਿਕ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ । ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਗਰੀਬ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ । ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਈਨ ਹੈ ? ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ? ਕੀ ਗਰੀਬ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ? ਨਹੀਂ । ਉਸ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜਿਹੜੇ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਊਸਿਜ਼ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ । ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ । ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੈ ਸਕੇ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਕੈਰੋਂ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪਾਸ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਫੀ ਏਕੜ ਕੀਮਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਕੀਮਤ ਇਕ ਕਰੋੜ 20 ਲਖ ਰੁਪੈ ਬਣਦੀ ਹੈ (ਵਿਘਨ) ਕੀ ਇਹ ਲੈਂਡ ਰੀਫਾਰਮਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ? ਆਖਿਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੇ ਕਿਵੇਂ ? ਇਕਲੇ ਫੀਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਸਦਾ $\frac{1}{2}$ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ ਛੇ ਵੱਡੇ ਲੈਂਡ ਲਾਰਡਜ਼ ਪਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ $\frac{1}{2}$ ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਟੱਬਰ ਆਬਾਦ ਹਨ । ਕੀ ਇਹੋ ਲੈਂਡ ਰੀਫਾਰਮਜ਼ ਹਨ ? ਅਗਰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੈਂਡ ਰੀਫਾਰਮਜ਼ ਨਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਰਬਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਠੀਕ ਵੰਡ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਸੀਲਿੰਗ ਨਾ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲੈ ਚੀਕਣਾ ਸਿਰਫ ਕਰਾਕੋਡਾਈਲ ਟੀਅਰਜ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਖਾਲੀ ਰੋ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ । ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਦੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਤੈਰਨਾ ਉਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਕਦੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ । ਲੈਂਡ ਰੀਫਾਰਮਜ਼ ਇਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਚੌਤੀ ਚੌਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੇ ਹਨ ਉਹ ਲੈਂਡ ਰੀਫਾਰਮਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਇਕ ਕਸਾਈ ਪਿਆ ਜੀਵ ਹਤਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜੈਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ । ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਰਡ ਵੈਲਜ਼ਲੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਫਾਰੇਨ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਹਨ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ

> "England has no permanent friend and no permanent enemies but it own self-interests are prrmanent."

[ਸਰਦਾਰ ਜਾਗੀਰ ਸਿੰਘ ਦਰਦ]

ਸੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮਿੱਤਰ, ਉਸ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਤਾਂ ਤਰਾਜ਼ੂ ਦੀ ਡੰਡੀ ਵੇਖਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰਫ਼ ਝੁਕਦੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਮਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤਕੜੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਹਾ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਵਾਲੇ ਤਕੜੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬਾਦ । ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚਿਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । None from this party spoke yesterday.

श्री सभापति (श्री राम सरन चन्द मित्तल) : कल आपोज़ीशन की तरफ से सरदार शमशेर सिंह जोश और सरदार गुरनाम सिंह बोले । मेरे पास सारा हिसाब लिखा हुआ है (Yesterday, Sarvshri Shamsher Singh Josh and Gurnam Singh spoke from the opposition. I have got the statement with me.)

Sardar Gurcharan Singh : Just find out the time.

श्री सभापति : कांग्रेस बैंचिज़ की तरफ से आठ मेम्बर पहले बोल चुके हैं और नौवाँ अब बोला है । आप की आपोज़ीशन पार्टीज़ की तरफ से नौ बोल चुके हैं (Eight Members from the Congress Benches had already participated in the discussion and the ninth one has just spoken. Whereas nine Members from the opposition parties have taken part in it.)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਸਨ । ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਤਨੀਆਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ।

श्री सभापति : यह जरूरी नहीं है । बहस में कोई मेम्बर हिस्सा ले सकता है । (It is not necessary. Any Member can participate in the discussion)

टिक्का जगजीत सिंह (नारायणगढ़) : चेयरमैन साहिब, मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ कि आपने मुझे बोलने के लिये मौका दिया । आज कमरशल क्राप्स सैस बिल पर बहस हो रही है । यह सन् 1963 में पहिले भी हाउस के सामने आया था और उस वक्त भी बहुत से लोगों ने इसकी मुखालिफत की थी लेकिन आज फिर इस बिल को दुबारा यहां पर पेश किया गया है । उस वक्त तो यह फैसला किया गया था कि यह सैस सिर्फ तीन साल के लिये लगाया जा रहा है और यह वादा किया गया था कि तीन साल के बाद इस सैस को और नहीं बढ़ाया जाएगा मगर फिर भी इस बिल को लाया गया है । ठीक है, एमरजेंसी है और सभी लोगों को इस वक्त हर तरह से मदद करनी चाहिए । सभी लोग इस लड़ाई में लड़े और आगे भी लड़ेंगे । इसमें किसी खास खास लोगों के हिस्सा लेने की बात नहीं है । देश के लिये जो भी कुरबानी की जा सकती है वह हर कोई करता है और करनी भी चाहिए । लेकिन शायद बहुत से लोगों को इसमें असली बात का पता नहीं । वह समझते हैं कि शायद यह सैस सरकार बड़े बड़े ज़मींदारों के ऊपर लगा रही है । लेकिन इस सिलसिले में मैं आपके सामने थोड़े से फैक्ट्स एंड फिगर्ज़ पेश करना चाहता हूँ । आप देखें कि हमारे पंजाब के अन्दर जो टोटल होल्डिंग्ज़ हैं वह गवर्नमेंट के अपने हिसाब किताब के मुताबिक 29,84,000 हैं । उसमें से 60 एकड़ से कम वाली होल्डिंग्ज़ 29,10,000 है और

जो 60 एकड़ से ज्यादा वाली हैं वह 25,000 होल्डिंग्ज़ हैं । अगर आप 25,000 पर लगा दें तो ठीक है, कोई एतराज़ वाली बात नहीं लेकिन जो 2,910,000 वाले लोगों पर टैक्स लगाया जा रहा है उनके लिये किसी के दिल में दर्द पैदा नहीं होता । जब मैं यह कहता हूँ कि शायद कोई यह समझ ले कि मैं भी ज़मींदार हूँ और इसीलिये यह कह रहा हूँ या यह टैक्स मुझ पर लग रहा है इसलिये इसके बारे में कुछ कहने के लिये खड़ा हुआ हूँ, यह बात नहीं है। मैं हाउस को बता देना चाहता हूँ कि मेरे ऊपर कोई टैक्स नहीं लग रहा लेकिन मैं इस बात पर ज़ोर देना चाहता हूँ कि जिसका असर 2,910,000 होल्डिंग्ज़ पर काम करने वालों पर पड़ना है उसके लिये भी किसी को दर्द होना चाहिए ।

इस सिलसिले में एक और बड़े ताज्जुब की बात है। आम तौर पर यह रवायत चली आ रही है कि जिस वक्त भी हमारी सैंटर की सरकार या स्टेट की सरकार कोई टैक्स लगाती है तो उस टैक्स को लगाने से पहले इतना इन्तज़ाम किया जाता है कि उसके सम्बन्ध में जो इत्तलाह है वह वक्त से पहिले लीक आउट न हो जाए, लोगों को पता न लग जाए ताकि वह किसी किस्म की कोई बात न कर डालें। सब दोस्तों को पता है कि जब जब भी सैंटर में टैक्स वगैरा की इत्तलाह, वक्त से पहले लीक आउट हुई है तो ऐसे केसिज़ में वहां पर बड़े-बड़े आदमियों को, बड़े-बड़े अफसरों को इस बात के लिये खैंचा गया है, डांटा गया है और उनके खिलाफ ऐक्शन लिया गया है। लेकिन इस टैक्स की पोज़ीशन क्या है ? 31 मार्च, 1966 तक तो पहले ही लागू है। उसके लिये तो कानून में कोई रुकावट नहीं है। उसके बाद आप इस बात का और डंडा उन लोगों को मार सकते हैं। लेकिन पता नहीं कि क्यों इस मकसद के लिये छः महीने पहिले ही इस बिल को यहां पर पेश कर दिया गया है। इसमें कुछ शरारत मालूम होती है। कुछ नीयत का पता चलता है और ऐसा मालूम होता है कि शायद दाल में कुछ काला हो और वह यह कि शायद अगले सैशन में सरकार कुछ और टैक्सों को भी लाना चाहती हो और न चाहती हो कि इनको इकट्ठा यहां पर एक ही सैशन में पेश किया जाए। इसलिये यह टैक्स तो इस सैशन में लगा लिया और दूसरे टैक्स अगले सैशन में लगवा लेंगे । वरना मैं समझता हूँ इस वक्त कोई ऐसा मौका नहीं था कि इस बिल को पेश किया जाता ।

इस साल खास तौर से ज़मींदार का, किसान का जितना एरिया है उसमें क्राप्स फेल हो चुकी हैं। कुछ पानी की कमी की वजह से फसलें फेल हुई हैं और कुछ बारिश न होने के कारण भी फसल नहीं हो पाई। ठीक ऐसे वक्त पर इस तरह का क्राप सैस लगा देना, मैं समझता हूँ, कि खुद गवर्नमैंट के लिये भी अच्छा साबित नहीं होगा । जिस तरह से कल बताया गया था कि गवर्नमेंट ने पहले भी कोई 13 या 14 टैक्स किसानों पर लगाए हुए हैं। इस वक्त मैं इस झगड़े में नहीं पड़ता कि यह ठीक लगे हुए हैं या ठीक नहीं लगे हुए।

12.00 noon

फिर बहुत सारे भाई सीलिंग के बारे में कहते हैं। मैं कहता हूँ कि सीलिंग कहीं भी नहीं लगनी चाहिए और अगर यह ज़रूर लगानी ही है तो यह आन इनकम लगाई जाए, चाहे किसान हों चाहे कैपिटलिस्टस हों, चाहे कोई व्यापारी हो, इन सब की इनकम पर एक लेवल पर सीलिंग हो। यदि इस तरह से कर दिया जाए तो इसमें किसी को एतराज़ नहीं होगा लेकिन जब यह एक किस्म की चीज़ों पर तो लगा दी जाती है और दूसरी किस्म की पर नहीं लगाई जाती तो लोग उस

[टिक्का जगजीत सिंह]
पर सोचने लगते हैं। इसलिये मैं कहता हूँ कि हर चीज़ किसी ग्रसूल के मुताबिक करनी चाहिए ताकि किसी को कोई एतराज़ का मौका न मिले।

फिर एक सवाल शहरी ग्रौर देहाती का उठाया जाता है ग्रौर इस बारे में यह कहा जाता है कि शहरियों को क्या-क्या फैसिलेटीज़ दी जाती हैं ग्रौर देहाती को क्या-क्या दी जाती हैं। ग्रभी ग्रभी एक सवाल शूगर के बारे में उठाया गया था कि देहात के लोगों को यह कितनी दी जाती है ग्रौर उसके मुकाबिला में शहर के लोगों को कितनी दी जाती है ग्रौर इसके जवाब में, बताया गया था कि देहात के लोगों को शहर वालों का चौथा हिस्सा मिलती है। इस बारे में मैं ग्रापके सामने एक मिसाल पेश करता हूँ कि किस तरह से देहात वालों से इमत्याज़ी सलूक किया जाता है। ग्रभी एमरजेंसी के दिनों में हलवाइयों को जो चीनी का कोटा मिलता था बन्द कर दिया गया था ग्रौर उसके थोड़े दिनों के बाद वह फिर खोल दिया गया था। लेकिन ग्राप सुन कर हैरान होंगे कि शहर के हलवाइयों का कोटा तो जब इस बारे में ग्रार्डर हुए उसी वक्त खोल दिया गया था लेकिन इसके मुकाबले में देहात के हलवाइयों का कोटा ग्रभी तक वहां पर नहीं पहुंचा। हालांकि दीवाली ग्रौर दुशहरा के त्यौहार भी गुज़र चुके हैं ग्रौर उनको चीनी नहीं मिली।

इसी तरह से कोई नेच्युरल कलैमेटी पड़ जाती है तब भी देहात के लोगों से रिलीफ देने में इम्त्याज़ी सलूक किया जाता है। जब यह देखते हैं कि किसी कलैमिटी की वजह से शूगर इण्डस्टरी को नुकसान पहुंचा है ग्रौर उन को घाटा पड़ रहा है तो यह किसी न किसी बहाने मदद देते हैं। ग्रभी इन्होंने शूगर इण्डस्टरी वालों को एक्सपोर्ट करने के बहाने से 20 लाख के करीब रकम दी, इसी तरह से पहले भी कोई 25 लाख रुपये की रकम उन्हें दी गई थी लेकिन इसके मुकाबिला में ग्राप देखें कि हमारी तहसील नारायण गढ़ में मार्च के महीने में ग्रोले पड़े थे ग्रौर उन ग्रोलों की वजह से वहां लोगों के हजारों जानवर मारे गये थे। इस बारे में एक सवाल नं: 8335 भी किया गया था ग्रौर उसके जवाब में गवर्नमेंट ने माना है कि इन ग्रोलों की वजह से वहां 836 मवेशी मरे थे ग्रौर उनमें सब तरह के मवेशी थे बड़े भी थे ग्रौर छोटे भी थे, यानी उनमें से भैंसें भी थीं, मेल बफेलोज़ भी थे ग्रौर गाय ग्रौर बकरियां भी थीं लेकिन उन लोगों की मदद के लिये सरकार की तरफ से एक पैसा भी नहीं दिया गया : इस की वजह यह है कि उनकी जो लोग ग्रावाज़ उठाते हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं है। इसलिये मैं कहता हूँ कि इस तरह से इम्त्याज़ी सलूक नहीं किया जाना चाहिए ग्रौर शहरियों को मदद मिलती है तो देहात वालों को भी मिलनी चाहिए।

एक बात मैं ज़मीनों की एकुइज़ीशन के बारे में कहना चाहता हूँ। बहुत ज़मीनें एक्वायर तो कर ली जाती हैं ग्रौर जिस काम के लिये वह एक्वायर की जाती हैं वह उसमें शुरू नहीं किया जाता ग्रौर इसका नतीजा यह होता है कि वह ज़मीन काफी ग्ररसा तक खाली पड़ी रहती है। इस बारे में कई मिसालें दे सकता हूँ। एक केस का मुझे पता है जिसमें तीन हज़ार एकड़ ज़मीन एकुग्रायर की गई हुई है ग्रौर इसको दो साल गुज़र चुके हैं ग्रौर जिस परपज़ के लिये यह एक्वायर की गई थी। वह काम वहां ग्रभी तक शुरू नहीं किया गया। ग्रगर उस ज़मीन को काश्त में लाया जाता तो उससे काफी ग्रनाज पैदा किया जा सकता था। यह ठीक है कि हमें डिफेंस के कामों

को प्रायर्टी देनी चाहिए ग्रौर जो ज़मीन उसके लिये चाहिए वह देनी चाहिए लेकिन जब तक वह खाली पड़ी रहती है उसमें काश्त का इन्तज़ाम ज़रूर होना चाहिए चाहे यह गवर्नमेंट खुद ही क्यों न कराए । इसके साथ ही मैं यह बात भी गवर्नमेंट के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि ग्रगर यह कोई ऐसी ज़मीन एक्वायर करती है जिसमें कोई ग्रबादी है तो उस ज़मीन को ग्रपने कब्ज़े में लेने से पहले इसे चाहिए कि जो लोग वहां पर बसते हैं उनको पहले यह वहीं दूसरी जगह पर ग्राबाद करने का इंतजाम कर ले ।

इसके बाद मैं एक बात एडमिनिस्ट्रेशन पर जो खर्च हो रहा है उस के बारे में भी कहना चाहता हूँ । यह खर्च पिछले कई सालों में पहले से दस या 15 गुना हो गया है । इसलिये जिस रेशो में यह बढ़ा है उसी रेशो में इसे कम भी करना चाहिए ।

यह ठीक है कि गवर्नमेंट को टैक्स लगाना पड़ रहा है क्योंकि इसे पैसे की ज़रूरत है इसलिये मैं कहता हूँ कि ग्रगर ग्रापने यह टैक्स ज़रूर लगाना है तो लगा लें लेकिन किसान की हालत पर रहम खाते हुए इन्हें ज़ोनल सिस्टम को भी खत्म कर देना चाहिए ताकि वह ग्रपना फालतू ग्रनाज दूसरे सूबों में भेज कर वहां पर जो रेट हैं उन पर बेच कर कम्पेंनसेट भी हो सके ।

इसके ग्रलावा एक बात मैं ट्रैक्टरज़ के बारे में भी कहना चाहता हूँ । मुझे पता चल है, पता नहीं कि इसमें कहां तक सच्चाई है, कि सैंट्रल गवर्नमेंट या हमारी स्टेट गवर्नमेंट ट्रैक्टरज़ की कीमत बढ़ाने लगी है ग्रौर इस हद तक बढ़ाने का ख्याल रखती है कि यह पहले से चार-चार या पांच-पांच हज़ार रुपये महंगे हो जायेंगे ग्रौर यह इसलिये कर रही है ताकि जो ट्रैक्टर हमारे ग्रपने देश में बनने लगे ह उनके लिये मार्किट पैदा हो सके क्योंकि इस तरह से इम्पोर्टिड ट्रैक्टरज़ की कीमत इतनी बढ़ जायेगी कि लोग उनको न खरीद कर देसी बने हुए ट्रैक्टरज़ खरीदने लगेंगे । इस तरह से जो ट्रैक्टरज़ मैनुफक्चर करने वाले कैपीटलिस्ट्स हैं उनको यह गवर्नमेंट सबसीडाईज़ करना चाहती है । लेकिन मैं समझता हूँ कि यह चीज़ कोई ग्रच्छी नहीं साबत होगी ग्रौर इसका हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पर बहुत बुरा ग्रसर पड़ेगा ।

इसके साथ ही मैं एक बात ग्रौर कहना चाहता हूँ कि यह सेस गवर्नमेंट ने लगाना ही है तो मैदानी इलाकों म यह बेशक लगा ले लेकिन जो हिल्ली एरियाज़ हैं या बैकवर्ड एरियाज़ है उन इलाकों पर यह सैस लागू न किया जाए क्योंकि वहां के किसान बहुत पिछड़े हुए हैं । यह ठीक है कि वहां पर यह कमरशियल कराप्स बहुत कम पैदा की जाती हैं फिर भी उनको इससे माफी होनी चाहिए ।

कामरेड राम प्यारा (करनाल) : चेयरमैन साहिब, यह जो बिल इस वक्त हाउस के सामने पेश है इस पर जो तकरीरें हुई हैं उनको मैंने सुना है ग्रौर उनके सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि उनमें से एक ग्राध तकरीर ऐसी की गई है जिसमें तकरीर करने वाले ने रियलिस्टिक वियू को सामने रखकर की है। चेयरमैन साहिब, मेरे ग्रन्दाज़ा के मुताबिक इस वक्त पंजाब में कोई 40 या 42 लाख कुल लैण्ड ग्रोनर्ज़ हैं जिन में से कुछ थोड़ी ज़मीन वाले हैं ग्रौर कुछ ज़यादा वाले हैं ग्रौर गवर्नमेंट की फिगर्ज़ पर मबनी जो मेरा ग्रन्दाज़ा है मुश्किल से 10 या 12 फीसदी किसान या ज़मींदार ऐसे नहीं हैं जिन पर यह टैक्स लागू होता है ग्रौर शायद 25 लाख

[कामरेड राम प्यारा]

ऐसे होंगे जिन पर इस टैक्स के अलावा जो सरचार्ज लगता है वह भी नहीं लगता क्योंकि वह जो मामला देते हैं वह भी दस रुपये से कम होता है। इसलिये जो बहुत भारी ऐडवोकेसी या नुमांयंदगी की गई है कि न लगाया जाय यह छोटे और गरीब जमींदार के नाम पर बड़े जमीदारों के फायदे के लिये की गई है, छोटों की आड़ लेकर बड़ों का फायदा सोचा जा रहा है। चेयरमैन साहिब, हमारी डिवलपिंग इकोनौमी है, इसमें टैक्सिज़ तो लगेंगे ही। अगर कोई मुझे यह कहे कि मैंने सेल्ज़ टैक्स की फिर मुखालिफित क्यों की तो वह मैं सेल्ज़ टैक्स बढ़ाने की नहीं की बल्कि उस हैरासमेंट की की जो इनके हाथों उन की होती है। तो टैक्सों के बगैर तो गुज़ारा नहीं है क्योंकि हम ही स्कूल, सड़कें, और हस्पताल वगैरह मांगते हैं। फिर यहां पर कैपसिटी टू पे की बात चली। मैं इस बात के हक में हूँ कि टैक्स उन पर लगना चाहिए जो दे सकने की हालत में हों, जिनकी कपैसिटी हो दूसरों पर अगर लगा हुआ भी है तो माफ होना चाहिए। मगर क्या मैं उनसे पूछूं जिन्होंने कपैसिटी के नाम पर क्रिटिसाईज किया कि जब यहां पर लैजिस्लेटर्ज़ के लिये मैडीकल रिलीफ का बिल आया था तो उस वक्त वह कहां थे, उस वक्त उन्होंने इस बात का ख्याल क्यों नहीं किया जिनकी आमदनी पहले ही ज्यादा है उनको वह सहूलतें क्यों मुहैय्या की जाए वह रिलीफ लेने के लिये असैम्बली की तनखाह भूल गये, पैनशनें भूल गये, ज़मीनों वगैरह की आमदनी भूल गये, क्या यही तरीका है डिबेट का? इतने लरनिड हो कर भी एक रूखी ही बात की गई। हम सोशलिस्ट पैटर्न को कमिटिड हैं यानी जिनकी आमदन कम है उनको रिलीफ मिले, जिनके रिसोर्सिज़ ज़यादा हैं उन पर टैक्स लगें। जहा तक पांच एकड़ वालों को छूट देने की बात है कोई भी इस बात के हक में नहीं हो सकता कि इन लोगों पर यह लगे। मैं तो कहता हूँ कि यह पांच एकड़ से बढ़ा कर दस एकड़ किया जाए यानी दस एकड़ तक जमीन वालों को छूट दी जाए। मगर चेयरमैन साहिब, यहां पर तो छोटे जमीदारों का नाम लेकर बड़े-बड़े मगरमच्छों का केस ऐडवोकेट किया जाता है। मैं एक दो मिसालें आपके सामने रखता हूँ: हमारे करनाल ज़िला के ज़िला परिषद के एक चेयरमैन हैं उन्होंने फौज में या अंग्रेज़ की कुछ खिदमत की होगी उसके सिले में उन की कुछ ज़मीन मिनटगुमरी में थी। उनके पास सात आठ सौ एकड़ ज़मीन अब करनाल में है। वह वहीं रहता है मगर जब सरपलस ज़मीन का ऐक्ट बना तो बजाए इसके उसके पास 50,60 एकड़ ज़मीन रहती उसने अपने आपको रफ्यूजी डिक्लेयर करवा लिया और अपने नाम ही नहीं, अपनी मां के नाम, अपनी बीवी के नाम और अपने तीन लड़कों के नाम अलग अलग ज़मीन करवा ली। उस ऐक्ट के लागू होने से एक दिन पहले इस तरह कर लिया और 350 एकड़ से ऊपर रिज़र्व करवा ली हालांकि हक उनका सिर्फ 70, 80 एकड़ तक ही का था। क्या यहां पर ऐसे मगरमच्छों के लिये आप लड़ रहे हैं? एक दूसरे साहिब हैं वह हमारे ज़िले में डिप्टी कमिश्नर थे, उनका भाई अमृतसर में डिप्टी कमिश्नर है, एक भाई हाई कोर्ट का जज है, एक भाई फिरोज़पुर में जिला परिषद् का चेयरमन है। उनसे दो सौ एकड़ ज़मीन सरप्लस निकली जो उन्होंने दबाई हुई थी। एक गोली गांव है वहां से सिर्फ पांच एकड़ जमीन सरप्लस निकली थी मगर जब मैं ने शिकायत की तो 297 एकड़ जमीन सरप्लस निकली। ऐसे लोग गरीब नहीं हैं। उन पर यह क्यों न लगे। मैं कहता हूँ कि यह सैस सलेब सिस्टम पर लगाया जाए। यह मेरी रैविन्यु मिनिस्टर साहिब को तजवीज़ है कि जिस तरह से स्पैशल चार्ज एक्ट में है यानी जो 50 रुपये मालिया देता है वह इतना

टैक्स दे, जो सौ मालिया देता है वह इतना टैक्स दे, जो 150 रुपय मालिया देता है वह इतना दे वगैरह इसी तरह से यह सैस भी दस एकड़ तक के मालिक को छोड़ कर सलैब सिस्टम पर लगाया जाए। अगर यह कहें कि अब तो सीलिंग मुकर्रर हो गई है लोगों के पास 30 एकड़ से ज्यादा जमीन है ही नहीं तो मैं इसे सही नहीं मानता। एक एक कुनबे ने बेईमानी से, धक्के से, रिश्वत दे कर या पोलीटिकल प्रैशर से बहुत ज्यादा ज़मीन अपने कब्जे में रखी हुई है और इस बात का सबूत यह है कि जहां पर बाप बेटे के नाम पर जुदा ज़मीन है वहां पर उनका काम काज इकट्ठा है, माल एक ही दुकान पर इकट्ठा ही जाता है, सारा रुपया बाप के नाम पर ही बैंक में जमा होता है। इन पर यह टैक्स लगना चाहिए और ज्यादा लगना चाहिए और इस तरह से जो आप दस एकड़ वालों को छोड़ेंगे तो उसकी कमी उनसे पूरी की जाए। यह नहीं कि गरीबों का नाम लेकर इनको भी छोड़ दिया जाए।

मेरी इत्तलाह के मुताबिक पंजाब में दो सवा दो करोड़ एकड़ रकबा है ज़मीन का। उसमें से जो टैक्स लगने के जुमरे मे आता है वह तकरीबन 20–25 लाख एकड़ ही है।

श्री सभापति (श्री रामसरन चंद मित्तल) : चूंकि इस समय सदन में कोई भी पेनल आफ चेयरमैन का सदस्य नहीं है और चूंकि मुझे बाहर जाना है इसलिये अगर सदन आज्ञा दे तो प्रिंसिपल रलाराम जी को यहां पर तशरीफ रखने के लिये कहा जाए। (Because no Member of the Panel of Chairmen is at the moment present in the House, and I have to go out, therefore, if the House agrees Principal Rala Ram may be requested to occupy the Chair.)

आवाजें : हां जी ठीक है।

कामरेड राम प्यारा : तो दो सवा दो करोड़ एकड़ जमीन में से सिर्फ 20–25 लाख एकड़ जमीन टैक्सेबल बनती है यानी कुल रकबे का 10–12 फीसदी रकबा ऐसा है जिन पर इसका असर होगा। इसमें से भी जिसके पास पांच एकड़ ही जमीन है वह गन्ना बीघा दो बीघा से ज्यादा नहीं बोता, हां खादर के इलाका में शायद लोगों को ज्यादा गन्ना बोना पड़ता हो वरना ज्यादा बड़े बड़े जमींदार ऐसे हैं जिन्होंने अपनी ज़मीन बेच ली है और उनका बैंकों में लाखों रुपया जमा है। कई दोस्त दुकानदारों की बात करते हैं मगर यह जमींदार जिनका लाखों रुपया बैंकों में जमा है यह लोग मनी लैंडिंग का काम करते हैं, सूद खाते हैं और इसमें एक दूसरा जुर्म यह करते हैं कि उनके पास इसके लिये लाईसेंस नहीं है (*At this stage Prtncipal Rala Ram occupied the Chair*) क्या ऐसे लोगों को इस टैक्स से बचाने के लिये यह कहा जाता है? इसलिये केटेगरीज़ बननी चाहिएं जिनकी आमदनी कम है उन पर यह न लगे, सरकार उनको सबसिडी दे, फर्टेलाइज़र सस्ते भाव पर दे मगर यह नहीं कि छोटे जमींदारों के नाम पर बहुत बड़े-बड़े लैंडलार्डज़ को, बड़ी-बड़ी तनखाहों वालों को पैनशनों वालों को इस टैक्स से छूट दी जाए। जब यह टैक्स लगा था तो यह अन्दाज़ा था कि तकरीबन 22 लाख लैंडलार्डज़ में से यह टैक्स 7 लाख पर लगेगा। अब कुछ लैंड, फ्रैगमेंटेशन की वजह से जो कुछ जायज़ की गई है और कुछ नाजायज़ भी की गई है, तो लैंड-लार्डज़ की तादाद बढ़ गई है और मेरी इत्तलाह के मुताबिक 10-12 फीसदी पर यह टैक्स एप्लाई होता है। जो छोटे ज़मींदार हैं, गरीब हैं उनको इस टैक्स से छूट दी जाए (घंटी) मगर जो

[कामरेड राम प्यारा]

बड़े जमींदार हैं उन पर सलैब सिस्टम के मुताबिक ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। एक चीज़ मैं आपकी इजाज़त से और कहना चाहता हूँ कि जो ज़मीनें लीज़ पर दी गई हैं उनमें से करनाल जिला में भी ऐसी ज़मीनें हैं। इसके बारे में गवर्नमेंट की तरफ से सीलिंग लगाई गई है तो फिर गवर्नमेंट को हक नहीं कि लैंड ओनर की जमीन को इकट्ठा करके दूसरे लोगों को दे दिया जाए। मैंने इसके बारे में प्राइम मिनिस्टर साहिब को एप्रोच किया कि पंजाब में लीज़ पर जो ज़मीनें दी जा रही हैं उन पर कोई सीलिंग लगा दी जाए और मेरे कहने पर सैंटर ने इस बात को टेक अप किया कि लीज़िज़ पर सीलिंग होगी। इसलिये मैं यह कहूंगा कि सैंटर की इस हिदायत के सामने यह गवर्नमेंट तो लीज़ देने के मुजाज़ नहीं और कम्पीटेंट नहीं है कि बिरला को बड़ी बड़ी ज़मीनें दे दी जाएं। इस बात का संबंध लीगल एसपेक्ट से है अगर बाकी के केसों में लीज़ पर सीलिंग लगाई जा सकती है तो इस लीज़ पर सरकार की तरफ से क्यों कोई सीलिंग नहीं लगाई गई जो कि बिरला को दी गई है। इससे साफ ज़ाहर है कि यह हकूमत बड़े बड़े सरमाया दारों को नाराज़ नहीं कर सकती। न बिरला को इन्कार कर सकती है और न ही थापर को। यह तो उन्हें ओबलाइज करना चाहते हैं और इसका क्या नतीजा निकलने वाला है? यह सब आपके सामने आएगा कि स्टेट का भट्ठा बैठेगा। मैं यह कहूँगा कि जितने भी लैंड रिफार्मज़ हैं उनमें त्रुटियां हैं और इससे बड़े ज़िमीदारों को फायदा होने वाला है। इसलिये मैं इस बात की तो मुखालफित नहीं करता कि यह टैक्स न लगाया जाए, लेकिन साथ ही यह भी कहना चाहता हूँ कि शहरी जायदाद पर भी सीलिंग लगा देनी चाहिए। शहर के मकानों पर सीलिंग हो दुकानों पर सीलिंग लगाई जाए, फैक्टरियों की इन्कम पर सीलिंग लगाई जाए और अगर इसके बारे में गवर्नमेंट या आपोज़ीशन वाले कोई भी चीज लायेंगे तो I will be the first man to support it whole heartedly. With these words I thank you, Mr. Chairman.

ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ (ਫਿਲੌਰ) : ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਤੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੋਲਣ ਲਈ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਕਮਰਸ਼ਲ ਕਰਾਪ ਤੇ ਸੈਸ ਲਗਾਣ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਿਲ ਅੱਜ ਕਲ ਚਾਲੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਮਾਰਚ, 66 ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਹਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਬੜੇ ਹੀ ਠੰਡੇ ਸੁਭਾ ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਕਿਥੋਂ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤਦ ਤਕ ਇਸ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਟੈਕਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਖਿਆ ਲਈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਪਰ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਇਕਨਾਮਿਕ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕਿਸ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਖੇਤਰ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਗਰੀਬ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਲਗਾਇਆ

ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੈਕਟਰ । ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਜੋ ਨੁਕਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ । (ਵਿਘਨ)

[*Depnty Speaker in the Chair*

ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੂਲ ਐਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਕਲਾਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਲਾਜ਼ 4, ਸਬ ਸੈਕਸ਼ਨ (1) ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ—

"4. (1) The Assessing Aut hority shall, in respect of each harvest for which a cess is payable under this Act. cause to be prepared in the prescribed manner a notice of demand jn respect of the cess payable by each landowner containing the following particulars, namely :—"

ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਆਫ ਡੀਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ । ਮੈਂ ਤਸੀਲ ਵਿਚੋਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਆਫ ਡੀਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ । ਫਿਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਸਤ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੋਟਿਸ ਆਫ ਡੀਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜਦ ਨੋਟਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਰਖੀ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਵਾਲਾ 30 ਦਿਨਾਂ ਤਾਈਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਨੋਟਿਸ ਆਫ ਡੀਮਾਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਕਿਹਦੀ ਕਰੇਗਾ ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਆਫ ਡੀਮਾਂਡ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਕ ਹੋਰ ਕਲਾਜ਼ ਹੈ 1 ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ

"11. (2)(a) the area of land on which no eess is to be levied undert he proviso to sub-scction (1) of section 3;"

ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਏਰੀਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਲੈਵੀ ਦੀ ਜ਼ਦ ਤੋਂ ਛਡਣਾ ਹੈ । ਮੈਂ 5 ਏਕੜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਮਿਰਚਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ । ਇਸ ਪਾਸੇ ਫੌਰੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ।

ਫਿਰ ਇਹ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੈਚਿਉਰਡ ਕਰਾਪ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਅਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸਨ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਚਿਉਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ । ਕਿਸੇ ਜਟ ਦੀ ਵੀ ਕਦੇ ਫਸਲ ਮੈਚਿਉਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ । ਹਾਂ ਪਟਵਾਰਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ

[ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ]

ਭਾਵੇਂ ਮੈਚਿਉਰਡ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ । ਕਿਉਂਕਿ ਸਨ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਚਾਲੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਕਸਾਲੀ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ । ਗੰਨਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ।

ਮੈਂ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਰਦ ਤਕਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਇਕ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਪਰ ਮੇਰਾ ਬੌਲਦ ਲੈ ਲਉ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਵਟ ਲਉ । ਇਥੋਂ ਤਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੌਲਦ ਤਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨਸੈਨਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ । ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਵਤਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮਰ ਮਿਟਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਮਰ ਮਿਟ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿਛਾਂ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ । (ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ)

ਇਹ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਤ ਮਰਦੇ ਹਨ ਪਰ

'ਵੋ ਅਪਨੀ ਖੂ ਨਾ ਛੋੜੇਂਗੇ ਹਮ ਅਪਨੀ ਵਜ਼ਹ ਕਿਉਂ ਬਦਲੇਂ ।

ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਜ਼ਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਜੀ. ਟੀ. ਰੋਡ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੇ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਫੌਜਾਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਚਾਹ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਲਾਲੀਆਂ ਭਖਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਗਾਂਦੇ ਸਨ

'ਵਾਹ ਰੇ ਸ਼ੌਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕੂਏ ਕਾਤਿਲ ਕੀ ਤਰਫ
ਗੁਨਗੁਨਾਤਾ ਰਕਸ ਕਰਤਾ ਝੂਮਤਾ ਜਾਤਾ ਹੂੰ ਮੈਂ"

ਇਹ ਇਸ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਓਰਿਜਨੈਲਿਟੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ।

ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਾਹਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੀਮ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੁਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ।

ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਵਕਤ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਲਈ ਹੈ ਖਾਦ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਜੇ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੁਕੰਮਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ......

Deputy Speaker : Please wind up now.

ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਚਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਮੈਥਡ ਹਨ ਉਹ ਅਡਾਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ । ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਜੇ ਤਕ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੰਪਲਸਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ । ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਪਲਸਰੀ ਕਰਨਾ ਸੀ । ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਉਥੇ ਲੈਂਡ-ਮੈਨ ਰੇਸ਼ੋ ਘਟ ਹੈ, ਪਰ ਫੀ ਏਕੜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਧ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਇਸਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਫਿਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ।

ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਲਾਕ ਡੀਵਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਿਹੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੀ ਉਨਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਉਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, that is, to block the development. ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ-ਅਹਿਲ ਹਨ । ਉਹ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।

ਭੁਵਨੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹੋ ਢੁਕਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਉਲਟਾ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਉਪਰ ਹਨ, ਟਹਿਣੀਆਂ, ਪੱਤੇ ਤੇ ਤਨਾ ਹੇਠਾਂ ਵਲ ਹਨ । ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਇਹ ਦਰਖਤ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ । ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਸਿਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਇਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ । ਇਹ ਸਾਇਲ ਹੈ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ । ਜਦ ਤਕ ਬਰਾਹੇਰਾਸਤ ਟੈਕਸ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਉੱਤੇ ਲਗਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ । ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਫਾਹਾ ਵਢਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ । ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਇਕਾਨੋਮੀ ਨੂੰ ਰੀਓਰੀਐਨਟੇਟ ਕਰੀਏ ।

ਇਕ ਗੱਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਫੀਅਰ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ । ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਕਾਨੋਮੀ ਵਿੱਚ ਵਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਐਸਾ ਅਨਸਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਲਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤਕ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ । ਸਾਨੂੰ ਐਸੀ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਟਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ, ਡਟ ਕੇ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਕ ਉਰਦੂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਲੈਣੀ ਵਾਜਬ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ । ਉਹ ਇਹ ਹੈ—

"ਬਜ਼ਮੇ ਸਾਕੀ ਮੇਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਾਮ ਅਕਲੋ ਹੋਸ਼ ਕਾ,
ਮਸਤ ਜਾਨਾ ਚਾਹੀਏ ਮਦਹੋਸ਼ ਆਨਾ ਚਾਹੀਏ ।"

ਮਾਲ ਮੰਤ੍ਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੇਜਰ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਇਹ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਇਹ ਹਾਊਸ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕਦੋਂ ਤਕ ਆਵੇਗੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਊਸ ਡੀਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਸ਼ੈਡੂਲਡ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹਾਊਸ ਡੇਢ ਵਜੇ ਤਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੋਂ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦਮ ਵੇਖਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਮ ਵੇਖ ਲਉ । ਅਕਲਮੰਦੀ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ ਸਮਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਕਹੋ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਜੇ ਕਹੋ ਇਕ ਇਕ ਤੋਂ ਪੁਛ ਲਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਵਕਤ ਲਵੇਗਾ । (The House can decide in this respect. According to the scheduled time this House will adjourn at 1-30 P.M., it was so decided at some previous stage. As regards the stamina of each side, both the sides may judge it themselves. They need not bother about me. The wisdom demands that you should take the least time to dispose of the business. If the House so desires I may enquire from the hon. Members in regard to the fixing of time limit for speeches.)

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਅੱਜ ਨਾਨ-ਸਟਾਪ ਸਿਟਿੰਗ ਹੈ । ਸਾਡਾ ਏਥੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਡੰਝ ਲਾਹੁਣਾ ਚਾਹੀਏ ਲਾਹ ਲਈਏ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਤਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਡੰਝ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹ ਲਉ । ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ । (I have no objection. The hon. Members may speak to their hearts content. What I wanted was to assess the sense of the House.)

ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ : ਜੇਕਰ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਜ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗਵਾ ਲਉ । ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਉ......

उपाध्यक्षा : I do not want your protection. आप अपनी आदत से मजबूर हैं । आप हमेशा चेयर को डिक्टेट करने की कोशिश करते हैं ।(I do not want your protection. The hon. Member is helpless by his nature. He always tries to dictate the Chair.)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ (ਮੋਗਾ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਿਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਆਇਆ ਹੈ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ । ਇਹ ਬਿਲ 1963 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਡਰ-ਟੇਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ

ਮਹਿਜ਼ ਦਸੰਬਰ 1965 ਤਕ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਾਏ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਇਹ ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ । ਜੇ ਕਰ ਸਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਨਾਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹਕਦਾਰ ਨਹੀਂ । ਅੱਜ ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਤਨੇ ਟੈਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ । ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈ । ਉਹ ਹਨ, ਵਾਟਰ-ਰੇਟ, ਲੈਂਡ-ਰੈਵੇਨੀਊ, ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਲੈਵੀ, ਸਰਚਾਰਜ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਰਚਾਰਜ, ਫੇਰ ਹੈ ਚੁਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ, ਚੌਕੀਦਾਰਾ ਟੈਕਸ, ਹਰੀਜਨ ਕਲਿਆਣ ਕਾਰੀ ਟੈਕਸ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਰਿਵਾਜ ਹਨ । ਇਸ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲੀਟੀਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਤਾਲੀਮ ਦਿਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਨੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ । ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਏਥੇ ਨੀਡ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਥੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਫੰਡਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤਾਈਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਘਟ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾ ਨਾ ਉਥੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਹੀਬ ਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ? ਜੇ ਪੁਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਜਟ ਦਾ 80% ਅਸੀਂ ਦਿਹਾਤੀਆਂ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਕਦੇ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਕੇ ਠੰਢੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਭਲੇ ਬਾਰੇ ਕਾਮਰੇਡ ਜੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਛਿਆ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਮਜਮਾ ਲਾਕੇ ਦੋ ਦੋ ਆਨੇ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਵੇਚਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਧੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਅੱਧੇ ਖੜੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ : "ਹਮ ਗ਼ੌਰ ਕਰੇਂਗੇ ।" ਅਜੀਬ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ । ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿਉ ਤਾਂ 2-2 ਘੰਟੇ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਥਕਦੇ । ਮੈਂ ਦਿਹਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਤਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਇਸ ਤਬਕੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ । ਇਹੋ ਤਬਕਾ ਹੈ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀ ਭਰਤੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਤਬਕਾ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ।

ਅੱਜ ਫਖਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ । ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ । ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਛੋਟਾ ਸੂਬਾ ਹੈ । ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ 56 ਫੀ ਸਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਡੀਫੈਂਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਫੌਜ ਵਿੱਚ 56 ਫੀ ਸਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ । ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ 99 ਫੀ ਸਦੀ ਹਨ ਤਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ । ਪਰ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡ ਜਾਂ ਪਰ ਟੂ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰਿਸਟ 99 ਫੀ ਸਦੀ ਡੀਫੈਂਸ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕੋਈ ਇਕ ਫੀ ਸਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ । ਜੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਾ ਦਿਉ ਪੇਂਡੂਆਂ ਤੇ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਲਈ ਡੀਫੈਂਸ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਤੇ ਏਥੇ ਆ ਕੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣਾ ਹੈ । ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੁਫਾਦ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ । ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਨਿਸਟਰ ਉਹ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ

[ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ]

ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਉ । ਏਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਵੀਨਿਉ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਮੈਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਇਕਠੇ ਕਰੋ । ਜੇਲ ਦੇ ਮਨਿਸਟਰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਾ ਕੇ ਦਿਉ । ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ? ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਲਾਸ ਤੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ? ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਲਾਉ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅੰਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਐਨੀ ਭੈੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ਲ ਕਰਾਪਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ—ਕਪਾਹ, ਮਿਰਚਾਂ ਤੇ ਗੰਨਾ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂ । ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ । ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗੰਨਾ ਘਟ ਬੀਜਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਦੇ ਬੀਜਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ । ਜੇ ਗੰਨਾ ਕਮਰਸ਼ਲ ਕਰਾਪ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਜਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਏਥੇ ਨਾ ਬੀਜਣ । ਅੱਜ ਯੂ. ਪੀ. ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ । ਯੂ. ਪੀ. ਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਓਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਬਾ ਗੰਨੇ ਥਲੇ ਰਖਦਾ ਹੈ । ਉਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ-ਲਾਗਿੰਗ ਹੈ । ਏਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਸ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ । ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੰਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਰਸ਼ ਘਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗੰਨਾ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਸਾਲ ਕਮਾਦ, ਗੰਨਾ ਬਹੁਤ ਘਟ ਬੀਜਿਆ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਖਾਂ ਏਕੜ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ 400 ਮਣ ਫੀ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਵਰੇਜ ਹੋਵੇਗੀ । ਮੇਰਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸ ਦਾ ਭਾਉ ਹੈ ਦੋ ਰੁਪਏ ਫੀ ਮਣ । ਉਸ ਤੇ ਲੇਬਰ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਮਿਲ ਤਕ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾੜਾ ਲਗਦਾ ਹੈ । ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਰੁਪਿਆ, ਸਵਾ ਰੁਪਿਆ ਫੀ ਮਣ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਖੱਟੀ ਹੈ । ਉਹ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਬੀਜ ਸਕਦਾ । ਜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਮੱਕੀ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਕਣਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਸਲ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਕਮਾਦ ਦੀ ਇਕੋ ਫਸਲ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ 400 ਮਣ ਫੀ ਏਕੜ ਗੰਨੇ ਦੀ ਉਪਜ ਤੋਂ ਐਕਸੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ । ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੰਨਾ ਕਮਰਸ਼ਲ ਕਰਾਪ ਹੈ । ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟ ਖੰਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੱਤਕ ਹੈ, ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'dogs and Indians are not allowed.' ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ । ਖੰਡ ਪੈਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੰਡ ਦਾ ਕੋਟਾ ਘਟ । ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੱਤਕ ਹੈ । ਦਿਹਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਮੋਬਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰੈਸ ਨਹੀਂ, ਦਿਹਾਤੀਆਂ ਕੋਲ ਸਟੇਜ ਨਹੀਂ । ਤੋ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਪਥੀਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਸੀ , ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੈਕਸ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ । ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਹਰ ਸਾਲ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ

ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ । ਜੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਛਣਾ ਨਹੀਂ । ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ? ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ? ਜੋ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉ । ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਉਸ ਤੇ ਨਾ ਲਾਉ । ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਦੀ ਈਵੇਜ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਮੇਰੇ ਲੀਡਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਵਾਸਤੇ ਏਥੇ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਈਵੇਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜੋ । ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਾਂ ਟੈਕਸੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਸੋ । ਇਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸ- ਪੋਰਟਰਜ਼ ਹਨ—ਮੈਂ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹਾਂ..(ਵਿਘਨ) ਮੈਂ ਟੈਕਸ ਈਵੇਜ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਟੈਕਸ ਈਵੇਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਕਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, । ਉਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਈਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਈਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦਸ ਦਸ ਜਾਂ ਵੀਹ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਲੈਂਦੇ ਹੋ । ਕਦੇ ਉਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਰਜਿਸਟਰ ਜਾਂ ਵਾਊਚਰ ਦੇਖੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਰੁਪਿਆ ਉਸ ਨੇ ਕਿਥੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂ ਬਲੈਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ ? ਕੀ ਉਸ ਤੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ? ਉਸ ਤੋਂ ਲਖਾਂ ਰੁਪਿਆ ਲੈਂਦੇ ਹੋ । ਕੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ? ਜੇ ਦਿਖਾਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ । ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਦਸਾਂਗਾ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਚੰਗੇ ਲਫਜ਼ ਵਰਤੋ, ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਹੋ । ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਫਜ਼ ਵਾਪਸ ਲਉ । (Please use decent language and say whatever you like. Please withdraw these words.)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿਦੇ ਨੇ..

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਇਹ ਲਫਜ਼ ਵਾਪਸ ਲਉ । (Please withdraw these words.)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਲਓ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਉ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਉ । (I would request Sardar Harinder Singh Major, the Minister for Revenue that he should better take a few members to the lobbies and consult them. He is doing very good work.)

ਮਾਲ ਮੰਤ੍ਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੇਜਰ) : ਉਹੀ ਗੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿਉ । (He may say now what he wants to say after full day's debate.)

ਮਾਲ ਮੰਤ੍ਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੇਜਰ) : ਮੇਰੇ ਵਿਚ ਐਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਪ ਏਧਰ ਜਾਂ ਓਧਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਾਂ । ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਪਰਸਪਰ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮਬਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ । ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ । ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਇਸ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਏਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਮੈਂ ਵੀ ਏਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਹੈ । (I was also of the view that they all will agree by his persuasive efforts.)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਪਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਜ਼ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਮੈਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਾਂ ਟੈਕਸੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੀ ਪਲੇਟ ਪਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਟੈਕਸੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ । ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਮ ਕੋਈ ਰੰਗ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀ ਦਾ ਇਕ ਪਰੈਸਕਰਾਈਬਡ ਰੰਗ—ਕਾਲਾ ਅਤੇ ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਹੋਏਗਾ ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਡੀਊਟੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੈਕਸੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਦੋ ਰੰਗੀ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੈਕਸੀਆਂ ਲਿਆਉ । ਪਿੱਛੇ ਜੇਹੇ ਏਥੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਨਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 80 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਡਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 80 ਦੀਆਂ 80 ਉਹ ਕਾਰਾਂ ਲਿਆਉ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ । ਹੁਣ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨਾ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੱਟਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਕਪਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ਲ ਬਣੀ । ਕਪਾਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਫੀਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ । ਕਪਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਉਦੋਂ ਸੈਸ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਫੀਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਵਾਈ ਛਿੜਕਾਉਂਦਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਪਾਇਲਟ ਵੀ ਮਰ ਗਏ । ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਠ ਦਸ ਆਦਮੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਾਰਣ ਵੈਸੇ ਕੀੜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ । ਅਜ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਬਲੈਕ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਪਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਨਹੀਂ । ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਸ ਘਾਟੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਸੈਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਉ । ਮਿਰਚ ਬੀਜਣੀ ਅਰਾਈਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕ ਅੱਧਾ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਬਾ ਲੈ ਕੇ ਗੋਡੀ ਕਰਨ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਰੋਟੀ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਏਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫਾਰਮਾਂ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਉਥੇ ਮਿਰਚਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਹਨ । ਮਿਰਚ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਬੀਜਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੈਸ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ,

ਜਿਹੜਾ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਹੈ । ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਕੇ ਕਈ ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਦਿੱਤਾ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਐਸੇ ਵੱਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਹਨ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਨਾਮ ਨਾ ਲਉ ਜੀ । (Please do not mention their names.)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਥੇ ਬਿਲ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ 40 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਛੋ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਅਨਾਜ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫੇਰ ਉਸ ਦੇ ਘਾਟੇ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ । ਜੇ ਮਾਮਲਾ ਮੁਆਫ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਮਨਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਰਾਬਾ ਲਿਖ ਦੇ । ਜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨਾ ਲਿਖੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕਾਰ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਈ ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਜੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਏਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦਸੋ ਸ੍ਰੀ ਡੀ. ਡੀ. ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਘਾਟਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ 40 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਦੇ ਦਿਉ । ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਆਪਣੀ ਰਿਆਇਆ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰਖਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਬੈਂਚਾਂ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਹਿਕ ਤੇ ਹੱਥ ਰਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਦੀ ਏਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮਦਾਦ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ । ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਮਨਿਸਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਦਮ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਹਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ, ਕੋਈ ਬੇਰੀ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਉਂਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇ ਬਲਾਕ ਬਣੇ ਹਨ ਬੇੜਾ ਹੀ ਰੁੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉਪਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਨਾਲਾਇਕ ਬੀ. ਡੀ. ਓ. ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਝਗੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬੀ.ਡੀ.ਓ. ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ । ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਬਲਾਕ ਤੋੜੋ ਜਾਂ ਨਾ ਤੋੜੋ ਪਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਰ ਦਿਉ, ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਅਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ । ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਛਡ ਕੇ ਯੂ. ਪੀ. ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ, ਏਥੋਂ ਦੇ 30 ਏਕੜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲੋਂ ਉਥੋਂ ਦਾ ਪੰਜ ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਚੰਗਾ ਹੈ । ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਉ। ਇਹ ਐਸੀ ਫ਼ਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੋਸਟ ਫਰਟਾਈਲ

[ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ]

ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੱਕੀ 34 ਰੁਪਏ ਕਵਿੰਟਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਔਰ ਹਾਪੜ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦਾ ਭਾ 70 ਰੁਪਏ ਕਵਿੰਟਲ ਹੈ । ਯੂ. ਪੀ. ਵਿੱਚ ਸੌ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਛੋਲੇ ਵਿਕਦੇ ਹਨ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 40 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾ ਨਹੀਂ । 30 ਮੀਲ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਦੁਗਣਾ ਭਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਏਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਪੀਣ ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਬੜੂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥਲੇ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ।

ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਸਾਰੇ ਗਰੁਪਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤਕਰੀਬਨ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ।(He has invited my attention towards this. That would do.)

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਸਾਡੇ ਗਰੁਪ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਜੋਸ਼ ਸਾਹਿਬ, ਤਸ਼ਰੀਫ ਰਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇਗਾ । (The hon. Member, Comrade Josh, may resume his seat. He will also get time to speak.)

ਸਰਦਾਰ ਤਿਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਰਿਆਸਤੀ (ਜੈਤੋ) : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੇ ਕਾਰਣ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ।

1-00 P.M.

(इस वक्त चौधरी देवी लाल न बैठे बैठे कहा कि क्या यह काला बिल्ला मेरे लिये ही रखा हुआ था ? कांग्रेस के मैम्बरों ने पहले बिल्ला लगाया और बाद में वह काला बिल्ला खोल दिया । जब यह बात सरदार त्रिलोचन सिंह रियास्ती ने सुनी, तो उसने भी अपना काला बिल्ला कमीज़ की बाईं बाज़ू पर लगा लिया ।)

ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਲ ਕੀਤੀ । ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।

उपाध्यक्षा : माननीय सदस्य अपनी पार्टी मीटिंग की बातें यहां पर रैफर न करें । (The hon. Member need not refer to his party affairs here on the floor of the House.)

ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਕੈਪਟਨ ਰਤਨ ਸਿੰਘ) : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਮੈਡਮ । ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈ ਹੈ ਅਤੇ

ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮੀਜ਼ ਦੇ ਖੱਬੇ ਬਾਜ਼ੂ ਉੱਤੇ ਬਿਲਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ? (ਹਾਸਾ)

ਸਰਦਾਰ ਤਿਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਰਿਆਸਤੀ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਛੁਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਊਸ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, । ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚੋਂ 53 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਉਥੇ ਉਸ ਬਿਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ। 53 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 18 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।

उपाध्यक्षा : आप कभी कभी डिस्कशन में हिस्सा लेते हैं। आप पार्टी मीटिंग की बातों का ज़िक्र न करें। आप बिल पर ही बोलें। (The hon Member participates in the discussion rarely. He should not refer to party meetings here. He should confine himself to the Bill only.)

ਕਾਮਰੇਡ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਮੈਡਮ। ਅਗਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੋ ?

ਸਰਦਾਰ ਤਿਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਰਿਆਸਤੀ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਰਖਿਆ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬੈਂਚਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਔਗੁਣ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਭੀ ਕਾਫੀ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਗੁਣ ਹੀ ਔਗੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤਕ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤਕ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਗ ਡੋਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੈਸੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ "ਜੈ ਜਵਾਨ" ਅਤੇ "ਜੈ ਕਿਸਾਨ" ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਉਪਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਖਿਆ ਲਈ ਚੰਦਾ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਆਇਤ ਸ਼੍ਰੀ ਥਾਪੜ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਬਿਰਲਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਨਾਅਰਾ ਤਾਂ "ਜੈ ਬਿਰਲਾ", "ਜੈ ਥਾਪੜ" ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ "ਜੈ ਜਵਾਨ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ "ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਭੁਲ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਫੀ ਮਜਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣ ਕੇ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ

[ਸਰਦਾਰ ਤਿਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਰਿਆਸਤੀ]

ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਰੀਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮਦਦ ਲਈ ਕਨਵਿੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ । ਸਰਕਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ 10 ਪਰੌਂਠੇ, ਇਕ ਕਿਲੋ ਛੋਲੇ, 6 ਜੂਸ ਦੇ ਗਲਾਸ, ਇਕ ਛਟਾਂਕ ਬਦਾਮ ਅਤੇ ਇਕ ਬੜਾ ਗਲਾਸ ਦੁਧ ਦਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਰਾਟੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਸਹੀ ਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ । ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ...

उपाध्यक्षा : क्या आपको भी सरकार ने दावत पर बुलाया है ? (Has the hon. Member also been invited by the Government in any parties ?

ਸਰਦਾਰ ਤਿਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਰਿਆਸਤੀ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਦੋ ਬਾਰ ਦਾਵਤ ਖਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ । ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਦਸ ਸਕਿਆ ਹਾਂ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਚੀਨ ਇਕ ਬਹੁਤ ਮੱਕਾਰ ਦੁਸ਼ਮਨ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਨ ਹੈ । ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭੀ ਚਾਲਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੈ । ਚੀਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ । ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੀਲੋਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਚਾਵਲ ਖਰੀਦਦਾ ਸੀ। ਸੀਲੋਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ 98 ਪੌਂਡਜ਼ ਤੇ ਚਾਵਲ ਖਰੀਦਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਚੀਨ ਨੇ ਸੀਲੋਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 54 ਰੁਪਏ ਫੀ ਮਣ ਤੋਂ ਚਾਵਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ । ਕੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ? ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਦੋ ਫਸਲਾਂ, ਕਾਟਨ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰਕੇਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫਾਰੇਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਅਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ।

ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਮਰਸ਼ਲ ਕਰਾਪਸ ਦੀ ਉਪਜ ਘਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਫਾਰੇਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਭੀ ਘਟ ਅਰਨ ਕਰ ਸਕੇਗੀ । ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜਾਈ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ । ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਬਹੁਤ ਘਟ ਬਣਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਾਰੇਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਅਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ । ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਉਤੇ ਸੈਸ

ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਡਿਸਕਰੇਜ ਹੋ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਘਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਵੇਲੇ 17 ਲਖ ਏਕੜ ਵਿੱਚ 11.25 ਲਖ ਕਾਟਨ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 7 ਲਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ । ਇਸ ਵੇਲੇ 11.47 ਲਖ ਮਣ ਗੰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਉੱਤੇ ਖਰਚ 50% ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ । ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਕਲਾਥ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ? ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਰੇਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਅਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ? ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਨਾ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੀਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ।

ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ । ਮੈਂ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਬੜੇ ਭਲੇ ਮਾਣਸ ਹਨ, ਮੈਂ ਹਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤਕ ਨਾ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇ । ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ non-stop ਸਿਟਿੰਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ request ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ । ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਉ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ । ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੁਡਵਿਲ ਤੁਸੀਂ ਅਰਨ ਕਰੋਗੇ, ਅਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਉ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡੀਫੈਂਸ ਲਈ ਵੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ ।

ਇਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਰੁਪਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫੰਡਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਕੜਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ । ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਰੁਪਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚਲਕੇ ਅਤੇ ਵਿਪ ਲਗਾ ਕੇ ਵੋਟ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋ ਤਿੰਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਹੀ ਸਮਝੇ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਧੜੱਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇਗੀ । ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵਿਨ ਓਵਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਮੇਰਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 50 ਫੀ ਸਦੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਅਗਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵਿਪ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰ ਵੋਟ ਦੇ ਦੇਣ ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ (*looking towards opposirion*) ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ।

चौधरी सत्यदेव (फाजिलका) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, आपने मुझे टाईम दिया है मैं आपका धन्यवाद करता हूँ । सरकार यह जो बिल पास करवाने जा रही है मुझे समझ नहीं आती कि इसका नाम कमर्शियल क्राप्स बिल कहा जाए या किसान कमर तोड़ बिल कहा जाए । बड़े

[चौधरी सत्य देव]

अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब आज से तीन वर्ष पहले इसी हाउस में यह बिल पास हुआ था तो उस वक्त मैम्बरों ने इसे एक आर्ज़ी बिल कह कर पास कर दिया था, अभी उस बिल की मयाद 31 मार्च, 1966 तक बाकी है फिर भी न जाने कि सरकार क्यों इतनी जल्दी इसमें तरमीम करने जा रही है । मैं आपके द्वारा हाउस में यह अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अभी देश में एमरजेंसी थी, इस बिल को पास करवाने का उचित समय नहीं था । एक तरफ तो हमारी सरकार यह पास करती है कि बार्डर एरियाज़ के ज़िलों में आब्याना माफ किया जाएगा और दूसरी तरफ यह टैक्स भी लगा रही है । मैं मिनिस्टर साहिब से दरखास्त करना चाहता हूँ कि आपने जो नारा 'जय किसान, जय जवान' का लगाया है वह बिल्कुल दुरुस्त है लेकिन यह जो इनाम आप किसानों को देने जा रहे हैं यह क्या सोच कर दे रहे हैं, यह बात शोभा नहीं देती । ये जो तीर आप अपने धनुष में चढ़ा रहे हैं इस से एक, दो, या तीन किसानों का खून नहीं होगा बल्कि इससे हज़ारों और लाखों किसान घायल होने वाले हैं । वे लोग आपको बददुआ देंगे । एक तरफ तो हमारे लीडर यह नारा लगाते हैं और लोगों को कहते हैं कि दिल्ली की कोठियों में अन्न पैदा किया जाए ताकि अनाज की कमी को पूरा किया जा सके । इस बात को मद्देनज़र रख कर किसानों ने जो एरिया उन की ज़मीनों के साथ अनकमांडिड था कमांडेबल बनाया । उस रक्बे को कमांडेबल बनाने के लिये उनको सख्त मेहनत करनी पड़ी । अपने पानी से बचत करके उन्होंने उस ज़मीन पर फसल बोई ताकि देश की उपज में वृद्धि हो । ऐसी नई ज़मीन निकालने के सिले में सरकार को किसानों को रियायत देनी चाहिए थी । लेकिन सरकार ने उनको क्या रियायत दी है ? दूसरी ज़मीनों पर तो अढ़ाई रुपये बैटरमेंट लैवी ली जाती है लेकिन जो ज़मीन किसान ने अपनी मेहनत से देश के भले के लिये बनाई है उस पर दस रुपये एकड़ बैटरमेंट लैवी ली जाती है । उनके साथ रियायत की जगह पर बेइनसाफी हो रही है । अढ़ाई रुपये की जगह पर उनसे दस रुपये फी एकड़ चार्ज किये जाते हैं ।

किसान खांड और गुड़ पैदा करने वाला है । लेकिन हाउस में बहुत से मैम्बरान ने बताया है कि देहात में खांड की पोज़ीशन क्या है । देहात में किसानों को बहुत कम खांड दी जाती है और जो भी दी जाती है वह भी बहुत मुश्किल से । शहरों में तो लोग हर महीने अपना कोटा मुकर्रर टाईम पर ले लेते हैं। अब गांव में गुड़ की कमी की वजह से किसान अपनी और अपने हल चलाने वाले पशुओं की जरूरतों को कैसे पूरा करें । अपनी जरूरत को भी पूरा करने के लिये उसको जा कर लाईन में खड़ा होना पड़ता है । लेकिन हमारे मिनिस्टर साहिब इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते और आंखें मूंदें बैठे रहते हैं । बार बार ज़िक्र करने पर भी बात नहीं सुनते । किसान की उपज का दारोमदार खाद, पानी और बीज तीन चीज़ों पर है । पानी तो वैसे नहीं मिलता और खाद की कीमत इतनी ज्यादा है कि किसान बेचारा बरदाश्त नहीं कर सकता । बीज के बारे में अर्ज़ करूँ । हमारे गांव में पंचायत अफसर और बी०डी०ओ० गए और कहने लगे कि बढ़िया बीज अमरीका से आ रहा है सब को दिया जाएगा । उसके लिये अपनी ज़मीनें तैयार कर लो । बीज बहुत बढ़िया है उससे अनाज बहुत ज्यादा पैदा होगा । किसानों ने मेहनत करके अपनी ज़मीनें तैयार कीं, अब सरकार का फर्ज़ था कि वक्त पर उनको बीज मुहैया किया जाता मैं अपने ब्लाक की बात करता हूँ कि वहां पर वह बीज केवल चार ऐसे ज़मींदारों को दिया गया जो कि बड़े ज़मींदार थे । जो बेचारे ज़मीन पर मेहनत करते रह गए उनको बीज नहीं दिया गया । लेकिन

जिनको बीज दिया गया उन्होंने अभी तक बोया ही नहीं । कर्मचारियों ने कहा था कि इस बीज को खाद के साथ बोना है और खाद उनको अभी तक हासिल नहीं हो रही, पानी नहीं मिल रहा । देश की पैदावार को नुकसान हो रहा है लेकिन मिनिस्टर साहिब इस तरफ ध्यान नहीं देते। पिछले दिनों इन्होंने ऐलान किया था कि ट्यूबवैल्ज़ के लिये बिजली देने के मामले में प्रैफ़ैंस दी जाएगी । जिन ज़िमींदारों ने कर्ज़े लेकर ट्यूबवैल लगाये उनको अभी तक बिजली का कुनैक्शन नहीं मिल रहा । कई बार मिनिस्टर साहिब के नोटिस में यह बात लाई जा चुकी है । मिनिस्टर साहिब जानते हैं कि भाखड़ा नहर से खेतों को पानी बीस फीट लम्बी और 6 इंच चौड़ी नाली से दिया जाता है । लेकिन वह पानी खेतों में पहुंचता नहीं है । अगर थोड़ा सा पानी भी खेतों में चला जाता है तो सरकार बैटरमेंट लैवी चार्ज कर लेती है । आज से चालीस पचास साल पहले रियास्त बहावलपुर में नई ज़मीनों को आबाद करने के लिये सरकार ने बड़े बड़े मोघे लगाए थे। वहां भी अगर थोड़ी सी फसल खराब होती थी, पानी नहीं आता था तो दरखास्त देने पर खराबे की छूट दे दी जाती थी । लेकिन आज कल खराबे की छूट नहीं दी जाती । अब सरकार कपास, गन्ना और मिर्चों की फसल पर टैक्स बढ़ा रही है ।

कपास उन्होंने बीज तो दी लेकिन पानी नहीं मिला। और अगर खराबे की दरखास्त पेश करते हैं तो उस तरफ ध्यान नहीं दिया जाता । इसलिये इन शब्दों के साथ मैं यही अर्ज़ करूँगा कि यह सैस बिल वापिस ले लिया जाए तो अच्छा है । इस तरह आप लोगों से मजाक न करवाएं ।

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ (ਫੂਲ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਮਰਸ਼ਲ ਕਰਾਪਸ ਸੈਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਰਿਲੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਥੇ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਆਰਜ਼ੀ ਟੈਕਸ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਬੜੇ ਦੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਇਕਾਨੋਮੀ ਦੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਬੜੇ ਦੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਉਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਫਟ ਮਿਲਿਆ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ । ਉਸ ਦੀ ਬਾਬਤ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਹੋਈ । ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਵਲੀਅਨ ਟਰੱਕਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ । ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਵਾਲਾ ਬਿਲ ਆ ਗਿਆ । ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੁਕੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ ਕੀਤਾ ! ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਸਿਉਂ ਪਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ—ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨੈਸਮੈਨ ਇਸ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਾਵੀ ਹਨ ਔਰ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਾਵੀ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁੰਗੇ ਕਿਸਾਨ ਬਾਰੇ ਇਹ ਬਿਲ, ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ । ਜੇਕਰ ਉਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ । ਸਾਡੇ ਚੀਫ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ 'ਕਾਮਰੇਡ' ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ ।

[ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ]

ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੇਡੀਓ ਉੱਤੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਕ ਕਾਮਰੇਡ ਚੀਫ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਸ ਬਝ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਰੀਜਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਵਰਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਰਲੇ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਹਨ, ਇੰਡਸ-ਟਰੀਅਲਿਸਟ ਹਨ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਲਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਹਰੀਜਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ।

ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮਰਸ਼ਲ ਕਰਾਪਸ ਸੈਸ ਅਗਲੀਆਂ ਦਸ ਫਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚਾਰ ਰੁਪਏ ਫੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ? ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ? ਇਕ ਕਰੋੜ ਨੌਂ ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਨੰਗਲ ਫਰਟੇਲਾਈਜ਼ਰ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਫਿਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਖਾਦ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਫੈਕਟਰੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਖੜਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਸਰਿਆ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਫੇਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਾਦ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲੇ, ਪ੍ਰਾਫਿਟ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਜਾਵੇ । ਸਾਡੇ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਥੇ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੁਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਉਪਜ 14 ਟਨ ਪਰ ਏਕੜ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਜਾਵਾ ਵਿੱਚ 46 ਟਨ ਔਰ ਸਮਾਟਰਾ ਵਿੱਚ 56 ਟਨ ਪਰ ਏਕੜ ਹੈ । ਉਸ ਦੀ ਰੀਕਵਰੀ ਉਥੇ 10 ਪਰਸੈਂਟ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਰੀਕਵਰੀ 8 ਪਰਸੈਂਟ ਹੈ। ਬੜੇ ਦੁਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਹੈ ਮਗਰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ । ਉਧਰ ਵਾਟਰ ਰੇਟ ਵਧਾਏ, ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਪਰ ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਰੁਪਏ ਮਣ ਦੀ ਥਾਂ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਮਣ ਕਰ ਦਿਉ ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ । ਇਸ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਬਾਲਣ ਵਾਲੀ ਲਕੜੀ ਦਾ ਭਾ ਵੀ ਚਾਰ ਰੁਪਏ ਮਣ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਜਿਸ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਬੀਜਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅਜੇ ਵੀ ਦੋ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ । ਫੇਰ ਉਸ ਗੰਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੰਡ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਾਲ ਅਟੈਨਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ । ਕੋਈ ਬੀਮਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਖੰਡ ਨਹੀਂ ਲਭਦੀ । ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਭਰਾ ਫੱਟੜ ਹੋ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ । ਚੀਨੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹਨ ? ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਿਲ ਮਾਲਿਕ । ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਫਗਵਾੜੇ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ । ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਾਰੇਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ

ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ । ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਵਡੇ ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪਿੱਛੇ ਸਨ 1962–63 ਵਿੱਚ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਐਕਸ ਗਰੇਸ਼ੀਆ ਗਰਾਂਟ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡਜ਼ ਇਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਮਈ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਜਦ ਗੰਨਾ ਪੀੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰੀਕਵਰੀ ਘਟ ਹੋਈ । ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ । ਉਸ ਵਕਤ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੈਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਰਪਟ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ, ਧਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕਾਮਰੇਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ? ਇਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਦੇ ਸੈਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ । ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਅਰਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ? ਇਥੇ ਹੁਣੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਸਨ । ਹੁਣ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ । ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਬੈਠੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ । ਮੇਰੀ ਕਾਂਸਟੀਚੂਐਂਸੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਦ ਗਏ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਤੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਉਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੋਘੇ ਪੁਟ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੇ । ਪਰ ਪਾਣੀ ਉਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ । ਸਿਰਫ 15–20 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਉਹ ਖੁਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਐਸ. ਡੀ. ਓ. ਨੇ ਕਰਾਈਆਂ । ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਕਟੇਮਾਈਜ਼ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ? ਵਿਕਟੇਮਾਈਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਰ ਇਤਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਠੱਪ ਦਿੱਤਾ । ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡਰੌਟ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਿੰਜ਼ ਹਨ । ਖਰੀਫ਼ ਦੀ ਫਸਲ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਰਬੀ, ਵੀ ਤਸਲੀ ਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ । ਜਦ ਬਿਜਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਿਥੋਂ ਹੋਵੇਗੀ । ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ "ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ" ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਪਏ ਲਗਾਉ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਫੋਕਾ ਨਾਅਰਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ । ਕੋਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਇਕ ਦੋ ਦੋ ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਬੀਜਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਸਿਆ ਹਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣ ਲੱਗੀ । ਬਿਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ । ਬਲਕਿ ਹੱਲ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਜਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ, ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਨ ਲਗਾਉਂਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦਿੰਦੀ । ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਫਿਕਸ ਕਰਦੀ । ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ ਉਹ ਇੰਜਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਲੈਕ ਵਿੱਚ 2500 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ! ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਅ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੈਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ । ਲੋਕ ਖੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹਸਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ । ਲੇਕਿਨ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉ ਕਿ ਇਕ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਢਾਈ ਢਾਈ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਇਕ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਨ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ । ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਪਾਨ ਨਾਲ ਕਾਰੈਸਪਾਂਡੈਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇਵੇਗੀ । ਪਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦ ਕਾਰੈਸਪਾਂਡੈਂਸ ਫਾਈਨੇਲਾਈਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਦ ਇਹ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਕਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ । ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਈਰਾਨ ਚੋਂ ਤਰਿਆਕ ਆਵੇਗਾ ਤਦ ਤਕ ਤਾਂ ਸੱਪ ਦਾ ਡਸਿਆ ਹੋਇਆ ਮਰ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ । ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜ ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੈਸਿਉਂ ਉਹ ਟੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ

[ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ]

ਤਾਂ ਫੇਰ ਉਹ ਫਸਲ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਗਾ ? ਇਹ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਾਕ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਲ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਚਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚਨੇ ਦਾ ਭਾ 50 ਜਾਂ 51 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਉਹੀ ਬੰਬਈ ਔਰ ਮਦਰਾਸ ਜਾਕੇ 170 ਰੁਪਏ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਫਿਟ ਹੈ ਇਹ ਇਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਫਿਟ ਫੇਰ ਕਿਸ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ? ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਿਰਲੇ, ਟਾਟੇ ਔਰ ਡਾਲਮੀਏ ਕੋਲ। ਇਹ ਚਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਰੱਖਣ। ਉਹ ਉਹੀ ਜਿਨਸ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਕੇ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ 170 ਔਰ 180 ਰੁਪਏ ਦੇ ਭਾ ਉੱਤੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਦੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬੜੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਚਾਰ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਮਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਥੇ ਦੇ ਭਾ ਵਿੱਚ ਔਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਭਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਅਹਿਲੀਅਤ ਦੀ ਵਜਹ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ? ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ। ਇਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਕ ਮੋਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਮਨ ਕਾਬਲੀ (ਸਫ਼ੇਦ) ਚਨਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਣ।

ਅਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆੜ੍ਹਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਤਲਬ ਲਈ ਆਏ ਦਿਨ ਇਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਕਾਫੀ ਖਰਚ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਆਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਟੈਂਡਰ ਭਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਨੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 1962 ਵਿੱਚ ਜਦ ਚੀਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਨੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੀਫੈਂਸ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ $4\frac{1}{2}$ ਕਰੋੜ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਪੇਂਡੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਜ਼ਿਲਾ ਪਰੀਸ਼ਦਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਮਾਰਕਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਜੋ ਬਿਰਲੇ ਵਰਗੇ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਔਰ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲੋਨ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲੇਟੀਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ $4\frac{1}{2}$ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਆਦਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਤਿ-ਆਜ਼ੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿਤਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਜ਼

ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਤ ਰਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਔਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇਣ । ਜ਼ਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਇਤਨੇ ਲਿਮਟਿਡ ਰੀਸੋਰਸਿਜ਼ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਇਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਕੂਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਐਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਜ਼ ਇਸ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ । ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ—

"If you want to see real India, go to the remotest corner."

ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਅਸਲੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਪਰ ਇਥੇ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਾਰਨ ਡਿਗਨੇਟਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੰਜੌਰ ਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ...

Deputy Speaker : Kindly wind up now.

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਤਾਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਔਰ ਬਿਲ ਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੋ । ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰੋ । (I have not said that the hon. Member is irrelevant. I have only requested him to kindly wind up now.)

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗਾ ।

ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੜੇ ਟੈਕਸ ਲਗੇ ਹੋਏ ਨੇ । ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗਿਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੈਲੇਂਜ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗਿਣ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਟੈਕਸ ਫੀ ਏਕੜ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਣਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪਟਵਾਰੀ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਉਹ ਪੁਛ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਇਕ ਏਕੜ ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਮਾਲੀਆ, ਕਿਤਨਾ ਆਬਿਆਨਾ, ਕਿਤਨੀ ਬੇਟਰਮੈਂਟ ਲੈਵੀ, ਕਿਤਨਾ ਸਰਚਾਰਜ ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਰਚਾਰਜ ਔਰ ਕਿਤਨਾ ਇਹ ਕਮਰਸ਼ਿਅਲ ਸੈਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ । ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁਛੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁਛੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ । ਕੁਝ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੇਸ਼ੋ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਨਾਸਬ ਨਹੀਂ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਭਾਰੀ ਦੁਖ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ।

[ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ]

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੀਸੋਰਸਿਜ਼ ਦੱਸਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰੁਪਿਆ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਰੈਵੇਨਿਊ ਮਨਿਸਟਰ ਸਨ ਔਰ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ ਰੀਸੋਰਸਿਜ਼ ਐਂਡ ਰੀਟਰੈਂਚਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਚ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਈ. ਏ. ਐਸ. ਔਰ ਆਈ. ਸੀ. ਐਸ. ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਪਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਮੈਮੋ-ਰੈਂਡਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਰੇਟੇਰੀਏਟ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਪਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਨਸਾਲੀਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਲਵਾੜੇ ਤੇ ਬਿਆਸ ਤੇ ਲਗੇ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ......

Dep uty Speaker : Kindly wind up now.

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕਹਿ ਲੈਣ ਦਿਉ।

ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੈਸ ਪਹਿਲੇ ਹੀ 31 ਮਾਰਚ, 1966 ਤਕ ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾਣ ਲਈ ਇਹ ਬੜੇ ਕਾਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਗਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਕਿ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸੈਸ ਵੀ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Deputy Speaker : Now please take your seat. There must be limit to everything.

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਬਸ ਜੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਾਧਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਰੁਪਏ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਗਾਣੇ ਪੈਣ।

ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟ ਟਰੇਡਿੰਗ ਤੋਂ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕੌਮੀਕਰਨ ਨਾਲ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਰੀਵੀ ਪਰਸ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਜ਼ਾਮ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਜਿਸ ਨੇ 1962 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਪਾਸ ਡੀਫੈਂਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰੀਵੀ ਪਰਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਉ ਬਿਰਲੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੀਫੈਂਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਭਰਤ ਲਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਕਲਾਥ ਮਿਲ ਭੀਵਾਨੀ ਦਾ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਡੀਫੈਂਸ ਫੰਡ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹਾਲੇਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 18 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਕਾਮਰੇਡ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵਟਦੇ ਹਨ ਪਰ ਟੈਕਸ ਲਾਣ ਲਈ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲ, ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲ ਔਰ ਗਰੀਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਵਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਫਿਰ ਜੋ ਰੁਪਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਸਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਔਰ ਬਚਿਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮਨਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ......

Deputy Speaker : Order please. Now please take your seat.

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਮੈਡਮ । ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ 'ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਤੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਕੀ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢ ਸਕੇ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੁਣ ਬਸ ਕਰੋ, ਭੜਾਸ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲ ਲਿਆ ਹੈ । (I request the hon. Member to resume his seat now. To vomit out every thing sometimes does not prove fruitful. He has made a very good speech.)

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਮੈਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਹੁਣ ਬਸ ਕਰੋ । (The hon. Member belongs to a well disciplined party. Now he should resume his seat.)

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੈਲੇਵੇਂਟ ਬੋਲਦਾ ਸੀ...

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੋ ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ । (I do not say he is irrelevant but he cannot go on speaking for 3 days.)

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਮੈਂ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ......(ਵਿਘਨ)

ਚੌਧਰੀ ਜਗਤ ਰਾਮ (ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਰੈਵੇਨਿਊ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਸਿਉਂ ਅਤੇ ਨਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਉਂ ਹੀ ਕੋਈ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਜੋ ਇਸ ਨੇ ਦਿਹਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਮਗਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਏ, ਮੁਲਕ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿਡ ਭਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ । ਇਥੇ ਨਹਿਰਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਧੀਆਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਅੱਧੀਆਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਪੁਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ । ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 3, 3

[ਚੌਧਰੀ ਜਗਤ ਰਾਮ]

ਮੀਲ ਤੇ ਪੁਲ ਹੋਵੇ ਮਗਰ ਪੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ, ਨਾ ਹਲ ਨਾ ਡੰਗਰ, ਕੁਝ ਵੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਫਿਰ ਇਕ ਹੋਰ ਰੂਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਈ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵੇਗੀ । ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਬੇਸ਼ਕ ਲਾਵੋ ਮਗਰ ਇਹ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਰਖੋ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲਣ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਸੇਮ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਖਿਆ ਹੈ, ਖਾਦ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਾਅਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ । ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖ਼ਿਆਲ ਰਖੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ । ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਮਲਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਗਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਲਭਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਲੀਆ ਮਾਫ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥੋਂ ਮਾਮਲਾ ਲੈ ਲਉ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਖ਼ਿਆਲ ਤਾਂ ਰਖੋ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰੋ । ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ; ਸੇਮ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੋ, ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪੁਲ ਬੰਨ੍ਹੋ, ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਲਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿਉ, ਖਾਦ ਸਪਲਾਈ ਕਰੋ ਆਦਿ । ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ । ਮੈਂ ਰਾਹੋਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਉਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਗਈਆਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ, ਸਾਲ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਮਹਿਕਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਆਰਿਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸੀਨਿਅਰਿਟੀ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੇ 2,000 ਰੁ: ਭੇਟਾ ਕਰੋ । ਉਹ ਕਿਥੋਂ ਲਿਆਵੇ ਇਤਨਾ ਪੈਸਾ । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਲਉ ਇਹ ਬਿਲ, ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਲਉ ਮਗਰ ਉਸਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤਾਂ ਹਲ ਕਰੋ । ਕਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਝਗੜਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ । ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਨਾਜ ਵੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਹਰੀਜਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਾਂਗਾ । ਇਹ ਲਾਰੇ ਲਪੇ ਦੇ ਢੰਗ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ । ਟੈਕਸ ਬੇਸ਼ਕ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਲਾਉ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਰੇ ਲੱਪੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਣ ਦਿਆਂਗੇ । ਆਪ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ । (ਵਿਘਨ)

चौधरी देवी लाल : On a point of order, Madam. यहां तीन दफा स्पीकर बदले हैं हमारी तरफ किसी का ध्यान नहीं आता । हमें भी मौका मिलना चाहिए ।

ਸਰਦਾਰ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ : On a point of order, Madam. ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ । 10–15 ਬੈਠਕਾਂ ਮੈਂ ਕਢ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੀਮਾਰ ਵੀ ਹਾਂ । ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਸ ਦਿਉ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਢਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਕੋ ਵੇਰ ਮੈਂ ਉਨੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਮਾਰ ਲਵਾਂ (ਹਾਸਾ) ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੇਵੋ । (*Interruption*)

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : On a point of order, Madam ਮੈਂ ਇਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਕਾਂ ਕਢਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਜ਼ਾਈ ਦੇ ਦਿਉ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਿਆਏ ਸਨ.....(ਹਾਸਾ) (ਵਿਘਨ)

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਇਹ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਹੈ? (What is this point of order? (*Interruption*).

श्री सुरेन्द्र नाथ गौतम : On a point of order, Madam.

Deputy Speaker : No please. (*Interruption*).

(*Shri Surendra Nath Gautam staged walk out.*)

ਸਰਦਾਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ (ਬੰਗਾ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਹ ਜੋ ਬਿਲ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਬੋਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿ ਚੁਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਬਿਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। (*At this stage, Shri Ram Saran Chand Mital a member of the Panel of Chairmen, occupied the Chair.*) ਮਗਰ ਜਿੱਥੇ ਤਕ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਤੱਅਲੁਕ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਨ ਵੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਗਣਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੁਪਿਆ ਸਰਕਾਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ, ਸੈਕਰੇਟੇਰੀਏਟ ਦੇ ਅਮਲੇ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਹੀ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੀਟਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਉਹ ਲੋਕਵਾਵੇਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਛੋ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ "ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ"। ਖਾਦ ਹੈ ? "ਨਹੀਂ ਬਲੈਕ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।" ਪਾਣੀ ਹੈ ? ਕਿਥੇ ਜੀ, ਇਸ ਬਾਰ ਤਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬੀਜ ਹੋਵੇਗਾ ? "ਕਾਹਨੂੰ ਜੀ ਅੱਜ ਕਲ ਬੀਜ ਕਿਥੇ ਲਭਦਾ ਹੈ।" ਜੇ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਬੀਜ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਤਕ ਨਏ ਕਿਸਮ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਲੈਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਹੈ ? ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। (ਵਿਘਨ) (ਆਵਾਜ਼: ਉਹ ਕਿਉਂ?) ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹਨ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਰਕਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਤਕਾਵੀ ਜਮਾਂ ਕਰਾਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤਕਾਵੀ ਲੈਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। (ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸੰਸਾ) ਇਕ ਵੀ ਮਹਿਕਮਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਢੰਗ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਤਬਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। **(ਵਿਘਨ)**

ਸ੍ਰੀ **ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਵਿਜ** : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ । ਕੀ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮਕਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? (ਵਿਘਨ)

Minister of State for Animal Husbandry and Agriculture (Captain Rattan Singh) : A lady offered me something and I have just kept it.

ਸਰਦਾਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ । ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਪਰ ਇਥੇ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਲਰਕ, ਤਸੀਲਦਾਰ, ਨਾਇਬ-ਤਸੀਲਦਾਰ, ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਸੌਖੇ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਹਨ ਇਸ ਪਾਸੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਅਮੀਰ । ਇਥੇ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ।

ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ । ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ 75 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਖੁਣੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਿਆ ਹੈ । ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਹੁੰਚਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ।

ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਸ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਪਾਸੋਂ ਇਤਨਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਵੀਹ ਜਾਂ ਤੀਹ ਮੀਲ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਜਾਂ ਸਤ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਏਡ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਦਿਹਾਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਘੰਟੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ ਵੇਲੇ ਮੌਤ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਨ ਵੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ। ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਰ ਟੈਕਸ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਥੇ ਬਿਰਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸ਼ੋਰ ਪਿਆ, ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਮੈਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਆਪ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਰਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਕ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ

ਦੁਗਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਚਪਾ ਚਪਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੇ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਇਕ ਇਕ ਸੌ ਏਕੜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਲਾਟ ਇਥੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਇਕ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਕੇ ਬੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਸਤ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪਲਾਟ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ । ਉਸ ਨੇ ਸਤ ਹਜ਼ਾਰ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਰਕੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪਾਸ ਜਮਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ । ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬਿਡ ਮਨਜ਼ੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਉਸ ਨੇ 15 ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ । ਜਦ ਬੀਜਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਉਸ ਪਾਸ ਗਈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਲੀਜ਼ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਤ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਮੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾ । ਸੋ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਲਾਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਝਟ ਮੁਨਕਰ) ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਕੋਈ ਕਾਇਦਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ । (**ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ** : ਸਤਿਨਾਮ (ਹਾਸਾ) ਮੈਂ ਇਹ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਆਪ ਦੀ ਰਾਹੀਂ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜੇਕਰ ਚਲਦਿਆਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਕਾਫੀ ਰੁਪਿਆ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਤਾਂ ਇਕ ਚੰਗੀ ਸਕੀਮ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਐਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ । ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਐਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਪਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ । ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਬਗੈਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਦੇ ਹੋਰ ਸੋਰਸਿਜ਼ ਨਾਲ ਰੁਪਿਆ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੇਕਰ ਉਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਆਇਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਦਾਮ ਸਨ । (ਵਿਘਨ) ।

श्री सभापति (श्री राम सरन चंद मित्तल) : क्योंकि मैंने ज़रा जाना है और पैनल आफ चेयरमन में से कोई भी इस वक्त हाऊस में हाज़र नहीं इस लिये अगर आप एप्रूव करें तो खान अब्दुल गफार खान को कुर्सी संभालने के लिये कहा जाए । (Since I have to go out and no member from the Panel of Chairmen is present in the House at the moment, therefore, if the House approves Khan Abdul Ghaffar Khan may be requested to occupy the Chair.)

आवाज़ें : ज़रूर ज़रूर ।

(इस समय खान अब्दुल गफार खां ने कुर्सी संभाली। हाउस की तरफ से प्रशंसा और जोरदार तालियां)

ਸਰਦਾਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ : ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸਾਡੇ ਪਾਸ ਆਇਆ ਹੈ ਕਣਕ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਗੁਦਾਮ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੀਡ ਸੀ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਹਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮਾਲ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕਾਰਆਮਦ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੰਦਮ ਦਾ ਸਟਾਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਤਨਾ ਮੋਟਾ ਦਾਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਸੀਡ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਜੇ ਇਹ ਸੀਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਰਕੀ ਵਿਖੇ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਣਕ ਦਾ ਸਟਾਕ ਉਥੋਂ ਕਢਵਾਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਡੀਟੇਲਡ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ (**ਇਕ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ** : ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬਾਲਮੀਕੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇਗੀ) (ਹਾਸਾ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਰਿਆ ਕਰਾਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਸੀਡ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਡਬਲ ਝਾੜ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਕੇਸ ਠਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਲਾਈਮੇਟ ਨੂੰ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਪੁਛ-ਗਿਛ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕਲਾਈਮੇਟ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਕਲਾਈਮੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫਰਕ ਹੈ ਜੋ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਇਤਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ।

2 p. m.

चौधरी देवी लाल (फतेहबाद) : चेयरमैन साहिब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जो आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया। आज किसान पर टैक्स लगने का सवाल है— किसान पर । मगर इनको क्या ? क्योंकि :—

वह क्या जाने पीर पराई,
जिसके पांव न फटी बिवाई।

यह कहते हैं कि एक मामूली सी बात थी जिस पर खाहमखाह में बहस हो रही है। पता नहीं क्यों मुखालिफत आगे वाले भी कर रहे हैं, पीछे वाले भी कर रहे हैं, इधर वाले भी कर रहे हैं और उधर वाले भी कर रहे हैं। कांग्रेस वाले भी कर रहे हैं, गैर-कांग्रेसियों ने तो करनी ही थी। मामूली सी बात थी। पहले 1963 से लेकर 1965 किया था, अब 1965 से 1970

यह करना चाहते हैं और कोई बात नहीं है (हंसी) मगर 4 दिन से इतना शोर शराबा इस पर हो रहा है। इस के इलावा यह कहते थे कि टैक्सों के पैसा से हम ने डिवैल्पमैंट प्लैन्ज़ तैयार करनी हैं, जिससे वह पैसा लोगों की भलाई पर खर्च होगा Fourth Five-Year Plan को चालू करने का पहला साल आने को है मगर इसके मुताल्लिक रिपोर्ट इस हाउस में आज तक नहीं आई। इसकी जगह जगह चर्चा हुई, बिजनेस ऐडवाइज़री कमेटी में भी इसके मुताल्लिक चर्चा चली। मगर आज तक सरकार ने इस हाउस की टेबल पर Fourth Five-Year Plan की एक साल के खर्चे की रिपोर्ट नहीं रखी। 1963 में, सरदार अजमेर सिंह जब रैवेन्यु मिनिस्टर थे, तो यह हरिजन कल्याणकारी टैक्स का एक टैंपरेरी टैक्स का बिल लाये थे और दूसरा कमरशल कराप्स सैस बिल, टैम्परेरी टैक्स लगाने की गर्ज़ से लाये थे। उस वक्त वह रैविन्यू मिनिस्टर थे। आज भी वह मिनिस्टरी में हैं, चाहे किसी शकल में हैं। जब यह बिल पास कराये गये थे तो उस वक्त कामरेड राम किशन की भी वैसी ही तकरीर थी जैसी आज आपोज़ीशन बैंचिज की तरफ से की गई है। 1963 में इन्होंने बोलते हुए कहा था कि इस किस्म के टैक्स लगाने की पालिसी को हमें बदलना चाहिए क्योंकि टैक्स लगाने से अनाज की प्रोडक्शन में रुकावट पड़ेगी जिससे अनाज की कीमतों में मंहगाई आयेगी। कामरेड जी ने उस वक्त बड़ी-बड़ी मिसालें दी थीं जिनमें एक मिसाल चाइना के चयांग काई शेक की भी दी गई थी कि वहां पर इसी तरह से टैक्सिज़ लगाये गये थे तो अनाज के निरख कहीं से कहीं पहुँच गये थे। इनकी बजट सैशन की स्पीच है जो मेरे से देखी जा सकती है। इतना मेरे पास टाईम नहीं कि मैं इस सारी को पढ़ कर यहां सुना सकूं। मैं यह अर्ज़ कर रहा था कि चीफ मिनिस्टर साहिब भी उसी ख्याल के थे जिस ख्याल के आज हम हैं। मगर 1965 का माडल जैसे बदल जाता है यह भी इस कुर्सी पर आकर तबदील हो गये हैं। शायद इस माडल में कुछ रिफार्म आ गया है जैसे यह आज इस ख्याल के हो गये हैं कि किसान पर टैक्स लगना चाहिए।

जिस दिन इस बिल पर बहस हुई थी इन्होंने, चेयरमैन साहिब, काले बिल्ले लगाये थे। तकरीबन सारे कांग्रेसी लगाये बैठे थे। मेरे भी इन्होंने यह एक काला बिल्ला लगा दिया था। इसको लगाने वाले से मैंने पुछा कि भाई यह क्या है, वह कहने लगा चौधरी साहिब किसानों पर 4 रुपये फी एकड़ के हिसाब से सैस बढ़ाया जा रहा है, इसलिये काले बिल्ले लगाये जा रहे हैं। मगर आज उन बिल्ले लगाने वालों में से कोई भी यहां मौजूद नहीं है। सब भाग गये हैं। एक मैं रह गया हूँ। उस वक्त मेरे सामने बैठे सरदार गुरदयाल सिंह ढिल्लों ने एक चिट भेजी थी जिस पर यह यह लिखा हुआ था कि :—

जो लगाते हैं बिल्ले, वह रहते हैं हमेशा थल्ले।

उनका लिख कर भेजने का मकसद यह है कि मैं तो मिनिस्टर बन गया मगर तुम थल्ले हो, इसलिये बिल्ले लगा रहे हो। वह आज कहते हैं कि सरकार की आपोज़ीशन न करो। मगर इस वक्त जो सवाल हमारे सामने है वह यह है कि जिस किसान ने ऐसे हालात में इस देश की रक्षा करनी है, इस देश की पैदावार को बढ़ाना है, हमारे प्रधान मन्त्री भी कहते हैं "जै जवान जै किसान" मगर आज यह सरकार उस किसान के रास्ते में जैसे रुकावट डालती है, पाबंदियां लगाती है। जिस चौउन लाई की मिसालें चीफ मिनिस्टर खुद देते थे आज वह यह नहीं देखते कि वह खुद क्या कर रहे हैं। किसान के ऊपर टैक्स पर टैक्स लगाये जा रहे मगर खेती की काश्त के लिये पूरा

[चौधरी देवी लाल]
पानी तक नहीं दिया जाता । यही नहीं, जितने भी टैकिसज़ लगाये जाते हैं वह किसान पर डायरैक्टली हिट करते हैं । मारकिट में जाओ, बसिज़ पर चलो, इस तरह की और बीसियों चीज़ों पर टैक्सिज़ लगाये जाते हैं । पहले सरकार ने यह यकीन दिलाया था कि यह तीन साल के लिये एक आर्ज़ी टैक्स है, मगर अब यह 1965 से 1970 तक 5 साल के लिये और बढ़ाना चाहते हैं । इनको सबसे बड़ी मुशकिल यह है कि कोई भी मैंबर इसकी हिमायत में अभी तक नहीं उठा । जितने बोले हैं सब इसके खिलाफ बोले हैं । हमारी तरफ से भी मुखालफित हो रही है और कांग्रेस बैंचिज़ से भी हो रही है । मगर किसी की एक भी नहीं सुनी जा रही । इससे बड़ी बदकिस्मती इस मुल्क की और क्या हो सकती है । चौधरी छोटूराम कहा करते थे कि:—

जट महासब बाह्मण शाह,
बनिया हाकम कहर खुदा ।

इस स्टेट की हकूमत का नक्शा बिल्कुल इसी हिसाब पर आ जाता है । जाट के हाथों में आज खज़ाना दिया हुआ है और कामरेड राम किशन जी जो इस हकूमत की बागडोर चला रहे हैं वह जात के बनिये हैं । अब तो खुदा का ही गज़ब होना है । नहीं तो यह कहावत जाती है फाईनेंस मिनिस्टर को सिवाये टैकसिज़ की वसूली के और कुछ आता ही नहीं । हमारे चीफ मिनिस्टर साहिब को सिवाए तकरीरें करने के और कोई तरीका नहीं आता । जो तकरीर हम करते हैं उससे ज़्यादा सख्त तकरीर उन्होंने की । और अपनी तकरीर के दौरान में बहुत सी मिसालें दी थीं कि बिजली ज़्यादा लगाई जाती है । बिजली टैक्स 15 यूनट तक साढ़े 15 पैसे फी यूनिट है, जो गरीबों पर लगता है और उससे ऊपर जो अमीर इस्तेमाल करते हैं उसपर दो पैसे फी यूनिट है । यह मिसाल दी थी कामरेड साहब ने बजट सैशन में । इसी तरह यह बताते हैं कि हमारा मुकाबला चीन जैसे दुश्मन से है, उन दिनों चीन से हमारा मुकाबला था, चीन ने जंग की तैयारी में दो साल में 27,000 करोड़ रुपया खर्च किया । यह सिर्फ उसने 2 साल में किया । हम इतना रुपया 10 साल में खर्च करते हैं । उस जाबर मुल्क के मुकाबले में हम लड़ने की तैयारी कर रहे हैं । हमारा दारोमदार किसान पर है । वही जवान और वही किसान है । जब लड़ाई में होता है तो उसके हाथ में राइफल होती है और अमन में हल होता है । किसान हमारी रक्षा करता है और उसके कंधे पर 28 सेर का हल होता है और हाथ में तलवार होती है । अगर वह हल चलाना छोड़ दे तो काम नहीं चल सकता । वह तलवार और ज़मीन दोनों चाहता है । उस पर टैक्स पर टैक्स लगाये गए हैं । उसके बचाव का, उसकी रक्षा का कोई साधन नहीं । मैं आपकी मार्फत इस सरकार का ध्यान दिलाता हूँ कि जब यह टैक्स लगाया गया था यानी तीन साल पहले तो कामरेड साहिब के उस पर अलफाज़ हैं । अब यह पहली सरकार की नीति पर चल रहे हैं ।

श्री सभापति : चीफ मिनिस्टर साहिब की पुरानी तकरीरों के बारे में आप कह चुके हैं । इस का कोई फायदा हो तो कहें । (He has already referred to the previous speeches of the Chief Minister, He should quote them only if there is any use in doing so.)

चौधरी देवी लाल : उनकी तकरीर पढ़ने लगें तो सारा दिन एक तकरीर पर ही सरफ हो जाए । वह यहां बैठें या वहा बैठें उसका कोई फर्क नहीं पड़ता । बात वही चल रही है अगर चेयरमैन हैं तो सरकार क मुतालिक ख्याल वैसा ही होगा । आपने बजा फरमाया है ।

श्री सभापति : मेरा ख्याल तो वहां बैठे भी वही है जो यहां बैठे है । उसके मुतालिक आप बता दें तो बता दें और तो किसी को पता नहीं। (My views are the same irrespective of the fact whether I sit there or here. Perhaps the hon. Member may be in a position to anticipate them but others have no knowledge about them).

चौधरी देवी लाल : सरदार अजमेर सिंह उस वक्त रैविन्यू मिनिस्टर थे और उन्होंने यह वायदा किया था कि यह सैस सिर्फ टेम्परेरी है। आइन्दा के लिये इसको नहीं लगाया जाएगा। तो उस वाइदा की तरफ ध्यान दें । इस वक्त मेजर साहिब रैविन्यू मिनिस्टर हैं । मैं सरदार अजमेर सिंह की बात नहीं कहता । मैं यह दरखास्त करूँगा कि इस बिल को वापिस लेकर किसान की तरफ ध्यान दें ताकि वह ज्यादा पैदावार बढ़ा सके ।

(इस समय सरदार गुरनाम सिंह ने चेयर संभाली)

चौधरी केसरा राम (डबवाली, ऐस. सी) : चेयरमैन साहिब, जिस बिल पर बहस हो रही है उसमें टैक्स का समय बढ़ाया जा रहा है । यह टैक्स पहले सिर्फ तीन साल के लिये लगाया गया था । सरदार अजमेर सिंह जी यहां बैठे हैं, उन्हें किसानों के साथ हमदर्दी है वह किसानों के हमदर्द हैं । उस वक्त उन्होंने यह वायदा किया था कि यह सैस तीन साल तक ही रहेगा लेकिन आज वह 6 महीने पहले ही किसानों पर यह सैस लगाना चाहते हैं । ठीक है टैक्स के बगैर देश की भलाई या तरक्की नहीं हो सकती । एक तरफ तो आप कहते हैं कि पैदावार बढ़ाओ और कहते हैं कि हम किसान को मदद देंगे । समझ में नहीं आता कि पानी मांगो तो है नहीं । खाद का थैला 15 रुपये का था अब 17 रुपये कर दिया है। जो एक एकड़ में दो थैले पड़ते हैं । चार रुपए एकड़ का खर्चा तो उस पर यह बढ़ गया और चार रुपये इस सैस के बढ़ा दिए । और पटवारी वहां ऐसे बिठा रखे हैं जो खराबे को भी पुख्ता लिख देते हैं। पानी जहां एक तोला भी नहीं मिला वहां ज़मीन को पुख्ता लिख देते हैं । टैक्स तो लगाया पर किसान को पानी नहीं मिला । खाद की कीमत बढ़ गई और उसकी फसल का अंदाज़ा भी गलत बताया जाता है। वहां पैदावार चार आने होती है तो कागज़ात में रुपया दिखलाते हैं । सरकार को भी ग़लतफहमी में डालते हैं और किसान को भी कमज़ोर बनाते हैं । इस हालत में सरकार को सोचना चाहिए यहां किसानों की हमदर्दी रखने वाले वज़ीर साहिब विराजमान हैं । इस तरह इस टैक्स से मसला हल होने वाला नहीं है और आगे आप पैदावार बढ़ाना चाहते हैं तो पानी और खाद की ज़िम्मेवारी सरकार को लेनी चाहिए कि किसान को पानी मिलेगा और खाद 17 रुपये थैला की बजाए 4 रुपये घटा कर 13 रुपये थैले के हिसाब से देनी चाहिए । क्योंकि आपकी सरकार का यह इरादा है कि हम ज़रायत को तरक्की देंगे और ज़रायत करने वाले आदमियों की मदद करेंगे । तो मैं आपसे दरखास्त करूँगा कि चार रुपये एकड़ गन्ना कपास और मिर्चों पर जो टैक्स लगा रहे हैं यह छोटे छोटे किसानों को छोड़ दें यानी जिसने 5 एकड़ तक काश्त की हो यह आपोज़ीशन को प्रोपेगन्डा करने के लिये मौका दे रहे हैं, इस से उनको हौसला होगा । आप किसान की मदद कीजिये । किसान की ज़रूरी चीज़ें पानी, खाद और ज़मीन हैं । जिस के पास ज़मीन नहीं उसको ज़मीन दें, पानी और खाद दें ताकि देश की पैदावार बढ़े और पैदावार बढ़ने से किसान को ताकत मिले, हकूमत को ताकत मिले, देश के व्यापारियों को ताकत मिले । एक बात और है । मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि खास कर जिला हिसार में पानी की बहुत कमी है। न तो नहरी पानी मिला है और न बारिश हुई है। मगर अफसोस है कि मैं पिछले एतवार को वहां गया तो कागज़ात उसी तरह से पुर हो रहे हैं और किसान के

[चौधरी केसरा राम]

ज़िम्मे वही टैक्स की वसूली शुरू हो जाएगी। यहां हम इसके बावजूद टैक्स लगा रहे हैं। किसान की मदद करनी चाहिए। ज़िला हिसार में सैंकड़ों गांव में कहत है लेकिन वहां मदद देने के लिये अभी तक कोई भी अमली कार्यवाही शुरू नहीं हुई—कोई असर नहीं पड़ा। मैं आप से दरखास्त करूँगा कि अगर पैदावार बढ़ानी है तो किसान को नहरों से सही मायनों में पानी दें। टैक्स में कमी कीजिये और किसान को मदद दीजिये। आप कहते हैं कि दूसरे मुल्कों में हमारा पैसा जाता है वह पैसा किसान की मदद में लगायें ताकि पंजाब ही सारे देश को अनाज दे सके लेकिन इस कागज़ी कारवाई से आपका कोई मतलब हल नहीं होगा। किसान की पैदावार का तखमीना गलत लगाया जाता है। पानी की कमी है और इस वजह से अनाज कम होता है। इस मामले में वाटर चारजिज़ ज्यादा हैं। इस संबंध में किसान को नहरी अफसरों के तहत न रखा जाय। उसकी गिरदावरी का जहां तक तुअाल्लुक है वह माल के तहसीलदार या माल के महकमा से कराई जाए ताकि गरीब किसान जो मेहनत करने वाला है लावारिस है उसकी थोड़ी बहुत मदद हो सके। वह नाजायज़ टैक्स के नीचे दब कर इतना मजबूर हो जाता है कि उस से कोई काम भी नहीं होता। वह लोग भागे फिरते हैं उनके पीछे वसूली करने वाले आते हैं और डण्डा लिये फिरते हैं। इस तरह न तो किसान खातरखाह काम कर सकता है और न अपने बच्चों का पेट पाल सकता है। ठीक है यह टैक्स लगा लें अगर आपका इरादा है लेकिन उसको पानी और खाद दें। जो खाद का थैला 17 रुपये में है आपसे अर्ज़ करूँ कि अगर आपने किसान की मदद करनी है तो उस खाद के थैले के 10 रुपये लें और पानी की ज़िम्मेवारी लें। हमेशा फसल के मौका पर वसूली करें। हम पर 15 टैक्स हैं और सोलहवां और लगा रहे हैं। सरचार्ज बैटरमेन्ट लैवी और बहुत से टैक्स हैं। यह नहीं बताते कि उससे कितने टैक्स लेने हैं। यह पहले ही बता देना चाहिए। कल परसों सेल्ज़ टैक्स बिल आया था जिसमें हिसाब देने के लिये कहा गया था लेकिन यह कहा जाता था कि हमसे हिसाब न लें, हम रोज़ाना बिक्री का हिसाब नहीं दे सकते। हम कहते हैं कि हमारा हिसाब कर लो अगर बचता है तो ले लो। (प्रशंसा)

बैटरमेन्ट टैक्स जब लगा तो हम ने कहा कि हमारा हिसाब लो कि हमें कुछ फायदा भी हुआ है या नहीं। हम कहते हैं हमारा हिसाब देखो लेकिन अफसोस है कि आप हमारी बात को नहीं सुनते। दूसरी तरफ जो व्यापारी है वह हिसाब देने से घबराते हैं और हड़तालें करते हैं उनको आप सब सहूलतें और रियायतें देते हैं। चेयरमैन साहिब, मैं कहना चहता हूँ कि जिस तरीके से यह चल रहे हैं उससे अनाज की पैदावार बहुत कम हो जायगी। लेकिन अगर आप किसान की मदद करेंगे तो अकेला पंजाब का किसान इतना अनाज पैदा कर सकेगा जोकि सारे हिन्दुस्तान के लिये काफी हो सकता है। आज हम देख रहे हैं कि किसान को पानी नहीं मिलता और न ही खाद मिलती है। पानी के लिये इतनी रिश्वत चलती है जिस का हद्द हिसाब नहीं। अगर आप सिरसे में आएं तो यह चीज़ मैं आपको दिखा सकता हूँ। जो बेचारा किसान पुश्तों से खेती करता आ रहा है अगर आप उस का हल चलाना खत्म कर देंगे तो उस से न तकड़ी पकड़ी जाएगी और न कोई और काम हो सकेगा किसान के सिवाए आप के पास कोई और वसीला नहीं जो आपको गेहूँ पैदा करके दे सके। यह जो "जै किसान" का आप नारा लगाते हैं वह तभी पूरा होगा अगर आप किसान की मदद करेंगे। आप इस तरह के टैक्स लगा कर किसानों का गला न घूटें। जो चार रुपए एकड़ आपने Tax लगाया है हम उसे बुरा न कहते अगर किसानों को सब सहूलतें दी जाती होतीं।

उन्हें सहूलतें मुहैया करने की भी तो आपकी ही ज़िम्मेदारी है। इस बात को आप मखौल में न उड़ाएं। मैं यह चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर किसान कमजोर हो गया तो सारा देश कमज़ोर हो जायगा और आपको खाने के लिये अनाज नहीं मिल पाएगा अगर किसान मज़बूत होगा तो सारा देश मज़बूत होगा। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। जै हिन्द।

Chief Parliamentary Secretary : I beg to move that question be now put.

ਸਰਦਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਧੌਲਾ (ਬਰਨਾਲਾ) : ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਏਥੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬਿਲ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਨੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਹਦ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਪਰੈਸ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਟਾਂਗਿਆਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਇਕ ਐਸੀ ਜਮਾਇਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਰੈਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਸੇ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਬਿਲ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਐਨੀ ਹਿਫਾਜ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਦਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮਹਿਕਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕਦੀ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਹਨ ਸਭ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਥਾਈਂ ਧਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਮੁਹੱਰਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਮੁਹੱਰਰ, ਥਾਣੇਦਾਰ, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਔਰ ਐਸ.ਪੀ. ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਥਾਈਂ ਵੀ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨੇ ਥਾਈਂ ਹੀ ਦੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਜੋਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਲਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੌਦਾਗਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸੇਲਜ਼ਟੈਕਸ ਵਾਲਾ ਬਿਲ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਲਈ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਕ ਪਊਆ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਹੀ ਫੜਨਾ ਹੋਵੇ। ਏਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਲ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਮੋਘਾ ਇਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਦਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੀ ਕਰਾਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਸਾਲ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਫੇਰ ਵੀ ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੁਰੱਬੇ ਬੰਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਸਿੱਧੇ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ। ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਪੁਲੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਪੁਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ। ਲੋਕ ਕਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭੌਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿਉ ਮਗਰ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲ

[ਸਰਦਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਧੌਲਾ]

ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਖੁਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ । ਏਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਜੀਬ ਹੀ ਢੰਗ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਪਰੋਂ ਕੋਈ ਮਨਿਸਟਰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ । ਇਥੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਸੀ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਰਜੇ ਚੰਗੀ ਸੀ । ਉਹ ਜੱਟਾਂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾੜੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁਕਣ ਦਿੰਦੀ । ਮਗਰ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਹ ਸੂਦ ਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਘੁਟਦੀ ਹੈ । ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ । ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਬਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਲਿਬਰੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਲਾ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਤੂਫਾਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੂੰਝ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਉਠੇਗਾ । ਇਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ

"ਜਿਸ ਖੇਤ ਸੇ ਦਹਿਕਾਂ ਕੋ ਮੁਯਸਰ ਨ ਹੋ ਰੋਟੀ
ਉਸ ਖੇਤ ਕੇ ਹਰ ਖ਼ੋਸ਼ਾਏ ਖ਼ਿਰਮਨ ਕੋ ਜਲਾ ਦੋ ।"

ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਲਿਬਰੇਜ਼ ਹੋਏ ਸਬਰ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ—

"ਐ ਖਾਕ ਨਸ਼ੀਨੋਂ ਉਠ ਬੈਠੋ
ਅਬ ਤਖਤ ਗਿਰਾਏ ਜਾਏਂਗੇ
ਅਬ ਤਾਜ ਉਛਾਲੇ ਜਾਏਂਗੇ ।"

ਬਸ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਕਹਿਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ।

चौधरी नेत राम (हिसार) : चेयरमैन साहिब, इस हाउस में जो बिल ज़ेरे बहस है, वह बिल पिछली सरकार ने 3 साल के लिये लाया था लेकिन यह सरकार उसी बिल को 5 साल के लिये और जारी रखना चाहती है। यह तो ऐसी बात बन गई है जैसी कि किसी आदमी के लिये हर साल या हर तीन साल के बाद कोई लाइसेंस रिन्यू कराना पड़ता है। हमारी सरकार कहती है कि प्लैनिंग कमीशन ने इस टैक्स को जारी रखने के लिये परामर्श दिया है ताकि किसानों की रीढ़ की हड्डी टूट जाए और वह भीख मांगने के लिये मजबूर हो जाए। सरकार की गलत नीतियों के कारण ही जो अमीर था वह और अमीर हो गया है और जो पहले गरीब था, वह अब बहुत गरीब हो गया है। बेचारा किसान भी गरीब की श्रेणी में आता है। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि किसान ही देश के लिये अन्न पैदा करता है और यह ही देश की रक्षा के लिये अपने बच्चों को फौज में भरती कराके भेजता है। लेकिन सरकार इन टैक्सों को लगाने के लिये बहाना बनाती है कि हम यह रुपये देश की रक्षा के लिये और डिवैलपमेंट के लिये लोगों से ले रहे हैं। किसान पर पहले ही काफी टैक्स लगे हुए हैं। किसान उन टैक्सों को अदा नहीं कर सकता है। किसानों पर इस टैक्स के लगाने से साफ नज़र आता है कि इस सरकार की किसानों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। इनकी नीयत बुरी है। मैं समझता हूँ कि सरकार की बदनीयत की वजह से देश का निर्माण

नहीं होगा बल्कि देश का नुक्सान होने का ही अन्देशा है । मैं समझता हूँ कि इस सरकार को किसानों की मेहनत का कोई भी ज्ञान नहीं है। इन को किसान की आमदनी का भी पता नहीं है। मैं किसान की हालत हाउस में बयान करना चाहता हूँ। वैसे एक मिसल मशहूर है कि— "नौ मंडा और दस गंडा।" गन्ना पैदा करने के लिये 10 बार हल चलाना पड़ता है।

चेयरमैन साहिब, इसी तरह की एक मिसल और मशहूर है कि—

कनक कमादी छल्लियां ते और खेती कुल ।
राखी बाझ न हुंदियां, इह न जायीं भुल ।

चेयरमैन साहिब, किसान को गन्ने की फसल पैदा करने के लिये ज़मीन को अच्छी तरह से तैयार करना पड़ता है। जब वहां पर 10 बार हल चलाया जाय तब वहां पर गन्ने की फसल बीजी जाती है। मैंने पहले अर्ज़ की थी कि मैं किसान की लागत का ब्यौरा हाउस में रखना चाहता हूँ।

ज़मीन का रैंट जो ठेके पर ली जाए –100 रुपये, उस ज़मीन पर 10 बार हल जोतने के लिये प्रबन्ध किया जाए, जैसा कि उस ज़मीन के लिये बहुत ज़रूरी है। अगर एक बार हल जोतने के लिये 15 रुपये देने पड़ें तो उस आदमी को 10 बार हल जोतने के लिये 150 रुपये देने पड़ेंगे। मैं यह हिसाब एक एकड़ का लगा रहा हूँ। अगर यह काम किसी ट्रैक्टर के द्वारा कराया जाए तो उस किसान को इससे ज्यादा खर्चा देना पड़ेगा। उस ज़मीन पर कम से कम गोबर खाद के 20 गड्डे डालने पड़ेंगे अगर म्युनिसिपल कमेटी से यह खाद खरीदी जाए तो भी एक खाद के गड्डे की कीमत 5 रुपये होगी तो उस किसान को 20 गड्डे खाद के लिये 100 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। विलायती खाद के लिये किसान को 100 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। मैंने एक मन खाद की चार आने कीमत लगाई है। और एक गड्डे में 20 मन खाद रखी है। उस किसान को ढुलाई के लिये अगर चार आने फी मन देना पड़े तो एक गड्डे के लिये 5 रुपये ढुलाई के खर्च होंगे। इस तरह से 20 गड्डों के लिये उसे 100 रुपये ढुलाई पर खर्च करना पड़ेगा। इस ज़मीन की गुड़ाई के लिये 30 आदमी चाहिए। अगर एक आदमी को 3 रुपये देने पड़ें तो उसे 90 रुपये खर्च आयेंगे। वहां पर 50 मन बीज लगेगा। अगर एक मन बीज की कीमत 2 रुपये लगाई जाए तो उसे बीज के लिये 100 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। लगभग 8 मास में गन्ने को 16 दफा पानी लगाना पड़ता है। अगर एक आदमी को पानी लगाने के लिये लगाया जाय और उसकी मजदूरी सवा रुपया रखी जाए तो किसान को 20 के करीब ही खर्च करने पड़ते हैं। मैं तो कम से कम किसान का खर्च शो कर रहा हूँ ताकि किसान को फसल में मुनाफा दिखाया जा सके। किसान को 4 बार नलाई करनी पड़ती है। अगर एक नलाई के लिये 5 आदमी की ज़रूरत हो तो 4 नलाइयों के लिये 20 आदमी की ज़रूरत होगी। अगर एक आदमी की मज़दूरी ढाई रुपये हो तो किसान को 50 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। किसान को साथ में 4 बार हल जोतना पड़ता है। इस पर किसान को 40 रुपये खर्च करने पड़ेंगे इसके बाद तीन दफा जब कमाद बढ़ती है तो उसकी बंधाई की जाती है। एक दफा बंधाई पर 5 आदमी लगाये जायें तो तीन बार के लिये 15 आदमियों की ज़रूरत है। अगर एक आदमी की मजदूरी 3 रुपये लगाई जाये तो किसान को 45 रुपये अदा करने पड़ते हैं। गन्ने की कटाई के लिये 8 आदमी होने चाहिएं। अगर इसकी मजदूरी 3 रुपये रखी जाए तो किसान को 24 रुपये देने पड़ते हैं। गन्ने की छिलाई के लिये 50 आदमी की ज़रूरत होती है। अगर एक मजदूर को 3 रुपये देने पड़ें तो किसान को 150 रुपये देने पड़ते हैं।

[चौधरी नेत राम]

(*Deputy Speaker in the Chair.*)

इस तरीके से रोज़ाना मज़दूरों का हिसाब लगा कर डेढ़ सौ रुपया कमाद के छीलने पर खर्च हुआ। फी एकड़ डेढ़ सौ रुपया खर्च आया। ईख को कारखाने तक पहुंचाने के लिये चार आने फी मन के हिसाब से अढ़ाई सौ रुपया खर्चा आया। यह मैं एक हज़ार मन के बारे में बता रहा हूँ, वह भी तब होता है अगर पूरा पानी मिले, पूरी खाद मिले, वक्त पर मज़दूर मिल जायें, सारी सहूलतों के मिलने के बाद एक हज़ार मन ईख एक एकड़ में से पैदा होता है। वरना पांच सौ मन से ज्यादा नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि सर्दी मार जाती है, कई बार पानी नहीं मिलता और कई और बीमारियां लग जाती हैं और सारी फसल तबाह हो जाती है उस सूरत में गन्ने का वज़न दो सौ मन भी रह जाता है। लेकिन सारी सहूलतें मिलने से एक हज़ार मन से ज्याद गन्ना कभी पैदा नहीं हो सकता। और उस पर खर्चा एक रुपया फी मन पड़ने से कुल हज़ार रुपया खर्च हुआ। कारखाने में ले जाने पर उसको डेढ़ रुपया मन का मिलता है। कहते तो दो रुपये फी मन हैं लेकिन मिलता डेढ़ रुपया ही है। इस तरह से उसको कुल 1,500 रुपया मिला। हज़ार रुपया निकाल कर उसको पांच सौ रुपया की फी एकड़ बचत हुई। पांच आदमियों का कुनबा सारा साल काम करता रहा, मज़दूरों को रोटी खिलाई और फिर भी एक सौ रुपया एक साल का एक आदमी के पीछे किसान को बचा। वह भी उस सूरत में जब कि पानी पूरा मिलता रहे, खाद पूरी मिले, फसल को कोई बीमारी न हो। फिर कहीं जाकर सौ रुपया पर हैड पर इयर उसको बचा........(विघ्न)

उपाध्यक्षा : प्लीज़ वाईंड अप। (Please wind up)

चौधरी नेतराम : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं बिल्कुल ठीक तौर पर बिल पर बोल रहा हूँ। इसलिये मुझे समय दिया जाना चाहिए। मेरे साथ बेइनसाफी नहीं होनी चाहिए। मुझे अपनी पार्टी के विचार सदन में रखने की इजाज़त मिलनी चाहिए। मैं इतने दिन से सेल्ज़ टैक्स बिल पर बहस सुनता रहा हूँ मुझे समय नहीं मिला। दरअसल मैं उस पर बोलना भी नहीं चाहता था। क्योंकि वह व्यापारियों का बिल था उसका मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं था। मैं सरकार की नीति की आलोचना कर रहा हूँ .....

Deputy Speaker : Please finish your speech within two minutes.

चौधरी नेतराम : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं अर्ज़ कर रहा था कि किसान किस ढंग से मेहनत करके पैदावार करता है और सरकार की नीति कितनी गलत है। (विघ्न) मैं अर्ज़ करने लगा हूँ कि मरला टैक्स का 54 लाख रुपया लगाया गया था। कानून बनाने पर 14 लाख रुपया खर्च हुआ। तीन लाख रुपया टैक्स का इकट्ठा हुआ लेकिन किसान का दम भरने वाली सरकार ने, "जय किसान, जय जवान" का नारा लगाने वाली सरकार ने 54 लाख रुपया मरला टैक्स का माफ कर दिया। लेकिन किसानों पर जो टैक्स इन्होंने सिर्फ तीन साल के लिये लगाया था अब उसको दोबारा लगा रहे हैं, इससे ज्यादा गलत बात और क्या हो सकती है? मिनिस्टरों के लिये 6 नई कारें मर्सिडीज़ की खरीदी गई, नए नए महकमे नित्य खोले जाते हैं, उन पर लाखों रुपये फ़ज़ूल खर्च किये जाते हैं। यह सरकार पंजाब के किसानों के साथ मजाक करती है। चंडीगढ़ में फुट पाथ पर अनाज पैदा करेगी, उसके लिये नया महकमा खोलेगी नया डायरक्टर मुकर्रर

करेगी। वह बीज जो वहां पर बोया जाएगा सारा पांव के नीचे ही रौंदा जाएगा । इससे ज्यादा मज़ाक पंजाब की जनता के साथ क्या हो सकता है ?

जब सूरजपुर सीमेंट फैक्टरी बनी थी तो मालिक से सरकार का वादा था कि 25 साल के बाद वह फैक्टरी सरकार की हो जाएगी। अब सुन रहे हैं सरकार उस फैक्टरी को न लेकर तीन करोड़ रुपया लगा कर अपनी अलग फैक्टरी खोलने जा रही है । बेईमानी का इल्ज़ाम इससे ज्यादा मैं सरकार पर और क्या लगा सकता हूँ। तीन करोड़ रुपये की मशीनरी थी जो शर्त के मुताबिक सरकार को ले लेनी चाहिए थी.....(विघ्न) (शोर)

साफ ज़ाहिर है कि कांग्रेस सरकार मालिकान से पैसा लेगी और उसको अपनी पार्टी के लिये खर्च करेगी। (विघ्न) मैं अर्ज़ करता हूँ कि पंजाब में पहले दो कमिश्नर होते थे लेकिन आज 14 कमिश्नर पंजाब में मुकर्रर किये हुए हैं। अपने रिश्तेदारों और अपने यारों के लिये नई नई पोस्टें क्रियेट की जाती हैं। उनको बड़े बड़े ओहदे दिये जाते हैं।

उपाध्यक्षा : आपको बोलते हुए 15 मिनट्स हो गए हैं। मेहरबानी करके तशरीफ रखिए। (He has been speaking for the last fifteen minutes. He should please resume his seat)

चौधरी नेत राम : मैं आपकी आज्ञा मान कर समाप्त करता हूँ। चाहे सरकार कैरों को ही चाहे सरकार कामरेड राम किशन को हो। इसमें कुछ फर्क नहीं है। कांग्रेस सरकार की नीति एक ही है, वही है। (विघ्न)

मुख्य संसद सचिव : प्वायंट आफ आर्डर। हम इस तरह से नहीं बोलने देंगे, यह कोई तरीका नहीं है बोलने का ।

उपाध्यक्षा : अब मेहरबानी करके समाप्त कीजिये। (Please wind up now)

चौधरी नेत राम : चेयर पर आप हैं या मिस्टर गर्ग स्पीकर है ? मैं आप की आज्ञा से समाप्त करने वाला हूँ। (विघ्न) मैं सरकार की नीति की आलोचना कर रहा हूँ। मैं अर्ज़ करूँ—
काली भली न कोडाली भली धौली भली न सफेद —

आपोज़ीशन के साथियो, हमारी नहीं यह कोई जनता की नहीं कांग्रेस सरकार की नीति एक ही है। इनको राखो एक खेत। यह किसानों और मजदूरों के हित के खिलाफ जाती है और मुनाफा खोरों के हक में जाती है। इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूँ।

PERSONAL EXPLANATION BY THE MINISTER FOR EDUCATION

शिक्षा मंत्री (श्री प्रबोध चन्द्र) : मैडम, आइ राइज़ आन ए प्वायंट आफ परसनल ऐक्सप्लेनेशन। मेरी गैर हाज़री में चीफ मिनिस्टर साहिब ने एक स्टेटमेंट दी थी । सरदार गुरनाम सिंह जी ने उस पर बोलते हुए मेरे ऊपर एक तो शायद यह अल्ज़ाम लगाया था कि मेरा कोई बिज़नेस काश्मीर में है और इसलिये मैंने २५,००० रुपया वहां के चीफ मिनिस्टर को दिया। इस सिलसिले में मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अगर यह जाहिर कर दें कि इस वक्त एक भी नए पैसे का मेरा कोई बिजनैस जम्मू या काश्मीर में है तो जो सज़ा आप कहें मैं वह भुगतने को तैयार

]शिक्षा मंत्री]

हू वरना एक आनरेबल मैम्बर को, जोकि आपोज़ीशन का लीडर रह चुका हो, इस तरह का अल्ज़ाम लगाते वक्त कुछ तो जिम्मेवारी का एहसास करना चाहिए था ।

दूसरा अल्ज़ाम उन्होंने यह लगाया कि मैंने २५,००० रुपया अपने लीडरों को पंजाबी सूबा के अगेन्स्ट फतवा लेने के लिये दिया । उन तीनों में तो एक ही आते हैं, बाकी दो यानी महावीर त्यागी साहिब और चौहान साहिब को तो दिया ही नहीं गया । उन्हें यह आशा नहीं करनी चाहिए कि किसी लीडर का ईमान इतना सस्ता है कि वह पच्चीस हज़ार रुपये के लिये अपने असूल को छोड़ सकता है । उनको ऐसा तजरुबा होगा अपने लीडरों का लेकिन हमारे लीडरों ने तो जिन्दगी भर देश की आज़ादी के लिये लड़ाई लड़ी है । वह ऐसे नहीं है कि पच्चीस हज़ार रुपये के लिये अपने असूलों को तरक कर देंगे । मैं आपोज़ीशन के लीडर को कहूँगा कि वह इस हाउस को दूसरों पर गन्दगी उछालने का आलाकार न बनायें कि इस तरह करने से किसी पर कुछ न कुछ गन्दगी तो चिमट ही जायेगी । हमने हमेशा अपने मुंह को बंद रखा है । अगर आपोज़ीशन के भाई इस तरह से बोल सकते हैं, दुसरों पर खाम खाह कीचड़ उछाल सकते हैं तो इधर से भी कुछ किया जा सकता है । हम आपोज़ीशन के भाइयों की इज्ज़त करते आए हैं । और यही कोशिश करते रहे हैं कि कोई ऐसी बात न कहें जिससे कशीदगी पैदा हो । मैं यहां पर हाउस में फिर यह बात कहने को तैयार हूँ कि अगर वह किसी तरह से भी ज़ाहिर कर दें कि जम्मू और काश्मीर में मेरा कोई एक पाई का भी बिज़नैस है तो मैं हाउस से इस्तीफा दे दूंगा वरना वह इस हाउस में मुझसे कम अज़ कम माफी तो मांगे ।

बाकी जो अल्ज़ाम पच्चीस हज़ार रुपये वाला लगाया गया कि हमारे लीडर इतने रुपयों में बिक सकते हैं, हमारे लीडर कोई भूख हड़ताल करके लीडर नहीं बने । उनके पीछे एक पुरानी कहानी है, उन्होंने देश के लिये कई कुरबानियां की हैं । इस तरह से किसी पार्टी के लीडर्ज़ के बारे में इतनी छोटी राए रखना, मैं समझता हूँ, ज्यादती है तंग दिली है । अगर उनकी यही पुज़ीशन है तो वह हमें मजबूर करेंगे कि हम भी उनके लीडरों के बारे में इसी तरह की बातें करें जैसा कि उन्होंने हमारे लीडरों के बारे में कहीं हैं ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ......

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ? (On what point the hon. Member wants to speak ?)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਮੈਡਮ । ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਅਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੁਪਿਆ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਨ । ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਅਲ ਸੀ ਉਹ ਵਾਕਈ ਕੁਐਸਚਨੇਬਲ ਸੀ ਯਾਨੀ ਰੁਪਿਆ ਲਿਆ ਜਾਣਾ । ਮਗਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਗਰਿਟੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ । ਉਹ ਇੰਟੈਗਰਿਟੀ ਦੇ ਆਦਮੀ ਹਨ । ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਕਈ ਦਫਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੈਸਟ ਹੈ । ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਵੀ ਦਵਾਂਗਾ ।

शिक्षा मंत्री : मैं हाउस में इस बात को चैलेंज करता हूँ कि अगर वह जाहिर कर दें कि इस वक्त वहां जम्मू और काश्मीर में मेरा एक नये पैसे का भी बिज़नैस है......

कुछ आवाजें : इस वक्त ?

शिक्षा मंत्री : हां, इस वक्त। बीस साल पहले की बात हो सकती है। वह अलग बात है। अगर वह साबत कर दें कि इस वक्त वहां पर मेरा एक नए पैसे का भी बिज़नैस है तो मैं हाउस से इस्तीफा देने को तैयार हूँ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਮੈਡਮ, ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵੇਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ—ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਨੈਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ? ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਜੀ ਆਏ ਕਦੀ ਫਲਾਨੇ ਆਏ। ਆਖਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟਰੈਸਟ ਹੈ ? ਜਦ ਇਕ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਬਗੈਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇਕ ਪਬਲਿਕ ਫੰਡ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਉਥੇ ਦਿੱਤਾ ? ਦੂਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਚੈਕ ਲਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਫੰਡ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਇਕ ਪਬਲਿਕ ਫੰਡ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਬਲਿਕ ਫੰਡ ਦੇ ਚੈਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਏ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਰੁਪਿਆ ਕਿਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ? ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਲਫਜ਼ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਲੀਡਰਜ਼ ਦੀ ਇੰਟੈਗਰਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਗਰਿਟੀ ਦੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੈਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਅੱਛੀ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ।

उपाध्यक्षा : मैं लीडर आफ दी हाउस और सरदार गुरनाम सिंह साहिब से यह दरखास्त करूंगी कि आज आप के सामने एक अहम बिल है और फिर आप नान स्टाप सिटिंग करने का फैसला कर चुके हैं। उसके बावजूद यह एक नई बहस बीच में आ गई है। मैं चाहूँगी कि इस बहस को यहीं पर खत्म किया जाए। यह जो बाहर के लोग हैं यह भी क्या ख्याल करेंगे कि बात तो बिल की चल ही थी और बीच में आपस में झगड़ा खड़ा कर दिया। जो कहा जा चुका है उसी तक महदूद रहने दिया जाए। यही बहुत काफी है। (I would like to submit to the Leader of the House and Sardar Gurnam Singh that today they have got an important Bill before them and above all they have decided to have a non-stop sitting. Despite that this new controversy has cropped up. I would like this controversy to be stopped here. What would the people, who have come from outside, think about this personal controversy having been introduced when the discussion of the Bill was in progress ? They should be content with what has already been said. This is quite sufficient.)

(*Interruptions*)

शिक्षा मन्त्री : हम आज तक इन की इज्ज़त करते रहे हैं। अगर अब वह एक कहेंगे तो इनको चार सुनने को मिलेंगी। हम भी मूंह में ज़बान रखते हैं।

At this stage some members of the Akali Party rose on point of order simultaneously.

उपाध्यक्षा : मैंने लीडर आफ दी हाउस और आपकी पार्टी के ग्रुप के लीडर से एक दरखास्त की है और उसके बावजूद भी अगर आप प्वांयट आफ आर्डर करना चाहते हैं तो करें। (I have already made a request to the leader of the House and the leader of the Akali Party. Despite that if they insist on raising points of order, they are at liberty to do so.)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਮੈਡਮ। ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਬੋਧ ਚੰਦਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਬੋਧ ਚੰਦਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉੜਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ; ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਇਕ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਇਕ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਬੋਧ ਚੰਦਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

(*Interruptions and noise*)

उपाध्यक्षा : प्रबोध चन्द्र जी, आपने क्या कहा था, मैंने सुना नहीं ? (What did the Education Minister say ? I did not hear.)

ਵਿਦਿਆ ਮੰਤਰੀ (ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਚੰਦਰ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉਪਰ ਇਕ ਹੋਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਚੈਕ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਅਗਰ ਇਕ ਪਾਈ ਵੀ, ਇਕ ਦਮੜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਚੈਕ ਆਏ ਹਨ ਉਹ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਡੀਫੈਂਸ ਐਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੀਲੀਫ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਿਚੋਂ 5–10 ਪਰਸੈਂਟ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੈਕ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕ ਮੈਸਜਰ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰੁਪੈ ਨੂੰ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਡੀ. ਸੀ. ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਭੇਜਣ। ਅਗਰ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਇਕ ਪਾਈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਦਮੀ ਕੋਲੋਂ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ, ਮੈਂ ਭੁਗਤਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮਗਰ ਇਹ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਚਿਕੜ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

(*Interruption and noice*)

उपाध्यक्षा : वह आपने एक एक दिन की भूख हड़ताल वाली क्या बात कही थी ? मैंने वह सुनी नहीं। आप बतायें कि आपने क्या कहा था। (What did the hon. Minister say about a day's hunger strike ? I did not hear that. He may repeat it.)

शिक्षा मंत्री (श्री प्रबोध चन्द्र) : मैडम, मैंने यह कहा था कि हमारे लीडरों के पीछे कुरबानी की एक पुरानी कहानी है और उन्होंने कोई मामूली भूख हड़ताल करके या शार्ट कट करके लीडर शिप को कबूल नहीं किया था। पता नहीं उन्होंने इस बात को अपनो तरफ क्यों ले लिया।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਭੁਖ ਹੜਤਾਲ ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ; ਖ਼ੁਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਦਫ਼ਾ ਗਰੈਂਡ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਵਿਦਿਆ ਮੰਤਰੀ : ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਾਗਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਗੰਦਿਆਂ ਨਾ ਕਰਾਉ। ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਥੇ ਹਾਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਗੰਦਗੀ ਉਛਾਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। (Interruption) ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਖ਼ੁਦ ਨਿਬੜ ਲਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੇ ਮੈਂ ਬੀਸੀਉਂ ਵੇਖੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। (noise) ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਕੋਈ ਭੁਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਰੀਫਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਇਹ ਖ਼ੁਦ ਦਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ। (Interruptions)

उपाध्यक्षा : आर्डर प्लीज़। (Order Please)

ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਲਾਇਲਪੁਰੀ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਮੈਡਮ। (Noise)

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਆਰਡਰ ਪਲੀਜ਼।

ਸ਼ਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਲਾਇਲਪੁਰੀ :ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਕਲ ਇਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ (noise) ਉਸ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ।

THE PUNJAB COMMERCIAL CROPS CESS (AMENDMENT) BILL 1965 (RESUMPTION OF DISCUSSION)

Shri Nihal Singh : Madam, I beg to move that the questions be now put.

3.00 P. M.

(बहुत से मैम्बरों की तरफ से विघ्न)

ਸਰਦਾਰ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਮੈਡਮ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਠ ਬੈਠ ਹੀ ਕਰਾਈ ਰਖਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਲਈ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਔਰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਮੈਨੂੰ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਸ ਦਿਉ ਕਿ ਕਿਸ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਵਕਤ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਖੜਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਠਣ ਬੈਠਣ ਦੀ ਪਰੇਡ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰਾਓ।

श्री निहाल सिंह : मैंने क्लोयर मोशन पुट की है।

उपाध्यक्षा : राम्रो निहाल सिंह जी आप इस तरह क्लोयर मोशन पुट करके मुझे आकवर्ड पोज़ीशन में न डालें। अभी तो कई मैम्बर बोलना चाहते हैं। (I request Shri

[Deputy Speaker]

Nihal Singh that he should not put me is an awkward position by pressing his closure motions. So many members are still keen to speak.)

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ : (ਸਰਦਾਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੇਜਰ) ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਮੈਡਮ...

(ਇਸ ਵਕਤ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਬੜਾ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ)

उपाध्यक्षा : Order please. श्री निहाल सिंह ने क्लोयर मोशन पुट की थी लेकिन मैंने उसकी इजाज़त नहीं दी । (Order please, Shri Nihal Singh had moved the closure motion but I did not allow it.)

(**ਇਕ ਆਵਾਜ਼** : ਫਿਰ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ)? वह तो **प्वाइंट** आफ आर्डर पर खड़े हुए हैं और डिबेट का जवाब नहीं देने लगे। (The Revenue Minister is on his legs as he wants to say something on a point of order. He is not replying the debate)

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਿਸ ਵਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਲੋਈਜ਼ਰ ਮੋਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਕਵਰਡ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨਾ ਪਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਕਵਰਡ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਸੁਝਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਇਤਨੀ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਬਿਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਰੀਡਿੰਗਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹਿਸ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਕਲੋਈਜ਼ਰ ਮੋਸ਼ਨ ਮੰਨ ਲਓ ।

उपाध्यक्षा : आपका तो अपनी पार्टी पर भी निज़ाम नहीं चल रहा । मेरे लिए मुश्किल तो यह है । (But the difficulty is that there is no discipline in the ruling party)

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲੀ ਆਪ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ......

(ਕੁਝ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ)।

उपाध्यक्षा : आर्डर प्लीज़ । नान स्टाप सिटिंग का मतलब यह नहीं होता कि सारा दिन ही बहस चलती रहे । इस वक्त तक बहुत सारे मैम्बर इस बिल पर बोल चुके हैं और बाकी कुछ और हैं जो बोलना चाहते हैं । वह बिल की दूसरी रीडिंग्ज़ पर भी बोल सकते हैं । यह कोई तरीका नहीं कि एक ही वक्त में इतने मैम्बर प्वायंट आफ आर्डर पर खड़े हो जाएं । जैसा कि मेजर साहिब ने कहा है, आप थर्ड रीडिंग पर भी तो बोल सकते ह, फिर अभी सैकिंड रीडिंग पर जब अमेंडमैंटस मूव होंगी उस वक्त भी तो आप बोल सकेंगे ।

(Order please. Non stop sitting does not imply that the debate should go on throughout the day. Most of the hon. Members have already taken part in the discussion and there are still some more who want to take part in it, who can do so at the time of the third reading stage. It does not look proper that a large number of Members should simultaneously rise on points of order. As the Minister for Revenue has rightly pointed out they can speak at the time of the third reading. They can also speak at the second reading stage when amendments are to be moved.)

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਮੈਡਮ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਵਲ ਖਿਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਨ ਸਟਾਪ ਸਿਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੋਈਅਰ ਮੋਸ਼ਨ ਲਿਆ ਕੇ ਇਕ ਬੜੀ ਨਾ ਮੁਨਾਸਬ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਨ ਸਟਾਪ ਸਿਟਿੰਗ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਜੇ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਇਸ ਐਸ਼ਿਓਰੈਂਸ਼ ਤੇ ਮੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਤੇ ਫੁਲ ਐਂਡ ਫਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਲ੍ਹਾ ਵਕਤ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਹਾਲੇ ਇਸ ਬਿਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਵੀ ਕਿਥੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਕਤ ਤਾਂ ਪਹਲੇ ਸਰਦਾਰ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਝੜਪ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਪ੍ਰਬੋਧ ਜੀ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਕਤ ਤਾਂ ਇਨਡੀਵਿਜ਼ੂਅਲ ਦੇ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਰੀਅਲ ਈਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਜੋ ਇਨਡੀਵਿਜ਼ੂਅਲ ਦੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਲੋਈਅਰ ਮੋਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਮਾਲ ਮਤਰੀ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੋ ਗਲਾਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਦਫਾ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਔਰ ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੁਪਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਏ ਕਹਿ ਲਉ। ਮੈਂ ਐਜ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਇਨਚਾਰਜ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਰਵੋਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਏ ਕਹਿ ਲਉ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਨੇ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ......

उपाध्यक्षा : सरदार नारायणसिंह शहबाज़पुरी खड़ा हुआ था जो आपकी पार्टी का एक सीनियर मेम्बर है। (Sardar Narain Singh Shahbazpuri who is a senior member of the ruling party had risen to speak when the Revenue Minister was on his legs.)

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ : ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੀ।

ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਮੈਡਮ ।

* * * * * *

* * * * * * *

* * * * * * *

* * * * * * *

उपाध्यक्षा : Order please. चौधरी दर्शन सिंह ने अब जो कुछ कहा है वह एक्सपंज कर दिया जाए । (Order please. Whatever has now been said by Chaudhri Darshan Singh, should be expunged from the proceedings.)

ਸਰਦਾਰ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ । ਇਹ ਬਿਲ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ।(interruption)ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੋਸ਼ਨ ਹੁਣੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਸ ਬਿਲ ਦੀਆਂ 3 ਰੀਡਿੰਗਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕਲਾਜ਼ ਇਕ ਹੀ ਹੈ । ਪਹਿਲੀ ਰੀਡਿੰਗ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੇ ਅੱਜ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਕਾਫੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਰ ਚਾਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੋ ਰੀਡਿੰਗਜ਼ ਵੇਲੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । (ਵਿਘਨ)

ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਊਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖ ਲਉ ਜਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਊਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤਕ ਵੀ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ । (ਵਿਘਨ)

खान अब्दुल गफ़ार खां (अम्बाला शहर) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह जो बिल है जिसे कि अमैंडिंग बिल कहा जाता है जिस पर बहुत से मैम्बर साहिबान बोल चुके हैं और बहुत बोलने के खाहिशमन्द हैं उनमें से एक मैं भी हूँ और चाहता हूँ कि कुछ थोड़ा बहुत अर्ज़ करूँ । डिप्टी स्पीकर साहिबा जहां तक टैक्सिज का तआल्लुक है, दुनियां में कोई भी ऐसी हकूमत नहीं— कोई भी ऐसा निज़ाम नहीं होता कि कोई प्राइवेट आर्गेनाईज़ेशन भी ऐसी नहीं है जो बिना पैसे के सोसिज़ के चल सके । फिर चाहे वो चन्दे की सूरत में आए या टैक्स की शकल में । बहरहाल, पैसे जमा करने के लिये चन्दा हो या टैक्स जो कुछ भी हो लेना पड़ता है हर आर्गिनाईज़ेशन को ख़ाह व पुलिटीकल हो या दूसरी । इसलिये टैक्स पर एतराज़ नहीं लगना चाहिए और ठीक तरीका पर सर्फ भी होना चाहिए । सरकार का काम सूरज की तरह होना चाहिए जो कि अपनी गर्मी से समुन्द्र में से पानी खींच लेता है । भाप की शक्ल में ऊपर ले जाता है और बारिश की शक्ल में दुनियां में पहुंचा देता है । ठीक है आप टैक्स लगाइये, मगर लोगों की बहबूदी के लिये उसे सर्फ कीजियें । लेकिन सवाल यह है कि आप टैक्स कैसे लगाते हैं और किन पर लगाते हैं, यह देखने की

Note :—Expunged as ordered by the Chair.

बात है। जब यह टैक्स पहले लगा था तो उस वक्त की हकूमत ने यह बात कही थी कि यह सिर्फ तीन साल के लिये लगाया जा रहा है । मगर आज उस बात को भूल कर उसको पांच साल के लिये और बढ़ाने की तजवीज सरकार हाउस के सामने लाई है। सरकार अब यह कैसे कहती है कि हम इसको पांच साल के लिये और बढ़ा रहे हैं । यह मेरी समझ में नहीं आता गो मेरी समझ बहुत थोड़ी और छोटी है। एक एलान आन दी फलोर आफ दी हाउस किया गया तो अब उससे इन्कार कैसे हो सकता है। अब अगर यह कहें कि यह तो पहली सरकार की बात थी—अवल तो मैं नहीं मानता कि यह और सरकार है और वह और सरकार थी। This is only one sarkar and no second sarkar. मैं अर्ज करूँ कि जो साहिबान आज बरसरे इक्तदार हैं या हमारे लीडर हैं या मिनिस्टर हैं उस वक्त नकी तकरीरें क्या थीं। यह ठीक कहेंगे कि हम ने उस वक्त लोगों के जजबात का इजहार किया और उस पर किसी को एतराज़ भी नहीं मगर सवाल यह है कि जिस चीज़ को उस वक्त यही कहते थे कि नहीं लगनी चाहिए, आज खुद ही लगा रहे हैं तो अब इसके लिये कौन सी जस्टीफिकेशन है। मैं नहीं कहूँगा कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहिब ने उस वक्त क्या फरमाया था या हमारे बिजली मन्त्री जी ने क्या फरमाया था। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि कोई झगड़े वाली बात नहीं उठाना चाहता कि आप साहिबान की तकरीरों से ऐसा मालूम देता था कि आप यह टैक्स नहीं लगवाना चाहते थे क्योंकि यह उन लोगों पर बड़ा भारी बोझ होगा और इसमें किसी को शक भी नहीं है कि यह जिमीदारों पर बड़ा भारी बोझ है। This will prove to be the last straw on the camels back. इस बोझ से जमींदार की कमर टटने वाली है लेकिन अगर उसकी कमर टूट गई तो क्या यह बचेगें या कोई और बचेगा ? हम कहते हैं कि अगर आप उसकी कमर तोड़ने के लिये तैयार हो जाएं और वह इसकी वजह से बेकार और बेबस होकर रह जाए तो ये उसके साथ ज्यादती होगी।

दूसरी अर्ज यह है कि आपने पहले टैक्स लगाया तो पैदावार में कमी हुई। अब यह लगायेंगे तो और भी कमी वाक्या होगी। डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप जानती हैं कि बिना इंडस्ट्री में तरक्की किए कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता और ज़रायत भी एक इंडस्ट्री है। इसकी तरफ आपकी खास तवज्जो होनी चाहिए । क्या आप समझते हैं कि आपके कारखानों में कोई बिना खाये काम करेगा ? मैं नहीं समझता कि कोई कर सकेगा।

दूसरी मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि आजका नारा है "जय जवान जय किसान" लेकिन मैं तो यह कहता हूँ कि हम इसके आदी नहीं हमें तो यह नारा देना चाहिए कि "फारमर्ज फार आर्म्ज"। हमारे पास अच्छे फारमर्ज आज भी अच्छे फार्म कायम करने वाले हैं और अगर ऐसे लोगों को फार्म कायम करने का मौका दिया जाए तो लोगों को मजबूर न होना पड़े और वह आसानी से आपको पैसा दे सकें और अपनी जान कुरबान कर सकें और आपको आर्म्ज खरीदने के लिये रुपया दे सकें । पाकिस्तान ने तो बाहर के देशों से खरैत मांग कर आर्म्ज खरीद किए हैं और हमने पैसा लगा कर लिये हैं और दुनिया को दिखा दिया है कि हममें कितनी हिम्मत और बहादुरी है। इसलिये मैं अर्ज कर रहा था, जनाबे वाला कि जवान और किसान दोनों को बयक वक्त मज़बूत बनाने की ज़रूरत है। जब तक सरकार किसान को और जवान को मज़बूत नहीं बनाती और बयक वक्त मज़बूत नहीं बनेंगे तो दोनों कमज़ोर रहेंगे। इसलिये मैंने

[खान अबदुल गफार खां]

यह अर्ज़ किया कि ऐसी चीज़ें की जाएं जिससे किसान और जवान दोनों की बेहतरी हो। अगर इस बात को सामने नहीं रखा जाना और सरकार एडमैंट है कि लोगों पर इस टैक्स को लगाया जाए और हमारी अर्ज़ और मारूज़ और दरखास्त को नहीं सुनना तो हम भी इनके कहे पर रबड़ की मुहिर लगा देंगे। (घंटी) मैं डिप्टी स्पीकर साहिबा एक दो मिनट में ही खत्म कर दूंगा।

आज पंजाब के किसान पर कितने टैक्स हैं इनकी गिनती नहीं। मेरी अर्ज़ यह है कि हमें आज यह नहीं कहलवाना चाहिए कि आज जितने टैक्स किसान पर हैं उनकी गिनती ही नहीं की जा सकती। बला आए, मरी आए तो किसान पर कोई कहत पड़े टिड्डी आए और कोई मुसीबत आए तो किसान पर। बारिश न हो तो किसान का नुकसान और अगर बारिश ज्यादा हो तो भी नुकसान किसान का। किसी इन्डस्टरी का कोई नुकसान नहीं होता। आज किसान पर इसके इलावा अनगिनत टैक्स लगाय गए हैं और इस सरकार को यह नहीं कहलवाना चाहिए कि किसान पर टैक्स इतने ज्यादा हैं। फिर देखना यह भी है कि इन ज़िमीदारों में और टैक्स देने की कैपैसिटी भी है कि नहीं। और इसको देख कर ही उन पर टैक्स लगाने चाहिए।

जनाब डिप्टी स्पीकर साहिबा एक तरफ तो सरकार यह कहती है कि जिमींदारों को इन्सैन्टिव दिया जाए लेकिन पीछे इन्सैन्टिव शूगर इन्डस्टरी को दिया गया है। और 24 लाख रुपये की छोट दी गई थी। और ऐग्रीकल्चर की भी एक इन्डस्टरी है। इसको भी इन्सैनटिव देना चाहिए। लेकिन इस पर एक और टैक्स लगाया जा रहा है। टैक्सों से गरीब जिमीदारों की कमर दूहरी हो गई है और वह किसी किस्म का भी और टैक्स अदा नहीं कर सकते। इसलिये आली जा, खुदा रा ज़िमीदारों पर रहम किया जाए। नहीं तो यह खत्म हो जायेंगे।

मैं यह अर्ज़ कर रहा था, जनाबे वाला कि सरकार को सारी बातें देखने के बाद ही नया टैक्स लगाना चाहिए। (विघ्न)

(आवाज़: आप अब बस करें। आपका दम खत्म हो रहा है।)

"मेरा तो दम अब भी इतना है कि आपका दम ले के भी दम न लूंगा।"

तो जनाबे वाला मैं अर्ज़ कर रहा था कि जिन हालात में से आज ज़िमीदार को गुरज़ना पड़ रहा है, उसका आपको भी ज़ाती तजुरबा है और मुझे भी है। आज उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है? जरायत के महकमा की तरफ से कहा जाता है कि हम इस काम में एक्सपर्ट हैं और नहरों के पानी के माहर हैं और नए नए छोकरे कालेजों से निकले और इस सरकार की मुलाज़मत में आ गए और अपने आपको एक्सपर्ट मानने लगे। लेकिन इन्हें किसी भी बात का पता नहीं। कहते हैं कि भाखड़ा पर जगह जगह नहरों पर इन्होंने कलवर्ट तैयार किये हैं और निहायत अफसोस के साथ जनाब, डिप्टी स्पीकर साहिबा, कहना पड़ता है कि तमाम के तमाम ऐसी जगह पर लगाये गए हैं जहां कि नैचुरल फलो नहीं था। यह उन एक्सपर्टस के बनाए हुए हैं जो सीधे कालेजों से निकल कर थोड़ी ट्रेनिंग लेकर आ जाते हैं, जिन्हें न तो इलाके का पता होता है और न ही वह पब्लिक से मिल कर ही पता करने की कोशिश करते हैं। इन कलवर्ट में नेचुरल फलो न होने के कारण फलड्ज़ आ जाते हैं, इलाका तबाह हो जाता है और लोगों को तकलीफ होती है।

इसके बाद, जनाबेवाला, मैं यह भी अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ऐग्रीकल्चर वालों के लिये कार्तिक का महीना ऐसा होता है कि उसमें उसे मरने की भी फुरसत नहीं होती और अगर ज़रायत का महकमा इसको न जाने तो क्या किया जाए और इस महीने में वह बहुत मसरूफ रहता है। कहा जाता है कि पगड़ी बांधने में उसको पछेता हो जाता है, इतनी भी फुर्सत नहीं होती, लेकिन इस महकमा ने लोगों को कार्तिक के महीने में बुलाया और कहा कि हम आपको सुझाव देना चाहते हैं कि ज़िमीदारी में कैसे बढ़ावा दिया जाए । वहां उन्हें हल छोड़न की फुर्सत नहीं और इन्होंने लगातार 8 दिन तक उन्हे बिठाए रखा । मुझे समझ नहीं आती कि आपके ऐक्सपर्ट्स वहां तक इस काम को समझते हैं यह तो समझने की बजाए और नुकसान करते हैं ।

एक और बात, जनाबेवाला, आपकी मारफत सरकार के सामने रखना चाहता हूँ कि इनके जो ऐक्सपर्ट हैं वह क्या करते हैं । कहां कहां और क्या क्या काम करते हैं । आप जानते ही हैं कि कालका में पीने के पानी की किल्लत है और कमी है और आज की नहीं बहुत देर से चली आ रही है और उस वक्त आज के जो एकटिंग गवर्नर हैं वह फिनांस मिनिस्टर थे । लोगों ने उन्हें कहा कि यहां से पानी निकलेगा (घंटी) मैं खत्म ही करने वाला हूँ । तो मैं यह अर्ज़ कर रहा था कि पानी के लिये लोगों ने कहा कि यहां से पानी बहुत निकलेगा तो सरकार ने कहा कि इसके लिए 5 हज़ार रुपया चाहिए ताकि इस इलाके की आज़माइश कर ली जाए और पानी निकाल कर दिया जाएगा 5 हज़ार रुपया एक्सपैरीमैंट के लिये दिया गया । इस पर सरकार न अपने एक्सपर्टस भेजे। पब्लिक हैल्थ और इरिगेशन के ऐक्सपर्ट भेजे गए कि जाकर देखा जाए और डिप्टी स्पीकर साहिबा आपको सुन कर रंज होगा कि उन अफसरों ने और ऐक्सपर्टों ने यह फतवा दिया कि यहां से पानी नहीं निकलेगा । लोगों ने उन्हें कहा कि छोड़ो और इसके बाद क्या हुआ ? हमने कालका में से लोगों से ही चंदा इकट्ठा किया और उस जगह की खुदवाई कराई और इतना पानी निकला कि आज आप वहां पर जा कर देखें कि पानी का वाटरवर्क्स बना हुआ है और पानी इतना है कि तीसरी मंजिल तक पहुंचता है ।

यही हालत ठीक ऐग्रीकल्चर के महकमा के एक्सपर्टों की है कि सिवाए यहां पर दफतर में बैठ कर सलाह देने के और कुछ नहीं कर सकते । यह जिमींदारों को क्या सलाह देंगे ? इनका बस ही गरीब जिमींदार पर चलता है क्योंकि उसमें ताकत नहीं होती आंख बंद और कानों में रूई डाले सरकार काम करती है और अफसर इन किसानों के लिये कुछ नहीं करते । इसलिये मैं आखिर में इतनी अर्ज़ करूँगा कि सरकार को यह देखना चाहिए कि किसान में कैपैसिटी है या नहीं और कैपसिटी देख कर ही कोई टैक्स लगाना चाहिए । अगर आप मान जाएं तो उनके लिये बेहतर होगा और अगर आप ऐडेमेंट हों तो फिर हमारा वही हाल है जो उस नौकर का होता है जो यह कहे कि अच्छा हम उसी तनखाह पर काम करेंगे ।

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੇਜਰ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਹ ਜੋ ਕਮਰਸ਼ਲ ਕਰਾਪਸ ਸੈਸ ਬਿਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ । ਜੋ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ

[ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ]

ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਅਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ:—

ਆਪਸ ਕਉ ਜੋ ਜਾਣੈ ਨੀਚਾ, ਸੋਊ ਗਣੀਏ ਸਭਸੇ ਊਚਾ ।

ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਇਕ ਤੁਕ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨ ਕੁਝ ਗੇਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ।

ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਜਦੋਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਜੋ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਿਲ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 27 ਮਾਰਚ, 1963 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜ਼ਾਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸਬੰਧਤ ਡੀਬੇਟਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਰੀਜ਼ਨਜ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਹੀ ਹਨ । ਇਤਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ ਹਨ । ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਸੂਬੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ (ਤਾਲੀਆਂ) (ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ, ਬੈਠੇ : ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ) । ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਟੋਕੋ ਨਾ ਇਹ ਟੋਕਾ—ਟਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਪਵੇਗੀ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਰੌ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਕੇ ਜ਼ਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਕੱਢਣ ਕਢਾਨ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ । ਝਗੜਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ ਅਤੇ ਰੂਪ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ (ਵਿਘਨ) ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਟੋਕੇ ਬਗੈਰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ । ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਮੂੰਹ ਵਿਚੋਂ ਹੋਰ ਕਢਾ ਲੈਣਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ । ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਖੀ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਤਨੀ ਕੁ ਸ਼ਕਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰੋਵੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਠੰਡੇ ਸੁਭਾਓ ਦਾ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੈਲੰਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਰੱਖਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ।

ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਤੇ ਜੋ ਤਕਰੀਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਮੈਂ ਏਥੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਤਜਰਬੇ ਵੀ ਵੇਖੇ ਹਨ । ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਬਦਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਖਿਆਲਾਤ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਤਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਦੇ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਸੀਟ ਰਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਚੁਪ ਕਰਕੇ ਸੀਟ ਤੇ ਆ ਬੈਠਣਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਚੁਪਕੇ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ । ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਬਦਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ । ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ । (ਹਾਸਾ)

ਇਥੇ ਕੁਝ ਇਕ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਨੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਇਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਦਾਦ ਦਿਆਂਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਦਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਇਕ ਗਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਢਗਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਲੱਭਣ ਚੜ੍ਹ ਪਿਆ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਇਆ ਉਥੇ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖ ਲਈ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਦਰ

ਆਇਆ ਉਥੇ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਸੁਖ ਲਿਆ ਜੇ ਮਸੀਤ ਆਈ ਤਾਂ ਚੂਰਮਾ ਸੁਖ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਲੇ ਮਾਣਸਾ ਇਤਨੇ ਦਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਢਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਤਨੇ ਦੀਆਂ ਤੈਂ ਸੁਖਣਾ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਆਂ। 100 ਰੁਪੈ ਦਾ ਜੇ ਤੇਰਾ ਢੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ 150 ਰੁਪੈ ਦਾ ਤੈਂ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਸੁਖ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਜ਼ਰਾ ਢੱਗੇ ਦੇ ਸਿੰਗ਼ੀ ਹੱਥ ਪੈ ਲੈਣ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਵਾਇਦੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਜ਼ਰਾ ਸਿੰਗ਼ੀ ਹੱਥ ਤਾਂ ਪੈਣ ਦਿਉ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਧਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਇਦੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਕੂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਗਵਾਕੇ ਖੁਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੌਧਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗ਼ਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗ਼ਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਬੂਟਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਖਾ ਦੇਣ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਚੀਕੂ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾ ਲਵਾਂ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿ ਉਥੇ ਚੌਧਰੀ ਜਗਤ ਰਾਮ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਨੇ ਵਾਇਦੇ ਕੀਤੇ ਸੈਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਇਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਆਤ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਏਥੇ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰੀਜਨ ਕਲਿਆਣ ਕਾਰੀ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਸੁਖਾਲੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ 5% ਬੋਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਬੋਲੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਕਰ ਗਏ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, । ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੌਂਡੀ ਪਿਟਣੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਨਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹਰ ਮੁਮਕਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਉਨਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਉਨਤੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਤਅਲੁਕ ਹੈ। ਏਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤਾਰਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਦੁਖ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਾ ਵੀ ਸਦਾਕਤ ਨਹੀਂ। (ਵਿਘਨ) ਮੈਂ ਫੇਰ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਪਸ਼ਨਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪ ਦੇ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪੁਆਇੰਟਸ ਫੇਅਰਲੀ ਡੀਲ ਵਿਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ। (ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ:—ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟਰਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ) ਕਲ ਏਥੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਯਾ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇਤਨੀ ਖੈਰ ਖੁਆਹ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਦੀ,

[ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ]

ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ । ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਗੱਲ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ । ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਲਸਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਲ ਭਜ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ । ਫੇਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਪੀਚ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ । ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਫਲਾਨੀ ਥਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਲਗੜਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਦੌੜ ਲਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜੇ ਆਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਵਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰੇ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਹੀ ਆਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਮੇਰੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਈਕਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ । ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ (ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ:—ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ) (ਹਾਸਾ) ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਲੈਕਚਾਰਾਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋਵਾਂ ।

ਜੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਓ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਭਜ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਆਖਿਓ। ਅਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਮਿਲਿਆ । ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ । ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਕਢੀ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ।

ਕਾਮਰੇਡ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ : ਸਾਨੂੰ ਪੁਛਣਾ ਪਏਗਾ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਨੋ ਇੰਟਰਪਸ਼ਨ । (*No Interruption*)

ਮਾਲ ਮੰਤ੍ਰੀ : 'ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਸਵੱਲੀਆਂ ਜੇ ਮਿਲਣ ਪਰਾਈਆਂ' । ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਿਗਰਾ ਬਣਾਓ । ਆਖਿਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸੁਣਨੀਆਂ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਕਾਮਿਊਨਿਸਟ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਥੋਂ ਉਜੜ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕੀ ਓਧਰੋਂ ਉਜੜ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਥੋਂ ਉਜੜ ਜਾਣਾ ਹੈ । ਏਥੋਂ ਉਜੜ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ । 'ਕਲ ਨਾਉਂ ਕਾਲ ਦਾ ।'ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ। If past experience is any guide, ਤਿੰਨ ਬਾਈ ਅਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ । (ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਵਲੋਂ ਪਰਸੰਸਾ) ਸਾਰੀ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ । ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਫਿਰਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਂ । ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੋਈ ਕੀਤਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪੰਜ ਛੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ?

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਓਧਰ ਕਿੰਨੇ ਲੈ ਗਏ ਹੋ ?

ਮਾਲ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ? ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ । ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਬਹੁਤਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਾਪੇਗੰਡਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ । ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰਤੱਵ, ਉਸ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਉਸ ਦਾ ਪਰਾਪੇਗੰਡਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਥੁਕ ਨਾਲ ਵੜੇ ਨਹੀਂ ਪਕਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ । ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ । ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੈਰ ਹੁੰਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਤਅਲੁਕ ਰਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ, ਆਲੂ, ਮੂੰਗਫਲੀ, ਤੇ ਤੋਰੀਆ ਆਦਿ ਵੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਬਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਕ ਗੱਲ ਭੁਲ ਗਿਆ ਸੀ । ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਓਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਦਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਯਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰੇਗਾ, ਛਾਤੀ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਗਿਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਓਦੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰੀ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰੀਂ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ? ਹੁਣ ਵੀ ਓਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ । ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚੋਂ ਰਾਜ ਬਣਤਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੇਣੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ।

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਮੈਡਮ । ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਛਾਤੀ ਤੇ ਹੱਥ ਰਖ ਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਓਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਓਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਮੈਂ ਛਾਤੀ ਤੇ ਹੱਥ ਰਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਘਟ ਗਏ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣੇ ਦਸੋ । ਬਾਦ ਵਿੱਚ ਪੁਛ ਲੈਣਾ । (It does not behave Comrade Shamsher Singh to say like this. He did not say to show it just now. This may be asked at some other time.)

ਮਾਲ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਕਾਮਰੇਡ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਲਿਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਗੱਲ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਕਲ ਬਾਬੂ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ । ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਇਨਚਾਰਜ ਮਨਿਸਟਰ, ਭਾਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੋਵਾਂ ਓਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਕੰਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮਨਿਸਟਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹੀ, ਸੋ ਜੋ ਮੈਂ ਖ਼ਿਆਲਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਖ਼ਿਆਲਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਓਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਵਾਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਕੁਲੀ, ਗੁਲੀ ਤੇ ਜੁਲੀ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਮਸਲੇ ਹਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਓਨ੍ਹਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਸਲਿਸ਼ਟ ਪੈਟਰਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : ਇਹ ਜੂਲੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਨੇ ।

ਸਰਦਾਰ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ : ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਨੇ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਸਪੀਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ । (There is some serious speech too. The hon. Members should listen to him.)

ਸ੍ਰੀ ਬਲਰਾਮਜੀ ਦਾਸ ਟੰਡਨ : ਇਹ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਸਰਦਾਰ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਜੂਲੀ ਕਹਿ ਕੇ ਖਜਾਉਂਦੇ ਨੇ ।

ਮਾਲ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਐਵੇਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਢਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ । ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਭੁਲ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਿਕ ਪੈਟਰਨ ਆਫ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਏ ਹਾਂ ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਓਧਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੇ ਚਲ ਪਏ ਤਾਂ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਓਥੇਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ । ਮੰਜ਼ਲੇ ਮਕਸੂਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ? ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਚਲਿਆ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। (ਵਿਘਨ) ਬੈਠੇ ਏਥੇ ਹੋ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹ ।

ਇਕ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ : ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਓਧਰ ਝਾਕਦੇ ਹੋ ।

ਮਾਲ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਮੰਗ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ, ਏਡ ਲੈ ਕੇ ਜੀਊਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ । (ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਵ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਡੀਪੈਂਡ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਭਾਵੇ ਰੂਸ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੋਵੇ । ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਚੰਗੀ ਪਰ ਕਣਕ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਲ ਤਕਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ । (ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ) (ਵਿਘਨ)

ਇਕ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ : ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਹੈ ।

ਮਾਲ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਕੀ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ।

ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਗੋਆਣੀ : ਸਾਈਕਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ।

ਮਾਲ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੁਝ ਜਾਨ ਵੇਖੀ । ਇਸ ਗਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ । ਕਈ ਵਾਰੀ ਏਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਖਦੇ ਹੋ । ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਜੇ ਅੰਜਾਣਾ ਰੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਦੁਧ ਨਹੀਂ ਪਲਾਉਂਦੀ । ਇਹ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਕਰਨ ਤਾਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਣ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗਾ । ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ

ਖੁਸ਼ੀ ਓਦੋਂ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਬਤੌਰ ਮਨਿਸਟਰ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਇਤਕਾਦ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਤਬਕਾ ਹੈ ਇਹ ਇਕਨਾਮੀਕਲੀ ਅਤੇ ਪੁਲੀਟੀਕਲੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਵੇਂ ਹਕ ਵੰਡਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਮੁਅਜ਼ਜ਼ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹਨ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਜਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕੈਰੀਅਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਇਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੀ ਰਵਾਇਤ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜੰਗ ਲਈ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਿੰਦੁ-ਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਚਾਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੰਨੋਗੇ ਕਿ 1947 ਦੇ ਘਲੂਕਾਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੁਝ ਘਟ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਵੀਰ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਸਨ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਜੜ ਕੇ ਆਏ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਅਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦਸਦਾ ਹਾਂ। ਉਥੇ ਮੈਂ ਇਕ ਵੇਰ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਫਰੂਟ ਜੂਸ ਪੀਣ ਨੂੰ। ਉਥੇ ਇਕ ਬੱਚਾ ਫਰੂਟ ਜੂਸ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾ ਲਫਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਢ ਦੇਈਏ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਦਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਫਰੂਟ ਦੇ ਜੂਸ ਦਾ ਇਕ ਗਲਾਸ ਲਿਆਇਆ, ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਚਾਰ ਆਨੇ ਕੀਮਤ ਮੰਗੀ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਟੁਟੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮਗਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਚਲਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਜ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, "ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 12 ਆਨੇ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।" ਮੈਂ ਕਿਹਾ, "ਕਾਕਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ।" ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਮੰਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਹੱਥ ਅੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁਖ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਮੰਗੋ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਡੀਫੈਂਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਸਕੀਏ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਅੱਡਿਆ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਾ ਪਾਉ। ਸਾਨੂੰ ਅਣਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹੱਥ ਅਡ ਕੇ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ ਮਨਿਸਟਰ ਦੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਤੌਰ ਮਿਸਟਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ ਮਨਿਸਟਰ ਦੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਮੰਗ ਕੇ, ਮੱਥੇ ਘਸਾ ਘਸਾ ਕੇ, ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਮਾਲ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਬਾਬੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ (ਵਿਘਨ)

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਝਗੜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। (If the hon. Minister goes to reply to what Babu Bachan Singh has said, it would raise a controversy.)

ਮਾਲ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਹੋ ਜਾਏ, ਫੇਰ ਜੀ ਮੈਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ । ਮੈਂ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਪਗ ਲਾਹੁਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਪਗ ਲਾਹੁਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ । ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਖ਼ੂਨ ਵਿਚ ਹੈ । ਖ਼ੈਰ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾਂ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਲਿਆ ਸਕੀਏ ਲਿਆਈਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਉਥੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡੀਫੈਂਸ ਫੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡੀਫੈਂਸ ਫੰਡ ਕਾਹਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਊਬਾ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕਿ ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ, ਕਪੜੇ ਔਰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਭ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਲੋੜ ਪਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰੇਗਾ ਔਰ ਇਕ ਇਕ ਬੱਚਾ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਬੁਢਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਲੜੇਗਾ । ਏਥੇ ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਏਥੇ ਯੂ. ਕੇ. ਅਤੇ ਯੂ. ਐਸ. ਏ. ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ । ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ।

ਮਾਲ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਏਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂ.ਕੇ. ਅਤੇ ਯੂ.ਐਸ.ਏ. ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਅਪਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸੇ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਫਾਲੋ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ 25/25 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੀਆਂ ਫਾਰਮਾਂ ਹਨ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕਾਜ਼ ਪਲੀਡ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਨਿਆਂ ਹੈ ਕਿ

4 p.m. । ਇਸ ਟੈਕਸ ਤੇ ਕੋਈ ਉਜਰ ਨਹੀਂ ਹੈ—ਅਗਰ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਗਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਟੈਕਸ 5 ਏਕੜ ਵਾਲਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ । ਜਿੱਥੇ ਤਕ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ । ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੁਖ਼ਾਲਫਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਢੰਗ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਗੌਰਮਿੰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਾਲਜਿਜ਼ ਖੁਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਸੜਕਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਇਹ ਭੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਅਲਾਦੀਨ ਦਾ ਚਰਾਗ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਹਿਸਟਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪੱਤੀ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਦਾ 85% ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਭੀ ਆਪੱਤੀ ਆਈ ਤਾਂ ਇਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਭੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ .....

चौधरी नेत राम : केन्द्रीय सरकार ने आमदनी के बेसिज़ पर टैक्स लगाने का अस़ूल माना है। सरकार 4 हज़ार की इन्कम पर ही इन्कम टैक्स लगाती है 15 एकड़ ज़मीन रखने वाले किसान की इनकम 4 हज़ार तो होनी दरकिनार है, मैं दावे से कह सकता हूँ कि 30 एकड़ वाले किसानों की इन्कम भी चार हज़ार नहीं होती । ......(शोर) (विघ्न)

ਮਾਲ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਕ ਆਦਮੀ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ? (ਚੌਧਰੀ ਨੇਤ ਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਵਿਘਨ)

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਢੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਸ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਫੰਡ ਹੋਵੇ । ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡੈਫਿਸਿਟ ਫਿਨਾਂਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਏ ਜਾਣ । ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਕਨਾਮਿਕ ਐਕਸਪਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਹਨ । ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕਨਾਮਿਕ ਐਕਸਪਰਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਮੱਥਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਡੈਫਿਸਿਟ ਫਿਨਾਂਸਿੰਗ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਗਰ ਡੈਫਿਸਿਟ ਫਿਨਾਂਸਿੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟਰੈਂਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਲਟੀ-ਮੇਟਲੀ ਜਨਤਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ । ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਹੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਈਲੈਕਸ਼ਨ ਸਟੰਟ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਈਲੈਕਸ਼ਨ ਸਟਟ ਜਿਹੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਫਿਗਰਜ਼ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ । ਮੈਂ ਉਹ ਫਿਗਰਜ਼ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਇਹ ਫਿਗਰਜ਼ 1964 ਦੀਆਂ ਹਨ । ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਗਰਜ਼ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਨ । ਹਾਂ ਉਹ of course subject to correction ਹਨ । ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫਿਗਰਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਨ । ਫਿਗਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਫਿਗਰਜ਼ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । After all to err is human. Total area under cultivation 1,85,94,214 ਏਕੜ ਹੈ and total

[ਮਾਲ ਮੰਤ੍ਰੀ]

area cultivated under Commercial Crops 23,71,278 ਏਕੜ ਹੈ । ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੋਟਲ ਦਾ 12.7% ਹੈ । ਇਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਲਗੇਗਾ । ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ । It is misrepresentation of facts. ਇਹ ਟੈਕਸ ਸਿਰਫ 3 ਮੈਚੋਰਡ ਫਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗੇਗਾ । ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਲ ਡਰਾਈ ਸਪੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਸਾਲ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਟੈਕਖ ਕਿਵੇਂ ਲਗੇਗਾ ? ਅਗਰ ਉਥੇ ਖਰਾਬਾ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਟੈਕਸ ਕਿਵੇਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਬਿਆਲ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਇਕ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਹੈ । ਉਸ ਐਕਟ ਦਾ ਨਾਂ The Maharashtra Education Cess Act, 1962, ਹੈ । ਉਥੇ ਸੈਸ Sugar cane grown on perennial irrigated land is Rs. 25 per acre and sugar cane grown in any other land is Rs 15 per acre. ਕਪਾਹ ਜਿੱਥੇ ਇਰੀਗੇਟਿਡ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਥੇ 5 ਰੁਪਏ ਫੀ ਏਕੜ ਸੈਸ ਲਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਿਗਰਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਡੀਮਾਰੇਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਈਫੈਕਟ ਹੋਵੇਗਾ । ਡਿਮਾਰੇਲਾਈਜ਼ੰਗਿ ਈਫੈਕਟ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਅਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਲਈ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਫਿਗਰਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਪਲੀਡ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਸਕੇ । ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਗਰਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਾਪਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਹੀ ਹੈ । ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਭਾਵੇਂ ਇਹ 100 ਏਕੜ ਸੀ ਜਾਂ 1000 ਏਕੜ ਸੀ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 3 ਕਰਾਪਸ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਅਗਰ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਭੀ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ । ਅਗਰ ਫਾਰ ਦੀ ਸੇਕ ਆਫ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਇਹ ਮੰਨ ਭੀ ਲਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਾਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਮਾਰੇਲਾਈਜਿੰਗ ਈਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੰਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਬਣਦੀ ਹੈ । ਸ਼ੂਗਰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਕੇ ਫਾਰੇਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਅਰਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਕੋਈ ਡੈਂਪਨਿੰਗ ਈਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਭੀ ਐਗਰੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਫੂਡਗਰੇਨ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਫਾਰੇਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਤੋਂ ਘਟ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਹੈ । ਪਹਿਲਾਂ 13% ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਮਾਨਯੋਗ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਰਲਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭੀ ਕੁਝ ਦੱਸਣ । (ਵਿਘਨ)

ਮਾਲ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸੁਣਨ । ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ । (ਵਿਘਨ)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ 3% ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 13% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ।

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ : ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 13% ਤੋਂ 6% ਤੇ ਲੈ ਆਏ । ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਵੇਯਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ within paying capacity ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅੰਡਰ-ਰਾਈਟ ਕਰਕੇ ਇਵੇਯਨ ਕਰਨ, ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਨੈਸਟੀ ਵਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ? ਮੈਂਬਰਜ਼ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ facts ਨੂੰ ਵੇਖਣ, ਫਿਗਰਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ । ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ । ਸੈਕਰੇਟਰੀਏਟ ਵਿਚ ਫਾਈਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਫੈਕਟਸ ਫਿਗਰਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੋਲਣ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਜਾਣ । ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ absolutely falls flat on the ground. ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਆਲਾਤ ਦਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਆਲਾਤ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਫ਼ੀਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸ-ਪੁਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਹਨ, ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵਾਰ ਹਿਟ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰੂੰਟ ਬੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ......

ਇਕ ਆਵਾਜ਼ : ਟੋਟਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਸੋ ।

ਮਾਲ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਟੋਟਲ ਟੈਕਸ ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿਉ ਚਾਹੇ ਨਾ ਦਿਉ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਸ ਫਿਗਰਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆ-ਇਆ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ lest I may be caught unaware. ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਇਨਕਮ 65 ਲੱਖ ਤੋਂ 63 ਲੱਖ ਤਕ ਵੇਅਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਡੀਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਰਕਬਾ ਕਰਾਪਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੈ । I again say subject to correction ਕਿ 1963-64 ਵਿੱਚ ਜੋ ਡੀਮਾਂਡ ਕਰਾਪਸ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ 7317659 ਦੀ ਸੀ । ਜਿਹੜੀ ਡੀਮਾਂਡ 1964-65 ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟ ਲਈ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ 6647439 ਦੀ ਸੀ । ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤਿੰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚੋਂ ਕਢ ਦੇਈਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵਸੂਲੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1964-65 ਵਿੱਚ 31.5% ਆਫ ਦੀ ਟੋਟਲ ਡੀਮਾਂਡ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 1963-64 ਵਿੱਚ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 34.4 ਆਫ ਦੀ ਟੋਟਲ ਡੀਮਾਂਡ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਰਕਮ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ । ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਵੀ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ

[ਮਾਲ ਮੰਤ੍ਰੀ]

ਜੋ ਕੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੀਜ਼ੀਊਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਐਬਸੋਲੀਊਟਲੀ ਇਨਕੁਰੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਿਸ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੈਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਕੰਟੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਚੈਲੈਂਜ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਦਰੁਸਤ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਗੋ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰਖ ਸਕਾਂ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਡੀਮਾਂਡ ਟੋਟਲ ਕਲਟੀਵੇਟਿਡ ਏਰੀਏ ਤੇਂ ਕੁਰੈਕਟਲੀ ਸਪਰੈਡ ਆਊਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ।ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਰ ਏਕੜ ਤਾਂ 35 ਪੈਸੇ ਸੈਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉ ਕਿ ਉਹ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਈ । 35 ਪੈਸੇ ਪਰ ਏਕੜ ਕੋਈ ਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.. (*Interruption*)

ਇਕ ਆਵਾਜ਼ : ਜੁਲਾਹਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ......

ਮਾਲ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਹ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਹਾ ਕੌਣ ਹੈ ......(*Interruption*)

ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਨਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ । ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ:—

ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਜਾਣੇ ਨੀਚਾ,
ਸੋਊ ਗੁਨੀਏ ਸਭ ਤੇ ਊਚਾ ।

ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵਲ ਹੈ.....ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ ਸਨ । (*Interruption*)

ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਗਿਆ । ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ......

ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ : ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੋ ।

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ: ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗਲ ਕੱਰੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਵੀ ਹਨ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਇਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਚੁੰਜਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਜੋ ਹਸਾਉਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਨਰਵਸ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੋ ਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤਾਂ ਹੀਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਸਵੇਰੇ ਉਠ ਕੇ ਪੁਛਣ ਲਗੇ ਕਿ ਹੀਰ ਆਦਮੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜ਼ਨਾਨੀ । (ਹਾਸਾ) ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਸਮਰਥਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ...(Interruption)(ਹੀਰ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ) ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਆ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ । ਉਹ ਕੁੱਜੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ, ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ ।(Interruptions)

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਖ਼ਿਆਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਆਜਜ਼ੀ ਅਤੇ ਇਨਕਸਾਰੀ ਨਾਲ ਲੇਕਿਨ with all the emphasis atmy command ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੈਸ ਲਗਾਇਆ

ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਾਹੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਥਰਡ ਫਾਈਵ ਯੀਅਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰੁਪਿਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ side by side ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਅਗ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਮਨਾਂ ਤੇ ਹੈ ਸੀ। ਚਾਈਨੀਜ਼ ਅਗ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਚਾਹੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕੋਹ ਦੂਰ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੰਪੈਕਟ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸੈਸ ਨੂੰ continue ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਰੀਜ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਇਨੋਸੈਂਟ ਮੇਈਅਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹਾਊਸ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। (Cheers from the Treasury Benches.)

Deputy Speaker : Now I will put the amendments to the vote of the House. The first amendment is in the names of Comrade Bhan Singh Bhaura, Comrade Gurbakhsh Singh and Comrade Babu Singh Master.

Question is—

That the Punjab Commercial Crops Cess (Amendment) Bill 1965, be circulated for eliciting public opinion thereon by the 31st December, 1965.

The motion was lost

Deputy Speaker : The next Amendment is in the names of Comrade Jagir Singh Joga and Comrade Shamsher Singh Josh.

Question is—

That the Punjab Commercial Crops Cess (Amendment) Bill, 1965, be circulated for eliciting pnblic opinion thereon by the 31st December, 1965.

The motion was lost.

Deputy Speaker : The other amendment is in the names of Babu Bachan Singh and Shri Ajit Kumar.

Question is—

That the Punjab Commercial Crops Cess (Amendment) Bill, 1965, be circulated for eliciting public opinion thereon up to 31 st January, 1966.

The motion was lost.

Deputy Speaker : Now I will put the main motion to the vote of the House.

Qnestion is—

That the Punjab Commercial Crops Cess (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The House divided.

डाक्टर बलदेव प्रकाश: आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडम। डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस रिज़ल्ट को एनाऊंस करने से पहले आप मेरी बात को सुन लीजिये।

Sardar Gurnam Singh : Madam, they (pointing towards Treasury Benches) are molesting a member.

उपाध्यक्षा : डाक्टर बलदेव प्रकाश, आप क्या कहना चाहते हैं? (What does the hon. Member Dr. Baldev Parkash want to say ?)

डाक्टर बलदेव प्रकाश : मैडम, मैं प्वायंट आफ आर्डर पर खड़ा हूँ। मैं चाहता हूँ कि रिज़ल्ट एनाऊंस करने से पहले आप मेरी बातें सुन लीजिये। जो अभी अभी वोटिंग हुई है उसी के सम्बन्ध में मेरा प्वायंट आफ आर्डर है।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, उधर आपके राईट पर जो लाबी है वहां कुछ आनरेबल मैम्बरज़ को अपना वोट देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जिस लिस्ट पर मैम्बरों के वोट मार्क किये जाते हैं, वह छपी हुई होती है और हरेक मैम्बर के नाम के आगे नम्बर दिया होता है। वह नम्बर बोल दिया जाता है तो उस मैम्बर का वोट दिया समझ कर वहां मार्क कर लिया जाता है .....

श्री सुरेन्द्र नाथ गौतम : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडम। यह बिल्कुल झूठ कह रहे हैं। किसी मैम्बर को मजबूर नहीं किया जा रहा।

डाक्टर बलदेव प्रकाश : डिप्टी स्पीकर साहिबा, पहले आप मेरी बात को सुन लीजिये। कुछ मैम्बरज़ के साथ यह हो रहा है कि उनको यहां से ज़बरदस्ती ले जाया जाता है और वहां जो आपका लिखने वाला आदमी बैठा है उसे उसको दिखा कर साथ ही उसका नम्बर बोल दिया जाता है हालांकि वह "न न" कर रहा होता है। अब वहां पर यह हो रहा है। आप जाकर चेक कर सकती हैं। मेरे ख्याल में तकरीबन 20 या 25 मैम्बरज़ ऐसे हैं जिनकी मर्ज़ी के खिलाफ उनके वोट डाले गए समझे गए हैं। इसलिये मेरी आपसे गुज़ारिश है कि डिवीज़न का रिज़ल्ट एनाऊंस करने से पहले दोबारा वोटिंग कराई जाए। (बहुत शोर)

Deputy Speaker : Order please.

ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਪ-ਮੰਤਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਪਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਸ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਥੇ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ ਇਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਆ ਕੇ ਘਸੀਟ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਇਥੇ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰੋਟੈਸਟ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲੇ ਬਿਲੇ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁੜਾਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਖਿਚਾ ਖਿਚੀ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੋ। ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੋਬਾਰਾ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। (I cannot believe that the hon. Member Sardar Narain Singh Shahbazpuri has been bodily lifted as I think it is impossible for any one to do so.)

ਸਰਦਾਰ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿਲ ਤੇ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਣ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਸਰਦਾਰ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਇਤਲਾਹ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਵਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। (The hon. Member Sardar Narain Singh Shahbazpuri has not been rightly informed. It is wrong to say that I have been approached by the Chief Minister or by any other Minister, not to allow him to speak on this Bill. The hon. Member, has every right to speak on this Bill and he can get opportunity to speak.)

ਸਰਦਾਰ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜਪੁਰੀ : ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਇਜ਼ਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਫਸਟ ਰੀਡਿੰਗ ਤੇ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ......

Deputy Speaker : All the members cannot speak at a time. There is still time and the hon. Member will be given time to speak on this Bill.

ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਮੰਤਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ): ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਦੋ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੋਂਦੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ।

पंडित चिरंजी लाल शर्मा : श्रान ए प्वायंट श्राफ श्रार्डर, मैडम। वोटिंग के बारे में यहां पर संगीन इलजाम लगाया गया है और इसके अलावा हाउस के सामने यह चीज भी आई है कि एक आनरेबल मैम्बर की उंगली जख्मी की गई है। आप देखें उनकी उंगली खून आलूदा है। इस लिये आप आनरेबल मैम्बर का मैडीकल एग्जामिनेशन कराएं ताकि पता चले कि आया यह सैल्फ इनफलिक्टिड है या इन्हें मारा गया है।

Deputy Speaker: I will now declare the result of the Division.

Ayes : 64

Noes : 25

The motion was declared carried.

AYES (Total No. 64)

1. Abdul Ghaffar Khan, Khan.
2. Ajmer Singh, Sardar
3. Amar Nath Sharma, Shri
4. Amar Singh, Shri
5. Baloo Ram, Chaudhri
6. Banwari Lal, Shri
7. Banarsi Dass, Shri
8. Bhagirath Lal, Pandit
9. Bhag Singh, Lieut.
10. Brish Bhan, Shri
11. Chand Ram, Shri
12. Chandrwati, Shrimati
13. Dalip Singh, Sardar
14. Darshan Singh, Chaudhri
15. Darbara Singh, Sardar
16. Dasondhi Ram, Chaudhri
17. Dev Raj, Anand, Shri
18. Dilbagh Singh, Sardar
19. Dina Nath, Aggarwal, Shri
20. Gian Chand, Shri
21. Gian Singh, Rarewala, Sardar
22. Gurmej Singh, Sardar
23. Gurmit Singh, Sardar
24. Guran Dass Hans, Bhagat
25. Gurmail, Shri
26. Gurdial Singh, Dhillon, Sardar
27. Harinder Singh, Major, Sardar
28. Hari Ram, Chaudhri
29. Hari Singh Sardar
30. Harkishan, Chaudhri
31. Hira Lal, Shri
32. Hoona Mal, Shri
33. Jagat Ram, Chaudhri
34. Jagir Singh Dard, Sardar
35. Jagjit Singh, Tikka

36. Jai Inder Singh, Sardar
37. Karam Singh, Kirti, Sardar
38. Kesra Ram, Shri
39. Mehar Singh, Thakur
40. Multan Singh, Shri
41. Nihal Singh, Shri
42. Nihal Singh, Rao
43. Partap Singh, Bakshi, Shri
44. Piara Singh, Sardar
45. Prabodh Chandra, Shri
46. Prem Singh 'Prem' Sardar
47. Pritam Singh Sahoke, Sardar
48. Rala Ram, Principal
49. Ram Chandra, Comrade
50. Ram Kishan, Shri
51. Ram Pal Singh, Kanwar
52. Ram Partap Garg, Shri
53. Ram Rattan, Chaudhri
54. Ram Saran Chand Mital, Shri
55. Ranbir Singh, Chaudhri
56. Rattan Singh, Captain
57. Rizaq Ram, Chaudhri
58. Roop Lal Mehta, Shri
59. Rup Singh Phul, Shri
60. Sagar Ram Gupta, Shri
61. Sita Ram Bagla, Shri
62. Surinder Nath Gautam, Shri
63. Ujagar Singh, Sardar
64. Sohan Singh, Jalalusman, Sardar

NOES (Total No. 25)

1. Ajaib Singh, Sandhu, Sardar
2. Babu Singh, Master, Comrade
3. Bachan Singh, Babu
4. Baldev Parkash, Dr.
5. Balramji Dass, Tandon, Shri
6. Bhan Singh Bhaura, Comrade

[Deputy Speaker]

7. Chiranji Lal, Sharma Pandit
8. Devi Lal, Chaudhri
9. Fateh Chand Vij, Shri
10. Gurmej Singh, Sardar
11. Gurbax Singh, Gurdaspuri, Sardar
12. Gurcharan Singh, Sardar
13. Gurnam Singh, Sardar
14. Hardit Singh, Sardar
15. Jagir Singh, Sardar
16. Jagjit Singh, Sardar
17. Kulbir Singh, Sardar
18. Makhan Singh Tarsikka, Comrade
19. Mohan Lal Dutt, Pandit
20. Net Ram, Chaudhri
21. Sat Dev, Chaudhri
22. Shamsher Singh Josh, Comrade
23. Surjit Singh Theri, Sardar
24. Tara Singh Layalpuri, Sardar
25. Tej Singh, Sardar

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਮੈਡਮ। ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸ-ਤਾਨ ਦੀ ਇੰਨਡਸਟਰੀ ਦੀ ਹੀਣਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਦਿਲੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਕ ਸਰਕਸ ਵੇਖਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।

Deputy Speaker : The House will now take up the Bill clause by clause.

ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਕੈਪਟਨ ਰਤਨ ਸਿੰਘ) : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਮੈਡਮ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਰੀਜ਼ਲਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇਲਲੀਗਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰੀਕਾਰਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੰਜ ਕੀਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

CLAUSE 2

Deputy Speaker : Notices of 30 amendments have been received from various hon. Members to this clause. Out of these, amendments Nos. 2, 3 and 4 given notice of by Comrades Bhan Singh Bhaura, Gurbakhsh Singh and Babu Singh Master are out of order. The rest will be deemed to have been read and moved and can be discussed along with the main clause.

1. Pandit Mohan Lal Datta :

After the clause, the following proviso be *inserted* :

"Provided that the provisions of this Act shall not apply to the owners of unirrigated land in backward hilly area owning five acres or less cultivated land".

5. Comrade Jangir Singh Joga :

6. Comrade Shamsher Singh Josh :

At the end of the clause *add* the following proviso :—

"Provided that the provisions of this Act shall not apply to the owners of five acres or less cultivated land".

7. Sardar Darshan Singh :

After the clause *add* the following :—

"Landowner owning land to the extent of 5 acres shall be exempted from this cess".

8. Sardar Hari Singh :

"In line 2, *for* "1970-71" *substitute* "1966-67".

9. Thakur Mehar Singh :

At the end of the clause *add* the following :—

"Landowner owing land of 5 acres shall be exempted from this cess."

10. Babu Ajit Kumar :

11. Chaudhri Net Ram :

At the end of the clause *add* the following :—

"No recoveries of this cess will be made from the effected areas of recent Pakistani aggression and draught-affecte areas and from the other areas it will be recovered from the year 196 8 9. Owners of five acres of land will be exempted from this cess"

12. Babu Bachan Singh :

At the end of the clause *add* the following :—

"This cess should be imposed on the landowners of economic holdings only."

13. Sardar Gian Singh Rarewala :

At the end of the clause *add* the following :—

"No recoveries of this cess will be made from the war-affected districts of Amritsar, Ferozepur and Gurdaspur for one year from the date of the enforcement of the amending Act. Cultivators of five acres of cash crops will be exempted from this cess.

14. Baboo Bachan Singh :

15. Babu Ajit Kumar :

16. Chaudhri Net Ram :

In the amendments appearing at serial Nos. 10, 11 & 12 *for* "will" and "should" wherever occurring *substitute* "shall".

17. Shri Balramji Dass Tandon :

18. Shri Fateh Chand Vij :

At the end of the clause, *add* the following provisos :—

"Provided that the same will not be levied on the persons having land less than 5 acres ;

Provided further that the same will not be levied on the persons living in the border districts of Amritsar Gurdaspur and Ferozepur".

19. Comrade Gurbakhsh Singh :

20. Comrade Shamsher Singh Josh :

21. Comrade Jangir Singh Joga :

22. Comrade Babu Singh Master :

23. Comrade Bhan Singh Bhaura :

24. Sardar Gurnam Singh :

At the end of the clause *add* "the same will not be levied on landowners owing 5 acres or less than 5 acres".

25. Comrade Bhan Singh Bhaura :

26. Comrade Babu Singh Master :

27. Comrade Shamsher Singh Josh :

28. Comrade Gurbaksh Singh :

29. Comrade Jangir Singh Joga :

In amendment appearing at serial Nos. 19, 20, 21, 22, 23 and 24 *for* "will" *substitute* "shall".

30. Sardar Shamsher Singh :

At the end, add "The same shall not be recovered from the owners of up to 15 acres of land."

चौधरी देवी लाल : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडम । मैं आपकी रूलिंग चाह रहा हूँ कि यहां अब जिस मोशन पर वोटिंग हो चुकी है इस पर जब पहले यहां तकरीरें हुई तो वह इस बिल के खिलाफ थीं और सारे के सारे हाउस की सैन्स इसक खिलाफ थीं लेकिन इनमें से कईयों ने इसके हक में वोट दिये हैं हालांकि यह पहले काले बिले लगा कर इसका मातम मना रहे थे । यह तो वही बात हुई —

ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸੀ ਨਾਲ ਮਰਾਂਗੇ
ਉਹ ਹੁਣ ਛਡ ਮੈਦਾਨ ਭਜੇ ।

हम इस के लिए आप की रुलिंग चाहते है (हंसी)

ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਮੰਤਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ): ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਬਿਲੇ ਭਜ ਗਏ ਹਨ ਔਰ ਬਾਕੀ ਇਕੋ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਭਜਾ ਦੇਣਗੇ । (ਹਾਸਾ)

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿਘ ਮੇਜਰ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਡੰਡੇ ਦਾ ਡਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ

ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਕੁਟਿਆ ਨਹੀਂ । ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ । ਪਰ ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੌਜਾਂ ਨੱਠ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ (ਮੋਰਿੰਡਾ, ਐਸ. ਸੀ.) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਹ ਜੋ ਬਿਲ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਇਕ ਹੀ ਕਲਾਜ਼ ਹੈ ਮਗਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਕਲਾਜ਼ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 65-66 ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਵਿਚ 70-71 ਲਿਖ ਦਿਉ । ਇਸ ਤੇ ਇਉਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਾਸੂਮ ਜਿਹਾ ਬਿਲ ਹੈ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਡੇਂਜਰਸ ਕਲਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 80 ਫੀ ਸਦੀ ਵਸੋਂ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਦਸਿਆ ਕਿ 1963-64 ਵਿਚ 73,17,659 ਰੁ: ਦਾ ਟੈਕਸ ਲਗਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ 1964-65 ਵਿੱਚ 66,47,441 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲਗਣਾ ਸੀ। ਮਗਰ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਰਫ 40-50 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ । ਇਧਰੋਂ ਤਾਂ ਇਹ 40-50 ਲਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਆਮਦਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ 40-50 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੀਲੀਫ ਫੰਡ ਦਾ ਸਕੂਲੀ ਬਚਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰੁਪਿਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਲੜਕਿਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਸਟਰ ਮਾਸਟਰਨੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਗਲੀ ਗਲੀ ਜਾਕੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ । ਇਹ ਬੜੇ ਦੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਮਾਸਟਰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭੈੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲਾਇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । (ਵਿਘਨ) ਮੈਂ ਦਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮਾਸਟਰ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਉਥੋ ਦੀ ਹੀ ਮਾਸਟਰਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੇ ਇਹ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਲਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿ ਕੇ, ਲਕੜੀਆਂ ਕਟ ਕੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਮੰਗ ਕੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੌਦਾ ਵੇਚਕੇ ਇਹ 40-50 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ । ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ (ਵਿਘਨ) ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਹਨ । ਮਗਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮੰਬਰ ਤੋਂ ਪੁਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪੈਸਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਪਹਿਲ ਹੀ ਬਣਾ ਲਈ । ਪਿੜ ਵਸਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਗਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਮੁੰਡਾ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਖੁਸਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਗਏ । (ਹਾਸਾ) ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ......

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ।(The hon. Member is speaking in the Vidhan Sabha.)

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ । ਜੋ ਪੈਸਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ **ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ।**

Deputy Speaker : You are irrelevant.

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੈਸ ਰਾਹੀਂ 40–50 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਦਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਤਨਾ ਹੀ ਰੁਪਿਆ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਨਾ ਕਰਕੇ, ਬਚਾਕੇ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਉਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਾਰਾ "ਜੈ ਜਵਾਨ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ" ਦਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਫੋਕਾ ਹੈ । ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਾਰੀ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਉ ਪਰ ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪ ਕਿੰਨੇ ਫਾਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿੰਨੇ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਹਰ ਗੱਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਵੇ ਅਗਰ ਉਸ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਉਸ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਨਚੋੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਜਾਂ ਬਟਾਈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ......

Deputy Speaker : Please wind up.

ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ । ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਲਟੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਪਾਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੋਟ ਇਸ ਦੇ ਹਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕੋ–ਨੋਮੀ ਸ਼ੈਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਹੁਣ ਪਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । (ਘੰਟੀ) ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੰਨਾਂ ਮਿਲਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 10 ਮੀਲ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਖੰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਸਿਰਫ $\frac{1}{4}$ ਹਿੱਸਾ ਗੰਨਾ ਹੀ ਰਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਮਿਲ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਮਿਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਟ ਦਾ ਗੰਨਾ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਜਿਹੜਾ $\frac{1}{4}$ ਹਿੱਸਾ ਗੰਨਾ ਉਸ ਪਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਪੀੜ ਕੇ ਖੰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ।

ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ।

ਇਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫੋਰਥ ਫਾਈਵ-ਈਅਰ ਪਲਾਨ ਲਈ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰੁਪਿਆ ਪਾਣਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਉਗਰਾਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦਲੀਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ।

(ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਫੂਲ, ਪੈਨਲ ਆਫ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ, ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਸੰਭਾਲੀ)

ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ । ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਲਾਨ ਲਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸਾ ਦੇਵੇ । ਉਹ ਦੇ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮਰਨ ਵੀ ਤੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ । ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਨ ਤੇ ਇਜ਼ਤ ਨੂੰ ਬਚਾਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਲਏ ਇਸ ਲਈ ਅਸਾਡੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਮਰੇ ਹਨ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮਰੇ ਹਨ ਜਿੰਨੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ । ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ । ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੀ ਕਮਰਸ਼ਲ ਕਰਾਪ ਸੈਸ ਬਿਲ ਲੈ ਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਦਿਤੀ ਹੈ ।

ਕਲ ਇਥੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਭਰਾ ਕਾਲੇ ਬਿਲੇ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਪੁਛਣ ਤੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲੇ ਬਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਲਾਏ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਜਟ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਲਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀਰ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । (ਵਿਘਨ) ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਬਿਲੇ ਲਾਇਆਂ ਵੇਖਿਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਿਪੋਕਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਜਦ ਰਾਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਕਤ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਿਲੇ ਲਾਹ ਕੇ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਹਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਪੋਕਰੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਆਪ ਕਾਇਮ ਕਰ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਬੇਸ਼ਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਲਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਤਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ । ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਲਾ ਬਿਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤਕ ਕਾਇਮ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਧਰ ਬੈਠੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਪੋਕਰੇਸੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਉ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੱਲ ਇਥੇ ਕਰਨ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਰਖਣ ।ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਹਨ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਪੋਕਰੇਸੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ । (ਘੰਟੀ) ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬਸ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੋ ਮਰਦੇ ਮਜਾਹਦ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਉਠਦਾ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਇਕ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਹੈ । ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਚਾਨਣਮੁਨਾਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਲਉ ਅਤੇ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਬਿਲੇ ਲਾਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ

[ਸਰਦਾਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ]

ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਸਰਦਾਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ (ਰਾਏਪੁਰ): ਅੱਜ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਅਮੈਂਡਿੰਗ ਬਿਲ ਰਾਹੀ ਕਰਮਸ਼ਲ ਕਰਾਪ ਸੈਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਰੈਵੇਨਿਯੂ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ 1964 ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ 74 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਵਸੂਲ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡੀਮਾਂਡ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ ਕਰਾਪ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 1965 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਡੀਮਾਂਡ 66 ਲੱਖ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਡੀਮਾਂਡ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ? ਪੰਜਾਬ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਇਸ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 34 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਗਰਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਚਾਲੀ ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮੀ ਖਟਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਕਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਦਨਾਮੀ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਫਿਰ ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਿੰਬਾਲਿਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਲ ਵੈਲਯੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟੁੰਬਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੋ ਮੋਰ ਫੂਡ ਕਰੇ। ਉਪਜ ਵਧਾਣ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ਲ ਕਰਾਪ ਬੀਜਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਡਿਸਗਸਟਿਡ ਫੀਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੈਜ਼ਨਟਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਜਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਹਿਤੂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਰਾਏ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਹੀ ਇਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਵੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਇਥੇ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਕੇਵਲ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਵਸੂਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਾਲ ਖੇਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ।

ਫਿਰ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਉਗਰਾਹੁ ਣ ਲਈ ਇਹ ਕੈਲੂਕੁਲੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਆਵੇਗਾ । ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਉਗਰਾਹੁਣ ਲਈ ਅਮਲੇ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਪੱਖ ਵਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਜਾਂ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਉਗਰਾਹੁਣ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਪਏਗਾ ।

ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸਾਨੂੰ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਲਾਨ ਦੇ ਖਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ । ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਹੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਰੁਪਿਆ ਪਲਾਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਸਨ । ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਮੌਜਦਾ ਜੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸ਼ੈਟਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਲ ਦੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕਾਨੋਮੀ ਸ਼ੇਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਵਾਜਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਟ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁਆਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵਾਜਬ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ । ਇਹੋ ਵਜਾਹ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਤਨੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰੀਲੀਫ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ । 18 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਹੋਏ, ਇਥੇ ਇਤਨੀ ਵਢ ਟੁਕ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ । ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਤਨੀ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪਈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਭਰਨੀ ਪਈ ਹੋਵੇ । ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੀ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ । ਜਿੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਇਮਦਾਦ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੀਸੋਰਸਿਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ । ਅੱਜ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ । ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਦੀ । ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਗੇਰੱਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ । ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵਟਾਏ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸੇ । ਅਸੀਂ ਹਰ ਨਵੀਆਂ ਪਲਾਨਾਂ ਤੇ

6-00 p.m.

[ਸਰਦਾਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ]

ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ । ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡੀਫੈਂਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਫੈਂਸ ਤਦ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵਧ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰਮੈਂਟ ਕਰੀਏ । ਇਤਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਉਪਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਧ ਰਹੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦੁਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ । ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਨੰਗੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੀਸੋਰਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ । ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਲੈਨਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਸਿਰੇ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ । ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਫ਼ਾ 90% ਬਾਰਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗੋਂ ਲਈ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬਿਜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ । ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਈਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇਸ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਮਾਲੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਫਸਲ ਦੀ ਉਨਤੀ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇਗਾ । ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਬਾਕਾਇਦਾ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਸ ਕੇਸ ਪੁਟ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ । ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਅਜੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਰੈਵੀਨਿਊ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲ ਅਜੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਕਨਸਿਡਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ।

ਮਾਲ ਮੰਤ੍ਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੇਜਰ) : ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਕ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਸ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਊਸ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਸੀ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਸਕੋਟ ਕਰਕੇ ਡੀਮਾਰੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕਮ ਘਟ ਹੋਵੇਗੀ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ 1963–64 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਇਸ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ 2,368,258 ਏਕੜ ਸੀ, ਪਰ 1964–65 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 2,371,278 ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਜਦੋਂ 3 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧੇਗੀ ਜਾਂ ਘਟੇਗੀ ।

ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ (ਨਕੋਦਰ) : ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਕਾਲੇ ਬਿਲਿਆਂ ਵਲ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ । ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਐਧਰ ਬੈਠਣ ਵਾਲਿਆਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਲੇ ਬਿਲੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਡੀਸੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਲੇ ਬਿਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਡਸਿਪਲਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੀਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਦਾ ਬੜਾ

ਇਕ ਨੋਬਲ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ । ਡੈਮੋਕਟਰੈਕ ਵੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੀਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਾ ਦਰਸਾ ਸਕੀਏ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਡਸਿਪਲਨ ਦੀ ਕੋਈ ਅੜਚਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੁਲ੍ਹ ਸੀ..... (ਵਿਘਨ)

ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਬਿਲ ਆਏ ਹਨ, ਪਹਿਲਾ ਬਿਲ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਸੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਇਕ ਮਿਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 10–12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਬਿਲ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ । ਦੂਸਰਾ ਬਿਲ ਬਿਕਰੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮੁਤਲਿਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮਾਂ ਹੋਈਆਂ ।

(Deputy Speaker occupied the Chair.)

ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਮਰਸ਼ਲ ਕਰਾਪਸ ਸੈਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਇਸ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ ਗੰਨਾ, ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਣਾ ਹੈ, 4 ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਚਾਹੀ ਅਤੇ 2 ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਬਾਰਾਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਿਆ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਫੌਜੀਆਂ ਤੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬਹਾਦਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰ ਚਕਰ ਤੇ ਪਰਮ ਵੀਰ ਚਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਓਸੇ ਕਲਾਸ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਿਆ ਹੈ । ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ । ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰ ਚਕਰ ਤੇ ਪਰਮ ਵੀਰ ਚਕਰ ਦਿੱਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਟਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਟਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ । ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਜੇ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ । ਮੇਰਾ ਇਹ ਖ਼ਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰਚ, 1966 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੈਸ ਟੈਕਸ ਨੇ ਆਟੋਮੈਟੀਕਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ । ਇਹ ਬਿਲ ਅਗਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅਜੇ ਕੋਈ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਠੀਕ ਹੈ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ । ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਉਨਤੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦੀ । ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ । ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ । ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲਾ ਹੈ 90 ਫੀ ਸਦੀ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਕਰੋ ਜੇ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ । ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਵਸਣ ਵਾਲੀ ਜਨਤਾ ਅੱਧੀ ਗਰੀਬ ਹੈ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਹੈ । ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਜਿਸ ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿਧ ਕੇ ਗੰਨਾ, ਮਿਰਚਾਂ ਤੇ ਕਪਾਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਉਹ ਗੰਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਖੰਡ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਉਸ ਖੰਡ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬਚੇ ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਤਰਸਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕਦੇ ਨੇ । ਅਸੀਂ ਕਪਾਹ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਕਪੜਾ ਮਿਲ ਰਾਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਪਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਉਸ ਦੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਕਪੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸੈਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਉਸ ਵਿਚ ਕੈਪੇਸਿਟੀ ਨਹੀਂ । 1887 ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਲੈਂਡ ਰੈਵੇਨਿਊ ਐਕਟ ਹੈ । 1947 ਤਕ ਉਸ ਵਿਚ

[ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ]

ਕੋਈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ । ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ । ਉਸ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿਚੋਂ ਲਕੜ ਕਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਰਹੇ ਹੋ । ਸ੍ਰੀ ਅੰਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੇ ਇਕ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 'ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ।'

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ । ਓਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ । (He does not know. He was not even born at that time)

ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੰਮਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜਿਹੜੇ ਵਲਾਇਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਲਾਇਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਨਾ ਦਸੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ 'ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ' । 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਂਡ ਰੈਵਿਨਿਊ ਐਕਟ 12 ਦਫਾ ਅਮੈਂਡ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਕਦੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਚਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਐਨਾ ਸਮਝਦਾਰ ਨਹੀਂ । ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟੀ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਾ ਲਓ । ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਆਈ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਰ ਇਕ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਾ ਲਓ । ਕਿਸਾਨ ਕੁਛ ਆਸ ਰਖਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਏਥੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੀ ਦਬੀ ਹਾਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਜਾਈ ਸੀ ਉਹ ਵਧ ਗਈ । ਇਨਕਮ ਘਟ ਗਈ । ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਕਲੇਮ ਹੋਈ। ਉਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ । ਜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ 6 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਸੀ ਉਥੇ 9 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਗਹਿਣੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਗਹਿਣੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਤ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਫਿਗਰਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ? ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਏਕੜ ਦੀ ਥਾਂ 9 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ। 100 ਫੀ ਸਦੀ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਕਟ ਲਾਈ । 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇਕ ਫਿਗਰ ਕੋਟ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ । 1965 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 675 ਰੁਪਏ ਇਕ ਪੰਪਿੰਗ ਸੈਟ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਗਰਾਂਟ ਵਜੋਂ ਤੇ 600 ਰੁਪਏ ਥਰੈਸ਼ਰ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ ਮਾਲ ਮੰਤ੍ਰੀ ਏਥੇ ਬੈਠੇ ਹਨ । ਦੋਵੇਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਕਿ 1965 ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਮਾਊਂਟ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਂ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਇਕ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਸੁਕੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਪਾਣੀ ਤੇ ਲੋਕਲ ਰੇਟ ਲਗਿਆ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 11,000 ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ

11,000 ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਦਸ ਦੇਣ ਜੋ ਇਕ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਤਕ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਚਾਰ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਲਿਆ ਹੈ ।

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੇਜਰ) : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਮੈਡਮ । ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ?

ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੇਰੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਦਿਆਂ 14 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਦੋ-ਤਿੰਨ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰੋ । (He has been speaking for the last 14 Minutes. He should wind up within two Minutes).

ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਸਾਢੇ ਸਤ ਫੀ ਸਦੀ ਇੰਟਰੈਸਟ ਸ਼ਰਾਹ ਸੂਦ ਹੈ । ਅਗਰ ਓਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਫੀ ਸਦੀ ਸੂਦ ਹੈ ।

चौधरी देवी लाल : जो यह सरकार से घर पर पूछ सकते हैं तो यहां क्यों तकरीर करते हैं । घर जा कर पूछ लें ।

ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ? ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਦਫਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 4,000 ਰੁਪਿਆ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਖਰਚ ਘਟ ਜਾਏਗਾ । ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 4 ਰੁਪਏ ਫੀ ਏਕੜ ਸੈਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਰਟੇਲਾਈਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤ੍ਰੀ ਜੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਦੋ ਤੇ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮਿਡਲਮੈਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨੋ-ਪਰਾਫਿਟ, ਨੋ-ਲਾਸ ਬੇਸਿਜ਼ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦਿੰਦੀ । ਦੂਸਰੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ । ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਟਰੈਕਟਰ ਦ ਵੱਧ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਤੇ । ਹੁਣ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 5,000 ਰੁਪਿਆ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ । ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 25,000 ਜਾਂ 30,000 ਰੁਪਏ ਤਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਿਡਲਮੈਨ ਨੂੰ ਵਿਚੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਏਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਡੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ । ਮਿਡਲ ਮੈਨ ਨੇ 28 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਡੀ ਖਰੀਦੀ ਔਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 40 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਲਈ ਹੈ । ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਡੀ ਦੀ ਸਟੇਟ ਟਰੇਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਦੋਂ ਪੈਡੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਡਲਮੈਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਇਕ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ । (He should resume his seat after a minute).

ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ : ਠੀਕ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਪੈਸ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਵਾਵੇਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ

[ਚੌਧਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ]

ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਝਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖਰਚਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ ! ਬਲਕਿ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਏਥੇ ਤਾਂ ਉਲਟ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਇੱਕਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਗੋਂ ਬਾਹਿਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੋਵੇਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਹਨ । ਫਰ ਕੋਈ ਵਜਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਨਾ ਮਿਲੇ । ਲੇਕਿਨ ਨੁਕਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਪਰਾਪਰਲੀ ਪੁਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਲਾਂ ਫਲਾਂ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹਨ । ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਲੜੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਜਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਨਸੈਸ਼ਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ।

ਸਰਦਾਰ ਹਰਦਿਤ ਸਿੰਘ (ਪੱਕਾ ਕਲਾਂ, ਐਸ. ਸੀ.) : ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ । ਇਹ ਇਕ ਕਾਲਾ ਬਿਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੱਖਪਤੀਆਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਏ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 18 ਸਾਲਾਂ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੀਵੇਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਉਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਮੈਂ ਖੁਦ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹਡ ਬੀਤੀ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ । ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ ਵੇਲਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪੋਹ ਮਾਘ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਭੁਖਾ ਤਿਆਇਆ ਰਹਿ ਕੇ ਇਖ ਦੀ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਰਚਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਬੀਜਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਹੀ ਅਸਰ ਕਰੇਗਾ । ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕਲਾਂ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਰਜਬਾਹਾ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਕਨੀਉਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਲ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ । ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵੇਲਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਬਸ ਏਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ।

ਸਰਦਾਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲਉਸਮਾਨ (ਬਿਆਸ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਏਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ

ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਕਾਫੀ ਤਕੜੀ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਖੁਲ੍ਹੇ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲੱਗੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਵਲ ਤਵਜੋਹ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ । ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਔਰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਿਆ ਦਾ ਅਨਾਜ ਬਾਹਿਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਚੰਦ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਨਾਜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਚ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਏਥੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਲਫਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਖਦੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇ ਠਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਈ ਕਈ ਪਿੰਡ ਸਨ। ਏਥੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਏਕੜ ਦੀ ਕਟ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ । ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ ਥੋੜੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਾਗਾਂ ਹੇਠ ਔਰ ਕੁਝ ਮੈਕਨਾਈਜ਼ਡ ਫਾਰਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬਚਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਏਸ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ । ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੰਜ ਏਕੜ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘਟ ਹੈ ਔਰ ਅਗਾਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਜਦੋਂ ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਚਾਰ ਭਰਾ ਸਨ ਜਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਰੂ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰਖਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਦੋ ਕਨਾਲ ਹਵੇਲੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਰਖਵਾ ਲਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਦਮੀ ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਛਣ ਲਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਚਾਹੀ ਰਕਬਾ ਕਿਥੇ ਹੈ । ਉਹ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਕਿ ਚਾਹੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਏਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ । ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਥੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਏਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੋਈ ਹਦ ਮੁਕੱਰਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਘਟ ਹੈ, ਉਥੇ ਵੱਡੇ ਪੁਤਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਧੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਕੌਣ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਪਾਹੀ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਜਰਨੈਲ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਰਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਕੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਸਾਡੇ ਵਲ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਨਾ ਵੇਖ ਸਕੇ ।

ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਧਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇ । ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੈਟਰੀਅਲ ਕਢਿਆ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਹੀ ਬਿਲ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ । ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਸਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ

[ਸਰਦਾਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲ ਉਸਮਾਨ]

ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰ ਸਕੇ । ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ , ਆਬਿਆਨੇ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਆਲਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ (ਲੁਧਿਆਣਾ–ਉੱਤਰ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਕ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਉਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ–

Baboo Bachan Singh : (speaking)

"This cess should be imposed on the landowners of economic holdings only."

ਮੇਰੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਰਖਵਾਲੀ ਹੈ । ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 1948 ਵਿੱਚ ਇਕ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 1955 ਵਿੱਚ ਅਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਿਕ ਪੈਟਰਨ ਆਫ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਸਲਿਜ਼ਮ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ? ਕੀ ਇਥੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ? ਕੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਵਰਗੀ ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕਾਨੋਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ । ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮੀਰ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਉਪਰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਵਧੀ ਹੈ । ਮਾਲ ਮੰਤ੍ਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ 1963 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਹੁਣ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ।(ਵਿਘਨ)

ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤਦ ਤਕ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜਾਂਗਾ । ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਤਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਤਦ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ । ਸਾਡਾ ਮੰਤਵ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਦਾ ਕਤਰਾ ਕਤਰਾ ਪੀਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਇਨਸਟੀਚਿਊਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਫੇਦ ਹਾਥੀ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ $1\frac{1}{2}$ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਲਾਵਾ $6\frac{1}{2}$

ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਐਨੀਸ਼ਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਿਆ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਸ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਫੇਦ ਹਾਥੀ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਕਿਉਂ ਮੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ? ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਕੁਲੈਕਟ ਕਰਕੇ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਵਿਲ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਵਿੱਚ ਭੀ ਸਫੇਦ ਹਾਥੀ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਫਿਨਾਂਸ਼ਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਜ਼ ਅਤੇ 10, 12 ਕਮਿਸ਼ਨਰਜ਼ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੀਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਕਤਰਾ ਨਿਚੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਵਾਕਈ ਸਰਕਾਰ ਇਥੇ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਰਡ ਆਫਲਿਵਿੰਗ ਲਈ ਕੋਈ ਡੈਫੀਨੀਸ਼ਨ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਦਵਾਈ ਦਾ ਅਤੇ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਟੈਪਸ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਤੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਅਸੂਲ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਉਸ ਦੀ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ 4000 ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ । ਮੈਂਬਰਜ਼ 300 ਰੁਪਿਆ ਕੰਪੈਨਸੇਟਰੀ ਅਲਾਉਂਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ । ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਕਮ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਸੂਲ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਸਰਦਾਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੈਵਨਿਊ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਖ ਪਤੀ ਜਾਂ ਕਰੋੜ ਪਤੀ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਏਕੜ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇੰਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਡਤ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਆਲ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਬਪਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ । ਉਥੇ ਕਰਾਪਸ ਦੀ ਉਪਜ ਪਰਮਾਤਮਾਂ ਦੇ ਬਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਥੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਬਾਰਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਫਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਬਾਰਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਫਸਲ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਲ ਮੰਤ੍ਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਮੀਰ ਸਨ ਜਾਂ ਕੀ ਹੁਣ ਉਹ ਪਾਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ । ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਲਗ ਭਗ 40, 50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਰੈਫਿਊਜੀ ਬਣ ਕੇ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਉਹ ਖੁਦ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ।

ਤੁਸੀਂ ਦਸੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਇਕ ਰਜ਼ਾਈ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਕ ਇਕ ਕਪੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਖੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ

[ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ]

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 50,000 ਆਦਮੀ ਉਜੜੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁੜਗਾਵਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਬਰਾਨੀ ਹੈ ਉਥੇ ਭਾਵੇਂ ਨੂਹ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਫੀਰੋਜ਼ਪੁਰ ਝਿਰਕਾ, ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਕਾਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਰੋਹਤਕ ਵਿਚ ਝਜਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਅਤੇ ਭਿਵਾਨੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਭੇਂਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤਸਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਉਜੜੇ ਹੋਏ ਆਦਮੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੌਰਮਿੰਟ ਲੰਮੀ ਸੋਚ ਸੋਚੇ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ। ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦਸਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਲੋਂ ਇਹ ਫਿਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 4,000,000 ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 3,500,000 ਮਾਲਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ 10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘਟ, ਔਸਤਨ 2 ਏਕੜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਦਸੋ ਕਿ ਦੋ ਏਕੜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ......ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੱਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਕੰਮ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਾਏ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੇ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਸੀ ਮੇਜਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਲਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਮੁਲਕ ਹਨ, ਉਥੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਕਿ ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਧੇਅ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਉਪਰ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਉਪਰ ਨਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਤਰਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ economic ਰੀਪੋਰਟਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਆਮਦਨ 4 ਰੁਪਏ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਰੁਪਿਆ ਔਸਤਨ ਆਮਦਨ ਹੈ। ਪਜਾਬ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ 3:1 ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ। ਕਾਲਿਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ, ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਉ, ਨਾਲ ਐਨਾ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਦਿਉ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਾਹਿਸ਼ ਜ਼ਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਦਿਉ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਉ ਅਤੇ ਨਾਲ 28,700 ਰੁਪਿਆ ਦਿਉ ਤਾਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ? ਕੀ ਇਹ ਸੋਤੀਲੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਹਸਪਤਾਲ

ਹਨ । ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਰੇਸ਼ੋ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਰੇਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ......

Deputy Speaker: Please wind up.

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਜ਼ਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਝਲਕੀ ਵੇਖੋ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਸਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਝਲਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੋ ਕਨਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਨਾ ਬੀਜ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਉਪਰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਮਾਇਦਾਰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਨਾ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ, ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ? ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ...... (*Interruption.*)

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੇਜਰ) : ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹਨ.....

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਹਾਂ, ਸਚਾਈ ਦਾ ਠੇਕਾ ਤੁਸਾਂ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਅਸੂਲ ਮੰਨਿਆ ਹੈ । ਉਹ ਅਸੂਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਰੈਂਟਲ ਵੈਲਯੂ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 300 ਰੁਪਿਆ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਮਸਲਨ ਸ਼ਿਮਲੇ ਵਿੱਚ 400 ਰੁਪਿਆ ਸਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ exempt ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਇਆ ਇਸੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰੈਂਟਲ ਵੈਲਯੂ 300 ਰੁਪਿਆ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 400 ਰੁਪਿਆ ਸਾਲ ਹੈ ਉਥੇ ਮਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ? ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਸੂਲ ਮੰਨ ਲੈਣ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਗਲ ਪੁਛ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ । ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਇਆ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਜ਼ੈਂਪਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ economic ਹੋਲਡਿੰਗ ਵਿਚੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਚੰਗੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਜ਼ੈਂਪਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਝੂਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

PERSONAL EXPLANATION BY THE REVENUE MINISTER

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੇਜਰ): ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਬਿਲ ਦੇ ਹਕ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿ ਬੈਠਾ ਹਾਂ । ਬਾਬੂ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ........
(ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਵਿਘਨ) ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਟੈਂਪਰ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ......ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲੜਕੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ? ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਦਾ ਠੇਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ । ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ , ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੇ

[ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ]

ਕਰਤਵਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਿਆਲਾਤ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । 1954 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਇਕ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਤਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਚਾਹੇ ਰੂਰਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਰਬਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬੈਂਕਸ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜੀਊਲਰੀ ਹੈ—ਸਾਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਤਾਲੀਆਂ)

ਇਕ ਆਵਾਜ਼—ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ?

(ਵਿਘਨ)

ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ (ਸਰਦਾਰਾ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ): ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ।

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੇਜਰ): ਇਹ ਮੇਰਾ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਐਸਪਰਸ਼ਨ ਕਾਸਟ ਕਰਨੇ ਹਨ ?

ਮੈਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਇਹ ਫਤਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਬਾਬੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ—ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਖਲਾਕ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਿੱਲੀਭੀਤ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ—ਮੈਂ ਤਾਂ ਈਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਖੁਲੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਂ ਔਰ 21,000 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾਮੀਨੇਟਿਡ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ।

PERSONAL EXPLANATION BY BABOO BACHAN SINGH

ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ, ਮੈਡਮ। ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੇਜਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਝੂਠਾ ਔਰ ਗ਼ਲਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਲੀਭੀਤ ਭਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬਰਖਿਲਾਫ਼ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਪੈਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਹੈ ।

ਸਰਦਾਰ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਦਰਦ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਫਤ ਬਾਬੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਿੱਲੀਭੀਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਗਏ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਿਥੇ ਗਏ ਸਨ ?

THE PUNJAB COMMERCIAL CROPS CESS (AMENDMENT) BILL, 1965 (*Resumption of Discussion*)

ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ (ਸਮਾਨਾ, ਐਸ. ਸੀ.): ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਪਾਹ, ਮਿਰਚਾਂ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਉੱਤੇ ਸੈਸ ਲਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੀਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਬਹਿਸ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼

ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਜਿਨਸ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਮਾਕੂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਿਆ । ਤਮਾਕੂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਥੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਬਹੁਤ ਘਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਮੇਰੀ ਕਾਂਸਟੀਚੁਅਂਸੀ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਨੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਮਿਰਚਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਸਾਰੇ ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਥੇ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਰਕਬੇ ਵਿਚ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਮਿਰਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਰਕਬੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਗਣਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਉਸੇ ਰਕਬੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਠੇ ਹੋਏ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਬਾਰਸ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਗਿਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਥੇ ਚਿਲੀਜ਼ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਦ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ । ਪਰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ? ਰੁਪਿਆ ਆਉਣਾ ਹੈ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿਚੋਂ ਔਰ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਦਸਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਲਖ ਤਜਰਬਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ।

ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਡੀਫੈਂਸ ਫੰਡ ਲਈ ਦੋ ਰੁਪਏ ਫੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਇਸ ਸੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਤਨਾ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਰੁਪਿਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਚਾਲੀ ਕੁ ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੇ ਪੈਣਾ ਹੈ । ਭਾਵੇਂ ਨਰਾਜ਼ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰ ਮੈਂ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈ ਲਾਕੇ ਰਖਿਆ ਜੇ ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ 36 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਠਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿਵੀ ਪਰਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ?

Revenue Minister : I have never supported the grant of Privy Purses in my life.

ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਨਾਮ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ ।

लोक कार्य मन्त्री (चौधरी रणबीर सिंह) : प्रिवी पर्स तो गोवर्नमैंट आफ इंडिया का सबजैक्ट है।

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿਘ ਮਾਸਟਰ : On a point of information. ਮੈਂ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਤਨਾ ਡਿਫੈਂਸ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ?

ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਫੰਡ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਇਟਲੀ ਦਾ ਐਮਬੈਸੇਡਰ ਲਗਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉ । ਲਗਾਉ ਭਾਈ ! ਲਗਾਉਣੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ । 21 ਜਾਂ 22 ਤਰੀਖ, ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਤੁਸਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ । ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਦ ਦੇ ਟੈਕਸ ਹੀ ਲਗਾਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ । ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ "ਖਾ ਲੈ ਸ਼ਾਮੋ ਨਾਸ਼ਪਾਤੀਆਂ, ਨਿੱਤ ਨਹੀਂ ਬਜ਼ਾਰੀਂ

[ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ]

ਆਉਣਾ", ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਜ ਲਉ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਣੇ ਜੇ ਲਗਾ ਲਉ। ਅਰਜ਼ ਸਿਰਫ ਇਤਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਸਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਇਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲਗਣੇ। ਕਿਤਨੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ 8 ਦਿਨ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਬਿਲ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ? ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਜਿਤਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਵਿਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਦੇਣਾ ਕਿਸ ਨੇ ਹੈ ? ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਟੈਕਸ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, 80 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਪਲਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਹੀ ਕੇਸ ਪੁਟ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਕ ਵੇਰ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਖਰੜ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਉਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੋਬਰ ਪਥਦੇ ਹੋ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਉ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਖਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਬਹੁਤ ਬੁਢਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਗੋਬਰ ਪਥੀਏ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਦਿਉ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਫਰਟੇਲਾਈਜ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇ-ਮਾਲ ਕਰੋ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਤਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ, ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਾ। 18 ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਤੀ ਔਰ ਦੇਹਾਤ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ? ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਕਰੇ—ਚਾਹੇ ਟਿਊਬਵੈਲਜ਼ ਲਗਾਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੀਹ ਏਕੜ ਦੀ ਸੀਲਿੰਗ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਹੋ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਰੂਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਇਕ ਪੱਕਾ ਖ਼ਿਆਲ ਬਣਾਉ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਅਪਣਾਉ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਝਗੜਾ ਮੁਕੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਉੱਤੇ ਚਲੀਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹੈ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਉ। ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ।

ਫੇਰ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਜਿਨਸ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾ ਕੀ ਹੈ ? ਯੂ. ਪੀ. ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾ 100 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 50 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ। ਯੂ. ਪੀ. ਵਿੱਚ ਧਾਨ 60 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ

ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਭਾ 35 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਲੇ ਯੂ. ਪੀ. ਵਿੱਚ 70 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿਕਦੇ ਹਨ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾ 50 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਮਕਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 34 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ ਔਰ ਯੂ. ਪੀ. ਵਿੱਚ 60 ਰਪਏ ਕੁਇੰਟਲ । ਕੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਭਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਨਿਸਟਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਭਾ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਫੇਰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਲਉ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਘਟ ਹਨ ਔਰ ਭਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਉਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ । ਇਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰਾਬ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਲੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉੜੀਸਾ ਔਰ ਮਦਰਾਸ ਭੇਜੇ ਹਨ।

ਪਰ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਿਟ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਚਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਤਾਂ 54 ਰੁਪਏ ਫ਼ੀ ਕਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਕੋਲੋਂ 49 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬੀਬੀ ਜੀ, ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮਾ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਰੋਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਭੱਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮਾ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਢ ਲਿਆ ਹੈ ?

6.00 p.m.

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਨੀ ਦੇਰ ਹੋਰ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ? (How, much more time would the hon. Member take?

ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ: ਬਸ ਜੀ, ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗਾ।

ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਕ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਿਰਫ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ, ਬੀਬੀ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਸ਼ਕ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਬਣ ਜਾਉ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਇਜ਼ਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਲਗਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ੋਨਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਉ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਉ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ ਅਸੀਂ ਉਥੇ ਆਪਣਾ ਅਨਾਜ ਭੇਜ ਸਕੀਏ। ਜੇ ਇਹ ਕਰ ਦਿਉ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ਕ ਇਸ ਸੈਸ ਨੂੰ ਲਗਾ ਲਉ।

ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ (ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਬਿਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਟ੍ਰਾਂਸ-ਪੋਰਟਰਜ਼ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਔਰ ਦੂਜਾ ਇਹ ਬਿਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰਿਸਟਪ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਟੈਕਸ ਬਿਲ ਰੀਐਕਸ਼ਨਰੀ ਔਰ ਅਨ-ਸੋਸ਼ਲਿਸ਼ਟਿਕ ਹਨ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਡਡ ਇਹ ਹੁੰਦਾਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਬਣਾਨ ਦਾ ਏਮ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਏਮ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ। ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਮਨਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ

[ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ]

ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਟੈਕਸ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਸਮਾਜ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਭਰ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਹਨ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਇਕੜ ਦੁਕੱੜ ਟਰਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਣ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਇਲਿਮੀਨੇਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਟੈਕਸ ਪਰੋ-ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਸਿਮੀਲਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੈਸ ਬਿਲ ਹੁਣ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤੇ ਹੁਣ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰੋ-ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡ ਰੈਵੇਨੀਊ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਅਕਬਰ ਦੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਬੋਸੀਦਾ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਕ ਪਰੋਗਰੈਸਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੇ ਲਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਥੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪਰਸੋਂ ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਠੀਕ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡ ਰੈਵੇਨੀਊ ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਤਨੀ ਇਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਨੈਟ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਸਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਲੈਂਡ ਰੈਵੇਨੀਊ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਲ ਰੇਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚਾਰਜ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਅਲਾਵਾ ਵਾਟਰ ਚਾਰਜ, ਵਾਟਰ ਰੇਟ ਔਰ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਲੈਵੀ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਹਨ, ਉਹ 30 ਪਰਸੈਂਟ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਟੈਕਸ ਯਾਨੀ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਹਨ ਉਹ ਸਭ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਦੀ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਡਰ ਡੈਟ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 95 ਫੀਸਦੀ ਪੈਜ਼ੇਂਟਰੀ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੰਡਰ ਡੈਟ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੀ 5 ਪਰਸੈਂਟ ਐਸੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰ ਡੈਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰਖ ਕੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਟੈਕਸ ਅਸੀਂ ਲਗਾਣ ਲਗੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ਲ ਹੈ ਉਸ ਵਲ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦਸਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਰੁਪਏ ਤਕ ਫੀ ਏਕੜ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਟੈਕਸ ਹਨ ਯਾਨੀ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਆਦਿ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਮਿਸਚੀਵੀਅਸ ਮੈਥਡ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਿਛੇ ਰਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੀ ਕਾਸਟ ਤੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਨਲ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਸਬਸੀਡਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸਬਸੀਡਾਈਜ਼ ਕਰੇ ਔਰ ਜ਼ੋਨਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ੋਨਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਸਟ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ

ਰੇਟਸ ਤੇ ਅਨਾਜ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਵਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਚਨੇ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਨਾਜ ਸਸਤੇ ਭਾਵਾਂ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੋਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਲ ਕਰਾਪਸ ਥੱਲੇ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਵਧਿਆ ਹੈ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 1963- 64 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਏਰੀਆ 2,368 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਸੀ ਤਾਂ 1964-65 ਵਿੱਚ ਇਹ 2,378 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਵਧ ਗਿਆ । ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਏਰੀਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਰੀਕਲੇਮ ਕਰਕੇ ਕਾਬਲੇ ਕਾਸ਼ਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨੌ ਤੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਵਧੇਰੀਆਂ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਾਪਸ ਹੇਠ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਟੋਟਲ ਰਕਬਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਤਾਂ in relation to total cultivated land ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।.ਮੇਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਘਟੀ ਹੈ ਵਧੀ ਨਹੀਂ ।

(*At this stage Sardar Gurnam Singh, a member of the Panel of Chairmen, occupied the Chair.*)

ਫਿਰ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਬ, ਇਸ ਬਿਲ ਬਾਰੇ ਟਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਨੇ 'ਸਟਿੰਟਿਡ ਏਡ' ਦੇ ਹੈਡਿੰਗ ਥੱਲੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੁਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ—

> "But the inconclusive week end discussions with the Planning Commission do not reveal the fullest awareness by the Delhi authorities of the colossal task facing the brave people of this border area.........."

ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਜ਼ਦ ਬਾਰੇ ਬੜ ਢੰਗ ਚੰਗੇ ਨਾਲ ਦਸਿਆ ਹੈ—

> "To impose more taxes on our people now would be grossly unfair and would add insult to injury; ....".

ਟਰਿਬੀਊਨ ਅਖਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੈਪਰੀਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ it will add insult to injury ਅਗਰ, ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਗਏ । ਸਿਮੀਲਰਲੀ ਉਸ ਨੇ ਸੈਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੂੰ ਵਾਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਜ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਫੇਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਟਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਨਲ ਸਿਸਟਮ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਨਜ਼ੀਊਮਰ

[ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ]

ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਖਰਚ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ. ਏ. ਐਸ. ਅਤੇ ਆਈ. ਸੀ. ਐਸ. ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੈਕਰੇਟਰੀਏਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਚ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਬਜਟ 127 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਜੈਨਰਲ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਤੇ 9 ਕਰੋੜ ਪੁਲਿਸ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਸੂਬੇ ਜਿੰਨੀ ਟਾਪ ਹੈਵੀ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ । ਅਸੀਂ ਇਕ ਰੀਫਾਰਮਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਕ ਸਜੈਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੀ ਸਟਰੈਂਗਥ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

(Deputy Speaker in the Chair.)

ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕੌਨੋਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਰਹੇ । ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ (ਘੰਟੀ) ਇਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਡੀਫੈਂਸ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਜੋ ਰਕਮਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਮਕਸਦ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਰੀਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ । (ਘੰਟੀ)

ਬਸ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਲਾਉਂਜ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੌਧਰੀ ਲਖੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀਂ ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਦੇਰ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਕਟਸ ਅਤੇ ਫਿਗਰਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਐਕਸਪਰਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਣ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕੇ । Thank you.

ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਗੋਆਨੀ (ਜ਼ੀਰਾ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਆਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਜੋ ਬਿਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਪ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਇਹੀ ਜਿਤਣਗੇ ਪਰ ਜੋ ਇਖਲਾਕੀ ਜਿਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਜੋ ਤਕਰੀਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਕ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਵਿਪ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ । ਸੋ ਇਖਲਾਕੀ ਜਿਤ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਚਲਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਕਿਸਾਨਾਂ

ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਸਬੰਧ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਬਿਲ ਤੇ ਵਿਪ ਦਾ ਡੰਡਾ ਕਿਉਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵੋਟ ਕਰਨ ਦਿਉ । ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ । ਅੱਗੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੇ 13 ਕਿਸਮ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਮਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਉਸ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਸੈਸ ਲਾ ਕੇ ਗ਼ਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਮਗਰ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਲ ਲੈ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਰ ਲਾਣਾ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵੀ ਬਦਲ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਮਗਰ ਇਨ੍ਹ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਛੁਰਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਮਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮਾਊ ਪੁਤ ਹੈ, ਵਿਹਲੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਜੋ ਕਮਾਈ ਕਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁਖਿਆ ਮਾਰੋ ਅਤੇ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਹਲੜ ਹੈ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਧ ਮਲਾਈ ਤੇ ਪਾਲੋ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ । ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੈ । ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਇਦੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈ । ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਘਟ ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਵੱਧ ਹੈ, ਕਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਸੂਦ ਦੀ ਸ਼ਰਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਘਟ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ $7\frac{1}{2}$ ਫੀ ਸਦੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ 3 ਫੀ ਸਦੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਲ ਦੇਖੋ । ਇਥੇ ਕਣਕ 60–65 ਰੁ: ਕੁਇੰਟਲ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਸੋ ਸਵਾ ਸੌ ਰੁਪਏ ਭਾ ਹੈ । ਇਹ ਵਿੱਚਦਾ ਮਨਾਫਾ ਕੌਣ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ? ਜੇ ਇਹ ਮਨਾਫਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਲਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਉਧੇੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ । ਫਿਰ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਹਨ, ਸਿਨਮੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ ? ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਰ ਆਮਦਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਦੁਸ਼ਮਨ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਆਰਮਾਮੈਂਟਸ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ । ਇਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਚੌੜੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਅਤੇ ਜਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੋਂ । ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਸੀਲ ਦੀ ਇਵੈਕਈ ਪਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਠੇਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਨਾ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਿਹਲੀ ਪਈ ਹੈ । ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨਾਜ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਤੇ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਪਰ ਵਿਪ ਡੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨਜ਼ ਦਬਾਣਾ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ । ਫਿਰ ਗੰਦੀਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤਾਂ ਡੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ । ਉਦੋਂ ਵਿਪ ਕਿਥੇ ਸੀ ਜਦੋਂ 12 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਾਈਡ ਬਦਲੀ ਸੀ ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਕਿਥੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ? ਅੱਜ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੁਝ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ । ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਨਾਰਾਇਨ ਸਿੰਘ ਹੀ ਬਹਾਦਰ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ..(ਵਿਘਨ) ਇਹ ਬਿਲ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਆਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ।

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ : On a point of order, (*interruption*) ਚਾਹ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ..... (ਵਿਘਨ) ਤੁਸੀਂ ਪਿਲਾਣੀ ਹੈ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਨਿਸਚਿੰਤ ਹੋਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ । (Keep sitting patiently.)

ਟਰਾਂਸਪਰਟ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੰਤਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਇਕ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਕਤ ਦਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦ ਤਕ ਬੈਠਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਈਏ? ਜੇਕਰ ਬਹਿਸ ਨੇ ਅਜੇ ਹੋਰ ਚਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਤ ਤਕ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਈਏ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਤਕ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝੋ ਮੈਂ ਬੈਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ । (It depends on Sense of the House. I can sit as long as you all think proper.)

ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ (ਧੂਰੀ-ਐਸ. ਸੀ.) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਅਮੈਂਡਿੰਗ ਬਿਲ ਤੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ । ਇਸ ਬਿਲ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤਰਮੀਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤਕ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤਕ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਇੰਚ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਜ ਏਕੜ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲਗਾਣ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਰਮੀਮ ਤੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ । ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਮੀਮ ਨੰਬਰ 5 ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । (ਵਿਘਨ) (I have permitted the hon. Member to speak because I had thought that he had been asked by his group to speak. He has now started to speak on his amendment No. 5 which has already been declared out of order by me.

ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ : ਮੈਂ ਤਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਤਰਮੀਮ ਨੰਬਰ 23 ਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਲਗਾ ਸਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਗੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਵਿਪ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ (ਵਿਘਨ) ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਮਨਾਂਦੇ ਰਹੇ । ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਸੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਲਗੇ ਰਹੇ । (ਵਿਘਨ) ਅਸਾਡੇ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ । (ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਵਲੋਂ......ਸ਼ੇਮ ਸ਼ੇਮ) ਰਾਤ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਵਜੇ ਤਕ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਲਗੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦੇਣ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਰਮੀਮ ਤੇ ਬੋਲੋ, ਕਾਮਰੇਡ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛਡੋ ।

(He should speak on his amendment and need not refer to the Chief Minister).

ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ : ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤਕ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਾਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮੰਨਦੇ ।

ਮੈਂ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਿਕ ਪੈਟਰਨ ਆਫ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵੀ ਇਜ਼ਤ ਅਤੇ ਕਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਪਾਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਏਕੜ ਤਕ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤਕ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ । ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ।

ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕੀਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰੁਪਿਆ ਬੇਇਨਤਾਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਰੁਪਿਆ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿੰਨੀ ਰਕਮ 40 ਲੱਖ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਲਗੇ ਹੋ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਸਣ ਲਗੇ ਹੋ । ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਅਜਿਹੇ ਸਜਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਰੁਪਿਆ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੋ ਇਕਠਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਬੋਧ ਜੀ ਨੇ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਇਕਠਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਿਆ ਪ੍ਰਬੋਧ ਜੀ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਰੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਬਾਉ ਪਾ ਕੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੁਪਿਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ । ਫਿਰ ਕਈ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡਲ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਪਿਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ । ਇਸ ਲਈ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 45–45 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਰਖ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਸੋਰਸ ਨੂੰ ਟੈਪ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭਾਰ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ।

ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਲ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ । ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਬਿਲ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਣ ਲਗੇ ਹੋ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਪ ਦੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਾ ਲਉਗੇ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ

[ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਨ ਸਿਘ ਭੌਰਾ]

ਤੇ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਨ 1967 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ । ਅਤੇ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਵਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਕ ਕਾਰ ਲਈ। ਕਾਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲ ਬਾਹਰ ਲੈ ਚਲ । ਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਦੋ ਮੀਲ ਜਾ ਕੇ ਖੜੋ ਗਈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰ ਦੇ ਹੇਠ ਉਪਰ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀ , ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ। ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਸੀ ਮਾਲਕ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇਥੇ ਖੜੋ ਕਿਉਂ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਸੀ। ਜਦ ਕੋਈ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਮਗਰੋਂ ਮੂਹਰਲਾ ਫੱਟਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੰਜਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਤੋਂ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੰਜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦੋ ਮੀਲ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ ? ਤਾਂ ਉਸ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਮੀਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। (ਹਾਸਾ) ਠੀਕ ਇਹ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਕਾਰ ਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਕ ਚਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? (ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸੰਸਾ) ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਕ ਵਕਾਰ ਕਾਇਮ ਰਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਨ 47 ਮਾਰਕਾ ਜਾਂ ਸੰਨ 57 ਮਾਰਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇਹ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦੇ । (ਵਿਘਨ)

ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਸਾਧਨ ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਨੇਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾਂ ਰੁਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਊ ਇਥੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਦੂਜਾ ਸਾਧਨ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਸਟੇਟ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦਾ ਹੈ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆ ਅੱਜ ਕਲ ਮਿਡਲਮੈਨ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਟੇਟ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰੁਪਿਆ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ।

ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਪਾਣੀ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੇਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਨਾਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਣ ਵਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਲ ਲਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ੂਨ ਚੂਸਿਆ ਜਾਵੇ । ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਇਹ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਬੈਠਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ 5 ਏਕੜ ਵਾਲੀ ਤਰਮੀਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਦੇਈਏ ।

प्रिंसीपल रला राम (मुकेरियां) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेजर साहिब ने बड़े मुदलल तरीका से इस बिल के संबंध में अपने पक्ष को पेश करने की कोशिश की है। मैं समझता हूँ कि इस के बाद और ज्यादा कुछ कहने की किसी को भी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपके ज़रिये से दो मिन्ट के लिय चंद एक बातें मेजर साहिब के ध्यान में ला देनी ज़रूरी समझता हूँ। सब से पहली बात तो यह है कि यह टैक्स कोई नया टैक्स नहीं है। अब तो महज़ इसके मुतालिक टाईम एक्सटैंड करने का सवाल है। इस छोटी सी बात पर इतना वावेला करना मुनासिब मालूम नहीं होता।

मैं तो यह कहूँगा कि जो भी टैक्स लगाया जाये वह छोटे ज़िमीदार की इमदाद पर खर्च होना चाहिए। 5 एकड़ जमीन के जो मालिक हैं वह इस काबिल नहीं कि कैमीकल खाद भी अपने खेतों में इस्तेमाल कर सकें। सरकार को ऐसे लोगों की इमदाद के लिय सबसिडी देनी चाहिए। अगर इस बात के लिये कुछ खर्च भी हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि उतनी ही पैदावार बढ़ती है मुल्क की तरक्की में अजाफा होता है और लोगों की डिवैलपमैंट होती है। टैक्स लगाना कोई बुरा नहीं मगर मैं इतना ज़रूर कहुँगा कि यह जो रुपया इकट्ठा हो यह छोटे ज़िमीदारों की इमदाद पर खर्च होना चाहिए ताकि वह देश में ज्यादा से ज्यादा अनाज पैदा कर सकें। यह सारा रुपया अगर छोटे जिमीदारों को सबसिडी की शक्ल में दे दिया जाता है तो यह एक निहायत ही अच्छी बात होगी।

दूसरी बात जो मैंने अर्ज़ करनी है, वह यह कि पहाड़ी इलाके में लोगों के पास थोड़ी थोड़ी ज़मीन के टुकड़े होतें हैं. उन लोगों के साथ यह बहुत बेइन्साफी होगी कि उनको भी इस टैक्स की ज़द में ले लिया जाये। मेरी इस सिलसिला में मेजर साहिब से दरखास्त है कि पहाड़ी इलाके में कम अज़ कम 4 कनाल की self consumption के लिये छूट होनी चाहिए। अगर आप ऐसा ही बिल पास कर देते हैं तो इसका पहाड़ी इलाके के लोगों पर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। मगर जिस ढंग से मेजर साहिब ने बिल पेश किया है. इसके लिये मैं आपको बधाई देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੰਤਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ) : ਬੀਬੀ ਜੀ, ਏਥੋਂ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੱਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਣੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਮੌਲਵੀ ਅਤੇ ਇਕ ਜੱਟ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ । ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਦਫਾ ਇਕ ਜੱਟ ਅਤੇ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਉਠਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਗਿਆ । ਇਕ ਪਾਸੇ ਜੱਟ ਬੈਠ ਗਿਆ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੌਲਵੀ । ਦੋਨੋ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਠਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ । ਮੌਲਵੀ ਜੱਟ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਾ ਓਏ ਮੁੰਡਿਆ। (ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ ਉਹਦਾ ਲੜਕਾ ਖੜਾ ਸੀ) ਘਰ ਤੋਂ ਕਲ੍ਹ ਦਾ ਖਾਣਾ

[ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੰਤਰੀ]

ਏਥੇ ਹੀ ਲੈ ਆਵੀਂ । ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਜੱਟ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਾਕਾ ਸਾਉਣੀ ਤਕ ਏਥੇ ਹੀ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਰੋਟੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ । ਮੌਲਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਕੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਉਠ ਖਲੋਤਾ (ਹਾਸਾ)। ਸੋ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਾੜੀ ਸਾਉਣੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਂ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲਗੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਉਠਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਓਦੋਂ ਤਾਈਂ ਦਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਆਈਏ ।

श्री अमर सिंह : On a point of order, Madam. मैं आपका रूलिंग चाहता हूँ। सवेर से कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं । आखिर हम को भी कुछ पता होना चाहिए कि यह हाउस कब तक चलेगा, 7 बजने को हैं ।

Deputy Minister for Food and Supply (Smt. Chandrawati) Madam, question be now put.

Deputy Speaker : I call upon Pt. Mohan Lal Datta.

पंडित मोहन लाल दत्त (अंब) : यह जो पंजाब राज्य के कर्णधार हैं मैं इन की बड़े दिल से इज्ज़त करता हूँ मगर यह जो बिल पास करके सरकार काम करने जा रही है, इससे इनकी बड़ी बदनामी होगी । यह टैक्स 5–5 एकड़ के छोटे छोटे जिमीदारों पर हरगिज़ लगना नहीं चाहिए। यह बात मैं ईमानदारी से कहता हूं कि यह टैक्स उन लोगों पर, जो 50 एकड़ बारानी ज़मीन के मालिक हैं, भी नहीं लगना चाहिए । आप ही अपने दिल को टटोल कर बतायें कि क्या कोई 5 एकड़ का मालिक अपने कुनबा की परवरिश उसकी पैदावार से कर सकता है? आज मुल्क में इतनी महंगाई है कि वह इतने में गुजारा तो क्या करेगा, वह कर्ज़ भी उतार नहीं सकता, खास तौर पर वह शख्श जो हिली एरिया का 5 एकड़ का मालिक हो । मैंने इसके मुताल्लिक एक तरमीम दी थी कि हिली ऐरिया के जो 5 एकड़ के मालिक हैं उन पर यह टैक्स नहीं लगना चाहिए । ऐसी बात करके मैं समझता हूँ कि यह सरकार एक तरह से अपने मुंह पर कालिख लगा रही है । यह बात समझ नहीं आती कि सब को यह सरकार एक ही पैमाने में कैसे तोल रही है । इरीगेटिड एरिया के लिये भी दो कनाल की छूट है । बारानी के लिये भी उतनी और पहाड़ी इलाके के लिये भी दो कनाल की शर्त है । आप इन सब इलाकों की पैदावार तो देखें । क्या दो कनाल में हर जगह यकसां पैदावार होती है ? आप समझदार आदमी हैं, कुछ तो सोचो जहां अच्छी फसल होती हो, वहां चाहे दो कनाल रखो नहीं तो 4 करो । (*Interruption.*)

ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਪਕੜ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਲਾਨਤ ਭੇਜਣੀ ਹੈ । ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਕੂਲ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ । ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਬਿਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ । ਸਾਡੀ ਮਾਕੂਲ ਤਰਮੀਮ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਦੂਸਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਹਾਊਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ । 5 ਏਕੜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰੋ । ਜੇ 5 ਏਕੜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹਿਲੀ ਏਰੀਏ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰੋ । ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ । ਇਹ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਧੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਮਾਕੂਲ ਗੱਲ ਹੈ । ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ।

(ਸ੍ਰੀ ਬਲਰਾਮਜੀ ਦਾਸ ਟੰਡਨ ਅਤੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇਤ ਰਾਮ ਖੜੇ ਹੋਏ)

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਟੰਡਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਥਰਡ ਰੀਡਿੰਗ ਤੇ ਬੋਲ ਲੈਣਾ । ਚੌਧਰੀ ਨੇਤ ਰਾਮ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥਰਡ ਰੀਡਿੰਗ ਤੇ ਬੋਲ ਲੈਣਾ । ਮੇਜਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ।(Shri Tandon and Chaudhri Net Ram may speak at the third reading stage. Now I call upon the Revenue Minister, Sardar Harinder Singh Major.)

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ,......

ਸ੍ਰੀ ਬਲਰਾਮਜੀ ਦਾਸ ਟੰਡਨ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਮੈਡਮ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਚਲਣ ਦਿਉ । ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ । ਮਨਿਸਟਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਮੈਂ ਮਾਲ ਮੰਤ੍ਰੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ । (Please let him proceed. Don't emphasise your point again and again. The hon. Minister has risen. I have already called upon the Revenue Minister to speak.)

श्री रूप सिंह फूल : आन ए प्वायंट आफ इनफर्मेशन, मैडम । बहुत माकूल बात है एक मिंट लगेगा ।

Deputy Speaker : I am very sorry. I have called upon Major Harinder Singh.

श्री रूप सिंह फूल : अगर मुझे बोल लेने दें तो माहौल बड़ा अच्छा हो जाएगा ।

Deputy Speaker ; Major Harinder Singh is on his legs.

श्री रूप सिंह फूल : आन ए प्वायंट आफ इनफर्मेशन, मैडम । मैं तो हमेशा आपका दास रहा हूँ । बात यह है कि मैं सिरफ यह पूछना चाहता हूँ कि यह कार्रवाई कब तक चलेगी ?

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੇਜਰ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜੇ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਥਰਡ ਰੀਡਿੰਗ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਵਾਂ ਤੇ ਜੇ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਹ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਕਹਿ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾ ਲਵਾਂ ।

ਸਰਦਾਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ : ਇਹ ਬਿਲ ਐਨਾ ਭਾਰਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ।

श्री बलरामजी दास टंडन : जो हम ने अमैंडमेंट्स दी हैं उन पर वोटिंग होगी । कौन २ सी अमेंडमेंट माननी है वह यह बता दें ताकि उसके मुताबिक चलें ।

ਮਾਲ ਮਤਰੀ : ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੁਅਦਬਾਨਾ ਇਲਤਮਾਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ।

उपाध्यक्षा : मुझे कोई अमेंडमेंट तो पुट करने दें । (Let me put any of the amendments.)

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ : ਜੋ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਲਿਕ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ੰਜ਼ ਹਨ । ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਉਸ ਮਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਨੇ ਕਿਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ । ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅਤੇ ਫੀਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੈਸ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲਗੇਗਾ ।

Deputy Speaker : Now I will put the Amendments to Clause 2 to the vote of the House.

Amendment No. 1 is in the name of Pandit Mohan Lal Datta.

Deputy Speaker : Question is—

After the clause, the following proviso be inserted :—

"Provided that the provisions of this Act shall not apply to the owners of unirrigated land in backward hilly area owning five acres or less cultivated land".

The motion was lost.

Some voices : The rest of the amendments be put together.

Deputy Speaker : If the House agrees Amendments Nos. 5 to 30 be put together to the vote of the House.

Voices : Yes, no objection.

Deputy Speaker : Question is—

That amendments Nos. 5 to 30 stand part of Clause 2.

The motion was lost.

Deputy Speaker : Question is—

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Deputy Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 2

5. **Comrade Jangir Singh Joga** :

6. **Comrade Shamsher Singh Josh** :

At the end of the clause *add* the following proviso :—

"Provided that the provisions of this Act shall not apply to the owners of five acres or less cultivated land."

7. **Sardar Darshan Singh:**

After the clause *add* the following :—

"Landowner owning land to the extent of 5 acres shall be exempted from this cess".

8. **Sardar Hari Singh:**

In line 2, *for* "1970-71" *substitute* "1966-67".

9. **Thakur Mehar Singh :**

At the end of the clause *add* the following :—

"Landowner owning land of 5 acres shall be exempted from this cess".

10. **Shri Ajit Kumar:**

11. **Chaudhri Net Ram:**

At the end of the clause *add* the following :—

"No recoveries of this cess will be made from the effected areas of recent Pakistani aggression and draught effected areas and from the other areas it will be recovered from the year 1968-1969. Owners of five acres of land will be exempted from this cess."

12. **Baboo Bachan Singh:**

At the end of the clause *add* the following :—

"This cess should be imposed on the landowners of economic holdings only."

13. **Sardar Gian Singh Rarewala:**

At the end of the clause *add* the following :—

"No recoveries of this cess will be made from the war affected districts of Amritsar, Ferozepur and Gurdaspur for one year from the date of the enforsement of the amending Act. Cultivators of five acres of cash crops will be exempted from this cess."

14. **Baboo Bachan Singh:**

15. **Babu Ajit Kumar:**

16. **Chaudhri Net Ram:**

In the amendments appearing at serial Nos. 10, 11 and 12, *for* "will" and "should" wherever occurring *substitute* "shall".

17. Shri Balramji Dass Tandon:

18 Shri Fateh Chand Vij:

At the end of the clause, *add* the following provisos :—

"Provided that the same will not be levied on the persons having land less than 5 acres:

Provided further that the same will not be levied on the persons living in the border districts of Amritsar, Gurdaspur and Ferozepur."

19. Comrade Gurbakhsh Singh:

20. Comrade Shamsher Singh Josh:

21. Comrade Jangir Singh Joga:

22. Comrade Babu Singh Master:

23. Comrade Bhan Singh Bhaura:

24. Sardar Gurnam Singh:

At the end of the clause *add* "the same will not be levied on land owners owning 5 acres or less than 5 acres".

25. Comrade Bhan Singh Bhaura:

26. Comrade Babu Singh Master:

27. Comrade Shamsher Singh Josh:

28. Comrade Gurbakhsh Singh:

29. Comrade Jangir Singh Joga :

In amendments appearing at serial Nos. 19, 20, 21, 22 23, and 24, *for* "will" *substitute* "shall".

30. Sardar Shamsher Singh :

At the end, *add* "The same shall not be recovered from the owners of up to 15 acres of land."

Deputy Speaker: Question is—

That the Title be the Title of the Bill.

(*The motion was carried.*)

Revenue Minister (Sardar Harinder Singh Major) : Madam, Deputy Speaker, I beg to move that the Punjab Commercial Crops Cess (Amendment) Bill be passed.

Deputy Speaker: Motion moved—

That the Punjab Commercial Crops Cess (Amendment) Bill be passed.

चौधरी नेत राम (हिसार सदर): डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैंने इस बिल की तीसरी रीडिंग पर बोलते हुए अर्ज़ करनी है कि मिर्च, कपास और गन्ने की जो फसलें हैं, जो ज़रा सी हवा लगने से खराब हो सकती है, जिससे किसान को सिवाए मुश्किल से रोटी मिलने के और खास मुनाफा नहीं होता उस पर Tax का बोझ न डाला जाए। जब जंग की वजह से बार्डर पर फसलें तबाह हो गई हैं, बारिश न होने की वजह से और नहर का पानी न मिलने से सारे पंजाबमें और खास कर हिसार में कहत के हालात हैं; फसलें नहीं हो रहीं तो आप कैसे उन पर बजाए

मुआवज़ा देने के उल्टा टैक्स लगा रहे हैं । डिप्टी स्पीकर साहिबा, आठ करोड़ रुपया सालाना बतौर वज़ीफों के princes को दिया जाता है । इसी तरीके से सूरजपुर सीमेण्ट फैक्ट्री आज पंजाब की हो चुकी होती लेकिन दो करोड़ रुपये की factory की Machinery आज सूबा से बाहिर ले जाने की इजाज़त दे दी । क्यों न वह factory वापिस ला कर पंजाब में सीमेंट का मसला हल किया जाए? डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं हाउस को चेतावनी दिलाना चाहता हूँ कि उन्होंने जो transport पर tax लगाया है यह उनसे वसूल नहीं करेगी बल्कि उनसे मिलकर लाखों रुपये election लड़ने के लिये हासिल करेंगे । आज पांच एकड़ वाले किसान के लिये हम इस सरकार से मांग करते हैं कि उन पर tax न लगाया जाए । डिप्टी स्पीकर साहिबा, इनका Agriculture Deptt. कहता है कि फी एकड़ से दो मन औसतन अनाज पैदा होता है । इसका मतलब है कि पांच एकड़ से 10 मन हुआ । व्यापारियों को तो 4 हजार से ऊपर वाले को tax लगाते हैं लेकिन किसान जिसकी 10 मन पैदावार हो उस पर टैक्स लगाया जा रहा है । जो किसान चमासे में खेतों में दोपहर को घूमता है, फिर बीमार हो जाता है और जिसके पास दवाई के लिये पैसे नहीं होते इस सरकार को उस पर रहम करना चाहिए । मैं आपका ज्यादा समय न लेता हुआ एक बात और कहना चाहता हूँ । हमारी सरकार बहुत सियानी सरकार है, जब यह बाहिर मीटिंग करते हैं तो सोशलिज्म का नारा लगाते हैं 'ईश्वर अल्ला तेरा नाम सब को सम्मति दे भगवान" वब्लिक में तो इस हेरा फेरी से काम लेते हैं। कांग्रेस के member यहां पर तो कहते हैं कि tax नहीं लगना चाहिए लेकिन जब लाइब्रेरी के परली तरफ जाते हैं तो कहते हैं "राम किशन, दरबारा ढिलन तेरे नाम हम को परमिट कोटा दे भगवान ।" तो इस तरह से यह लोगों को धोखा देते हैं । इनके मुंह में राम राम और बगल में छुरी है । इस तरह की सरकार ज़्यादा देर तक नहीं चल सकती । मैं कहता हूँ कि किसानों के साथ सौतेली मां का सलूक न करो । एक तरफ मेहनत करने वालों को बरबाद किया जा रहा है और लुटेरों की हौसला अफजाई की जाती रही है ताकि वह लूट कसूट करते रहें । यह बात मुनासिब नहीं है । मैं तो कहता हूँ कि भगवान इन से देश को छुटकारा करवाये ।

श्री **बलरामजी दास टण्डन** (अमृतसर शहर पश्चिम) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस बिल की अब तीसरी reading है जिसके ऊपर काफी बहस हो चुकी है । मैं एक दो बातें कह कर उम्मीद करता हूँ कि गवर्नमेंट उन बातों को ध्यान में रखते हुए इस बिल के बारे में दोबारा गौर करने की कोशिश करेगी । इसमें शक की बात नहीं कि सरकार को कुछ अपने कामों के लिये पैसा चाहिए जिसके अंदर defence और दूसरे देश की भलाई के काम आते हैं । लेकिन जहां तक पंजाब सरकार का ताल्लुक है, हमें इस बात का अफसोस है कि इनको जिस ढंग से प्लैनिंग कमीशन के सामने या Centre के सामने पंजाब का case रखना चाहिए था वैसे इन्होंने नहीं रखा । लेकिन थोड़ी देर के लिये अगर यह समझ लिया जाए कि सरकार ने अच्छी तरह से अपना case रखा लेकिन प्लेनिंग कमीशन और Central Government ने हमारे case को sympathetically consider नहीं किया, मगर डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप जानते हैं कि पंजाब के अंदर जो बड़े बड़े अफसरान लगे हुए हैं वह खुद कहते हैं कि I.A.S. और I.C.S. जो bulky ढांचा बनाया हुआ है, उस में सरकार बड़ी आसानी के साथ 1/3rd reduction कर सकती है जिससे efficiency पर भी असर नहीं पड़ सकता ।

[श्री बलरामजी दास टंडन]

डिप्टी स्पीकर साहिबा, अगर दफ्तरों में रिडक्शन कर दी जाए, तो उससे सरकार को 15–20 करोड़ रुपये की बचत हो सकती है। इसके बारे में आई.ए.एस. आफिसर्ज़ एसोसीएशन ने भी सरकार को लिख कर दिया था।

7-00 p.m.

उन्होंने सरकार को यह लिख कर राष्ट्रीयता की भावना दिखाई है। हमने इसी सैशन में यह मामला सरकार के नोटिस में लाया था लेकिन पता नहीं कि सरकार इस तरफ क्यों नहीं ध्यान देती। इसके लिये सरकार को एक कमेटी बनानी चाहिए। इस कमेटी में ट्रेज़री बैंचिज़ और आपोजीशन बैंचिज की तरफ से कुछ रीप्रीजेंटेटिव लिये जाने चाहिएं और साथ में उक्त एसोसीएशन के कुछ रीप्रीजेंटेटिव लिये जाने चाहिए। सरकार को चाहिए कि वह कमेटी दो-तीन महीने के अन्दर अपनी रिपोर्ट सरकार को दे ताकि जल्दी ही इस रिपोर्ट पर अमल किया जा सके। ऐसा मालूम देता है कि सरकार इस विषय में सीरियस नहीं है क्योंकि सरकार ने हमारे कहने के बावजूद भी कोई कदम नहीं उठाया है। इस समय देश के, विशेषत: पंजाब के लोगों के अन्दर कौमी जज़बात भरे हुए हैं। यही कारण है कि आई.ए.एस. आफिसर्ज की एसोसिएशन ने सरकार को रिडक्शन के द्वारा बचत करने के लिये कहा है। एक तरफ 15–20 करोड़ रुपये की बचत हो सकती है लेकिन सरकार उस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है लेकिन दूसरी तरफ इस टैक्स के द्वारा 40 लाख रुपये ही इकट्ठे किये जायेंगे। अगर सरकार 5 एकड़ जमीन रखने वाले को छूट दे देगी तो हो सकता है कि इस टैक्स के द्वारा 30 लाख रुपये इकट्ठे किये जायेंगे जिस से सरकार को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। आपको पता ही होगा कि मंत्रियों को एक एक मैम्बर के पास जाकर मिन्नतें करनी पड़ रही है कि भगवान के वास्ते इस बिल के बारे में सरकार को क्रिटीसाइज न किया जाए और सरकार को एम्बैरेसिंग पोजीशन में न डाला जाए। मुझे पता नहीं लगता क सरकार इस बिल को पास कराने में क्यों बजिद है। सरकार ने पहले जब यह बिल लागू किया था तो उस वक्त हाउस में वायदा किया था कि यह बिल दोबारा किसानों पर लागू नहीं किया जायगा। इससे सरकार को कोई ज्यादा आमदनी नहीं होने वाली है। सरकार तो लोगो को इस बिल के द्वारा तंग करना चाहती है। किसानो की हालत बहुत खराब हो चुकी है। किसान टैक्स दे करने के काबिल नहीं हैं। जहां पर सरकार बचत कर सकती है, उधर कोई ध्यान नहीं देती है। अगर सरकार यह समझती है कि प्लैनिंग कमीशन वाले इस टैक्स को कुलैक्ट करने वाले सोर्स को छोड़ने से नाराज होंगे, मैं समझता हूँ, यह ऐसी बात नहीं हो सकती है। अगर उनको किसानों की सही हालत का जायजा कराया जाए तो वह इस टैक्स को खत्म करने के हक में हो जायेंगे। अगर सरकार 5 एकड़ वाले किसानों को इस टैक्स से छूट दे देती तो मैं समझता हूँ कि इस बिल की आपोजीशन की तरफ से और ट्रेजरी बैंचिज़ की तरफ से इतनी टफ आपोजीशन न होती। अन्त में मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अगर सरकार ने डिवैल्पमेंट के लिये रुपया इकट्ठा करना है तो सरकार को दफ्तरों के स्टाफ में रिडक्शन करनी चाहिए। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि वह हाउस में इस बारे में कमेटी बनाने के लिये एसोरेंश दें ताकि वह कमेटी तीन महीनों के अन्दर अपनी रिपोर्ट दें। इस वक्त किसानों पर टैक्स न लगाया जाए। उनको टैक्स में रियायत देने की ज़रूरत है। मैं इस बिल की मुखालफत करता हूँ।

ਸਰਦਾਰ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ, ਮੈਡਮ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਚੁਪ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ

ਕਮੇਟੀ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੇਗੀ ?

उपाध्यक्षा : कमेटी किसने कायम की है? (Who has constituted the Committee ?)

ਸਰਦਾਰ ਨਰਾਇਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ : ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ।

उपाध्यक्षा : मैं ने आपको कहा था कि आप मुझे लिखकर दे दें। आपकी दरखास्त मेरे दफतर ने मेरे सामने रखी थी लेकिन मैं किसी कमेटी को बनाने की मजाज नहीं रखती हूं। गवर्नमेंट के पास कमेटी मकर्रर करने की पावर है। (I had requested the hon. Member to send his suggestion to me in writing. His request was placed before me by my office but I am not competent to appoint such a Committee. Power to appoint such a Committee vests with the Government)

ਸਰਦਾਰ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ । ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਮੁਕਰਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ । ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਸੀ । (ਵਿਘਨ)

उपाध्यक्षा : यह बात मेरे नोटिस में नहीं है कि स्पीकर साहिब ने जांच करने के लिए कोई कमेटी मुकर्रर की थी । अगर आप यह बात पहले मेरे नोटिस में लाते तो देख लेती । (विघ्न) (It is not in my knowledge that the hon. Speaker constituted any Committee to look into this matter. Had the hon. Member brought this matter to my notice earlier, I would have thought over it.) (*Interruption*)

ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਲਾਇਲਪੁਰੀ (ਨਾਗੋਕੇ, ਐਸ. ਸੀ.) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇੰਡੋ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫ਼ਖ਼ਰ ਹੈ । ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ । ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਸਿਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਭੀ ਭੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ । ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਖਿਆ ਲਈ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਨ, ਮਨ ਅਤੇ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਰਹੀ

[ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਲਾਇਲਪੁਰੀ]

ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਅਨਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਢੰਗ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਬਕਰਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਾਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਛਾਤਾ ਬਰਦਾਰ ਪਕੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਸਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਰੁਪਿਆ ਮਿਲ ਸਕੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕੇ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਸਰਕਾਰ industrialist ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ 3 ਪਰ ਸੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 9 ਪਰ ਸੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੁਲਹਾੜਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Deputy Speaker : Kindly wind up.

ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਲਾਇਲਪੁਰੀ : ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਰੁਪਿਆ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮਿੰਟ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਲਾ ਬਿਲ ਹੈ, ਮਨਹੂਸ ਬਿਲ ਹੈ। (*Interruption*) ਇਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ .....

ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਟ੍ਰੈਯਰੀ ਬੈਂਚਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਥੰਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਹਾਊਸ ਸੁਬਹ ਤਕ ਚਲੇਗਾ, ਅਸਾਂ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ, ਹਾਊਸ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਣਾ ਹੈ। (*Addressing Dr. Baldev Parkash*) (I have to conduct the proceedings of the House.)

ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਲਾਇਲਪੁਰੀ : ਇਹ ਗਰੀਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਗਰਗੂੰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਇਹ ਬਿਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇ ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ : On a point of order. ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਲਈ ਇਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ । ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿਉ ।

ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ (ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ interrupt ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਰਖ ਦੇਵਾਂਗਾ ।

ਪਹਿਲੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮੇਜਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਨੁਕਤੇ ਉਠਾਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰਖਣੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੜਾ ਬਹਾਦਰ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰ ਵਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲੋਂ ਰੁਪਿਆ ਮੰਗੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਹੀਂ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਚੋਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਮਾਫ ਕਰਕੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਸੂਲ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸੋਰਸਿਜ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਰੁਪਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲੋਂ ਮਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ । ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਟੇਟ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਇਥੇ ਪੈਪਸੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਹਰ ਸਾਲ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੂੰ ਬਚਦਾ ਹੈ । ਅਜੇ ਅੱਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਲੀਟ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਰਪਏ ਦੀ ਹੋਰ ਆਮਦਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਥੇ ਟੰਡਨ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਾਪ-ਹੈਵੀ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਵਲ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੁਪਿਆ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਕ ਜਗੀਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗੜੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਕੁਠਿਆਲ ਨੂੰ ਜਗੀਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੁਪਿਆ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸੈਂਟਰ ਵਲ। ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਲੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਮੈਚਿਉਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸੈਸੱ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ । ਉਹ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਬਿਆਨੇ ਦੀ ਮਾਫੀ

[ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ]

ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਮੈਚਿਉਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ(*Interruption*) ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਪਾਹ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਮਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਕਦੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖਰਾਬੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ? ਰੀਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਸਲਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਬੀ ਸੁਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫਸਲ ਦੀ ਮੈਚਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ agency ਮੁਕੱਰਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਮੈਚਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਠੀਕ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹੋ ਹੋਵੇਗੀ।

ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਲ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਪਰ ਜਵਾਬੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨ ਲੈਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ amendments ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਸੇ ਫਰਾਖ ਦਿਲੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਕਾਨੌਮਿਕ ਹੋਲਡਿੰਗ $4\frac{1}{2}$ ਏਕੜ ਹੈ, ਜੇਕਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਤਾਂ $4\frac{1}{2}$ ਏਕੜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣ ਜੇਕਰ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਾਂਦੇ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਹਾਊਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ (ਮੋਗਾ) : ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਜੈਸ਼ਨਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 50/50 ਬੇਸਿਜ਼ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੈਂਪ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਵਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਦਸਦੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। 50:50 ਸਕੀਮ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਜਿੰਨੀ ਮਾਈਲੇਜ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਕੋਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੈਟਰਡ ਰੂਟ ਤੇ ਲਈ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਕੰਸਾਲੀਡੇਟਿਡ ਰੂਟ ਤੇ ਦੁਗਣੀ ਮਾਈਲੇਜ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਈਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਸੌ ਮੀਲ ਲੰਮੇ ਰੂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ,ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ more income lesser vehicles. ਇਕ ਇਕ ਬੱਸ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਰੂਟ ਤੋਂ 40, 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਢਿਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੌਰਮਿੰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੂਟ ਦੇਣ ਲਈ ਬਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਰੂਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰੂਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੰਮੇ ਰੂਟ ਮਸਲਨ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹਿਸਾਰ ਨੀਲਾਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹਾਈ ਬਿਡ ਦੇਵੇ ਉਹ ਲੈ ਜਾਵੇ।

ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੁਠੀ ਭਰ—ਪੰਜ ਸਤ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਧਰ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਚੂਸਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਚਲਾਵੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰਨਾ ਚਾਹੋ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ (ਰਾਇਕਟ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਵਿਚ ਕੋਤਾਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਨਾ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਕਿਸ ਸਟੈਮਿਨੇ ਨਾਲ ਔਰ ਕਿਸ ਇੰਪਾਰਸ਼ਿਏਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਹਾਊਸ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ 7.30 ਵਜਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਚਲਾਇਆ ਹੈ । (*Thumping of desks*)

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਸਾਡਾ ਵਿਧਾਨ ਜ਼ਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ । ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫਖਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ—ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਖਰ ਜਿਹੜੇ ਟਰੇਜ਼ਰੀ ਬੈਂਚਿਜ਼ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਕਾਨਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੌਕੇ ਬੇਮੌਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ, ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਸੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਹੈ । ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਪਰਸੂਏਡ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ—ਪਰਸੂਏਡ ਕਰਕੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲੈਣਾ । ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਊਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ । ਮੈਡਮ, ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ—ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੈਂਚਿਜ਼ ਤੋਂ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਧਰ ਦੇ ਬੈਂਚਿਜ਼ ਤੋਂ, ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ।

ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤ੍ਰੀ(ਕੈਪਟਨ ਰਤਨ ਸਿੰਘ): ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ । ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਹਨ । (*Interruptions*)

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਆਰਡਰ ਪਲੀਜ਼ । ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ । ਮੈਂ ਇਥੇ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਬਠੀ ਹੋਈ ਹਾਂ (Order please. The hon. Members need not perform my duty what for I am sitting here?)

ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਕੈਪਟਨ ਰਤਨ ਸਿੰਘ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟੋਕਣ ਦਾ । ਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ । ਗਲਤ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕੋ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਪਾਰਲੀ-ਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਰੋਕਣਾ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ । ਮੇਰਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ । ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ; ਬਹੁਤੇ ਬੋਲੇ ਹਨ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਪੰਡਿਤ ਰਲਾ ਰਾਮ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਹਨ । (Pandit Rala Ram has supported it.)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਲਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਬੋਲੇ ਹਨ । ਪਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ—"ਨੀਮ ਦਰੂੰ ਨੀਮ ਬਰੂੰ" ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਹਨ ਨਾ ਬਰਖਿਲਾਫ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਿਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਉ । ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ । ਸੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ । ਫੇਰ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ? 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਹਾਊਸ ਮਜਬੂਰ ਹੋਕੇ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਦੇ ਬਰਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਹਨ । ਇਸ ਸਾਰੀ

[ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ]

ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਕੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਇਆ ਇਹ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਆਟੋਕਰੈਟਿਕ ? ਅਗਰ ਇਹ ਵਾਕਈ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ੰਜ਼ ਫਾਲੋ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊਸ ਦੀ ਟੈਂਪਰ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਜਮੂਈ ਰਾਏ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰ ਲਏ। (*Interruptions*) ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਇਤਨੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਟੋਕਰੈਟਿਕ ਨਹੀਂ ਬਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮਿਸਟਰ ਗਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਬੈਠਕੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ,ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਬਿਲ ਬਾਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊਸ ਦੀ ਟੈਂਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚੇ, ਵੇਖੇ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਕੀ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਜਮਹੂਰੀ—ਡੈਮਾਕਰੈਟਿਕ ਕਾਂਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ? ਇਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਏ ਆਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨੋ। (*Thumping from the opposition*) ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਹਨ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਜ਼ਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮਗਰ ਤਕੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣ। ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕਾ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਵਾਂ ਕਿ "ਅੰਨ੍ਹੇ ਅੱਗੇ ਰੋਣਾ, ਤੇ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਖੋਣਾ" ? ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸਾਂ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।

ਇਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ। 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਏ। 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਇਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ? ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 75 ਫੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ....

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਜਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੁਗ਼ਾਲਤੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਨ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਕੈਬੀਨਿਟ ਮਨਿਸਟਰ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੰਟ ਦੇ ਕਾਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਜ਼ਬਾਨ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਵਰਤਿਆ ਕਰੋ। (The hon. member should at least, use some dignified language.)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਤਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਖਿਰ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸੂਏਡ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਹੋ ਜਾਂ ਆਟੋਕਰੈਟਿਕ। ਸੋ,ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਸੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 18 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਸੁਧਰੀ ਹੈ ? (Interruptions)

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇੰਟਰਪਟ ਨਾ ਕਰੋ । (*No interruption, please*).

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਇਥੇ ਟਰੈਜ਼ਰੀ ਬੈਂਚਿਜ਼ ਉੱਤੇ ਚੌਧਰੀ ਰਿਜ਼ਕ ਰਾਮ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਹਨ, ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਢਿਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੈਪਟਨ ਰਤਨ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੇਮ, ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੀਟਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ । (*Interruptions*) ਸੋ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ । ਕੀ ਇਹ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਬਕਾ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਹੇਠ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਖੁਦ ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ 75 ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਤਬਕਾ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਦਬਿਆ ਪਿਆ ਹੈ । ਖੁਦ ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਿਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਅਨਇਕਾਨਿਮਕ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਅਨਇਕਨਾਮਿਕ ਹਨ । ਅਨਇਕਨਾਮਿਕ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਹੋਣ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਤ ਦੀ ਪਾਵਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਚਾਰ-ਚਾਰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਏਕੜ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 9 ਫੀ ਸਦੀ ਸੂਦ ਉੱਤੇ ਮਿਲੇ ਜਦਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ 4 ਫੀ ਸਦੀ ਇੰਟਰੈਸਟ ਉੱਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬਿਲ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪੇਂਡੂਆਂ ਦੀ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਹਮਦਰਦ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਵਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਕੀ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਰੀਬੀ ਵੰਡਣਾ ਹੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੀਨਜ਼ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਸਟਰੀਬੀਊਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੇਖੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇਕ ਤਬਕਾ ਦੂਜੇ ਤਬਕੇ ਉਪਰ ਡਾਮੀਨੇਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ।

Deputy Speaker : Kindly wind up.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋਗੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗਾ । ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ । ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਦਰ ਗਰੀਬੀ ਵੰਡੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਸੋਸਲਿਜ਼ਮ ਆ ਗਿਆ ਸਿਵਾਏ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰ ਲਿਆ । ਉਹ ਤਬਕਾ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਸ ਤਬਕੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫੰਡਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਸ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਉਪਰ ਚੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ।

ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂ. ਪੀ. ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਯੂ. ਪੀ. ਵਿੱਚ ਕਣਕ 42 ਰੁਪਏ ਮਨ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 20 ਰੁਪਏ ਵਿਕਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ੋਨਜ਼ ਤੋੜ ਦੇਣ ਲਈ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨਾਲ ਲੜੇ ਔਰ ਕਹੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਨਸ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇਣ । ਜੇ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਵੀ 40 ਜਾਂ 45 ਰੁਪਏ ਮਣ ਵਿਕੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਬੇਸ਼ਕ ਸੈੱਸ ਲਗਾ ਲਓ । ਜੋ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਪ੍ਰਤਾਪ ਗਰਗ ਵਰਗੇ ਬੈਠੇ ਨੇ......

ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਰੇਟਰੀ : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ, ਮੈਡਮ। ਸੈੱਸ ਤਾਂ ਗੰਨੇ ਮਰਚਾਂ ਤੇ ਕਪਾਹ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਏ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ?

श्री सुरेन्द्र नाथ गौतम : ग्रान ए प्वायंट ग्राफ ग्रार्डर, मैडम। सरदार गुरनाम सिंह के साथ लिहाज़ हो रहा है। उन को इस बिल पर पहले एक बार ग्राप ने टाईम दिया था, फिर दूसरी बार दिया। फिर एक घंटा भर फिर दिया ग्रौर ग्रब वह फिर बोल रहे हैं। ग्रौर दूसरी तरफ हालत यह है कि हम बार बार खड़े होते ग्रौर ग्राप हमें वक्त नहीं दे रहीं। हम सारा दिन यहां पर भूखे बैठे हुए हैं।

Deputy Speaker : Order, Order. Will you take your seat please?

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਲੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਜੇ ਅੱਗੇ ਚਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। (ਹਾਸਾ) ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ੋਨਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕੋਨਾਮਿਕ ਜ਼ੋਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਹੈ ਉਹ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਵਾਧੂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਇਤਨੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸੀਡਾਈਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਦੇਵੇ।

ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਵੇਸਟਫੁਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਘਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਸਾਡੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਈ. ਸੀ. ਐਸ. ਔਰ ਆਈ. ਏ. ਐਸ. ਅਫਸਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਡਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੀਡਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਰੁਪਿਆ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੈਲ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਭਣ ਲਈ ਸਵਾ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖੀ ਸੀ। ਔਰ 73 ਲੱਖ ਵਸੂਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇਹ ਹੁਣ 40 ਲੱਖ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵਿਪ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਪ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੋਲੀ ਜਾਓ ਪਰ ਵੋਟ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿਓ, ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮ-ਅਜ਼-ਕਮ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਹਨ......(ਚੌਧਰੀ ਨੇਤ ਰਾਮ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਿਘਨ) ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਸਾਰੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸ ਲਈ ਕੋਈ ਇਜ਼ਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਜ਼ਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ।

PERSONAL EXPLANATION BY THE CHIEF PARLIAMENTARY SECRETARY

ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਪਰਤਾਪ ਗਰਗ (ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਰੇਟਰੀ) : ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ, ਮੈਡਮ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੇਰਾ ਇਸ ਬਿਲ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ

ਇਰਾਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਜ ਸਾਹਿਬ, ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਔਰ ਬਾਬੂ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਮਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਤੇ ਸਰ ਸਿਕੰਦਰ ਹਯਾਤ ਦੀ ਮਨਿਸਟਰੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੇਂਡੂਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ । ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਜਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਤੰਗਦਿਲੀ ਦੀ ਔਰ ਸੈਕਰੇਟੇਰੀਅਨ ਸਪੀਚ ਸੀ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੰਗਦਿਲੀ ਦੀ ਔਰ ਸੈਕਰੇਟੇਰੀਅਨ ਸਪੀਚ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਤਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਸੀ ਜਿਤਨੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਬਿਲ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੀਸ਼ਨ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਜਟ ਬਿਸਵੇਦਾਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਗਰੀਬ ਜਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ । (ਚੌਧਰੀ ਨੇਤ ਰਾਮ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਿਘਨ) ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੈੱਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ......

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹੋ ਜਾਂ ਜੋ ਜਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹੋ ? (Has the Chief Parliamentary Secretary risen to give his personal explanation or to reply to what the hon. Member, Sardar Gurnam Singh, has said?)

ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਰੇਟਰੀ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ. ਪੀ. ਵਿੱਚ ਕਣਕ 42 ਰੁਪਏ ਮਣ ਹੈ ......

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ?

Deputy Speaker : Please let him say.

ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਰੇਟਰੀ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੰਨੇ, ਕਪਾਹ ਔਰ ਮਿਰਚਾਂ ਤੇ ਸੈੱਸ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ. ਪੀ. ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਥੇ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾ ਯੂ.ਪੀ. ਨਾਲੋਂ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂ. ਪੀ. ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੈੱਸ ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਭਾ ਗੰਨੇ ਦਾ ਉਥੇ ਹੈ ਉਹੋ ਹੀ ਇਥੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ । ਉਹ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮਿੰਟ ਫਿਕਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਰੇਟ ਤੇ ਸਟੇਟ ਟੂ ਸਟੇਟ ਬੇਸਿਜ਼ ਤੇ ਇਥੋਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੇਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਚਾਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ।

ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸ਼ਿੰਘ ਮਾਸਟਰ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਇਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ 8 ਵਜਣ ਲੱਗੇ ਨੇ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਇਮਪਲਾਈਜ਼ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾ ਤਾਂ ਕਲ ਦੀ ਛੁਟੀ ਦਿਉ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰ ਟਾਇਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਆਰਡਰ ਪਲੀਜ਼ । ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਦਫਤਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਛੋੜੋ । (Is the hon. member more interested in the affairs of my Secretariat than myself? He should leave it to me.)

श्री रूप सिंह फूल : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आप की विसातन से जज साहिब से यह पूछना चाहता हूं कि उन्हों ने जो सरदार दरबारा सिंह और सरदार गुरदयाल सिंह ढिल्लों को यह सर्टीफिकेट दिया है कि यह जाट बैठे हुए हैं क्योंकि वह गांव के रहने वाले हैं, मैं उन से पूछता हूं कि क्या वह भी गांव में रहते हैं ? (ਹਾਸੀ)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ।

THE PUNJAB COMMERCIAL CROPS (AMENDMENT) BILL, 1961

(Resumption of discussion)

ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤ੍ਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ। ਇਤਨਾ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਲਾਸ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ, ਫਿਰਕੇਦਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਸਮਾਜ-ਵਾਦ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ । ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਲਭਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕੇ । ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ । ਅਗਰ ਇਹ ਸੈਸ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਚਾਂਸਿਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੁਝ ਇਸ ਤੋਂ ਭੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਪੈਂਦਾ, ਆਬਿਆਨਾ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਮਾਲੀਆ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਘਟ ਤੋਂ ਘਟ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਟੰਡਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਬਾਈ ਡੀਫਾਲਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਿਜ਼ ਲਾਏ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਨੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ। (ਵਿਘਨ) ਯੂ. ਪੀ. ਨੇ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਹਨ। ਉਥੇ ਦੀ ਐਸੰਬਲੀ ਨੂੰ ਉਠਣਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਬੋਝ ਪਵੇ । ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਲੜੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਰੀਸੋਰਸਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਰਮਲ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖੀ । ਸੈਂਟਰਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਭੀ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਫੀਕਲਟੀਜ਼ ਦਸੀਆਂ, ਫਿਨਾਂਸਿਜ਼ ਦੀ ਤੰਗੀ ਹੈ, ਰੀਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਪਰੈਡ ਓਵਰ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਭੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ । ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੋਰ ਟੈਕਸਿਜ਼ ਨਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ । ਇਹ ਟੈਕਸ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਟੀਨੂਇੰਗ ਟੈਕਸ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਨਵਾਂ ਹੀ ਟੈਕਸ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ । ਸਾਨੂੰ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਲਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੀ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਕਰੋ । ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰਾਏ ਸੋਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ.....

ਸਰਦਾਰ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰੀ : On a point of information Madam. ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਭੁਖ ਨੂੰ ਘਟ ਤੋਂ ਘਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਇਕ ਕੂਲਾ ਲੇਲਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲਭਾ ? (ਵਿਘਨ)

ਕਾਮਰੇਡ ਜੰਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ (ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਅਗਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਵੀ ਕਰਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਪਸੂ ਅੰਦਰ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਮਗਰ ਰੂਲਜ਼ ਦੋ ਸਾਲ ਨਾ ਬਣਾਏ । ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੇਚ ਲਈ ਗਈ । ਫਿਰ ਇਹ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਮਗਰ ਜਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਡੁਬਦੀ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ, ਤਿੰਨ ਦਫਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਚੌਥੀ ਦਫਾ ਫਿਰ ਮਿਲਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਣਗੇ । ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਟ ਤੋਂ ਘਟ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਡਿਆਂ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਖਰਚ ਹੀ ਹੈ । ਇਹ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ । ਟੈਕਸ ਗਰੀਬ ਤੇ ਲਾਂਦੇ ਹਨ ਅਮੀਰ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕਿਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਅਗਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰੀਏ । ਸੋਰਸਿਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਦਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ।

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਹਸਾਉਣਾ । ਸੋ ਚੂੰਕਿ ਇਥੇ ਕੁਝ heat generate ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਗਾਲਬਨ ਕਾਮਰੇਡ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਾਣੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ (ਵਿਘਨ) ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਕਾਣਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਾਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । (ਤਾੜੀਆਂ) (ਵਿਘਨ)!......

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : On a point of order, Madam. ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ । (ਹਾਸਾ) ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ । (ਵਿਘਨ) ਅੱਜ ਜੋ ਇਹ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ । ਸੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਵਲ ਤਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ । ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । (ਵਿਘਨ) ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ।

उपाध्यक्षा : मैं समझती हूं कि इस आगस्ट हाऊस के आनरेबल मैंबरों को आपस में ऐसे अलफाज़ को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि जो किसी को चुभने वाले हों जैसे कि किसी को काने कर रक्खा है या कुछ और । यह ठीक नहीं । इन की इजाज़त नहीं दी जा सकती । (विघ्न) (I am of the view that the hon. Members of this august House should avoid the use of pinching words like some body has been purchased etc. for each other. This is not proper and will not be allowed.) (Interruption)

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿਣੀ ਹੈ । ਕਾਮਰੇਡ ਜੋਸ਼ ਨੇ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਕ ਗਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਉਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ **ਇਨ੍ਹਾਂ** ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਨ 1946 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਬਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨੌਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਲੋਂ ਨੌਮੀਨੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਵੇਲੇ ਮੁਸਲਮ ਲੀਗ ਗਰੁਪ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਗਰੁਪ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਕ ਇਕ ਵੋਟ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਨੌਮੀਨੇਟਿਡ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । (ਤਾੜੀਆਂ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਤਾੜੀਆਂ)

ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ : ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨਸਟੀਚੂਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਟੋਡੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚੁਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ । (ਵਿਘਨ)

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਕਾਮਰੇਡ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤਾਂ ਬੋਲੋ, ਕਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ । (The hon. Member should seek permission of the Chair on the point on which he wants to speak.)

ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਪ ਵੀ ਤਾਂ ਸੰਨ 42 ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ । (ਸ਼ੋਰ)

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ : ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਦੋ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਕੱਢ ਲੈਣ । ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਜੋਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਨੇ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ । ਇਹ ਤਾਂ ਫੈਕਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ।

ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਣਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਾਂ ਕਿ

ਤੇਰੀ ਇਕੋ ਅੱਖ ਸੁਲਖਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦਮਕਾਂ ਮਾਰੇ
ਤੈਨੂੰ ਝੁਕ ਝੁਕ ਕਰਨ ਸਲਾਮਾਂ ਦੋ ਅੱਖੀਆਂ ਵਾਲੇ ।

(ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ) (ਹਾਸਾ)

ਸਰਦਾਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ : ਭੌਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ : ਬਾਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੁਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਬੁਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੈ । ਫਿਰ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਬੁਧੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ । (ਵਿਘਨ) ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੀਡ ਤਾਂ ਇਕੋ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਮਗਰ ਹੀ ਰਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । (ਹਾਸਾ)

ਜਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਅੱਲਕ ਹੈ......(ਵਿਘਨ)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ : ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟਸ ਅਤੇ ਰੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ।

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ : ਥੈਂਕ ਯੂ ।

ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸੈਂਟ ਪਰ ਸੈਂਟ ਮੁਤਫਿਕ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਵੀ ਪਰਸ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸਿਜ਼ ਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਚਲਾਣ ਲਈ ਜਾਂ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਚਲਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ । (ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ)

ਸ੍ਰੀ ਬਲਰਾਮ ਜੀ ਦਾਸ ਟੰਡਨ : ਪਰੀਵੀ ਪਰਸ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਕਰਾ ਲਉ । (ਵਿਘਨ) ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨਰੇਬਲ ਹੋਮ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਦਵਤਾ ਭਰਿਆ ਭਾਸ਼ਨ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਹਕ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਵਾਂ ।

ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੇਰੀ ਟੀਕਾ ਟਿਪਣੀ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਅਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਅੰਨਿਆਂ ਆਖਣ, ਕਾਣਾ ਆਖਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਕ ਹੈ ਪਰ ਅਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਕ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਆਖੀਏ । ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਲਫਜ਼ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਲਫਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ । ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮਲ੍ਹਮ ਲਾਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ । ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪੱਗ ਨੂੰ ਆਣ ਲਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾਇਆ ਨਹੀਂ । (He has not made the Members laugh.)

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਉ । (ਹਾਸਾ)

Deputy Speaker : Question is—

8.00 p. m. | That the Punjab Commercial Crops Cess (Ammendment) Bill be passed.

The House then divided.

Ayes = 56

1. Ajmer Singh, Sardar
2. Amar Nath, Sharma, Shri
3. Amar Singh, Shri
4. Balwant Singh, Sardar
5. Banwari Lal, Shri
6. Bhagirath Lal, Pandit.
7. Bhag Singh, Lieut.
8. Brish Bhan, Shri
9. Chand Ram, Shri
10. Chandrawati, Shrimati
11. Darbara Singh, Sardar
12. Dasondhi Ram, Chaudhri
13. Dilbagh Singh, Sardar
14. Dina Nath Aggarwal, Shri
15. Gian Chand, Shri
16. Gurmej Singh, Sardar
17. Gurmit Singh, Sardar
18. Guran Dass Hans, Bhagat
19. Gurmail, Shri
20. Gurdial Singh, Dhillon, Sardar
21. Harchand Singh, Sardar
22. Harinder Singh, Major, Sardar
23. Hari Ram, Chaudhri
24. Har Kishan, Chaudhri
25. Hira Lal, Shri
26. Hoona Mal, Shri
27. Jagir Singh Dard, Sardar
28. Jagjit Singh, Tikka
29. Jagdev Singh Sandhu, Sardar
30. Karam Singh 'Kirti', Sardar
31. Kesra Ram, Shri
32. Manphul Singh, Chaudhri
33. Mehar Singh, Thakur
34. Nihal Singh, Shri
35. Nihal Singh, Rao
36. Om Prabha Jain, Shrimati
37. Prem Singh 'Prem', Sardar
38. Rala Ram, Principal
39. Ram Chandra, Comrade
40. Ram Dhari Balmiki, Shri
41. Ram Kishan, Shri

42. Ram Pal Singh, Kanwar
43. Ram Partap Garg, Shri
44. Ram Parkash, Chaudhri
45. Ram Rattan, Chaudhri
46. Ram Saran Chand Mittal, Shri
47. Ranbir Singh, Chaudhri
48. Rattan Singh, Captain
49. Roop Lal Mehta, Shri
50. Rup Singh 'Phul', Shri
51. Sagar Ram Gupta, Shri
52. Sunder Singh, Chaudhri
53. Surinder Nath Gautam, Shri
54. Ujagar Singh, Sardar
55. Lal Chand Prarthi, Pandit
56, Sohan Singh Jalalusman, Sardar

Noes (Total No. 21)

1. Ajaib Singh, Sandhu, Sardar
2. Babu Singh, Master, Comrade
3. Bachan Singh, Babu
4. Baldev Parkash, Dr.
5. Balramji Dass Tandon, Shri
6. Bhan Singh Bhaura, Comrade
7. Fateh Chand Vij, Shri
8. Gurmej Singh, Sardar
9. Gurbax Singh Gurdaspuri, Sardar
10. Gurnam Singn, Sardar
11. Hardit Singh, Sardar
12. Jagjit Singh, Sardar
13. Jangir Singh Joga, Comrade
14. Kulbir Singh, Sardar
15. Mohan Lal Dutt, Pandit
16. Net Ram, Chaudhri
17. Sat Dev, Chaudhri
18. Shamsher Singh Josh, Comrade
19. Surjit Singh Theri, Sardar
20. Tara Singh Lyalpuri, Sardar
21. Tej Singh, Sardar

(*The motion was carried*).

Deputy Speaker : Now the Secretary will make an announcement.

ANNOUNCEMENT BY THE SECRETARY

Secretary : Under Rule 2 of the Punjab State Legislature (Communication) Rules, 1959, I have to inform the House that the Punjab General Sales Tax (Amendment) Bill, 1965, which was passed by the Vidhan Sabha on the 17th November, 1965, and transmitted to the Vidhan Parishad on the same day, has been agreed to by the said Parishad on the 24th November, 1965 without any recommendation.

8.05 p.m. **Deputy Speaker** : The House stands adjourned *sine die.*

(The House then adjourned sine die)

APPENDIX

to

Punjab Vidhan Sabha Debates Vol. II, No. 26, dated the 24th November, 1965.

REPLY TO THE CALL-ATTENTION MOTION NO. 1 BY

COMRADE SHAMSHER SINGH JOSH, REGARDING THE FACT THAT ADEQUATE AND TIMELY HELP OR RELIEF HAS NOT BEEN PROVIDED TO THE VICTIMS OF PAKISTANI AGGRESSION IN RURAL AND URBAN AREAS OF PUNJAB PARTICULARLY CHHEHARTA, PREMIER INDUSTRIAL TOWN OF THE STATE.

Sardar Gurdial Singh Dhillon (Transport and Elections Minister) : The hostilities, which broke out between India and Pakistan in the first week of August, 1965 in Jammu and Kashmir and extended to the three border districts of Punjab, i. e., Amritsar, Ferozepore and Gurdaspur, in the first week of September, 1965, came to an end on the 23rd September, 1965. Besides a number of villages, towns and cities bombed by the Pakistani Air-Force, 51 villages and 2 Basties were occupied by the Pakistani Forces and 50 villages more were badly affected by the enemy action and were consequently considered unsafe for their inhabitants to return to them. In all about 55,000 persons including infants were uprooted from these areas and the overwhelming majority of them had lost their immovable and movable properties. As many as 193 civilians were killed due to air bombardment.

2. This State was thus faced with a host of problems including those of providing shelter, food, clothing to the destitutes, payment of compensation or token grants to those who had been bereaved or who had sustained injuries or suffered losses of immovable property by enemy action. No possible effort was spared to assess the extent of damage to property or loss caused to the civilians and to acquire first-hand knowledge of the dimensions of the problem in the shortest possible time. To tackle this problem on top priority basis and to ensure that the measures adopted should be conducive to expeditious resettlement of the uprooted persons, a full-fledged department of Relief and Resettlement was set up on the 1st October, 1965.

3. The work of assessment was undertaken on top priority basis but it would not be completed early for want of proper verification of claims and on account of difficulty to contact the next of kin and or the families of the victims who had migrated to other places and whose whereabouts were not easily ascertainable. Thus no delay was caused in making payment of the *ex gratia* or relief grants. In the case of Chhehrata, a payment of Rs. 1,11,490 was made up to the 13th October, 1965 to persons whose bread-winners had been killed or who had been injured or permanently disabled or whose immovable property has been damaged and to the owners of the cattle killed. The extent of *ex gratia* grants/relief given up to the 7th January, 1966 was as under :—

	Rs.
Persons bread-winners have been killed	1,95,200
Persons injurred	42,900
Owners of cattle killed	1,37,405
Damage to houses	2,02,320

An assessment of the loss or damage to movable property is still being made.

4. With a view to providing immediate relief to the uprooted and the adversely affected and to enabling them to tide over their immediate difficulties, they have been paid *ex gratia* grants. Because Government can not be expected to make the uprooted persons a permanent liability, the question of sanctioning any family pension to persons whose bread-winners had been killed does not arise. Although the law of the land does not provide for payment of compensation for the damage to houses and buildings by enemy action, yet with a view to giving relief to the affected persons provisions for the *ex gratia* grant of Rs 2,000 for a pacca house and Rs. 1,000 for a kacha house and long-term loans under the Low-Income-Group Housing Scheme at a low rate of interest and arranging material for construction on priority basis have been made, The relief measures adopted are quite adequate and sufficient,

STATEMENTS IN REPLY TO CALL ATTENTION NOTICES RECEIVED LATE FROM GOVERNMENT

STATEMENT IN RESPECT OF CALL ATTENTION NOTICE (*Serial No. 142*) BY SARDAR TARA SINGH LYALLPURI, REGARDING REMOVAL OF RESTRICTIONS ON THE MINIMUM CHARGES OF ELECTRICITY IN RESPECT OF TUBE WELLS.

Chaudhri Rizaq Ram (Irrigation and Power Minister) : Annual minimum Consumption Guarantee is charged where the expenditure of of the Board is more than Rs. 250 per kW, or Rs. 4,000 per connection in the case of Small Power and Agricultural Connections (or more than Rs. 100 per kW in the case of Large and Medium Supply Consumers). In the case of Small and agricultural connections the rate is Rs. 60 per O.H.P. per annum. In the case of Large and Medium supply Consumers, the rate is 15% of total cost of works. The M.C.G. is applicable for a period of 5 years.

The Board, have decided to postpone the payment of M.C.G. for a period of two years from 1st August, 1965 in respect of large and Medium consumers and small power consumers in six districts (Amritsar, Ferozepur, Gurdaspur, Ludhiana, Jullundur and Kapurthla) of Punjab affected during the present emergency. But the rate of M.C.G. in case of Agricultural connections is very nominal and can easily be made up if the tube-wells work on the average of about 3 hours a day. It provides incentive for producing more food by using tube-wells for sufficiently long periods. The Board spends about Rs 4,500 on each tube-well connection. The Board is charging about 9 paise per unit against the cost of about 24 paise per unit and thereby substaining a loss of about Rs. 150 lacs per annum. It is, therefore, not possible to waive of M.C.G. in case ef tube-well connections.

Statement by the Irrigation and Power Minister in reply to Call-Attention Notice (S. No. 143) regarding supply of water in Jind Distributary No. 4

Areas covered by the Western Jammu Canal depend on the free-flow in the river for irrigation supplies and in such a case it is not possible to conserve water during a particular period for utilisation later on. Efforts are made to take the maximum advantage of the free flow in the river at a particular time. During some of the summer months, the flow in the rivers is in excess of the demand. The supplies in the remaining months are, however, less than the maximum demand in the various systems. It thus becomes necessary to ensure equitable distribution in the entire system by rotational running of canals.

2. The rainfall has been extremely poor during the current year, throughout the State. This has been the position in the catchment areas of all the rivers. In particular the rainfall has been extremely poor during the months of July and August, the rainfall was invariably much below the average rainfall in the past years. The discharge of the river Yamuna has also been unusually low, this year, which is insufficient to meet the demand.

3. Due to poor availability of water, all channels are running by rotation. Hansi Branch has got 52,250 cusecs days equivalent to the full supply days from 15th October, to 18th November, 1965 against which Jind Distributary No. 4 has also been run for 14 days full supply da y's i.e., 2 full supply turns of 7 days each. On account of silt and berm growth in some of the outlets in the Head reaches, there has been some shortage at the tail of this Distributary. Now the silt and berm are being cleared and it is expected that the condition of tail portion will improve considerably and the villages Kinana, Anupgarh and Biroli will get their authorised share in next turn.

Statement by the Irrigation and Power Minister in reply to Call-Attention Notice (S. No. 144) regarding supply of water in Jind Distributary No. 3

Areas covered by the Western Jumna Canal depend on the free-flow in the river for irrigation supplies and in such a case it is not possible to conserve water during a particular period for utilisation later on. Efforts are made to take the maximum advantage of the free-flow in the river at a particular time. During some of the summer months, the flow in the rivers is in excess of the demand. The supplies in the remaining months are, however, less than the maximum demand in the various systems. It thus becomes necessary to ensure equitable distribution in the entire system by rotational running of canals.

2. The rainfall has been extremely poor during the current year, throughout the State. This has been the position in the catchment areas of all the rivers. In particular the rainfall has been extremely poor during the months of July and August, the rainfall was invariably much below

the average rainfall in the past years. The discharge of the river Yamuna has also been unusually low, this year, which is insufficient to meet the demand.

3. In view of the shortage of water, the channels are running by rotation and Jind Distributary No. 3 is also getting its share. The Jind Distributary No. 3 in its turn gets water for a week in one month. There is some shortage of water in the tail of this Distributary, because Reclamation shoots had to be continued till 31st October, 1965 on account of complete failure of rains. Now reclamation shoots have been removed and it is expected that the next full supply turn, proper supply will reach the tail of Jind Distributory No. 3, irrigating areas of villages Dighana, Shamlo—Kalan and Khurd, Lalit Khera, Nidana and Bhaironkhera.

STATEMENT MADE BY IRRIGATION AND POWER MINISTER IN REPLY TO CALL-ATTENTION NOTICE NO. 147 (BY COMRADE BHAN SINGH BHAURA, M.L.A.) REGARDING TRANSFER OF DIESEL ENGINES TO AGRICULTURE DEPARTMENT.

In pursuance of the orders of the Chief Minister, for the transfer of pumps to the Agriculture Department, all the Superintending Engineers of Drainage Organisation were asked on telephone to intimate the number of pumps available for transfer/loan to the Agriculture Department. On the basis of the information received from these Superintending Engineers orders for the transfer of under-mentioned number of diesel pumps to the Agriculture Department have since been issued to the officers concerned :—

(1)	Patiala Drainage Circle	..	53 Nos.	(for transfer)
(2)	Amritsar Drainage Circle	..	24 Nos.	,,
(3)	Ferozepur Drainage Circle	...	70 Nos.	,,
(4)	Karnal Drainage Circle	..	10 Nos.	,,
	Total	...	157 Nos.	

The above number includes the pumps of the Malerkotla Drainage Division also.

Besides the above, Director Agriculture has been requested to take over 84 Nos. diesel pumps belonging to the Flood Pool on loan basis In addition, the Superintending Engineer, Central Mechanical Circle, has also informed the Agriculture Department on 2nd November, 1965 that 650 Nos. Electric pumps are available in Gurgaon Canal/Feeder Project Circle for transfer to the Agriculture Dapartment making the total 891.

So far, only 5 Nos. pumps have been lifted by Panchayat Samiti Majitha. The Director of Agriculture Department has again been requested to make sure that the pumps are also taken over immediately in order to make full and timely use of these pumps for agricultural purposes.

STATEMENT BY THE IRRIGATION AND POWER MINISTER IN CONNECTION WITH CALL-ATTENTION NOTICE (SERIAL NO. 148) BY SHRI SAMPURAN SINGH DHAULA, M. L. A., REGARDING REMODELLING OF DHANAULA DISTRIBUTARY

The water allowance of this channel is as follows, provided in the Bhakra Nangal Projects :—

(1) Perennial area south-west of the straight line joining Ferozepur and Jakhal	2.75 cusecs per 100 acres of C. C. A. at Distributary headt and 2.4 cusecs per 1,000 at outlet head
(2) Perennial area north-east of the straight line joining Ferozepur and Jakhal	2.37 cs. per 1,000 acres of C.C.A. at Distributary head and 2.04 cs. at outlet head

It is not correct that the water allowance of Dhanaula Distributary, has been reduced from 2.5 cs. to 2.04 cs. per 1,000 acres of C.C.A.

2. The last designed full supply discharge of Dhanaula Distributary was 73 cusecs against which the discharge as per revised L-section is 83 cs. at head. The total number of outlets of Dhanaula Distributary system are 60 out of which 31 number outlets were remodelled in the beginning of Rabi, 1965. The modelling of Dhanaula Distributary system has been necessitated due to the fact that most of the outlets were drawing excess discharge than permissible.

3. It is not a fact that a large number of cuts occurred on Dhanaula Distributary as a result of remodelling. Only one cut during current Rabi crop at RD 11,220-R Dhanaula Distributary on 26th October, 1965 occurred which was closed on 27th October, 1965. During Kharif, 1965 also one cut had occurred at RD 31,000-L on 25th September, 1965 which was closed on 26th September, 1965.

4. Wherever any outlet was found drawing less than its authorised full supply discharge Imdadi pipes have been sanctioned on Dhanaula Distributary for supplementing the discharge of such outlets. The shareholders of the outlets which were previously drawing excess discharge are not satisfied with the remodelling of Dhanaula Distributary. There is no danger to the law and order situation.

STATEMENT BY IRRIGATION AND POWER MINISTER IN REPLY TO CALL-ATTENTION NOTICE (S. NO. 149) IN REGARD TO REMODELLING OF DHANAULA AND MANDI DISTRIBUTARY

Areas covered by Sirhind Canal depend on the supplies of Bhakra Reservior. The discharges from the reservoir are regulated in such a way that —

(i) Adequate water is available for the Kharif and Rabi crops ; and

(ii) Requirements for the purpose of power generation are fully met throughout the year.

It has further to be ensured that sufficient water is available as far as possible, during the sowing and maturing period. It has, however, to be kept in view that the extent of supplies made during each period will depend on the overall supplies that are available in the reservoir.

2. The rainfall has been extremely poor during the current year throughout the entire State. This has also been the position in the catchment areas of all the rivers. In particular, the rainfall has been extremely poor during the months of June and September. During the months of July and August, the rainfall was invariable much below the average rainfall in the past years.

3. The live storage in the Bhakra reservoir is supposed to be of the order of 5.6 M.A.F. The live storage available during the current year was only to the extent of 2.6 M.A.F. This clearly brings out the poor availability of waters in the Bhakra reservoir. As such there is no failure on the part of the Government.

4. The water allowance of Dhanaula and Mandi Kalan Distributaries is as follows :—

(i)	Perennial area south-west of the straight line joining Ferozepur and Jakhal	2.75 cs. per 1,000 acre of C. C. A. at Disty head and 2.4 cs. per 1,000 acres at outlet head
(ii)	Perennial area north of the straight line joining Ferozepur and Jakhal	2.37 cs. per 1,000 acres of C.C.A. at Disty. head and 2.04 cs. at outlet head

It is incorrect that water allowance of these Distributaries has been reduced from 2.5 cusecs to 2.04 cs. per 1,000 acres of C.C.A.

The scheme for remodelling of Rajbaha Dhanaula and Mandi Kalan has been necessitated due to the fact that most of the outlets on these distributaries were drawing discharge exceeding the permissible limit. It is not correct that with the connivance of the S.D.O. Harigarh, day to day cuts are being made. Only two cuts on Dhanaula Disty. have occurred, which have since been closed. No cuts have been reported on Mandi Disty. The situation is by no means alarming to cause anxiety.

5. Government is taking all steps to make best use of the available supplies and to ensure the authorised supplies to the cultivators.

STATEMENT IN RESPECT OF CALL-ATTENTION MOTION NO. 152 BY COMRADE MAKHAN SINGH TARSIKKA, M.L.A. REGARDING REHABILITATION OF BORDER VILLAGES, WHICH ARE UNDER MILITARY OPERATION

Sardar Gurdial Singh Dhillon (Transport and Elections Minister) : Uprooted inhabitants of the villages which are under the occupation of

Pakistani forces as well as the uprooted residents of the areas to which civilians do not have access for various reasons have been and are being issued wheat at the prescribed scale on monthly basis. If the District authorities, after consulting the army authorities, are satisfied that any area is inaccessible for the civilians and the former residents of those areas do not have any gainful occupation now, it is in the power of District Authorities to issue cash doles and other formal sporadic *adhoc* relief to the uprooted persons. Accordingly there is no reason to believe that any discrimination is made against the residents of the affected villages or areas including those listed in the Call-Attention Motion.

STATEMENT IN RESPECT OF CALL-ATTENTION NOTICE NUMBER 154 GIVEN BY SARVSHRI AJIT KUMAR AND AJAIB SINGH SANDHU, M.L.As. REGARDING NON-PAYMENT OF SALARY TO DEPUTY REGISTRARS AND ASSISTANT REGISTRARS OF INDUSTRIAL CO-OPERATIVES IN THE STATE

1. The Call-Attention Notice is not clear in so far as the particulars of the Assistant Registrars and Deputy Registrars, whose salaries are said to have not been paid, have not been specified. It may, however, be stated that two posts of Deputy Registrars, namely, Deputy Registrar at Headquarters and Deputy Registrar at Ludhiana and 11 posts of Assistant Registrars of Industrial Co-operatives were provided in the Budget estimates for the financial year 1965-66. The Finance Department, to whom the matter was referred for the continuance of these posts, did not agree to the continuance of one post of Deputy Registrar at Ludhiana and 4 posts of Industrial Assistant Registrars beyond 31st May, 1965. The Director of Industries, Punjab, who was asked to abolish these posts had again represented to the Government for their continuance as according to him it would be highly detrimental to the interest of Industrial Co-operative Organisation to abolish these posts. As such the posts not agreed to by the Finance Department, have not been abolished. The matter is being pursued vigorously with the Finance Department for their concurrene for the regularisation of these posts for the period for which the salaries have not yet been paid.

2. In case of the two Assistant Registrars, Industrial Co-operatives, namely, the Lady Assistant Registrar, Industrial Co-operatives, Chandigarh and the Industrial Assistant Registrar, Ludhiana, the payment of their salaries is held up for want of their suitability from the Public Service Commission. The matter is being taken up with the Commission.

STATEMENT IN RESPECT OF CALL ATTENTION NOTICE (SERIAL No. 158) MOVED BY SARVSHRI KULBIR SINGH AND SATYA DEV, M. L. As. REGARDING ABSENCE FROM DUTY OF GOVERNMENT SERVANTS POSTED IN THE BORDER AREAS OF FEROZEPORE DISTRICT

Shri Ram Kishan (Chief Minister) : The State of Punjab was a direct hit during recent Indo-Pak conflict. The Government servants have had to play an important role in the defence of our motherland. The Government servants came up to theexpectation of the Government and did remarkable work leaving aside some very few black sheep who were found absent on one pretext or the other from their duties at the time when National security was in danger. This sort of behaviour on the part of Government servants has been considered to be gross deriliction of duty and misconduct calling for deterrent punishment. Accordingly all the State Departments had been asked to take disciplinary action against all those Government servants who had absented themselves from duties at that critical juncture without permission from the competent authority. The Government of India who have also sought for detailed information on the subject would be informed in due course.

2. As regards the defaulters in the Central Bank and the Railway authorities, it may be added that the two departments do not fall within the purview of the Punjab Government.

STATEMENT IN RESPECT OF CALL-ATTENTION MOTION (SERIAL NO. 166) BY COMRADE MAKHAN SINGH TARSIKKA, M.L.A. REGARDING DISCONTENTMENT AMONGST PUNJAB ROADWAYS EMPLOYEES DUE TO AN ORDER OF THE GENERAL MANAGER, AMRITSAR

(Transport and Election Minister).

Gurdial Singh Dhillon The contention that the General Manager, Punjab Roadways, Amritsar has ordered recovery of the amounts of cash rewards disbursed to some drivers, conductors, technicians and helpers of Punjab Roadways, Amritsar three years ago, due to any personal, vengeance is unfounded. The payment was made in August, 1964. The order for recovery from the officials was issued by the General Manager, Punjab Roadways, Amritsar in March, 1965 on the basis of an objection raised by the Internal Audit which was subsequently reiterated by the O.A.D. Party of the Accountant-General, Punjab, Simla in para 10 of Part III of their audit and Inspection Note on the accounts of Punjab Roadways, Amritsar for the period April, 1964 to March, 1965, an extract from which is as under :—

> "The officials detailed in appendix 'E' to this Audit and Inspection Note had been paid awards for the year 1962-63 though they were not entitled to receive the same either because they had not completed one year's service as on 31st March, 1963 or for other reasons as indicated against each of them. The total amount so paid in excess thus worked out to Rs. 2,208, which may please be recovered from the officials concerned under intimation to this office. The circumstances under which the payments were made to the officials who were not entitled to receive the awards may please be investigated and results thereof intimated to this office."

From the information received from the General Manager, Punjab Roadways, Amritsar, it transpires that in pursuance of his Recovery Order a sum of Rs. 551 has been recovered from some of the officials. However in order to avoid hardship to the employees, the General Manager, Punjab Roadways, Amritsar has been asked to stay the recoveries and to make out a proposal for regularisation of the payments made, on the merits of each case.

STATEMENT BY SARDAR DARBARA SINGH, HOME AND DEVELOPMENT MINISTER IN RESPECT OF CALL-ATTENTION NOTICE (SEREIAL NO. 171). BY PANDIT MOHAN LAL DATTA REGARDING THE GRAVE IRREGULARITY IN CONTINUING THE OLD ZILA PARISHAD HOSHIARPUR ETC.

The Zila-Parishad, Hoshiarpur could not be constituted partly due to the pending writ petitions and in account of the acceptance of election petition by the Prescribed Authority. Recently, in view of the existing emergency and to ensure that the attention of the people should continue to be focussed on war efforts, pending elections to Panchayati Raj bodies were postponed all over the State. The constitution of Zila Parishad will, however, be completed soon.

STATEMENT IN REPLY TO CALL-ATTENTION NOTICE NO. 173 RE. GOVERNMENT'S FAILURE TO IMPLEMENT MAHAJAN COMMITTEE'S RECOMMENDATIONS

Home and Development Minister

Shri Fateh Chand Vij, M.L.A. has tabled a Call-Attention Motion (Serial No. 173) in the Vidhan Sabha in 18th November, 1965. The Motion draws attention to the Government's failure to implement Mahajan Committee's recommendations to provide a jeep in every Police Station or at least in Sadar Police Stations of the State to control effectively the Law and Order situation. The Call-Attention Notice further states that Law and Order situation is a serious problem in some of the Sadar Police Stations of the State and that immediate measure to control it by providing means of transportation for the Police officials should be taken.

2. The recommendations of the Police Commission are still under the consideration of the Government. The particular recommendation to which the attention of Government has been drawn has yet to be considered. The implementation of this particular recommendation, which involves huge financial implications, would also depend on the availability of funds. Government are, however, keen to implement the re ommendations of the Punjab Police Commission and it is hoped that

the above additional requirement in the shape of jeep would be met in due course when additional funds are made available. However, I would like to assure this House that Government are in complete control of the Law and Order situation in the State and adequate measures to control it are being taken.

Statement in respect of Call-Attention Notice (Serial No. 186) by Comrade Gurbakhsh Singh Dhaliwal regarding shortage of fertilizers in district Ferozepore

SARDAR DARBARA SINGH, HOME AND DEVELOPMENT MINISTER, PUNJAB

The position regarding supply of fertilizers to Ferozepur district is given below —

			Tonnes
1.	Target fixed for 1965-66	..	63,500
2.	Stock held on 1st April, 1965	..	9,447
3.	Supplies made up-to-date	..	28,709
4.	Total stock made available	..	38,156

Out of the above supplies of 28,709 tonnes of fertilizers, 4,300 tonnes were supplied to Moga alone. More supplies of fertilizers could not be made as against our requirements of 1.58 lakh tonnes of fertilizers for the quarter September to December, 1965, we were allotted 40,000 tonnes of fertilizers only, i. e., 30,000 tonnes of CAN and 10,000 tonnes of Ammonium Sulphate, for the whole of the State excluding I.A.D.P, District Ludhiana· The production of fertilizers in the country is not sufficient to meet the demand of the State Government. The imports of fertilizer to large extent is also not feasible on accoun of foreign exchange difficulties

Special efforts were made to rush supplies out of the imported stocks. 41,200 tonnes of fertilizers were arranged through special trains during October, and November. Out of this 5,100 tonnes were supplied to Ferozepore.

The Government of India was requested to allot more fertilizers. A fresh allotment of 5,000 tonnes has been made, out of which 1,100 tonnes are being supplied to Ferozepur District.

STATEMENT MADE BY THE CHIEF MINISTER IN REPLY TO CALL-ATTENTION NOTICE NO. 187 RE. THE ALLEGED MISUSE OF MEDICINES OF THE DISTRICT RED CROSS SOCIETY BY THE DEPUTY COMMISSIONER, FEROZEPORE

Discreet enquiries made in the matter reveal that the allegation made in the Call-Attention Notice (Serial No. 187) is absolutely baseless and incorrect. It is, however, correct that the son of Shri Kuldip Singh Virk, Deputy Commissioner, Ferozepore, was seriously ill at Ferozepore. He was confined to the Military Hospital at Ferozepore for about a month and a half and was later on transferred to the Military Hospital, Poona. During his stay in Ferozepore all along he remained an indoor patient in the Military Hospital and the question of purchasing any medicine from outside did not arise. In this respect it has further been reported that he was never under the treatment of any civilian doctors.

Statement by the Irrigation and Power Minister in reply to Call-Attention Notice No. 190 regarding opening of Purchasing Centres within 20/25 Miles Radius of the Batala Co-operative Sugar Mills, Ltd., Batala during the Crushing Season 1965-66

It is a fact that the Joint Registrar (Sugar Mills), in exercise of his powers as Registrar, issued a directive, dated the 6th November, 1965, to the General Manager, Batala Co-operative Sugar Mills, Ltd., Batala,

under rule 45 of the Punjab Co-operative Societies Rules, 1963, directing him that in view of the fact that there was plenty of cane available within a radius of 20 to 25 miles of the Sugar Factory to meet its full requirement of the season 1965-66, he should not open purchasing centres beyond 25 miles radius of the factory. In case this area failed to meet its full requirement, the General Manager was further directed to refer the case to the Joint Registrar (Sugar Mills) for further examination if he should be allowed to go beyond the aforesaid distance for more cane supplies. A copy of the directive issued is being placed on the table.

2. As the House is aware, the success of a sugar factory depends on the procurement of cane from the shortest distance possible of the factory. This has two advantages:—

(i) It ensures freshness of cane.

(ii) It reduces cost of transportation of cane.

3. The Batala Co-operative Sugar Mills Ltd., Batala, has a maximum licensed capacity of 1000 metric tons per day. At the most, therefore, the sugar factory's optimum daily crush cannot exceed 27,000 maunds. On account of the fact that the area around the factory does not grow early variety of cane, it is not in the interest of the factory to start the season earlier than the last week of November or the first week of December. Again, on account of rising temperature in April (which affects recovery adversely and also causes more driage of cane) and on account of busyness of the cultivator with harvesting of 'Rabi', it is not possible to prolong the crushing season beyond the middle of April or at the maximum the end of April. Within these two limits, the sugar factory is left with a season of five months or say, roughly 150 days. It is common knowledge that some hours are lost on account of breakdowns and periodical general cleaning after every fortnight. Sugar industry, therefore, takes it for granted that the average hours, thus, lost are two in a day. Out of the total season of 150 days, a margin of 13 days on account of loss of hours on account of mechanical break downs and general cleaning has to be made. Factory is, thus, left (under very normal working conditions) with 137 effective crushing days. Assuming that the factory crushes at the optimum rate of 27,000 maunds a day (which in actual practice will not be the case) up to the end of April, it can crush at the most 37 lac maunds of cane. This is the maximum crushing capacity of factory during the season. But in actual practice, it may not crush more than 35 lac maunds of cane. This is more so because certain defects in the machinery came to notice last year. Efforts have been made to get these defects removed after the close of the year. Whether the defects have been completely removed or not, only the working of the machinery this season will show. The efforts of the factory will be to produce this requirement of cane from as short a distance of the factory as possible.

4. Given below is the position of bonding of cane as on the 21st November, 1965, at the gate as well as at the various purchasing

centres together with the distance of each purchasing centre from the factory :—

S. No.	Name of Centre		Distance from the factory (in miles)	Qty. of cane bonded (in quintals)
1.	Gate	..	—	643,290
2.	Mehta	..	14	47,590
3.	Dhariwal	..	9	1,01,825
4.	Gurdaspur	..	17	1.02,145
5.	Gahbri	..	25	41,415
6.	Aliwal	..	9	80,910
7.	Qadian	..	15	59,380
8.	Katli Surat Malli	..	14	93,160
9.	Pakhar Pura	..	10	69,365
10.	Fatehgarh Churian	..	19	60,565
11.	Dina Nagar	..	25	46,695
12.	Kala Afgana		exact distances not known but are less than 25 miles	82,890
13.	Shri Hargobindpur			68,280
14.	Jaito Sarjai			36,595
15.	Sekhwan			46,760
	Total	..		1,580,865

In terms of maunds, the bonding up to 21st November, 1965 works out to 42.37 lac maunds approximately. It is understood that more offers of cane are still coming forth from the cultivators within a radius of 25 miles of the factory. This bonding within a radius of 25 miles is considered to be sufficient to meet the full requirement of the factory. It may be pointed out that in case the factory bonds for more than what it can crush, under the Sugar-cane (Regulation of Purchase and Supply) Act and the rules framed thereunder, the factory is under obligation to pay compensation to the cane-growers for the quantity of cane which it fails to lift. In the matter of bonding, therefore, the sugar factory has to be very very careful. On their part, if the bondees failed to supply less than 85 per cent of the bonded cane, they are subject to penalty @ 10 per cent of the cane price.

5. During the last two years, gur and khandsari prices were very high. The cane-growers in the factory areas had a strong tendency to divert their cane crop to manufacture of gur and khandsari so much so that even though the Government of India made it obligatory for the cane growers within the reserved areas of the sugar factories to deliver at least 75 per cent of their cane crop to the sugar factory concerned, most of the sugar factories did not get enough cane to meet their full requirement. The Batala Co-operative Sugar Mills Ltd., Batala, was one of them. It suffered heavy losses during the last two crushing seasons for want of full cane supplies. In the 1963-64 crushing season, it crushed 2.56 lac quintals or 6.86 lac maunds. In other words, it crushed only 19.43 per cent of its licensed capacity. The factory's losses were of the order of Rs 11.91 lacs. In the year 1964-65, the factory crushed 4.96 lac quintals or 13.29 lacs maunds. This represents 38 per cent of the licensed capacity of the factory. The factory's loss this year is estimated to be Rs 10.65 lacs. It may not be correct to say that the paucity of cane was due to the lack of availability, it was mostly due to the diversion of cane to the manufacture of gur and khandsari. In the circumstances, the factory had to go to far off places such as Patti (53 miles) and Tarn Taran (41 miles) for the purchase of cane and established purchasing centres there.

6. During the last three years, area under cane cultivation has steadily risen in Punjab. In 1963-64, the total area under cane cultivation in Punjab was 5.69 lacs acres. In 1964-65, it rose to 6.52 lac acres. In 1965-66, although the correct figures are not yet available,but the area is very much more than in the preceding year. This increase in acrage is entirely due to the steep rise in gur and khandsari prices because the price fixed for supply of the cane to the sugar factories has been Rs 2 per maund all these years. It will not be, therefore, correct to assert that the area under cane cultivation in Amritsar District rose simply because the cultivators there had hoped to supply their cane crop to the Batala Co-operative Sugar Mills.

7. Even though there is little scope for further bonding to sugarcane by the Batala Co-operative Sugar Mills Ltd., Batala, yet as a concession to the shareholders of Amritsar District. Government are issuing instructions that the offers of such of the share-holders of Amritsar District as would like to deliver their cane at the factory gate or at the nearest purchasing centre should be accepted.

Copy of memorandum No. JRSM/65, dated the 6th November,1965 from Shri J. S. Sarohia,.I.A.S., Joint Registrar (Sugar Mills), Co-operative Societies, Punjab, Chandigarh (Camp Batala) (in exercising his powers as RCS) to the General Manager, The Batala Co-operative Sugar Mills, Ltd. Batala, district Gurdaspur,

Subject .—Opening of Purchasing Centres for the 1965-66 Crushing Season.

Memorandum

For the successful working of a sugar factory, it is necessary that the sugarcane should be hauled from as short a distance of the sugar factory as possible. This has two distinct advantages: first, the factory gets fresher cane and it gives a long way to improve recovery; secondly it reduces cost of transportation of cane.

2. I am satisfied that this year there is plenty of cane available within a radius of 20 to 25 miles of the factory to meet your full requirements of the Season 1965-66. You should not, therefore, open purchasing centres beyond 25 miles radius of your sugar factory. In case this area fails to meet your full requirements, you should refer the case to me for further examination if you should be allowed to go beyond the aforesaid distance for more cane supplies.

3. This direction issues under rule 45 of the Punjab Co-operative Societies Rules, 1963.

Please acknowledge receipt.

Call-Attention Notice No. 197 by S. Ranjit Singh, M.L.A., regarding stoppage of construction works of Irrigation drainage on account of paucity of funds.

In order to meet the challenge of nature and to avoid huge lasses sustained by the residents of the State, Drainage Schemes worth Rs 83.18 crores were put up for consideration to the Emergency Committee meeting of the Council of Ministers held on 30th and 31st October, 1962. The committee decided that due to paucity of funds, emergency items of the various schemes, costing about Rs 38.72 crores be executed by the monsoons of 1965. The phasing of the expenditure as approved by the Committee was as under.—

Year	Rs
1962-63	7.55 crores
1963-64	20.65 crores
1964-65	10.52 crores

However ceiling fixed by the Government of India for the Third Plan both for the flood protection, drainage and Anti-water logging Schemes was of the order of Rs 15.01 crores. The allocations actually made for the year 1961-62 was. however, Rs 175.00 lacs. This allocation was supplemented by the State Government and an amount of Rs 290 lacs, viz. Rs 255 lacs on Flood Control and Drainage Schemes and Rs 35.0 lacs on Anti-waterlogging works were spent.

During the year 1962-63 the final allotment was Rs 590 lacs against which there has been an expenditure of Rs 593 lacs. During the year 1963-64 the Plan allocations were kept at Rs 798.18 lacs against Rs 20.65 crores as decided in the Council of Ministers' meeting held on 30th/31st October, 1962. But subsequently the Planning Department imposed a cut of Rs 60 lacs and 10 lacs on Flood Control and Drainage Schemes leaving the total allocations at Rs 728.18 lacs for the year 1963-64.

During the year 1964-65 the original demand for flood Control, Drainage and Anti-waterlogging as made by the Department was of the orders of Rs 17.62 crores which was revised to Rs 10.50 crores. The allocation originally made available for Flood Control Drainage and Anti-waterlogging schemes was Rs 2.94 crores and was subsequently increased to Rs 7.24 crores.

During the year 1965-66 a sum of Rs 1.03 crore was allocated in the beginning but keeping in view the importance of the schemes it was enhanced to Rs 4.03 crores.

With the available funds, it has been possible to construct embankments along with the subsidiary protection works along the rivers in the length of 330 miles and drains in Pilot Section/in termediary stages, in a length of about 3,500 miles have been completed.

The above narration will show that efforts have been made to do the maximum in regard to Flood Control and Drainage and the works for whatever stage have been constructed are fully operative and are rendering the maximum benefits for which they are constructed and save the State and its people from undergoing huge losses.

Statement in reply to Call-Attention Notice No. 198 by Sardar Ajaib Singh Sandhu regarding complaints against some Officers of the Medical Department at district headquarters.

There had been complaints from the Deputy Commissioners Ludhiana and Ferozepore against Dr. M. L. Blaggana, Chief Medical Officer, Ludhiana and Dr. Chander Bhan, Deputy Chief Medical Officer (Health), Ferozepore. Immediately on receipt of the complaint from the Deputy Commissloner, Ludhiana, due action on it was taken by the Director of Health Services, Punjab and firstly the Senior Medical Officer, Ludhiana was ordered to take the responsibility of handling the War Emergency arrangements and later on Dr. Harkishan Singh, formerly Chief Medical Officer, Ludhiana was urgently posted at Ludhiana. Dr. M. L. Blaggana was ordered to take over as Blood Transfusion Officer at Chandigarh. He has also been conveyed displeasure of the Government for his carelessness in the War Emergency.

2. Likewise due cognizance was taken about the complaint lodged by Deputy Commissioner, Ferozepur against Dr. Chander Bhan, Deputy Chief Medical Officer (Health), Ferozepore. A prompt warning was sent to Dr. Chander Bhan by the Director of Health Services to stick to his station of duty. Later on further probing was made and consequently he was also administered a warning for improving himself. The aspect of his transfer was also taken notice of and it has been decided on account of administrative convenience not to take it up till the next general transfer.

Statement in reply to Call-Attention Notice (211) by S. Ranjit Singh, M.L.A., regarding land revenue rates in Malerkotla Tehsil.

In the various princely States of erstwhile Pepsu 62% to 80% of the net assets were absorbed in fixing the demand of land revenue, whereas the cases charged in the erstwhile Pepsu varied from 2% to 17% of the land revenue. With a view to give some relief to the highly assessed landowners of tehsils like Malerkotla, Kapurthala, Nalagarh, etc.,an *ad-hoc* remission of annas -/2/- per rupee was allowed by the Pepsu Government. A scheme to bring the land revenue rates in the erstwhile Pepsu at par with those of the adjoining areas of the erstwhile Punjab was also already in hand before the merger of Pepsu with Punjab. In the meantime

the merger took place and the integrated State Government implemented the aforesaid scheme thereby bringing the land revenue rates of all the areas comprised in erstwhile Pepsu at par with those of the adjoining areas of the erstwhile Punjab. For this purpose, three Officers on-Special-Duty were appointed who selected sets of similar adjoining assessment circles in erstwhile Pepsu as well as in erstwhile Punjab in consultation with the Deputy Commissioners of the Districts of the erstwhile Pepsu. After this selection the incidence of land revenue in both the similar assessment circles was calculated and wherever the incidence of land revenue in the similar assessment circle of the erstwhile Pepsu was found higher than that of the similar adjoining assessment circle of the erstwhile Punjab, the former was brought down to the level of the erstwhile Punjab.

2. So far as Malerkotla Tehsil is concerned, the position is as under :—

Assessment circle of Malerkotla Tehsil		Incidence of land revenue	Assessment circle of erstwhile Punjab reckoned similar	Incidence of land revenue	Proposed rate per rupee of the existing demand
					P.
Lohat Baddi	..	3.00	Upper Dhaia of Ludhiana	2.22	74
Panjgrain	..	3.99	Upper Dhia of Ludhiana	2.22	56
Malerkotla	..	4.42	Powadh of Ludhiana	2.48	56
Amargarh	..	2.73	Powadh of Kaithal	1.36	50
Nabha	..	2.91	Ditto	1.36	47
Bhadson	..	3.46	Ditto	1.36	[illegible]
Sherpur	..	1.91	Jungle of Ludhiana	1.08	57

The new rates came into force with effect from Rabi harvest of the agricultural year 1958.

3. On representation from the people of Malerkotla Tehsil against the alleged injustice to them in levelling down the land revenue rates, the question was reopened in 1963, and the matter was examined thoroughly from all possible angles, viz., contiguity of areas compared, similarities of conditions, such as class of soil and means of irrigation, etc., quantum of relief over the original incidence granted to the various

circles and productivity of soil as judged from yield per acre of principal crops. From the comparison thus made, it was only the Lohat Baddi assessment circle of Malerkotla Tehsil which stood the test and the cultivators of this circle got 28% further relief in their land revenue demand.

4. The contention of the Hon'ble Member that the land revenue rates of Malerkotla Tahsil have not been lowered is not correct. After the integration of Punjab and Pepsu, the State Government was committed to removing disparity in the land revenue rates of the erstwhile Pepsu *vis-a-vis* the erstwhile Punjab and not the disparity in the land revenue rates of the assessment circles of the same tehsil of the erstwhile Pepsu. Such sort of disparity is common in the areas of the erstwhile Punjab also, as the assessment in a circle is based on average money value of the net assets which are different in each assessment circle on account of different factors which come into the calculation of net assets.

Statement in reply to Call-Attention Notice No. 212 regarding exemption of border districts from the payment of property tax.

There are three border districts in the State, namely, Ferozepur, Amritsar and Gurdaspur. Re-assessment operations are going on in the following rating areas in these districts :—

1. Ferozepur City .. Ferozepur District
2. Ferozepur Cantt .. Ditto
3. Amritsar City .. Amritsar District
4. Amritsar Cantt .. Ditto
5. Batala .. Gurdaspur

The draft valuation lists in these rating areas have since been published and due opportunity has been afforded to the assessees to file objections within thirty days from the date of publication of the lists. In case they feel aggrieved by the enhancement of the Gross Rental Value by the assessing authority, they can further seek legal remedy by filing appeals/ revisions as provided under the Act.

2. It is not desirable to grant general exemption in these areas as that would cause substantial loss to Government. It may be added that the approximate income from each of the rating area in border districts is as under:—

Sr. No.	Rating area	District	Approximate income
			Rs
1.	Moga	.. Ferozepur	2,17,145
2.	Mukatsar	.. Ditto	1,00,729
3.	Gidderbaha	.. Ditio	40,213

S. No.	Rating area		District	Approximate income
				Rs
4.	Malout	..	Ferozepur	85,675
5.	Abohar	..	Do	1,18,101
6.	Ferozepur City	..	Do	1,45,982
7.	Ferozepur Cantt	..	Do	80,487
8.	Zira	..	Do	16,380
9.	Basti Tankanwali	..	Do	10,850
10.	Fazilka	..	Do	76,000
11.	Jallalabad	..	Do	20,000
12.	Guru Har Sahai	..	Do	14,237
13.	Amritsar City	..	Amsitsar	13,68,192
14.	Amritsar Cantt	..	Dc	6,033
15.	Tarn Taran	..	Do	58,743
16.	Patti	..	Do	27,764
17.	Jandiala	..	Do	27,211
18.	Pathankot	..	Gurdaspur	2,62,000
19.	Gurdaspur	..	Do	70,000
20.	Batala	..	Do	1,61,529
21.	Dhariwal	..	Do	2,500
22.	Dina Nagar	..	Do	16,170
23.	Sujanpur	..	Do	9,527
24.	Dalhusie	..	Do	25,763

It may be mentioned that the Dalhousie rating area already stand exempted from the levy of property tax for the year 1965-66 and Dalhousie Cantt. rating area up to 31st March, 1967.

3. In view of the fact that general exemption from the payment of property tax will entail huge loss to Government and particularly since there is hardly any justification for general exemption, it is not possible to take any decision on these lines. However, Government is prepared to consider individual-cases of hardship on merit if applications are made by persons actually affected by enemy bombing.

Statement in reply to Call-Attention Notice No. 213 regarding anti-prohibition policy of the State Government.

The State Government have broadly accepted the recommendations of the Tek Chand Committee on prohibition. These are to be discussed by the Chief Ministers and Excise Ministers of all the States in a meeting to be convened by the Government of India. Further action in the matter will be taken in the light of decisions to be arrived at in the said meeting.

2. The Council of Ministers in their meeting held on the 6th October, 1965, however, decided that the civilian clubs in the districts of Amritsar, Ferozepur, including Fazilka, and Gurdaspur, including Pathankot, should be given temporary Bar licenses for a period of three months for the convenience of the servicemen, United Nations Observers and other foreign visitors.

3. In accordance with this decision of the Council of Ministers, the Excise and Taxation Commissioner has issued instructions to the Deputy Excise and Taxation Commissioner, Jullundur Division, to issue licences to three clubs at Amritsar. These licenses are being issued on temporary basis for three months only. In respect of others, the matter is still under consideration.

———

Statement in respect of Call-Attention Notice (Serial No. 220) by Sarvshri Kulbir Singh and Satya Dev, regarding defective drainage at Faridabad New Township.

It is true that an unfortunate death took place of an infant aged less than one year when he crawled into a drain in Industrial Township, Faridabad while he was unattended to by his mother or other members of the family. This is the second case of death and it is incorrect that 10 accidents of this nature have so far taken place.

2. The drains in the Industrial Township, Faridabad, are about 80 miles in length having width ranging between $1\frac{1}{4}'$ to $60'$. These are meant only for storm water and do not possess the usual regular flow because of their faulty gradients and lack of disposal arrangement at the end. This naturally results in water about one feet deep standing therein at many places. These defective drains are the legacy of the Faridabad Development Board from which the present Municipal Committee took over on 1st January, 1961. The Committee is, however, fully seized of the drainage problem and has been endeavouring all along to tackle it to the best of its meagre resources. When the committee took over, there were only 73 sweepers but now there are 190; and all possible efforts are made to clean the roads and drains in a much better manner than before. The drains are being cleaned, with a limited staff, after 15 to 25 days, but, despite best efforts, the water remains standing in the storm-water drains which are otherwise defective. Obviously, the trouble will continue to a more or less extent so long as the 80-mile long storm-water drains exist and are not replaced by underground sewerage.

3. With the view to overcome this nuisance, the Municipal Committee Faridabad resolved to have an underground drainage scheme at an estimated cost of Rs 59,80,158 in seven phases. This work could

not be taken in hand earlier by the Committee due to its lean finances. The Government of India was approached in the matter but they did not agree to finance the sewerage scheme of this Township. The Committee therefore, decided to levy new taxes to increase its income so as to enable it to take up the scheme. They raised a loan of Rs 5,00,000 from the Life Insurance Corporation for this purpose, and deposited Rs 5,65,000 with the Public Health Branch of the Punjab P.W.D. for the execution of the first phase of the drainage seheme on 27th July, 1964. The Committee further deposited a sum of Rs 1,65,000 on 9th March, 1965 for this purpose, and another sum of Rs 1,00,000 on 7th May, 1965, for making temporary disposal arrangement for the storm water. The work is being executed by the Punjab P.W.D. Public Health Branch and it is expected that the first phase will be completed during the current financial year. In addition, the Committee has applied for another loan of Rs 5 lakhs during the current year and for still another loan of Rs 25 lakhs for this schemes under the Fourth Five-Year Plan. The full drainage scheme will, never the less, take about 7 years to complete, subject to the availability of necessary funds.

AJMER SINGH

Planning and Local Govt. Minister.

Dated, Chandigarh.
the 14th December, 1965.

Statement in respect of Call-Attention Notice No. 222 given by Sardar Jasdev Singh Sandhu, regarding the merger of Municipal Committee Rajpura with the Notified Area Committee Rajpura Township.

On receipt of representations from certain persons and associations of Rajpura Township and of Rajpura Town, the proposals regarding conversion of Notified Area Committee, Rajpura Township into a Municipal Committee or the merger of the Notified Area Committee, of Rajpura Township with the adjoining Municipal Committee, Rajpura, were examined and it was decided that the Notified Area Committee Rajpura Township should be merged with the Municipal Committee, Rajpura. The preliminary notification for inviting objections for the extension of the limits of Municipal Committee, Rajpura in order to include therein the area comprising Notified Area Committee Rajpura Township, was also issued under section 5 of the Punjab Municipal Act, 1911. The objections received thereto were considered and it was observed as under :—

(i) Under the Punjab Municipal Act, it was not possible to give representation to the residents of the Notified Area Committee Rajpura in the amalgamated Municipal Committee, of Rajpura through the members of Notified Area Committee till general elections to the new Committee were subsequently held. In fact, there is no provisions in the existing Punjab Municipal Act for the merger of the two adjoining urban local bodies into one Municipal Committee. According to the existing law, limits of a Municipal Committee can be extended so as to include adjoining area but the effect of such extension of limits is that the proposed Municipal Committee continue to function till the next elections and representation is

given to the newly extended area in the interim period. If the limits of Rajpura Municipality had been extended under the extant law so as to include Notified Area Commmttee Rajpura Township, the latter local body would have got no representation in the bigger local body which was not considered desirable.

(2) The Municipal Committee, Rajpura could not be forced to take up the liabilities as well as the employees of the Notified Area Committee Rajpura Township.

2. The law was thus considered inadequate to effect smooth merger of the two local bodies. It was, therefore, decided to acquire powers by enacting necessary legislation through the State Legislature n order to overcome the above-mentioned difficulties. The amending egislation was firstly proposed to be introduced in the Autumn Session 1965) or in the next Budget Session (1966) of the State Legislature. But subsequently it was not considered to be advisable to introduce a separate amending Bill and it was decided that an amendment be introduced in the Municipal Bill, 1963, The said Bill is, at present, under the consideration of the Regional Committees of the State Legislature. The merger of the two local bodies will be effected as soon as the new Municipal Bill, 1963, is enacted by the State Legislature.

P. N. BHALLA
Secretary to Government, Punjab,
Local Government Department.

Statement by the Irrigation and Power Minister in connection with Call-Attention Notice (Serial No. 223) by Sardar Jasdev Singh Sandhu, M.L.A., regarding construction of bridges.

The Panchayat Samiti Bhunerheri requested for permission for the construction of the following bridges :—

(i) R. D. 12,600 Fatehpur Minor,

(ii) R. D. 15,700 Shekhupura Minor, and

(iii) R. D. 44,353 Arnauli Disty.

Designs for the bridges at R.D. 15,700 Sheikhupura Minor and R.D. 44353 Arnauli Disty. have been approved while that for the bridge at R. D. 12,600 Fatehpur Minor is under scrutiny. The Superintending Engineer, 1st Bhakra Main Line, Circle, has been asked to approve the same immediately.

However, permission to allow the Panchayat Samiti to construct these bridges according to the designs approved by the Irrigation Department involves a policy decision with regard to the levy of or waiving off the Departmental charges in such cases and is under consideration of Government.

REPLIES TO STARRED QUESTIONS CONVERTED INTO UNSTARRED QUESTIONS

REPORT INTO THE RIOTS OCCURRED AT JULLUNDUR DURING JULY/AUGUST, 1965

***8463 (c.u.)Comrade Ram Chandra** : Will the Minister for Home and Development be pleased to lay on the Table of the House a copy of the report, if any, submitted by the Judicial Officer appointed by the Government to enquire into the facts and causes of the riots which occurred at Jullundur between the students and the Transport workers during July/August, 1965 ?

Sardar Darbara Singh : The Judicial Enquiry ordered by the Punjab Government to look into the causes which led to the clashes between students and Punjab Roadways staff at Jullundur in August, 1965, is still in progress.

ARRESTS OF PAKISTANI INFILTRATORS IN PUNJAB STATE

***8498 (c.u.)Comrade Ram Chandra** : Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

(a) the total number of Pakistanis arrested for un-authorised entry into the Punjab State since August 1, 1965 ;

(b) the number of Pakistani spies and infiltrators, if any, arrested within the State during the above-mentioned period ?

Sardar Darbara Singh : (a) Fifty-four.

(b) It is not in public interest to place the details regarding Pak. Spies on the floor of the House because their desclosure will not only jeopardise our counter espionage measures but will also alert the Pak. Espionage services.

REVISION OF MINIMUM WAGES OF CERTAIN TRADES IN THE STATE

***8499 (c.u.)Comrade Ram Chandra** : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the total number of trades in the State in which the revision of minimum wages is due ;

(b) the reasons for the delay in the appointment of a Minimum Wages Committees for the purpose ?

Chaudhri Rizaq Ram : (a) Fourteen.

(b) Committee for revising minimum wages in ten employments have yet to be appointed. Recommendations for this have been received by Government and the matter is likely to be finalised shortly. It could not be finalised earlier as the necessary particulars of the representatives of the employers, employees and independent members for constitution of these Committees had to be ascertained by the field staff which took quite some time on account of the field staff's multifarious pre-occupation.

CASES OF SACRILEGE OF TEMPLES ETC.

***8522 (c.u.)Comrade Ram Chandra :** Will the Minister for Home and Development be pleased to state the number of cases of sacrilege of Hindu Temples and idols and Gurdwaras reported in the State during the years 1964-65 and 1965-66 (to date) together with the action taken by the Government in each case ?

Sardar Darbara Singh : Three sacrilege cases, all pertaining to Gurdwaras were reported during the year 1964-65. Two of these cases were sent as untraced. The third case was tried and the accused was convicted and sentenced to six months rigorous' imprisonment.

Nine sacrilege cases (8 pertain to Gurdwaras and 1 to Hindu temple) were reported during the year 1965-66 (upto 8th September, 1965). The police investigation has revealed that three cases were accidental. Two cases were traced and challaned in court. Out of these two cases, conviction has taken place in one case and the accused has been sentenced to six months' rigorous imprisonment and the other case is pending in court. The remaining four cases including one of Hindu temple are still under investigation.

ENQUIRY AGAINST SARPANCH OF REHAN PANCHAYAT IN INDORA BLOCK, DISTRICT KANGRA

***8524 (c.u.)Comrade Ram Chandra :** Will the Minister for Home and Development be pleased to state—

(a) the details of the allegations into which an enquiry was held against Shri Narsing Dial, Sarpanch of Rehan Panchayat, in Indora Block, district Kangra together with the result of the enquiry and the orders, if any, passed by the Minister thereon;

(b) the date when the said orders were conveyed to the Deputy Commissioner, Kangra along with the instructions, if any, issued to him in this behalf;

(c) whether any action has been taken by the said Deputy Commissioner, to implement these orders ; if so, when and the details of the action so taken ?

Sardar Darbara Singh : A statement is placed on the Table of the House.

STATEMENT

(a) (i) Two enquiries one by the Deputy Commissioner, Kangra and the other by the Assistant Director of Panchayats, Jullundur Division, were held against Shri Narsing Dial, Sarpanch, Gram Panchayat Rehan. Details of allegations are mentioned in the enclosed Appendix 'A'.

(ii) The first enquiry conducted by the Deputy Commissioner, Kangra had contained four allegations. These allegations were not substantiated and the papers were filed.

(iii) The second enquiry was conducted by the Assistant Director of Panchayats, Jullundur Division. It contained sixteen allegations as mentioned in Part II of Appendix 'A' out of which allegations, 6, 14, 15 (partial) and 16 had been proved against the Sarpanch. The Minister had ordered thereon that a copy of the enquiry report of the Assistant Director of Panchayats, Jullundur Division may be supplied to the Deputy Commissioner, Kangra to take action as recommended by the Assistant Director of Panchayats.

(b) The orders were communicated to the Deputy Commissioner, Kangra on 15th July, 1965 requesting him to take necessary action in the light of the report and the suggestions of the enquiry officer.

(c) The Deputy Commissioner, Kangra,—*vide* his orders dated 8th October, 1965 has placed Shri Narsing Dial, Sarpanch under suspension as provided under section 102 (1) of the Punjab Gram Panchayat Act, 1952, as amended upto date.

APPENDIX 'A'

PART I.—Details of allegations of first enquiry conducted by the Deputy Commissioner, Kangra.

(i) The Sarpanch has constructed a shop on land of the Girls Primary School, Rehan donated for the public good by a local family.

(ii) He is in illegal possession of about a kanal of land of Shamlat deh near the Government Higher Secondary School, Rehan.

(iii) He ejected forcibly and unlawfully Chuhru Ram from the land comprised in Khasra number 230 measuring 7 Kanals 13 marlas which he had been cultivating for the last 60 years taking undue advantage of his position as the Sarpanch.

(iv) Although this item was not mentioned in the complaint it was alleged before the Sub-Divisional Officer (Civil), Nurpur who was investigating the complaint that one Dulo Ram at the instance and instigation of the Sarpanch had planted an orchard in the land comprised in Khasra No. 406 measuring 15 kanals which vested in the Panchayat and had been earmarked for the construction of a hospital.

PART II.—Details of allegations of other enquiry conducted by the Assistant Director of Panchayats, Jullundur Division.

(1) That the Sarpanch Sh. Narsingh Dyal has constructed a shop on the land meant for the Girls Primary School, Rehan donated for the Public cause by a local family.

(2) That he is in illegal possession of about a kanal of shamilat land near the Government Higher Secondary School.

(3 That he ejected forcibly and unlawfully one Churu Ram from the land comprised in Khasra No. 230 measuring 7 Kanals 13 marlas which he (Churu Ram) had been cultivating for the last 60 years, taking undue advantage of his position as Sarpanch of the Panchayat.

(4) That one Dolo Ram at the instance and instigation of Sarpanch has planted an orchard in the land comprised in Khasra No. 406 measuring 15 kanals which vasted in the Panchayat and had been earmarked for the construction of Hospital.

(5) That the sarpanch adopted partisan attitude while advising the professional tax officer of the Panchayat Samiti Indora, in the assessment of the professional tax and thus the tax has been assessed most arbitrarily without any notice to the assessees, and that the assessment of the professional tax against this Sarpanch (Narsing Dayal) is only Rs 10 where as proprietors of similar business concerns have been assessed professional tax is up to Rs 63.

6. That the Sarpanch Shri Narsingh Dyal failed to hold any gram sabha meeting and never laid before the public the budget and accounts of the Panchayat and that he also did not take any interest to earn any grant from the block budget for this village although he was Chairman of the Standing Committee No. 3 of Panchayat Samiti, Indora.

7. That the radio receiving-set with the panchayat is not being properly used and is lying out of order since long thereby the public has been deprived of the day-to-day information broadcast by the A.I.R. especially during the Rural Programme Timings.

8. That the Sarpanch failed to collect any Royalty for the Panchayat from the contractors who used huge quantity of stone bullets, on the works completed by them, out of the Panchayat land.

9. That the Panchayat failed to utilise its land adjacent to the main road as it could be leased out for errecting business stalls to attract prospective bidders or the Panchayat ought to have constructed residential quarters under the Revenue Earning Scheme which could easily earn decent revenue to the Panchayat.

10. That some years back the Panchayat received a grant for the construction of Talab for drinking-water purposes but the scheme has not been executed so far.

11. That the Sarpanch took Begar from one Munshi Ram, son of Beli Ram of village Raur included in this Panchayat and another Rania Ram, son of Larja Ram and on their refusal to comply with the wishes of the Sarpanch at certain juncture both of them were unnecessarily harassed and were got haulled up by the police authorities as suspects in a theft case.

12. That the Sarpanch allowed one Rania Ram, son of Larja Ram of village Raur included in this Panchayat to errect a stall near the School assuring him that if he (Rania Ram) continued rendering some service to the Sarpanch no action will be taken against him at the Panchayat level, but later on when he could not continue serving him (Sarpanch) for long he was unnecessarily harassed and was subjected to unnecessary interrogation by the police authorities under false suspicion created by the Sarpanch in a theft case which occurred in the house of a lady, i.e., auntee of the Sarpanch.

13. That the Panchayat Rehan specially Shri Narsingh Dial, Sarpanch fined one Rania Ram a sum of Rs 25 for constructing a shop and Rania Ram was not supplied copy of the Panchayat order in spite of the fact he applied for the same on 18th April, 1965.

14. That the Panchayat disposed of old material of the old Girl School by sale and the sale-proceeds have not been accounted for.

15. That the Sarpanch arranged for the construction of culvert through one contractor Shri Bani Ram without inviting tenders in a regular manner and the tenders, so invited and placed on file by him are simply fictitiously.

16. That the Sarpanch had been retaining panchayat funds in his custody in excess of the authorised limit of Rs 50 from time to time which is irregular.

FOREIGNERS ARRIVING IN THE STATE FROM PAKISTAN

***8636 (c.u.) Comrade Ram Chandra :** Will the Minister for Home and Development be pleased to state whether the State Government maintain any record as to the number of foreigners who arrive in Punjab from Pakistan so as to find out if any of them are over-staying in the country?

Sardar Darbara Singh : The reply is in affirmative.

POLITICAL DETENUS

***8713 (c.u.) Comrade Shamsher Singh Josh :** Will the Minister for Welfare and Justice be pleased to state —

(a) the total number with names of Political detenus at present detained under the D.I.R. in various Jails of ths Punjab ;

(b) the daily diet allowance given to each of the said detenus ;

(c) whether any family allowance is being given to them, if not, the reasons therefor?

Sardar Darbara Singh : (a) 59 (List giving the names of detenus is placed on the Table of the House)

(b) 'A' Class detenus : @ Rs 2.75 per day

'B' ,, ,, : @ Rs 2.25 ,, ,,

'C' ,, ,, : on the same scale as allowed to criminal prisoners of 'C' Class

(c) No. Family allowance is granted by the State Government on an *exgratia* basis, in those cases in which it is satisfactorily proved that the detenu was the bread-winner and his detention has substantially affected the means of subsistence of his family. As this condition was not fulfilled in any case, the representations, received from detenus for the grant of family allowance, were rejected.

List of the names of detenus

Sarvshri

1. Rachhpal Singh
2. Chhattar Singh
3. Mange Ram Vats
4. Raghbir Singh Jhakhar
5. Udhe Singh Keshav
6. Gian Singh
7. Dharam Singh
8. Ishar Singh
9. Gurbakhash Singh
10. Mehar Singh Khanpni
11. Prof. K. R. Palta
12. Dr. Bhag Singh, Ex-M.L.A.
13. Chanan Singh Dhut
14. Ram Kishan Bharolian
15. Bhag Singh Sajjan
16. Harkishan Singh Surjit
17. Kishori Lal Rattan
18. Gurcharan Singh Randhawa
19. Pt. Bakhshi Ram
20. Gurbux Singh Atta
21. Sarwan Singh Cheema
22. Dhanpat Rai Nahar
23. Kesar Singh
24. Gandharav Sen
25. Satwant Singh
26. Rachhpal Singh
27. Bhajan Singh
28. Chanan Singh Brar
29. Daya Singh Prem
30. Dalip Singh Tapalia

Sarvshri

31. Fauja Singh
32. Makhan Singh Tarsika
33. Hazura Singh
34. Darshan Singh Jhabal
35. Hazara Singh Jassar
36. Kartar Singh Gujapir
37. Bishan Singh
38. Sulakhan Singh
39. Amarmeet Singh
40. Prem Chahd Bhardwaj
41. Bhim Singh Advocate
42. Harnam Singh Chamak
43. Hardit Singh Bhattal
44. Vidya Dev Longowal
45. Ghuman Singh Ugrahan
46. Partap Singh Dhanaula
47. Dalip Singh Bhatiwal
48. Janak Singh Bhattal
49. Ganda Singh
50. Gajjan Singh Tandiana
51. Karnail Singh Phide
52. Ram Singh Harinau
53. Gurnam Singh Sibbian
54. Balbir Singh
55. Dharam Singh Kasni
56. Devki Nandan
57. Satya Mandan
58. Ganpat Singh
59. Mangal Singh

COMMUNIST M.L.A. DETENUS

***8714 (c.u.) Comrade Shamsher Singh Josh :** Will the Minister for Welfare and Justice be pleased to state —

(a) the class in which the Communist M.L.A. detenus are being kept in the Jails;

(b) the details of the allowances and other facilities given to the said detenus?

Shri Chand Ram : (a) 'A' Class.

(b) (i) Diet allowance @ Rs 2.75 per day.

(ii) Toilet allowance @ Rs 7 (lump sum).

(ii) Washing soap @ 1 Kg. per month.

(iv) Facilities like interviews, supply of newspapers, etc., available to various detenus are also provided as admissible under the Punjab Detenus Rules, 1950.

1603—24-3-66—384—C., P. and Pb., Patiala

Replies to Starred Questions received late from Government

COMPLAINTS REGARDING NON SUPPLY OF WATER FROM TAPS ERECTED IN 54 VILLAGES IN TEHSIL NUR PUR, DISTRICT KANGRA

***8378. Comrade Ram Chandra :** Will the Minister for Health be pleased to state whether the Government have received complaints to the effect that due to inadequacy of the supply of electricity, water taps erected in 54 villages around Rehan in tehsil Nurpur, district Kangra do not supply water regularly; if so, the action taken thereon ?

Shrimati Om Parkash Jain : (a) Yes. Defects have been removed.

COLLECTIONS MADE TOWARDS NATIONAL DEFENCE FUND FROM DISTRICT HISSAR

***8760. Shri Jagan Nath :** Will the Chief Minister be pleased to state the details of the amounts in cash, gold, silver and clothes collected during September and October, 1965, from district Hissar, tehsil-wise, towards the National Defence Fund ?

Shri Ram Kishan : No contribution in the form of cash, gold, silver or clothes was collected during September and October, 1965, from district Hissar, towards the National Defence Fund.

VISITS BY MINISTERS TO SANGRUR DISTRICT

***8779. Comrade Bhan Singh Bhaura :** Will the Chief Minister be please to state—

(a) the names of the Ministers who visited Sangrur District in the month of September, 1965 alongwith the names of places where they addressed rallies;

(b) whether the legislators of the said district were informed about the said tours etc., if not, the reasons for the same ?

The answer to Starred Vidhan Sabha Question No. 8779, appearing in the list of Questions for the 4th November, 1965 and standing in the name of Comrade Bhan Singh Bhaura, M.L.A. is not ready. The information is sent to the Speaker, Punjab Vidhan Sabha, who is requested to extend the date under proviso (ii) to rule 41 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly. This

Question may kindly be included in the list of Questions for any date after the 20th November, 1965.

Sd/-
Chief Minister, Punjab.

To,

The Speaker,
Punjab Vidhan Sabha,
Chandigarh.

U.O. No. 10928-Pol(1P)-65, Dated Chandigarh, the 3rd November, 1965.

Replies to Unstarred Questions received late from Government

RESIDENTIAL QUARTERS FOR INDUSTRIAL WORKERS IN ROHTAK

2951. Sardar Kulbir Singh : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) whether any amount was received by the Labour Department authorities as cost of the Hand Water Pump from the occupants of Quarter No. 23 built for Industrial Workers in Sonepat; if so, how much and the circumstances leading to the receipt of the amount;

(b) whether any of the occupants of the said quarter were asked by the Labour Inspector in October, 1964, to vacate the said quarter; if so, their list and the reasons for the same;

(c) whether any representation was received by the Labour Inspector in reply to the notice for vacating the quarter by the Industrial Workers occupying this house; if so, a copy of the same be laid on the Table;

(d) the extent to which the points raised in the said representations were found to be correct and the decision taken in the matter.

Sardar Prem Singh Prem : (a) No.

(b) Yes. Shri Jia Lal an unauthorised occupant of quarter No. 23 was asked by the Labour Inspector, Sonepat in September, 1964, to hand over the possession of the house which had been allotted to one Shri Mahesh Chand. Shri Jia Lal had occupied the quarter illegally and without any proper allotment.

(c) Yes. A copy of the representation of Shri Jia Lal is laid on the Table.

(d) The points raised in the representation were denied by the Labour Inspector, Sonepat and he wrote to Shri Jia Lal that he never verbally or otherwise permitted him to occupy the quarter.

To

The Labour Inspector,
Punjab Government, Sonepat.

Re. Allotment of quarter No. 4/13-Industrial Colony, Sonepat.

Kindly refer to the eviction Notice served on me *vide* No. 3853, dated 25th September, 1964 by the S.D.O..P.W.D. (B & R), Sonepat, copy to you asking me to vacate the above noted quarter, failing which I will be forcibly evicted.

In this connection I beg to state that I was living in Nihal Nagar and was waiting for my turn for the allotment of a Government quarter as my number on the waiting list stood at No. 194. Suddenly in the last week of September, 1964 the flood came and the house in which I was living was inun-dated and my friend and relatives evacuated me along with my family out of that place. Most of my household effects got damaged and became unserviceable. In this distress (especially when my wife is in the family way) I approached your goodself to allot me a quarter as a special case on compassionate grounds. You were kind enough to permit me verbally on 13th October, 1964 to occupy the said quarter which had luckily fallen vacant, on the under-standing that the same will be allotted to me in due course. I also understand that many persons much junior to me on the waiting list, have since been allotted accommo-tion and my name has been omitted probably through an over-sight. The receipt of notice in question has completely upset me and I request you to kindly regularise the allotment of the said quarter to save me from a financial ruin as I am a low paid employee and cannot afford a costly place, and the S.D.O. advised accordingly. I shall ever remain grateful to you for this act of kindness.

Yours faithfully,
Sd/-
(JIA LAL) GOSWAMI,
Inspection Section,
Atlas Cycle Factory, Sonepat.

Dated 6th October, 1964

Statements in reply to Call Attention Notices received from Government at Printing stage.

REPLY TO THE CALL ATTENTION NOTICE (S. NO. 6) BY COMRADE BABU SINGH MASTER, M.L.A.

Sardar Gurdial Singh Dhillon : The Indo-Pakistan hostitilies brought in its wake a host of problems relating to the grant of relief to the uprooted persons numbering more than 50,000 resettlement of farmers businessmen, rehabilitation of industrial economy and providing employment opport-unities to as many as 46,000 workers thrown out of employment. Of the uprooted persons, about 5,000 persons are residing in tents, where they have been provided tented accommodation while the remaining about 45,000 persons are living with their relatives or friends. Immedia-ately after the cease-fire, the problems of providing relief and resettlement were sized up and various measures aimed at providing food, shelter, and immediate relief to the uprooted persons were adopted. The uprooted persons and their cattle are being provided food, cash doles and fodder or cash in lieu thereof at the following scale irrespective of the person being inmates of the camps or putting up with their relatives and friends :—

	For one Adult per mensem	For one child per mensem
1. Wheat Flour/Wheat	16 K.G.	10 K.G.

	For one Adult per mensem	For child per mensem
(2) Cash grant for purchase of Dal, Ghee, Sugar, Salt, Tea, Etc.	Rs. 18.00	Rs. 9.00
(3) Cattle per head per day.	Rs. 0.50	

At the close of the month of December, 1965, 17,174 quintals of wheat or wheat flour had been distributed to these persons. An amount of Rs. 19,69,0654 had been distributed as cash doles in lieu of other items of ration, e.g., tea, ghee, salt and other condiments etc., and an amount of Rs. 21,681 had been disbursed as grant for cattle fodder. Further, 45,145 pounds of milk powder had been distributed for use of children, aged and infirm persons, expectant mothers etc.

With a view to saving them from the rigours of cold weather, 25,414 quilts have been distributed and of the 1,436 blankets received through private donation, 822 have since been distributed among the uprooted persons. Every possible effort had also been made to get durries manufactured in the shortest possible time and of the 20,000 had been distributed among the uprooted persons.

Each adult resident of a Camp had a quilt and a durrie given to him by end of December, and with a view to enabling the uprooted persons to purchase one set of waring apparel each, cash doles at the rate of Rs. 17/- per male, Rs. 16/- per female and Rs. 7/- per child are being given and it is estimated that the total expenditure on this account will be to the tune of Rs. 8.47 lacs.

To facilitate early resettlement of the uprooted persons, funds to the extent of Rs. 10 lakhs have been allocated to the Deputy Commissioners of the three border districts for advancing interest free relief loans ranging from Rs. 1,000 to 5,000 for agricultural and businesses purposes. The loan will be recovered in 10 easy instalments and recovery would start two years after the permanent rehabilitation of the loanees.

Of the 46,000 workers, 33,583 were industrial labourers and workers. As the problems of providing employment opportunities and rehabilitation of the industrial economy are intimately connected to each other, a number of relief measures aimed at revival of industry economy such as postponement of recovery of various taxes, grant of loans, obtaining orders for manufacture and supply of goods from the Director General of Supplies and Disposal, securing supply of raw material, ensuring availability of liberal credit facilities and creating a sense of normalcy have been taken. With the revival of the industrial activity as many as 14,606 industrial workers had been reemployed towards the end of the month of November, 1965. The work relating to repair, reconstruction and widening of the following roads and bridges has also been undertaken and instructions have been issued for the employment of the uprooted persons as labourers on these works:—

(i) Bhikiwind Khemkaran Road;

(ii) Bhikiwind Khalra Road;

(iii) Amritsar-Bhikiwind Harike Road

(iv) Jandiala Guru—Tarn Taran Road;

(v) Patti Khemkaran Road;

(vi) Moga-Harike Road; and

(vii) Dharamkot-Isa Khan-Zira Road.

Lastly, to provide relief to the unemployed industrial workers scheme was adopted in November, 1965, for advancing interest free loans to the industrialists for enabling them to make advances therefrom to the individual unemployed workers. As some of the industrialists were hesitant to accept the financial responsibility on behalf of the un-unemployed workers, another scheme has been framed whereunder the Labour Commissioner has been empowered to advance intrest free loans recoverable in easy instalments to the extent of Rs. 200/- or two months average pay, whichever is less, direct to the unemployed worker. A sum of Rs. 10 lakhs has been placed at the disposal of the Labour Commissioner for this purpose. As such, it is incorrect to say that the State Government has in any way, been remiss in its functions of granting relief to the uprooted persons and providing employment opportunities to the unemployed workers.

———

Reply to the Call Attention Notice (S. No. 51) by Comrade Shamsher Singh Josh, M.L.A.

Sardar Gurdial Singh Dhillon : As a result of the Indo-Pakistan hostilities 132 Government servants in Khem Karan area of Amritsar District and in Fazilka area of Ferozepur District were dislocated from their places of postings, but all of them were immediately absorbed in their respective Departments. Besides, 31 employees of Khem Karan Municipality were also uprooted and 15 had already been absorbed against suitable posts. The particulars of the remaining uprooted employees of the Local Body have already been circulated among all the Deputy Commissioners and the various Local Bodies in the State to the Director of Employment for arranging their absorption on preferencial basis. Further to provide relief to these unabsorbed employees, they have been paid their salaries for the months of September, October and November through the Executive Officer, Municipal Committee, Patti.

2. As regards the grant of relief concession, these Government servants and the employees of the Local Body were treated at par with other uprooted persons till the 3rd week of November, 1965, when consequent upon their absorption being provided with means of sustenance, the grant of relief such as wheat ration, cash doles, etc., were stopped Relief is granted to the uprooted persons, who have no other ostensible means of livelihood and is not paid as a compensation for any type of loss. However, the Government servants whose families were residing in the areas, occupied by the Pakistan Armed Forces and where they had some source of livelihood which had been denied to them on leaving their villages are still being given relief in accordance with the prescribed scales. As these Government servants were absorbed immediately in

their respective departments, the question of advancing them loans or sanctioning any grant for their resettlement does not arise.

3. Books and stationery articles are being supplied free to the children of the uprooted persons including those of the uprooted Government employees by Philanthropic organization. In addition to this the amounts of Rs. 4,000 for Amritsar District and Rs. 4,000 for Ferozepur District have been sanctioned for meeting the expenses of the students whose parents/guardians were uprooted towards their fees (tuition fees and other charges), hostel charges, admission fee for examinations to be conducted bythe Education Department/Universities and for free supply of books/ articles of stationery. The Principals/Headmasters of the local schools have been advised not to charge any tuition fee and hotel fee charges, etc. from such students.

4. As regards the question of issuing free duplicate copies of the certificates, the rules of the Punjab University do not allow it, but in view of the special circumstances, the matter is being placed before the Syndicate of the Punjab University.

5. As such there is no reason to believe that the Government servants and the employees of the Local Bodies have not been granted any relief or there has been delay in their absorption.

STATEMENT

Dr. Mangal Sein, M.L.A., tabled a Call Attention Motion No. 76 in the Punjab Vidhan Sabha on 23rd October, 1965, regarding the suicide committed by Shri Inder Mohan Chopra, Inspector of Police.

2. The facts of the case in brief are as under :—

Shri Inder Mohan Chopra, Inspector of Police committed suicide in his residential quarter in the District Police Lines, Rohtak on 23rd October, 1965, by shooting himself with a Service Revolver. He was a good Police Officer with clean and sobre habits and generally enjoyed the esteem of his colleagues and subordinates. He was posted as District Inspector and held the supervisory charge on Police Station Kalanaur.

Three folded loose sheets of paper were recovered from Shri Chopra's shirt at the time of committing suicide which contained the following matter.

1. One of these papers indicated the addresses of his near relations. This paper was signed and dated.

2. The second note was on Shri Chopra's personal printed letter-head and indicated that he was dying as a coward and he implored the Government to look after the welfare of his children. This note was also signed and dated.

3. The third note mentioned some details of his insurance policies **and G.P. Fund. This note was neither signed nor dated.**

4. No other document indicating the reasons of committing suicide was recovered from the person of Shri Chopra or his personal effects, which were got searched after his death.

3. The Circumstances leading to the suicide by the deceased officer have been carefully enquired into but the real motive which compelled him to take this drastic step has not been established. The documents recovered from his dead body do not either give any indication of the state of his mind. However, the insinuation made in the motion has not been found correct from the documents recovered.

Statement in reply to Call Attention Notice

(*Serial No. 84*)

A decision regarding the removal of this statue from the Baradari Gardens, Patiala and its consignment to the State Museum has since been taken. The P.W. D. authorities who were directed to effect the removal have intimated that this is a specialised job. They are trying to obtain the services of a specialist who was associated with the removal of almost all the statues at Delhi. As soon as the statue at Patiala is removed, the fact will be intimated.

1698—5H.—66

Statement regarding Call Attention Notice No. 114 Item No. 4(v) admitted for 3rd October, 1964

Sarvshri Kulbir Singh and Satya Dev, M.L.A.s vide their Call Attention Notice No. 114 drew the attention of the Minister concerned towards the situation created by A.S.I. Teja Singh, by arresting Shri Wishwa Mitter Bashnoi, Secretary, Jan Singh and his father Sant Kumar u/s 107/151 Cr. P. C. in village Dotianwali, bringing them to Police Station Abohar, lodging them in Havalat, insulting, abusing and maltreating them and not allowing them any food because previously a complaint had been filed before DSP/Fazilka against this ASI. It was further asserted that some Mazhbis had killed a deer in fields of Wishwa Mitter to which the Bishnois took a strong exception and the ASI had injured the feelings of Bishnois by taking action against both the parties.

Enquiries made into these assertions show that there is no truth in these allegations. The A.S.I. had arrested Sarvshri Wishwa Mitter and Sant Kumar U/s 107/151 Cr. P. C. on the complaint of Chanan Singh who apprehended danger to his life from these persons, who had beaten him on 20th September, 1964 with sticks inflicting 3 injuries on his person. The ASI had arrested Chanan Singh on one side and Sarvshri Sant Kumar and Wishwa Mitter on the other as he apprehended breach of peace. Chanan Singh Showed his willingness to get himself bound down U/s 107 Cr. P. C. on 1st October, 1964. The proceedings against the other party were transferred from one Court to another and remained pending in as many as five courts. The matter being subjudice no statement could be made earlier. Both the respondents were finally discharged by

the court on 19th November, 1965 on the ground that the case had become more than one year old. The court had also directed that the proceedings against the respondents may be launched afresh if deemed necessary. The matter was looked into and it was found that due to lapse of time both the parties had patched up their differences mutually. As such no action was taken afresh.

In view of the facts that Shri Chanan Singh had been actually injured by the respondents, that he had got himself bound down U/s 107 Cr. P.C. and the enquiry report of D.S.P./Fazilka concluding that the allegations were incorrect, the A.S.I. was justified in taking preventive action against the respondents. No action is called for against the A.S.I.

Statement by Comrade Ram Kishan, Chief Minister, Punjab in reply to Call Attention Notice

(*Serial No. 130*)

A complaint regarding the use of coercion for the collection of National Defence Fund was received by the Government. It was sent to the Deputy Commissioner Bhatinda for enquiry and report. From the perusal of the enquiry report so far as it related to the collection of National Defence Fund, the allegations have not been substantiated.

As regards other allegations relating to the S. D.O. (Civil) Kotkapura and Food Inspector Faridkot, these were also enquired into and found to be baseless.

Statement in reply to the Call Attention Notice No. 131 by Sarvshri Kulbir Singh and Satya Dev, M.L.A.s

Sardar Gurdial Singh Dhillon : Uprooted inhabitants of the villages which are under the occupation of Pakistani forces as well as the uprooted residents of the areas to which civilians do not have access for various reasons have been and are being issued wheat at the prescribed scale on monthly basis. If the District authorities, after consulting the army authorities, are satisfied that any area is inaccessible for the civilians and the former residents of those areas do not have any gainful occupation now, it is in the power of District Authorities to issue cash doles and other formal sporadic *ad hoc* relief to the uprooted persons.

2. The criterion kept in view in demarcating border areas in Ferozepur, Amritsar and Gurdaspur Districts for grant of relief concessions is the extent of loss/damage caused to properties by enemy action or/and by our own Army's movement or camping. Accordingly it has been decided that land revenue and abiana for Kharif 1965 should be remitted in the areas falling within 10 miles of the International Border in Ferozepur District and further if a part of any village is situated within the said limit the orders of remission would apply to the entire village. It has

also been decided that the remission orders would apply to all the Operational Villages whether situate within the said limit or beyond it.

3. As regards the question of payment of compensation for the crops destroyed/damaged, this matter is engaging the attention of the State Government and the decision when taken on the question of payment of compensation or ex-gratia grants for the moveable properties damaged/lost/destroyed throughout the State due to enemy action would cover it also.

4. Accordingly, there is no reason to believe that any discrimination is being made against the residents of the affected villages or areas including those referred to in the Call Attention Motion.

Statement by Chief Minister, Punjab in reply to Call Attention Notice

(*Serial No. 159*)

The Fertilizer Corporation of India Ltd. Naya Nangal have already released 1,023 acres of land, out of which about 300 acres have not yet been taken over by the original land owners as they have not refunded the amount of compensation which amounts to Rs 5,93,438. The number of such owners is 810. The release of land has to be made under and in accordance with the provisions of the Land Acquisition Act and unless the compensation is paid, the land cannot be returned to the erstwhile owners.

2. The Fertilizer Corporation of India Ltd. have stated that it is not possible for them to lease out the surplus land, which has not been restored to the original land owners. They have, however, in the interest of agricultural production asked the Deputy Commissioner, Hoshiarpur, to allot this land for cultivation under the Land Utilisation Act, till the original land owners are in a position to pay for it. About 562 acres of the surplus land has already been placed at the disposal of the Deputy Commissioner, Hoshiarpur for cultivation under the said Act.

3. It may be mentioned that the Revenue Department's proposal to the Finance Department, for funds for grant of loans to those land-owners who are not in a position to buy back the land, released by the F.C.I., has been accepted by that Department. As soon as the necessary funds are made available, those will be placed at the disposal of the Deputy Commissioner, Hoshiarpur, for the grant of loans to those who will need it.

Statement by Home and Development Minister in reply to Call Attention Notice

(*Serial No. 167*)

Sardar Darbara Singh : A report of Shri B. R. Chadha, Additional D.I.G./P.A.P. was received about some grave irregularities in the

accounts of the construction of P.A.P. Pickets on the Amritsar Border. Consequently an audit party was sent to conduct the audit of the accounts of the Commandant, 33rd Battalion, P.A.P., Amritsar. Their report has since been received and is under examination.

Statement by the Irrigation and Power Minister, in Reply to Call Attention Notice (*Serial No. 181*) regarding outlets on distributaries of Sirhind Feeder.

With the completion of Chakbandi, the old outlets are required to be remodelled, so that equitable distribution of supplies is ensured. The size of these outlets is fixed according to the authorised discharge supply. Accordingly, the outlets of Mohorana Disty. system were remodelled and new outlets fixed. The outlets of Bhagwanpura Distributary have not been remodelled/removed so far because the Chakbandi has not yet been completed on this Distributary.

2. It is not a fact that irrigation has suffered due to the remodelling of outlets. On account of failure of rains, the supplies from the rivers are very low. To ensure proper utilisation and equitable distribution of water, the supplies in canals are being regulated on a rotational basis. The State Government are trying their best to provide maximum help to the cultivators in sowing the crops with the available supplies.

Statement by the Capital and Housing Minister, Punjab in reply to Call Attention Notice (*Serial No. 184*) Moved by Pandit Mohan Lal Datta, M.L.A., regarding levy of Property Tax at Chandigarh

In order to encourage the construction of Private houses in Chandigarh and thus accelerate the development of the Capital, it had been decided by the Government and the decision announced through a Press Note issued on 22nd May, 1959 (copy enclosed), to exempt the property in Chandigarh for 25 years from the operation of the East Punjab Rent Restriction Act, 1949, from Marla Tax and from the provisions of the Punjab Urban Immovable Property Tax Act, 1941 and the Punjab Municipal Act, 1911, for the purposes of House Tax and Property Tax. The levy of the property Tax on the properties at Chandigarh thus stands deferred.

Press Note

In order to encourage the construction of private houses in Chandigarh, the Punjab Government have decided to exempt Chandigarh for 25years from the operation of the East Punjab Restriction Act, from Marla Tax and from the provisions of the Punjab Urban Immovable Property Act, 1941 and the Punjab Municipal Act, 1911 for purposes of House Tax and Property Tax.

Similarly the security of tenure (Urban Immovable Property) Bill according to which residential/business premises beyond one unit of one house/one shop per individual are proposed to be declared as surplus, will also not appltyo Chandigarh for 25 years.

Statement by Captain Rattan Singh, Minister for Animal Husbandry and Agriculture in respect of Call Attention Notice

(*Serial No. 185*)

The prizes are awarded to the breeders of Haryana/Sahiwal Cows, Nili/Murrah Buffaloes etc., etc., by a Committee consisting of Deputy Director, Animal Husbandry, District Animal Husbandry Officer, Veterinary Assistant Surgeon of the area presided over by the Deputy Comimssioner. In October, 1962 a Cattle Fair Show was organised in District Amritsar. The Committee awarded prizes to the owners of Haryana/Sahiwal Cows and their heifers, Nili-Buffaloe, Bulls and their Heifers etc. The judging Committee was presided over by the Deputy Commissioner, Amritsar. Among other residents of Sialka Village who were also awarded prizes, a prize of Rs. 50, with one medal, was given to Shri Ranbir Singh, Sarpanch of village Panchayat, son of Shri Mohan Singh Malhi, the then Deputy Director, Animal Husbandry, Jullundur Division in respect of Haryana Cow Calf. This prize was awarded purely on merit as judged by the members of the Judging Committee.

Necessary corrections are made in the rough list, as and when become necessary, during the course of judging. Immediately after judging, the rough list is finally approved and signed by the competent authority. In the final list of prize winners, District Cattle Show Amritsar held on the 27th October, 1962, duly signed by the Deputy Commissioner, Amritsar, no cutting was made.

2. A sum of Rs. 372 was given to the Panchayat Deh Sialka, in the year 1960, District Amritsar, by the Deputy Director (Headquarters) Incharge Key Village Scheme, for the construction of Silo Tower for the conservation of fodder. The amount was accounted for in the panchayat's budget who have actually spent Rs 800 for the construction of a Silo Tower. The amount of Rs 372 was given to the Panchayat through its Sarpanch and not to Shri Ranbir Singh.

Statement by Chief Minister, Punjab in reply to Call Attention Notice

(*Serial No. 188*)

I submit in this connection that Government have called tenders for this purpose on 26th November, 1965. (The reply was given by the Chief Minister on the floor of the House on 24th November, 1965, in 'Hindustani' which has been translated into English).

Statement in reply to Call Attention Notice (*209*) asked by Shri Sampuran Singh Dhaula

---

Statement made by Shri Rizaq Ram, Minister for Irrigation and Power

As regards distributories, there are 2 such cases of bridges.

1. Villagers have demanded bridge at R. D. 59700 of Dhanaula Distributory for village road Kahneke to Dhaula. One fall-cum-village

Road bridge exists at RD 59375 and an other bridge exists in the vicinity at R.D 64340. As the site of new bridge RD 59700 lies within 3/4 mile of the existing bridge RD 59375, so the villages have to deposit the full cost of bridge as per standing instructions for new bridges. They have refused to deposit the amount. Approximate cost of the bridge is Rs. 9,000.

2. There is also a request for a bridge at RD 96650 Dhanaula Distributary for village Pakhokalan to Tapa. Following bridges exist in vicinity of the proposed site:—

1. V. R. Bridge RD 93750
2. Foot Bridge RD 95200
3. V. R. Bridge RD 98000

At present these three bridges are being used by the villagers. The new site lies within 3/4 miles of the nearest existing bridge site. In such cases villagers have to deposit the full cost of bridge as per rules. They have refused to deposit the amount. Approximate cost of the bridge will be Rs. 8,000. The bridge can only be constructed if the villagers deposit the amount.

The required information in respect of bridges on the drains is given below:—

Village Dhilwan : There is a village road connecting village Dhilwan with Ghunas Railway Station and crossing Lissara Nallah. near R.D. 23000. A bridge has been proposed at this site.

Bhaini Jassa and Fatehgarh Chhana : These villages fall on the left side of Dhanaula Drain and there is a village road connecting them with Hadiya Town which crosses Dhanaula Drain at R.D. 4000. A bridge has been proposed to be constructed at this site also.

The construction of both these bridges is, however, not possible at present due to paucity of funds.

Statement by Minister for Irrigation and Power in reply to Call Attention Notice No. 214 by Sardar Sampuran Singh Dhaula, M.L.A.

The area of the villages Kaleke Madan, Aspal Kalan, Kot Duna and Bandher are included in the catchment of proposed Kaleke Drain which would start from village Kaleke and will have its outfull into Lissara Nallah at R. D. 354000 left in village Rai Khana. The length of the proposed drain is about 33 miles. Out of which about 87 miles fall in the Bhatinda District and about 6 miles in the Sangrur District.

The drain would pass through the lands of about 20 villages in Sangrur and Bhatinda District.

1. Kaleke, 2. Badra, 3. Aspal, 4. Kot Duna, 5. Bhani Fatahh in Sangrur District and Village 1. Joga, 2. Anupgarh, 3. Ubha, 4. Burj Harike, 5. Gobindgarh, 6. Ghumman, 7. Kutiwal, 8. Maisar Khanna, 9. Ramgarh, 10. Muroawali 11. Garahi, 12. Kishangarh, 13. Jandoke, 14. Nanak Khana, 15. Rai Khanna, in Bhatinda District.

The lands of villages of Sangrur District are in the upstream reach while those of Bhatinda District are in the downstream reach.

It is mentioned in the Call Attention Notice that the villagers of villages Kaleke Aspal Kalan, Kot Duna and Bandher have offered their lands coming under the drain free of cost and also offered their free services for digging of the drain. In the first place, no such offer from those villages is available. In the second place, even if this offer would be there, it is not techanically feasible to dig the drain till the downstream 27 miles in Bhatinda District are also dug. No such offer from villages of Bhatinda District has been cited in the Call Attention Notice. It would be wrong to dig the drain only in upstream 6 miles without providing proper outfall, as otherwise it will accentuate flood situation in the downstream villages.

Statement in reply to Call Attention Notice No. 216, submitted by Shri Jagan Nath, M.L.A.

266 mm. of rain fell in the four months from July to October, 1965, whereas rainfall for the corresponding period in 1964, 1963, 1962 and 1961 was 739, 465, 350 and 533 mm., respectively. This Sub-Division has been having poor crops for the last three years. Number of villages in which more than 25% kharif crops had failed to mature in this Sub-Division is 206.

2. Financial Commissioner, Revenue, visited the drought-affected areas of Bhiwani Sub-Division twice, the first time from 18th October, 1965 to 20th October, 1965 and the second time in the first week of December, 1965. The Chief Minister, Revenue Minister and other Ministers visited Tosham in this Sub-Division on the 2nd of December, 1965.

3. *Relief Measures.*—Government is fully aware of the situation caused by drought in Bhiwani Sub-Division and other parts of Hissar District. Relief works, such as roads, *johars*, lift irrigation schemes and soil conservation works have been sanctioned to improve the economy of the affected areas and also to provide gainful employment to people in these areas. The following amounts have been sanctioned for Relief Works and other purposes:—

(1)	Construction of roads ..	Rs. 15,00,000
(2)	Digging of Johars ..	Rs. 500,000

(3) Lift Irrigation Schemes .. Rs. 48,58,000

(4) Soil Conservation Works .. Rs. 10,00,000

(5) Subsidy for fodder .. Rs. 1,75,000

(6) Water-Supply Schemes .. Rs. 8,50,000

This amount has been sanctioned in lieu of people's contribution to the scheme for which the Government of India has made special grant of Rs. 50 lakhs. The total cost of the scheme is Rs 70.95 lakhs. This scheme will serve 62 villages of Bhiwani Tahsil.

(7) Taccavi loans for purchase of seed and fodder .. Rs. 19,50,000

The roads sanctioned for Bhiwani Tehsil are the following—

(a) Tosham-Jui road .. 20 miles
(b) Mohammad Nagar-Bahl road .. 12 miles
(c) Sandawa to Patodi road .. 2½ miles
(d) Bajina-Dhani Mahu road .. 5 miles
(e) Naloi-Siwani road .. 6 miles

It is estimated that about 4,550 persons will be employed on the earth work of these roads for two months.

As regards Minor Irrigation Works, for which Rs. 45 lakhs have been sanctioned in the current year, work has started on the Gujrani, Khanak, Bhurtana, Dang and Halwas minors. These works are expected to employ about 6,000 persons for two months.

Soil conservation.—

Out of Rs. 10 lakhs sanctioned for the district, 50% is to be spent in Bwiwani Tehsil. Work in Lohani and Biran centres has already started and the work in the Jhumpa Kalan and Rodan centres is also being taken up shortly.

Johars

Out of Rs. 5 lakhs sanctioned for the district, Rs. 2 lakhs are to be utilized in about 20 villages of Bhiwani Tehsil.

4. Other Relief Measures

In addition to the steps mentioned above, Government has ordered

(1) *Remission of land revenue* according to the following scales:—

(a) where the damage to the crop is more than 50% .. total remission

(b) where the damage to crop is below 50% but more than 25% .. 75% remission

The total amount to be remitted is Rs. 1,13,000.

(2) *Suspension of Taccavi Loans.*—The recovery of all taccavi loans has been suspended till Rabi 1966. The amount involved is Rs. 16.42 lakhs.

(3) Highest priority to be given to Village Water-Supply Schemes and rural electrification.

(4) That a Recruiting Centre be opened in Hissar District.

5. *Other arrangements and Relief Measures taken by the Deputy Commissioners.*

(1) *Distribution of fodder.*—23 fodder depots are already functioning and several more are expected to be set up according to the needs of the affected areas. Fodder is being made available at subsidized rates. Rs. 1.75 lakhs have been sanctioned as fodder subsidy at @Rs. 0.75 per maund.

(2) *Fair Price Shops.*—Six wholesale depots have been set up in Bhiwani tehsil. These depots feed 57 sub-depots and each sub-depot serves 3 to 4 villages lying within a radius of five miles. The wholesale depots have adequate stocks of bajra, wheat and atta.

The Deputy Commissioner, who personally checked the functioning of fodder and foodgrain depots in several villages of Bhiwani Tehsil, has reported that they are functioning fairly efficiently and that the quality of fodder is fairly good.

(3) *Amenity articles.*—The following articles supplied by the District Red Cross have been distributed to needy people in the affected villages of Bhiwani Tahsil :—

(1)	Dhotis	..	44
(2)	Shirts of Mazri cloth	..	25
(3)	Shirts Mazri	..	14
(4)	Sweet shirts	..	24
(5)	Khes	..	46
(6)	Shirting cloth		98 pieces
(7)	Ribbed Ves cloth	..	71
(8)	Woollen jackets	..	32
(9)	Night Pyjama suits	..	25
(10)	Bed Sheets	..	77

(11) Woollen blankets .. 49

(12) Mazri cloth .. 45 pieces

(13) Vests cotton flannalette .. 52

6. Government is maintaining a constant vigil over the drought situation in Bhiwani Sub-Division and other affected parts of the State. Government has also appointed a Committee with the Financial Commissioner, Revenue as Chairman, to prepare a long-term plan for the drought affected areas of Hissar, Rohtak, Mahendragarh and Gurgaon Districts of the Haryana Region and certain parts of Hoshiarpur District. A special girdawari of all the districts affected by drought was also ordered some time ago and the results of this girdawari are due by 15th February, 1966. As soon as these results have been consolidated and examined, Government will consider such further relief measures as may be required.

Statement by the Irrigation and Power Minister in connection with Call Attention Notice (*Serial No. 221*) by Sardar Jasdev Singh Sandhu, M.L.A. regarding construction of V. R. Bridge at R. D. 104275 Narwana Branch

An estimate for the construction of village road bridge at R.D. 104275 Narwana Branch was sanctioned for Rs. 29,112 on 17th March, 1961. Some material for the construction of the Bridge was also collected and work allotted to the contractor.

2. In the mean time Government took the policy decision that for construction of bridges on Irrigation channels, the minimum distance for the provision of bridges on main canals should be 2.5 miles and on distributaries and minors, it should be 1.5 miles. It was also decided that provision should be made for construction of V.R. bridges on demand by the villagers provided:—

(i) the distance between the adjoining bridges is not less than 3/4 miles; and

(ii) the villagers contribute 50% of the cost of the bridges as estimated by the Department, without including establishment charges.

It has also been decided that in case the necessity of a bridge is great, but the villagers are not in a position to bear their share of cost, the demand should not be rejected out right, but the case should be considered by Government.

3. The case for construction of bridge at R.D. 104275 was examined in the light of the above policy of Punjab Government and it was found that bridges already exist at R.D. 98054 upstream and at R.D. 109961 downstream of the proposed site. The new bridge is thus proposed

from the nearest existing bridge at a distance of 1.14 canal miles and according to the above policy of the Government, the beneficiaries are required to contribute 50% of the cost of the bridge which they are not willing to pay.

4. The case is now further being examined in the light of Government policy referred to in the latter part of paragraph 2 above. For this purpose. the Superintending Engineer has been asked to report the paying capacity of the beneficiaries and on receipt of S.E.'s report, the matter will be considered by Government, if the bridge be constructed entirely/partly at Government cost.